



# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ५६

७ जुलाई, १९४६ से १३ जुलाई, १९४९ तक ।



मुद्रक

प्रधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेबन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद ।

१६५०

---

मूल्य बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने ।  
वार्षिक चम्पा बिता मजसल १० रुपये. मजसल सत्रित १२ रुपये ।





## विषय-सूची

बृहस्पतिवार, ७ जुनाई, १९४६ ई०

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची .. ..	१-४
प्रश्नोत्तर .. ..	५-३४
श्री भूवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद ..	३४-३६
श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद ..	३६-३९
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दूकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा .	४०
सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज स्टोरेज रिक्वीजिशन (कंदिनुएंस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा ..	४०
सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा .	४०
सन् १९४९ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा ..	४१
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनैस की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना ..	४१
सन् १९३९ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना ..	४१
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४१-६०
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (विशिष्ट समिति के अधीन करने के प्रस्ताव पर विवाद जारी) ..	६०-९१
नत्थियां .. ..	९२

शुक्रवार, ८ जुनाई, १९४६ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची .. ..	९९-१०१
प्रश्नोत्तर .. ..	१०२-१२०
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज मेटेनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही को वैध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज पर रखा जाना ..	१२०
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल (एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी) ..	१२०-१६५
नत्थियां .. ..	१६६-१७३

शनिवार, ६ जुलाई, १९४६ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	..	१७५—१७७
प्रश्नोत्तर	..	१७८—२००
सन् १९६८ ई० के संयुक्त प्रान्त के नई ओडने का और गाँठे बनाने के कार्यक्रम के विषय पर महामान्य गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की घोषणा	..	२००
सन् १९६८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिमिपैलिटीज ( असेडमेट ) बिल पर महामान्य गवर्नर-जनरल की स्वीकृति की घोषणा	..	२००
सन् १९६९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ( एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी )	..	२००—२६०
समाप्ति	..	२६१—२६९

स मवार, ११ जुलाई, १९४६ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	..	२७१—२७३
प्रश्नोत्तर	..	२७४—२९४
सन् १९६९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ( एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी )	..	२९५—३४८
समाप्ति	..	३४९—३५१

मंगलवार, १२ जुलाई, १९४६ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	..	३५३—३५५
असेम्बली में अनुपस्थित रहने के लिये श्री अजीज अहमद खान का प्रार्थना-पत्र (स्वीकृत)	..	३५६
संयुक्त प्रान्तीय डिम्बारट प्रिजनर्स ऐंड सोमाइटी की केन्द्रीय समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	३५६
सन् १९६९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ( एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार-जारी )	..	३५७—४१९

बुधवार, १३ जुलाई, १९४६ ई०

उपस्थित सदस्यों की सूची	..	४२१—४२३
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ( एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन करने का प्रस्ताव और सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित करने के संशोधन पर विचार जारी )	..	४२४—५०३

## शासन

गवर्नर

हिज एक्सलेन्सी श्री हारमसजी पेरोशा मोदी

सचिव-परिषद्

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा अर्थ, न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन सचिव ।

माननीय श्री मुहम्मद इब्नाहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, निर्माण सचिव ।

माननीय श्री संपूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा तथा श्रम सचिव ।

माननीय श्री हुकूम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, वन तथा माल सचिव ।

माननीय श्री निसार अहमद शेखानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन सचिव ।

माननीय श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर सचिव ।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वशासन सचिव ।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अन्न सचिव ।

माननीय श्री लालबहादुर, पुलिस तथा परिवहन सचिव ।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा प्रकाश सचिव ।

## सभा-मंत्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० ।

(२) श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० ।

(३) श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए० ।

माननीय निर्माण सचिव के सभा-मंत्री ।

(१) श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए० ।

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री महफूज़ुर्रहमान, एम० एल० ए० ।

माननीय उद्योग सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री बहीद अहमद, एम० एल० सी० ।

माननीय माल सचिव तथा कृषि सचिव के सभा-मंत्री—

(१) श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी० ।

मदभ्यः का प्रस्तावित सुची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल सिंह, श्री	..	आगरा नगर।
२—अजित प्रताप सिंह, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एशोसियेशन।
३—अजीज अहमद खा, श्री	..	बरेली-पीलीभीत नगर।
४—अब्दुल गनी अल्मारी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
५—अब्दुल बाकी, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पूर्व)।
६—अब्दुल मजीद, श्री	..	मुरादाबाद-अमरोहा-चन्दौसी नगर।
७—अब्दुल मजीद खान, श्री	..	अलीगढ़-हाथरस-मथुरा नगर।
८—अब्दुल बान्निद, श्रीमनी	..	जिला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)।
९—अब्दुल हमीद, श्री	..	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)।
१०—अम्मार अहमद खा. श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
११—अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१२—अनुराग टास्त्री, श्री	..	जिला आजमगढ़ (उत्तर-पूर्व)।
१३—अन्दी जरर जाफरी, श्री	..	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
१४—अल्फ्रेड धर्मदाम, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई।
१५—अ गज अली खा, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)।
१६—अध्यापक सिंह, श्री	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम)।
१७—आमाराग गोविन्द खेर, माननीय श्री	..	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर।
१८—आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्यम, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय एंग्लो इंडियन।
१९—इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री	..	जिला गाजीपुर (पश्चिम)।
२०—इनाम हबीबुल्ला, बेगम	..	लखनऊ नगर।
२१—उदयवीर सिंह, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)
२२—ऐजाज रसूल, श्री	..	जिला हरदोई।
२३—कमलापति निवारो, श्री	..	जिला बनारस (पूर्व)।
२४—करीमुरा खा, श्री	..	बदायूं-शाहजहाँपुर-संभल नगर।
२५—कालीचरण टंडन, श्री	..	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)।
२६—किशनचन्द पुरी, श्री	..	संयुक्त प्रान्तीय चेम्बर आफ कामर्स तथा संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
२७—कुंज बिहारीलाल शिवानी, श्री	..	जिला झांसी (उत्तर)।
२८—कुशलचन्द जैरोला, श्री	..	जिला गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम)।
२९—कृपाशंकर, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण)।
३०—कृष्णचन्द्र, श्री	..	जिला मथुरा (पश्चिम)।
३१—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	जिला सीतापुर (दक्षिण)।
३२—केशव गुप्त, श्री	..	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)।
३३—केशवदेव मालवीय, माननीय श्री	..	जिला मिर्जापुर (दक्षिण)।
३४—जानचन्द चौतम, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)।
३५—कृष्णचरण राय, श्री	..	जिला सीरी (उत्तर-पूर्व)।
३६—कृष्णीराम, श्री	..	जिला अल्मोड़ा।
३७—कृष्ण सिंह, श्री	..	जिला बिजनौर (पूर्व)।
३८—मंगेश्वर, श्री	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
३९—मंगलप्रसाद, श्री	..	जिला गढ़ा (उत्तर-पूर्व)।
४०—मंगलसहाय चौधरी, श्री	..	जिला कानपुर (पश्चिम)।
४१—मंगलप्रसाद, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)।
४२—मधुपति सहाय, श्री	..	जिला सुल्तानपुर।

४३—गणेशकृष्ण जैतजी, श्री	..	जिला फैजाबाद (पूर्व) ।
४४—गिरधारीलाल, माननीय श्री	..	जिला सह रनपुर (दक्षिण-पूर्व) ।
४५—गोपाल नारायण सक्सेना, श्री	.	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) ।
४६—गोविन्द वल्लभ पंत, माननीय श्री	..	बरेली-पीलीभीत-शाहजहापुर-बदायूं नगर ।
४७—गोविन्द सहाय, श्री	.	जिला बिजनौर (पश्चिम) ।
४८—चतुर्भुज शर्मा, श्री	.	जिला जालौन ।
४९—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	.	लखनऊ नगर ।
५०—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	.	जिला गोडा (दक्षिण) ।
५१—चरण सिंह, श्री	..	जिला मेरठ (दक्षिण-पश्चिम) ।
५२—चेतराम, श्री	.	जिला बाराबंकी (उत्तर) ।
५३—छेदालाल गुप्त, श्री	.	जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम) ।
५४—जगन्नाथदास, श्री	.	जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम) ।
५५—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री	.	जिला सीतापुर (पूर्व) ।
५६—जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन ।
५७—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	जिला बलिया (उत्तर) ।
५८—जगनप्रसाद रावत, श्री	.	जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम) ।
५९—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	.	जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व) ।
६०—जयकृष्ण श्रीवास्तव, श्री	.	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स ।
६१—जयपाल सिंह, श्री	..	जिला फैजाबाद (पूर्व) ।
६२—जयराम वर्मा, श्री	.	जिला बाराबंकी (उत्तर) ।
६३—जवाहरलाल रोहतगी, श्री	..	कानपुर नगर ।
६४—जहीरुल हसनैन लारी, श्री	..	जिला गोरखपुर (पूर्व) ।
६५—जहर अहमद, श्री	..	इलाहाबाद-झासी (नगर) ।
६६—जाकिर अली, श्री	..	आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर ।
६७—जाहिद हसन, श्री	..	जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम) ।
६८—जुगुल किशोर, श्री	..	मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर ।
६९—त्रिलोकी सिंह, श्री	..	जिला लखनऊ ।
७०—दयाल दास भगत, श्री	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व) ।
७१—दाऊदयाल खन्ना, श्री	.	मुरादाबाद (पूर्व) ।
७२—द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री	..	जिला जौनपुर (पूर्व) ।
७३—दीनदयालु अवस्थी, श्री	..	जिला इटावा (पश्चिम) ।
७४—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ्फरनगर नगर ।
७५—दीपनारायण वर्मा, श्री	.	जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर ।
७६—नफीसुल हसन, श्री	..	जिला इटावा और कानपुर ।
७७—नवाजिश अली खां, श्री	..	फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर ।
७८—नवाब सिंह चौहान, श्री	..	जिला अलीगढ़ (पूर्व) ।
७९—नाजिम अली, श्री	..	जिला सुल्तानपुर ।
८०—नारायण दास, श्री	..	लखनऊ नगर ।
८१—निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री	..	जिला मेनपुरी और एटा ।
८२—नेहालुद्दीन, श्री	..	जिला बदायूं (पूर्व) ।
८३—परागीलाल, श्री	..	जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम) ।
८४—पुरुषोत्तम दास टंडन, माननीय श्री	..	इलाहाबाद नगर ।
८५—पूर्णमासी, श्री	..	जिला गोरखपुर (उत्तर) ।

- ८३—पूजिमा बनर्जी, श्रीमती  
 ८३—प्रकाशबनी सूद, श्रीमती  
 ८८—प्रयाग नागायण, श्री  
 ८९—प्रेमकिशन खन्ना, श्री  
 ९०—फखरुल इस्लाम, श्री  
 ९१—फजलुर्हमान खां, श्री  
 ९२—फतेह मिह राणा, श्री  
 ९३—फलाज अली, श्री  
 ९४—फतेह मिह, श्री  
 ९५—बदन मिह, श्री  
 ९६—बलराम दाम, श्री  
 ९७—बलदेव प्रसाद, श्री  
 ९८—बलराम मिह, श्री  
 ९९—बशीर अहमद हकीम, श्री  
 १००—बशीर अहमद अन्सारी, श्री  
 १०१—बादशाह गुप्त, श्री  
 १०२—बाबराम वर्मा, श्री  
 १०३—बृजमोहनलाल शास्त्री, श्री  
 १०४—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री  
 १०५—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री  
 १०६—भगवानदीन, श्री  
 १०७—भगवानदीन मिश्र, श्री  
 १०८—भगवान मिह, श्री  
 १०९—भारत सिंह यादवाचार्य, श्री  
 ११०—भीमसेन, श्री  
 १११—मंगलाप्रसाद, श्री  
 ११२—मनुरियादीन, श्री  
 ११३—महफूजुर्हमान, श्री  
 ११४—महमूद अली खां, श्री  
 ११५—मिजाजी लाल, श्री  
 ११६—मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री  
 ११७—मुजफ्फर हुसैन, श्री  
 ११८—मुनफैत अली, श्री  
 ११९—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री  
 १२०—मुहम्मद असगर अमहद, श्री  
 १२१—मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री  
 १२२—मुहम्मद इस्माईल, श्री  
 १२३—मुहम्मद उबैदुर्हमान खां शेखानी, श्री  
 १२४—मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री  
 १२५—मुहम्मद नबी, श्री  
 १२६—मुहम्मद नबीर, श्री

- .. जिला फर्रुखाबाद (उत्तर) ।  
 .. जिला मेरठ (उत्तर) ।  
 .. अवध का ब्रिटिश इंडियन एसो-  
 सिएशन ।  
 .. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम) ।  
 .. जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-  
 पूर्व) ।  
 .. जिला शाहजहांपुर ।  
 .. जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) ।  
 .. जिला फेजाबाद  
 .. जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व) ।  
 .. जिला बदायूं (पश्चिम) ।  
 .. जिला बुलन्दशहर (उत्तर) ।  
 .. जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व) ।  
 .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. जिला सीतापुर ।  
 .. जिला बिजनौर (दक्षिण-पूर्व) ।  
 .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व) ।  
 .. जिला एटा (उत्तर) ।  
 .. जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम) ।  
 .. कानपुर नगर ।  
 .. जिला बहराइच (दक्षिण) ।  
 .. जिला पीलीभीत (दक्षिण) ।  
 .. जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. जिला बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. जिला रायबरेली (दक्षिण-पश्चिम) ।  
 .. इलाहाबाद नगर ।  
 .. जिला बहराइच (दक्षिण) ।  
 .. देहरादून-हरिद्वार-सहारनपुर-मुजफ्फरनगर  
 नगर ।  
 .. जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व) ।  
 .. जिला पीलीभीत (उत्तर) ।  
 .. लखनऊ नगर ।  
 .. जिला सहारनपुर (उत्तर) ।  
 .. जिला बस्ती (पश्चिम) ।  
 .. जिला बदायूं (पश्चिम) ।  
 .. जिला गढ़वाल और बिजनौर (उत्तर-  
 पश्चिम) ।  
 .. जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पूर्व) ।  
 .. जिला अलीगढ़ ।  
 .. जिला मेरठ (पश्चिम) ।  
 .. जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व) ।  
 .. जिला बनारस और मिर्जापुर ।

१२७—मुहम्मद फाहूर, श्री	..	जिला गोरखपुर (पश्चिम) ।
१२८—मुहम्मद याकूब, श्री	..	जिला गाजीपुर और बलिया ।
१२९—मुहम्मद मुसुक, श्री	..	जिला इलाहाबाद (दक्षिण-पश्चिम) ।
१३०—मुहम्मद रजा खा, श्री	..	जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम) ।
१३१—मुहम्मद शकर, श्री	..	बनारस—मिर्जापुर नगर ।
१३२—मुहम्मद शमी, श्री	..	जिला रायबरेली ।
१३३—मुहम्मद शाहिद फाखरे, श्री	..	लखनऊ नगर ।
१३४—मुहम्मद शौकत अली खां, श्री	..	जिला बुलन्दशहर (पश्चिम) ।
१३५—मुहम्मद सनादत अली खां, श्री	..	जिला बहराइच (उत्तर) ।
१३६—मुहम्मद सुदेमान अहमदी, श्री	..	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व) ।
१३७—यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री	..	जिला बनारस (पश्चिम) ।
१३८—रघुनाथ विनयक धुलेकर, श्री	..	जिला झांसी (दक्षिण) ।
१३९—रघुनाथ नारायण मिह, श्री	..	जिला मेरठ (पूर्व) ।
१४०—रघुबीर सहाय, श्री	..	जिला बदायूं (पूर्व) ।
१४१—राघवदास, श्री	..	फैजाबाद—बहराइच—सीतापुर नगर ।
१४२—राजकुमार मिह, श्री	..	आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन ।
१४३—राजाराम मिश्र, श्री	..	जिला फैजाबाद (पश्चिम) ।
१४४—राजाराम शास्त्री, श्री	..	कानपुर औद्योगिक फैक्टरी श्रम ।
१४५—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	जिला हरदोई (मध्य) ।
१४६—राधामोहन सिंह, श्री	..	जिला बलिया (दक्षिण) ।
१४७—राधेश्याम शर्मा, श्री	..	जिला बस्ती (पश्चिम) ।
१४८—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व) ।
१४९—रामकृपाल मिह, श्री	..	बुलन्दशहर—मेरठ—हापुड़—खुर्जा नगीना नगर ।
१५०—रामचन्द्र पालीवाल, श्री	..	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व) ।
१५१—रामचन्द्र सेहरा, श्री	..	आगरा नगर ।
१५२—रामजी सहाय, श्री	..	जिला गोरखपुर (मध्य) ।
१५३—रामधर मिश्र, श्री	..	इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्व-विद्यालय ।
१५४—रामधारी पांडे, श्री	..	जिला गोरखपुर (उत्तर-पूर्व) ।
१५५—रामनारायण, श्री	..	अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स ।
१५६—रामबली, श्री	..	जिला सुल्तानपुर (पूर्व) ।
१५७—राममूर्ति, श्री	..	जिला बरेली (उत्तर-पूर्व) ।
१५८—राम शंकर लाल, श्री	..	जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व) ।
१५९—रामशरण, श्री	..	मुरादाबाद—अमरोहा—संभल—चन्दौसी नगर ।
१६०—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	जिला कानपुर (दक्षिण) ।
१६१—रामेश्वर सहाय सिंह, श्री	..	जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व) ।
१६२—रघुनुद्दीन खां, श्री	..	जिला प्रतापगढ़ ।
१६३—रोशन जमा खां, श्री	..	जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम) ।
१६४—लक्ष्मी देवी, श्रीमती	..	जिला फैजाबाद (पश्चिम) ।
१६५—लताफत हुसैन, श्री	..	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम) ।
१६६—लालनदास जाटव, श्री	..	जिला बदायूं (पूर्व) ।
१६७—लालबहादुर, माननीय श्री	..	जिला इलाहाबाद (गंगापार) ।
१६८—लालबिहारी टंडन, श्री	..	जिला गोंडा (पश्चिम) ।
१६९—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	जिला उन्नाव (पूर्व) ।



१३०—सुरकमलानी खा, श्री	..	जिला मेरठ (पूर्व) ।
१३१—सादतुराम, श्री	..	जिला जालौन ।
१३२—बसोपाल, श्री	..	जिला फतेहपुर (पूर्व) ।
१३३—बशीर मिश्र, श्री	..	जिला खारी (दक्षिण-पश्चिम) ।
१३४—विजयानन्द मिश्र, श्री	..	जिला मिर्जापुर (उत्तर) ।
१३५—विद्युधर बाजपेयी, श्री	..	जिला मुन्नानपुर (पश्चिम) ।
१३६—विद्युधर झाडा, श्रीमती	..	जिला एटा (दक्षिण) ।
१३७—विनय कुमार मुखर्जी, श्री	..	लायनऊ-आगरा-अलीगढ़-इलाहाबाद औद्योगिक फेडररी श्रम ।
१३८—विजयनाथ प्रसाद, श्री	..	जिला मिर्जापुर (उत्तर) ।
१३९—विजयनाथ राय, श्री	..	जिला गार्जीपुर (पूर्व) ।
१४०—विजयनाथ ठाकुर त्रिपाठी, श्री	..	जिला उन्नाव (पश्चिम) ।
१४१—विजयनाथ दुमिल, श्री	..	जिला मेरठ (उत्तर) ।
१४२—बजरंग सिंह, श्री	..	जिला जौनपुर (पश्चिम) ।
१४३—बोरहण शाह, श्री	..	आगरा प्रान्त जर्मदार एसोसियेशन ।
१४४—बेहटा नारायण निवारो, श्री	..	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व) ।
१४५—शकर बहादुर शर्मा, श्री	..	जिला मुरादाबाद (पश्चिम) ।
१४६—शक्ति प्रयत्न शर्मा, श्री	..	जिला देहरादून ।
१४७—शिवकुमार पाण्डेय, श्री	..	जिला इलाहाबाद (द्वारा) ।
१४८—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	जिला शाहजहापुर (पश्चिम) ।
१४९—शिव दयाल उपाध्याय, श्री	..	जिला फतेहपुर (पश्चिम) ।
१५०—शिवदान सिंह, श्री	..	जिला अलीगढ़ (पश्चिम) ।
१५१—शिवशङ्कर सिंह, श्री	..	जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम) ।
१५२—शिवमगल सिंह कपुर, श्री	..	जिला आजमगढ़ (दक्षिण) ।
१५३—श्यामलाल वर्मा, श्री	..	जिला नैनीताल ।
१५४—श्याममन्दर शुक्ल, श्री	..	जिला प्रतापगढ़ (पूर्व) ।
१५५—श्रीधर मिश्र, श्री	..	जिला अलीगढ़ (मध्य) ।
१५६—श्रीपति शर्मा, श्री	..	जिला हमीरपुर ।
१५७—मज्जनदेवी मज्जन, श्रीमती	..	बनारस नगर ।
१५८—संयुक्तानन्द, माननीय श्री	..	बनारस नगर ।
१५९—मन्मत हुसैन, श्री	..	जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व) ।
२००—मल्लोम नामिब खा, श्री	..	जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर ।
२०१—माजिद हुसैन, श्री	..	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ।
२०२—मास्तिनाम बयसवाल, श्री	..	जिला इलाहाबाद (यमुनापार) ।
२०३—सिद्धान्त सिंह, श्री	..	जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व) ।
२०४—सिराज हुसैन, श्री	..	जिला पीलीभीत ।
२०५—सीताराम अठाला, श्री	..	जिला आजमगढ़ (पश्चिम) ।
२०६—सुबेता कृष्णानी, श्रीमती	..	जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व) ।
२०७—सुबामाप्रसाद, श्री	..	जिला गोरखपुर (उत्तर) ।
२०८—सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	..	जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व) ।
२०९—सुन्मान कालम खा, श्री	..	जिला फर्रुखाबाद ।
२१०—सूर्य प्रसाद अबरही, श्री	..	जिला उन्नाव (दक्षिण) ।
२११—सईद अहमद, श्री	..	जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर) ।
२१२—सुबोधका अम्सारी, श्री	..	जिला लखनऊ तथा उन्नाव ।

( ३ )

- २१३—हबीबुर्रहमान खां, श्री  
 २१४—हरगोविन्द पन्त, श्री  
 २१५—हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री  
 २१६—हरप्रसाद मिह, श्री  
 २१७—हरिहरनाथ गास्त्री, श्री  
 २१८—हसन अहमद शाह, श्री  
 २१९—हमरत मोहानी, श्री  
 २२०—हिफजुर्रहमान खां, श्री  
 २२१—हुकुम सिंह, माननीय श्री  
 २२२—होतीलाल अग्रवाल, श्री  
 २२३—हैदर बख्श, श्री  
 २२४—( रिक्त )  
 २२५—( रिक्त )  
 २२६—( रिक्त )

- .. जिला खीरी।  
 .. जिला अल्मोड़ा।  
 .. जिला बाराबंकी (दक्षिण)।  
 .. जिला बांदा (दक्षिण)।  
 .. ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्र।  
 .. जिला फतेहपुर और बांदा।  
 .. कानपुर नगर।  
 .. मेरठ—हापुड़—बुलन्दशहर—धुर्जा—नगीना  
 नगर।  
 .. जिला बहराइच (उत्तर)।  
 .. जिला इटावा (पूर्व)।  
 .. जिला मथुरा तथा आगरा।  
 .. जिला बाराबंकी, मुस्लिम ग्रामीण  
 .. जिला बांदा (उत्तर), सामान्य ग्रामीण  
 .. जिला बस्ती (दक्षिण-पूर्व), मुस्लिम ग्रामीण



( अ )

## संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

के

### पदाधिकारी

स्पीकर

१—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, एम० ए०, एल—एल० बी० ।

डिप्टी स्पीकर

२—श्री नफीसुल हसन, एम० ए०, एल—एल० बी० ।

सेक्रेटरी

३—श्री कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए० ।

असिस्टेंट सेक्रेटरी

४—श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए० ।

सुपरिण्टेण्डेंट

५—श्री राघोरमण सक्सेना, एम० ए०, एल—एल० बी०, डी० एल० एस०—सी० ।

६—श्री सी० जे० एडम्स, बी० ए० ।



# संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बृहस्पतिवार, ७ जुलाई, सन् १९४६ ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली-भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

## उपस्थित सदस्यों की सूची ( १६१ )

अचल सिंह	कालीचरण टण्डन
अजित प्रताप सिंह	किशनचन्द पुरी
अर्दाल अब्बासी	कुंज बिहारी लाल शिवानी
अब्दुल गनी अंसारी	कुशलानन्द गैरोला
अब्दुल मजीद	कुपाशीकर
अब्दुल मजीद खवाजा	कृष्ण चन्द्र
अब्दुल वाजिद, श्रीमती	कृष्ण चन्द्र गुप्त
अब्दुल हमीद	केशव गुप्त
अम्मार अहमद खाँ	केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
अर्नेस्ट माइकेल फ्रिजिप्स	खानचन्द गौतम
अलगूराय शास्त्री	खुशबक्त राय
अल्फ्रेड, धर्मदास	खुशीराम
अली जरौर जाफरी	खुश सिंह
अष्टयवर सिंह	गजाधर प्रसाद
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	गणपति सहाय
आर्चिबाल्ड, जेम्सफ्रैथम	गणेश कृष्ण जैतली
इन्द्रदेव त्रिपाठी	गिरधरालाल, माननीय श्री
इनाम हजीबुल्ला, श्रीमती	गोपाल नारायण सक्सेना
एजाज रसूल	गोविन्द वरजभ पन्त, माननीय श्री
करीमुर्रजा खाँ	गोविन्द सहाय

गंगाधर  
 गंगा प्रसाद  
 गंगा सहाय चौधे  
 चतुर्मुख कर्मा  
 चन्द्रमानु गुप्त, माननीय श्री  
 चन्द्रमानु शरदा सिंह  
 चरक सिंह  
 चेतनाम  
 छेदाकाश गुप्त  
 जगन्नाथ दास  
 जगन्नाथ प्रसाद  
 जगन्नाथ सिंह  
 जगन्नाथ बरकत सिंह  
 जगन प्रसाद राय  
 जगमोहन सिंह नेगी  
 जगमोहन अली खान  
 जवाहरलाल रोहतगी  
 कादिर हसन  
 कुमुद चिरोर  
 कोकिल सिंह  
 कच राम कर्मा  
 दवाकदास मजरा  
 दाऊदास कल  
 हारिक प्रभाद मोर  
 दीन दवाहू जयराणी  
 दीन दवाहू शास्त्री  
 दीप नारायण कर्मा  
 जयसुख हसन  
 नवान सिंह  
 जयसिंह कली  
 जयसिंह दास  
 निहार अहमद रोहवाली, माननीय श्री  
 निहामुदीन  
 पूर्णसिंह कर्मा, श्रीवती  
 पूर्णसिंह  
 नारायण दास, श्रीमती

प्रागनारायण  
 परागीलाल  
 कलकल इस्लाम  
 कतेह सिंह राणा  
 फूख सिंह  
 बदन सिंह  
 बंश गोपाल  
 बनारसी दास  
 बलदेव प्रसाद  
 बलभद्र सिंह  
 बशीर अहमद  
 बशीर अहमद जंजारी  
 बाहराद गुप्त  
 बीरबल सिंह  
 बृजमोहनलाल शास्त्री  
 भगवती प्रसाद दुबे  
 भगवती प्रसाद शुक्ल  
 भगवानदीन  
 भगवानदीन मिश्र  
 भगवान सिंह  
 भारत सिंह बालाचार्न  
 भीम सेन  
 भंगल प्रसाद  
 भसुनिवा दीन  
 महफूजुर्रहमान  
 महमूद अली खान  
 मिर्जाजी कल  
 मुकुन्दलाल अमरनाथ  
 मुनजैत अली  
 मुकेशकर हुसैन  
 मुहम्मद अखतर अहमद  
 मुहम्मद इफ्तीम, माननीय श्री  
 मुहम्मद नबीर  
 मुहम्मद फारूक  
 मुहम्मद फारूक  
 मुहम्मद वसुध

## उपस्थित सदस्यों की सूची

मुहम्मद रजा खॉ  
 मुहम्मद शकूर  
 मुहम्मद शाहिद फाखरी  
 मुहम्मद शौकत अली खॉ  
 मुहम्मद सुलेमान अबमी  
 यज्ञनारायण उपाध्याय  
 रघुनाथ विनायक धुलेकर  
 रघुबीर सहाय  
 रघुवंशनारायण सिंह  
 राजब दास  
 राजकुमार सिंह  
 राजाराम मिश्र  
 राजाराम शास्त्री  
 राधाकृष्ण अभवाल  
 राधामोहन सिंह  
 राधेश्याम शर्मा  
 राम कुमार शास्त्री  
 रामकुमार सिंह  
 रामचन्द्र सेहरा  
 रामचन्द्र पालीवाल  
 रामजी सहाय  
 रामधर मिश्र  
 रामधारी पांडे  
 राम नारायण  
 रामबली  
 रामशंकर लाल  
 राम शरण  
 राम स्वरूप गुप्त  
 रामेश्वर सहाय सिंह  
 रक्तुद्दीन खॉ  
 रोशन ज़मा खॉ  
 रुक्मी देवी, श्रीमती  
 रत्नप्रत हुसैन  
 रत्नान दास जाटव  
 रत्नबहादुर, माननीय श्री

लाल बिहारी टुण्डन  
 लीलाधर अष्ठाना  
 लोटन राम  
 विजयानन्द मिश्र  
 विद्यावती राठौर, श्रीमती  
 विनय कुमार मुकजी  
 विश्वनाथ प्रसाद  
 विश्वनाथ राय  
 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी  
 विष्णु शरण कुब्लिश  
 बीरेन्द्र शाह  
 बंशीधर मिश्र  
 बेंकटेश नारायण तिवारी  
 शंकर दत्त शर्मा  
 शान्ति प्रपन्न शर्मा  
 शिव कुमार पाण्डेय  
 शिव कुमार मिश्र  
 शिव दयाल उपाध्याय  
 शिवदान सिंह  
 शिवमंगल सिंह कपूर  
 सुचेता कृपलानी, श्रीमती  
 श्याम लाल वर्मा  
 श्याम सुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द सिंघल  
 श्रीपति सहाय  
 सच्चादत अली खॉ, मुहम्मद  
 सज्जन देवी महनोत, श्रीमती  
 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 साजिद हुसैन  
 सालिग्राम जैसवाल  
 सिंहासन सिंह  
 सिराज हुसैन  
 सीताराम अष्ठाना  
 सुदामा प्रसाद  
 सुरेन्द्र बहादुर सिंह



मूलान अन्न खा  
 मूलप्रसाद अन्नस्थ  
 मूलप्रसाद अन्न  
 मूलप्रसाद अन्न  
 मूलप्रसाद अन्न

हरगोविन्द पन्त  
 हरप्रसाद सत्यप्रेमी  
 हंती लाल अन्नवाल  
 त्रिलोकी सिंह

---

## प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ७ जुलाई, सन् १९४६ ई०

### ताराङ्कित प्रश्न

प्रान्त में गेहूँ, चना, मक्का इत्यादि की उत्पत्ति तथा बाहर से आये हुये अनाज की मात्रा

\* १—श्री .रावत्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि:—  
(क) सन् १९४६-१९४७ व १९४८ ई० के वर्षों में कुल कितनी भूमि पर प्रान्त में कृषि की गई ?

(ख) इन सालों में कितनी-कितनी भूमि पर गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की काश्त की गई ?

(ग) इन सालों में कितनी-कितनी उत्पत्ति गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की हुई ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९३७ ई० से लेकर सन् १९४५ ई० तक प्रतिवर्ष कितनी उत्पत्ति, गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, धान, मकाई, बाजरा व रुई की हुई ?

(ङ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त की वर्तमान जन-संख्या को देखते हुए प्रान्त को प्रतिवर्ष कितने अनाज की आवश्यकता होती है ?

(च) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४६, १९४७ व १९४८ ई० के वर्षों में कितना अनाज बाहर से क्रय किया गया ?

(छ) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन वर्षों में बाहर से क्रय किये जानेवाले अनाज पर प्रान्तीय सरकार को अपने पास से कितना व्यय करना पड़ा ?

माननीय कृषि सचिव ( श्री निसार अहमद शेरवानी )—

(१) सन् १९४६, १९४७ व १९४८ का कृषि क्षेत्रफल निम्नलिखित है—

साल		क्षेत्रफल
१९४५-४६ ( १३५३ फसली )	...	३, ६७, ८०, ६६३ एकड़
१९४६-४७ ( १३५४ फसली )	...	३, ६५, ३८, ८५० ,,
१९४७-४८ ( १३५५ फसली )	...	३, ६६, ५५, ३८२ ,,

- (क), आवश्यक सूचना मंलग्न विवरण पत्र संख्या 'अ' में प्रस्तुत है।  
 (ग) आवश्यक सूचना मंलग्न विवरण पत्र संख्या 'ब' में प्रस्तुत है।  
 (द), सब प्रकार के अनाजों की खपत का वार्षिक तत्वमीना १,०२,५८, ५३२ टन है। उन आँकड़ों में जो अनाज, वज और मवेशियों के चारे के लिये इस्तेमाल होते हैं अनाज व्यय हो जाता है, वह नहीं शामिल है।  
 (च) आवश्यक सूचना मंलग्न विवरण पत्र संख्या 'स' में दी हुई है।  
 (झ) इन बारे में सूचना नहीं मिल सकी, क्योंकि बाहर से मंगाये गये और स्थानीय खरीद से हासिल किये गये गन्ने के सम्बन्ध में लाभ या हानि का हिसाब अलग-अलग नहीं रक्खा गया है।

( देखिये नंथी 'क' आगे पृष्ठ ६२ पर )

**श्री रामजी महाय—**क्या यह सत्य है कि सन् १९४० में प्रति एकड़ गन्नों की वज्र ३२० मन थी, और आज वह १२४ मन प्रति एकड़ रह गयी है ?

**माननीय कृषि सचिव—**मेरे खयाल में यह आँकड़े सही नहीं हैं, मगर मैं इसके मुनास्सिक सही तौर से जवाब देने के लिये नोटिस चाहता हूँ।

**श्री खानचन्द गौतम—**क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४६ से १९४८ तक जो गन्ने की काश्त बढ़ती गई है, उसकी वजह क्या है ?

**माननीय कृषि सचिव—**इसकी कई वजहें हैं। एक तो कीमत का मसला है। जिसमें किमान का ज्यादा कायदा होता है। उसी तरह किसान जाता है। चूँकि गन्ने की कीमतें बढ़ती गईं, इसलिये गालिवन् रकबा भी बढ़ता गया।

**श्री खानचन्द गौतम—**प्रान्त में अनाज की कमी को देखते हुए प्रान्तीय सरकार ने गन्ने की पैदावार कम करने और उसकी जमीन को अनाज की पैदावार में लाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ?

**माननीय कृषि सचिव—**गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई कानूनी कार्यवाही अभी तक नहीं की है। यह एक इकनामिक फेक्टर ( आर्थिक कारण ) है, जिसके ऊपर इस बिल गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है।

**श्री शिवकृष्ण राय—**क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय जो अनाज की कमी है, उसको हम कब तक पूरा कर लेंगे ?

**माननीय कृषि सचिव—**सन् १९५१ तक इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

## प्रश्नोत्तर

**श्री खान चन्द गौतम**—क्या हमारे प्रान्त में कृषि प्लानिंग वा कोई सिस्टम जारी है ?

**माननीय कृषि सचिव**—जी, नहीं ।

**श्री गणेश कृष्ण जैतली**—सूबे के अन्दर जो रास्ते की पैदावार है, वह खेती की पैदावार के अनुपात में कितने वर्ष में उस अभाव को पूरा कर देगी ?

**माननीय कृषि सचिव**—इसका इनहसार उस लगन के ऊपर है । जो जनता में पैदा हो और उस उत्साह के ऊपर है जो किसान में पैदावार की वृद्धि करने में पैदा हो ।

## प्रान्त में गूँगे और बहरों की शिक्षा का प्रबन्ध

\* २—**श्री हरगोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )**—क्या युक्त प्रान्तीय सरकार ने गूँगे और बहरों की शिक्षा के निमित्त कोई शिक्षणालय खोला है ?

**माननीय शिक्षा सचिव ( श्री सम्पूर्णानन्द )**—लखनऊ के गूँगे और बहरों के स्कूल के अधिकारियों ने एक शिक्षणालय इस निमित्त खोला है । उसको सरकार से अनुदान मिलता है । सरकार ने कोई शिक्षणालय नहीं खोला है ।

\* ३—**श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )**—इस शिक्षणालय में कितने अध्यापक शिक्षाक्रम की शिक्षा ले रहे हैं ?

**माननीय शिक्षा सचिव**—ग्यारह अध्यापक ।

\* ४—**श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )**—उक्त अध्यापकों की शिक्षा की अवधि कितनी है ? और किन-किन विषयों में उन्हें शिक्षा दी जा रही है ?

**माननीय शिक्षा सचिव**—एक वर्ष । नीचे दिये हुये चार विषयों में शिक्षा दी जाती है—

( १ ) मूक, बधिर शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान ।

( २ ) बोना और बोली पढ़ाना ।

( ३ ) मूक, बधिर शिक्षा का इतिहास उनको पढ़ाने की भिन्न-भिन्न प्रणाली ।

( ४ ) कक्षा-प्रबन्ध, स्वास्थ्य, शारीरिक और खाद्य विज्ञान ।

❧ ५—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—इस अध्यापकों को किस संस्था में रोजगार मिलाना जा रहा है और उस संस्था में कितने मूक और बधिर विद्यार्थी हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव—गंगे और बधिरों का स्कूल लखनऊ, लगभग ३५ विद्यार्थी

❧ ६—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—अध्यापकों का शिक्षण इन समय कौन-कौन कर रहे हैं ? उनकी योग्यता क्या है और उन्हें क्या वेतन मिलना है ?

माननीय शिक्षा सचिव—श्री शैलेन्द्र नाथ बनर्जी एम० ए०, ग्लाउडेट कालेज अमेरिका ५५ वर्ष का अनुभव डेढ़ व डेढ़ स्कूल में, ३७५ रु० मासिक ।

❧ ७—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—इस वर्ष की पढ़ाई में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

माननीय शिक्षा सचिव—लगभग १५००० रुपया जिसमें अध्यापकों की दरभार भी सम्मिलित है ।

❧ ८—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—क्या शिक्षा का काम सीखने-बातें अध्यापकों को कुछ बजोका मिलना है ? यदि हाँ, तो कितना ?

माननीय शिक्षा सचिव—जी हाँ । ३० रु० मासिक के हिसाब से ।

❧ ९—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—सरकार अध्यापकों की शिक्षा पूरी होने पर उनसे क्या और कहाँ काम लेना चाहती है ?

माननीय शिक्षा सचिव—पुराने और नये खोले जानेवाले स्कूलों में ।

किस्मत कुमायूँ में मूक और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध

❧ १०—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—सन् १९४१ ई० की जनगणना के अनुसार किस्मत कुमायूँ में कितने मूक और बधिर थे ?

माननीय शिक्षा सचिव—यह सूचना प्राप्त नहीं है ।

❧ ११—श्री हर गोविन्द पन्त ( अनुपस्थित )—क्या सरकार कुमायूँ में मूक और बधिरों के लाभ के लिए कोई पाठशाला खोलना चाहती है ?

**माननीय शिक्षा सचिव—**नये स्कूल खोलते समय इस पर विचार किया जायगा।

### खीरी में सीमेंट का वितरण

❁ १२—**श्री खुशवक्त, राय—**(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में सन् १९४८ ई० में प्रतिमास कितनी सीमेंट आयी ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जितनी सीमेंट आयी, उसमें से कितनी शहरवालों को और कितनी गाँववालों को दी गयी ? उनका अनुपात क्या रहा ?

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि सीमेंट वितरण के लिए जो हाउसिंग कमेटियाँ जिले जिले में बनायी गयी हैं, उनसे सीमेंट का मिलना सरल नहीं, किन्तु दुष्कर हो गया है ?

**माननीय अन्न सचिव ( श्री चन्द्रभानु गुप्त )—**(क) फरवरी, १९४८ ई० में ४२० बोरे, अगस्त १९४८ ई० में ११६४ बोरे, अक्टूबर १९४८ ई० में ३८० बोरे, कुल १९६४ बोरे।

(ख) ५०४ बोरे शहरी क्षेत्रों में और ४८२ बोरे देहाती क्षेत्रों में इस्तेमाल में आये। इनका अनुपात  $१\frac{२२}{२३}$  है।

(ग) नहीं।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—**क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विदेशी सीमेंट पर कोई नियंत्रण है या नहीं ?

**माननीय अन्न सचिव—**नियंत्रण इस तरह से तो नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेड सीमेंट सूबे में आती है, उसकी कीमत के ऊपर अब प्रान्तीय सरकार ने ज़रूर नियंत्रण सा कर दिया है।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—**क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न जिलों में विदेशी सीमेंट के भाव विभिन्न हैं ?

**माननीय अन्न सचिव—**हाँ, ऐसा है।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—**यह विभिन्न जिलों में दामों में फर्क क्यों है ?

**माननीय अन्न मन्त्रि—**मुख्यतः जगहों में सीमेंट मुख्यतः दामों पर काम है और हमने जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया है कि वे ऐसी सीमेंट की कीमत तय करें और जिन मुन का निर्धारित करके वहाँ पर सीमेंट के बिना काम की जायत का इन्तजाम करें।

**श्री गधाकृष्ण अग्रवाल—**यह दाम जिला मैजिस्ट्रेट किस आधार पर कायम करने हैं यह इनकी खुशी पर है जितना दाम चाहें निर्धारित कर दें ?

**माननीय अन्न सचिव—**दाम कीमत, ट्रान्सपोर्ट चार्ज, हैंडलिंग चार्ज इत्यादि का नज़र में रखकर जिला मैजिस्ट्रेट तय करते हैं।

**श्री गधाकृष्ण अग्रवाल—**क्या सरकार को पता है कि विदेशी सीमेंट के ऊपर नियंत्रण लगाने से विदेशी सीमेंट की बहुत कमी हो गई है ?

**माननीय अन्न सचिव—**नहीं, येनी बात तो नहीं है। जहाँ-जहाँ विदेशी सीमेंट पर जिला मैजिस्ट्रेटों ने नियंत्रण लगाया है वहाँ-वहाँ पर दाम घटे हैं, न कि बढ़े हैं।

### विभिन्न जिलों में स्त्रियों को भगानेवाला संगठित गुंडों का गिरोह तथा उसकी रोकथाम

❧ १३—**श्री अचल सिंह—**क्या सरकार को मालूम है कि आगरा, मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ आदि जिलों में संगठित गुंडों के गिरोह हैं जो स्त्रियों और लड़कियों को भगाकर लाते हैं और उनका व्यापार करते हैं ?

**माननीय पुलिस सचिव ( श्री लाल बहादुर )—**सरकार को सूचना मिली है कि औरतो और लड़कियों के भगाने के लिये इन पाँच जिलों में गुंडों के संगठित गिरोह तो नहीं हैं परन्तु आगरा, मथुरा व मेरठ जिलों में कुछ ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं का पता अवश्य चला है जो कि व्याह कराने के बहाने औरतों को भगाकर बेच देते थे। उनके खिलाफ जाँच हो रही है।

**श्री अचल सिंह—**क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो जाँच सरकार इन संस्थाओं और व्यक्तियों की कर रही है उसका क्या नतीजा हुआ ?

**माननीय पुलिस सचिव—**पूरा ब्योरा देने के लिये मुझे नोटिस चाहिये।

❧ १४—**श्री अचल सिंह—**क्या सरकार ने इस गुंडेपन की कुप्रथा को रोकने का कोई प्रयत्न किया है ? यदि हाँ, तो क्या ?

**माननीय पुलिस सचिव—**इस प्रकार की संस्थाओं तथा व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है तथा उनके सहायक व साथियों को ढूँढ़ निकालने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। अन्य प्रान्तों में उनकी शाखाओं का पता चलाने के लिये सी० आई० डी० की सहायता ली जाती है।

**श्री अचल सिंह—**क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की संस्थाओं और व्यक्तियों पर किस प्रकार की कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है और उनको ढूँढ़ने के क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**माननीय पुलिस सचिव—**प्रयत्न की बात तो मैंने अपने जवाब में बतलाई है कि इन लोगों के कई ऐसी जगहों पर रेडूम किये गये। जहाँ इस प्रकार की संस्थाएँ कायम हैं वहाँ तलाशी ली गई और कुछ उनके अकम्पलिसेज भी पकड़े गये। फीरोजाबाद वगैरह में कई गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमें वगैरह भी चलाये गये।

**श्री अचल सिंह—**अन्य प्रान्तों में सी० आई० डी० विभाग से पता लगाने में कहाँ तक कामयाबी हुई ?

**माननीय पुलिस सचिव—**इसका पूरा ब्योरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन दूसरे सूत्रों से पता लगाने का काम तो शुरू किया ही गया है और उनके जरिये वहाँ की सी० आई० डी० से सम्पर्क रक्खा जा रहा है। क्या परिणाम हुआ, इसकी सूचना मैं अभी नहीं दे सकूँगा।

### सन् १९४७-१९४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरी के पदाभिलाषियों की संख्या

\* १५—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य ( अनुपस्थित )—**क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४७ ई० व सन् १९४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरी के लिए कितने सब-इंस्पेक्टर मुरादाबाद ट्रेनिंग के लिए भेजे गये ?

**माननीय पुलिस सचिव—**सन् १९४७ में २७८ तथा सन् १९४८ में ५०० छम्मीद्वार सब-इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिये पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद भेजे गये।

\* १६—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य ( अनुपस्थित )—**क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सन् १९४७ ई० व सन् १९४८ ई० में जो लड़के सब-इंस्पेक्टरी के लिए मुरादाबाद ट्रेनिंग में भेजे गये, उनमें से कितने, किस-किस जाति के थे ?

**माननीय पुलिस सचिव—**इसका उत्तर देना जनहित की दृष्टि से उचित न होगा।



**शेरपुर, जिन्ना गार्जीपुर के किमानों तथा ज़मींदारों के बीच मनमुटाव**

❧ १७—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार के पास निम्नलिखित काया है कि गार्जीपुर जिले में शेरपुर में किसानों पर ज़मींदारों की तरफ से अन्याय हो रहे हैं ?

स्य ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

**माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)**—(क) जी नहीं, परन्तु 'अन्याय' शब्दों से जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि गाँव-पंचायत के चुनाव के समय में शेरपुर गाँव के ज़मींदारों और झोंटी जातवालों के बीच कुछ मनमुटाव बना हुआ है।

(स्य) जिज्जिकाशियों का शान्ति-रक्षा का पूर्ण ध्यान है और वे शान्ति-स्थानों के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

**प्रान्त के जिलों से खुफिया रिपोर्ट**

❧ १८—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यू० पी० के हर जिले की खुफिया-रिपोर्टें मिलती हैं ?

**माननीय माल सचिव**—सरकार को सब जिलों की उन विषयों की रिपोर्टें मिलती हैं जो उनके जानने योग्य हैं।

**प्रान्त में शरणार्थियों तथा युद्ध से लौटे सैनिकों के लिये भूमि की प्राप्ति**

❧ १९—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार प्रान्त में लड़े गये गाँव बसाने की योजना कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या वे गाँव परती में बन ये जायेंगे या मज़रूआ ज़मीन में ?

**माननीय माल सचिव**—ऐसी कोई व्यापक योजना तो नहीं की जा रही है परन्तु 'कानूनी' योजनाओं के अन्तर्गत नैनीताल तथा मेरठ जिले में तराई और गंगा नदी के मज़रूआ परती भूमि पर युद्ध से लौटे सैनिकों तथा शरणार्थियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये सरकार कुछ आधुनिक ढंग पर नये गाँव बसाने की योजना कर रही है।

**प्रान्तीय रक्षक दल, बुलन्दशहर द्वारा राष्ट्रीय पताकाओं का खरीदा**

**जाना और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचना**

❧ २०—श्री बलभद्र सिंह—क्या यह सत्य है कि गत स्वतन्त्रता दिवस के मुअवमर पर प्रान्तीय रक्षा दल बुलन्दशहर की ओर से राष्ट्रीय पताकाएँ श्री गाँधी

आश्रम से खरीदी जाकर अधिक मूल्य पर जिले में बेची गयी थीं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की ना- (वाइज) वार इनकी संख्या क्या थी ? आश्रम से किस दर से खरीदी गया तथा किस दर पर उन्हें बेचे जाने का आदेश दिया गया ? पताकाओं के दाम आश्रम को नकद दिये गये थे या वे उधार ली गयी थीं ?

❧ २१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रक्षा दल की ओर से यह व्यवसाय (खरीद फरोख्त) किस अधिकारी के आदेश से किया गया था ?

❧ २२—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पताकाओं की विक्री से कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

(ख) इस विक्री कार्य में कोई कैशमीरों अथवा रसीद आदि का प्रयोग किया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या प्रमाण है कि विक्री का कुल रुपया सही तौर से कोष में जमा हुआ ? कृपया उक्त पताकाओं से आय-व्यय का कुल हिसाब बताया जाय ?

❧ २३—(क) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत अप्रैल मास से नवम्बर, सन् १९४८ ई० तक बुलन्दशहर जिले में प्रान्तीय रक्षा दल के लिए किस किस अवसर पर कितना-कितना रुपया जनता से जमा किया गया ?

(ख) इन चन्दों के लिए सरकार की ओर से क्या रसीदों का प्रयोग हुआ ?

(ग) यदि हाँ, तो रसीदों से प्राप्त रुपया की संख्या क्या है ? इस रुपया के व्यय का व्योरा क्या है ?

❧ २४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बीच में जिले में प्रान्तीय रक्षा दल पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और इस में सरकारी सहायता क्या है ?

❧ २५—(क) क्या यह ठीक है कि जिले में प्रान्तीय रक्षा दल की एक कमेटी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दल के सरदारों के चुनाव के पश्चात् गत ८ मास में अर्थात् मार्च से अक्टूबर सन् १९४८ ई० के अन्त तक उक्त कमेटी की कोई मीटिंग कभी बुलाई गयी ?

(ख) रक्षा दल का कोई हिसाब (आय-व्यय) अब तक उक्त कमेटी के सामने पेश हुआ या नहीं ?

**माननीय पुलिस सचिव**—इन प्रश्नों के सम्बन्ध में जो सूचना जिलाधीश बुलन्दशहर से प्राप्त हुई थी वह कुछ अंश में अपूर्ण थी। जिलाधीश से शेष सूचना माँगी गई है और उसके मिलने पर उत्तर दिया जायेगा।

### गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ पर सरकारी व्यय

२३—श्री राम कृपाल सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ में कितने विद्यार्थी क्रमशः १९४६—४७, १९४७—४८ व १९४८—४९ में पढ़ते थे और कितना सरकारी खर्चा इन तीन वर्षों में प्रति वर्ष इस स्कूल पर हुआ है ?

माननीय शिक्षा सचिव के समा मंत्री ( श्री महफूजुर्रहमान )—  
संघ में जगी हुई सूचना देखिये ।

( देखिये नत्था, 'ख' अगे पृष्ठ ६५ पर )

### वनस्पति घी में रंग देने के लिये जनता की माँग

२४—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कभी यह परीक्षा करवाई है कि जो रंग हलवाई लोग मिठाइयाँ बनाने में प्रयोग करते हैं वे मिठाइयों के सेवन करनेवालों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ ।

२५—श्री बादशाह गुप्त—यदि हाँ, तो क्या उक्त रंग हानिकारक पाये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की परीक्षा करने का इरादा रखती है ?

माननीय अन्न सचिव—परीक्षा करने पर कुछ रंग हानिकारक पाये गये हैं ?

श्री बादशाह गुप्त—कौन-कौन से रंग हानिकारक पाये गये हैं ?

माननीय अन्न सचिव—इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ । मैं कोई दक्खण्ट तो हूँ नहीं और न मेरे पास विभाग से कोई जवाब आया है । यदि माननीय सदस्य इसका उत्तर चाहते हैं तो मैं इसकी नोटिस चाहूँगा ।

श्री बादशाह गुप्त—जो रंग हानिकारक पाये गये हैं वे सूबे में किसी मिठाई में इस्तेमाल न किये जायें, इसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

माननीय अन्न सचिव—यहाँ से तो कोई हिदायत नहीं की गई । लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है हमारे डाइरेक्टर ऑफ़ हेल्थ, जो इस चीज का निरीक्षण करने हैं, समय समय पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर्स को आदेश देते हैं कि इस तरह के रंग मिठाइयों में सम्मिलित न किये जायें ।

२६—श्री बादशाह गुप्त—यदि उक्त रंग हानिकारक नहीं हैं, तो उनमें से किसी रंग के वनस्पति घी में सम्मिलित करने में सरकार की क्या आपत्ति है ?

❧ ३०—क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता की माँग वनस्पति घी में रंग देने की है ? यदि हाँ, तो सरकार कब तक उसे पूरा करने का इरादा रखती है ?

**माननीय अन्न सचिव**—वनस्पति घी में रंग देने की व्यवस्था संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य आलेख (बिल) में कर दी गई है। यह (आलेख) बिल अभी विशिष्ट समिति के विचाराधीन है जिसने इस विषय को केन्द्रीय सरकार को लिखा है।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि वनस्पति घी को बन्द करने की माँग जनता में बहुत ज्वरदस्त है ?

**माननीय अन्न सचिव**—हाँ, सरकार को इस बात का ज्ञान है।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल**—वनस्पति घी को कतई बन्द करने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

**माननीय अन्न सचिव**—अभी वनस्पति घी को कतई बन्द करने का सवाल तो उठता नहीं है क्योंकि इस तरह की आवाज तो नहीं उठी। जो माँग उठाई गई है वह तो यह है कि जो वनस्पति घी बाजार में बिकता है वह रँग दिया जाय जिससे लोगों को असली घी और वनस्पति घी के खरीदने में कोई दिक्कत न हो।

**श्री राधाकृष्ण अग्रवाल**—क्या सरकार को यह मालूम है कि कई बार यह बात उठाई गई कि वनस्पति घी में हल्दी का रंग मिला दिया जाय जो कि हजारों वर्षों से जनता इस्तेमाल करती आई है और उसमें कोई हानि नहीं होगी ?

**माननीय अन्न सचिव**—इस प्रकार की सलाह प्रान्तीय सरकार के पास आई है और इसके बारे में जानकारों ने यह सलाह दी है कि हल्दी के रंग से कोई नुकसान नहीं होगा। परन्तु यह बात अभी कतई तौर से नहीं तय हुई है कि वह रंग बराबर रहेगा। ऐसा मालूम होता है कि थोड़े दिनों के बाद वह रंग डिकल-राइज्ड हो जायगा और घी फिर सफेद हो जायगा।

**श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी**—क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि वनस्पति घी पर किसी तरह का नियंत्रण रखने से सूबे के रोजगार में कुछ कमी आ जायगी ?

**माननीय अन्न सचिव**—हो सकता है, लेकिन जनता की माँग तो यह है कि उसको रँग जाय।

**श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी**—क्या सरकार जनता की इस माँग को जल्द से जल्द स्वीकार करने की कोशिश कर रही है ?

**माननीय अन्न सचिव—**१, इन्ही कारण से सरकार ने शुद्ध खाद्य विल इस भवन में उद्घाटित किया है और आगामी सेशन में यहीं पर उसके ऊपर बहस होगी और वह विल ऐक्ट के रूप में शायद इस हाउस के द्वारा पास किया जायगा।

**श्री गणेश कृष्ण जैनली—**वनस्पति धी के संबंध में रिसर्च कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है कि यह धी स्वास्थ्य के लिये उपयोगी है या हानिकारक है ?

**माननीय अन्न सचिव—**इस सिलसिले में प्रान्त में तो कोई रिसर्च हुई नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार बहुत सी बातों की जानकारी इस सिलसिले में कर रही है अभी कन्हू तौर पर इस सम्बन्ध में वह किसी राय पर नहीं पहुँच पाई है।

**श्री खानचन्द गौतम—**वनस्पति धी में रंग मिलाने का अधिकार क्या प्रान्तीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर है या उसके बाहर है ?

**माननीय अन्न सचिव—**वहले तो यही समझा गया था कि वह प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत है, इसी कारण से उस विल में, जिसका उल्लेख अभी इस उन्नर में किया गया है, इस बात का समावेश किया गया था कि जो होजिटेबिल धी तैयार किया जाय उसमें रंग दिया जाय। इस सिलसिले में कई बातें केन्द्रीय सरकार की तरफ से पिछले महीनों में उठाई गईं परन्तु अब केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को इजाजत दे दी है कि वह इस विल में जो रंग देने की बात है उसकी जो थारा शुद्ध खाद्य विल में रखी गई है वह आगे चलावे।

### प्रतापगढ़ सिटी के पास डाकुओं की गिरफ्तारी

§ ३१—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—**क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि लगभग डेढ़ या दो महीने हुए ग्रामवासियों ने प्रतापगढ़ सिटी के पास जंगल में कुछ लोगों को डाकु समझकर गिरफ्तार किया ?

**माननीय पुलिस सचिव—**जी हाँ।

§ ३२—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—**क्या यह सही है कि वे लोग जिस समय गिरफ्तार किये गये आरक्ष में कुछ माल बाँट रहे थे ?

**माननीय पुलिस सचिव—**जी हाँ।

§ ३३—**श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—**गिरफ्तार हुए लोग जौन और कहीं के थे ? क्या सरकार कृपा करके उनका हर एक का नाम और पता बतलायेगी ?

**माननीय पुलिस सचिव—**गिरफ्तार हुये व्यक्तियों के नाम व पते निम्न-लिखित हैं—

१. श्री कुर्बान कुरेशी      केवार, थाना रानीगंज
२. श्री सख्तूम पासी      पृथ्वीगंज थाना छोटवाली
३. श्री छंगा पासी      पृथ्वीगंज थाना बाघराय
४. श्री भूरे पासी      चर्रा, थाना बाइशाहपुर जिला जौनपुर
५. श्री बत्ती पासी      मौसुराबाद, थाना नवाबगंज जिला इलाहाबाद
६. श्री काशीराम ब्राह्मण      मुहल्ला सुखईटोला, ग्यालियर

❖ ३४—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—क्या गिरफ्तार हुये लोगों के पास कुछ हथियार भी बरामद हुए, यादे हुए त। क्या ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ, एक दो नली टोपीदार बन्दूक ।

❖ ३५—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार उन बहादुर ग्रामवासियों को जिन्होंने उन डाकुओं को गिरफ्तार किया कुछ इनाम देने को सोच रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ ।

श्री खानचन्द गौतम—सरकार ने ग्रामवासियों को जिन्होंने डाकुओं को पकड़ा था, इनाम देने के खिलखिले में निर्णय क्या किया है और उनको क्या क्या इनाम देने को सोचा है ।

माननीय पुलिस सचिव—निर्णय शीघ्र होनेवाला है और इरादा है कि इनाम काफी माकूल दिया जायगा ।

श्री खान चन्द गौतम—क्या सरकार ने उन डाकुओं को पकड़ने के लिये १० रुपया का इनाम जो रक्खा था उससे ज्यादा भी देने का इरादा कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—इरादा तो ऐसा ही है ।

\* ३६—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या यह सही है कि उन गिरफ्तार हुए लोगों में से एक अभियुक्त केवल मुचलके पर छोड़ दिया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—बोमारी की वजह से काशीराम मुत्तजिम को केवल मुचलके पर छोड़ दिया गया था और उसको जमानत देने के लिये एक हफ्ते का वक्त दिया गया था ।

❖ ३७—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या यह सही है कि वह अभियुक्त जा मुचलके पर छूटा अपने साथ कुछ अस्पताल का सामान लेकर भाग गया ?

माननीय पुलिस सचिव—जो हों ।

कै ३८—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस भागे हुए मुत्ताझम का अब तक कुछ पता चला कि नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं ।

प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों की संख्या और उनकी रोक-थाम

कै ३९—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में १ जनवरी, सन् १९४८ से २८ फरवरी, सन् १९४९ तक कितनी डकैतियाँ पड़ीं ?

माननीय पुलिस सचिव—४१ डकैतियाँ पड़ीं ।

कै ४०—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—उपर्युक्त समय के अन्दर डकैती से सम्बन्धित कितने आदमियों का चाजान हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव—इस सम्बन्ध में अब तक ७१ आदमियों का चाजान हुआ ।

कै ४१—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—( क ) कितने लोगों को डकैती में सजा मिली ?

( ख ) किनने छूट गये ?

( ग ) कौन-कौन डकैती में चाजान हुए लोग जमानत पर छोड़े गये ?

माननीय पुलिस सचिव—( क ) १३ आदमियों को सजा मिली ।

( ख ) ३६ छूट गये ।

( ग ) विभिन्न डकैतियों से सम्बन्धित ६६ आदमी जमानत पर छोड़े गये ।

कै ४२—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में कुल कितने थाने हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जिले में कुल ११ थाने हैं ।

कै ४३—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा बतलायेगी कि प्रत्येक थाने की डकैतियों की संख्या १-१-४८ से १-२-४९ तक कितनी रही ?

**माननीय पुलिस सचिव—सूचना निम्न प्रकार है—**

थाना	डकैतियों की संख्या
१. कोतवाली	२
२. कुम्हा	३
३. बाघराय	२
४. जेठवारा	८
५. रानीगंज	७
६. संग्रामगढ़	४
७. लालगंज	५
८. संगीपुर	४
९. चंदिगा	२
१०. कंघई	२
११. पट्टी	२

❧ ४४—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिन जिन गाँवों में डकैतियाँ पड़ीं उनमें या उनके सन्निकट ग्राम में किसी के पास बन्दूक का लाइसेंस था ?

**माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।**

❧ ४५—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—यदि कोई लाइसेंसदार बन्दूक का था तो क्या डकैती को रोकने के लिये उसका प्रयोग किया गया ?

**माननीय पुलिस सचिव—घटना के समय लाइसेंसदारों की अनुपस्थिति के कारण बन्दूक का प्रयोग नहीं किया गया।**

**प्रतापगढ़ में बन्दूक के लाइसेंसों के लिये प्रार्थना-पत्र**

❧ ४६—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—प्रतापगढ़ जिले में कुल कितने लोगों ने १-१-४८ से १-३-४९ तक बन्दूक के लाइसेंस की दरखास्तें दीं ?

**माननीय पुलिस सचिव—कुल १२५ दरखास्तें दी गईं।**

❧ ४७—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—उनमें से कितने लोगों का लाइसेंस मंजूर हुआ और कितनों का नहीं ?



**माननीय पुलिस सचिव—**५६ लाइसेंस मंजूर हुये और ५२ नामंजूर तथा शेष पर कायवाह। ५१ जा रहा है।

❧ ४८—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—**उन नामंजूर हुई दरखास्तों पर कितनों के लिये एम० एल० ए० या कांग्रेस के अन्य जिम्मेदार आदमियों की सिफारिशें थीं ?

**माननीय पुलिस सचिव—**६ दरखास्तें जिन पर एम० एल० ए० तथा अन्य व्यक्तियों की 'सिफारिशें' थीं न मंजूर की गईं।

### प्रतापगढ़ जिले में बाढ़ से क्षति

❧ ४९—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—**क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में आन्ध्रपट्ट तथा बाढ़ से कितने और कौन-कौन ग्राम तथा कितने मकानों का नुकसान हुआ ?

**माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री ( श्री चरण सिंह )—**अति बृष्टि तथा बाढ़ के कारण १५ ग्रामों तथा २१४ मकानों को क्षति पहुँची। बाढ़-पीड़ित ग्रामों के नामों की सूची पर शिष्ट 'अ' में दी हुई है।

( देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६ पर )

❧ ५०—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—**क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ में अधिकांश ग्रामों में फसल और चारे का अधिक नुकसान हो गया है ?

**श्री चरण सिंह—**जी हाँ।

❧ ५१—**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—**क्या सरकार ऐम क्षेत्रों को लगान में कुछ छूट देने का विचार रखती है ?

**श्री चरण सिंह—**जी हाँ। सरकार ने २०,००० रु० १४ आने की लगान में छूट दी है।

### किछौछा शरीफ जिला फ़ैजाबाद में बम-दुर्घटना

❧ ५२—**श्री गजाधर प्रसाद—**क्या सरकार को यह ज्ञात है कि किछौछा शरीफ, तहसील टांडा, जिला फ़ैजाबाद में उर्म के मेले के मौके पर मजमे के अन्दर मशीन के ठके हुए तीन बम टूटे और ५ बम बगैर टूटे मिले ?

**माननीय पुलिस सचिव—**जी हाँ।

❧ ५३—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि बम टूटने से सात व्यक्ति घायल होकर दाखिल अस्पताल हुए जिसमें दो मर गये ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ। बम फटने से सात व्यक्ति घायल हुए जो अकबरपुर के अस्पताल में दाखिल कर दिये गये। इनमें एक ८ वर्ष की बालिका थी जो दूसरे ही दिन मर गई और एक औरत जो लगभग एक महीना बाद मर गई।

❧ ५४—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि केवल एक व्यक्ति इस बारे में गिरफ्तार हुआ है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हाँ।

श्री गजाधर प्रसाद—सरकार उस व्यक्ति के मामले में क्या कार्रवाई कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव—अभी तक मुकदमा चलाया नहीं गया है। वहाँ के अधिकारियों की राय है कि बावजूद गिरफ्तारी के मुकदमा बहुत कमजोर है। वहाँ से उनको हिदायत दी गई है कि वह जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

❧ ५५—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस बारे में स्थानीय कर्मचारियों ने किसी शख्स के मकान की तलाशी ली या नहीं ? अगर नहीं ली तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—किसी घर की तलाशी नहीं ली गई क्योंकि इस बात का न तो सन्देह ही था और न कोई सबूत ही कि किसी मकान में ऐसे बम छिपाये गये होंगे।

### कुन्हटा जिला हमीरपुर के जंगल में खेती

❧ ५६—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुन्हटा के जंगल का जो जिला हमीरपुर में है कितना रकबा है ?

श्री चरण सिंह—२,७८६ एकड़।

❧ ५७—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त जंगल के कितने रकबे में खेती होती है और कितना जंगल है ?

श्री चरण सिंह—१,७१४ एकड़ रकबे में खेती होती है।

❧ ५८—श्री श्रीपति सहाय—क्या उक्त जंगल में खेती करने के लिये कुछ लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हाँ, तो वे प्रार्थना-पत्र किस-किस के हैं और उन पर क्या-क्या आज्ञायें हुई हैं ?

**श्री चरण सिंह**—जिन लोगों ने वृक्ष जंगल में खेती करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये उनके नाम (नमनांवत है और जो काझाये उनके प्रार्थना-पत्रों पर हुई उनके सामने लिखी हैं—

१. श्री कल्याण शंकर, २. श्री हर चरण लाल... ..

मंजूर

३. श्री चन्द्र नाथ, ४. श्री श्याम लाल इत्यादि, ५. श्री गौरी शंकर, ६. श्री देवकी, ७. श्री वैज नाथ, ८. श्री भइया लाल, ९. श्री चुनू बाब, १०. श्री उजागर, ११. श्री माता दीन, १२. श्री विल् सिह, १३. श्री राम कास इत्यादि, १४. श्री पूरन नाई, १५. श्री सुख लाल सिंह, १६. श्री बल्लता तथा १७. श्री मथुरा ।

नामंजूर

❧ ५६—श्री श्रीपति सहाय—क्या उपर्युक्त जंगल अभी हाल में काट कर उड़ाया गया है ?

**श्री चरण सिंह**—६१.३२ एकड़ परती जमीन खेती के योग्य है और उसी का पट्टा हाल में दिया गया है ।

❧ ६०—श्री श्रीपति सहाय—क्या सरकार की कोई योजना है कि उक्त जंगल में ट्यूबवेल लगा कर खेती कराई जाय ?

**श्री चरण सिंह**—जी नहीं ।

**फैजाबाद शहर में शरणार्थियों की गुमटियों के कारण जनता को कष्ट**

❧ ६१—श्री राजाराम मिश्र ( अनुपस्थित )—( क ) क्या सरकार को विदित है कि फैजाबाद शहर के अन्दर लगभग एक सौ से अधिक शरणार्थियों की गुमटियाँ ( लकड़ी की दुकानें ) चौक और बजाजे में सड़क के बीच में अभी भी लगी हुई हैं, जिससे जनता को कष्ट पहुँच रहा है ?

( ख ) वहाँ की जनता और दुकानदारों की ओर से उपर्युक्त गुमटियों को वहाँ से हटाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

( ग ) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़कों पर गुमटियों के लग जाने से सवारियों और मोटर आदि के आने जाने से मार्ग में तंगी आ गई है और इस कारण वहाँ छोटी-छोटी कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं ?

**माननीय प्रधान सचिव ( श्री गोविन्द वल्लभ पन्त )**—( क ) जी हाँ ।

( ख ) जी हाँ । वहाँ के रहने वालों ने उन लकड़ी की दुकानों को हटवाने के

लिए प्रार्थना-पत्र भेजे, परन्तु उन दुकानों के लिए कोई दूसरा स्थान न मिलने के कारण वे अभी तक हटाई नहीं गई हैं।

( ग ) सड़क पर गाड़ी इत्यादि चलने के लिए पर्याप्त जगह में कमी अवश्य हो गई है और रास्ता संकरा हो गया है, परन्तु इसके कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

### फैजाबाद के कमिशनरी के दफ्तर को लखनऊ लाने पर विचार

❧ ६२—श्री राजाराम मिश्र ( अनुपस्थित )—क्या यह सही है कि सरकार फैजाबाद शहर से वहाँ के कमिशनरी के दफ्तर को हटा कर लखनऊ लाने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय माल सचिव—सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी, बाद में उत्तर दे दिया जायगा।

### लखनऊ स्थित कमिशनर के ऑफिस को फैजाबाद ले जाने के

#### सम्बन्ध में पूछ-ताछ

❧ ६३—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि लखनऊ में स्थित कमिशनर का ऑफिस हटा कर फैजाबाद में ले जाने की योजना है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

❧ ६४—क्या यह सही है कि लखनऊ में कमिशनर के कार्यालय का भवन एवं कम्पाउंड फैजाबाद के कार्यालय के भवन से बहुत बड़ा है, और फैजाबाद में दोनों कमिशनरियों के कार्यालयों क रहने की सुविधा नहीं है ?

❧ ६५—क्या यह सही है कि लखनऊ के कमिशनर को लखनऊ में कई संस्थाओं के अध्यक्ष पद की हैसियत से काम करने के लिए प्रायः जाना पड़ता है ?

❧ ६६—क्या यह सही है कि लखनऊ से कमिशनर का दफ्तर फैजाबाद ले जाने की अपेक्षा फैजाबाद से कमिशनर का दफ्तर लखनऊ लाने में कम व्यय होगा ?

श्री चरण सिंह—सूचना अभी एकत्रित नहीं की जा सकी, बाद में उत्तर दे दिया जायगा।

## नहमाल पड़रौना. जिला देवरिया के विभिन्न गाँवों की मालगुजारी और लगान

क ६७—श्री गजधर प्रसाद—( क ) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि परसौनी गुनौली, परसौनी जनुबी, हनुमान गंज, नरायनपुर और बाधाचौर, सहस्रान्त पड़रौना. जिला देवरिया की पृथक पृथक प्रत्येक गाँव की मालगुजारी मरकाज और लगान कितना है और प्रति एकड़ क्या दर है ?

ख ) पिछले वर्ष यानों १३५५ फसली में उक्त गाँवों में कितनी रकम किसानों से बसूल हुई थी ?

ग ) उक्त गाँवों में पिछले वर्ष १३५५ फसली में कितने बारण्डस गिरफ्तारी, कुर्की और नैनम की कार्यवाही के लिये लगान वसूली के सम्बन्ध में निकाले गए थे ?

श्री चरण सिंह—एक ब्योरा मेज पर प्रस्तुत है ।

( देखिये तथी 'घ' भाग पृष्ठ ६७ पर )

## दैनिक पत्र 'उजाला' के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

क ६८—श्री शिवदान सिंह—( क ) क्या सरकार को पता है कि आगरे का दैनिक पत्र 'उजाला' सन् १९४२ के दमन का शिकार हुआ था और १ साल तक बन्द रक्खा गया था ?

( ख ) क्या सरकार ने उसकी क्षति पूर्ति के लिये कोई सहायता दी ?

( ग ) क्या अब फिर 'उजाला' का प्रेस २६ जनवरी से सील किया गया है ?

( घ ) क्या सच करने से पहिले उसे अपराध बताकर कोई जवाब तलब किया गया ?

( ङ ) क्या इस विषय में कोई चेतावनी दी गई ?

( च ) क्या जमानत माँगी गई ?

( छ ) क्या किसी आगेप की सत्य-प्रसत्यता बताने का कोई अवसर दिया गया ?

माननीय पुलिस सचिव—( क ) जी हाँ । 'उजाला' प्रेस तथा पत्र अगस्त, सन् १९४२ ई० से अगस्त १, सन् १९४३ ई० तक बन्द रहा ।

(ख) उस समय की सरकार ने इस प्रेस की क्षतिपूर्ति के लिये कोई सहायता दी या नहीं, यह पता नहीं है।

(ग) जी हाँ। यह प्रेस जावरी २६, सन् १९४६ ई० को सील किया गया और मार्च ६, सन् १९४६ ई० को फिर उसके मालिक को लौटा दिया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं।

(छ) जी नहीं।

❖ ६६—श्री शिवदान सिंह—(क) क्या सरकार को पता है कि 'उजाला' के लेख काग्रम नानि व समथक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की हरकतों के विरोधी रहे हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो प्रेस का बंद कराने का क्या कारण है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) कांग्रेस के संबंध में उसकी जो नीति रही हो परन्तु दूसरे हिस्से का जवाब नहीं में है।

(ख) सरकार को पता चला था कि इस प्रेस में संघ संबंधी कार्यवाही होती थी और चूंकि संघ अवैध घोषित किया जा चुका था इसलिये प्रेस के विरुद्ध कार्यवाही करना जरूरी समझा गया।

विभिन्न जिलों में अछूतों की सहायता के लिये जिला अफसरों की नियुक्ति

❖ ७०—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला अफसर नियुक्त करने की कोई योजना करेवाली है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में अब तक क्या काम हुआ है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—(क) जा हाँ। परन्तु इस समय यद्यपि २२ जिलों में जहाँ हरिजन आबादी अधिक है हरिजन-सुधार का कार्य घनिष्ठ रूप से करना निश्चय हुआ है, जिला हरिजन अफसरों की नियुक्ति की योजना केवल ६ जिलों के लिये है।

स्व) इस सम्बन्ध में सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन से लिखा पढ़ी कर रही है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या प्रत्येक जिले में ऐसे अफसर रखे गये हैं ?

श्री गोविन्द महाय—इस प्रश्न के उत्तर लिखे जाने के बाद में काफ़ी नज़रें होंगे। यह है और हर जिले में यह काम शुरू किया जायगा।

### टाइम्स पंचायत अफसर की योग्यता तथा उनका वेतन

ॐ ७१—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) प्रत्येक पंचायतों को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर कब तक नियुक्त करेगी ?

स्व) उन की योग्यता और वेतन की क्या क़ैद है ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम गोविन्द खेर)—यह विषय अभी शासन के विचाराधीन है।

### जौनपुर जिले में नये अस्पतालों का खोला जाना

ॐ ७२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में सरकार कितने नये अस्पताल खोलने जा रही है और कहाँ कहाँ ?

माननीय अन्न सचिव—इस साल सरकार सूबे के ग्रामीण क्षेत्र में १२० औषधालय खोलने जा रही है। इनमें से कुछ औषधालय जौनपुर जिले में भी खुलेंगे। यह अभी तय नहीं हुआ है कि किस जिले में कितने औषधालय खुलेंगे और कहाँ कहाँ।

### नये प्रेमों तथा नये अखबारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति

ॐ ७३—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—नये प्रेम खोलने और नये अखबारों के निहालने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

माननीय अन्न सचिव—१. बाहर से बहुत सा काराज आ जाने के कारण सरकार ने जिला मैजिस्ट्रेटों और प्रान्तीय पेपर कंट्रोलर की सिफारिश पर नये छापने वाले खोलने की इजाजत देना तय किया है।

२. नये अखबार निकालने से प्रान्तीय सरकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संसद काराज पर अखबार निकालने की इजाजत देने का अधिकार केवल

भारत सरकार को ही है। अखबारों का राज (न्यूजप्रिंट) पर अखबार निकालने के लिये किमी इजाजत की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस का राज में कंट्रोल हटा लिया गया है।

### जौनपुर जिले में सिंचाई का प्रबंध

कै ७४—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—(क) क्या सरकार ने जौनपुर जिले में सिंचाई के लिये ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना की है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अब तक क्या कार्य किया है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा मंत्री (श्री लताफत हुसैन)—(क) सरकार बाघरा नदी के दक्खिन की तरफ जौनपुर और दूसरे जिलों में सिंचाई की सहूलियतें पम्पड कैनाल्स और ट्यूबवेल योजनाओं द्वारा पहुँचाने की जाँच कर रही है।

(ख) अभी सर्वे हो रहा है।

### जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्रान्तीयकरण

कै ७५—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्राविशलाइज करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी नहीं।

कै ७६—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[स्थगित किया गया।]

### जौनपुर जिले में बेदखलियाँ तथा किसानों को भूमि की वापसी

कै ७७—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में दफा १७१ क्रानून के अन्तर्गत कुल कितनी बेदखलियाँ हुई थीं ? वापसी के क्रानून द्वारा कुल कितनी जमीन किसानों को वापिस दी गई और कितनी बेदखलियों के बावत वापसी की दरखास्त किसानों ने नहीं दी ?

श्री चरण सिंह—यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट १९३६ की धारा १७१ के अन्तर्गत जौनपुर जिले में कुल १,७४८ बेदखलियाँ हुईं।

६२४.५५ एकड़ भूमि वापसी के क्रानून द्वारा कृषकों को लौटा दी गई।

८५६ बादों के सम्बन्ध में कृषकों ने भूमि लौटाने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिये।



श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि वेदखल की नदी नम नों के बावसी का पूरा पूरा प्रोवेनैण्डा न होने के कारण किसान प्रार्थना-पत्र न दे सके ?

श्री चरण सिंह—सरकार को आशा है कि माननीय सदस्य जैसे व्यक्तिओं से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उन सबका काफी प्रचार होगा। यह कानून गजट में छपने के और पत्रकारों में भी छप जाते हैं। और इसके अज्ञाता भी मानन योग्य होते मुक्त हो तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने किसानों से ऐसी वेदखली जमान के वषरों के लिये पुनः कोई समय निर्धारित किया है ?

श्री चरण सिंह—कानून के अन्दर ६ महीने की मियाद है, उसके बाद प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते और गवर्नमेंट ने इस ससजे पर विचार नहीं किया है।

### मड़ियाऊँ-केराकत सड़क का प्रान्तीयकरण

३८—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार ने जौनपुर जिले में मड़ियाऊँ से बगान जामेगली सड़क को प्राविंशियलाइज कर लिया है ?

श्री लताफत हुसैन—जी नहीं

३९—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—[ स्थगित किया गया। ]

४०—श्री मुहम्मद अमरार अहमद—[ स्थगित किये गये। ]

### राजनीतिक कैदियों के घरवालों को भत्ता

४१—श्री मुहम्मद अमरार अहमद—सरकार ने उन राजनीतिक कैदियों के जो नजरबंदी किये गये हैं फौमन्ता अलाउन्स देने के बारे में क्या तै किया है ? फौमन्ता के कैदियों के खानदानों को दौरान कैद भत्ता दिया जायगा ?

श्री गोविन्द महाय—नजरबन्द कैदियों के घरवालों को गुजारे का भत्ता दिया जाता है, यह नजरबन्दी के पहले घरवाले उस पर आश्रित रहे हों और कैदी के निष्पत्ति के फलस्वरूप उसके कुटुम्ब की आर्थिक अवस्था ऐसी हो गई हो कि बिना सरकारी सहायता के उनका काम न चल सके।

श्री मुहम्मद अमरार अहमद—क्या गवर्नमेंट यह बतलावेगी कि किन किन राजनीतिक कैदियों के कैदियों को राजनीतिक कैदी करार कर दिया है ?

श्री गोविन्द महाय—यह सवाल नहीं उठता है।

**माननीय स्पीकर**—यह तो मेरा काम है। पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी अपने ऊपर इसका बोझ न लें कि कौन सा सवाज मुनासिब है और कौन सा नामुनासिब है। उनका अधिकार है जबाब देने का।

**श्री गोविन्द सहाय**—किसी क़ैदी को पार्टी के आधार पर राजनीतिक क़ैदी करार नहीं दिया जाता है।

**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि इस वक्त कितने क़ैदियों के कैमिलीज को एलाउंस दिया जा रहा है ?

**श्री गोविन्द सहाय**—ठीक नहीं बता सकता हूँ, करीब ४५ के हैं।

**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या गवर्नमेंट यह बतलायेगी कि कितने क़ैदी नज़रबन्द हैं जिनको एलाउंस नहीं दिया जाता है ?

**श्री गोविन्द सहाय**—जितनी तादाद मैंने बताई है उसके अलावा जो हैं उनको नहीं दिया जाता है।

**किसानों द्वारा खेतों की सिंचाई करते समय पानी का बेकार बहाना**

❖ ८६—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)**—क्या सरकार को यह मालूम है कि जो किसान नहर का पानी अपने खेत में ले जाते हैं, वे प्रायः जितना पानी खेत में लगाते हैं उससे कहीं अधिक पानी गलियारों या गड्ढों में भर देते हैं जिससे दूसरे किसानों को पानी नहीं मिलता ?

**माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)**—जी नहीं, लेकिन सरकार को यह मालूम है कि पानी ले जानेवाली नालियों से जब किसान पानी अपने खेतों की सिंचाई के लिए ले जाते हैं तो उसमें का कुछ हिस्सा गाँव के गलियारों और गड्ढों में जाया हो जाता है। यह जाया हो जानेवाला पानी खेतों में सिंचाई के काम में आनेवाले के मुकाबिले में बहुत थोड़ा होता है।

❖ ८७—**श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)**—क्या सरकार के पास इस बात की रिपोर्ट हल्के का पतरोल देता है कि अमुक किसान ने इतना पानी अपने खेत में लगाया और उससे अधिक खराब किया ? ऐसी रिपोर्टों पर सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

**माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव**—हल्के का पतरोल पानी जाया होने के बारे में जो वाक्यात उसकी नज़र में आते हैं एक रिपोर्ट बिलेदार को भेजता

है, जो कि नामने के जांच करता है और अगर जुम सचिन हो जाता है तो जाया किये गये पाने १ अन्दाजा लगा कर क्रिमानों पर प्युनिटिव रेट लगाया जाता है।

### पतरौल का अश्रुतकारों से रिशवत लेना

\* ८८—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि पतरौल प्रायः दारुनकारों से कुर्या लेकर नल, नहर या बम्बे से उखाड़ कर गहर में उधर कर दिया करता है ?

माननीय मार्गजनिनिक निर्माण सचिव—जी नहीं। सरकार को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

### सरकारी विभागों में रिशवतखोरी

\* ८९—श्री भारत सिंह यादवाचार्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि उसके पास आई हुई सूचनाओं के अनुसार रिशवत किन किन डिपार्टमेंटों में बन्द हो गई या बहुत कम हो गई और अभी किन में जारी है ?

माननीय प्रधान सचिव—इन मामलों के सम्बन्ध में जहाँ तक हो सकता था काफी सूचना बजट पर बहस के सिलसिले में दी जा चुकी है। जितनी सूचना इस समय प्राप्त है उनके आधार पर इससे अधिक नहीं कहा जा सकता है। सरकार के सब विभागों को पूर्ण तरह से जाँचने में बहुत समय लगेगा और काफी धन भी खर्च होगा कि आवश्यक मालूम नहीं देता।

### प्रान्त के विभिन्न जिला बोर्डों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

\* ९०—श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त के जिला बोर्डों के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण के विषय में सरकार ने कोई नतीजा निर्धारित कर ली है ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ।

श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार सूबे की ऐसी मस्थाओं के सब अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने की कृपा करेगी ?

माननीय अन्न सचिव—सरकार ने उन स्थानों के अस्पतालों को जो शहरों में हैं और उन स्थानों में हैं जहाँ रिलीजस फेअर्स इत्यादि होते हैं उन नामक अस्पतालों का प्रान्तीयकरण की योजना में लिया है और उनका प्रान्तीय-

करण भी कर लिया है। जहाँ जहाँ जिला बोर्डों के अस्पतालों में ठीक इन्तजाम न हो रहा है और ऐसे अस्पतालों को जहाँ से अधिक संख्या में जनता फायदा उठाती है उन अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करने का प्रश्न सरकार के सामने है और ज्यों ज्यों सरकार का कोप उनके प्रान्तीयकरण की इजाजत देता है वहाँ पर प्रान्तीयकरण किया जा रहा है।

**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन अस्पतालों के अलावा जो अस्पताल हैं उनका प्रान्तीयकरण करने को सोच रही है ?

**माननीय अन्न सचिव**—अभी तक इस बात के ऊपर विचार नहीं किया गया है। इन अस्पतालों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। जब सरकार के पास रिपोर्ट आयेगी और जहाँ जिला बोर्ड अस्पताल चलाने में असमर्थ हैं और जहाँ जहाँ इन्तजाम खराब है उनके प्रान्तीयकरण करने के सिलसिले में भी विचार करेगी।

**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार के पास ऐसे प्रार्थना-पत्र आये हैं ?

**माननीय अन्न सचिव**—मुझे इसके बारे में सूचना नहीं है।

॥६१॥—**श्री हर गोविन्द पन्त**—यदि हाँ, तो क्या सरकार बतलायेगी कि उस नीति के अनुसार प्रान्त भर में कुल कितने अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो चुका है ?

**माननीय अन्न सचिव**—१०१

॥६२॥—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिले अल्मोड़ा में जिला बोर्ड के कुल १६ अस्पताल हैं और उनमें से कितनों का प्रान्तीयकरण अब तक हो सका है ?

**माननीय अन्न सचिव**—१४। सदर अस्पताल अल्मोड़ा का प्रान्तीयकरण हो चुका है, १३ प्रांतीय अस्पतालों में से अभी किसी का प्रान्तीयकरण नहीं हुआ है।

॥६३॥—**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा के चम्पावत तडसीन के लोहाघाट में स्थित अस्पताल के प्रान्तीयकरण के बाबत कोई सिफारिशें आई हैं ? क्या इस अस्पताल के आँदड़े भी सरकार के पास पहुँच चुके हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसके विषय में किसी निश्चय पर पहुँच पाई या नहीं ?

माननीय अन्न सचिव—हाँ, अब अभी इस विषय में सरकार विचार कर रही है।

### रानीखेत तहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव

॥ ६४—श्री हर गोविन्द पन्त—क्या रानीखेत तहसील के हेड क्वार्टर में चिकित्सा बोर्ड का या प्रांतीय सरकार का कोई अस्पताल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की वहाँ कोई अस्पताल बनाने की योजना है ?

माननीय अन्न सचिव—क नहीं।

ज) रानीखेत में एक सिविल अस्पताल बनाने की योजना कर

### रानीखेत की छावनी का अस्पताल

॥ ६५—श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि रानीखेत की छावनी के अस्पताल में देशी जनता के इलाज का पूरी सुविधा नहीं है ?

माननीय अन्न सचिव—जी हाँ, सूचनाओं से ऐसा ही प्रतीत होता है।

### जिला अल्मोड़ा में ग्रामसुधार आर्गेनाइजर्स की दुबारा नियुक्ति का आधार

॥ ६६—श्री हर गोविन्द पन्त—( क ) जब प्रान्त में कांग्रेस के मंत्रिमण्डल स्थापित होने पर जिला अल्मोड़ा में ग्रामसुधार विभाग खुला था, उसमें कितने आर्गेनाइजर नियुक्त हुए थे और उनमें से कितने राजनैतिक पीड़ित थे ?

ख, वर्तमान समय में उन राजनैतिक पीड़ितों की संख्या अब कितनी रह गई है ?

माननीय उद्योग सचिव ( श्री केशव देव मालवीय )—( क ) सन् १९४६ में जब कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने पद ग्रहण किया। उस समय सरकार के आदेश के अनुसार ग्रामसुधार आफिसर ने उन १८ सक्रिय आर्गेनाइजर्स के फ़र से नियुक्त करने का आदेश दिया, जिन्होंने राजनैतिक आधार पर त्याग पत्र दिया था। इनमें से कुछ १२ आर्गेनाइजर्स ने चार्ज लिया और ५ आर्गेनाइजर्स ने चार्ज लेना उचित नहीं समझा।

( ख, छ:।

श्री हर गोविन्द पन्त—क्या सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि जो आर्गेनाइजर राजनैतिक खयाल के कारण अलग किये गये थे, वह फिर लिये जा सकते हैं ?

**माननीय उद्योग सचिव**—कई बार सरकार ने इसका प्रस्ताव किया है कि जो आर्गनाइजर राजनीतिक विचार के कारण अलग हुए वे फिर से आ सकते हैं। कई बार माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह फिर लिये जायें। इस सम्बन्ध में जब काफ़ी दूरक्षास्ते आयेंगी तो सरकार उन पर विचार करेगी।

**श्री हर गोविन्द पन्त**—क्या इन आर्गनाइजर्स की संख्या घटने का कारण इन राजनीतिक पीड़ितों के साथ उचित व्यवहार न होना तो नहीं है ?

**माननीय उद्योग सचिव**—सरकार को तो ऐसा मालूम नहीं होता है।

❖ ६७—**श्री हर गोविन्द पन्त**—(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामसुधार का काम अब सहयोग समितियों के पास दे दिया गया है और आर्गनाइजर्स का नाम बदल कर सुपरवाइजर रखा गया है, और कुछ नये सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है ?

(ख) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये सुपरवाइजर्स को कितना मासिक वेतन मिलता है और पुराने आर्गनाइजर्स को कितना ?

**माननीय उद्योग सचिव**—(क) १. जी हाँ।

२. जी नहीं।

३. जी हाँ।

(ख) कोओपरेटिव सुपरवाइजर्स का स्केल ३०-६५ रु० है, और हाई स्कूल पासवालों का शुरू में ३६ रु० दिये जाते हैं। उन लोगों का मंहगाई भत्ते के अलावा बँवा सफ़र खर्च ११ रु० कांटेजेंसो १ रु० और वारवरदारो का भत्ता (पोर्टर पलाइंस) १० रु० मिलता है। ग्रामसुधार आर्गनाइजर्स को भी ३०-६५ रु० का स्केल मिलता है और बँवा सफ़र खर्च १० रु० और मंहगाई भत्ता सरकार के कानून के मुताबिक मिलता है। इसके अलावा इन लोगों का ७ रु० जालाना कागज पेन्सिल टिकट इत्यादि के लिये भी मिलते हैं।

**ग्रामसुधार के सुपरवाइजर तथा आर्गनाइजर्स की योग्यता में भेद**

❖ ६८—**श्री हर गोविन्द पन्त**—सुपरवाइजर तथा आर्गनाइजर्स की योग्यता में क्या भेद है ?

**माननीय उद्योग सचिव**—सरकार ने कोओपरेटिव सुपरवाइजर्स और संकिल आर्गनाइजर्स के लिये जो शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएँ निर्धारित की हैं, उनमें बहुत कम फर्क है। उन लोगों का कम से कम हिन्दी मिडिल पास होना चाहिये, हाई स्कूल पासवालों को तरजीह दी जाती है।

टाँडा, जित्त कैत्र राई को घाटे को चक्कियों का तेल का मासिक कोटा

❧ ९९—श्री जय राम वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि फैजाबाद जिले में टाँडा म्यूनिसिपैलिटी को सोमा के भीतर जो घाटे की चक्कियाँ हैं उन्हें अलग अलग कितना कितना मासिक तेल का कोटा मिलता है ?

माननीय पुलिस सचिव—जिलाधीश फैजाबाद वर्मा शेज कम्पनी लखनऊ स्टैण्डर्ड त्रैकल कम्पनी व इत्यादि वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी कचर्रा के प्रत्युत्तरों से मान्य हुआ है कि टाँडा म्यूनिसिपैलिटी को सोमा के अन्दर १२ चक्कियाँ हैं। इन चक्कियों में से १४ आन्ध्र हैं और बाकी नहीं चल रही हैं। इन चक्कियों को अलग अलग कम्पनियाँ द्वारा मासिक कोटा निश्चित है जिनके द्वारा माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं। चक्की नं० ८ और १० का तेल देना मार्च, १९४६ से बन्द है और चक्की नं० १७ का तेल फरवरी, १९४६ से बन्द है।

❧ १००—श्री जय राम वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त घाटे की चक्कियों में से कुछ गत कई महीनों से बन्द हैं, लेकिन उन्हें बराबर मासिक तेल का कोटा मिलता जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं। वर्मा शेज के कथनानुसार ये सब अवसर कभी नहीं आया कि चक्कियों के बन्द होने पर भी उन्हें तेल दिया गया हो।

### श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद

माननीय प्रधान मन्त्रि—श्रीमान स्पीकर महोदय, मुझे अकसोस है कि हमारी असेम्बली का आखिरी बैठक के बाद हमारा इस असेम्बली के एक प्रमुख सदस्य श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा का स्वर्गवास हो गया। वर्मा जी अपने बाल्यकाल से ही लगन के साथ देश की सेवा करनेवाले स्वतन्त्रता के यादगारों में प्रमुख स्थान रखते थे। उन्होंने पहले जब इस देश में गांधी जी का मूवमेंट शुरू हुआ तो पढ़ाई ब्राह्मणों को और फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ में कुछ समय तक शिक्षा पायी थी। वे निरन्तर तब से अपने आखिरी क्षण तक देश की ही सेवा में व्यस्त रहे और उन्होंने उच्च को सबसे ऊँचा स्थान दिया और अपनी और जरूरतों और अपने कष्टों का भी उन्होंने कभी किसी तरह से ध्यान नहीं किया और हर तरह का तकलीफें उन्होंने अपनी जिन्दगी में सही। वे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मॉन्ट्रा में, इलाहाबाद में और कानपुर में स्थानीय शासन की संस्थाओं में कार्य किया और हमारी इस असेम्बली के वे एक सम्मानास्पद व्यक्ति थे। हमारे सदस्यों में उनका एक उच्च स्थान है। हमारी पार्टी के वे एक पथ-प्रदर्शकों में थे। मुझे बड़ा अकसोस है कि कम उम्र में ही वह

हमको झोड़कर चले गये । उनके परिवारवालों के साथ इस छारे भवन की पूरी सद्धानुभूति होगी, यह मुझे पूरा विश्वास है । हमारी जो श्रुति उनके इस अकाङ्क्ष स्वर्गप्रयाण से हुई, उसकी अधिक कहना बठिन है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भवन की ओर से उनकी विधवा बत्नी और अन्य कुटुम्बियों को सद्धानुभूति भेजने की कृपा करें ।

**श्री फखरुल इस्लाम—**जनाबवाला, अपने दोस्त वर्मा जी से मेरा काफी ज़ाती ताल्लुक था और उनकी सियासी जिन्दगी के तमाम पहलुओं की मैंने अपने तौर पर देखा, उसमें जो चीज मैंने महसूस की वह यह थी कि वह अपनी जिन्दगी के सपनों पर सख्ती से कायबन्द हुआ करते थे । चाहे लोग उनके राजी हों या न हों या उनकी उन बातों को न मानें लेकिन जिन बातों को वे सही समझते थे उन पर सख्ती से कायबन्द होते थे । इसका कभी ख्याल नहीं करते थे कि लोगों का उनके मुताल्लिक क्या ख्याल है । वे अपने दिक्की ख्यालात का इजहार बहुत ही बहादुरी, बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ हर एक के सामने कर दिया करते थे, चाहे उनके मुखालिफ या उनके दोस्त उसे पसन्द करें या न करें । मुझे अफसोस है कि आज वे हम में नहीं हैं और इलाहाबाद के लिए खास तौर से यह अफसोस की बात है क्योंकि उनकी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ही शहर में गुज़रा । यह ऐसी कमी है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते । यह जरूर सही है कि इधर वे कुछ दिनों से कानपुर में रह रहे थे और बीमार थे और हम सब एक दूसरे से मिल न सके लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी । मैं भी जनाबवाला, जैसा कि जनाब प्रीमियर साहब ने कहा है, आप से इततदुआ करूँगा कि हमारी हमदर्दी उनके पसमान्दगान के पास भेज दें । उनकी मौत से हमें बहुत अफसोस है ।

**श्री जगन्नाथ बरूवा सिंह—**माननीय स्पीकर महोदय, यद्यपि वर्मा जी से मुझे इसी भवन में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ परन्तु इतने दिनों ही मैं मैं उनकी योग्यता, दूरदर्शिता और सौजन्यता का सदैव प्रशंसक रहा । ऐसे विचारशील और योग्य व्यक्ति का संसार से अकस्मय उठ जाना जनता के लिए ही दुःख का कारण नहीं बल्कि राज्य के प्रबन्ध में और इस धारा सभा की कार्यवाही में त्रुटि विशेष रूप से पैदा करता है । मुझको अत्यन्त खेद है कि ऐसा योग्य व्यक्ति इस धारा सभा का ऐसे समय में उठ गया । मैं उनके परिवार के साथ सद्धानुभूति और माननीय प्रधान सचिव के इन शब्दों से सहयोग करता हूँ ।

**श्री सुल्तान आलम ख़ाँ—**जनाब स्पीकर साहब, हमारे दोस्त और साथी श्री बी० एन० वर्मा के मुताल्लिक जो हमारे आनरेबल प्रीमियर साहब ने फरमाया उससे हम सबको इतकाफ है । मैं आशी तौर पर वर्मा जी से बहुत



श्री सुलतान आबुलमजिद ]

जबकि बाकि क नहीं था मेरी चर्च मुलाक़ात इसी भवन में हुई थी, लेकिन जो कुछ मुझे उनके इस्तान्बुल मालूम हुआ उससे मैं जानता हूँ कि वह एक बहुत वास्तविक और बड़े कैरेक्टर के आदमी थे। और इस भवन में और इस भवन के बाहर भी उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है वह खिदमत काबिले लिहाज़ हैं और पदार्थ है मुझे अफ़सोस है कि आज हम उनके यहाँ से उठ जाने से मात्तम करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बराबर जब हम यहाँ पर असेम्बली में बैठते हैं तो हमको किसी न किसी साथी का मात्तम करना पड़ता है। उनमें आज यह एक और इजाफ़ा हो गया है। मुझे र्कन है कि हम सब लोग उनके अजीजों और जिनको यह सद्मा पटाना पड़ा है उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। मैं यह भी र्कन करता हूँ कि माननीय स्पीकर साहब हम सब की तरफ़ से उनके सब अजीजों को हमारी हमदर्दी का पैराम पहुँचा देगे।

**माननीय स्पीकर—**श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा का इस कम उम्र में चले जाना हमारे प्रान्त के लिये दुःख देनेवाली घटना है। वह हमारे पुराने तपे हुए कांग्रेस के रुपाइयों में से थे; उन दिनों में जब कांग्रेस का सदस्य होना अपने ऊपर गवर्नमेंट का क्रोच लुलाना था वह एक बहादुर कांग्रेस के सिपाही थे। अब तो कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गयी है, बहुत लोग कांग्रेस में आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन दिनों में, जब स्वतन्त्रता की लड़ाई का कुछ बौद्ध कांग्रेसवालों पर था, वह समय था जब कांग्रेस का सदस्य होने का कुछ विशेष अर्थ था। भुवनेश्वरी नारायण वर्मा हमारे उन युवकों में से थे जिन्होंने त्याग की भावना और देश को स्वतन्त्र करने की भावना को सामने रख अपने वैयक्तिक भविष्य को तिकाबलि की। मैं निजी रीति से जानता हूँ कि उस आदमी में कितनी हिम्मत थी और कितनी पारिवारिक कठिनाइयाँ उन्होंने सहनी थी और साथ ही किस मुम्कराहट के साथ वह उन कठिनाइयों के बीच में बरतते थे मेरे साथ वह जेलखाने में भी रहे थे और बाहर भी मेरा उनका बहुत आपसी सम्बन्ध था। मेरे लिये तो उनका जाना विशेष रीति से दुःखद हुआ है। हृदय की बात तो सब कही भी नहीं जा सकती। आप सबों की तरफ़ से मैं उनके कुटुम्ब को आपके विचार और आपकी सहानुभूति की सूचना दूँगा। मेरा निवेदन है कि सब मेम्बर सके स्पीकर अपना खेद प्रकट करें !

( सदस्यों ने खड़े होकर शोक प्रकट किया । )

**श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद**

**माननीय प्रधान सचिव—**मुझे सख्त अफ़सोस है कि ग़ालिबर् सवा, महीना हुआ मेरे कुछ ज़रा दौग़त अब्दुल हकीम साहब जो कि हमारे इस असेम्बली के एक दिदी र्कन भी थे, का इन्टज़ाक हो गया। वह एक बहुत मुम्बिज्ज, चम्पने

के थे और उन्होंने कहीं-कहीं सुनिवृत्ति में तालीम पायी और उसके बाद वह हमेशा एक सच्चे नेशनलिस्ट बने रहे।

हमारे मुल्क में बहुत से मोर्चे आये और उन मोर्चों में बहुत मजबूत कम्मे भी लूच गये, मगर वह बमजोर और दुबले पतले जिरम से होते हुए हमेशा एक पक्के तरीके पर नहीं बौमी उस्तों पर जिनको उन्होंने बहुत किया था, डटे रहे और कोई भी बातें जो कि हमारे मुल्क में या बाहर हुईं उनसे वह बभी ठीले नहीं हुए। वह एक बहुत अच्छे बकील थे। उनकी प्रैक्टिस भी, जब वह बकालत करते थे, बहुत अच्छी थी, मगर वह हिन्दुस्तान की मातहतती और मुलामी की न्यथा को बरदाश्त नहीं कर सके और काकादी के जंग में उन्होंने पूरा हिस्सा लिया। जेल में भी गये और वहीं से उनकी तन्दुरुस्ती शायद रुगब हो गयी। तभी से बारहा उनको दिल की और और तरह की बीमारियों के दुखों को बरदाश्त करना पड़ा, मगर अपनी कगल में वह कायम रहे। एक जमाना था जब अपने सिबासी ख्यालात की वजह से उनको बहुत सी मुसीबतों को भी बरदाश्त करना पड़ा। मगर उनको भी, उन्होंने हिम्मत के साथ मुकाबला करके बरदाश्त किया और अपने इरादे पर कायम रहे। उनकी काबिलियत से, उनकी शराफत से, उनकी दरियादिली से, और उनकी मुल्क के साथ गहरी मुहब्बत से इस हाउस के सभी मेम्बर वाक़िफ हैं। हम लोगों के लिए तो उनका जाना एक सच्चे भाई से अलग होने की तकलीफ़ देनेवाली बात है। वह हमारी पार्टी के एक रक्न थे और उनसे हम लोग मशविरा पाते थे और जब भी कोई मुश्किल खालात हमारे सामने आते थे, तो उनकी मदद के ख्वाहिशगार रहते थे। कुछ दिनों से उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गयी थी मगर वह फिर भी बहादुरी से अपनी बीमारी में भी हिम्मत से काम लेते रहे।

मुझे अफसोस है कि आज वह हमारे बीच में नहीं हैं और मैं आपसे दरखवास्त करता हूँ कि आप उनके घर के लोगों को हमारी तरफ से सहानुभूति और हमदर्दी का सन्देशा भेजने की कृपा करें।

**श्री फखरुल इस्लाम**—जनाबवाला, अब्दुल हकीम साहब की मौत इस भक्न के मेम्बरों के लिए ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस यू० पी० के तमाम सुसलमानों के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब्दुल हकीम साहबकी एक ऐसी मायनाम हस्ती थी जिसके मुताल्लिक हर आदमी चाहे वह किसी जमात, किसी पार्टी या किसी ख्याल का हो या सियासी इस्लामाफ़, रखनेवाला हो वह ईमानदारी से यही कहने पर मजबूर होगा कि वह एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही शरीफ़ और अपने ख्यालात को रखते हुए दूसरे मुक़ालिफ़ की बातों को गौर से सुनने के आदी थे और कभी भी ऐसी बात जिससे नफ़सानी पैदा हो अपनी कबान पर नहीं लाते थे।

[ श्री लक्ष्मण इत्याम ]

उस ऐसे दुरवार गुजार लगाने में जब कुछ ताल्लुकात खराब हों, वह बहुत काफ़ी असें तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि उनका कितना असर दूसरे भाइयों के ऊपर था, जिससे वह इस तौर पर अपना काम कर सके थे।

आज हमें अफसोस है कि वह हमारे दरमियान में नहीं हैं, जब कि ऐसे वक्त में उनकी बड़ी जरूरत थी। इसके लिए हम उनके पसमान्दगान से अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हैं और जो प्रीमियर साहब ने कहा है उसकी तारीफ़ करने हैं।

**श्री जगन्नाथ बल्लभ सिंह**—महोदय, अब्दुल हकीम साहब की प्रधानता में मुझे इस बारा सभा में एक असें तक काम करने का अवसर, इसके पहले, मिला था। राजनीति में, उनके विचारों की स्वतन्त्रता तथा मानसिक स्वतन्त्रता उनकी एक विशेषता थी। यद्यपि स्वतन्त्रता मनुष्य का प्राणीमात्र का स्वाभाविक धर्म है, तथापि समयानुसार सच्ची स्वतन्त्रता अधिकांश लोगों में पायी नहीं जाती। ऊँचे दर्जे की स्वतन्त्रता का होना और देशसेवा की लगन का होना यह मानसिक बल का द्योतक है।

वह ऐसा विशेषण मनुष्य में है जो उसके अनेक अवगुणों को दबाकर उसको प्रशंसा का पात्र बना देता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की यह विशेषता बारा सभा के कार्य को अति उत्तम बनाने वाली है। आज हम अपने उन स्पीकरों को जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय कार्य करते हैं उसी श्रद्धा और सगाहना के रूप में देखते हैं। खास कर वह ग्रुप्स जिनका नम्बर बहुत कम है वह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की न्यायप्रियता और स्वतन्त्रता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों का कल्याण कर सकते हैं और इस बारा सभा में काम कर सकते हैं। ऐसे पुरुष के महाप्रयाण पर हम अत्यन्त खेद प्रकट करते हैं और माननीय प्रधान मन्त्री से हार्दिक सहयोग करते हैं।

**श्री सुल्तान आलम ख़ाँ**—जनाब स्पीकर साहब, मौलवी अब्दुल हकीम साहब के मुताल्लिक अभी प्रीमियर साहब और दूसरे मेम्बर साहबान ने जो कुछ कहा है मैं उसके एक एक लफ्ज की तारीफ़ करता हूँ। अब्दुल हकीम साहब हमारे लिए कोई नये भाइसी नहीं थे। वह हमारे पुराने साथी रहे हैं और इस भवन के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और बहैसियत डिप्टी स्पीकर के हम में से बहुत से मेम्बरान को उनसे मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बहैसियत डिप्टी स्पीकर के उनको हाउस के तमाम मेम्बरों का पूरा पतवार और भरोसा हासिल था और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वह अपने जितने और सूबे की वज्जिक लाइफ़

मैं १६ नुमायाँ दिखाता था। वहैतियत के तहत एजुकेशन कमिटी बस्ती में उन्होंने बहुत हा नुमायाँ कान किया है। मुझे इस हैसियत से भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अपनी पब्लिक साइफ के अलावा अब्दुल हकीम साइब वहैतियत ईसान एक बड़ी खुशी के मातृक थे और बड़े अखलाक के ईसान थे। लोगों का उनसे मित्रर बड़ा खुशी पैदा होती थी और वह इस बात की खाहिश रखते थे कि उनसे फिर मुलाकात हो। अगर वह बहुत ही कमजोर ईसान थे लेकिन अपने अन्दर बड़ी कूबत और इनर्जी रखते थे। असेम्बली के पिछले इजलास में जब वह आये थे और बड़ आखिरी बार आये थे तो कौन समझ सकता था कि उनकी इस भवन के अन्दर यह आखिरी आमद है। विज्ञ-आखिर मात के आखिम हाथों ने ऐसे शक्स को जिस पर सूबे के लाग फल कर सकते थे उनसे हमेशा के लिए छुड़ा लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आनरबिल स्टाकर साइब हमारी सबका तरफ से उनके पसमान्दगान को और मजीबाँ का जिनका वह अपने पाछे छाड़ गये हैं हमारी सबका हमदर्दी का पैगाम पहुँचायेंगे।

**माननीय स्पीकर—**श्री अब्दुल हकीम साइब को जानने का अवसर मुझे सर १९३७ ई० में मिला जब वह इस भवन के डिप्टी स्पोकर चुने गये। स्पोकर होने के नाते मुझे उनसे बहुत काम बराबर पड़ता रहा कई नाजुक अवसर आये जब कुछ ऐसे मसलों पर मुझे आज्ञा देनी पड़ी। जिनके बारे में इस भवन में बहुत मतभेद था। मुझको ऐसे कई अवसर याद हैं जब अब्दुल हकीम साइब ने मेरे कमरे में आकर मुझको मेरे निर्णयों पर हृदय से और प्रेम से बसाइयाँ दीं। मैं उनके हृदय का भावनाओं से देख सकता था कि वह कितने सच्चे आदमी थे और साम्प्रदायिक भावनाभा से कितने दूर थे। वह राष्ट्र के उपासक थे और हाज़ाकि मुस्लिम लोग उस समय मुसलमानों में बहुत फैला हुई था और उसका अन्तर था फिर भी अब्दुल हकीम साइब ने बराबर उसका विरोध किया और बराबर उसको नीति के खिलाफ रहे और उन्होंने राष्ट्रियता का हिम्मत के साथ पोषण किया। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह से मुसलमानों में वह बइनाम भी हुए। मुझको जब जब कोई जरूरत पड़ती थी, सलाह वगैरा की किसी नाजुक मसजे में, जिस पर कि मुझे स्पोकरी को हैसियत से राय देनी रहती थी, मैंने हमेशा उनके विचारों में सलाह और ईमानदारी देखी। सबमुब इस भवन का उनके चले जाने से और केवल इस भवन को ही नहीं, इस सूबे का गहरो हानि हुई है। मैं आपकी इच्छा के अनुसार उनके कुदुमियों के प्रति आपको सहानुभूति भेजूँगा। मेरा निवेदन है कि आप बड़े हाकर अपना शोक प्रकट करें !

( सदस्यों ने एक मिनट खड़े होकर शोक प्रकट किया । )

**सन् १९४८ के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के ( संशोधन ) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा**

**माननीय स्पीकर—**मुझे घोषणा करनी है कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के ( संशोधन ) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १६ अक्टूबर, सन् १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ५ नवम्बर, सन् १९४८ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति २५ जनवरी, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का पहला ऐक्ट बन गया।

**सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज स्टोरेज रिफ़ीजीशन ( कंटीन्यूएस ऑफ़ पावर्स ) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा**

**माननीय स्पीकर—**मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज स्टोरेज रिफ़ीजीशन ( कंटीन्यूएस ऑफ़ पावर्स ) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ७ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी ६ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति ४ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का चौथा ऐक्ट बन गया।

**सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के ( विशेषाधिकार ) ( अस्थायी ) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा**

**माननीय स्पीकर—**मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के ( विशेषाधिकार ) ( अस्थायी ) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपना २४ नवम्बर, १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १० जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति १३ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गया और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का पाँचवाँ ऐक्ट बन गया।

( संयुक्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल

सन् १९४८ ई० के कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीज्योर

( संयुक्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल पर महामान्य

गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा

**माननीय स्पीकर**—यह भी मेरी घोषणा है कि सन् १९४६ ई० के कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीज्योर ( संयुक्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी २० जनवरी, सन् १९४६ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ७ मार्च, सन् १९४६ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति ३० मई, सन् १९४६ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्त का आठवाँ ऐक्ट बन गया ।

सन् १९४६ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज इवैकुई प्रापर्टी

आर्डिनेंस की प्रतिलिपि का मेज़ पर रक्खा जाना

**माननीय प्रधान सचिव**—मैं सन् १९४६ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज इवैकुई प्रापर्टी आर्डिनेंस की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूँ ।

[ आर्डिनेंस की प्रतिलिपि छापी नहीं गई है । ]

सन् १९३६ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई०

के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधन

की प्रतिलिपि का मेज़ पर रक्खा जाना

**माननीय पुलिस सचिव**—मैं सन् १९३६ ई० के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट की धारा १३३ ( ३ ) के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज़ पर रखता हूँ ।

[ संशोधन की प्रतिलिपि छापी नहीं गई है । ]

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी

आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव

❖ **माननीय प्रधान सचिव**—मैं आपकी इजाज़त से संयुक्त प्रान्तीय लेजि-

---

❖ माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ( United Provinces Legislative Assembly Rules and Standing orders.) में निम्नलिखित संशोधन किया जाय, यह प्रस्ताव करता हूँ

## RULES ( नियम )

१—नियम २९ (Rule 29) के पश्चात् निम्नलिखित नियम २९-ए० (Rule 29-A) के रूप में जोड़ा जाय :—

“29-A. (1, The Secretary shall send to every member a copy of the message received from the Council asking for the concurrence of the Assembly in a motion passed by the Council that a Bill be referred to a Joint Select Committee of both Chambers.

(2) At any time after the receipt of such message from the Council, a Minister in the case of a Government Bill and any member in the case of a non-Government Bill, may move that the motion passed by the Council be agreed to.

(3) If the Assembly agrees, a motion may be made by the mover mentioned in sub-rule (2) nominating the members of the Assembly who are to serve on the Joint Select Committee. If necessary, an election for the requisite number of representatives of the Assembly on the Joint Select Committee will be made. A message shall then be sent to the Council, intimating the concurrence of the Assembly to the motion passed by the Council and the names of the members, elected by the Assembly for the Joint Select Committee.

(4) If the Assembly does not agree to the motion passed by the Council, a message intimating its disagreement shall be sent to the Council.”

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ४३  
में संशोधन करने का प्रस्ताव

### STANDING ORDERS ( स्थायी आदेश )

२—स्थायी आदेश १ ( Standing Order 1 ) के वाक्य खंड ( १ ) [ Clause 1 ) ] में उप-वाक्य खंड ( सी० ) [ Sub-Clause (c) ] के पश्चात् निम्नलिखित उप वाक्य ( खंड सीसी ) [ Sub Clause (cc) ] के रूप में रक्खा जाय ।

“(cc) ‘Joint Select Committee’ means a Committee of members of the Council and the Assembly to which a Bill is referred under these rules after it has been introduced in either Chamber.”

३—स्थायी आदेश ४७ ( Standing Order 47 ) को स्थायी आदेश ४७ ( Standing Order 47 ) का वाक्य खंड ( १ ) [ Clause (1) ] कर दिया जाय तथा निम्नलिखित वाक्य खंड ( २ ) [ Clause (2) ] के रूप में जोड़ दिया जाय ।

“(2) A motion recommending that a Bill should be committed to a Joint Select Committee of both Chambers of the Legislature may be moved at any stage at which a motion for the reference of the Bill to a Select Committee may be moved.”

४—स्थायी आदेश ४८ ( Standing Order 48 ) में जहाँ जहाँ शब्द “Select Committee” आये हैं, उनके पश्चात् शब्द “or a Joint Select Committee” रख दिये जायें ।

५—स्थायी आदेश ५६ ( Standing Order 56 ) के पश्चात् निम्नलिखित स्थायी आदेश ( Standing Orders ) “CC—Joint Select Committee” शीर्षक के अन्तर्गत रख दिये जायें ।

#### “CC—JOINT SELECT COMMITTEE.”

56-A. (1) If the motion recommending the reference of a Bill to a Joint Select Committee of both Chambers is carried, the Secretary shall send a message to the Council asking for their concurrence to the said motion and, in case of their concurrence, for the nomination of the requisite number of members to serve on the Joint Select Committee.

Joint Select  
Committee.

(2) If a message to the effect that the Council does not concur is received by the Assembly, there shall be no reference to a Joint Select Committee.

56-(B) (a) Unless decided otherwise by the two Chambers by mutual agreement the Joint Select Committee shall consist of 25 members.

Election of  
Members by

(b) The Minister in charge of the Department to which the Bill relates shall be a member of every Joint Select Committee.

(c) Of the remaining 24 members including the member, who introduced the Bill, 16 shall be elected by the Assembly and 8 by the Council.



[ सदन के अध्यक्ष का संबोधन ]

56-C. The Minister in charge of the Department to which the Bill relates shall be the Chairman of the Joint Select Committee, unless he waives his right, in which case the Committee shall elect a Chairman from among its members. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or a casting vote.

56-D. After the presentation of the final report of a Joint Select Committee on a Bill, the member in charge may move that the Bill as reported by the Joint Select Committee be taken into consideration.

56-E. The provisions of Standing Orders 49(4), 49(5), 49(6), 49(7), 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 shall, *mutatis mutandis*, apply to a Joint Select Committee.

मैंने इन भवन के सामने एक प्रस्ताव रक्खा है, वह एक बहुत सरल और सीधा है। हमारे असेम्बली के नियम और स्थायी आदेशों में अब तक इस बात के लिये किसी तरह का नियम नहीं है कि जिसके जरिये से एक बिल सेलेक्ट कमेटी के एक ज्वाइंट (सम्मिलित) सेलेक्ट कमेटी को, जिसमें असेम्बली और कौंसिल के मेम्बर हों, भेज सकें। काउन्सिल के नियम और स्थायी आदेशों में इस किस्म के नियम मौजूद हैं। उनके मुताबिक काउन्सिल में अगर कोई बिल पेश हो तो काउन्सिल ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव कर सकती है। मगर हमारे यहाँ इस तरह का अब तक कोई नियम नहीं है। आमकर जमींदारी उन्मूलन बिल के सिलसिले में यह ख्याल हुआ कि यह एक ऐसा महत्त्व का बिल है कि जिसके लिये अगर दोनों भवनों के सदस्यों के प्रतिनिधि मिलकर बैठें और एक मुश्तर्क सेलेक्ट कमेटी के जरिये अपना काम करें, तो सद्गुणियन हो सकेगी। इसी सिलसिले में इस बात की जरूरत मालूम हुई कि हमारे यहाँ के नियमों में कोई संशोधन किया जाय, ताकि इन किस्म की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी हम बना सकें। इसी मतलब को हल करने के लिये यह नियम आपके सामने रखे गये हैं। यदि इस तरह के नियम बनाये जायेंगे, तो जब भी हम चाहें इसी तरह से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी कायम करके ऐसा कर सकते हैं। और बिना इन नियमों के काउन्सिल वाले भी अगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जब तक दोनों भवनों की नियमावली में ऐसे नियम न हों, जिनके द्वारा ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बन सके तब तक एक भवन के नियमों से वह मकसद हासिल नहीं हो सकता। इसलिये इन नियमों को लागू करने के लिये भी इस किस्म की व्यवस्था की आवश्यकता है। इसमें हमने यह नियम रक्खे हैं कि जब कोई ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव यहाँ पेश हो तो उसकी सूचना काउन्सिल को दी जाय और जब काउन्सिल भी इससे सहमत हो, तब इस भवन और काउन्सिल के सदस्य ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये चुन लिये जायें। इसमें सदस्यों की संख्या २५ रक्खी है। इन २५ में एक तो वह मिनिस्टर होगा, जिसके मुहकमे से उस बिल का तात्बुक होगा और बाकी

२४ में से १६ असेम्बली के और ८ काउंसिल के होंगे। असल में हम काउंसिल को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जैसे तो काउंसिल के मेम्बरों की संख्या हमारे असेम्बली के मेम्बरों की संख्या से बहुत ही कम है। और उस अनुपात से अगर उनकी तादाद मुकर्रर की जाय तो वह बहुत कम होती है, मगर काउंसिल के सदस्यों की तरफ से यह एक प्रस्ताव किया गया। उनमें से कुछ ने यह चाहा कि इस तरह से जैसा कि हमने इसमें रक्खा है, एक तिहाई उनके सदस्य हो सकें तो अच्छा हो। उनके यहाँ जो नियम बने हुए हैं, उनमें भी यही है कि मिनिस्टर इञ्चार्ज को छोड़ कर जितने सदस्य हों उनमें तिहाई से कम काउंसिल के न होने चाहिये। इसलिये हमें नियमों को ऐसा बनाने की जरूरत है जो उनके नियमों से बेजोड़ न हों और उनसे मिल सकें। इसलिये जो नियम आपके सामने मैंने रक्खा है वह इस तरह का है कि जो उनके नियम से भी मेल रख सकता है और जिसके द्वारा हम जब चाहें ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को कायम कर सकते हैं। बाज वक्त जब कोई बिल यहाँ से पास होकर और यहाँ की सेलेक्ट कमेटी में उसपर गौर होकर काउंसिल में जाता है तो वहाँ के सदस्यों की कुछ ऐसी भावना होती है कि उनका कोई हाथ उस बिल के ढालने में और उसको आखिरी शकल देने में नहीं रहा और इससे उनको पूरी तरह से बाज मौकों में संतोष नहीं होता। इस कृति को भी हम इन नियमों के द्वारा दूर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन नियमों के बारे में यहाँ कोई मतभेद नहीं होगा और उनको भवन स्वीकार करेगा।

❀ श्री फखरुल इस्लाम—जनाबवाला, आनरेबिल प्रीमियर ने जो तजवीज़ हमारे सामने रखी है, वह उनके कहने के मुताबिक बहुत मामूली है, लेकिन मुझे बहुत हैरत है कि उन्होंने कैसे ऐसी बात कह दी इस सूबे के अन्दर दो भवन इसलिये बनाए गये हैं कि अगर हमारा लोअर हाउस किसी वक्त जल्दी में कोई तजवीज़ बगैरह सोचे समझे मंजूर कर दे तभी सेकंड चेम्बर की जरूरत पेश आती है कि वह उसपर अपनी राय का इज़हार कर सके और उसको रोक सके। यह बहुत अहम और जरूरी सवाल है कि आया अब इस सूबे में सेकंड चेम्बर की जरूरत है या नहीं है और एक ही लेजिस्लेशन के मुताबिक कार्यवाहियाँ होती रहें। अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मैं खुशी के साथ आपकी तजवीज़ को मंजूर करता हूँ। लेकिन कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली की प्रोसीडिंग्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें यह कहा गया है कि हमें एक सेकंड चेम्बर की जरूरत है और उसके लिये एक खास तजवीज़ मंजूर की गयी है। जब यह तजवीज़ हमारे सामने है और जब भवन में यह मंजूर कर लिया गया है कि एक सेकंड चेम्बर हो तो मैं नहीं समझता कि एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की क्या जरूरत पेश आती है।

❀ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[ श्री फखरुल इस्लाम ]

जहाँ तक जमींदारी अवालीशन बिल का सवाल है उसके लिये अगर आप जेम्स क्लॉक नियम बनाने चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह बिल क्लॉक नियम नहीं है कि अगर चेम्बर की यह ड्यूटी है कि वह हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करें, उनकी देखभाल करें और उनकी रोकथाम करें जहाँ तक वह कर सकते हैं, और अक्सर उसने ऐसा किया है। आनरेबिल मिनिस्टर साहब अनन्त मर दिना रहे हैं, लेकिन वह से बहुत से बिल वापिस आ रहे हैं और उनमें से बहुतों को मंजूर किया है और मंजूर किया है। यह एक बहुत अच्छा मकान है और हमारे इस हाउस को ध्यान देना चाहिये।

जहाँ अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस भवन के अन्दर बहुत से कानून चन्द मिनटों के अन्दर खत्म हो गये। नतीजा क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद अमेंडमेंट आए। जो भी जहाँ में बंगर मोचे समझें आप काम करते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि टेक्निकल का रुखा बरबाद होता है। आपको लेजिस्लेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। कानून बनाने वाले को संजीदगी के साथ सोच समझकर मामलान की तरफ देखना चाहिये। मैं इन हालात के पेशेवर में समझता हूँ कि यह प्रायोजन (प्रस्ताव) जो प्रिमियर साहब ने रखा है, किसी हालत में मुनासिब नहीं है। अगर यह बात है तो सेकंड चेम्बर इस सूबे से हटा दिया जाय। इसकी जरूरत नहीं है। इस के बाद मैं यह भी कहूँगा कि ऐवान में उस तरफ ज्यादा राय है। अगर यह मंजूर कर लेंगे तो मैं इसमें यह तरमीम लाऊँगा कि जहाँ तक लोअर हाउस का ताल्लुक है, सोलह की तादाद बहुत कम है। इक्कीस की तादाद होनी चाहिये गो इक्कीस की तादाद भी कम है। इस ऐवान में बड़े-बड़े कितने जिलों और शहरों और कन्स्टीट्यूएन्सियों के नुमाइन्दे हैं। इक्कीस की तादाद में कम महसूस करता हूँ सोलह कर देना तो किसी तरह जायज नहीं है। जनाबाला, इसके लिये अगर आप इजाजत दे सकें तो जबानी तरमीम पेश करूँ कि सोलह के बजाय इक्कीस कर दिया जाय, आठ काउन्सिल के और इक्कीस असेम्बली के इस तरह २६ तादाद हो जायेगी। उसी तौर पर मैं इस का मुखालिफ हूँ। आनरेबिल प्रिमियर साहब इस पर गौर करेंगे। हो सकता है कि तैयार हो जाय।

**माननीय स्पीकर**—श्री फखरुल इस्लाम ने प्रस्ताव के खिलाफ कुछ कहा। वह समय में आया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी बीच में कहा कि अगर ऐसा न हो तो ऐसा हो। वह चीज मेरी समझ में नहीं आयी, मैं उसको तरमीम नहीं मानता।

**श्री फखरुल इस्लाम** मैं उसको वापस लेता हूँ।

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ४७  
में संशोधन करने का प्रस्ताव

**माननीय स्पीकर**— वह तरमीम थी ही नहीं। वह गलत तरीका था। आप तरमीम लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं।

❧ श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—महोदय, उसूलन इस सूरत में मैं इस उसूल से इत्तिफाक नहीं करना कि इस ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को इतना फैलाया जाय कि दोनों हाउसों को अलग सेलेक्ट कमेटी बनाने का मौका न मिले, मगर मैं यह देखता हूँ कि सुरतें ऐसी हैं कि छोटे बिल आते हैं तो सरकार का खर्च बहुत होता है, दो सेलेक्ट कमेटियों में। अगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी न करेंगे तो काउन्सिल इस से महरूम हो जायगी कि वह अपनी राय पेश करे। इस सूरत में इस उसूल को मैं बेजा नहीं समझता कि छोटे बिल में बजाय इस के कि काउन्सिल की सेलेक्ट कमेटी अलग हो एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के जरिये से मामलात तय कर लिये जायँ। इससे खर्च कम होगा। मेरा ख्याल है कि यह मुनासिब है। मगर खासकर जो अहम मसले हैं। उनके लिये दोनों भवनों की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से जैसा, कि लीडर ऑफ् अपोजीशन ने कहा इस दोनों चेम्बर्स का मकसद फेल हो जायेगा। मगर मैं यह देखता हूँ कि इन रूल्स में वह रियायत की गई है यानी असेम्बली जब नामजूर करे या काउन्सिल जब ना मंजूर करे तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी न हो। और उस सूरत में दोनों हाउसों में उसका कोई अन्देशा नहीं है। अन्देशा मुझे इस बात का जरूर है कि अब तो जिस तरह की बातें लीडर ऑफ् अपोजीशन ने कही हैं। उनकी राय से मैं इत्तिफाक नहीं करता हूँ कि ज़िम्मीदारी उन्मूलन बिल इतना छोटा और कम अहम है कि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी की दो कमेटियाँ बनावें। इसको मैं सही नहीं समझता हूँ। मेरा ख्याल बिल्कुल उसके बरअक्स है। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा बिल है कि शायद इस हाउस की ज़िंदगी में अब तक इतना अहम बिल नहीं आया है। इस लिहाज से नहीं कि यह जमींदारों से ताल्लुक रखता है या जमींदारी उन्मूलन करता है जो बात गालिबन लीडर ऑफ् अपोजीशन के जेहन में है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस लिहाज से मैं इसको निहायत अहम समझता हूँ कि यह हमारे सूबे के तमाम खेतों की व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी उलटफेर करता हूँ। इसी लिहाज से इस बिल को मैं निहायत अहम समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल में अगर इस तरह के क्रायदे बना दें तो मुझे ऐसा शुबहा है कि शायद जमींदारी एबालिशन बिल के मामले में इसका निफाज किया जाय। इस बिल के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जमींदारी एबालिशन कमेटी का जो तरीका है, इसका जो अलिफ, बे, क, ख, ग, या ए० बी० सी० है, जिस तरह से यह स्टार्ट (प्रारम्भ) हो रहा है कि इसमें इस तरह का नियम रख दिया जाय जो इतना अहम है यह गलत है। रहा यह कि

❧ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[ श्री जगन्नाथ बडर सिंह ]

इमर्क नमून में मैं इनकी सुव्यवस्था नहीं करता हूँ। मैं यह जानना हूँ कि सरकार दो बड़े अन्विष्ट है कि अगर वह चाहे तो कौन्सिल को सेलेक्ट कमेटी से महसूस कर दे और अन्विष्ट हूँ नहीं है, बल्कि टिनेन्नी बिल के मौके पर जब कमेटी बैठे थे तो कौन्सिल की यह स्वादिष्ट थी लेकिन उनको सेलेक्ट कमेटी से महसूस कर दिया गया मैं नहीं चाहता हूँ कि जिम्मेदारी ऐसे अहम मामले में जो कमेटी है उनमें कौन्सिल के १६ और ८ के हिसाब से मेम्बर न हों लेकिन इस वसूल से मैं हरगिज इन्फाक नहीं करता हूँ कि ऐसी अहम चीज की बुनियाद ही खत्म हो जाय इन बातों को पढ़कर मैंने यही समझा है कि इसका बुनियादी उसूल यही है कि ऐसे अहम मामले में असेम्बली और कौन्सिल दोनों के मेम्बर मिलकर काम करें इम कानून में क्या जरूरत थी ? इसके लिये मैं इतनी गुजारिश कर दूँ कि ४६ बी० ए० में नहीं समझा और रून में यह है—

55—(८) (A) Unless decided otherwise by the two chambers by mutual agreement the joint select committee shall consist of 25 members

55—(ख) (क) जब तक दोनों सभाएँ पारस्परिक समझौते से अन्य प्रकार का निर्णय न करें, संयुक्त विशिष्ट समिति २५ सदस्यों की होगी। ]

यानी यह कि डिसाइडेड बाई म्युचुअल ऐग्रीमेंट, ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी २५ से ज्यादा भी हो सकती है। और उस म्युचुअल ऐग्रीमेंट की परिभाषा और डेफिनिशन क्या है ? आया दो चेंबर्स जब हाउस में शामिल हों तब म्युचुअल ऐग्रीमेंट जाहिर करता है या हाउस के बाहर बिना म्युचुअल ऐग्रीमेंट के जाहिर करता है। इसका नियम के अन्दर मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर म्युचुअल ऐग्रीमेंट न हो, तो ४० मेम्बर भी हो सकते हैं। तो क्या बजाय २५ के आप ४० मेम्बर मंजूर करेंगे ? और—

अनुगत १६ और ८ के बजाय या २५ के अलावा क्या होगा। ये बातें ४६, बी० ए० में जो हैं, उनको मैं जरूरी नहीं समझता। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधान मंत्री इसको नाक करेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर श्री नफीसुल हसन डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

\* श्री मुल्तान आलम ख़ाँ—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त इस भवन के सामने यह मसला है कि हमारे यहाँ के रूल्स और स्टैंडिंग आर्डर में यह तरसीम कर दी जाय कि जब कभी भी असेम्बली इस बात को मुनासिब समझे तो वह कौन्सिल की मंजूरी के साथ और उसकी इत्तिफाक राय लेने के बाद एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बना सके। मैं समझता हूँ कि भवन के सामने जो मोशन है वह एक बहुत जरूरी मोशन है और इससे ऐवान के वक्त की और रुपये की भी बहुत बचत हो सकती है। जहाँ तक मुझे मालूम है खुद इंगलिस्तान

के माननीय सदस्य ने अपना लाफण शुद्ध नहीं किया।

दोनों हाउसों में, पार्लियामेंट के हाउस ऑफ नार्ड्स और हाउस ऑफ कामन्स के कायदों में भी यह मौजूद है कि वहाँ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी जरूरत के बने बनाई जा सकती है। हमारे कॉमिन के क्वायद में भी यह चीज मौजूद है कि ऐसी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई जा सकेगी, लेकिन असेम्बली के क्वायद में यह चीज अब तक नहीं थी कि इस किस्म की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई जा सकती है अगर जरूरत महसूस हो इन मोशन के जरिये इस कमी को दूर किया जा रहा है। जहाँ तक इस कमी को दूर करने का ताल्लुक है, मुझे इससे पूरा-पूरा इन्चिन्क है लेकिन इस सिलसिले में मैं एक बात बहुत सफाई से कह देना चाहता हूँ और वह यह है कि इस कायदे को बरतने के लिये बहुत सोच समझ कर और बहुत गौर खोज के साथ कदम उठाना चाहिये। यह जरूरी है क्योंकि इस ऐवान में बहुत से ऐसे बिल आते हैं, जिनकी कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होनी और उसके ऊपर अगर इस ऐवान की एक सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय और उसके बाद अपर हाउस में उसके पहुँचने के बाद वहाँ एक दूसरी सेलेक्ट कमेटी बैठे तो उसमें बहुत भी बहुत सर्फ होगा, रुपया भी बहुत सर्फ होगा और देरी होने का भी इम्कान है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस कानून से फायदा उठाना चाहिये और एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के जरिये, वह मसला हल कर लेना चाहिये। लेकिन जहाँ तक और बिलों का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि उन बिल्स को हल करने के लिये इन कायदों का इस्तेमाल करके और इसके नफा उठा करके अपर हाउस को उसके खास अख्तियारात से महरूम करना मुनासिब नहीं होगा। इसलिये जैसा कि अभी चन्द दोस्तों ने अपनी तकरीर में बताया कि अपर हाउस का मकसद है कि लोअर हाउस से जो चीज आती है वह उसके सामने जाती है और अगर उसके अन्दर कोई खामियाँ रह जाती हैं, वह उसको दूर करता है। इस तरह से हमारी जल्दी की वजह से वह उस पर पूरी तरह से गौर नहीं कर सकेगा; तो इस किस्म का एक जो चेक (रोकथाम) है, वह ढीला-सा हो जायगा। इसलिये इस सूरत में जो यह हक कौंसिल का है वह कायम रहना चाहिये और कम से कम उन मामलात में जो कोई खास अहमियत के नहीं हैं, बाज्र ऐसे बिल होते हैं, जिनमें एक सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय और उस पर गौर कर ले तो फिर कोई और जरूरत बाकी न रह जाय, ताकि दूसरे ऐवान में एक दूसरे सेलेक्ट कमेटी उसके ऊपर बैठे। ऐसे मामलों में इस कायदे का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है और जैसा कि मैंने कहा कि इंगलिस्तान की पार्लियामेंट भी ऐसा कायदा है और इसके अलावा अपर हाउस में भी यह चीज है लेकिन मैं एक मरतबा फिर इस चीज को अर्ज करूँगा कि जहाँ तक अहम मामलों का ताल्लुक है उनमें इस ख्याल से कि थोड़ा सा वक्त बच सकता है यह न किया जाय और इस एतबार से भी ऐसा न किया जाय कि अगर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय तो इससे इस बात का अन्देशा है कि अपर हाउस का वह

[ श्री सुल्तान गालम गाँ ]

अन्तिमवार जो है वह खत्म हो जायगा इसे न किया जाय । कज़रुल इसलाम न बचने का है कि अभी तो हमें इसका फैसला करना है कि आया अपर हाउस ने ज़रूरत है या नहीं । लेकिन जहाँ तक कान्स्टीट्यूट असेम्बली की प्रेजिडेंट के देखने में मन्द होना है और आइन्दा भी अपने यहाँ अपर हाउस के अन्दर और अपर हाउस को जो ज़रूरत है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है इसलिये ऐसा मूल में मैं आनरेबिल प्रीमियर की तबज़ह खास तौर से इस तरह दिनाङ्क कि वह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के मोशन को मंजूर तो करालें क्योंकि हमारे खत्म में इन किस्म की एक कमी थी लेकिन जहाँ तक अहम मामलों का सम्बन्ध है, उसमें यह प्रोपोजर ( डंग ) न लाया जाय ।

लेकिन जमींदारी खत्म करने के लिये जो खास बिल है, वह बहुत अहमियत रखता है और इस तरह से सेलेक्ट कमेटी कायम होने से काफी बल उसपर गौर करने में बच सकता है । लेकिन इसके साथ ही अगर अपर हाउस को उसके ऊपर एतराज करने का मौका न दिया जाय, तो यह भी मुनासिब नहीं होगा । बहर मूल आनरेबिल प्रीमियर साहब ने यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी का जो मोशन पेश किया है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ ।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, इससे पहले ३० मेम्बरान ने तकरीरें करके आपके सामने चन्द ख्यालात जाहिर किये हैं । मैं अपने दोस्तों से इतनाक करता हूँ । मेरे ख्याल में जब दो हाउस होते हैं और अगर एक हाउस को राय किना किस्म की होनी है और जब वह बिल दूसरे हाउस के सामने जाता है, तो उन पर एक तरह से आजादी से गौर किया जाता है और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी राय हासिल होती है । अलग अलग तरह से उस पर विचार होता है । और सब अपना राय पेश करते हैं और उससे एक अच्छा नतीजा निकलता है । मैं इसको छोटे में करके कह दूँ और मेरी यह राय है कि यह ज्यादा अच्छा है कि हमारी जो दो सेलेक्ट कमेटी हैं उनकी एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी नहीं होनी चाहिये थी लेकिन इस बात को देखते हुए कि यह प्रस्ताव हमारे आनरेबिल प्रीमियर साहब ने भेजा है और यहाँ पर हमारे सामने पेश किया है और बहुत अहम है, इस बात को सोचते हुए तो यह मालूम होता है कि यह मंजूर तो ज़रूर हो जायगा लेकिन मैं सिर्फ़ एक तरमीन इसके अन्दर पेश करना चाहता हूँ और वह यह है कि जहाँ पर लज्ज २५ मेम्बर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर ३१ मेम्बर उनकी जगह पर कर दिये जाँय और उसके बाद लोअर हाउस और अपर हाउस के रिप्रिजेंटेटिव की तादाद २० और १० कर दिये जाँय तो यह बहुत आसान हो जायगा और जो हमारे यहाँ मुखलिफ़ ग्रुप हैं, वह भी उसके अन्दर आ सकेंगे । हमारे यहाँ जनता पार्टी है जो पहले मुसलिम लीग पार्टी थी । उसमें भी

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ५१

में संशोधन करने का प्रस्ताव

अब डिभिजन हो गया है, कुछ लोग अपने को इंडिपेंडेंट पार्टी के कहते हैं। मैं भी उनको इंडिपेंडेंट समझता हूँ, लेकिन वह उस तरह से मेम्बर नहीं हैं। जैसे कि हमारी पार्टी के लोग हैं।

लेकिन मैं यह सही कहता हूँ कि कई मंत्र हैं जो कि मुस्तलिफ ख्याल रखते हैं। जो अच्छा ख्याल रखते हैं, वह अपना ख्याल वहाँ पर पेश कर सकेंगे। मैं यह सोचता हूँ कि इस तरह से आपको सब मंत्र की राय मिल जायगी। उन सब की राय से आपको बहुत फायदा पहुँचेगा। मेरी गुजारिश यह है कि अगर आप इसको मंजूर कर दें तो बहुत आसानी से यह हिस्सा तरमीम हो जायगा कि २५ की जगह पर ३१ कर दिया जाय और उसको वाद २० और १० की तादाद कर दी जाय।

डिप्टी स्पेकर—इस तरमीम की इत्तिला आपने मुझे नहीं दी। इस तरीके पर तरमीम पेश करने की इजाजत आपको नहीं दी जा सकती।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इसे पेश करूँ।

डिप्टी स्पीकर—मुझे मालूम नहीं कि आपकी तरमीम क्या है। मुझे कम से कम पहले लिखकर भेजनी चाहिये थी।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—बहुत छोटी सी तरमीम है। सिर्फ हरेफ '२५' को '३१' से तरमीम करना है। आपसे दरखास्त है कि इसे पेश होने की इजाजत दे दें।

डिप्टी स्पीकर—अगर आप लिखकर दें तो मैं जानना चाहूँगा कि भवन को इसे पेश करने में एतराज है या नहीं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं अभी लिखकर पेश किये देता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—माननीय उद्योग सचिव ने मेरे पास कुछ तरमीमों लिख कर भेजी हैं। वह पेश करें।

माननीय उद्योग सचिव—आपकी इजाजत से मैं कुछ शाब्दिक संशोधन उन संशोधनों में जो माननीय प्रधान मंत्री ने रूल्स और स्टैंडिंग आर्डर्स में पेश किये हैं उनमें पेश करता हूँ।

१. शीर्षक "Rules (नियम)" के नीचे व खंड १ के पहले निम्न-लिखित बढ़ा दिया जाय :—

'नियम २३ ( Rule 23 ) में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee) और "आर" ( or ) के बीच में शब्द "आर ए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी" ( or a Joint Select Committee ) बढ़ा दिये जायँ'

और वर्तमान खंड १ को खंड १ ( क ) किया जाय।



[ सदन की स्थायी समिति ]

२. प्रस्तावित नियम २६—ए के उपनियम ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द 'सूचक' के स्थान पर शब्द 'मेम्बर' ( - ) रखा जाय।

३. प्रस्तावित स्थायी आदेश ( स्टैंडिंग ऑर्डर्स ) १ (सी सी १००) की नौवीं पंक्ति में शब्द 'सूचक' के स्थान पर शब्द 'स्टैंडिंग ऑर्डर्स' रखा जाय।

प्रस्तावित स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर्स ५६ ( बी ) 56-B) के खंड ए बी के स्थान पर निम्न लिखित खंड रखे जायें:

( ) के स्थान पर

— otherwise by the two chambers by

) shall consist of 15 members.

'बी' ( २ ) के स्थान पर

— Minister in charge of the Department to which the Bill is referred, when the Bill is moved by a member of the House. Each member shall be a member of the Joint Select Committee.

'सी' ( ३ ) की जगह पर

( ३ ) Of the remaining members, 8 shall be elected by the two chambers, one having 15 or 16, as the case may be, by the members.

कुछ और प्रस्तावित संशोधन भी हैं, जिन्हें मैं उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ, यह इन प्रकार हैं—

१. नियम ३१ में जहाँ जहाँ शब्द 'Select Committee' आए हैं उनके बाद शब्द 'Joint Select Committee' रख दिये जायें।

२. स्थायी आदेश ६ ( ३ / ४ ) व ( ५ ) में व स्थायी आदेश २१ के प्रतिबन्ध ( ३ ) में शब्द 'Select Committee' के बाद शब्द 'Joint Select Committee' जोड़ दिये जायें।

यह सब प्रस्तावित संशोधन हैं जो मैंने उपस्थित किये हैं। मैं आशा करता हूँ कि भवन उन्हें स्वीकार करेगा।

डिप्टी स्पीकर—श्री फिलिप्स अब आप की तरसीम आ गई है। अब आप जानने के लिए उस अपनी तरसीम पेश कर दें।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—जनाबवाला, आप की इजाजत से मैं यह तरसीम पेश करता हूँ कि क्लॉ ५६ ( बी ) लास्ट ( आखिरी ) लाइन।

**डिप्टी स्पीकर**—यह आपका पेश करने का तरीका सही नहीं है। आप को गालिबन मालूम होगा कि यहाँ कार्यवाही हिन्दी में होती है। और आप हिन्दी में इस तरह से कह सकते हैं कि “आखिरी सतर या पंक्ति में २५ के बजाय ३१ कर दिया जाय।” आप जो चाहते हैं, वह हिन्दी में कहिये।

**श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स**—गुजारिश यह है कि स्थायी आदेश की ५-६ (बी) (ए) की आखिरी लाइन में जहाँ २५ लिखा हुआ है, वहाँ ३१ कर दिया जाय। और इसी कायदे के मातहत (सी) में, पहली लाइन में जहाँ २४ लिखा हुआ है, वहाँ २०, और दूसरी लाइनों में जहाँ १ और ८ लिखा हुआ है वहाँ क्रमशः २० और १० कर दिया जाय।

इस की जरूरत के मुताल्लिक दुहराना मेरे ख्याल में बेकार है। मगर अगर यह मंजूर हुआ तो इस में नुमाइन्दगी का ज्यादा हो जायगी। यह सबसे अहम बात है अगर ऐसा हुआ। अगर यह गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर कर लिया जायगा तो इस में कोई इंजस्टिस (अन्याय) नहीं होगा।

**\* माननीय प्रधान सचिव**—मैंने श्री फखरुल इस्लाम, राजा जगन्नाथ बख्श सिंह और दो मेम्बरों की तकरीरों को सुना। मुझे फखरुल इस्लाम साहब की तकरीर को सुनकर एक वकील की दलील याद आई। उन्होंने अपने मुवक्किल की तरफ से जिसे फाँसी की सजा हुई थी या कालेपानी की हुई हो, अपील में बहुत बहस की तो जज ने कहा कि गनोमत है कि मेरे सामने कोई अपील नहीं, नहीं तो आपकी दलील को सुनकर मैं उसको कालेपानी की जगह फाँसी की सजा दे देता। मैं उनकी बहस को समझ नहीं पाया। उनकी दो दलीलें थीं। एक तो यह कि कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली ने यह तय कर दिया है कि अपर हाउस हो। दूसरे यह कि जो बिल यहाँ पर पास होते हैं, वह बहुत उजलत में होते हैं और हाउस को गौर करने के लिये काफी मौका नहीं मिलता।

इन दोनों दलीलों की बुनियाद पर अगर कोई नतीजा निकल सकता हो तो वह यह हो सकता है कि जो तजवीज मैंने की वह उसी को पसंद करते हैं और तार्ईद करते हैं। मगर उन्होंने बजूहात ऐसे दिये जिससे तार्ईद होजाती थी मगर यह समझ कर कि उन्हें तो लीडर आफ् अपोजीशन की हैसियत को कायम रखना है इस लिये दलील चाहे कुछ भी क्यों न हो, इसका विरोध किया मगर इसका मेरे ऊपर या सुननेवालों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राजा साहब की बात को सुनकर मुझे कुछ नाउम्मीदी सी हुई। क्योंकि यह जो तरमीम रक्खी गई थी वह इस गरज से रक्खी गई थी कि उनकी तबियत में अगर किसी तरह की कोई परेशानी

[ सदन में बयान सदिब ]

हृदय में जो उस मजदूर के दिल में है वह तब तक नहीं पड़ेगा। आज कुछ और भी है, जो मैं नहीं कह सकता। मैं भी अच्छे काम दे रहे हूँ। मैं और भी राजा महार का क्या, इतना गर्मी पैदा हुई, क्यों उन्हें तब तक इतना नाराज़ मत मानूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह मान में बात है और वह यह कि अगर यह हाउस चाहे और कौंसिल भी चाहे तो यह उन लोगों को और लोग में से एक भी न चाहे तो नहीं बनेगा हमने क्या उज्र हो सकता है मेरी समझ में यह नहीं आया। अगर यह होता कि चाइल्ट कमेटी बनाना नज़िमें होना चाहे यह हाउस चाहता या न चाहता या दूसरा काम चाहता या न चाहता। तब तो डर हो सकता था कि उन्हें न हो मगर जब लोग भवनों की रजामंदी से कमेटी हो सकेगी तब खतरा किम बात है मगर यह कि अगर उनमें और ऐतबार न हो और धोखा खा जायें। हमने उन अंग्रेजों को बाधकर रखने के अंग्रेजों और कोई बजह समझ में नहीं आती।

और दूसरी बात यह है कि इस बिल में ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के बनाने के मताना यह होगा कि उन नमाम लोगों की राय बिल के आखिरी शक्ति देने के बने इस में आ सके और इन को सुधारने में सब की मदद हो सके और मैं समझता हूँ कि इस के लिए किमी को न किमी तरह का उज्र न होना चाहिए। पार्लियामेंट ( राजनीति ) में शुक्रिया की गुंजाइश नहीं होती निहाय मैं भी उम्मीद कम रखता हूँ मगर बिना जरूरत जिस बात से अपने को फायदा होता है, उसको ठुकराने से कोई नफा नहीं हो सकता। मान लीजिये कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी न हो और इस हाउस से यह बिल कतई तौर पर बन जाय मगर इस से भी तो जमींदारों को कोई ज्यादा फायदा न होगा। मेरा और दूसरे लोगों का सभी का यही ख्याल होगा कि कुछ फायदा इस तरह से नहीं होगा ऐसी हालत में जब आसानी पैदा करने के लिए कोई काम किया जाय और उस पर खानपान हो तो इस से तो यह नतीजा निकलता है कि उन के फायदे और नुकसान की क्या बात है यह वह नहीं समझते हैं और अगर ऐसी ही बात है तो किमी बिल की ताईद या मुखांलफत करना कोई भी माना नहीं रखता और न उस का कोई असर होता है। क्योंकि उन को तो इस के समझने में ही दिक्कत होती है कि क्या चीज उन के फायदे की है और क्या बात उनके नुकसान की है। लिहाजा इस तरह से उन की बात की कद्र भी कम हो जाती है और कुछ बकत नहीं रहती।

जहाँ तक इस की तादाद की बात है मैंने आप से पहले भी कहा था कि अपर हाउस के साथ जिस तरह से उदारता की जा सकती है वह उदारता का व्यवहार है। १६ यहाँ के और ८ अपर हाउस के मेम्बर हमने रखे हैं, गोकि हमारे इस हाउस के मेम्बरों की तादाद ज्यादा है और उस अनुपात से अपर हाउस

वालों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन चूँकि अपर हाउस का कायदा एक लिहाज से कम न होने का है और दूसरे अपर हाउस की तरफ से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी होने की खाहिश थी, लिहाजा उनकी खाहिश को पूरा करने के लिए यह चीज आप के सामने रखी गई है। मैं समझता हूँ कि राजा जगन्नाथ बक्श सिंह साहब के मुकाबले में मैंने अपर हाउस के मेम्बरों की नुमाइन्दगी ज्यादा बेहतर तरीके पर की है लिहाजा इस बिल के मामले में मेरी राय न मानना और उन की राय मानना एक गलती होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक इस संशोधन का ताल्लुक है फिलिप्स साहब ने ३१ की बाबत तजवीज़ की है। मैं समझता हूँ कि २५ की तादाद काफी है और उसे ज्यादा बढ़ाना फायदेनन्द न होगा। इस में इतनी गुंजायश जरूर रखी गई है कि दोनों हाउस वालों को हक होगा कि वह दोनों मिलकर अगर चाहें तो इस को २५ के बजाय ४० या ५० कर दें। पीछे ऐसा होगा जैसे और तमाम कार्यवाही दोनों भवनो की होती है। हमें उम्मेद है कि दोनों हाउस के मेम्बरों के बहसमुबाहिसे के बाद सब की रज़ामन्दी हो सकेगी और इसलिए इस में कोई खतरा की बात नहीं है। जो संशोधन उद्योग सचिव ने पेश किए हैं वह बिल्कुल लफ्जी हैं और लफ्जों को साफ करने के लिए हैं। उनमें कोई नई बात नहीं है। मैं उम्मेद करता हूँ कि इस में किसी को इख्तलाफ न होगा और जि साहबाज ने अब तक कोई मुखालफत की है वह अब यह समझेंगे कि उन का फायदा इसी में है कि वह इसे मंजूर कर लें। इस के बाद भी हाउस को अख्तयार होगा कि वह इस बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी बनावे या न बनावे और यह भी अख्तयार है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी न बनाकर सब मसलत यहीं तै कर दिए जायँ।

यों तो अपने को पूरी आजादी है। हाउस की यह खाहिश हो कि यह जमींदारी एबोलूशन बिना किसी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को सुपर्द किए हुए यहीं फैसला हो जाए तो उसमें मुझे कोई उज्र नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—अब मैं माननीय उद्योग सचिव द्वारा उपस्थित किए गये संशोधनों पर राय लेता हूँ।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैंने जो तरमीम पेश की है, जनाबवाला इजाजत देंगे कि मैं उसे वापिस ले लूँ।

डिप्टी स्पीकर—आप वापिस लेना चाहते हैं।

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स—मैं सोचता हूँ कि यह ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट को नामंजूर है। लड़ना बेफायदा है। यह काम तो मुखालिफ पार्टी का है।

( भवन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया )

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि शीर्षक (नियमों) 'Rule' के नीचे ब  
 ड १ के अन्तर्गत यह शब्द बढ़ा दिये जायँ—

(१) नियम २३ अथवा २३) में शब्द "सेलेक्ट कमेटी" (Select Committee)  
 व शब्द "आर" के बीच में शब्द "आर ए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी" (or a Joint  
 Select Committee) बढ़ाये जायँ और वर्तमान खंड १ को खंड १ (क)  
 किया जायँ

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि प्रस्तावित नियम २६—A के पीछे नियम  
 ३ के प्रथम पंक्ति में शब्द "मूवर" ( mover ) को हटाकर "शब्द" "मेम्बर"  
 ( member ) रखा जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि नियम ३४ में जहाँ-जहाँ शब्द "सेलेक्ट  
 कमेटी" ( select committee ) आए हैं, वहाँ उसके बाद शब्द "आर ए ज्वाइन्ट  
 मिनेक्ट कमेटी" ( or a joint select committee ) और बढ़ा दिए जाएँ ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि प्रस्तावित स्थायी आदेश ५६ ( बी ) के  
 स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय ।

56- —Unless decided otherwise by the two chambers by

( a . I = Joint Select Committee shall consist of 25  
 members.

( २ ) The Minister incharge of the Department to which the  
 Bill relates, and, where the bill is moved by a member other  
 than the Minister, such member shall be members of every  
 Joint Select Committee.

( c ) Of the remaining members 8 shall be elected by the  
 Council and the remaining 15 or 16, as the case may be by the  
 Assembly.

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि प्रस्तावित स्थायी आदेश (cc) की तीसरी

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ५७  
में संशोधन करने का प्रस्ताव

पंक्ति में शब्द रूल्स ( rules ) के स्थान पर शब्द स्टैंडिंग आर्डर्स ( standing orders ) रखे जायँ ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

डिप्टी स्पीकर—सवाल यह है कि स्थायी आदेश 6 ( 3 ) ( iii ) और ( iv ) में और स्थाई आदेश २१ के प्राविजो ( ए ) [ Proviso ( a ) ] में शब्द “सेलेक्ट कमेटी” ( Select Committee ) के आगे शब्द “आर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी” ( or Joint Select Committee ) बढ़ा दिये जायँ ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

डिप्टी स्पीकर—अब इन संशोधनों के पश्चात् इस प्रस्ताव का रूप इस प्रकार रहता है :—

संयुक्त प्रान्त के लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये जायँ ।

### RULES ( नियम )

१—नियम २३ ( Rule 23 ) में शब्द “सेलेक्ट कमेटी” ( Select Committee ) और शब्द “ or ” के बीच में शब्द “आर ए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी” ( or a Joint Select Committee ) बढ़ा दिये जायँ

१ ( क )—नियम २६ ( Rule 29 ) के पश्चात् निम्नलिखित नियम २६-ए० ( Rule 29—A ) के रूप में जोड़ा जाय—

“29-A ( 1 ) The Secretary shall send to every member a copy of the message received from the Council asking for the concurrence of the Assembly in a motion passed by the Council that a Bill be referred to a Joint Select Committee of both Chambers.

Motion for  
reference to  
a Joint  
Select Com-  
mittee.

( 2 ) At any time after the receipt of such message from the Council, a Minister in the case of a Government Bill and any member in the case of a non-Government Bill, may move the motion passed by the Council be agreed to.

( 3 ) If the Assembly agrees, a motion may be made by the member mentioned in sub-rule ( 2 ) nominating the members of the Assembly who are to serve on the Joint Select Committee. If necessary, an election for the requisite number of representative of the Assembly on the Joint Select Committee

will be made. A message shall then be sent to the Council intimating the concurrence of the Assembly to the motion passed by the Council and the names of the members elected by the Assembly for the Joint Select Committee.

( 4 ) If the Assembly does not agree to the motion passed by the Council, a message intimating its disagreement shall be sent to the Council."

अब इसका दूसरा हिस्सा आता है। अब तक इस संशोधन के संबंध में ? ( क ) हुआ। अब ? ( ख ) आता है; वह इस प्रकार है—

“ १ ( ख ) क्लॉ ३४ में जहाँ-जहाँ शब्द “a Select Committee” आए हैं, वहाँ उनके बाद शब्द “or a Joint Select Committee” रखे जायँ।

### STANDING ORDERS ( स्थायी आदेश )

० स्थायी आदेश १ ( Standing Order 1 ) के वाक्य खंड ( १ ) [ Clause ( 1 ) ] में उप-वाक्य खंड सी [ Sub-clause ( c ) ] के पश्चात् निम्नलिखित उप वाक्य खंड ( सी सी ) [ Sub-clause ( cc ) ] के रूप में रक्खा जाय।

“( cc ) ‘Joint Select Committee’ means a Committee of members of the Council and the Assembly to which a Bill is referred under these standing orders after it has been introduced in either chamber,”

२ ( क ) स्थायी आदेश ६ ( ३ ) ( iii ) व ( iv ) [ Standing Order 6 ( 3 ) ( iii ) and ( iv ) ] में और स्थायी आदेश २१ के प्राविजो ( ए ) [ Poriso ( a ) ] में शब्द “a Select Committee” के बाद शब्द “or a Joint Select Committee” बढ़ा दिए जायँ।

३. अस्थायी आदेश ४७ ( Standing Order 47 ) को स्थायी आदेश ४७ ( Standing Order 47 ) का वाक्य खंड ( १ ) [ Clause ( 1 ) ] कर दिया जाय तथा निम्नलिखित वाक्य खंड ( २ ) [ Clause ( 2 ) ] के रूप में जोड़ दिया जाय।

“( 2 ) A motion recommending that a Bill should be committed to a Joint Select Committee of both Chambers of the Legislature may be moved at any stage at which a motion for the reference of the Bill to a Select Committee may be moved.”

४. स्थायी आदेश ४८ ( Standing Order 48 ) में जहाँ जहाँ शब्द “Select Committee” आए हैं, उनके पश्चात् शब्द “or a Joint Select Committee” रख दिए जायँ।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों ५६  
में संशोधन करने का प्रस्ताव

५. अस्थायी आदेश ५६ ( Standing Order 56 ) के पश्चान् निम्नलिखित  
स्थायी आदेश ( Standing Orders ) "CC—Joint Select Committee"  
शीर्षक के अन्तर्गत रख दिए जायें ।

**"CC—JOINT SELECT COMMITTEE."**

56-A. ( 1 ) If the motion recommending the reference of  
a Bill to a Joint Select Committee of both Chambers is carried,  
the Secretary shall send a message to the Council asking for  
their concurrence, to the said motion and, in case of their  
concurrence for the nomination of the requisite number of  
members to serve on the Joint Select Committee.

Joint Select  
Committee.

( 2 ) If a message to the effect that the Council does not  
concur is received by the Assembly. there shall be no reference  
to a Joint Select Committee.

56-(B). Unless decided otherwise by the two Chambers by  
mutual agreement—

Election for  
Member by  
Assembly.

( a ) The Joint Select Committee shall consist of 25 mem-  
bers.

( b ) The Minister in charge of the Department to which  
the Bill relates, and, where the Bill is moved by a member other  
than the Minister, such member shall be members of every  
Joint Select Committee.

( c ) Of the remaining members, 8 shall be elected by the  
Council and the remaining 15 or 16, as the case may be, by  
the Assembly.

56-C. The Minister in charge of the Department to  
which the Bill relates shall be the Chairman of the Joint Select  
Committee, unless he waives his right, in which case the  
Committee shall elect a Chairman from among its members.  
In case of an equality of votes, the Chairman shall have a  
second or a casting vote.

Procedure  
of Joint  
Select  
Committee.

56-D. After the presentation of the final report of a  
Joint Select Committee on a Bill, the member in charge may

Motion after  
Presentation  
of report.



move that the Bill as reported by the Joint Select Committee be taken into consideration.

A - 131 a  
C - 131 a  
S - 131 a  
( 7 )

55-E The provisions of Standing Orders 49 ( 4 ), 49 ( 5 ), 49 ( 6 ), 49 ( 7 ), 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 shall, mutatis mutandis, apply to a Joint Select Committee.

सवाल यह है कि यह संशोधित प्रस्ताव मंजूर किया जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

मन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

\* माननीय प्रधान सचिव—मैं मन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल उपस्थित करता हूँ ।

( ध्याता नहीं गया )

माननीय प्रधान सचिव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय ।

डिप्टी स्पीकर—इस प्रस्ताव में आपको कुछ समय बताना चाहेंगे ।

माननीय प्रधान सचिव—इसके लिये तो समय मुकर्रर है ।

डिप्टी स्पीकर—दो महीने होंगे ।

माननीय प्रधान सचिव—दो महीने से कम नहीं होता है । रूल यह है कि दो महीने से कम न हो ।

मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आज इस भवन के सामने इस बिल को उपस्थित करने का यह मौका मिला है । जिस बात का हम और कांग्रेस और हमारे सूबे के करोड़ों अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान वर्गों से आशा लगाए हुये थे । जो हमारे आदर्श के अनुसार हमारा एक मुख्य कर्तव्य था । एक दिन के स्वप्नों को हम बहुत दिनों से एक क्लिप्स की कल्पना में देखा करते थे, उनको व्यावहारिक रूप देने उनको की आज इस शक्त में यहाँ पेश करने का यह अवसर मुझे वर्गों के परिश्रम और यत्न करने के बाद आज मिला है । इसके लिये मैं इस हाउस के सब सदस्यों को, जिन्होंने इस काम में सहयोग दिया, धन्यवाद देता हूँ । जमींदारी एबोलीशन कमेटी के सदस्यों को इसके बाद उन सब को जिन्होंने इस बिल को तैयार करने में हिस्सा लिया, सेक्रेटरिएट के अधिकारियों को, अपने साथी, सचिवों को और अपने सहकारी पार्लमेंटरी सेक्रेटरियों को विशेषकर चरणसिंह जी को धन्यवाद देता हूँ ।

§ माननीय प्रधान सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

मुझे आप को इस बारे में बहुत सी बातें कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है मैं समझता हूँ कि यह विषय, यह मसला इतना आम लोगों के सामने आया है कि उसके बारे में बहुत लम्बी तकरीर की जरूरत नहीं है। कम से कम आखिरी बीस साल में बार-बार इसकी चर्चा होती आई है। हमारे स्पीकर महोदय यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने आज से बीस वर्ष हुये जमींदारी उन्मूलन की बात को बड़े जोर के साथ देश के सामने रक्खा था। जवाहरलाल जी ने भी इस आदर्श को हमारे सामने रक्खा था। तब से कांग्रेस की कुछ कमेटियाँ भी हुईं। एक एमेरियन कमेटी भी हुई। उससे भी मेरा कुछ थोड़ा सा सम्बन्ध है। और इस विषय में विचार विनिमय होता रहा। आपको याद होगा, ७ अगस्त, सन् १९४६ ई० को अगर मुझे तारीख ठीक याद है तो इस भवन ने श्री रफी अहमद किदवाई के प्रस्ताव पर इस बात को स्वीकार किया था कि जमींदारी खत्म कर दी जाय, मध्यवर्तियों को अलग किया जाय और एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जो इस प्रान्त के उपयुक्त हो। इसी सिलसिले में उस कमेटी ने बहुत दिनों तक काम किया और मैं समझता हूँ कि ६ अगस्त को पारसाल उस कमेटी की रिपोर्ट छपी थी। उस कमेटी में इस भवन के सभी दलों के प्रतिनिधि थे और उस कमेटी ने जिस योग्यता से काम किया, श्री अमीर रजा, श्री भा साहब और उसके तमाम मन्त्री और सदस्यों ने जिनमें श्री अजित प्रसाद जी जैन का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है, उन सब ने उद्योग किया। हमने उसकी रिपोर्ट शाया की। आज वह दिन आया है कि जब कि यह बिल हम उपस्थित कर पा रहे हैं। और इसमें हमारे जुडिशियल सेक्रेटरी श्री वशिष्ठ भार्गव, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री निगम और औरों ने पूरी तरह से सहायता पहुँचायी, तब इस बिल को आपके सामने रखने का मौका मिला। किसी नये क़ानून को बनाना, उसके मसविदे को बनाना काफी कठिन काम होता है। मैंने आपसे कहा कि यह बिल हमारे हाँसिले को पूरा करने वाला है, यह कांग्रेस के आदर्शों को पूरा करने वाला है। और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इस देश के जितने जिन्दा दिल लोग हैं, जिनकी जनता के साथ वास्तविक सहानुभूति और हमदर्दी है, जो यह चाहते हैं कि इस मुल्क का हर आदमी अपना माथा ऊँचा करके और अपनी कमर को सीधी करके चल सके, जो चाहते हैं कि हर किसी को खाने को मिले और पहनने को मिले, रहानी जिस्मानी और माली तरक्की हो और हर आदमी शान के साथ यहाँ रह सके, उन सब को इस बिल का स्वागत हृदय से करना चाहिये।

मैं समझता हूँ कि हमने यदि स्वराज्य प्राप्त किया है तो वह स्वराज्य प्राप्त करने से दो उद्देश्य हमारे सिद्ध होने चाहिये। एक तो यह है कि हमारे वहाँ हर मनुष्य ऊँचे से ऊँचे स्तर को उठा सके, किसी का दबाव उस पर न हो, कहीं रुकावट उसके रास्ते में जिस मंजिल को वह पहुँचना चाहता हो वहाँ पहुँचने में न हो।

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

चाहे हर एक आदमी मुची हो और बड़ा हो, मगर कोई दुखी न हो और कोई छोटा न हो। यह हमारा आदर्श है। इसलिये जमींदारी का उन्मूलन एक एथीकल नेमेनिटी (नैतिक आवश्यकता) चाहे और बात जो भी हो, हो जाता है। इसलिये हमारे यहाँ का हर एक मनुष्य जो कि मेहनत करता है वह अपने मनुष्यता के हक को पा सके, उसके और सरकार बीच में कोई मध्यवर्ती, मदाखलत करनेवाला न हो; यही उसकी नैतिक उन्नति के लिये परमावश्यक है।

“मैंने निम्न नाट बाई ब्रेड एलोन” (मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीता है) चाहे हमारे किस्मतों को खाने के लिये सब पदार्थ न भी मिलने हों, मगर उनकी अन्मा को यह सुख हो, उनको यह संतोष हो, उनको यह विश्वास और अख्यान हो कि वे न्वतंत्र होकर अपने अपने घरों में अपने अपने गाँवों में रह सकते हैं और कोई दूसरा उनके ऊपर हावी होने का कोई मौका नहीं रखना है। यह परमावश्यक है। इसलिये इस एथीकल (नैतिक) जरूरत को पूरा करने के लिये जमींदार को खतम करना जरूरी हो जाता है। कोई हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम जमींदारों को भी अपने को मित्र समझते हैं, और उनकी मैत्री को प्राप्त करन हमेशा हमने अपना आदर्श माना है। परन्तु उनकी मैत्री के माने भी यही हैं कि वे कार्य हों, जिनसे हमारे देशान एक नये जीवन से गुँज उठें। उनके भाई और पड़ोसी सब समता के भाव में उनके करीब रहने हुये सुखी हो सकें और आनन्द के साथ, अगर पूरी तरह से नहीं, तो कम से कम आत्माभिमान को बगैर ठेस लगाये हुये गर्व के साथ अपनी दिनचर्या कर सकें। इसलिये उनके आत्माभिमान की सुरक्षा के लिये इस योजना की परमावश्यकता है।

इसके द्वारा हम और भी काम कर सकते हैं। आज हमारे देश में बहुत से सवाल हमारे सामने हैं। जैसा मैंने अभी कहा, यह जमींदारी खतम करने की बात जब हम परार्धान थे, तब से चत रही है। यह कम से कम बीस तीस वर्ष से हमारे यहाँ एक प्रेक्टिकल पॉजिटिक्स (क्रियात्मक राजनीति) के अन्दर आई हुई बात है और किसी मसले पर अगर पूरी तरह से गौर करने का यत्न और कोशिश की गई है तो वह इस जमींदारी के मसले पर की गई है। इसलिये यह वैसी ही परम आवश्यक है; परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि इस बीच में हमारे देश में और भी बड़े, परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जिससे इस प्रथा का रखना, या ऐसी प्रथा का रखना, जिससे कि एक मनुष्य दूसरे के ऊपर उसके आर्थिक संकट में एक दबाव की हालत को रखे, वह अब हमारे इस मौजूदा राजनैतिक क्षेत्र में असम्भव सा हो गया है।

हमने, १५ अगस्त सन् १९४७ ई०, को स्वराज्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक यह आशा करता है कि उस स्वराज्य के

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ६३

फलस्वरूप उसका स्तर ऊँचा हो, उसको दबानेवाला कोई न रहे, वह सुख के साथ रह सके और एक नागरिक की तरह उसका बराबरी का दर्जा हो और उत्साह के साथ, ज्ञान के साथ, आत्माभिमान की सुरक्षा करते हुये हर जगह पर उसको हासिल हो।

इसलिये १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० के बाद, स्वराज्य प्राप्त करने के बाद, इस तरह की एक प्रथा का जो कि विदेशियों ने इस देश में आरम्भ की थी और जैसा कि बहुत से सदस्यों को मालूम होगा लोगों को इसलिये नियुक्त किया था कि वह उनके लिये लगान जमा करते रहें और उसमें से १० फी सैकड़ा या ५ फी सैकड़ा कमीशन खुद ले लें और ६० या ६५ फीसदी उनको दे दें। यह प्रथा विदेशियों की बनाई हुई एक प्रथा थी और यह हमारे देश के अपने मौलिक जीवन के विपरीत एक प्रथा थी। हमारे यहाँ, वैदिक काल में भी और उसके बाद भी जो लोग यहाँ के साहित्य से परिचित हैं जानते होंगे कि हमेशा धरती पर जोतनेवाले का अधिकार रहा और उसके और शासक के बीच में कोई मध्यवर्ती नहीं रहा। इसलिये आज जो भी कार्यवाही की गई, वह इसलिये की गई कि विदेशी अपना काम निकालने को और लोगों को उसमें डाल देने को और अपना मतलब हल करने के लिये यह प्रथा लाये थे मगर वह कोई हमारी नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रथा नहीं थी। आज जब हमारा स्वराज्य हो गया है, हमें अपने देश में अपनी प्राचीन संस्कृति और उन स्तम्भों को जो कि आज के जमाने में भी हमारे देश को ऊँचा करने में, हमारे देश की अवस्था सुधारने में, कारगर हो सकते हैं, फिर पुनर्जीवित करना है। हमारे वहाँ ग्रामों की अवस्था प्राचीन काल में एक तरह से रिपब्लिक (जन-तंत्र) की - सी हो जाती थी और उनका सब प्रबन्ध विलेज कम्यूनिटी ही किया करती थी। आज हमको जब स्वराज्य प्राप्त हो गया है तो उससे उस स्तर का पूरा अंश हमारे ग्राम-वासियों और खेतिहरों को मिले और उसको मिलने के लिये इस जमींदारी उन्मूलन बिल का बनाना परमावश्यक है। इसलिये भी जब स्वराज्य आ गया, तब जो पहले से हमारा उद्देश्य था जिसको प्राप्त करने में हम लगे हुये थे, जो हमारा आर्द्रश था वह और भी एक प्रबल शक्ति को प्राप्त कर गया और उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य हो गया। आपने शायद जो मैंने जिस दिन यह बिल निकला था, उस दिन प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था सुना होगा। मैंने तब भी कहा था और मैं समझता हूँ कि आज भी यदि मैं उसे दोहराऊँ तो अनुचित नहीं है कि हमारे प्रान्त के इतिहास में पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना सबसे बड़ी बात थी और उसके अनन्तर अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी बात हो सकती थी और है, तो वह जमींदारी का उन्मूलन करना है।

आज हम अपने देश में, अपने वहाँ के पाँच करोड़ लोगों में अपने वहाँ के एक लाख से अधिक गाँवों में, वास्तविक स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। आज

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

हम अपने देश के उन लोगों को जिनकी कि जर्जरित अवस्था रही है, जो बहुत मं. क्रिमी जमाने से. यातनाओं को भोगते आये हैं, आज उनको फिर उनके स्वाभाविक स्तर को प्राप्त करने और उसके अनुसार ऊँचे से ऊँचे स्तर का क्षेत्र उनके लिये तैयार कर रहे हैं। इसलिये हमें इस बात को देखना है कि आज हमें इस चिन्त को यह पेश करने का मौका मिला है। पर यह विल वैसे भी एक तरीकों का और उन बातों का जो कि समय समय पर होती आयीं, एक स्वाभाविक परिणाम हैं। आप जानते हैं जमींदारों के जो कुछ जत्र थे या उनमें से कुछ के जो थे. उनको रोकने के लिये विदेशी सरकार ने भी समय - समय पर कानून बनाये।

पढ़ने जिसको वह चाहते थे. उसको कान पकड़ कर निकाल सकते थे। उसके लिये बेदम्वन करने की नुमानियत की गई। उसके बाद फिर कुछ और कानून इस तरह के बनाए गये कि जिस से ७ साल १० साल, १५ साल तक आदमी काविज रह सके। उसके बाद फिर उनको हैरिडिटेरी लाइफ टेनेन्सी अवध में दी गई और आगम में ओकुपेन्सी टेनेन्सी के हक दिये गये। मगर इन सब बातों के होने पर भी जो कृषक वर्ग था, उसकी कठिनाई दूर नहीं हुई। उनके और जमींदारों के बीच संघर्ष बढ़ता ही गया और आपस में जो मायुर्य का वर्ताव देहातों के अन्दर था वह टूटना गया और उसके बदले में आपस में कड़वाहट आ गई। इन सब बातों के करने पर भी और हम लोगों के नये कानून बनाने पर भी चंद काश्तकारों को अपने खेतों. अपने पेड़ों और अपनी आवादी के हर तरह के हक दिये गये, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली और तसकीन नहीं हुई और आपस में भ्रंश और भगड़े चलने लगे। अब इलाज क्या इलाज रह गया? जितनी दवायें थीं वह सब की गईं लेकिन मर्ज दूर नहीं हुआ। आखिर में एक ही इलाज रह गया और वह था जमींदारी का खतम करना। जमींदारी के किस ढाँचे को रखना चाहिये यह सोचकर जितने भी अधिकार दिये जा सकते थे, वह सब दिये गये। परन्तु उससे मामला सुलझा नहीं। वह भ्रंश बढ़ता ही गया। इसलिये एक रिस्टोरिक ऐतिहासिक तरीके पर वह जिस तरह से डेवलपमेंट होता गया, उसके लिये यह एक बिल्कुल जरूरी हो गया कि जमींदारी को खतम किया जाय। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है वह सब इन सब बातों से नहीं कि यह शिकायतें थीं उनको दूर किया जाय बल्कि इसके साथ ही साथ हम तो यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करके आये थे। जिस वक्त चुनाव हुआ था कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कह दिया था कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था। कि इंटरमिडियरिज ( मध्यवर्ग ) का दूर करना और जमींदारी प्रथा को खतम करना हमारा आदर्श और उद्देश्य होगा। जो हमारा एलेक्शन मनिफेस्टो था, उसमें कहा गया था The reform of the land system which is so urgently needed in India involves the removal of intermediaries between the

peasant and the State. The rights of intermediaries should therefore, be acquired on payment of equitable compensation. ( भारत में भूमि व्यवस्था के ऐसे सुधार की तुरन्त आवश्यकता है जिसमें किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ व्यक्ति न रहें। इसलिये उचित हरजाना देकर मध्यस्थ व्यक्तियों के अधिकारों को हस्तगत कर लेना चाहिये। )

हमको काश्तकारों ने वोट दिया और हम से कहा गया और जमींदारों ने भी अपने बयान में कहा था कि उन्होंने भी हमको वोट दिया था इस मेनिफेस्टो के आधार पर, जिसके माने यह हैं कि दोनों ने यह मान लिया था कि इस तरीके पर यहाँ इंटर-मिडियरिज को दूर करके इक्विटेबिल कम्पन्सेशन (उचित मुआबिजा) उनको दिया जाय और यही एक उचित रास्ता है और यही होना चाहिये। इस मेनिफेस्टो के आधार पर हम लोग एलेक्शन में कामयाब होकर यहाँ आये और हमने अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनाई, इसलिये भी हम वचनबद्ध हैं और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इस मेनिफेस्टो के आधार पर जिन लोगों ने हमको भेजा तो उसी तरह से करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको पूरा करें। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि जमींदारों को यह नहीं भूलना चाहिये कि जिस वक्त इस मेनिफेस्टो के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में कामयाब हुई और जिस वक्त देश ने हमको यह मॅंडेट दे दिया कि हम जमींदारी को खतम करें तो उसके विरुद्ध कुछ कहना देश में मत दाताओं के विरुद्ध कहना है। जो लोग कहते हैं कि कम्पन्सेशन न दिया जाय उनको यह याद रखना चाहिये कि हम इक्विटेबिल कम्पन्सेशन देंगे।

इसलिये जो आज सोशलिस्ट हो गये हैं या जो हमारे साथ नहीं हैं उनको भी यह याद रखना है कि उन्होंने और हमने मिलकर यह चुनाव लड़ा था और उस वक्त हमने इस मेनिफेस्टो के आधार पर, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इससे उनका और हमारा दोनों का यह नैतिक कर्तव्य है कि इन सिद्धान्तों को जिनके आधार पर कि हमने चुनाव लड़ा था, हम पूरा करें और मैं आशा करता हूँ कि जो कोई पहले कांग्रेस में थे और जो चुनाव के वक्त कांग्रेस में थे वे यदि आज इसके विपरीत कोई बात कहेंगे या किसी ने कही हो तो उन्होंने भूलकर कही होगी और जब यह बात उनके सामने आ जायगी कि उन्होंने और हमने इस बात का अपने ऊपर जिम्मा लिया था कि हम जमींदारी खतम करेंगे और इक्विटेबिल कम्पन्सेशन देंगे तो फिर कम्पन्सेशन के खिलाफ आवाज उठाना उतना ही अनुचित है जितना कि जमींदारों का जमींदारी के खिलाफ आवाज उठाना है। इसलिये दोनों को इसको मान लेना चाहिये। क्या कम्पन्सेशन इक्विटेबिल है या क्या नहीं है, इसके बारे में मतभेद हो सकता है। इक्विटी (न्याय संगत) कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कि कोई अप्रैरेट्स (आला) ऐसा बना हो कि आप नाप कर कह दें

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

कि यह इक्विटी होती है. इक्विटी वह चीज है जिसमें मनुष्य दूसरों के साथ उनकी आवश्यकता को देखते हुए उचित व्यवहार करे। बड़े आदमी को बड़ा समझकर उसके साथ बड़ों का व्यवहार करे और छोटे को कमजोर समझकर उसकी कमजोरी का गवयान करके उनके साथ वैसा व्यवहार करे। उस इक्विटी के प्रिंसिपल 'निद्रान्त' को हम बिल में पूरी तरह से माना गया है।

मगर मैं आपसे कह रहा था कि इस मेनिफेस्टो के आधार पर यह कार्यवाही की गयी है और इसके बाद जो रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था वह भी इसी मेनिफेस्टो के आधार पर हुआ था। इस रेजोल्यूशन में जो कि न अगस्त, सन् १९४६ ई० को इन हाउस ने मंजूर किया, कहा गया था कि—

"This Assembly accepts the principle of the abolition of the Zamindari system in this province which involves intermediaries between the cultivator and the State and resolves that the rights of such intermediaries should be acquired on payment of equitable compensation and that Government should appoint a committee to prepare a scheme for the purpose."

(इस प्रान्त की जमींदारी प्रथा को जिसमें किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ व्यक्ति रहते हैं उन्मूलित करने के सिद्धान्त को यह असेम्बली स्वीकार करती है और मन्तव्य करती है कि ऐसे मध्यस्थों के अधिकार उचित हर्जाना देकर हस्तगत कर लिये जायें और सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति की योजना बनाने के लिये एक कमेटी नियुक्त करे।)

जिम समय इस भवन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया उसी समय जमींदारी का अन्तर्निर्माण हो चुका। अब तो सिर्फ उसको एक कानूनी जामा पहनाना बाकी है और उसको एक कानूनी शक्ति देना है जहाँ तक इस भवन के निर्णय और फैसले का तात्पर्य है। दूसरे हमने जो कि एक साफ़ हिदायत की गयी वह यह थी कि इंटरमिडरीज़ कोई स्टैंट और कल्टीवेटर के बीच में न रहें और तीसरे एक यह थी कि कम्पन्सेशन इक्विटीबिल हो. मार्केट वैल्यू (बाजार का मूल्य) न हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू इक्विटी से तात्पर्य नहीं रखती इसलिये इक्विटी के आधार पर कम्पन्सेशन निश्चित हो. यह तीसरी बात इस भवन में निश्चित हुई थी। उसके अनन्तर और भी बातें हमारे देश में हुई हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ स्वराज्य आया और उसके आने के बाद हमारे देश में और भी बातें हुईं। हमारे प्रान्त में पंचायतें कायम हुईं और पंचायतों को हमने इसलिये बनाया कि हमारे देश की जो प्राचीन प्रथा थी उसी के अनुसार हम अपने प्राकृतिक आधार पर अपने देश का पुनर्संगठन करें। जो क्रान्ति सोवियट रूस में हुई थी, उसी प्रकार की हमारे प्रान्त में पंचायतें हुई हैं। मगर सोवियट के बनाने में लाखों आदमी रूस के खत्म हुए। हमारी पंचायतें प्रेम और सद्भावना के साथ बनी हैं।

आज भी कांग्रेस और हमारा एक उद्देश्य और कर्तव्य है। वह है देश में क्रान्ति का करना। मगर क्रान्ति का शान्तिमय उपायों के द्वारा करना और उस क्रान्ति को करने के लिये जो सबसे आवश्यक है, वह जमींदारी उन्मूलन है। अगर हम अपने देश में एक आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके पर अपनी पंचायतों में एक नये जीवन को डालना है और कृषकों में एक नयी भावना को नये हौसले को और नये उत्साह को पैदा करना है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ आज खाने का सवाल है। हमारा देश उतना अन्न पैदा नहीं कर सकता, जितनी कि उस को आवश्यकता है। सौ, सवा सौ करोड़ रुपये हमें विदेशों में इसलिये भेजना पड़ता है कि यहाँ किसी तरह से हम पेट भर सकें। इसके लिये जरूरत यह है कि हर एक मनुष्य जिस का सम्बन्ध जमीन से है वह उस से अपनी मुहब्बत रखे, वह उसे बिराने की चीज न समझे और वह अपनी सारी शक्ति उसके मुधार में लगा सके। इसलिये इस फूड प्राबलम (खाद्य-समस्या) के सल्यूशन (हल) के लिये भी इस बात की जरूरत है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन हमारे देश में हो। और उसके लिये जो हमारे खेतिहर हैं उन की भावना हो कि वह अपनी जमीन से एक स्थायी सम्बन्ध रखते हैं, और स्वामीत्व करीब करीब प्राप्त है। कोई दूसरा बेदखल कराने वाला नहीं है। इस लिये फूड प्राबलम के सल्यूशन के लिये भी इस बात की जरूरत है। भवन के सदस्यों को मालूम होगा कि विशेषज्ञों की राय है कि जब तक लैंड टेन्योर में उचित सुधार न हो तब तक फूड प्राबलम का प्रभावकारी सल्यूशन नहीं निकल सकता है। इस लिये इस ढंग से इस काम को करना आवश्यक है।

इस के अतिरिक्त आज हमारे देश में इन्फ्लेशन (मुद्रा फुलाव) फैला हुआ है। इन्फ्लेशन की वजह से कुछ मुद्रा के विषम वितरण से ऐसी अनूठी परिस्थिति पैदा हो गयी है, जिस से हमारा आर्थिक जीवन खतरे में है और इस हद तक खतरे में है कि उस से हमारा सामाजिक जीवन और राजनैतिक स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ गयी है। इसलिये हमें उस का भी हल निकालना है। उस के लिये हमें कोई ऐसी शैली निकालनी है, जिस से हम अपने देश के हर एक के स्तर को ऊँचा कर सकें, हर एक के रुपये का सदुपयोग करते हुए, उसको उसे लाभ पहुँचाएँ और देश तथा जन समुदाय को भी लाभ पहुँचाएँ। इसलिये भी इस में जो योजना रक्खी गयी है, वह इस ढंग से रक्खी गयी जिस से हमारे जिनके मौलिक प्रश्न हैं वह सब हल हो सकें। उन के साथ-साथ हम ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस बिल में जो भी हम प्राविजन (व्यवस्था) करें उस से कमसे कम दिक्कत लोगों को हो और इस विचार से इस बात का यत्न किया गया है कि जो जिस जमीन के कब्जे में है, वह उस से बेदखल न हो। ताकि जो हर एक आदमी की हालत आज है, जो कि उत्पादन का काम करता है, वह आगे भी कर सके। स्वराज्य के माने होते हैं कि हर आदमी पैदा करनेवाला हो।



[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

इसलिये पैदा करनेवालों को, जो भी तथा ज़िम्मे भी कब्जे में जो जमीन है, उसको यथामूल्य हम हटाना नहीं चाहते हैं। और इस बिल में ऐसी योजना की गई है जिससे सबका यथामूल्य कब्जा कायम रहे और किसी की कोई कठिनाई न हो। इन बिल में और हमारे पड़ने की जमींदारी अवांतीशन कमेटी की रिपोर्ट में कुछ बातों में अन्तर है। उनमें अन्तर करने में हमने सब बातों का विचार किया है। मर जगदीश प्रसाद तथा और लोगों की बातों का भी तथा जो बातें अववागों में निकलीं उनका भी और अन्य जमींदारी ने जो बातें कहीं उन सब बातों का विचार किया है। और उनको अपने ध्यान में रक्खा है। जो जमींदारी उन्मुन्न समिति की रिपोर्ट में लाखों मव टेनेन्ट्स बेदखल किये जा रहे थे यह उनके साथ ज़रूर हो रहा था निहाय ऐसी बात हम नहीं होने देना चाहते थे और हमने इसके लिए भी उपाय निकाला है ताकि वह लोग बेदखल न हों। उनके साथ जो हमदर्दी थी उनका असर हमारे ऊपर हुआ है इस तरीके पर हमने यह रक्खा है कि मव टेनेन्ट्स न सिर्फ पाँच साल तक ही कायम रहेंगे बल्कि जिन जमींदारों की उनके साथ हमदर्दी थी उनको यह सुन कर खुशी होगी कि उनको भी उनके बराबर का दर्जा दिया जायेगा। जब वह भी भूमिधर हो जायेंगे। इसलिए इस तरह से यह दिक्कत दूर होगी।

इसके अलावा कुछ बातें मुआवजे के बारे में हुई हैं। मुआवजे के बारे में कुछ उभ्र किये गए थे कि जब जमीन एक सी है तो मुआवजा भी एक सा ही होना चाहिये। उम्मी मुहाल में किसी को ज्यादा और को कम क्यों दिया जाता है। इस बात को हमने माना है और सबके लिये हमने एक सा मुआवजा कर दिया है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो सबको अठगुना मिलेगा। हाँ मुआवजा देने में ज़रूर हर एक की हैसियत का ख्याल किया गया है और जो कोई खर्च करना है और जो कोई वह टैक्स देता है उन सब को भिन्नता करके जो उनकी खालिस मुनाफा होना है उसके आधार पर उनके इस मुआवजे की निकदार कायम की गई है और यही मुनासिब ढंग भी है क्योंकि वगैर खर्च को काटे हुये खालिस मुनाफा नहीं होना। जो टैक्स लगता है वह तो खर्चा होता ही है। बड़ी आमदनी होने पर ज्यादा टैक्स देने हैं लेकिन जो गरीब है उनको इतना नहीं भिन्नता कि अपना गुजारा भी अच्छी तरह से कर सकें तो फिर वह टैक्स क्या देंगे। इसलिये इन सब बातों का ख्याल करके यह किया गया है।

इसके अलावा इस बिल में एक तरीका यह रक्खा गया है कि इसको सम्पिल (सादा) बनाने की कोशिश की गई है जिससे सब काम आसानी से हो जाय। हम उम्मीद करते हैं कि अगर सब बातें ठीक हुईं तो एक साल के भीतर इस बिल का निफाज होकर जमींदारी खत्म हो जायगी। इसलिये इस बात का उपाय किया गया है कि जहाँ तक मुआवजा कायम करने की बात है चाहे कोई एक रुपये का देनेवाला हो या हजार रुपये का देनेवाला हो उसकी खालिस आमदनी निकाल कर के

अठगुना कर दिया जायेगा। अब उसको खतौनी बगैरह को देख कर एक एक दिन में मुआवजा कायम किया जा सकता है। इससे पहले जो सिलसिला था यानी जमींदारी अवालीगान कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि हर एक की मालगुजारी बगैरह देख कर यह कायम हो सकता था। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता था। इसलिये यह ठङ्ग ऐसा है जो आसानी से अमल में आ सकता है इसके अलावा हमने इसमें यह भी किया है कि जो खेवट में इन्दराज है वह इस ऐक्ट के लिये करीब करीब कतई समझे जायेंगे ताकि मुकदमें बाजी की कोई गुंजायश ही न रहे और उसकी बुनयाद पर ही फैसला कर दिया जायगा। इस बिल को अमल में लाने के लिये यह आसान तरीका कायम किया गया है। इसके अलावा आजकल हमारे यहां कई किस्म के टेनेंट्स हैं। कोई फिक्स्ड रेंट्स के हैं, कोई एक्स प्रोप्रायटरी हैं और कोई ओकूपेन्सी हैं। इस तरह से बहुत से टेनेंट्स हैं। अब इसमें सबको एक करने का उपाय किया गया है।

हम चाहते हैं कि सब लोगों के बीच में मोहब्बत हो और इसके लिए इस बात की जरूरत है कि एक दूसरे को अपने बराबर समझने लें। इसलिए इस बिल में इस बात की कोशिश की गई है कि तमाम लोगों को एक तरह से सिर्फ दो दर्जों में बाँटा गया है। एक तो सीरदार और दूसरे भूमिधर। सीरदार वह हैं जो चन्द रोज रहेंगे और फिर भूमिधर हो जायेंगे और भूमिधर वह हैं जो हमेशा ही भूमिधर रहेंगे। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि तमाम गाँवों में भूमिधर ही होंगे और सब का बराबरी का दर्जा होगा। और इस में ऐसा तरीका बरता गया है कि सीरदार जो हैं वह भी अपने लगान का दस गुना रुक्या देकर भूमिधर के हक को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद से उन का लगान भी आधा हो सकता है, वह अपनी जमीन बेच सकेंगे और जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकेंगे और फिर उनके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट न रहेगी सिवा इसके वह अपनी जमीन किसी दूसरे को जोतने को न दे सकेंगे और अगर दे सकेंगे तो भी सिर्फ विधवा अनाहज या पंगु को दे सकेंगे क्योंकि जिन के हाथ पैर हैं उनको काम करना चाहिए। इसी सिद्धान्त को सामने रखकर ऐसा किया गया है और इस तरह से जो जमीन रखेंगे वह उस को जोतेंगे और अगर खुद नहीं करेंगे तो वह उसी को देंगे जो खुद उसे जोते इस बिल से हमारा वह भ्येय पूरा हो जाता है जिस से हम चाहते हैं कि सब लोग पैदा करने, काम करने वाले बनें और कोई बेकार न बैठे और हम किसी को उसकी थैली में जबरदस्ती पैसा डालकर बेकार न बनावें।

इसके अलावा इस बात की भी जरूरत थी कि हमारे यहाँ जो जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं वह और छोटे न होते चले जायें। इसलिए इस बिल में प्राविजन किया गया है कि किसी भी होलडिंग का इस तरह से बदवारा न होगा कि कोई

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

मैंने देखा कि मने ६ एकड़ में कम हो सके जिनमें आगे और प्रैगमैन्टेशन (टुकड़े) न हो सके और इसकी वजह से जिन के पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन मिले और जमिंदार भी जमीन पर सकें। इसमें यह भी रक्खा गया है कि जो कोई जमीन बेचे वह उनके हाथ न बेचे कि जिस के पास खेती या और सब जमीन मिलकर ३० एकड़ जमीन मौजूद है। इससे गरीब लोगों को भी जमीन खरीदने के गुंजायश होगी और हर एक जमीन हासिल कर सकेगा। इस के अलावा जैसा कि आप से कहा गया इस बिल में इस बात की भी कोशिश की गई है कि मुआवजा इस ढंग से दिया जाय कि जिस को जितनी जरूरत हो उसकी वह उचित पूर्ण हो सके। इस बिल में यह तजवीज की गई है कि कम्पन्सेशन सब के लिए एक ही राह से हो और वह ग्वालिम मुनाफे की बुनियाद पर ८ गुना रहे और उनको कायम करने में १५ फीनदी जो लगान या कर्जा बमूल नहीं होता उसके हिस्से में कमी कर दी जायगी और जो कोई टैक्स वह देते हैं उस को निकाल कर बाद में जो ग्वालिम निकासी रह जायगी उसका ८ गुना कम्पन्सेशन दिया जायगा। इसके अलावा यह चीज भी की गई है कि जो लोग ऐसे हैं कि जिन को पास इस मुआवजे के मिलने पर नए कामों के शुरू करने के लिए पूंजी नहीं होगी या जिन्हें पैसे की जरूरत होगी उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी दी जायगी। और यह रिहैबिलिटेशन ग्रांट २० गुने से लेकर २ गुने तक दी जायगी। जो लोग २५ रु० तक सालगुजारी देते हैं उनका २० गुना रिहैबिलिटेशन मिला कर यानी कम्पन्सेशन समेत उनको खालिस आमदनी का २८ गुना मिला करेगा और जो माढ़े ३ हजार से ५ हजार तक देते हैं उनको ८ गुना मिलेगा। इसका मतलब यह होता है कि १५०० में से १४६६ जो आज काश्तकारी करते हैं उनको मुआवजा मिलेगा और कुछ न कुछ रिहैबिलिटेशन भी मिलेगा सिर्फ १५०० में से १ गैना रहता है जिसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप सिर्फ उनको तब जो २५० रु० तक सालगुजारी देते हैं उनको ११ गुना तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट और ८ गुना कम्पन्सेशन यानी करीब करीब २० गुने तक मिलता है और इसमें करीब करीब सब लोग आते हैं, यानी २०० में से १६७ आदमियों को १६ गुने तक कम्पन्सेशन उनके ग्वालिम मुनाफे का मिल जाता है। अब मेरी समझ में कोई यह नहीं कह सकता है कि इसाफ से इसमें ज्यादा से ज्यादा रियायत मिलाने की कोशिश नहीं की गयी है। बाजे लोग समझते हैं कि जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन थी अगर वह ले ली जाती तो अच्छा होता। मैं चाहता हूँ कि हर शर्त को जो जमीन जोतना चाहता है जमीन मिल सके मगर सिवाय कुछ सोशलिस्ट लीडरों के मैं नहीं जानता कि और लोग भी जमीन को खड़ा समझते हैं या नहीं, मेरे लिए तो जमीन एक मद्द्द सी चीज है, जितने एकड़ है इस मूबे में उतनी ही समझता हूँ। बाजे लोग समझते हैं कि वह हर एक को २० एकड़ जमीन के दे देते, हर एक को ५ गाँव दे देते और शायद एक दो हाथी

भी, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ, जमीन इतनी है कि अगर सारी जमीन का बटवाग किया जाए तब भी हर एक को साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा नहीं पहुँच सकती। इसके अलावा जो हमारी सीर है उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा छोटे जमींदारों के पास है। बाजे लोग जमींदारों की तादाद २० लाख कहते हैं, २१ लाख कहते हैं। मैं जानता नहीं कि उनके ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन में कितने लाख मेम्बर हैं या आगरा जमींदार एसोसियेशन में इस २२ लाख में से कितने लाख उनके मेम्बर रहे हैं। यह मैं जानता हूँ कि जो लोग ५ हजार या इससे ज्यादा मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद १५०० के करीब है और जो २५० रु० या इससे कम देते हैं उनकी तादाद करीब २० लाख है, लिहाजा उनका नाता इतना ही है कि दोनों को जमींदार कहा जाता है मगर इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन में उनको शायद भाँकने को भी न मिला होगा और उस सुनहरी कुर्सी पर बैठने का मौका उन्हें जमाने कदीम से मिला या नहीं मैं नहीं जानता। इसलिए इन बड़ी बड़ी तादादों को कहने से कोई नतीजा नहीं निकलता। नतीजा यह है कि उन २० लाख में से २ हजार को छोड़ कर या ज्यादा से ज्यादा ५ हजार को छोड़ कर बकिया तो ऐसे हैं जो काश्तकारों से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं बमुकाबले बड़े २ जमींदारों के। वे काश्त करते हैं तभी गुजर कर पाते हैं। इसलिए उनका तबका बिल्कुल दूसरा है।

असल जो बात है वह तो यह है कि इससे सिर्फ कोई दो या ढाई हजार आदमियों को, जो कि आज तक इस जमींदारी के जरिये से काफी आमदनी करते थे, ठेस पहुँचेगी। मगर उनको और हमें सब को मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जैसे भी उनकी दिक्कत जितनी भी कम हो सके, वह की जाय। मैंने आपसे कहा था कि मुआविजा देने के लिये हमने यह तज्जवीज को है कि अगर वे जो लगान देते हैं, अपने लगान का दस गुना हिस्सा देंगे तो उनका लगान आधा हो जायगा और उन सबको भूमिधारी हक मिल जायगा। यह बात करीब करीब यह हाउस कबूल कर चुका है।

मैंने जमींदारी एबालीशन फंड के बारे में जब कि बजट पेश किया था, जिक्र किया था और उस सिलसिले में मैंने कहा था —

“The report of the Zamindari Abolition Committee has been before the public for several months. The reform is now overdue and we accordingly propose to bring before the House shortly a Bill to give effect to the scheme of abolition. We hope that the implementation of the policy will herald a new

[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

era in the countryside. In the new scheme, which we have evolved for our province, which has a most complicated land tenure system, we have restored the village communities and the villages to the position which they deserve and which they had prior to the passing of the country under foreign rule. Out of the current year's surplus we propose to transfer Rs. 1 Crore to a fund called the "Zamindari Abolition Fund." Our immediate idea is that the savings of the tenants should be incorporated for feeding this Zamindari Abolition Fund. A tenant who contributes an amount equal to his 10 years' rent will be entitled to a reduction of 50 per cent on the sum now paid by him as rent and will pay to the state only half of this sum as revenue. This scheme will at once bring together scattered surplus purchasing power into a pool to be utilised for eliminating middle men and reviving agricultural and prosperity. It will exert a healthy downward pressure on inflation by canalizing savings into productive channels. There will remain no legal or other difficulty in our way. There will be no strain on the finances or credit of the Provincial Exchequer and the question of compensation will be settled in a manner that may prove satisfactory to all parties."

( "जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट कई मास से जनता के सामने है। यह सुधार बहुत पहिले ही हो जाना उचित था और इसलिये हमारा इरादा है कि उन्मूलन की योजना को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र ही भवन के सामने एक बिल लावें। हमें आशा है कि यह नीति कार्यान्वित हो जाने पर देहात में एक नये युग का आरम्भ होगा। हमारे प्रान्त की भूमि व्यवस्था बहुत उलझन वाली है और इस प्रान्त के लिये हमने जो योजना बनायी है उसमें हमने किसानों का तथा देहात के अन्य लोगों को उस परिस्थित में पहुँचा दिया है जो उनके लिये उपयुक्त है और जिन में वह उस समय तक थे जब तक कि विदेशी शासन इस देश में नहीं आया था। वर्तमान वर्ष के अनिरिक्त धन से हम एक करोड़ रुपया उस निधि में हस्तान्तरित करने वाले हैं जिसको 'जमींदारी उन्मूलन निधि' कहते हैं। हमारा विचार यह है कि किसानों की वचत को इस निधि में एकत्र किया जाय। जो किसान अपने दस वर्ष के लगान के बराबर रकम दे उनके वर्तमान लगान में ५० प्रतिशत की कमी कर दी जायगी और वह सरकार को केवल आधी रकम सालगुजारी के रूप में देगा। बिस्वरी हुई क्रयशक्ति इस योजना से तुरंत एकत्र हो जायगी और

उसका उपयोग मध्यस्थ व्यक्तियों का निराकरण करने के लिये तथा कृषि विषयक सम्पन्नता का पुनरुद्धार करने के हेतु किया जा सकता है। ऐसा करने से बचत का धन उत्पादन कार्य में लग जायगा और मुद्रा बाहुल्य भी रुकेगा। हमारे मार्ग में कोई कानूनी या अन्य प्रकार की कठिनाई न रहेगी। प्रान्तीय धन कोष के ऊपर कोई बोझ न पड़ेगा और हरजाना देने के प्रश्न को ऐसी रीति से तय किया जायेगा, जिससे सब दलों में सन्तोष रहे।” ) यह जमींदारी एबालीशन फंड, जिसके लिये एक करोड़ रुपये बजट में रक्खा गया था यह इस हाउस ने मंजूर किया, उसमें किसी ने कोई उन्न नहीं किया। जाहिर है, इससे नतीजा निकलना है कि इस हाउस को यह तरीका मंजूर है और इस ढंग से चलने से वह फायदा समझता है। इस सिलसिले में मैं आप को यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जायगा, मगर इससे पहले ही हम एक बिल और लाना चाहते हैं, जिससे कि हम इस दस गुने रुपये को जमा कर सकें और उस रुपये को जमा करके जमींदारों के लिये एक रकम कायम कर सकें जिससे कि उनको फायदा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जमींदारों की मदद होगी। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने एक बड़े समझदार और आलिम जमींदार से सुना कि काश्तकारों से यह दस गुना क्यों लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वे क्या समझते हैं कि मुआविजा बिल्कुल न दिया जाय। अगर उनकी ख्वाहिश हो कि मुआविजा न लें तो मैं चाहूँगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन और आगरा जमींदार एसोसियेशन रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास कर दें कि हम मुआविजा नहीं चाहते और उन रिजोल्यूशनों के पास होने पर हम इस बात पर गौर कर सकेंगे कि मुआविजा देना चाहिये या नहीं।

अगर वे चाहते हैं कि बोर्डों से उनको दिया जाय और उन्हें यही पसंद है तो वह इस तरह का रिजोल्यूशन कर दें। अगर वे यह समझें कि इस तरीके से अड़ंगा लगाने से जमींदारी उन्मूलन नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ कि किसी किस्म का अड़ंगा इस बारे में हमारे सामने नहीं आने पायेगा, चाहे वह ऊपर से कानूनी होकर आये या कोई दूसरी चीज हो। चाहे वह सेंटर हो या कोई और, हमें अपना मकसद पूरा करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिये किसी तरीके को समझना कि इस तरीके से अड़ंगा लगा कर फायदा हो सकेगा, यह गलतफहमी की बात होगी। मैं तो चाहता हूँ कि लोग साचें कि आखिर में यह तो उनके लिये फायदेमंद ही होगी। काश्तकारों से किसके देने को लिया जा रहा है? आखिर नफा किसको होने वाला है? अगर आप समझते हैं कि हम तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार हैं, बर्रा कि अगर बिल्कुल छोड़ दें। मैं बहुत गौर से सुनूँगा कि इस बारे में बड़े-बड़े जमींदार साहबान और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स (नुमाइंदे) जो यहाँ पर हैं, वे कितनी कैयाजी के साथ इस बारे में ऐलान करते हैं। अगर उनकी तरफ से यह ऐलान हो जाय कि वे कोई मुआविजा नहीं लेना चाहते हैं

[ माननीय प्रधान मन्त्री ]

तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जायगी। कानूनकारों ने १० गुना गन्त लेकर उनको जो सहुलियत दी जा रही है, उससे तो उन्हें क' फायदा है अगर मुकदमा है तो केवल गवर्नमेंट का। हम को जो चार-पाच करोड़ रुपये की वचन होनी वह न हो पायगी, निगोशियेबिल बोम्ब्स और निफिंग फंड के तरीके से गवर्नमेंट को काफी वचन हो जाती है, वह न होगी हमारा ६ करोड़ की आमदनी में से जो करीब ४ करोड़ की वचन हम को होनी है, वह न हो पायेगा। जमींदारी कमेटी ने जो सिकारिश की थी, उससे कारनकारों को ४ करोड़ रुपये और ज्यादा मिलेगा। इसलिये जो चीज हमने की है उसमें अगर किसी ने मुकदमा उठाया है तो वह स्टेट ने। आज गवर्नमेंट को जो आमदनी हो रही है, उसमें कमी होने की गुन्जायश तो है लेकिन ज्यादा होने की गुन्जायश नहीं मान्य होनी है। इसके अलावा जो खैराती वक्फ हैं उनको कुछ आमदनी गवर्नमेंट एनयुइटी (वापिक) के रूप में देना चाहती है जिसमें उनकी आमदनी में किसी किस्म की कमी न हो। इसके अलावा हम एक ऐसा कानून भी बनाना चाहते हैं कि जमींदारों पर जो मुआवजा देने की वजह से आर जमींदारों उन्मूलन की वजह से जो भी काम किये गये हैं, उससे जमींदारों के ऊपर जो कर्जा हो जायगा उसको भी कम किया जाय। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटियाँ और अरबन एरिया (शहरी हल्कों) में जो काश्त की जमीन हैं उनके बारे में भी हम अलदुदा कानून ला रहे हैं। मैं समझता हूँ यह जमींदारों के लिये फायदे की बात है। कारनकारों से जो रुपया हम जमा करेंगे वह बुराई नहीं है क्योंकि उससे सब से ज्यादा उन्हीं को फायदा होने वाला है। मगर किसी वजहसे अगर यह न भी हो तो भी मैं यह समझता हूँ कि यह समझना कि जमींदारी अवालिशन नहीं होगा यह एक धोखे की टट्टी होगी और जिस धोखे में लोगों को नहीं रहना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि इस बिल ने सिर्फ जमींदारी को खत्म करने या कम्पेन्सेशन देने या नये टेन्थोर को कर के जो काश्त करता है, उनकी हासिल के सुधारने की कोशिश है नहा का गई है बल्कि एक नये आर्डर के जारी करने की कोशिश की गई है।

विलेज पंचायतों का, गाँव समाजों का, और गाँव समितियों को खास हकूक दिये गये हैं। जितन भा मानवर लैंड (चराई) हैं, वेस्ट लैंड (बेकार भूमि) हैं, वेज (रास्ते) हैं, वेल्ड (कुयें) हैं, ट्रीज (दरख्त) हैं बहुत किस्म के उन सब में जो कि आम जगहों में हैं विलेज कम्युनिटी (ग्रामनिवासियों) को हक रहेगा। और उन सब का नजान कर विलेज कम्युनिटी के हाथ में रहेगा। इस तरह आज हम फिर सऊड़ा बरिह हजारों वर्ष के बाद अपने गाँव पंचायतों को वह पूरा हक अपने गाँव के अन्दर उस जमीन में, उस आबादी में, उन घरों में और उन बाँजों में दे रहे हैं जो कि उनका कुदरती हक किसी जमाने में था और इससे मैं उम्माद करता हूँ कि उनमें एक सारा रसगान्सबिलिटी का खयाल,

एक सामाजिक जिम्मेदारी की भावना और आपस में मिल-जुलकर काम करने की और अपने गाँव को ऊँचा उठाने की ताकत पैदा होगी।

मैंने आपसे कहा था कि हममें हमने इस बात की कोशिश की है कि आगे कोई प्रैगमेन्टेशन न हो सके। हमने इस बात को भी इस बिल में रक्खा है कि जहाँ तक जमीन का ताल्लुक है जमीन की विरासत करीब २ डीसी ढंग की हो जिस तरीक़े की टेनेन्सी ला में रक्खी गयी है ताकि काश्त करने वाले आसानी से जमीन को पा सकें और दूर-दूर से विरादरी के नाते से जमीन न चली जाय। इन बातों के अलावा हमने इसमें कोओपरेटिव फार्मिंग के लिए खास तौर पर गुंजायश रक्खी है। हमने यह तजवीज किया है कि जो अनएकनामिक होल्डिंग वाले हैं वह अगर कोओपरेटिव फार्मिंग करना चाहें और दो तिहाई लोग भी चाहें तो सब को उसमें शरीक होकर कोओपरेटिव फार्मिंग करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से हम अनएकनामिक होल्डिंग के मसले को हल कर सकते।

बाज लोगों ने यह कहा है कि बाजों के पास जमीन नहीं बाजों के पास अनएकनामिक होल्डिंग है, तो जिनके पास कुछ ज्यादा जमीन है, उनसे लेकर अगर उनको दी जाती तो अच्छा होता। मगर उसमें सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम उस भूखंड में फँसे तो यह मसला दस वर्ष तक तै नहीं हो पायेगा। हमें हर एक की जमीन को देखना होगा, उसका नक्शा बनाना होगा, उसके हिस्सों को अलग करना होगा। और फिर किसको कितनी जमीन दी जाय इसका इन्तजाम करना होगा। इसके बाद भी जैसा मैंने कहा यह गैरमुमकिन है कि हम २० परसेन्ट ( फीसदी ) होल्डिंग्स भी एकोनामिक होल्डिंग्स बना सकें। ऐसा करने में हमारी सारी स्कीम गड़बड़ में पड़ जाती है और हम इस तरह के मसले पैदा कर देते हैं जिनका हल नहीं कर पाते हैं मगर इसका कुदरती इलाज दूसरा रक्खा गया है, जिसका जिक्र हमने आपसे पहले किया था और वह यह है कि अनएकनामिक होल्डिंग को बेहतर करने के लिए और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिलाने के लिए हर एक शख्स को अपनी जमीन की काश्त खुद करना पड़ेगी। इस तरह अगर किसी आदमी के पास एक हज़ार एकड़ जमीन है तो उसको काश्त का इन्तजाम करना पड़ेगा और अगर वह इन्तजाम नहीं कर सकेगा तो वह जमीन गाँव के दूसरे लोगों को मिलेगी और उनको मिलेगी जिनके पास जमीन न हो। इस तरह से जमीन भी तकसीम हो जायेगी और उसका कुदरती इन्तजाम भी हो जायेगा। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि जब गाँव पंचायतों को हम हक दे रहे हैं तो वह इस बात पर नज़र रखेंगे कि इन पंचायतों में केवल जमीन ही जोतने वाले नहीं हैं। लैंडलेस लेबर्स ( बेजमीन मजदूर ) इस बात पर



[ माननीय प्रधान मन्त्रि ]

नजर रखेंगे। यह जान हम ढकोमने में नहीं कह रहे हैं। इसलिये गाँव-पन्चायतों की निगरानी में हर एक चल सकेगा और अच्छे ढंग से कार्यवाही होगी। उधर लोगों से जिन को जमीन की जरूरत है, उनके पास जिस हद तक वह लोग खुद काशन करने हैं, वह जमीन छिन जायगी।

मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बिल में एक नया जमाना हमारे मूँव में आयेगा। मुझे यकीन है कि जो साहबान इस बिल के बारे में शकूक रखते हैं, इससे इस्तिफाक रखते हैं, उनको नजुर्बा बननायेगा कि यह सबसे जरूरी चीज है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में दो साल पूरे नहीं हुये कि जो छः सान सौ देसी रियासतें थीं, बड़े राजा महाराजा, निजाम, ग्वालियर के सिंधिया बड़े लोग थे, महाराजा उदयपुर, रीवा के नरेश आज सब रियासतें हिन्दुस्थान की रियाया के हाथ में हैं। राजाओं ने खुशी के साथ अपने तमाम हकूक और ताकत जिन को सैकड़ों हजारों आदमियों की काँसी देने और रियाया को जमीन से निकाल देने के अधिकार थे, वह जिससे चाहते थे जमीन छीन लेते थे और उन्हें उन अधिकारों को इस्तेमाल में लाने के पूरे हक थे, वह हकूक उन्होंने खुशी के साथ अपनी रियाया को सुपुर्द कर दिये। क्या कुन जमींदारों की जमीन मिलायी जाय तो निजाम हैदराबाद या सिंधिया ग्वालियर के या टावनकोर के महाराजाओं की जमीन के बराबर आ सकती है? मगर उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने खुशी से अपने हकूक लोगों के सुपुर्द कर दिये। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई लोग जो गुलामी की गदिशों को भेले हुए हैं और पहने का नजुर्बा कर चुके हैं उन को आज यह मौका मिला है कि वह दरियादिली में काम लें उन भाइयों के साथ जिनकी मदद से आज तक उन्होंने आराम और ऐश किया। उन को गले से मिलायें, बराबरी से अपने साथ बिठला कर मेहमानदारी करें, उनसे अपनी मित्रता कायम करें। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आज चीन की क्या हालत है। लोग समझते हैं कि चीन की यह हालत सिर्फ कम्युनिज्म की वजह से हुई। कम्युनिज्म पनपा क्यों? क्या वजह है? यह हमको मालूम है। कम्युनिस्टों ने लोगों को ऊँचा उठाने की कोशिश नहीं की। उसने जो वेकुअम (खाली स्थान) पैदा किया, कम्युनिस्ट ने आकर किसी न किसी तरह से कब्जा कर लिया। हम कम्युनिस्ट को दबा सकते हैं। उनका जोर यहाँ नहीं चल सकता। हमें और आप को मिलकर यहाँ ऐसी आवाज पैदा करना है कि गरीब लोग सुख से रह सकें। उनकी शान ऊँची हो सके। हिन्दुस्थान के हर एक आजाद नागरिक को ऊँचे से ऊँचे दर्जे तक उठने का पूरे तौर से मौका हो। उसके रास्ते में कुछ हायल न हो। देश के आजाद नागरिक होने के नाते उसको यह मौका हो। देश को ऊँचा उठा कर देश को रहनुमाई हासिल करे तो वह दुनिया की रहनुमाई हासिल कर सकता है।

❧ श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं संशोधन उपस्थित करता हूँ कि उपर्युक्त बिल, ३१ दिसम्बर, सन् १९४६ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय।

महोदय, ऐसे प्रस्ताव में बहुधा 'पहला आक्षेप' यह होता है कि यह अवरोधक प्रस्ताव है। इस वास्ते मैं पहले इस बात को साबित करने का प्रयत्न करूँगा आया मेरा प्रस्ताव अवरोधक है अथवा सच्चा है आज जो प्रधान सचिव ने एक भावपूर्ण और बड़ी वक्तृता दी, मैं उसकी आलोचना के लिये न तैयार हूँ और न मैं इस संशोधन के सम्बन्ध में उस पर कुछ आलोचना कर सकता। मैं केवल यह दिखलाना चाहता हूँ कि वास्तव में इस बिल पर इस भवन के बाहर और विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं। आप जानते हैं कि यह बिल १२ जून को प्रकाशित हुआ। आज ७ जुलाई है और अभी एक महीना भी इस बिल को प्रकाशित हुये नहीं हुये। इस बात को बचाने के लिये इस बिल के उद्देश्य में यह लिखा गया है कि ज़मीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट एक बहुत अरसा हुआ शायद हो चुकी है। लोगों ने जिसके ऊपर विचार किया, प्रेस में भी उस पर आलोचना हुई और प्लेटफार्म पर भी उसके ऊपर आलोचना की गयी। शायद इन शब्दों को इस बिल के उद्देश्य में रखने का यही मतलब है कि फिर इस बिल के ऊपर किसी को विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज़मीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल निर्धारित है और उस पर काफ़ी विचार एक अरसे से हो चुका है। अगर ऐसा है तो वास्तव में यह विचार सही है कि और वह बिल उतनी जल्दी भवन के सामने आ सकता है। परन्तु मैंने अभी माननीय प्रधान सचिव की वक्तृता में यह सुना, उन्होंने स्वयं अन्त में यह कहा कि रिपोर्ट में और इस बिल में कुछ अन्तर है। और हमने इन बातों को इस बिल के बनाने के लिये काफ़ी विचार कर लिया है। बल्कि हमारे आदरणीय मित्र सर जगदीश प्रसाद का भी उन्होंने नाम लिया कि हमने उनके कुछ विचारों पर भी विचार कर लिया है और औरों के विचारों पर भी विचार करके इस बिल को बनाया गया है। मैं यह नहीं समझता कि उन्होंने कहाँ तक इन बातों पर विचार कर लिया है और कहाँ तक इन बातों पर विचार कर लिया है और कहाँ तक उनके आधार पर इस बिल में परिवर्तन किया है। मगर मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनका इन बिल से और उस रिपोर्ट से अन्तर है और वह मुख्य है। वह बेसिक है। ऐसी बातें जनता के विचार में इस रिपोर्ट और इस बिल में अनेक हैं, जो बदली गई हैं। मैं उन सबका चित्र भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस समय भवन अपना अधिकांश कार्य समाप्त कर चुका है और अब कोई लम्बी तकरीर करके उनको अधिक थकित करना

[ श्री जगन्नाथ दास सिंह ]

मुनास्बिब नहीं है मैं आज जहाँ तक मुनास्बिब है, खास-खास बातें जो अन्तर की हैं वहीं कहूँगा। प्रश्न दान तो यही विचारणीय है कि उस रिपोर्ट और इस बिल के अन्तर का वर्णन करने हुए इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह रिपोर्ट जिस पर कि माननीय प्रधान सचिव ने अभी अपना धन्यवाद प्रदर्शन किया, वास्तव में जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस बिल को बनाया, टैक्सपेयर्स का इतना रुबया उस पर खर्च हुआ, वह रिपोर्ट इस भवन के सामने बहस के लिए नहीं रखी गई। मैं नहीं समझता कि क्यों यह रिपोर्ट इस भवन में बहस के वास्ते नहीं रखी गई। दूसरे सभासद भी इस बात को जानते हैं कि दूसरे प्रान्तों में भी ऐसी रिपोर्ट हुई है और उनपर बहस हुई है। लिहाजा शायद यही मतलब है कि इन रिपोर्टों से अन्तर करने की आवश्यकता पड़ती है।

एक तो यह बात नोट करने के काबिल है।

अब अगर हम बिल के और रिपोर्ट के अन्तर पर ध्यान देते हैं, तो पहले निगाह हमारी मुआवजे के ऊपर जाती है। रिपोर्ट के २२१ सफ़े के ऊपर एक तालिका मुआवजे की दी गई है। मुआवजा, प्रधान मंत्री की स्पीच के अनुसार, एक बहुत आवश्यक चीज़ है, जिस पर उन्होंने काफी जोर इस मुआवजे के सम्बन्ध में रिपोर्ट के और बिल के अन्दर बितना अन्तर है। ४२१ सफ़े पर रिपोर्ट में जो तालिका दी हुई है उसमें किसी रिहैबिलीटेशन ग्रांट का कोई जिक्र नहीं है। वे लिखते हैं कि २५ रुपये और दस हजार रुपये तक की मालगुजारी देने वालों को मुआवजा देने के लिये मुन्नतलिक दूसरी दूसरी तरह के स्केल उन्होंने दिखाये हैं। २५ रुपये तक २५ गुना, २५ से ५० रुपये तक २२,१।२ गुना, इस तरह से वे एक पूरी तालिका देने हैं। और अन्त में उन्होंने लिखा है कि दस हजार से अधिक वालों को आठ गुना और अगर उनकी दस हजार से ऊपर कोई आमदनी है तो उसका तीन गुना। पर जो लोग दस हजार से अधिक मालगुजारी देने हैं, इस पर उसे तीन गुने के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यह तो एक स्कीम है।

अब बिना यह कहना है कि आठ गुना सबको मुआवजा मिलेगा। जिसके अनावा कुछ को एक रिहैबिलीटेशन ग्रांट के बारे में हम बिल की दफ़ाएँ ७६ और २६ देखने के नायक हैं। इसके जरिये से वह रिहैबिलीटेशन ग्रांट, जो अभी कही गई है कि छोटे जमींदारों को हम २० गुने तक मुआवजा देंगे, यानी आठ गुना उनके नफ़े पर और २० गुना उनकी रिहैबिलीटेशन ग्रांट। इसकी सूरत यह है कि जो रिहैबिलीटेशन ग्रांट होगी, उसकी निस्वन यही नह कहा गया कि वह कब दी जायगी और किस सूरत में दी जायगी। क्या वह नक़द दी जायगी या किसी और तरीके से दी जायगी? रिपोर्ट की ऐसी कोई सिकारिश नहीं है। वे कहते हैं कि हम पूरा मुआवजा सबको देंगे।

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ७६

मैं कहता हूँ कि यह छोटा अन्तर है। अगर आप दफा ७५ को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि यह पुनर्वासन अनुदान भी उस दिनांक से तय होगा, जिसमें मध्यवर्ती तथा उन क्षेत्रों पर जिनमें यह ऐक्ट लागू होता है उन पर सब स्थानों के प्राप्त करने का अधिकार हो। मैं जानता हूँ कि इसकी इवारत ऐसी है जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आ सकती। लेकिन मैं इसका मतलब अर्ज कर सकता हूँ कि यह दफा २६ के पढ़ने से इसमें कुछ थोड़ी सी सफाई हो जायगी। दफा २६ (१) यह है।

जिसको ऐक्ट के आधीन पहले स्थान को हस्तगत करने के निमित्त देने के लिये—

जिस दिन से यह जमीन गवर्नमेंट की वस्तु हो जायेगी, उस दिन से कम्पेन्सेशन का मामला शुरू होगा और जितने दिनों में यह मामला तय होगा, उन दिनों में २॥ फी सैकड़ा रिहेबीलीटेशन का सरकार सूद देगी। मुआविजा कायम होने में कितना समय लगेगा। प्रधान मंत्री के जो आँकड़े हैं, उससे २० लाख के करीब औसत लगाई जाती है तो २०० में १६७ आदमी रिहेबीलीटेशन ग्रांट के मातहत हो जायेंगे। कितने दिनों तक उनको ढाई रुपया फी सैकड़ा का व्याज मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं है कि उनको रुपया नकद दिया जाय बल्कि जिस तुरत में मुमकिन हो सरकार उनको रुपया देगी। ऐसा इसका मतलब है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं कोई आलोचना बिल की इस समय नहीं करता। उसके लिये दूसरा मौका मिलेगा, मैं अभी यह दिखा रहा हूँ—

डिप्टी स्पीकर—राजा साहब ! क्या आपने यह कहा है कि आप को इस प्रस्ताव पर दूसरा मौका तकरीर करने का मिलेगा ?

श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—मैं समझता हूँ कि मुझे अपने प्रस्ताव पर बोलने का दूसरा अवसर होगा। मैं तो इस समय संशोधन पेश कर रहा हूँ।

डिप्टी स्पीकर—यह ठीक है आप संशोधन तो पेश कर रहे हैं, लेकिन असल प्रस्ताव पर बोलने का आपको अब दूसरा मौका नहीं मिल सकता। आप तो पुराने मेम्बर हैं। इस प्रस्ताव के मुतालिक एक ही मौका आप को तकरीर करने का है।

श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—मैं शायद इस पुराने तरीके को भूल गया हूँगा लेकिन मैं तो अभी अपने संशोधन को पेश कर रहा हूँ कि इस बिल को सरकुलेट किया जाय।

डिप्टी स्पीकर—यह ठीक है लेकिन, इसके अलावा प्रस्ताव पर बोलने का दूसरा मौका नहीं है। मैं अभी से आपसे कहे देता हूँ, वरना आप इस ख्याल में रहें कि दूसरा मौका तकरीर करने का मिलेगा।

श्री जगन्नाथ बरूश मिह — बहुत अच्छा. आपकी यही राय है तो मैं यही केशिज करूँगा. मैंने सुअविजे की बात अर्ज की थी कि यह बहुत बड़ी जरूरी चीज इन बिल में है. दूसरे इस बिल में एक रैनवारी प्रथा जिसको भूमिधर के नाम से कहा है यह कायम किया गया है. यह भी इस बिल की एक न्यून सुग्न है. इन रैनवारी को जो इस बिल में कायम किया गया है, मैं भवन के विचार रिपोर्ट को ओर आकर्षित करता हूँ कि रैनवारी की प्रथा के बारे में इन रिपोर्ट को क्या राय है? नका ५०५ ऊपर अपनी शिफारिशों में लिखा है कि रैनवारी प्रथा को यह बातें खेती की पैदावार बढ़ाने के विरुद्ध हैं. अपनी शिफारिशों में वह यह कहती है कि रैनवारी प्रथा दोषपूर्ण है, इसलिये उसको काम में नहीं लाना चाहिये. मैं नहीं समझता कि यह रैनवारी प्रथा जो यह बिल निर्धारित करता है उसकी रिपोर्ट में इतना विरोध क्यों होता है. मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी बात है जिसपर अभी विचार करने को बहुत बड़ी आवश्यकता है।

तीसरा नुकता वसूल मालगुजारी का और लगान में कमी का है। उस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि काश्तकारों का लगान कम कर दिया जाय और उन्होंने उनका एक स्केल सन् ५२६ में कायम किया है। उसमें उन्होंने दिखलाया है कि छोटे लगान की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उसमें एक आना कम कर दिया जाय। मगर मैं देखता हूँ कि बिल में कोई लगान में कमी नहीं है। मालगुजारी के वसूल करने के मामले में रिपोर्ट और बिल में बहुत बड़ा इखतलाफ है। बिल यह कहता है कि गाँव सभा को जो कि मालगुजारी वसूल करेगी और सरकार को देगी उसको पाँच प्रतिशत दिया जायगा। बिल में मालगुजारी के वसूल का हक सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है। जिसको सरकार चाहेगी, उस गाँव सभा का यह हक देगा और जिसको नहीं चाहेगी, उसको नहीं देगी। और एक सब से बड़ा उम्मत यह भी रक्खा है कि मालगुजारी की वसूल ज्वाइन्ट हो। केवल वह मालगुजारी जो बाकी रह जायगी वह २, ४ गाँव के आदमियों से ले ली जाय। कई आदमियों का मालगुजारी कुछ एक से लेना यह एक ऐसी बात है जिसको हम जरूर कह सकते हैं कि यह कोई इन्साफ की बात नहीं है। कुल आदमियों का मालगुजारी एक या दो से ले ली जाय यह कोई इन्साफ नहीं कहता है। इसकी रिपोर्ट में कोई सिकरिश नहीं है। उसके बाद एक अहम बात उस बिल में यह है और जिसका सिकर रिपोर्ट में कुछ नहीं किया गया है वह है टैक्सेशन। बिल जो है वह किसी किसम के टैक्सेशन को तसत्ताम नहीं करता है चाहे वह हिन्दू ला का हो और चाहे किसी विराजत के तरीके का हो। बिल तो सिर्फ अपने दस्तूरे काश्तकारों का कायम करता है। मैं नहीं समझता कि यह बात हमारे सूबे को दुनियाँ कहाँ तक मंजूर करेगी। रिपोर्ट में किसी

तरह से कोई सिफारिश नहीं की गई है बल्कि रिपोर्ट यह कहती है कि उत्तराधिकार काश्तकारों का विलेज ऐक्ट के बमोजब होगा। यह एक ऐसी बात है जिसका विरोध किया जायगा और अधिक विरोध होगा। और लोग यह जरूर सोचेंगे कि इस तरीके से उत्तराधिकार को एक बिल के जरिये से कानून बनाना यह धर्म पर और मजहब पर आघात है।

और उन सब के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि अभी भी माननीय प्रधान मन्त्री ने अपनी लम्बी तकरीर में यह दिखलाया कि हम छोटे को बड़ा बनाते हैं और बड़ों को छोटा करके सबको एकबारगी बराबर करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही कानून का उद्देश्य रहा है और इसी के आधार पर हम जनता का कल्याण करने के लिये यहाँ आये हैं। मैं देखता हूँ कि इस बिल में यह बात बिल्कुल गायब है। जमींदारी आप भले ही कहें, हजार दफा कहें कि उन्मूलन हो रही है मगर भूमिधर और जमींदार सिर्फ एक लफ्जी बदलाव है; जमीं मानी भूमि और दार के मानी धर और इस प्रकार एक उर्दू के लफ्ज को बदल कर इतना बड़ा वितंडा बनाते हैं। अलबत्ता यह सही है कि २० लाख जमींदारों को मिटाकर आप डेढ़ करोड़ जमींदार बना रहे हैं। क्या दुनिया इस पालिसी को इतना भी नहीं देख सकती है। जमीन आप उसको दे रहे हैं जिसके पास रुपया है। गरीब को आप जमीन नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि सीरदार के पास जब रुपया होगा तब उससे हम १५ गुना लेकर जमीन दे देंगे। यही गरीब को उठाने का तरीका है? मैं समझता हूँ कि हरगिज यह गरीब को उठाने का तरीका नहीं है। मैं जरूर जमींदारों की नुमायंदगी करने आया हूँ, मैं गरीब की बकालत करने नहीं आया हूँ मगर इस बिल के जो फर्क हैं उनको कहना मैं अवश्य चाहता हूँ और जो इस्तेलाफ करते हैं वह इसे साफ करें। लेकिन आलोचना और आक्षेप करना आसान है कुर्सी पर बैठे-बैठे। मगर वह उठकर साबित करें कि यह भूमिधर जमींदार नहीं हैं। और यह कि वे मार्केट वैल्यू सरकार को देकर जमीन नहीं खरीद रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई इसे साबित नहीं कर सकेगा, लिहाजा जो बेसिक प्रिंसिपल कानून का है जिसको माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हम गरीब को उठाते हैं तो कहाँ वह उठता है? जिसके पास दस गुना देने को है वही मालिक हो जायगा जिसके पास नहीं है वह सीरदार होगा, आसामी होगा या क्या होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता। कहा गया है कि रिपोर्ट और बिल एक ही है, न दुनिया को जरूरत है राय देने की न सरकुलेट करने की। कल ही इसको शायी किया है और आज सिलेक्ट कमेटी को दे रहे हैं। मेरी समझ में यह मामला इतना छोटा नहीं है कि जो इस तरह से अबाम की निगाह से रोका जाय। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के किसी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा गया है कि तुम

[ श्री जगन्नाथ बक्श सिंह ]

जमींदार कारतकार को बनाओ उससे जमीन क दाम लेकर। क्या नेकी सरकार किमा कारतकार के साथ करेगा जब कि आप मार्केट वैल्यू लेकर उसे जमीन देने हैं। आप बेकार इतना बिल बनाते हैं, कहीं भी वह खरीद सकते हैं। मैं देखता हूँ कि जमीन उसको मिल जायगी, पूरे जमींदार के हकूक मिल जायेंगे। लिहाजा यहाँ एक ऐसा नुक्स इम बिल में है और जो बातें मैंने दिखलायीं वह महज इस बिल में ऐसी हैं कि जिन पर असल में मेरा यह कहना है कि इस बिल पर काफी गौर करने की जरूरत है

यह बिल आर्थिक दशाओं पर और धार्मिक दशाओं पर भी आक्षेप करता है। इस प्रकार के बिलों के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है जिनमें सम्मति लिये जाने का अवसर सहर्ष न प्रदान किया गया हो। अभी मैंने देखा कि हिन्दू कोड के ऊपर किननी सम्मतियाँ आयी हैं। स्टेट्स ड्यूटी बिल पर तमाम मुल्क की सम्मतियों का एक बड़ा सा वाल्यूम है। मैं समझता हूँ कि स्टेट्स ड्यूटी बिल और हिन्दू कोड दोनों का अंश इस में सम्मिलित है। मैंने केवल छः मास का समय रक्खा है। इस छः मास के समय में न तो इस प्रान्त में, परमेश्वर न करे, कोई घोर विपत्ति आ जायेगी और न यह प्रान्त देवलोक में परिवर्तित हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जमींदारों से राय लीजिये। मैं तो चाहता हूँ कि आप कारतकारों से पूछिये कि इसको मन्जूर करने हैं या नहीं। आपके विशेषज्ञ जो सरकारी अधिकारी हैं, केवल उन्हीं की राय आपने ली है। आप उन मान के विशेषज्ञों से पूछिये जो आप के दबाव में नहीं हैं। कितने विद्वान लोग हैं जो माल के विशेषज्ञ हैं, वे अच्छी तरह से विचार करके इसके ऊपर राय दे सकने हैं और जनता की भी इस के ऊपर राय लीजिये। मैं आज इस बात को करने को तैयार हूँ कि जनता के सामने एक दूसरी स्कीम रखिये और कहिये कि जो कारतकार दस गुना लगान को देना चाहेगा, उस को जमींदार जमीन दे देगा। इस तरह से एक ऐक्ट सिर्फ दो चार धाराओं का बना लीजिये। अगर आप को यही करना है कि दस गुना लगान दे दे तो कारतकार और जमींदार आपस में मामला कर लें। मैं समझता हूँ कि आप की मालगुजारी जो ४५ फीसदी है ५० फीसदी उस मूलत में भी रह सकती है। तो यह रुपया आप को बजट में देने की जरूरत नहीं है। इसके अनिर्विक्त स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन का जो २०,२२ लाख, रुपया है वह भी रुपया मिलेगा।

मैं इस स्कीम को अपनी तरफ से पेश कर रहा हूँ। और आप से यह भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको लीजिये। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप राय लीजिये कि आया यह साबित स्कीम है जो इस बिल की ३१० धाराओं में है, वह आसान पड़ेगी जब सरकार को, इसी सरकार को कोई काम करना होता है तो उसके पास इतने साधन मुहैया होते हैं कि आम तौर से आदमी उसको समझ नहीं सकता।

प्रधान मन्त्रि ने जमींदारी के ऊपर जमींदारी का ऐतिहासीकरण करते हुये बनाया कि जमींदार एक तरह के ठेकेदार थे जो आगे चलकर जमींदार बन गये और एक विदेशी राज्य ने यानी फवरेन गवर्नमेंट ने उनको जमींदार बना दिया। जमींदारी को अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाय तो मैं जानता हूँ कि जमींदारी ने इस प्रांत की स्वतंत्रता को रक्षा करने के वास्ते विदेशी फौज के सामने जितना रक्तपात किया उतना किसी और ने नहीं किया मगर जो लोग इस बात को न मानें उन्हें किसी बात को समझाना बेकार है आप तबारीख को देख सकते हैं, आप उन लोगों को देख सकते हैं, जिनकी रियासत जब्त हो गई और जिनको बगावत करने के लिये फाँसी दी गई। खासकर इसी सूबे में विदेशी फौज का विरोध हुआ। विदेशी राज्य ने इस लालच में उन्हें जमींदार नहीं बनाया कि यह पड़े रहें यह समझें कि इनके बिना शत्रु का आक्रमण नहीं रोका जा सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भूल न जाइये कि अगर राज्य बिना शत्रु के रहता है तो वह बहिश्त के बराबर है लेकिन यह नहीं होता। राजगद्दी पर बैठने पर दुश्मन का सरदर्द २४ घंटे बना रहता है। ऐसी हालत में आपको एक ऐसी संस्था की जरूरत अवश्य पड़ेगी। चाहे आप जमींदारी को मिटाकर दूसरे जमींदार बनायें और मैं जानता हूँ कि इसी लिये आप दूसरे जमींदार बना रहे हैं। लेकिन मैं यह भी कहे देता हूँ कि साल दो साल छ महीने के अन्दर यह आदमी उन हिस्सों को पैदा नहीं कर सकते जो सैकड़ों पुशों से चली आई है। आप जमींदारों को मिटाकर दूसरे जमींदार बनाकर यह उम्मीद करते हैं कि कल को मोर्चे पर वह दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे।

अब फौजी दुश्मनी या हथियार की दुश्मनी नहीं रह गई है। यह मैं जानता हूँ बल्कि आईडियल्स की दुश्मनी है। चीन की मिसाल आपने दी है कि कहाँ बिगाड़ पैदा हुआ है। इसमें कम्युनिनटांग का दोष नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का दोष है क्योंकि अमरीका के रुपये के ऊपर वह उम्मीद करते थे कि हम कम्युनिस्टों के आईडियल्स को रोक देंगे। लिहाजा उनका डाउनफाल हुआ। दुश्मन गवर्नमेंट की कमजोरी से जीतता है। जमींदार, किसान तथा इंडस्ट्रियलिस्ट्स से नहीं जीतता। चाहे लड़ाई आईडियलिस्ट्स की हो या हथियारों की मगर दुश्मन का मुकाबला करना सरकार को लाजिमी होता है ऐसी सूरत में मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप भूल न जाइये कि आपको उन लोगों की जरूरत होगी जिन्होंने इस देश के लिये अपना खून बहाया है और शायद फिर भी वह अपना खून बहाने के लिये तैयार हो जायेंगे। उन लोगों से आपका काम नहीं चलेगा जिन्होंने कभी यह नहीं जाना कि बंदूक आगे से दबती है या पीछे से? चाहे आप रक्षा दल बनायें चाहे दीक्षा दल बनायें। हर चीज पेशेवर के हाथ में रहती है। लिहाजा मैं कोई सरगर्मी पैदा करना नहीं चाहता हूँ। मेरा ख्याल यह है कि इन विचित्र पंखों के होने पर तो ठंडक होनी चाहिये थी लेकिन फिर भी सरकार ने काफी



[ श्री जगन्नाथ बक्श सिंह ]

गर्मी दिवाई है लेकिन मैं मरगर्मी पैदा करना नहीं चाहता हूँ मगर जब डिप्टी स्पीकर महोदय ने आज्ञा दी है कि आगे बोलने का मुझे मौका नहीं दिया जायगा तो मैं थोड़ा सा बयान कर देना चाहता हूँ।

मैं फिर आप से निवेदन करूँगा कि आप इस राय पर मुस्तकिल न हो जाइये आप यह न समझिये कि जमींदारी कमेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में पावर है और हम सब कुछ कर सकते हैं। यह बात नहीं है यह ठीक है कि देश के लोग आपके हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन बेइन्साफी ऐसी चीज है जो इन्सान के दिल को दुखा देती है और बेइन्साफी का ही नतीजा रियासतों का डायनफाल होता है। अगर इन्साफ ठीक हो, अगर सरकार इन्साफ पर मबनी हो तो रियासत के वैसे भी बागी कुछ नहीं कर सकते और अगर इन्साफ नहीं है तो बागी क्या कोई भी ताकत उसको मिटा सकती है लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि आप जमींदारी मिटाइए, अगर इसी में आपका भला होता है तो जरूर मिटाइए और आप उनको चाहे भले ही भूमिधर या कृषिधर कुछ भी बनाइए, लफ्जों की कोई बात नहीं है लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिए कि आप किस उमूल पर और किस इन्साफ के साथ मुआवजा दे रहे हैं। माननीय प्रधान सचिव ने लफ्ज “इक्वीटेबिल” (न्याय-संगत) को काफी महंजर रक्खा है और मुझे इस बात की खुशी है लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो बतलाया कि वह इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन क्या होगा उससे मैं महमत नहीं हूँ और मैं उनकी परिभाषा और व्याख्या को नहीं समझ सका। जमींदार यह नहीं मान सकते कि प्रधान मंत्री जी ने जो बतलाया है वह इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन है। यह कम्पेनसेशन तो मालियत पर न होकर मालदारों को कम और गरीबों को ज्यादा मिलेगा मैं उनकी इस तरह की परिभाषा को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन इस बात का फैसला और न्याय कौन कर सकता है कि कितना कम्पेनसेशन इक्वीटेबिल है और कितना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप की आज मैजारिटी है और वह आपके कहने से कुछ भी फैसला इक्वीटेबिल के बारे में कर सकती है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह आप की मैजारिटी के लिए ही किसी बक हानिकारक होगा। आप यह न समझें कि सदा सबेरा ही रहेगा कभी शाम भी होगी और आपकी यह मैजारिटी भी एक दिन माइनारिटी होगी और पना न लगेगा और यह जितना मैजारिटी के लिए हानिकारक होगा उतना हमारे लिए नहीं। आप अगर इन्साफ करते हैं तो इस मामले को किसी न्यायालय में भेजिए और जो न्यायाधीश का फैसला हो उसे आप और हम मानें तो हम तैयार हैं। इस हाउस का पुराना मेम्बर हूँ और किसी के आक्षेपों से भी मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ सकता। मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप इस “इक्वीटेबिल” के फैसले के लिए इस बात को मंजूर कीजिए कि इसे न्यायालय के वास्तुक कर दीजिए। पंत जी खुद मुझसे ज्यादा समझते हैं कि कान्सटीट्यूशन का

एक्ट क्या है, २५ आर्टिकल पास हो गया है जो रेमेडी है उसमें यह दिया है कि फन्डामेंटल राइट्स तै करने के लिए दि रेमिडी बुड बी दि ला कोर्ट, उपचार न्यायालय से होगा, आप इस बात को मान लीजिए कि फन्डामेंटल राइट्स का फैसला करने के लिये आखिरी फैसला न्यायालय का होगा और उसे हम मानने को तैयार हैं। आप अपने बल और मैजोरिटी के जोर पर जो चाहें कर लें लेकिन आप दुनिया को ऐसी चीज नहीं मनवा सकते और हरगिज तसलीम नहीं करा सकते कि यह फैसला सही है। अब मैं भवन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं तो इस से भी कम वक्त अपने बोलने में लेता गो मैं पन्त जी का जवाब देने के काबिल नोट नहीं कर सका हूँ और चूँकि डिप्टी स्पीकर साहब की आज्ञा हुई कि मुझे जो कुछ कहना है वह इसी स्पीच में कह दूँ और आगे फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा।

इस वास्ते मैंने इतना वक्त लिया, फिर भी यह अनुरोध करूँगा कि मेरे इस संशोधन को मंजूर किया जाय वर्ना आप पब्लिक के सामने जवाबदेही न कर सकेंगे। मेरा ख़ास मतलब इस वक्त यह था कि इस बिल में ६ महीने के अन्दर कोई हर्ज नहीं हो सकता और अवधि को आप चाहें तो कम कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि विशेषज्ञों और काबिल आदमियों से हम राय कम समय में ले सकते हैं तो आप वक्त कम कर दें लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं और ख़ाम ख्वाह सिलेक्ट कमेटी के हवाले करते हैं और जाहिर है कि आप मैजोरिटी से पास करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी इंसफ़ नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।

श्री रोशन जमा ख़ाँ—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मुझे यह देख कर सख्त हैरत हुई कि राजा साहब हिन्दोस्तान में और दुनिया में तमाम इन्कलाबात को जानते हुए भी इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि हमारे सूबे से जमींदारी का नामोनिशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाय। राजा साहब ने जमींदारों की तरफ से ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को जो रिजोल्यूशन इस ऐवान में पेश हुआ था उस सिलसिले में बहुत जोरों से विरोध किया था लेकिन उनकी यह लड़ाई कारगर साबित नहीं हुई उन्होंने यह भी कहा केवल जमींदार साहबान ही हमारे सूबे की सरकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन राजा साहब जिन हथियारों से हुकूमत की मदद करने की अपील करते हैं वह खुद उनकी तन्जीम के सिलसिले में बड़े जमींदार कामयाब साबित नहीं हो सके। यही नहीं अभी हाल में जो तन्जीम बड़े जमींदारों ने किया था उनके बड़े भारी नेता, एक बड़े भारी मुकर्रिर सर जगदीश प्रसाद हैं। उन्होंने ताल्लुकेदारियों में कहीं कहीं जल्से किये, आसामियों को जबरदस्ती बुलाया गया लेकिन हमने यह नहीं देखा कि उनकी तन्जीम कहीं

[ श्री रोशन जमा खाँ ]

कामयाब हुई हो छोटे जमींदारों को भर्नाई करने की बात उन्होंने कही लेकिन वह भूल गये कि जब उन्होंने नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी को आर्गनाइज किया था जनाव डिप्टी स्पीकर साहब हमारे राजा साहब जो खुशकिस्मती से मेरी बगल में बैठे हुए हैं कुछ कहना चाहते हैं मैं आपके जरिये से यह गुजारिश करूँगा कि अगर वह कुछ नर्जद कहना चाहते हैं तो मैं अपनी जगह पर बैठ जाने को तैयार हूँ और उनको मौका दूँगा कि वह अर्ज करें।

उन्होंने जो दबी जवान में फरमाया वह यह है कि मैंने तो नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी की तंजीम नहीं की। मुमकिन है कि आप न रहे हों लेकिन मैं जब आपको कहना हूँ तो आपका जिक्र बहैमियत जमींदार और ताल्लुकेदार के नुमाइन्दे के होता है। यह हकीकत है कि हमारे सूबे के जमींदार साहब ने १९३६ ई० में एग्रीकल्चरिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी की तंजीम की थी, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते और उन्होंने उस वक्त यह समझा था कि १९३५ का कानून आने के बाद हम अपनी कार्यवाहियों की मदद से सूबे में हुकूमत बना लेंगे। उस वक्त कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी यह हालत थी कि वे समझते थे कि इनके मुकाबले में ५० सीटों से ज्यादा न मिल सकेंगी। लेकिन जब ५० नेहरू ने इस सूबे का दौरा किया तो २२८ सीटों में आधी से भी ज्यादा तादाद कांग्रेस को मिली। जब आपको उममें कामयाबी न हुई तो उसके बाद हमारे दोस्त नवाब जमशेद अली खाँ साहब की मददरत में इसी लम्बनऊ में एक कांग्रेस हुई, जिसमें छोटे जमींदार भी बुलाये गये। लेकिन मैंने यह सुना है कि जब छोटे जमींदार बाद को इन बड़े जमींदार के पास पहुँचे तो उन्हें साफ जवाब दे दिया कि आप हजरात अपनी तंजीम करें। हमारे पास तो हुकूमत राजाजिण के दिये हुए बड़े बड़े कागजात हैं और हम अपना मामला फेडरल कोर्ट या दूसरी जगहों से तय करा लेंगे। यह हमदर्दी आपने छोटे जमींदारों के साथ दिखाई और आज आप कहते हैं कि लोगों को मौका दीजिए वह हमसे जमींदारी को खरीद लें आपके मुँह में जवान है, आपको गरीबों से हमदर्दी करने का अख्तियार है, आप अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आपकी तवारीख बताती है कि जब कभी मौका आया आपने गरीबों का खून चूसा है, आपने गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं की। आज भी आपकी यह हालत है कि इस बिल को दिसम्बर तक के लिये मुलतवी करवाना चाहते हैं, इस बिना पर कि राय आम हासिल की जाय। यह महज एक तरकीब है। आप चाहते हैं कि गरीबों को अब भी जो कुछ थोड़ी बहुत आसाइशें और आराम मिलनेवाला है वह भी न मिल सके। राजा साहब की यह तजवीज ऐसी है कि एक मिनट के लिये मंजूर नहीं की जा सकती। इस बिल के बारे में राय आम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जमींदारी का मसला ऐसा है जिस पर बहुत दिनों से बहम होती रही है और बहस होती रहेगी। जब तक कि जमींदारी यककलम इस सूबे से खत्म नहीं कर दी जाती तब तक

यह बहस बन्द नहीं हो सकती। राजा साहब शायद यह समझने हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट बदला देने की खानिर यह कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कांग्रेस गवर्नमेंट मजबूर है। कांग्रेस गवर्नमेंट की यह हिम्मत नहीं कि वह जमींदारी के मिटाने को रोक दे और अगर नहीं मिटाती है तो ऐसे वाक्यात दुनिया में मौजूद हैं कि इस जमींदारी को न मिटाने की वजह से इस हुकूमत को खतरे में पड़ना पड़ेगा और देश को भी खतरे में पड़ना पड़ेगा। यह हालात हैं जिनकी बिना पर कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी दोनों इस बान के लिये जोर दे रही हैं कि जल्दी से जल्दी जमींदारी को खत्म कर दिया जाय। जैसा कि हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया, कम्युनिस्टों ने चीन में लैंड रिफार्मस नहीं किये, जमींदारी नहीं मिटाई, उसका नतीजा यह हुआ कि उस डिसकन्टेन्ट असन्तोष में कम्युनिस्ट आइडियालजी साम्यवादी सिद्धान्त बहुत ज्यादा कामयाब हुआ और अब कम्युनिस्टों के नेता क्यांकाई शेक का हाल यह है कि उसे करीब के समुन्दर में गर्क होना पड़े। यह मूरत है जिसकी बिना पर हम जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं। हम जमींदार साहबों के खैरखाह हैं, उनकी भलाई चाहते हैं उनको भी इम्सान बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे आराम की जिन्दगी बसर करें, लेकिन हम इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे कि दूसरे जानवरों की जिन्दगी बसर करें और वह ऐशोआराम में अपने महलों में रहें। उनका यह तरीका जो बिल के पास होने में रुकावट डाल रहे हैं किसी तरह मुनासिब नहीं।

आज भी उनका यह तरीका कि वे इस बिल के पास होने में रुकावट डाल रहे हैं, किसी तरह मुनासिब नहीं है। अब मैं उस रिजोल्यूशन के बारे में जो हमारे वजीर आजम साहब ने पेश किया है कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ तक वजीर आजम साहब की तक्रिर का सवाल है वह निहायत ही अहम है और उसमें जिस तरह से वाक्यात को पेश करने की कोशिश की गई है मैंने देखा कि हमारे वजीर आजम साहब ने अगर्चे उन्होंने शायरी तो नहीं की मगर उन्होंने आज तक्रिर में शायरी जरूर की। बहरहाल यह मौका ऐसा होता है जब एक शख्स चाहे वह वजीर आजम हो या कोई दूसरा ही आदमी हो जब जमींदारी मिटाने का कानून पेश हो रहा हो तो वह अपने जज्बात को नहीं रोक सकता है गो उस तक्रिर की बातों से मुझे इख्तिलाफ है फिर भी वजीर आजम साहब की तक्रिर ऐज ए होल सामूहिक रूप से ऐसी है कि हम उन्हें मुबारकबाद दे सकते हैं। अब मैं वजीर आजम साहब को उनकी उस तक्रिर की याद दिलाऊंगा जो उन्होंने ७ अगस्त १९४६ ई० को जमींदारी अबोलीशन पर इस हाउस में दी थी। जो वक्त ३ बजे का आज है, उस दिन भी ३-४ बजे के दरमियान का वक्त था उन्होंने उस दिन अपनी तक्रिर में फरमाया था—

सवाल आपके सामने यह है कि इस सूबे के जो साढ़े पाँच करोड़ या ६ करोड़

[ श्री रोशन जमा खान ]

आदमी हैं उनमें उनके बारे में क्या किया जा रहा है। ये साढ़े पाँच करोड़ आदमी जो इस सूबे में बसने हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनको देखकर नरम आता है। जनाबवाला रोशनी कम होने की वजह से बज्जीर आजम की तकरीर का बाकी हिस्सा नहीं पढ़ा जा सकता।

बहादुर जनाब बज्जीर आजम साहब ने उस तकरीर में जो बतलाया था वह यह था कि जमींदारी के भिगने का अमली मंरा यह है कि इस सूबा के गरीबी के मसले को हल किया जाय और वह लोग जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, दवा के लिये कुछ नहीं है, रहने के लिये कुछ नहीं है, उनका इन्तजाम किया जाय। लेकिन यह जानने हुये भी कि इस सूबे में गरीबी और दूसरी मुसीबतों के बिना अमनोष है बेचनी और परेशानी अबाम में बढ़ रही है उसके लिये कोई ऐसी बात नहीं रक्खी गयी है जिससे सूबे की गरीबी या दूसरी मुसीबतें दूर हो सकें। मैं तो यह कहूंगा कि बज्जीर आजम साहब ने जो तकरीर ७ अगस्त, सन् १९४६ ई० में की थी उसके मुकाबले में जमींदारी अवालिशन कमेटी की रिपोर्ट रोपेक्शनरी रिपोर्ट थी और जो बिल आज उन्होंने इस ऐवान के सामने रक्खा है वह उस रिपोर्ट से ज्यादा रोपेक्शनरी है। जमींदारी अवालिशन कमेटी के रिपोर्ट के हिस्सा अब्बल का आखिरी पैराग्राफ जो है, वह जमींदार साहबान को मुख्ताब करके लिखा गया था। लेकिन मैं उस पैराग्राफ के जरूरी हिस्सों को खुद गवर्नमेंट को मुख्ताब करते हुये पढ़ना चाहता हूँ—

“The age long simmering discontent, occasionally bursting into acts of open defiance and sometimes of violence in our province and other parts of India, has reached a critical stage. Whatever forbearance and self-restraint we find in the country side among the tenants is due to the hope that those who are running the State will undo the wrong done to them. Once that hope has gone the tenants will be driven to desperation. The discontent may develop into revolt and our social security may be threatened by the outbreak of violence.

In the words of Professor J. Laski “To the threat of revolution, there is historically only one answer, viz., the reforms that give hope and exhilaration to those to whom otherwise the revolutionaries made an irresistible appeal.” One can only hope that the entire Congress and the Congress Government are not blind to the writing on the wall.

( हमारे प्रान्त में तथा भारत के दूसरे भागों में जो सन्तोष दीर्घकाल से परिपक्व हो रहा है और जिसके कारण कभी कभी आजा उत्तुंग और हिंसा के कार्य हो जाने हैं, वह एक भयंकर परिस्थिति को पहुँच गया है। देश में किसानों के अन्दर जो कुछ भी आत्मनियन्त्रण और नरनरगतता हम देने हैं, - वह इस कारण से है कि उन लोगों को आशा है कि जो लोग शासनाखड़ हैं वे हमारे प्रति किये गये अन्याय को दूर कर देंगे। यह आशा यदि जाती रही तो किसान लोग दुस्मादस्त करने पर तत्त जायेंगे। असन्तोष में क्रान्ति उत्पन्न होगी और हमारी सामाजिक शांति का अहिंसात्मक कार्य से भय रहेगा। प्रोटेनर जे लस्का के शब्द हैं—“इतिहास में क्रान्ति के डर का केवल एक उत्तर है और वह ऊपर ऐसे मुधार के रूप में है, जिससे उन लोगों का शान्त किया जा सके जिन्हें क्रान्तिकारियों ने भड़का दिया हा।” केवल यही आशा की जा सकती है कि सभी भूमि रखन वाले सज्जन ( कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ) ऐसी सज्ज वाता का ध्यान रखेंगे। )

जनाबवाला, वजीर आजम साहब ने अपनी तक्रौर के दौरान में खुद कम्यूनिस्ट का जिक्र किया है और इस नुक्ते जिगाह से जिक्र किया है कि जमींदार साहबान को इस बात पर राजी हो जाना चाहिये। खुशी है कि जल्द से जल्द जमींदारी मिटा दी जाय, ताकि मुश्क को कम्यूनिस्ट खतरे से बचाने में आसानी हो।

मैं भी जनाब वजीर आजम साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में से जो इवारत पढ़ी है, उसको देखते हुये यह हकीकत मालूम होती है कि हम जमींदारी मिटाने के बाद जो सोसाइटी इस सूबे में बनाना चाहते हैं, वह ऐसी हो जिससे यह बेचैनी और परेशानी और यह असन्तोष जल्द से जल्द दूर हो जाय। मुझे अकसोस के साथ कहना पड़ता है कि वजीर आजम साहब ने इस बिल को जमींदारी मिटाने का नाम दिया है, लेकिन मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। हकीकतन आप इस बिल से इस सूबे में जमींदारी नहीं मिटा रहे हैं यह और बात है कि मौजूदा जमींदार साहबान को थोड़ा सा नुकसान पहुँच जाय। लेकिन हकीकत यह है कि जो चीज इस बिल में रखी गयी है, उससे तो जमींदारी हमारे सूबे में नहीं मिटती। हाँ, यह और बात है कि एमीकलचरल कैपिटलिस्ट ( खेती करनेवाले पँजीपति ) का एक क्लास हमारे सूबे में पैदा हो जाय। वह गरीबों का शोषण करे। खून चूसते जिस तरह आज तक जमींदार साहबान इस सूबे में गरीबों का खून चूसते रहे हैं, एक मोह भूमिधर लोगों का बनाया गया है और इस भूमिधर क्लास को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी जोत का बैनामा कर सके, हिंसा कर सके, अपने परसनल ला ( व्यक्तिगत कानून )

[ श्री रोशन : माँ लॉ ]

के मुताबिक बर्मीयन कर सके। मैं समझता हूँ कि जो अख्तियारात भूमिधर को दिये जा रहे हैं, उनका मतलब यह है कि इस भूमिधर को आप पीजेंट प्रीमाइटर कहने तो ज्यादा अच्छा होना। बजाय इसके कि आप यह कहें कि यह किसान का एक क्लाम होगा, वह शोषण नहीं करेगा मैं नहीं मानता, जब इन भूमिधर लोगों को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी जोत और अपनी आराजी को ट्रांसफर कर सकें, मुन्तकिन और हस्तांतरण कर सकें। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि फिर हिज मैजिस्ट्री को क्या चीज वेस्ट करेगी। राइट ऑफ ट्रांसफर (हस्तांतरण करने का अधिकार) न होना चाहिये। इन लोगों को ट्रांसफर करने का अख्तियार, बैनामा, हिबानामा और वसीयत करने का अख्तियार और सारे अख्तियारात उस जमीन और और आराजी के बारे में रहेगा जिसके वह भूमिधर कहलायेंगे ऐसी सूरत में मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि इकीकतन इम बिल से कोई चीज हिज मैजिस्ट्री में वेस्ट करेगी। जहाँ तक उस आराजी का ताल्लुक है जिस के भूमिधर हमारे सूबे में बनाये जा रहे हैं। यह तरीका तो सही और मुनासिब नहीं कहा जा सकता। कहा यह जाता है कि जो सीरदार हैं वह अगर दसगुना लगान अदा कर दें तो वह भूमिधर बन सकते हैं। यह चीज ऐसी है जिस से गरीबों को नुकसान ही नुकसान होगा। आज किसान गरीब हैं। खुद जर्मोदारी एवाशिन कमेटी की 'रपोर्ट' में यह बात कही गयी है कि चार एकड़ तक जोतनेवाला किसान इतना कमाता है, जो उसके खाने को काफी हो सकता है। इससे कम जो जोतता है वह इतना कमाता है जिससे उसका पेट नहीं भरता। ऐसी सूरत में मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो गरीब किसान और फारस्तकार हैं वह अपनी आमदनी से इतना बचा सकेंगे कि दस गुना मुआविजा बानी दस सान का लगान अदा करके वह भूमिधर हो जायें। नतीजा क्या होगा? यह बेचारे गरीब लोग इतना कमा न सकेंगे कि कुछ बचायें। और बचाकर भूमिधर हो सकें। उनकी आमदनी उनके खाने के लिए काफी न होगी। नतीजा इसका यह होगा, जब यह शर्त रक्की गई है कि उनकी मालगुजारी अदा न हो तो बेदखली हो जायगी इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि वह आराजी से महकूम हो जायेंगे और वह बकीनन दूसरे शरूब के पास जावेगी।

ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि जो क्लाम आप भूमिधर का पैदा कर रहे हैं, वह इकीकतन इम सूबे के एक्सप्रोप्रायटेसन को कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ा देगा। आपने जिस चीज को खत्म करने का एलान किया है, वह चीज खत्म नहीं होगी। प्रीमियर साहब ने सोशलिस्ट पार्टी पर कुछ इसारा करते हुये डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का बिल किया और यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तो कहती है कि एक आदमी को बीस बीघे जमीन और एक गाँव देंगे और शरूब इससे ज्यादा भी देने की कोशिश करें। बहरहाल, जहाँ तक प्रीमियर साहब का ताल्लुक

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ६१

है, उनको यह है कि एक पार्टी जो अपोजीशन में है उसके बारे में वह अपने ध्यान को जाहिर करें। लेकिन मैं भी आजादी चाहूँगा कि सोशलिस्ट पार्टी के नुक्तेनिगाह को इस ऐवान के सामने पेश कर सकूँ।

डिप्टी स्पीकर—अब आप खत्म करें। बाकी तकरीर कल होगी।

( इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर शुक्रवार, ८ जुलाई, १९४६, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया। )

लखनऊ  
७ जुलाई, १९४६

कैलासचन्द्र भटनागर,  
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,  
संयुक्त प्रांत।

---



## नरथी 'क'

( देखिये प्रश्न संख्या १ (क-ग), (घ) और (स) के उत्तर दीये हुए हैं पर )

## विवरण पत्र संख्या ( अ )

इस गेट्टे का की बाजरा मकान बाजरा की	हमारे में		उनमें में १ टन २२५० पौंड	
	सन् १९४२-४३	सन् १९४३-४४	सन् १९४४-४५	सन् १९४५-४६
	( १९४३ फसली ) ( १९४४ फसली ) ( १९४५ फसली ) ( १९४६ फसली )			
	१,८१८,८०८	२,०८८,००८	२,२८८,०००	२,५८६,०००
	७,६०७,८६२	७,८२७,८०८	७,८२७,८६६	२,५७२,०००
	६,१४०,१४७	८,६६०,७२६	८,८७७,६६६	१,७१६,०००
	४,३६१,४७८	४,४६८,८०८	४,४७६,७४८	१,७१८,०००
	६,६१४,४८८	७,८४७,६६८	७,४२०,८१८	१,७७८,०००
	२,८६६,६२४	२,८६४,१४१	२,८६६,१८०	७४७,०००
	२,८८८,६०८	२,८८८,०४६	२,८८८,०४६	२०८,०००
	१९८,६६६	१९८,१७०	१९८,७८६	७,०००

इस गेट्टे का बाजरा मकान बाजरा की



## विवरण पत्र संख्या 'स'

सन १९४६, १९४७ व १९४८ के वर्षों में बाहर से अनाज आये हुये का विवरण पत्र टनों में

मासमी	१९४६	१९४७	१९४८
गेहूँ	७७,०२४	५६,६२६	१,०४,२६०
गेहूँ से बनी हुई वस्तुयें	१५,५२७	५,६०२	८२७
चना	१०,०३८	१७,६२१	१४,७३०
जौ	१०,२००	१,२३,६६७	२४,७२७
चावल	३४,६२३	३७,२४२	३,७३२
जुआर	८०१	६२५	...
बाजरा	३४२	...	...
मक्का	५,४६६	३१,८४४	१५,६६०
बाई	४,६६६	७,१८८	...
कुल	१, ५६ ५६५	२, ८३, ७१५	१, ६३, ६५६

नत्थी 'ख'

( देखिये प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर )

साल	व्यय			विद्यार्थियों की संख्या
	रु०	आ०	पा०	
१९४३-४७	८०, ३५३	१४	३	५०२
१९४७-४८	८१, ००१	५	३	४८१
१९४८-४९	८४, ४५४	५	०	४८०

## नत्थी 'ग'

( देखिये प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर )

बाद पीड़ित ग्रामों के नामों की सूची

१. बेन्ती उपरहार
२. बेन्ती ताबाब
३. बेनीमऊ उपरहार
४. बेनीमऊ ताबाब
५. शाहपुर उपरहार
६. शाहपुर ताबाब
७. शाहपुर कटार
८. खवा सुखदेवपुर
९. मोहिउद्दीन नगर उपरहार
१०. मोहिउद्दीन नगर ताबाब
११. मोहिउद्दीन नगर कटार
१२. पुरनीमऊ उपरहार
१३. पुरनीमऊ ताबाब
१४. कटारनाबाद कटार
१५. मऊ दारा उपरहार

## नत्थी 'घ'

( देखिये प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर )

व्योरा	गाँवों के नाम				
	बाधाचौर	हनुमानगंज	परसौनी जनूबी	परसौनी शुमाली	नरायनपुर
गाँव के क्षेत्रफल का जोड़	१०६७.३४	७५१.७८	१२८०.०३	१३२३.६६	८६८.७३
जलमग्नभूमि का क्षेत्रफल	१६३.५६	३०५.१२	८३२.०५	७७५.३५	६०४.२२
बालू से ढकी भूमि का क्षेत्रफल	८०.१०	६०.०५	१३०.०६	१७५.१०	१२१.६०
१३५५ फसली में जोती					
गई भूमि का क्षेत्रफल	७६६.८२	३१४.६३	२७१.२८	५११.५७	१२६.२७
मालगुजारी	८४७।२।५	३१६।४।८	४४०।०।०	८८।०।०	१११।५।२
प्रत्येक जोती गई भूमि के क्षेत्रफल की मालगुजारी का परता	१।२।०	१।०।३	१।१।०।०	।२।६	०।१।६
नक़द लगान देनेवाली भूमि का क्षेत्रफल	७५३.७१	२४७.५५	१६०.६२	११६.२५	१७२.५४
नक़द लगान	२१७६।४।२	४५२।२।६	४६३।६।६	३२५।६।०	४१३।१।६
प्रत्येक एकड़ की नक़द लगान का परता	२।१४।०	१।१३।०	३।०।०	२।१२।०	२।६।०
बटाई लगान का क्षेत्रफल	१४.५०	१०६.०६	१५५.३०	५७.०६	०.२६
बटाई लगान में प्राप्त अन्न का मूल्य	२४८।६।०	१३३९।९।०	१७८१।५।९	११४१।१३।६	२।०।६
बटाई लगान वाले क्षेत्रफल की प्रत्येक एकड़ का परता	१७।१२।०	११।११।०	११।८।०	२०।०।०	७।८।०
१३५५ फसली की नक़द प्राप्ति	१७४६।६।११	३८५।७।०	४६३।६।६	३११।१।३	४१३।१।६
१३५५ फसली में बटाई लगान में प्राप्त अन्न का मूल्य	२४८।६।०	१३५०।६।६	१७७४।६।६	११४१।१३।६	२।०।६
वारन्ट गिरफ्तारी	१२	...	...	...	...
वारन्ट कुर्की	१८	...	...	...	...
वारन्ट बिक्री	...	...	...	...	...



# संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शुक्रवार, ८ जुलाई, १९४६

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

## उपस्थित सदस्यों की सूची (१८५)

अचल सिंह  
अजित प्रताप सिंह  
अब्दुल ग़नी अन्सारी  
अब्दुल मजीद  
अब्दुल वाजिद, श्रीमती  
अब्दुल हमीद  
अम्मार अहमद खाँ  
अल्लगूराय शास्त्री  
अली जर्जर जाफरी  
अक्षयवर सिंह  
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री  
इन्द्रदेव त्रिपाठी •  
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती  
एजाज रसूल  
करीमुर्रज़ा खाँ  
कान्हीचरण टंडन  
कुंजबिहारी लाल शिवानी  
कुशलानन्द गैरोला  
कृष्णशंकर  
कृष्णचन्द्र  
कृष्णचन्द्र गुप्त  
केशव गुप्त  
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री  
खुशवह्तराय  
खुशीराम  
खन् सिंह

गजाधर प्रसाद  
गणेश कृष्ण जैतली  
गोपाल नारायण सक्सेना  
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री  
गोविन्द सहाय  
गंगाधर  
गंगा प्रसाद  
गंगा महाय चौबे  
चतुर्भुज शर्मा  
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री  
चन्द्रभानुशरण सिंह  
चरण सिंह  
चेतराम  
छेदालाल गुप्त  
जगन्नाथ दास  
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल  
जगन्नाथ सिंह  
जगन्नाथ ब्रह्म सिंह  
जगमोहन सिंह नेगी  
जवाहरलाल रोहतगी  
जाकिर अली  
जाहिद हसन  
जहीरुल हसनैन लारी  
जुगलकिशोर  
जयपाल सिंह  
जयराम वर्मा





रामचन्द्र मेरु  
 रामचन्द्र वरुणा  
 रामजी मन्त्र  
 रामधर मिश्र  
 रामधारी गंड  
 राम वर्मा  
 राममूर्ति  
 रामदांकर लाल  
 रामदास  
 रामस्वरूप गुप्त  
 रामेश्वर मन्त्र मिह  
 रघुनाथजी मन्त्र  
 गेगन ज्ञान मन्त्र  
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती  
 ललाट हुसैन  
 लालन दाम जाटव  
 लालबहादुर, माननीय श्री  
 लाल विहारी टण्डन  
 लालाधर अष्टाना  
 लाल राम  
 पिजयानन्द मिश्र  
 विद्यावती राठौर, श्रीमती  
 विनय कुमार मुकुर्जी  
 विश्वनाथ प्रसाद  
 विश्वनाथ राय  
 विश्वनाथराय त्रिपाठी  
 विष्णुदास दुर्गा  
 वीरेन्द्र शाह  
 वेंकटेश नारायण निवासी  
 शंकरदत्त शर्मा  
 शक्ति प्रसाद शर्मा

शिवकुमार पाण्डेय  
 शिवकुमार मिश्र  
 शिवदयाल उपाध्याय  
 शिवदान सिंह  
 शिवमंगल सिंह  
 शिवमंगल सिंह कपूर  
 मुचेता कृपानी, श्रीमता  
 श्यामलाल वर्मा  
 श्यामसुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द्र मिश्र  
 श्रीपति सहाय  
 सईद अहमद  
 सज्जन देवी महनोन, श्रीमती  
 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 सलीम हामिद खां  
 माजिद हुसैन सत्यद  
 सालिग्राम जैसवाल  
 सिंहासन सिंह  
 सिराज हुसैन  
 सीताराम अष्टाना  
 सुदामा प्रसाद  
 मुन्तान आलम खां  
 सुरेन्द्र बहादुर सिंह  
 सूर्य प्रसाद अवस्थी  
 हिफजुर्रहमान  
 हबीबुर्रहमान अन्सारी  
 हरगोविन्द पन्त  
 हरप्रसाद सत्यप्रमी  
 होतीलाल अग्रवाल  
 त्रिलोकी सिंह

## प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ता० ८ जुलाई, मन १८४८ ई०

## तारांकित प्रश्न

मेडिकल लाइसेंशियेट संघ के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट

\* १-श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)—क्या मेडिकल लाइसेंशियेट संघ का डेपुटेशन माननीय मिनिस्टर चिकित्सा विभाग से नवम्बर सन् १९४८ ई० में अपनी मांगों के लिये मिला था ?

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां ।

\* २-श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)—अगर हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और माननीय मिनिस्टर उनकी मांगों को पूरा करने के लिये किम निर्णय पर पहुंचे ?

माननीय अन्न सचिव—उनकी मांगें बहुत विस्तृत थीं । जिनमें मुख्य मुख्य यह थीं कि सभी अंगियों की मेडिकल सरविसेज का एकीकरण हो, ग्राम चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण हो, अन्विल भागनीय मेडिकल कांसिल के रजिस्टर में लाइसेंशियेट भी दर्ज हों, उनको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने की सुविधायें दी जायं, उनके वेतन और पदवृद्धि के लिये प्रचुर सुविधायें हों, इत्यादि इत्यादि । इनमें कुछ मांगें (जैसे अन्विल भारतीय मेडिकल रजिस्टर में नाम दान्त्रिक करना) केन्द्रीय सरकार से सम्भव रहती हैं । बहुत सी मांगें सरकार ने पूरी कर दी हैं जैसे वेतन वृद्धि, कण्डेन्स कोर्स की सुविधा और बहुत सी की जा रही हैं जैसे ग्रामीण चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण । परिस्थिति समझ लेने के बाद डेपुटेशन के सदस्य अपनी सभी मांगों पर संतुष्ट हो गये थे । केवल एक मांग रह गई थी कि बड़े हुए वेतन-क्रम के लगू होने पर उन पी० एस० एम० एस० अफसरों के वेतन क्रम में जिनका वेतन उस समय २०० रु० मासिक के लगभग था कुछ तरक्की दी जा सकती है अथवा नहीं । इस प्रश्न पर भली भांति पूछ-ताछ के पश्चात् देखा गया कि केवल एक ही अफसर का वेतन उस समय २०० रु० था । वह अफसर अब अवकाश ग्रहण कर चुका है अतएव उसके लिए कुछ करना सम्भव नहीं था । बाक़ी १८ अफसर १७५ रु० पुराने वेतन-क्रम में पाते थे और नये क्रम में वे १७६ रु० पायेंगे । पुराने वेतन-क्रम में केवल २ प्रतिशत अफसर २०० रु० के ग्रेड में जाते थे और बाक़ी १७५ रु० पर ही रुक जाते थे । अब यह सभी अफसर १७५ के आगे १२०-४-१६०-८-२०० के वेतन-क्रम में जा सकेंगे । इन मीनियर अफसरों में जो योग्य होंगे उनको पी० एम० एस० द्वितीय में कद देने का भी प्रस्ताव तत्काराधीन है ।

बाराबंकी के सीमेंट के एजेंटों द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई

\* ३-श्री हर्षदास सत्यप्रेमी—क्या सरकार जानने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के सीमेंट के एजेंटों से किस-किस जिले के किस-किस व्यक्ति या संस्था को गत दो वर्षों में कितना कितना सीमेंट देने के परमिट जारी किये गये ?

नोट—तारांकित प्रश्न सं० १ तथा २ श्री हरी लाल अग्रवाल ने पूछे ।

**माननीय अन्न सचिव**—एक सूची जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है, सम्बद्ध है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६६ पर)

\* ४-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या यह सही है कि अल्मोड़ा-गोरगपुर और लैंसडाउन आदि दूर स्थानों के लिये भी बाराबंकी जिले के एजेन्टों में सीमेंट प्राप्त करने के परमिट जारी किये गये ?

**माननीय अन्न सचिव**—जी हां, लैंसडाउन को छोड़कर। बाराबंकी केन्द्रीय स्थान है और ओ० टी० रेल से सम्बन्धित स्थानों के लिये माछ लटने का मुख्य स्टेशन है।

**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या गवर्नमेंट को मान्य है कि यह स्टेशन ओ० टी० आर० में नहीं है बल्कि ई० आई० आर० में है ? उत्तर में कहा गया है कि जो स्टेशन ओ० टी० आर० में हैं वहां के लिये बाराबंकी से परमिट्स दिये गये हैं लेकिन यह स्टेशन तो ई० आई० आर० में है ओ० टी० आर० में नहीं है।

**माननीय अन्न सचिव**—यह तो सरकार को मान्य है कि कुछ उन स्टेशनों को दिये गये हैं जो ओ० टी० आर० पर नहीं हैं।

**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या गवर्नमेंट इन असुविधाओं को दूर करने के लिये प्रयत्न करेगी।

**माननीय अन्न सचिव**—हमेशा ही प्रयत्न करती रहती है।

**प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की इजाजत**

\* ५-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि युक्त प्रान्त में ऐसे कितने व्यक्ति (ताल्लुकदारान) हैं जिनके हथियार रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ?

**माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)**—इस सूचे में इस समय कुल १०५ व्यक्ति (ताल्लुकदारान) ऐसे हैं जिनके लिये हथियार रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

\* ६-**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—उक्त व्यक्ति किस उसूल पर लाइसेंस से मुक्तसना किये गये ?

**माननीय पुलिस सचिव**—इण्डियन आर्म्स ऐक्ट के शिख्यूल १ में कुछ ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है जिनको भारत सरकार ने लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया है। जिनका बिक्र उपर किया गया है वे उन्हीं वर्गों में आने के कारण उस ऐक्ट के अनुसार लाइसेंस लेने से मुक्त हो गये हैं।

**श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या प्रान्तीय सरकार ताल्लुकदारों के लाइसेंसों को जारी कर रखना पसन्द करेगी ?

**माननीय पुलिस सचिव**—ताल्लुकदारों का रहना ही मुश्किल हो रहा है। लाइसेंसों जारी रखने का प्रश्न तो मुश्किल से उठेगा।

**बन्दरों तथा अन्य जङ्गली जानवरों द्वारा फसल की हानि**

\* ७ **श्री हरप्रसाद सत्यप्रेमी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुमान से युक्त प्रान्त में प्रति वर्ष बन्दरों से कृषि और फलादि सम्बन्धी कितनी सम्पत्ति का विनाश होता है ?

माननीय कृषि सचिव (श्री भिस्मिल अहमद शेरवाना)।—युक्त प्रान्त में बन्दरों में जगों की लम्बाई १५ से २० फी मीटर तक का भाग नष्ट होना है। इस क्षति का अनुमान लगाने में दोष नहीं किया जा सकता है।

\* ८-अ। सरदार अमृतलाल—क्या सरकार इन अन्न संकट के वर्षों में बन्दरों तथा अन्य जगहों पर जलवायु क्षति में घटने का कोई विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या?

माननीय कृषि सचिव—बन्दरों तथा अन्य जगहों और पालतू जानवरों द्वारा क्षति को रोकने के लिये एक योजना सरकार के विचारधीन है। यह योजना पहले ही प्रारम्भ कर दी गई होगी किन्तु बन्दरों के प्रति लोगों की प्रचलित भावनाओं में उन्नत कठिनाइयों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हो सका। इस क्षति में सरकार माननीय सदस्यों के प्रस्तावों का स्वागत करेगी।

अ। सरदार अमृतलाल—यह कौन सी स्कीम है जिसने नुकसान पहुंचाने वाले बन्दरों को पकड़ना ज़रूरी है?

माननीय कृषि सचिव—मानन हुआ है कि उड़ीसा में गवर्नमेंट ने बन्दरों को पकड़वाया है और जिन लोगों ने बन्दरों को पकड़ा उन लोगों को फी बन्दर ३-४ रुपया इनाम दिया गया है।

**सुल्तानपुर जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना**

\* ९-अ। रामबली मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला जेल को सेनीटोरियम जेल क्यों बनाया गया है?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)।—सुल्तानपुर जिला जेल में सूखे के क्षय रोग में ग्रस्त कैदियों को वर्षों से रखा जा रहा है। चूंकि उस समय का रिजर्व अब मौजूद नहीं है, इसलिये यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि यही जेल तपेदिक वाले कैदियों के लिये क्यों चुना गया।

**सुल्तानपुर जिले में क्षय की रोगियों की सूची**

\* १०-अ। रामबली मिश्र—क्या सरकार सुल्तानपुर जिले के क्षय रोग के रोगियों की कोई सूची रखती है?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं।

**सुल्तानपुर जिला जेल के मुर्दों के जलाने या दफनाने का प्रबन्ध**

\* ११-अ। रामबली मिश्र—सुल्तानपुर जिला जेल में मुर्दे, विशेषकर क्षयरोग से मरे हुए, के जलाने या दफनाने का क्या प्रबन्ध है?

अ। गोविन्द सहाय—हिन्दू कैदी को लाश को जेल कम्पाउण्ड के एक कोने में जेल अधिकारियों की संरक्षकता में बच दिया जाता है। मुसलमान कैदी की लाश को अंजुमन इस्लामिया को १५ से २० प्रति लाश की दर से व्यय देकर सौंप दिया जाता है और वह उन्हें शहर के बाहर दफन करती है।

**दियरा राय, जिला सुल्तानपुर के, राजा साहब का सरकार को दान**

\* १२-अ। रामबली मिश्र—क्या सुल्तानपुर जिले के दियरा राज्य के राजा साहब ने सरकार को अपना माधवकुंज नामक बरग, मैनेजर का बंगला और वहां का अस्पताल दान दिया है?

माननीय अन्न सचिव—राजा साहब दियरा ने निम्नलिखित चीजें हमारे महात्मा गांधी की स्मृति में दान की हैं।

१. तुम ने — २. श्री — ३. डिप्टी कमिश्नरियर ।  
उत्तर — मैंने उनसे पूछा नहीं है। उन्होंने मैनेजर के बगले का दान  
मैंने लकड़वा से नहीं लिया है।

\* १३ श्री रामबली मिश्र — श्री — यह है, तो सरकार ने उनका क्या प्रदत्त किया ?

माननीय प्रमुख सचिव — मैं इस विषय पर कुछ नहीं जानती हूँ और उस पर पूरा व्यवस्थापक कोप है।

\* १४ श्री रामबली मिश्र — क्या सरकार को जान है कि दान देने के पश्चात् उस  
अल्पमूल्य का दान लकड़वा ने बन्द कर दिया है ?

माननीय प्रमुख सचिव — जूनि अल्पमूल्य अब सरकार को दिया है, उसके राजा साहब  
द्वारा बन्द कर दिया जाने का प्रश्न उ नहीं उठता। यह ठीक है कि दान देने के पहले जो धन  
राजा साहब अपने राज्य के कोष से उस अल्पमूल्य के ऊपर जमा करते थे अब उन्होंने उसे व्यय  
करना बन्द कर दिया है।

सूबे में बने हुए हवाई अड्डों का प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना

\* १५ श्री रामबली मिश्र — क्या सरकार सूबे में बने हुए हवाई अड्डों को अपने  
अधिकार में लेने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव — जी हाँ, इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने पत्र व्यवहार हो  
रहा है।

\* १६ श्री रामबली मिश्र — क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हवाई अड्डों की बनी हुई  
इमारतें समुचित देख रेख न होने के कारण धराशायी हो रही है ?

माननीय पुलिस सचिव — इन हवाई अड्डों की देख रेख का भार प्रान्तीय सरकार  
पर नहीं है।

जिला अधिकारियों को शासन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में गुप्ताज्ञा

\* १७ श्री रामबली मिश्र — क्या सरकार ने कोई गुप्ताज्ञा (डी० ओ०) द्वारा  
जिला अधिकारियों का यह सलाह दी है कि वे धारा सभा के सदस्यों की सलाह विशेषकर शासन के  
मामले में न सुनें ?

श्री गोविन्द सहाय — जी नहीं।

सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार

\* १८ श्री रामबली मिश्र — क्या सरकार को विदित है कि सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार बढ़  
रहा है ?

श्री गोविन्द सहाय — सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

सुल्तानपुर पुलिस का एक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न

\* १९ श्री विद्याधर बाजपेयी (अनुपस्थित) — (क) क्या सरकार को यह पता है कि  
ता० २१ मार्च को लगभग २ बजे रात में सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान डी० एस० पी० शहर  
कोतवाल गारद के साथ किसी बदमाश की तलाश में शहर तथा कई गांवों में गए और लोगों  
के घरों की तलाशियां लीं ?

२. इस सरकार का इरादा जो हुआ कोना कि इन मशीनों के 'परिष्कार' स्वतंत्र पुलिस को करना के अन्तर्गत होवे या न हो ?

३. अगर नहीं, तो राज्य सरकार ऐसे कार्यों के विस्तृत स्थानीय पुलिस ने क्या कार्य करेगी ?

**माननीय पुलिस सचिव—** २. सरकार को सूचना मिली है कि मशीन २१ मार्च को चलाया गया था। इसे से ३ घंटे तक काम किया गया। बाद में मेइडो नामक एक व्यक्ति की लोड में यह कारो को चलाया जा रहा है।

३. को नहीं।

४. सवाल: पुलिस ऐसे कार्यों के विस्तृत कोई कार्य नहीं करेगी। जहाँ जहाँ तक यह बातें आते हैं। यह तो ज्ञात कि सरकार ऐसे कार्यों के अन्तर्गत को इन्हें पकड़ाने के इरादे में है। इस सम्बन्ध में जो सूचना मिली थी उसने बारे में यह तो 'सूचना' है कि 'विस्तृत' अर्थ है जो इसीसे सूचना ऐसे कार्यों के विस्तृत कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

**मुन्शीनपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के मिस्टरमानों द्वारा वास्तुशिल्पियों की भर्ती**

५०० श्री विद्याधर राजपेयी अनुसंधित—(क) क्या सरकार को यह ज्ञान है कि मुन्शीनपुर में मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड के मिस्टरमानों अगले पुनर्निर्माण से वास्तुशिल्पियों की भर्ती कर रहे हैं और यदि हाँ तो कितना कर रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कृत्याद क्यों होने दी जा रही है ?

**माननीय पुलिस सचिव—** (२) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

३. सरकार के अन्तर्गत कोई ग्रेड के जो उसे सेवा करेगा।

**मेयो मेमोरियल पुस्तकालय को सहायता**

५०१-श्री विश्वनाथ प्रसाद अनुसंधित—क्या सरकार यह बनाने की कृपा करेगी कि पुस्तकालयों की सहायता देने की जो लिस्ट अगले बैच में हुई है उनमें मेयो मेमोरियल पुस्तकालय को कितना रकम दिया गया है। यदि कुछ नहीं, तो क्यों नहीं ?

**माननीय शिक्षा सचिव श्री संपूर्णानन्द—** (क) सम्भवतः मेयो मेमोरियल पुस्तकालय निकटपुर में स्थित है। इस पुस्तकालय को १९४८-४९ में कोई सहायता नहीं दी गई।

(ख) शिक्षा सचिव, संयुक्त प्रान्त, ने इस पुस्तकालय को सहायता देने के लिये निर्दिष्ट नहीं की थी।

५०२-श्री विश्वनाथ प्रसाद अनुसंधित—क्या सरकार यह बनाने का कष्ट करेगी कि इस पुस्तकालय को कितना रकम दिया गया था ?

**माननीय शिक्षा सचिव—** २५० रुपये

**कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों के सम्बन्ध में पूछताछ**

५०३-श्री राजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञान है कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विद्यार्थियों के अध्यापकों को २०० रुपये में ४५० रुपये तक वेतन दिया जाता है ?

**माननीय कृषि सचिव—**जं ह

\*२४-श्री गजाधर—क्या यह भी सत्य है कि कृषि महाविद्यालय कानपुर, अपने विद्यार्थियों में सम्मिलित हैं। यदि जवाब हाँ में है, तो उनके अध्यापकों को क्या १५० मर्रा में २५० मर्रा तक ही वेतन दिया जाता है ?

**माननीय कृषि सचिव—**जी हाँ यह बात गलत है कि कृषि महाविद्यालय कानपुर के सब अध्यापकों को १२० न० से २५० न० ही वेतन दिया जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल का वेतन १०५० न० से १०५० न० तक है, तथा प्रोफेसर्स को ३००० न० से १०००० न० तक, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को २५०० न० से ८५०० न०, लेक्चरर्स को २००० न० से ४५०० न०, असिस्टेंट लेक्चरर्स को १२०० न० से २५०० न० दिया जाता है।

\*२५-श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि महाविद्यालय में कुछ मित्रों ने अध्यापन कार्य कर रहे हैं ?

**माननीय कृषि सचिव—**जी हाँ।

\*२६-श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि कानपुर कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों के लिये प्रतिदिन काम पर आने जाने का समय क्या है ?

**माननीय कृषि सचिव—**कृषि महाविद्यालय में नदी का समय प्रातःकाल ६ बजे से ८.१५ तक गर्मियों में तथा ७ बजे से ९.१५ तक जाड़ों में और १०.३० से १ बजे तक गर्मियों में तथा ११ बजे से ३.१५ तक जाड़ों में है। प्रोफेक्टर और लेक्चरर्स दोनों समय होते रहते हैं।

\*२७-श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कानपुर कृषि महाविद्यालय के अध्यापकों के लिये रहने की व्यवस्था क्या है ?

**माननीय कृषि सचिव—**कृषि महाविद्यालय में अध्यापकों के रहने के लिये कुछ घर भी बने हुए हैं। यह घर अध्यापकों को तथा कृषि विभाग के अन्य कर्मचारियों को एक-दूसरे द्वारा दिये जाते हैं।

\*२८-श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकांश अध्यापकों के निवास स्थानों में बिजली का प्रबन्ध नहीं है ?

**माननीय कृषि सचिव—**कृषि महाविद्यालय के निम्नलिखित वर्गों में अपनी-अपनी तक बिजली का प्रबन्ध नहीं हो सका है।

१. कृषि महाविद्यालय के डेयरी तथा विद्यार्थी क्लबों के घर।
२. दल सुपरवाइजर्स के घर।
३. एक अन्य घर।

**जिला गढ़वाल की जन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकाउण्ट्स की मुअत्तली**

\*२९-श्री जगमाहन सिंह नेगी—(क) क्या यह सत्य है कि जिला गढ़वाल की जन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकाउण्ट्स ता० २४ सितम्बर १९४८ ई० से मुअत्तल हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो किस अपराध के लिये ?

**माननीय रद्योग सचिव (श्री देशवदेव मालवीय)—**(क) हाँ, यह सत्य है कि जिला गढ़वाल जन योजना के इन्स्पेक्टर आफ एकाउण्ट्स २८ सितम्बर १९४८ से मुअत्तल किये गये थे।



श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका इन्स्पेक्टर आन एन्डर्सन गढ़वाल के विरुद्ध क्या क्या आरोप थे, जिनके कारण वह इन्स्पेक्टर बनने की आज्ञा नहीं पाई ?

माननीय अध्यक्ष—जी हाँ।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका इन्स्पेक्टर आन एन्डर्सन गढ़वाल के विरुद्ध क्या क्या आरोप थे, जिनके कारण वह इन्स्पेक्टर बनने की आज्ञा नहीं पाई ?

माननीय अध्यक्ष—इन्स्पेक्टर आन एन्डर्सन के विरुद्ध आज्ञा-उल्लंघन का आरोप था जिनके कारण तार द्वारा उनकी मुअत्तिह करने की आज्ञा देनी पड़ी।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका इन्स्पेक्टर आन एन्डर्सन गढ़वाल के विरुद्ध क्या क्या आरोप थे, जिनके कारण वह इन्स्पेक्टर बनने की आज्ञा नहीं पाई ?

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका इन्स्पेक्टर आन एन्डर्सन गढ़वाल के विरुद्ध क्या क्या आरोप थे, जिनके कारण वह इन्स्पेक्टर बनने की आज्ञा नहीं पाई ?

(ग) यदि नहीं दिया है और वे इन्स्पेक्टर अभी भी मुअत्तिह में हैं, तो क्या सरकार इस देरी का कारण बतलावेगी ?

माननीय अध्यक्ष सचिव—(क) आरोप साबित हुए उपरोक्त इन्स्पेक्टर गढ़वाल उन योजना से हटा दिये गये और उनकी तरफकी दो साल के लिए रोक दी गयी।

(ख) वे अब मुअत्तिह नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वे हटा दिये गये और उनकी तरफकी रोक दी गई इसका क्या अर्थ है ?

माननीय अध्यक्ष सचिव—उनको सजा मिली।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—उनकी मुअत्तिह किस तारीख से हटाई गई ?

माननीय अध्यक्ष सचिव—इसकी तारीख तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं माननीय मन्त्रियों को फिर बतला सकता हूँ।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के नियमानुसार इन्स्पेक्टरों को तब तक मुअत्तिह रहे ?

माननीय अध्यक्ष सचिव—ठीक वक्त तो इस वक्त मैं नहीं बतला सकता मगर वह जल्द ही बतला दूँगा।

श्री जगन्नाथ सिंह नेगी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह अब किस विभाग में कार्य कर रहे हैं ?

माननीय अध्यक्ष सचिव—इसकी इच्छा तो मैं अभी नहीं दे सकता।

संकेत, वरुण कृतेन और गवर्नर के जुबन के अन्तर्गत - बालक - अन्तर्गत  
अभ्यासक - स - म्यूजिक (संगीत) सम्बन्ध

३३ श्री : गायन दाम (अनुपस्थित) - (क) क्या सरकार ने आदेश दिया कि ११ मार्च १९४९ को नई दिल्ली विश्वविद्यालय कलेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल इम्प्लान अर्पित हुआ और १२ मार्च को निश्चित था।

(ख) क्या यह सत्य है कि परीक्षक नं० ३ नई दिल्ली में आये और ८ मार्च को परीक्षा दी गई?

यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया?

(ग) क्या यह सच है कि लड़कियाँ प्रिपरेशन नई दिल्ली (नेवागी की छुट्टी) पर थी और दिक्कत में हुआ है।

(घ) क्या सरकार को आगे से कोई ऐसा आदेश था कि ११ मार्च के बजाय परीक्षा ८ मार्च को ही हो जाए।

माननीय शिक्षा सचिव - (क) जी नहीं। निर्धारित तिथि ३ मार्च से १० मार्च तक थी।

(ख) जी हाँ। यह पूर्व सूचित कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

(ग) सरकार को इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

\*३४-श्री नारायण दास (अनुपस्थित) - (क) क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट जुबली कलेज, लखनऊ में १० मार्च, सन् १९४९ ई० को म्यूजिक का इम्प्लान होने वाला था और लड़के परीक्षा की तैयारी करने की छुट्टी पर थे?

(ख) क्या यह सत्य है कि परीक्षक ८ मार्च को ही आ गये और ९ मार्च को लड़कों को बुला कर इम्प्लान लिया गया? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया?

(ग) क्या सरकार ने उनको इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया था?

माननीय शिक्षा सचिव - (क) (१) जी नहीं।

(२) इस विषय में कोई सूचना नहीं है लेकिन अभ्यासिक परीक्षाएँ बहुधा तैयारी करने की छुट्टियों के दिनों में ही जाती हैं।

(ख) पूर्व प्रश्न के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

लखनऊ नगर के बहुत से मुहल्लों में रोशनी का प्रबन्ध

\*३५-श्री गायन दास (अनुपस्थित) - क्या यह सच है कि आजकल लखनऊ नगर में बहुत से मुहल्लों में रोशनी के नेट के लैम्प हटाये जा रहे हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

माननीय सार्वजनिक शासन सचिव (श्री अत्माराम गोविन्द खेर) - जी हाँ। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी ने लैम्प हटा लिये हैं जो या तो आवश्यक न थे या उन स्थानों या ग्रामों में लगाये गये थे जो एक प्रकार से निजी स्थान वा ग्राम कहल्यते हैं और वहाँ से न तो बोर्ड को कोई फायदा हो सकेगा और न बोर्ड की तरफ से और कोई सफाई इत्यादि का प्रबन्ध होता है।

नगर-विभाग, जिस सम्बन्ध शहर में जन-जनों के निवेदन-लिखित  
इन्तर्जी विद्युत शक्ति

‘यद्वा’ नर ह्यसौ नदीं गच्छी ।

**माननीय स्वशासन सचिव**—कानून के अन्तर शेड्यूल्ड कस्टम् या परिगणित वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन लिखने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके स्थान सुरक्षित हैं ; बाकी लोगों को यह देने की आवश्यकता नहीं है

### गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के नियम

४४८-श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांव सभा के सेक्रेटरी के चुने जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ?

**माननीय स्वशासन सचिव**—माननीय सदस्य का ध्यान पंचायत राज नियम १६७ १६९ के अंगे आकर्षित किया जाता है जो कि माननीय सदस्य को गजट के साथ दिये जा चुके हैं

### सन १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़िया तथा खमा ग्रामों की क्षतिपूर्ति

४४९-श्री श्रीपति सहाय—सन १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़िया ग्राम तथा ग्राम ग्राम की जो हानि हुई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की।

**माननीय पुलिस सचिव**—सरकार को जहां तक मालूम है पहाड़िया और खमा गांव के रहने वालों को अगस्त सन् १९४२ के आंदोलन में कोई सीधा और सक्रिय भाग लेने के निमित्तले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जनवरी सन् १९४४ में लड़ाई का चन्दा दमूल करने के सम्बन्ध में इन गांवों वालों तथा तहसील की एक पार्टी में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से इन गांवों के कुछ लोगों पर नुकसान चला।

**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़िया ग्राम के वैजनाथ स्कूलों और उनकी कांग्रेस पार्टी के १० व्यक्ति सन् १९४२ में नजरबन्द कर दिये गये थे ?

**माननीय पुलिस सचिव**—जी, हां। सम्भव है ऐसा हुआ हो।

**श्री श्याम सुन्दर शुक्ल**—क्या यह सही है कि उस समय के आन्दोलन में जिन लोगों ने स्टेशन जलाये और इकैतियां डालीं वे सब दफ्ता १०९ में दिखलाये गये ?

**माननीय पुलिस सचिव**—माननीय सदस्य की नंशा मैं स्पष्ट कर दूँ। जो सवाल उन्होंने पूछा है उसने कोई खास तात्पर्य जो वह जानना चाहते हैं नहीं निकलेगा। यह जो परिभाषा सन् १९४२ के नुकसान के सिलसिले में मुआविजे के वास्ते बनाई गई है उस परिभाषा के अन्दर काफ़ी जांच करने के बाद भी यह मानला नहीं आता। इस वजह से गवर्नमेंट को मुआविजे की शर्त में कुछ देने में कठिनाई है। फिर भी जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा तो मैंने इस बात की पुनः जांच कारवाई कि क्या किसी तरह में अधिकारी वर्ग इसको उस परिभाषा के अन्दर ला सकते हैं या नहीं। उसके बारे में अभी उत्तर नहीं आया है परन्तु फिर भी इसमें कठिनाई होगी। दफ्ता १०९ का कोई सवाल इसमें नहीं उठता क्योंकि यह मामला सन् १९४२ के बहुत बाद का है और सन् १९४२ से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। इस वास्ते दिक्कत पड़ रही है।

### आगरे के थामसन अस्पताल में दांतों के इलाज का प्रबन्ध

४५०-श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या आगरे में थामसन अस्पताल में दांतों के इलाज का कोई इन्तजाम है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?



महानगर पुलिस कमिश्नर-नौबूत जिला मैजिस्ट्रेट के सम्मान में इस बात की पूरी तरह जांच की गई कि कितने लोगों को ऐसे इशियार गबने का हक है क्योंकि पहले से इशियार दिवे

गये थे उनमें नियमों की पूरी गारन्टी नहीं की गई थी। जांच करने के बाद जब यह पता चला कि बहुत से लोगों को हथियार रखने का हक नहीं है उन लोगों के लाइसेन्स कैंसिल कर दिये गये।

**श्री बदरीर अहमद अंसारी**—इन ७७ के अलावा २०० के करीब जो लाइसेन्स दिये गये थे किम आधार पर दिये गये ?

**माननीय पुलिस सचिव**—जो हथियार देने का कायदा है उसके आधार पर दिये गये हैं।

### फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय का विकास

\* ५६-**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—सरकार ने अब तक ऐसे कौन से उपाय किये हैं जिनमें फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय का विकास हो ?

**माननीय उद्योग सचिव**—फिरोजाबाद के कांच के व्यवसाय के विकास का मुख्य आधार बड़ा की भट्टियों का सुधार है। कांच विभाग ने दो आधुनिक ढंग की भट्टियां आयोजित की हैं तथा उन्हें शिकोहाबाद में जो कि फिरोजाबाद से केवल ११ मील दूर है बनवाया है। इन भट्टियों की विशिष्टता एक निश्चित सत्य है। फिरोजाबाद के बहुत से कारखाने वालों ने इनका निरीक्षण किया है तथा कांच के विशेषज्ञ ने स्वयं इनकी कार्य तथा निर्माण विधि समझाई है। अब यह उन पर निर्भर है कि वे इस सुविधा का उपयोग करें। यद्यपि कुछ कारखानों ने अपने तरीके से इन रेक्यूरेटिव भट्टियों का अनुकरण किया है परन्तु मावारणतया फिरोजाबाद उद्योग की इन मौलिक सुधारों की ओर रुचि कम है।

सबसे महत्वशाली केवल एक तरीका हो सकता है जिससे कि फिरोजाबाद के उद्योग में मौलिक परिवर्तन हो सकता है और वह है वहां पर एक गैस प्लान्ट का निर्माण करना। इस विषय में लगभग २ वर्ष पूर्व कांच विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा था जो कि अभी सरकार के विचारधीन है। फिरोजाबाद के उद्योग ने कांच विभाग की प्रयोगशाला में निर्माणित भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगीन तथा विभूषित कांच के विकास में विशेष रुचि दिखाई है। गत कुछ वर्षों में कांच विभाग के बहुत से नये नुस्खे फिरोजाबाद उद्योग को दिये हैं।

देखा जाय तो फिरोजाबाद में व्यापक आर्थिक विचारों को विकास सम्बन्धित विचारों से अधिक महत्व दिया जाता है। इस समय वहां का उद्योग अत्यधिक फैल गया है। वहां पर ८६ बड़े कारखाने हैं तथा अनगिनत घरेलू कारखाने हैं, जिनके लिए न तो पर्याप्त ईंधन ही है और न यातायात की सुविधाएं हैं। इस समय विद्यमान साधन किस प्रकार इस उद्योग को जीवित रख सकते हैं। यह ही समस्या अन्य समस्याओं से अधिक महत्व रखती है तथा कांच विभाग का ध्यान भी इसी ओर आकर्षित है।

**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि फिरोजाबाद को छोड़ कर शिकोहाबाद में डिमान्डेशन भट्टी लगाई गई है ?

**माननीय उद्योग सचिव**—इसकी तो मुझे सूचना नहीं है लेकिन वहां लगाने के लिए कोई कारण मुनासिब समझा गया होगा।

**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि जो भट्टी शिकोहाबाद में लगी है वह पहले फिरोजाबाद में लगाने की थी मगर कांच के विशेषज्ञ ने फिरोजाबाद के कारखानों के ऊपर जब करके वह शिकोहाबाद में लगा दी।

**माननीय उद्योग सचिव**—मैं माननीय सदस्य से दरखास्त करूंगा कि वह हमारे विशेषज्ञ से इस सम्बन्धमें बात करलें। सम्भवतः वह समझ जायेंगे और इस बात को मान लेंगे कि फिरोजाबाद के अन्धावा ऐसी डिमांट्रेशन भट्टी शिकोहाबाद ने ही मुनासिब है जिसको लगे देख कर फायदा उठा सके। इसके लिए सरकार यह मुनासिब समझती थी कि वह वहां से कुछ दूर ही लगाई जाय।

**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या गवर्नमेंट फिरोजाबाद में कांच की तरक्की के लिए वहां विज्ञानशाला और अनुसंधानशाला खोलने के लिए तैयार है ?

**माननीय उद्योग सचिव**—सरकार फिरोजाबाद के कांच के उद्योग में तरक्की देने के लिए हर प्रकार की तजवीबों पर गौर करने के लिये तैयार है। जहाँ तक भट्टी का सम्बन्ध है वह शिकोहाबाद में खोल दी गयी है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में हमारे विशेषज्ञ से बात करलें और उसके बाद उन्हें कोई विकल्प हो तो मुझसे बात कर लें।

**पुलिस सुपरिटेण्डेंट आजमगढ़ के मातहत (सरकारी) जीप कार का नीलाम**

**\*५७- श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पुलिस सुपरिटेण्डेंट आजमगढ़ के मातहत कोई जीप कार (सरकारी) हाल ही में नीलाम की गयी है ? यदि हां तो उने किसने कितने रुपये में नीलाम में लिया ?

**माननीय पुलिस सचिव**—सुपरिटेण्डेंट पुलिस आजमगढ़ के मातहत सन् १९४८ में या इस साल कोई सरकारी जीपकार नीलाम नहीं की गयी। किन्तु सितम्बर २, १९४८ को एक ट्रक जो काम के लायक नहीं रह गयी थी आजमगढ़ के ठाकुर श्री चन्द्रबली सिंह जी के हाथ जिनकी बोली सबसे अधिक थी ५९० रु० पर नीलाम की गयी।

**श्री गजाधर प्रसाद**—जो ट्रक नीलाम हुई है वह किसके नाम नीलाम हुई है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—वह तो बताया गया है। ठाकुर चन्द्रबली सिंह के नाम नीलाम हुई है।

**\*५८ श्री गजाधर प्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नीलाम करने की सूचना आम जनता को किस प्रकार दी गयी थी ?

**माननीय पुलिस सचिव**—इस ट्रकके नीलाम की सूचना बनारस, कानपुर, लखनऊ, दलाहाबाद और आजमगढ़ में मोटर व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को और कबाड़ियों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा दी गयी थी। लखनऊ में कैसरबाग थाना के नोटिस बोर्ड पर इस्तहार भी चिपका दिया गया था।

**\*५९ श्री गजाधर प्रसाद**—क्या यह सच है कि उस पुलिस सुपरिटेण्डेंट का कहीं दूसरे स्थान पर अभी हाल ही में तबादला हो गया है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—जी हां। श्री अवध नारायण सिंह जो उस समय आजमगढ़ में सुपरिटेण्डेंट पुलिस के पद पर काम कर रहे थे वह ट्रक उनकी मातहती में नीलाम की गयी थी। श्री अवध नारायण सिंह का तबादला १५ नवम्बर सन् १९४८ ई० को कमांडेंट पी० ए० सी० ब्रदेलियन मुगलसराय के पद पर हुआ।



**फिशरीज और एनिमल हस्वैण्डरी की नयी योजनायें**

\*६०-श्री मुहम्मद असरार अहमद—फिशरीज और एनिमल हस्वैण्डरी ने कौन कौन सी नयी योजनायें इस साल तैयार की हैं और उम्में जहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है ?

**माननीय कृषि सचिव**—आर्थिक वर्ष १९४८-४९ ई० में फिशरीज ऐण्ड एनिमल हस्वैण्डरी डिपार्टमेंट (मछली और पशुपालन विभागों) की जो नयी योजनायें मंजूर की गयीं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। इन योजनाओं को चयन में जो सफलता मिली है उसके बारे में मंथन दीये नयी की जाते हैं।

( देखिये नयी 'ख' भाग पृष्ठ १६८ पर )

श्री मुहम्मद असरार अहमद—जानवरों के रोग को रोकने के लिये अब तक कितने मोबाइल यूनिट्स कायम हुए हैं ?

**माननीय कृषि सचिव**—मोबाइल यूनिट तो गार्गलवन एक है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—बजट में कितने मोबाइल यूनिट्स का प्राविजन किया गया था ?

**माननीय कृषि सचिव**—जहाँ तक मुझे याद है, एक का।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—कितने ड्राई कैटिल अब तक ऐसे सेप्टर्स में जमा किये गये हैं ?

**माननीय कृषि सचिव**—इसके लिये नोटिस चाहिये। कृषीकेश के पास एक कन्सेप्ट्रेशन कैम्प कायम किया गया है जिसकी इन्चार्ज मीगवेन हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—पिछले साल के मुकाबले में इस साल जौनसर बावर के सेंटर पर कितने लाइव-स्टॉक हैं ?

**माननीय कृषि सचिव**—तादाद के मुतल्लिक तो नोटिस चाहिये।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ५६१ मंस, २६१ गाये और ८२ कैल की क्रोमत के अलवा जो वैटिक पचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन पर कितना खर्च हुआ है ?

**माननीय कृषि सचिव**—यह सवाल जो सुअब्जिज मम्बर साहब कर रहे हैं वे बिल्कुल नये सवाल हैं और उनका जवाब देने के लिये मुझे इत्तिहा इकठा करने की जरूरत है।

**गौर सरकारी किराये पर चलने वाली लारियाँ के किराये की शरह और सवारियों की संख्या**

\*६१-श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार ने गौर सरकारी किराये पर चलने वाली सवारी की लारियों के बारे में भी कोई किराये की शरह और तादाद सवारी निश्चित कर रखी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

**माननीय पुलिस सचिव**—जी हां, सरकार ने किराये की शरह और हर एक लारी के लिये सवारी की तादाद निश्चित कर दी है। किराये की शरह निश्चित करते समय लारी चलाने की लागत, ड्रट फ्रूट, लयम के खिस्सिले की सब बातों पर विचार किया जाता है।

**श्री बादशाह गुप्त**—स्वारियों की तादाद न्य करने के लिये क्या लारी की कैपेसिटी के अन्तर्वा और भी किमी बात का ख्याल किया जाता है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—तादाद जब शुरू में सुकरंग की जाती है तो लारी की कैपेसिटी ही देखा जाती है जिससे लारी अच्छी हालत में रहे।

**\*६२-श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार को पता है कि इस नियम का पालन आम तौर पर उसके उल्लंघन में ही होता है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—सरकार के पास कभी कभी इन नियमों के उल्लंघन और त्वास का स्थिर की हुई तादाद में अधिक मवारी ले जाने के प्रतिकूल शिकायतें आई हैं।

**\*६३-श्री बादशाह गुप्त**—उक्त अनियंत्रण को दूर करने के लिये सरकार ने प्रत्येक जिले में क्या प्रयत्न किया है ? क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अधिकार गैर-सरकारी लोगों को भी दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

**माननीय पुलिस सचिव**—उनके लिये ट्रामपोर्ट विभाग में एक इन्फोर्समेंट ब्रांच कायम किया गया है। प्रान्त में १६ स्क्वाड हैं और हर एक के आधीन ३ या ४ जिले हैं। इन स्क्वाड्स का यह कर्तव्य है कि वह देखें कि नियमों का पालन होता है और उनका उल्लंघन न होने दें। इनके अलावा आर० टी० ओज़० और ए० आर० टी० ओज़० और ट्रामपोर्ट कमिश्नर के प्रधान कार्यालय के अफसरों का भी यह कर्तव्य है कि गलत कामों को रोके। सरकार ने इस संबंध में गैर-सरकारी लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया है।

**श्री बादशाह गुप्त**—मैनपुरी किस स्क्वाड में है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—यह आगरा में होना चाहिये।

**श्री बादशाह गुप्त**—मैनपुरी के साथ साथ और कौन कौन से जिले इस स्क्वाड में हैं और उसका प्रधान दफ्तर कहाँ है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—यह अलग २ रीजन्स हैं और आगरा रीजन के अन्दर कई जिले हैं और उनका प्रधान दफ्तर आगरा में है।

**श्री बादशाह गुप्त**—स्क्वाड का जो प्रधान अफसर है उसको किस नाम से पुकारा जाता है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—यहां जो हेडक्वार्टर्स पर हैं वे डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट स्क्वाड कहलाते हैं और जो रीजन्स में हैं वे सर्किल इन्स्पेक्टर कहलाते हैं। अब जिलों में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के रैंक के आदमियों के चार्ज में रखे जाते हैं।

**श्री गणेश कुण्डू जैतली**—क्या सरकार इन लारियों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—माननीय सदस्य इस बात के कायल हैं कि ट्रामपोर्ट को नेशनलाइज किया जाय और चूकि गवर्नमेंट बहुत जल्द जल्द नये नये रूट्स ले रही है इस वास्ते शालिबन वह पसन्द नहीं करेंगे कि प्राइवेट लारियों को मौका दिया जाय और तीन महीनों के बाद ही उनसे लारिया वापस ले ली जाय या परमिट्स कैंसिल कर दी जाय।

**\*६४-श्री बादशाह गुप्त**—क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिससे उक्त लारियों के मालिकों के कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा सरकार द्वारा छपाई हुई इन्प्रीन्टेड रसीदों पर किगया वसूल किया जाया करे ?

माननीय पुलिस सचिव—जी नहीं, सरकार के विन्यासधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

\*६५-श्री बाबूशाह गुप्त—(क) दो से पांच तक और छे और छे से अधिक स्टेंज प्राइवेट और पब्लिक कैबिनमें के परमिट रखने वाले व्यक्तियों की संख्या पृथक-पृथक क्या है?

(ख) इनमें से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या पृथक-पृथक क्या है?

(ग) इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से अप्रैल १९४६ ई० के बाद परमिट पाने वालों की पृथक-पृथक संख्या क्या है?

माननीय पुलिस सचिव—(क, एक विवरण पत्र मेज़ पर रख दिया गया है।

(ख), (ग). ऐसी सूचना ट्रांसपोर्ट डफ़्तर में नहीं रखी गयी। अगर ना० मेम्बर चाहें तो यह सूचना परमिट पाने वालों से पूछ कर इकट्ठा की जा सकती है परन्तु इसमें बहुत समय लगेगा।

( देखिये नटथी 'ग' आगे पृष्ठ १७२ पर )

गाज़ीपुर में वर्तमान बिजली कम्पनी के ठेके की अवधि

\*६६-श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बनाने की कृपा करेगी कि गाज़ीपुर में मौजूदा बिजली कम्पनी का ठेका कब तक रहेगा?

श्री जवाफ़त हुसैन—जून १४, १९६४ तक।

\*६७-श्री विजयानन्द मिश्र—क्या यह सच है कि म्युनिसिपल बोर्ड गाज़ीपुर ने कई बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया कि यह ठेका बदल दिया जाय, परन्तु ठेका फिर भी नहीं बदला गया?

श्री जवाफ़त हुसैन—सरकार के पास इस आशय का एक प्रस्ताव जून १९४६ में आया था परन्तु कम्पनी के विरुद्ध इण्डियन एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४ (१) के आदेशानुसार कोई स्टाप लगायी नहीं गयी। इसलिये लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। इसकी सूचना कर्मभर द्वारा म्युनिसिपैलिटी को भेजी गई थी। बोर्ड ने मार्च १९४७ में फिर लिखा कि कम्पनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाय। विद्युति निरीक्षक के जांच करने पर यह पता चला कि वहां के पावर हाउस में कोई खराबी नहीं है। मगर वह मांग को पूरा नहीं कर सकता और इसके लिए दूसरा इन्जन लगाना दो साल हुए मंगाने को लिखा था मगर अभी वह आया नहीं है। आने पर २४ घंटे बिजली मिन्ने लगेगी।

\*६८-श्री विजयानन्द मिश्र—क्या यह सही है कि गाज़ीपुर में केवल एक सड़क पर ही बिजली की रोशनी है और दूसरी सड़कों पर, जैसे स्टेशन रोड इत्यादि, रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है?

श्री जवाफ़त हुसैन—जी नहीं। मियापुरा मिस्त्री बाजार से रेलवे स्टेशन और डाकघर से मोरा बाजार के अथवा लगभग सभी सड़कों पर रोशनी है। स्टेशन वाली सड़क पर बिजली अभी नहीं है, किन्तु म्युनिसिपैलिटी के चाहने पर कम्पनी वहां रोशनी का प्रबंध कर सकती है।

\*६९-श्री विजयानन्द मिश्र—क्या यह सच है कि वर्तमान बिजली कम्पनी ने केवल रोशनी के लिए बिजली दी है और फंक्श इत्यादि के लिए नहीं?

श्री जवाफ़त हुसैन—जी नहीं, बिजली रोशनी और फंक्श दोनों के लिये दी जाती है।

### मिर्जापुर में विद्युत सप्लाई के बारे में पूछताछ

\*७०-श्री विजयानन्द मिश्र— क्या सरकार यह बनाने की कृपा करेगी कि:—

- (क) मिर्जापुर में विद्युत सप्लाई का कार्य किम कम्पनी के द्वारा हो रहा है ?
- (ख) उक्त कम्पनी का ठेका कब प्रारम्भ हुआ है और कब तक चालू रहेगा ?
- (ग) क्या निर्जापुर म्युनिसिपैलिटी के साथ उक्त कम्पनी की कुछ बातें निश्चित हुई हैं ? अगर हैं, तो वे कौन शर्तें हैं ?
- (घ) वर्तमान बिजली रोगनी की क्या दर है ?
- (ङ) क्या रोगनी की दर पंप, रेडियो, स्टोव, औद्योगिक मोटर्स की दर में अन्तर है ? अगर हा, तो कितना और किन रूप में ?
- (च) क्या निर्जापुर की बिजली कम्पनी का दर प्रान्त की अन्य बिजली कम्पनियों की दर से ऊँचा है ? अगर हा, तो किम जिले की किम कम्पनी से कितना ? और नीचा है, तो किम कम्पनी से कितना ?

श्री लतारुत हुसैन—(क) नंसर्स मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ।

(ख) उक्त कम्पनी का ठेका अगस्त २४-१९२९ में प्रारम्भ हुआ और अगस्त २४-१९७९ तक चालू रहेगा ।

(ग) कम्पनी और म्युनिसिपल बोर्ड के बीच में मड़कों पर रोशनी के वास्ते बिजली देने के लिये एक इकरारनामा है जिसकी शर्तें सरकार को मादम नहीं हैं ।

(घ) वर्तमान दरें बिजली की रोशनी देने के लिए निम्नलिखित हैं जिन पर आज कठ १५ फी सदी वार कास्ट्स सरचार्ज भी लिया जाता है ।

१. रोशनी, पञ्जा, रेडियो और घर के कामों में इस्तेमाल होने वाली मोटरों ( जो कि आधा हार्स पावर से अधिक शक्ति की न होंगी ) का दर आठ आना फी यूनिट है पर बिज को १५ दिनों के अन्दर चुका देने में २५ प्रतिशत कमीशन दे दिया जाता है । इससे फी यूनिट बिजली की दर छे आना ही होती है ।

२. बाजार में दुकानों पर बिजली देने पर जिसकी माप मोटर द्वारा नहीं होती और एक ही ४० वाट का बल्ब जो कि दिन में ५ घण्टे से अधिक न जलया जाय तो दो रुपया प्रतिमास के हिसाब से प्रत्येक दुकान से लिया जाता है ।

(ङ) विभिन्न कार्य के लिए बिजली इस्तेमाल करने के लिए भिन्न-भिन्न दरों की सूची माननीय सदस्य की मेज़ पर रखी हुई है ।

(च) बिजली देने का दर हर कम्पनी में अलग अलग है । कुछ कम्पनियों का दर मिर्जापुर की बिजली के कम्पनी के दर से ऊँचा है और कुछ में नीचा । किन्तु यह कहा जा सकता है कि मिर्जापुर के बाहर वाले पावर हाउस वाली प्रान्त की अन्य कम्पनियों के दरों में और मिर्जापुर के दर में प्रायः समानता ही है । इसके अतिरिक्त प्रान्त भर की कम्पनियों के विभिन्न कार्य में इस्तेमाल होने के लिए बिजली देने के दरों की एक बृहद तालिका मेरी मेज़ पर रखी है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसे देख सकते हैं ।

( देखिये न थी 'घ' आगे पृष्ठ १७३ पर )

श्री विज्ञानन्द मिश्र—का सरकार को म्युनिस्लिटी बोर्ड और विजली कम्पनी के बीच में निर्माण किये गये इकायनमें श्री प्रिंस को प्राप्त करने में कोई कठिनाई हुई ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—कोई दिक्कत नहीं हुई

श्री विज्ञानन्द मिश्र—का सरकार निर्माण विजली कम्पनी के दर को घटाने के लिए प्रयत्न करेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—आजहलेक्यूक स्टेशन का घटना बहुत मुश्किल है। म्युनिस्लिटी और इलेक्ट्रिक का नया कायून जो है उसके मातहत जिस कदर नफ़ा किमी को नष्ट कर रहे हैं उसमें कटौत अगर वह न होना है तो उसकी इन्हें नष्ट करवा दी जा सकती है।

श्री विज्ञानन्द मिश्र—का सरकार यह बनाने की कुरा करेगी कि विजली मालिकों को अलग-अलग करने के लिए विद्युत शक्ति प्रवाह प्राप्त करने को कितनी दरगवाहों पर लागू कर देंगे कि कम्पनी अलग-अलग के पास रहेंगे और उन पर किस उमूर में स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री महाफन हुसैन—विजली कम्पनी के पास रोशनी के लिए ८४१ प्रार्थना पत्र १ जनवरी १९४९ में लेकर अब तक आये हैं और इनमें से २८५ प्रार्थनों को विजली दी जा चुकी है। इसी प्रकार १५ जून १९४९ में लेकर अब तक २८८ प्रार्थना पत्र औद्योगिक कार्यों के लिये आये हैं और इनमें से १७ प्रार्थनों को विजली दी जा चुकी है।

रोशनी के लिए प्रार्थना पत्रों के कम्पनी में प्राप्त होने की तारीख के अनुसार विजली कम्पनी के द्वारा दी जाती है। उद्योग धंधों के लिए कम्पनी प्रार्थना पत्रों को इकट्ठा करके सरकार की मंजूरी के लिए भेज देती है और सरकार उन उद्योग धंधों की आवश्यकता पर विचार करने के लिए अपनी मंजूरी देती है। सरकार द्वारा मंजूर किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों के अनुसार कम्पनी प्रार्थनों को विजली देती है।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने के कारण शेष तारांकित प्रश्न ९ जुलाई, सन् १९४९ के सत्रमें से रख दिये गये।)

सन् १९४६ के यूनाइटेड प्राविसेज मैटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही का वैध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज़ पर रखा जाना।

माननीय पुलिस सचिव—मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज मैटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (कार्यवाही का वैध करने के) अध्यादेश, मैटिनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (प्रोसी-यूटिव के लिए) अध्यादेश, की प्रतिलिपि (यहां छापी नहीं गई है) मेज़ पर रखता हूं।

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल

माननीय स्पीकर—अब हम माननीय प्रधान सचिव के इस प्रस्ताव पर कि संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय विचार करेंगे। कल श्री गैंगान जैन खां इस पर बोल रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रोहनचमरा खां—जनावर स्पीकर महोदय, खाने जमींदारी की यह बहम हमारे खे में एक बर्तनी अहमियत रखती है। आज वे चाहे जो इस मुद्दे के रहने वालों के साथ किये गये थे

उन्हे दूर करने के तरीकों पर चर्चा हो रही है। मच तो यह है कि इस वक्त कांग्रेस आर्गनाइजेशन अपने इन्निहान भी बड़ी में गुजर रही है। कांग्रेस ने क्लानलेस मोसाइटी (वर्गविहीन समाज), इनने के लिये दूर दूर बड़े किये और अभी इस साल ही जब कांग्रेस का सालाना इजलास हुआ तो उनमें उन्होंने क्लानलेस मोसाइटी (वर्गविहीन समाज) बनाने का वादा किया है। कांग्रेस गवर्नमेंट भी एक इन्निहान के दौर में गुजर रही है इसलिये कि उसने अगस्त सन् १९४६ में जमींदारी को खत्म करने के लिये एक तजवीज नाम की थी, और उसने तीन साल तक या तीन साल के करीब तक इस मसले में इल्तवा द्या, असोजाशन भी एक इन्निहान के दौर से गुजर रहा है इसलिये कि उसकी भी जिम्मेदारियां हैं कि वह ऐसे अहम मौके पर अपने सुझावों को पेश करे। देखना यह है कि इन जमींदारी क्यों मिटा रहे हैं और जिन तरह में इस बिल के जरिये से जमींदारी मिटाई जा रही है क्या वह अगराज और मकासिट पूरे होते हैं जिनके लिये आज जमींदारी को मिटाने की जरूरत पेश आई है या नहीं? जहां तक गोर किया गया है जमींदारी मिटाने के अगराज व मकासिट चार हैं। मच में पहली बात तो यह है कि जमींदारी मिटा देने से इस सूबे की पैदावार बढ़ जायगी, दूसरे यह कि जो अठम नमावात, इनइक्वलिटी (नाबगवरी) और एक्स्प्लोयटेशन, शोषण और खून चूमना है वह खत्म हो जायगा। तीसरे यह कि जो अनएकनामिक होलंडिंग यानी अनाथिक या छोटी छोटी खेती है वह खत्म हो जायेगी और उनकी जगह हम एकनामिक होलंडिंग यानी आर्थिक खेती कायम करेंगे। भविष्य में महयोगी खेती की जायगी।

चौथ यह कि जमींदारी अवालिशन के जरिये हम जमीन का फिर से बटवारा करेंगे। अगरचे जमीन के बटवारे के मसले को हमने इस फेहरिस्त में आखरी जगह पर बयान किया है लेकिन चूंकि कल मेरी तकरीर के आखरी हिस्से में जमीन के फिर से बटवारे की बात आ गयी थी इसलिए मैं पहले उसी पर कहूंगा। खसूमन इसलिए कि हमारे माननीय वज़ीर आजम साहब ने अपनी तकरीर के दौरान में मुआवजा और जमीन के फिर से बटवारे के सिलसिले में सोशलिस्ट पार्टी का खास तौर पर जिकर किया और जहां तक जमीन का फिर से बटवारे का सवाल है उसमें उन्होंने हमारी पार्टी का मज़ाक सा उड़ाया। यह मही है कि सोशलिस्ट पार्टी २० बीघा जमीन और एक गाय का नारा लगाती है और यह भी सही है कि सोशलिस्ट पार्टी यह कहती है कि जमीन का फिर से बटवारा किया जाय ताकि कोई खानदान, कोई कुटुम्ब हमारे सूबे का ऐसा न हो जिसके पास १२½ एकड़ या २० बीघा पक्का या ६० बीघा कच्चा न हो और ज्यादा से ज्यादा होलंडिंग जो जेत का रकबा हो वह सोशलिस्ट पार्टी ने ३० एकड़ माना है। हमारे वज़ीर आजम साहब ने फरमाया था कि जमीन कोई खबर नहीं है। सुमकिन है कि हमारे वज़ीर आजम साहब ने किसी खास लहजे में यह बात कही हो और ताना दिया कि सोशलिस्ट पार्टी २० बीघा और एक गाय बल्कि हाथी भी देगी। लेकिन मैं इस बात को कहने में शर्म महसूस नहीं करता कि सोशलिस्ट पार्टी की यह कोशिश है कि हमारे सूबे के हर आदमी के पास न सिर्फ २० बीघा जमीन और एक गाय हो बल्कि एक हाथी और एक घोड़ा और एक मोटर भी हो। बहर-हाल हमारी यह कोशिश जारी है और देखना यह है कि हम कहां तक इसमें कामयाब होते हैं। अब मैं जमीन के बटवारे पर आता हूं। कल हमारे वज़ीर आजम साहब ने फरमाया था कि अगर जमीन का फिर से बटवारा किया जाय तो एक खानदान के लिए साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा का



जब जमीन के बिल में बटवारे के सुझाविक जब कमेटी ने राय का इजहार किया तो उसके बाद उसने जमीन के बिलों का मसाला लेकर यह दिखाया है कि यह तो प्रैक्टिकल शेष नहीं अखिल्याय का मसाला में जमीन के बटवारे की जमीन के अज्ञातों के बटवारे के बिलों के लिए से से से और इन चीजों के लिये जहां तक हो सके इस बिल में प्रवर्जन है अगर कोई देश के लिये यह बात मान ली जाय कि हर आदमी को साढ़े बारह एकड़ नहीं मिल सकेंगे तो इनसे हुकूमत के सुझावों को कोई नजरबंदी नहीं हासिल होती है। अपने जमीन के अज्ञातों के बटवारे की रिपोर्ट में १० एकड़ को एकोनामिक होल्डिंग्स मानी है। अब हम बिल में एकोनामिक होल्डिंग्स की कोई शर्त नहीं दी है, लेकिन जब बटवारे के बिलों का बिल हम बिल में लाने हैं तो कहते हैं कि सवा छः एकड़ से कम आराज़ी का बटवारा नहीं हो सकता। इनसे अगर यह नीति निकल सकता है कि आप सवा छः एकड़ आराज़ी को एकोनामिक होल्डिंग्स मानते हैं तो भी आपके लिये जरूरी है कि आप फिर से बटवारा करें। अब यह कहते हैं कि हमारे मूल में नजरबंदी नहीं मिल सकेगी। अगर आपको देना चाहें तो ४१ लाख बजट का आज एकोनामिक होल्डिंग्स नहीं दे सकते हैं लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर आप ३० ही लाख बजट का जो आपने देना है मुनसिफ एकोनामिक होल्डिंग्स दे सकें तो भी देना जरूर कीजिये। क्योंकि इनसे अगर उन रामने की तरह बड़ा जो मुनामिव है और जिसका एक अग्लयकी पौगी इन्फेक्ट पड़ेगा, जिसके जरिये ने हमारे मूढ़ में बहुत बड़ा इन्फेक्ट होगा और बहुत बड़ी नशीली पैदा होगी। अगर जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता है तो उसने न तो जमींदारी खप करने का जो माग है वह पूरा हो सकता है और न इसने और कोई फायदा हो सकता है।

अब मैं दूसरे मसाले पर आता हूँ। लेकिन कब्र इसके कि मैं उन मसालों पर आऊँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि पूरा बिल पढ़ने के बाद और तमाम हालत को मद्देनजर रखते हुए मेरे ऊपर जो असर हुआ वह यह था कि:

‘थी खबर गर्म कि गालिव के उड़ेंगे पुजें, देखने हम भी गये थं पे तमाशा न हुआ।’

इस बिल को पढ़ने के बाद जो नीति निकलता है वह यह है कि हुकूमत को सबसे ज्यादा जो फिक्र है वह यह है कि जमींदार साहयान को, बड़े जमींदार साहयान का खुश करना है, मुआविजा ज्यादा देना है। और हम ज्यादा मुआविजा देने के लिये कहीं न कहीं से रुपया लाना है। यह एक सबसे बड़ा नुस्तेनजर था। इसी नुस्तेनजर से उन्होंने सारे बिल को तैयार किया और जिस तरीके से मुनसिफ हो सका उन्होंने सारा जमा करने की कोशिश की। चुनावों से पहले जमींदारी अनालिसिस करने की रिपोर्ट में मुनाफे का एक ग्रेडिंग स्केल रखा गया था। उसमें यह था कि बड़े जमींदार का मुनाफे का तीन गुना मुआविजा दिया जायगा। अब आठ गुना कर दिया गया है। और छोटे जमींदारों के लिये पहले पच्चीस गुना रखा गया था वह अब सिर्फ आठ गुना कर दिया गया है और रिहोमिजिटेशन ग्रांट के नाम से जो दिया गया है छोटे जमींदारों के लिये वह भी कम है। इससे नीति यह निकल कि आप [ (एक आवाज) उस पर भी मैं अर्ज करूंगा, आप धनराएं नहीं। ] जनाववाला, तरुणों का सिलसिला खराब करने की कोशिश हमारे लायक दोस्त कर रहे हैं। तीन गुना और दस गुना की बात नहीं है। पहले आपने बड़े जमींदारों के लिये आठ गुने से कम मुआविजा रखा था। लेकिन आज आपने उस फैसले को बदल



[ श्री गेहलजान ख ]

किया है। सभित्त की रिपोर्ट में पहले आपने २०० न० माछुजगी देने वाले को छोटा जमींदार माना था, लेकिन अब आप सब इतर २० माछुजगी देने वाले को छोटा जमींदार मानते हैं और उनके रिहैबीलिटेशन ग्रांट देने। रिहैबीलिटेशन ग्रांट ने आपने सोशलिस्ट पार्टी में लिया है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, उनके मुनसिफ में बात में अर्ज करूंगा बीच बीच में बोलने से आपको कोई फायदा नहीं हो सकता है। अब यह न समझे कि इसमें मैं डर जाऊंगा और तकरार न करूंगा, आपको भी मैक मिलेगा उस वक्त, मैं समझन कह देना हूँ कि, आपको अविचार होगा कि जिस कदम मुझे मुनसिफ चाहे मुनसिफ और मेरी पार्टी की नजबीजों में जिस कदम शामिल हों वगैरह, मैं निश्चय मुक्ति के साथ करूँगा। ज़रूर वही होता है जिसका मुकदमा कमजोर होता है। बहरहाल, जनबवाला, मैं अर्ज कर रहा था कि हम तरह से कम्पेन्सेशन के मामले में हुकूमत ने यह कोशिश की कि जिस तरह से मुमकिन हो रुपया हासिल किया जाए। यह बात हम वजह से की है कि प्रोविन्सियल हाई कमांड में जमींदारों का बहुत ज्यादा जोर है। इनके अलावा बड़े जमींदारों ने जो कुछ रजिस्ट्रेशन हम सूत्र में किया है उसका बहुत काफ़ी अलग हमारे हुकूमत के ऊपर पड़ा है। यह वा बजह है जिनकी चिन्ता पर हुकूमत ने अपने उस जैसा के बदल दिया जो उसने सभित्त की रिपोर्ट में पहले अख्तियार किया था।

हम इस हद तक गवर्नमेन्ट के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने रिहैबीलिटेशन ग्रांट के मामले को सोशलिस्ट पार्टी से लिया। यह जरूर है कि हमने जिस तरह से इस सवाल को पेश किया था उसकी शकल व मूरत बदल दी है लेकिन यह वही चीज़ है और यह निश्चय खुशों की बात है कि आपने आखिर रिहैबीलिटेशन ग्रांट के मामले को लिया तो सही। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जब सोशलिस्ट पार्टी ने रिहैबीलिटेशन ग्रांट की बात कही थी तो उस वक्त जो पूर्ण बात थी वह यह थी कि हम इस सूत्र के किसी जमींदार को प्रान्टों कम्पेन्सेशन देने को तैयार नहीं हैं लेकिन रिहैबीलिटेशन कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं, लेकिन इस बिल में वह चीज़ नहीं रखी गई है। और यह भी कहा था कि चूंकि इस सूत्र में जमींदारी मिटाने के लिये जिनकी जल्दी मुमकिन हो सके कोशिश करनी चाहिये इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने यह भी कहा था कि हम किसी शब्द को किसी भी हालत में एक लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार नहीं हैं। सोशलिस्ट पार्टी की पूर्ण बात जो थी उसको तो हुकूमत ने नहीं लिया लेकिन बहरहाल रिहैबीलिटेशन ग्रांट के नाम से एक चेन्टर कायम जरूर किया गया है और इस बात की कोशिश की है कि रिहैबीलिटेशन ग्रांट के नाम से मुआवजा देना चाहिये। जैसा कि मैंने अर्ज किया है।

इस रिहैबीलिटेशन ग्रांट के बारे में दो बड़े एतराज़ यह हैं कि जो लिमिट रखी गई है कि कौन छोटा जमींदार है और कौन बड़ा जमींदार है और कौन वह लोग हैं जिनको रिहैबीलिटेशन ग्रांट मिलना चाहिये और कौन वह लोग हैं जिनको यह न दिया जाये। इस बारे में मैं सोशलिस्ट पार्टी को तुरन्त से सख्त एतराज़ करता हूँ। आपने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में छोटे जमींदारों को यह तारीफ़ की थी कि जो २५० रुपये तक माछुजगी देते हैं वह सब छोटे जमींदार हैं। उनकी तादाद ९८ दशमलव कुछ थी यानी साढ़े अठानवे फीसदी बताई थी। अब आपने इस बिल के जरिये से सिर्फ ८०४ जमींदारों का छोड़ा है। आपने यह भी बताया है कि

जो ५००० रुपये में ज्यादा मालगुजारी देने हैं उनकी तादाद ८०४ है। अब आपने इस बिल के उद्देश्य में ८०४ आदमियों को छोड़ दिया जो प्रापण्टी कम्पेंमेंशन पावेंगे। बाक़ी सब आदमियों को रिट्रैब्यूटेशन ग्रंट देने हैं। मैं यहां पर यह गुजराना करूंगा कि जो २५० रुपये तक मालगुजारी देने हैं उनको रिट्रैब्यूटेशन ग्रंट मिलनी चाहिये बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिये।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस इस बिल में कुछ अजीब-अजीब बातें रखी गई हैं जो एक दूसरे को कांटेडिक्ट करती हैं और कुछ नामुनासिब बातें भी हैं। इस बिल में यह भी कहा गया है कि जिस कदर जमींदारी है वह एक नोटिफिकेशन के बाद महा मुद्दिन यानी हिज मैजेस्टी में वैस्ट करेगी। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हिज मैजेस्टी के वजाय यह होना कि जिस कदर जमींदारी है वह सब इंडियन यूनियन में वैस्ट करेगी तो बात ठीक थी। एक मंत्री ने आप यह कहने हैं कि हुक्मन बग़ानिया से हमारा बरायनान ताल्लुक है और हम मन्वेन रिपब्लिक हैं। ऐसी मूल में जमींदारी सब नोटिफिकेशन के बाद हिज मैजेस्टी में वैस्ट करेगी कोई नाने नहीं रखनी और इस बात का प्रोवीज़न होना चाहिए कि सारी आराज़ी सावरन इंडियन रिपब्लिक के नाम में वैस्ट करेगी। हां इसमें एक सवाल उठ सकता है वह यह कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट यह कहना है “हिज मैजेस्टी (मम्रट) देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं” और यह कहना है कि सबको एक ही रेट्स में आराज़ी के जान दो, वगैरह वगैरह। लेकिन यह कमज़ोरी है। क्योंकि “जहां इरादा है वहां रास्ता निकल भी आता है”। अब तो सब अख्तियारात हिंदुस्तान के आदमियों के हाथ में हैं। आज सूबे से लेकर सेंट्रल तक, सब जगह कांग्रेस की हुक्मत है। अगर कांग्रेस अपने “मैनीफेस्टो” का लिहाज़ करती है तो उसको इस पर अमल करने के लिये तैयार होना चाहिये। जब कांग्रेस अमल करने को तैयार हो जायगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो सकती है। आप कंस्टिट्यूटेंट असेम्बली में एक बिल लाइये जिसके जरिये से आप गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट को तब्दील कर दें। अगर आप ऐसा कर देंगे तो जो ज़रूरतें हैं वह सब पूरी हो जायंगी।

दूसरी चीज़ जो काबिले एतराज़ है वह यह है कि टफ़ा ५ और ६ के पढ़ने से यह ज़तीज़ा निकलता है कि ज़मींदारी को सूबे से मिटाने के लिये चले तो हैं लेकिन एक साथ सारे सूबे में नहीं मिटाना चाहते हैं। क्योंकि आप फरमाते हैं कि इस ऐक्ट का निफाज उन हिस्सों में और उन ज़िल्लों में होगा जहां हुक्मत मुनासिब समझेगी और जब कभी जहां के लिये हुक्मत नोटिफिकेशन जारी करेगी उस पर एप्लाइ होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह चीज़ गलत है। इसमें नेवरटिज़ होने का अन्देशा है। और जो मुल्क में डिस्कन्टेन्मेंट फैला हुआ है उसमें इज़ाफ़ा होने का अन्देशा है। इसलिये सारे सूबे में जमींदारी एक साथ मिटाइये न कि टुकड़े टुकड़े करके मिटाये।

तीसरी बात यह है कि यह कतई नामुनासिब है कि जो टिलर्स आफ़ दि स्वायल हैं उनको कोई सिक्क्योरिटी आफ़ टिन्योर नहीं दिया गया है। यह ज़रूर है कि आप भूमिधर को प्रोप्राइटर बना रहे हैं और आप उसे बेचने, हिबा करने और वसीयत करने का अख्तियार दे रहे हैं मगर जैसा कि मैं आगे अर्ज करूंगा, वह भी महफूज़ नहीं है। आप जिस तरह से मालगुजारी बसूल करना चाहते हैं उससे मैं समझता हू कि उसका भला नहीं है लेकिन मैं खास तौर से आदिवासी कास्तकारों के वास्ते अर्ज करूंगा कि उनके लिये जो प्राविज़न किया गया है वह काफ़ी नहीं है। आपको ऐसा कानून बनाना चाहिये कि बकाया लगान में भी बेदखली न हो सके।



दुन्दुनों ने अपने हाथ में ले लिए तो मुझ को बहुत लज्जा पैदा हो जायेगी। निहायत में अर्ज  
 उसका कि लेखिए प्रत्यक्ष का सम्मान करना चाहती समझती नहीं है कि आप उसको जमींदारी  
 एजेन्सिज विध में सम्मिलित कर दें और आप जब उन सौत न लगाने, एक और चीज नेहावन  
 हैरतअंगेज है और यह यह है कि अगर भूमिधर लोग अपनी आगजी को न जोंगे, दो साल तक  
 या तीन साल तक न जोंगे तो उनके जिम्मे कोई देनदारी नहीं है लेकिन जब आसानी का सवाल  
 आता है तो इस विध में यह लिखा गया है कि अगर वह दो साल तक न जोंगे, जानवरों की  
 परवरिश न करें तो वह अपने हक में महसूस हो सकता है। मैं इसको बहुत सख्त काबिनेट-  
 राज समझता हूँ क्योंकि यह बेइसामी पर मक्की है। यह सुनकर नहीं है कि आप इस विना पर  
 सिर्फ आसानी को उनके हुकूम में महसूस कर दें कि उन्होंने दो साल तक नहीं जोंगा। यह  
 उसकी चीज हो सकती है कि किसी गांव को यह हक न होगा कि वह आगजी ले ले और फिर  
 उसको न जोंगे लेकिन यह केवल आसामियों पर सख्त जाल सुनामिव नहीं है, भूमिधर पर भी  
 इसको लागू होना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी स्टेज पर इस मामले पर गौर करना चाहिए। एक  
 चीज हमारे सूत्र में चली आई है। अगर सैकड़ अम्बरन नर जाय और उनके हुकूम खत्म  
 हो जाएं तो गेमी सूत्र में यू०पी० एनेन्सी ओर दूसरे कदमों में यह कायदा पड़ा है कि जो उनके  
 शिकमी हों उनके भी हुकूम खत्म हो जाय।

मुझे अकमोस है कि इस विध में भी वही पुराना रिवाज रखा गया है। मैं समझता हूँ  
 कि इस मामले पर भी हुकूमत को सेलेक्ट कमेटी में निहायत मंजीदगी के साथ गौर फरमाना  
 चाहिये। एक और सुनिश्चन जो हमारे सूत्र में ८ अगस्त १९४६ के बाद से हो गई है वह यह कि  
 जब इस अनेन्सिज ने यह कानून पास कर दिया कि यहां पर जमींदारी खत्म कर दी जायगी तो  
 उसके बाद गवर्नर, गायब या दूसरे ऐसे सुकामान जो सुशगरा इन्तेमाल हो सकते हैं, जो गांव  
 भर के इन्तेमाल के लिये थे, जो किसी एक आदमी की आगजी नहीं थी, उसको भी जमींदार  
 साहबान ने लगान लेकर लेट कर दिया, लगान पर उठा दिया। ऐसे पट्टों को विद्वान मन्सूब हो  
 जाना चाहिये और वह आगजी जल्द से जल्द फिर उम्मी तरफ से विलेज कम्युनिटी या पंचायतों  
 के साथ दे देना चाहिये।

**श्री साजिद हुसैन**—ग्रो मोर फूड कम्पेन (अधिक उन्नत उपज; ओ आंदोलन) के सिल-  
 सिले में दी गई है।

**श्री रोशन जमा खां**—हमारे बंगाल में बैठे हुये दास्त साजिद हुसैन साहब जो ब्रिटिश  
 इण्डियन एसोसियेशन के मेम्बर भी हैं, फरमा रहे हैं कि ग्रो मोर फूड कम्पेन के सिलसिले में दी  
 गयी है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे लयक दोस्त को पैदावार बढ़ाने की बड़ी फिक्र है।  
 बहरहाल देखना यह है कि उनके दिल में इस सूत्र की पैदावार बढ़ाने का कितना खयाल है और  
 उनके जमींदारों की गरीबों के साथ कितनी हमदर्दी है।

एक और बात, जो उसकी तौर पर गलत है इस विध में रखी गई है वह यह है कि  
 असामियों का जो जमींदार से तयशुदा लगान है वही लगान उनको देना पड़ेगा। मेरे खयाल में  
 मुल्क जिस स्टेज से गुजर रहा है और दुनिया के जो हालत सबको दिग्बाई दे रहे हैं, उससे यह  
 सुनामिव नहीं है। यह साफ है कि जमींदार साहबान ने हकों का गलत इस्तेमाल किया और जो  
 माहदार तबका है उसने गरीबों से फायदा उठाया। रक्षा-रक्षा ऐसे दर (रेट) बने जो

‘ श्री मेजरलाल खन्ना ’

सरकार के इन ठोस, ठोस स्टैंडर्ड्स पर सरकिल गेट कहे जाते हैं उस रेट के बमूजिव जो नया नया इनके सामने आया है सरकार को कि मेलेकन कमेटी इस पर गौर फरमाये। वह स्टैंडर्ड मेलेकन को आनमाने को है, वह किसी तरह मुनासिब नहीं। क्योंकि हकीकत यह है कि नही लोगों में दिल आला ही लायल रही आनामी है और इनके हक का आरक्षों द्वारा हथकड़ा रक्ता चाहिये १९४९ ई० में जो नजदीक असेम्बली में पेश की गई थी उसमें मिला गया कि जिस आरक्षों द्वारा जो उनके हक दिखें और उनके हक किसी तरह लाने में मोहल्लिस्ट गेटों का गेट के बारे में कहना है कि एकानामिक रेट मिला चाहिये, और वह रेट ऐसा हो कि जो उनके खाने पीने में मुनाफा हो, बचत हो, उमी को गेट मिला जाय अभी तो नही केवल इतना है कि पहले जमींदारों के अधिकार लगान वसूल करने वाले और अब जमींदारों का अधिकार जायग। इसमें काश्तकारों को किसी इन्कियाव का लाना नहीं हो सकता। किहू ज मोहल्लिस्ट गेटों अब भी नहीं कहनी है कि जो लगान आसामियों के लिये, जो जो मालगुजारी भूमिधरों के लिये आर मुकम्मल कर रहे हैं वह ज्यादा है, उसको कम करिये। सारांश और दूसरे लोगों के लगानों को भी आरक्षों कम करना चाहिये, ताकि उनको यह महसूस हो सके कि आज जमींदारी खत्म हुई है और उन्हें वाकई तौर पर फायदा पहुंचा है।

मैं कहसूस करन हूं जैसा कि मैं अभी आगे अर्ज करूंगा कि इसमें सारी बुनियादी शक्ती बढ़ है कि कमिन्सिशन देने और कमिन्सिशन ज्यादा देने की बात ध्यान में रखी गई है उसी ने यह सब इकट्ठा करवा है, जमींदारी कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि छोटे खाने वाले किसानों के लगान में कमी कर दी जायगी लेकिन वह कमी भी मौजूदा बिल में नहीं रखी गई है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि वह सब चीज उस डमीनेटिंग आइडिया में आई कि कहीं में वह खयाल लाया जाय जिसमें मालगुजारी को खदा किया जा सके। इसलिये इस बुनियादी शक्ती के घटना पर और सब शर्तियां हुई हैं इस बिज में यह कहा गया है कि इस सूत्र में बंदोबस्त ४० साल के बाद होगा मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि यह चीज ज्यादा मुनासिब नहीं है। यह ठीक है कि आप बंदोबस्त गोजाना नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि २० साल की मुदत तो देनी चाहिये एक बहुत बड़ा मबाल यह है कि जब आप इनने बड़े कानून को इस सूत्र में लागू करेंगे कि जिसके ज़रिये में पुरानी ज़मींदारियां खत्म हो जायंगी, पुराने समाज की तरह नये दुर्ग का समाज आयेगा, ऐसी सूत्र में यह मुनासिब है कि इस बिल के नाफिज होने के बाद इस सूत्र में जल्द में जल्द बंदोबस्त करायें। और इसके बाद जो बंदोबस्त करायें उसको जो मुदत जो उसमें अगर दो-चार साल की कमी होगी तो कोई बात नहीं है।

यह बात भी समझ में नहीं आती है कि जब आप कहते हैं कि हर किसान अपनी अपनी आरक्षों का मालिक होगा, प्रोप्राइटर होगा। तो फिर मालगुजारी के लिये ज्वाइन्ट लाइवेलिटी होने के क्या मार्ग हैं। आज तक सूत्र में जो प्रथा चली आई है मालगुजारी वसूल करने की उस में हर हिस्सेदार की जिम्मेदारी ज्वाइन्ट और मेवन्ट रखी है। यह सरकार के हाथ में है कि वह किसी एक आदमी से वसूल कर ले या सबसे अलग अलग वसूल करे। यह चीज सरकार बरतानिया के जमाने में चली आ रही है लेकिन वह हमारे लिये उचीक नहीं हो सकती कि वह अब भी

कायम रहे। वह वन उम जमाने की थी। वह जमाना ही ऐसा था लेकिन आज के जमाने में हम लोग जो मैजिस्ट्रेट इन्डोस्ट्रिय को बनाने वाले हैं उसकी तानीक करें और वैसे ही करें यह सुनासिव नहीं है लेकिन अगर अगर वीने हुए जमाने की वीने हुई बात को अब भी कायम रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ नानुमानित बात है।

इस मालगुजारी के साथ एक निश्चयन ही नमकीनदेह और इतर चीज और आ गई है जा एक हद तक का (कानून, नद) कहा जा सकता है वह यह है कि भूमिधर से जो गेवेल्यू वसूल किया जायगा उसके अनुसार के नगेके ने कुर्की, गिरफ्तारी वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हुकूमत कांग्रेस ने १९३७ ई० में हुकूमत में आते ही बन्द कर दिया था उनके अजनामे जनी किया जा रहा है। यह चीज आपके लिये सुनासिव नहीं है। इसलिये जो नगेक मालगुजारी का अपने बनया है वह गलत है। उसके सिधसिधे में जो गिरफ्तारी अपने रखी है वह बन्द कर दीजिये। दूसर तरीके हैं जिनसे मालगुजारी वसूल की जा सकती है। इनारे कांग्रेसी दास्त जो इनारे पान बैठे हुए हैं लगना रहे हैं कि वसूलयावी डंडे के सहारे ही होनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अब अबन के सहारे रहे और कांग्रेसी कमेटीयों के सहारे रहे और उन पचायतों के सहारे रहे जिनका चुनन अपनी अपने किया है, तो फिर वे ट्रिक्कनें जो आपके सामने आती हैं नहीं आयेंगी। अब इस प्रीजनशन को लेकर क्यों चर्चे हैं कि सब लोग जानवर ही है और वे केवल डंडे की बात ही सुनेंगे। अब तो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह आतंक फैलाकर, डर फैला कर लोगों को नाथ ले सकें। लेकिन यह तरीका गलत है। ताल्लुकदार नाइवान और जमींदार साहबान ने यह तरीका अखिनवर किया था लेकिन इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। भविष्य इसका नतीजा आपको दिखायेगा। सवाल यह नहीं है कि आप मालगुजारी वसूल न करें। अब पैना पैस, कौड़ी कौड़ी वसूल करें। लेकिन किसी शाख को उसके लिये गिरफ्तार करना या उसकी फसल की कुर्की करना सुनासिव नहीं है। इसलिये इस पर आप सेलेक्ट कमेटी की स्टेज पर गौर करमयें। बहुत से तरीके हो सकते हैं और आप उनमें अपनी मालगुजारी वसूल कर सकते हैं।

एक और चीज जो निश्चयन ही सरप्राइजिंग है वह यह है कि यह लिखा गया है कि अगर कोई भूमिधर आराजी को मारगेज या रेहन का दे तो ऐसी सूरत में वह मारगेज इल्लीगल होगा, खिन्नक कानून होगा, नाजायज होगा लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि ऐसे मारगेज का ही इस विध के मुताबिक वैनामा मान लिया गया है और उसके जरिये सारे हुकूम मारगेजी को मिल जायेंगे। मैं यह कहूंगा कि इस तरह से आप कानून तोड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करेंगे लेकिन मेरा सुझाव यह है कि कानून तोड़ने वाला का फायदा नहीं पहुंचना चाहिये।

आप इकानामिक होलंडिंग के मसले को लोजिये। जैसा मैंने अर्ज किया है कि कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि १० एकरों को आराजी इकनामिक होलंडिंग होती है लेकिन इस बिल में कोई चीज साफ नहीं है। इसके लिये खासतौर पर कोशिश करना है कि हमारे सूबे की जो होलंडिंग हैं वह इकानामिक बन सकें। कोअपरेटिव फार्म का जो प्राविजन इस बिल में किया गया है उसमें जरूर इस बात की कोशिश की गयी है कि होलंडिंग जो अनइकनामिक हैं वह इकनामिक हो जायें लेकिन वह चीज कामी नहीं है। मेरी मंशा यह है कि इसके अलावा भी आपको सोचना है कि अनार्थिक खातों को किस तरह से आर्थिक खाता बनाया जा सकता है।

[ श्री मेहनतमाला ]

अब हम उनसे जो हम चाहते हैं किया जा सकता है वह यह है कि जमींदार साहबान को सारा जमीन जमा करके दे दी जाए। ऐसी विचारों को उनके साथ नहीं होना चाहिये।

जब हम जमीन माफ़ दे जमीनदारों को जिन कमेंसेशन के मिशमिन्ट में किया था और वह था कि वह जमीन को जमीनदारों के पास था उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी का मत था कि जमीन देवना यह है कि इकॉन्ट्रिब्यूटरी कमेंसेशन को जो नाने और पहना रहे वह सब ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ, इकॉन्ट्रिब्यूटरी कमेंसेशन जो दिया जा रहा है वह भी किसी तरह जमीन को दे दिया जा रहा है। हमें यह नहीं दिया जा रहा है कि हमको देना है। हमें यह है कि कमेंसेशन को वह सोशलिस्ट पार्टी ने जो कमेंसेशन तो इन तीनों पर मानी कि आगे जाकर जमीन में बदलाव होगा।

हम को समझने है कि हम जमींदारी को जल्द से जल्द इस सू-से मिटाना है। हम चाहते हैं कि जमीन का बदलाव कम से हो। जमीन के बदलने का मतलब इन इठ नहीं कर रहे हैं। उन लोग जमीन को जमीन का सबाल देना नहीं होता है, आपने जमींदार साहबान के साथ जमीन को देना, मैं इसके एक एक ओर एक हिस्से पर गैशनी डाल चुका हूँ। आपने उनमें हमें जो आश्चर्य है कि वह हिस्सा, जो और जमीन के जमिये में अपने हक़ को मुक्त कर सकते हैं, उनको फ्री गैट आऊट दूँगा है। दूसरी चीज यह है कि उन के जो जमिये में, अर्थात् जमिये है जो को मेन्सिशन में जमिये नहीं करिये की गई है। यह बड़ी बात है कि जमिये जमिये पर वह नतीज सुनकर हुआ कि हमारे सू-में एकनमिक होल्डिंग नहीं बन सकी, सरकार का हाथ माफ़न है और मैं कहूँ कि माफ़न है कि जब से जमींदारी मिटाने का सवाल एलेक्शन के बाद अवाम के सामने आया है उस वक्त से जमींदार साहबान ने बराबर यह कमेंसेशन की है कि जिनसे अउमिन्टों को जिन तरह मुमकिन हो वेदवर्क किया जा सके वेदवर्क करे ताकि जमीन वे जमीन आगे जाकर उनका असली खुदशाय में कर दें और वह उनकी जीत में हो जब और उन जमीन को जितने जल्द मुमकिन हो वह फार्म में तबदील कर सके, लेकिन यह बहुत सवाल यह है कि जो छोटे जमिये होते हैं उनसे मुनसिब मुनाफ़ा नहीं होता। उसी तरह बड़े जमिये से भी नफ़ा नहीं होता। इस मतलब पर भी हमें गौर करना है। आप जमींदार साहबान को मुनसिब नफ़ा उठाने का मौक़ा देगे या नानुनासिब। ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद किसानों के साथ बग़ावत जमादनी होती गयी है। जमादानी ने श्रीगठ या इल्लुशीगठ जिस तरह मुमकिन हुआ किसानों को वेदवर्क करने की कोशिश की है। आपको इस बारे में यह तय करना चाहिये कि जो आगजियाँ ऐसी थी जिनसे जमींदार साहबान ने चाकरी से किसानों का वेदवर्क किया है वह उन लोगों को वापस की जाय। दूसरे यह कि डिमिट कर देनी चाहिये। मैं इस वक्त एक बड़े नाज़ुक मतलब की तरफ़ हुकूमत की तरफ़ जो दिया हूँ कि एक मैकिन्सन डिमिट त्वाने की आराजी की जीत की नहीं सकती है। सोशलिस्ट पार्टी ने इस एक डिमिटेशन रक़ब एक होल्डिंग का वेदवर्क है। अपने कुछ नहीं बतलाया इनका बिना पर आज और इस वक्त यह हो रहा है कि किसानों को जिस तरह हो वेदवर्क किया जाय और लोगों को सही तौरपर फायदा नहीं पहुँच रहा है। आप एक आडिमेंस के जरिये से इस बात का हुकम दे दें कि कानूनी और गैरकानूनी वेदवर्क नहीं की जायगी। आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितनी भी हमदर्दी आप चाहें इस बिज के जरिये

मे अगला चाहते हैं वह नहीं होगा ! अपने इस बिल में उन लोगों को जो दूसरासर्त हैं उनको कम्पन्स हुक़ देने की कोशिश की है । इस बिल में अपने वह नहीं किया है कि फलों गरीबों में जो देना चाहते हैं उन्हें उनको जमीन बाँट दी जाय जैसा अपने यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में किया था, अतिरिक्त आप जमींदारी अधिनियम इस दृष्टि में क्यों नहीं ले रहे हैं कि किसी ज़मीन की देनदारी कानूनी या गैरकानूनी आज की गरीबों में नहीं हो सकती ! अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप दि न्याय को उन्हे हुक़ में मद्धूम कर रहे हैं । इस तरह से निश्चयन अपने ज़मींदार माह्वान के साथ की है यह नानुमतिव है मेन्टेक्ट कमेटी के स्टेज में आपको उस पर रोक करना है और ग़लत कायम करना है ।

इसके हुक्म ने वह ज़ेअरमन्स यानी जमींदार माह्वान के साथ इतनी ज्यादा रियायत इन्फिरे की है कि उनको अन्तेका है कि उन्हे ग़रीबों की हानि दी जाय न हानि हो सके और उन्हे वह बड़े जमींदारों और बड़े किसानों का सहारा लेकर जिन्दा रहना चाहती है । मैं अर्ज करता हूँ कि आपको इस मामले पर दोबारा गौर करना है और इस नियम में गौर करना है कि जो बुराईयाँ हैं वे दूर हो जायें । अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अपने गरीबों भी खुश रहेंगे और अमीर भी खुश रहेंगे । इन सब की खुशी चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ इन वह नहीं देख सकते कि किसी को गरीबों का एकम्पन्सआयट करके अमीर बनने का मौका मिले । और इस तरह से अमीर बनकर अमीरलोग ग़रीबों का ज्यादा एकम्पन्सआयट कर सकें । निहाय ऐसी मूरत में आपको इस बारे में कोशिश करनी है कि जो रियायतें आप ने जमींदार माह्वान को दी हैं उससे जितनी ज्यादा कमी आप मेन्टेक्ट कमेटी के स्टेज पर कर सकें वह जरूर करें ।

(इस समय १ घंटा का १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ घंटा का २ मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई )

**श्री रोशन जमां खां**—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस गिल से यह मान्य होता है कि यह बिल नइज़ खपया पैदा करने का जरिया बनाया गया है, मनी मेकिंग डिवायम है, जिसके जरिये से रुपया जमा किया जायगा । आप ख्याल फरमाइये कि सीरदार से यह कहा जाता है कि तुमको हम भूमिधर का हक़ दे देंगे अगर तुम १० साल का लगान पेशगी अदा करोगे और उसके लिये दो लालच दिये जाते हैं । एक लालच यह है कि उनको इंतकाल करने का हक़ दे दिया जायगा । दूसरा यह कि वह अपना लगान आधा अदा करेंगे । अब आप जरा गौर फरमाइये कि एक तरफ तो आप उनको लालच देते हैं कि तुमको हम इससे बेहतर हक़ देंगे । यह हक़ तो, हकीकतन यह है कि, आज ही उनको देना चाहिये । अगर आप भूमिधर के हक़ को सबसे बड़ा हक़ मानते हैं तो जितने सीरदार हैं उनको आप आज ही भूमिधर का हक़ जरूर दे दें । अगर यह मान भी लिया जाय कि उनके सामने आप टुकड़ा फेंक रहे हैं तो भी यह आपके लिये नुनामिव नहीं है कि आप उनसे नितर लगान बसूल करते जायें । आप १० साल का लगान आज ही ले लेते हैं और फिर २० साल तक आधा लगान लेंगे तो आपने उनके साथ क्या रियायत की ? यह बेइन्साफी है, अन्याय है । क्योंकि अगर वह शुरू में ही मामूली तौर पर लगान अदा करने तो उनी शर्ह से उनको लगान देना पड़ता । और आप जो यह १० साल का लगान लेंगे तो कब से इसका साल शुरू होगा वह ठसवें साल शुरू होगा, या ११ वें साल शुरू होगा या आज ही शुरू होगा । लेकिन जहाँ तक मैं गवर्नमेंट का मन्दा समझता हूँ वह यही है कि जो १० साल का लगान आज ही अदा कर देंगे



[ श्री गेम्बलरमान या ]

उनको २० साल तक आजाद करान देना होगा, मैं समझता हूँ कि अगर हम तरह से उनको आजाद करेंगे तो अगर आप उनका साथ करेंगे तो उनको नहीं कर रहे हैं और यह तरीका सुनसिध नहीं है। इस तरह हमारे पास मालबुका है और उनको भी मालबुका देने है। उनसे कहा जाता है कि अगर तुम १० साल आजाद दे देंगे तो तुमको सीरदार बना दिया जायगा और उसमें एक अजीब सजाक है। इससे वह लोग से गवर्नमेंट के साथ सज्जद करने को कोहिन की गई है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं यह तरीका को अपनाना किया गया है सुनसिध नहीं है। फिर यह भी समझना पड़ेगा कि अगर हमें उसका नाम मंडल विधान मिल गया है, भूमि व्यवस्था दिल का नाम दिया गया है, लेकिन उन्हें भी तरीका को अपनाना है, और जिसने किसान का नायदा हो उसमें अगर-उस नहीं किया गया है जिसने वह समझना है कि हकीकत और आरजी के सुनसिध कोई ऐसी हकीकत करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिये से हम सूबे के रहने वालों का नायदा को भके निम्नलिखित के लिए जो हम फिर से कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए भी कमजोरी नहीं गया रहा है कि वह हर सूबे में कोआपरेटिव फार्मिंग करें, अगर यह समझते हैं कि जो एकात्मिक इन्फिडल है वह एक सूबे में अपना कोआपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि अगर एकात्मिक इन्फिडल वाले की मदद हो दिखाई हो जय तो एक दिखाई को मजबूर किया जा सकता है, तो जिस तरीके से यह काम किया जा रहा है उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे सूबे में नहीं हो सकेगी। फिर कहा जाता है कि हमारे सूबे की पैदावार कम हो गयी है। हकीकत है कि पैदावार कम हो गयी है, उसके अंदर एक तरीका तो वैसा कि नोडफिल्ट पार्टी ने बताया था और बताया है और अगर हुकूमत उस चीज को अमल दरमद नही करनी है तो कुछ पार्टी उस काम का अपने जिम्मे ले लेने को तैयार है वह एक कंटेनर यन्त्र की तजवीज थी। अब जरूरत यह है कि अगर ऐसे तरीकों को अपनाना करें जिससे पैदावार बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका तरीका अच्छा नहीं होगा, मेट्रोल गवर्नमेंट ने अभी ऐलान कर दिया है कि सन् १९५१ ई० के बाद हम बाहर ने गन्ना नहीं मंगायेंगे और अगर दुनिया की तियासियात को देखा जाय तो यह तरीका तो पर मुद्रा होना है कि साल दो साल या उसमें भी दो एक साल ज्यादा के असे में रॉबिन्सन हम और गेम्ब्रे अमेरिकन ब्रदर मे जंग छिड़ जायगी और हमारा मुल्क उसमें न्यूट्रल रहे या किसी ब्रदर का साथ दे उसे गन्ने की जरूरत पड़ेगी। अगर पैदावार की कमी रही तो हमारा मुल्क ब्रदर हो जायगा इसलिए हमको अपनी पैदावार जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिये। गवर्नमेंट का यह ऐलान है कि बाहर से गन्ना नहीं आयेगा और हमारा मुल्क इनना मेल्ल सफी-इयें हो जायगा कि हम अपने मुल्क की सारी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसके लिये आपको इस दिल में हम बात का इंतजाम करना चाहिये था कि माइर्नाइड इन्फिडेशन यानी काश्तकारी के जो मजदूर तरीके हैं उनको अख्तियार किया जाय। मगर उसके बारे में आपने कोई चीज हम दिल में नहीं रखी। फिर यही मूलतः जो जोन के बारे में है वही हार्डिक्लव यानी बरगान के बारे में है। इस दिल में बरगान के बारे में और जानवरों के बारे में कुछ नहीं किया गया है और सबसे बड़ी चोज यह है कि हम सूबे में बिना सिंचाई के बढ़े हुए, बिना पानी को बढ़ाये हुए हमारी पैदावार नही बढ़ सकती। आज हमको सबसे बड़ा रोना यह है कि हमारी पैदावार बाहिर के ऊपर सुनसिध है। अगर बाहिर टिकाने से और बक से हो गयी, ज्यादा न हुई और न कम हुई, तो

जमीन खाली होती है, वरना अगर ब्रिटिश ने साथ नहीं दिया तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। हमने इनके लिये यह जमीन है कि हम यहां आवासीयों के जो जगहों हैं उनको बढ़ाने का चेष्टा करें। हमारी हुकूमत ने इस तरह कदम बढ़ाया और यह किया कि तालाब खुदवाने की एक स्कीम जारी की जिसमें जहां तक मेरी जानकारी है कलम के हल से कागज पर बहुत से कुएँ और तालाब खोदें गये लेकिन जमीन पर बहुत कम खोदें गये और उसमें सरकार का बहुत खर्च व्यर्थ हो गया।

मैं यह चाहता हूँ कि मित्राई का भी कुछ न कुछ इन्तजाम इस बिज में जरूर होना चाहिये। जहाँ तक मुझे याद है गाल्लियन नाननोय वजीर अजम साहब ने अपनी ७ अक्टूबर वाली प्रेस कान्फ्रेंस में यह बात ही में जो प्रेस कान्फ्रेंस हुई है उसमें कहा था कि हम इस सूत्र में क्यामलेस सम्मति देना चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह इस बिज के जरिये से उसे कैसे बन सकते हैं। आपने खुद चार क्लासेज रखे हैं, जिनमें में दो को आपने बड़ा और दो को छोटा माना है। भूमिधर को सींगदार से बड़ा हक दिया है, सींगदार को असामी से बड़ा हक दिया है, और असामी को अधिवासी से बड़ा हक दिया है। ऐसी सूत्र में जो चार क्यामलेज बने हैं, वे एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसी सूत्र में स्ट्रिंग्लि आफ एग्जिस्टेंस हमारे सूत्र में शुरू हो सकती है। इस बिज के जरिये से आप एक क्लास स्ट्रिंग्लि पैदा कर रहे हैं जो किसी तरह सुनामित्र नहीं है।

अब मैं चन्द्र अम्फाज़ में कम्पेन्सेशन के बारे में सोशलिस्ट पार्टी का नुक्तेनजर साफ तौर से बयान कर दना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी कम्पेन्सेशन के उसूल को कभी मानने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन ग्रांट का सवाल है वह तैयार है। लेकिन इसके लिए सोशलिस्ट पार्टी यह चाहती है कि २५० रु० तक मालगुजारी देने वाले जमींदार को पुनर्वास अनुदान और ज्यादा दिया जाय और आप जो बड़े बड़े जमींदारों को कम्पेन्सेशन दे रहे हैं उसको खत्म कर दें। जब तक आप यह नहीं करेंगे नरे ग्व्यान्ट में, जो सही मकसद इस जमींदारी अवा-  
न्डिशन बिल का है वह पूरा नहीं हो सकता। जनादवाय, मेरे लायक दोस्त, कांग्रेस वेंचेज से करना रहे हैं कि आप कितना देना चाहते हैं। अगर आप अव्वारात देखते हों, सोशलिस्ट पार्टी के बक्से में जाते हों तो आप निहायत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी ने यह कहा था कि हम एक शख्स को एक लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं और यह उस मूलन ने जब कि अगली जमींदारी अव्वान्डिशन कमेटी ने दस लाख सुआविजा देना तजवीज किया था। इसके साथ साथ यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि इस सूबे भर में सब लोगों को भिन्नाकर पचास करोड़ में ज्यादा न दिया जाय। इस तरह सोशलिस्ट पार्टी ने पचास करोड़ और एक लाख का तरीका बताया था, जिसके लिये गवर्नमेंट एक प्लानिंग के साथ आये, एक नक्शा बनाये जिसके जरिये से इंडस्ट्री या दूसरे तरीकों से रुपया वसूल हो। अगर ऐसा न हो सके तो कम्पेन्सेशन टैक्स लगाया जाय जो मालगुजारी के आधे से ज्यादा न हो। सोशलिस्ट पार्टी इन चीजों का बतला चुकी है। जहाँ तक कम्पेन्सेशन के उसूल का सवाल है सोशलिस्ट पार्टी विल्कुल मानने को तैयार नहीं है और रिहेबिलिटेशन ग्रांट उस सूत में मानने को तैयार है कि २५० रु० तक के मालगुजारी देने वाले जमींदार को रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी जाय और बकिया को कुछ न दिया जाय।

[ श्री मेहनतमाला ]

अगर अगर नेशनलिस्ट कांग्रेस को यह चाने है कि मैं नकरीर खत्म कर दूँ तो यकीन रखिये कि मैंने नकरीर तोड़ डाले। मैं जानता हूँ कि बहुत से नेशनलिस्ट मेम्बरान नकरीर करने के बजाय-बजा है और हम सब से उनके हुक्म को आप तुझमान पहुँचा रहे हैं।

जनाब-साहब, वहाँ तक मेन्सलिस्ट पार्टी के मेम्बरों का मतलब है मैंने उसके मुताबिक नकरीर करने का आप कर दिया है और अगर मेन्सलिस्ट कांग्रेस के बाद यह बिल इस हाउस में आयेगा और कुछ सैंडर्स मिलेंगे तो मैं इस बिल पर क्लोज वाइज, सेटर वाइज, अपनी और अपनी पार्टी की तरफ का बड़ा बुरा करूँगा। लेकिन अगर इसके कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूँ तो कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों से इस बिल के लिए और बिल के नाम पर अर्ज करत हूँ जिसका उत्तर में कांग्रेस कांग्रेस से जान लिया है। जो कुछ नकरीर मेन्सलिस्ट पार्टी की तरफ से की गई है उन नकरीरों से आप सँभलिये। हम उम्मीद नहीं करते कि आप हमारी तरफ से इस बिल के लिए अगर अगर अपनी तकरीर को सामने रखेंगे तो बहुत सौ चीजें ऐसी हैं जिनसे न हम और आप इन्फार्म कर सकते हैं अपने जिस इन्फार्म को लाने का वाक्य है उसको बिना न हम उम्मीद है कि आप मेन्सलिस्ट के साथ सँभलिये। जिस नाम जमींदारी अवामीशन कांग्रेस को रिपोर्ट में और मौजूदा बिल में मेन्सलिस्ट पार्टी के मुताबिक से जमीं देना कांग्रेस के लिए है उसमें तरह से जमीं से ऐसी जमीं हो सकती है जिसकी बिना पर अगर इन नकरीरों पर सँभलिये जायेगा है कि हमारी इस हाउस में ताबाद कुछ नीन है और हम मेन्सलिस्ट तरफ से किसी तरह का वाक्य में जीन नहीं सकते हैं लेकिन एक चीज है जिससे आपसे वाक्य लाना चाहिये। यह यह है कि अगर हमारे मुताबिक या तजवीज ठीक हैं तो हम आप के हाथ से एक बहुत बड़ी आवाज है, वह आवाज और हमको दोनों को देख सकते हैं। अगर हमारे हाथ से वह है और साथ ही साथ हमारा भी इन्तहाल हो रहा है। अगर जमीं नामक नकरीर पर हमारी नकरीरों को ठुकरा दिया तो आपको तुझमान होगा हमने कुछ नहीं होगा। हम अपोलेशन में अर्ज करते हैं कि वह भी हम सँभलिये जमीन के मेम्बर हैं। वह हम सँभलिये के रहने वाले के खडिन हैं। इसलिये वह हम नकरीरों पर मेन्सलिस्ट से सँभलिये और जिसको मुताबिक समझे उनका ले। हम जमींदार पार्टी से भी हम आप के नाम पर अपील करते हैं कि हुक्मने कानून ने जमींदारी सौंपते उस इन जमीं को ठुकरा बनाया था और मैं यह चाहता हूँ कि वह अमानत में खयालत नहीं करें और अपील में तरफ नहीं करेगा। जो कुछ उनसे उम्मीद की गई थी उसको वह पूरा करें और बरीडो के लिये, लखाने के लिये, भूखों नंगों के लिये आज वह अपनी तरफ से जरूर थोड़ी सी कुर्बानी करेगा, क्योंकि यह है कि जमींदार मेन्सलिस्ट को आज भिन्न एक हिस्सा देकर उस चीज का जिसे से महकम किया जा रहा है जिससे उसको लगान मिलता था। ऐसी मूरत में सँभलिये में अगर हुक्मने चाहती तो इस तरह का इंतजाम कम्प्लेसरी कौर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट बनाकर दूर कर सकती थी लेकिन हुक्मने जमींदारी अवामीशन ऐक्ट का नाम इसको दिया है। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि जमींदार पार्टी कम्प्लेसरी पर ज्यादा जोर न दे और भूखों नंगों के नाम पर उस अमानत को पूरा करे जो उनको हुक्मने कानून की तरफ से सुपुर्द की गई थी।

इतना कहने के बाद मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर हम लोग सम्मेलन में पूरे न उतरे, अंग्रेज पूर्ण न उतरी और हाउस के मेम्बरान पूरे न उतरे तो वह शायद होगा कि (The writing on the wall cannot be obliterated) यानी यह संकेत न मिटती हुई चीज है जो कभी मिट नहीं सकती है। देश में ऐसे एलीमेंट्स अब भी मौजूद हैं जो भूखे लोगों को लेकर इस मुकाम को खाने में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बात को भी ध्यान देना चाहिये कि आप इस मुकाम में हाकिम की हैसियत से नहीं हैं बल्कि जज की हैसियत से हैं। अगर आपने उस सम्मेलन में गुरेज किया तो खूब की जनता आपको इस सम्मेलन में सहभागी कर देगी।

० श्री कृष्ण सिंह— श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समिति का हार्दिक स्वागत करने के लिए आ रहा हूँ। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस समिति को देश करते समय यह भी बयान दिया कि गवर्नमेन्ट स्वयं के बाद यह समिति इस देश में आर्थिक स्वराज्य भी कायम करने जा रही है। बाल्जिक स्वराज्य हम कानून से ही इस देश में हो सकेगा कि जिसका समीप आज भारत के सामने है। हम समिति की वड़ी अहमियत इसलिए है कि यह कानून जो इन समिति की विना न बनना जा रहा है इन देश के ज्यादा से ज्यादा आदमियों पर लागू होने वाला है। १. जमीन २० लाख किसानों और १७ लाख बड़े जमींदारों को अपनी जमीन पर स्वतन्त्रता करते हैं इन कानून में फायदा उठाने जा रहे हैं। इनके अलावा ४० लाख बड़े मजदूर जो पेनी से मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी इन कानून से लाभ होने जा रहा है। अल्पवत्ता २ लाख के अल्पवत्ता से लोग भी इन कानून में कुछ नुकसान पहुंचेगा लेकिन इस तरह देश ऐसी जगह पहुंच चुका है कि अगर जमींदारी के तरीके का कोई खानिरेखाह हल नहीं निकाला जाता है तो देश का नक्का रुक जाएगा। मैं इन सिचुमिन्टों में जो मौजूदा स्थिति जमींदारी की है उस का जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह ध्यान दें तो यह नाट्यम होगा कि इस देश में बहुततर लेने कास्तकार हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं है कि जिस को जोत कर वह अपनी खर कर सकें। जमींदारों में भी ऐसे जमींदारों की तादाद ज्यादा है। कुल जमींदार जो इस सूत्र में आते हैं उनकी तादाद २० लाख है जिनमें से १७ लाख जमींदार ऐसे हैं जिनकी मालगुजारी कुछ २५ रुपये साबना है। २५ रुपये में ५० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों की तादाद डेढ़ लाख के करीब है और वह जमींदार जिनकी मालगुजारी दस सौ रुपये से ज्यादा है महज २०,००० हैं। वह बड़े जमींदार जिनकी मालगुजारी ५,००० रुपये से ज्यादा है महज ८४० हैं। अगर आप जमीन की तकमीन को देखेंगे तो मात्सम होगा कि वह ९८.२१ फी सदी जमींदार जिनकी मालगुजारी २५० रुपये से कम है उनके पास महज ४२ फी सदी जमीन है। वह १.४१ फी सदी जमींदार ४२ फी सदी जमीन के मालिक हैं और वह ८०० जमींदार जिनकी मालगुजारी ५,००० रुपये से ज्यादा है वह २७ फी सदी मालगुजारी अदा करते हैं, यही नहीं दूसरे मानी में वह लोग एक चौथाई हिस्से पर काबिज हैं और इससे भी कास्तकारों की दशा खराब है। वह कास्तकार जिनके पास एक एकड़ जमीन से कम हैं कुल तादाद का ३४ फीसदी है।

— माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[ श्री सुब्रह्मण्यम् ]

अगर १० एकड़ जमीन को एकनामिक होल्डिंग मानें तो फिर १५ फी सदी के करीब कृषकानों में मिलेगी जिनके पास अनाकनामिक होल्डिंग हैं। ऐसी दशा में कोई ताज्जुब नहीं कि इस देश में अन्न की पैदावार घट जाये और यहां अन्न की कमी की वजह से लोग भूखे मरने लगे। मैं इस कमेटी का, जिसने यह रिपोर्ट लिखी है, आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं जिनसे हम सारी समस्याएँ जिनमें पब्लिक में फैल गयी थीं दूर हो जाना चाहिये। मसलान एक चर्चा होगी कि यह है कि किसान के पास तो आज इतने नोट हैं कि वह छप्पर बांध सकता है। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि ५० तीसरी गेहूँ पैदा करने वाले लोग इतना गेहूँ पैदा करने हैं कि उनके पास देने को कुछ नहीं रहता। इसके अलावा २३ फी सदी लोग देने हैं जो अपना सब गेहूँ देव कर अगली मासगुजारी अदा करते हैं और महज २२ फी सदी देने लगे हैं जिनके पास कुछ अनाज है जिसको वह बेच सकें। इस किताब में यह भी चर्चा है कि लोनी कल्ले बाला में लोनी करने के जो मजदूर हैं उनके दाम लगाये जायें तो यह मान्य होना कि बहुत सारी समस्याएँ पर चर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है। एक मिस्त्र साहब ने कानून के एक भाग का सर्वे किया और उनकी रिपोर्ट है कि ज्वार पर तो ४२ रु.० फी एकड़ मुनाफा है, लेकिन गेहूँ पर फी एकड़ मुनाफा ७, ८ रु. के करीब है और चने पर यह मुनाफा ८ रुपये की एकड़ है। तो यह हाथ हमारी ग्लोबी की है और जब तक कोई खातिरखाह सरकार नहीं अस्तित्व में आता इस देश की खूराक का मसला हल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के लक्ष्य के दृष्टि से मैं आभारी हूँ। उन्होंने इस बात का जिक्र और किया था वह यह कि ५० एकड़ में ज्यादा जमीन जिनके पास हो जायगी उनकी पैदावार घटती चली जायेगी। तो इन कारणों से यह जरूरी है कि जमींदारी के कानून में कोई न कोई चीज लाएं जो एक बड़ी मजदूरी को जिसके बिना कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जमात मुद्दों से कोशिश करती चली आई है अगर वह यह था कि जमीन जमीन जोतनेवालों के पास सहज कर दी जाये। मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी मजदूरी है जो इस ऐक्ट से लेने जा रही है। कल श्री जगन्नाथ बख्श सिंह साहब जब इस बिजनेस को ले रहे थे तो उन्होंने इस बात का मजाहिरा करने की कोशिश की कि यह बिजनेस अनाज जमींदारों को जमा करने का बिल नहीं है बल्कि जमींदार नाम के बजाय भूमिधर नाम के दुर्गमों को इस देश को इस बिजनेस की सह से लड़ा कर दिया जायगा। यह कहने की मैं जुरत करूँ कि अगर जमींदारों को जमीन मालिक कहा जाय तो भूमिधर को आप खड़ का सांप कह सकते हैं। जहाँ बिलों और जो कुछ जमींदारी सिस्टम में थे वह सब भूमिधर से निकाल दिये गये हैं मसलान जमींदारों को यह दूना था कि वह अपनी जमीन औरों को जोतने को दे सकता था। यह एक भूमिधर से लेकर इस बिजनेस को चला कर दिया गया है। दूसरी दिक्कत जो जमींदारी प्रथा की वजह से थी वह यह कि कानूनकारों को ही नहीं बल्कि तमाम रियायतों को बेगार करनी पड़ती थी, ऐसी सब चीजों को भूमिधर को न देकर गाँव पंचायत को दे दिया गया है। राजा साहब का यह ख्याल था कि अच्छा होगा कि कानून इस तरह से बनता कि अगर कोई कानूनकार अपने लगान का १० गुना जमींदारों को अदा कर दे तो वह उसका भूमिधर हो जायेगा। मगर राजा साहब ने यह नहीं समझा कि अगर यह कानून बन जाता तो उन कानूनकारों का क्या होता जो अपने लगान का १ गुना जमा न कर पाते।

राजा साहब को हमका भी स्थान नहीं था। यदि यह कानून राजा साहब की खातिर के लिये बना तो जमींदारों पर, चरगाहों पर, इमरानों पर, खानों और बंगलों पर, इन सब जगहों पर तो जमींदार का अधिकार बना ही रहता। इन सब बातों को सामने रख कर मैं कहना चाहता हूँ कि जो जमींदारी हम सरकार ने खरीदी है वह काफी इन्कमदा है और उस जमीन से जो देना की मौजूदा दिक्कत है वे रखा हो जायेगी। इस कानून में एक बात बात सुआविजे की है, कन्वेंशन का है, कन्वेंशन के मुताबिक दो तरह के व्यापार व्यापार किये जा रहे हैं एक मर्क नाम है जिसका कहना है कि जमींदारों को कोई सुआविजा न मिलना चाहिये हमने देना जो अभी मोडलिफिकेशन की तरफ में तकरीर करना रहे थे, उनका तो कहना है कि जमीन में ज्यादा सुआविजा एक लाख हो और कुछ सुआविजा ५० करोड़ हो। ५० करोड़ हो या ६० करोड़ हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा मर्क भी है जिसका कहना है कि सुआविजा बिल्कुल न होना चाहिये। जो मर्क यह कहता है उसका यह भी कहना है कि जमीन की मलिकियत भी किसी को न मिलनी चाहिये। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो मर्क सुआविजे की सुवलिफिकेशन करना है वह जमींदारों की सुवलिफिकेशन करना है, काश्तकार की सुवलिफिकेशन करना है। उस तरीक से किसी को हमददी नहीं हो सकती है। दूसरे लोग जो सुआविजे के मुताबिक सिफायत करते हैं उनका सिफायत कई तरह की है। राजा साहब ने कल जो तकरीर की उसमें इस बात की चर्चा की कि जो सुआविजा जमींदारी रिपोर्ट में लिखा था वह बहुत मौजू था और वही कायम रहना चाहिये था। मैं राजा साहब का ध्यान इस चीज़ की तरफ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप उस सुआविजे के नक्शे की तरफ देखें तो आपको नाश्तम होगा कि २५ ६० तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को २५ गुना सुआविजा मिलता। अगर २५ ६० मालगुजारी हो तो ६२५ ६० हो गया और अगर २६ ६० देना हो तो उसे उमका २३॥ गुना मिलता, इसके माने उमका ५८५ ६० सुआविजा हो जाता है। यानी २५ ६० वाले को ६२५ ६० और २६ ६० वाले को ५८५ ६० सुआविजा मिलता। इसी तरह से आप हर कदम पर देखें। जिसकी ५० ६० हैसियत है उसको ११२५ ६० मिलेगा। और मिलेगा और ५० ६० से ५१ ६० मालगुजारी होती तो उसे १०२० ६० मिलेगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो मसौदा इस जमींदारी रिपोर्ट में दर्ज है वह नाकिस था और उस स्कीम से लोगों को काफी डिक्कत पैदा होती। लिहाजा वह स्कीम काबिले कबूल नहीं है। एक दूसरी बात जो शायद राजा साहब भूल गये वह यह है कि जमींदारों की मालगुजारी के अलावा एक आइटम और है जो मालगुजारी में शामिल होता है और उसका नाम है अकूपायर्स रेन्ट। यह उन जमीनों पर देना पड़ता है जिनमें आबादाशो होने लगी है और जिसका बन्दोबस्त नहीं हुआ है, लेकिन इस सुआविजे में अकूपायर्स रेन्ट को नहीं रखा गया है और इस लिहाज से जमींदारों को काफी मुनाफा है।

मुझे एक बड़ी बुराई जो इस कानून में मालूम होती है वह यह है कि इसमें काश्तकारों या भूमिधरों की कोई हक नहीं रखा गया है जिससे वह अपनी जमीन दूसरे को दे सके। पिछली सालों की तवारीख को देखने से मालूम होता है कि जो पहले जमींदार थे वे नहीं रहे उनके ऊपर कर्जा हो गया और माहूकार ने उस जमीन को खरीद लिया और वे केवल एक काश्तकार रह गये। कल तकरीर के दौरान मैं राजासाहब ने एक बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कहना

[ श्री फुलनिह ]

मन्त्र है कि जमींदार महज ठेकेदार थे वल्कि राजा साहब ने कहा कि इनमें कुछ जमींदार ऐसे जो थे जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जाने दीं। मैं अर्ज करना हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो आजादी के लिए कुरबान हो गये मगर उनकी जमींदारी जब्त हो चुकी है उनको इस कानून ने नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है। अन्वयता ऐसे जमींदार हैं जिनको जमींदारियां इस बिना पर मिली हैं कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। इस कानून में एक खामी है वह यह कि इसकी रू से ऐसे जमींदार भी मुआवजा पा जाने वाले हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। हम चाहते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है कोई मुआवजा न दिया जाय और उनसे जमीन ले ली जाय और उन लोगों को जिन्होंने देश की हिदमत की है उनको विश्व मुआवजा जमीन दी जाय। जमींदार कमेटी की रिपोर्ट में यह नौजूद है कि और दूसरे देशों में जो लोग देश की आजादी की रक्षा में देश के साथ गद्दारी करते रहे उनको उनकी जमींदारी के एवज में कोई मुआवजा नहीं मिला। इनलिये मैं समझता हूँ कि कम से कम उन जमींदारों को जो देश के खिलाफ उड़ते रहे कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिये। शायद राजा साहब भी इस सुधार को समर्थ करेंगे। काश्तकारों को जमीन नहीं उठानी चाहिये यह बात सही है। लेकिन इसमें भी मुझे कुछ सुधार की जरूरत मान्दूम होती है। ऐसा अक्सर होता है कि बाज़ साल किसी वजह से कोई काश्तकार इस काबिल नहीं रहता कि वह अपनी जमीन को जोत सके। इसी साल ऐसा हुआ कि मवेशियों के अन्दर बीमारी फैल गई। बाज़ मर्तवा ऐसा होता है कि गांवों में आग लग जाती है। एक गांव में दो दफा आग लगी। लोगों के पास पहनने के कपड़े तक नहीं रहे। ऐसी हालत में यह सुमकिन है कि उस गांव के काश्तकार अपनी जमीन को न जोत सकें और उसका अच्छा इन्तजाम न कर सकें। अब अगर कानून में यही रखा गया कि कुछ भी हो काश्तकार किसी को अगर जमीन दे देगा तो जमीन उससे निकल जायगी तो उसका एक नतीजा हो सकता है वह यह कि वह जमीन खाली पड़ी रहेगी या काश्तकार उसका पूरे तौर से बन्दोबस्त नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में देश में पैदावार बढ़ने के बजाय घटने का अन्देश है। मैं समझता हूँ कि इस कानून में ऐसे मौके रहने चाहिये कि अगर कोई काश्तकार किसी खास वजह से किसी साल अपनी जमीन में काश्त न कर सके तो वह एक साल के लिये अपनी जमीन को ओर को जोतने के लिये नहीं दे सकता है और जो इस जमीन को जोतेगा वह उस जमीन में भूमिधर या सीर के राइट्स नहीं पायेगा। इसके लिये अगर ६ माह का समय भी रख दिया जाय तो मेरे ख्याल में वह भी ज्यादा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वह जो जमीन को जोतने वाला है अगर वह यही समझेगा कि यही फसल मुझे मिलने वाली है तो वह उस जमीन की कोई तरफकी करने को तैयार नहीं होगा अगर ऐसा न हुआ तो इससे देश की पैदावार में कमी पड़ेगी और इसीलिए मैं समझता हूँ कि यह जो काश्तकार के न उठाने वाला कानून है उसमें इतना हेर-फेर करने की जरूरत है इसी तरीके के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती में किसी को शामिल कर लेते हैं। अगर उस माली को शामिल करने के माने यह हो जायें कि उसके भी हुक्क पैदा हो जायेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि कोई आदमी किसीको खेती में शामिल नहीं करेगा और उसका यकीनन पैदावार पर असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस कानून का मंशा यह नहीं है कि ऐसे साक्षियों के कुछ हुक्क पैदा हों लेकिन फिर भी यह जरूरत है कि यह बात साफ कर दी जाय।

नोनरी गन यह है कि जहां खेती अच्छे पैमाने पर होती है वहां अगर किसी काश्तकार के पाम खेत नहीं होता है तो वह दूसरे से खेत लेकर खेती करता है। अगर इस कानून का असर पड़ हो जाय कि जो काश्तकार दूसरे से खेत लेकर बोये वही उसका मालिक हो जाय तो यकीनन कोई काश्तकार किसी को खेत नहीं देगा और इनसे खेती की पैदावार में नुकस पहुंचेगा। इस कानून में तबादिले का हक तो नहीं है लेकिन यह एक आरज़ी तबादिला है और मैं यह समझता हूं कि ऐसे तबादिलों के लिए इस कानून में जगह रखनी चाहिये।

दरख्तों के मुताबिक इस कानून के अन्दर बहुत कुछ मामला तय हो गया है लेकिन फिर भी इसमें दो तीन टिक्कतें हैं। एक टिक्कत यह है कि जब यह कानून पाम हो जाय और जब इसका गजट हो जाय उसके बाद फिर यह तय होगा कि उसके बाद कोई जमींदार कोई दरख्त नहीं देच नकेगा, मगर जमींदार होगा तो इस कानून के पाम होने तक सब दरख्तों को साफ कर डालेगे। तो मेरा यह कहना है कि सरकार को फौरन कोई ऐसा आर्डर निहायना चाहिए जिससे दरख्तों का कटना बन्द हो जाय वना सब दरख्त कट जायंगे और इन्का जवाली हो जायेगे। जहां दरख्तों की मिलिकयत गांव पञ्चायतों को दी गई है वहां एक फिर्मा के दरख्तों की मिलिकयत कानूनीकरण को मिलनी चाहिये और वह वह दरख्त हैं जो खेतों की मेंड़ पर हैं। जो पिछला कानून काश्तकारों के लिये सन् ३६ में बना था उसमें हमने यह रक्खा था कि खेत के अन्दर के दरख्त काश्तकारों को दिया और खेत के बाहर के दरख्त जमींदारों को दिया। मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी गलती थी। आज वक्त है कि हम उस गलती को दुरुस्त कर दें। दो खेतों की मेंड़ पर अगर कोई दरख्त होता है तो वह दोनों खेतों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिये अगर ऐसे दरख्त का कोई मालिक हो सकता है तो वही हो सकता है जो उन दोनों खेतों का मालिक हो और अगर उन दोनों खेतों के दो मालिक होंगे तो वह मुश्तरीका मिलिकयत होगी। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे दरख्त काश्तकारों को मिल जाय तो जो गलती हमने सन् ३९ में की थी उसकी तयफती हो जायगी। जमींदारों के बारेमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जमींदारों के हपने दो तीन तरह के ग्रेड बनाये हैं, एक तो हमने यह किया है कि जो मौजूदा जमींदार हैं वह चाहे जितनी जमीन जोतते हों वह उनके हाथ पाम रहेगी। अच्छा यह तो सही है कि ५० एकड़ तक जमीन के वह भूमिधर हो जायंगे लेकिन बाकी जमीन अगर वह जोतते हैं वह उनके कब्जे से जायगी नहीं। मैं समझता हूं कि इससे देश की पैदावार को नुकसान पहुंचता है। मैंने जैसा शुरू में अर्ज किया कि इस जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जितना जितना रक्बा जमीन का जमींदारों के पास बढ़ता जायगा उतनी ही पैदावार कम होनी जायेगी। जो होशियार जमींदार हैं वह रक्बा बढ़ाते हैं लेकिन पैदा कुछ नहीं करते हैं। मैंने एक जमींदार को देखा कि उसके पास ३ हजार बीघा जमीन थी लेकिन ब्रैल सिर्फ १५ थे। जहां जरूरत होती थी वहां वह बेल भेज देता था। एक मैस उसकी तहसीलदार के यहां थी और वही मैस उसकी सारी खेती कराती थी। अगर पैदावार बढ़ाना है तो हमको जमीन की अपर लिमिट फिक्स करना चाहिये। जैसे हम लोअर लिमिट फिक्स करने के हक में हैं वैसे ही हमें अपर लिमिट भी फिक्स करना चाहिये।



[ श्री फुलमिंह ]

बहुत से जमींदार जो दूरदेश कहे जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सी जमीनों में बाग लगा कर छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि जो अपर लिमिट (ऊपरी हद) की बात है वह इन बागों के मुताल्लिक भी होना चाहिये। एक एक आदमी ने कई कई हजार बीघे बाग खड़े कर दिये हैं गो कि उन बागों को न वह तस्करी कर सकते हैं और न उनसे देश का कुछ फायदा हो सकता है। कितनी जमीन किमके पास हो इसके मुताल्लिक दो तीन बातें नुझे अर्ज करना है।

इस कानून में ३० एकड़ की कैद लगायी गयी। जो शख्स जमीन खरीदे तो इस तरीके से कि खरीदी हुई जमीन और पहिले की जमीन मिला कर ३० एकड़ से ज्यादा न हो। लेकिन जिनके पास पहले से मौजूद है उनके लिए कोई कैद नहीं लगाई, मेरा सुझाव यह है कि ५० एकड़ की कैद लगाना चाहिये उन सब जमीनों के लिये जो खुद काश्त जमीनें हैं, बागीचे हैं। अगर आप इनको को देखेंगे तो आपको मान्य होना कि २३ सौ जमींदार ऐसे हैं जिनके पास ६३ लाख एकड़ है और १ हजार जमींदार ऐसे हैं जिनके पास ६९ लाख एकड़ है। अगर ५० एकड़ के हिस्से में आप जमीन दें तो फायदा जमीन में आर एक लाख नये आदमी ६३ एकड़ के हिस्से में दया सकते हैं। बची हुई थोड़ी जमीन जिनके पास है वह थोड़ी है। इतनी जमीन है जिससे गुजर बसर कर सकें। जिनकी होल्डिंग अनइकनामिक है तो २ लाख खानदानों को हमने नफा पहुच सकता है और दो लाख खानदान के माने उस लाख आदमी, यह एक बड़ी तादाद है जिससे देश को फायदा होगा। जहां तक जमीन के इंतकाज का ताल्लुक है वे करने के माने इस कानून में यह किये हैं कि ६३ एकड़ की तकसीम नाजायज होगी। जिसके पास जमीन है वह बेचना चाहे तो कितनी जमीन बेच सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी होना चाहिये। इसमें यह खतरा है कि हमारे दोस्त शायद यह प्रोपेगैंडा करें कि जमीन की निष्क्रियता के क्या माने हुए, वह कहेंगे कि कांग्रेस सरकार एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से छीन लेती है। इसलिये जमीन के बंटवारे में हमारी सरकार हिचकिचाती है। मेरा कहना है कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि किसान जो जमीन हासिल कर सकता है वह हासिल न कर सकेगा। मैं अपने तजुबों से कह सकता हूँ कि जमीन के बेचने पर पाबन्दी लगाई जाय तो काश्तकार को नफा होगा। पाबन्दी किसी किस्म की हो। मेरा सुझाव है कि कोई आदमी ६३ या कम का बैनामा करना चाहे वह आदमी बेचे जिसके पास पहले से जमीन हो और जिसका खाना अनइकनामिक न हो। एक खाना जो कम होगा वह इकनामिक हो जायगा। अगर यह पाबन्दी की जाय तो देश का नफा होगा। बैनाने के मुताल्लिक मैंने अर्ज कर दिया।

यह चर्चा भी हुई थी कि कोअपरेटिव फार्मिंग हो। मेरे दोस्तों ने कहा, जो मेरे दोस्त सोशलिस्ट पार्टी को नुमाइन्दगी करने का दावा करते हैं, उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव फार्मिंग कम्पल्सरी (अनिवार्य) कर दी जाय। उनको कोआपरेटिव के माने याद नहीं रहे। कोआपरेटिव अपनी मर्जी से काम करता है कम्पल्सरी तो कोआपरेटिव का मुतजाब है। उनका बरअक्स है। देश भर में कोआपरेटिव फार्मिंग हो या कम्पल्सरी फार्मिंग हो इसके नतायज खतरनाक होते हैं। यह प्रोपेगैंडा से, तालीम से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यह कोआपरेटिव फार्मिंग मुफीद चीज़ है। इससे बड़ा नफा होगा। कुछ तकरीर करने वक्त राजा साहब यह फरमा रहे थे कि कोआपरेटिव इस देश में कभी कामयाब नहीं हुआ। उनको शायद मान्य नहीं है गन्ना जो कुछ बिना है हमारे प्रान्त में कोआपरेटिव के

जरिये से विकता है। कोई शख्स गल्ला नहीं बेच सकता। जितनी गल्ले की दूकानें हैं वह कोआपरेटिव की हैं। हमारे देश में कोआपरेटिव तरक्की कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि पूरा मौका मिले तो बहुत जल्द छा जाय।

एक बात मैं और अर्ज करूं। कम्पेन्सेशन के मुताल्लिक जो यह कहा जाता है कि बिला मुआविजा की जमीनें ले ली जायं तो मैं समझता हूं कि इसमें एक खामी है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि गालिबन दो लाख ६ हजार जमींदार हैं और दो लाख किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ता है। यह सही है कुछ लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत जमीन किसी को दे रखी है। मगर अगर इतने आदमियों की जमीन बिना मुआविजा दिये हुए ले ली जाती है तो फिर इतने आदमियों को रिहेबिलिटेट करने का सवाल पैदा होता है। सरकार का यह मन्दा नहीं है कि किसी फिर्के को इस मुल्क के, बेघरवार कर दिया जाय बल्कि मन्दा तो यह है कि जो पिछले लोग हैं, यहां पर पहले से बसे हुए हैं, और जो मोटे हो गये हैं वह पतले हो जायं ताकि उनको कोई बीमारी वगैरह न हो और जो बहुत दुबले पतले हैं वह ज्यादा मोटे हो जायं। तो इस तरह से सही तौर पर मुआविजे की बात जरूरी है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें कुछ चीजें और हैं। इस कानून में मुझको दो बातों को चर्चा और कर देनी चाहिये। एक तो कर्जे के मुताल्लिक है और एक है जमीन के इंतकाल के मुताल्लिक। मैं समझता हूं कि यह न तो मुनासिब है और न यह कानूनी बात है। रहा यह कि आज के बाद जितने बैनामे वगैरह होंगे, जितने ठेके वगैरह होंगे, यकीनन उन अनपढ़ और गांव के भोलेभाले लोगों की नावार्कफियत में नाजायज तौर पर होंगे और उनसे रियासतें नाजायज फायदा उठायेंगी। मैंने सुना है कि कुछ रियासतें अभी से काश्तकारों को ठेका दे रही हैं। इस तरह से गांव के भोलेभाले काश्तकार अपना सब रुपया निकाल कर जमींदार को दे देंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को फौरन यह कदम उठाना चाहिये जिसमें आज के बाद सब इन्तकाल बन्द हो जाय। ताकि जमीन का बैनामा, क्या ठेका, क्या पट्टा तमाम कोई शख्स, कोई जमींदार न उठा सके। जब तक इस कानून का निफाज न हो मुमकिन है कि जमींदार काश्तकार के ऊपर जितनी दीवानी में नालिशों की डिग्रियां हैं जमीन नीलाम कराने के मुताल्लिक हैं उस फंडामेंटल राइट्स के मुताल्लिक सब जमीनें नीलाम हो जायंगी तो फिर तो इस कानून का मंशा ही फौत हो जायगा। यह भी हो सकता है कि कुछ जमींदार चालाकी से झूठा नीलाम करा लें तो यह भी नामुनासिब है। अच्छा तो यही होगा कि जब तक यह कानून नाफिज न हो तब तक के लिये ये तमाम डिग्रियां रोक दी जायं। इस कानून का निफाज तमाम प्रान्त में होगा लेकिन म्युनिसिपैलिटियां, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज, कैंट्रमेंट्स वगैरह सब इससे बरी रहेंगे। मेरे खयाल में उन काश्तकारों को जो टाउन एरियाज में रहते हैं, जो म्युनिसिपैलिटियों में रहते हैं उनके ऊपर यह एक किस्म का जब्र है। कानून में यह लिखा है कि जब तक वेस्टेड एरिया में कानून के नाफिज होने के वक्त तक टाउन एरियाज बन जायंगी तब वहां भी यह कानून लागू हो जायगा। मैं चाहता हूं कि यह कानून टाउन एरियाज, म्युनिसिपैलिटियों और नोटिफाइड एरियाज में साथ ही साथ लागू होना चाहिये। मैं यह नहीं जानता कि यह कानून इस स्टेज में भी लागू होगा या नहीं होगा। मेरे दोस्त जो देहरादून के श्री शान्ति स्वरूप शर्मा हैं उन्होंने इस बात को देखा होगा कि उनके में जो टी गार्डन है, वहां के जो मजदूर हैं उनके मवेशियों के गोबर को वे लेते हैं लेकिन

[ श्री कृष्णसिंह ]

चारे का दाम उनको देना पड़ता है। यह कानून टो गार्डन ही नहीं बल्कि सारे स्टेट के लिये ही लागू हो जाय तो मैं समझता हूँ कि इससे सब किसान पूरा नफा उठा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि श्री रोशनजमां खां ने कहाँ तक इस चीज़ पर गौर किया था। उन्होंने यह कहा था कि अस्तानियों को वे राइट्स हो जाने चाहिये जो भूमिधरों को हैं। उनको शायद यह मालूम है या नहीं कि दो तीन किल्ले के लोग उसमें हैं यानी अंधे लंगड़े जो जमीन को जोतते हैं उनका भी जिक्र उसमें है। उनका मंशा था कि उनको भी हक दिया जाय तो फिर मैं पूछता हूँ कि क्या अंधे, लंगड़े को खत्म कर देना चाहिये। फिर दूसरी बात जो उसमें है वह है उनको जो रिवर ब्रेड्स को जोतते हैं। उस जमीन में किसी को हक देना मैं समझता हूँ कि उस जमीन को ब्रेकर कर देना है। यह एक तयशुदा बात है कि रिवर ब्रेड्स बदलते रहते हैं और इस तरह अगर एक साल एक जगह एक को हक दिया जाय मैं समझता हूँ कि यह उनकी गलतफहमी थी जिसकी दिना पर उन्होंने ऐसा कहा था। फिर उनका यह कहना कि क्लासलेस सोसाइटी तो गवर्नमेंट बनाना चाहती है लेकिन इस कानून में चार किल्ले के कास्तकार कर दिये गये हैं। लेकिन सीरदार तो फौरन ही १० गुना देकर भूमिधर होता है और तीसरा जो है वह ५ साल के बाद १५ गुना देकर उस हक को पा सकता है। और चौथा जो असामी है वह एक ऐसी चीज़ है जो रहनी चाहिये। तो उनका जो चार क्लासेज़ का ख्याल था वह गलतफहमी पर मबनी था। किल्लेकीकन उसमें दो ही क्लासेज़ कास्तकारों के रह जायंगे। मैं समझता हूँ कि इस कानून से इस किल्ले की सारी दिक्कतें रफा हो जायंगी। ठेकेदारों और मुर्तहिनों को जो हक दिया है उन पर फिर दोबारा गौर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो मुख्तलिफ हद रखी गई है वह ठीक नहीं है। ठेकेदारों को इस कानून में तीन दलों में बांटा गया है। इसमें भी बहुत भेद रखा गया है। सब के लिए हद अलग अलग रखी गई है। मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिये एक सा होना चाहिये वह चाहे ठेकेदार हो या मुर्तहिन हो या असल मालिक हो। ठेकेदार के लिए जो शर्त रखी गयी है कि ५० एकड़ ज़मीन से वह ज्यादा नहीं रख सकता है लेकिन मुर्तहिन के लिये दूसरी शर्त है कि अगर राहिन की सीर मुर्तहिन के कब्जे में है तो वह राहिन की सीर खुदकास्त हो जायगी लेकिन अगर राहिन की जमीन खुदकास्त नहीं थी और अगर मुर्तहिन उसे जोतता है तो वह तमाम ज़मीन को रख सकता है। मैं समझता हूँ कि यह तर्कान ठीक नहीं है। एक ही पैमाना होना चाहिये हर शख्स के लिये कि ज्यादा से ज्यादा कितनी ज़मीन रख सकेगा। और कम से कम कितनी ज़मीन रख सकेगा। इस कानून से जो बहुत बड़ा फायदा होगा वह थोड़ी जमीन वालों को होता है ताकि वह ज़मीन में इजाफा कर सकें लेकिन अहल तो नफा तब होगा कि जब उसको चकबन्दी हो जायगी। इस कानून में चकबन्दी की ज्यादा गुञ्जाइश नहीं है अलावा कोआपरेटिव फार्मिंग होने के चकबन्दी भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि सरकार अनकरीब ही चकबन्दी का कानून लावेगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले में सब लोगों ने ध्यान दिया है और मैंने भी चन्द बातें जो इस कानून के मुताल्लिक थीं आपके सामने अर्ज कर दीं। मगर मैं बिल किसी खौफ के यह कह सकता हूँ कि यह कानून अपने किल्ले का एक बड़ा लाजवाब कानून है और बावजूद इसके कि जो नुकनाचीनी इस पर की गई और दूसरे साहबान ने भी इस पर की और मैंने भी

कुछ कहा इस सब नुक्सानो के बावजूद भी यह कानून देश के रहने वालों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। रोशनजमां साहब ने एक बात कही कि दस गुना आप लगान तो ले लेते हैं लेकिन उससे किसान को फायदा क्या पहुंचता है। लेकिन उनको यह शायद मालूम नहीं कि किसान क्या चाहता है। शायद वह खेती नहीं करते हैं और खेती करने वालों से उनका वास्ता कुछ कमोवेश मालूम होता है। किसान तो अपनी हिफाजत चाहता है जो सबसे जरूरी बात उसके लिए है वह यही है कि उससे कोई ज्यादा वसूल न कर ले। किसान उससे परेशान न हो। अगर उससे १० गुना लगान लेकर उसको मिलिक्यत दी जाय तो वह खुशी से इसके लिये तैयार हो जायगा और खुशी से इस मिलिक्यत को लेने के लिये तैयार है और उसको अपनी मिलिक्यत मिलने के लिये समझा देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कानून बहुत जल्द ही इस हाउस में गम हो जायगा। मेरे वह दोस्त जो जमींदार हैं और जो इस कानून की मुखालफत करना चाहते हैं मैं उनसे कहता हूं कि उनको इसकी मुखालफत नहीं करना चाहिये, उनका तो इसमें नफा है। इसलिये उनको चाहिये कि वह इसकी मुखालफत न करें। आज यह गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वह इस बात के लिये कायल है कि आपको इसका मुआविजा मुआविजा दिया जाय और अगर कोई और दूसरी गवर्नमेंट आई तो वह बिल मुआविजे के ही आपसे जमीन ले लेगी और आपको इसका कोई मुआविजा भी नहीं देगी। इसलिये बाज वक्त यह ढेर करने वाली बात आपका बहुत नुकसान देनेवाली बात हो जायगी। आपका इसमें नफा है कि आप जल्द इस कानून को पान कराने में मदद दें और जो कुछ आपको मिलने वाला है वह आपको मिलने वाला है वह आपको मिल जाय और वक्त गुजरने पर जो थोड़ा बहुत मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल की तारीफ करता हूं कि यह बिल जो पेश किया गया है किसानों के लिये बहुत मुफीद है।

**श्री मुहम्मद यूसुफ**—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बहुत बड़ी कोई तूलानी तकरीर करने के लिये तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई तूलानी तकरीर इस पर की जाय तो दरअसल दो दिन इसमें लग जायेंगे। मैं उन प्वाइंट्स को लेता हूं जिनको मैं समझता हूं कि बहुत अहम हैं और जो ऐसे प्वाइंट्स हैं जिनके ऊपर जरूर, बिल जरूर, गौर व गौर करने की खासतौर पर जरूरत है और जिनको हमारे भाइयों को समझना चाहिये और देखना चाहिये ताकि हमको इस हाउस में उनको हमदर्दी हासिल हो सके। इस उद्देश्य को मान लेने से किसी को और हमारे प्रीमियर साहब का कोई दिक्कत नहीं होगी। इन अलफाज़ के साथ मैं सबसे पहले मुबारकवाद देना चाहता हूं प्रांतिपर मादर को जेन्हां ने निहायत काबलियत और बहुत तजुर्वे के साथ इस बिल को पेश किया है। यह बिल बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ दूरदर्शी के साथ और नवाजुन खयालत के साथ जो कि हर स्टेट्समैन को अपने सामने रखनी चाहिये वह सब समझ कर रखा गया है। हमारे प्रीमियर साहब, मैं जानता हूं कि कोई मामूली हस्ती नहीं है। बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं जिनके ऊपर हमारे सूत्रे को नाज़ है, और सारे हिन्दुस्तान को नाज़ है और जिनके नुक्के खयाल निहायत वसीह हैं और जो सब मसलों पर नज़र डालते हैं और हर मसले को तय करते हैं। यह खुशी हुई बात है कि इस वक्त हमारे दिव्य निहायत ही भरे हुए हैं। हम जानते हैं कि हमें इसको मानना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हैं, खयाल हम पामाल हो जायें, हमारी रोटी छिन जाय, खयाल सड़कों के भिलमंगे हो जाय लेकिन वह चन्द टुकड़े चांदी के

[ श्री मुहम्मद यूसुफ ]

जो आप हनको देंगे उससे कोई हमारा प्राबलम साल्व नहीं होगा । इन पैसों से कोई हमारी दुश्वारियां दूर हरगिज़ नहीं होंगी और न यह इतने ही होंगे कि हमारे प्राबलम को साल्व कर सकें । आप अगर हर आदमी की जिन्दगी का कोई प्ज़ान बनाते हैं तो आप फल कर सकते हैं लेकिन जहां आज एक करोड़ आदमियों की जिन्दगी वाक्स्ता है उसको आप तबाह किये देते हैं । आप ने कहा कि बार बार हमने उसपर गौर किया लेकिन फिर गौर कीजिये, फिर गौर कीजिये, क्योंकि जमाना ऐसा है कि कुल हालत पर नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है । देखिये कि दुनिया में क्या हो रहा है । दुनिया के निज़ाम में आज तबदीलियां हो रही हैं लेकिन जो मुल्क कि आज डिमाक्रेसी का सबक दे रहा है जैसे कि इंगलिस्तान, वहां पर अवालीशन आफ जमींदारी अब तक नहीं हुई । यह एक एकनामिक प्राबलम है । आपको गौर करना है कि एकनामिक प्वाइंट आफ व्यू से, मुल्क की बेहतरी के प्वाइंट आफ व्यू से, यह चीज़ सही होगी या नहीं । यह कहना कि नेशनलिज़्म एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है, सोशलिज़्म एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है तो सोशलिज़्म का जो घर है, डिमाक्रेसी का जो घर है वहां भी अवालीशन आफ जमींदारी नहीं हुआ । यह कह देना कि अरे यह तो राक्षस हैं, यह तो खून चूमने वाले हैं और यह कह कर आप टण्डे टिल में किसी की तबाही और बरबादी देखें, क्या यह जायज़ है ? जमींदारों ने चाहे कोई भी गलतियां की हों लेकिन आप उनको इस तरह से तबाह व बरबाद नहीं कर सकते । आप मसावात के हानों हैं, आपके ऐक्शन में नान वाइलेंस होना चाहिये, ख्यालात में नान वाइलेंस होना चाहिये । हम लोग एक क़ौन के हैं, एक मुल्क के हैं । एक शख्स दूसरे की तबाही और बरबादी का निहायत राइन् के साथ, निहायत सुकून के साथ मज़ाक उड़ाये, क्या यह कहीं जायज़ है ? क्या यह जायज़ है कि हम सब महात्मा गांधी के तरीके पर न चले ? तशद्दुद के जो हानी हैं वह हम नर हमला करें, हमारी इक्तादी मौत, ज़ाने की कोशिश करें बेईमानी से, दगाबाज़ी से, गद्दारी से, नक्करी से, फरेव से, जाल से यही नहीं बल्कि बहैसियत एक चोर के और बहैसियत एक ठग के हनारी तमाना ढाल्टें जो लूहानी हैं छीनने की कोशिश करे । यही नहीं बल्कि वह हमारी इक्तादी हैसियत इस तरीके से कर दें कि हम दुनिया में मुंह दिखाने और फर्ज़ क़ौमी अदा करने के काबिल न रहें । जीतने वाले तुम वहीं रहो और हम तुम पर हुकूमत करेंगे । हमको तुम्हारी कोई इक्तादी मंज़ूर नहीं है, तुम अपनी गरीबी में रहो मगर दूसरा नज़रिया यह भी है कि तुम्हारी सारी जो पैदावार है वह हम तुम्हारे पास सिर्फ खाने के लिये छोड़कर बाकी सब ले लेंगे । यह गलत है । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी जिंदगी से बहुत आदमियों की जिन्दगी वाक्स्ता हैं, ख्वाह वह रिश्तेदार हों, ख्वाह वह डिपेंडेंट्स हों, ख्वाह वह वह लोग हों जो हमसे नाल्लुक रखते हैं । यह ऐसे लोग सब मिलाकर करीब एक करोड़ के हैं, जिनका मसला है । यह कोई मज़ाक नहीं है । आप कह सकते हैं कि जरा देखिये यह लाइक ए डाइंग डक खड़ा हुआ है । इसको देवकर आन हंसिये । लेकिन अगर हंसेंगे तो आप अपने ब्रान्ड फिलसफे जिंदगी पर हसेंगे, अपने मुल्क पर हसेंगे और जितनी भी बुलन्दी आपने हासिल की है उसको खत्म कर देंगे । आपका वह फिलसफा है जिसकी शिक्षा राम, कृष्ण और महात्मा गांधीने दी थी, आप उसको खत्म कर रहे हैं । क्या वह आप की बुलन्दी है कि एक शख्स दूसरे शख्स को जालिमाना तरीके से बर्बाद करें ? ख्वाह वह फर्द हो, तबका हो या क़ौम हो । आप जिन्दगी को ऊंचा उठाएँ, इक्ता-

माथी हालत को दुस्त कर दें, लेकिन मिनहेमुष्ट कौन कीजिये, नहीं तो आपका एक पेटी फिल्लसका न जायगा, अपना पोच्छिकल एंडन को पूरा करने के लिये, और अपने बोटों को हासिल करने के लिये, और आप उसी फिल्लसके के हानी रह जायेंगे, और घृणा के हामी हो जायेंगे। आनका इन्सान का फिल्लस, ग्वादानी का फिल्लस, सच्चाई का फिल्लस, विद्वान का फिल्लस और मस बात का फिल्लस है। मसावात के मुताल्लिक दो अल्फाज कह देना चाहता हूं। ग्नुदा के मानने मसावात है, जस्टिस और सिविक राइट के सामने मसावात है, मगर इक्तसादी और माली मसावात नहीं है और न होगी। आप लोग इतने आदमी यहां पर बैठे हैं लेकिन आप लोगों में से कोई साहब एक ही माली हालत नहीं रखते। माली हालत एक नहीं हो सकती, जब तक डिमाग का फर्क है, अक्ल का फर्क है, तजुब का फर्क है इल्म का फर्क है, और ईमानदारी का फर्क है, तब तक मसावात का मसला मान्यदिन के दिवसों में नहीं हो सकता। इक्तसादी मसावात का कानून कुदरत से नहीं माना है। जब आपको जरूरत होती है वोट्स लेने की तब तो आप यह कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए यह किया है वह किया है लेकिन अब यह कहते हैं। यह चीजें थोड़े ही दिन तक चल सकती हैं। यह खुरी हुई बात है। इसमें सब बग़ावर होने चाहिये। इसको इक्वायिटी कहते हैं। जनायवाला, डेमोक्रेसी के माने आगे समझिये। यह वह दिन होगा जब रवायदारी का तरीका होगा, अवलक का तरीका होगा, इन शरूफ का इक्वठ अगरचुनिटी मिलेगी। यह शकल रही तब तो ठीक है वना हमारे सामने एक ग्वतरगा नकशा होगा।

डेमोक्रेसी में डिफेक्ट यही है कि यह चीज शुरू में तो अच्छी होती है लेकिन आगिर में जा कर डेमोक्रेसी अथारीटेरियन हो जाती है यानी डेमोक्रेसी फासिज़म हो जाती है, नाजिज़म हो जाती है। इसलिये अगर आप लोगों के दिलों में एक कैफियत पैदा कर देंगे तो वह अपनी ब्यूटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपना फर्ज समझेंगे कि मुल्क के मुताल्लिक उनका क्या फर्ज है और उन्हें किस तरह से उमको निभाना है। आपको वही रास्ता अख्तियार करना चाहिये जो महात्मा गांधी जी ने आपको सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने इस चीज को बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ पेश किया है। इससे हम हिंदू धर्म की जान भी कह सकते हैं। यही चीज हमारे मजहब में भी बुलन्द है और ईसाइयों के मजहब में भी यह एक ग्वास चीज है। इसका नेचुरल बेसिस होना चाहिये कि हम सब एक वर्ड फैमिली हैं, उमके रहन-सहन का चाहे कैसा ही तरीका क्यों न हो, कैसा ही सिवलीजेशन क्यों न हो। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ग्वबरदार रहिये कि यह चीज बहुत जल्द होने वाली है। जहांतक मयनीरिटीज़ (अक्ल चले) के राइट्स (हक) का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको ही फैसला करना है। हम लोगों ने अपनी आज्ञादी को अपने हुक्क को आपके सिपुर्द कर दिया है और आप ने पूरी पूरी तयककोह रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह सच्चाई और रवायदारी जो कि महात्मा गांधी जी ने आप लोगों की ही नहीं बल्कि सारे जमाने को सिखाई है उसकी बिना पर हम लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। यह सच है कि आपको हक है आप जो सिस्टम चाहें ले लें लेकिन इसको लेने में आप यह हर्गिज न भोचें कि यह मैजारिटी का है या यह मायनारिटी का है। इसमें सबका फायदा होगा। जमींदारी का भी फायदा होगा। इसलिये आपको रवायदारी का तरीका अख्तियार करना चाहिये। लेकिन आप हमारी माली मौत करते हैं इस हद तक कि हमारी विदेशी मुल्क

[ श्री सुहृन्मन्त यूनुक ]

ने कंटेन्ट हो। हन एक मिक्सीजेसन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम में भी आज वही इन्फ्लेक्शन है। अनरीका में बड़े बड़े इंडस्ट्रीयलिस्ट हैं और कैपिटलिस्ट हैं और इसी तरह में इंग्लिन्ड में भी हैं वह इंडस्ट्रीयल मैनेजर्स हैं। अगर आप उन पर २० फीसदी भी घटा बढ़ा दें तो कोई अगर उन को इकनसाइयास पर नहीं पड़ता। यहां के नजदूगे की हालत आप के यहां की कोअर रिटिड क्लान के बराबर है और वह लोग ४ या ५ तो डॉलर पाते हैं। उनका आप का क्या मुक़ाबला हो सकता है, उनकी तो इकतसादी बलन्दी हो चुकी है। आपकी तरफ़ी जब ही हो सकती है कि जब आप अपने लेबर से यह मंजूर करा लें कि वह एक नेयर शेयर लेगा और मुक्त की बरबरी को मदेनजर रखेगा और कौम की विडमन का करते हुए बाल्य की गेटियां खदेगा और जो उनके मुनाफे का मुनासिब हिस्सा होगा मिर्क नहीं लेगा और जो कैपिटलिस्ट इन्वर्ने के देगा उसे मंजूर करेगा। गांवों की इकतनादी हालत तो आपके यहां एक अजीब व रूढ़िवादी है। आप कह रहे हैं कि गांवों में जितना लेबर क्लान है उसको हम जमीन दे देंगे। अगर आप ६-७ बीघा जमीन उसे दे देंगे तो उसका क्या भला होगा, वह उस जमीन को जोतेगा या कि आप के कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल होगा? हमारे दोस्त चरणसिंह साहब जिनकी नजर स्पष्ट है और उनका ख्याल सही है कि बड़ी फार्मिंग खतरनाक चीज है और अगर वह नतीका किसी बन्क फेल होता है तो उसका मुल्क की माली हालत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनका यह कहना कतई ठीक है कि लमाल होल्डिंग्स पर कामयाबी ज्यादा होती है क्योंकि उस पर इन्डिविजुअल काश्तकार शौक व अरमान के साथ अपना काम करता है उनकी ज्यादा संकल्पेन्दी होती है। और आप पहले ही आकुपैन्सी बना चुके हैं और सबको सीकशर कर चुके हैं और आप के कानून से ५ साल तक तो कोई भी किसी काश्तकार को नहीं निकाल सकेगा। इन लोगों में से बहुत सों के पास तो रोटियां खाने की भी जमीन नहीं है। आप बतलाइये कि आरने हमारे लिए क्या सोचा है। उनको जो इस तरह के लोग हैं जमीन पर प्रायस्टी मिलना चाहिये। और जमीन जो सवटीनैन्ट्स को दिलवा दी गई हैं वह पहले जमींदारों को मिन्नी चाहिये। इस ५ बरस में हम ग्वायेगे क्या? हम तो आप की नजरों में हकीर हैं और जलील हैं। आप समझते हैं कि हम लोग रईस हैं, ताल्लुकेदार हैं, और हमारे पास रुपया ज्यादा है। मुमकिन है कि कुछ के पास जो इंडस्ट्रीयलिस्ट हों या बहुत बड़े जमींदार हों कुछ रुपया हो लेकिन उन की शक्क दूसरी है और उनकी तादाद भी बहुत कम है। अस्त में हमारे पास कुछ नहीं है काश्तकारों के पास भी कुछ नहीं है कि वह स्टेट को दे और माली हालत ठुस्त कर सकें। रुपया कहाँ है? सरकार किस तरह से रुपया देगी। दरअसल जब तक आप काश्तकारों को एग्रीकल्चरल फैमिलिटीज, मैन्योर और सीमेंट न देंगे तबतक उनकी इकतमादी हालत नहीं सुधर सकती है और न आपकी 'ग्रो मोर फूड' की कोई स्कीम ही कामयाब हो सकती है। अगर किसी काश्तकार ने जबगदस्ती कोई जमीन जो लिया तो आप के कानून से उस पर उसका कब्जा हो जायगा। यह भूमिधर और सीरदार तो अलबत्ता आपको कुछ दे देंगे लेकिन जहां तक बिछा लगानी का ताल्लुक है वह आपको कुछ नहीं देंगे। आप हमारी जिन्दगी को बरबाद करते हैं, खराब करते हैं, सिर्फ इस वास्ते कि आपके पास कुछ फंड्स हो जायेंगे। हन भी इस बात को मानते हैं कि आपको रुपया मिन्ना चाहिये,

इंग्लैंड के आप कैसे हुक्मन चलायेगे ; यह जमींदारों का ही जिगरा है जो ४० से लेकर ६० फीसदी तक आपका नामगुजारी और सेम देता है, इसके अलावा जो अनरियालाइज्ड लगान रह जाता है वह अन्ध चीज है। मुलाजमीन की अर्जावोगरीब हालत है। वह मिरा यही समझते हैं कि उन्हें लड़ना पारना और चर जाना है। अलावा इसके वक्फ अउल और अउल है इनको भी मुआवजा उर्जा तरह ने देना चाहिये जैसा कि आउट ऐन्ड आउट पब्लिक वक्फ में समा गया है। वक्की गहा हा क्या। ऐसी हालत में आप हमारे ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लादना चाहते हैं। जब आप मुआवजा तय करें तो उसमें आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स न रखें। अपने जो वजत बताया है उसमें २ करोड़ ५ लाख की सेविंग होती है वह आप हमें दीजिये। आपको सिस्टम बदलने का अखिनयार है लेकिन यह अखिनयार नहीं है कि आप हमें बिल्कुल बरबाद कर दें, हम मुंह दिवाने के लायक न रहें। कुछ माहवान कहते हैं कि मुआवजा बिल्कुल न दिया जाये। उनके ऊपर यह नुमीशन आती तो उन्हें पता चलता। लोग हैरत में सुनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लड़ाइयां होंगी। मैं तो यही कहूंगा कि जीतने वाला भी बेवकूफ है और हारने वाला भी बेवकूफ है। कोई लड़ाई नहीं होगी, न इक्तासादी लड़ाई होगी और न लड़ाई तबके तबके, ग्रुप ग्रुप या भाई भाई में ही होगी। गांधियन प्रिन्सिपल पर हमें चलना चाहिए। यह तोहना जिसे हमने गैर मुल्कों के सामने पेश किया है जिससे उम्मीद है कि तमाम मुल्कों की जंग खत्म हो जायेगी, मोहब्बत की फिजा पेदा होगी, माथी हालत दुस्त होगी और एक दूसरे का काम करना अपना फर्ज समझेंगे। जो कुछ भी हमारा हथर हो जब भी मुल्क का नामला आयेगा, जहां आनर का नामला आयेगा वहां हम जान से कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह चीज है जो कि आपके सामने मैं पेश करता हूं। मेहवान इस पर गौर कीजिये। इक्तासादी मामलों पर आप बहन कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कर सकते कि हमको कल कर दें हमसे बरबाद कर दें। एक दफा हमने कहा था कि आपको अखिनयार है कि किसानों के मुफाद के लिये बिल लायें, लेकिन आप तो कहते हैं कि यह किसानों की डेमोक्रेसी के लिये है। यह कौन सी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो पीपुल की हुआ करती है, लोगों की हुआ करती है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हुआ करता है, रेडिकल सोशलिज्म हुआ करता है और हर किस्म के इज्म हैं। जिसको जो चाहे आप बगा लें, लेकिन यह गलत तरीका है। स्त्रोगन्स पर गवर्नमेंट नहीं चला करनी, आप क्या समझते हैं कि अगर स्त्रोगन्स से ही हम सब को मिटा देंगे। एक दिन मैं बैठा था कि मैंने स्त्रोगन सुना कि “जमींदारों का नाश हो”। मेरे साथ एक दूसरे शख्स बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि नवाब माहब देवा आने। मैंने कहा मुझको तो दिलार्द दिया ही ; फिर उन्होंने कहा कि इस फंसले से आपको दिल तो दहल गया होगा, मैंने उनको जवाब दिया कि शर्म से नजर गिर गई। क्या हम लोग इतने गिर गये हैं, इतने ज़खील हैं, इतने खूबवार हैं कि जानवरों की तरह से चीख और नफरत के नारे लगायें। मैं जानता हूं कि आपकी मेजारिटी है और यह मेजारिटी की जंग है। लेकिन मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी मुल्क की खिदमत की है, जिन्दगी कुर्बान की है। हमने भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। आजादी दिलायी है लोगों की हालत को दुस्त करने के लिये, उनको खत्म करने के लिये नहीं। डेमोक्रेसी के माने यह नहीं है कि मासेज आपको लीड करें बल्कि यह कि आप मासेज को लीड करें। वह उसी को कायम रखेगी जो कि सच्चे हैं, जिनमें तजुर्बा है, जिनमें भुक्तिकर खयालत हैं। जब हम



[ श्री मुहम्मद युनुस ]

युनानी चीजों की तारीफ करते हैं तो बिल्कुल इसलिये कि उनमें कुछ चीज है। इन उसके फंडामेंटल प्रिन्सिपल की तारीफ करते हैं, इंडियुजनिज्म और उस अनडेवलप्ड स्टेट की नहीं। लेकिन उसी में हमारे नदी, गम, कृष्ण, ईसा वगैरह रहे हैं, उसे इन कन्टेन्ट की निगाह से कैसे देख सकते हैं। उस जमाने के जज़बान की भी कद्र करनी पड़ेगी। वह राइट टाइप का फिल्लिप्स ज़िन्दगी था। वह सच्चाई पर, मोहब्बत पर, टिकी थी। हमको भी चाहिये कि कुरबानो कर सकें और मच्चे बन सकें।

यह मतलब कि हम आपको थ्रेट दे सकते हैं। हम आपको क्या थ्रेट देंगे। हम तो खुद इस समय अपने दिन गिन रहे हैं, याद रखिये कि जब आप एलेक्शन जीते तो हमने जर्मीदारों ने, छोटे जर्मीदारों ने एलेक्शन कराके आपको जिताया। यह ख्याल करके कि ये अपने भाई हैं, गैर जोगों की हुकूमत से इनकी हुकूमत जरूर दुस्त होगी। यह हमारी माली हालत को दुस्त करेंगे, हमारी तकलीफों को रफा करेंगे। हमने ही प्रोपेगेंडा किया था कि इनको वोट दो, हम गुलाम हैं, आजादी हामिल करो। पर हम देखते हैं कि हमें ही कल किया जा रहा है, हमें ही बरबाद किया जा रहा है। वे यह नहीं समझते कि हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। अगर आप वह समझते हैं कि किसानों से यह कहने में हमारा बड़प्पन होगा कि तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा गुलाम तो वह गलत चीज होगी। इससे वह अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जायेंगे। चीज यह है कि इज्जत के साथ रहने के माने वह यह समझते हैं कि लोटी लेकर घूम और वक्तमीजियां करें। आपकी इस गालिमी ने बदमाश डंडे लेकर घूमेंगे। क्या आपको मालूम नहीं इलेक्शन के जमाने में कलकत्ते में क्या हालत हुई? जो कोई इस इलेक्शन की फ़िज़ा में आया कि डण्डे चले। डण्डेबाज इसने घूमते हैं और कोई पूछे तो कहते हैं कि हम लीडर हैं। मैं कहता हूँ इस तरीके से काम नहीं चला करते। जिस जहानियत को आप पंदा करेंगे जिस तरीके को आप आर्गनाइज करेंगे वैसा ही होगा। जो आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं उनका दिमाग आप दुस्त कीजिए। मिर्ज़ा - क दिन आपको यानी वोटों के दिन आपको उनका बड़प्पन मानना पड़ेगा और आपको साफ तौर पर कह देना चाहिये कि अगर आप हमको अहल समझते हैं तो हमको आप वोट दीजिए। और बाकी दिनों मैं आपको उनको समझाना चाहिये और उन्हें गाइड करना चाहिये, और उन्हें सही रास्त पर लाना चाहिए आपको कह देना चाहिये कि मुल्क के लिये जरूरत होगी वह करेंगे। वह जमाना चला गया जब कि देहात में चोग पड़े सड़ा करते थे। आप मेजरिटी पार्टी को अपने साथ जरूर रखिये, लेकिन जो चीज अनजस्टीफाइड है उसको खत्म कर दीजिये।

मैं मशकूर हूँ जनाब प्रीमियर साहब का कि उन्होंने हमारी तरफ से यह आर्गुमेंट पेश किया और मोशल्लिस्ट भाइयों से वह कहा कि आपने इमी बिना पर इलेक्शन जीता है। आपके इलेक्शन का मनीफेस्टो यही है कि आप एडीक्वेट कम्पेन्सेशन ( काफी मुआविजा ) दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि वह आपको नज़र आता होगा, लेकिन बकरी को खुद कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप हमें बलिदान का बकरा न समझें और हमारे फंडामेंटल हक़ की हिफाजत करें। उसके बाद आप मेजरिटी की तरफ देखिये। यह डेमोक्रेसी कुछ अजीब चीज है। तीन आदमी हैं और उनमें से दो आदमी यह कह देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा तो

मय चीज गवर्न ही हो गयी । यह मय गवर्न प्रिमिपल् है । सोशलिस्ट साहवान ने रिडिस्ट्रीब्यूशन की स्क्रीन पेश की । आम्की हुकूमत के जो हेड्न् हैं उनके पास उनकी फैंक्स् और फिगर्स आई होंगी । लेकिन क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन १० बरस तक हो जायगा ? १० बरस में क्या होगा कौन जानता है । दो साल में तो यह हो गया । मेल्ल कल्टीवेशन इस कदर खूबसूरत चीज है लेकिन रुपया कहां से आयेगा । क्या आप देंगे ?

यह जरूर है कि इनसे आप काफी रुपया लेंगे । जो फन्डामेंटल नीड्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं ।

विलेज पञ्चायतों को लीजिए । इस मुहकमे से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं । बहुत दिनों तक मैं ओकल मेल्ल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूं । मैं इसकी हालत को खूब अच्छो तरीके से देख चुका हूं मैं अच्छी तरह जानता हू कि लोगों की जहनियत और तझ-ख्याली एक दिन में नहीं दूर हो सकती है । धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोपेगेंडा होते होते यह चीज एक जन-रेशन के बाद दूर हो सकती है । बहरहाल जो कुछ हम लोगों ने किया है, चाहे सही किया है चाहे गलत किया है, वह एक एक्सपेरीमेंट है । अगर गांधियन फल्सफा कामियाब होता है तो बेड़ा पार है और अगर नफरत के फल्सफा की तरफ लोग झुकते हैं और लोगों में एक दूसरे को तबाह करने का अरमान होता है तब तो गूदा ही हाफिज है ।

अब मैं इन्फ्लेशन सिचुएशन की तरफ आता हूं । मैं बिल्कुल ऐग्री करता हूं प्रीमियर साहब से कि जहां जहां तक इन्फ्लेशन सिचुएशन का ताल्लुक है “इट इज वेरी डेन्जरस” यानी यह बहुत ही खतरनाक है और इससे तमाम तबाहियों के मज्राहिरे हमारे सामने आ रहे हैं । इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने ब्राण्ड वाली स्कीम को खत्म कर दिया जिससे ४ करोड रुपया आपको मिलता । कम्पेन्सेशन आपको देना पड़ेगा कानून यह कहता है । जूरी-स्पूडेंस है और ला है । जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, मैं निहायत मश्कूर हूं कि इसका फैसला आपने स्लैब बेसिस पर किया है । एवालिशन कमेटी की दूसरी स्कीम यह है कि कम्पेन्सेशन का विभिन्न आधार पर दिया जाना गलत है । आप कहीं हमारी जिन्दगी को तबाह और बर्बाद न कर दें । हमारी कौम को तबाह न कर दें । अब जो एक्सेकशन होगा उसमें कहीं जमींदार सोशलिस्टों से न मिल जायं । हम अपनी कौम के लिये और मुल्क के लिये जान दे देंगे । हमारे पास रुपया न हो और हम रुपये से चाहे मदद न कर सकें लेकिन हम जान की कुरबानियां देने के लिये हर वक्त तैयार हैं । आपके साथ खुदा की रहमत है और महात्मा जी की दुआयें । कश्मीर में आप कामयाब रहे तो खुदा की इमदाद थी । हैदराबाद में कामयाब होने की वजह से आपका सदर्न डिफेन्स बहुत मजबूत हो गया । उसी तरह आपका ईस्टर्न डिफेन्स भी मजबूत हो गया । आज कल जो मसायल हैं उन पर आपको ठंडे दिल से गौर करना है । बंगाल की हालत अभी काबिल इत्मीनान नहीं है जहां तक कि उसका ताल्लुक जालिम पबलिक से है । लोगों की शिकायतें हैं, आपको देखना चाहिए जब तक आप बढ़ने के लिये तैयार न होंगे वह सर झुकाने के लिए आमादा न होंगे । यह कम्यूनिज्म बंगाल में क्यों आया इस पर आपको गौर करना चाहिये । और शान के साथ उसको खत्म करना चाहिये । हमारी आइडियालोजी हमारे साथ होगी । फौजें भी हमारे साथ होंगी । हम जाने लड़ा देने के लिए तैयार होंगे । हर शख्स अपने मुल्क की भलाई के लिए जान लड़ा देगा । यह हमारा मुल्क है । आज कल यहां तबाहियां हैं, बर्बादियां हैं ।

[ श्री मुहम्मद यूसुफ ]

इंसान का कोई सवाल नहीं, हमदर्दी और रवादारी का कोई नज्जारा नहीं दिखाई देता। ऐसी हालत में हर शख्स पूछता है कि क्या करें ? हम जमींदार भी इस मुल्क के बाशिन्दे हैं। आप हमारे साथ रवादारी और बुलन्दी और मुहब्बत दिखलाइये। इस तरह जब आपने हमसे कहा कि तुम भी रवादारी से काम लो। आनकी सेवा है रवादारी, यह आपका कर्तव्य और फर्ज है। रफी साहब ने परमाया कि सीर और खुदकाश्त के काश्तकारों को टीनेन्सी बिन्ड पांच बरस के लिये रहने दो। हमारा दिल भर आया, हमारी आंखों में आंसू आ गये कि उनको नुकसान पहुंचता है। हमने मान लिया कि यह जिदगी दूसरे तरीकेसे बदल लें। काटेज इंडस्ट्रीज सीख लें, नौकरी कर लें और अपनी माली हालत ठीक कर लें और हमारी जमीन हमको दे दें। यह आपका गलत खयाल है। ओर अगर आपने किसानों को जबरदस्ती ज़मीन जोतने दिया और खाने में उसका गलत इंतज़ाज कराने दिया और इस तरह अगर आपने उनको बिना लगानी बना दिया तो आप उनसे गल्ल बसूल नहीं कर सकते। और आपकी 'थो मोर फूड' की स्कीम आगे न चलने पायेगी। तीन साल के बाद मुमकिन है कि आपके सामने कोई और शक्ल निकल आवे। इस तरह की स्कीमों को आपोरेशन से हुआ करती हैं, मुहब्बत से हुआ करती हैं। जो चीज आप पैदा करें वह मुहब्बत से पैदा करें, एक दूसरे की जरूरतों को देखें। अपने मफाद को देखें और दूसरे के मफाद को भी देखें। हर आदमी के साथ हुकूमत इन्साफ करे। अगर आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेजारिटी की अहमियत क्या रही ? यह अजीबोगरीब मेजारिटी है कि आप अपनी रिसिंसिबिलिटी को नहीं समझते हैं। आपको यह नहीं करना चाहिये कि माइनरिटी को कुरबानी का भेड़ा बना कर, फट फूट चढ़ा कर उसे मेजारिटी पर चढ़ा दे। यह क्या कंसेप्शन है आपका ? डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है कि अगर मेजारिटी है तो वह सबको जिन्दा रखने का उपाय करे।

मैं आपको यकीनी सुवारकवाद देता हूँ। आप यकीन जानिये मैं किसी खास मकसद में यकीन लब्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिये तो दिक्कत यह है कि अगर अंग्रेजी में तकरीर करूं तो दिक्कत, अगर उर्दू में तकरीर करूं तो दिक्कत। उर्दू की तो बात ही नहीं, हिन्दुस्तानी में अगर बांद्रं तब भी दिक्कत। यह अजीब तीतर बटेर का मामला हो रहा है। अगर बटेर की टूटी हुई टांग वाली उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोल्दं जो इस मुल्क में बोली जाती है और किसी दूसरे मुल्क में नहीं बोली जाती है तब भी बड़ी दिक्कत है। मेरे सामने यह बड़ी मजबूरी है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं ? इसे मैं अपनी बदकिस्मती ही समझता हूँ। मैं प्रीमियर साहब को पूरे तरीके पर यकीन दियता हूँ कि जहां तक कंसेप्शन के सिस्टम यानी तरीके का ताल्लुक है मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनको सुवारकवाद देता हूँ कि वह इस उसूल को काम में लाये हैं। लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा कानूनी मजबूरियों की वजह से किया है। लेकिन फिर भी मैं जमींदारों और ताल्लुकेदारों की तरफ से उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोगों के रिप्रेजेन्टेशन की वजह से आपने किया।

श्री एजाज़ रसूल— किसके रिप्रेजेन्टेशन से ?

श्री मुहम्मद यूसुफ हम लोगों के, और उसमें मैं शामिल हूँ। क्योंकि मैं आगरा प्राविंस जमींदार एसोसियेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमने गवर्नमेंट के सामने कोई दिक्कत नहीं पैदा की

है। हम कोई एलेक्शन रनिंग वाडी नहीं हैं। हमें कोई युद्ध या जंग करना नहीं है। जो सियासी कुञ्ज होनी, जो पार्टी होगी वे अपनी पालिसी के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन मैं कम्युनिस्ट ट्रेड्सयूनिंग केंद्रों के साथ ठेके के लिये हरगिज तैयार नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि नये जजमान होंगे, नया तख्तबुन होगा, नमदुन होगा, गौर होगा, फिक्र होगी, मुहब्बत की लहर दौड़ेगी और लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और जहाँ तक डिफेन्स का ताल्लुक है दुनिया के मुकाबिले में सभी न्यडे हो जायेंगे। मगर जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक है भाइनारिटी की सबसे ज्यादा और सबसे पहिले फिक्र करेंगे। जहाँ तक होगा ह्यूमन राइट्स और फण्डामेंटल राइट्स के ब्रैसिम यानी दुनियाद पर दुनिया के तमाम भाइनरटीज के मसले हल किये जायेंगे। दुनिया से बैनुअकवासी जंग को महात्मा गांधी के बमूल पर खत्म कर देंगे। तबके तबके और पार्टी पार्टी के दरमियान जो झगड़े हैं वे खत्म कर देंगे। गलत रजोगन से आप एलेक्शन में अब कामयाब नहीं हो सकते।

आज हमारा आजादी खतरे में है। इस वक्त हमें सच्चे माने में मुल्क की खिदमत के लिये तैयार रहना चाहिये। वार कन्डीशनस के लिये भी तैयार रहना चाहिये। हमारे यहाँ आइडियायोजीकल इन्वेज़न भी हो सकता है और फिजीकल इन्वेज़न भी हो सकता है उन सबके लिये आपको लोगों को तैयार करना है। लेकिन जब तक आप सब बातें समझ कर नबको एकजाँ और इकट्ठा न करेंगे तब तक आप उस मकसद को हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं ज्यादा बक्त न दूंगा लेकिन मैं यह कन से कम जरूर कहूंगा कि एक कोम जिसकी इकवादी मोत होने जा रही है, एक तबका यानी जमाँदार जिसने इतनी खिदमत की है उसकी कोई तारीफ भी नहीं होने जा रही है और वह तबका और बरवाद होने जा रहे हैं इस तबके के साथ आप मुहब्बत करें, इन्साफ का तबका अवेगन्यार करं उनसे कहें भाई आ जाओ भिउ जाओ, वे तर बुरा देंगे आपके आगे और कहेंगे कि हम खिदमत करेंगे अपने मुल्क की, अपनी कान की और अपनी जागों को भी उसी के लिये खपा देंगे। अब यह खुली हुई बात है कि यह खतरे का जमाना है और हमको अपने को इसको देखते हुए बदलना है, कांग्रेस आगेंनाइजेशन को बदलना है, उसके तख्तबुन को बदलना है, उसकी पालिसीज को भी बदलना है। नफरत के फिलसफे से हम और आप पनप नहीं सकते, न काँइ मुल्क पनपा है। आप देख लीजिये जर्मनी बदला, इटली बदला और चीन भी आज बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। (एक आवाज आप नहीं बदल रहे हैं)। मेरी नजर से तो जो हर रोज बदला करता है वह किसी काम का आदमी नहीं होता। खैर मैं अब ज्यादा बक्त नहीं लेना चाहता और न हाउस को ज्यादा दिक करना चाहता हूँ। (एक सदस्य : नवाब साहब, जय कम्पेन्सेशन पर भाँ रोशनी डालिये।) आपका तख्तबुन ही यह हो गया है कि विला खून की होली खेलें रिबोल्यूशन नहीं होता, वाहरे, आप हैं रिप्रेजेन्टेटिव गांधी जी के। यह कैसा तुम्हारा ढङ्क है। तुमको चाहिये तो यह था कि मुहब्बत की बिना पर, इन्साफ की बिना पर, खादारी के बिना पर और हमारे भाई की बिना पर हमसे कहते कि आओ मुल्क की खिदमत करो और मुल्क के लिये कुर्बानी करो और अपनी जान को भी निसार कर दो। यह सब चीज़ आपके सामने है, आप इन पर गौर करें। लिहाज़ा मैं इस्तदुआ करता हूँ कि हम लोग बहुत गरीब हैं और तबाह हाल हैं। किसी गुरबत के यह माने नहीं हैं कि गरीब वही है कि जिसकी माली हालत कमजोर हो या १०, २० कहीं से अपनी गुज़र औकात के लिये पैदा करता हो।

[ श्री सुब्रह्मण्यम् ]

लेकिन हमने जो डेरा की विद्वान की है, पुराने आर्डर को आप देखिये कि हमने इस सूचे के लिये क्या नहीं किया। हमने अस्मान और स्कूल, कांज बगैर में बहुत ही ज्यादा खिदमत इस सूचे की की है जो कि और किसी सूचे ने नहीं की है। हम यह कह सकते हैं कि महज हम ही लोग थे जिन्होंने इतनी जबरदस्त खिदमत सूचे की की है। सूचे की जिन्दगी से हमारी जिन्दगी बचता रहा है। हो सकता है कि जुल्म भी किये हों और नज़रबंद भी रहे हों लेकिन यह हिस्ट्री ही बतलायेगी, आप चाहे इसको नज़रबंद कर दें कि हमने सूचे के लिये क्या किया है और हमारा कानून इस सूचे से कितना रहा है। इन अल्फ़ाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

\* श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल—जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जमींदार साहबान की विदमत में चन्द फ़िकरे नज़र के अर्ज करना चाहता हूँ।

डिप्टी स्पीकर—जो प्रस्ताव ज़रे बहस है आप उसी के मुताल्लिक कहना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल—जी हाँ, उमी के मुताल्लिक यह है।

मेरे जन्मे मुहब्बत में बड़ा की है फिरावानी,  
रहा करती है दिल को जुस्तजूए दर्दे इंसानी,  
इसी में मुद्दतों राहे वफा की खाक है छानी,  
गहे कैदे सितम में मुद्दतों तक बन के जिन्दानी,  
यह दिन फ़जले खुदा मे जो मयस्सर हमको आया है,  
अगर सच पछिये तो जान देकर इसको पाया है। १।

किमानों की हमें उजड़ी हुई दुनियां बसाना है,  
जमींदारी की दुनियाए मजग़लम को मिटाना है,  
सितमरानों के कन्दों ने गरीबों को छुड़ाना है,  
हमें दस्तेक़रम में रक आईना बनाना है,  
वह आईना कि ज़िम्मे एक मो ग़रब नज़र आए,  
तनीजे बन्दी आक्र की दुनियां खत्म हो जाए। २।

ज़माने में किया बरनाम किसने आदमियत को,  
लगा दी आग किमने “शाद” दुनियाए मुहब्बत को,  
घटा के क़ौम की इज्जत बढ़ाया किसने ज़िल्लत को,  
छुपाया किसने दुनिया की निगाहों से हकीकत को,  
जमींदारी की यह सब शिद्दतों का बोल बाला है,  
इसी के जोर ने देहांत में ग़ुरबत को पाला है। ३।

कलेज धान लेगे अहले दिव मुन मुन के अफसाना,  
हमाग़ ज़िक्र क़ब्र, रीत है जो मुनता है बेगाना।  
नज़र अन्ता है बीराना जहां कल था परीखाना,  
जमींदारी के हाथों लुट गया इज्जत का काशाना,  
बनौना के हैं फूल और आसमानों के ये तारे हैं।  
किसान अपनी हुकूमत को जमाने भर में प्यारे है। ४।

माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

किसानों की यह हाथन बट्ट में बदतर किसने कर डाली,  
नयत्सर ही नहीं होती उन्हें दुनिया की गब्रहाली,  
जमींदारी की कूबत ने मुसीबत उनपे यह डाली,  
कि जिससे रात दिन होती रहे इन सब की पामाजी,  
सितम का जोर है गुरवतज्जदा आफत के मारे हैं।  
यह फरियादी मजालिम के हुक्मत के सहारे हैं ॥ ५।

हुक्मत का है फजें अब्बली फरियाद मुन लेना,  
रिआया परवरी करना रिआया को मदद देना,  
हमें अद चाहिये है दामने उम्मीद भर देना  
जो बादा कर लिया है उसको पूरा आज कर देना,  
जमींदारी को कर दें खत्म दुनिया में उजाला हो।  
किसान आजाद हों और कांग्रेस का बोलचाला हो ॥ ६।

फिजाए गुलशने आलम की यह खामोश तसवीरें,  
मजालिम की हदों में आ गई थीं जिनकी तकदीरें,  
खुदा ने बरखा दी उनकी दुआओं में वह तासीरें,  
निकटवा दी हजारों साठ के कब्जे की जागीरें,  
पच्छ डाला जमींदारी का तग्वना उनकी आँखों ने।  
जमींदारों को बेकस कर दिया उनके गुनाहों ने ॥ ७।

किसान आजाद होकर कूबतें अपनी बढ़ायेंगे,  
सियासत में तद्वर में यह आगे बढ़ते जायेंगे,  
तिजारत में तरक्की करके दुनिया को दिखायेंगे,  
उठूमे मशरिकी से फैजे रूहानी उठायेंगे,  
नज़र आयेंगे जलवे हर तरफ हिन्दोस्तां भर में,  
हर एक फन में तरक्की होगी हर देहान के घर में ॥ ८।

खुदा हाफिज रहे ऐ “शाद” इस बरमे हुक्मत का,  
कि जिसने नाम रोशन कर दिया क़ौमी सियासत का,  
यह बिल का पास हो जाना नमूना है शियाकत का,  
जमाना भर मोअरिफ होगा इस फ़ेहम्मे फ़रासत का,  
दिखाई शाहिदे मक़सूद ने शकले मसीहाई।  
लगा दें साकिया होठों से मरे जामे सेहबाई ॥ ९।

जनाब वाला, अभी दो शेर और हैं। ये शेर जमींदार पार्टी के दफ्तर पर कुन्दां थीं।  
शायर की हैसियत से जहां गरीबों के मुहल्ले में जाता हूं, वहां राज दरबार में भी गुजरने का  
इत्तिफाक होता है। मुत्ताहिजा कीजिये, शेर अर्ज करता हूं :

“श्रीमार की आंखों का इशारा है दमे नज़ा,  
जाती हुई दुनिया हूं मुझे देख लो आके।  
फरियाद है ऐ शहरे खामोशों के मकीनो,  
तुरबत ने दबाया है अकेला मुझे पाके ॥

\* श्री कन्वरल इन्जाम—जनाब वाला, यह बिल हमारे सामने ७ जुलाई को रखा गया था। वह दिन इस ऐवान की तारीख में एक यादगार का दिन रहेगा और सिर्फ इस ऐवान में ही नहीं बल्कि इस ऐवान की वरसरे इकतदार पार्टी यानी कांग्रेस की तारीख में एक तारीखी हैसियत रखेगा। और इस ऐवान के बाहर, इस मुल्क के रहने वाले गरीब और अमीर दोनों के सामने एक नज़रिये हयात रखा गया जो यकीनन तीन हैसियतें रखता है, और रखेगा एक सियासी, दूसरी इकतसादी, जिस में जमींदारों की इकतसादी, तंगी और खराबी और काश्तकारों की बहुत हद तक भराई और वहबूरी होगी। और तीसरी इस बिल के अन्दर एक सोशल पहलू भी है और मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही अहम और जरूरी है। जब जमींदारी अवॉलिशन के मुताल्लिक तजवीज इस हाउस में पेश हुई थी उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास के जमींदार, बड़े जमींदारों के लिये नही कहता, बल्कि मिडिल क्लास के जमींदार यह महसूस करते हैं कि वह अपने पैरों और हाथों को ज्यादा जरूरी और मुनासिब कामों की तरफ नहीं लगा सकते जिससे वह अपनी तरक्की कर सकें और मुल्क के अन्दर एक नायनाज् जगह हासिल कर सकें। दुनिया में जहां तक तिजारत का ताल्लुक है, उसमें हर एक शख्स नज़र रखता है कि अपनी अक़ल और होशमन्दी बढ़ाये, किसी तौर पर काहिल न हो और तरक्की कर सके। लेकिन जमींदारों का ऐसा होशमन्दी और तरीका रहा है कि जिससे इन्सान बेकार, काहिल और बहुत हद तक खराब हो जाया करता है। इसलिये जहां तक मिडिल क्लास का ताल्लुक है इससे उन लोगों की बहुत ही बुलन्दी होगी और उनमें जो कुछ भी खराबियाँ और काहिली पैदा हो गई है वह दूर हो जायगी। यह जरूर है कि इससे उनकी आमदनी कम हो जायगी और उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर तकलीफ में सहत और हर इनकशाय में एक नयी जिन्दगी है, एक नई रूह है। इसलिये मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास जमींदारों के लिये यह इनक़ाब की शरूक है उसे खुशामदीद कीजिये। आज से वह अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी क़वत और बाज़ू के जोर से अपनी रोजी कमायेंगे।

जहां तक इसका सियासी पहलू है वह बहुत ही अहम और जरूरी है। जब से ब्रिटिश साम्राज्य की क़त्ते आयीं, उन्होंने अपने चन्द उम्मीद मुरत्तब किये। उन्होंने सबसे पहले जिलों में बुनियाद रखी। वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक बहुत बड़ी पोस्ट रखी उसके बाद एन० डी० ओ०, तहसीलदार, स्थान आफ़ेउर और उसके बाद गांव के अन्दर एक जमींदार, एक पटवारी, एक चौकीदार और एक मुखिया को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखी। इस तौर से इस मुल्क की गरीब जनता के ऊपर उन्होंने हुकूमत शुरू की। मैं तमाम जमींदारों के लिये नहीं कहता, लेकिन आम तौर से ये जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट के आलाकार रहे। और इस तरह से खानबहादुर और रायबहादुरों के जरिये से मुल्क के अन्दर हमारे सामने रिपब्लिकनी फोर्स (प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ) आईं, और वह हमारे सामने हैं। मैं जानता हूँ कि जमींदारों ने इस सूत्र की तामीनी और कन्वरल (सांस्कृतिक) हालत को बढ़ाने में मदद की। वह इस ऐवान को खुद मान्दम है। वह सही है कि इसके मुताल्लिक उनके बहुत बड़े कारनामे हैं। लेकिन उनके सियासी कारनाने जो हैं उनको न तवारीख भूल सकते हैं, और न यह ऐवान भूल सकता। इसलिये

\* माननीय सदस्यने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मैं समझता हूँ कि सियानी तौर पर यह विध खास अहमियत रखता है। मुझे डर था, मुझे ख्वाब था कि कहीं कांग्रेस भी पावर में आने के बाद, उनकी दावतों और मोटरों और जैसा कि बाज जिलों के अन्दर हुआ है, उसके जोर से अपनी राय बढ़ा दें और जमींदारी के खाल्मे को रोक दें। जमींदारों की तवारीख बतानी है कि इन्होंने कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं समझता था कि ये कांग्रेस के इसलिये मुखालिफ हैं और खहर पहनना इसलिये गुनाह समझते हैं कि कांग्रेस के उसूलों को गलत समझते हैं। लेकिन जब से आप बरसरे इक्तदार आये हैं मैं यह महसूस करता हूँ कि आज उनके दिमागों के अन्दर कांग्रेस की अहमियत घुस गई है और मिनिस्ट्री की खुशामद करना और उनके चश्मे आवरु पर चलना यह लोग अपना दीन और ईमान समझते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज के ऐसे अफराद को हमारा फर्ज है जिस तरीके से भी हो, मैं उनके खिलाफ नहीं कहता बल्कि इस ज़हिनियत को कुचलना चाहिये। इस ज़हिनियत को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिये ताकि इससे नई फ़िजा हमारे मुल्क में पैदा हो और इसान की जो सही राय है उसका इजहार हो। लागू क्या कहने हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, यह नहीं बल्कि उसकी एक राय होनी चाहिये। लेकिन आपने हवा के साथ ही अपना रुख बदल दिया। आज यह बुनियादी चीज है कि हर आदमी कहता है कि जमींदारी खत्म होनी चाहिये ताकि मुल्क में नई फ़िजा पैदा हो। जहाँ तक इसका सियासी पहलू है वह मैंने आपके सामने रख दिया। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह मुनासिब और जरूरी इकदाम है जिसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट और हमारा हाउस आगे बढ़ा है।

जहाँतक जमींदारों का ताल्लुक है उनके दिन् में भी एक अहसास है। वह सही है और वह हक बजानिव है। वावजूद इसके कि मैंने उनके खिलाफ इतनी बातें कही हैं लेकिन मैं मजबूर हूँ यह कहने के लिये कि कम्पेन्सेशन इक्विटेबिलि मिलना चाहिये। यह बिल्कुल मुनासिब है। इसलिये नहीं कि उन्हें मार्केट प्राइज (बाजारू कीमत) मिलनी चाहिये। इसलिये नहीं कि मैं इस का हामी हूँ। मैं तो इसका मुखालिफ हूँ। गवर्नमेंट जब अपनी पालिसी को सही और मुनासिब तरीके पर चलाना नहीं चाहती है, वह अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर (ढांचे) को जिसकी बदौलत वह इतनी आगे बढ़ी है नहीं बदलना चाहती है। अपने उसूलों से आगे नहीं बढ़ना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि जमींदारों का यह कहना कि कम्पेन्सेशन मार्केट वैल्यू के लिहाज में मिलना चाहिये, सही है। अगर आप चाहते हैं किसी में कोई फर्क न हो, अमीर गरीब का कोई फर्क न रहे और सबको एक लेवल (सतह) पर लाना चाहते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपके जमींदारों ने कौन सा ऐसा कसूर किया है कि आप उनको सबसे पहले लेते हैं। इसकी कोई बुनियाद होनी चाहिये। आज आप जमींदारों के खिलाफ बोल रहे हैं उनके दिल में यह चीज चुभी और उनके दिल में एक क्रिस्म का गुस्सा और नाराजी पैदा होती है। जब आप यह समझते हैं कि इस मुल्क के अन्दर के गरीब और अमीर का तफर्का मिट जाना चाहिये। अगर यही चीज होती तो जमींदारों को कोई एतराज न होता। लेकिन आज कैपिटलिस्ट्स तो मोटरों पर चढ़े फिर रहे हैं और बिचारे जमींदार जो कल तक नवाब थे उनको आप कह दें कि फकीरी अख्तियार कर लो। यह कैसे मुमकिन है। उनके दिल में इससे एक गुबार पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द तवज्जुह होना चाहिये। यह नाइंसाफी क्यों है। अगर आप कैपिटलिस्ट्स को खत्म



## [ श्री जम्मू इत्यादि ]

करते हैं तो जमींदारों को भी खबर कर दें। इसमें कम्पेन्सेशन का कोई मसाला पैदा ही नहीं होता। आप कम्पेन्सेशन देकर उन लोगों को फिर से जिन्दा रखना चाहते हैं और उनकी मौत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब एक प्रिन्सिपल (विद्वान) तै हों गये तो उनका जारी करना चाहिये और देखना चाहिये कि उसके नतीज क्या होते हैं। तनान स्कीने साथ ही साथ चर्चाई जाय तो नई नयन निकटेंगे और एक एटनासफियर (वातावरण) बनेगा। एक व्यक्ति दोन ने कहा कि वह नव कम्प्युनिस्ट हो जायेंगे, ऐसा ब्याल दुरन्त हो सकता है। आप को सोचना है कि जमींदारों के बच्चों का क्या इन्तजान होगा और यह स्टेट का फर्ज है वना यह सह है कि वह कम्प्युनिस्ट और रिक्वेस्टनरी बनेंगे। आप उनकी दुश्मनी में यह ऐक्ट नहीं थिये हैं और उनको अच्छे नागरिक बनाने के लिये थिये हैं और आपको सोचना है कि आप उन की भर्खा के लिये क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इस बिल के पढ़ने के बाद कहीं पर भी यह नहीं देखते कि जो नकराज है जिनकी जायदाद रेहन हैं उनका क्या ह्श्र होगा। इसका इस बिल में कोई बिक्र नहीं है लेकिन आन्तरेबिल प्रीमियर साहब ने अपनी तकरीर में इन्तारा किया था कि इन के नुनालिक दूसरा बिल आएगा ता उससे सन्तोष हो जायगा। और जो जायदाद हमारे की जा रही है उसके एवज में कजें में भी कोई रिआयत हो सकेगी। ऐसा होता तो उनके सामने भी दूसरा नजरिया होता और उनको कुछ इत्मीनान होता। लेकिन बहरसूरत जो वक्त का नफाजा है इस वक्त जमींदारों की जावन सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप ही इस नुक्क और सलनन के सबसे प्यारे और दुलारे रहे हैं, आप भी बजोर रह चुके हैं और हुकुमत कर चुके हैं, यकीनन आज नहीं हैं लेकिन आप एजूकेशन के पायनियर हैं और आप को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिये कि आप इस सूत्र में इक्तादी दुनिया में पायनियर्स (अग्रगामियों) की हैसियत रखते हैं और आज भी आप दुनिया को दिखला रहे हैं कि हम अपनी उस जायदाद को जो हम अपने खून पीने से बनाई थी कम नुआवजा लेकर ही दे रहे हैं। आपको इस बात पर गौर करना चाहिये कि इससे किसानों की माली हालत पर क्या असर पड़ेगा और काश्तकारों की जो आपसे तक्को थी वह कहाँ तक पूरी हुई। इस बात पर आप को गौर करना है और यही सबसे बड़ा और अहम मसाला है और जरूरी पहलू है और इससे हमारे मुल्क की इक्तादी हालत पर क्या असर पड़ता है। काश्तकारों के लिए यहां सन् २१, २६ और ३९ में काफी रिफार्म हुए, आपके पहले भी हुए और आपके जमाने में भी हुए। और सन् २६ का एक्ट जमींदारों ने अपनी हॉसलामन्दी से ही लागू किया था और बहुत से हक्क काश्तकारों को दिये थे। देखना यह है कि जमींदारों के हटने से काश्तकारों को क्या फायदा होता है। कुल बिल को देखने के बाद यह पता नहीं लगता कि जमींदारों के हटने के बाद आखिर वह कौन सी एजेन्सी के होगी जो इन इण्टरमीजियरीज को हटा कर इनकी जगह लेगी। कौन होगी आप बतलाइए? एक जगह यह जरूर लिखा है कि यह चीज रूल्स के जरिये से मुरत्तिव होगी और बताया जायगा कि फलां फलां रूल्स से होगा। मैं यह नहीं समझता कि यह कहा तक मुनासिब है कि इस मामले को एवान में न लाकर आप रूल्स के जरिये से बतलावें कि आप किस एजेन्सी के जरिये से अपना काम चलावेंगे और उस एजेन्सी का बिक्र तक इस बिल में मौजूद नहीं है और न कोई हवाला ही है और न अमल में लाने का कोई तरीका ही दिया गया है जिससे इस हाउस के मेम्बरान उस पर गौर कर सकते

और आई और तर्मीम या बेहतर तरीका आप के सामने पेश कर सकते। अगर मैं यह समझूँ कि आपने वही तरीका तहसीलदारों, कोर्ट आफ वार्डस या कुर्क अमीनों का अखिनयार किया वसूली का, तो मैं अन्दर से गुजारिश करूँगा आपने एक मामूली जमींदार को हटा कर जबरदस्त जमींदार को जगह दे दी है। इस ऐक्ट में बहुत से मेम्बरान को कुर्क तहसीलदार या कुर्क अमीन का तजुर्बा होगा किम तरह से वह तहसीलों में जाकर रुपया वसूल करते हैं। हर शख्स जानता है कि वह उस तरह से, जिस तरह से जमीन्दार नजराना लेता है, रसीद लिखता है तो लेता है, यह तमान कार्यवाहियां करते हैं और हजारों गवाहियां आपको इस सिलसिले में मिल सकती हैं। मैं समझता हूँ कि यह निश्चयत नाइन्साफी है। मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर विचार किया जायगा और बेहतर यही होगा कि गांव पंचायत या गांव समाज के सुपुर्द ही आप काम को कर दें। जब वह लोकल फण्ड्स रेज (मुकामी चन्दा वसूल) करेंगी तो कलेक्शन (वसूली) का काम भी बहुत आसानी से कर सकती हैं और उन पर ट्रस्ट (एनवार) किया जा सकता है कि वह रुपये को वसूल करके गवर्नमेंट ट्रेजरी (खजाने) में जमा कर दें। कुर्क अमीनों का जो तरीका मैंने बताया काश्तकारों के लिए मुसीब साबित नहीं होगा।

दूसरा सवाल एक और है जो बहुत अहम और जरूरी है वह यह कि कम्पेन्सेशन का तरीका क्या होगा इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। कम्पेन्सेशन आप किस तरह से देंगे, आया वह बांड की सूरत में होगा या कैश (नगद) होगा, इसके मुताबिक आप बिल्कुल खामोश हैं। इसका कोई जिक्र बिल में नहीं है। आप कह सकते हैं कि बड़े जमीन्दार इस मुल्क के ऐसे हैं जिनके पास कुछ सरमाया है और वह उसे खा पी सकते हैं लेकिन जैसा कि आप कहते हैं २० लाख का तादाद ऐसे जमींदारों की है जो छोटे जमींदार हैं, जिनको जमींदार कहना गलत है। उनके लिए आपने क्या तरीका सोचा है। आप उनको कैश देंगे या बांड देंगे। मैं समझता हूँ कि आप उनको कम्पेन्सेशन कैश दें ताकि वह किसी दूसरी लाइन में जा सकें और अपने कामों को मुनासिब तौर पर कर सकें और सोसाइटी पर एक बार न हों।

अब मुझे यह देखना है कि काश्तकारों की भलाई के लिए आपने इस बिल में क्या किया है वजुज इसके कि आपने टेनेन्ट्स ३ किस्म के बना दिये। एक को १० फीसदी देने के बाद आप उनको ट्रान्सफर राइट्स देते हैं। यह एक ऐसी डिमांड थी जो काश्तकार और इस मुल्क की जनता और यहां की सियासी जमातें और आप लोग भी यह कहते थे कि माजुदा टेनेंसी ला के अन्दर ट्रान्सफर राइट्स दे देना चाहिये अगर आपने ऐसा किया तो कोई बड़ी निधामत आपने काश्तकारों को नहीं दे दी जब कि यह आम मतान्त्रा था और हमेशा से था कि ट्रान्सफर राइट्स को हर हालत में मिलना चाहिए, चाहे वह १० फीसदी दे या न दे। यह तो वही मसल हुई कि एक घोड़े के सामने एक गाड़ी लाकर खड़ी कर दी और कहा कि पहले दस फीसदी दो तब हम ट्रान्सफरेबिल राइट्स देंगे। यह तो कोई अच्छी चीज काश्तकारों के लिये नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अगर उसे परमानेंट राइट्स मिलते हैं तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा ५ परसेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हाना चाहिये। अगर स्टेट को कोई नुकसान होता है तो जो इन्टरेस्ट (सूद) स्टेट एक्जुमुलेट (जमा) करेगी, उसमें वह कम्पेन्सेट (पूरा) कर लेगी। इससे जमींदारों को जो कमिटमेंट (वादा) है उसमें भी पूरा करने में कोई जहमत न होगी।

[श्री फ्रान्ज इस्गम]

इसी मिलमिले में मैं यह भी कह दूँ कि कारनकारों के लिये आपने जो तरीका रक्खा है वह गौर नज़र में और उन पर देखना और सोचना है। उनसे काश्तकार कहाँ तक फायदा उठा सकते हैं और कम्पेन्सेशन जो आपने रक्खा है वह कहाँ तक मुनासिब है। आप इस पर भी गौर करें कि आपने इन सूबे के जमींदारों के लिये कुछ न कुछ दिया है या बड़े बड़े कारनकारों के लिये आपने कुछ इन्जामान दिये हैं, लेकिन आपने उन कारनकारों के लिये क्या किया जो आज सूबे में सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं, जो सनाज के लिये, सोमाट्टी के लिये एक भार हैं और जिनकी हालत देख कर हर इन्सान खून के आँसू रो देता है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर इनकी हालत क्या दुखाने वाली है। इस बिज़ के अन्दर उनके लिये न कोई मदद है न कोई सहाय, जिसमें कि उनके अच्छे तालीम हासिल कर सकते, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वे अपने अच्छे का नाम स्कूलों में लिखा सकें, या उनके खान पीने का इन्जाम कर सकें। अगर आप देखना में जाय तो हजारों बच्चों का आप नंगे देखेंगे, आंगवें दबी हुई हैं, खून तो बदन में जैने हैं ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप उन कारनकारों के लिये क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह रिपोर्ट जिस पर आपने हजारों रुपया बरबाद किया है बिनाकुल बेकार है और इसे रद्दी की थोकरी में फेंक देना चाहिये। जब कि आपने उन गरीब और मुसीबत ज़दा कारनकारों के लिये कुछ नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट फिर किसके लिये है। इसे तो जरूर रद्दी की थोकरी में फेंक देना चाहिये। (आवाज़ें—खूब, खूब) उस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं जिससे मालूम होता है कि वे इस रिपोर्ट के बड़े हामी हैं। मुझे वह बात गाने की कोशिश करें कि इसमें क्या बान रखी है। कम्पेन्सेशन के बारे में क्या डिस्मिशन (फैसल) है, टेनेन्सी के बारे में क्या स्कीम है और दूसरे मामलों पर क्या डिस्मिशन है। यह ज्यादा अच्छा होता कि अमीर राजा साहब अपने कमरे में बैठ कर एक रिपोर्ट तैयार कर दें और हमारे सामने रख दें। वह डिपार्टमेंटल रिपोर्ट होती जिसमें स्टेटिस्टिक्स (आंकड़े) होते और उनकी बिना पर हम कुछ समझ सकते। मैं फिर पूछता हूँ कि इस बिज़ के अन्दर उन मुसीबतज्जदा किसानों के लिये कुछ जिक्र किया गया है? जहाँ तक अनएकोनामिक होमिडिंग का सवाल है और छोटे लोगों के रिलीफ (इमदाद) का सवाल है वह कहाँ तक दिया गया है कितना दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ। और क्या वह रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है? (एक आवाज़—शायद आपने बिज़ को नहीं पढ़ा है) इन तौर पर मैं समझता हूँ इन कारनकारों की तरफ आपको कुछ तवज्जह देनी चाहिये और गौर करना चाहिये कि ऐसे लोगों को जो २ ६०, ३ ६० या ४ रुपया लगाने देते हैं उनके लगान में आप को रेमोशन (छूट) करना चाहिये। आप ८ आना रुपया, ४ आना रुपया या २ आना रुपया कुछ भी रेमीशन करें लेकिन मैं यह कहूँगा कि रेमीशन की जरूरत है। अब भी अगर आप कर सकते हैं तो करें कोई हर्ज नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में उसे करा दीजिये।

सबसे आखिर में जो सवाल है वह लैंडलेस लेबरर्स का है। उनके लिये भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। कहाँ भी उनका खाल नहीं रक्खा गया है। अमी मेरे एक दोस्त ने एक शेर पढ़ा। शायद उसका मतलब यह था कि ऐसे लोगों की ऐसी हालत कुछ दिनों के लिये और रहने दी जाय ताकि वे उनके ऊपर हुक्मन कर सकें और उनको गलत या सही रास्ते पर जिस पर वे ले

जान चाहें ले जा सकें। मैं नहीं समझता हूँ कि लैंडलेस लेयरर्स के लिये कोई तजवीज़ इस बिल में की गई है। आखिर वह कहाँ जावें। आखिर उनके लिये समाज में क्या जगह होगी। अफ़सूस इस विध के अन्दर उनको कोई जगह नहीं है। और न यही बताया गया है कि उनके साथ कैसा सुन्दर किया जायगा। आप खुदकास्त की हद सुकरर कर दीजिये।

कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार मेम्बर और कास्तकारों के बड़े हमदर्द अभी यह फरमा रहे थे कि कास्तकारों को यह मौज़ा दिया जाय कि अगर एक साल वह चाहें तो दूसरे किसी किसान में कास्त करा ले और वह बेइखल न हो। मैं तो कहता हूँ कि जो आदमी ६ महीने भी कास्त नहीं करता है वह बेइखल होना चाहिये। किसी शख्स को हक हासिल नहीं कि वह खुद कास्तकारो न करे और उससे फायदा उठाये। जिसे ज़मीन में कोई हक नहीं होगा उसे ज़मीन से क्या मोहब्बत होगी, क्या जोश होगा और कैसे खेती बढ़ सकती है। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी खेती करे और दूसरा उससे फायदा उठाये। (एक आवाज़—अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आप का बैल मर जाता है तो आप क्या करेंगे।) एक आदमी के बीमार होने से कोई काम नहीं रुक जाता है। दूसरे आदमी रहेंगे, उनके मुआजिम रहेंगे। भाई भीजे रहेंगे और आबक़ूत की बीवियां भी काम कर सकती हैं। यह कोई सवाल नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि लैंडलेस लेयरर्स की तरफ आप को तवज़ुह देनी चाहिये। उनकी तरफ आपको गौर करना चाहिये। उनके लिये आप क्या करते हैं आपको तो यह देखना है। वे दबे हुये लोग हैं। उनके लिये अवश्य ही कोई मुनासिब ओर जरूरी सज़ारा होना चाहिये। तभी वे मुनासिब तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और इसी तरह पर हमारी और हमारे मुक्त की तरफ़ी हो सकती है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इस तरह से मोटी मोटी बातें आपके सामने मैंने रख दीं और आशा है कि आप उन पर ध्यान देंगे और आप सोचेंगे कि इन बातों पर आप क्या कर रहे हैं।

एक और बात यह है कि गांव सभा और गांव समाज क्या चीज़ है इस चीज़ को मैं समझ नहीं सका। यह क्या है? क्या वे पंचायत राज सभा से डिफरेंट (मुख्तलिफ़) होंगे, क्या उनका नाम यह रख दिया जायगा। इनका इलेक्शन कैसे होगा? ये सब बातें हम विध में नहीं पाई जाती कि ये लोग किस तरह से आयेंगे और किस तरह अपने काम का मुधार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

फिर इसके बाद मैं और मसालत पर बोलूंगा। अभी मेरे एक सोशलिस्ट दोस्त ने यह बतलाने की कोशिश की है कि वक्फ के मसले में यह बिल मुनासिब कार्यवाही नहीं करना है। मैं समझना हूँ कि जहां तक वक्फ का ताख़्त है गवर्नमेंट ने बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर तरीका अख्तियार किया है। मुझे भी वक्फ बोर्ड में काम करने का मौक़ा मिला है। तजुर्ब की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि आजकल औकाफ की बहुत ही खराब हालत है। उनका हिसाब किताब, उनकी आमदनी और उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुतबल्लियान बहुत ही नाजायज़ और गलत तरीका अख्तियार करते रहे हैं। आपने एक मुनासिब कदम यह उठाया है कि जितना चैरिटेबिलि और रेज़ीज़न्स परपज़ेज (खैरती और धार्मिक कार्यों) के लिये वक्फ होगा, चाहे वह १० हजार हो या ५ हजार हो, उतना आप मुतबल्लियान को देंगे। और वह उसको सर्फ़ करेंगे। इस सिलसिले में मैं इतना चाहूंगा कि वह अपना वक्फ बोर्ड या जो हिन्दू सभाज या बोर्ड या असोसियेशन हो उसके ज़रिये से मुतबल्लि के पास जाय। ऐसा करने से वक्फ बोर्डों को हिसाब किताब की देखभाल करने में आसानी होगी। कास्ट आफ मैनेजमेंट (प्रक्व के खर्व) के मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि इसमें

[श्री लखनू ग्राम]

मेरी स्कम न बगाई जाय कि जो बक्फ के अग्राज हैं वही निट जायें । बक्फ की बुनियाद यह है कि एक आदमी एक जायदाद को अपने ग्वानदान वालों के लिये बक्फ करता है और जब उस ग्वानदान में कोई मर्द शक्ती नहीं रहता है तब वह जायदाद किसी रेलीजस परपज के लिये डेडीकेट (समर्पण) हो जाती है । आप अपनी स्कीम के मुताबिक कुल रुपया मुतवल्ली को दे देंगे और वह मुतवल्ली जिस तरह चाहेगा उसको खर्च करेगा लेकिन इससे डेडीकेटर (समर्पण करने वाले) की जे ख्वाहिशें थीं वह खत्म होती हैं । इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक कन्वेन्शंस का नवाल है आप हर एक ब्रेनीफिशियरी को एक यूनिट तसलीम कर लें और जितनी ब्रेनीफिशियरीज हों उनको अलग २ कन्वेन्शंस दें । मेरे ख्याल में यह ज्यादा मुनासिब होगा ।

अग्विर में मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने जो कदम उठाया है वह बहुत ही मुनासिब और बेहतर कदम है लेकिन यह कहना कि यह एक बहुत बड़ी सीढ़ी है मेरी समझ में किसी हालत में नहीं है । हमें यही कहना चाहिये कि यह फर्स्ट स्टेप आनवर्ड (आगे पहला कदम) है गो कि इस दफा में यह शुबहा पैदा होता है या हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप आनवर्ड न हो ।

Provided that the Provincial Government may, by notification in the gazette, extend the whole or any portion of this act to any such area or state subject to such extensions, additions or modifications as it thinks fit.

(किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार गज़ट में विज्ञप्ति करके इस पूरे ऐक्ट या इसके किसी भाग को, ऐसे विस्तारों, वृद्धियों या परिवर्तनों की पाबन्दी के साथ, जिनको वह उचित समझे, ऐसे किसी क्षेत्र या रियासत पर लागू कर सकती है ।)

यह कहा जाता है कि बिहार गवर्नमेंट के ऐक्ट में जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अमेंडमेंट कर दिया है उससे ऐसा ख्याल पैदा होता है । यह कहा जाता है कि बिहार सरकार ने एक तरमीन की और हिन्दू सरकार ने भी तरमीन की । इसी नौग ने आने लग्वा है ऐसा ख्याल होता है । आपको बाज स्कीमें लखनऊ और कानपुर में चल् रही हैं जैसे प्रोहिबिशन की स्कीम चन्द जिलों में जारी है । जुडिशरी और एक्जिक्यूटिव के सेपरेशन की स्कीम दस जिलों में है । इसी तरह से मोटर ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कुछ जगहों में बसें चल् रही हैं और बकिया सड़कों को छोड़ दिया है । बस वाले जिनका रोजगार मारा गया है वह आपको गालिया दे रहे हैं । कमायून् ट्रांसपोर्ट चल रहा है उनके ओनर्स (मास्कि) मजा कर रहे हैं । जिन तरह नशाबन्दी दस जिलों में हो रही है उसी तरह आप इसको भी करने का इरादा करें तो यह किसी हालत में मुनासिब नहीं है कि आगरा में किया जाय और अवध में न किया जाय । मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है और जो कुछ करने का इरादा किया है उसकी तरफ जल्द से जल्द कदम उठावें । उसकी खानापुरी में देर न कीजिये । उसे पीसनीय (डकड़ों में) न कीजिये । गुस्सा और नाराजगी पैदा हो रही है । यह जनैन्दार और कारखाना के मालिक और वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं, यह सब एक साथ होंगे । इन सबको मिटाना चाहिये । इसमें देर न करना चाहिये । इसमें तरकी करना चाहिये । इस वक्त जो कदम आपने उठाया है, उसके लिए आप काबिले मुबारकवाद हैं । हम वादा करते हैं कि हमारा कोऑपरेशन, हमदर्दी और सहयोग आपके साथ होगा ।

**श्री रघुनाथ विनयक धुलेकर**—श्रीमान स्पीकर नहोदय, यह जो जमींदारी विनाश बिल है, इसके सम्बन्ध में बहुत नी बातें कही गयी हैं। कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं कि यह बिल जितना आगे जाना चाहिये था, नहीं जाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि जिस प्रकार का समाज हम आगे बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का समाज पूरे तौर से आगे बना हुआ दिखाई नहीं देता है। कुछ जमींदार बन्धु हैं, यह इस बात को कहते हैं कि हमारे ऊपर दंड नगो जुर्मान किया जा रहा है। जो मुआविजा हमको दिया जा रहा है बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें इस पर पेश की गयी हैं। पहली बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, वह यह है कि यह बिल भारतवर्ष में जो इस प्रान्त में पेश किया गया है वह ऐसा बिल है जिनके कारण हमारे संयुक्त प्रान्त का स्थिति बहुत ऊंचा हो गया। अन्य प्रान्तों में जमींदारी विनाश बिल पेश हुये हैं परन्तु उनका यह स्वरूप न था जैसा इस बिल का है। हमारे प्रान्तों में जो वहां के काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। वे यह कहते थे कि हमारे यहां का बिल बहुत असंतोषजनक है। मैंने मद्रास का भी बिल देखा और बिहार का भी बिल देखा। नगर उनमें जो बातें हैं वे बातें अभी तक उस प्रकार की नहीं हैं जैसी हमारे बिल में हैं। इस बिल में जो बातें हमने मुख्यतः रखी हैं वे ये हैं कि हमारे भारतवर्ष का पहला सिद्धान्त अध्यात्मवाद है। उसकी बुनियाद इसमें पायी जाती है। हमारे भारतवर्ष में समय समय पर जितने ऋषि मुनि हुये, जितने साधु सन्त हुये, जितने राजनैतिक कार्यकर्ता हुये, उन्होंने भारतवर्ष के मनुष्यों को रात दिन इसी बात को कह कर जगाया कि देखो, यह जगत इस प्रकार का नहीं है कि एक मनुष्य के पास अधिक वस्तु हो और दूसरे मनुष्य के पास कम वस्तु हो। यह समाजवाद और साम्यवाद बिल्कुल अशूरावाद है क्योंकि अभी इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। केवल इस बात को कहने से कि हम सब मनुष्यों को बराबर समझते हैं समाज में सभी मनुष्य बराबर हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। केवल इस बात को कहने से कि देखो, प्रत्येक मनुष्य को बराबर अन्न और कपड़ा मिलना चाहिये, इसमें मनुष्य का मस्तिष्क और दिल संतुष्ट नहीं होता है। हमारा अध्यात्मवाद यह कहता है कि हम उस परमात्मा, परमब्रह्म, और उस परम तत्व को, प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जीव में एक सा देखना चाहते हैं। इसी का नाम अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद कहता है कि चाहे चाण्डाल हो या गाय हो या हस्ती हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जो इस जगत् में है उसको हम एक सा देखना चाहते हैं। हमारे संयुक्त प्रान्त ने इस बिल को सामने रख कर उस अध्यात्मवाद की तरफ पहला कदम उठाया है और भारतीय संस्कृति को कायम किया है। अभी हमारे एक मित्र ने राम कृष्ण का नाम लेकर यह कहा कि भारतीय सभ्यता के यह बिल विरुद्ध है। लेकिन मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में किसी जगह ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के बाद लाखों बीघे जमीन हो, लाखों रुपये हों और वह ऊंचा हो और लाखों गरीब हों। इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में कभी नहीं थी। हमारे भारतवर्ष में वही मनुष्य सर्वोच्च मनुष्य समझे जाते हैं जिनके पास कम से कम भूमि हो, जिनके पास कम से कम मकानात हों, जिनके पास कम से कम धन हो किन्तु उन्होंने सबसे ऊंचा त्याग किया हो, तपस्या की हो। हमारे यहां के राजाओं में अगर किसी की गिनती की जाती है तो राजा जनक की की जाती है। हमारे यहां सबसे बड़ा मनुष्य और कोई माना जाता है तो राजा हरिश्चन्द्र माना जाता है जिसने सत्य के

[ श्री मनुष्यवन्तः पुलेकर ]

ऊपर अपने को नोछाकर कर दिया। अपना राज पाट दे दिया, अपनी नौ को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और उन सब का पालन करने के लिये अपने को डोम के घर बेच दिया। हमारे यहां जितने उन्मुख सन् हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मानव जाति, इस बात को देखो कि बने, बने और बने में तुम्हारी उच्चता नहीं है। तुम्हारी उच्चता नैतिक उच्चता ही में है। और सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस का आंदोलन प्रारम्भ हुआ तो यही नैतिकता है जिसके बल पर सफलता प्राप्त हुई। जितने लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि ५०, ६० वर्ष में जितने राजनैतिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं वे सभी इसकी कदर को जानते हैं। और यदि उनमें उच्चता पायी जाती है तो अगर इस बात को देखेंगे कि उनकी त्याग और तपस्या का ही फल है कि आज प्रत्येक मनुष्य कांग्रेस को और उसके कार्यकर्ता को एक उच्च दृष्टि में देखता है। अगर आज कांग्रेस कार्यकर्ता कोई गप्पी करता है तो सभी उसकी तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि यह ऐसा है वैसा है। अतः हमका क रण क्या है मैं आपसे कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाय कि मनुष्य स्वयं अपना स्तर (स्टैण्डर्ड) अच्छा से अच्छा निर्धारित करता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो मनुष्य इस बात का दावा करता है कि वह बड़ा उच्च है तो उसको उसी तरह का कार्य करना चाहिये जिस तरह की लोग उससे आशा करते हैं। खासतौर से कांग्रेस से लोग उसी तरह की आशा करते हैं। आज बहुत से पाप लोग हैं, अनेकों पतन के गड्ढे में गिरे हुए हैं लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली उठा कर कुछ नहीं कहता है। परन्तु हर एक आदमी कांग्रेसमैन की तरफ उंगली उठाता है। आखिर क्यों? क्योंकि कांग्रेसमैन एक अमानन है। कांग्रेसमैन नैतिकता का आधार है। कांग्रेसमैन नैतिकता का आंदोलन करने वाला है। उसके साथ इस बात का दावा करने वाला है कि वह इस जगत् में मानवता को फैलाने वाला है, मानवता को ऊंचा करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज हमने यह महत्त्व कदम उठाया है कि हम इस बिल के जरिये से ऊंच और नीच की जो व्यवस्था, जो व्यवहार इस भारतवर्ष में था उठा दें। हमारे ही युक्त प्रान्त में लाखों रुपये रखने वाले हैं जो न पढ़े न लिखे हैं, न उनमें सदाचार है, न उनमें किसी तरह का आचार है और न कोई और बात है उनके पास लाखों रुपये हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और छोटे-छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ५० वर्षों ने गरीबी को अपनाये हुये हैं, गरीबी को गले में बांधे हुये हैं। हमारे जमींदार लोग कहते हैं कि आज हमको पूरा पूरा प्रतिकार नहीं दिया जाता है, आज हमको पूरा दाम नहीं दिया जाता है। हम उनसे इस बात की प्रार्थना करते हैं, हम उनसे करबद्ध प्रश्न करते हैं कि जब दुनिया आग रही थी तब आप क्यों जो रहे थे। जब ५० वर्षों से यह आंदोलन चल रहा था और बार बार यह कहा जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी को हिन्दुस्तान में पैदा किया है, जमींदारों को लार्ड कार्नवालिस ने पैदा किया है, जमींदारों से उन्होंने ऐसा कट्टर कर लिया है कि तुम किसानों से रकबा वसूल करो, और हमको दो तब आपने हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की। पहले दण्डाली करके ६० साला दण्डोबस्त बनवाया, आपका इतिहास यह जाहिर करना है कि आप केवल १० फी सदी लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ९० फी सदी देते थे, फिर धीरे धीरे खुशामद करते करते, ६० फीसदी, ४० फीसदी और ५० फीसदी और ५५ फीसदी तक आप लेने लगे और बाकी अंग्रेजों को देने लगे। अंग्रेजी राज को कायम

गवने<sup>१</sup> में आपने इतनी बड़ी सहायता की। हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि हमने इस भारतवर्ष में पैसा लगाकर बहुत सी चीजें कायम कीं। वह कहते हैं कि संगीतशास्त्र हमने कायम किया, अच्छे मकान हमने बनवाये और अगर कोई सभ्यता या कोई तहजीब है तो हमने ही हिन्दुस्तान में कायम रखी। बकी लोग मामूली तौर से जो इसे हुये थे वह गंवार थे। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस सूचे में, संयुक्त प्रान्त में, जमींदारों ने कौन सी ऐसी बड़ी इमारत बनाई है कि जिसके कारण हम इस बात को कहे कि निर्माण कला उन्होंने कायम रखी। हम उस आर्ट को देखना चाहते हैं जो जमींदारों ने यहां कायम किया। (श्री वीरेन्द्रशाह-यूनिवर्सिटी बनवाई।) मेरे मित्र कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनवाई। मैं पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी किस कला का इजहार करती है। कौन सी कला उसमें है? अंग्रेजों ने बनवाई। अगर आप बहुत अच्छे थे तो क्या आपने दूसरे मुल्कों की तरह कुछ किया? रूस में जैसे जमीन के अन्दर अंदर तमाम चारों तरफ रेलें दौड़ रही हैं क्या आपने वैसी कोई चीज यहां कायम की? या जो कि मेक्रेटेरियट है जिसे अंग्रेजों ने बनाया उस प्रकार की कोई बिल्डिंग क्या किसी जमींदार ने पहले बनवाई। आज रेडियो के गाने हम सुनते हैं और जो वर्तमान संगीत कला मानी जाती है क्या वैसी कोई भी संगीत कला किसी जमींदार ने कायम की? नहीं की। कभी कभी गादियों ने नाच और गाने का लेने से क्या आप समझते हैं कि आपने संगीत को कायम रखा है, क्या आप यह बतला सकते हैं कि आपने संगीत पर कोई पुस्तक लिखवाई है? और दूसरी बातें भी जो अंग्रेजों के जमाने में हुईं उनमें भी आपने कौन सा हिस्सा लिया है। आज जितनी कम्पनियां आपको दिवाई देती हैं, जितनी अंग्रेजों के जमाने में यहां खुली हैं, अगर उनमें देवा जाय तो सारा कैपिटल दूसरे लोगों का है। जमींदारों का तो उनमें ५ फी सदी भी नहीं लगा हुआ है। वकील, कंटेक्टर, डाक्टर और दूसरे लोगों का ही सारा रुपया उसमें लगा हुआ है। जब कि स्वदेशी की मूवमेंट चली तो इन लोगों ने रुपया लगा कर यहां पर मिलें खोलीं और देशी कपड़ा तैयार करके लोगों को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो जमींदारी बिल आज आपके सामने है यह तो वक्त की जरूरत के ऊपर ही यहां पर आया है और जो कांग्रेस ने तय किया था उसके मुताबिक ही है, और यह तो इस प्रकार की घटना है कि जब धीरे धीरे जमींदारों के पैर उखड़ने लगे और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं रहा तब वक्त की जरूरत यह हुई कि इस बिल को यहां पर लाया जाय और उसी तरह से जमींदारी का विनाश किया जाय। आज कहीं पर, किसी जगह पर, कोई आदमी, कोई तबका, कोई फिरका जमींदारों की मदद करने को तैयार नहीं है और न यह कहने के लिए तैयार है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जमींदारी प्रथा को ५ मिनट के लिये भी कायम रखा जाय। जो मौका जमींदारों को हिन्दुस्तान में मिला उस मौके को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। मैं जमींदारों से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस आंदोलन में हजारों, लाखों लोगों ने, विद्यार्थियों ने और दूसरे लोगों ने, डाक्टरों ने, वैद्यों ने, वकीलों ने २५ वर्ष तक अपने जीवन को बरबाद कर दिया, अपने जीवन को मिटा दिया और अपने को तबाह कर दिया, खुद गरीब बन गये। क्या जमींदार ने कभी यह सोचा कि इसके पीछे देश की कौन विचारधारा काम कर रही है। क्या कभी उन्होंने अपनी आमदनी का ८ गुना, १० गुना या १५ गुना मांगा। आज जो २५ वर्ष से आन्दोलन चला आ रहा था जिसका नेतृत्व



[ श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर ]

गान्धी जी ने जिया था और आपको बतलाया था कि यह अनानस है, यह चीजे सब आपके पास गगेहर हैं। उम वक्त आप मनबते थे कि यह कोई दूरदेशी की बात नहीं है। मैं आपको याद दलाना चाहता हूँ कि गांधी जी ने “क्विट इंडिया” रेजोल्यूशन उपस्थित किया था और फिर उसके गहले जव २६ जनवरी को बराबर शपथ पढ़ी जानी थी और इसी तरह की और बातें हुईं तो क्या कभी आपने सोचा। अगर आप इन सब बातों को सोचते होते और इन पर विचार करते होते तो यह चीज आज इस प्रकार न होती और न आपको इस प्रकार से तकलीफ गवारा करनी होती। मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूँ कि आप अपनी जमांदारी के लिये दुहाई देते हैं। क्या कभी आपने महाराजा बीकानेर, महाराजा कोचीन, महाराजा इन्दौर, महाराजा ग्वालियर का जमांदारी का भी विचार किया है कि उनको करोड़ों की जायदाद क्या कोमतें रखती थीं, लेकिन उन्होंने एक मिनट के अन्दर अपनी लाखों करोड़ों की सम्पत्ति सब जनता के हवाले कर दी और न्योछावर कर दी। फिर भी अगर कोई यू० पी० का जमांदार यह कहे कि मेरी जमांदारी बीकानेर के महाराजा से ज्यादा कीमत रखती है तो यह बड़े जाजुब की बात है। अगर आप देखें तो मान्य होगा कि उन्होंने कांग्रेस के कहने पर अपना करोड़ों की जायदाद को कांग्रेस के और जनता के हवाले कर दिया। क्या आप अपनी जमांदारी को कोचीन के महाराजा और बीकानेर के महाराजा के बराबर समझते हैं। यह जो आप लड़े होकर कहते हैं कि हाय हम मर गये। अरे आप को तो अक्लमन्दी इसी में थी कि जिस तरह से इतने बड़े बड़े राजाओं ने इंडियन यूनियन के सामने सर झुका दिया और सब कुछ समर्पण कर दिया, उसी तरह आपको भी यही चाहिये था। वे राजे जिनकी करोड़ों रुपये की आमदनी थी, इतने बड़े प्रीमी रस, करोड़ों की जायदाद जिनकी थी जब वक्त आया और हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो उन्होंने अपने को हटा दिया लेकिन आपने तो हैदराबाद की तरह, दूसरे मुल्कों की तरह समझ लिया कि हम बहुत बड़े हैं और लड़ते ही जा रहे हैं। आपको मान्य है कि इतने बड़े राजाओं की क्या कम्पेन्सेशन मिला? महाराजा ग्वालियर को २.१२ लाख दिया गया है, उनके लड़के नोकरी कर रहे हैं। आपसे जो हजारहा दर्जे बड़े लोग थे जिनके पास आपसे हजारों दर्जे अधिक जायदाद थी और मिलिक्रयन थी उन्होंने बिना चूँ व चरा के नेशनल गवर्नमेंट को समर्पण कर दी लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि हम खुशी से जमांदारी को खत्म करते हैं।

**डिप्टी स्पीकर**—वक्त हो चुका है। अब आप अपनी तकरीर कल जारी रखेंगे। कल के मुतालिक माननीय प्रधान सचिव बतलायें कि इजलास होना चाहिये या नहीं।

**माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वरजभ पन्त)**—मैं दरखास्त करता हूँ कि कल असेम्बली की बैठक की जाय क्योंकि कल ही से शुरू हुई और कल फिर न करना बुरा लगता है, खाली बैठे क्या करें?

**डिप्टी स्पीकर**—मेरा ख्याल है कि कल बैठक हो, क्योंकि पहले एक निर्णय इस बात के लिये हुआ था कि सनीचर को न हुआ करे लेकिन चूँकि कल से ही शुरू हुई है इसलिये कल

भी होनी चाहिये और कल न करना मुनासिब नहीं मान्द्रम होता । मैं समझता हूँ कि सब भवन की यही राय है । अब हम कल ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १ मिनट पर दूसरे दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

लखनऊ :

८ जुलाई, १९४९

कैलास चन्द्र भटनागर,

मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,

संयुक्त प्रांत

## नश्री 'क'

( देखिये प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर )

## बारामंडी जिले के एजेंटों द्वारा भिन्न भिन्न जिलों में सीमेंट के विवरण का (चार्ट)

क्रम संख्या	परमिट संख्या व दिनांक	परमिट पानेवाले का नाम व पता	बोरों की संख्या	संचयकर्ता का नाम	टिप्पणियां
१.	संख्या ३३३३ दिनांक २२-११-१९४८	महन्त सल्लि राम दास, फैजाबाद	२५० बोर	सर्वश्री राम किशन मीताराम, जैदपुर	
२.	" ३४५८ " २५-११-४८	डिविजनल फोरेस्ट आफिसर, गोरखपुर डिवीजन, गोरखपुर	१०० बोर	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता	
३.	" ३४६० " २५-११-४८	" " बहराइच डिवीजन, बहराइच	८० बोर	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता	
४.	" १००३ " ८-१२-४८	लाला केशव देव, सीतापुर	२०० बोर	हाजी चादवाह हुसैन, नवाबगंज	
५.	" १००४ " "	श्री लोकेश्वर तम्बाकू के शोक विज्ञेता, सीतापुर	५० बोर	सर्वश्री रामलाल फतेहचन्द, सप्तदरगंज	
६.	" १००५ " "	श्री अम्बिका प्रसाद, सीतापुर	८० बोर	सर्वश्री रामलाल फतेहचन्द, सप्तदरगंज	
७.	" १००७ " "	श्रीमती कृष्णा देवी, सीतापुर	१०० बोर	सर्वश्री मोहम्मद अली नवाब अली, सदौली	
८.	" ३९१८ " १-१२-४८	श्री एल.एन. भटनागर, मजिस्ट्रेट तथा असिस्टेंट कलेक्टर, सीतापुर	५० बोर	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता, नवाबगंज	
९.	" १०१२ " १०-१२-४८	श्री भावती प्रसाद, सीतापुर	४० बोर	सर्वश्री छोटेलाल गुप्ता, नवाबगंज	
१०.	" १०१३ " "	श्रीमती सितारी देवी कपूर, सीतापुर	१०० बोर	सर्वश्री मगीरथ मन्नालाल, नवाबगंज	
११.	" १०१४ " "	" राजेश्वरी देवी, सीतापुर	४० बोर	" " " "	
१२.	" १०१५ " "	बाबूराम गुलजरीलाल गुप्ता, सीतापुर	१०० बोर	" " " "	
१३.	" १०१६ " "	सर्व श्री भोलनाथ बैजनाथ टंडन, सीतापुर	१०० बोर	" " " "	



## नस्थी 'ख'

( देखिये पीछे प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पृष्ठ ११६ पर )

मछली और पशुपालन विभागों Fisheries and Animal Husbandry Deptts.) की उन नदी या जगहों की सूची जो आर्थिक वर्ष १९४८-४९ ई० में तैयार की गयीं।

१. दूर दूर की जगहों में जाकर मवेशियों के रोगों को रोकने के लिये एक मोबाइल यूनिट कायम करना।

२. भरारी, इन्वुगढ़, माथुरीकुंड, मझरा और हेमपुर के मवेशियों को नरकशी के सरकारी फार्मों ( Govt. Cattle Breeding Farms ) और नीलगंज तथा निवलेट के सरकारी फार्मों के यन्त्रीकरण (Mechanisation) की योजना।

३. मवेशियों की खरीद करने वाली एक संस्था (Cattle Purchase Organisation) कायम करना।

४. मथुरा जिले में गोशालाओं का विकास।

५. बृढ़े और अनुपजाऊ (unproductive) मवेशियों के लिये देहरादून, हरद्वार, ऋषीकेश इलाके में एक कमेन्टेशन कैम्प ( ऐसा कैम्प जिसमें ऐसे मवेशी लाकर रखे जाते हैं ) कायम करना।

६. देहरादून, हरद्वार, ऋषीकेश इलाके में ऐसे मवेशियों के लिये जिनका दूध सूख गया हो ( dry cattle ) एक रक्षा केन्द्र ( Salvage centre ) कायम करना।

७. गोरखपुर जिले में सांड, भेड़ों का एक केन्द्र ( Stall Ram Centre ) कायम करना।

८. फतेहपुर और मथुरा जिलों में भेड़ों और उनके उद्यान का विकास।

९. अन्धीगढ़ में एक सेंट्रल डेयरी फार्म खोजना।

१०. गाजीपुर में कृत्रिम रूप से गाम्बिन करने का एक केन्द्र (Artificial Insemination Centre) कायम करना।

११. देहरादून जिले में जामार-भावर परगने में पशुधन ( livestock ) को बढ़ाना।

१२. मछली विभाग ( Fisheries Deptt. ) की योजनाएँ।

## अब तक की गई उन्नति पर टीपें (Notes)

१. दूर दूर की जगहों में जाकर मवेशियों के रोगों को रोकने के लिये एक मोबाइल यूनिट कायम करना

जब इट गिट की जगहों के मवेशियों में छूत की और दूसरी अप्रचलित बीमारियाँ एका-एक फैल जायं तो यह जरूरी हो जाता है कि उन जगहों में जहाँ बीमारियाँ फैली हों तुरन्त पहुँचा जाय तथा बीमारी का निदान किया जाय और उनको फैलने से रोकने के लिये आवश्यक कार्य-वाहियाँ की जायं। यह तभी हो सकता है जब वेटेरीनरी असिस्टेंट सर्जन के अधीन एक ऐसा 'मोबाइल वेटेरीनरी यूनिट' जिसके पास पूरी टवाइयाँ हों, कायम किया जाय। शुरू में यह प्रस्ताव था कि इस मोबाइल यूनिट को मेरठ में रखा जाय। अब यह विचार है कि इस यूनिट को अवनऊ में रखना और भी फायदेमंद होगा जो एक केन्द्रीय स्थान है और जहाँ बैक्टीरिया

(vaccines) को कोल्ड स्टोरेज में रखने की नहूशियन हैं। जिस वेटरीनरी इन्वेस्टीगेशन अफसर के मन्तापन तथा नियंत्रण में यह मोबाइल यूनिट काम करेगा उनकी सेवायें भी उपलब्ध होंगी। इन सम्बन्ध में जिस गाड़ी की जरूरत होगी उसके लिये एक उपयुक्त चॅसिस (chassis) देने का निवेदन वाहन विभाग (Transport Deptt.) ने किया गया है। ज्यों ही यह मित्र जायेगा त्यों ही गाड़ी को तैयार करने की कोशिश की जायगी।

२. भरतपुर, बाहूगढ़, माधुरोकुंड, मभरा, हेमपुर के मवेशियों की नस्लकशी के सरकारी फार्मों और नानाजों तथा विक्टेट के सरकारी फार्मों के यन्त्रीकरण (mechanisation) का प्रयत्न।

इस वर्ग को बनने योग्य खास बात मवेशियों की नस्लकशी के फार्मों के यन्त्रीकरण (mechanisation) है। प्रान्त में अनाज, चारे और दूध की पैदावार का बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उद्योग को आधुनिक रूप देने के लिये सरकार द्वारा यन्त्रों से खेती करने के तरीके काम में लाये गये। इन सात फार्मों का कुल रकबा १०,००० एकड़ है जिनमें से ५० प्रतिशत खेती करने के योग्य है। आर्थिक वर्ष में जो कि समाप्त हो गया है कुल खेती योग्य रकबा के आधे भाग में अनाज और चारे की खेती की गई है। और यह आशा की जाती है कि बचे हुए भाग में भी अगले कुछ महीनों के भीतर ही फसलें तैयार की जायंगी। इन फार्मों में सुधरी नस्ल की भेड़ों, बकरियों, और मुर्गियों इत्यादि की संख्या बढ़ाने के लिये जोर शोर से काम शुरू कर दिया गया है।

३. मवेशियों की खरीद करने वाली एक संस्था (Cattle Purchase Organisation) कायम करना।

आर्थिक वर्ष सन् १९४८-४९ ई० में खरीद करने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है और सितम्बर, १९४८ ई० से पशुपालन विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर के अधीन मवेशियों की खरीदारी के बारे में पूरा जानकारी रखने वाला एक दल पूर्वी पंजाब में तैनात किया गया है, इस दल को दिसम्बर, १९४८ ई० तक ५६१ मुराई में, २१४ हरियाना गाँवों और ८२ नस्लकर्मी के काम में आने वाले सांडों को खरीदने में सफलता प्राप्त हुई है। नगीदारी का काम अभी जारी है, और यह आशा की जाती है कि साल में कुल जितनी खरीदारी की जाने वाली है वह साल के अंत तक करीब हो जायगी।

४. मथुरा जिले में गोशालाओं का विकास

प्रान्त की गोशालाओं के (उत्पादक) मवेशियों को अनुत्पादक प्रकार मवेशियों से अलग रख के उन्हें उन्नतोगी मवेशियों की नस्लकशी की और डेरी का काम करने वाली संस्थाओं में बदलने के लिये एक योजना चालू की गई है। शुरुआत में सरकार ने आरम्भ में मथुरा जिले की ६ गोशालाओं को आधे दान पर वर्ष में यानी १९४८-४९ ई० में १२० शुद्ध नस्ल की हरियाना गाँव दी।

५. बूढ़े और अनुत्पादक (unproductive) मवेशियों के लिये देहरादून, हरद्वार, ऋषिकेश कन्वेंशनल कैम्प (ऐसा कैम्प जिसमें ऐसे मवेशी लाकर रखे जाते हैं) कायम करना।

श्रोतों नीचा वेन की देख रेख में सरकार ने हाल ही में बूढ़े और बेकार मवेशियों के लिये डेहरादून, रुद्रा, ऋषिकेश इत्यादि में एक कन्सेंट्रेशन कैम्प चलाया है। चूंकि यह योजना अभी शुरुआत में चालू हुई है इसलिए अभी कोई यथार्थ परिणाम नहीं निकला है।

६. ऐसे मवेशियों के लिये जिनका दूध सूख गया हो (Dry cattle) एक रक्षा केन्द्र (Salvage Centre) कायम करना।

भारत में मवेशियों के मरने के कारण बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गायें दूध सूख जाने की अवधि में बचकनों (slaughter-houses) में पहुंचा दी जाती हैं। इससे प्रान्त के पशुधन में कमी कमी हो जाती है। इस भारी नुकसान को रोकने के लिये विभाग ने ऋषिकेश में डेहरादून, रुद्रा, ऋषिकेश के इलाकों के लिये श्रीमती मीराबेन के चार्ज में, दूध सूखे हुए मवेशियों की रक्षा के हेतु एक फार्म खोलने की मंजूरी दी है। इस फार्म में कुछ इमारतें और शेड (sheds) बनाये गये हैं। इनारती सामान के मिचने में कठिनाइयाँ होने के कारण इस फार्म में मवेशियों का जाना रोक गया है।

७. गोरखपुर जिले में सांड भेड़ों का एक केन्द्र (Stud Ram Centre) कायम करना।

स्थानीय भेड़ों से तैयार किये जाने वाले ऊन की मिकदार और किस्म में सुधार करने के लिए गोरखपुर जिले में भेड़ों के शुद्ध में शुद्ध नस्ल के बीकानेरी भेड़ों के रखने की एक योजना तैयार की गई है। इन भेड़ों (Rams) को वहां रखने के सम्बन्ध में सभी प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं। भेड़ खरीदे जा चुके हैं और उरई के भेड़ों के फार्म में रख दिये गये हैं जहां से वे रेलवे अधिकारियों द्वारा उनके भेजने का प्रबन्ध कर दिये जाने पर गोरखपुर भेज दिये जायेंगे।

८. फतेहपुर और मथुरा जिलों में भेड़ों और ऊन के उद्योग का विकास

गोरखपुर की तरह फतेहपुर और मथुरा में भी भेड़ों और ऊन के उद्योग के विकास के लिये एक योजना तैयार की गई है। भेड़ (Ewes) और भेड़ (rams) खरीदे जा चुके हैं और बांटे जाने वाले हैं।

९. अलीगढ़ में एक सेंट्रल डेयरी फार्म खोलना

१ नवम्बर १९४८ ई० को सरकार ने अलीगढ़ की मशहूर फर्म एडवर्ड कबेटर लिमिटेड खरीदी और उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। इस फार्म का नया नाम, सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ (Central Dairy Farm Aligarh) रखा गया है। इस फार्म में एक नवीनतम डेरी सुअखाना (piggery) और डेरी तथा सुगोखाने का साज सामान बनाने के लिए एक कारखाना है। इस डेरी में पूर्वी पंजाब से खरीदी हुई १०० भैंसों में हैं और वह अब अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से प्रति दिन २० मन दूध और १००० से १२०० पोण्ड तक मक्खन तैयार कर रही है।

१०. गाजीपुर में कृत्रिम रूप से गाभिन करने का एक केन्द्र (Artificial Insemination Centre) कायम करना।

इस साल का कार्यक्रम मेरठ, बरेली, लखनऊ और देवरिया में ४ कृत्रिम रूप से गाभिन

करने के केंद्र बना था। पूर्वी जिलों में इस काम को बढ़ाने के लिये गाजोपुर जिले में कृत्रिम रूप से गाम्बिन करने का एक अनिश्चित केंद्र खोलने की मजूरी दी गई है। और वह वहां काम करना रहा है। कृत्रिम रूप से गाम्बिन कराने के काम के लिये आवश्यक मछली में साढ़ा और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और आवश्यक सज्जा की खरीद के लिये प्रवन्ध किया जा रहा है।

११. देहरादून जिले में जौंसार भावर परगने में पशुधन (Livestock) को बढ़ाना

देहरादून जिले में जौंसार भावर परगना इस प्रान्त के उन इलाकों में से है जो कई बातों में पिछड़े हुये होने पर भी विकास के लिये काफी क्षमता रखते हैं। इसलिये १९४६-४७ ई० में एक योजना चालू की गयी जिसका उद्देश्य पशु-धन की कार्यवाहियों का विकास करना था। सम्बन्धित दरिद्रों को प्रति अकृषान सांड के लिये १५० रु० प्रतिवर्ष और प्रति मेंढा के लिये ४८ रु० प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी गयी। १९४७-४८ ई० में इस इलाके में चार ओहानी मांड भेजे गये और उनके भरण पोषण के लिये १५० रु० प्रति वर्ष के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी। १९४७-४८ में मेंढों में दो सौ नब्बे मेंढे गाम्बिन करायी गयीं और ४५ गायें गाम्बिन कराई गईं।

१९४८-४९ ई० में विकास के काम के लिये दो और यूनिट खोले गये हैं और आर्थिक सहायता के आधार पर गाम्बिन कराने के काम के लिये उन्हें ६ मांड और २० मेंढे दिये गये।

## १२. मछली विभाग

विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही तालाबों में मछली पालने के काम का विकास करना और उनमें मछली जमा करना (stocking) है। भारत सरकार से मिलकर बेकार तालाबों (Idle tanks) में और अधिक संख्या में मछलियों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये इस वर्ष उनमें मछली जमा करने का काम जारी रखा गया। विकास और मछली जमा करने के लिये अब तक इन जिलों में आठ सौ सत्ताईस तालाब चुने गये हैं।

तराई और भावर के मछली पालने के स्थानों को अजीब समस्याएँ हैं क्योंकि युक्त प्रात की जो आम तौर पर खाई जाने वाली मछलियाँ हैं वे न इस इलाके में पाई जाती हैं और न पैदा हो होती हैं और खाई जाने वाली दूसरी उपयुक्त मछलियों के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

जल-पिशुन विभाग के निवेदन पर मछली पालने के स्थानों के सम्बन्ध में और इस किस्म के फिश लेडर (Fish ladder) के सम्बन्ध में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है जो मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये होना चाहिये।



## नस्थी 'ग'

(डेम्बो प्रश्न संख्या ४६५ का उत्तर पाछे पृष्ठ ११८ पर)

किम प्रकार का परमिट	२ से ५ तक परमिट रखने वालों की संख्या	६ या ६ से अधिक परमिट रखने वालों की संख्या
स्टेज कैरेज	२५७	३६
पब्लिक कैरेज	२७०	४१
प्राइवेट कैरिअर	१६२	२७

( नत्थी 'ब' )

( देखिये प्रश्न संख्या \*७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर )

मिर्जापुर एलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल के लिये दी जाने वाली बिजली के दर की नूची ।

वर्तमान दरें बिजली की रोशनी देने के लिये निम्नलिखित हैं जिन पर आज कल १५ फीसदी वार कास्ट्स सरचार्ज भी लिया जाता है ।

१. रोशनी, पङ्खा, रेडियो और घर के कामों में इस्तेमाल होने वाली मोटरों ( जो कि आधा हार्म पावर से अधिक शक्ति की न होंगी ) का दर आठ आना फी यूनिट है पर बिल को १५ दिनों के अन्दर चुका देने में २५ प्रतिशत कमीशन दे दिया जाता है । इससे फ्री यूनिट बिजली की दर छः आना ही होती है ।
२. बाजार में दुकानों पर बिजली देने पर जिसकी माप मीटर द्वारा नहीं होती और एक ही ४० वाट का बन्ध जो कि दिन में ५ घण्टे से अधिक नु जलाया जाय दो रुपया प्रति-मास के हिसाब से प्रत्येक दुकान से लिया जाता है ।
३. रेफ्रिजरेटर, कुकर, पन्ना और हाटर्म के दो आना छः पाई फ्री यूनिट की दर से लिया जाता है ।
४. सिनेमा के लिए तीन आने तीन पाई फ्री यूनिट की दर से लिया जाता है ।
५. बैटरी चार्जिंग के लिये जिसका इस्तेमाल केवल कुछ घण्टों के लिये ही हो सकता है दो आना छः पाई फ्री यूनिट की दर से लिया जाता है और चौबीसों घण्टे इस्तेमाल के लिये तीन आना छः पाई फ्री यूनिट की दर से लिया जाता है ।
६. औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली का दर ईंधन के मूल्य सम्बन्धी नियम के अनुसार होता है ।

विद्युति शक्ति का मोबा दर (Power on Flat Rate)

- क. उद्योग धन्धों के लिये शाम के ५ बजे से रात को १० बजे तक के समय के अलावा मोटर का इस्तेमाल करने पर दो आना छः पाई फ्री यूनिट ।
- ख. चौबीसों घंटे मोटर के इस्तेमाल पर तीन आना छः पाई फ्री यूनिट के हिसाब से ।

द्विविध शुल्क (Two Part Tariff)

बिजली की अधिकतम मांग पर सात रुपया आठ आना प्रति के० वी० ए० प्रति मास तथा इसके ऊपर एक आना प्रति यूनिट के हिसाब से ।



# संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

शनिवार, ९ जुलाई, सन् १९४९ ई०

असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।  
अध्यक्ष— श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर

## उपस्थित सदस्यों की सूची (१८८)

अचल सिंह  
अजित प्रताप सिंह  
अब्दुल रानी अन्सारी  
अब्दुल बाक्री  
अब्दुल मजीद  
अब्दुल मजीद खाजा  
अब्दुल वाजिद, श्रीमती  
अब्दुल हमीद  
अम्मार अहमद खाँ  
अलगूराय शास्त्री  
अली जरार जाफरी  
अक्षयवर सिंह  
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री  
इन्द्रदेव त्रिपाठी  
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती  
ऐजाज रसूल  
करीमुर्रजा खाँ  
कालीचरण टण्डन  
किशनचन्द्र पुरी  
कुशलानन्द गैरोला  
कृपा शंकर  
कृष्ण चन्द्र  
कृष्ण चन्द्र मुन्ना

केशवदेव मालवीय, माननीय श्री  
खानचन्द गौतम  
खुश वक्त राय  
खुशी राम  
खूब सिंह  
गजाधर प्रसाद  
गणेश कृष्ण जैतली  
गिरधारी लाल, माननीय श्री  
गोपाल नारायण सक्सेना  
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री  
गोविन्द सहाय  
गंगा धर  
गंगा प्रसाद  
गंगा सहाय चौबे  
चतुर्मुज शर्मा  
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री  
चन्द्रभानु शरण सिंह  
चरण सिंह  
चेतराम  
छेदालाल गुप्त  
जगन्नाथ दास  
जगन्नाथ प्रसाद, अग्रवाल  
जगन्नाथ सिंह

जगन्नाथ बख्श सिंह  
 जगन प्रसाद रावत  
 जगमोहन सिंह नेगी  
 जाकिर अली  
 जाहिद हसन  
 जहीरुल हसनैन लारी  
 जुगुल किशोर  
 जयकृष्ण श्रीवास्तव  
 जयपाल सिंह  
 जैराम वर्मा  
 दयालदास भगत  
 दाऊदयाल खन्ना  
 द्वारिका प्रसाद मौर्य  
 दीन दयालु अवस्थी  
 दीन दयालु शास्त्री  
 दीप नारायण वर्मा  
 धर्म दास, एल्फ्रेड  
 नवाब सिंह  
 नाजिम अली  
 नारायण दास  
 निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री  
 निहालुद्दीन  
 पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती  
 पूर्णमासी  
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती  
 प्राग नारायण  
 परागी लाल  
 प्रेम किशन खन्ना  
 फखरुल इस्लाम  
 फतेह सिंह राणा  
 फिलिप्स, अर्नेस्ट माइकेल  
 फूल सिंह  
 बदन सिंह  
 बंश गोपाल  
 बंशी धर मिश्र  
 बनारसी बख्श

बलदेव प्रसाद  
 बलभद्र सिंह  
 बशीर अहमद  
 बशीर अहमद अन्सारी  
 बादशाह गुप्त  
 बाबू राम वर्मा  
 बृज मोहन लाल शास्त्री  
 भगवती प्रसाद दुबे  
 भगवती प्रसाद शुक्ल  
 भगवान दीन मिश्र  
 भारत सिंह यादवाचार्य  
 भीमसेन  
 मंगला प्रसाद  
 मसुरिया दीन  
 महफूजुर्रहमान  
 महमूद अली खाँ  
 मिजाजी लाल  
 मुकुन्द लाल अभवाल  
 मुजफ्फर हुसैन  
 मुनकैत अली  
 मुहम्मद असरार अहमद  
 मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री  
 मुहम्मद इस्माइल  
 मुहम्मद उबैदुर्हमान खाँ शेरवानी  
 मुहम्मद जमशेद अली खाँ  
 मुहम्मद नजीर  
 मुहम्मद फारूक  
 मुहम्मद युसुफ  
 मुहम्मद रजा खाँ  
 मुहम्मद शकूर हाजी  
 मुहम्मद शाहिद फाखरी  
 मुहम्मद शौकत अली खाँ  
 मुहम्मद सुलेमान अधमी  
 मुहम्मद सुल्तान आलम खाँ  
 यज्ञ नारायण उपाध्याय  
 यमुनाथ विनायक मुलेकर

रघुवीर सहाय  
 रघुबंरा नारायण सिंह  
 राघव दास  
 राज कुमार सिंह  
 राजा राम मिश्र  
 राजा राम शास्त्री  
 राधा कृष्ण अग्रवाल  
 राधा मोहन सिंह  
 राधेश्याम शर्मा  
 रामकुमार शास्त्री  
 रामचन्द्र सिंह  
 रामचन्द्र सेहरा  
 राम चन्द्र पालीवाल  
 रामजी सहाय  
 राम धारी पांडे  
 राम नारायण  
 रामबली  
 राम मूर्ति  
 राम शंकर लाल  
 राम शरण  
 राम स्वरूप गुप्त  
 रुक्नुद्दीन खाँ  
 लक्ष्मी देवी, श्रीमती  
 लताकृत हुसैन  
 लाखन दास जाटव  
 लाल बहादुर, माननीय श्री  
 लाल बिहारी टण्डन  
 लीलाधर अष्ठाना  
 लोटन राम  
 विजयानन्द मिश्र  
 विद्यावती राठौर, श्रीमती  
 विनय कुमार मुकर्जी  
 विश्वनाथ प्रसाद  
 विश्वनाथ राय  
 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी

विष्णु शरण दुबलिश  
 वीरेन्द्र शाह  
 वैकटेश नारायण तिवारी  
 शंकर दत्त शर्मा  
 शान्ति प्रपन्न शर्मा  
 शिव कुमार पांडे  
 शिवकुमार मिश्र  
 शिव दयाल उपाध्याय  
 शिव दान सिंह  
 शिवमंगल सिंह  
 शिव मंगल सिंह कपूर  
 सुचेता कपलानी, श्रीमती  
 श्याम लाल वर्मा  
 श्याम सुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द्र सिंहल  
 श्रीपति सहाय  
 सज्जन देवी महनोत, श्रीमती  
 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 सरवत हुसैन  
 सलीम हामिद खाँ  
 साजिद हुसैन  
 सालिग राम जैसवाल  
 सिद्दासन सिंह  
 सिराज हुसैन  
 सीता राम अष्ठाना  
 सुदामा प्रसाद  
 सुरेन्द्र बहादुर सिंह  
 सूर्य प्रसाद अवस्थी  
 हबीबुर्रहमान अन्सारी  
 हबीबुर्रहमान खाँ  
 हरगोविन्द पन्त  
 हर प्रसाद सत्यप्रेमी  
 ह्योतीलाल अग्रवाल  
 हैदर बख्श  
 त्रिलोकी सिंह

## प्रश्नोत्तर

शनिवार, ९ जुलाई, सन् १९४९ ई०

( शुक्रवार, ८ जुलाई, सन् १९४९ ई० के शेष प्रश्न )



## संश्लेषित प्रश्न

**मिर्जापुर जिले के बीज गोदामों के विषय में विवरण**

॥७२—श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के किस-किस स्थान में कितना गज्जा बीज गोदामों का बकाया है ?

माननीय कृषि सचिव ( श्री निसार अहमद शेरखानी )—माननीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। विवरण पत्र में बकाया गल्ले की तौल की जगह उसकी क्रीमत दी गई है, क्योंकि प्रतिवर्ष ३१ मई के बाद जब क्रिस्म में गल्ले की वसूली समाप्त हो जाती है, तो बकाया गल्ले का हिसाब रुपयों की शक्ल में रखा जाता है।

( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६१ पर )

॥७३—श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार निम्नलिखित विवरण सहित एक नक्शा मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(क) जिले में कितने बीज गोदाम हैं ?

(ख) किस बीज गोदाम के अन्तर्गत कितना गज्जा, कितने मूल्य का बकाया है ?

(ग) बकाया गज्जा किस-किस सन् का है ?

(घ) उक्त सन् में तत्सम्बन्धी बीज गोदामों के कौन-कौन सुपरवाइजर इंचार्ज थे ? उनके नाम क्या हैं ? वे इस समय कृषि विभाग या सहकारी विभाग की सेवा में हैं या नहीं ? अगर नहीं तो वे अब कहाँ हैं ?

**माननीय कृषि सचिव—**

(क) प्रश्न ७२ के उत्तर में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में जिले के सब बीज गोदामों के नाम दे दिये गये हैं।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान प्रश्न ७२ के उत्तर में प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र की और आकर्षित किया जाता है।

(ग) माननीय सदस्य की मेज पर + विवरण पत्र प्रस्तुत है।

(घ) माननीय सदस्य की मेज पर एक + विवरण पत्र प्रस्तुत है।

॥७४—श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में अत्यधिक बकाया रहने का क्या मुख्य कारण है ?

माननीय कृषि सचिव—अत्यधिक बकाया के मुख्य कारण एक सूची में लिखे हुये हैं जो माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत हैं।

( देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६२, २६३ पर )

॥७५—श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत सन १९४६-४७ ई० और १९४८ ई० की भीषण बाढ़ से मिर्जापुर के परगने किरियात सीखड़, हवेली चुनार, भुइली, अर्द्ध भगवत, कसिवार, तप्पा, कौन, तप्पा छानवे और तप्पा चौरासी पूर्ण विनष्ट हो गये हैं और इस हिस्से के किसान बीज गोदाम का कर्ज चुकता करने में पूर्ण असमर्थ हो गये हैं ?

माननीय कृषि सचिव—सन १९४६, १९४७ और १९४८ के बाद से किसानों को जो हानि हुई वह सरकार को विदित है। उस हानि में सहायता पहुँचाने के विचार से सरकार ने यह आदेश जारी किया कि जिला मिर्जापुर के पीड़ित क्षेत्रों को बीज गोदामों से जो बीज उधार दिया गया था वह बिना सूद सवाई व पिनाल्टी के गल्ले या उसके दाम के रूप में वापस ले लिया जाय।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इन क्षेत्रों में सहायता पहुँचाने का आदेश दिया था उसका पालन किया गया ?

माननीय कृषि सचिव—अगर उसका पालन न करने के खिलाफ कोई शिकायतें पेश की जायँ तो हुकूमत उसका जवाब दे सकती है।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर में बहुत अधिक अनाज बाकी रह जाने के कारण कृषि की उन्नति में बाधा पड़ रही है ?

माननीय कृषि सचिव—जी, हाँ।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या सरकार किसानों के इस कष्ट को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ।

श्री इंद्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार के पास किसानों की तरफ से ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि गल्ला अदा करने पर भी रसीद नहीं दी जाती और उनके नाम बकाया में लिख कर वसूल करने की कोशिश सुपरवाइजर करते हैं ?

—यहाँ पर छापा नहीं गया।



**माननीय कृषि सचिव**—जो शिकायतें इस क्रिस्म की गवर्नमेंट के पास आई हैं उन पर कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ महकम न कार्रवाई की है।

**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो किसान गल्ले के कर्ज से लदे हुए हैं उनके कर्ज को दूर करने के लिये सरकार कौन सा उपाय कर रही है ?

**माननीय कृषि सचिव**—यह मेरे महकमे से ताल्लुक नहीं रखता। जो मदद किसानों को दी जाती है वह ज्यादातर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दी जाती है। कृषि विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**डिप्टी स्पीकर**—क्या मैं यह समझूँ कि इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट की जानिब से देने को कोई खादिसा नहीं है। अगर माल के विभाग से इसका सम्बन्ध है तो माल की तरफ से इसका जवाब दिया जा सकता है। जब मैंने सवाल की इजाजत देदी है तो जवाब देना चाहिए।

**माननीय कृषि सचिव**—जो इस क्रिस्म की दरखवास्ते आई हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने विचार किया है और जहाँ किसानों को मदद देने की जरूरत थी वहाँ दी गई है।

**मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि**

§ ७६—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार को पता है कि मिर्जापुर जिला लगातार तीन वर्षों से अर्थात् सन् १९४६ ई० से ही गंगा एवं अन्य पहाड़ी नदियों की बाढ़ से पीड़ित हो रहा है ?

**माननीय प्रधान सचिव के सभा-मन्त्री ( श्री चरणसिंह )**—जी हाँ।

**श्री अचलसिंह**—गंगा नदी में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

**श्री चरणसिंह**—बाढ़ किसी नदी की रोकी नहीं जा सकती। बाढ़ आने से नुकसान कम से कम हो, उसके लिये प्रयत्न किया जा सकता है और वह किया जा रहा है।

§ ७७—**श्री विजयानन्द मिश्र**—क्या सरकार को पता है कि बाढ़ प्रकोप से खरीफ और ओला वृष्टि से रबी फसलों की भी भीषण बरबादी विगत वर्षों में हुई है ?

**श्री चरणसिंह**—मिर्जापुर एवं चुनार दोनों तहसीलों में बाढ़ के कारण क्षति हुई। किंतु चुनार तहसील के हवेली परगने के कुछ ग्रामों को छोड़कर रबी की फसल को क्षति नहीं पहुँची। इन थोड़े ग्रामों को ओले से नुकसान पहुँचा और उनको छूट दी गई।

❁ ७८—श्री विजयानंद मिश्र—क्या सरकार बता सकती है कि —

- (१) विगत सन् १९४८ ई० की बाढ़ में जन-रक्षार्थ सरकार ने बाढ़ के समय क्या-क्या सहायताएं जनता को क्रिन-क्रिन क्षेत्र में पहुँचाई ?
- (२) कौन-कौन सरकारी अधिकारी और जन-सेवक ने किस-किस क्षेत्र में सेवा और सहायता का कार्य किया ?
- (३) जनता को कितना अन्न व भूसा बाढ़ के समय और बाढ़ पशु-प्राणी रक्षार्थ बाँटा गया ?
- (४) कितनी तक्रावी बाँटी गई ?
- (५) गृह-निर्माण सहायतार्थ बाढ़ पीड़ितों को कितना रुपया बाँटा गया ?
- (६) कितने मज्दूरों की सेवा ली गई और उन्हें पारिश्रमिक मिला या नहीं ?

श्री चरणसिंह—( १ ) बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये तहसील मिर्जापुर १० भागों में विभाजित किया गया—

१—बाली पुरवा, २—चील्ह, ३—मवैया हरसिंहपुर ४—बबुरा, ५—अकोढ़ी, ६—कनतित, ७—नेवधिया, ८—मटौली, ९—छट्टहा, १०—खमरिया । तहसील चुनार तीन भागों में बाँटा गया ।

१—सीखड़, २—चुनार एवं ३—नारायनपुर ।

२—निट्टी का तेल, नमक, दियासलाई और अनाज दोनों तहसीलों में बाँटा गया था । अनाज मुफ्त बाँटा गया था और दूसरे पदार्थ उचित मूल्य पर दिये गए थे ।

मनुष्य, और पशुओं को निरापद स्थान में पहुँचाने में सहायता दी गई ।

३—(१) इसके लिए छोटी और बड़ी नावों का प्रयोग किया गया ।

(२) दोनों तहसीलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी और जन-सेवकों ने दुखियों को बाढ़ से बचने के लिए बहुत परिश्रम किया ।

(३) तहसील मिर्जापुर में ३०० मन अन्न और तहसील चुनार में ३६६७ रुपया का अन्न सहायता के रूप में बाँटा गया था । तहसील मिर्जापुर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में १५६ बैगन भूसा बाँटा गया । जितना भूसा प्राप्त हो सका, तहसील चुनार में बाँटा गया ।

(४) बोर्ड ने ५० हजार रुपया तक्रावी बाँटने की स्वीकृत जिलाधीश को प्रदान कर दी है ।

(५) नकान बनाने के वास्ते कोई रुपया नहीं दिया गया ।

(६) नहर्ना मिर्जापुर में ३०० और तहजील चुगार में २१६ मल्लाहों से सेवा ली गई थी और उन्हें २००० रुपया पारिश्रमक दिया गया ।

श्री विजयानन्द मिश्र—सरकारी अधिकारियों में से जिन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सेवा की, क्या उनमें से जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान भी थे ?

श्री चरणसिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री विजयानन्द मिश्र—क्या मिर्जापुर बाढ़ क्षेत्र में कोई आदर्श ग्राम बनाने की व्यवस्था की गई है या नहीं ?

श्री चरणसिंह—इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री विजयानन्द मिश्र—जो भूसा बाढ़ क्षेत्र में बाँटा गया वह बाढ़ खत्म होने के कितने दिनों बाद बाँटा गया ?

श्री चरणसिंह—बाढ़ खत्म होने के फौरन ही बाढ़ बाँटा गया ।

क०५६—८३—श्रीमती पूणिमा बनर्जी [ स्थगित किये गये । ]

नायर नदी में बाँध बाँधने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा  
नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट

क०५७—श्री जगमोहन सिंह नेगी—(क) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा नियत किए गए ५ विशेषज्ञों ने नायर नदी में मरोड़ा बाँध बाँधने के पक्ष में रिपोर्ट सरकार के पास पेश कर दी है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखेगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभा-सदस्य (श्री लताफत हुसैन)—

(क) जी हाँ !

(ख) रिपोर्ट की केवल एक ही नकल आई है और यह विभाग के विचाराधीन है । रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की राय और चीफ इंजीनियर की टीकाओं का ध्यान रखते हुये सरकार अपने फैसले पर पहुँचेगी । इस हालत में कोई नकल मेज पर नहीं रखी जा सकती है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह विशेषज्ञों की रिपोर्ट कब पेश हुई थी और कब तक गवर्नमेंट इस पर अपना अन्तिम निर्णय देगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—मैम्बर साहब ने जवाब से यह नहीं समझा कि वह रिपोर्ट अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँची ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या यह बात सही है कि प्रान्त में जो अन्य डैम बनाये जा रहे हैं उनसे केवल एक ही चीज अर्थात् पावर काम में लाई जायगी और इस डैम से विद्युत शक्ति और सिंचाई दोनों का काम होगा ।

**माननीय सावजनिक निर्माण सचिव**—यह तो हाउस में बहुत सी दफा बयान किया जा चुका है कि विजली बनेगी और इरीगेशन होगा।

**श्री जगमोहन सिंह नेमी**—मैं यह जानना चाहता था कि इस डैम के बनने पर क्या इसके दो चरों का लाभ ग्रामों को होगा, यानी सिंचाई का काम भी होगा और बाजार का भी ?

**माननीय सावजनिक निर्माण सचिव**—मैंने जो जवाब दिया उसके माने यह हैं कि इरीगेशन भी होगा और विजली भी बनेगी।

**श्री भवैर सिंह रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पशु विभाग की पेंशन का भुगतान**

क०५—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह सही है कि पशु विभाग के इंस्पेक्टर श्री भवैर सिंह लगभग ५ वर्ष हुए रुखाबन्धा में पेंशन पर नौकरी से अलग (रिटायर) हुए थे ?

**माननीय कृषि सचिव**—जी हाँ।

क०६—**श्री बलभद्र सिंह**—क्या यह भी सत्य है कि पेंशन का आज तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है ?

**माननीय कृषि सचिव**—जी हाँ। इसमें देर होने को वजह के बारे में जो रिपोर्ट तहकमे ले आई है वह माननीय सेक्टर की भेज पर रख दी गई है। कारण है कि अब एकाउंटेंट जनरल इसमें जल्द ही कार्रवाई करेंगे। गवर्नमेण्ट को जो देरी हुई है उसका अफसोस है।

**श्री बलभद्र सिंह**—क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि अभी इसमें कितना समय और लगने की आशा है ?

**माननीय कृषि सचिव**—इसका ठीक कहना मुश्किल है। मामला एकाउंटेंट जनरल के हाथ में है।

**श्री बलभद्र सिंह**—क्या सरकार को पता है कि यह अधिकारी एक असे से बीमार हैं और इस वक्त विस्तरे मर्ग पर हैं ?

**माननीय कृषि सचिव**—जी हाँ। मगर सुवर्जित मेम्बर को मालूम हुआ होगा कि इस बात में जो देरी हुई है उसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी श्री भवैर सिंह जी पर खुद है। उन्होंने मिलिटरी डिपार्टमेंट में जब नौकर थे तो वहाँ कुछ उम्र बताई और सिविल में दूसरी बताई। इसकी तहकीकात करने में काफी छानबीन करने की जरूरत पड़ी। जहाँ तक उनकी बीमारी का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को उनसे बहुत हमदर्दी है और जो भी जल्दी गवर्नमेंट इस काम कर सकती है वह करने की कोशिश कर रही है।

**श्री बनारसी दास**—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मिलने में प्रायः इस प्रकार की देरी होती है ?

—यहाँ पर छापी नहीं गयी।

**माननीय कृषि सचिव**—मुझे सिर्फ उन कसों के मुताल्लिक मालूम है जो गवर्नमेंट की नोटिस में आये हैं। बाक़ी हजारों आदमियों को पेंशनें होती हैं, उनकी तरफ़ से कोई शिकायत इस सिलसिले में नहीं आई।

**श्री बनारसी दास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस देरी की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

**माननीय कृषि सचिव**—बहुत हद तक तो भँवर सिंह जी के ऊपर खुद है और उसके अलावा जो सवालाल एकाउन्टेन्ट जनरल के यहाँ से किये गये उनके मुताल्लिक मेरे पास कोई ऐसी खास बात नहीं है जिससे मैं यह समझूँ कि इन मामले में कोई खास कर्मचारियों की तरफ़ से देर हुई है।

**मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफ़सर के सम्बन्ध में पूछताछ**

॥८८७॥—**श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)**—क्या सरकार मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफ़सर के सम्बन्ध में नीचे लिखे नक्शे के अनुसार सूचना देने की कृपा करेगी ?

न०	नाम स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफ़सर	मुक़दमों की संख्या जो फैसल किये			संख्या मुक़दमात जिनमें अपील हुई			संख्या मुक़दमात अपील मंजूर होने की		
		१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९	१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९

**माननीय माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)**—मेज़ पर रखी सूची में सूचना दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६४ पर)

॥८८८॥—**श्री भगवान सिंह**—[ स्थगित किया गया ]।

॥८८९-९०॥—**श्री कृपा शंकर**—[ स्थगित किये गये ]।

**सचिवालय में हिन्दी का प्रयोग**

॥८९१॥—**श्री कृपा शंकर**—क्या यह सच है कि सचिवालय के जो असिस्टेंट हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से उनके उच्चाधिकारी रोकते हैं ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—अब तक ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—अभी तक सचिवालय में पूर्ण रूप से हिन्दी में क्यों नहीं काम किया जाता है ?

श्री गोविन्द सहाय—इस सिलसिले में अभी तक कोई स्टैंडर्ड हिन्दी नहीं बन पाई है। इस वजह से देरी करनी पड़ती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—सचिवालय में हिन्दी किस हद तक प्रयोग में लाई गई है ?

श्री गोविन्द सहाय—जिस हद तक सम्भव हुआ उस हद तक प्रयोग में लाई जा रही है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार उन अहलकारों को जिन्होंने अब तक हिन्दी का काफ़ी ज्ञान हासिल नहीं किया है हिन्दी सीखने के लिये और मौका देने को तैयार है ?

श्री गोविन्द सहाय—इसका जबाब तो मैं दे चुका हूँ।

श्री बनारसी दास—क्या सचिवालय के सब सेक्रेटरी हिन्दी जानते हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—इसकी मुझे कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो नहीं भी समझते होंगे वे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं।

फ़िरोज़ाबाद में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच बनाने के विषय में पूछताछ

॥६२—श्री गंगाधर—क्या यह सही है कि सरकार ने फ़िरोज़ाबाद के लिये एक आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बेंच बनाना निश्चय किया है ?

श्री चरण सिंह—जी, नहीं।

श्री रामचंद्र पालीवाल—गवर्नमेंट ने जो कहा है उसका खुलासा करना चाहता हूँ फ़िरोज़ाबाद में कोई बेंच क़ायम करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री चरण सिंह—अगर कहीं कोई बेंच क़ायम करना हो तो ज़िला मैजिस्ट्रेट एक सेलेक्शन कमेटी बुलाते हैं और वह कमेटी आदमियों का चुनाव करती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा था कि वहाँ बेंच क़ायम करना मुनासिब नहीं है। इसलिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

श्री रामचंद्र पालीवाल—क्या यह सही है कि फ़िरोज़ाबाद में एक बेंच खोलने का इरादा था ?

श्री चरण सिंह—अगर यह इरादा न होता तो कमेटी बुलायी नहीं जाती। पहले उनका विचार था कि वहाँ एक बेंच खोल दिया जाय, लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदल दिया। शुरू में कमेटी बुलाना नहीं चाहिए था।

श्री रामचंद्र पालीवाल—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आद में जो बेंच न बनाने का इरादा बदला वह जिन कारणों से करता है ?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब बनाना मैं पब्लिक इंस्ट्रुमेंट में उचित नहीं समझता ।

§८३—श्री गंगाधर—क्या यह सही है कि मजिस्ट्रेटों की सिफारिश करने वाली कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट थे, तीन नाम सर्वसम्मति से तय किये हैं ?

श्री चरण सिंह—कमेटी ने दारुना सर्वसम्मति से तय किये थे ।

§८४—श्री गंगाधर—क्या सरकार के पास उन नामों की सिफारिश आ गयी है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

§८५—श्री गंगाधर—क्या यह सही है कि जिला मीटिंग में ये मामलत हुए थे उस मीटिंग को करीब तीन महीने हो चुके हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

§८६—श्री गंगाधर—क्या यह सही है कि कमेटी के सिफारिश किये हुए आगरे जिले के अन्य बेंचों के आनरेरी मजिस्ट्रेटों के नाम गजट हो चुके हैं और वे बेंच बराबर काम कर रही हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

§८७—श्री गंगाधर—क्या यह सही है कि फिरोजाबाद न्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि जिन नामों की सिफारिश जिला कमेटी ने आनरेरी मजिस्ट्रेटों की फिरोजाबाद बेंच के लिए की है उससे बोर्ड को असन्तोष है ?

श्री चरण सिंह—जी हाँ ।

§८८—श्री गंगाधर—क्या सरकार बतायेगी कि बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में क्या कारण बताये हैं ?

श्री चरण सिंह—बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में असंतोष का कोई विशेष कारण नहीं बताया है । केवल यही कहा है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद के लिये अधिक अनुभवी और प्रांढ़ पुरुषों को चुना जाय ।

मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता

§८९—श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ने मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव कर लिया है ? यदि हाँ, तो किसको चुना और उनकी योग्यतायें क्या हैं ?

**माननीय उद्योग सचिव श्री के.व.देव नालदीय**—जी हाँ। श्री दर्म्मलाल पांडे। ये जिला ग्राम दुधार के मूलभूत संयोजक थे। ये कृषि कार्य और ग्राम उद्योग में अधिक योगदान रखते हैं और जिला दुधार कार्यों में शुद्ध से हाथ बँटाते रहे। ये मैन्पुरी जिले के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं।

४१००—**श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)**—क्या सर्वनमेट के पास ऐसी शिकायत छः है कि जब से उनकी प्रतिक्रिया की गई है वे अस्वस्थ हैं और बोर्ड का सार्वजनिक के लिए अस्वस्थ हैं? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

**माननीय उद्योग सचिव**—जी नहीं। प्रश्न उठाया नहीं।

### पब्लिसिटी वान्स का जिलों में काम

४१०१—**श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)**—क्या सरकार बनवाने की कृपा करेगी कि जो पब्लिसिटी वान्स जिलों में भेजा गया है वे किन काम के लिए भेजी गयी हैं?

**माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)**—पब्लिसिटी वान्स जिलों में प्रचार कार्य में उपयोग के लिए भेजी गई हैं।

### सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ समाचार-पत्र निकालने की योजना

४१०२—**श्री बादशाह गुप्त (अनुपस्थित)**—सरकारी योजनाओं की सूचना जनता तक पहुँचाने के लिए क्या सरकार के विचाराधीन कोई समाचारपत्र जिले या ग्राम से निकालने की योजना है?

**माननीय प्रधान सचिव**—नहीं।

### फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या

४१०३—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में तारीख १७ व १८ मार्च, सन् १९४९ ई० को कितने ऐसे कैदी थे जो कम्युनिस्ट होने के कारण जेल में थे?

**माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहादुर)**—आठ कैदी ऐसे थे।

४१०४—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—इन पर जो डिटेन्शन (नज़रबन्दी) नोटिस लगायी गयी थी क्या उसके खिलाफ उन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेशन (प्रार्थना पत्र) किया? यदि किया, तो वह क्या था?

**माननीय पुलिस सचिव**—हाँ हर एक ने किया। इसके बाद चार कैदी छोड़ दिये गये और चार की दरखास्त नामंजूर कर दी गई है।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—जब नज़रबन्दी की दरखास्तें आती हैं तो उन पर जिला के किन किन अधिकारियों की राय प्राप्त की जाती है?



**माननीय पुलिस सचिव**—ज़िला ले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय आती है और उनकी राय पर गौर किया जाता है।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—गिरफ्तारी क्या पुलिस या उनके अधिकारियों द्वारा होती है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—जी हाँ।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—अगर कोई नज़रबन्द इन अधिकारियों से अपने को पकड़ित समझे तो उनके पास कौन-सा चारा है कि नरकार के पास अपनी राय पहुँच सके ?

**माननीय पुलिस सचिव**—हर डिटेनू को इस बात का मौक़ा दिया जाता है कि जो चार्जज उसके खिलाफ़ लगाए गए हैं उनका वह जवाब दे सकें और उसके खिलाफ़ जो कहना चाहें कहें। जब डिटेनू अपना रिप्रेजेन्टेशन भेजता है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या कोई और अधिकारी उसको रोक नहीं सकता और वह यहाँ गवर्नमेंट में आता है और फिर होम सेक्रेटरी और उसके बाद इस ख्याल से ताकि एक जुडिशल व्यू भी उसका लिया जा सके जुडिशल सेक्रेटरी उस पर गौर करते हैं और रिप्रेजेन्टेशन में दिये हुये जवाब को देख कर फिर फैसला करते हैं।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—जो दरखवास्तें सरकार के पास आई हैं उनमें से कितनी में यह कहा गया है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर नहीं हैं और उसके कार्य का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ?

**माननीय पुलिस सचिव**—चार में।

§१०५—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी**—क्या यह सच है कि इन लोगों में से केवल चार कम्युनिस्ट हैं और बाक़ी सब साधारण रेलवे कर्मचारी हैं ?

**माननीय पुलिस सचिव**—कुछ रेलवे कर्मचारी हैं परन्तु वे भी कम्युनिस्ट के प्रभाव में हो सकते हैं और उनके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

### आगरा ज़िले की हाउसिंग कमेटी में फ़िरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व

§१०६—**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि आगरे में हाउसिंग कमेटी है ?

**माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**—जी हाँ।

§१०७—**श्री रामचन्द्र पालीवाल**—क्या यह सही है कि ज़िले की हाउसिंग कमेटी में फ़िरोज़ाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

**माननीय अन्न सचिव—**जी हाँ, किराजावाद म्युनिसिपल बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड का एक ही प्रतिनिधि इस कमेटी पर है और वह चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड आगरा है।

### ग्रान्त में नये विधान के अनुसार मतदाताओं की सूची

४१०८—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—**क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हमारे ग्रान्त में नये विधान के अनुसार बाल-मताधिकार के बिना पद मतदाताओं की सूची तैयार हो गयी है ?

**श्री चरण सिंह—**इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है।

**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—**इन सूचियों और वॉलेट के छापने में क्या कार्रवाई की कर्ना का कोई डर है ?

**श्री चरण सिंह—**ऐसी कोई बात नहीं है।

४१०९—**श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी—**यदि नहीं, तो कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

**श्री चरण सिंह—**नये विधान के अनुसार मतदाताओं की सूची इस वर्ष के अन्त तक छप कर तैयार हो जाने की आशा है। फिर कुछ समय आपत्तियों के निर्णय करने में लगेगा और इसके बाद सूची तैयार सम्झी जा सकेगी।

४११०-११२—**श्री वंशीधर मिश्र—**[स्थगित क्रिये !]

**सन् १९४८-४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनो के लिये शिक्षा के मद में निर्धारित रकमों**

४११३—**श्री डारिकाप्रसाद मौर्य—**(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनो के लिए सन् १९४८-४९ ई० में शिक्षा के मद में अलग-अलग कितना रुपया निर्धारित हुआ था ?

(ख) निर्धारित रकमों में से कितना कितना खर्च हुआ और किस-किस ढंग से खर्च हुआ ?

**माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री ( श्री महफूजुर्रहमान )—**(क) सन् १९४८-४९ में पिछड़ी जातियों, परिगणित और मोमिनो की शिक्षा के लिये निम्नलिखित धन निर्धारित हुआ था:—

पिछड़ी जातियों के लिये	...	६०, ७६० रु०
अछूता क	...	११, ३१, २१५ रु०
मोमिनो के लिये	...	५१, ६७२ रु०

(ख) करीब-करीब सभी निर्धारित रकमों जो ऊपर दी गई हैं खर्च हो गईं। जिस जिस ढंग से यह रकम खर्च हुई उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

† यहाँ पर छापी नहीं गयी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बनवाने की कृपा करेगी कि जो छात्रवृत्तियाँ दी जान हैं उनका निर्णय कौन अधिकार करता है ?

श्री महफूजुर्रहमान—दस्तावेज क्लर्क को जिला इंस्पेक्टर करता है और इंटरमिडियेट क्लर्क की दवाँ ले दी जाती है !

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—उनके निर्णय का आधार क्या है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जो मुस्तहक हैं उनको दिया जाता है ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुस्तहक होने का फैसला किन बजूहात से किया जाता है ?

श्री महफूजुर्रहमान—डिप्टी इंस्पेक्टर उसकी जाँच कर लेते हैं और डाइरेक्टर आफ एजुकेशन भी इसकी जाँच कर लेते हैं ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मुस्तहक होने के बारे में सरकार ने कोई क्रायदा भी बनाया है ?

श्री महफूजुर्रहमान—इन परिगणित जातियों में जो गरीब हैं और जो क्राबिल हैं उनको दी जाती है ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जो रुपया निर्धारित किया गया है उसका क्या कोई जिलेवार हिस्सा भी कायम किया गया है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जिले जिले के लिये तो कोई मुस्तहक जेडा नहीं है ।

§ ११४—श्री यज्ञनाथयण उपाध्याय—[स्थिति निर्धारण]

बनारस जिले के इंटरमीडियेट कालेजों में लैनिंग शिक्षा

§ ११५—श्री यज्ञनाथयण उपाध्याय—बनारस जिले के इंटरमीडियेट कालेजों में से कितने विद्यार्थियों को लैनिंग शिक्षा दी जाती है ? इन विद्यार्थियों को पहनने के लिये क्या क्या सामान दिया जाता है और उसका क्या दाम है ?

श्री महफूजुर्रहमान—७४६. इनको निम्नलिखित सामान पहनने के लिये दिया जाता है ! दाम प्रत्येक सामान के सामने लिखा हुआ है :—

सामान	दान
१ शर्ट खाकी ड्रिल ( कमीज ) ...	... ५ रु०
२ शर्ट " " ( जांघिया ) ...	... ४ रु० ८ आना
३ बेल्ट " " ...	... २ रु०
४ ऊनी मोजा ...	... २ रु० ८ आना
५ ऊनी होजटाप ...	... २ रु० ८ आना
६ ऐंकेलेट या पट्टी ...	... ३ रु० या ५ रु० ८ आना
७ पेटी.....	... ४ रु० ८ आना
८ काला बूट ...	... ८ रु०
९ ऊनी जरसी ...	... १४ रु०

### राष्ट्रभाषा विद्यालय, बहराइच

❧११८—श्री लाल विहारी टण्डन—क्या सरकार को ज्ञान है कि बरहज जिला देवरिया में राज्य बापू जी द्वारा स्थापित राष्ट्र भाषा विद्यालय संस्था है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

श्री लाल विहारी टण्डन—रूज्य बापू जी ने इस संस्था की स्थापना कब की थी ?

श्री महफूजुर्रहमान—जहाँ तक याद आता है सन् १९३७-३८ में इसकी स्थापना हुई थी ?

श्री लाल विहारी टण्डन—इस संस्था की स्थापना के बाद यू० पी० सरकार के माननीय सचिव तथा सभा सचिव निरांकुश करने के लिए कब वहाँ गये थे ?

श्री महफूजुर्रहमान—जिन जिलों से बुलावा आता है वहाँ जाते हैं और वहाँ की संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं। इस संस्था से कोई आवेदन नहीं आया इसको देखा जाय।

❧११९—श्री लाल विहारी टण्डन—क्या गवर्नमेंट जानती है कि उसमें अब तक बर्मा, सिलान, कम्बोडिया, स्याम, बंगाल, आसाम, उत्कल, आंध्र, मद्रास, त्रावंकूर, गुजरात, महाराष्ट्र आदि देश तथा प्रान्तों से आये हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र भाषा की शिक्षा दी गयी है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार का मालूम है कि प्रश्नकर्ता ने जिन जिन देशों का नाम लिया है उनके आज भी विद्यार्थी इस संस्था में मौजूद हैं।

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—जी, हाँ। जहाँ तक इत्तिला है शायद इन सब देशों के विद्यार्थी मिलाकर केवल ५, ६ हैं।

❧१२०—श्री लाल विहारी टण्डन—क्या सरकार इस संस्था को सहायता देता है ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री महफूजुर्रहमान—सरकार इस संस्था का कोई आर्थिक सहायता नहीं देता। इसका कारण यह है कि इसके लिए संस्था ने कभी आवेदन-पत्र नहीं भेजा।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार ने बिना प्रार्थना पत्र भेजे ही संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की है या नहीं ?

माननीय शिक्षा सचिव—जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इस संस्था में अब यू० पी० के अलावा दूसरे सूबों के लड़के बहुत कम आये हैं।

( शनिवार, ९ जुलाई सन् १९४९ ई० के लिये रक्खे गये प्रश्न )

### ताराङ्कित प्रश्न

परगने मंगलौर की मुन्सिफी, देवबन्द जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा

❧१—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह सही है कि परगने मंगलौर की मुन्सिफी, देव बन्द जिला सहारनपुर में है ?

श्री चरण सिंह—सही है।

❧२—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह सही है कि मंगलौर से देवबन्द का फासला १४ मील है जिसमें एक मील पुख्ता बाक्री कच्चा है ?

श्री चरण सिंह—मंगलौर से देवबन्द सवा तेरह मील है जिसमें मंगलौर के पास की सवा मील सड़क पक्की है।

श्री अब्दुल हमीद—क्या बाक्री कच्ची सड़क पक्की बनाने का इरादा है ?

श्री चरण सिंह—जी, हाँ। इसको पक्की बनाने की योजना बन चुकी है।

❧३—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह ठीक है कि इस रास्ते में डाकखाना नहीं है और काली नदी पर पुल भी नहीं है ?

श्री चरण सिंह—ठीक है।

❧४—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह ठीक है कि इस रास्ते पर कोई मोटर या घोड़ा ताँगा नहीं चल सकता ?

श्री चरण सिंह—मोटर और ताँगे नदी के किनारे तक जा पाते हैं पर वह उसे पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्ष भर नदी और नालों में पानी बहता रहता है।

❧५—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह सही है कि मंगलौर से देवबन्द आने जाने में जनता को बहुत तकलीफ होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सुविधाजनक बात सोच रही है ?

श्री चरण सिंह—ठीक है। सरकार ने इस संबंध में यह निश्चय किया है कि देवबंद की मुंसिफी तोड़ दी जावे और उसकी जगह पर सहारनपुर में एक एडीशनल मुंसिफी बढ़ा दी जावे।

श्री अब्दुल हमीद—एडीशनल मुन्सिफी कब तक बन जायगी ?

श्री चरण सिंह—यह निश्चय हो चुका है बहुत जल्द बन जायगी।

### न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेंस का फरनीचर

❧६—श्री अब्दुल हमीद—क्या यह सही है कि न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेन्स में फरनीचर वगैरह किराये पर मँगा कर रखा गया है ?

श्री कृताफुत हुसैन—जी हाँ। न्यू रेजिडेन्स में ज्यादातर फरनीचर किराये पर मँगा कर रखा गया है।

४५—श्री अब्दुल हमीद—क्या मेहरबागी नरके हुक्मन बतायेगी कि कब से यह फरनीचर किस तादाद में और किम-किस किराये पर मँगाया गया और अब तक कितना रुपया किराये पर खर्च हो चुका है ?

श्री लताफत हुसैन—एक नक़्शा जिसमें माँगी हुई सूचना दी हुई है मेज़ पर रखा है इन मद में मार्च १९४६ तक का कुल खर्चा ७१५८ रुपया था ।

( देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६५ पर )

श्री मुहम्मद असरार अहमद—कौन्सिलर्स रेजिडेन्स के लिये अभी तक नया फरनीचर क्यों नहीं खरीदा गया है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—इसलिये कि अभी तक इसके लिये कोई स्टैंडर्ड क़ायम नहीं किया गया है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह स्टैंडर्ड कब तक क़ायम किया जायगा ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—जिस वक़्त तक कमेटी से फैसला होगा ।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकांश फरनीचर गन्दा और टूटा हुआ है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—मुझे मालूम नहीं है, मुमकिन है कोई टूटा हुआ हो ?

श्री बशीर अहमद अंसारी—यह जो ७,१५८ रुपये किराये के दिये गये हैं क्या यह इसी गन्दे फरनीचर का है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव—यह तो जवाब दिया जा चुका है ।

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व इस साल में शहर बदायूं और उजहानी के रहने वालों को सीमेण्ट व लोहे के परमिट

४६—श्री मुहम्मद असरार अहमद—शहर बदायूं और उजहानी (जिला बदायूं), के रहने वालों को सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० और साल हाल में नये मकान आदि बनाने के लिये जिलों के आफिसरों से और प्राविश्यल कण्ट्रोलर, कानपुर से कितना सीमेंट और लोहे के परमिट दिये गये हैं ? यह सूचना निम्नलिखित प्रकार दी जाय ?

- (१) जगह का नाम—उजहानी या बदायूं ।
- (२) परमिट लेने वाले का नाम मय पता ।
- (३) किस चीज़ का परमिट मिला—सीमेंट का या लोहे का ।
- (४) किस क़दर लोहे या सीमेंट का ।
- (५) किस काम के लिये परमिट दिया गया ।
- (६) इन परमिटों के देने की किसने सिफ़ारिश की ।
- (७) यह परमिट किन तारीखों को जारी हुये ।

(छोटे-छोटे कामों के परमिट जे 'जिलों' के आफिसरों ने दिए हों, और जो छोटे-छोटे और मरम्मत के लिये दिये गये हों उनकी सूचना की आवश्यकता नहीं है।)

**माननीय अन्न सचिव**—प्रश्न में पूर्ण गड़ सूचना सम्बद्ध परिशिष्ट में दिखाई गई है।

( देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २६६, २६७ पर )

४८—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—क्या परमिट देने वाले अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ऊपर लिखे हुए जो परमिट दिये गये उनके माल परमिट वालों ने उसी काम में लगाये जिस काम के लिये वे दिये गये थे ?

**माननीय अन्न सचिव**—जी नहीं। १९४६-४७ और १९४७-४८ ई० में जारी किये परमितों के बारे में इस बात की जाँच नहीं की गई है, और इतनी देर हो जाने पर यह जाँच संभव भी नहीं है। १९४८-४९ में जारी किये गये परमितों के दुरुपयोग का कोई उदाहरण बनाया जाय तो उसके बारे में जाँच की जायगी।

**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—नई इमारतों के बनाने के लिये गवर्नमेंट ने कितने लोहे और सीमेंट का मेक्सिमम मुक़रर किया है ?

**माननीय अन्न सचिव**—नई इमारतें जितनी बनेगी उनमें १२००० रुपये से ज्यादा लोहा और सीमेंट नहीं खर्च किया जा सकता है। इस तरह की हिदायत सीमेंट कण्ट्रोलर और आयरन-कण्ट्रोलर को दे दी गई है। और जो हाउसिंग कमेटी सिफ़ारिशें भेजती है उनसे भी कहा गया कि वे इस बात को अपने सामने रख लें।

**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—तब १९४६-४७ और ४८ के परमिट्स के रिकार्ड्स क्यों जाया हो गये हैं और किसके हुक्म से ?

**माननीय अन्न सचिव**—परमितों के रिकार्ड्स तो नहीं जाया हुए हैं लेकिन जिन-जिन बातों की जानकारी आप चाहते हैं उसमें तो समय लगेगा और समय बेकार खर्च हाँगा।

### विभिन्न विभागों के इन्तज़ाम में सरकार के अधीन नुमाइशें

४९—**श्री मुहम्मद असरार अहमद**—(क) सन् १९४६-४७, सन् १९४७-४८ ई० और इस साल में सरकार के अधीन किस-किस विभाग के इन्तज़ाम में किस-किस जगह और कितन-कितन तारीखों में नुमाइशें हुई ?

( ख ) हर एक नुमाइश पर अलहदा-अलहदा विभागों ने कितना खर्चा किया ?

**माननीय उद्योग सचिव**—( क ) एक † नक़शा जिसमें माँगी गई सूचना दी गई है, माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दिया गया है।

( ख ) यह सूचना † नक़शे में दी हुई है।

† यहाँ पर छाप नहीं गया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—यह नुमाइशें किस तरह से की जाती हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—गाँव में नुमाइश करने का यही मतलब होता है कि जो नरक़्तों हार चाहते हैं किमान उन्हें देखें और उसे क्रयूल करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—आज तौर से रुपया बड़े शहरों में नुमाइशों में बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल किया गया है और गाँवों की नुमाइशों में बहुत मामूली खर्च की गई है। इसकी क्या वजह है ?

माननीय उद्योग सचिव—ऐसा तो वहाँ है। अब इधर गाँवों में नुमाइशें ज्यादा हो रही हैं और वहाँ में बहुत कम।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेण्ट को मालूम है कि लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और मरठ की नुमाइशों में हज़ारों की तादाद में रुपया खर्च हुआ है और गाँवों में सिर्फ़ १०० या पचास के करीब ?

माननीय उद्योग सचिव—जहाँ की नुमाइशें ठीक तौर से की जाती हैं वहाँ ज्यादा रुपया लगता है और जहाँ ठीक तौर से नहीं हो सकती वहाँ रुपया की मदद करना ठीक नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—क्या गवर्नमेण्ट हर जिले में गाँव और शहरों में रोडेशन के हिसाब से नुमाइश करने का इन्तज़ाम करती है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं। कोई ऐसी योजना नहीं है।

### रोडवेज़ की मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में पूछताछ

❧ ११—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ ई० के प्रारम्भ से अब तक कितनी मोटर गाड़ियाँ रोडवेज़ के लिये क्रय की गई हैं ?

(ख) इन गाड़ियों में से कितनी चल रही हैं और कितनी खराब या बेकार हो गई हैं ?

(ग) उपरोक्त गाड़ियों के क्रय पर सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज़ के प्रारम्भ, अर्थात् १ मई, १९४७ से ३१ मार्च, १९४८ तक १५६५ मोटर गाड़ियाँ रोडवेज़ के लिये खरीदी गईं।

(ख) इन गाड़ियों में से ११०५ गाड़ियाँ चल रही हैं। ३८६ गाड़ियों की मरम्मत हो रही है और ७४ गाड़ियाँ जो राशनिंग विभाग की पुरानी गाड़ियाँ थीं बेकार हो गई हैं।

(ग) उपरोक्त गाड़ियों को खरीदने में सरकार का कुल १,६७००७७८ रुपया खर्च हुआ।

श्री खुशवक्त राय—जो मोटरों की तादाद दी गई है उनमें से कितनी नई खरीदी गई और कितनी विभिन्न विभागों से आई ?



माननीय पुलिस सचिव—करीब ३०० गाड़ियाँ रारानिंग डिपार्टमेंट से आईं। ५ क्री गाड़ियाँ नई खरीदी गई हैं लेकिन जा रेल रोड कोऑर्डिनेशन स्क्रीम जो पहले चलन को थी उस वक्त रेलवेज की तरफ से १०० गाड़ियाँ खरीदी गई थी और वह लेनी पड़ीं जो काफी अच्छा हालत में मिली।

श्री खुशवक्त राय—जो नई गाड़ियाँ खरीदी गई हैं उनमें से कितनी चल रही है और कितनी नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—उनमें से बिल्कुल ठीक तादाद तो मैं नहीं बता सकता लेकिन नई गाड़ियाँ जो खरीदी गई हैं करीब-करीब सभी इस वक्त सड़क पर हैं। शायद ही एक क्री सड़ी ऐसी हों जो खराब पड़ी हों।

४१०—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज पर वार्षिक व्यय क्या है और वार्षिक आय गत दो वर्षों में क्या हुई ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो धनराशि रोडवेज के मूलधन पर लगी है वह सरकार की निजी है या ऋण लेकर लगायी गयी है ?

(ग) यदि यह धनराशि ऋण लेकर लगाई गयी है तो उस पर सरकार को क्या सूद देना पड़ता है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज संचालन के प्रथम वर्ष में (मई सन् १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक) रु० ३२,०२,०३४) और दूसरे वर्ष में (अप्रैल सन् १९४८ से ३१ मार्च १९४९ तक) रु० १,४८,१५,४०१) खर्च हुआ। मई, सन् १९४७ ई० से ३१ मार्च सन् १९४८ ई० तक रु० ३६,५७,३६६) और अप्रैल, सन् १९४८ से मार्च सन् १९४९ ई० तक रु० १,६२,१३,४१०) की आमदनी हुई।

(ख) जो धनराशि रोडवेज के मूलधन पर लगी है वह सरकार की निजी है।

(ग) हालांकि रोडवेज में कर्ज लेकर कोई रकम नहीं लगाई है और सारी रकम सरकारी है मूलधन के ऊपर ३ रुपया सैकड़ा सूद हर साल नफा नुकसान के हिसाब के लिये निकाल लिया जाता है।

४१३—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज की गाड़ियों के सुधार के लिए सर्विस और मैन्टीनेंस स्टेशन कितने और किन-किन स्थानों पर हैं ?

(ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन स्टेशनों में किस प्रकार की मरम्मत की जा सकती है ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज की गाड़ियों के सुधार के लिये २६ मैन्टीनेंस स्टेशन्स हैं जिसकी सूची साथ नत्थी है।

(ख) इन २६ कारखानों में केवल प्रश्न श्रेणी की तथा बहुत ही साधारण देय भात का प्रबन्ध है।

देखिये न्तर्ही 'च' आगे पृष्ठ २३८ पर ;

५१४—श्री खुशवक्त राय—(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रोडवेज की गाड़ियों की बड़ी से बड़ी मरम्मत करने वाले कितने कारखाने रोडवेज विभाग के अन्तर्गत हैं और वह किन-किन स्थानों पर हैं ?

(ख) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन कारखानों में कितना रुपया प्रति मास व्यय होता है ?

(ग) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन कारखानों में पृथक-पृथक कितने आदमी और किन्-किस वेतन पर काम कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि ये कारखाने मिलाकर एक दिन में केवल ५ या ६ गाड़ियाँ ठीक कर पाते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—(क) रोडवेज गाड़ियों का खाम और बड़ा कारखाना कानपुर का सेण्ट्रल वर्कशॉप है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आठ और रीजनल कारखाने हैं जहाँ नानूली मरम्मत होती है।

१. रीजनल वर्कशॉप कानपुर	५. रीजनल वर्कशॉप आगरा
२. " " लखनऊ	६. " " बरेली
३. " " इलाहाबाद	७. " " गोरखपुर
४. " " मेरठ	८. " " काठगोदाम

(ख) इन कारखानों में प्रतिमास कुल मिलाकर ७६६५६ रुपया व्यय होता है।

(ग) इन कारखानों में काम करने वालों की तादाद और वेतन की सूची बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य उसे मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

(घ) जी नहीं। कुल रीजनल कारखानों में प्रायः सौ (१००) गाड़ियों की रोजाना मरम्मत होती है और सेण्ट्रल वर्कशॉप कानपुर में रोजाना तीन गाड़ियाँ दुबारा खोल कर पूरी बनाई जाती है। इस के अतिरिक्त वहाँ अन्य नये पुरे आदि भी बनते हैं और दो वसे (बस बाड़ी) रोज नये तैयार होती हैं।

**गाँव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़पीड़ितों की व्यवस्था**

५१५—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से गाँव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के बाढ़-पीड़ितों के बसाने के लिए कोई व्यवस्था हो रही है ? यदि हाँ, तो वह क्या ?

श्री चरण सिंह—सरकार की ओर से कुर्था गाँव के निकट छावनी, जहाँ ग्राम में एक ब्रह्म स्थान पर आदर्श ग्राम बनाने की कार्यवाही हो रही है, जिसके लिये सरकार के द्वारा जमीन ली गई है उस और स्थान पर मकान इत्यादि के लिये स्थान बाँट दिया गया है। कुछ लोगों ने मकान बनाने की नींव भी डाल दी है।

४०६—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बाढ़ पीड़ितों के दानाने के लिए सर्व प्रथम इंजीनियर ने गांव कुर्मी में हो ब्रह्म स्थान और बैर वाली बाग के बीच बाता पत्तों को पसन्द किया था और उर्ती की नाप की थी ? यदि जवाब हाँ में है तो उस जगह उन्हें बसाने में क्या कठिनाई है ?

श्री चरण सिंह—बैरवाल बाग व ब्रह्मस्थान को बीच वाली भूमि जिसको इंजीनियर साहब ( फलट्टारलाक ) ने पहिले देखा था गाँव के निकट की उपजाऊ भूमि था। श्री इंद्रव व त्रिपाठा और दूसरे कृषकों ने इस भूमि के लेने के विरोध में प्रार्थना पत्र दिन २० तारीख को देना था कि उक्त भूमि बहुत उपजाऊ है उसको लेने ल कृषकों को बहुत हानि पहुँचेगी। जाँच करने पर ये बातें ठीक प्रतीत हुई। कृषकों को देड़ दोड़ वाली भूमि जहाँ से सरसराहें और बैर पड़ी थी, ली गई। उसका कुल क्षेत्रफल १६ बीघा ७ बि० ७ घूर है जिसमें से १० बीघा ८ बि० १७ घूर गैर मजबूत है और ८ बीघा १८ बि० १० घूर मजबूत है। यह भूमि ऊँची है, सड़क के किनारे है और गाँव बसाने के लिये आदर्श स्थान है।

श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस जमीन को पहले इंजीनियर साहब ने पसन्द किया था उसका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये सवाल १७ का जवाब देखें।

४०७—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गाँव कुर्मी के बाढ़ पीड़ितों के पुराने घरों से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है और उसका क्षेत्रफल २ बीघा से ज्यादा नहीं है ?

श्री चरण सिंह—बैर की बाग वाली जमीन जो इंजीनियर साहब ने पसन्द किया था, बाढ़ से इनके पुराने घरों से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर है और उसका क्षेत्रफल २ बीघा से ज्यादा नहीं है।

४०८—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जो पुराना बाढ़ पसन्द की गयी है, उस जमीन के कितने किसान किस-किस जाति के हैं और उनको कितनी जमीन ली जा रही है और ले लेने के बाद उनके पास जावन विवाह के लिये कितनी जमीन बच रही है ?

श्री चरण सिंह—एक दिवस पत्र मेज पर प्रस्तुत है जिसमें कृषक और खेत गाँवों का विवरण दिया गया है। सरकार जाति सम्बन्धी सूचना देना उचित नहीं समझती।

[ देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६६ पर ]

४०९—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार के पास मौजूदा पसन्द की हुई जमीन ले लेने के खिलाफ उस जमीन के किसानों ने कोई प्रार्थना पत्र ता० ३ जनवरी, सन् १९४८ ई० को दिया था ? यदि जवाब हाँ में है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**श्री चरण सिंह—**जी. डी. प्रार्थना का प्रान्त होने के समय भवन निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका था और वहाँ प्रार्थना पत्र में कोई कारण विशेष न था अतः प्रार्थना अर्म्बकृत कर ही न डे ।

### प्रान्त में जिलेवार गुण्डों की संख्या

॥२०—**श्री गजाधर प्रसाद—**क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४५ ई० में जिलेवार कितने गुण्डे इन सूचों में थे ?

॥२१—**क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ता० ३१ मार्च, सन् १९४५ ई० को जिलेवार कितने गुण्डे इन सूचों में थे ?**

॥२२—**क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ता० ३१ दिसम्बर सन् १९४५ ई० को जिलेवार कितने गुण्डे थे ?**

**माननीय पुलिस सचिव—**गुण्डा शब्द की कोई सहज व्याख्या नहीं जा सकती । परन्तु ऐन वक्त जिन की पुलिस निगरानी करती है उनकी संख्या संयुक्त प्रान्त में १९४५ ई० में लगभग ७८४० थी, ३१ मार्च सन् ४५ को लगभग १३६५२ और ३१ दिसम्बर सन् ४५ को लगभग १५६६२ थी । जिलेवार संख्या निश्चित रूप से नहीं बतलाई जा सकती ।

॥२३—**श्री गजाधर प्रसाद—**क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि थाना बलुवा, जिला बनारस के अन्तर्गत कितने गुण्डे ३० अप्रैल, सन् १९४५ ई० के पहले थे और अब कितने हैं ?

**माननीय पुलिस सचिव—**थाना बलुआ जिला बनारस के सम्बन्ध में जो सूचना सरकार को मिली थी वह कुछ अंश में अपूर्ण थी । पूरी सूचना सानियर सुपरिण्टेंडेंट बनारस से माँगी गई है उसके आने पर उत्तर दिया जायगा ।

### बलुवा, जिला बनारस के थानेदार के खिलाफ शिकायत

॥२४—**श्री गजाधर प्रसाद—**क्या यह सच है कि इस थाने के थानेदार के खिलाफ आम जनता की शिकायत आयी है ? यदि हाँ, तो वह शिकायत क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

**माननीय पुलिस सचिव—**सरकार की जा कारी में थानेदार बलुआ के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है ।

### गुण्डों की संख्या बढ़ने के कारण

॥२५—**श्री गजाधर प्रसाद—**क्या यह सच है कि आजकल गुण्डों की संख्या बढ़ गई है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

**माननीय पुलिस सचिव—**पिछली लड़ाई के जमाने में हालत पहले से बदलने लगी । लड़ाई के बाद वह और खिजा गई । रंग कानूनी हथियार भी काफी संख्या में लोगों के हाथ में पहुँच गए । १५ अगस्त सन् १९४५ के बाद जो

स्थिति पैदा हुई उसका भी असर पड़ा। स्वराज्य का अर्थ कुछ लोग स्वच्छन्दता लगा रहे हैं निर्णय को पसन्द नहीं किया जाता। पुलिस को बहुत सतर्कता आंग कड़ा ने ज्ञान करने की जरूरत है। यदि सब राजनैतिक दल तथा जिम्मेदार व्यक्ति जनता को सही नेतृत्व करें और कानून व व्यवस्था के प्रति जनता में अधिक उत्पन्न करें तो दुश्मनों की संख्या में काफी कमी हो जायगी।

( प्रश्नों का समय समाप्त होने पर शेष प्रश्न ११ मई १९४६ के कार्यक्रम में रख दिए गए )

**सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांत के रुई ओटने और गाँठें बनाने के कारखानों के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा**

**डिप्टी स्पीकर**—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने और गाँठें बनाने के कारखानों के बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २३ अक्टूबर, सन् १९४८ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १७ जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति ३१ मई, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का नववाँ ऐक्ट बन गया।

**सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय म्युनिसिपैलिटीज़ ( अमेंडमेंट ) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा**

**डिप्टी स्पीकर**—मैं घोषणा करता हूँ कि सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय यूनाइटेड प्राविलेंज़ म्युनिसिपैलिटीज़ अमेंडमेंट बिल पर, जिसे संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ३० नवम्बर, सन् १९४८ ई० की बैठक में, तथा संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने अपनी १९ जनवरी, सन् १९४९ ई० की बैठक में कुछ संशोधनों सहित स्वीकार किया था, जिन संशोधनों को संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी ६ मार्च, सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति २७ मई, सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गई और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांत का सातवाँ ऐक्ट बन गया।

**सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ( जारी )**

**डिप्टी स्पीकर**—अब माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय, तथा श्री जगन्नाथ बख्श सिंह के संशोधन पर कि उपरोक्त बिल ३१ दिसम्बर, सन् १९४९ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय, विचार जारी रहेगा।

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय असीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २०१

श्री रघुनाथ विनायक धुले-र जन जन सत्य सत्य मानने दे रहे थे।  
कृपया वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर—श्री नूडिटी स्पष्ट साहब, मैं कल मध्या समय यह निवेदन कर रहा था कि निर्णय लेना राजाओं में विना भेद है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भारत के इतिहास में जिन राजाओं ने भारत सरकार के साथ अपने अथवा अपने सर्वेष्वंकरों एक-एक राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया है, उनमें अंतिमी मद्रास, तमिल ताना, और अंतिम देश भक्ति दिखा देता है। यदि इसी प्रकार हमारे जमींदार भी ऐसा ही करते तो नर्तक चला होता लेकिन उन्होंने यह मनमंजूर कि एक कण्डा मचा कर और यह मनमंजूर कि इस जमाने में यदि हम इसके विरुद्ध प्रोपेगंडा करें तो कदाचित् हमको कुछ सफलता होगी लेकिन मैं उन्हें बना देना चाहता हूँ कि जैसा कि फल देने बताया था कि यह एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर किसी का भी दखल नहीं हो सकता। यह तो एक प्रकार की ऐसी घटना है जिसका करना हमारे लिये, तथा प्रांतीय सरकार के लिए बिल्कुल आवश्यक था। किंतु मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ जिससे हमारे जमींदार यह बात मनमंजूर जायें कि जो कुछ उनको कम्पेन्सेशन मिल रहा है वह उनके साथ एक बहुत बड़ी रियायत है। जब कि आप लोग यह कहते हैं कि इक्की-टेबिल कम्पेन्सेशन होना चाहिये अर्थात् औचित्य और न्याय को देखकर कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर औचित्य के ऊपर जायें तो काँग्रेस सरकार को इस बिल में फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा और आपका कम्पेन्सेशन जो आपको दिये जाने वाला है उसको घटा करके शून्य रखना पड़ेगा।

आप देखें कि राजाओं और महाराजाओं का एक बहुत बड़ा इतिहास है। राजे और महाराजे इसलिए स्थिर नहीं रहे कि ब्रिटिश राज्य की उनके ऊपर कोई खास मेहरबानी थी। यदि आप प्रत्येक राज्य का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा और आप देखेंगे कि क्या जैपुर, क्या जोधपुर, क्या पटियाला, क्या उदयपुर, क्या कोल्हापुर, क्या शोलापुर और क्या आपकी ग्वालियर तथा इंदौर इन सब राजों के पीछे एक बड़ा इतिहास है। जिस वक्रत भारतवर्ष में विदेशियों के आक्रमण हुए उस समय इन लोगों ने क्या किया था। आप शिवा जी को देखिये, गुरु गोविन्दसिंह को देखिये, रणजीतसिंह को देखिये और महाराणा प्रताप को देखिए। आप यह कदापि नहीं कह सकते कि वह गद्दी की लालसा से विदेशियों का मुकाबला करने के लिये खड़े हुये थे। उस समय जो भारत के जवांमर्द थे उन्होंने विदेशियों का सामना किया था। वह भारत की प्रतिष्ठा तथा संस्कृति को बचाने के लिये खड़े हुये थे। यदि राज्य की लालसा से यह लोग खड़े हुये होते तो महाराणा प्रताप इससे ज्यादा अच्छी तरह से रह

[ श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर ]

सकते थे। उनके लड़के तथा लड़कियाँ तो घान की रोटी कदापि न खाना पड़ती। शिवाजी तथा अन्य महापुरुषों को जो जे. याननायें भुगतना पड़ीं, वह उन्हें न भुगतना पड़तीं। अंग्रेजों को मालूम है कि भारतवर्ष पर जब अंग्रेजों द्वारा आक्रमण हुये तो उस जनसमूह का वर्ण की मदनन्त्रता की रक्षा करने में इंदौर, ग्वालियर तथा पटियाला का विशेष हाथ रहा है। आप सब लोग भली-भाँति जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने विदेशी राज्य ने टक्कर ली थी। अंग्रेज अनेक प्रयत्नों के बावजूद उन्हें बरबाद न कर सके। इसलिए अंग्रेजों को दबकर उनसे सन्धि करना पड़ी। आगे चलकर ज्यों-ज्यों अंग्रेजी राज्य मजबूत होता गया यह राज्य उनके अधीन होते गये। इस हजार वर्ष के अन्दर देशी राज्यों ने अगर कोई काम किया तो वह यह कि एक-तहाई भारतवर्ष का हिस्सा भारत के हाथ में रखा। आज भी उन्होंने सब कुछ भारत राज्य के हाथ में सौंप दिया है। जमींदार वर्ग इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उनके अधिकार भी उतने ही बड़े थे जितने कि देशी राजाओं के और जो सुविधायें उनको दी जा रही हैं वह उनको भी दी जायें। मेरे कुछ जमींदार मित्रों ने यह कहा था कि ग्वालियर और इंदौर का तो अनेक सुविधायें दी जा रही हैं। मैं यह कहता हूँ कि आप इस बात को बतलाइए कि क्या आपके १५,२० लाख जमींदारों ने भारतवर्ष की ओर से लड़ाइयाँ लड़कर के यह जमींदारियाँ फायम की हैं? या बंगाल में जिस समय परमानेंट सैटिलमेंट हुआ उस समय आपने कोई लड़ाई लड़ी थी? उस समय अंग्रेज अपना राज्य मजबूत करना चाहते थे, आपने उनसे यह वादा किया था कि आप हमको अपने बीच में रखें। हम आपकी तरफदारी कर सकते हैं। हम अपने नौकर रखेंगे और हम बैगार लेंगे और आपको कुछ निश्चित रुपया दिया करेंगे।

अब दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, और यह एक इतिहास की बात है कि ग्वालियर, पटियाला आदि जितनी भी रियासतें थीं और उनकी जो कुछ भी आमदनी थी उस में से एक हिस्सा उनकी फौज पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर सड़कों पर म्यूनिसिपैलिटी पर खर्च होता था लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि जमींदारों की आमदनी में से भी कोई पैसा ऐसे कामों में खर्च होता है? आप अगर बलरामपुर के बारे में कहते हैं तो मेरे खयाल में ६० लाख की आमदनी में से वह इस पर ज्यादा से ज्यादा २ लाख ४ लाख खर्च कर देते होंगे। आप में से कितनों ने अपनी आमदनी का कितना हिस्सा अस्पतालों, स्कूलों सड़कों और अदालतों पर खर्च किया है? आप कहते हैं कि बलरामपुर अस्पताल खोला गया है लेकिन मैं कहना हूँ कि जो राजा १ करोड़ रुपया ले रहा है अगर उसने लाख २ लाख या चन्द रुपया इस तरह से दे भी दिया तो कोई खास बात नहीं। वह तो आप लोग अपने नाम के लिये, सर और आनरेबिल कहलाने के लिये और यहाँ पर बुर्सियाँ लेने के लिये किया करते थे। आप का नाम ही 'ताल्लुकेदार' है इसी से साफ़ जाहिर है कि आप का

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २०३

नाल्लुक्क बड़े-बड़े नवाबों ने रहने के कारण आप 'नाल्लुकेदार' कहलाये जहाँ नाल्लुकेदार के माली ने मेरी सल्लुक्क में कोई खास नहीं होते। राजा जगन्नाथ बग्गुश त्रिह साहब ने एक संतोषक पेश किया था कि इस बिल को आप ४ महीने के लिये टाल दें और पब्लिक की राय जानने के लिये छोड़ दें। मैं आप से पूछता हूँ कि अगर पब्लिक की राय किसको कहते हैं? इस भवन के पास १० मं. अर्जजु दासों के सिवा इस भवन के लिए हिस्से ने आप को मदद मिल रही है? मैं समझता हूँ कि आप के एक ग्रुप के अलावा जो ८, १० मेम्बरों का ही है, वह तनान मेम्बर जो एक-एक १० लाख आदिमियों की तरफ से रुमा-इन्दे होकर आ रहे हैं आप की मदद नहीं दे रहे हैं। रोशन जमा खाँ साहब आप की मदद नहीं करने, फखरुल इलाज साहब ने भी आप की मदद नहीं की और मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी के लीडर लार्दी साहब जो आज अपनी पार्टी की तरफ से बोलने वाले हैं वह भी यह नहीं कहेंगे कि जमींदारी प्रथा रहनी चाहिये। चैम्बर आफ कानर्स वालों ने भी ए. ए. रिजोल्यूशन पास किया है कि वह व्यापारी वर्ग भी जमींदारी प्रथा के खिलाफ है। यूनीवर्सिटी का रिजोल्यूशन, स्टूडेंट कांग्रेस, मजदूरों मिलों, वार एलेमिएशन समी की तरफ से कहीं भी कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि जमींदारी एबालिशन नहीं होना चाहिये। अगर वहीं से भी इस तरह की आवाज़ उठाई गई होती तो आप का यह दावा हो सकता था कि इसे पब्लिक की राय के लिए भेज दिया जाय।

मेरा कहना यह है कि जो मनुष्य अपनी किसी बात का दावा पेश करता है उसका चाहिए कि पहले सबूत इस बात का पेश करे कि आपकी राय, आप की चीज़ पब्लिक सुनने के लिए भी तैयार है या नहीं। मैं समझता हूँ कि जमीन से लेकर आसमान तक कोई तबक्का ऐसा नहीं है जो आपके साथ हो। कोई भी शख्स जमींदारों का साथ नहीं दे सकता। इसलिये आपका यह कहना कि ४-५ महीने के लिए और रोक दिया जाए व्यर्थ है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब सन् ४६ में एक प्रस्ताव पेश हुआ था कि जमींदारी यहाँ से हटा दी जाय यदि आप उसी वक्त उसको मान लेते तो मैं समझता हूँ कि आपको २०-२५ गुना कम्पेन्सेशन मिल जाता लेकिन आपने इसको टालना चाहा और उसका नतीजा यह हुआ कि हजार आँखें उस पर पड़ीं। नतीजा यह हुआ कि एग्रीकल्चुरल इनकम टैक्स और लगा दिया गया इसलिए आपकी इनकम जो है वह अब इस टैक्स को काट कर लगाई जाती है। अगर उस वक्त रजामंद हो जाते जब कि यह एग्रीकल्चुरल टैक्स नहीं लगता था उस वक्त आपको ज्यादा मुआविजा मिल जाता। आप इसे अब ४-५ महीने और टालता चाहते हैं तो मैं आप से कहे देता हूँ कि शायद नया बिल इस बात का आ जाए कि जो हिस्सा आपलोगों का बचता है उसमें से १० परसेण्ट आपको मिलेगा और ६० फ्रीसदी सरकार के पास चला जायेगा। वक्त बढ़ा-बढ़ा कर, मैं आप से कहता हूँ, कि आप अपने ही साथ शत्रुता कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। अब



[ श्री खुन्नाय विनायक मुलेकर ]

आप कहते हैं कि गान. ले लो जाए इन बातों को कि जमींदारी रखी जाये या न रखी जाए. लेकिन आज यह स्पष्ट है कि हर शख्स समझता है कि जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये. मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं या अन्य सदस्य बोल रहे हैं इसलिये नहीं बोलते कि भवन के अन्दर जो सदस्य मौजूद हैं वह समझ लें कि जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये। वह इसलिये बोल रहे हैं कि पब्लिक इस बात को समझ ले कि जमींदारी रहना चाहिये या न रहना चाहिये। इस वजह से मैं दो चार मिनट और लेना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कि आप अच्छी तरह से समझ ले और पब्लिक इस बात को समझ ले। ज़िम्मी का मुल्क में काश्तकार के ऊपर जो ज़मीन का टैक्स लगता है जिसे लगाना चाहते हैं मूलतः १० रुपए में से ४ रुपए तो एक आदमी को दे दिए जायें और ६ रुपए दूसरे आदमी को दे दिए जायें तो जो चार रुपए सरकार के पास पहुँचें उन पर तो उसका अख्तियार है कि वह उनका प्रबन्ध कर सके लेकिन जो ६ रुपए उन पर उसका कोई अख्तियार प्रबन्ध करने का नहीं है। जमींदारों में जितना लगान जमींदार को मिलता है उसमें से जो हिस्सा सरकार को जाता है उस पर तो प्रजावंत के अनुसार इस बैठक में, इसके बाहर चर्चा हो सकता है। उसके हिसाब को देखा जा सकता है, जाँच पड़ताल की जा सकती है। हर एक आदमी जो यू० पी० में रहता है वह उसको जाँच सकता है लेकिन जो हिस्सा जमींदार को जाता है उस पर किसी का अख्तियार नहीं है यह देखने का कि वह किस तरह से खर्च किया जाता है। आप मोटर पर खर्च करते हैं, मकानात में खर्च करते हैं, शार्दियों में खर्च करते हैं, किसी को अख्तियार नहीं कि वह आप से पूछ सके। स्वराज का अर्थ यह है कि जो मनुष्य भारतवर्ष में पैदा हुआ है और वह सरकारी गैरसरकारी किसी भी रूप में टैक्स देता हो उनको पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिए यह पूछने का कि वह टैक्स किन प्रकार खर्च किया जाता है। आप हमें बतलाएँ कि आपको जो ६० फीसदी रुपए मिलना है पिछले ३० वर्ष में जो आमदनी आपको हुई उसका आपने क्या किया? भारतवर्ष के लिये आपने क्या किया, उसके उत्थान के लिये आपने क्या किया? मैं पूछना हूँ कि आपने इन ३० सालों के बीच में किसानों के लिये गरीबों के लिये और यहाँ को निर्दिष्ट जनता के लिये क्या किया? हम नहीं चाहते कि आप किसानों के बीच में रहें और बिना उनका कुछ लाभ किये हुये आराम की जिन्दगी बमर करते रहें।

आप कहते हैं कि अगर लैंड एक्वीजीशन के अन्तर्गत किसी से अगर कोई मकान लिया जाता है तो उसे उसकी कीमत दी जाती है, उसी तरह से हमने भी मेहनत की है और हमें भी मुआविजा मिलना चाहिये। मैं आप से पूछता हूँ कि यह मुआविजा कैसे हो सकता है। जो मकान बनवाता है, वह अपनी मेहनत से रुपया कमाता है, उसके बाद सीमेंट खरीदता है, लोहा

खरीदता है, दिन-दिन उस गड़बड़ कर नार बढाता है। नारा इंतजाम उसके बनवाने का करता है लेकिन आप क्या करते हैं। मकान में जो रहता है वह कुछ नहीं करता। सदर रिपट देकर रहता है, जो कि केवल मकान मालिक को लाई है। आदमी और नेह-नवा मुक्ति हो जाता है। जब मकान को मरम्मत करनी होती है तो वह मकान मालिक करता है। जमींदार की वह स्थिति नहीं है जना, आपने कहा बनाई, जमी-ना प्रह्ला ने बनाई। आप उस पर खेती ना रहा करत, आप ग्राह नहीं डालते आप बैल बगेरह भी नहीं देते। वह तो काश्तकार है जो कि दिन रात जमीन की देख-भाल करता है। दिन भर पसीने को बहा कर, चिलचिलाती धूप में उसको जोतता है। रात भर पानी में भिंकाकर नी बही बैठा रखवाला करता रहता है। फिर भी आप कहते हैं कि इनको आविजा दिया जाय, प्रतिकर दिया जाय, क्योंकि आप ऐसी हालत में निर्मीया मकान के मालिक का दज। मैं तो कहता हूँ कि आपकी स्थिति उस नमाशवान की है, जामु, की लहरे जितनी है। जमु, तो परमात्मान बनाया है, फिर भी वह नमाशवान कह सकता है कि इनको उसको देखने और गिज का मेहनताना दिया जाय, हम उसका दान दिया जाय। मेरा तो यहाँ कहना है कि जमा, परमात्मा न बना रहे, आप तो केवल उसके दृष्टा हैं। आपने कि ह दिया है तू जमान जोत ल, और फिर अपने महल के अन्दर खत का दृष्टा में आराम से पड़े रहे। मैं कहता हूँ कि अब हाँ तनान चोपा ना जमाना चला गया। इसके सिवा जा हज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे महान पंत जो और हमारी यह महान कांग्रेस सरकार दिल रखती है। आपकी इन काला करतूतों के बावजूद भी वह आपको मुक्तान नहीं पहुँचाना चाहता। आप कांग्रेस का शुक्रिया अदा कीजिये, महात्मा गांधी का शुक्रिया अदा कीजिये, कि हम कन से हम यह तो कहते हैं कि अगर यह कुछ भी पाने लायक नहीं है तो यह हमारे भाई हैं, और इन्हें कुछ दो। हम तो उहिंसा के ऊपर चल रहे हैं। बार बार इस बात को दुहरा दी जा रही है कि हिन्दुस्तान इसलिये आजाद नहीं हुआ है कि किसी खास तबक्के को एकदम मिटा दिया जाय।

आप जानते हैं दूसरे मुल्कों में रिवोल्यूशन हुआ है। वहाँ पर वैसी हालत में कोई आदमी कह सकता था कि जनाब जमींदारी जा रही है आप हमें दाम देते जाइये। रुस में क्या हुआ, लाखों और हजारों आदमी जो जिन्दा कहे जाते थे दूसरे ही दिन नब खाक में निला दिये गये। खून का नदियाँ बह गई। क्या आप उनको बुलाना चाहते हैं और जल्द बुलाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप दृष्टि रखते हैं, यदि आप केवल चर्म चक्षुओं से ही नहीं देखते हैं तो आप देखिये कि इन तीन साल में भारतवर्ष में क्या हुआ। एक रात में ही सब कुछ हो गया। जो जहाँ सोया था वहीं रहा लेकिन जिन्होंने इसे तलवार के बल पर जीता था वे क्रलम से दूर चले गये।

[ श्री रघुनाथ त्रिनाथक धुलेकर ]

प्राप्त स्वरूपान्तर नवावानी गांधी की मेहरबानी से से यह सब कुछ हो गया जिसके कारण आज जमींदार लोग सुरक्षित हैं। इतना विरोध करते हुये भी आपका जान का खतरा नहीं है। अब भी जब कभी कोई साशालिस्ट यह कहना है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप वाह-वाह करते हैं कि यह बिल चन्द दिनों में टल जाय लेकिन अगर टल जायगा तो कहा नहीं जा सकता कि इस भारतवर्ष में आपकी दुराक्या होगी। हमारे दोस्त नवाब साहब ने कहा कि उनसे कुछ अनजबो और खादाग से बात कर ली जाय। हम भी यही कहते हैं और आहसा के आन्दोलन का पहिला उद्देश्य ही यह है कि जो विरोधी हैं पहिले हम उनसे बातें करे और उसे संशुद्ध करेंगे, उसे मनवायेंगे और जब उनका गले में वह बात उतर जायगी तभी कुछ कार्य करेंगे। आपको जो कम्पेन्सेशन मिल रहा है वह बहुत अधिक मिल रहा है। अगर आपको मुर्तहान भी लगाना जाये और हिन्दोस्तान की जमीन को आपने यहां रहने भी सनमा जाये जो उसमें २० वर्ष का हिसाब देना पड़ता है। सूद दर सूद से उस जमीन के बोल लाल के मुनाफे का हिसाब लगा लोजिये। इ. बीस सालों में आपने हिन्दोस्तान के लिये क्या किया और और नहीं किया है तो आप व्याज दर व्याज से उसे वापिस कीजिये। एक को आप नोट कर लोजिये और फिर विचार कीजिये कि जमींदारों के साथ कितनी रियायत वरती गई है। मेरे दिल में ऐसी ही एक रियायत थी जिसे न नवाब के सामने इसलिये नहीं कहा जा चाहता कि कहीं ऐसा न हो जाय कि इसी हाउस के हमारे कुछ दोस्त अभी दरखवास्त पेश कर दें और कानिशा करे जा कुछ आपका मिला है वह भी न मिले (आवाजे—रहने दीजिये, न कहिये)।

आप यह देखें कि दूसरे लोग भी इन्स्तान हैं। उनके लिये यह शर्त है कि ३० ऐकड़ से ज्यादा नहीं जेत सकेगा। सवा छै ऐकड़ जिन्दगी का भियार समझा गया है। लेकिन आपके यहाँ का जो घसखोदा है वह भी उतना कमा सकता है जितनी आदमी इन नवा छै ऐकड़ में होती है। लेकिन यह सब भी आपकी बजह से करना पड़ा है क्योंकि यदि आपके १ हजार ऐकड़ का फार्म है तो आप भूमिधर हो जायेंगे। हर गाँव में आपकी सीर हो जायेगी और सब आपका हो जायगा और आप फिर भी मौज में रहेंगे।

जरा कराखदिली देखिये कांग्रेस की। पहले कहा जाता था कि छोटे जमींदार ढाई सौ रुपया तक सनमे जाने वाले हैं लेकिन अब ढाई सौ से पाँच हजार हो गया है। कांग्रेस ने आप लोगों पर रियायत करके पुनवसिन अनुदान पाँच हजार तक दे दिया है। अब आप देखिये कि इतनी बड़ी रियायत के होने हुये आप कहते हैं कि इस बिल में हमारे हाथ ज्यादाती हुई है।

एक चीज और कहकर मैं समाप्त करूंगा। सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह बात बड़ी जोरदार कही गई है कि हमको यह चाहिये था कि हम जमीन का बटवारा दुबारा कर देते। मेरा कहना यह है कि आप बटवारे की बात तो

करते हैं तो जिन यह नहीं बताते हैं कि बच्चारा किस तरह होना चाहिये। अगर यह चाहते हैं कि पहले इस तरह कह दें कि सब जमीन जवत की गयी और फिर हम बच्चारा कर देंगे इस तरह १०४२ के अन्तर्गत हम इस बात के लिए लड़ते रहें कि जिन जमीनदारों ने अपने और किसानों के अन्तर्गत न मिले। मैं तो यह कहूंगा कि क्रेम ने यह बहुत ही ठोस बातों को है कि उसने यह कहा है कि जो जमीनें जिनके कब्जे में हैं वह उन्हीं के कब्जे में रहें। जब लोग पहले काबिज कर दिये जायेंगे उसके बाद यह सोचने का जवाब रहेगा कि कौन-कौन सी और बातें हैं। मैं उन आदमियों में नहीं हूँ जो यह कहते हैं कि जमींदारी के सिलसिले में यह अन्याय बिल है हिन्दुस्तान में जो एक बड़ा भारी जुल्म मध्यवर्तियों के ऊपर चला आ रहा था उसके हटाने के लिए हमने पहला कदम उठाया है। जो काश्तकार जो सारदार जो जमींदार जिस जमीन पर काबिज है उसको उसी जमीन पर काबिज कर दिया है और जो जमीन बाकी बची उसको ग्राम समाज को दे दिया है।

यह भी कहा गया है कि महानगिन के बजाय रिपब्लिक या इण्डियन यूनियन शब्द होना चाहिये। मैं यह नहीं हूँ कि महा नगिन का शब्द रखना केवल एक फार्मेलिटी है। अभी बिल चल रहा है और लोग महानगिन के अंदर अगर विधान परिषद ने रिपब्लिक डेक्लेयर कर दिया तो यहाँ इण्डियन यूनियन शब्द कर दिया जायेगा।

जमीन का सारा इन्तजाम हमने जनता के हाथ में रख दिया है। अभी तक जो जमीन जिनके पास थी उन्हें को वह जमीन हमने दे दी है। अब जो जमीनें बाकी हैं उनका पटवारा हम इस तरह करेगे कि जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको जमीनें देंगे।

इसके बाद आप यह देखेंगे कि लड़करी खेती संस्था की योजना कितनी उच्च कोटि की है। यदि १० लाख लोग चाहते हैं कि वह मिलजुल कर सहकारी खेती संस्था बना लें तो वह बन जायेंगे। इसी तरह अगर किसी मंडल के दो तिहाई लोग यह चाहते हैं कि वह सहकारी खेती संस्था द्वारा खेती करें तो वह कर सकते हैं और उनके साथ एक तेहरी पाकरी लोगों को भी शरीक होना पड़ेगा। धारा २२२ के जरिये उनकी मालगुजारी कम कर दी जायेगी सुविधायें दी जायेंगी। जिससे भूमि की तरक्की की जा सकती है।

अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। वह यह है कि जिस वक्त यह जमींदारी बिल काम में आयेगा, उस वक्त लाखों अजिबियाँ कागजात की दुरुस्ती और सेइत की गुफरेगी। यह भी इस वक्त का कानून है कि १५ आने का ठिकट हुआ करे। इसमें कई लाख रुपये का खर्चा होगा। तलबाना का लाखों रुपया होगा सब से जहलत की कार्यवाही और बुरी बात यह है कि इस के अन्दर जितनी कार्रवाईयाँ हैं वह अदालती कार्रवाईयाँ हैं। मैं कहता

[ श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर ]

हूँ कि हमारा गराव क्रिस्तान तो मर गया। इसलिए उचित समय पर इस बात का सुझाव करूँगा और अब भी सुझाव करता हूँ कि इस बिल के अन्दर यह घोषणा हो जाना चाहिये कि जो कारवाइयाँ इस बिल में हों वह अदालती कारवाइयाँ न समझी जायें। उनके ऊपर क्रिकट और टेम्प लगे तो एक आना दो आने का। इस प्रकार बर सकते हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वकील सजाज पहले से ही अजगर की तरह मुँह बाएँ वेठे हुए हैं कि यह बिल आने दो। जमींदार बिल से लाखों मुकदमों होंगे और लाखों रुपया हमारी जेब में आयेंगे। मुकदमा होगा, अपील होगी, सपील होगी लाखों रुपया हम कमायेंगे। मेरा सुझाव है कि इन कार्यवाहियों में वकील का प्रवेश न होना चाहिये। जिस प्रकार पंचायत राज्य ऐक्ट में कोई वकील नहीं जाता है उसी तरह वकालतनामा लगाकर कोई शख्स नहीं जा सकेगा। इसके बाद जो हिस्से गराव हिस्से हैं जैसे कि बुन्देल खंड वहाँ के शासकारों के साथ रिआयत होना चाहिये। ६। एकड़ बहुत कम हैं। मैं उचित समय पर इस बान को पेश करूँगा। अन्त में प्रभियर साहब और विशेष कर अपने साथी चरण सिंह जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। चरण सिंह जी ने जमींदारी अवालिशन कमेटी में रात दिन मेहनत की और कोशिश करके इसकी रिपोर्ट और इस बिल को तैयार किया। मैं समझता हूँ कि यह अथक परिश्रम जिसके कारण मौजूदा बिल इस सूरत में आया और जिन्होंने इस सम्बन्ध में काम किया है, उन सब की प्रशंसा करता हूँ। उन सबकी बड़ी भारी सद्भावना रही है। अन्त में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में जमींदार विनाश शब्द रक्खा है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। कान को खरखरा मालूम होता है। महात्मा गांधी भी 'जमींदारों का विनाश' शब्द नहीं चाहते थे। मैं कहूँगा कि 'जमींदारी का विनाश' उठा दीजिये केवल 'भूमि की सुव्यवस्था बिल' इसका नाम रक्खा जाय। वह ज्यादा अच्छा है। मैं यह कह कर समा चाहता हूँ।

श्री श्रीराम लाल हसनन लारी—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मोहतरम वजीर आजम की तजवीज की जो उन्होंने ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की पेश की है ताईद करता हूँ। जमींदार पाटों की जो तरमोम है उसकी मुखालफत करता हूँ।

जहाँ तक तरमोम का सवाल है चन्द जुमलों में इसका जवाब दिया जा सकता है। जमींदारों का मसला बीस बरस से मुल्क के सामने है। हर जमा-अत ख्वाह वह कांग्रेस से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखती हो, ख्वाह जमींदार तबके से ताल्लुक रखती हो, सब ने अपने-अपने नुक्ते खयाल को मुल्क के सामने रखा है। इस मसले पर बेशरत हज़ारात ने अखबारों, रिसालों और

श्रीमाननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २०६ क्लिटावां में अपने खयालात का इजहार किया है। जमींदारी अवालिशन कमेटी की रिपोर्ट एक बरस से लुक्क के सामने है। मैं नहीं समझता कि ऐसा बिल जितने इन्तजारों करोड़ों को मुडन से थो और जं खुदा-खुदा करके आज इस ऐशान के सानने आया है ताकि वह कानून की शक्ति अखितयार कर सके, यह कहाँ तक मुनासिब होगा कि इसका पास करने में एक मिनट की भी देर को जाय ? अलावाबरीं मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा देर करना जमींदार भाइयों के भी खिलाफ होगा। जो मेहरबानी आज जमींदार भाइयों के साथ यह कांग्रेस गवर्नमेंट कर सकती है वह कल को आने वाली एक दूसरी गवर्नमेंट करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। अगर दूसरा चुनाव हुआ और उसके बाद एक जमात आयी तो मैं समझता हूँ कि उसका फैसला जमींदार भाइयों के खिलाफ बहुत हद तक होगा इसलिए जो लोग जमींदार भाइयों से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी जमींदारी का खतना इस तरीके से किया जाय कि वे बिल्कुल मुफलिस न हो जायें तो मैं समझता हूँ कि वे इस जमींदार लीडर के इस तहरीक की कृतअन मुखालफत करेंगे और जमींदार भाइयों को समझावेंगे कि जो मेहरबानी आज इस मसजिदे कानून में हो रही है उससे ज्यादा कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसलिये आपको चाहिये कि उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। खाल कर के जब मैंने प्रीएम्बिल को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रीएम्बिल में यह लिखा हुआ है “चूँकि यह अम्र करीने मसलहत है कि सूबे मुतहदा में काश्तकार और हुकूमत के माबैन दरमियानी अशखास के हकूक खत्म करने और उनके हकूक हकूक मिलिकयत और इस्तहकाक हासिल करने और कब्जे आराज्जी से मुताल्लिक ऐसे कानून की इसलाह करने के लिये जिस पर ऐसे खाल्मे और उसूल का असर पड़ेगा और उनसे मुताल्लिक दीगर उमूर की बाबत इन्तजाम किया जाये। इसलिए मुन्दरजे जैल कानून बनाया जाता है।” प्रीएम्बिल अपनी जगह पर बेहतरीन है कोई भी जीहोश आदमी इसकी मुखालिफत नहीं कर सकता है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ता हूँ और दफा ६ बी० को देखता हूँ तो जो खयाल इस प्रीएम्बिल को देखने के बाद पैदा हुआ था उसमें कुछ कमी हो जाती है और कुछ मायूसी का खयाल भी दिल में पैदा हो जाता है। दफा ६ बी० में यह है... “सूबेजाती हुकूमत को जायज होगा कि अगर वह ऐसा करना जरूरी समझे तो तहत दफा १ में मुतजकिरा इश्तहार सिर्फ ऐसे रकबा या रकबेजात की बाबत बक़तन फक़तन जारी करे जिसकी या जिनकी तशरीह इश्तहार मजकूर में कर दी गयी हो।” गोया अगर यह दफा कायम रखते हैं तो यह कानून सिर्फ कहने के लिये ही कानून रह जाता है। यह गवर्नमेंट के अखितयार में हो जाता है कि वह जमीन्दारी को खत्म करने के लिये जिस तरह की कार्यवाही करना चाहे करे। यह उस पर मुनहसर है कि वह एक तहसील ले या एक जिला ले या कब्जे में न आने वाले एक जमीन्दार को ले या एक ज्यादा इंडिपेंडेंट (आजाद) ताल्लुकेदार को ले। यानी इसका पता नहीं है कि गवर्नमेंट कब तक इसका

और जमींदार हसन लारी :

निकाज करे. मुझे तो ऐसी बातें मालूम हैं कि नहीं एल्का भी तो इसी हथ नहीं होगा जो ग्राह बिशन ( ग्रेवें ) का लक्ष्य है ? हमने ग्राह बिशन को सन् १९२६ ई० में शुरू किया. हमने कहा कि हमने यह कालिस्ती अखितकार की है लेकिन आज तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं जो निहान आसानी से गिन सकेंगे. कहा जा रहा है कि इस निजात में यह कह रहा था कि इस दफा के खते में तो ज्वालात केरे निजात में पैदा हुये थे उसमें थोड़ी सी कमी पैदा हो गयी है. कुछ मायनों में सत्य है तो है. इस दफा को देखने के बाद जब मैं जालिस्ती दफा प. पहुँचता हूँ तो वहाँ पर मेरी मायूसी कुछ और बढ़ी हो जाती है. मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप जमीन्दारी के बजाय स्टेट लैंडलाडिज्म को लायेंगे. वहाँ ऐसा तो नहीं होगा कि सारा सूबा कोर्ट आफ वाईस के मातहत आ जाय और उसका कुछ नतीजा नजर न आये ? इन तीन बातों को सानने रखते हुये मैं समझता हूँ कि बहस मजमूई का एक अगला कदम उठाया गया है और इसलिये मैं इस मसविदे कानून का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी इन तमाम खामियों पर जो इस मसविदे कानून में हैं गौर करेगी और यह प्रीएम्बल कोई फाट नहीं होगा बल्कि प्रीएम्बल का निकाज कराने पर ही सही तौर पर मसविदा कानून होगा ।

मैं जमींदारी का खात्मा जैसा कि हमारे लायक प्रीमियर ने कहा था इसलिये नहीं चाहता कि मैं जमींदारों का कोई दुश्मन हूँ बल्कि मेरे नजदीक जमींदारी का खात्मा एक सामाजिक जरूरत है. पहली चीज तो यह है कि यह एक सामाजिक जरूरत है, दूसरी यह कि तारीखी लाआवादियत ( हिस्टारिकल इनएविटेबिलिटी ) जरूरत है और तीसरी यह कि यह एक एकनाभिक नेसे-सिटी ( इक्विसादी जरूरत ) है. अगर इन तीन बातों के लिहाज से देखा जाय तो गालिवन जमींदारी का खात्मा जरूरी है. अगर सामाजिक जरूरत को मैं आपके सामने पेश करूँ तो १२ साल के तजुर्वे से आपको यह बतलाता हूँ कि जमींदार तबका एक क्रदागत परस्त तबका है और सरकार परस्त तबका है और हमेशा रहा है. जाहिर है कि आजाद मुल्क ऐसी जमाअत का, एक ऐसे निजाम का जो क्रदामत परस्ती पैदा करता है, जो हुक्मन परस्ती के ख्यालात में पैदा करता है मेरे ख्याल में उसका रहना किसी तरह से मुनासिब नहीं है. यह खुद जमींदारों के नोजदान तबके के खिलाफ है. जाहिर है कि एक निजाम जो उनको कज़रवाटेव ( दकियानूस ) बना दे, जो उनको काबिल न करे कि मुल्क की बढ़ती हुई लहर में भी वह अपने शाने शायों हिस्सा ले सकें, ऐसा एक समाज जो हमारे सामने है उसका खात्मा जरूरी हो जाया करता है. दूसरी चीज जो हिस्टारिकल इनएविटेबिलिटी की है. मुमकिन है कि मेरे दोस्त इस पर मुझसे मुख्तलिफ राय के हों जमींदारी निजाम क्यों वजूद में आया लेकिन मैं अपनी जगह पर तमाम कितारों के मुताले के बाद इस नतीजे पर





[ श्री जहीरुल हसनैन लारी ]

चाहे जैसा भी हो। जमींदारी का ख़ातमा होना लाज़िम् है लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि जो निज़ाम आप आज पेश कर रहे हैं वह कहाँ तक मुफ़ीद है। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि आपने टेनेण्ट के इण्टरेस्ट को कहाँ तक बढ़ाया है इस वक़्त निज़ाम क्या है? एक वह क़ल्टीवेटर (खेतिहर) है जो सीर की खुदकाशत रखता है वह ज़मींदार है वह सीरदार है। दूसरा उन कारशकारों का तबक़ा है जिनको पञ्चशन के पूरे हक़ हासिल हैं जैसे ओकुपेन्सी और हैरिडिटरी के राइट जिनको हासिल हैं। तीसरे वह तबक़ा है जो मज़दूर असामी है जो जब चाहे तब निकाला जा सकता है। चौथा तबक़ा है जो सीर की काशत करता है वह क़ानून से उसमें से निकाला जा सकता है लेकिन आपने क़ानून बनाया उससे उनको बेदख़ल करने से ममनून करार दिया। यह चार क़ास इस वक़्त टेनेण्ट की है। अब इस बिल में जो आपने बनाया है क्या पैदा होता है। भूमिधर और सीर वाले में कोई फ़र्क़ नहीं है जो खुद मालिक बन जायेगा उसी को आप भूमिधर कहेंगे। दूसरा तबक़ा सीरदार का आता है वह कौन है वह वही काशतकार है जिसको पाञ्चशन के राइट हासिल हैं आकुपेन्सी राइट वगैरा जिसको हासिल होता है। तीसरा तबक़ा असामी का है यह वहाँ है जिसको आज भी ज़मींदार निकाल सकते हैं। चौथा तबक़ा है अधिवासी जिसको आप कहते हैं वह सीर की काशत करने वालों का तबक़ा है जिसको आप ५ वर्ष के लिये हक़े मक़ाबज़त दे रहें हैं। वह ज़मीन से ५ वर्ष तक निकाला नहीं जा सकता। गोया यह चार सूरतें आपने टेनेण्ट की अपने यहाँ रखी हैं जो कि मैंने आपके सामने अभी बयान की। आप उसी चीज़ को दूसरे अलफ़ाज़ में दूसरे नाम से क़ायम रख रहे हैं। तो आपने क्या अख़्तियार दिये। आप यह कहेंगे कि इसमें दो फ़क़ हैं एक तो यह है कि अगर सीरदार चाहे तो वह १० गुना लगान देकर भूमिधर हो सकता है और दूसरा यह है कि अधिवासी १५ गुना लगान देकर सीरदार हो सकता है। तो यह अख़्तियार तो उनको पहले से ही हासिल है जो सीरदार के हक़ हैं वह भी उसको पहले से हासिल हैं। आपका यह क़ानून अपनी जगह पर अपने ज़रिये से कोई अख़्तियार नहीं देता है। यह सवाल कि वह अपना हक़ हासिल कर सकेंगे या नहीं यह दूसरी बात है। अगर किसी सीरदार के पास पैसा नहीं है और आपको वह १० गुना लगान अदा नहीं कर सकता है तो वह सीरदार ही रहेगा। और अगर अधिवासी अपना १५ गुना लगान अदा नहीं करता है तो वह ५ साल के बाद उससे अलग कर दिया जायगा। तो जो कुछ इस क़ानून के ज़रिये से उनको हक़ मिलता है वह सिर्फ़ यह मिलता है कि वह एक ख़ास क़िस्म के हक़ अपनी ज़मीन पर हासिल कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा आप यह देते हैं कि गाँव समाज को यह अख़्तियारात अगर गवर्नमेंट चाहे तो दिये जा सकते हैं जैसे कि लैंड का इन्तज़ाम आबादी का इन्तज़ाम करना। लेकिन उनके ऊपर निष्क्रियत स्टेट की रहेगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यह अख़्तियार उनको या तो गाँव समाज को मुन्तक़िल

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २१३

कर सनती है। तो यह कहना कि हमने बहुत राइट उनको दे दिये यह गलत है। आप यह नहीं कहते कि जिस रोज जमींदार हट जायेंगे तो जो हकूक हैं, जो टेनेंट में बेन्ट होंगे वह कौन से हैं जो कि उनके लिये वसीय किये जायेंगे। फिर आप की तरफ़ी का सवाल पैदा होगा। बाज़ गाँव में आप देंगे बाज़ में नहीं देंगे बावजूद इसके कि आप यह कानिशा करें कि अनइम्प्लाइमेंट पैदा हो। जैसा सप्लाई डिपार्टमेंट ने करप्शन को बढ़ाया कहीं यही हालत न पैदा हो जाय। इन दफ्तर के अन्दर दफ्ता ७ और दफ्ता १६७ में। इसी लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि टेनेंट को अख्तियार देने का क्या सवाल है और आपने क्या उनको दिया आपने जमींदारी अवालेशन रिपोर्ट में इस बात से इखतलाफ़ किया है। जमीन के टेनेंट जो दो क्रिस्म के हैं उनको तमाम अख्तियार हासिल हैं जैसे कि भूमिधर और जैसे असामी को होंगे। हाँ यह खराबी उसमें थी कि आपने सीर के टेनेंट को और सब टेनेंट को कोई अख्तियार नहीं दिया था। मिनिट आफ़ डिस्सेंट में मैंने कहा था कि उनको अख्तियार मिलना चाहिये लेकिन आप क्या करते। एक तरफ़ तो आपने उस अख्तियार को जो जमींदारी अवालीशन कमेटी दे रही थी कि बिला रकम दिए वह जमीन पर क्राबिज हो जाँय, उसे छीन लिया दूसरी तरफ़ आपने कहा कि हम इस शर्त का तो मानते हैं कि सब टेनेंट को मिलना चाहिये लेकिन वह लगान का १५ गुना अदा करे। अब सवाल यह है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि रुपया देहातों में फटा पड़ा हुआ है, दौलत की वहाँ कसरत है, अफ़रात है। उसमें खासकर हमारे चरण सिंह साहब हैं जो कहते हैं कि काश्तकार बहुत आसानी से यह रकम दे सकेगा। लेकिन मैं आपकी तबज्जह खुद जमींदारी अवालीशन कमेटी की रिपोर्ट की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि यह कहाँ तक ठीक है। अगर आप जमींदारी अवालीशन कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा ५६१ की तरफ़ देखें तो आपका मालूम होगा। सेंसस रिपोर्ट जो सन् १९३१ ई० में हुई थी उसमें यह कहा गया था कि:—

“Yet even the debt-free peasant is desperately poor. We have seen that a considerable proportion of cultivators are working on uneconomic holdings from which even in favourable years they can scarcely derive sufficient to keep body and soul together.”

( इस पर भी जित्त काश्तकार पर ऋण नहीं है वह अत्यन्त निर्धन है। हम ने देखा है कि काश्तकारों का एक बड़ा भाग ग़ौर इकितसादो ज़ातों पर काम कर रहा है जिनसे अच्छे वर्षों में भी वे बड़ी कठिनाई से इतना पैदा कर सकते हैं कि जिससे उनका पेट भर सके। )

यह तो रिकार्ड सन् ३१ का था अब सन् ४८ में भी जमींदारी अवालीशन कमेटी क्या कहती है। उसके फ़ाइंडिंग्स यह हैं:—

[ श्री जहीरुल हसनैन लारी ]

"The high prices of food-grains and commercial crops really benefited only the substantial landlords and the small section of the peasantry which held economic holdings; for the poor peasants and agricultural labourers, the war really meant further pauperisation. It may, therefore, be safely said that they did not get any advantage as a result of the rise of prices."

( खाद्य पदार्थों और विजारती फसलों की ऊँचे दामों से वास्तव में केवल बड़े-बड़े जमींदारों का और उन थोड़े से काश्तकारों को ही लाभ पहुँचा है जिनके पास इकतेसार्दा ज़ोते हैं। निर्धन काश्तकार और खेतिहर मजदूर तो लड़ाई में और भी निर्धन हो गए हैं इसलिए यह आसानी के साथ कहा जा सकता है कि दामों के बढ़ने से उनका कोई फायदा नहीं पहुँचा । )

तो यह फाइंडिंग है सन् ४८ की। सन् ३१ से लेकर ४८ तक यह हालत है। टेनेंट की कि जो अनएकनामिक होल्डिंग के टेनेंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है। इसी कमेटी की फाइंडिंग यह है कि क्राफ़ा फोसर्दा टेनेंट की होल्डिंग ५ एकड़ से कम है। ८१ फ्री सदी ऐसे टेनेंट्स हैं जिनकी ५ एकड़ से कम है। ६७ फ्री सदी ऐसे टेनेंट्स हैं जिनकी १० एकड़ से कम है। ३८ परसेंट टेनेंट्स ऐसे हैं जिनकी होल्डिंग एक एकड़ से कम है। इसके मानी यह हुए कि अगर यह भी आवश्यकताएँ जो मैंने आपके सामने पेश किये हैं सही हैं तो ८५ परसेंट पी.जेंट्स इस पोजीशन में नहीं हैं कि वह आपको रेंट दे सकेंगे। अगर वह नहीं दे सकते तो टेनेंट्स का जो लाट था वह वहीं पर कायम रहना। वह एक इंच भी नहीं बढ़ता। हाँ हमें यह तय्यकी जरूर होती है कि जमींदारों जरूर खत्म होती है और हुकूमत को यह इत्तिमान हो जाता है कि वह भारी रेंट हमारे काफ़र में आयेगा, हमें नॉशन मिलेगा कि हम सरकार-जान को बढ़ा सकें और बजट में इजाफ़ा दिखला सकें। आप यह तो पूछ सकते हैं अब एकनामिक होल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं उनको नहीं देना पड़ेगा या उन्हें लिये कोई तरीका निकालते। अगर नहीं करते हैं तो नताजा क्या होगा कि जाने बड़े बड़े टेनेंट्स हैं, ५० एकड़ के और ३० एकड़ के हैं वह तो इस क्राबिल होंगे कि वह भूमिधर के हुकूक हासिल कर सकें लेकिन वह टीभिग मिलियंस जिनकी घंसी हुई आँखों की तरफ़ आप इशारा किया करते हैं उनके हुकूक वहीं रहेंगे जो पहले थे। अभी मौक़ा है। अभी तो यह बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है। आपकी तवज्जह की जरूरत है कि आप टेनेंट के हुकूक को बढ़ायें।

अब आप दूसरी बात देखें। टेनेंट पर बरडिन (बोम) क्या कम हुआ ? रेंट.....

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २१२

**डिप्टी स्पीकर**—अब आप वक्त्रों के बाद अपनी तक्रारें जारी रखेंगे।

(इस समय १ वक्त्र भवन स्थगित हुआ और २ वक्त्र २ मिनट पर डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री ज़हीरुल हसन लारी**—जन्मद वाला, मैं लंच टाइम से पहले इस ऐजेंड के सामने यह अर्ज कर रहा था कि जहाँ तक टिलर्स के हकूक का सवाल है यह मसविदा कानून उन के हकूक में कोई इजाफा नहीं करता। अब मैं दूसरी बात लेना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस मसविदा के मातहत टेनेंट पर जो लाइवेलिटीज या बर्डेन है उस में कोई कमी होती या नहीं। लेकिन क्लर इस के कि यह सवाल पैदा हो कि बर्डेन में कोई कमी हुई है या नहीं आप लानुहाला पूछेंगे कि क्या कोई बर्डेन भी उस पर है। अगर टेनेंट इन वक्त्र इस क्लॉबिल है कि जो उसकी जिम्मेदारी रेंट की शक्ति में है वह अदा कर सकता है तो जिसो बर्डेन के कम करने का सवाल पैदा नहीं होता। जा हज़रत जमींदारी अधालेशन कमेटी के मेम्बरान थे वह मुझ से इतिहास करेंगे कि वह कमेटी तयान जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि वह टेनेंट जिन्दगी होल्डिंग्स छोटी हैं, उन पर बर्डेन ज्यादा है और उसमें कमी करने की जरूरत है। चुनावे उन्होंने यह तय किया था कि रेंट में उड़ारा के तय की जाय, जिस के पास कम जमीनें हैं उन के रेंट में नरते हिस्सा कम कर दी जाय, इस सिफारिश को बिना खत्म कर देता हूँ और जा ज़ूम रेंट है वही दर राखस का अदा करना पड़ेगा।

हमारे लायक वर्डर आज़म ने कहा है कि यह बिल हमने जो वादे काश्तकारों से किये थे, उनको पूरा करता है, जो हमारी खेजेज हैं उन को पूरा करता है। मैं पूछता हूँ कि क्या यह वाक्या नहीं है कि कांग्रेस ने काश्तकारों से यह प्लेज किया था कि काश्तकारों की वह तमाम अनएकोनामिक होल्डिंग्स के रेंट को माफ कर देंगे? मेरे दास्त गालिबन भूल न गये होंगे कि सन् १९३१ ई० में कांग्रेस कमेटी ने उसके मुताबिक तद्दीकात शुरू की थी। उस वक्त्र जो कमेटी ऐग्रेरियन डिस्ट्रेस कमेटी के नाम से हुई थी उसने कहा था कि रेंट ख्वाह उस को कोई भी नाम दिया जाय जो पैदावार किसी होल्डिंग से होती है, जो खर्चा और खाने पाने के बाद जो बचता है उस से तो रेंट लिया जा सकता है। रेंट जो है सर्प्लश का जुड़ा है जो खर्चा पड़ता है उसका जुड़ा नहीं है उन्होंने यह अल्फाज कहे थे, "Rent should be the first-charge on surplus but it can be a charge on surplus alone."

(बचत से सबसे पहले लगान लेना चाहिये किन्तु यह केवल बचत से लिया जा सकता है)।

[ श्री जहीरुल हसनैन खान : ]

यह उन के अल्लाह थे। उस के बाद सन् १९३६ ई० में जब कांग्रेस एग्रीगियन कमेटी बैठी, र. लिब. उस के मेम्बर हमारे क्राबिल वजीर आज़म भी थे, और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन भी थे, उन्होंने जो कहा था मैं उन अल्लाह को आपके सामने पढ़ा हूँ।

"The correct theory of rent ought to be that a tenant should pay only that amount as rent which remains after meeting his personal and family expenses and the prime cost of production."

(लगान का ठीक सिद्धान्त यह होता चाहिये कि किसान लगान के रूप में केवल वह रुपया दे जो उसके अपने और घर भर के खर्चे और पैदावार का ठीक-ठीक खर्चा पूरा करने के बाद उसके पास बच रहे।)

इसके बाद उन्होंने एड. लिक्कारिश की थी कि हमें एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिये जिसकी रू से अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स का रेंट कतअन माफ़ कर दिया जाये। उनकी लिक्कारिश यह भी थी कि—

"It is essential that the existing burden of rent should be reduced and uneconomic holdings exempted from rent."

(यह आवश्यक है कि लगान का मौजूदा भार कम किया जाय और गैर इक़तेलादी ज़ोतों को लगान से बरी किया जाये।)

यह यह वायदा है जो कांग्रेसी हज़रात ने यू० पी० की इस बसनेवाली जनता और खेती करने वाली जनता के साथ किया था। मैं पूछता हूँ कि क्या इस वायदे के मुताबिक उनकी अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स बाकी नहीं रह गई है। खुद इस कमेटी की रिपोर्ट है कि १० एकड़ से कम ज़मीन अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। हमारे पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी श्री चरण सिंह जी का भी यही खयाल था कि साढ़े छै परसेण्ट एकड़ से कम एरिया जिनके पास है वह अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। अगर हम उनकी तज़वीज़ मान लेते हैं तब भी बहुत काफ़ी अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। सोशलिस्ट व्यू (समाजवादी विचार) के लिहाज़ से मानें तब भी जिनके पास १२ एकड़ से कम एरिया है वह सब अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। ज़मींदारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जिनके पास १० एकड़ से कम एरिया है वह अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। मैं इन सबको छोड़े देता हूँ। सिर्फ़ केबिनेट के एक मिनिस्टर के तख़्मीने को लेता हूँ जो यह फ़रमाते हैं कि जिनके पास साढ़े छै फ़ीसदी एकड़ से कम एरिया है वह अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स है। अगर इसको सही मान लेते हैं और कोई वजह नहीं है कि यह सही न हो तो ज़मींदारी अबालीशन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके लिहाज़ से ८७ फ़ीसदी अनइकोनॉमिक होलिडिंग्स हैं। अगर आप फिर भी रेंट में कमी नहीं करते हैं तो इसके माने यह है कि

आप जमींदारी एवालिशन कमेटी की सिफारिशों को पनेपुस्त डाल देने हैं क्या आप न जलाने के लिए नये दायें का पूरा करना यही है। क्या जलाने की ताल्लुक व इतरना यही है। हाँ एक खास नबक्रे को यह कह सकते हैं जो कि सक्सर्टि एल टनेट्स (पर्याप्त किसान) हैं उसके जज्ज व का किसी हद तक तनहो हो जाती है लेकिन बहुत बड़ी अवस्थिति इन सूचे का रहनेवालों का तनहो हर्जि नहीं हो सकती। इतलिये मैं अज्ज कहूँगा और जैसा कि मेने तनहो जाफ प्रोसीडिंग्स में भी लिखा था कि डेढ़ करोड़ रुपया बन कल्ला तनहो नहीं था। दूसरी वजह यह देखिये कि हमारे कायसी भाड़े हमें यह कहा करते थे कि इन २० वर्षों के अन्दर जमींदारी ने एक बड़ी हद तक स्टेट में इजाजत कर दिया है और यह चीज नहीं थी है। जा फिगस मुहय्या किये गये हैं उनसे पता चलता है कि सन १९६६-६४ एक दो सौ चोबाल हजार रैयटल था यह ४४-४५ में यह एक लाख चार सौ तिरासी हजार हो गया। यानी ५५६ लाख का इजाफा हो गया। यानी बरखिलाफ इसके रेवन्यू पहले ५ लाख ६३ हजार था अब ६ लाख ६८ हजार हो गया, इस तरह से चार करोड़ का इजाफा हुआ। वही यह जाता था कि जमींदार बड़े जाली हैं। इन्होंने पहले जमींदारी के उर्मा तनहो से मालगुजारी अदा करके हर साल चार करोड़ रुपया अपनी जेब में रखा। इंतजाम सही था। लेकिन जब जमींदारी खत्म हो रही है और इसका इन्तजाम स्टेट के हाथ में पहुँच रहा है तो क्या स्टेट का यह फर्ज नहीं था कि वह यह कहे कि जो दगा के चारेये हासिल किया गया है मैं उसकी वसूल नहीं करूँगा।

तो फिर क्या वजह है कि आज यह गवर्नमेंट नहीं कहती कि हम इस ४ करोड़ रुपये को अपने खजाने में नहीं लेंगे और इसको खत्म कर देंगे। आप गौर करें कि खुद जमींदारी एवालिशन कमेटी ने कहा था कि डेढ़ करोड़ की कमी इस में कर दी जाय लेकिन आज आप उसको भी नहीं मानते। आप जिसको टेण्डेड मनी कहते थे उसको आप हर साल अपनी ट्रेजरी में वसूल करते हैं और पहले से आप कहते चले आते थे कि टीनेट्स पर बार ज्यादा है तो आप का यह रुपया आज भी बदस्तूर वसूल करना कहाँ तक जायज हो सकता है? जहाँ तक अनएकानामिक हॉलडिंग का ताल्लुक है, आज जब आपको पूरा मौका मिलता है और जमींदारी एवालिशन कमेटी भी सिफारिश करती है कि उनको एकानामिक बनाया जाय लेकिन आप उसको भी रद्द कर देते हैं और आप के लिये वह सिफारिश नाकाफी और रही हो जाती है। इसलिए साफ नतीजा यह निकलता है कि जहाँ तक किसानों पर बरडेन का ताल्लुक है उसमें किसी तरह की भी कमी नहीं हुई है।

अब तो यह चीज मैंने आपको बतलाई कि उनके हक्क में कोई इजाफा नहीं हुआ और दूसरे यह कि उनके बरडेन में कोई कमी बाके नहीं हुई। तीसरी चीज जो बहुत अहम है वह यह है कि इस कानून से फूड प्रोडक्शन

[ श्री जहीरुल हसनैन लारी ]

में कमी वेशी के क्या कर इनकानात हो सकते हैं और कहाँ तक इससे आइन्दा की पैदावार की एकड़ बढ़ सकेंगी। अगर कोई प्राबलम ऐसी है कि जिसका असर यहाँ की रियासत पर पड़ सकता है और मुस्तक़विल पर पड़ सकता है तो वह यही मसला है। जमींदारी एग्जालिशन कमेटी के सेक्रेटरी ने जो फ़िगर्स आंकड़े तैयार दिये थे उनका नतीजा यह था कि जब तक कोई होलडिंग ५० एकड़ तक रहती है तो उसकी पैदावार के रिज़ल्ट्स अच्छे रहते हैं और जब वह बढ़ जाती है तो उसकी पैदावार कम होने लगती है। अगर ऐसी बात है तो अच्छा होता कि अब तक के किसी भी टाई एट द जमींदार की होलडिंग की तादाद मुक्रर कर दी जाय कि २० एकड़ से ज्यादा किसी की होलडिंग न हो। कहा जाता है कि हमारे पास जमीन काई है जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि वह स्कीम कहाँ है जिसके जरिए रिडिस्ट्रोब्यूशन हो सके। इस रिपोर्ट की रूह ने आपको २५ लाख एकड़ ज़मीन मिलती है और इसके अलावा आप और ज़मीन रिक्लेम भी कर सकते हैं। अगर आप १० एकड़ भी फ़ी आदमी तक़सीन कर दें तो आप इस तरह से ढाई लाख टेनेण्ट्स को एकनामिक बना सकते हैं और १० लाख की ज़िन्दगी का माकूल इन्तज़ाम आप कर हैं और जबकि शरणार्थियों का सवाल है और जिनकी वजह से मुल्क में काफी डिस्टरवेंस मौजूद है और आज जब कि कहा जाता है कि लैण्डलैस लेबरर के लिये ज़मीन नहीं है तो क्या ऐसी हालत में १० लाख आदमियों की ज़िन्दगी को इस क़ाबिल बनाना कि वह आराम से रह सकें और ज़िन्दगी बसर कर सकें सूखे की खिदमत करना नहीं होगा? कहा जाता है कि आज हमारे यहाँ रिफ़्यूजी प्राबलम है और इन इन पंजाब के लाखों आदमियों को बसाने में काफी परेशान हैं। आप उनको क्यों नहीं इस तरीके से बसाने का इन्तज़ाम करते? इससे आप हर काश्तकार को ज़मीन दे सकेंगे और जो बेहाती रिफ़्यूजीज़ हैं उनको भी बसा सकेंगे। मैं आप से कहता हूँ कि आप ने जो यह स्कीम बनाई है उससे मुल्क के मर्ज का इलाज नहीं होता। आपने जो चैप्टर रखा है, कॉन्फ़िडेंटिअल और कंसालिडेशन (चकबंदी) के बारे में, उस तरह की चीज़ तो पहले से ही स्टैट्यूट बुक में मौजूद है जिसकी रू से जो भी चाहे कंसालिडेशन करा सकता है लेकिन तज़ुर्बा बतलाता है कि उससे कुछ भी नहीं हो सका है।

इसलिए आप जिस चीज़ को अपना चुके हैं और आजमाने के बाद कोई फ़ायदा मुल्क को नहीं पहुँचा उसी को आप लाते हैं। चरुरत यह थी कि आप एकनामिक होलडिंग की तादाद मुक्रर कर दें, परिया मुक्रर कर दें कि इससे ज्यादा किसी के पास नहीं रहेगी। मान लीजिये वह ५० बीघा है, मेरा अन्दाज़ा है कि आपको ४० लाख के करीब लैंड मिलेगा और उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे इन्बिता होगी सोशलराईजेशन की।

मैं इस ऐवान के सामने तीन इसलाह पेश करता हूँ। पहली चीज़ यह है कि सीरदार और अधिवासी को यह लाजिमी न हो कि वह १५ गुना या

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २१६ १० गुना रेंट अदा करे नहीं। उसको भूमिधर के हुक्क मिल सकते हैं, उनको आउट राइट हुक्क पूरे मिलना चाहिए। जा कि आपने भूमिधर को दे रखे हैं। अगर आप समझते हैं कि यह नारुमकिन है तो मैं कहूंगा कि कम से कम वह सीरदार और वह दूसरे सब टेनेण्ट्स अधिवासी जिनके पास अनएकानामिक होलिडिंग हैं उनके लिए कीजिए कि उनको १० गुना या १५ गुना न देना पड़े जो इस पंजाब में नहीं हैं कि वह उनको अदा कर दें उनको भजवूर करना कि वह वे नहीं हुक्क हासिल होंगे और नजदोक्त उन हुक्क से इंकार करना है। दूसरी तर्जवा यह है कि ३ एकड़ से कम जिनके पास होलिडिंग है उन पर कोई रेंट न होना चाहिए मेरे कुछ दोस्तों ने तो लाखों ६ लाख तक कहा है लेकिन मेरा जो खर्चा है उनमें मैंने यह दिखलाया है कि जिनके पास ३ एकड़ से कम जमीन है वह इतनी पैदावार कर सकते हैं कि अपना गुजारा कर सकें उनके पास कोई सरप्लस नहीं है, किसी रेंट का उनसे वसूल करना सहीह जुल्म और नाइंसाफी है। तीसरे यह कि होलिडिंग के साइज की लिमिट होना चाहिए और किसी के पास खवाह वह टेनेण्ट हो या जमींदार ५० एकड़ तक की इजाजत होना चाहिए और उससे जो जमीन बचे जो कम से कम २५ लाख एकड़ होगी उसको आप तकसीम करें १० एकड़ के हिसाब से लैंडलेस लेबर और रिफ्यूजीज में। इस तरह से आप १५ या २० लाख आदमियों को नये सिरे से जिन्दगी गुजारने का मौका देंगे।

अब कम्पेनसेशन का सवाल पैदा होता है। मुझे सोशलिस्ट प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टि कोण) से काफी हमदर्दी है। नोट आफ डिसेण्ट में भी मैंने इसका तत्पर किया है लेकिन जो कानून इस वक्त इस मुल्क में रायज हैं और गालिबन हर शख्स को उससे बाकफियत होगी, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के मुताबिक इक्विटेबिल कम्पेनसेशन देना लाजिमी है अगर कोई कानून बिला इक्विटेबिल कम्पेनसेशन दिए जमींदारी को एबालिश करने का लाया भी जाता है तो हर हाईकोर्ट उसको रद्द कर देगी। जो मसविदा हमारी इस असेम्बली में इस वक्त पेश है और जिस पर गौर किया जा रहा है उसका आर्टिकल २४ जो है वह भी कहता है कि किसी की प्रापर्टी उसी वक्त ली जा सकती है जब इक्विटेबिल कम्पेनसेशन अदा कर दिया जाये। जो विधान बन रहा है, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट इस वक्त है उसके मातहत तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कम्पेनसेशन दें या न दें। हाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि यह विधान जेरे गौर है और जो पार्टी आज यहाँ ताकत में है वही पार्टी वहाँ भी ताकत में है वह आर्टिकल २४ को इस तौर पर रख सकती है कि बिना इक्विटेबिल कम्पेनसेशन दिए हुए ही कोई प्रापर्टी हासिल की जा सकती है लेकिन यह उसूल तो सिर्फ जमींदारों पर ही नहीं लागू किया जा सकता। फिर तो जो प्रापर्टी सरकार चाहे बिना मुआविजा दिए ही उसे एक्वायर कर सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है वह एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है वह खवाहिश नहीं करेगी कि आर्टिकल २४ को



[ श्री जहीरुल हसनैन लारी ]

बदले और उसके लिए मुक्ति मिलेगी है। जाएँ बिना जमाने की बिना कम्पेनसेशन दिये ही वह जमानेदारी को हासिल कर सके।

क्योंकि अगर एक दफा इन वसूल माना इसका असर इण्डस्ट्रियलिस्टों (व्यवसायिकों) पर पड़ेगा और अगर ऐसा विधान आ जायगा तो जाने जो नेशनलाइजेशन (राष्ट्रियकरण) होगा इंडस्ट्री और दूसरी चीजों का, उस पर इसका असर पड़ेगा। इनलिये मैं समझता हूँ कि हमारी अक्सरियत जो इस वक्त तक और सूबाई दुकानों पर क्राविज है, वह अपनी पालिसी के मानहान, जो कि बहुत हद तक कैपिटलिस्ट (पूँजपनियों) की है, इस बात के लिये प्रजदूर है कि वह आर्टिकल २४ (धारा २४) को रखे। और अगर वह आर्टिकल २४ को रखती है तो मेरा यहाँ बहस करना कि कम्पेनसेशन (मुआविजा) दिया जाय या न दिया जाय, बेकार है। हाँ बहसियत एक वकील के है यह जरूर कह सकता हूँ कि अगर यह इक्वेटिविल कम्पेनसेशन (मानान्य प्रतिकर) न देगी, तो जाहिर है कि इस आर्टिकल के रखते हुये जमानेदारी को खत्म नहीं कर सकते। इसके माने यह होगा कि जमानेदारी को ७ वर्ष के लिये और कायम रक्खा जाय। इनारे संश्लिष्ट, जैसा कि रोशन जमाँ साहब ने अपनी तक्रार में कहा कि कोई मुआविजा न देना चाहिए, इस नजरिए को छोड़ देते हैं। हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि अभी तो मस्यदा बन रहा है उसमें तरजीब करने की कंशिश की जाय। अगर वहाँ पर यह तरमीम हो सकी तो सेलेक्ट कमेटी मैं हम गौर करते हैं कि आया मुआविजा देना मुनासिब है या नहीं। लेकिन जाहिर है कि जहाँ तक इस असेम्बली का ताल्लुक है वह सिर्फ इस बात पर गौर कर सकती है कि क्या कम्पेनसेशन इक्विटिविल होगा। जब तक कि आर्टिकल २४ में तब्दीली की जाय, उस वक्त तक केवल एक सूरत है कि इक्वेटिविल कम्पेनसेशन देने के बारे में यह असेम्बली गौर करे। अगर कोई अनइक्विटिविल कम्पेनसेशन रक्खा गया तो इसके माने यह होगा कि तीन वर्ष तक हाईकोर्ट में मुकदमा चलेगा और हो सकता है कि यह कानून रह करार दे दिया जाय और जमानेदारी बदस्तूर कायम रहे। मुझे जम्मीद है कि गवर्नमेंट ने अपने वकीलों से मशविरा ले लिया होगा कि किस हद तक कम्पेनसेशन देना इक्वेटिविल समझा जायगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वह यह खयाल रखे जिससे कि आगे चल कर यह कानून नाकिस न हो सके।

दो तीन बातें और अर्ज करनी हैं। पहली चीज यह है कि यह कानून म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया वगैरा पर लागू न होगा और वादा यह किया है कि आइन्दा कोई कानून इसके मुताल्लिक न लाया जायगा। मैं पूछता हूँ कि क्या खुसूसियत है उन जमानेदारियों की जो कि म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया वगैरह में बाँटे हैं कि उनमें और देहात की जमानेदारियों में फर्क किया जाय। क्या इसकी यह वजह नहीं है कि वे

कैनिटिजिस्टों की है इंडस्ट्रियलिस्टों की है। यह फर्क करना मुनासिब नहीं मालूम होता। आप देखेंगे कि शहरे में प्राबलम और भी ज्यादा है। एक बंगला बनवाने के लिये जमीन नहीं मिलती और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ४०, ४० फीट का है, और हर एक में ४, ४ या ५, ५ एकड़ जमीन है, न वह खेतों के काम आती है और न उस पर मकान ही बन पाते हैं। क्या वजह है कि वहाँ के जमींदारों को इस तरह की आसानी दी जाय, तब ही लिये कि वहाँ पर ज्यादातर वे जमींदार हैं जो 'पेपिडलस्ट' ('पूजीपति') हैं, जिनका वाशकारास कोर का लुक नहीं है, बहुत से ऐसे भी हैं जो साहूकार हैं। मैं इलाहाबाद की हालत जानता हूँ, वहाँ देखना है जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनके दानर डरिये माल भी है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह फर्क क्यों किया गया। यह नक़्सद हो सकता था कि जनाब मिडिल क्लास से बहुत बार नाउम्नेद हो चुके हैं, शहरी लोगों ने तो हमें कई मतवा मायूस किया है। एक बार दोबारा और सेबारा नहीं बल्कि कई बार वह हमसे नाराज हो चुके हैं। देहात में अभी गनीमत है वहाँ पर इसके असरात अभी कम हैं। लेकिन इंसफ के लिहाज से मैं पूछता हूँ कि मिडिल क्लास भी तो इन्जानो जनाअन हो है। फिर टाउन परिया और म्युनिपल परिया को सबसे बरी क्यों किया है और अगर बरी किया है तो दूसरा कानून अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं लाये। जब आपने जमींदारी बिल का रिजोल्यूशन पास किया था उस वक़्त, जैसा कि हमारे दोस्त फज़रुल इस्लाम साहब ने कहा, एक और दूसरा रिजोल्यूशन भी पास किया गया था जिसमें नेशनलाइजेशन आफ अदर सोर्सेज (दूसरी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण) भी था। जमींदारी अबालीशन बिल से जो असरात होने वाले हैं उन पर भी आपने गौर नहीं करमाया और अगर करमाया तो उसके बारे में अभी तक अमल क्यों नहीं किया। जाहिर है कि जो आप जमींदारों को कैश (रुपया) देने वह सब कर्जे की अदायगी में साहूकार के पास चला जायगा। अगर आप लाने का वाज़दा करते हैं तो आप इस सेशन में क्यों नहीं लाये। आपने कमेटी भी बनाई लेकिन उसने अभी तक क्या किया। जो प्राबलम जमींदारी अबालीशन से पैदा होंगी उनका हल आप हमारे सामने अभी तक क्यों नहीं लाये। आपने डेट (ऋण) के मुताल्लिक क्या किया। जैसा कि मैंने अपने नोट आफ डिस्सेन्ट में कहा था कि आप एक बिल तो लैजिस्लेचर में ला रहे हैं और २ को बाक़ी रख रहे हैं। एक ग्युनि० के मुताल्लिक और दूसरा डेट (ऋण) के मुताल्लिक। इस बिल के लाने में आपने क़ाफ़ी तसादुली की है। जिस तरीक़े से आप चल रहे हैं उससे तो हमें उम्मीद कम मालूम होती है कि आप इलेक्शन से पहले जमींदारी का अबालीशन कर लेंगे। ताकि आप पब्लिक के सामने जा सकें कि कानून तो अब पास कर दिया है आप हमें वोट दे दीजिये आगे जाकर हम उसे लागू कर देंगे। इस तरह दो तीन बरस

[ श्री जहीरुल हसनैन लारी ]

मेरे खयाल से इसमें लग जायेंगे। वे तमाम क़वानीन जो इकानौमिक हालत के लिये जरूरी थे, जो कि इस बिल से पैदा होने वाली थी, आपको साथ में ही लाने चाहिये थे। हम इस बिल की ताईद इसलिये करते हैं कि आपने वादे किये हैं कि हम ज़मींदारी को खत्म करेंगे और साथ ही साथ ऐसे क़ानून बनायेंगे जिनसे जनता को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन इन दोनों बातों में मुझे ख़तरा नज़र आता है। पहिला ख़तरा दफ़ा ६ (ब) से मुझे लगता है। बहुत से असह्यब को तो इसकी वाक़फ़ियत भी नहीं है। अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। उसने कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इस काम को ज़िले ज़िले या स्टैंड-स्टैंड में काम में लाया जाय। बहुत से मेम्बरों को तो यह देख कर नाज़्जुब हुआ। शौर सेलेक्ट कमेटी में इस पर फिर शौर होना चाहिए। और इसे दूर कर देना चाहिए। मुझे इसके रहने से बहुत बड़ा डर रिश्तत सितानी का लग रहा है। इसके होने से उसके लिये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जायगा। किसी एक रियासत को जिसे १५ लाख रुपया सालाना की आमदनी है उसे यह मालूम हो जाय कि एक लाख रुपया ख़र्च करने से हमारी ज़मींदारी दो साल के लिये बच जायेगी तो वह ऐसा करने के लिये फ़ौरन तैयार हो जाएगा। आप यूँ ही परेशान थे कि इस सप्लाई डिपार्टमेंट ने पब्लिक के मारतल को गिरा दिया है। अगर आप ने यह रखा तो रिश्तत सितानी का दरवाज़ा फिर खुल जायगा। मेरी गुनगुनाहट है कि आप इसे रोक दीजिये ताकि कम से कम इस काम में तो नैपटि... पेवर्टिज्म और रिश्तत सितानी को मंज़ूर न मिले।

इन तमाम ख़तरानियों को दूर करने की कोशिश कीजिये, टेनेण्ट्स को पूरे हक्क दीजिये, वर्ना जै... कि अभी कई आदमियों ने कहा है कि स्ट्रॉगंस का ज़माना गुज़र गया है और अब स्ट्रॉगन्स से कान नहीं चलेगा। ज़ाहिर है कि अब पब्लिक ज्यादा हंशियार हो गई है। वह हमसे उम्मीदें रखती थी और अब हमारे पास कोई तज़ह नहीं है कि हम कहे कि फलों फलों रुकावटें हैं। अपोज़ीशन की तरफ़ से भी कोई रुकावट नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज़ करूँगा कि आप ऐसा कीजिये कि टेनेण्ट्स को पूरे हक्क मिलें, इकनामिक होल्डिंग्स ज्यादा से ज्यादा वजूद में आयें जिससे जनता को सकून हो और उनको वाक़ई महसूस हो कि हमें इक़तसादी आज़ादी मिली है। यह ठीक है कि सियासी आज़ादी हमको मिल चुकी है और इक़तसादी आज़ादी हमको अभी तक नहीं मिली है लेकिन इक़तसादी आज़ादी का ताल्लुक ज़मीन की पैदावार से है और किसानों की वहबूदी से है। यह सच है कि यह मसविदा इक़लाबी है लेकिन जिसे आप इक़लाबी तज़वीज़ कहते हैं वह इक़लाबी तरमोम की मुस्तहक़ है। जब तक आप इक़लाबी तरमीमात नहीं करेंगे यह एक बिल्कुल बेजान चीज़ होगी और इससे सूबे को और जनता को ज्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैं उम्मेद करता हूँ कि आप सेलेक्ट कमेटी में ऐसे बाहोश अश्वास रखेंगे जो यह समझें कि हमें ऐसा क़ानून बनाना है जिससे काश्तकारों का ज़ख़्बा फिर से

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २२३

ऊँचा हो जाय नाहि हम उल्लेख यह कह सकें कि हमने सियासी आजादी लेने के बाद अब तुम्हारे लिये जनसादी आजादी हासिल की है।

श्री विश्वम्भर दयाल बिपठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे सामने एक इतना महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है और मुझे भी इस पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर मिला है। मैं इस शिष्टाचार में जाना नहीं चाहता कि मन्त्रिमंडल को बधाई दूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि मन्त्रिमंडल का कर्तव्य था कि वह जल्द से जल्द इस बिल को धारा सभा के सामने लावे और जमींदारी उन्मूलन-कार्य को जल्द से जल्द समाप्त करे। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है और जिस बिल की प्रतीक्षा उसके इन ही लोग नहीं बल्कि हमारा समस्त प्रान्त और प्रान्त ही नहीं बल्कि समस्त देश कर रहा था उसको पेश करके यहाँ की जनता को अनुगृहीत किया है। हमें मालूम है कि लगभग १०० वर्ष से हम तीन अभिशापों से डूबे हुए थे, हमारे ऊपर तीन बोझ लदे हुए थे। पहला बोझ था अंग्रेजी साम्राज्यवाद का, दूसरा जमींदारी प्रथा का और तीसरा पूँजीशाही का। ६० या उससे कुछ अधिक साल हुये जबसे कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे सूबे में आयी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ जमींदारा-प्रथा भी हमारे सिर पर लादी गयी। उसके बाद पूँजीशाही भी आयी और ६० वर्षों तक हम बराबर इन तीनों अभिशापों से—इन तीनों बोझों से लदे हुये रहे।

इसमें सन्देह नहीं कि जब तक अंग्रेजी साम्राज्य हमारे बीच में था यह असम्भव था कि हम बाक़ी दो अभिशापों से अपने को मुक्त कर सकें। इसलिये देश ने सबसे पहले यह कोशिश की कि इन जल्द से जल्द अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करें ताकि राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने और स्वाधीन होने के बाद आर्थिक स्वाधीनता और समानता अपने देश में कायम कर सकें। हमें खुशी है कि कांग्रेस की कोशिशों से, महात्मा गांधी की कोशिशों से तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से जिन्होंने अपनी जान हमारी स्वाधीनता के लिये दी। आज हम स्वाधीन हो गये। आज इस स्वाधीनता की मलक गाँव-गाँव में दिखलाई दे रहो है। यह जरूर है कि जिन समय हमको स्वाधीनता मिली, वह बड़ा उपयुक्त समय नहीं था। इसलिये जितनी मलक इस स्वाधीनता की दिखलाई देनी चाहिये थी, उतनी नहीं दिखलाई दी, क्योंकि जिस समय स्वाधीनता हमें मिली, हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। पिछली लड़ाई के कारण हमारी दशा और संसार की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ी में पड़ गई थी और अब भी पड़ी हुई है।

हमारे देश में हिन्दू-मुसलमानों के मगड़े हुए। काश्मीर और हैदराबाद की समस्याएँ आईं। हमारे देश में छः सौ देशी रियासतों की समस्या उपस्थित हो गई। इन बातों का वजह से जितना आनन्द स्वराज्य की मलक से लोगों को होना चाहिये था, उतना आनन्द दिखलाई नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

इसमें सन्देह नहीं कि एक नयी भावना पैदा हो गयी और अब राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर आर्थिक स्वाधीनता भी स्थापित कर सकेंगे।

हाँ, यहाँ पर मैं एक बात का और जिक्र कर देना आवश्यक समझता हूँ, राजनीतिक स्वाधीनता के लिललिले में। वह इतलिले कि उसका सम्बन्ध इस बिल से है जो आज हमारे सामने पेश है। कुछ दिन हुये मुझे याद है कि माननीय प्रधान मन्त्री पंत जी ने मुझसे यह सवाल किया कि क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वराज्य की भलक नहीं प्राप्त हुई है जिन्होंने महसूस नहीं किया है कि हम अब स्वाधीन हो गये हैं। और हमारा देश आजाद हो गया है। मैंने उस समय कहा था कि अब तो कोई ऐसा नहीं मालूम होता जिस के पास यह सन्देश न पहुँच गया हो, जिसके पास स्वाधीनता की भलक न पहुँच गई हो। लेकिन इस बिल के देखने से यह जलर मालूम होता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ स्वाधीनता की भलक अब तक नहीं पहुँची है। मुझे एक मिसाल याद आती है। सन ३४ में कुछ लोग साइबेरिया में गये। वहाँ के जंगली और रेगिस्तानके निवासियों ने वान चीत में कहा हमारे देश में जार की हुकूमत चली आ रही है। उनको यह नहीं मालूम था कि १७ वर्ष पहले ही जार की हुकूमत समाप्त हो गयी है, रूस में क्रांति हो चुकी है और नये समाज की स्थापना हो चुकी है। साइबेरिया के रहनेवालों में से बहुत से ऐसे लोग थे जिनको यह भलक नहीं मिली थी। यहाँ भी एक कोना है जिनको आजादी की भलक नहीं मिली है वह है प्रान्तीय सरकार का सेक्रेटेरियट। आपने देखा होगा कि वहाँ अब भी अंधेरा रहता है और दिन में भी रोशनी करनी पड़ती है। वहाँ स्वराज्य की रोशनी नहीं पहुँची। यही कारण है कि जब हम बिल पढ़ते हैं तो जहाँ पर इण्डियन रिपब्लिक अथवा प्रान्तीय सरकार होना चाहिये उसके स्थान पर 'हिज मैजेस्टी' शब्द आता है। मैं माननीय मन्त्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि जरा वह बिल जो हमारे सामने पेश होते है उन्हें स्वयं देख लिया करें।

माननीय प्रधान सचिव—चूँकि आपको जो ठेस लगी है वह कुदरती है और मैं आपकी उस भावना को समझता हूँ इस लिए मैं चाहता हूँ कि जरा इसको साफ कर दूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इस वक्त गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के मुताबिक "हिज मैजेस्टी" लफ्ज लिखना लाजिमी है। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा ऐक्ट पास होगा तब तक सावरेन इण्डियन रिपब्लिक लिखने का मौक़ा हमें मिल जायेगा।

श्री विश्व दयालम्भर त्रिपाठी—मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने उस विषय को स्पष्ट कर दिया और हम आशा करते हैं कि जब तक इस क़ानून को पास करने का मौक़ा आवेगा उस समय तक "हिज मैजेस्टी" का नाम इस क़ानून से निकल जायेगा।

श्री ज़हीरुल हसनैन लारी—क्या मेरे दोन को नहीं मालूम है कि इसका ऐलान २६ जनवरी सन् १९५० को होगा ? क्योंकि वे भी कांस्टीटुएण्ट असेम्बली के मेम्बर हैं ?

श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—नगर में अब भी यही समझता हूँ कि अगर मसविदे में यह शब्द नहीं रखा जाता और रिपब्लिक लिख दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं होता। बहरहाल जब हमारे प्रधान मन्त्री जी कहते हैं और इसके लिये यज़ीन दिलाते हैं तो कोई बजह नहीं है कि हम उनकी बात को न मानें। हमें पूरी आशा है कि वह शब्द उससे हट जायगा और उसके स्थान पर प्रान्तीय सरकार या सावरेन इण्डियन रिपब्लिक आ जायगा।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लगभग ६० साल तक अंग्रेजी हुकूमत हमारे सर पर लदी रही। जब से अंग्रेजी हुकूमत आयी उसने हमारे देश में जमींदारी प्रथा का विकास किया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके पहले भी हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की जमींदारी प्रथा अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर क़ायम की है वह प्रथा अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ नहीं थी। यह मैं मानता हूँ कि सौ दो सौ वर्षों से नाम के लिए बीज-मात्र स्वरूप जमींदारी का प्रारम्भ हो गया था, अगर अंग्रेजी हुकूमत न आयी होती तो शायद वह बीज भी समाप्त हो गया होता और जमींदारी प्रथा जो इस समय हमारे सामने है यहाँ पर क़ायम नहीं हुई होती। मैं आपको दूर इतिहास में नहीं ले जाना चाहता और न आपका समय बेकार नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे बहुत से जमींदार लोग इस बात की दोहाई देते हैं कि जमींदारी प्रथा पुरानी है इस लिये इसको नष्ट नहीं करना चाहिये—पुरानी होने की वजह से इसमें पवित्रता है, इस लिये मैं इतिहास के अन्दर दूर तक न जाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि न तो कभी प्राचीन काल में और न मध्य कालीन समय में ही जमींदारी प्रथा थी और जो कुछ उसके बीज मात्र मौजूद थे वह भी समाप्त हो गये होते, अगर अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर न आई होती। आप कहेंगे कि पैतृक आधार पर कुछ लोगों का रेवेन्यू फार्मिंग लगान वसूल करने का अधिकार था, यानी पिता के बाद पुत्र के हाथ में रेवेन्यू फार्मिंग जाती थी और वे पैतृक आधार पर लगान वसूल करते थे। यह बात ठीक है। बंगाल और अवध में भी कुछ समय तक ऐसा रहा कि पिता के बाद पुत्र राज्य की ओर से मालगुजारी वसूल करता था, लेकिन साथ ही साथ यह भी होता रहा कि जब कभी राज्य चाहता था तो उसको बरखास्त भी कर देता था और तनख्वाहदारों को रेवेन्यू फार्मर मुक्त कर देता था इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जमींदारी प्रथा का विकास आज जिस तरह हुआ है उस तरह से न तो अवध के नवाबों के जमाने में और न बंगाल या दूसरी जगहों में ही था। ऐसी सूरत में अगर जमींदारी के समर्थन में दोहाई दी जाती है तो यह बिल्कुल ग़लत है। ऐतिहासिक दृष्टि से

[ श्री विशदम्भर दयाल त्रिपाठी ]

सकत है। अंग्रेज जब यहाँ आये तो उन्होंने देखा कि यहाँ गाँवों का संगठन बहुत मजबूत है और उसने यह भी देखा कि अगर हमें अपना आतंक गाँवों में क्रायम करना है तो ग्राम-संगठन को नष्ट करना चाहिये। और इसीलिये उन्होंने यह चाहा कि गाँवों में जो पंचायतें पहले से क्रायम थीं उन्हें मिटा दिया जाय। पंचायती संगठन के कारण यहाँ के निवासियों ने कभी यह परवाह नहीं की कि कौन सा शासन हिन्दुस्तान में क्रायम है और कौन सा नहीं है। अंग्रेजों ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। वे एक तरफ तो उनका नाश करते गये और दूसरी तरफ जमींदारी की प्रथा को क्रायम करते गये। सच बात तो यह है कि जमींदारी प्रथा और जनसत्तात्मक शासन एक दूसरे के विरोधी हैं और इसीलिए जब हम फिर जनसत्तात्मक शासन की स्थापना कर रहे हैं और उसके अनुसार देहातों में फिर से पंचायतें क्रायम कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है कि या तो जमींदारी प्रथा रह सकती है या हमारी पंचायतों का तरीका ही रह सकता है। मैं आपका ध्यान आजकल के समाज की ओर दिखाना हूँ। मैं किसी की अच्छाई और बुराई की दृष्टि से नहीं कहता लेकिन सच तो यह है कि जो जमींदारी प्रथा आज हमारे गाँवों में है वह जनसत्तात्मक शासन के बिल्कुल विरुद्ध है। आज गाँवों में जो जमींदार हैं वही लम्बरदार भी हैं, वही गाँव का मुखिया भी है। उसी की राय से पटवारी मुक़रर होता है, और उसी की राय से चौकीदार भी मुक़रर होता है अगर कोई कानूनगो वहाँ पर आता है तो उसी के यहाँ ठहरता है और कोई सब-इन्स्पेक्टर पुलिस भी आता है तो वह भी उसी के वहाँ ठहरता है। इस तरह से जमींदार आज गाँव के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का केन्द्र है। मैं अच्छाई और बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ बल्कि एक वास्तविक स्वरूप आपके सामने रख रहा हूँ। आज के समाज में जमींदार हमारे ग्रामीण आर्थिक जीवन का केन्द्र है। अब अगर आर्थिक जीवन का केन्द्र जमींदार को न बनाकर, एक अमी को न बनाकर आप यह चाहते हैं कि वहाँ की पंचायत, वहाँ की प्रजा, वहाँ का जनसमुदाय ऐसा केन्द्र हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप जमींदारी की प्रथा को समाप्त करें। पंचायत राज के सम्बन्ध में मैंने हमेशा यह कहा है कि जब तक जमींदारी प्रथा क्रायम है और जमींदार के हाथ में शासन की शक्ति और राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति केन्द्रित है उस समय तक प्रजासत्तात्मक शासन देहातों में नहीं हो सकता और पंचायतें वहाँ पूरी तौर से सफल नहीं हो सकतीं। लिहाजा अगर पंचायतों को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि हम एक अमी के हाथ से वहाँ की सारी शक्ति जो इस समय केन्द्रित है निकाल लें और उसे वहाँ की जनता के हाथ में दे दें। जब हमने यह कदम उठाया कि हम गाँवों में पंचायतें स्थापित करें वो हमारा मतलब यही था कि हम यहाँ की निरंकुश शक्तियों को खत्म करना चाहते हैं। इसमें न तो कोई संदेह हो सकता है और न है। अतः वर्तमान जमींदारी प्रथा को जो इस समय

६० साल से हमारे यहाँ इस स्वरूप में चलता आता है, हमें खत्म करने का निश्चय किया है। इसका भी एक इतिहास है। लगभग तीस वर्ष हुए जब यह आवाज हमारे देश में और खास तौर से हमारे प्रान्त में उठी कि हमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी ने शायद पहले पहल यह आवाज उठाई कि हमें अपने प्रान्त से और अपने देश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। साथ ही साथ हमारे देश के और हमारे प्रान्त के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी यह आवाज उठाई कि हमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना है। परन्तु वह उपयुक्त समय नहीं था, और इसलिये जब तक कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर रही तब तक यह सम्भव नहीं था कि हम जमींदारी प्रथा को समाप्त कर सकते। लेकिन अब जब अंग्रेजी साम्राज्य समाप्त हुआ है तब यह आवश्यक है कि जो प्रतिगामी शक्तियाँ ऐसी थीं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी शक्ति को संगठित करने के लिये, उसकी रक्षा करने और उसे बढ़ाने के लिये क्रायम किया था वे सभी समाप्त हो जाँय जब कि अंग्रेजों का हुकूमत यहाँ से खत्म हो चुकी हो। हाँ, अगर हम यह समझते कि कोई ऐसी शक्ति अंग्रेजों ने यहाँ क्रायम की है जो हमारे देश के हित के लिये है तो हम उसको क्रायम रखें इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि जमींदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो दुनियाँ से समाप्त हो रही है और करीब करीब समाप्त भी हो चुकी है। इस प्रथा को सभी अर्थ-शास्त्रियों ने, समाज-शास्त्रियों ने यह मान लिया है कि वह आजकल के समाज के लिये उपयुक्त नहीं है और समाज को पीछे खींचने वाली है। ऐसी दशा में उस प्रथा का क्रायम रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है। आज यह कहा जाता है कि आखिर जमींदारी प्रथा को ही क्यों पहले समाप्त किया जा रहा है, इसके साथ ही साथ पूँजीशाही प्रथा को भी क्यों समाप्त नहीं करते। मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह दलील बिल्कुल गलत है। हम अभी तक अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने में लगे हुए थे, हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद को समाप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। लेकिन इसी प्रकार अंग्रेज लोग यह कह सकते थे कि आपके लिये पूँजीशाही और जमींदारी प्रथा भी उतनी ही हानिकार हैं, पहले इनको समाप्त क्यों नहीं करते। यह दलील बिल्कुल गलत है, यह तो हमारे देशवासियों के लिये है कि हम कब एक को समाप्त कर दूसरी समाप्त करना उपयुक्त समझते हैं। अंग्रेजी सरकार को पहले समाप्त करना था क्योंकि वह इन दोनों की समर्थक थी। जब तक अंग्रेज यहाँ पर थे, तब तक इन दोनों को समाप्त करना मुश्किल था। पहले हमने उस जड़ को समाप्त किया। अब दूसरी की बारी आई है,—जब जमींदारी समाप्त करने की बारी आई है, और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत जल्द वह समय भी आयेगा जब हम पूँजीशाही को इस प्रान्त से और इस देश से



[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

समाप्त कर सकेंगे। इस बिल में जो योजना हमारे सामने पेश की गई है उसको सब से अधिक महत्वपूर्ण मैं इसलिये समझता हूँ कि हमारे प्रान्त के लिये कोई दूसरा प्रस्ताव हमारे सामने इतना महत्वपूर्ण अभी तक न तो आया है और न आयेगा। जहाँ तक अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त करने का सम्बन्ध था उसमें हमारे प्रान्त ने हिस्सा लिया और हमारी धारा सभा ने भी उसमें कुछ हिस्सा लिया, लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह भारतवर्ष भर का प्रश्न था। हम स्वयं किसी एक प्रस्ताव से अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से पूंजीशाही का भी मसला है। हमको उसके लिये भी जो कुछ करना है वह अवश्य करेंगे लेकिन वह एक अखिल भारतीय प्रश्न है, पर तो भी उसमें हमारा हिस्सा होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उसको अखिल भारतीय आधार पर ही समाप्त करना होगा। इसलिये उसके उन्नूलन का श्रेय प्रान्त के आधार पर केवल आंशिक रूप में ही इस धारा सभा को हो सकेगा। यह तीन सामाजिक अभिशाप हैं। इन में से जमींदारी का एक ऐसा अभिशाप है जिसको हमारी धारा सभा अपने कानून द्वारा समाप्त कर सकती थी। वह उसको समाप्त करने जा रही है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह बिल इतना महत्वपूर्ण है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना अभी तक हमारी धारासभा के सामने न आई है और न भविष्य में आ सकती है।

अब जहाँ तक इस बिल के गुण-अवगुण का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में हमारे बहुत से मित्रों ने उस पर काफी प्रकाश डाला है। मेरा ख्याल यह है कि चाहे कहीं एक दो जगहों पर मेरा मतभेद हो लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो योजना इस बिल के अन्दर हमारे सामने पेश की गई है उससे अधिक अच्छी योजना मौजूदा परिस्थित में पेश नहीं की जा सकती थी। अभी हमारे कुछ मित्रों ने यह कहा कि इस बिल के लाने में बड़ी देर की गई। सब से ज्यादा लोगों का एतराज और ख़ास तौर पर लारी साहब का एतराज इसी बात पर है कि दो साल या तीन साल इस बिल के लाने में लग गये। मैं उनके विचारों से हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन शायद अगर उनकी सहायुभूति इसमें मिली होती तो इस बिल को हम और पहले ला सकते थे। जिस तरह से भी हमारे देश की प्रगति को रोक सकते थे, उन्होंने और उनके साथियों ने रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से हमारी तमाम विकास की योजनाएँ अभी तक रुकी रहीं। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश न की होती और हमारे काम में सहायता की होती तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत पहले हमारी सरकार इस बिल को हमारे सामने ला सकती थी। आपने देखा कि इस बीच में क्या-क्या हुआ ? किस तरह से हमारे देश के दुश्मने हुये ? किस तरह से हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हुये ? किस तरह से देशी रियासतों की समस्या हमारे सामने आयी ? किस तरह से काश्मीर

इत्यादि की समस्या हमारे सामने आई ? किस तरह से शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने आई ? ऐसे नाना जटिल मुद्दे हमारे देश के सामने एकाएक आ गये जिसके कारण यह अस्मभव हो गया कि हम इस चीज को जल्दी पूरा कर सकें । ऐसी स्थिति में यह दान लगाना कि हमारे मन्त्रिमण्डल ने इस योजना को लाने में देरी की, मैं समझता हूँ, बिल्कुल निरर्थक है । लारी साहब तो यह अभियोग लगा ही नहीं सकते जब कि उन्हीं के कारण यह देरी हुई । अगर वह कामों में बाधा न डालते, देश की प्रगति में बाधा न डालते तो इसमें सन्देह नहीं कि हम इस कानून को, इस योजना को, यहाँ जल्द ला सकते थे और इसको कार्यान्वित कर सकते थे ।

अभी हमारे इसी भवन में तीन तरह की आलोचनाएँ की गईं । एक ओर तो हमारे जमींदार लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ से सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आलोचना हुई है । जहाँ तक जमींदारों की आलोचना का सम्बन्ध है मैं बहुत अधिक कहना नहीं चाहता । अब जब कि जमींदारी की प्रथा समाप्त हो रही है तो इस संबंध में जमींदारों के खिलाफ ज्यादा कहना कुछ बहुत अनुचित नहीं मालूम होता । यद्यपि आज भी उनके खिलाफ कहने को बहुत सामग्री मेरे पास मौजूद है । आज जमींदार लोग यह कहते हैं कि आखिर जमींदारों को खत्म करने से किसानों का क्या लाभ होगा ? लगान तो कम नहीं हो रहा है, खाली जमींदार हट जायेंगे, उनकी जगह सरकारी कर्मचारी हो जायेंगे । यह एतराज जमींदार लोग करते हैं । लेकिन आज भी जो कुछ वे देहातों में कर रहे हैं, वह अत्यन्त शोचनीय है । उससे उन्हें आश्चर्य तो क्या होगा क्योंकि वे स्वयं जानते ही होंगे यद्यपि वे यहाँ इसका इजहार नहीं करेंगे कि देहातों में क्या हो रहा है । लारी साहब ने भी कहा कि आखिर काश्तकारों को क्या फायदा होगा ? मैं लारी साहब की इत्तिला के लिए और जमींदार लोगों की भी इत्तिला के लिए बतला देना चाहता हूँ कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ, सिर्फ ५ - ६ दिन हुए जब कि मेरे पास दो काश्तकार आए । एक काश्तकार से ४ सौ रुपया और दूसरे काश्तकार से १४०० रुपया इस तरह दोनों से मिलाकर १८०० रुपया जमींदारों ने नजराना लिया और इसके अतिरिक्त २०० रुपया पटवारी ने लिये । जमीन थी सिर्फ साढ़े ३ बीघा । मैं यों ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने उन दोनों जमींदारों को भी अपने सामने बुलाया और उन्होंने स्वीकार किया कि हमने १८०० रुपया लिया । यह हालत आज भी बाकी है । तो क्या आप यह समझते हैं कि जमींदारों खत्म होने पर किसानों को कोई फायदा नहीं होगा ? मैं आपको बतलाऊँ कि आज भी ऐसे जमींदार हैं जिनके गाँव में एक इंच जमीन काश्तकार के नाम नहीं लिखी है । आखिर वह जमीन क्या की जाती है । आज भी एक ऐसे जमींदार हैं—मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्हें ८ हजार रुपये का गल्ला प्रोक्क्योरमेंट में देना था । उनके नाम बहुत सी जमीन लगी हुई है, परन्तु उसमें से अधिकांश जमीन वास्तव में किसान

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिगठी ]

दिये हुये हैं, परन्तु उनके नाम बाराजों में दर्ज नहीं हैं। कुछ जमीन सो रही है अर्थात् जमींदार महोदय न तो खुद कर पाते हैं और न किसानों को देते हैं। बाकी जमीन खुद किये हुये हैं। किसान लोग तब तक राह देने को तय्यार नहीं हैं जब तक कि जमींदार का नाम काटकर वह जमीनें उनके नाम दर्ज न कर दी जायें। एक नहीं सैकड़ों ऐसी मिसालें मैं अपने जिले की दे सकता हूँ। दर्जनों मिसालें तो मैं अभी गाँव और नाम के साथ बतला सकता हूँ। यह हालत आज भी जमींदारों की है। तो मैं लारी साहब से पूछता हूँ कि जब जमींदारी नहीं रहेगी, जब जमींदार बहैसियत जमींदार के नहीं रह जायेंगे तो क्या काश्तकारों को फायदा नहीं होगा? इस प्रकार यह कहना, कि यह कानून जब पास होगा तो जमींदारी तो खत्म हो जायगी लेकिन काश्तकारों को कोई लाभ न होगा, यह बड़ी गलत बात है।

यह तो सिर्फ काश्तकारों को बहकाने की बात हुई। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप की इन फिकरे-बाजियों से काश्तकार बहकेंगे नहीं। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जमींदारी को खत्म करने की आवाज किसने उठाई, वह जानते हैं कि मौन्सो हक किसने दिया, वह जानते हैं कि उनका बकाया लगान किसने माफ कराया, वह यह भी जानते हैं कि जब हम लोग जेलों में थे और हमारे बहुत से दोस्त बाहर मौजूद थे, उस वक़्त कितनी बेदखलियाँ हुईं। सन् १९४१ ई० से १९४५ ई० तक क़रीब आठ सौ खाते बेदखल कर दिये गये। जो आज बड़े हमदर्द बन कर आये हैं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से, कोई सोशलिस्ट पार्टी के नाम से, कोई जमींदार पार्टी के नाम से और कोई जनता पार्टी के नाम से उनमें से अधिकांश लोग जेलों के बाहर मौजूद थे। लेकिन उनके होते हुये भी आठ सौ खाते बेदखल कर दिये गये। तब आपने क्या किया? तब आपकी देशभक्ति कहाँ गयी थी? तब तो आप बराबर कांग्रेसों का साथ देते थे, उनके पीछे-पीछे चलते थे। हमारे जमींदार भाई लड़ाई के ज़माने में काश्तकारों से जबर्दस्ती चन्दा वसूल करवा रहे थे, और अगले देशभक्त बन कर हमारे बीच में आते हैं और कहते हैं कि जमींदारी खत्म करने से काश्तकारों को क्या लाभ होगा। आप से क्या मतलब? आप अपने मुआवज़े के लिये लड़िये। आप इसके लिये लड़िये कि जमींदारी खत्म न हो। आप बेकार में काश्तकारों के बर्दों हमदर्द बनते हैं काश्तकार बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आप कैसे हमदर्द हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इस लिये फिकरेबाजी कर रहे हैं कि यह बातें कांग्रेस के खिलाफ काश्तकारों के कान में पड़ें और काश्तकार कांग्रेस से भड़कें। मैं आप को बतला देना चाहता हूँ कि काश्तकार कभी भी भड़कने वाले नहीं।

सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर रोशन जमाँ खाँ साहब ने बड़ी लम्बी चौड़ी तक्रार की। वह इस वक़्त मौजूद नहीं हैं। उनकी तक्रार केवल एक प्रचार मात्र थी। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि कम्पेन्सेशन (मुआवज़ा)

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २३१

जमींदारों को न देना चाहिये। और फिर कहा कि हॉ कम्पेन्सेशन तो नहीं देना चाहिये, लेकिन रिहेबिलिटेशन ग्रांट ( पुनर्वासन अनुदान ) जरूर दे देना चाहिये। कितना देना चाहिये? पचास करोड़ देना चाहिये। यह भी कहा कि जो २५० रु० से कम सालगुजारी देने वाले जमींदार हैं उनको ज्यादा रिहेबिलिटेशन ग्रांट देनी चाहिये, ताकि छोटे जमींदार खुश हो जायें। आज मैं इस हाउस में यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रान्त में और देश में इस पार्टी के नेता आचार्य नरेन्द्र देव हैं या रोशन जमा खाँ साहब? मैं किसको बात मानूँ? मैं आपके सामने आचार्य नरेन्द्र देव की राय पेश करता हूँ। इसीलिये जब हमारी जमींदारी अवालिशन कमेटी ( जमींदारी उन्मूलन समिति ) की बैठक हुई थी तो उसमें जितने राजनैतिक दल हैं उन सब के नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसान समा, इन सब के नेता आये थे।

आचार्य नरेन्द्र देव, स्वामी सहजानन्द और डाक्टर अहमद साहब आये थे। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ और आप देख भी सकते हैं कि उनके दस्तखती कागज मौजूद है। यह उनका लिखित बयान है। आचार्य जी ने यह पेश किया था कि दस गुने से लेकर पच्चीस गुने तक जमींदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। इसके अलावा उन्होंने एक बात और रखी थी और वह यह कि किसी को ५ लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा न दिया जाये। आज सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से रोशन जमा खाँ साहब आते हैं और कहते हैं कि किसी को भी एक लाख से ज्यादा मुआवजा नहीं देना चाहिये और यह भी कहते कि छोटे जमींदारों को जो २५ गुना रखा गया है उससे भी ज्यादा देना चाहिये क्योंकि यह बहुत कम है। लेकिन उनके नेता आचार्य जी ने जो हमारे भी मित्र हैं सिर्फ २५ गुना रखा था। १७ लाख छोटे जमींदारों के लिये उससे कहीं ज्यादा हमने रखा है।

फिर दूसरी बात वह यह कहते हैं कि बड़े जमींदारों को मुआवजा बिल-कुल नहीं दिया जाना चाहिये। हम तो सिर्फ आठ गुना रखते हैं; परन्तु आचार्य जी ने तो उनके लिये दस गुना रखा था। हमने आठ गुना जो रखा है वह एग्रीकल्चरल टैक्स ( कृषि कर ) को निकाल कर रखा है लेकिन आचार्य जी ने उस वक्त जो आमदनी थी उस का दस गुना रखा था। इस प्रकार आचार्य जी की राय के अनुसार बड़े जमींदारों को हमारी योजना से कम से कम ड्योड़ा दिया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि हम लोग आचार्य जी की राय सोशलिस्ट पार्टी की राय मानें या रोशन जमा खाँ साहब की राय को सोशलिस्ट पार्टी की राय मानें। यह तो मैं आप लोगों के जजमेंट ( फैसले ) पर छोड़ता हूँ।

अभी लारी साहब ने जमींदारों का मुआवजा देने के खिलाफ बहुत कुछ कहा लेकिन अन्त में उन्होंने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट है उसका अनुसार जो जो जमींदारों को मुआवजा देना है उसी २५ गुना के

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

अनुसार कम्पेंसेशन (मुआवजा) देना आवश्यक है इसलिये अवश्य देना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह धारा तरमीम हो जाय तो हम कहेंगे कि कोई मुआवजा दिये जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट यह देना चाहता हूँ कि धारा २४ जरूर तरमीम हो जायगी और प्रान्तीय गवर्नमेंट को पूरा अधिकार हो जायगा कि अगर वह सार्वजनिक जमीन के लिये किसी की सम्पत्ति को लेती है तो उसको पूरा अधिकार है कि जितना मुआवजा मुनासिब समझे उतना दे। लेकिन इस धारा के तरमीम हो जाने के बावजूद भी हम मुनासिब समझते कि जमींदारों को मुआवजा दिया जाये और उसका कारण यह है कि १७ लाख जमींदार आपके ऐसे हैं जो २५ रुपये या इससे कम मालगुजारी देते हैं। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि उनको हालत काश्तकारों से अच्छी है। अगर नहीं कह सकते तो क्या आप मुनासिब समझते हैं कि उनको कोई मुआवजा न दिया जाये। स्पर्क फिकरबाजी करने से काम नहीं चल सकता। आप बड़े जमींदारों को ही ले लीजिये। क्या आप यह चाहते हैं कि वह लोग जो अब तक किसी न किसी तरह से अपनी गुजर करते थे, कल से असहाय हो जायँ। क्या आप चाहते हैं कि इनारे यहाँ के जमींदार जो अच्छे काश्तकार या अच्छे नागरिक हो सकते हैं और हमारी योजना के अनुसार होने जा रहे हैं वह बजाय अच्छे नागरिक या काश्तकार होने के असहाय हो जायँ और उनमें से बहुत से लोग मजबूर होकर चोरी-डकैती करने लगें। इससे क्या हमारे समाज में अव्यवस्था पैदा नहीं हो जायगी? अगर हम उनको मुआवजा नहीं देते हैं तो गाँवों में लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा क्योंकि अगर एक आध आदमी चोर या डकैत हो जाता है तो गाँव वालों का रहना मुश्किल हो जाता है और जब इतने आदमी बेरोजगार हो जायेंगे तो फिर न जाने क्या होगा? गाँव के लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जायगी। मैं आपको फिर यह बतला देना चाहता हूँ कि शासन-विधान की दफा २४ जरूर तरमीम हो जायेगी और प्रान्तीय सरकार को पूरा अधिकार हो जायेगा कि जितना चाहे उतना मुआवजा जमींदारों को दे लेकिन फिर भी हम यही मुनासिब समझेंगे कि उनको उचित मुआवजा दिया जाय ताकि जमींदार भी देश की उन्नति में हमारे साथ-साथ चल सकें और वह हमारे देश के अच्छे और प्रगतिशील नागरिक बन जायँ। क्या आप चाहते हैं कि उनको अच्छा नागरिक न बनाया जाये और वह चोर और डकैत बन जायँ। ऐसी सूरत में मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि दफा २४ के तरमीम हो जाने पर भी हम यह मुनासिब समझेंगे कि जमींदारों को मुआवजा उसी हिसाब से दिया जाय जिस हिसाब से इसमें प्रस्तावित किया गया है।

जहाँ हम यह चाहते हैं कि हम जमींदारों को मुआवजा दें ताकि वे हमारे भावी आर्थिक जीवन में ठीक तौर से अपने को ढाल सकें वहाँ हम यह भी चाहते हैं कि उसका बोझ हमारे समाज और किसानों पर अधिक न पड़े और

मन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारों विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २३३

यह मुआवजे की रकम इनकी न बढ़ जाय कि जिसको प्रान्त अदा न कर सके। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वह इससे ज्यादा के हकदार भी नहीं हैं। मैं आपका ध्यान ६० साल पहिले ले जाना चाहता हूँ जब अंगरेजों ने जमींदारों को जमींदारियाँ दी थीं। उस वक्त ६० फ्रीसदी अंगरेज ले लेते थे और केवल १० फ्रीसदी जमींदार के पास रहना था। अपनी शक्ति को मजबूत करने की दृष्टि से अंगरेजों ने लिये यह जरूरी था कि प्रान्तीय पंचायतों की शक्ति को तोड़ें और जमींदारों को लुप्त करें अतः उन्हें मालगुजारी को घटाकर ८० फ्रीसदी किया, फिर ६६ फ्रीसदी, उसके बाद ४० फ्रीसदी और अब आमतौर पर घटाकर ३० फ्रीसदी कर दिया था; परन्तु ऐसा होने पर भी हम आप से उस फायदे का हिसाब नहीं माँगते जो आपने ६० साल तक उठाया है। अगर किसी तरह से दर्जल दी जाय और हम यह मान भी लें कि यह जमींदारियाँ जो अंगरेजी हुकूमत ने आप को दी थीं जायज थीं, तब भी आपको १० फ्रीसदी से ज्यादा सालाना मुनाफे का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपको जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बाजार भाव से कहीं ज्यादा है।

अब मैं आप का ध्यान उन आलोचनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो इस बिल पर यहाँ की गई हैं। अबल तो यह कहा गया है कि जमींदारी एवालिशन कमेटी (जमींदारी उन्मूलन समिति) ने जो रिपोर्ट तैयार की थी और जो रायें उसमें उसने दी थीं वह इस बिल में शामिल नहीं की गई हैं। मैं आप से कह देना चाहता हूँ कि जो ऐसा कहते हैं उन्होंने या तो बिल को नहीं पढ़ा है, या जमींदारी एवालिशन कमेटी की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है या दोनों को ही नहीं पढ़ा है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक फंडामेंटल उसूलों (आधारभूत सिद्धान्तों) का ताल्लुक है वहाँ तक पूरे तौर से उस रिपोर्ट के सुभाव इस बिल में आ गये हैं। पहली बात तो यह है कि जमींदारी और अन्य सभी मध्यवर्ती स्वार्थों को समाप्त करने की योजना इस बिल में पूरे तौर पर रखी गई है। दूसरी बात यह है कि हम जमींदारों की सीर, खुदकाश और बाराँ को छोड़कर जितने भी उनके जमींदारी अधिकार हैं उन सभी को समाप्त करेंगे। हाँ मुआवजे की रकम के मजिस्ट्रेट्स में थोड़ा सा अन्तर जरूर हो गया है। आपने देखा होगा कि पहले छोटे जमींदारों के लिए मुनाफे का २५ गुना रखा गया था और अब इस बिल में वह बढ़ाकर २८ गुना कर दिया गया है। और जहाँ तक बड़े जमींदारों का सम्बन्ध है उनके लिए ८ गुना रखा गया है। बड़े जमींदारों के मुआवजे में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि रिपोर्ट की योजना के अनुसार १० हजार मालगुजारी तक तो ८ गुना मुनाफा देने की और उसके ऊपर ३ गुना देने की राय थी। इस तरह से अगर ऐग्रीकलचरल इनकम टैक्स (कृषि-कर) का हिसाब लगाने लिया जाय तो कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। जो रकम पहले रिपोर्ट के हिसाब से होती थी उतनी ही इस योजना के हिसाब

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

से भी आती है। इससे छोटे जमींदारों का मुआवजा जरूर बढ़ गया है लेकिन कुल रकम पर जो सूबे भर में दी जायगी कोई असर नहीं हुआ है और न खास तौर से किसी भी वर्ग के मुआवजे में ही कोई अन्तर हुआ है।

तीसरी जरूरी बात यह है भविष्य में भूमि-प्रणाली किस तरह की होगी। अभी जैसा मैंने बतलाया, हमारे ग्रामीण आर्थिक जीवन का केन्द्र जमींदारी प्रथा थी। अब उसके स्थान पर कौन सी प्रथा होगी ? यह भी उसमें स्पष्ट कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में भी बहुत सी आलोचनायें की गई हैं। लारी साहब और फखरुल इस्लाम साहब ने यह आलोचना की है कि आइन्दा भूमि-प्रणाली कैसी होगी इस पर इस बिल में कोई रोशनी नहीं डाली गई है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस बिल को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। उसमें बहुत साफ है कि भविष्य में किस तरह की भूमि-प्रणाली होगी। इस बिल की योजना के अनुसार काश्तकार अपनी जमीन का क़रीब-क़रीब मालिक होगा और उससे लगान वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जैसे जलाशय, पड़ती, रास्ते, बाज़ार, सायर वगैरह वह सब पंचायतों के हाथ में दे दी जायेंगी। तहसील वसूल करने में भी इन पंचायतों का हाथ होगा। लारी साहब ने एतराज किया है कि इस क़ानून में प्रांतीय सरकार को यह अधिकार क्यों दिया गया है कि वह जहाँ पर चाहे स्वयं लगान वसूल कर सकती है। मैं समझता हूँ कि यह अधिकार बिल्कुल मुनासिब है। मुझे यक़ीन है कि हमारी गाँव पंचायतें बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी और लगान वसूली में वह पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध होंगी। लेकिन मैं आप से पूछता हूँ कि अगर कहीं पर गड़बड़ी हो जाये और पंचायतें लगान वसूली में ठीक तौर से काम न कर सकें तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ लगान वसूल न किया जाए और प्रांतीय सरकार को कोई भी अधिकार न हो कि वह वहाँ का लगान किसी दूसरे जरिये से वसूल कर सके। मुझे बहुत अफसोस है कि लारी साहब इतने चतुर वकील होते हुये भी इस तरह के एतराज करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत आवश्यक था कि प्रांतीय सरकार कुछ अधिकार अपने हाथ में रखे ताकि अगर कहीं पर पंचायतों का प्रबंध असफल रहे, अथवा अगर कोई गड़बड़ी हो तो ऐसी दशा में प्रांतीय सरकार किसी दूसरे जरिये से उसका प्रबन्ध कर सके। दूसरा एतराज लारी साहब ने यह किया है कि दफ़ा ६ में प्रांतीय सरकार ने अपने लिए कुछ ऐसी गुज़ाइश रखी है कि प्रांत के जितने हिस्से पर चाहे इस बिल को लागू करे। लारी साहब का ध्यान मैं इस ओर फिर दिलाना चाहता हूँ कि जब हम क़ानून तैयार करते हैं तो उसमें बहुत तरह की गुज़ाइश रखने की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम जमींदारी को जल्द से जल्द और एक साथ ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें हमें गुज़ाइश की जरूरत पड़े। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम दो महीनों में आवे

प्रांत का प्रबन्ध करें और दूसरे दो महीनों में दूसरे आधे प्रांत का प्रबन्ध करें और अगर कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है तो सरकार क्या करेगी ? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि न तो सरकार का मंशा है और न काँग्रेस पार्टी का कि हम उसके एक एक अंश को लेकर सनाप्त करें । हम तो सभी जमींदारी को एक साथ समाप्त करेंगे और मैं लारी साहब को पूरे तौर से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इनमें अगर किसी तरह की बाधा पड़ी तो मैं उनके साथ हूँगा ।

एक बात उन्होंने और कही है कि ऐसा मालूम होता है कि इस कानून के अनुसार इस प्रान्त में स्टेट लैंडलाडिज्म पैदा हो जायगी, स्टेट के हाथ में सब अधिकार आ जायेंगे । मैं पूछता हूँ कि प्रजासत्तात्मक राज्य में स्टेट और समाज में क्या अन्तर होता है ? लारी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं । मुझे यकीन है कि उन्होंने राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन किया होगा । अगर उन्होंने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है तो उन्हें जानना चाहिये कि प्रजा सत्तात्मक राज्य में, यानी जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ पर स्टेट और सोसाइटी में कोई अन्तर नहीं होता, राष्ट्र और समाज में कोई अन्तर नहीं रहता । जब यह कहा जाता है कि प्रान्तीय सरकार के हाथ में कोई अधिकार है तो उसके माने यह होते हैं कि वह अधिकार समाज के हैं और समाज की तरफ से प्रान्तीय सरकार, या प्रान्त में जो कोई भी वैधानिक संस्था हो, उस कार्य का सम्पादन करती है । अगर आप जमीन का पूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति में निहित करते हैं तो क्या आप यह नहीं समझते कि कुल जमीन महाजनों के हाथ में चली जायगी । अगर सारे अधिकार अबाध रूप से काश्तकारों को दे दिये जायें तो यह काश्तकारों के लिये हानिकर हो जायगा और उनकी सब जमीने महाजनों के पास चली जायँगी । आप देखें कि जमींदारों के पास अबाधरूप से ट्रान्सफर करने के जो अधिकार थे उनका क्या परिणाम हुआ । अभी कुछ दिन पहले ८० प्रतिशत जमींदार मकरुज हो गये थे, उनकी जमींदारियाँ महाजनों के पास चली गई थीं और अगर पिछली काँग्रेस सरकार कानून बना कर उनके इस अधिकार को न रोकती, उसमें बाधा न डालती, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण न लगाती, तो आज सब जमींदारी महाजनों के पास चली गई होती । इसलिये अगर अबाध रूप से हम किसानों को सब अधिकार दे देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा । कल से किसान बेचारे बेरोजगार हो जायेंगे, उनके पास जमीन न रहेगी और सारी जमीन महाजनों के पास पहुँच जायगी । इसलिये उनके हक में यह आवश्यक है कि जमीन की मिल्कियत स्टेट के हाथ में हो, और स्टेट की तरफ से उनको पूरा अधिकार हो, उनको ही नहीं उनके लड़कों, उनके खानदान वालों को, ताकि उस जमीन का, जिस पर वह काबिज हैं, पूरी तरह उपभोग कर सकें । इससे ज्यादा अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती है ।

मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यही मसला, अभी करीब डेढ़ साल हुये, एक प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन के सामने आया था । मेरे मित्र



[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

श्री अलगूपाय राखी, जो वहाँ मौजूद हैं उस प्रान्तीय सम्मेलन की स्वागत-कारिणा सभा के अध्यक्ष थे, और सम्मेलन के सभापति थे श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी। यह सम्मेलन आजमगढ़ में हुआ था जिसमें लगभग दो लाख किसान मौजूद थे। इस जमींदारी एबालीशन (उन्मूलन) का मसला जब उसके सामने आया तो वहाँ पर दो तरमीमें पेश हुईं, एक तो यह कि इस प्रस्ताव में "बिना मुआविजा" शब्द बढ़ा दिये जायँ और दूसरी तरमीम यह थी कि किसान अपनी जमीन का मालिक हो जाय। जब यह दोनों तरमीमें वहाँ पर पेश हुईं तो किसान बेचारे भोचक्के हो गये। क्या बात है, कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो प्रस्ताव पेश होता है उसमें तो यह कहा जाता है कि मुआविजा देकर हम जमींदारी खत्म करें और दूसरी ओर कुछ कांग्रेसमैनों की तरफ से यह तरमीम पेश होती है कि 'बिला मुआविजा' जमींदारी खत्म होनी चाहिये और 'जमीन का मालिक काश्तकार को हो जाना चाहिये'।

मुझे उक्त संशोधनों के विरोध करने का काम सौंपा गया। स्वयं आचार्य नरेन्द्र देव जी ने मुझे यह काम सौंपा। मैंने खड़े होकर पेश की हुई दलीलों का जवाब दिया और मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूँ कि २ लाख किसानों में ५०, ६० किसान भी ऐसे न थे जो इन तरमीमों के पक्ष में वोट देते। उन्होंने लगभग सर्वसम्मति से मूल प्रस्ताव के हक में वोट दिये जो कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। मैं स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस फ़िःरे-वाजी का अर्थ कि किसान जमीन का मालिक हो जाय। किसान बहुत अच्छी तरह से जानता है वह यह भी जानता है कि उसका क्या हक है और यह कि ला महदूद हक मिलने से उसका वही हाल होने वाला है जो जमींदारों का हुआ है। उसकी तमाम जमीन साहूकारों के पास चली जायगी। इसके अलावा यह कहना कि यदि समस्त भूमि पर राज्य का स्वामित्व हो जायगा तो ऐसा करने से स्टेट लैन्ड-लार्डिज्म पैदा हो जायगी—यह बिल्कुल गलत है। स्टेट लैन्डलार्डिज्म डेमोक्रेटिक स्टेट (प्रजासत्तात्मक राज्य) में नहीं हुआ करती है। जनसत्तात्मक राज्य द्वारा उपज के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिये 'स्टेट लैन्डलार्डिज्म' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि उसके लिये तो 'नेशनलाईजेशन' राष्ट्रीयकरण और 'सोशलाईजेशन' (समाजीकरण) शब्दों का प्रयोग होगा।

एक ऐतराज और बड़े जोरों के साथ किया गया है कि इस बिल में, जिन काश्तकारों की जोत अनएकोनौमिक हैं, उनको वे अधिकार नहीं दिये गये हैं जिन अधिकारों के लिये खुद कांग्रेस पिछले १८ सालों से लड़ती आई थी। लारी साहब एक बड़े चतुर वकील हैं। उन्होंने काफ़ी चालाकी के साथ इस बिल का समर्थन करते हुये भी कांग्रेस पर आरोप लगाये हैं। उन्होंने बड़ी चतुरता के साथ यह पुरानी बातें कांग्रेस की निकाली हैं ताकि वे हम लोगों को

नन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २३७

गलन पोजीशन में डाल सकें और प्रान्त के लोग कांग्रेस से असंतुष्ट हो जायें। लेकिन उन्होंने यह विचार नहीं किया कि वह कौन जमाना था जब कि अनैकोनॉमिक होलिंग्स के लिये कांग्रेस ने एक विशेष योजना रखी थी। वह जमाना ग्लम्प (मर्ही) का जमाना था। उस समय में आपने देखा होगा कि लोग जमीनों को छोड़ने जा रहे थे। वह समय ऐसा था जब कि अनैकोनॉमिक होलिंग्स के लिये विशेष कोशिश करना आवश्यक था। जहाँ तक एकोनॉमिक होलिंग्स का ताल्लुक था, लोग बर्ज़ा लेकर भी अपने लगान को अदा करते थे। लेकिन जहाँ तक छोटें काश्तकारों का सवाल है वे लोग अपने-अपने लगान को नहीं दे पाते थे और उसका नतीजा यह होता था कि वे बेदखल हो जाते थे या उनको स्वयं स्तीफा दे देना पड़ता था। लेकिन क्या आप आज यह कह सकते हैं कि कोई भी काश्तकार ऐसा है जो लगान न दे सकने की वजह से बेदखल दिया गया हो। छोटें काश्तकारों के पास जमीन कुछ जरूर कम है लेकिन उसके पास उसके अतिरिक्त दूसरे कान काफी हैं। मान लिया कि ऐसा घर है जिसमें चार लोग हैं। उनमें से एक मजदूरी करता है, एक स्कूल मास्टर है और बाक़ी दो कोई दूसरा कान करते हैं, और उनके पास दो या तीन बीघा जमीन भी है।

ऐसी सूरत में यह बात नहीं है कि उनकी गुज़र नहीं होती है, बल्कि उनकी छोटी सी जांत एक तरह से उनके लिए सल्लिमेटरी इनकम (अतिरिक्त आय) का साधन है। ऐसी दशा में उसको अनैकोनॉमिक होलिंग्स कहना बिल्कुल 'अनैकोनॉमिक होलिंग्स' के गलत माने लगाना है। यही नहीं मैं आपको यहां भी बतला दूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे जमींदार हैं लेकिन उनके पास खेती की जमीन उस गाँव में नहीं है जिसमें वह रहते हैं। फिर भी वह लोग दूसरे जमींदार से एक बीघा, दो बीघा या तीन बीघा जमीन लेकर चरी बेते हैं ताकि वे गाय भैंस या दूसरे जानवर को पाल सकें। अगर आप इसको 'अनैकोनॉमिक होलिंग्स' कहेंगे तो यह बिल्कुल गलत चीज़ होगी। हाइ कोर्ट के कमरे में बैठ कर और केवल किताबों को पढ़कर अनैकोनॉमिक होलिंग्स की गलत डेफ़िनिशन (परिभाषा) कर लेना बिल्कुल गैर-मुताबिक है। इस तरह से चिथित 'जनता पार्टी' के होते हुए भी जनता का भ्रम में डालना कुछ मुनासिब बात नहीं है। हमारे मित्र फख़रुल इस्लाम साहब ने बहुत फ़्लेवरली (चतुरता के साथ) जमींदारी का समर्थन किया है। मुझे न तो लारी साहब की स्पीच से और न फख़रुल इस्लाम साहब की स्पीच से पता चलता कि आखिर जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है। फख़रुल इस्लाम साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल इस बात के खिलाफ़ हैं कि जमींदारों को कोई मुआविज़ा दिया जाय, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया ऐक्ट में यह लिखा है इसलिये देना ही पड़ेगा और जब देना ही पड़ेगा तो मुआविज़ा बढ़ाकर मार्फ़ेंट वैल्यू (बाज़ार भाव) के अनुसार देना चाहिये। वह बड़े चतुर व हील हैं, वह जमींदारों का समर्थन करते हैं लेकिन दूसरे ढंग से करते हैं। सच बात तो यह है कि यहाँ

[ श्री विरवम्भर दयाल त्रिपाठी ]

यह चीज सिद्ध हो गई कि अन्त में चरम वाम पक्षी और चरम दक्षिण पक्षी दोनों ही एक स्थान पर आफर मिल जाते हैं। यह एक राजनैतिक सर्किल है जिसमें भिन्न-भिन्न स्थानों से चलकर दोनों ही अर्थात् एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीम राइटिस्ट आकर एक ही बिन्दु पर मिल जाते हैं। सोशलिस्ट पार्टी वाले बड़ी लम्बी-लम्बी बातें करते हैं और ऐसी चीजें रखते हैं जो असम्भव हैं। वह यह चाहते हैं कि किसी तरह से जमींदारी का खात्मा अभी न हो, क्योंकि यह समझते हैं कि अगर जमींदारी का खात्मा काँग्रेस के जमाने में हुआ तो हमारी स्लोगनबार्ज खत्म हो जायेगी। (तालियाँ...।) हमारी जो फिक्करे-बाजी या दवा-फरोशी हुआ करती है वह खत्म हो जायेगी। काँग्रेस का मुक्कावला करने के ख्याल से वह यह चाहते हैं कि काँग्रेस के द्वारा जमींदारी खत्म न हो बल्कि जब हम पावर में आयें उस समय जमींदारी खत्म हो। मैं तो यह कहूंगा कि अगर उनका रवैया यही है तो १०, १५ या २० साल क्या, वह कभी भी पावर में नहीं आ सकते हैं। कथित सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री रोशन जमाँ साहब ने कल बड़े जोरों के साथ हमको (काँग्रेस को) चेतावनी दी है और चुनौती भी दी है। जहाँ तक चेतावनी का सम्बन्ध है मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हम चेतावनी बहुतों से सुनते आये हैं। जब से महात्मा गाँधी ने काँग्रेस की बाग-डोर अपने हाथ में ली उस समय से हमने अंग्रेजों की चेतावनी सुनी, हमने जमींदारों की चेतावनी सुनी, हमने पूंजीपतियों की चेतावनी सुनी, हमने कम्युनिस्टों की चेतावनी सुनी और अब आप आ गये हैं, आपकी भी चेतावनी सुन लेंगे, कोई बात नहीं है।

लेकिन जहाँ तक चुनौती का सम्बन्ध है, इसी साल के अन्दर तीन मतें बाँटे चुके हैं। जब-जब वह चुनौती देंगे तब-तब उसका जवाब दिया जायगा। साल भर के अन्दर हमने पहला जवाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में दिया। वह समझते थे कि काश्तकार हमारी तरफ हैं, काश्तकार काँग्रेस को गालियाँ दे रहा है। जगह-जगह काँग्रेस की आलोचना हो रही थी। जिस पार्टी के हाथ में शक्ति (पावर) होती है थोड़ी बहुत उसकी आलोचना होती ही है। उससे वह समझते थे कि वह वाकई काँग्रेस को गिरा सकते हैं। वह यह स्वप्न देख रहे थे लेकिन वह खुद ही चारों खाने चित्त गिर पड़े। असेम्बली के चुनाव में भी वही हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन में हुआ था। इसके बाद प्रोक्वोरमेंट (गञ्जा वसूल) के जमाने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब उन्होंने यह अच्छी तरह से देख लिया कि गल्ले की फरा-हमी रोक नहीं सकते तब खामोश हो गये। उन्होंने एक ओर शहर के लोगों को काँग्रेस से नाराज करने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें खाने को नहीं मिलता। काँग्रेस सरकार इतनी खराब है कि गञ्जा इतना महँगा मिलता है। ठुम्गी ओर देहात में जाकर कहते थे कि यह काँग्रेसी अपने को काश्तकार के

मन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २३६

नक हुकूमत में नहीं रहेंगे। शहर और देहानों में यह अलग-अलग दो जवानों से बोलने लगे। यह बात ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। फिर कहने लगे कि हम तो ज्यादा ही दूर करना चाहते हैं। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्यादा ही दूर करना चाहता है। ज्यादा ही दूर करने का हमने प्रत्येक यत्न किया। प्रोव्क्योरमेंट को हमारा कमजोर पॉइंट समझ कर उन्होंने उसको जोर से पकड़ा। और हमें चुनौती दी लेकिन उसका जवाब भी उन्हें उचित रीति से मिल गया। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जहाँ नक किसान का ताल्लुक है उनकी चुनौती का वह स्वयं जवाब देगे वह जहाँ पर चाहें काँग्रेस का मुक़ाबला कर लें। जिस जिले, जिस लोकैलिटी में चाहें वह काँग्रेस के मुक़ाबिले में चुनाव लड़ लें। आज क्या हालत है? आज हालत यह है कि शहर के सारे ब्लैक मार्केटियर आर० एस० एम० के सनथक हैं और देहान में सारे पुलिस दलाल और प्रति-क्रियावादी जमींदार सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर होते जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे सोशलिस्ट साथी यह देख ले कि उनकी पार्टी के वह मेम्बरान जो कल तक यह कह रहे थे कि तलवार के जोर से जमींदारी का रत्ता करेंगे। दूसरे ही दिन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। वह जानते हैं कि कांग्रेस में हमारा स्थान नहीं है आज ऐसे सभी लोग सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह हालत सोशलिस्ट पार्टी का है फिर भी वे हमको चैलेंज करते हैं।

**श्री मुहम्मद शौकत अली ख़ाँ—**मैं जनाब वाला से यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि मेम्बर साहब बिल को कौन सी दफा पर रोशनी डाल रहे हैं?

**श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी—**जहाँ तक किसानों के हित का सम्बन्ध है, उसके सब पहलुआ पर पूरे तौर से गौर कर के यह बिल इस भवन के सामने पेश किया गया है। इस बिल की योजना के आधारभूत सिद्धान्तों को बहुत ध्यान तथा सतर्कता के साथ निवारित किया गया है। और इससे ज्यादा हमारे सहो होने का सबूत नहीं हो सकता, जबकि दोनों तरफ के यानी एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ से आर एक्सट्रीम राइट की तरफ से हम पर हमले हो रहे हैं। ऐसी दरा में हमें समझ लेना चाहिये कि हमारा दृष्टिकोण बिलकुल ठीक और सच्चा है। अगर कोई शक भी हो सकता था तो वह शक भी आज चला गया जबकि हमने देखा कि एक तरफ से सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ से हमारे जमींदार लोग हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस कानून में देरी हो। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब देर नहीं होने की। अब तो ७, ८ जहाँ के अन्दर जमींदारी नाम की कोई चीज़ भी बाक़ी नहीं रहेगी। यह समाप्त हो जायगी और मुझे पूरी आशा है कि इसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। आप कहते हैं कि आप काश्तकारों से दस गुना लगान क्या लेते हैं। यह हम कब काश्तकारों से कहते हैं कि हमें दस गुना रुपया दो? अगर काश्तकार चाहें तो दें, अथवा न दें। हम तो जमींदारी को एक दम खत्म करके सारे इक्कू काश्तकारों का देने जा रहे हैं।

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

परन्तु उसके अलावा हम उनको एक और कंसेशन ( रियायत ) दे रहे हैं अगर एक भी काश्तकार भूमिधर होने के लिये अपने लगान का दस गुना नहीं देगा, तो भी जमींदारी खत्म होगी। इसमें कोई भ्रम न होना चाहिये। जमींदारी तो हर सूरत में खत्म होगी लेकिन काश्तकारों को एक और अवकाश मिला है कि अगर वे चाहें तो दस गुना लगान देकर अपने अधिकार को कुछ और बढ़वा सकते हैं और साथ ही साथ अपना लगान भी आधा करवा सकते हैं। यह तो किसानों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी ( जायद आसानी ) है। यहाँ पर यह भी कहा गया है, इशारा किया गया है, कि इस चीज के खिलाफ भी काश्तकारों में प्रचार किया जा रहा है। या किया जाने वाला है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मित्रों को प्रोक्क्योरमेंट के खिलाफ प्रचार करने में असफलता मिली है उसी तरह से रुपये के फराहम न होने देने के प्रयत्न में भी वे बिल्कुल असफल होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रान्त के तमाम काश्तकार इसमें हमारा साथ देंगे कई काश्तकारों से मेरी बातचीत हुई। पश्चिम के काश्तकार तो और ज्यादा रुपया देने के लिये भी तैयार हैं, लेकिन अवध या पूरब के कुछ जिलों के किसान गरीब हैं फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि वे लोग भी अपने लगान का दस गुना दे देंगे और दस गुना देकर जमींदारी का नाम जल्द से जल्द समाप्त करने में हमारी मदद करेंगे। पहले तो हमारा ख्याल था कि जमींदारी का नाम तीस - चालीस साल तक कायम रहेगा और जमींदारों को तीस चालीस साल तक इन्सटालमेंट में मुआविजा देने से तीस साल तक जमींदारी का नाम चलता रहेगा। लेकिन इस तरह से तो हम नौ, दस महीने के अन्दर ही जमींदारी के नाम को समाप्त कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रान्त के काश्तकार किसी के बहकावे में नहीं आवेंगे, वह बहकाना चाहे जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से हो, चाहे जमींदारों की तरफ से हो। अगर जमींदार साहबान इसमें बाधा डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारा क्या बिगड़ता है? हम कैश ( नक़द ) नहीं देंगे, बॉण्ड देंगे, इन्सटालमेंट अदा करेंगे। जिस तरह से हो सकेगा देंगे, लेकिन जमींदारी अवश्य खत्म होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। हम तो कैश ( नक़द ) देना चाहते हैं, लेकिन अगर कैश नहीं दे सकेंगे तो भी जमींदारी खत्म होगी। जमींदारी रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जमींदारी को कोई कायम नहीं रख सकता है। इसमें किसी को किसी तरह का भी भ्रम नहीं होना चाहिए।

एक बहुत बड़ा एतराज और किया गया है। यह कहा गया है कि जब आप जमींदारी को खत्म कर रहे हैं तो फिर जमीन का बटवारा क्यों नहीं करते हैं? यह चीज दूसरी है, वह चीज दूसरी है। जमींदारी के खत्म करने की योजना का सैंड के डिस्ट्रिब्यूशन से क्या नाकलुफ़ है? हाँ, जब हम जमींदारी को खत्म

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्ताय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २४५

कर लेंगे तो फिर संचेंगे और उसके बाद जो पोजीशन होगी उसके मुताबिक जमीन का बटवारा करेंगे। लेकिन इसका जमींदारी एबालीशन (जमींदारी उन्मूलन) से क्या संबंध है? यह कोई नई बात नहीं है। एक साहब अपने ऊँट पर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि हम इसका चार आने में बेच देंगे। जब वे उसको चार आने में बेचने में मजबूर हुए, तो उन्होंने एक बिज्जी मार कर उसके गले में बाँध डाला, ऐसा करके उन्होंने कहा कि हम ऊँट को तो चार आने में बेचेंगे लेकिन बिज्जी को पाँच सौ रुपये में बेचेंगे, और बेचेंगे दोनों का साथ ही साथ। यही क्रिस्ता यहाँ पर भी है। जमींदारी खत्म कर मैं नहीं समझता कि जमींदारी खत्म करने के साथ ही साथ लैंड डिस्ट्रीब्युशन का क्या ताल्लुक है? सच बात तो यह है कि आप जमीन के बटवारे का मसला सामने लाकर जमींदारी का खत्म करने की योजना को कुछ समय के लिये टाल देना चाहते हैं।

**श्री मुहम्मद शौकत अली खान**—फिर आपने साँस लिया। अगर आप इसी तरह बोलते रहें तो शाम हो जाएगी।

**श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी**—आप इसकी परवाह न कीजिये। बोल-बोल कर तो हमने अंग्रेजों को खत्म कर दिया और इसी तरह से अब जमींदारों को खत्म कर देंगे। खैर, प्रांत भर में तमाम आँकड़े प्राप्त होना तो मुश्किल था तो भी आपको इत्तिला के लिये बता दूँ कि जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में ६ जिलों के आँकड़े दिये हैं। वे जिले हैं, बिजनौर, मैनपुरी, सीतापुर, बस्ती, बाँदा और गाजीपुर। अगर हम दस एकड़ जमीन को एकनामिक होल्डिंग मान लें तो इन सब में मिल कर जो ज्यादा जमीन वहाँ होगी वह सिर्फ ६ लाख ७५ हजार एकड़ होगी, और जितनी अनएकनामिक होल्डिंग हों उन सबको अगर दस एकड़ पूरा कर दें तो १ करोड़ १७ लाख ८३ हजार एकड़ जमीन और चाहिए। सबकी जायद जमीन छीनने के बाद भी २० होल्डिंग्स (जोतों) में हम एक होल्डिंग को मुश्किल से एकनामिक कर सकते हैं। यह मसला भी हम लोगों के सामने था और इस पर जमींदारी उन्मूलन समिति में काफ़ी ग़ौर हुआ। यह न समझिये कि कोई ग़ौर नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस चीज़ को समझते कि इससे कोई असर किसानों की हालत पर पड़ता है तो हमको कोई भी एतराज़ इस बात पर न होता और हम इस बात की सिफ़ारिश अवश्य करते। लेकिन हमने देखा कि यह गुनाह बैलज्जन है। इससे छोटे किसानों की समस्या हल नहीं होती। तब हमने दूसरा उपाय निकाला। कमेटी ने सोचा कि जितनी छोटी होल्डिंग्स (जोतें) हैं उनके लिये जल्द से जल्द हम को-ऑपरेटिव फ़ार्मिंग का इन्तजाम करें। आपने रूस और अमेरिका की को-ऑपरेटिव और क्लेक्टिव फ़ार्मिंग का हाल पढ़ा होगा। मेरा खयाल है कि हम में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज़को पढ़ा होगा। अगर उन्होंने पढ़ा है तो वह समझ सकते हैं कि सहयोगी आधार पर खेती करने से हमारी पैदावार में कितनी वरक़्की हो सकती है। अगर हम नया तरीक़ा अख्तियार करें और जो

[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं उनके आधार पर अगर म खेती करें अर्थात् मिकेनाइज्ड फार्मिंग करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम खेती की उपज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मिकेनाइज्ड फार्मिंग ( यंत्रों द्वारा सामुहिक खेती ) तभी हो सकती है जब कि हम छोटी-छोटी होल्डिंग्स (जोतों) को एक में कर दें। लिहाजा जिनको हम अनएकनामिक या छोटी होल्डिंग्स कहते हैं उनको यदि हम एक में मिला दें और सहयोगी आधार पर कृषि करें तो इसमें सन्देह नहीं है कि हम अपने देश की उपज को बढ़ा सकते हैं और व्यक्तिगत तौर से भी किसान का फायदा हो सकता है इसलिये जितनी अनएकनामिक होल्डिंग्स हैं उनके लिये हम लोगों ने सोच कर यह उपाय निकाला कि उनको मिलाकर हम कोआपरेटिव फार्मिंग कराने का प्रबन्ध करें ताकि किसानों के लिये भी अच्छा हो, देश का आर्थिक स्तर उठ सके और साथ ही साथ खाद्य की समस्या भी हल हो सके। यह ठीक है कि उसमें तरक्की और प्रगति धीरे धीरे हो सकती है। हम यह नहीं चाहते कि जिस तरह से रूस में कलेक्टिवाइजेशन किया गया और जिस तरह से वहाँ पर बन्दूकों और संगीनों का इस्तेमाल किया गया वह बन्दूकें और संगीनें हमारे यहाँ इस्तेमाल की जायँ। हम तो काश्तकारों को समझा कर, कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रचार करना चाहते हैं, और हमें यकीन है कि हमारे देश का काश्तकार कोआपरेटिव फार्मिंग में आने को संगठित करेगा और संगठित करके अपनी उन्नति करेगा और देश की सम्पत्ति में भी वृद्धि करेगा और हमारे यहाँ इस समय जो अनएकनामिक होल्डिंग्स दिखलाई देती हैं जिनमें कम पैदावार होती है उसमें कम पैदावार नहीं होगी और उनकी उन्नति हो सकेगी।

ऐसी दशा में यह कहना कि इस बात पर हमने विचार नहीं किया बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी अवस्था में, किसी स्टेज पर ज़मीन का बटवारा करना देश के हित के लिये, प्रांत के हित के लिये आवश्यक हुआ तो हमको ऐसा करने में किसी तरह से भी संकोच नहीं होगा। अगर सार्वजनिक हित के लिये हमारे लिये ऐसा करना जरूरी हो जाय तो हम जरूर ज़मीन का फिर से बटवारा करेंगे।

हमारी योजना में पहली बात यह है कि ज़मींदारी प्रथा नहीं रहेगी। दूसरी यह है कि हमारे काश्तकारों के वर्ग बहुत सीधे सादे हो जायँगे। एक तो 'भूमिधर', दूसरे 'सीरदार' और तीसरे 'असामी'। 'असामी' शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन 'असामी' में कौन-कौन लोग रखे गये हैं यह अगर वह देखते तो शायद उनको इस बात की आलोचना करने की आवश्यकता न पड़ती। असल में तो हमारे सामने दो ही क्लासेज ( वर्ग ) रह गये हैं। एक तो भूमिधर और दूसरा सीरदार। असानी क्लास तो कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसकी ज्यादा तादाद हो और जिसके ऊपर ज्यादा महत्व दिया जा सके। जहाँ तक शिकमी काश्तकार का मसला है, मैं हमेशा इस बात के पक्ष में रहा हूँ कि उनको भी अधिकार होना चाहिये, और मुझे खुशी है कि हमारे मंत्रि-

सन १९४६ ई० का संयुक्त ग्राम्मीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २४३.

मंडल ने जो योजना नैयार की है उसमें कुछ अधिकार उनका भी दिये हैं, लेकिन फिर भी शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में फिर से विचार कर लेना चाहिये। अक्सर असली काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास कार्की जोत है और वह अपनी थोड़ी जोत शिकमी काश्तकार को उठाये हुए हैं। लेकिन अगर शिकमी काश्तकार से वह हिंसा जमीन का ले लिया जाता है तो उसके पास जमीन नहीं रह जाती है या बहुत कम रह जाती है। ऐसी हालत में, शिकमी काश्तकार को उस जमीन पर पूरे तौर से मौरसी हक हो जाना चाहिये। यह बहुत आवश्यक बात है। हमारे प्रांत में ज्यादातर शिकमी काश्तकार हरिजन हैं, और हरिजनों की दशा को हमें ऊँचे उठाना है। लगभग १५ फ्रीसदी हमारे प्रांत में शिकमी काश्तकारों की तादाद है, यद्यपि बिल्कुल ठीक संख्या तो बतलाना कठिन है। बहुत से शिकमी काश्तकारों के नाम कागजात में इन्दराज नहीं हैं लेकिन जितने इन्दराजात हैं उनके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि १५ फ्रीसदी काश्तकार शिकमी काश्तकार होंगे और उन १५ फ्रीसदी काश्तकारों में से तीन चौथाई हरिजन हैं। हरिजनों के रहन-सहन के स्तर का ऊँचा उठाना है: इसमें किसी प्रकार का भी मतभेद नहीं है। ऐसी दशा में, अगर हम उनके आधार को ऊँचा करना चाहते हैं तो हमें शिकमी काश्तकारों के अधिकारों को कुछ और ज्यादा बढ़ाना चाहिये। जब तक हम उनके अधिकारों को और नहीं बढ़ाते हैं तब तक हम उनकी अवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा यह सुझाव है कि शिकमी काश्तकारों को कुछ और अधिकार देना चाहिये शिकमी काश्तकार वास्तविक किसान (actual tillers of soil) हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनके अधिकारों पर ध्यान दें और उन्हें भी हम उसी हद तक अधिकार दें जिस तरह के अधिकार सीरदार और भूमिधर को दे रहे हैं। इस तरह की और भी तफसील की चीजें हैं और उन पर राय देने का फिर अवकाश यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुल बिल पर विचार किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं है कि जो योजना हमारे सामने रखी गई है वह बहुत सुन्दर है और उसका द्वारा हम ६, १० महीने या एक वर्ष के अन्दर जमींदारी समाप्त कर सकते हैं और सिर्फ जमींदारी ही नहीं समाप्त कर सकते हैं बल्कि काश्तकारों के ऊपर जो बोझ लदा हुआ है उसको हटा सकते हैं और हटाकर उनको इस बात का मौक़ा दे सकते हैं कि वह अपनी और देश की उन्नति कर सकें। मैं समझता हूँ कि अब हमें इस मामले में जल्दी करनी चाहिये।

मैं जमींदारों से भी अपील करूँगा कि वे अब ज्यादा हठ न करें, उनको चाहिये कि बिला किसी उज्र के वे हमारी इस योजना को स्वीकार कर लें। अभी हमारे नवाब यूसुफ साहब ने हमारे सामने एक ऊँचे सिद्धान्त की बात कही थी और यह कहा था कि हमको चाहिये कि “लिव ऐंड लेट, लिव” के सिद्धान्त का अनुसरण करें। मैं समझता हूँ कि जो यह योजना हमारे मंत्रि-



[ श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ]

मंडल ने आपके सामने पेश की है उसमें इस सिद्धान्त का पूरे तौर से ख्याल रखा गया है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जमींदार साहिबान इस बात का ख्याल नहीं करते थे। मुझे खुशी है कि नवाब यूसुफ साहब को अब यह ध्यान आया कि “लिव ऐंड लेट लिव” के सिद्धान्त पर हमको रहना चाहिये। मेरा ख्याल है कि जमींदार साहिबान ने इस सिद्धान्त को पहले से अपनाया होता तो आज यह दशा नहीं हुई होती। जमींदारी तो समाप्त होती, इसमें शक नहीं, लेकिन जिस बदनामी के साथ जमींदारी समाप्त हो रही है उस बदनामी के साथ समाप्त नहीं होती। मैं पूछता हूँ कि क्या कभी जमींदारों ने काश्तकारों के जीवित रहने का भी ख्याल किया। वह तो अच्छी तरह से रहे, वह तो आराम से रहे, लेकिन उन्होंने कभी यह ख्याल नहीं किया कि जो उनके काश्तकार हैं वह किस तरह से गरीबी में पड़े हुए हैं, उनमें कितने रोग भरे हुए हैं, उनकी कैसी खराब दशा है। लेकिन अगर देर में भी इस बात का ख्याल आया, तो मैं नवाब साहब को इस बात के लिये बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ कि भविष्य में वे और उनके जमींदार साथी इस सिद्धान्त पर चलने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमने तो अपनी योजना में इस बात की पूरी गुंजायश रखी है कि काश्तकार भी रहें, जमींदार भी रहें, परन्तु समता के आधार पर रहें, समान अधिकार लेकर दोनों आगे बढ़ें और दोनों अपनी और अपने देश की उन्नति करें। आज जमींदार लोग नाराज हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि १० वर्षों के बाद वह देखेंगे कि जमींदारों की हालत आज की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हो जायगी। आज उनके गले के चारों तरफ जमींदारी पत्थर की तरह लटकी हुई है जो उनकी गर्दन को तोड़े डाल रही है। ऐसी हालत में जो पत्थर उनके गले के चारों तरफ लटका हुआ है उसको वह फेंक दें ताकि वे गर्दन उठा कर, सीधे होकर चल सकें और खुद भी अपनी जिन्दगी बना सकें और काश्तकारों को भी जो आज उनके और उनके उस पत्थर के बोझ से दबे हुए हैं उन्नति करने का मौका मिल सके।

मुझे आशा है कि आज वे बहुत खुशी के साथ इसस्कीम को स्वीकार करेंगे और देश की उन्नति में उसी तरह से हिस्सा लेंगे जिस तरह से और देशवासी ले रहे हैं।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग सर्व सम्मति से इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बीरेन्द्र शाह—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने इस भवन के सामने पेश किया है, उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब साहबों को यह बात भली भाँति मालूम है कि यह बिल कितना अहम है कि सब तरफ से, विरोधी पार्टी, तथा कॉंग्रेस पार्टी दोनों की ओर से इसकी अहमियत को भवन के सामने रखा गया है।

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २४५

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने यह बतलाया है कि जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट और इस बिल में कितना अन्तर है, जिसके कारण हमको इसके ऊपर जनता की सम्मति लेनी अत्यन्त आवश्यक है। मैं उन्हीं बातों को दुहराना नहीं चाहता। फिर भी मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मैंने यहाँ जो तक्रारीयें सुनीं, उनसे मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि यहाँ राजनैतिक पार्टियों के आपस के झगड़े और आपस की होड़ होने की वजह से लैंड-रिफार्म्स का हमारी प्रामीण जनता पर इस बिल का जो प्रभाव पड़ेगा उसका खयाल बहुत कम रखा गया है। मैं जमींदार होने की हैसियत से और काश्तकार होने की हैसियत से यह नहीं कहता कि आप जमींदारी को खत्म न कीजिये। यदि इससे काश्तकारों का फायदा है। श्रीमियर साहब ने जो भाषण दिया था उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं इतनी योग्यता नहीं रखता कि उनके भाषण की आलोचना करूँ। लेकिन मैं यह अवश्य कहूँगा कि काँग्रेस ने जो एलेक्शन में फेस्टो निकाला था, उसकी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह है कि जो यह कहा जाता है कि जमींदार भी कहते हैं कि उन लोगों ने काँग्रेस की मदद की और काँग्रेसी सदस्यों को निर्वाचित कराने में वोट दिये। इस लिये जमींदार भी जमींदारो उन्मूलन के लिये बाध्य हैं। इसके मुतालिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सन १९४६ ई० का एलेक्शन छोटी-छोटी बातों के ऊपर नहीं हुआ था। मैं आपकी इजाजत से उस मैनिफेस्टो को पढ़ देना चाहता हूँ, आपने एलेक्शन लड़ा था और आप कामियाब होकर आये।

The Congress, therefore, appeal in these elections that other issues do not come in, nor do individuals, not sectarian principles but only one thing counts and it is the independence and freedom of our motherland.

( इस लिये इन चुनावों में काँग्रेस अपील करती है कि इसमें दूसरी समस्याएँ नहीं आतीं, व्यक्तिगत प्रश्न या जातीयता के सिद्धान्त नहीं आते, किन्तु सिर्फ एक ही बात का महत्व है और वह है हमारी मातृ भूमि की आजादी और स्वतन्त्रता )।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि काँग्रेस की इस अपील पर किसी ने अपने हित का ध्यान न देकर इस बात पर वोट दिये कि हमारी काँग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो स्वतन्त्रता के युद्ध में अधिक कामियाब होने की आशा रखती है। इस लिये हमने आपको वोट दिये। न कि जमींदारी खत्म करने के लिये वोट दिये।

आपने जिस समय जमींदारी उन्मूलन बिल के लिये कहा था उस समय श्री पन्त जी ने यह माना था कि (equitable) कम्पेंसेशन देने के बाद जमींदारी खत्म की जाय और लैंड रिफार्म्स के बारे में यह कहा कि जब आप लैंड रिफार्म्स करेंगे तब किसानों की सम्मति लेकर करेंगे ऐसी अन्तिकारी

[श्री वीरेन्द्र शाह]

चीजें आप आगे करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप Manifesto में यह कहा है—

Any such changes can, however, be made only with the good will and agreement of the peasantry concerned.

(बहरहाल ऐसे परिवर्तन सम्बद्ध कार्रवारों की नेकनियती और समझौते से किये जा सकते हैं)।

आप किसानों की राय के बिना कांआपरेटिव फार्मिंग वगैरा ऐसी चीजें आप नहीं ला सकते हैं। इसके जरिये आप बाध्य हैं। काँग्रेस को चाहिये कि वह इस बिल का भेजकर कार्रवारों से दरियाफ्त करे। ज़मींदारी खत्म करने न करने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता लेकिन इसके साथ साथ जो आप उनको देने जा रहे हैं उसके बारे में उनसे पूछने की आवश्यकता है। आप इसमें बाध्य हैं कि उनसे यह पूछें कि जो चीज आप इसके एवज में उनके लिये ला रहे हैं वह उनके हित की है या अहित की है इस लिये मैं चाहता हूँ कि आपको रिजॉल्यूशन के पास किये दिये करीब दो साल हो गये हैं। सरकार तो ध्यान नहीं देती। आपको इतनी देर लगी और लगनी भी चाहिये थी क्योंकि यह बिल बहुत अहम है लेकिन अब आप छै महीने का समय देने के लिये तैयार नहीं हैं; जिससे जनता को यह मालूम हो जाय कि आप जो करने जा रहे हैं वह कहाँ तक उनके लिये हितकर होगा। इस तरह से आप ज़मींदारी के खान्दान वगैरह को मिला कर एक करोड़ आदमियों को बेकार करेंगे और उस समय उनसे यह भी दरियाफ्त नहीं करते कि उनकी इतनी कुरबानी के बाद उनको क्या फायदा होगा।

दूसरी चीज यह है कि आपने अपनी मैनीफेस्टो में यह कहा है कि लैंड के ऊपर जो दवाव पड़ रहा है उसको अलग करने की कोशिश की जायेगी और इन्डस्ट्रीज का केन्द्रीकरण करेंगे। आप एक करोड़ आदमी बेकार कर रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या स्क्रीम है उनको किस काम पर लगाया जायेगा। आप मुआवज़ा तथा रिहैबीलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं। इतने आदमी बेकार होंगे उनके लिये सरकार कोई स्कीम नहीं ला रही है जिसके लिये हमें इत्मीनान हो कि हमारा भी काम होगा।

यहाँ पर हमारे श्रीमान् पंडित धुलेकर जो ने जा कहा कि हम ज़मींदारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया उस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। डा० भगवान दास जो कि एक वयोवृद्ध नेता हैं, उन्होंने एक लेख स्वतंत्र भारत में दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मींदारों ने देश के लिये क्या किया और ज़मींदारी प्रथा कब से चली आई है। मैं पंडित जी से निवेदन करूँगा कि ये उसको पढ़ें और समझें। इतिहास को कोई गलत नहीं कर सकता है। आप स्वयं अंग्रेजों की बहुत सी चीजें मानते हैं। और उसी कानून बैलथ में अभी तक चलते चले आ रहे हैं। कारण सिर्फ यह

मन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २४७

हो सकता है कि आप यह कहें कि जो काम आज तक जमींदार करते चले आये वह काम अब हमें करना है। जमींदारों ने हर शासन के जमाने में हर तरह का शान्ति रखने में देहांत में शान्ति और सहायता पहुँचाने में भरसक प्रयत्न किया है। आप ही रिपोर्ट में स्वयं यह बतलाया गया है कि जमींदारों के जरिए ४० का सदी आर्थिक सहायता कारत्कारों को मिलती थी। आज आप कहते हैं कि जमींदार इतने बेकार हैं और यह कि सरल एरियाज में किसी काम के नहीं हैं और उनको फाटा हुआ दिया जाय उन की जो जायज माँगें हैं उनको भी आप तुलना को तैयार नहीं हैं मैं यह आपसे अर्ज करूँगा कि यह जो बानावरण हो रहा है वह जिक्र इस वजह से हो रहा है कि कॉंग्रेस, मोरलिस और दूसरी जो भी पार्टियाँ हैं वे सब यह चाहती है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर जनता के सामने आये जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सकें। राज्य शासन का मुद्धार और राज्य शासन तथा राजनीति दो बातें हैं। इस प्रकार के बानावरण में आकर आप इस चीज की प्लीड करें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में कोई गवर्नमेंट हो वह सब देशवासियों की होगी और वह यहाँ के रहने वालों को ख्याल करेगी। इस समय आपको यह फुर्ज है कि आप हर एक को मौका दे और ऐसी चीजों में जैसे लैंड रिफार्म्स और जमींदारी एवालाशन इसमें आपको ठण्डे दिल से काम करना चाहिये। सोच समझकर हाथ लगाना चाहिए। ऐसी हालत में ये स्पीच हो रही हैं कि इसको अभी पास कर दिया जाय या इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में और बिल में इतना अन्तर है और इसमें इतने रुधारों की आवश्यकता है कि इस बिल का आपको कम से कम २ महीने के लिए ही जनता की राय के लिए भेज देना चाहिए। ताकि वह इसे पढ़ कर और समझने के बाद आपके सामने रिप्रेजेंटेशन रख सके और समझ सके। न कि इसका २० : २१ आदमियों को कमेटी बैठा कर इसका निर्माण करायें।

आप उस कारत्कार को मौका क्यों नहीं देते। वह जमीन जो उसने कर्ज में लगा रखी है, उसका कर्जा अदा कर दे तो वह जमान उसको वापिस मिल जाना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आया कि आप उस महाजन को क्यों जमीन देते हैं जो इतना ज्यादा सूद खाने वाला है। मैं यह भी अर्ज करूँगा कि सरकार ने इधर जितने टैक्स बढ़ाये हैं उनका भी कम्पेनसेशन में मुजरा मिलना चाहिये, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपना लोकल रेट बढ़ाया है। एग्रिकलचर टैक्स कमेटी में मैंने यह उज्र किया था कि यह ठीक नहीं है और जहाँ तक मुझे याद है यह आश्वासन भी दिया गया था कि यह बिल इंटरिम टाइम के लिए है। जब तक यह जमींदारी एवालाशन नहीं होता उस समय तक के लिए यह है और उसके बाद इसका असर हमारी जमींदारी कम्पेनसेशन में न होगा। अब मैं देखता हूँ कि इसमें भी कमी की जा रही है। आपके देने के बाँट दूसरे हैं और लेने के बाँट

[ श्री वीरेन्द्र शाह ]

दूसरे हैं। सरकार को खयाल करना चाहिए कि छोटे जमींदार या सब के लिये आपने १५ परसेण्ट का फ्लैट रेट गवर्ने का काटने के लिये रक्खा है।

सीर खुदकाशत के लिये भी मैं अर्ज करूँगा कि छोटे जमींदारों ने जो सीर शिकमियों को उठाया है वह आपके ही कानून के द्वारा उठाई है और आपने आश्वासन दिया था कि उनका फ़ैसले के बाद जमीन मिलेगी। मैं समझता हूँ कि न्याय होगा कि उन्हें मौक़ा मिले, चाहे वह एक साल का हो या ६ महीने का हो। वह जितनी सीर जमीन रखना चाहते हैं उसको जातने के लिये उन्हें मौक़ा मिलना चाहिए। यह कोई वजह नहीं कि जो जमीन वह शिकमी उठाए हुए हैं वह उनके हाथ से निकल जाय।

२५० रु० तक के नालगुजारी देने वाले जमींदार को आपने चाहे जितनी मार रखने की आज्ञा दे रखी थी और वह बेचारे इसी कानून के जरिये अपनी अच्छी सी सीर-खुदकाशन की जमीन शिकमियों को उठा रखी थी जो करीब ८ लाख एकड़ के हैं और काशतकारों को खुदकाशत की जमीन भी १७ लाख एकड़ शिकमियों को उठी हुई है। अब आप इन शिकमी ज़मींदारों को ५ साल के लिये वेदखल होने की रोक कर रहे हैं, और ५ साल बाद वह लोग बहुत थोड़ा सा मुआवज़ा देकर भूमिधर बना दिये जावेंगे। आप इन छोटे जमींदारों की अच्छी ज़मीन लिये लेते हैं और उनको कोई मौक़ा नहीं देते कि वह जमीन अपनी जोत में ले सकें। इन लोगों की यही मिलकियत है जिसे सरकार इस तरह से निकाल रही है। एक मौक़ा इन जमींदारों व काशतकारों को मिलना चाहिये, चाहे वह तीन माह का ही हो कि वह जमीन अपने शिकमियों से वापिस ले सकें।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर डिप्टी स्पीकर के उठ जाने पर, सभापति तालिका के एक सदस्य श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अब मैं कुछ खास खास बिल की धाराओं के बारे में कहूँगा। मुआवज़ा—

१. आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ८ गुना मुआवज़ा जो आप देने जा रहे हैं वह इक्वीटेबुल नहीं है क्योंकि आप रीहेबिलीटेशन ग्राण्ट के रूप में जमींदारों को ११ गुना से लेकर २० गुना तक आप देने जा रहे हैं। यह बात साबित करती है कि मुआवज़ा इक्वीटेबुल न्यायपूर्ण नहीं है।

२. आज भी जो सरकार एक्वीज़ीशन ऐक्ट द्वारा जमीन लेती है उसमें १६ गुना मुआवज़ा देती है, फिर जो नहर के वास्ते जमीन ली जाती है उसमें भी २५ गुना से ३५ गुना तक दिया जाता है।

३. आप ने जो काशतकारों से उनके लगान का १० गुना माँगा है उससे भी यह साबित होता है कि पूरी का २० गुना मुआवज़ा माना गया। आप हमारी चीज़ की कीमत ले रहे हैं और हम लोगों को पूरी न दे कर बहुत थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं।

४. दूसरे जहाँ हम मध्यवर्ती (इन्टर मीडिएरी) नहीं हैं वहाँ तो हमसे वह चीजें नहीं ली जानी चाहिये, जैसे परती-जमीनें, दरखतान-परती, मछली, तालाब, और परती-आबादी। इनका सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है।

५. ३ लाख एकड़ जमीन जो जमींदारों ने चाकरी (काम करने वालों को) को लगा रखी है विला लगानी, उस पर सरकार लगान लगाने जा रही है, पर इस पर मुआवजा नहीं दे रही है या तो यह जमीन वापिस दिलाई जावे या इस पर भी जमींदार को मुआवजा मिलना चाहिये।

६. आपने ८ अगस्त सन् १९४६ को जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव स्वीकार किया जिस की बिना पर आप आज यह जमींदार-विनाश और भूमि-व्यवस्था का बिल पेश कर रहे हैं प्रस्ताव के बाद गत वर्षों में सेसेट दू टैक्येज जो भी नये कर बढ़ाये गये हैं वह हमारी प्रापरटी (जायदाद) की क्रीमत घटाने के लिये किये गये हैं। इसलिये यह नये कर जो अब लगे हैं हमारी आय में नहीं घटाये जाना चाहिये।

१. कृषि-आय-कर यह तो बीच के समय के लिये लगाया गया था, और इसका सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि यह नहीं घटाया जावेगा, पर यह घटाया जा रहा है, जो अन्याय है। ऐसे दूसरे कर भी जो अब लगे हैं उनको भी नहीं घटाया जाना चाहिये। सिर्फ मालगुजारी, वह वह कर जो प्रस्ताव के पहले लगते थे काटे जाना चाहिये।

२. आप जो लगान-वसूली के खर्चा १५% काट रहे एक सर से वह बहुत बेजा है, जब आप अभी कृषि-आय-कर में हमें १२% अधिक से अधिक दे रहे हैं, यह तो वही बात रही कि चीज देने के बाँट दूसरे और लेने के बाँट दूसरे।

बिल की धारा ७१ में यह साफ नहीं किया गया किस तरह से (जायदाद) का तबादला होगा जब तक यह बात साफ नहीं बताई जाती तब तक जमींदारी का लेने का गजट नहीं होना चाहिये। जब मुआवजा पूरा नक़द मिलने पर ही ऐसा होना न्याय है।

सरकार जो सम्मिलित-रूप से हर भूमिधर वह सीरदार से एक खाते के रूप से समझ कर लगान जिम्मेदारी का डाल रही है यह ठीक नहीं। इस संयुक्त-जिम्मेदारी से बड़ा दमन फैलेगा, क्योंकि मेहनती काश्तकार और अच्छे काश्तकारों को सुस्त और नादिहंद काश्तकार का लगान देना पड़ेगा।

मालगुजारी वसूल कर के लिये सरकार ने बड़ी सख्ती से वसूल कर के लिये रक्खा है अलावा उन सब तरीकों के जो १९०१ के रेवन्यू ऐक्ट में है यह और रक्खें हैं। १. कलक्टर अपनी आज्ञा से खेत का लुनना या फसल का इकट्ठा करना या फसल का खेत या खलियान से हटाना रोक सकता है। फसल काटने या खलियान से हटाने से रोक के लिये (सेहना) चौकीदार नियुक्त कर सकता है। यह आज्ञा गाँव के सारे भूमिधर या सीरदारों पर या कुछ पर

[ श्री वीरेन्द्र शाह ]

लागू की जा सकती है। बिल की धारा २५६, कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह फसल को बेचकर मालगुजारी बसूल कर ले। इससे साफ़ जाहिर है कि सरकारी मालिकता बड़ी सख्ती से बसूल किया जायेगा, और इसके लिये कलेक्टर को कहीं अधिक-अधिकतर वर्तमान अधिकार से दिये गये हैं।

यह सब बातें हैं जिन पर हम चाहते हैं कि एक मौका मिलना चाहिये कि ताकि वह समझी जा सकें। इस बिल से प्रान्त की ग्रामीण-जनता पर क्रान्तकारी असर पड़ने जा रहा है। इसलिये मैं फिर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें उजलत न करे और इसे सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जावे। इन शब्दों के साथ मैं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

**श्री रघुवीर सहाय**—श्रीमान् चैयरमैन साहब, मैं सबसे पहिले इस महत्वपूर्ण बिल को पेश करने पर माननीय प्रधान मन्त्री, श्री चरणसिंह, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, और उनके जरिये सारे गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत और जाँकिसानी और क्वालिटी के साथ इस बिल को भवन के सामने पेश किया है मुझे इसके कहने की आवश्यकता नहीं कि ज़मींदारी को खत्म करने का प्रस्ताव सन् १९४६ में ८ अगस्त को पास हुआ था।

उसके करीब करीब २ वर्ष के उपरांत जो ज़मींदारी अबोलिशन कमेटी मुक़र्रर की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश होने के लगभग एक साल के बाद इस भवन में यह बिल आया है यानी रिजोल्यूशन पास करने के तक्करीबन ३ साल बाद यह बिल भवन में पेश किया गया है। जहाँ तक कि देरी का सवाल है मैं समझता हूँ कि इस देरी में कुछ ख़ूबी भी है। एक अंग्रेज़ी का मसला है "to every dark cloud there is a silver lining" (दुख के साथ सुख भी सम्मिलित रहता है)। मैं समझता हूँ कि तीन साल के बाद यदि यह बिल भवन में आया है तो उसमें भी फायदा ही हुआ है। वह यह है कि तीन साल के बाद ज़मींदारों में से ६५ प्रतिशत इस बात के हामी हो गए हैं कि ज़मींदारियाँ जल्द खत्म की जायँ मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो विचार राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने और नवाब मुहम्मद यूसुफ़ साहब ने यहाँ पर रखे हैं वही विचार आम तौर पर ज़मींदारों के हैं। जिन ज़मींदारों से मिलने का हम लोगों को अवसर मिलता रहता है वे सभी इस बात को चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज़मींदारी खत्म होनी चाहिये। अगर उनके दिल में किसी क़त्म की कोई फ़िक्र है तो वह इस बात की है कि उन्हें मुनासिब मुआवज़ा मिल जाना चाहिये और मैं समझता हूँ कि यह खयाल उनका मुनासिब है। और इस मुनासिब खयाल को पूरा करने में जहाँ तक गवर्नमेंट कोशिश कर सकती थी उसने कोशिश की है। आठ अगस्त सन् ४६ के प्रस्ताव में यह बात साफ़ है कि ज़मींदारियों का ख़ात्मा करना चाहते हैं लेकिन मुनासिब मुआवज़े के साथ। अगर प्रस्ताव में महज़ ज़मींदारी खत्म

करन का मानना होता था कि सम्झौता हुआ है। राजा इस बिल के पेश करने में तीन माल की दरी नहीं लगनी। इसके साथ साथ छोटे-छोटे भी जमींदारी सवालान थे। उन मालाला के हल नि-लने में देरी लज्जित और जरूरी थी। इस बिल को देखने में मालूम पड़ा कि जो जमींदारी अबेलीमान कमेटी की रिपोर्ट है, अगले बड़े बड़े मालाला रिपोर्ट है, अगले वह बड़ी योग्यता से लिखी गई है फिर भी मैं समझता हूँ कि कई मामलों में यह बिल उत्तम भी बेहतर है। इसलिये जमींदार अबेलीमान कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि जो मुआवजा जमींदारों को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जायगा वह बांडूम की रकत में होगा और वह बांडूम ४० माल तक चलते रहेंगे। इस चीज में काफ़ी बेचैनी जमींदारों में पैदा हो गई थी। और उनका एतराज था कि इधर तो हमारा खाला मिया जा रहा है उधर आइन्दा के लिये भी हमारा गला घोंटा जा रहा है। लेकिन इस बिल के अन्दर उनके जायज मुतालिवे का खयाल किया गया है और बिल में बड़ी इ. कलनन्दी के साथ इस बात को लिखा गया है कि जमींदारों को मुआवजा नक़द दिया जावे और एक मुश्त।

मैं समझता हूँ कि इस चीज के लिये तमान जमींदारों छोटे और बड़ों का कांग्रेस सरकार का भ्रूण होना चाहिये। मुझे ताजुव हुआ जब राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने जो इस असेम्बली के एक बड़े मोअज्जिज मेम्बर हैं और बड़े पुराने पार्लमेंटेरियन हैं, फ़ायदे, क़ानून के अन्दर बात करते हैं, रिलिवेंट और इररिलिवेंट का खयाल रखते हैं, उन्होंने यह कहा कि आप मुआविजा काश्तकारों से दस गुना लेकर दे रहे हैं, इसमें तो काश्तकारों की मौत है—इससे क्या फ़ायदा। आप यह खयाल कीजिये जो नक़द मुआविजा दिया जा रहा है, वह जमींदारों के मुतालबात पूरा करने के लिये, उनका दिल रखने के लिये, उनको इत्मीनान देने के लिये है। कहा जाता है काश्तकारों का गला घोंटकर रुपया वसूल किया जायगा। राजा साहब और दूसरे जमींदारों को मालूम होना चाहिये कि जमींदार छोटे बड़े सभी काश्तकारों से बड़ी-बड़ी नज़राने की रक़म लेकर जमीने उठाते रहे हैं ! ५०० रु० तक फ़ी बीघा नज़राने का लिया गया है गरजे कि नज़राने की कोई तादाद नहीं है। इस पर आप को क़लक नहीं आता है। लेकिन आज क़लक इस बात पर है कि सरकार आप को मुआविजा दिलाने के लिये, काश्तकार को सहूलियतें देते हुये, उसको ज़मीन का मालिक बनाकर दस गुना लगान माँगती है इस शर्त पर कि जिस वक़्त काश्तकार दस गुना लगान दे देगा तो आइन्दा उसका लगान आधा कर दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी बात एतराज के काबिल है। प्रधान मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि बड़े जमींदारान अपने असोसिएशन से यह प्रस्ताव पास कर दें कि उन्हें मुआविजे की जरूरत नहीं है तो वह उसका स्वागत करेंगे और छोटे जमींदारों के मुआविजे के बारे में सोचेंगे कि किस तरीक़े से वह अदा किया जा सकता



[ श्री रघुबीर सहाय ]

है। आया काश्तकार से १० गुना लगान लिया जायगा या नहीं, लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं करते यह एतराज महज एतराज के लिये किया जाता है, इसमें कोई तत्व नहीं है। इसके अलावा हम इस बिल में एक और बेहतरी देख रहे हैं। न सिर्फ यह कि मुआविजा नक़द में दिया जायगा बल्कि एक एतराज जो ज़मींदारों की तरफ से किया जाता था यानी मुआविजे की रक़म में कोई तश्खीस न होना चाहिये। बड़े छोटे का लिहाज़ न करना चाहिये। लिहाज़ा सरकार ने इस ख़याल को मद्देनज़र रखकर छोटे बड़े ज़मींदार सबका मुआविजा ८ गुना उनके नेट असेट्स का कर दिया है। यह एक बड़ी चीज़ है। इस के अलावा बिल में एक नयी चीज़ सरकार की तरफ से पेश की गई है। रिहैबिलिटेशन ग्रांट। इस का जिक्र एबालिशन रिपोर्ट में नहीं आया है। इससे पहले इसका जिक्र माननीय प्रधान मंत्री की तरफ से किसी बयान में नहीं आया है। इसके पेश करने से यह जाहिर होता है कि सरकार के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है कि वह ज़मींदारों के खिलाफ कोई बदला लेने का जज्बा रखती है। बल्कि इससे जाहिर होता है कि वह ज़मींदारों के साथ फ़राखदिली और उदारता का बरताव करना चाहती है। वह चाहती है कि ज़मींदार मुआविजों की रक़म से अपनी जिन्दगी आराम व आसायश के साथ बसर कर सकें। वह किसी रोज़गार में रुपया लगाकर अपनी आइन्दा की बह्युद्दी का इन्तज़ाम कर सकें।

मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों पर विचार करते हुये ज़मींदारों को बिला किसी शर्त के गवर्नमेंट का मशकूर होना चाहिये। लेकिन उसके साथ ही साथ जहाँ पर मैंने इस बिल का वह रुख इस भवन के सामने रखा है जिसकी बजह से मुझे यह मालूम पड़ता है कि एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट से यह बिल बेहतर है मैं यह भी समझता हूँ कि अभी इस बिल में कुछ बेहतरी की और गुज़ायश है। कांग्रेस हमेशा से और आज तक इस बात का दावा करती आई है, कि जो ज़मींदार ढाई सौ रुपये तक मालगुजारी देते हैं वे असल में ज़मींदार नहीं हैं बल्कि वे काश्तकार ही हैं। एक ख़याल इससे पहले यह भी था कि अगर ज़मींदारी को ख़त्म किया जायगा तो ढाई सौ रुपये तक मालगुजारी देने वाले इससे मुस्तसना किये जायँगे। मैं उस चीज़ को यहाँ पर कहने के लिये तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़मींदारी ख़त्म करने का जो उसूल है वह सब के साथ एक सा बरतना चाहिये, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों। क्योंकि ज़मींदारी का ख़ात्मा इसी तरीके से हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिन उसूलों की तरफ माननीय प्रधान मन्त्री जी ने अपनी शुरू वाली स्पीच में इस भवन का ध्यान दिलाया था कि उन्होंने मुआविजा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने में बड़े ज़मींदारों के बड़प्पन का ख़याल रखा है और छोटे ज़मींदारों के छोटेपन का ख़याल रखा है। उनकी जो दिक्कतें और परेशानियाँ हैं उनका ख़याल रखा है। मैं चाहता हूँ कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट

देने में आप उन दोनों उसूलों का और ज्यादा खयाल रखें। मैं किसी तरह पर भी यह कहने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जो मुआवजे की रकम आपने मजमुई मुक़रर कर रखी है उसमें इजाफ़ा किया जाय या रिहेबिलिटेशन ग्रांट के लिये जो मजमुई रकम आपने मुक़रर कर रखी है उसमें इजाफ़ा किया जाय। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने के लिये तैयार हूँ कि अगर आप मुनासिब तरीके पर इन मजमुई रकमान में कुछ कमी करना चाहते हैं तो कमी कर दीजिये। क्योंकि अगर आप इन रकमात में कमी करेंगे या इजाफ़ा करेंगे तो तमाम बातों पर विचार करके ही करेंगे। जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उनकी तमाम बातों और उनकी तमाम दिक्कतों का आपको खयाल रखना चाहिये। इन खयालात को मद्देनजर रखते हुये मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि गवर्नमेंट द्वारा इस पर ध्यान दे कि आया ढाई सौ रुपये मालगुजारी जो लोग देते हैं उनका हम जितना रिहेबिलिटेशन ग्रांट दे रहे हैं वह मुनासिब है या नहीं है। मेरा जाना खयाल यह है कि वह ग्रांट मुनासिब नहीं है। उसमें कुछ इजाफ़ा करने की जरूरत है या जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मजमुई रकम रिहेबिलिटेशन ग्रांट की आपने मुक़रर की है, अगर आप चाहते हैं कि २५० रु० तक मालगुजारी देने वाले जमींदारों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट देने में ज्यादा रकम दी जाएगी तो मैं अर्घ करूँगा कि जो पाँच हजार तक मालगुजारी देने वाले लोगों को रिहेबिलिटेशन ग्रांट देने का फैसला किया है उसमें थोड़ी सी कमी कर दीजिये। आप ४ हजार तक की मियाद मुक़रर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तीन हजार कर सकते हैं। इस तरह से रिहेबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय जिसमें कोई बेकार न रहे। ढाई सौ रुपए तक मालगुजारी देने वालों को इतनी ग्रांट दी जाय जिससे वे अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकें। बहुत से ऐसे जमींदार हैं जो बेकार हैं, बूढ़े हैं, विधवायें हैं, आपको यह भी मालूम है कि बहुत से जमींदार अपनी गुज़र बसर सिर्फ़ जमींदारी के ही रुपये से करते चले आये हैं कोई दूसरा रोज़-गार उनके पास नहीं है। आज रुपये की क़ीमत चौथाई हो गई है अगर उन्हें कम्पेन्सेशन या रिहेबिलिटेशन ग्रांट कम देते हैं जिनका कोई जरिया माश नहीं है तो वह कैसे अपनी और अपने खान्दानों की गुज़र कर सकेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इन जमींदारों में वे जमींदार भी हैं कि जिनके पास कोई सीर या खुदकाशत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपने जिस दरियादिली और फ़ैयाज़ी के साथ इस बिल में काम लिया है वह दरियादिली और फ़ैयाज़ी अब भी जारी रहना चाहिए। उन लोगों का खयाल रखें और इस बात का खयाल रखें कि आइन्दा इनकी जिन्दगी दूभर न हो जाय और मुश्किल न हो जाय। बल्कि जहाँ तक इस बिल के जरिये हम उनके लिये आसानियाँ दे सकते हैं वह दी जायँ। रिपोर्ट के पढ़ने से यह मालूम पड़ता है कि ऐसे जमींदार जो कि सौ रुपए से ढाई सौ रुपए तक मालगुजारी देते हैं उनकी तादाद ५१ हजार ५६४ है। यह बहुत बड़ी तादाद नहीं है और इनमें से वह लोग और भी कम होंगे

[ श्री खुशीर सहाय ]

कि जिनके पास सीर और सुदकारन नहीं है वह जिनका गुजारा आमदनी जमींदारों से है। तो न समझता हूँ कि उन लोगों को ज्यादा रिहबिलिटेशन ग्रांट देने से गवर्नमेंट के पास पर कोई ज्यादा असर न पड़ेगा। इसी सिलसिले में एक बान और भी कहना चाहता हूँ। उच्चाविज्ञे के देने में यह रक्खा गया है कि नेट एसेट्स का अनुमान मिलेगा और रिहबिलिटेशन ग्रांट भी नेट एसेट्स पर स्कीम के अनुसार दो जाएगी। इसी के साथ साथ यह भी रक्खा गया है कि १५ फी सदी जमींदारों के खर्च की रकम ग्रेस एसेट्स में से निकाल दी जाएगी। अब देखना यह है कि १५ फीसदी खर्चा जमींदारों काटने के बाद २५० रु० तक के मालगुजारी को क्या रकम मुआवजा व रिहबिलिटेशन ग्रांट में मिलेगा। मेरा खयाल है ऐसा करने में उन जमींदारों के साथ बड़ी ज्यादाती होगी। क्या यह मुनासिब है कि जो जमींदार ढाई सौ रुपये तक मालगुजारी देते हैं और जिनका कोई खर्च जमींदारों के इन्तजाम में नहीं होता उनसे यह १५ परसेंट क्यों काटा जाय। खर्चा उन लोगों का होता है कि जिनके पास बड़ी-बड़ी स्टेट्स है जिनके पास बड़ी-बड़ी ताल्लुकदारियाँ हैं और जिन्हें पूरा स्टॉक उसके इन्तजाम के लिये रखना पड़ता है और जो वगैरे स्टॉक के अपनी जमींदारी का इन्तजाम नहीं कर सकते। अगर आप उनके पास इन्कम में से इसे निकालें तब तो वह इक बजानिब है लेकिन छोटे जमींदारों का ग्रेस इन्कम में से यह रकम काटना मुनासिब नहीं है। उनके लिए एक बहुत बड़ी ज्यादाती की बात होगी। इस मसले पर बिल अंबालिशन कमेटी की रिपोर्ट के सिकारियों से बेहतर नहीं है क्योंकि रिपोर्ट के सला ५६७ पर यह कहा गया है —

“Estimated percentage of gross assets to be deducted as cost of management and irrecoverables, varying from 5 percent. in the case of the small Zamindars to 15 percent. in the case of the biggest Zamindars,”

( प्रबन्ध और वसूल न लिये जा सकने वाली रकमों के खर्चों के तौर पर जो कुल पूँजी कम की जायेगी उसके प्रतिशत का अनुमान छोटे जमींदारों की सूरत में ५% से लेकर बड़े जमींदारों की सूरत में १५% तक होगा।

मैं समझता हूँ कि कमेटी की सिकारिश मुनासिब है।

इस के माना यह है कि ढाई सौ रुपये के मालगुजारी तक कास्ट आफ मैनेजमेंट सोच विचार करके रखना चाहिये। इन छोटे जमींदारों को कम्पेन्सेशन व रिहबिलिटेशन आफिसर के सामने जाकर यह माफ़ा मिलना चाहिये कि वह अपने खर्च जमींदारों के बारे में यह सकें कि कितना खर्चा बाकई में उनका होता है जो बाकई में होता है वही मिनाहा किया जाय बाकई नहीं। १५ फी सदी का रेट सबके लिये मुकर्रर करना किसी तरह पर भी मुनासिब नहीं है।

इस बान को दाइराने का जरूरत नहीं है कि जमींदारी बिल के लाने का उद्देश्य क्या है। जमींदारी बिल के लाने का उद्देश्य जहाँ तक मैं समझता हूँ

सिर्फ यही नहीं है कि जमींदारी और जमींदार को खतम किया जाय बल्कि जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपनी पहली तक्रार में कहा था यह भी है कि हम किसानों कि गिरती हुई दशा को उठाकर उनके रहन सहन के स्तर को ऊँचा कर सकें और जो कमी पैदावार आज हमारे मुल्क के अन्दर है जिसकी वजह से चारों तरफ त्राहि त्राहि फैली हुई है उसको पूरा कर सकें। अगर इस जमींदारी अवालिशन के बाद यह दोनों चीजें नहीं हासिल होती हैं तो मैं समझता हूँ कि जमींदारी अवालिशन से कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा हमको इस बिल को इस नज़र से भी देखना चाहिये कि आया उन दोनों चीजों को जिनको हमने अपना ध्येय बनाया है उनके हासिल करने में यह बिल मदद देगा या नहीं। यह देखने की बात है। आपने लैंड टैन्वोर जमीन किस तरीके से काश्तकारों को दी जायगी उसका ब्योगा इस बिल में लिखा है। आपने बताया है कि हम भूमिधर काश्तकार बनायेंगे, सीरदार बनायेंगे, असामी बनायेंगे, अधिवासी बनायेंगे और आपने यह भी प्तिक् किया है कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी तरफ़ी देंगे और उसके चलाने के लिये जो कुछ भी कर सकते हैं वह करेंगे। ये सब बातें ठीक हैं लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि इनसे फूड प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जायगा। मुझे शक है और मैं समझता हूँ कि अगर बिल के अन्दर कोई इस क्रिस्म की चीज़ नहीं रखी गई कि जिससे जल्दी से जल्दी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने पर असर न पड़े तो यह सब बेकार होगी। जरूरत इस बात की है कि जहाँ पर काश्तकार को इस बात का इत्मिनान दिलाया जाता है कि अगर तुम लगान देते चले जाओगे तो तुमको जमीन से बेदखल नहीं किया जायगा, तुम्हारे और स्टेट के बीच में कोई तीसरा शख्स नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर ज्यादाती कर सके उसके साथ साथ हमको यह भी देखना चाहिये कि जो पैदावार की दिकत इस वक़्त हो रही है उसमें इस बिल के पास करने के बाद दूर हो सकेगी या नहीं और मैं समझता हूँ कि इजाफ़े का सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है और वह तरीक़ा यह है कि जहाँ हम काश्तकारों को इतनी सहूलियत दे रहें हैं और काश्तकारों के साथ पूरी हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं और हमारी हमदर्दी नेकनियती पर मुनहसिसर है वहाँ पर हम काश्तकार को इस बात के लिये भी तैयार करें कि वह फूड प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के तरीकों को अख्तयार करे वह तरीक़ा यह है कि जो आराजियात काश्तकारों के पास हैं वह क्रिस्म जमीन की बिना पर तकसीम की जायँ और काश्तकारों से यह कहा जाय कि वह अपनी जमीन के एक हिस्से पर गेहूँ व चना व खाने में इस्तेमाल आनेवाली चीजों को पैदा करें, बाकी हिस्से में अपनी मर्जी के मुताबिक फसल करें। मैं अपनी इस तजवीज़ की तार्ईद में आपको प्तिक्ला एक तजुर्बा सुनाना चाहता हूँ। आज काश्तकार की ज़िदियत क्या है? काश्तकार ने, जहाँ पर वह बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा मेहनती है वहाँ पर उसने बहुत सी कमजोरियाँ शहर वालों से हम लोगों से सीख ली हैं। जो कमजोरी मैं ने देखी है और महसूस की है वह यह है कि वह चाइता है कि येही कस्ब बोर्ड जाय कि उससे दुरन्त इक़द कपया लिख जाय।

[श्री रघुवीर स्हाय]

किसान आज देश काप बांता चाहता है वह फूडकाप नहीं बांता चाहता आपका प्रो मार फूड केम्पेन, आपका ट्रेक्टर्स का केम्पेन, आपका मैन्योर का केम्पेन, इर. गेशन का केम्पेन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली का पहुँचाना यह सब लॉगरेज प्लान है। कौन जानता है कि हमारा इन्दिगो में उसका फायदा मिलेगा और देखेंगे कि उससे तरका होगी या नहीं, कोई नहीं कह सकता। ट्रेक्टर्स आवें या न आवें, कानियाब हों या नाकामियाब हों, मैन्योर का तजुर्बा कामयाब हो या नालमयाब हो? लेकिन मैं उस पर कोई नुक्ताचार्ज नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ जितनी आपकी स्कीम है वह सब चल जायें क्योंकि वह नेकर्नीयता पर मबनी है लेकिन वह चोज क्यों अनल में नहीं लाते जिससे आपको तुरन्त फायदा हो मिलता है। पिछली ग्रेन प्रोक्योरमेंट स्कीम में हमको काफी तजुर्बा हुआ है। हजारों ऐसे काश्तकार हम लोगों के पास आये हैं जिन्होंने यह कहा कि पर्चा रबी के लगान का भिला है लेकिन हमने रबी की ही नहीं यानी हमने गेहूँ बोया हों नहीं। हमारा पास दूसरे जिलों से भी खतूत आये हैं। उन्होंने कहा है यह आपकी क्या जबरदस्ती है हमने गेहूँ नहीं बोया, हमने चना नहीं बोया मगर हमसे कहा जाता है कि गेहूँ और चना दो। नतीजा यह हुआ उन हजारों काश्तकारों ने उन फार्म होल्डर्स ने क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट के लिये लाजमी था कि वह रबी के लगान का गल्ला बसूल करती लिहाजा उनको ब्लोक मार्केट से गल्ला खरीदना पड़ा और उस गल्ले को गवर्नमेंट को देना पड़ा। इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा यह निकला कि बहुत से काश्तवार रबी की फसल में चना और गेहूँ नहीं बोना चाहते। क्यों नहीं बोना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत देर बाद मुनाफा मिलता है गन्ने में फौरन क्रॉमत मिल जाती है। अफीम में फौरन क्रॉमत मिल जाती है। तम्बाकू में भी ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिये वह आदि हो गये हैं कि ऐसी फसलें बोये जिससे कि उन्हें फौरन रुपया मिले। इस बात का आज किसान को लिहाज नहीं है, वह समझ नहीं सकता कि अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो गेहूँ वहाँ से आयेगा, चना वहाँ से आयेगा। तो मैं अर्ज करता हूँ कि आपको इस बिल के अन्दर कोई ऐसा प्राविजन रख देना चाहिए कि बिल के अमलदरामद होने के बाद काश्तकारों को जमीन को इस तरीके से तक्रसीम कर दिया जाय कि जो अच्छे क्रिस्म की जमीन है जो गेहूँ और चने की फसल के लिये मुनासिब है उसमें के एक हिस्से में उसको गेहूँ और चना बोना लाजमी होगा। बाकी जो जमीन है उसमें जमीन की क्रिस्म के मुताबिक फसल बोयें। जैसे आप कम्पलसरी ग्रेन प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं उसी तरह से इसे भी कम्पलसरी कर सकते हैं और काश्तकार को भी यह नहीं-अखरेगा, क्योंकि काश्तकार भी तो आखिर को गेहूँ खायेगा, चना खायेगा। उसको ईख की फसल बोने के बाद ब्लोक मार्केट से गेहूँ और चना खरीदना पड़ता है। इसलिये आपको ऐसा प्राविजन इस बिल में जरूर करना चाहिये कि काश्तकार

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय अधीनदार विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २५७

मजदूर हो जाय और उसको अपनी आराजी में गेहूँ और चना बोना पड़े, मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी तरतीब कर देते हैं तो आपको बाहर से किसी क्रिस्म के गल्ले को मँगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको राशनिंग बगैर करने का जरूरत नहीं पड़ेगी और जो इस लिललिले में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं वह नहीं पड़ेंगी।

यह चीज आसानी से हो सकती है मेरा भरोसा है कि बिल की दफा २०३ और २१८ में इसी क्रिस्म की तरतीब कर दी जाय कि क्रायदों के मुताबिक अधीन की तकसीन कर दी जायगी और किसान को उसी के मुताबिक फसलें बोना पड़ेंगी।

इसके बाद मुझे एक और मसले पर इस भवन की तबज्जह दिलानी है और वह यह कि मालगुजारी वसूल करने का जो तरीका आपने इस बिल के अन्दर दिया है वह यह कि आप गाँवों में गाँव समाज और गाँव सभा स्थापित करके उनको यह जिम्मेदारी देंगे कि वह मालगुजारी वसूल किया करें। जहाँ तक कि गाँव सभा का ताल्लुक है बिल की डेफिनीशन्स को देखने से यह मालूम पड़ता है कि इस बिल में गाँव सभा वही क्रार दी जायगी जो पंचायत ऐक्ट में गाँव सभा है। लेकिन गाँव समाज एक दूसरी चीज है। गाँव समाज में वही लोग शामिल हो सकेंगे जो उस हल्के और उस गाँव में २१ वर्ष की उम्र के होंगे। पंचायत ऐक्ट में भी जो गाँव सभा का कांस्टीट्यूशन रखा गया है उसमें भी यही शर्त है कि २१ वर्ष के बालिग मर्द और औरत उस सभा में शामिल हो सकेंगे। यह दो क्रिस्म की सभाएँ और समाजों को स्थापित करने से क्या लाभ है। आपने अभी हाल में पंचायतों को क्रायम किया है। गालिबन उन्होंने अपना काम करना भी शुरू नहीं किया है। हम सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि यह पंचायतें किस तरीके से काम करेंगी। परमेश्वर से सब लोगों की यही प्रार्थना है कि यह पंचायतें ठीक तरीके से काम करें और हमें उम्मीद है कि यह ठीक तरीके से काम करेंगी और उन लोगों की उम्मीदें पूरी न हो सकेंगी जो यह समझते हैं कि यह पंचायतें नाकामियाब होंगी। लेकिन फिर भी यह देखते हुये कि गाँव वालों में शिक्षा कम है, क्या यह मुनासिब है कि एक तरह पंचायत ऐक्ट के जरिये से गाँव सभा क्रायम करें और दूसरे बिल के जरिये से गाँव समाज उन्हीं सब लोगों की बनाई जावे। इस से मैं समझता हूँ कि गड़बड़ी होगी। आप नये नये नाम गाँव के सामने न लाइये। जिन जिन संस्थाओं को आपने क्रायम किया है उनको कामियाब होने दोजिये। गाँव वालों के दिमाग में फितूर पैदा हो जायगा, वह गड़बड़ा जाएँगे कि गाँव सभा का काम क्या है और गाँव समाज का काम क्या है। आपने मालगुजारी की वसूली का काम गाँव सभा को दिया है यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बावजूद इसके कि मैं उन लोगों में हूँ जो यह चाहते हैं कि पंचायतें कामियाब हों और मुझे उम्मीद है कि कामियाब होंगी, लेकिन गाँव सभाओं पर जरूरत से ज्यादा

[ श्री रघुवीर सहाय ]

जिम्मेदारी ढालना यह कोई अत्रलमन्दी की बात नहीं है। जितनी जिम्मेदारी पंचायत ऐक्ट में ढाली है वही काफी है। उसका तजुर्बा होने दीजिये। दो, तीन साल देखिये, अगर वह ठीक तरीके से अपना काम करे तो यह नई जिम्मेदारी भी ढालिये। लेकिन शुरू से ही मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी गाँव सभा के ऊपर ढालना मैं समझता हूँ कि एक खतरनाक चीज है।

गाँव में रहने वाले बहुत सी चीजों में गड़बड़ी कर सकते हैं लेकिन उनसे स्टेट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर वह स्टेट की मालगुजारी में गड़बड़ी करते हैं तो खतरनाक नुकसान पैदा हो सकता है। इसलिये बावजूद इसके कि जहाँ पंचायतों के साथ हमारी हमदर्दी है वहाँ हम यह भी चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारियाँ महदूद होनी चाहिये। उनकी जिम्मेदारियाँ ला महदूद नहीं होनी चाहिये और मालगुजारी की जिम्मेदारी अहम और ज़बर्दस्त जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ और समझता हूँ कि यह मुनासिब नहीं है कि वह जिम्मेदारी उनके ऊपर ढाली जाय। यह दरियाफ्त किया जा सकता है कि क्या और कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिसके जरिये मालगुजारी वसूल की जाये। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ख्यालात पेश करने का मौक़ा सिलेक्ट कमेटी में आवेगा और जो साहबान वहाँ जायेंगे वह मशविरा व सलाह दे सकेंगे कि मालगुजारी वसूल करने का क्या तरीका बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज के ऊपर भी गौर कर लिया जाय और यह मसला भी सिलेक्ट कमेटी में रखा जाये।

मैं अपनी तकरीर को अब ज्यादा लम्बी करना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि इस भवन में जो बहुत सी तकरीरें मुख्तलिफ़ कमिटीयों की तरफ़ से हुई हैं उनमें आप मुझे माफ़ करेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो बिल से कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका यह ख्याल है कि आज इस मसले पर हम भवन में बहस नहीं कर सकते हैं कि जमींदारी खत्म होना चाहिए या नहीं। इसकी बहस तो उस वक़्त मुनासिब थी जब जमींदारी अबोलिशन का प्रस्ताव हाउस के सामने रखा गया था और तमाम बहस और मुबाहिसे के बाद जब वह तय कर दिया गया कि जमींदारी अबोलिशन ही हमारा मक़सद है और होना चाहिए फिर इसके बाद यह बहस ग़ैर ज़रूरी हो जाती है। बहस के दौरान में सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स बताने गए और यह कहा गया कि हमारा यह प्रोग्राम है वह प्रोग्राम है, इन सब बातों की ज़रूरत नहीं थी बल्कि हमें बिल को बिलकुल ठंडे दिल से देखना चाहिए था कि आया जो मक़सद हमने ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० के प्रस्ताव में रखा था वह इससे हल होता है या नहीं। मैं उन में से हूँ जो यह समझते हैं कि बिल के जरिए से हमने उस मक़सद को पूरा किया है।

मैं राजा जगन्नाथ बलरा सिंह सक्सेना के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ कि जिसमें उन्होंने बिल के सरकुलेशन के बारे में कहा है मेरे कबाल में पञ्जिका में

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल २५६ सरक्यूलेट किये जाने की जरूरत नहीं है। और न कोई वजह ही है क्योंकि भवन में बहुत से ऐतराजात हो चुके हैं कि इस बिल के लाने में काफ़ी देरी की गई है और वाकई देरी हुई भी है। कोई शक़्स इससे नावाक़िफ़ नहीं है कि ज़मींदारी एबालीशन की क्यों जरूरत है और क्यों जरूरत नहीं है। इसलिये इस पर बहस करना महज़ भवन का समय ख़राब करना है। और पब्लिक के कर्षों को भी ख़राब करना होगा, अगर यह बिल दुबारा प्रकाशित किया जाता है। अन्त में मैं उस प्रस्ताव का जो राजा जगन्नाथ बख़्श सिंह साहब ने पेश किया है उसकी मुख़ालिफ़त करते हुए जो प्रस्ताव माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ।

❧ श्री निहालुद्दीन—जनाब वाला, इस वक्त तक कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से और दूसरे मेम्बरान की बहुत सी तक्ररीरें हुईं लेकिन बजुज इसके कि जो स्पीच अभी बदायूँ के मेम्बर साहब ने दी और सब में उस मौजूद पर गुफ़्तगू की गई कि जो इस मौक़े और वक्त के नामौजूद है। ज़मींदारी ख़त्म करने के प्रिंसिपल (उसूल) को तो भवन पहले ही पास कर चुका है। अब उस फिरके के मुताज़िफ़ उस की बुराई का तबसरा करना मैं इस भवन के मेम्बरान के विचार के खिलाफ़ समझता हूँ और न मौक़े की मौजूमियत रखता है। हकीक़तन तो ज़मींदारी बिल के आने से पहले ही ख़त्म हो चुकी। सन् ३७ में हमारे नज़दीक़ उनकी हैसियत कुछ थी लेकिन अब वह एक सयासी मुर्दा है। इसलिए इस समाजी मुर्दे का पोस्टमार्टम करना हमारे नज़दीक़ मुनासिब व मुफ़ीद न होगा। जहाँ तक उसूल का ताल्लुक़ है ज़मींदारी एबालीशन से किसी को एख़ितलाफ़ नहीं है और न सूबे में ज़मींदारी मौजूद रहने की कोई जरूरत ही है। सिर्फ़ सवाल यह है कि यह निज़ाम किस तरह से तब्दील किया जाय। उस के लिये हमारे नज़दीक़ यह बिल एक नाकामयाब कोशिश है। बिल में सब से बड़ा नुक्स यह है कि दो मुख़तलिफ़ चीज़ें बिल के अन्दर दी हुई हैं। अन्वल तो यह कि ज़मींदारी का ख़त्म करना और उसका मुआविज़ा देना। दूसरे यह कि नये निज़ाम का पैदा करना और उनके हक़ूक़ का तहफ़फ़ुज करना। यह दोनों चीज़ें हकीक़तन बिल्कुल अलग-अलग होनी चाहियें यानी ज़मींदारी के ख़ात्मे का बिल एक अलग ऐक्ट और नये हक़ूक़ जो ज़मींदारी के बाद पैदा होते हैं वह एक अलग ऐक्ट में आने चाहिए। दूसरी बातों के लिहाज़ से मौजूदा बिल में जो नुक्स है वह यह है कि हक़ूक़ और उनके निफ़ाज के मुताज़िफ़ जो वक़ात हैं वह इस तरह से एक दूसरे में मिला दी गई हैं कि उनका अलग-अलग समझना मुश्किल है, अगर इस बिल के दो हिस्से होते तो बेहतर था, अन्वल तो यह कि जो पोसिड्योर से ताल्लुक़ रखता है और दूसरे जिसका ताल्लुक़ सन्सटेंटिव

❧ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।



२६०

लेजिस्लेटिव असेम्बली

[ ६ जुलाई, १९४६ ]

[ श्री निहालचौधरी ]

( खास, अलग ) हकूक से है दोनों को एक जगह इकट्ठा करना मेरे नज़दीक एक ग़लत प्रैक्टिस है ।

डिप्टी स्पीकर—अब सवा पाँच के ऊपर हो गया है । आप की तक्रार परसों जारी रहेगी ।

( इस के बाद भवन ५ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, ११ जुलाई १९४६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया । )

लखनऊ,  
६ जुलाई, १९४६

कैलास चन्द्र भटनागर,  
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,  
संयुक्त प्रान्त ।

## नत्थी 'क'

( देखिये ८ जुलाई, १९४६ के प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर )

क्रम संख्या	नाम बीज गोदाम	कुल बकाया जो कि रु० की शक्त में १-७-४८ को था	क्रम संख्या	नाम बीज गोदाम	कुल बकाया जो कि रु० की शक्त में १-७-४८ को था
१	मिर्जापुर	१५,०१४ ३ ३	३३	सलखन	१०,५६१ १४ ६
२	श्री पट्टी	२०,७३० ० ०	३४	अमोखर हरगढ़	१३,६५४ ५ ३
३	कछवा	१२,६६३ ११ ०	३५	घोरावल	४६,६७३ १३ ६
४	पंडरी	२२,४८२ १२ ६	३६	शिवद्वार	२७,६६४ ६ ६
५	तिलुही	६,६४७ ८ ३	३७	मैरवा	३७,४६३ १३ ०
६	कलवारि	१६,८०६ ८ ३	३८	शाहगंज	२७,४८५ ६ ०
७	बघीडा	२,५३३ १५ ६	३९	जमागाँव	४८,८७७ ४ ६
८	राजगढ़	३२,७७३ १४ ०	४०	तिलौली	३३,४१६ १५ ०
९	गयपुरा	२७,३७१ १० ६	४१	कर्मा	२८,५४३ १३ ०
१०	लालगंज	१६,६३३ ४ ०	४२	कवराहो	४४,४२६ ४ ३
११	बरोधा	१४,८१० ६ ६	४३	दुर्डी	४,०४८ २ ६
१२	लहंगपुर	५,००२ ३ ३	४४	विठमगंज	१,७३६ ४ ६
१३	सुखरा	५,५५२ १३ ०	४५	म्योरपुर	२,१०६ ६ ३
१४	कोटा	६,४६८ ५ ३	४६	गहरवारगाँव	२,६६५ ८ ३
१५	पथरीर	४,२६७ ० ०	पूर्ण योग ...		१०,८६,८१३ ४ ०
१६	मलवा	८,८६२ ५ ०	नोट—१-७-४८ से		
१७	चुनार	३८,५६२ ३ ३	लगायत २८-२-४६ तक		
१८	सीखड़	३८,४६४ ८ ६	जो रुपया वसूल हुआ	२,६१,७७६ ३ ६	
१९	इमिलिया चट्टी	११,०२५ ६ ६	शेष	८,२५,०३७ ० ३	
२०	जिवनाथपुर	२०,५६८ १० ६	तावान सन् ४७-४८ का		
२१	जनालपुर	१८,०८८ ८ ०	रबी का ५० प्रतिशत के		
२२	परोरा	४४,३८८ ४ ३	बजाय १२१ प्रतिशत होने		
२३	अदलहाट	१६,८२३ ८ ३	से जो रु० कम हुआ	६३,३६७ ११ ३	
२४	मुहर्ली	४३,६५२ ११ ०	शेष जो अब वसूली		
२५	चौकिया	२१,२४२ १० ०	करने को बाक़ी है	७,६१,६६६ ५ ०	
२६	अहरौरा	१६,५३७ ३ ६			
२७	राबर्टसगंज	८६,६८७ ११ ३			
२८	बैनी	१६,१४८ ० ०			
२९	मधुपुर	२५,८६० १३ ०			
३०	पुर्वनियाँ	१७,४८६ ६ ६			
३१	नई बाज़ार	४६,०६० ११ ३			
३२	राम गढ़	५६,६१० ७ ६			

## नत्थी 'ख'

(देखिये ८-७-४६ के प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७६ पर)

प्रायः गल्ले की वसूली समाप्त होने के समाह में जो रेट तहसील से प्राप्त हुआ वह इतना महँगा रेट था कि बक्राया जो रुपये की शकल में पड़ा वह बहुत अधिक हो गया। क्योंकि महकमे के कानून के अनुसार बक्राया उसी रेट पर लगाया जाता है जो वसूली के आखिरी समाह का होता है। इसके अलावा कानून साढ़े बारह फीसदी तावान इसके ऊपर और लगाया गया। इस तरह से बक्राया कमी डेढ़े या दूने के लगभग हो गया।

२ सन् १९४५-४६ और १९४६-४७ में भी बरसात की कमी होने के कारण पैदावार न हो सकी जिसके कारण बक्राया अधिक पड़ गया और अधिक दिनों तक यह निर्णय न हो सका कि यह बक्राया माफ कर दिया जाय या वसूल हो और यदि वसूल किया जाय तो किस प्रकार वसूल हो और इस कारण अधिक दिनों तक बक्राया वैसे ही पड़ा रहा। केवल ४५-४६ का बक्राया राबर्टसगंज तहसील का कुल बक्राये का आधा है।

३. गंगा और अन्य सहायक नदियों में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण बहुत अधिक फसल का नुकसान हुआ। मिजापुर और चुनार तहसीलों में बहुत अधिक क्षति पहुँची और खेतों में खड़ी फसल पानी के अन्दर रहने से काफी सड़ गई और किसान बीज भंडारों से लिया हुआ गन्ना वापस न कर सके। जिसके कारण अत्याधिक बक्राया पड़ गया।

४. इस जिले में प्रायः पहाड़ी जिला होने के कारण फसल देर में बोई जाती है और देर में काटी जाती है। इस प्रकार फसल की मढ़ाई भी देर में होती है। किसान सर्वाई पर लिया हुआ गल्ला उचित समय पर बीज भंडारों पर वापस नहीं कर पाते। सन् १९४७-४८ में गल्ले की वसूली की आखिरी तारीख जो १५ जून को हुआ करती थी वह ३१ मई को ही समाप्त हो गई। क्योंकि बीज भंडारों को सहकारी विभाग में स्थानान्तरित करना था। इस कारण वसूली अधिक न हो सकी और बक्राया अधिक पड़ गया।

५. प्रायः जाड़े के दिनों में असामयिक और अधिक वर्षा हो जाने से खरीफ और रबी दोनों फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव फसल के उचित बाढ़, उचित समय पर पकना और सामयिक मढ़ाई पर पड़ता है और किसान प्रायः सर्वाई पर लिया हुआ गन्ना उचित समय पर वापस नहीं कर पाते। अस्तु अधिक बक्राया पड़ गया।

६. प्रायः ऐसा भी हुआ है कि बीज गोदामों के सुपरवाइजर्स ने सीमा के बाहर बीजों को बाँट दिया है और वसूली के समय में शत प्रतिशत वसूली न कर सके हैं।

७. इस जिले के अधिकतर कृषि उपरवाइज़र गल्ले की शत प्रति वसूली करना अपना प्रधान कर्तव्य नहीं समझते थे।

८. जब जब बक्राएँ की तेहरिस्त रेविन्यू तहक़में में वसूली के लिए दी जाती थी तब तब वे इस तहक़में की वसूली पर कोई ख़ास ध्यान न देते थे।

९. इस जिले में अब तक ४६ बाज़ भंडार रहे हैं और गेदामों की संख्या दूसरे जिलों की वरिष्ठत बहुत अधिक रही है इससे बक्राया बहुत पड़ा गया।

१०. इस जिले में अधिकतर रुपए के बक्राएदार प्रभावित जन ही लोग हैं। उन लोगों का यह मिश्रण हो गया है कि वे वसूली को बन्द करने की या क़िस्त बंधाने की आज्ञा प्रदान करवाने हैं जिसके कारण कुर्क अमीन तथा वसूली करने वाले लोग वसूली करने से रहिन हो जाते हैं। यही लोग छोटे लोगों पर भी दसर डाल रहे हैं जिसके कारण अच्छी वसूली नहीं हो पाती और अत्याधिक बक्राया पड़ा है।

११. प्रायः प्रत्येक बाज़ भंडार के क़ुरक ऋण को वसूली का किसी न किसी बहाने से जैसे हमें रज़्ज़ा नहीं मिला है, जैसे बाँड पर दस्तख़त नहीं किया है, मेरे दस्तख़त क़र्ज़ी बनाये गये हैं या मेरे नाम के साथ ज़्यादा रज़्ज़ा लिखा है, विरोध करते हैं। इन कारणों से ऋण की वसूली में अत्याधिक विलम्ब हो रहा है।

## नयी 'ग'

( देखिये ८-७-४६ के प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८४ पर )

क्र०	राम सेशल मैजिस्ट्रेट व रेवेन्यू आफिसर	मुकदमों की संख्या जो फेसले किये			संख्या मुकदमात जिसमें अपील हुई			संख्या मुकदमात अपील मंजूर होने की		
		४६-४७	४७-४८	४८-४९	४६-४७	४७-४८	४८-४९	४६-४७	४७-४८	४८-४९
१	श्री हेमचन्द्र मिश्र सेशल मैजिस्ट्रेट	११७	१५२	१३०	२२	१४	१०	४	-	-
२	श्री राजा लाल सेशल मैजिस्ट्रेट	८६	२८७	३४३	१	३०	३२	-	१३	७
६	श्री कै० पी० युवार रेवेन्यू आफिसर	१८३१	३२२२	११७४	१३	४६	२६	४	५	६

नस्थियाँ 'घ'

इ.वि.दे २-५-१६ के २५-७ का अन्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

नान क-नीच	मादाद	रि.राय- प्रतिनास	कब न रि.राये पर लिया गया
-----------	-------	---------------------	--------------------------

रु० आ०

१ ड्रेसिंग टेबुल	६	० ८	नवम्बर, १९४७ से जनवरी, १९४८ तक
२ टाबेल रैक	११	० ८	नवम्बर, १९४७ से
३ कमोड	२५	० ८	नवम्बर, १९४७ से नवम्बर, १९४८ तक
४ सोफालेट	१	१० ०	नवम्बर, १९४७ से अगस्त, १९४८ तक
५ बाथ पट्टा	१६	० ४	नवम्बर, १९४७ से
६ नेवार ब्रेड	२०	३ ०	" " "
७ नेवार ब्रेड	२०३	३ ०	१६ अक्टूबर, १९४८ से
८ आर्मलेस चेयर	११७	१ ०	" " "
९ आर्मड चेयर	४५	१ ८	" " "
१० वाशहैंड टेबुल	५	१ ०	" " "
११ डाइनिंग टेबुल	८	२ ०	" " "
१२ ड्रेसिंग टेबुल	१४	३ ०	" " "
१३ फ्राग चेयर	४८	२ ०	" " "
१४ टी टेबुल	२६	१ ०	" " "
१५ टाबेल रैक	३२	० ८	" " "
१६ बाथ बोर्ड	४२	० ८	" " "
१७ इनानल जग	२७	१ ०	" " "
१८ पिलपाट	४०	० ८	" " "
१९ बेसिन	१७	१ ०	" " "
२० स्पिटून	१७	१ ०	" " "
२१ आर्मलेस चेयर	७०	१ ०	फरवरी, १९४६ से
२२ टी टेबुल	३७	१ ०	" " "
२३ आर्मड चेयर	४०	१ ८	" " "
२४ कमोड	२०	१ ८	" " "
२५ वाशहैंड टेबुल	२०	२ ०	" " "
२६ वाशहैंड बेसिन	२०	१ ०	" " "
२७ नेवार ब्रेड	४७	३ ०	" " "
२८ राइटिंग टेबुल	३३	२ ०	" " "
२९ डाइनिंग टेबुल	४	२ ०	" " "
३० फ्राग चेयर	३७	२ ०	" " "
३१ ड्रेसिंग टेबुल	१८	३ ०	" " "
३२ आर्मलेस चेयर	१६	१ ०	" " "

# नत्थी 'कु'

नत्थी जिसमें १९४६-४७, १९४७-४८ के प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)  
(देखिए ९-७-४६ के प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९४ पर)  
दिया गया सीमेंट और फौलाद बनावे के प्रयोजन के लिये बदायूं और उमैनी में  
उन लोगों के नाम और पते  
जिनमें परमिट दिया गया

साल	जगह	उन लोगों के नाम और पते	आया फौलाद का परिमाण	प्रयोजन	जिसको सिफा-जारी होने पर परमिट की दिया गया तारीख
१९४६-४७	२	बौटने का काम सीधे भारत सरकार करती थी और कोई रिकार्ड नहीं मिल सका है।	५	५	५
		श्री साहू जगन्नाथ सिंह, भूतपूर्व सीनि-यर वाइस चेरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, उमैनी	४	५	५
		जो० टो० आयल, राइस ऐंड दाल मिल्स, उमैनी	१ टन १०	गोदाम बनाने के लिये	२०/२५-६-४८
	बदायूं	श्री बहीद अहमद, एम० एल० ए० बदायूं	२ टन	गोदाम बनाने के लिये	२७-५-४८
	उमैनी	गंगाराम राजाराम, उमैनी	५ टन १०	भूतपूर्व बनाने के लिये	२५-४-४८
१९४७-४८	बदायूं	श्री बहादुर लाल चौधरी बदायूं;	२ टन	भूतपूर्व बनाने के लिये	३०-८-४८
		सर्व श्री कन्हैयालाल रतनलाल बदायूं, मोहल्ला मौलवीगंज।	१०० बोरे	भूतपूर्व बनाने के लिये	१८-९-४७
		श्री अब्दुल करीम मोहल्ला खौवसाली	१५ बोरे	भूतपूर्व बनाने के लिये	१८-१०-४७

लोअरलेटिफ असेम्बली

१८ जुलाई, १९४८

# बदायूं

"	श्री बाबूराम मुल्तार घौसला रेलवे स्टेशन बदायूं	"	१० बोरे	"	१६-६-४७
"	श्री नन्धू माफत भाल मोहदी करशन के दफ्तर के पास, लास्ट एरिया मोहल्ला पानवारी, बदायूं ।	"	६ बोरे	"	१८-६-४७
"	श्री हरिहर सरन, मुंशिफ, माफत श्री आर० सो० वर्मा, सेशन जज बदायूं श्री हरवंस सिंह, पिता का नाम गुलाबसिंह, शरणार्थी कोठी, हकीम सिंह ।	"	५० बोरे	"	१०-१२-४७
बदायूं		फौलाद	(१) टन, १० हंडर	मकान और डिस्ट्रिक्ट हाउस दुकान बिराये सिंग कमेटी के लिए	२२-११-४८
"	श्री शिव दरसन लाल, पिता का नाम बाबू राम, मोहल्ला चौधरी श्री गजराजसिंह, माफत सर्वश्री गजराजसिंह, मथुरा प्रसाद	"	१ टन	"	२८-१२-४८
"	श्री ज्वाला प्रसाद, पिता का नाम, बिहारीलाल मदवारगंज श्री सोतीलाल, मदवारगंज श्री रान मदन लाल पिता का नाम काशी राम, ब्रह्मपुर सर्व श्री श्यामचरन बुधसेन, चक्की के पास	"	१ टन १० हंडे ४ टन	"	२२-११-४८
बदायूं		"	१० हंडे ४ टन	"	२७-१२-४८ ३-१-४९
"	श्री श्याम चरन चक्की गजाराग के पास	"	४ टन १० हंडे	"	३-१-४९
"	श्री आर० पी० टंडन (२ परभिट)	"	२ हंडे	"	१०-१-४९
"		"	५ टन ६ हंडे	"	१५-१-४९

१६४८-४९

मतिश्रय

२७



## नत्थी 'च'

(देखिये ६-७-४६ के प्रश्न १३ (क) का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

रोडवेज की गाड़ियों के सुधार के लिये मैन्टिनेन्स स्टेशनों के नाम:

१. गोरखपुर रीजन ।आ। विदघाट ।वा। बत्ती ।सा। कसिया
  २. इलाहाबाद रीजन ।आ। जौनपुर ।वा। बनारस
  ३. कानपुर रीजन ।आ। विल्लहौर ।वा। सराय मीरा ।सा। घाटमपुर  
।ख। फतेहपुर ।ग। इलाहाबाद ।पा। मद्दोबा ।घ। बांदा
  ४. लखनऊ रीजन ।आ। सीतापुर ।वा। सुल्तानपुर
  ५. आगरा रीजन ।आ। मथुरा ।वा। अलीगढ़ ।सा। शिकोदाबाद
  ६. बरेली रीजन ।आ। शाहजहाँपुर ।वा। मुरादाबाद ।सा। बिजनौर  
।पा। पीलीभीत
  ७. मेरठ रीजन ।आ। दिल्ली ।वा। खतौली ।सा। मुजफ्फरनगर  
।ख। रुढ़की ।ग। सहारनपुर ।घ। हरद्वार
  ८. कुमायूं रीजन ।आ। रामनगर ।वा। रानी खेत
-

नत्थी 'छ'

( देखिये ६-७-४६ के प्रश्न सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६६ पर )

ब्योरा खेत व कृषक जिनका खेत लिया जा रहा है

.....

नाम कृषक	कुल जमीन जो कृषक के पास है।			भूमि जो ली जा रहा है।			भूमि जो कृषक के पास बच जाती है।		
	बीघा	बिस्वा	धुर	बीघा	बिस्वा	धुर	बीघा	बिस्वा	धुर
परमानन्द	१	१६	७	०		१२	१	१४	१५
गिरधारीसिंह	२	८	१०	०	१८	०	१	१०	१०
रामचरन	३	३	४	०	५	४	२	१८	०
धूरन	५	१०	१२	०	५	०	१	५	१२
रामनाथ	४	११	१३	१	१२	१६	२	१८	१७
मिखू	२०	३	१	०	५	१२	१६	१७	६
चुल्ली	११	१३	३	०	६	१८	११	६	५
परसोतम	२	१८	१८	०	३	८	२	१५	१०
मु० लडमारी	८	१६	१६	०	५	०	८	१४	१६
धूरा	२	०	६	०	५	०	१	१५	६
बेचू	१७	११	१६	०	१७	८	१६	१४	८
रघुनन्दन	६	२	३	१	१६	८	४	४	१५
सहदेव	७	१६	१०	०	१२	१४	७	३	१६
रामदीन	२	०	०	०	७	१४	१	१२	६
लखन	७	५	१४	०	६	०	६	१६	१४
गनपत	२	१६	१	०	६	१६	२	६	५
योग	१०३	०	१४	८	१८	१०	६४	२	४



# संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

सोमवार, ११ जुलाई सन् १९४६ ई०

(असेम्बली की बैठक असेम्बली-भवन, लखनऊ, में ११ वजे दिन में आरम्भ हुई।)

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदाम टण्डन

## उपस्थित सदस्यों की सूची ( १७६ )

अचल सिंह  
अजित प्रताप सिंह  
अदील अब्बासी  
अब्दुल गनी अन्सारी  
अब्दुल वाक्की  
अब्दुल मजीद  
अब्दुल मजीद ख्वाजा  
अब्दुल वाजिद, श्रीमती  
अब्दुल हमीद  
अम्मार अहमद ख़ा.  
अलगाय शास्त्री  
असगर अली ख़ा  
अक्षयवर सिंह  
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री  
इन्द्रदेव त्रिपाठी  
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती  
ऐज़ाज़ रसूल  
करीमुर्रज़ा ख़ा  
कालीचरण टंडन  
किशनचन्द पुरी  
कुंजबिहारी लाल शिवानी  
कुशलानन्द गैरोला  
कुपाशंकर

कृष्ण चन्द्र  
कृष्ण चन्द्र गुप्त  
केशव गुप्त  
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री  
कुशवर्त राय  
कुशीराम  
ख़ूब सिंह  
गजाधर प्रसाद  
गणपति सहाय  
गणेश कृष्ण जैतली  
गोपाल नारायण सक्सेना  
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री  
गोविन्द सहाय  
गंगाधर  
गंगा प्रसाद  
गंगा सहाय चौबे  
चतुर्भुज शर्मा  
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री  
चन्द्रभानु शरण सिंह  
चरण सिंह  
चेतराम  
छेदालाल गुप्त  
जगन्नाथ दास

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल  
 जगन्नाथ सिंह  
 जगमोहन सिंह नेगी  
 ज़ाहिद हसन  
 ज़ुगुल किशोर  
 जयपाल सिंह  
 जय राम वर्मा  
 दयालदास भगत  
 दाऊदयाल खन्ना -  
 द्वारिका प्रसाद मौर्य  
 दीन दयालु अवस्थी  
 दीन दयालु शास्त्री  
 दीप नारायण वर्मा  
 धर्मदास, अल्फ्रेड  
 नफ़ीसुल हसन  
 नवाज़िश अली खां  
 नवाब सिंह  
 नाज़िम अली  
 नारायण दास  
 निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री  
 नेहालुदीन  
 पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती  
 पूर्णमासी  
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती  
 प्रागनारायण  
 प्रेम किशन खन्ना  
 फ़ज़लुल इस्लाम  
 फ़तेह सिंह राणा  
 फ़ैन्थम, आर्चिबाल्ड जेम्स  
 फ़िलिप्स, अर्नेस्ट माईकेल  
 फूल सिंह  
 बदन सिंह  
 शीघर मिश्र  
 बनारसी दास  
 बलदेव प्रसाद  
 बलभद्र सिंह

बशीर अहमद  
 बशीर अहमद अंसारी  
 बादशाह गुप्त  
 बाबू राम वर्मा  
 बीरबल सिंह  
 भगवती प्रसाद दुवे  
 भगवती प्रसाद शुक्ल  
 भगवानदीन मिश्र  
 भारत सिंह  
 भीम सेन  
 महफ़ज़ुर्रहमान  
 महमूद अली खां  
 मिजाजी लाल  
 मुकुन्दलाल अग्रवाल  
 मुनफ़ैत अली  
 मुहम्मद असरार अहमद  
 मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी  
 मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री  
 मुहम्मद इस्माईल  
 मुहम्मद जमशेद अली खां  
 मुहम्मद नज़ीर  
 मुहम्मद फारुक  
 मुहम्मद यूसुफ़  
 मुहम्मद रज़ा खां  
 मुहम्मद शकूर, हाजी  
 मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री  
 मुहम्मद शौकत अली खां  
 मुहम्मद सुलेमान अघमी  
 यशनारायण उपाध्याय  
 रघुनाथ विनायक धुलेकर  
 रघुबीर सहाय  
 रघुवंश नारायण सिंह  
 राघव दास  
 राजकुमार सिंह  
 राजाराम मिश्र  
 राजाराम शास्त्री

राधाकृष्ण अग्रवाल  
 राधा मोहन सिंह  
 राधेश्याम शर्मा  
 राम कुमार शास्त्री  
 रामकृपाल सिंह  
 रामचन्द्र सेहरा  
 रामचन्द्र पालीवाल  
 रामजी सहाय  
 रामधर मिश्र  
 रामधारी पांडे  
 राम बली  
 राम शंकर लाल  
 राम शरण  
 राम स्वरूप गुप्त  
 रामेश्वर सहाय सिंह  
 रक्तुद्दीन खा  
 लताकृत हुसैन  
 लाल बहादुर, माननीय श्री  
 लाल बिहारी टंडन  
 लीलाधर अष्ठाना  
 लुत्फ अली झा  
 लोटन राम  
 विजयानन्द मिश्र  
 विजय कुमार मुकर्जी  
 विश्वनाथ प्रसाद  
 विश्वनाथ राय  
 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी  
 विश्वनाथ दुबिष  
 वीरेंद्र झा  
 वैकटेश नारायण तिवारी  
 शंकर दत्त शर्मा

शान्ति प्रपन्न शर्मा  
 शिव कुमार पाण्डेय  
 शिव कुमार मिश्र  
 शिव दयाल उपाध्याय  
 शिवदान सिंह  
 शिवमंगल सिंह  
 शिवमंगल सिंह कपूर  
 शुचेता कृपलानी, श्रीमती  
 श्याम लाल वर्मा  
 श्याम सुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द्र सिधल  
 श्रीपति सहाय  
 मजन देवी महनोत, श्रीमती  
 मम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 सरवत हुसेन  
 सलीम हामिद खा  
 साजिद हुसैन सैयद  
 सालिग्राम जैसवाल  
 सिंहासन सिंह  
 सीताराम अष्ठाना  
 सुदामा प्रसाद  
 सुरेन्द्र बहादुर सिंह  
 सूर्यप्रसाद अवस्थी  
 सैयद जाकिर अली  
 सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन  
 हबीबुर्रहमान अंसारी  
 हरगोविन्द पंत  
 हरप्रसाद सत्यप्रेमी  
 होती लाल अग्रवाल  
 त्रिलोकी सिंह

## प्रश्नोत्तर

सोमवार, ११ जुलाई, सन् १९४६ ई०

( शनिवार, ६ जुलाई, सन् १९४६ ई०, के शेष प्रश्न )

## तारांकित प्रश्न

तहसील नकुर ( सहारनपुर ) में सिंचाई

२०६. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर व तहसील सहारनपुर में कितने एकड़ भूमि में नहर से सिंचाई होती है और कितने में कुएँ और अन्य जगहों से ?

माननीय कृषि सचिव ( श्री निसार अहमद शेरवानी )—

तहसील का नाम	भूमि की सिंचाई एकड़ में	अन्य जगहों में
नहर से	कुएँ से	
( १ ) नकुर	१६,८००	४२,४७३
( २ ) सहारनपुर	४३,६००	२,३०४
		८६६

२०७. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर, जिला सहारनपुर में खूब के कुएँ कितने हैं ?

माननीय कृषि सचिव—इस समय तहसील नकुर, जिला सहारनपुर, में ६ खूब के कुएँ हैं ।

२०८. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार को मालूम है कि नकुर गोदाम में जो ५२ रूबट लगभग दो साल से पड़े हैं अब तक उनमें से दो रूबटों की बिक्री हुई इसका मुख्य कारण क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—यह सच है कि अभी तक कुल दो रूबटों की बिक्री हुई । शेष रूबटों की बिक्री इस कारण नहीं हुई कि किसानों ने उन्हें लेना स्वीकार नहीं किया । इन रूबटों में बकेट का और बकेटों के पहिए का नाप उससे भिन्न है जो पहिले से इस्तेमाल में थी । किसान को यह समझने में समय लगेगा कि नई रूबटें पहिली रूबटों से हल्की चलती हैं ।

श्री जगन्नाथ दास—जिन दो किसानों ने रूबट खरीदे हैं क्या वे हल्का चलाने की तरकीब सीख चुके हैं या नहीं ?

माननीय कृषि सचिव—इसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है । उन किसानों से पूछ कर बता सकूँगा ।

श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रूबट गोदाम में पड़े हैं वे कितने दिनों से पड़े हैं ?

माननीय कृषि सचिव—मैं इसमें ठीक तारीख नहीं बता सकता ।

\* २६. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुर में जिन गहटों में किमान आबपाशी करने हैं उनकी तादाद क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—तहसील नकुर में जिन गहटों में किमान आबपाशी करते थे उनकी संख्या आन्दोलन २००० है

ज़िला महारनपुर के जुलाहों को सरकारी सहायता

\* २७. श्री जगन्नाथ दास—क्या सरकार बतायेगी कि ज़िला महारनपुर में शुद्ध न्वादी बुनने वाले जुलाहों में सरकार न्वादी प्रसार योजना के अन्तर्गत कोई सहायता देती है ? यदि हाँ, तो क्या ?

माननीय उद्योग सचिव ( श्री ब्रेशवदेव मालवीय )—महारनपुर जिले के जुलाहों को न्वादी तैयार करने के काम के लिये अभी तक कोई अनुदान या राज-सहायता नहीं दी गई है

श्री जगन्नाथ दास—जो जुलाहे शुद्ध न्वादी बुन कर देहातों में अपनी गुज़र करते ह, क्या सरकार उनकी सहायता करने का विचार रखती है ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार शुद्ध खादा तैयार करने वालों की हर प्रकार की सहायता करने को तैयार है । इसके लिये एक प्रान्तीय न्वादी प्रचार कमेटी बना दी गई है जो ऐसे तनान प्रश्न पर विचार करती है । मैं माननीय सदस्य को यह सुभाष दूँगा कि वह इन जुलाहों का इस कमेटी में सम्पर्क करा दें ।

अयोध्या शुगर मिल, राजा का साहसपुर, और उसके  
नौकरों के बीच समझौता

\* २८. श्री मुकुन्द लाल अभ्रवाल—क्या यह ठीक है कि अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर और उनके नौकरों के बीच में हुआ एक समझौता रीजनल कान्सिलियेशन बोर्ड (शुगर) बरेली रीजन [Regional Conciliation Board (Sugar) Bareilly Region] के सम्मुख पेश हुआ ?

माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मन्त्री ( श्री महफूज़ुर्रहमान )—जी हाँ !

\* २९. श्री मुकुन्द लाल अभ्रवाल—क्या यह सच है कि उपरोक्त समझौते की मद ७ में :—

(क) शान्ति स्वरूप, रहीम बख्श, जहांगीर और रामस्वरूप, मिल-कुली, सरकारी आदेश दिनांक २६-६-४६ के अनुसार मिल के रिकार्ड ( Record ) के आधार पर स्थायी माने गये ?

(ख) उपरोक्त व्यक्तियों को चार-चार मास का वेतन दिया जाना निश्चित हुआ ?

(ग) यह भी लिखा गया कि जिस समय से उक्त मज़दूर पृथक किये गये और जिस समय वह काम पर फिर से वापिस लिये जायेंगे वह बीच का समय उनकी बिला वेतन की छुट्टी मानी जावेगी ?



श्री महफूजुर्रहमान—(क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ !

(ग) जी हाँ !

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि जो सगर्भाता इस जून के जवाब में बतलाया गया है वह सरकारी आदेश दिनांक २६ जून, सन् १९४७ के विरुद्ध है ?

माननीय शिक्षा सचिव ( श्री सम्पूर्णानन्द )—ऐसी तो कोई इच्छा तो उभे नहीं है ।

\* ३३. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके उल्लेखित समझौते की एक प्रतिलिपि मेज पर रखेगी ?

श्री महफूजुर्रहमान—एक + प्रतिलिपि मेज पर रखी गई है ।

\* ३४. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि गुगर्ग फ़ैक्टरी बहेड़ी के क्वार्टर्स में रहने वाले मज़दूरों का टाउन एरिया टैक्स पिछले वर्षों में उक्त फैक्टरी ही दिवा करती थी ?

श्री महफूजुर्रहमान—यह सच है कि उक्त फ़ैक्टरी १९३५-३६ से लगातार टैक्स देती चली आई थी । टैक्स नोटिफाइड एरिया का था ; टाउन एरिया का नहीं क्योंकि बहेड़ी नोटिफाइड एरिया है ।

\* ३५. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उक्त फैक्टरी ने इस साल उल्लेखित टैक्स देने से इन्कार कर दिया है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ, सन् १९४७ ई० से फैक्ट्री ने यह टैक्स देना इन्कार कर दिया है ।

\* ३६. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि रीजनल कन्सिलियेशन बोर्ड ने यह सिफ़ारिश की थी कि उक्त फैक्टरी टैक्स को पूर्ववत् स्वयं दे, किन्तु इण्डस्ट्रियल कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया है और उक्त फैक्टरी टैक्स देना स्वीकार नहीं कर रही है ?

श्री महफूजुर्रहमान—जी हाँ, इण्डस्ट्रियल कोर्ट ने यह कहा है कि टैक्स देना न देना मिल मालिक की इच्छा पर निर्भर है ।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इण्डस्ट्रियल कोर्ट के निर्णय से और फैक्टरी की ज़िद से वहाँ के मज़दूरों में घोर असन्तोष है ?

माननीय शिक्षा सचिव—ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है ।

केन कोआपरेटिव सोसाइटी पीलीभीत के कर्मचारियों का वेतन

\* ३७. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि केन कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, पीलीभीत के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को ५० रु० मासिक वेतन का नोटिस देकर रखा था और उक्त सोसाइटी ने अपने १९४८-४९ ई० के आय-व्ययक में इसी दर के वेतन की व्यवस्था भी की थी ?

माननीय कृषि सचिव—केन कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के असिस्टेंट सुपरवाइज़र उसी रूप में हैं जिस प्रकार कि गन्ना विकास विभाग के अन्य कामदार । प्रान्तीय

+ प्रतिलिपि यहां छपी नहीं गई है ।

सर्कार अभी कामदारों के वेतन को दुहराने के लिये विचार कर रही है। पीलीभीत सोसाइटी ने इस आशय में कि कामदारों का वेतन १० रु० मास तक निर्धारित होगा, विचार किया कि इन्स्टिट्यूट सुगर उद्योग ने १० रु० कुल प्रति मास की दर से नियुक्त किया जावे तब अरुण १२/१८—१२/१८ के आग्र-व्यय (वज्रट) में इसकी व्यवस्था की थी।

४३८. श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उक्त इन्स्टिट्यूट सुगरवाइज़रों के ५० रु० मासिक न केवल केवल २५ रु० मासिक दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्यों?

माननीय कृषि सचिव—सोसाइटी के वेतन देने वाले कर्मचारी उसी वेतन के अधिकारी हैं जो कि उक्त उद्योग के मासिक कर्मचारियों के हैं। उनका चुनाव करते समय यह स्पष्ट न किया गया कि यदि मासिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया तो उनका वेतन बढ़ाया जायगा। चूंकि मासिक कामदार २०-३-२५ रु० के स्केल में इस समय वेतन पा रहे हैं, तो वे बहुत दिन से निर्धारित हैं अतः इन्स्टिट्यूट सुगरवाइज़रों के वेतन पा रहे हैं।

४३९. श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह ठीक है कि सुगरवाइज़रों के चपरासी को सुगरवाइज़रों के अधिक दानी २५ रु० मासिक वेतन मिलता है?

माननीय कृषि सचिव—देना नहीं है कि सुगरवाइज़र को उनके पोर्टर से कम वेतन मिलता है। पोर्टर का वेतन २०-३-२५ रु० के स्केल में है क्योंकि वे देहाती क्षेत्रों में काम करते हैं न कि जिला के हेडक्वार्टर पर।

४४०. श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि चीनी मिलों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सरकारी आदेशों द्वारा की गई है?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ!

४४१. श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या यह सच है कि उपरोक्त केन सोसाइटी के कर्मचारी उसी शुगर मिल और उसी शकर उद्योग के लिए काम करते हैं जिसके लिये शुगर मिल में काम करने वाले कर्मचारी करते हैं?

माननीय कृषि सचिव—जी हाँ!

४४२. श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसी शकर कारखाने और उसी शकर उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले उपरोक्त केन सोसाइटी के कर्मचारियों को वही वेतन और वही सुविधायें जो शकर कारखाने वाले कर्मचारियों को सरकार दिलवाती हैं, दिये जाने का प्रबन्ध सरकार की ओर से न होने का क्या कारण है?

माननीय कृषि सचिव—केन सोसाइटियों के कर्मचारियों का वेतन, सोसाइटियों की आय पर निर्भर रहता है। सोसाइटियों की आय सीमित है और उनके कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधायें, जो कि चीनी मिलों द्वारा अपने श्रमिकों तथा विशेषज्ञों को प्रदान की जाती हैं, नहीं दी जा रही हैं। केन कमिशनर ने इस बात की व्यवस्था करने की कोशिश की है कि वे सुविधायें अवश्य ही सोसाइटी के कर्मचारियों की दी जावें जो सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी गई हैं।

श्री सुकुन्द लाल अग्रवाल—जो केन कमिशनर ने सुविधा देने की कोशिश की उसमें कदा तक कामयाबी मिली।

( उत्तर नहीं दिया गया । )

॥४३. श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल—शकर के कारखानों और केन सोसाइटियों के कर्मचारियों को समान वेतन, समान सुविधाएं और समान अधिकार दिये जाने के निषय में सरकार की नीति क्या है ?

माननीय कृषि सचिव—सरकार की नीति तो यह है कि जहां तक मुमकिन हो वेतन बढ़ाया जाय मगर इस नीति के पूरा करने में कठिनाइयां हैं ।

**रुद्रप्रयाग से भीरी तक की सड़क**

॥४४. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय - क्या इस वर्ष रुद्रप्रयाग से भीरी तक यात्रा-काल के पूर्व मोटर सड़क ठीक हो जायगी और जहाँ पर पहाड़ पड़ गया है, टनल बना दी जायगी ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के .सभा-मंत्री ( श्री लताफत हुसैन )—जी नहीं । मय सुरंग के सड़क को पूरा करने में कम से कम दो साल लगेंगे ।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या यह सच है कि सड़क न होने के कारण यात्रियों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है ?

श्री लताफत हुसैन—मुमकिन है ऐसा हो ।

**ज़िला गढ़वाल में अन्न, बीज और शिक्षा का प्रबन्ध**

\* ४५. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सन् १९४८-४९ ई० में गढ़वाल के तीनों तहसीलों को अलग-अलग कितना ग़ुल्ला दिया गया ?

माननीय अन्न सचिव ( श्री चन्द्रभानु गुप्त )—गढ़वाल की तहसीलों में अलग-अलग अप्रैल सन् १९४८ ई० से मार्च १९४९ तक निम्नलिखित मात्रा में सरकारी अन्न वितरण किया गया ।

तहसीलें	मात्रा ( मनों में )
१. लैन्सडाउन	७६६४१
२. बारहस्यो	५९७०
३. चमोली	१०५६७

**ज़िला गढ़वाल की चमोली में गत दो वर्षों में स्थापित सहकारी संस्थाय**

\* ४६. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गढ़वाल ज़िले की चमोली तहसील में कितनी सहकारी संस्थायें गत दो वर्षों में स्थापित हुई हैं और इन संस्थाओं ने किस प्रकार किसानों को सहायता पहुँचाई ?

माननीय उद्योग-सचिव—गढ़वाल ज़िले की चमोली तहसील में अब तक निम्न-लिखित सहकारी संस्थायें खोली गई हैं :—

( १ ) रजिस्ट्री हुए तहसील फेडरेशन की संख्या	....	१
( २ ) रजिस्ट्री हुए सहकारी यूनियनों की संख्या	....	१४
( ३ ) रजिस्ट्री हुयी बहुधन्वी सहकारी समितियों (Multi-purpose Co-operative Societies) की संख्या		६७
( ४ ) विकास ब्लॉकों (Development block) की संख्या ।	....	१५

इन संस्थाओं ने किसानों को निम्नलिखित प्रकार में सहायता पहुँचाई :—

( १ ) यानायात—३००० रु० १० विकास ब्लॉकों को यानायात की उन्नति के लिए २५० रु० प्रति ब्लॉक के हिस्से में दिये गए ।

( २ ) खाद—७६१ मिलवा खाद के गढ़े खोदें और भरे गए ।

( ३ ) विकास—यद्यपि यह कान कृषि-विभाग द्वारा किया जाता है तो भी सहकारी विभाग के फ्रील्ड स्टॉक को पेड़ लगाने के तरीकों और साधनों को उन्नत करने के लिये कहा गया था । रिपोर्टों से सम्बन्धित समय में लगाये गए वृक्षों की संख्या नीचे दी हुयी है :—

( १ ) फलों के वृक्ष	....	४७५
( २ ) ईंधन के वृक्ष	....	२८००
( ३ ) इमारती लकड़ी के वृक्ष	....	२८७५

( ४ ) कपड़े का वितरण—चमोली तहसील में अब तक लाइसेन्सदार फुटकर व्यापारियों द्वारा लगभग २०० गाँठ कपड़ा बाँटा गया है । जिसमें से १,००,००० रु० का कपड़ा नवम्बर, सन् १९४८ ई० की उद्योग प्रदर्शिनी, गौचर, में बेचा गया था, इसके अतिरिक्त मिट्टी का तेल, नमक और दूसरी राशनिंग की वस्तुएँ भी इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं द्वारा बाँटी गई हैं और ३० जून १९४८ ई० तक कुल ७,६१,०४१ रु० की विक्री हुई ।

( ५ ) प्रदर्शिनी—दो उद्योग प्रदर्शिनियाँ ( एक सन् १९४७ ई० में और दूसरी सन् १९४८ ई० में ) रिपोर्ट में सम्बन्धित अवधि के भीतर हुई थीं और १००० रु० गोचर प्रदर्शिनी को दिया गया था ।

#### गुप्तकाशी ( गढ़वाल ) में फलों के बीज के वितरण केन्द्र

॥४७. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गुप्तकाशी ( गढ़वाल ) में फलों के बीज के वितरण करने का केन्द्र स्थापित हुआ है ?

माननीय कृषि सचिव—गुप्तकाशी में फलों के बीज तथा पौध वितरण का केन्द्र खोलने के लिये सरकार ने स्वीकृति दे दी है । जैसे ही कोई उचित स्थान मिलेगा, कार्य आरम्भ कर दिया जायगा ।

#### चमोली तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल और उन्हें सरकारी सहायता

॥४८. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि चमोली तहसील में सन् १९४७-४८ ई० और सन् १९४८-४९ ई० में कितने प्राइमरी लोअर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल हुए और इनको सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता मिली ?

माननीय शिक्षा सचिव—

वर्ष

१९४७-४८

२४ राजकीय प्राइमरी स्कूल

राजकीय सहायता या व्यय

रुपया

२४,०००

१ लोअर सेकेंडरी स्कूल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

२,७५१

१९४८-४९

४० राजकीय प्राइमरी स्कूल

७४,०००

१० लोअर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट, रेकगनाइज्ड

५,०००

### चमोली तहसील गढ़वाल में प्रान्तीय रक्षक दल के केन्द्र

४४६. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि चमोली तहसील (गढ़वाल) में प्रान्तीय रक्षक दल के कितने केन्द्र स्थापित हुए हैं और कितने व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है ?

(ख) क्या नीती के पास में भी इस दल का कोई केन्द्र है ?

(ग) क्या नीती पास के ४३ मील लंबे दर्रे के १५,००० फीट ऊंचे रहने वाले नर-नारियों के रक्षा, शिक्षा का सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

(घ) क्या इस दर्रे वाले अपने रक्षार्थ हथियार रख सकते हैं ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—(क) तहसील चमोली, जिला गढ़वाल, में प्रान्तीय रक्षक दल के चार केन्द्र स्थापित किये गये हैं और १२६० व्यक्तियों को रक्षक दल की शिक्षा दी जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । नीती पास के दर्रे के समीप जोशी मठ में रक्षक दल का केन्द्र है और यहीं से नीतीपास के रहने वालों की रक्षा-शिक्षा का प्रबन्ध करने में सुविधा रहती है और कोई उचित स्थान करीब में नहीं है ।

(घ) जी हां ।

### चमोली तहसील गढ़वाल में विकास योजना के अंतर्गत कार्य

४४७. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—विकास योजना के अन्तर्गत चमोली तहसील गढ़वाल में गत दो वर्षों में क्या कार्य हुआ ? और इस कार्य में कितना व्यय हुआ है ?

माननीय उद्योग सचिव—चमोली तहसील जिला गढ़वाल (पौरी) में सन् १९४७-४८ ई० तथा सन् १९४८-४९ ई० में निम्नलिखित विकास-कार्य किये गये ।

१. गत दो वर्षों में ३१ मार्च सन् १९४९ ई० तक कृषि-विभाग ने ५६० मन बीज, ७३ मन आइल केक्स तथा २६ मन फर्टिलाइजर्स का वितरण किया । इस विभाग ने ३०६ रुपये के सब्जी के बीज भी बेचे तथा १०१६५ पौदों तथा कलमों का वितरण किया । उक्त विभाग ने ८६० रुपये का व्यय पौदों तथा कलमों के लिये राज-सहायता (Subsidy) के रूप में किया तथा कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये १३० रुपये के इनाम भी बाटे । अस्तु गत दो वर्षों में कृषि-विभाग ने ३६,४५० रुपये का कुल खर्चा किया ।

२. पशुपालन विभाग के अन्तर्गत ५००० रुपये तथा १०,००० रुपये का व्यय भेड़ों के फार्म पीपलकोटी और ग्वालडम के लिये क्रमशः किया गया । १४०० रुपये भेड़ों के प्रदर्शन पर व्यय किया गया । ६३७ रुपये का खर्चा पशुओं के प्रदर्शन और प्रदर्शनी पर

किया गया। इसके अतिरिक्त ६०० रुपये सॉइ यंत्रों पर और २४०२ रुपये पशु-सुधार योजना पर व्यय किये गये। इस अवधि में पशुपालन विभाग ने कुल २०,०३६ रुपये का व्यय किया।

३. इन तहसील में उद्योग-विभाग के १० कताई के केन्द्र, १ बुनाई का केन्द्र तथा २ व्युशनल क्लासिज थे जिन पर ५३,००० रुपये का कुल व्यय हुआ। सहयोग विभाग के अन्तर्गत १५ सहकारी संघ, ६७ बहुधनी सहकारी समितियाँ, १ तहसील संघ तथा १५ विकास केन्द्र उद्युक्त समय में इस तहसील में कार्य करते रहे। इसके अतिरिक्त ३००० रुपये और १०० रुपये का व्यय क्रमशः गाँवों के रास्तों के निर्माण और मरम्मत तथा प्रदर्शनियों पर किया गया।

४. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा ५ गाँव, अर्थात् रतुग धानपुर, डुंगरी नारा नागपुर, कंडई गुरादस्यू, भारीखाल कोरिया और अलीमंजारी माला चाँदपुर, के लिये सामान करीदने के निमित्त ६५ हजार रुपया खर्च किया। इन गाँवों में ने डुंगरीमाला, नागपुर और अलीमंजारीमाला, चाँदपुर चमोली तहसील में हैं। क्योंकि प्रत्येक गाँव पर किये गये व्यय का व्योरा नहीं रखा गया है, इस लिये इन दो गाँवों पर जो खर्च हुआ उसका सही व्योरा नहीं दिया जा सकता।

५. शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ३१४०० रुपया प्राइमरी स्कूल खोलने पर खर्च हुआ। इनके अलावा ११ जूनियर हाई स्कूलों पर ७७५१ रुपया खर्च हुआ।

**बनारस तहसील में बाढ़पीड़ितों की सहायता**

४५१. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि अति वृष्टि और गंगा बाढ़ के कारण बनारस तहसील के किन किन ग्रामों को क्षति पहुँची? सरकार ने क्षतिग्रस्त ग्रामों को किस प्रकार सहायता पहुँचाई?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्री चरण सिंह)—बनारस तहसील में अति वृष्टि और गंगा जी की बाढ़ के कारण ८६३ ग्रामों को क्षति पहुँची। हर प्रकार की सहायता शीघ्र ही पहुँचाई गई। बाढ़ पीड़ितों को खाद्य पदार्थ, मिट्टी का तेल तथा दियासलाई और पशुओं के लिये भूसा एवं चारे का प्रबन्ध किया गया। तकाबी के लिये पूरे जिले में २ लाख रुपये की स्वीकृति हुई। दीन-जनों को बीज-तकाबी भी दी गयी। बनारस तहसील के ६० ग्रामों में लगान में ४३,५०० रु० १० आने और मालगुजारी में १२,५३७ रु० ८ आने की छूट दी गयी। अतिवृष्टि एवं बाढ़ के पश्चात् भी पशुओं के लिये कम मूल्य पर चारे की व्यवस्था समस्त क्षेत्र में कर दी गई।

८६३ ग्रामों के नाम की सूची बनाने और छपवाने में सार्वजनिक समय एवं परिश्रम का व्यय उसकी उपयोगिता से अधिक होगा।

**बनारस तहसील में नये स्कूल और उनको सहायता**

४५२. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में बनारस तहसील में कितने प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोले गये और उनको सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई?

श्री महफूजुर्रहमान—सूची प्रस्तुत है।

( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४६ पर )

बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से दूध का क्रय व उसके विक्रय का मूल्य  
 ४५३. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा देहाती किसानों में कितना दूध लिया जाता है व किस भाव में और नागरिकों के हाथ वह दूध किस भाव से बेचा जाता है ?

(ख) सन् १९४७-४८ और १९४८-४९ ई० में इस संस्था को कितना आय व कितना व्यय हुआ ?

(ग) एनिमल हस्वैण्डरी द्वारा कितनी गायें खरीद कर यहां के किसानों को दी गयीं और इसमें कितना व्यय हुआ ?

माननीय उद्योग सचिव—(क) सहकारी संस्था बनारस लगभग ३५ मन दूध प्रति दिन के हिसाब से २६ संस्थाओं से १६ रु० प्रति मन की दर से खरीदती है और विश्वविद्यालय को रियायत पर २० रु० प्रति मन तथा जनता को २५ रु० प्रति मन के हिसाब से बेचती है।

(ख) बनारस मिल्क यूनियन की सन् १९४७-४८ ई० की कुल आय १३, ८६० रु० थी जब कि सम्पूर्ण व्यय ५०,६७६ रु० था इस प्रकार से ३६,८१६ रु० की हानि हुई। किन्तु सम्बन्धित समितियों को ७०,५३३ रु० का लाभ हुआ जो कि मध्यवर्तियों को मिलता अगर सहकारी दुग्ध संघ न होता। सन् १९४८-४९ ई० के अंक अभी अप्राप्त हैं क्योंकि सहकारी वर्ष ३० जून १९४८ को समाप्त हुआ है और आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) बीते हुये दो वर्षों में पशुपालन विभाग ने ३४ गायें खरीद कर बनारस तहसील में तकाबी पर किसानों को बाँटी जिस पर कुल व्यय १०,६८३ रु० का हुआ।

बनारस शहर में निजी बधागार व उनमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या

५४. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बनारस शहर में कितने निजी गाय व भैंसों के मारने के बधागार हैं और जो पशु वहां मारे जाते हैं उनकी म्युनिसिपैलिटी द्वारा डाक्टरी परीक्षा होती है ?

(ख) औसत में इन बधागारों में कितने पशु मारे जाते हैं ?

माननीय स्वशासन सचिव ( श्री आत्माराम गोविन्द खेर )—

(क) केवल भैंसों के मारने के लिये ५ बधागार हैं। बधागार में गायों का मारना बन्द है। म्युनिसिपैलिटी द्वारा उन पशुओं की डाक्टरी परीक्षा नहीं होती है।

(ख) औसतन छः सात सौ प्रति माह

गोशाला के सुप्रबन्ध के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति

\*५५. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गोशाला के सुप्रबन्ध के लिये जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है उसने सन् १९४७-४८ व १९४८-४९ ई० में क्या-क्या कार्य किया और इस अफसर के वेतन, दफ्तर व सफ़र में इन दो वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

माननीय कृषि सचिव—गोशाला डेबलपमेंट अफसर के सन् १९४७-४८ ई० और १९४८-४९ ई० के कामों के बारे में एक छोटा नोट माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

( देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५० पर )

२. गोशाला डेवलपमेंट अफसर और उसके अमले के वेतन और सफरी भत्ते में जो खर्चा हुआ है वह नीचे दिया जाता है।

	१९४७-४८	१९४८-४९
वेतन	३७५० रु० ६ आने	४१९९ रु० २ आने
सफरी भत्ता	३२६३ रु० ४ आने	२८०३ रु० ११ आने
मंहगाई और		
निर्वाह भत्ता	३८१ रु० ६ आने	२३७ रु०

### राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और बनारस के बन्दी

\* ५६. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गत वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आन्दोलन में :—

- ( १ ) कितने पकड़े गये ?
- ( २ ) कितने को सजा मिली ?
- ( ३ ) कितने व्यक्ति माफ़ी माग कर छूटे ?
- ( ४ ) इनके भोजन वस्त्र में कितना व्यय हुआ व जुर्माना में कितना वसूल हुआ ?
- ( ५ ) इन समय अब कितने व्यक्ति जेलों में हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—शायद माननीय सदस्य का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सत्याग्रह आन्दोलन से है जो दिसम्बर ९, सन् १९४८ ई० से शुरू हुआ था। इस आन्दोलन के सिलसिले में जून १५, सन् १९४९ तक।

- ( १ ) ९,५८८ व्यक्ति पकड़े गये।
- ( २ ) ८,०८० व्यक्तियों को सजा हुई।
- ( ३ ) ३,७५६ व्यक्ति माफ़ी, ज़मानत तथा आगाही देकर छोड़े गये।
- ( ४ ) ६,६५,६४१ रु० उनके भोजन वस्त्र में खर्च हुआ व लगभग १,६१, ८१० रु० जुर्माने से वसूल हुआ।
- ( ५ ) जून १५, सन् १९४९ ई० को कुल १७९ व्यक्ति उपर्युक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में जेल में थे।

### सेंट्रल तथा जिला जेलों के सम्बन्ध में पूछ ताछ

\* ५७. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि :—

- ( १ ) बनारस के सेंट्रल व जिला जेल में कितने कैदियों की वार्षिक औसत है और प्रत्येक कैदी के खिलाने में कितना औसत व्यय पड़ता है ?
- ( २ ) इनके निगरानी में कितना व्यय होता है ?
- ( ३ ) जेल के व्यवसाय से कितनी आमदनी होती है ?
- ( ४ ) क्या बनारस सेंट्रल जेल में कपड़ा बिनने के लिये केवल ४३ लूम चालू हैं ?



( ५ ) क्या बनारस सेण्ट्रल जेल से लगी क्ररीब १०० एकड़ उपजाऊ ज़मीन सिचाई का प्रबन्ध न होने के कारण बेकार पड़ी रहती है ?

( ६ ) क्या इस जेल से सिचाई का प्रबन्ध करने के लिये कोई इस्टीमेट आया है, यदि हाँ, तो उस पर क्या हुआ ?

**माननीय मादक-कर सचिव ( श्री गिरधारीलाल )—**

१. बनारस के सेण्ट्रल और जिला जेलों में कैदियों की दैनिक औसत संख्या ६४६ और ५७६ है।

सन् १९४८ ई० में प्रत्येक कैदी को खिलाने का वार्षिक व्यय सेण्ट्रल जेल में १८५ रु० १५ आ० १ पाई था और जिला जेल में १५८ रु० १ आ० था।

२. निगरानी पर सेण्ट्रल जेल में १,१५,६७१ रु० और जिला जेल में ३६,७२७ रु० व्यय होता है।

३. पिछले वर्ष व्यवसाय से सेण्ट्रल जेल में ८३१५ रु० और जिला जेल में १५२ रु० का लाभ हुआ।

४. इस समय बनारस सेण्ट्रल जेल में ४८ करघे चालू हैं।

५. जी हाँ, पर ऐसी भूमि केवल ८० एकड़ है।

६. अभी ऐसा कोई इस्टीमेट सरकार के पास नहीं आया है परन्तु एक इस्टीमेट इन्स्पेक्टर जनरल ने इलेक्ट्रिक इन्स्पेक्टर के पास भेजा है और उनसे यह प्रार्थना की है कि उसकी तुरन्त जाँच के बाद लौटा दें।

**बनारस व गोरखपुर में चने का विक्रय**

\* ५८. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—( क ) बनारस व गोरखपुर के रीजनल फूड कंट्रोलर ने कितने हज़ार मन चना बेचने का टेण्डर माँगा था ?

( ख ) यह चना उक्त अधिकारी को कब व किस कार्य के लिये दिया गया था ?

( ग ) यह चना किस भाव से खरीदा व बेचा गया ?

**माननीय अन्न सचिव—**( क ) सन् १९४७ ई० का ३८३७६ मन चना नीलाम किया गया था।

( ख ) यह स्टॉक अक्टूबर से दिसम्बर १९४८ ई० तक आस्टेरिटी प्राविज़निंग स्कीम के अन्तर्गत बनारस रीजन के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में वितरण के लिये दिया गया था।

( ग ) खरीदने का भाव ८ रु० ३ आना, विक्री का भाव प्रति मन ११ रु० से ११ रु० ४ आना तक था।

\* ५९. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बनारस के कोआपरेटिव फेडरेशन ने लगभग ४,००० मन चना १ रु० का ३ सेर ११ छुटौक के भाव से विश्वेसरगंज के बनिया को गत मास बेचा ?

**माननीय अन्न सचिव—**१९६५ मन ३४ सेर ७ छुटौक चना रुपये का ३ सेर ११ छुटौक के भाव से विश्वेसरगंज के दो व्यापारियों के हाथ बेचा गया था।

### बनारस में बिजली की सप्लाई

६६०. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बनारस की मार्टिन इलेक्ट्रिक कम्पनी के पास सन् १९४६ ई० में कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये व कितने को बिजली दी गई ? इसी प्रकार सन् १९४७-४८ व १९४८-४९ ई० में कितने प्रार्थना-पत्र मिले व कितने को बिजली दी गई ?

(ख) अब तक कितनी अर्जियाँ कम्पनी के दफ्तर में पड़ी हैं ?

(ग) बिजली देने के क्या-क्या नियम हैं ?

श्री लताप्रताप हुसैन—माननीय सदस्य द्वारा मागी हुई सूचना नीचे दी जाती है।

साल	बनारस की मार्टिन इलेक्ट्रिक कम्पनी के पास कनेक्शनों के लिये दी गई कुल अर्जियों की कुल गिनती	दिये गये कनेक्शनों की कुल गिनती
१९४६	३६३३	५१०
१९४७	१७६५	४८२
१९४८	४३७६	७१०
१९४९		
(मार्च ३०, १९४९ तक)	८२२	२८४

(ख) इस समय कम्पनी के पास तक्ररीबन ६००० अर्जियाँ हैं।

(ग) मौजूदा तरीके के मुताबिक रोशनी पंखों या घरेलू मशीनों के लिये मांगी जाने वाली बिजली की दरखास्तों पर बिजली कम्पनियाँ वगैर सरकार को हवाला दिए हुए उसी सिलसिले से कार्यवाही करती हैं। जिस सिलसिले से वे दरखास्तें कम्पनियों को मिलती हैं।

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को नीचे लिखे हुए मामलों में तरजीह (Priority) के साथ बिजली देने के अधिकार दे दिए गए हैं :—

(१) सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं के लिये।

(२) और दूसरी मंजूर शुदा पब्लिक की जमातों के लिये जैसे स्कूल, कालेज, अस्पताल, लाइब्रेरी, दवाखाने, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिर्जाघरों के लिये।

(३) रहने के लिये नई बनी हुई उन इमारतों के लिये जिनसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की राय में मकानों की मांग में कमी होने की उम्मीद हो।

(४) उन जगहों में घरेलू मशीनों के लिये जहाँ रोशनी और पंखों के लिये बिजली पहले से ही मिल रही हो।

इण्डस्ट्री और खेती के कामों के लिये बिजली इण्डस्ट्री विभाग या ऐग्रीकल्चर विभाग की सिफारिश पर मंजूर की जाती है।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या इन प्रार्थना-पत्रों में स्कूल और कालेज भी शामिल हैं ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहिम)—जी हाँ, शामिल हैं।

### बनारस में प्रौढ़ शिक्षा

॥६१. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—बनारस में प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये कितनी पाठशालाएँ कार्य कर रही हैं और इस सम्बन्ध में सन् १९४७—४८ ई० में कितना व्यय हुआ है ?

श्री महफ़्जुर्रमान—बनारस ज़िले में प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये ४५ पाठशालाएँ हैं। इस सम्बन्ध में सन् १९४७—४८ ई० में १४२२२ रु० व्यय हुआ है।

### बनारस शहर में बाढ़ पीड़ा

॥६२. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत वर्ष के बाढ़ में बनारस शहर में कितने मकान गिरे ?

श्री चरण सिंह—गत वर्ष की बाढ़ में बनारस में लगभग एक सहस्र घर गिर गये, दो सहस्र घरों को घोर क्षति पहुँची और लगभग चार सहस्र घरों को अल्प क्षति पहुँची।

॥६३. श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि घसियारी टोला मुहल्ले के कितने मकान गिरे हैं, कितने को सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह—बनारस में घसियारी टोला मुहल्ला में लगभग ५० मकान गिर गये। गीता ज्ञान मन्दिर काशी की ओर से पाँच सहस्र रुपये बाटे गये।

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि बाढ़ में गिरे हुए मकानों के बनाने के लिये सीमेंट वगैरह कंट्रोल रेट्स पर नहीं मिल रही है ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की ज़रूरत है।

### मैनपुरी की सहकारी समितियों में श्वसन तथा चुनाव सम्बन्धी शिकायतें

॥६४. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि ज़िला कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैनपुरी के कुछ सुपरवाइज़र्स या आर्गनाइज़र्स के सन् १९४६—४७ व १९४७—४८ तथा १९४८—४९ ई० के हिसाबों की आडिट रिपोर्टों में गंभीर श्वसन के अभियोग लगाये गये हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ, सन् १९४६—४७ और १९४७—४८ ई० में समितियों के आडिट करने पर कुछ अभियोग प्राप्त हुए थे। सन् १९४८—४९ ई० का एकाउण्ट अभी आडिट नहीं किया गया है अतः उस वर्ष का कोई विवरण प्राप्त नहीं है।

श्री बादशाह गुप्त—यह श्वसन कितने रुपयों का पाया जाता है ?

माननीय उद्योग सचिव—इसके बारे में अभी ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई हजार रुपयों का श्वसन है।

श्री बादशाह गुप्त—यह सन् १९४८—४९ ई० का एकाउण्ट जो आपने कहा है कि अभी तक आडिट नहीं हो पाया है, यह कब तक की रिपोर्ट है ?

माननीय उद्योग सचिव—मैंने तो ५ मार्च तक की बात आप से कही है।

॥६५. श्री बादशाह गुप्त—ये अभियोग किन-किन के विरुद्ध लगाये गये हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—(अ) श्री बाबूराम दीक्षित, सुपरवाइजर महकारी संस्था ।

(ब) श्री विवेकानन्द दूबे, ,, ,, ,,

(स) श्री शिशुपाल सिंह (मृत), ,, ,, ,,

(द) सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के कुछ अस्थाई कर्मचारी ।

\*६६. श्री बादशाह गुप्त—क्या इनमें से किन्हीं के कागजात की जांच पुलिस इन्स्पेक्टर, मैनपुरी के द्वारा भी कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुलिस रिपोर्ट को एक कारी मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हां, रिपोर्ट की कापी जन-सुरक्षा के हित में प्रस्तुत नहीं की जा सकती ।

श्री बादशाह गुप्त—यह पुलिस इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट क्या सरकार ने देखी है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी, हाँ । वह तो देखी जाती है ।

श्री बादशाह गुप्त—क्या इस रिपोर्ट में ग़बन की तारीफ़ होती है ?

माननीय उद्योग सचिव—इसके बारे में सरकार इस वक्त कोई बयान करना मुनासिब नहीं समझती ।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि श्री विवेकानन्द और बाबूरामजी ने अभी तक अपना चार्ज नहीं दिया है ?

माननीय उद्योग सचिव—जवाब में तो यह कहा गया है कि वे मुअत्तिल कर दिये गये हैं ।

श्री बादशाह गुप्त—अभी तक इन लोगों ने अपना-अपना चार्ज दिया है या नहीं ?

माननीय उद्योग सचिव—अभी उन लोगों से जवाब तलब किया गया है और उनमें से कुछ लोग मिलते नहीं हैं और जब तक उनके जवाब न आ जायेंगे तब तक ज़ान्ना की कोई कार्रवाई करने में दिवक्रत है ।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को शत है कि श्री विवेकानन्द मफ़रूर हो गए हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—इसका जवाब तो मैंने अभी दिया है कि कुछ लोग मिल नहीं रहे हैं ।

श्री बादशाह गुप्त—उनकी मफ़रूरी की हालत में और उनका उत्तर या एक्स्प्लेनेशन न मिलने पर सरकार क्या रास्ता अपनाने का इरादा करती है ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार मुनासिब ढंग अख्तियार कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इस मामले में कामयाब हो जायगी । इस मामले में जो अभियुक्त लोग हैं और उनके ऊपर जो अभियोग हैं उन्हें जनहित में यह मुनासिब नहीं है कि भवन के सामने उनका इज़हार किया जाय ।

\*६७. श्री बादशाह गुप्त—इस पुलिस इन्स्पेक्टर के समकालीन ज़िला कोआपरेटिव आफिसर कौन हैं उनकी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में क्या है ?

माननीय उद्योग सचिव—श्री रामबिहारी शुक्ल उस समय डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर थे । उन्होंने श्री बाबूराम दीक्षित और विवेकानन्द पर अभियोग लगाये जिनको मुअत्तल कर दिया गया है । डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि सुपरवाइज़रों ने अपना उत्तर नहीं दिया है ।

४६८. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर, नैनपुरी को कपड़े की रिटेलरी का लाइसेंस सन् १९४८-४९ ई० से मिला हुआ है और वह इस काम को कर भी रहा है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ ।

४६९. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनपुरी में एक राष्ट्रीय सहकारी सघ स्थित है ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ ।

४७०. श्री बादशाह गुप्त—क्या इस संघ के चुनाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत जिला कोआपरेटिव आफिसर, नैनपुरी के पास की गई है ? यदि हाँ, तो यह शिकायत कब की गई ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ । शिकायत जनवरी २६, १९४९ ई० को की गई ।

४७१. श्री बादशाह गुप्त—क्या जिला कोआपरेटिव आफिसर ने उक्त चुनाव के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों के पास भेजी है ? यदि हाँ, तो कब ? क्या सरकार कृपा कर उक्त रिपोर्ट की एक नक़ल मेज़ पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय उद्योग सचिव—जी हाँ, रिपोर्ट ५ मार्च, सन् १९४९ ई० को भेजी गई । रिपोर्ट मेज़ पर नहीं रखी जा सकती क्योंकि यह मामला अभी न्यायालय के आधीन है ।

श्री बादशाह गुप्त—यह मामला किस न्यायालय के बिचाराधीन है ?

माननीय उद्योग सचिव—जो न्यायालय मुनासिब है ।

जिला विकास बोर्ड नैनपुरी तथा उसका खर्चा

४७२. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला विकास बोर्ड नैनपुरी के अध्यक्ष वहाँ के जिलाधीश सन् १९४८-४९ में कब से कब तक रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—मार्च ३१, १९४८ से जनवरी ३०, १९४९ तक ।

४७३. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिलाधीश के बजाय उसने किन सज्जन को उक्त पद पर नियुक्त किया है और यह नियुक्ति कब और क्यों की गई ?

माननीय उद्योग सचिव—श्री दम्मी लाल पांडे, जनवरी ३१, १९४९ से । ये जिला ग्राम सुधार के भूतपूर्व चेयरमैन थे । ये कृषि कार्य और ग्राम-उद्योग में अधिक योग्यता रखते हैं और जिला सुधार क़ार्यों में शुरू से हाथ बटाते रहे । ये नैनपुरी जिले के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं ।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि इन सज्जन की नियुक्ति के पूर्व ही उनके विरुद्ध ऐसे अभियोगों की दरखास्तें आई थीं वह बहुत बीमार रहते हैं और काम करने के लायक नहीं हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—मुझे तो ऐसे अभियोग की सूचना नहीं है और दूसरे बीमारी कोई अभियोग नहीं है ।

श्री बादशाह गुप्त—इस रिपोर्ट का आधार सरकार के पास क्या है कि वह एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव—माननीय सदस्य और उनके साथियों की रिपोर्ट और वही उनकी सनर्पक हैं।

\* ७४. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार निम्नलिखित नक़शे के रूप में बतलाने की कृपा करेगी कि जिला विकास बोर्ड नैनपुरी ने शुरू दिमम्बर सन् १९४८ से आखिरी जनवरी सन् १९४९ ई० तक कितना रक़म किस काम के लिए और किसको दिया है ?

नक़शा

१	२	३	४	५	६
नाम उन सज्जन का जिनको रक़म दिया गया है	उनका पूरा पता	उन में हैंभियन लागत मात्र—गुज़राने आदि सम्बन्धी क्या है	कितना रक़म दिया गया	किस काम के लिये दिया गया	संबंधित सज्जन दलित-वर्ग के हैं या नहीं

माननीय उद्योग सचिव—नक़शा मेम्बर की मेज पर रखा है।

( देखिये नक्की 'ग' आगे पृष्ठ ३५१ पर )

\* ७५—श्री बादशाह गुप्त क्या सरकार ने इस रूपए के बांटने के सम्बन्ध में कोई हिदायत दलित या पिछड़े क़ाओं के पक्ष में दी थी ? यदि हाँ, तो क्या ?

माननीय उद्योग सचिव—जो हाँ। दलित वर्ग को पानी पीने के कुआँ के लिये कुल लागत का आधा हिस्सा सरकारी सहायता के रूप में दिया जाता है। इसी तरह ग़लियों तथा ग्रामों के सड़क, पुलियाँ इत्यादि बनाने में लागत का तिहाई हिस्सा सरकारी अनुदान दिया जाता है किन्तु जिला विकास बोर्ड हरिजन बस्तिया में लागत का आधा हिस्सा तक सरकारी अनुदान के रूप में दे सकता है।

\* ७६. श्री बादशाह गुप्त—इस रुपये की सहायता पाने का प्रार्थना-पत्र देने के लिये जनता को सूचना देने का कौन सा साधन व्यवहार में लाया गया था ?

माननीय उद्योग सचिव—सरकारी अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र भेजने की सूचना ग्राम-सुधार विभाग के ग्राम और सरफ़िल आर्गनाइजर तथा सहकारी विभाग के सुपरवाइजर तथा इन्स्पेक्टरों द्वारा जनता को दी जाती है।

बलरामपुर अस्पताल लखनऊ, के कर्मचारियों की लापरवाही

\* ७७. श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि स्थानीय बलरामपुर अस्पताल में एक जगह अभी नई सुपरिन्टेंडेंट की बनाई गई है ?

माननीय अर्थ सचिव—जी हाँ।

\* ७८. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—इस स्थान पर कौन साहब नियुक्त किये गये हैं ?

माननीय अन्न सचिव—२६-७-४८, से २८-२-४९ तक इस पद पर डाक्टर हरीकृष्ण रस्तोगी ने कार्य किया तत्पश्चात् १ मार्च १९४९ से डाक्टर देवनारायण शर्मा नियुक्त किए गए हैं ।

७९. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—इन सुपरिटेण्डेंट साहब के आने के पश्चात् अब तक कितने मरीज भर्ती हुए और ठीक इनके आने के पहिले उतने ही समय में कितने मरीज भर्ती हुए थे ?

माननीय अन्न सचिव—नये सुपरिटेण्डेंट डाक्टर देवनारायण शर्मा के आने के पश्चात् १-३-४९ से ३१-५-४९ तक ७०८ मरीज अस्पताल में भरती हुए । इनके आने के ठीक पहले १-१२-४८ से २८-२-४९ तक ६६३ रोगी इस अस्पताल में भरती हुए थे ।

८०. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पान सिंह नामक राजनैतिक पीड़ित मरीज की मृत्यु इस अस्पताल में किस प्रकार से हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि पान सिंह के आंतों का आपरेशन सर्जन चोधरी साहब ने किया और आपरेशन करने के पश्चात् दो घंटे तक ठीक उसी हालत में आंत को रख छोड़ा और अपने विद्यार्थियों को उस प्रयोग को समझाते रहे जिसमें उनकी मृत्यु हो गई ?

माननीय अन्न सचिव—यह सूचना मिली है कि पान सिंह राजनैतिक पीड़ित नहीं था । इसकी मृत्यु आपरेशन के ३६ घंटे के पश्चात् हृदय की धड़कन बन्द हो जाने के कारण हुई थी ।

(ख) जी नहीं ! आपरेशन आंतों का नहीं था, जिगर की रसौली निकालने का था । पेट खोलने पर मालूम हुआ कि रसौली मैलाइग्नैन्ट (Malignant) है इस लिए पेट तुरन्त ही बन्द कर दिया गया । इसमें केवल २० मिनट लगे । आपरेशन के बीच में विद्यार्थियों का प्रयोग समझाने वाली बात असत्य है ।

८१. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या यह सही है कि श्री पूरनचन्द राजनैतिक पीड़ित रोगी अल्मोड़ा के रहने वाले इस अस्पताल में एक साल से बीमार हैं ?

माननीय अन्न सचिव—जी हा ।

८२. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या श्री पूरनचन्द ने अस्पताल के प्रबन्ध की शिकायत डाइरेक्टर मेडिकल विभाग के पास भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय अन्न सचिव—जी नहीं । प्रश्न का द्वारा भाग नहीं उठता ।

८३. श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—क्या बलरामपुर अस्पताल के प्रबन्ध और डाक्टरों श्री लापरवाही की दूसरी शिकायतें भी सरकार के पास पहुँची हैं ?

माननीय अन्न सचिव—अभी हाल में दो-तीन शिकायतें आई थी । पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि उनमें कोई तथ्य नहीं था ।

### फैजाबाद के हवालाती कैदी

८४. श्री राजाराम मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस समय फैजाबाद जिला जेल के अन्दर कुल हवालाती कैदियों की संख्या कितनी है ? उनमें से

किनने काविल जमानत अपराधों में और कितने बिला जमानती अपराधों में हवालात में हैं और वे वह कितने समय में रह रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—पहली अप्रैल सन् १९४६ ई० को फैजाबाद जिला जेल में कुल ३५४ हवालाती कैदी थे जिनमें ३४ ऐसे जुर्मों के सम्बन्ध में थे जो जमानत के काविल हैं, शेष बिना जमानती अपराधों के हवालाती थे। कुल अभियुक्तों में से १०१ तीन माह से अधिक हवालात में थे और शेष २५३, तीन माह से कम के थे, सब से पुराना कैदी हवालाती ५-१-४८ में हवालात में है।

सन् ५. श्री राजा राम मिश्र—क्या यह सही है कि हवालाती कैदियों की वृद्धि के सम्बन्ध में विशेष कारण यह है कि अदालतों में उनके मुकदमों बहुत अरसे से चल रहे हैं, मन्तु मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके मुकदमों के जल्दी फैसला किये जाने का उपयुक्त प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह—यह पूर्णतया सही नहीं है कि हवालाती कैदियों की वृद्धि के सम्बन्ध में विशेष कारण यह है कि अदालतों में उनके मुकदमों में बहुत अरसे से चल रहे हैं और मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता है। मुकदमों के मुलजिमों की तादाद में भी काफी वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में हवालातियों की तादाद भी बढ़ी है। मुकदमों में देर होने से भी कुछ बढ़ती हुई है। इस देरी का मुख्य कारण गवाहों के नियत तारीख पर न आने और बहानों की कार्यवाही में सब गवाहों के न आने से अधिक समय लगता है। अभी हाल में सरकार ने मुकदमों को जल्दी फैसला करने के सम्बन्ध में कुछ आदेश जारी किये हैं।

श्री राजाराम मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आज कल गवाहों का नियत समय पर अदालतों में न आने का कारण पुलिस अधिकारियों का मुकदमों पर ध्यान कम देना है ?

श्री चरण सिंह—ऐसी तो कोई वजह नहीं है।

श्री राजाराम मिश्र—तो इसका क्या कोई विशेष कारण है ?

श्री चरण सिंह—एक कारण तो यही है कि पुलिस वालों को यह हिदायत है कि मार पीट कर गवाह पैदा न किये जायें।

श्री राजाराम मिश्र—सरकार ने मुकदमों को जल्द फैसला करने के सम्बन्ध में कानून सा आदेश जारी किया है ?

श्री चरण सिंह—सरकार ने अपने ऊँचे अधिकारियों की एक समिति बनाई है। उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस पर विचार हो रहा है। इसके अलावा ठीक समय पर कौर्ट आने के सम्बन्ध में और इसी क्रिसम के और अहकाम जारी किये गये हैं।

फैजाबाद में मिट्टी के तेल का वितरण

\* ८६. श्री राजाराम मिश्र—(क) क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि फैजाबाद जिले में कुल कितना मिट्टी का तेल आता है ?

(ख) उसमें से कितना देहाती क्षेत्र में और कितना शहरी क्षेत्र में बाँटा जाता है ?



( ग ) क्या यह सही है कि देहात में जो तेल विभिन्न हल्कों में दिया जाता है वह उस हल्के की जन-संख्या के अनुपात से नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया जाता है ?

माननीय अन्न सचिव—( क ) फैजाबाद जिले में प्रति मास ७, ६०० मिट्टी के तेल के पीपे आते हैं ।

( ख ) उनमें से ५, ३०० पीपे देहाती क्षेत्र में और बाकी २, ६०० पीपे शहरी क्षेत्र में बाँटा जाता है ।

( ग ) जी नहीं । देहाती क्षेत्र में बाँटने के लिये जो मिट्टी का तेल विभिन्न हल्कों को दिया जाता है वह जन-संख्या के अनुपात से दिया जाता है । हल्कों का कोटा प्रति परिवार को आधी वोटल प्रति मास के आधार पर है ।

श्री राजाराम मिश्र—क्या देहाती रकबे में और शहरी रकबे में तेल का अनुपात आबादी के हिसाब से लगाया जाता है ?

माननीय अन्न सचिव—जी, नहीं ।

फैजाबाद जिले में चीनी की चोरबाजारी

६८७. श्री राजाराम मिश्र—(क) क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर थाने के अन्दर बवां क्रस्वे के एक चीनी के लाइसेंस की ६ बोरा के लगभग शकर सन् १९४७ ई० में अगस्त या सितम्बर महीने में चोर बाजारी में जाती हुई पकड़ी गयी ?

(ख) उस शकर के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की और सप्लाई मोहकमे ने क्या किया ?

माननीय अन्न सचिव—(क) जी हाँ । ४ जुलाई सन् १९४७ में लगभग ८ बोरी चीनी ३ बैलगाड़ियों से जाते हुये पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी ।

(ख) पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की । इस बीच में चीनी पर से कन्ट्रोल उठ गया और यह भी सन्देह था कि वह चीनी बिकने के लिये जा रही थी । इस कारण जिलाधीश की आज्ञानुसार जो लोग पकड़े गये थे उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया गया । सप्लाई विभाग ने उस दुकानदार का जिसके यहां से वह चीनी जा रही थी, लाइसेंस रद्द कर दिया ।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलायेगी कि आया वह चीनी ज़ब्त कर ली गई या लाइसेंसदार को वापिस कर दी गई ?

माननीय अन्न सचिव—चीनी के बारे में यह शक किया गया कि वह बिकने के लिये जा रही है या वैसे जा रही है । इसलिये वह चीनी छीनी नहीं गई ।

६८८—६०. श्री बलभद्र सिंह—[ स्थगित किये गये । ]

शकर की उपज में कमी

६८९. श्री बशीर अहमद अंसारी—क्या यह सही है कि शकर की पैदावार रोज़-बरोज़ घट रही है ।

माननीय उद्योग सचिव—जी नहीं ।

६९०. श्री बशीर अहमद अंसारी—अगर सही है तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट यह बतायेगी कि सन् १९४६-४७, १९४७-४८ व १९४८-४९ ई० में इसकी पैदावार क्या थी ?

माननीय उद्योग सचिव—प्रश्न उठता ही नहा ।

धामपुर, जिला बिजनौर, के शुगर मिल पर काश्तकारों का कर्जा

ॐ६३. श्री बशीर अहमद अंसारी—(क) क्या सरकार कृपया बतलावेगी कि धामपुर जिला बिजनौर के शुगर मिल पर पिछले साल का कितना कर्जा काश्तकारों का बाकी रहा ? उसमें से कितना दिया गया और अब कितना बाकी है ?

(ख) सन् १९४९ ई० में खरीदारी गन्ने के वक्त से लेकर अब तक कितने का गन्ना खरीदा गया और उसमें से अब कितना रुपया बाकी रहा ?

माननीय उद्योग सचिव—(क) धामपुर मिल पर पहली नवम्बर सन् १९४८ को पिछले साल का ८,४५,५५७ रुपये ६ आने ९ पाई गन्ने के मूल्य के तौर पर काश्तकारों का बाकी था । इसमें से ७,८५,१३५ रु० १५ आ० ९ पाई का भुगतान कर दिया गया है और ६०,४२१ रु० ७ आने बाकी हैं ।

(ख) १९४८ और ४९ के सीजन में मिल ने ३३,६०,०४२ रु० का गन्ना खरीदा जिसमें से ३२,८०,०१० रु० १ आ० का भुगतान कर दिया गया है और ८०,०३१ रु० १५ आ० बाकी है ।

श्री बशीर अहमद अंसारी—मिल वाले जो गन्ना उधार लेते हैं तो ऐसे कब तक चलेगा ?

माननीय उद्योग सचिव—यह तो चलता ही रहता है । केन सोसाइटीज़ के जरिये गन्ना खरीदा जाता है और उनके दाम आमतौर पर दे दिया जाता था । मगर इस वक्त रुपये की कमी के कारण यह बकाया रह गया है ।

ॐ६४. श्री बशीर अहमद अंसारी—क्या सरकार कृपया यह बतलावेगी कि ऐसी कितनी मिलें हैं जिन्होंने १९४८ का रुपया १९४९ में अदा किया है ?

माननीय उद्योग सचिव—लगभग सभी मिलों ने सन् १९४८ के गन्ने की कीमत के बकाया रुपये का भुगतान सन् १९४९ में किया ।

मैनपुरी जिला बोर्ड की सब कमेटियों की समाप्ति

ॐ६५. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन विभाग के दिनांक २३ सितम्बर, सन् १९४८ ई० की विज्ञप्ति संख्या ४०३३/९—५३४/४८ के द्वारा सरकार ने मैनपुरी जिला बोर्ड की किन किन सब—कमेटियों को समाप्त कर दिया था और इस विज्ञप्ति के अनुसार उसकी कार्यकारिणी कमेटी के कौन-कौन सदस्य बहाल रह गये थे ?

माननीय स्वशासन सचिव—विज्ञप्ति संख्या ४०३/९—५३४/४८, दिनांक २३ सितम्बर सन् १९४८ ई० व्यापक प्रभाव की वस्तु थी । किसी बोर्ड विशेष के सम्बन्ध में नहीं । उसके द्वारा पिछली विज्ञप्ति संख्या ३४६८/९—५२४/४८, दिनांक २४ जून, सन् १९४८ का संशोधन किया गया था जिसके फलस्वरूप टिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कार्यकारिणी समिति के उन पाँच सदस्यों की सूची में जो दिनांक २४ जून सन् १९४८ की विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित की गई थी, परिवर्तन किया गया था । पहली विज्ञप्ति द्वारा सरकार ने पाँच कमेटियों की एक सूची इस उद्देश्य से प्रकाशित की थी कि उनके प्रेसीडेंट बोर्ड की कार्यकारिणी

ममिति के सदस्य होंगे। पश्चात् दिनांक २३ सितम्बर सन् १९४८ की विज्ञप्ति द्वारा उक्त सूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये—

१. “जन स्वास्थ्य तथा सफ़ाई कमेटी” का नाम बदलकर “जन स्वास्थ्य कमेटी” कर दिया गया।

२. दो कमेटियों—चिकित्सा कमेटी तथा अर्थ कमेटी को सूची से निकाल दिया गया और उनके स्थान पर दो कमेटियों की नामजदगी बोर्ड की सिफ़ारिश पर छोड़ दी गई। इस विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में उपर्युक्त दो कमेटियों के प्रेसीडेण्टों के अतिरिक्त कार्यकारिणी ममिति के सभी सदस्य यथा पूर्व स्थित रहे।

### वाहन विभाग का राष्ट्रीयकरण

ॴ६६. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार की नीति वाहन विभाग के धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अनुमान में पूरे प्रान्त में इस विभाग के राष्ट्रीयकरण करने में कितने वर्ष लगेंगे?

माननीय पुलिस सचिव—सरकार ने राष्ट्रीयकरण पर अनुसंधान करने के लिये एक ऐडहाक कमेटी बैठाई है जो कि सरकार को सलाह देगी कि राष्ट्रीयकरण को कौन सा रूप दिया जाय और इस योजना की पूर्ति किस प्रकार हो, इस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार यह तै करेगी कि राष्ट्रीयकरण कितने दिनों में पूरा किया जाय।

### मैनपुरी के नोटीफ़ाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व

ॴ६७. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि नोटीफ़ाइड एरिया, गोला बाज़ार, ज़िला मैनपुरी में जनता के चुने हुए कोई सदस्य नहीं होते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव—गोला बाज़ार कोई नोटीफ़ाइड एरिया नहीं है। यदि माननीय सदस्य का मतलब मैनपुरी सिविल स्टेशन से है तो यह बात ठीक है।

ॴ६८. श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की नीति स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत कुल नोटीफ़ाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व देने की है?

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव—जी हाँ।

ॴ६९. श्री बादशाह गुप्त—सरकार गोला बाज़ार नोटीफ़ाइड एरिया तथा अन्य नोटीफ़ाइड एरियाओं की इस कमी को कब दूर करने जा रही है?

माननीय स्वशासन सचिव—सरकार का विचार मैनपुरी सिविल स्टेशन व अन्य ऐसी नोटीफ़ाइड एरियाओं को समीपवर्ती म्यूनिसिपैलिटियों में शीघ्र ही मिला देने का है और ऐसा हो जाने पर इन क्षेत्रों का प्रबन्ध जनता के सदस्य करेंगे।

(प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न दूसरे दिन की कार्यवाही में रख दिये गये।)

सन १९४६ ई० का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल x

माननीय स्पीकर—अब आज कार्यक्रम की दूसरी मद पर अर्थात् माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव और श्री जगन्नाथदास सिंह के संशोधन पर विचार जारी होगा।

❁ श्री निहालुद्दीन—जनाब स्पीकर साहब, पिछली बैठक में मैं उस तरीके के मुताबिक अर्ज कर रहा था जो कांग्रेस वेन्च में और संश्लिष्ट मेम्बरों की तरफ से जमींदारों के मुताबिक और जमींदारी को खत्म करने के मुताबिक इजहार किया गया था। मैंने अर्ज किया था कि हकीकत जमींदारों का खात्मा हो चुका है, हो नहीं रहा है और सिर्फ इस वक्त जो काम है वह उस वाक्या को कानूनी मूरत में लेकर एक तहरीर में कौम के सामने पेश करना है। हम माँके पर जब एक ग्रुप, क्लास या फिर्के का कानूनी खात्मा हो रहा है गाली और बुवाई ने याद करना किसी तरह इस ऐवान की नौअइयत और रुतबे के जो हम लोग बहैसियत मेम्बरान के रखते हैं, मुनासिब और शायाने शान नहीं है। जमींदारी एक वक्त की जरूरत के मातहत पैदा हुई थी। उन्होंने अपने मौके और वक्त के लिहाज से मुल्क और कौम की खिदमत की थी। आज इन सूत्रों में और इस सूत्र के बाहर मुल्क में जो यूनीवर्सिटियाँ और अस्पताल बगैरह हैं वह जमींदारों द्वारा की गयी खिदमत के जिन्दा और जीते जागते नमूने हैं।

बाकी रहा यह कि 'हरू', 'इन्सान' ये लफ्ज जो इस्तेमाल किये जाते हैं, मेरे नज़दीक हर वक्त और हर माँके पर मुस्तलिफ माने रखते हैं और आज की हकीकत अमली दुनिया में ये बेमानी लग्न हैं। इनका अगर बजूद है तो सिर्फ डिक्शनरी और लुगद में है। यह इन्साफ था और कानून के मुताबिक था कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर कब्जा किया। यह इन्साफ था कि मज़बूत और ताकतवर ने कमजोर को अपने मकासिद, अपने कवायद और अपने अगराज के लिये इस्तेमाल किया। यह भी इन्साफ था कि अगर कोई शख्स एक मकान खाली करके सफर के लिये चला गया तो उस मकान का अलाटमेंट कानून के मातहत दूसरे को दे दिया गया। कानून और इन्साफ में यह हमेशा रहा और आज भी है। काश्तकारों ने जो अपना गल्ला और अनाज पैदा किया उसे अनएल्मानिक और और इक्तसादी कीमत में कानून के मातहत लिया गया। यह भी इन्साफ था कि सूरजवंशी और चन्द्रवंशी महाराजाओं के राज्यों पर कब्जा किया गया और यह भी इन्साफ है कि जमींदारी का खात्मा किया गया। इस वक्त जब राय आम्मा इस पर मुतफिक है कि जमींदारों को खत्म किया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि दरिया के बहाव को भग्डू से नहीं रोका जा सकता है। जब राय आम्मा की यह ख्वाहिश है कि हुक्मत के कब्जे में वे तमाम अख्तियारात आयें जो पहले जमींदारों के हाथ में थे तो उसे हकीकी और वाकई समझकर जमींदारों को अपने आप ऐसा करना चाहिये कि मौजूदा निजाम को बरकरार रखते हुये वह जिन्दा रह सकें। यह कहना कि हकूक और इन्साफ के मुताबिक यह ठीक नहीं है, अपने आप को और मुल्क को धोखा देना है। सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि किस तरीके से आर कैसे इस पर अमल किया जा सकता है। मेरे नज़दीक बिल जिस सूरत में पेश किया

x ७ जुलाई को प्रस्तुत किया गया।

❁ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[ श्री निहालुदीन ]

गया है उसमें बहुत कुछ तरमीम की जानी चाहिये और इस तरह से तरमीम की जाय कि कम से कम वे मकामिद और अगराज़ जिनके लिये बिल बनाया गया है पूरा किया जा सके।

द्वितीय के दो टुकड़े हैं। अव्वल, जमींदारी का ख़ात्मा करना और दूसरे एक नये और जदीद इन्तजाम का पैदा करना, जो उन लोगों के हुक्क का एतराज करे और ताययुन करे जिन्हें जर्मन के ऊपर कब्जा और दखल मेरा है। ये दोनों जुज अपनी-अपनी जगह पर अलग हैं। पहला जुज, जमींदारी ख़त्म करने के मुताल्लिक है और वह बक्ती होगा। जैसा कि बर्ज़ार आज़म साहब ने कहा है कि मुमकिन है एक माता में उसका तखमीना हो जाय और यह कानून बेकार हो जाय। दूसरा जुज कानून का है जो दवामी और इस्तमरारी है। ये दोनों कानून मेरे नज़दीक अलग-अलग सूत में आना चाहिये था और सुपेयन और मन्त्रमूस दफात दोनों अलग-अलग होना चाहिये। इन दो मुख्तलिक जुजों को एक ही बिल में पेश किया गया है। इसका नतीजा यह होगा कि कुछ सालों के बाद यह बेकार हो जायेगा और उसके लिये रिपीटिंग (रद्द करने वाला) ऐक्ट लाना पड़ेगा।

दूसरा जुज जैसा कि मैंने अर्ज किया, दवामी और इस्तमरारी है। वह इसमें अलहिदा होना चाहिये। मैंने उन लोगों से, जिन्होंने इसे डाफ्ट किया था या जिनको इसकी वाकफ़ियत थी उनसे मिलकर इस बात की कोशिश की कि यह बिल दिन हालात में डाफ्ट किया गया। मुझे बताया गया कि बावजूद कोशिश के जैसा कि मैंने ऊपर बताया उस तरीके से बिल को डाफ्ट करना मुमकिन न था। मेरे नज़दीक सैलेक्ट कमेटी में जाने पर एक बार और कोशिश की जाय और इस बिल को दो टुकड़ों में लाकर पेश किया जाय। आवज़ैक्टस और रोज़न्स (उद्देश्य और कारण) जो बिल के आद्विर में दिये गये हैं उनमें चन्द मसविदा कानून और पेश करने की ओर इशारा किया गया है एक कर्जे के बारे में और दूसरा दीगर ज़मीनों के मुताल्लिक। मेरे नज़दीक और दोनों जुज अलहिदा अलहिदा आना चाहिये और यह भी किया जाय कि जो बिल और आने वाले हैं उनको भी इसके साथ सैलेक्ट कमेटी के सामने रक्खा जाय। जहाँ तक बिल के टेक्निक (कला) का सवाल है उसके दो जुज होते हैं एक हुक्क के तय्युन की तारीफ़ का जिसे सबस्टेन्टिव लॉ (अलहिदा कानून) कहते हैं और दूसरा हुक्क के निज़ाज़ का जिसे प्रासीजरल लॉ कहते हैं। बिल के अन्दर ज़रूर यह कोशिश की गई है कि सबस्टेन्टिव लॉ ऐक्ट की सूत में इस भवन के सामने पेश किया जाय। जहाँ तक प्रासीजर और जाबते का ताल्लुक है बिल में इस तरह की दफात दी गई हैं कि कायदे गवर्न-मेन्ट बाद को बनायेगी और उन्हीं रूल्स के मातहत उन हुक्क का फैसला हो जो इस ऐक्ट के मातहत पैदा हों। मुझे हमेशा इस पर एतराज़ है कि इस किसम के अख्तियारात ऐक्ज़ी-क्यूटिव (कार्य-कारिणी) या ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रबंध कारिणी) को दिये जायें। यह जायज़ है किमी लेजिस्लेचर का ही है कि वह सबस्टेन्टिव लॉ बनाये। यह ज़रूर है कि ऐक्ट के आखिर की दफात में यह दिया गया है कि रूल्स जो ऐक्ज़ीक्यूटिव बनायें या कैबिनेट या उसके मातहत अकसर लोग बनायें वे इस भवन के सामने बगरज़ गोर के रखे जावेंगे। यह चीज़ दूसरी है और कानून का बनाना दूसरा। इसके मानी यह है कि अख्तियारात कैबिनेट या ऐक्ज़ीक्यूटिव को होंगे लेकिन जिम्मेदारी हमारे कंधे पर रखने के लिये वह हमारे सामने

यह कह देंगे कि मैंने इससे भी बड़ा दुःख भोगा है। एक यह कि जहाँ तक इन्स्ट्रिग का सम्बन्ध है यह दो दुःखों में बदलते सामने आना चाहिये। दूसरा यह कि कलून बनाने के कुछ अविद्यमान इन भयानक होने चाहिये।

अब वहाँ दून दान जो इन जेज के मुताबिक नहीं है वह असरात और पालिसी की है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया जर्मनदारी एतना ता की जाय लेकिन इसलिये नहीं कि यह हक और इन्फान्ट है लेकिन इसलिये कि वह पवान और तनाम मुल्क की इवाइश है कि जर्मनदारी एतना की जाय जिस लिहाज इनके जिते कि उसके असरात क्या होंगे। वहाँ यह दान नहीं है जो इनके यह दान कर जितना जनादारी को इक्वाटेबिल कम्पेन्सेशन (उच्चिद मुद्राविज्ञा) दिया जाय। अब समाप्त यह है कि कम्पेन्सेशन जिते इक्वाटेबिल कहा जाता है और के तब करेगे कि वह इक्विटेबिल है भी कि नहीं। जर्मन वहाँ आज्ञा से जर्मन का कि इक्विटी कितनी मुअइयन कानून के मातहत नहीं है। मैं उन्हें कहूँगा कि जब वह लार्ड इलाइन का जमाना नहीं है जब इक्विटी बदलता रहता था। इक्विटी (अंतर्वित्त) के जो प्रिन्सिपल (निदान) है वह न सिर्फ इस मूया में बल्कि हर एक मूया में बतान के साथ तत्काल किये जा सकते हैं। इक्विटेबिल कम्पेन्से न क्या है उसके जिते इस दूरे में खुद कवानीन मानूँ ह। लैंड ऐक्वाजोरान के मातहत जब जर्मन लो जायों है ता उसके जिते एक स्टैंडर्ड मानूँ ह और वही इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन कहा जाता है। इन निजार्त में जो मुद्रातत्किक केनेज हाईकोर्ट में पहुँचे और उनमें जो तय किया गया वह है कि उस चोज को, कि जो गवर्नमेंट अक्वायर करे जिता नरजो मातिक को, वह क्लोनत होनी चाहिये जो बाजारी क्लोनत हो या यूटिलिटी या तबर्क के लिहाज से जो उसको क्लोनत वअइयन हो। बाकी उसके ऊपर १५ फ्रीसदी उस क्लोनत के और मुद्रावज्ञा दिया जाता है। अब क्या इक्वाटेबिल कम्पेन्सेशन होगा उसके मुताबिक मेर नज़दोक्त सिजेक्ट कमेटी में और इस भवन में तर्मीम करना पड़ेगा। तर्मीन इस बुनियाद पर करना पड़ेगा कि इक्वाटेबिल कम्पेन्सेशन वह मुद्राविज्ञा है जो बाजारी क्लोनत उस जायदाद को जो ला जा रहा हो मुकर्रर को जाय खवाह बाज जगह वह २४ गुना होगी कहीं ३३ गुना होगा और कहीं २२ गुना होगी। इसका नियार कि इक्वाटेबिल क्लोनत एक जायदाद को क्या है इंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के शेड्यूल में आपका जगह वजगह मिलेगी लेकिन वह इस काबिल नहीं है कि उसको आप कुलियतन तसलीम कर लें। क्योंकि वह क्लोनत उस जमाने में मुकर्रर को गयी थी जब सिके की तब्दोजी और सिके का नियार उसने मुख्तलिफ था जा इस वक्त है। मगर रहयरा और हिदायत के लिए इंकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट सुकंद और कागानद हो सक्ता है। विल के अन्दर चन्द वइएन नुक्स और मानूँ है निजार्त के तार में चरिटेबिल इंडोन्ट खवाह वह वक्त हों या हिन्दू एंडोमेंट्स हों उसके मुताबिक दफात निहायत सुवहन, गर बाजिव और किसी उसूल के मातहत नहीं हैं। इसके बाद विल में कुछ इन्तकाल जो एक तारीख मुअइयन से हो चुके हैं उन्हें नाजायज करार दिया गया है। या खरीदार को विल के आने के वक्त या इससे पहले मालूम नहीं था मैं जो अपना रुपया जायदाद पर लगा रहा हूँ, वह बयककलम और बयककलम बेकार हो जायगा। फर्ज कीजिये क्लिमी ने एक लाख रुपये की जायदाद खरीदी।

[ श्री निहालुद्दीन ]

यह हक किसी तरह सूबे की सरकार को पैदा नहीं होता कि वह जायदाद और उसके मुआहिदे को अदम कानूनी करार दे। मेरे नज़दीक सिलेक्ट कमेटी से इन दफ़्तात को आप को निकालना पड़ेगा। अगर आप ने नहीं निकाला तो वह आदमी जिसकी खता और कसूर सिर्फ़ यह है कि जब जमींदारों से आम बेजारी और नाराजगी है तो वह जमींदार बन गया। उसने एक जायदाद खरीद ली। इसके बाद बिल के अन्दर दफ़्तात इस किस्म की रखी है जिस में जमींदारी यह बिल आइन्दा ऐक्ट बन कर खत्म कर रहा है। उसे वह जमीन जो रहनदारों या ठेकेदारों के कब्जे में है वह वापस हो सकती है यह निहायत महदूद की जाती है मेरे नज़दीक यह दफ़्तात तर्मीम करना पड़ेगी। जो जमीने रहनदार या ठेकेदार के कब्जे में है, उसमें अगर कोई खुदकाशत या सीर है तो कुल जमीन वापस मिलना चाहिये। और कम से कम एक मोका उसे यह हो कि वह खुद अपनी काशत कर सके। इन अलफ़ाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र किया जाय और पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट न किया जाय।

श्री अलगूराय शास्त्री—नाननीय स्पीकर महोदय, जो प्रस्ताव प्रधान मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है कि यह बिल प्रवर समिति के सामने भेजा जाय मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। श्री राजा जगन्नाथबक्श सिंह जी ने यह संशोधन किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रकाशित और वितरित किया जाय। मैं उसका विरोध करता हूँ। जितने वादे कांग्रेस ने इस देश के किसानों के सामने किये, जितना पानी गंगा में अब तक बहा गया है, इस प्रश्न पर उसको देखते हुए इस पर कार्य करने में कोई विलम्ब न होना चाहिए। मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ जब मेरे मित्र फ़ख़रुल इस्लाम साहब ने यह कहा कि जो जॉच समिति की रिपोर्ट है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाय। जो इस पर धन खर्च किया गया और जो परिश्रम किया गया, वह सब बेकार हुआ। मुझे हैरानी हुई कि किस तरह एक आदमी थोड़ा भी न्याय और बुद्धि रखनेवाला ऐसी बात कर सकता है। जॉच समिति की रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी जाय तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। मैं बिला किसी अतिशयोक्ति, मुबालगे और इक्ज़ेजेशन के कह सकता हूँ कि इसको कृषक और उसकी समस्याओं का विश्वकोष कहा जा सकता है। जितनी बातें किसानों के सम्बन्ध की हैं और उसकी जो प्राबलेम हैं उनका इसमें उल्लेख है इसे किसानों की एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। जितनी मेहनत की गई है और जितने आँकड़े इसमें रखे गये हैं जितनी जानकारी एक विद्यार्थी को इन समस्याओं के सम्बन्ध में कहीं एक जगह आसानी के साथ मिल सकती है वह सब जानकारी जिस पुस्तक के अन्दर उपलब्ध होती है, उसके सम्बन्ध में भवन के एक प्रतिष्ठित सदस्य का ऐसा कहना कोई तर्क की बात नहीं है। हम एक चीज़ का विरोध करते हैं तो उसमें दोष ही देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र का इसको ऐसा कहना ठीक नहीं है।

उस रिपोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है और यदि मैं कह सकूँ तो यह कहना चाहूँगा, जैसा हम पढ़ते हैं कि ६२० ई० में सोलन ने अपने रिफ़ार्म के सम्बन्ध में कहा था, आज उसी के शब्दों को हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री और हमारी जॉच समिति ने अपनी रिपोर्ट में घोषित किया है। सोलन ने क्या कहा था १ वे शब्द ये हैं।

Those who on this earth suffered cruel servitude and trembled before a master, them have I set free.

(इस धरा पर जिन्होंने कठोर अन्याचार सहे हैं, जो अपने स्वामी के सामने काँप उठने थे, उन्हें मैंने स्वतंत्र और बन्धन मुक्त किया है।)

उसने कहा था। यह परिस्थिति थी पुराने ग्रीस और रोम की जहाँ की जनता पर मम्भ्रान्त परिवार के लोग शासन करते थे। उनके हाथ में सारी ज़मीनें थी, सर्क और स्लेवज उनके खेतों में काम करते थे। उनके लिये सुधार की आवश्यकता आई, क्रान्तियाँ हुई, रक्त क्रान्तियाँ हुई। उन क्रान्तियों में लोगों के सर कटते थे। उन क्रान्तियों और विद्रोहों के परिणाम पर ६२० में सोलन ने जो कहा था आज हमारे प्रधान मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने उन्हीं शब्दों को गर्व के साथ विनय के भाव से कहा। यदि उस कान को देखा जाय तो उसने भी वही ध्वनि निकलती है कि जो सदियों गुलाम रहे हैं, जिनके खेत बेरहमी से बेदखल कराए गये हैं, जो अपने जानवरों के लिये एक नाद गाड़ने पर भी पीटे जाते थे, जो एक पेंड लगाने पर भी अपने खेतों से बेदखल कर दिये जाते थे, त्वास करके अवध में, आज वही आज़ाद होने जा रहे हैं। अब उनके वहाँ जमीन्दार के कारिन्दे मालगुजारी वसूल करने के लिये जाकर ज़्यादती नहीं करेंगे। एथेन्स और स्पार्टा की बात वहाँ पर नहीं होने पावेगी। वहाँ पर मज़दूर जब जमीन्दारों के सामने जाते थे तो काँप जाते थे और नृशंसता और निर्दयता और दासता का जीवन व्यतीत करते थे। वहाँ पर ऐसे कितने थे जिनको आज़ादी मिली थी। स्पार्टा में दो लाख पचास हजार सर्क और स्लेवज थे। वे वहाँ के बड़े बड़े ज़मीन्दारों के खेतों पर जाकर काम करते थे। केवल दो लाख पचास हजार आदिमियों को ही वहाँ आज़ादी मिली थी लेकिन हमारे यहाँ जिनको आज़ादी मिलने जा रही है उनकी तादाद ५, ६ करोड़ की आबादी में ८४ प्रीसदी है। हमारे सूबे की इतनी ज़्यादा तादाद है जो ग्रीस और रोम के आबादी की तीन गुनी चौगुनी तक हो जाती है। इतने ज़्यादा लोगों को हम आज आज़ाद करने जा रहे हैं और वह भी विनयपूर्वक। महीनों के मेहनत के बाद आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आँकड़े आपके सामने हैं। सब कुछ होते हुए भी आप कहते हैं कि इसकी क्या कीमत है इसको रद्दी की टोकरी में डाल दो। मैंने एक किताब में पढ़ा है मुर्गों के सामने मोती डालने से क्या फायदा। इसके सामने ज्वार दो। मुर्गों के सामने मोती बिखेर देने से उसका मूल्य वह नहीं आँक सकता है, उसके लिये उसका कोई मूल्य नहीं है। 'कहा मयो दिनकर विभव, देख्यो जो न उलूक।' वही हालत आपकी भी है। सोलन के शब्दों में हमने उन्हीं को आज़ाद किया है जो सदियों से गुलाम थे, परेशान थे। इस बिल में उनकी आज़ादी घोषित की गई है जो दूसरों के हल जोतते थे। इस बिल में उनको स्वतंत्र बनाया गया है जो दूसरों के पानी भरते रहे हैं। इस बिल में उनको अधिकार दिया गया है जिन्होंने सदियों से अपनी आज़ादी को समझा नहीं था। जो हरी बेगारी और दुनिया भर के अत्याचारों से त्रस्त और पीड़ित थे उनके बन्धन को खोल दिया गया है और उस बन्धन के खोलने की सारी घोषणा इस जॉच समिति की रिपोर्ट में आ गई है। जॉच समिति की रिपोर्ट ऐतिहासिक विकास क्रम से आई है, एकाएक नहीं आई है। किसानों



[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

की समस्या एक जटिल समस्या इस देश में रहो है। उसके लिये नारे लगते थे। खेती सत्याग्रह हुआ, चम्पारन और मुजफ्फरपुर के किसानों की जो दुर्गति थी उसके लिये सत्याग्रह हुआ।

सन् १९२० में गांधी जी का आन्दोलन चला, अबध के इलाके में बादा रामचन्द्र का आन्दोलन चला और आपको मालूम है कि सन् १९३०-३१ के आन्दोलन के बाद इलाहाबाद में करवन्दी का आन्दोलन चला जिसके संचालक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन और टी० ए० के० शेरवानी इनकी अरेस्ट्स हुईं। इन आन्दोलनों में हम किसानों को आजाद कराने के लिये बार-बार घोषणा किया करते थे। कांग्रेस की अग्रेरियन कमेटी मुक़र्रर हुई। उसने जांच की और किसानों की समस्याओं को देखा। लार्ड लिनलिथगो का ऐग्रीकलचर कमीशन बैठा। उसने किसानों की समस्याओं की जांच की। उसने देखा कि यहां के किसान दरिद्र हैं और ऋण से तबाह हैं। होर्लिंडज छोटी-छोटी हैं। कमाते किसान हैं और खाते दूसरे हैं। इन सारी समस्याओं को हमने देखा और देश की मांग थी कि उन समस्याओं को हम हल करें। हमारे कुछ भाइयों ने, मैंने देखा जिनमें बेगम एजाज रसूल साहिबा भी हैं, रिपोर्ट से अपनी असहमति प्रकट की। माननीय लारी साहब ने अपनी असहमति प्रकट की है। मैं देखता हूं कि एक ही चीज बराबर उन दोनों के दिमाग में काम कर रही है। वे दोनों ही एक ओर से इस बात को समझते हैं कि केवल राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर ही यह सारा का सारा बिल हमारे सामने पेश हुआ है। यह बेगम एजाज रसूल साहिबा का खास तौर से ख्याल है कि जमींदार तबके को कांग्रेस के लोग गद्दार मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं और यह समझ कर ही यह बिल पेश किया गया है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का कोई भी समझदार आदमी इस भावना से प्रेरित होकर इस काम को कर रहा है। हम इतिहास के साथ विश्वासघात करेंगे यदि हम यह समझें कि हम इस भावना को जमींदारों के प्रति अपने हृदय में रखेंगे कि चाहे छोटा हो या बड़ा सब के सब जमींदार देशद्रोही रहे हैं। जिन्होंने मिसेज एनी बेसेण्ट की 'हाउ इण्डिया फ़ाट फार फ्रीडम (भारतवर्ष ने कैसे अपनी स्वाधीनता का संग्राम चलाया)' नामक पुस्तक या पटामि सीतारमैया का कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है वह यह जानते हैं कि सन् १८८४ में अद्वार में कांग्रेस का जन्म हुआ जहां ७२ आदमी इकट्ठे हुये थे। इन ७२ आदमियों के एकत्र होने का फल था कि कांग्रेस का जन्म हुआ। यह वही कांग्रेस थी जिसने विदेशी हुकूमत से लोहा लिया जो अपने साठ हजारों खराबियां लेकर आई थी, रोमन साम्राज्य से जिसने साम्राज्यवादी प्रथा को सीखा था और जिसने आकर वह बला हमारे मत्थे मढ़ दी थी उस हुकूमत से यहाँ के लोग परेशान हो उठे। सन् १८८५ की कांग्रेस वही कांग्रेस थी जो अजीमुशान बनी। अद्वार नदी के किनारे जो कांग्रेस एक छोटी नदी के समान थी वह कांग्रेस बम्बई में आकर विशाल सागर की तरह फैल गई कि अंग्रेजों के होशहवाश उड़ने लगे कि न जाने यह जनसंस्था क्या कर देगी? उसी वक्त से उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश हुई। तीसरा सेशन इलाहाबाद में होने वाला था और तत्कालीन गवर्नर ने अड़ंगे लगाये और कोई जमीन कांग्रेस सेशन

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३०१

करने के लिये नहीं मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त में अवध के एक ताल्लुकेदार थे जिन्होंने कंग्रेस अधिवेशन के लिये जमीन दी थी उस हुकूमत को मिटाने के लिये जिसने नवाब वाजिदअली शाह को तबाह किया था जिन्होंने सिराजुद्दौला को तबाह किया था और जिन्होंने हमारे टोपू नुत्तान को तबाह किया था, जिस हुकूमत ने वे ब्रह्म यह दगा देने थे उसका मिटाने के लिये अवध के ही एक ताल्लुकेदार ने जमीन दी थी। उस जमीन का कोई जरा नहीं था जो तैयार न हो कि इस हुकूमत को खत्म किया जाय। तो यह देशद्रोह की बात कैसे हो सकती है। स्वार्थ की बात तो हो सकती है। यदि मुझे आज पांच सौ रुपये मिलते हैं तो मुझे ६ सौ रुपये चाहिये। सभी अपने वर्गस्वार्थों के लिये लड़ते हैं। वर्गस्वार्थों की लड़ाई हमेशा संसार में रही है। इनमाहवजोपीडिया प्रिटेनिका में अमेरिकन मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ने में पता चलता है कि किस तरह से अमेरिकन मूवमेंट वर्ल्ड भर में चला है? आप आयरलैंड का अमेरिकन मूवमेंट पढ़ लें। आयरलैंड में अमेरिकन मूवमेंट की शक्ल यह थी कि अर्मर आदमी अपने पैसों के बल पर गरीब किसानों की जमीन ले लेना चाहते थे। खूनी क्रूरता हुई। यह तो एक शक्ल थी अमेरिकन मूवमेंट की और दूसरी तरफ सुदखोर जमीन को किसानों से ले लेना चाहते थे। तुर्किस्तान और खुर्दिस्तान में जो अमेरिकन मूवमेंट की शक्ल थी वह यह थी कि वहां सुदखोर किसानों की जमीन छीन लेना चाहते थे। आर्मीनियों के विरुद्ध खुर्दिस्तान में और तुर्किस्तान के किसान लोग लड़े और वहां के आन्दोलन को चलाया। यह आन्दोलन इस्लामी शरियत में मूद के विरुद्ध जो भावना है उसके शरण एक धार्मिक आन्दोलन बन गया था। अमेरिका में जो अमेरिकन ट्यूबल हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि वहां जो टैक्सेशन लगने जा रहा था, उस टैक्सेशन की पालिसी किसानों के खिलाफ पड़ती थी। उसका लाभ वहां के पूँजीपतियों को पहुँचता था। इसलिये वहां के किसानों ने उसकी मुखाफत की थी। सन् १९३६ ई० में अमेरिका के व्यापारियों का एक कमीशन कायम हुआ कि किस तरह से ऐग्रीकलचरल रिफार्म किये जाय और किस तरह से भुगड़े कम हो। अगर आज हम २५ रुपया मालगुजारी वाले जमींदार को भी मिटाना चाहते हैं तो उसकी वजह यही है कि वह प्रया नाकिस है और उसके अन्दर दोष भरे हुए है चाहे बरैइया छोटी ही हो लेकिन डंक उसके अन्दर भी रहता है और उस जहर को मिटाना लाजिमी है। उस जहर को हम बिलकुल ही खत्म करना चाहते हैं। अगर साप का बच्चा कितना ही छोटा हो लेकिन उसके अन्दर विष भरा रहता है। उसमें सोशल इन्टरेस्ट नहीं रहता है। जमींदारी से सोसाइटी को कोई लाभ नहीं पहुँचता है। उसका एक वेस्टेड इन्टरेस्ट रहता है उसकी वजह से वह एक निग्रोपेन की शक्ल हासिल करती है जिसके जरिये से फिर मुसीबत पैदा हो सकती है। यही वजह है कि जिससे हम इसको मिटाना चाहते हैं चाहे वह कोई छोटा जमींदार हो या कोई बड़ा जमींदार हो। चाहे कोई २५ रुपये का मालगुजार ही क्यों न हो किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे देशद्रोही हैं। छोटे छोटे जमींदारों के गाज़ीपुर, बलिया और आजमगढ़ में हजारों और सैकड़ों गाँव जला दिये गये। १८५७ में हमारे यहाँ की ठाकुरों की जायदाद दुबारी और लोहरा में ज़ब्त की गई यह सब देशद्रोही नहीं थे। यह सब उच्च कोटि के देश मत्त थे। मैं बंगम एजाज रसूल को यकीन

[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

दिलाना चाहता हूँ कि आज जो यह बिल लाया गया है यह इसलिये नहीं लाया गया है कि हमारे दिल में कोई किसी तरह का बुग़ज़ है। आप के किसी आदमी ने हमारे खिलाफ़ गवाही दी या किसी कमिश्नर से मिल कर कुछ और खिलाफ़ कार्यवाही करा दी इस लिये हम यह कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत बात है। हम उन सब बातों को नज़रअन्दाज़ करते हैं। हमारे आन्दोलनों की मुखालफ़त की गई और भी बहुत तरह से हमारी मुखालफ़त की गई लेकिन हम किसी बात को भी लेकर ज़मोंदारी को मिटाने नहीं जा रहे हैं और न हमारे दिल में कोई किसी तरह का द्वेष है। चूँकि यह तो अमीर और गरीब का सर्वाल है और सदियों से करोड़ों आदमी गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे थे हम उनको इस गुलामी की जिन्दगी से निकालना चाहते हैं और सोसाइटी का इन्तजाम ठीक तरह से करना चाहते हैं। पहले जमाने में हम यह जानते हैं कि ज़मींदारों ने जो भी किया वह एक विशेष परिस्थिति के अन्दर ही ऐसा किया। इसलिये आपको देशद्रोह करार देकर हम यह कानून बनाने नहीं जा रहे हैं। अगर लारी साहब के या बेगम साहब के दिल में कोई इस तरह की बात हो तो वह फिज़ूल सी चीज़ है। लारी साहब की बात तो मैं राजनीति की मान सकता हूँ लेकिन बेगम साहब को मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे दिल में किसी तरह का कोई बुग़ज़ नहीं है। गान्धी जी दुनियां से चले गये लेकिन उनके आइडिया आज भी हमारे सामने हैं और उन आइडियाज़ पर बराबर चलने की कोशिश करते आये हैं। हम आज जो कुछ भी करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं उसका आधार जस्टिस है, इक्विटी है और न्याय है। और उससे प्रजा का हित होता है, हम यह जानते हैं कि जिसका आधार सत्यता पर नहीं होता है वह चीज़ चल नहीं सकती। हम जो कुछ भी आज करने जा रहे हैं वह जनता के लाभ के लिये है किसी एक आदमी का लाभ उसके अन्दर नहीं है। “त्यजेदेकं कुलस्यार्थे”, यह उसूल हमारे सामने है। किसी एक के फायदे के लिये हम यह नहीं कर रहे हैं। हम तो एक आदमी के इण्टरेस्ट से इस चीज़ को हटाकर पूरे गाँव की सेवा करना चाहते हैं। यक़ीनन हम पूरे गाँव का इण्टरेस्ट देखते हैं किसी एक इंडिविजुअल का इण्टरेस्ट हम नहीं देख रहे हैं और अगर गाँव का इण्टरेस्ट हटा कर हम पूरे सूबे और जिले का इण्टरेस्ट कर सकते हैं तो उसको कर देंगे, और अगर एक पूरे सूबे को कुर्बान कर सकते हैं मुल्क के लिये तो कर देंगे। इससे कौमें जिन्दा रहती हैं। अंग्रेजों ने जो हमारे मुल्क के साथ किया वह इस वजह से कि उनके सामने कम्युनिटी लाइफ़ थी, लार्जर इण्टरेस्ट था। तो आया हम लार्जर इण्टरेस्ट में करने जा रहे हैं या नहीं, इसको अनालाइज़ करना होगा। इसकी तरफ़ आप तवज़ह करें। आंकड़े हमने देखे कि १.६६ प्रतिशत जिनकी आबादी इस सूबे में है उनके पास ५७.७७ प्रतिशत जमीन पड़ी हुई है और ‘बाकी लोगों’ के पास ४३.२३ प्रतिशत ! मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी समझ में मुनासिब मालूम होता है कि जो यह डिक्लेअर्ड पालिसी है, दुनिया के सब अर्थशास्त्रियों ने यह बात एक स्वर से मानी है कि लैंड इज़ दि सोर्स आव आल वैल्थ, ज़मीन सारी सम्पत्तियों की आधार है। यह संसार भर के अर्थशास्त्रियों ने और राजनीतिज्ञों ने माना है। मेरे भाई विश्वम्भर दयाल जी मुझे याद दिला रहे हैं कि “रत्न गर्भा वसुन्धरा”। यह भूमि

गन्ना को धारण करने वाली है। बसुधा, वसु सारे प्रकारकी सम्पत्ति-धन का नाम है। जिस भूमि का यह रूप है, जो सोर्स आव आल बैल्थ है, आप समझते हैं कि वह किसी इंडिविजुअल की जायदाद बना दी जाय ? किसी व्यक्ति विशेष की जायदाद बना दी जाय कि जिसमें सारी सम्पत्ति पैदा होती है ? जिसमें खेत हैं, पानी है, पानी में कमल है, पानी के बीच में मछली हैं। जितने उद्योग धंधे हैं सारे जमीन पर आश्रित हैं। बड़ी बड़ी मिलें जमीन की छाती पर खड़ी होती हैं। अगर लकड़ी का कारखाना है तो जमीन पर ही रख कर आर से लकड़ी चीरी जाती है। यदि जूट का कारखाना है तो खेतों से ही जूट वहां जाता है। इसी प्रकार कपास और सब चीजें तो खेत से ही जाती हैं। तो आखिरश जो सब चीजों की मां है जिस पर सारी प्रजा आश्रित है, अवलम्बित है वह किमी एक की जायदाद कैसे हो सकती है ? “न अस्माकं ज्येष्ठा सो न कनिष्ठा रुद्रः पिता अदितिर्माता” ऋग्वेद में इतने वेदमन्त्र मिलते हैं, हम में न कोई लहुरा है, न जेठा है, न कोई बड़ा है न छोटा है।” इस्लामी मसावियात की तो आप खूब दाद देते हैं, जरा इस मसावियात को भी देख लीजिये। ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो संसार में मिलती है लिखी हुई, वह ऋग्वेद है, वह इसका परिचय देता है “न अस्माकं ज्येष्ठा सो न कनिष्ठा सः रुद्रः पिता अदितिर्माता” सारी मानवता में न कोई छोटा है, न बड़ा। यह बड़े-बड़े ताल्लुकेदार, यह अदना अकवाम, जो आपने भेद बनाये हैं यह ईश्वर के बनाये हुये नहीं हैं, यह आदमी के बनाये हुये हैं। इनको न मिटाया जाय ? एक तरफ तो धी की गगरी ढरक रही हो और दूसरी तरफ होली और दीवाली के त्योहार भी सूने ही रह जाय ! इसमें शक नहीं हो सकता है कि यह जो स्ट्रगिल है, एकानामिक स्ट्रगिल लेबर स्ट्रगिल की बातें तो राजा-राम बताते हैं। मैं क्या कहूँ स्पीकर साहब, राजाराम पहले बोल लिये होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो अग्रेयियन मूवमेंट की जो शक्ल मैंने बताई वह इस वजह से कि लड़ाई है। लेबर मूवमेंट में यह चीज बहुत सफाई से दिखलाई जाती है मार्क्स ने बतलाया कि यह स्ट्रगिल और भगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि लेबर, जो श्रमिक है वह मेहनत करता है। मेहनत का जो घंटा है उसके दो हिस्से होते हैं। अगर एक रेखा ‘अ’ से लेकर ‘स’ तक खींच दी जाय तो उसके मध्य में ‘द’ बिन्दु तक, श्रमिक का अनिवार्य श्रम समय, कम से कम छः घंटे का दुनिया में माना गया है कि इतने घंटे लेबर को काम करना ही पड़ेगा, ताकि मशीनों के टूटने और घिसने, जो मजदूर खाता पीता है, तथा जो कच्चा माल लगता है उसका मूल्य निकल आये। इसके लिये अनिवार्य हैं कि ‘अ’ से ‘द’ तक पहुँचना ही पड़ेगा। लड़ाई ‘अ’ से ‘द’ तक पहुँचने की नहीं है। लड़ाई तो तब होती है जब वह ‘अ’ से ‘स’ तक हांकना चाहता है। बैल को हमने भूसा दिया, खली दी, पानी पिलाया और अब हल में जोतना शुरू कर दिया। और उस वक्त तक जोतते हैं, जब तक कि वह परुआ कर बैठ न जाय। बैठने के बाद भी करामात की जाती है। एड लगाते हैं, पूंछ मरोड़ते हैं, नथुने में पानी डालते हैं, कितनी ही तरकीबें की जाती हैं। यह लेबर स्ट्रगिल का इतिहास है। जब पूंजीपति चाहते हैं कि ‘अ’ से ‘स’ तक वह जाय, वहां लेबर चाहता है कि ‘द’ की बुनियाद से भी पीछे चला जाय तो अच्छा होगा। वह सेबोटेज तक आ गया है, स्ट्राइक तक आ गया है। आखिर उसने शेखचिखी की तरह से कहा कि न काम करेंगे और न काम करने देंगे। स्ट्राइक

[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

पुगनी चीज है। शेखचिल्ली की किताब आपने पढ़ी होगी। काजी साहब से जब समझौता हो गया तो दस्तखत कर दिये। 'बस्ता ले जाना होगा', उन्होंने कहा कि ले जायेंगे। बस्ते की किताबें निकाल कर रख दीं, और उसमें लतरे जूते और इंटे वगैरह भरकर पहुँचा दिया। बरखास्त हो नहीं सकता था ! अहमक, ईडियट कह लीजिये। जो लेबर स्ट्रगिल है उसमें वह शक्ति पैदा हो गयी। अब जमींदार क्या चाहता है ? जमींदार यह चाहता है कि किसान हमारे लिये कामाता रहे और खाने को कुछ न दें। हमारे यहां चोटा देते हैं। इतनी बड़ी धरिया होती है, उसको चोटही धरिया कहते हैं। यह एक खास माप है। पहले तो शीरा कुछ अच्छा भी मिलता था, आज कल का शीरा तो पीने के बिल्कुल लायक नहीं होता। तो वही एक धरिया चोटा और एक चिखना बोलते हैं, वह देते हैं। मटर, चना अथवा कोई दूसरा मोटा सब कच्चा, इसलिये कि आंच भी लगने न पाये, ईंधन खराब न होने पाये। वह हल जोतता था लेकिन किसी को दया नहीं आयी कि उस आदमी का पेट भरता है या नहीं। एक अंगौछा और एक लंगोटी लगा रखी है। चमारिन भीग रही है पानी में लेकिन खेत पर उसका कमी कब्जा नहीं हुआ। हल जोतते हुये सदियां गुजर गईं, तीन पुश्त बीत गईं इस पर भी होता यह था कि वर्षों गुजर जाते थे और जैसा कि पंडित विशम्भर दयाल जी ने कहा था। मैं देखता था सौदे होते थे और बहुत ज्यादा नजराना उसको देना पड़ता था अन्यथा वह बेदखल हो जाता था। यह करण शब्द मेरे कानों में आज तक गूँजते हैं। अषाढ़ का महीना है और वह बेदखल हो रहे हैं। वह खेती में खाद नहीं डाल सकता मेंढ़ नहीं बना सकता। उसका सब कुछ नजराने में चला जाता है। उसके अलावा उपज की क्या हालत है। एक एक्सपर्ट लिखता है कि सन् १९५१ तक ६२८६ हजार टन से ज्यादा घाटा होने का अनुमान किया है। जो इंगलैंड इंडस्ट्रियल कंट्री है वहां की पैदावार ३१.२ ब्रुशल्स फी एकड़ है। पढ़े लिखे आदमी ने यह लिखा है। मधुमक्खी क्या करती है फूलों फूलों से रस लेकर ही तो शहद बनाती है। आपको तो बरैया का छत्ता ही प्यारा है। श्री चरण सिंह ने अपनी कमर तोड़ डाली। वहां की जैसी लाइफ है उसी चीज को वह देखता है और अपने अनुभव के आधार पर श्री अमीर रज़ा ने लेबर लगवा दी इसी का यह नतीजा है।

श्री फखरुल इस्लाम—आपने ५० हजार रुपया नैनीताल में खर्च कर दिया।

श्री अलगूराय शास्त्री—अच्छा तो यह जो कूलर्स यहां पर लगा दिये हैं इनके आग खिलाफ हैं। ऐसी बात आप न कहें क्योंकि जनता यह समझेगी कि यह तो आग में बैठ कर काम करने को तैयार है हम ही को ठंडक चाहिये। ठंडक तो हर एक आदमी को चाहिये। इसलिये कूलर क्वाइटमेंट की जरूरत है और काम भी ज्यादा और अच्छा होता है। इंगलैंड में लोग ज्यादा काम करते हैं। अगर ठंडी हवा मिल जाती है तो आप उसकी इस तरह से मुश्कालफत न करें !

मैं यह कहता हूँ कि इंगलैंड में ३१.२ ब्रुशल्स फी एकड़ पैदावार होती है और ६० पौंड का एक ब्रुशल होता है। इंगलिस्तान की पैदावार २५ मन फी बीघा के हिसाब से होती है। जो उद्योग प्रधान मुल्क हैं जहाँ पर जमीन के नीचे कोयला और लोहा है और जहां तरह तरह की मशीनें बनती हैं और लौहे का सामान बनता है और बुनिया भर से व्यापार होता है

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३०४

उस मुल्क में २५ मन फी एकड़ पैदा होता है और वहां का यह औसत है। हमारे यहां का औसत इन्कवायरी कमेटी ने निकाला था कि फी एकड़ १० मन पैदा होता है। यह वहां की बात है कि जहां का गैन्जेज़ प्लेन ब्रैज़ीलियन प्लेन के अलावा दुनिया में सब से ज्यादा उपजाऊ माना जाता है। इटली का किमान लोहे से पत्थर को खोद कर उस में खाद डाल लेता है और नल के जरिए में पानी दे लेता है वहां बहुत तादाद में बढ़िया अंगूर पैदा होता है और इटेलियन मिर्च पैदा होती है। अगर आप चोधरी मुखतार सिंह की किताब “रूरल इंडिया” पढ़ेंगे तो आप को मालूम होगा कि उस में लिखा हुआ है कि यह मुल्क अपनी कुरीतियों की वजह से बरबाद हुआ और पैदावार मारी गई। मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम इस मसले को पैदावार के लिहाज से देखें। हुज़ूर वाला, ५.४० अरब रुपया किसानों के ऊपर कर्जे का १९२१ में आका गया था। यह सन् ३१ में ६, सन् ३५ में १५ और सन् ३७ में १८ अरब हो गया। यह कर्जा क्यों हुआ? यह एक एकनामिक स्ट्रगिल थी। होता क्या है? होता यह है कि अगर किसी खेत को चमरू जोत रहा है और अगर उस का लगान घुरहू ८ रुपये से १० रुपया कर देता है और नज़राना भी अगर १०० रुपए दे देता है और जो बछेड़ी उस के यहां है और जिस पर जमींदार के कारिन्दे की निगाह है, कि अगर मिल जायें तो अच्छी सवारी होगी, बस इस लालच में चमरू मारा जाता है और घुरहू को जायद लगान और नज़राने पर जमीन छीन कर दे दी जाती है। वहां इसी तरह के “घुरहू” जैसे नाम होते हैं। यहां तक कि मेरा नाम भी अलगू कर के होंड दिया गया। महज गरीबी की वजह से ऐसा हुआ है और गाँवों में अकसर इसी तरह के नाम होते हैं पहले जैसे राम और कृष्ण होते थे वह अब नहीं होते। उन के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। मैं आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि सन् ३४ से ४४ तक १ लाख १२ हजार से ज्यादा बेदखलियों के मुकदमे हुए और किसान खेता से बेदखल किए गए। और इस तरह से लोग उजाड़े जाते रहे हैं और उन को डैज़रटेड विलेज कहना ठीक ही है। इस तरह से किसान बरबाद हुए। मुझे २ लाइन याद आ गईं जो किसान लोग गाया करते हैं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर डिप्टी स्पीकर श्री नज़ीमुल हसन, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डिप्टी स्पीकर—मुझे यह निवेदन करना है कि किसी बिल पर जब बहस होती है तो उसके लिए कोई समय सीमित नहीं किया जाता, और न मुझे कोई ऐसा अधिकार है लेकिन जो वक्ता साहब इस समय बोल रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि भवन के बहुत से अन्य सदस्य भी अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, वह खुद जितना ही कम समय ले सकें उतना ही अच्छा होगा।

श्री अलगूराय शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो बेदखलियाँ १९३४-४४ तक हुई थीं उनके खेतों के निकल जाने के बाद उसके खर्चे और बकाया लगान के लिए किसानों को अपनी दूसरी चीजों से जुकता करना पड़ता था। नतीजा यह हुआ, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, किसानों की औरतें जो गाना गाया करती हैं उसको मैं अर्ज करना चाहता हूँ ताकि वह रिकार्ड में आ जाए :—

[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

“अरे जमींदारन का राज, हमार बाजू बन्दा बिकाय गए। नथिया बिकाय गई, भुलनी बिकाय गई, तरकी बिआजतर आय। हमार बाजू बन्दा बिकाय गए।”

हिन्दुओं के यहाँ यह स्त्री-धन है और उसे विकना नहीं चाहिए। यही कारण है जिसमें इस प्रकार का लोगो पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा आपने कहा मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस भवन के माननीय सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रगट करना चाहते हैं किन्तु जितनी अहमियत और जितने महत्व का यह प्रश्न है उसको सामने रखते हुए और खास तौर से छोटे-छोटे जमींदारों की बहुत बड़ी तादाद इस सूबे में है सबके ऊपर यह प्रभाव पड़ता है कि जानबूझकर राजनैतिक दृष्टि और दूसरे कारणों, विद्वेष भावना, से कांग्रेसी सरकार उन्हें तबाह कर रही है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन कारणों की विवेचना की जाए जिन कारणों से यह बिल सामने लाना पड़ा है। हेराल्ड मेनन ने दक्षिणी भारत के सम्बन्ध में बतलाया है कि जहाँ १७७१ में फी आदमी ४० एकड़ औसत आराजी थी वहाँ १९१५ में ७ एकड़ रह गयी और आज हमारे सूबे में औसत आराजी ढाई से सवा तीन एकड़ तक किसानों के पास रह गयी है। अगर ५ आदमियों का परिवार हो या ४ का औसत परिवार हो तो पौन एकड़ भी एक के पास नहीं पड़ती। यह सब है इसलिए कि यह जो प्रथा यहाँ चला दी गयी और थोड़े से हाथों में खेतों को रख दिया गया जिनका दृष्टिकोण यह था जैसा कि मैंने बतलाया कि अधिक से अधिक लाभ अपने वर्ग को पहुँचे दूसरा वर्ग चाहे तबाह हो जाए। उसी का यह नतीजा है।

अदब के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ज़मींदार भाई इस बात को सोचें कि यह एक कुप्रथा है जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है, पैदावार घटती जा रही है। जहाँ पैदावार १२४० लाख टन यहाँ थी, आज वह घटकर ८४ लाख टन हो गई है और यह घटती ही जा रही है। जो आँकड़े हैं उसके मुताबिक हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ६ छूटों से ज्यादा लोगों को खाने के लिये मिलना मुश्किल हो जायगा। कुल ज़मीन जो जोती जा सकती है उसमें से १७ प्रतिशत ऐसी है जो खेती के अयोग्य है, १६ प्रतिशत टोटल एकरेज जो खेती में लाई जा सकती है वह परती है या कुल ज़मीन का ३६ प्रतिशत हिस्सा आज जोता बोया नहीं जा रहा है। यह जोताई बोआई तभी की जा सकती है जब जोतने बोने वाले का उस पर अधिकार हो। यह माना हुआ सिद्धान्त है, आइने अकबरी में भी हमने पढ़ा है कि (land belongs to him who tills The land) (ज़मीन पर उसका अधिकार है जो उसको जोता बोता है)। प्राचीनतम समय में भी यही था कि जो भूमि जोतता है, उसे उपजाऊ और सजीव बनाता है, भूमि उसी की है।

श्री वीरेन्द्र शाहजी (राजा जगम्भनपुर)। ने कहा कि यह गलत है कि अंग्रेजों ने ज़मींदारी प्रथा को चलाया। मैं तो इसे ऐतिहासिक तथ्य मानता हूँ। चाणक्य के कौटिल्य अर्थ शास्त्र में ज़मींदारी प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, न आइने अकबरी में ही। हाल्ट मैकेंजी के १८१८ के नोट हैं, जिसके आधार पर १८२२ के रेग्युलेशन नं० ७ के द्वारा एक नई व्यवस्था पैदा कर दी गई जिससे कुछ मुड़ी भर आदमियों द्वारा आसानी के साथ

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३०७

लगान, मालगुजारी वमूल किया जा सके और बहुत से आदमियों के पास उसके लिये न जाना पड़े। इसी वजह से जमींदारी प्रथा यहाँ प्रचलित हुई जो हमारे सामने है। लार्ड मोंटाग के शब्द हैं, कि बिहार में, बंगाल, कानपुर और बनारस में हजारों वर्षों से खेती करनेवाले और उस पर अधिकार रखनेवाले उसको जोतने बोलनेवाले जिस तरह से इस नई भूमि व्यवस्था के कारण रोने लगे चीखने लगे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

जिन लोगों ने यह प्रथा प्रचलित की थी उनके दिमाग में यह नकशा नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट का रेग्युलेशन है उसमें दो शब्द हैं जो ध्यान देने के योग्य हैं।

The Governor-General-in-Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by public assessment being fixed permanently will exert themselves in the cultivation of their land.

(अपने सलाहकारों समेत गवर्नर जनरल यह आशा करते हैं कि जमीनों की साधारण तमखीस स्थायी रूप में नियत हो जाने से जमींदारों को जो लाभ हुआ है उस लाभ का ध्यान रख कर जमींदार लोग अपनी जमीनों को जोतने में परिश्रम करेंगे।)

यह उम्मीद की जाती थी कि जिन लोगों पर इतनी मेहरबानी की जा रही है और जिनको इस तरह से फायदा पहुँचाया जा रहा है, परमानेंट सेटलमेंट करके, वे जमीन को जोतेंगे, बोयेंगे, उसके ऊपर अपनी शक्ति लगायेंगे। क्या इसके शब्दों से यह मालूम नहीं होता है कि एक परमानेंट सैटिलमेंट दिया जा रहा था। जो जमीन की नई व्यवस्था कर रहे थे उनको इस बात का अहसास था वे इस बात को महसूस कर रहे थे कि वे उन जमींदारों पर अपार कृपा कर रहे हैं। वे उनको मुस्तफीद फ़रमा रहे हैं। जब वे यह समझ रहे थे और उन्हें यह मालूम था कि इससे पहिले उन्हें यह लाभ न था जिस समय यह लाभ सन् १८२२ में उन्हें दिया गया इससे पहिले यह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं था। जो अंग्रेज़ लेखक हैं उनके शब्दों से यह साबित हो जाता है कि राजा साहब जगम्मानपुर की चारणा ग़लत है। यह ताल्लुकदारी प्रथा इससे पहिले इस तरह की नहीं थी। लार्ड कैनिंग को ताल्लुकदारों से जो आशाएँ थीं वह भी इन लोगों से पूरी नहीं हुई। उस समय जो शब्द उन्होंने कहे थे वे इस प्रकार हैं:—

“The sanads are liable to be confiscated if they fail to promote the agricultural prosperity of their astates.”

(यदि वे लोग अपने देश के कृषिविषयक ऐश्वर्य को उन्नत करने में असमर्थ रहे तो सनदें जब्त की जा सकती हैं।)

इन शब्दों के क्या मानी हैं। यह सनद और इस गारन्टी के क्या अर्थ हैं। राजा साहब को यह पता होना चाहिये कि लार्ड कैनिंग साहब का इसके मुतालिक क्या ख्याल था। उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह एक नई व्यवस्था हो रही थी, नया इनाम बाँटा जा रहा था। तब यह कहना कि यह प्रथा पुरानी है, आज यह जो नई सरकार कांग्रेस की है यही सारे मजालिम ढा रही है, बिल्कुल नामुनासिब है। आज यह जो नई व्यवस्था हो रही है वह महज एक सोशल मूवमेंट है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिस व्यवस्था



[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

में कमाने वाले को खाना मिल सके। ऐसा न हो कि कमाता कोई रहे और खाता रहे कोई और। किस तरह से यह नई व्यवस्था आई यह हमें समझना चाहिये। यदि जमींदारों के द्वारा देश की सम्पत्ति बढ़ाई गई होती तो ऐसा नहीं होता। सम्पत्ति तो बढ़ी नहीं घटी अवश्य। खेतों के नन्हें नन्हें टुकड़े हो गये जिसका नमूना इस जमींदारी कमेटी की रिपोर्ट की हरदोई जिले की एक तालिका में मिलता है। उसमें लिखा है कि ०.१८ एकड़ ज़मीन के भी टुकड़े किये गये। ०.०३ ०.३, ०.२ एकड़ ज़मीन के भी टुकड़े हुये हैं। इस तरह से होता रहा, असामियों को अपने कब्जे में रखने के लिये। एक ही खेत में से दूसरे को हिस्सा दे दिया जाता रहा। अगर दो भाई हैं एक का नाम रखा गया दूसरे का नहीं रखा गया। पटवारियों से मिल कर इस तरह की बहुत सी बातें कराई गईं। जो विदेशों हुकूमत थी उसने उत्पादक जनता को हटा दिया और जो सत्ताधारी लोग थे उनको ज़मीनें दे दीं। उसने इस देश के उद्योग धंधों को नष्ट किया और सारा बोझ खेती के ऊपर आ गया उसने सामूहिक धन संपत्ति को नष्ट किया और शरीरों को नष्ट किया नतीजा यह हुआ कि देश गरीब हो गया और जहां आस्ट्रेलिया में वहां की आमदनी का २२ प्रतिशत निर्माण के कामों पर खर्च किया जाता है वहां यहां की सरकार ६६ प्रतिशत खर्च करती है। यदि देश सम्पन्न होता और संपत्तिशाली होता तो यह बात नहीं होती। तब ज़मींदारी प्रथा को नष्ट होना ही चाहिये था। रोटी कपड़े का इन्तज़ाम यदि ठीक तरह से होता तो फिर कोई वजह या आवश्यकता नहीं थी कि इनको निकाला जाता। मगर एक बात है जैसा कि एक फ्रेंच राइटर का कहना है कि सरकार किसी की हो, मालिकों से ज़मीन का लेना उसका अधिकार है। पब्लिक यूटिलिटी के लिये जनता के हित के कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो सरकार किसी की ज़मीन ले सकती है। लैन्ड एक्वीज़िशन ऐक्ट इसी बीमारी का इलाज है। सारी दुनिया में यह चीज़ प्रचलित है कि रेल के लिये, अस्पताल के लिये, स्कूलों के लिये और दूसरे जनहित के कार्यों के लिये ज़मीन ली जाती है। वही फ्रेंच आथर कहता है कि अगर जन हित के लिये भूमि का लिया जाना किसी राज्य का अधिकार है तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी और कपड़ा है। यह मैं मानता हूँ कि रेल जरूरी है और अस्पताल भी जरूरी है लेकिन अगर रेलगाड़ी न हो तो आदमी पैदल चल सकता है, अस्पताल न हो तो आदमी चार दिन बीमार रह सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि बिना खाये आदमी कितने दिन भूखा रह सकता है। इसीलिये फ्रेंच आथर लिखता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी और कपड़ा है। अगर रोटी और कपड़े की व्यवस्था के लिये ज़मीन का प्रबन्ध किसी नए ढंग से करना पड़े तो ऐसा करना सरकार का परम कर्तव्य है। इसी दृष्टि से मुस्लिम देशों में क्रांतियां हुई हैं। यहां पर जो कुछ हो रहा है उससे जमींदार भाइयों को भी संतोष होना चाहिये। उनको वह दृश्य देखने को नहीं मिला है जो दृश्य दूसरे देशों में देखने में आया है। मैंने सोलन का ज़िक्र किया था। वह बड़ी पुरानी चीज़ है। आप देखिये कि मगारा में क्या हुआ और समोस में क्या हुआ। वहाँ पर बड़े-बड़े अमीरों को लूट लिया गया और उनकी ज़मीनों पर ज़बर्दस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। इसी तरह

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३०६

आप देखिये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या चीज़ उपस्थित करता है और रशन रेवोल्यूशन १९०५ क्या बतलाता है। इसी तरह तुर्कस्तान और अन्य देशों में क्रान्तियां हुईं और वह इस लिये हुई कि वह भू-व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर भू-व्यवस्था करने जा रही है। भू-व्यवस्था चाहे लड़ कर कीजिये चाहे प्रेम में कीजिये परन्तु यह निश्चित है कि ज़मीन का एक सामाजिक वितरण होगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति बन कर एक आदमी के हाथ में न सारे कल कारखाने रह सकते हैं, न खानें रह सकती हैं और न सारे खेत रह सकते हैं। उनको कम्युनिटी की प्रापर्टी होना ही पड़ेगा। जो मौजूदा बिल है मैं उसके मूल्य को समझता हूँ। सदियों के अत्याचार पीड़ित जनता को हम मुक्त करने जा रहे हैं। अगर यह बिल सर्वाङ्ग सुन्दर होता और चंद की तरह इसमें कोई कलंक भी होता जो इसके रखरखाव को खूबसूरत बना देता तब भी हम इसको स्वीकार कर लेते। मगर जब प्रधान मन्त्री ने यह उपस्थित किया कि यह सिलेक्ट कमेटी के सिफ़ुर्द किया जाय तो यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ खामियां हैं। कहीं बाल उड़ गये हैं कहीं बहुत बढ़ गये हैं इसलिये इसमें कहीं कैंची चलाना ही पड़ेगी कहीं कहीं बाल जमाने पड़ेंगे। प्रवर-कमेटी इसको देखेगी और अगर उसकी रेकमेंडेशन ज्यादा मुनासिब होंगी तो उनको संशोधन के रूप में उपस्थित किया जायगा। यह प्रवर समिति के सामने जायेगा और कई तरीके से इसके अन्दर सुधार करने की कोशिश की जायेगी। दिसम्बर तक इसको टाले जाने की बात मेरे समझ में नहीं आई है। आखिर किस क्रांति की सम्भावना करके राजा जगन्नाथ बख्श सिंह इसको दिसम्बर तक टालना चाहते हैं। मौत मुअय्यन है लेकिन सवाल यह है कि जिसको जाना ही है उसको खाना कीजिये मगर हंसते हंसते। मर्द मैदां ऐसा ही किया करते हैं। आप यह देखिये कि जमींदारी की व्यवस्था की गई परन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि उस व्यवस्था ने ज़मींदारों का चरित्र नीचा कर दिया और उनके लड़कों को निकम्मा बना दिया। कुछ काम करने के बजाय वह केवल लुल्ला ज़िन्दगी लेते रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण यह था कि वहां पर एक अरिस्टोक्रैटिक क्लास पैदा होगया था जो परी देश में या पेरिस में रह कर आमोद प्रमोद किया करता था जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने विद्रोह किया। यदि इस बिल में खामियां हैं तो प्रवर कमेटी उसको दूर करेगी। मौजूदा बिल में कम से कम किसानों की किस्में रखी गयी हैं। पहले जिम्न १ से १८ तक थे। हर रेवेन्यू अफसर को मुश्किल होती थी कि क्या करें, सारे चक्कर थे। अब पटवारी का बस्ता बन्द हो जाने वाला है। एक बड़ा आराम और रिलीफ़ हो जायगा। पटवारी खेतों के इन्दराज करने में काली स्याही से नाम दर्ज किया करते थे और उसके बाद सुर्ख से भी। दूसरे गवाही दोनों तरफ से दिया करते थे। जब पूछा जाता था कि यह क्या है सही इन्दराज कौन सा है तो कहते थे मैं परताल करके आ रहा था यह रास्ते में मिल गए और कहा कि तुम्हारी जान मार डालेंगे मैंने इनका नाम काली स्याही से लिख दिया। बाद में सही इन्दराज लाल स्याही से दिया। ऐसा बयान पटवारी का होता रहा है। इस बिल के पास हो जाने पर इस किस्म की बातों की आवश्यकता न होगी। अभी यह ज़रूरी है आज हम देखते हैं जैसा कि गांधे के एक मित्र ने उन जातियों का वर्णन किया जिनको क्रीमिनल ट्राइब्स के

[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

नाम से पुकारा जाता है। बरार जाति, उनकी जमीने डी० सी० के नाम से इन्दराज होता है। उनके नाम से न मौरूसी है न सीर है न खुदकाशत है। यह ज़्यादाती है। वह किम कोटि में आवेंगे। इस तरह के जो खेत हैं उनका किसी तरह का इन्दराज नहीं है। सबको लेकर एक शक्क देना है। खेत का जो जोतने वाला है उसको खेत का अधिकार मिले। उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इस किस्म के एतराजों का जवाब देना मेरा फर्ज नहीं है। ऐसी सूरत में ख़ास तौर से कि प्रधान मन्त्री स्वयं इस बिल का संचालन कर रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त चौधरी चरणसिंह जी जिन्होंने इसको तैयार किया इसके ऊपर इतनी मेहनत की और परिश्रम किया है। वह लोग इन एतराजों का जवाब देंगे मगर जो चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ कहना पड़ता है। यह सवाल है कि मुआविजा कम मिल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं ज्यादा मिल रहा है। यह तो भगड़े और आन्दोलन की बात है। दोनों को राजी करने के लिए बीच का रास्ता लेना पड़ता है। किसी को कम करना पड़ता है किसी को अधिक। दूसरे सूबों में जो कुछ हुआ, मद्रास में वम्बई में और जगहों में जो चीज़ें पेश हुई हैं उनको उठा कर देखें। उसकी तुलना करें। यहां यूनिफार्मिटी आफ कम्पेन्सेशन और पुनर्वास के लिये जो रकमें दी गई हैं। उन्हें देखिये तो कम नहीं हैं। बाजार भाव का अर्थ यह है जो चीज़ जितने की है। यदि बाजार भाव का प्रश्न उठाया जाय तो फिर समझौता कैसे हो। कभी नहीं हो सकता है। तभी तो इस पर लड़ाई चलती रहती है। समझौता वहां होता है जहां कुछ आप हटिये। जो खेत को जोतता बोता है और जिसका खेत पर अधिकार नहीं था उसको अधिकार मिल जाय वह इससे प्रसन्न होगा। जिन लोगों के अब तक अधिकार रहे हैं उनको गुजारे के लिये कुछ मिल जाय। इसके हिसाब से तालिका बनाई गई है। जो कुछ दिया जा रहा है मैं नहीं समझता कि कोई खास अत्याचार है। सब को कुछ न कुछ मिलता है। एक दूसरे विचार के लोग हैं वह कहते हैं कि ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है जैसा कि लारी साहब ने राजनीतिक दृष्टि से जिक्र किया है। उनकी पूरी तकरीर इस सम्बन्ध में राजनीतिक है। एक वर्ग जिसको वह समझते हैं हैबनाट्स हैं गरीब हैं। मुआविजा दे नहीं सकते। पैसा होगा नहीं। मुआविजा मिलेगा नहीं। जमींदारी जायगी नहीं। देखने में गरीब किसान के हामी हैं। पूरी स्कीम के समाप्त करने के लिये वह जो कुछ कह सकते थे कह गये।

अगर आप किसानों से इकट्ठे रुपया नहीं लेते और वे अपनी लगान का दस गुना और पन्द्रह गुना दाखिल नहीं करते तो जो 'पुल' आप बनाना चाहते हैं वह नहीं बन सकेगा। जमींदारों को आप मुआविजा न दे सकेंगे। फिर जमींदारी की प्रथा कैसे जायगी? गवर्नर जनरल बिना मुआविजे के जमीन नहीं लेने देगा। लारी साहब इस प्रकार जमींदारी प्रथा को कायम रखने में सफल हो जायेंगे मैं तो कहूँगा कि आपको खुली छूट दे देनी चाहिये कि जो अधिवासी बनना चाहता है वह अपने लगान का पन्द्रह गुना रुपया जमा कर दे और भूमिधर बन जाय। जहां पर रिपोर्ट में यह लिखा है कि आज किसान बहुत गरीब हो गये हैं और लड़ाई के जमाने में उनकी गरीबी और बढ़ी है, जब मैं उसको पढ़ा रहा

या तो उसी जगह पर मैंने अपना नोट लगा दिया है कि यह आवेश में आकर लिख दिया गया है। रिपोर्ट का यह अंश बेवुनियादी है। और शायद उसका मतलब कुछ दूसरा ही है। मतलब यह है कि अगर कोई यह समझे कि नाज का भाव मंहंगा होने की वजह से आज किसान लगवपती बन गये हैं तो यह बेवकूफी है। उस अंश का केवल यही अर्थ हो सकता है लेकिन यह सही नहीं है कि आज किसान में यह क्षमता नहीं है कि वह अपनी लगान आधी कराने के लिये अपनी लगान का दस गुना जमा नहीं कर सकते। उसमें दस गुना और पन्द्रह गुना लगान देने की क्षमता है। जो कागज का नोट चला है वह उसके पास भी पहुँच गया है और उसने उसको सम्भाल कर रख भी लिया है, कुछ ने गहने भी बनवा लिये हैं। यह कह कर मैं किसानों से कोई रश्क नहीं करता ? वे हमेशा से गरीब रहे हैं, मगर यदि आज उस आरगूमेंट को इसमें लगाया जाय कि चूंकि वे गरीब हैं और उनमें पैसा देने की क्षमता नहीं है इसलिए उनसे न लिया जाय तो इतनी बड़ी तादाद जो ८५ फीसदी आदमियों की है कि जिनके पास सवा छः एकड़ उत्पादक जमीनें नहीं हैं, और उनके पास अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं, उनसे पैसा न लिया जाय तो फिर पैसा नहीं आवेगा। और अगर पैसा नहीं आवेगा तो अभी जैसा कि हमने विधान परिषद् में पास किया है कि किसी की जायदाद को हम बिना मुआविजा दिये नहीं लेंगे, और वह हम करने जा रहे हैं, तो फिर वह पूरा नहीं होगा। अगर कम्पेन्सेशन नहीं देंगे तो जमीन्दारी हकूक नहीं लेंगे और रुपया नहीं होगा तो लावेंगे कहाँ से ? इन बातों को सँचें तो फिर आज यह इश्तआल देना कि किसान गरीब हैं, वे रुपया कहाँ से देंगे, यह एक चाल है, शुद्ध राजनैतिक चाल है। देखने में तो हितकर मालूम होती है लेकिन है अहितकर। हम खेतिहर समाज को उसके हाथों में उसके खेत दे रहे हैं, हम उनको खेत दे रहे हैं जो उनको जोतते हैं, बोते हैं, कम खेत का बटवारा रोक दिया गया है, लगान आधा कर देने की बात है, छोटे खेतों के अब टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जबरदस्ती की सब बातें रोक दी गयी हैं, घर में रहने वाले सबों को एक साथ काम करना होगा। अगर दो भाई सवा छः एकड़ जमीन को आपस में दो टुकड़े में बाँटना चाहें तो नहीं बाँट सकेंगे। उनको आपस में मिल जुलकर काम करना होगा, सहयोगिता के आधार पर उनको काम करना होगा। जहाँ सवा छः एकड़ से कम जमीनें हैं, अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं वहाँ उनको हम सहयोग द्वारा चलाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि धीरे धीरे करके मानवता आपस में मिल जुलकर काम करने की प्रेरणा पा रही है। इस बिल का कुल नक्शा अगर शुरू से आखिर तक देखा जाय तो हर समस्या जिस बुद्धिमत्ता के साथ सुलझायी जा सकती थी उसे सुलझाने की चेष्टा की गयी है। सचमुच वे लोग हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस योजना को तैयार किया है। मैं एक चीज अपने समाजवादी भाइयों से कहना चाहता हूँ। मैंने लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में जो मार्क्सवाद का अध्ययन किया है उसके हिसाब से मुझे सन्देह है कि आया पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप को सचमुच नेशनलाइजेशन कहा जा सकता है। एक फ्रेंच आथर ने इनसाइक्लोपीडिया में लैंड के बारे में लिखा है कि इसका अन्तिम सुधार यही है एक क्रान्तिकारी सुधार यही है, कि जमीन पर राज्य का अधिकार हो जाय व्यक्ति का अधिकार नहीं हो। राज्याधिकार का यह अर्थ नहीं है कि राज्य का

[ श्री अलगूराय शास्त्री ]

अधिकार हो गया तो वह थोड़े से आदमियों में बाँट दिया जाय । बल्कि जैसे रूस में बड़े-बड़े फार्म बने हुए हैं जहाँ पर ट्रक्टर्स चल रहे हैं, जैसा रिफार्म्स सन् १९२८ और ३० के बीच में हुआ है वैसा किया जाय । छोटे-छोटे प्रोप्राइटर जो जमीन जोतते हैं उनको वे जमीनें दे दी जायँ ।

यह जो योजना हमारी है उसमें उसी तरह के छोटे-छोटे पीजेण्ट प्रोप्राइटर्स हैं कि जो खेत जोतते हैं खेत की मिलकियत उनको दी गई है । जमीन पर मिलकियत किसी की नहीं है । प्राचीनतम हमारी भावना यही रही कि राजा भी जमीन को दान में नहीं दे सकता । सारी चीज़ें दे दी नचिकेता के बाप ने, “सर्व वेधसं ददौ” सब कुछ दे दिया, नचिकेता को भी दे दिया यम को लेकिन भूमि को वह भी नहीं दे सके । इसमें अगर तुलसीदल लेकर भी पंतजी स्वयं चाहें कि ज़मीन का दान कर दें तो नहीं कर सकते । यह उनके बस की बात नहीं है । इकाई किसी एक व्यक्ति की जमीन में नहीं हो सकती वह तो सारे समाज की होती है । इस तरह से अगर आप देखें तो पता चलेगा कि पीजेण्ट प्रोप्राइटरशिप का सारा ढाँचा इसके अन्दर दिखलाई देता है । यदि शुद्ध मार्क्सवादी की दृष्टि से देखा जाय तो मैं नहीं समझता कि कोई समाजवादी किस तरह से इसके ऊपर आक्षेप कर सकता है । लेकिन जो स्टेटमेंट सोशलिस्ट पार्टी की किसान समिति ने अभी हाल में निकाला है उसमें एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं कहा गया है कि आया जो हम चीज आज पैदा कर रहे हैं वह सन् १९०५ के बाद, सन् १९०६ से लेकर १२ तक रशा में लैण्डरिफार्म्स को जो ऐक्ट्स बने हैं उनको पढ़ने से या जो यूरोपियन गवर्नमेंट की मातहत में जो ऐक्ट्स बने हैं यह उनसे भिन्न हैं । आज हमारी समाजवादी पार्टी इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है । वह चुपके से इसे मान लेती है । १९२० से ३० तक रूस में जो भूमि व्यवस्था हुई उसके पक्षपाती वे नहीं हैं ! क्यों ? इस लिये कि हमारे समाजवादी साथी जानते हैं कि यदि किसानों से जमीन लेकर उसे नेशनलाइज किया तो कुल आबादी का ८४ प्रतिशत उनके विरुद्ध हो जायगा । वह कहते हैं कि इसको रिहैविलिटेशन कहो मुआविजा न कहो । नाक ऐसे न पकड़ो ऐसे घुमाकर पकड़ों । २८ गुना तो दिया जाता है, २० गुना इस नाम से और ८ गुना उस नाम से । वह जानते हैं कि अगर इस तरह से नहीं कही गया तो वोट का सवाल कैसे हल होगा । बात वही कही लेकिन घुमाकर, “रिन्द के रिन्द रहे, हाथ से जन्नत न गई” । वह जानते हैं कि किसान एक स्वार्थी वर्ग है । वह प्रोपर्टी ओनर है वह जायदाद चाहता है, वह प्रालीटेरियट नहीं है । वह आज नंगा नहीं है कि जिसके पास “तन नाते थरिया और पोसाक नाते करधन” हो । प्रालीटेरियट की यह परिभाषा है कि न उसके पास टूल्स हो और न प्लांट्स । सिर्फ शरीर हो और उस शरीर में काम करने की शक्ति । लेकिन यहां का आज का किसान ऐसा नहीं है । किसान के पास उसका हल है, और उसके पास बैल हैं, किसान के पास हंसुआ है, उसके पास हथौड़ा है, उसका गँडासा है, उसके पास खुरपी है और उसके पास कुदाल है । उसके पास खेत हैं, उसके पास बगीचे हैं, बाग हैं । उसके पास औरत है और बच्चे हैं । दिन भर काम करता है और रात को ठंडी हवा में सोता है । यह कहा गया कि किसान की ज़मीन को लेकर कलेक्टिवाइजेशन कर दिया

जाय तो वह रेजीनेटेशन जो है इस देश में वह नहा चल सकता। इस देश का अपना एक ढंग रहा है। दूसरा ढंग यह नहीं चल पाया। बोद्धा की समस्या यहां पैदा हुई परन्तु वह टिक नहीं सकी। यहां का किमान प्रोलीटेरियट नहीं हो सकता। यहां उसे अपना मकान चाहिये, जमीन चाहिये, हथ चाहिये और बैल चाहिये। हवनकुंड चाहिये और गैया चाहिये जो दूध देती हो और उसके दूध में लोग पुष्ट हो फलें फूलें ऐसे देश में प्रोलिटैरियनिज्म की किलास को नहीं चल सकेगा, यह हमारे सनाजवादी मित्र कदाचित्त समझ गये हैं।

कविता—योग ठगोरी ब्रज न विकैहै॥

जापै लै आये हो ऊधव वाके उर न समैहै।

यह बानि जो तुम्हारो ऊधव ऐसो ही फिरि जैहै॥

हमको ऐसा प्रोलीटेरियट नहीं बनाना है। लोग कहते हैं कि तुम क्या कहते हो। मैं कहता हूँ कि यह क्या नहीं है। यह वास्तविकता है। है किस्म में हिम्मत जो यहां प्रोलीटेरियट की स्कीम को चला दे। कहा है वह मार्क्सवाद जो इस चीज़ को बना दे। यह चीज़ मार्क्सवाद से यहां बन भी नहीं सकती। लेकिन हमें सन्तोष है कि पीजेन्ट प्रोप्राइटरशिप की पूरी स्कीम को हमारे सनाजवादी भाई भी मानते हैं। उसमें बड़े-बड़े हमारे आचार्य लोग हैं। यह वही प्रथा है जिसमें हमारे चरणसिंह साहब विजयी हुये। क्योंकि अभी तक कम से कम जो अन्न को समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं और जो हमारे देश में सब में मज़दूर पार्टी है उन्हें ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। कल से इसके बारे में कुछ कहना शुरू करें तो दूसरी बात है। मेरा भी वास्तविक रूप से सोशलिस्ट पार्टी के साथ कुछ ताल्लुक था, यह बातें मैंने उसके मुताल्लिक कहीं। लिहाज़ा अगर यह स्कीम इस दृष्टि से दूषित नहीं है तो इसमें कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मंत्रि मंडल का शुक्रगुज़ार होना चाहिये कि उसने हमको यह योजना दी है और इससे ८४ फ्रीसदी आबादी के लोगों का ताल्लुक होगा। उनके पास खेत हैं, बैल हैं और उनके बच्चे और स्त्रियां हैं। वह अब आज़ाद होंगे और सच्चे मायनों में आज़ाद होंगे। मैंने बहुत समय लिया और दूसरे सज्जना को भी इस पर बोलना है और यह उचित न होगा कि मैं ही सारा समय लें लूँ और दूसरों को अवसर न दूँ जो कि इस पर बोलना चाहते हैं। इसी भावना से यह कह कर कि यह स्कीम सब को माननी चाहिये और प्रवर समिति में जल्द से जल्द इसको भेजकर इस भवन में इसको कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिये और किसी प्रकार से समय का अतिक्रमण नहीं होना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का और रिपोर्ट का इसके ऊपर परिश्रम करने वालों को धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मुहम्मद जमशेद अली ख़ाँ — जनान्नवाला, दो तीन रोज़ से बराबर इस बिल के ऊपर बहस हो रही है और मैं बड़ी ख़ामोशी के साथ यह देखता रहा हूँ कि हर शख्स जो सामने आता है वह काश्तकारों की हमदर्दी और हिमायत का गीत गाता है और कोशिश इस बात की जाती है कि हमसे ज़्यादा काश्तकारों का दोस्त और हमसे ज़्यादा काश्तकारों का हमदर्द कोई दूसरा नहीं है। चूँकि मैंने कल देखा कि जनता पार्टी के लीडर साहब ने भी बड़े जोश खरोश के साथ काश्तकारों के साथ हमदर्दी जाहिर की और हिमायत की।

[ श्री मुहम्मद जमशेद अली खॉ ]

त्रिपाठीजी ने और भी बड़ी कोशिश की और उनसे भी आगे बढ़ गये। यह तमाशा बराबर जारी है। वजह इसकी यह है कि यह ज़बानी जमाखर्च है। इसमें तकलीफ तो कोई उठानी पड़ती नहीं। जमीदारान जितने यहाँ पर इस एवान के अन्दर मौजूद हैं वह इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वह कोई गैरज़िम्मेदार हैं और काश्तकारों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हज़ूवाला, अगर काश्तकारों से रायदेहन्दी होने का हक ले लिया जाय तो फिर मैं देखूँ कि ऐसे कौन-कौन हैं जो काश्तकारों की हमदर्दी में खड़े होते हैं। यह सारी राय देहन्दी की अक्सरियत है जिसकी बिना पर हरएक इस बात की कोशिश करता है कि वह काश्तकारों का सबसे ज़्यादा दोस्त माना जाय। लेकिन मैं इस बात को यकीन के साथ और जोर के साथ कहता हूँ कि जमीदारों ने उस जमाने में जब कि उनकी अक्सरियत थी और जब कि वे बरसरे हकूमत थे। अपने हकूक को निकालकर काश्तकारों को दे दिया। इसकी मिसाल आप इस वक्त पेश नहीं कर सकते। सात साला पत्रा के मुकाबले में हीनहयाती हक काश्तकारों को उस वक्त जबकि वह बरसरे हकूमत थे दिये और विला किसी मुवाविजा के उनको जमीनें दीं। उसकी एवज में जो आज यह बिल यहाँ पर पेश होता है यह आपके सामने है। वज़ीरआज़म साहब ने अपनी तकरीर के दौरान में फ़रमाया था कि जमींदारों को हमारा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हम यह “जमींदारी अवालिशन बिल” यहाँ लाये हैं। जनाबवाज़ा, रहा वज़ीर आज़म साहब को शुक्रिया अदा करने के बारे में, तो चूँकि बराबर एक जागने की जिन्दगी जमीदारान के लिये बना दी गयी थी और हर वक्त सबसे पहले तलवार का वार और सबसे पहले बरछी और खंजर का वार उन्हीं के ऊपर होता रहता था, कमी “एग्ज़िक्यूटिव इन्कम टैक्स” की शक्ल में, कमी अबवाब, कमी लोकल टेक्सेज़ को बढ़ाकर, गरज़ कि हर तरीक़े से उनको परेशान किया जाता था और उनकी जिन्दगी बवाल की जाती थी और इस वजह से अगर उनको एक दम गला काटकर ख़त्म किये देते हैं तो बेशक शुक्रिये के वह मुस्तहक हैं। वह शुक्रिया सिवाय इसके कि इन अलफ़ाज़ में अदा किया जाय और दूसरे लफ़्ज़ जवान पर नहीं आते।

“ख़ूब ही मुठियाँ भर भर के मुझे मिट्टी दी,

आज तो लाद दिया आपने अहसानों से !”

जनाब वाला, वज़ीर आज़म साहब की लियाकत, काबिलियत, स्टेडस्मैनशिप का मैं हमेशा से मौतरिफ़ हूँ, और मैं क्या बल्कि ज़माना मौतरिफ़ है, और फख़ है कि वह हमारे सबे के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन इस बिल के पास करने में उनको जो कुर्बानी देनी पड़ी वह भी बहुत बड़ी थी। “सेंस आव फेयरप्ले, जस्टिस एंड इक्विटी”, इन सब चीज़ों की कुर्बानी उनको देनी पड़ी और मैं भी उनकी मजबूरी को समझ सकता हूँ कि किस तरह से मजबूर होकर उनको ऐसी चीज़ें लानी पड़ीं जो ‘इक्विटी और फेयरप्ले’, इंसफ़ और बाजबियत से कतअन दूर हैं। बहर हाल मुझे उनसे काफी हमदर्दी है कि जिन हालात के अन्दर उन्होंने इस बिल के अन्दर ज़मीदारान के साथ जो सलूक किया, इसके सिवा उनके पास चारा ही क्या था ?

कहा जा रहा है कि जमीदारान ने काश्तकारान को तबाह कर दिया और काश्तकारों

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३१५

के सब से बड़े दुश्मन ज़मींदार हैं। जबान की ४,५ गर्दिश से एक जुमला बना दिया है। आप अपनी जबान में जो जी चाहे फरमाएं लेकिन मैं तो यह देख रहा हूँ कि जो चीज अंग्रेजों ने पैदा की कि जमींदार और काश्तकार के ताल्लुकात अच्छे न रहे चुनाचे जितने कवानीन और लेजिस्लेशन उन्होंने लगान के सिलसिले में बनाए वह इसी तरह के थे कि “चोर ने कहा कि चोरी कर और मकानदार से कहा कि तेरे घर में नकब लग रहा है” और इस तरह में “डिवाइड एंड रूल” की पालिसी पर उन्होंने अमल किया, लेकिन ताज़ुब है कि हमारी ‘पापुलर गवर्नमेंट’ और ‘नेशनल गवर्नमेंट’ भी उसी तरीके और वरसे के ऊपर क्यों कायम है और उसे वह क्यों दोहराती है? मैं देख रहा हूँ कि जबकि बार-बार यह तय किया जा चुका है कि हम जमींदारियों को खत्म कर रहे हैं तो चाहिये यह था कि यह खात्मा और एक हाथ में दूसरे हाथ को तबादला खामोशी के साथ और अमन के साथ हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बराबर हर तकरीर में अब भी गवर्नमेंट का हर जिम्मेदार मेम्बर, वजीर हो या पार्लियामेण्टरी नेक्रेटरी चाहे किसी मजमे में, किसी मौजूं पर तकरीर करे, उसका यह फर्ज अव्वलीन हो गया है कि वह काश्तकारान को यह बतलाए और समझाए कि जमींदारों से ज्यादा तेरा दुश्मन कोई नहीं, और यह सब से बड़ी खौफनाक और हौलनाक चीज है जो तेरे लिये हो सकती है। मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस तमाम प्रोपैगेंडे के बावजूद काश्तकारान और जमींदारान के ताल्लुकात जैसे अब तक खुशगवार रहे वह खुदा का एक इनाम है, वरना तो यह हो सकता था कि काश्तकार जमींदारों के सर कलम कर देते, बलबे होते, खूरेजिया होती और न जाने क्या-क्या होता! इस तरफ की यह सूरत है। दूसरी तरफ मुलाहजा कीजिये। ज़मींदारों को भी कहते हैं कि पूंजीपति हैं। उनको भी पूंजीपतियों के साथ ब्रैकेट किया जाता है। मैं आप के तबस्सुल से पूछना चाहता हूँ कि कितने मौके ऐसे होते हैं कि मजदूर ‘स्ट्राइक’ करते हैं जब कि गवर्नमेंट की मशीनरी कोशिश करती है कि स्ट्राइक न हो, और गवर्नमेंट ने इस बात के लिये मशीनरी तैयार कर रखी है कि किसी तरह से लेबर को मुतमईन किया जाय, इसके खिलाफ जमींदारी के साथ यह सूरत क्यों है कि किसानों को उभारा जाता है और तकरीबन मजबूर किया जाता है कि वह उठ कर ज़मींदारों के खिलाफ हो जायें, और ज़मींदारों को अपना दुश्मन समझने लगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज जब कि आप ज़मींदारों को खत्म करने जा रहे हैं, उस वक्त भी काश्तकारों और ज़मींदारों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार और बेहतर हैं।

ऐसे जबर्दस्त बिल के जिसका करोड़ों आदमियों से ताल्लुक हो, किसी पहलू पर कोई नज़र नहीं की जा रही है। मैं तो देखता हूँ कि एक दौड़, एक सूबे और दूसरे सूबे के दर-मियान हो रही है और इसकी बराबर कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले ज़मींदारी को कौन खत्म करे और कौन इस तुरियेइम्तियाज़ को अपने नाम से वाविस्ता करे कि हमने ज़मींदारों के साथ सबसे ज्यादा सख्ती की और उनको खत्म कर दिया। आपने कभी यह गौर नहीं किया कि यह कदीम इत्तिसादी निजाम जिसको आप दरहम बरहम कर रहे, इसके बाद कहीं ऐसी सूरत न पैदा हो जाय जिस पर आप को अफसोस करना पड़े। आज हर तरफ से कहा जा रहा है कि ज़मींदार को अगर दुनिया से खत्म कर दिया जायगा, तो



[ श्री मुहम्मद जमरोद अली खाँ ]

दुनिया जन्नत बन जायगी, तमाम दुनिया ने खराबियाँ एक कलम दूर हो जायंगी लेकिन मैं पूछता हूँ कि आपके ख्वाब की तारीर अगर दुरुस्त न हुई तो क्या होगा? यह इस जमाने के लिये कोई नयी चीज़ नहीं है। आज आप एक चीज़ को बुरा कह रहे हैं, एक चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, क्या अजब है कि वह दिन आये जब कि आप कहें कि यह हमारी सज़ा ग़लती थी। तारीख़ इसकी राहदस्त देती है। सज़ा को पब्लिक ने क़त्ल किया, और उसी पब्लिक ने उसके कातिलों को क़त्ल किया। इसी तरह ने आप जो निहायत मसरत के साथ आज ज़मींदारों के गले पर छुरा चलाना चाहते हैं और उनके साथ बेइन्साफी करना चाहते हैं, क्या अजब है कि कल को आप यही कहें कि आपने सब्से बड़ी ग़लती की। तवारीख़ के सफ़हात के ऊपर यह नाम आ जाना किफ़लां की वज़ात के अन्दर ज़मींदारों को ज़त्न किया गया, यह बड़ा तुर्रये इम्तियाज है, यह काफी नहीं होता है। तारीख़ के अन्दर रान, रावण, नाशेरवाँ, जहांगीर, हलाकू और चंगेजखां सभी के नाम हैं लेकिन देखना यह है कि आइन्दा के मुअरिख़ किस को किस लफ़्ज़ के साथ याद करते हैं। फ़क्त नाम का आ जाना काफी नहीं है।

इसके 'प्रिपेन्डिबल' में वही पुराना रोना रोया गया है कि ज़मींदारी निजाम तो अंग्रेज़ों का 'क्रिएशन' है। मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या खास चीज़ है। अगर फर्ज कीजिये कि आपका ही यह कहना दुरुस्त है और चौधरी चरण सिंह जी का यह फरमाना दुरुस्त नहीं है कि सदियों से यह निजाम कायम है। यह कह देने से इसमें क्या फर्क पड़ता है कि यह अंग्रेज़ों के जमाने से कायम है। क्या यह कह देने से कि कांग्रेस की बुनियाद की पहली ईंट एक अंग्रेज़ ने डाली थी कोई फर्क आ जाता है। क्या इसमें कोई बुराई पैदा हो जाती है। इसमें कोई बुराई पैदा नहीं होती अगर यह कहा जाये कि यह निजाम ज़मींदारों ने अपने सहूलियत के लिये कायम किया था लिहाज़ा इसको बदलना है। अगर आप यह कहते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें बदलना पड़ेंगी जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं और आप उनके अख्तियार किये हुये हैं। मुझे याद है कि एक साहब ने यह 'आरगू' किया था कि यह निजाम बहुत पुराना फरसूदा हो गया है, बेकार हो गया है इसलिये हम इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर हम यह कहें कि ज़मींदारियां अंग्रेज़ों के जमाने की कायम हुई हैं तो काम नहीं चलता और अगर यह कहे कि यह बहुत पुरानी चली आती है तब भी काम नहीं चलता। गरज़ यह कि आप हर तरह से बहस पेश कर सकते हैं।

बहरहाल देखना यह है कि इस बिल के अन्दर ज़मींदारों के साथ कैसा बर्ताव किया गया है और किस तरह से उनको इसमें खींचा गया है। सब से पहली चीज़ जो हमारे सामने है और जिससे ज़मींदारी का सब से ज्यादा तात्क़ुक है वह मुआवज़ा है। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है कि मुआवज़ा ८ गुना दिया जायेगा तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यह 'फिगर' किस तरीके से रखी गई है। 'इक्विटीबिल कम्पनमेशन' के ऊपर आनरेबिल प्रीमियर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था और कहा था कि मुनासिब और वाजिब है और हम लोग इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। यह

## मन १९४६ ई० संयुक्त प्रान्तीय का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३१७

किंग' जिस कयदे और करीने ने मानने छाई है जब आपने खुद 'सीलिंग प्राइस' जमीन में 'टुवेन्टी टाइम्स' अगर दी है क्योंकि आपने फरमाया है कि अगर काश्तकार १० गुना लगान दे दे तो हम तिसर लगान मात्र कर देंगे। इनके मते यह है कि इसकी 'सीलिंग प्राइस' थीम चुनो हो गई कि आठ गुना मुआवजा किन तरह ने रखा है यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है इनके बाद नितन दर मितन यह कि आपने फरमाया है कि 'वेक्शन चार्जेज' १५ न मर्दा कर किये जायेंगे। यह गलत बात है क्या कि कल की बात है कि 'एक्जक्शन' इनका टेन 'कट' ने आपने 'वेक्शन चार्जेज' १०-१२ फी सदी करार दिये हैं आज किन तरह ने आप १५ फी सदी रखते हैं। क्या इनके मते यह है कि खरीदने के बंट और बेचने के और यह गज और जिम्मे आप बढ़ा लेते हैं और वह गज दूसरा जिम्मे आप बढ़ा लेते हैं। आपकी शान के लिये यह चीज ठीक नहीं है। एक ही बात हम गवान में पास करके दूसरी चीज में फर्क नहीं होना चाहिये।

इनके माय-मन कि जिस वक्त 'एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स बिल' जेरे वहस था तो मेरे दोस्तों ने दावदा यह होगा कि यह कहा गया था और हर शख्स यकीन किये हुये था कि जिस वक्त मुआवजे का सवाल होगा। यह सुजना नहीं किया जायेगा और 'वैल्यूएशन' कम नहीं की जायेगी बल्कि उस वक्त कहा यह गया था कि यह तो 'इंटेरिम' जामने के लिये बनाया जा रहा है यह न मनभिने कि इसने मुआवजा कम होगा आज वही 'एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स' हनारे मुआवजे के लिए नुक्सानदेह साबित हो रहा है। एक तरफ सूरत यह है कि तनान सूबा में उसका रेट आपने ज्यादा रखा है और दूसरी तरफ आप इस बढ़े हुए रेट को, जो कहीं भी इतना ज्यादा सुल्क भर में नहीं है, लगाकर हमारे मुआवजे को कम कर रहे हैं। तो फिर आप बतलाइए कि हम यह कैसे समझें कि आप 'इक्विटेबिल' मुआवजा देना चाहते हैं? क्या यही आपकी 'जस्टिस और इक्वीटी' है कि जो आप जमींदारों, के साथ करने जा रहे हैं? इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं इस वक्त तफसील के साथ पेश नहीं करूँगा। इस बिल की खास-खास चीजें हैं जो मुझे स्ट्राइक हुई हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं इस वक्त पेश करूँगा।

इस बिल के अन्दर कहा गया है कि 'नोटिफिकेशन' होने पर फौरन ही उसके बाद जमींदारों को लगान वसूल करने का या जमींदारी के दरख्तों वगैरा पर कोई हक नहीं रहेगा। मुझे ताजुब होता है कि जब आप एक चीज खरीद रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि बर्गर कीमत की अदायगी के कैसे आप मालिक बन सकते हैं। इस तरह से आप मालिक बने जाते हैं और कहते हैं कि बाद में देखा जायगा। अगर एक शख्स है कि जिस के खाने पीने का दारमदार और बाल बच्चों और बीमारों का दारमदार जमींदारी पर ही है और आप उनको तमाम जायदाद एक 'नोटिफिकेशन' से ही ले लेंगे और बाद में २५ फीसदी मुआवजे बढ़ा देंगे और साथ ही कोई खबराने की बात नहीं है तो कैसे कान चल सकता है यह आप को खुद ही सोचना चाहिए। इससे उस भूखे को कैसे सकून मिल सकता है। इसलिए यह चीज जब आपके पास 'सेलेक्ट कमेटी' में जाय तो आप उस पर हमदर्दी और नेहव्यत ने इन्सानियत के साथ गौर करके दुरुस्त करें, वहरवाल जमींदार भी इन्सान ही हैं।

[ मुहम्मद जमशेद अली खॉं ]

आखिर में मैं यह अर्ज़ करूँगा कि आप जो यह एक 'एलोबरेट मशीन' इस काम के लिये मुरतब करना चाहते हैं जिसके जरिये से आप काश्तकारों को जमीन देना चाहते हैं और मुआवजा वगैराह तै कराना चाहते हैं। आपने एक सेलिंग प्राइस तय कर दी है। अच्छा हो कि आप यह काश्तकारों और ज़मींदारों पर ही छोड़ दें कि वह आपस में ही यह तै कर लें और इस तरह से तमाम किस्सा खत्म हो सकता है और प्राइवेट तरीके पर यह चीज़ तै हो सकती है। अगर यह ख्याल हो कि ज़मींदार इन्कार करेंगे तो कल्चर मजबूर कर सकते हैं।

गरज यह चीज़ निहायत सहूलियत और बिला किसी मजीद दिक्कत के हो सकती है। एक जरा सी चीज़ यह भी काबिले गुजारिश है कि जब यह बिल कानून बन जायेगा और उसकी दफात अमल में आयेंगी तो जमींदार के पास कोई बाड़ा या मामूली सा सीर का टुकड़ा होगा तो वह भी वहाँ भूमिधर होगा और आपने मालगुजारी वसूल करने का कायदा मुस्तकिल और मुनफर्दन रखा है लिहाजा मुझे डर है कि लगान कहीं दो दफे वसूल न किया जाय। अच्छा हो कि काम आप पंचायतों के सुपुर्द कर दें और वह तमाम लगान वसूल कर लिया करें। यह तमाम चीज़ें मुझे अर्ज़ करना थीं। अब कोई शिकवा-शिकायत का मौका नहीं है। एवोलीशन का बिल पेश है, ज़मींदारी खत्म होने जा रही है, उसके लिए तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं।

❖ श्री श्रीचन्द्र सिंघल—डिप्टी स्पीकर साहब, हर पार्टी ने जो यह बिल पेश है उसका बहुत स्वागत किया है और मैं भी उसका स्वागत करना अपना फर्ज समझता हूँ। ४ दिन से इस पर बहस चल रही है। हर पार्टी के नुमाइंदे बोल चुके हैं। विरोधी दल ने भी इस बिल का स्वागत किया है लेकिन इसके कुछ हिस्सों की आलोचना भी की है। मैं उन आलोचनाओं का जवाब देने को तैयार नहीं हूँ। कारण यह है कि बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है जो क्रिटिसिज़्म कांस्ट्रक्टिव हैं उन पर सिलेक्ट कमेटी विचार करेगी और जो आलोचनाएं बेफायदा हैं उनका जवाब देना मुनासिब नहीं है। वह तो सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और मुखालिफों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए की गयी हैं। जो विरोधी दल आज कल जनता पार्टी के नाम से है वह इससे पहले मुस्लिम लीग के नाम से था और जब ज़मींदारी एवोलीशन का बिचार दो साल पहले इस भवन में पेश हुआ था तो उन्होंने जोरो से उसकी मुखालफत की थी। मैं देखता हूँ कि हमारे ज़मींदार भाई आज बहुत उदासीन हैं, परेशान दिखाई देते हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है लेकिन मुझे उनसे यह कहना है कि उन्हें समय पहचानना चाहिए।

उन्होंने जो संशोधन पेश किया है उस पर जितनी शान्ति के साथ कांग्रेस सरकार विचार कर सकी है उतनी शान्ति के साथ कोई भी पार्टी या सरकार नहीं कर सकती है। अगर किसी और पार्टी का राज्य हो जाता तो मैं समझता हूँ कि उन्हें मुआविजा क्या मिलता बल्कि उन्हें अपने जान के लाले पड़ जाते। ज़मींदारों ने इतनी गद्दारी दिखाई लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने उनके साथ हमदर्दी ही दिखाई है और उनको काफी मुआविजा दिया है।

\* माननीय सदस्य ने भाषण शुद्ध नहीं किया है।

मेरी तो राजा माइय ने प्रार्थना है कि मेहरबानी करके अपने संशोधन को वापिस ले लें अगर वह संशोधन को वापिस नहीं लेते तो मेरा कहना है कि यह उनके खिलाफ ही जायगा।

जमींदार भाइयों ने कहा कि हम तो हमेशा से चले आ रहे हैं, यह प्रथा तो हिन्दुस्तान में हमेशा से चली आई है। मैं कहता हूँ कि यह ग़लत है, यह प्रथा तो अंग्रेजों के साथ आई और अंग्रेजों ने देश के फ़ायदे के लिये नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिये इसे चलाया और जिन राज अंग्रेज यहां से चले गये, उसी दिन यह प्रथा भी उनके साथ चली गई थी। मैंने पढ़ा था कि Don't speak ill of the dead (जो आदमी मर गया है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिये) इसलिये मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी राज्य खत्म होते ही जमींदारी खत्म हो गई और अब तो उनकी लहाश रह गई है, जिसे इस असेम्बली के जरिये हमें दफनाना है।

अब तब जिन जमींदार भाइयों ने किमानों के लिये कोई हमदर्दी नहीं दिखाई थी, वे इस बिल के बइस में उनके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि The wisdom has come very late (बुद्धि देर में आयी है।) अगर यह विज़्डम उनमें पहले आती तो यह दिन न देख पाते और किसी न किसी तरह से उनका वजूद यहां पर रहता।

मैं फिर कहता हूँ कि उनका यह कहना कि जमींदारी प्रथा हमेशा से चली आई है ग़लत है। हिन्दुस्तान में यह प्रथा अंग्रेजों के पहले कभी नहीं थी। अगर आप इतिहास को देखें तो पायेंगे कि मनु के समय में प्राचीन भारत में गाँव एक छोटे-छोटे ग्राम राज्य थे। राजा सिर्फ़ १६ हिस्सा करके रूप में उपज का लेते थे और गाँववालों को पूरा अधिकार था कि वे जैसा चाहें इंतजाम करें। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल बादशाहों ने भी इसमें कोई दस्तन्दाज़ी नहीं की थी। टोडरमल का जो बन्दोबस्त हुआ था वह भी बिल्कुल रयतवारी के ऊपर हुआ था। लेकिन जब अंग्रेजी राज्य बंगाल में आया तो १७६७ में ला० कार्निवालिस ने परमानेण्ट सेटेलमेंट के नाम से एक बन्दोबस्त लागू किया और उस सेटेलमेंट में जमींदारों को ठेका दिया। यह ठेका भी इस आधार पर दिया था कि अगर पहली तारीख के शाम तक रुपया वसूल जमींदारों से नहीं होता तो उनकी जमींदारी नीलाम करके दूसरे को दे दी जाती थी। सरकार ने सोचा कि इस तरह से रुपया वसूल करने में कोई दिक्कत नहीं है और इसमें अगर कोई बदनामी होती है तो जमींदारों की ही होती है और अंग्रेजी सरकार को इससे कोई बुरा भला नहीं कहता। उन्होंने इस तरीके को इस लिये और निकाला कि किसी तरह से अंग्रेजी राज्य की जड़ इन ठेकेदारों की सहायता से पुख्ता बना दी जाय। इस जड़ को पुख्ता करने के लिये उसने लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि देहात में एक इस तरह की क्लास पैदा करे जो अंग्रेजी राज्य से फले और फूले। अगर उसे ताकत मिलती रहेगी तो वे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करते रहेंगे। क्योंकि वे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही फलेंगे और फूलेंगे। इस तरह से जमींदारों को ताकत और कायदेक़स दिये गये ताकि उनका रुपया भी आसानी से इकट्ठा होता रहे और उनकी जड़ भी जम जाय और सरकार आखिर तक यही करती रही। सन् १९३६ तक जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य रहा और कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में नहीं आई अंग्रेजों का राज्य इन्हीं दो उसूलों पर चला। जो भी बड़े-बड़े ओहदे होते थे वे सब जमींदारों को ही फा० नं० ७

[ श्री श्रीचन्द्र सिंघल ]

दिये जाते थे और जो कानून आते थे वे सब ज़मींदारों के पक्ष के होते थे। किसानों के हक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इस तरह से ज़मींदारी चली और देश के लिये, जनता के लिये और किसानों के तथा खेती के लिये किसी काम में कोई तरक्की नहीं की गई। जो कुछ उन्होंने किया वह यही कि उन्होंने ग़रीब किसानों का खून चूसा और यही कारण है कि ज़मींदार इतने बदनाम हुए। हिन्दुस्थान में जितनी भी रूलिंग क्लासेज़ हुई हैं चाहे वे मुग़ल हों, मंसबदार हों, मरहठे हों या और कोई आज तक हर एक की निशानी मौजूद है। लेकिन ज़मींदार भाइयों के चले जाने के बाद उनकी कोई यादगार शेष नहीं रहती है कि उन्होंने देश में क्या काम किया। उन्होंने न इमारत बनवाई, न किसी कला को जन्म दिया। उन्होंने तो केवल एक काम किया और वह यह कि अपने देशवासियों का खून चूसा। अफ़सोस तो यह है कि इतनी बड़ी प्रथा का अन्त हो गया लेकिन देश में कोई भी आदमी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहा है। किसी ने भी उनके लिये सहानुभूति के दो आँसू भी नहीं बहाये। हमने जो यहाँ कानून बनाया है उसमें किसी प्रकार की न तो बदले की भावना है और न कोई बात ऐसी है जिससे गुस्सा जान पड़ता हो। हमने तो यह सोचा कि देश के लाभ के लिये इस प्रथा को समाप्त करना लाज़िमी है और इसीलिये इस प्रथा को समाप्त किया। लेकिन मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जमींदारों की काफी रक्षा की है। छोटे लोगों और बीच के लोगों को मुआवज़ा मिलेगा वह तो परियाप्त है ही लेकिन १० हजार रुपये से ज़्यादा के लोग जो करीब ४००।५०० हैं उनको भी मुआवज़ा इतना मिल जायेगा कि उनको अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिये कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन हाँ यह जो रईसाना ठाठ आज भुगत रहे हैं वह नहीं रहेगा। एक बात और भी है राजाओं ने कितनी आसानी से अपने मसले को हल कर लिया। हमारे ज़मींदारों से भी हमें यही आशा थी कि वे भी अपना मसला इसी आसानी से हल कर लेंगे लेकिन ज़मींदार भाइयों ने इतना नहीं सोचा।

बिल के प्रावीजन दो हिस्सों में तकसीम किये जा सकते हैं। एक हिस्सा तो यह कि सब जमीन सरकार के हाथ में पहुँच जाय और उसके सिलसिले में जो समस्यायें हों उनका हल। दूसरा हिस्सा हमारी रूरल एकोनॉमी के बारे में है। मध्यवर्तियों के बारे में उनके अधिकारों के बारे में जो कायदे और कानून हैं उनसे तो मुझे सहानुभूति है लेकिन जो आर्थिक नीति उसमें बताई गई है उसमें मुझे कुछ आपत्ति है इसके बारे में मैं आगे कहूँगा। दफ़ा २५२ में सरकार ने यह अधिकार ले लिये हैं कि किसानों से जिस तरह सरकार चाहे लगान वसूल करे और जो एजन्सी चाहे कायम करे। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा अधिकार है। सरकार को इसके बारे में कानून बना कर लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने पेश करना चाहिये। हमें डर है कि जो चीज़ हम ख़त्म कर रहे थे वही चीज़ फिर दूसरे रूप में कहीं न आ जाये। अगर किसी तरह से यह अधिकार तहसीलदारों या उनके नीचे के लोगों को मिल गया तो जनता सुखी नहीं होगी सरकार ने यह बतलाया है कि अगर सरकार मुनासिब समझे तो लगान वसूल करने का काम ग्राम पंचायतों को दे सकती है। इसके लिये भी हमारे सामने कायदे कानून आने चाहिये। देहात में जो गांव पंचायतें बनी

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्त य जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३२१

हैं वह बहुत अच्छी हैं लेकिन यह एक नया ऐकमेरीमेंट है शायद इसकी वजह से कहीं किसानों को दिक्कत न उठाना पड़े, चेप्टर ७ में सरकार ने ग्राम समाज और ग्राम समाजों के बारे में बताया है। यह दो चीजें पुरानी समस्या में नहीं आती हैं। सरकार ने ये दो चीजें क्यों रखी हैं। दोनों में कर्गद-कर्गव तानने एक ही हैं तो फिर ये डुप्लीकेशन क्यों किया गया है। हम बात को सरलतर को सरल कर देना चाहिये और एक बात यह है कि ग्राम समाज को जो ताकत दी जा रही है वह बहुत बड़ी ताकत है। उनको यहां तक ताकत दी जा रही है कि जिनकी जमीने खाली होंगी या खाली हैं या जितने बंजर होंगे, हाट बाजार होंगे मिगाड़ा बंगरा बाने के पोखरे होंगे उनका इंतजाम ग्राम समाज ही करेंगे। क्या सरकार का यह ख्याल है कि वह हम तानत का दुहनयोग नहीं करेंगे कर सकते हैं। इस बात का भी हमें खयाल रखना चाहिये कि देहात के आदमी पढ़े-लिखे नहीं होते हैं।

दफा २६५ में सरकार ने यह बताया है कि अगर १० आदमी मिलकर ५० एकड़ से ज्यादा जमीन में शामिल हो जायेंगे तो उनको सरकारी समिति बनाने का हक होगा। दफा २८८ के अनुसार ऐसी संस्थाओं को कई तरह की सुविधायें मिलेंगी। और भूमि भी मिलेगी परन्तु बड़े-बड़े जमींदारों का जमीन देना में गलत समझना हूँ। दफा २६६ के अन्तर जो सोसाइटीज बनेंगी उनमें तो छोटे-छोटे काश्तकार होंगे परन्तु दफा २६५ के अनुसार जो सोसाइटीज बनेंगी उनमें बड़े बड़े जमींदार ही होंगे। मेरी समझ में जो छोटे काश्तकारों को सोसाइटीज बनें उन्हीं को सुविधायें मिलनी चाहिये।

जो गरीब मजदूर हैं उनके लिये सरकार ने इस बिल में कुछ नहीं किया है। दफा १६५ में जरूर जिक्र आता है कि अगर ग्राम पंचायतें ठीक समझें तो वह बची हुई जमीन या खाली जमीन मजदूरों को दे सकती हैं। मैं समझता हूँ कि यह काफी नहीं है। ग्राम पंचायत में अगर कोई जमीन खाली होगी तो मेरा अन्दाजा यह है कि वह जमीन मजदूरों को नहीं मिलेगी बल्कि सब आपस में बांट लेंगे। इस तरह जमींदारों के हटने से मजदूरों को कोई फायदा नहीं होता है। उनको फायदा पहुँचाना सरकार का बड़ा भारी फर्ज है।

अनइकोनामिक होल्डिंग के बारे में भी सरकार ने कोई खास इन्तजाम नहीं किया है। सरकार ने यह जरूर किया है कि जहाँ अनइकोनामिक होल्डिंग हो वहाँ अगर दो तिहाई आदमी कलेक्टर के यहां दरखास्त दे कि हम कोओपरेटिव फार्म चाहते हैं तो कलेक्टर बचे हुये लोगों को बुलायेगा। उनकी दरखास्त सुनने के बाद वह सोचेगा कोओपरेटिव सोसाइटी बनाने की परमिशन दूँ, या न दूँ। इसके बाद भी उस आर्डर की अपील करने का हक है। जब एक तरह से वह अपील नहीं जीत सकते हैं तो कोओपरेटिव सोसाइटी बन सकती है। एक तिहाई आदमी रह गए हैं उनको मुआविजा मिल जायगा। सरकार ने सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए इतना सोचा है। जहाँ तक अनइकोनौमिक होल्डिंग वाले हैं यह चाहें तो कोओपरेटिव सोसाइटी बना सकें। इस से देश का भला हो जायगा। आर्थिक उन्नति मेरे समझ में नहीं आई। आर्थिक दृष्टि से फायदा नहीं पहुँचेगा। आर्थिक दृष्टि से ३-४ बातें सोचनी हैं। एक तो देहात में जो गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं। उन्हें साल भर में कुछ दिना के लिए काम मिलता है और ज्यादातर बेकार रहते हैं। वह परेशान हैं उनके रहने को मकान नहीं है। मजदूरी नहीं है। मैं देहात का रहने वाला हूँ। बुरी हालत

[ श्री श्रीचन्द सिंघल ]

है उनकी । जमींदारी एवालिशन के बाद उनको फायदा होना है । उनका ध्यान करना है । जो अनइकानामिक होल्लिंग है उसको इकानामिक बनाने का प्रयत्न नहीं किया है । ६३ एकड़ जमीन को इकानामिक समझा जायगा । मेरी समझ में यह कम से कम १२ एकड़ हो इन से कमती जो जमीन है वह अनइकानामिक डिक्लेअर करना चाहिए । जो इस डेफिनिरन में आ सकती है । फिगरस देखने से सरकार देखेगी कि १२ एकड़ से कम जमान इकानामिक हो नहीं सकती है । दूसरे यह कि किसी आदमी की ६-७ एकड़ जमीन है और चारों तरफ फैली हुई है । उसकी सरकार को सफ़ाई करना चाहिये । उसकी सफ़ाई के बिला फायदा नहीं है । मुझे अनइकानामिक प्लॉट के बारे में कहना है । जिस आदमी के पास २-३ बीघे जमीन है क्या वह बैल रख सकता है ? अगर रखता है तो चारा कहाँ ले खिला सकता है । न उसके पास १२ महीने काम है । थोड़े दिन काम करने के बाद बेकार हो जाता है । फिर जब फसल बोनो का अवसर आता है सीड नहीं मिलता, कुआँ खोदने के लिए रुपया नहीं है । अगर इन चीज़ों के लिए कर्ज़ लेता है । कोई खाद नहीं है । गोबर खाना पकाने के काम आता है । दूसरी समस्या जो है वह खेती के तरीके हैं । कोई कितनी ही तारीफ़ करे । पुरानी बातें अच्छी समझी जाती हैं । वह तरीके इतने ग़राब हैं कि उनसे देश का कोई लाभ नहीं है । ७५ फीसदी आदमी देहात में रहते हैं । वह खेती के काम में लगे हुए हैं । अफसोस यह है कि इतना करने पर भी और जमीन होने पर भी इतना ग़ल्ला नहीं होता है कि हम अपने प्रांत का पालन कर सकें । पेट भर सकें । मैं आपके सामने आँकड़े पेश करता हूँ कि दुनियाँ में किस हिसाब से किस तरह गेहूँ हो रहा है । हमारे देश में फी एकड़ ५ हंडरवेट, यू० एस० में ५ पौंड ६ हंडरवेट, यू० एस० ए० में ६ हंडरवेट, कनाडा में ६ हंडरवेट, यू० के० में १६ हंडरवेट, चीन में ८१ हंडरवेट आस्ट्रेलिया में ५ हंडरवेट जो बड़े देश हैं जैसे अमरीका इत्यादि, वहाँ पर जो पैदावार है वह करीब-करीब इस देश के बराबर है ।

लेकिन डेनमार्क में हिन्दुस्तान के करीब-करीब चौगुनी पैदावार है, यूनाइटेड किंगडम में भी चौगुनी है तथा फ्रांस में भी करीब-करीब इतनी ही है । तो ये आँकड़े बड़ी होशियारी से समझने चाहिए । फिर मैं देखता हूँ कि अमेरिका में हिन्दुस्तान के बराबर पैदावार है । हमें यह देखना है कि हिन्दुस्तान में कितनी जमीन काम में आ रही है और रूस और अमेरिका में कितनी जमीन काम में आ रही है । अमेरिका में एवरेज होल्लिंग १२० एकड़ के है और हिन्दुस्तान में डेढ़ एकड़ के करीब एवरेज होल्लिंग है । तो इस तरह से वहाँ पर जो खेती की जा रही है वह बड़े लम्बे पैमाने पर की जा रही है । यूनाइटेड किंगडम जहाँ एवरेज होल्लिंग २० एकड़ है वहाँ पर जो खेती की जा रही है छोटे पैमाने पर की जा रही है और वहाँ इन्टेसिव खेती की जा रही है जिससे वहाँ पर उपज प्रति एकड़ ज़्यादा होती है । अमेरिका में जो जमीन जोती और बोई जाती है उसका एरिया हिन्दुस्तान से चौगुना है उसमें इतना गेहूँ पैदा होता है कि वह केवल अमेरिका के लिए ही पूरा नहीं होता बल्कि संसार के और देशों को भी एक्सपोर्ट होता है । वहाँ पर जो ग्रामीण आबादी है वह करीब-करीब दो करोड़ के है । उनमें ८५ लाख लोग ऐसे हैं जो खेती के काम में एक्जुअली लगे

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३२३

हूँ हैं वे वहाँ ८५ लाख अदनी इतना खेत जोतते हैं जो हिन्दुस्तान के एरिया से चौगुना है ५० लाख २५० अंगु में १० फी सदी अदनी देहातों में रहते हैं। वहाँ पर खेती ही नहीं बल्कि इण्डस्ट्रीज में भी आनी लग्नकी हुई है। वहाँ पर इण्डस्ट्रीज का कोटा ८० प्रतिशत है।

श्री राजाराम शास्त्री—डिप्टी स्पीकर महोदय, क्या किसी मेम्बर को इस हाउस के सनने टाइन को हुई मिताव में गड्डने का अधिकार है ?

डिप्टी स्पीकर—वे अकड़े नड रहे हैं ; यह तो क्लिप में होगा या कहीं टाइन किया हुआ होगा ई इनको नहीं रोका जा सकता है !

श्री अचन्द्र मिश्र—वे वॉल रमेंट जो एग्जिक्यूटिव का कोटा बचता है उसने इतनी ज्यादा पैदावार नहीं है कि वह अकड़ खेत के लोगों के गुजर के लिए ही काफी नहीं होती बल्कि वे बड़े भी एक्स्पेंड कर देते हैं ; तो नरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान में जमीन बरबाद हो रही है और सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक्स्पेंसिव फार्मिङ के बदले इन्टेन्सिव फार्मिङ करना, अगर ऐसा करने को कोशिश की जायगी तो खाने की समस्या अपने आप हल हो जायेगी, मे सरकार ने नज़रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि तीन एकड़ में कम को इंटेंडिंग किसी की जेत में न हो और तीस एकड़ में ज्यादा होल्लिंग जिनके पास हो वहाँ पर कंजर्वेशनरेटिव संसाइटी बनाकर ज्यादा जनोनें उनको दे दी जायें। इसी तरह मे वहाँ की समस्या हल हो सकती है। जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं जिनकी फील्ड कम है उनको फील्ड बढ़ाने की कोशिश करना चाहिये जिससे हमारे यहाँ की हालत सुधरे। हमारे देश को हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। सन् १९४७ ई० में एक अरब साठ करोड़ का नाज हमारे देश को बाहर से मँगाना पड़ा और ट्रेड बैलेंस भी करीब ७० करोड़ के हिन्दुस्तान के खिलाफ रहा। तो इस पर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिये।

हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, हमारे जो प्रीमियर साहब हैं उनका कहना है कि हमें इस समस्या को पूरी तौर से हल करना चाहिये। अगर यह समस्या नहीं सुलझती तो देश गारत हो जायगा। उन्होंने बतलाया है कि हमको फूड की समस्या को बार फूटिंग पर लाना चाहिये और जब तक हम इसे बार फूटिंग पर नहीं लायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी यही कहना है कि इस समस्या को हल करना हिन्दुस्थानियों का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन यह आसान बात नहीं है। उसमें बड़ी-बड़ी दिक्कतें हैं और हमें उन दिक्कतों को पार करना है। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि हमारे किसान भाई खेतों के नये तरीकों को नहीं समझते हैं। दूसरे यह कि खेतों की उपज भी कम हो चुकी है। तीसरे होल्लिंग भी अनइकानामिक हैं। उन्हें भी ठीक करना है। हमारे देश के लिये यह एक फायदा रहा है कि हमारे यहाँ बारिश हो जाती है? दूसरे हमारे देश में यह भी अच्छाई है जो और मुल्कों में कम है या नहीं है कि हमारे यहाँ जमीन के नीचे पानी मिल जाता है जिसे कुओं या दूसरे रूप में हम सिंचाई के लिये काम में ला सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एकनामिक प्लान के लिये इस बिल में ११वाँ चैप्टर लिखा है लेकिन मुझे इससे इख्तिलाफ है। आपने इस बात को मान लिया है कि अगर हम खेत की हद को बढ़ाते हैं तो एक खेत ५० एकड़ का होना चाहिये या ३० एकड़ का हो या जिन आदमियों के पास मिलाकर ५० एकड़ से



[ श्री श्रीचन्द सिंवल ]

ज्यादा जमीन हो वह कोआपरेटिव फार्म बना सकते हैं लेकिन इतना कहने के बाद हम फिर चुप हो गया कि आगे क्या करना चाहिये। दूसरी बात जो अनएकनामिक होलैंडिंग के लिये दी है वह भी नाकाफी है। अगर किसी को कोआपरेटिव फार्मिङ्ग बन हो तो पहले कलेक्टर के यहाँ अर्जों दे और अगर कलेक्टर राजी हो जाय तो वह कोऑपरेटिव फार्म चला सकता है। यह जो तरीका सरकार ने रखा है उससे कोआपरेटिव फार्मिङ्ग कामयाब नहीं हो सकती है और न यह एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) कारगर करना चाहेगा कि वह अपनी जमीन कोआपरेटिव फार्म को दे दे या उसकी जमीन उसके कब्जे में चली जाये और कोआपरेटिव फार्म के पास हो जाय। दूसरे वह अगर चाहे तो भी मैजिस्ट्रेट और (बहुमत) माइनारिटी (अल्पमत) की वजह से नहीं करेगा क्योंकि अगर उसकी मैजिस्ट्रेट न हुई तो उसकी मर्जी से कोई काम उसमें न हो सकेगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर सरकार इस ठोके ढालेपन से इस स्कीम को चलायाना चाहती है तो हम कोआपरेटिव फार्मिङ्ग की स्कीम को आगे बढ़ा नहीं सकते और न हम उपज को ही आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उपज अगर बढ़ सकती है तो सिर्फ एकनामिक होलैंडिंग की वजह से ही और यह कोआपरेटिव फार्मिङ्ग की स्कीम वालण्टरी होनी चाहिये। लेनिन साहब ने भी एक तर्क में कहा था कि अगर कोआपरेटिव फार्मिङ्ग वालण्टरी (स्वेच्छापूर्वक) न हो तो उनमें क्रेड वाइटीलिटी काम करने के लिये नहीं आयेगी लेकिन इतिहास कहता है कि उन्होंने नृद सख्तियों की ओर लोगों को साइवेरिया तक भेज दिया और दबाव डालकर कोआपरेटिव फार्म बनाये।

• नतीजा यह हुआ कि वह लोगों को इतनी पसन्द आई कि इतना दबाव डालने पर भी आज ३०० आदमियों में से १ आदमी ऐसा है कि जो अपनी इंडिविजुअल फार्मिंग चाहता है। नहीं तो सब कोआपरेटिव फार्मिंग पसन्द करते हैं। इसी कोआपरेटिव फार्मिंग की वजह है कि वहाँ पर इतनी तरक्की हुई। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यहाँ पर भी वह दबाव डाला जाय और दबाव डालकर इस तरह से कोआपरेटिव फार्मिंग खोली जाय। हम लालच जरूर दे सकते हैं और उस लालच के जरिये से किसान कोआपरेटिव फार्मिंग खोल सकते हैं। जो पावर आपने पंचायतों को दी है उसमें भूमि का भी कुछ अधिकार उनको दें। जैसे गाँव सभा को आप कुछ अधिकार दे रहे हैं, बाजार का इन्तजाम, हाट का इन्तजाम, पोखर का इन्तजाम, कुआँ का इन्तजाम हैं इनको आप गाँव समाज को देने का इरादा कर रहे हैं। अगर यह चीज कोआपरेटिव फार्मिंग का इन्तजाम भी उनको सौंप दिया जाय तो वहाँ पर काफी लोग इसमें शामिल हो जायेंगे। इसके फायदे के देखकर बहुत लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जायेंगे। और कोआपरेटिव फार्मिंग जब एक व दो दफा वहाँ पर चल जायगी तो इतने लोग उसको पसन्द करेंगे कि पूरा गाँव उसमें शामिल होने को तैयार हो जायगा। तो मेरी यह सरकार से प्रार्थना है कि सरकार को ऐसी बात नहीं देखनी चाहिए कि जनता इसकी तरफ आती है या नहीं जब इसके अन्दर कुछ सच्चाई उनको दिखाई देगी तो वह खुद ही इसकी तरफ आ जायगी। सच बात तो यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग के बिना हमारा काम

हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे सामने पेश किया गया है।  
हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जिस  
कारण से हमें अपने देश की सेवा करने में बाधा मिल रही है। हमारे देश इतनी ज्यादा अन्न  
की जरूरत है कि वह बहुत ही कम मात्रा में ही हो सके। हमारे देश की जमीन का जोड़ा चाहिए  
हम इसे अपने हाथों में ले सकें। इस दिल में उम्मा कहीं थोड़ा सा  
देश के हित पर ध्यान देना चाहता हूँ कि अगर  
हमें सरकार के काम करना है, उन सभी कारखानों के पास २-३ बीघे  
जमीन देकर हमें यह दिखाने में मदद करनी है, मैं ज्यादा  
काम नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत है, बड़े हैं, मुझे एक बैल की जोड़ी चाहिए  
मुझे इस काम में मदद मिले, जिसे अधिक देना होगा नंगा काम नहीं चल सकता, ताकि  
हम अपना काम पूरा कर सकें। उनके लिए एक महत्वपूर्ण आ जाना है तो उसका  
हमारे लिए यह काम करना चाहिए वह नहीं कर सकते कि भाई तुम कोआपरेटिव  
फार्मिङ्ग का काम करो और बहुत ही कम निवेश कर दो गाँव को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके  
देकर दो। उसके बाद २, ४ आठवां भी भी गये तो क्या उसने कोआपरेटिव फार्मिङ्ग  
का काम शुरू करा? अगर २, ४ आठवां उसने रक्षित भी हो जाय तो क्या वह  
उसकी मर्जी से उसे दे कि उसने वह काम करना चला सकते हैं। अगर वह दफ्तर में  
हमारे देशवासियों को देता है तो वहाँ पर उनकी बहुत सुखालिखत हो सकती है क्योंकि गाँवों  
के अन्दर बहुत सी आज कल मार्टिया बन गई हैं। तो उसका किसी तरह से भी फैलोअर  
देना है तो उसकी जिम्मेदारी आती है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारखानों  
हम यह ने तैयार हो जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस तरह का जिक्र कोआप-  
रेटिव फार्मिङ्ग का पर्याप्त जिक्र इसके अन्दर कहीं नहीं आया है। हमारी अन्न की  
मनस्सा हम यह भी है कि वह दिन कोआपरेटिव फार्मिङ्ग में हल किसी तरह से नहीं  
हो सकती। तो मेरी सरकार ने प्रार्थना यह है कि सरकार यह इन्तजाम करे कि वह  
हर एक को बचाने, हर काम का इन्तजाम किया जाय और उस काम में हर एक की  
मदद करे यह जरूरी काम है और बहुत जरूरी प्रोग्राम इसको बनाना चाहिये ताकि  
फलते अच्छे यह ने तैयार हो और देश का भत्ता हो। सरकार को चाहिये कि जो  
सरकारी बंध है उनमें हर एक सर्किल के ऊपर बांट दें। कोआपरेटिव फार्मिङ्ग के लिये  
अगर २, ४ आठवां भी यह हो जाय तो वह घर फौजन ही खोल देनी चाहिये और  
उनमें जितनी महिलाएँ सरकार दे सकती है उतनी सहूलियत देनी चाहिये ताकि और  
लेना नी जो उनमें अपने काम करने दें वह भी कोआपरेटिव फार्मिङ्ग में आने के लिये  
बना रहे जब और जहाँ हमारे क्षेत्र में कोआपरेटिव फार्मिङ्ग का काम शुरू हो जाय  
तो फिर हमारे देश में उनका बहुत सारा हमारी समस्याएँ हल हो सकें। इस इन्तजाम  
में एक डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिकल्चर कमिश्नर होना चाहिये जो कि खेली वाड़ी का इन्तजाम  
करे। उन लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिये ताकि वह काम आगे बढ़ सके। उस डिस्ट्रिक्ट  
कॉन्फेरन्स के ऊपर एक कमिटी की हैतियत ने एक बोर्ड होना चाहिये। इसी तरह से  
उसके ऊपर एक प्राइमरियल क्रमीशन होना चाहिये जिसके मातहत सारे सूबे का इन्तजाम

[ श्री श्रीचन्द सिंघल ]

हो। तब देश का भला हो सकता है। मुझे सरकार से एक बात और कहनी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को आये हुये तीन साल होगये हैं। हमारे देश की समस्यायें दिन बदिन बढ़ती जाती हैं अभी तक हम अपने यहां की हालत दुरुस्त नहीं कर सके हैं और हम इस बात से भी सन्तोष नहीं कर सकते कि हमें स्वराज्य मिल गया है। हमारे प्रान्त की हालत और प्रांतों से अधिक खराब है क्योंकि यहां पर सिवाय खेती करने के और कोई दूसरा रोजगार नहीं है। न तो और कोई काम है और न खनिज पदार्थ ही है जैसा कि बंगाल वगैरा में। हमारे यहां की जनता खेती पर ही मुनहसिर है। ७५ फ्रीसदी लोग खेती का काम करने वाले होने पर भी यहां पर हमारे लिये अन्न की कमी हो जाती है यहाँ से जो चीजें दुनियाँ के बाहर भेजी जा सकती हैं उनमें चीनी और गुड़ और तमास तिलहन हैं, इसके अलावा जो बाहर से आती हैं वह करीब करीब अनगिनती हैं यानी करीब करीब सभी चीजें बाहर से आती हैं। आप रुई को ले लीजिये, हमारे यहाँ जितनी यार्न, (सूत) या कपड़ा पैदा होता है वह करीब-करीब हमारे प्रान्त की जरूरत के मुआफ़िक आधा होता है। उस आधे कपड़े और सूत के लिये हमें ५ लाख गांठें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। अगर हमें मकान बनाना पड़ता है तो उसकी ईंटें पकाने के लिये कोल डस्ट भी बाहर से मंगानी पड़ती है। अगर हमें कोयले की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है तो वह बाहर से मंगाना पड़ता है। इस तरह से हमारे प्रान्त की माली हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अगर माली हालत का सुधार करना है तो सरकार को खादी पर पूरी तवज्जह लगा देनी चाहिये। सब ताकत खादी की तरफ़ पहुँचनी चाहिये और मैं समझता हूँ कि खादी का डेवलपमेंट करने के लिये जो रूस के तरीके हैं, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज़ रूस में खुली हैं वह सबसे अच्छी हैं, उन्हीं का अनुसरण हमको करना चाहिये। मैं रूस की बहुत सी बातों के बिलकुल खिलाफ हूँ वहाँ पर जो तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं वह बहुत ही निन्दनीय हैं, लेकिन जो तरक्की उन्होंने की है उसकी तारीफ़ किये बिना नहीं रह सकता। देश के हर अंग की तरक्की आवश्यक है इसी प्रकार जैसे कि शरीर के हर अंग की तरक्की जरूरी है। अगर शरीर का कोई हिस्सा तरक्की करता जाय और कोई वैसे का वैसे ही रहे तो शरीर बेढंगा रहेगा। अगर शरीर में एक आँख बड़ी हो जाय और दूसरी ज्यों की त्यों रहे तो कितना भद्दा मालूम होगा तो इस तरह से जब तक शरीर का हर एक हिस्सा तरक्की नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं की जा सकेगी। इसी तरह से जब तक राजनीति का हर एक अंग तरक्की नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं हो सकती। मैंने रशा के बारे में काफी लिट्रेचर पढ़ा। किसी ने रशा की तारीफ़ की है किसी ने बुराई। मैं उल्भन में पढ़ गया। सन् १९३१ ई० में कवि रवीन्द्र रूस पहुँचे और उन्होंने जो वहाँ के बारे में लिखा है वह पढ़कर खुशी होती है। मैं सुनाना चाहता हूँ कि तरक्की किस तरह की होनी चाहिये : —

“जो मूक थे, उन्हें भाषा मिल गई। जो मूढ़ थे उनके मन पर से पर्दा हट गया है, जो दुर्बल थे उनमें आत्मशक्ति जाग्रत हो गई है। जो अपमान के नीचे दबे हुए थे आज वे समाज की अन्ध कोठरी में से निकलकर सबके साथ समान आसन के अधिकारी हो गये हैं। इतने ज्यादा आदमियों का इतनी तेजी से ऐसा भावान्तर हो जायगा, इस बात की कल्पना

करना कठिन है। जमाने में सूखी पड़ी हुई नदी में शिन्ना की वाढ़ आई है, देखकर हृदय पुलकित हो जाता है। देश में इस छोर से उस छोर तक सर्वत्र जाग्रति है। इनकी एक नई आशा की वीथिका मानो दिगन्त पार हो गई है, जीवन का वेग सर्वत्र पूरी मात्रा में मौजूद है। इन तीनों चीजों को लेकर अत्यन्त व्यस्त हैं। शिन्ना, कृषि और यंत्र। इन तीन रास्तों से सम्पूर्ण जातियों को एक करके हृदय, अन्न और कर्मशक्ति को सम्पूर्णता देने के लिये ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे देश की तरह यहां के लोग भी कृषि जीवी हैं। परन्तु हमारे यहां की कृषि एक ओर से मृढ़ है और दूसरी ओर में असमर्थ, शिन्ना और शक्ति दोनों ही से वंचित। उसका एकमात्र क्षीण आश्रय है प्रथा, वान दादों के जमाने के नौकर की तरह वह काम करती है कम आर कर्तव्य करती है ज्यादा। जो उसे मानकर चलेगा, वह आगे बढ़ नहीं सकता। और आगे बढ़ना ही है, क्योंकि मैकडों वपो से वह लंगड़ाता हुआ चल रहा है।”

तो यह है हमारे कवि सम्राट टेंगोर जी का कहना। उन्होंने लिखा है कि रूस ने ८ साल में इतनी तरक्की की है कि आश्चर्य होता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ५, ७ आदमियों को जो विशेषज्ञ हों, उनको रूस भेजे और इस बारे में देख भाल करे कि वहां के लोगों ने कैसे तरक्की की और वही बातें यहां पर भी लागू हों। यह जरूर है कि मैं रूस की तरक्की को स्थायी तरक्की नहीं समझता। वहां पर जो तरक्की है वह है दुनियावी तरक्की, वह है भौतिक तरक्की। जब तक भौतिक तरक्की का आध्यात्मिक तरक्की में मेल नहीं खाता है तो वह स्थायी नहीं रहती है। हमारे उपनिषद् में कहा है कि वह आदमी मूर्ख है कि जो “क्राइनाइट” को देखता है, जो सिर्फ संसार को देखता है। वह आदमी उससे भी मूर्ख है जो सिर्फ इन्क्राइनाइट को देखता है, यानी सिर्फ परमात्मा को देखता है।

होशियार वही है जो दुनिया की हद तक दुनिया को देखता है और परमात्मा की हद तक परमात्मा को देखता है। हिन्दुस्तान ने जब तक इन दोनों चीजों को देखा तब तक हमेशा तरक्की की। जैसा तुलसीदास जी ने कहा है।

जगते रहू छत्तीस हूवै, राम चरन छः तीन।

तुलसी देख विचार हिय, यह मत परम प्रवीन ॥

अगर हिन्दुस्तान इन दोनों बातों को देखेगा तो बहुत तरक्की करेगा। मैं सरकार को बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा बिल उसने पेश किया है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द पास होगा।

श्री साजिद हुसैन—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहाँ तक इस बिल का तात्पर्य है दो तीन चीजें वास्तव में हैं। एक सवाल तो यह है कि गवर्नमेंट कहती है कि ज़मींदार और ज़मींदारी बुरी चीज हैं। लिहाजा उन्हें कम्पेन्सेशन देकर अलग कर दिया जाय और उसे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गल्ला ज्यादा पैदा होगा। अब आप यह देखिये कि जहाँ तक कम्पेन्सेशन का तात्पर्य है मैं तो नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मसला है जिस पर कोई स्टास बहस की जरूरत पड़ना चाहिये, क्योंकि यह तो अक्सर होता रहता है कि गवर्नमेंट को किसी मकान की जरूरत हुई, किसी ज़मीन की जरूरत हुई, उसने अक्वायर कर लिया और किसी को कानोकान खबर भी नहीं हुई। अगर बेचने वाला सुतमइन नहीं हुआ तो उस ने अदालत में दादरसी चाही अगर आप

[ श्री साजिद हुसैन ]

किसी मकान सहन या जमीन को अगर इसी को फैला दें और फ़र्ज कीजिये कि यह तब हो कि लखनऊ के शहर को पूरा गिरा दिया जाय और उस पर एक एरोडोम बनाया जाय तो उसके लिये लें तो (अगर वह किसी असरदार आदमी का हुआ तो मुमकिन है कि असेम्बली में सवाल पूछ लिया जाय) शायद उस पर बहस हो जाय या एक रेजोल्यूशन हो जाय और बिल पास हो जाय, तो इस के मानी यह हैं कि सिर्फ़ डिग्री का सवाल है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मैं इस वक्त इस चीज को नहीं ले रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि ले लेंगे तो फिर उसको यह चीज की आठ गुना देंगे या दस गुना देंगे यह तो मामूली आदमी की बात हुई। लेकिन स्टेट की डिगनिटी का सिद्दाज होना चाहिये।

अब फ़र्ज कीजिये कि आप इंटरमीडियरी हटा देना चाहते हैं यानी स्टेट और टेनेन्ट्स के बीच में जो हैं उनको हटा देना चाहते हैं। जंगलों के बारे में और तालाब के बारे में यह चीज नहीं है। इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल में ठीक नहीं हैं। अगर वर्डिंग्स में कोई बात हो तो उसकी इस्लाह कर दी जाये। जंगलों के बारे में यह है कि गवर्नमेंट और लैंड-लार्ड के अलावा और कोई है ही नहीं। क्या वहाँ के जानवरों को टेनेन्ट्स समझा जायेगा। बहरहाल आप देखिये कि इंग्लैंड में नेशनलाइज़ेशन की पालिसी एडाप्ट की गई तो वहाँ पर जो सही कम्पेन्सेशन था वह सबको दे दिया गया इसलिये वहाँ कोई डिसेटिसफ़ैशन का सवाल ही नहीं उठा। अगर वह लोग अपनी जायदाद पास रखते तब भी उनको उतनी ही आमदनी होती जितनी कि अब होती है। अगर आप यह मानते हैं कि प्राइवेट प्रापरटी हटा दी जाये और स्टेट प्रापरटी रखना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन ओनरशिप तो किसी न किसी में जरूर वेस्ट करेगी चाहे वह लैंड लार्ड्स हो या स्टेट हो। मगर स्टेट में और वैसे आदमी में एक फ़र्क़ हो जाता है कि स्टेट के हाथ में पावर होती है। अगर स्टेट लेना चाहती थी तो जो मामूली तरीका था, उसी के जरिये लेना चाहिये था। यह बड़ी बेजा बात है। यह स्टेट की डिगनिटी और शान के खिलाफ़ चीज है।

सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने फ़ूड प्रोडक्शन का है। इसके बारे में मैं आपको चन्द लोगों के रिमार्क्स जिनको कि इसमें एक्सपर्ट कहा जाता है, पेश करना चाहता हूँ। जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में से जिसको कि आपनो अथारिटी कहना चाहिये उसके कुछ कुटेशन्स पेश करना चाहता हूँ।

“Agricultural inefficiency being one of the principal causes of India's poverty, the improvement of agriculture forms the focal centre of her economic planning.”

(“कृषि विषयक अयोग्यता भारत की निर्धनता का प्रधान कारण है और इस कारण से उसकी आर्थिक योजनाओं का केन्द्र कृषि की उन्नति ही है।”)

और आगे वह कहते हैं कि—

“A consideration of these difficulties has a chilling effect upon the most ardent enthusiast and rules out any facile optimism that the

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३२६

abolition of zamindari will, by itself, bring in an era of plenty and prosperity by removing all the impediments to increased production and assuring the cultivator a high standard of living."

( "इन कठिनाइयों पर चिन्तन करने ने वड़े आशावादी व्यक्ति के ऊपर भी निराशा-जनक प्रभाव पड़ता है और वे सब आशाएँ समाप्त हो जाती हैं जिनको अधिक उपज के मार्ग की कठिनाइयाँ दूर करके और किसान को सम्पन्नतर जीवन की आशा देकर, ज़मींदारी का उन्मूलन, सम्पन्नता और ऐश्वर्य के समय में, उत्पन्न करेगा ।" )

और फिर आगे वह ज़रमते हैं कि—

"While it is true that no progress is possible today until this obstacle is removed, we must remember that the zamindari system is only one among a number of factors contributing to agricultural inefficiency. It would be unfair and even risky to blame the zamindar for all the ills from which agriculture suffers."

( "यह सच है कि वर्तमान समय में जब तक यह बाधा दूर न कर दी जाय, उन्नति सम्भव नहीं, तथापि हमको यह याद रखना चाहिए कि कृषिविषयक अयोग्यता के कारणों में से यह केवल एक कारण है। कृषि में जो दोष व्याप्त हैं उन सबके लिये केवल ज़मींदार को ही दोषी ठहराना अन्याय होगा और ऐसा करने में डर भी है ।" )

यह तो आपकी रिपोर्ट है मुझे इस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अब यह यू० पी० आई० की रिपोर्ट है। मि० रतनचन्द्र हीराचन्द्र कहते हैं :—

Mr. Ratanchand Harichand, a prominent industrial magnate of Bombay, who was at Nagpur a few days ago to preside over the first annual session of the C. P. & Berar Electrical Conference, addressing a press conference said that he was of opinion that the abolition of zamindari would defeat its own purpose, in the sense that it would lead to fragmentation of land when the consolidation of land was the need of the hour to ensure large scale farming.

( "श्री रतनचन्द्र हीराचन्द्र जो बम्बई के एक प्रमुख व्यापारी हैं और जो कुछ दिन पहले मध्य प्रांत और बरार की इलेक्ट्रिक कान्फ़रेन्स के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में, समापति बनकर नागपुर गये थे, उन्होंने प्रवक्तारों की कान्फ़रेस में यह कहा कि उनके मतानुसार, ज़मींदारी का उन्मूलन हो जाने से वह उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा जिससे उन्मूलन किया जाता है, क्योंकि इससे भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जायगी जबकि बड़े पैमाने पर खेती कराने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि को समाहित रखा जाय ।" )

यह सेशन नागपुर में हुआ था उसमें वह आगे फरमाते हैं :—

He suggested that as an effective solution of the problem it would be better that zamindari areas be run on the basis of a limited concern to be managed by the zamindars under the supervision of

[ श्री साजिद हुसैन ]

government who should get 10 per cent of the profit, i. e., the government.

Speaking about the labour and agrarian unrest in the country, Mr. Ratanlal said that it was not genuine, but was fomented by leaders with ulterior political motives rather than the professed economic ones.

( उन्होंने यह सुझाव दिया कि समस्या को हल करने के लिये यह होगा बेहतर कि ज़मींदारी के क्षेत्रों को लिमिटेड व्यवसाय के आधार पर चलाया जाय जिसका प्रबन्ध ज़मींदार लोग सरकार की देख भाल के अन्तर्गत करें और सरकार को लाभ का दस प्रतिशत मिले । )

देश में मजदूरों और किसानों की अशान्ति के विषय में बोलते हुये श्री रतन लाल ने यह कहा कि यह झूठी अशान्ति है जिसको नेताओं ने आर्थिक उद्देश्यों की आड़ लेकर, केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उत्पन्न किया है ।

यह उन लोगों का ख्याल है कि जो बिजिनेस वाले लोग हैं और एक सही नजर रखते हैं । एक साहब जो चैम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेंट हैं वह फरमाते हैं और जब वह इस दर्जे पर पहुँचे तो उनमें कुछ न कुछ सलाहियत तो जरूर ही होगी । वह कहते हैं :

The President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, in a memorandum submitted to our Prime Minister, said that the Federation also thinks that the abolition of zamindari will have serious repercussions on the financial stability of the country.

( हमारे प्रधान सचिव को भेजे गये एक स्मरणपत्र में फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री के प्रेसीडेंट ने यह कहा कि फेडरेशन का भी ख्याल है कि जमींदारी के उन्मूलन से देश की आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । )

बहरहाल यही वह नकायस हैं कि जो लोगों ने पेश किये हैं और वही मैंने आपके सामने पेश किये । आपको यह देखना चाहिये कि आप जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं इससे फायदा मुल्क को पहुँचेगा या नहीं । यह कोई खिलौना या घराँदा तो है नहीं जो जरा देर में तोड़ दिया जाय । आप को इसके अच्छे बुरे नतायज देखने चाहिए । आप इसको अच्छा समझें या बुरा लेकिन यहां ज़मींदारों को इस तरह से बुरा कहना कोई असफल बात नहीं है :—

शेर :—“कूसर ढूँढ़ के पैदा किये जफ़ा के लिये”

सरकार की इस तरह की पालिसी मुनासिब नहीं है और यह किसी भी स्टेट की डिग्निति या शान के खिलाफ़ है । कहा गया कि ज़मींदार अंगरेजों के साथ रहे और हमेशा नेशनल एसपीरेशन्स के खिलाफ़ रहे । एक साहब ने उनका मुकाबला महाराजा ग्वालियर से करना शुरू कर दिया । एक इंडिपेंडेंट स्टेट का और यहां के ज़मींदारों का क्या मुकाबला ?

## सन् १८४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३३१

वह साहब खुद एक वकील होकर ऐसी बात कहते हैं जिसमें उनकी काबिलियत का अन्दाज़ा हो जाय। आपके सामने चन्द्र कोटेशनस और पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अयोध्या के ताल्लुकेदार का जिक्र करूँगा जिसको सबसे ज्यादा खैरख्वाह ब्रिटिश कहा जाता है। मैं आपको दिखलाता हूँ कि हचिसन के भारतीय गदर के कोटेशन (उद्धरण) के जगिये में मैं आपको दिखलाता हूँ कि वह खैरख्वाही कितनी थी, कितनी नामिनल थी और क्या अहमियत रखती थी।

“I must remark that Man Singh was in confinement on a revenue question. when Captain Alexander Orr., the Assistant Commissioner, who had known him for several years, begged his release, and it was entirely owing to his former long acquaintance with Capt. Orr. under the old regime that Man Singh first offered to save Captain Orr's wife and children and afterwards was induced to extend his protection to the large number he saved”

(मुझको यह कहना पड़ेगा कि मानसिंह एक मालगुजारी के सवाल पर हिरासत में था जबकि अमिस्टेट कनिश्चर कैप्टन अलेक्जेंडर ओर ने, जो उसको कई साल से जानते थे, उसकी रिहाई के लिये प्रार्थना की। पुराने शासन काल में इतनी पुरानी जान-पहचान के कारण ही मानसिंह कैप्टेन ओर की स्त्री और बच्चों की रक्षा करने को तैयार हुआ और बाद में उन बहुत से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए भी उसको तैयार किया गया जिनको उसने बचाया।)

यानी मतलब यह है कि उनके पर्सनल ताल्लुकात की बिना पर इनसानियत के नाते उन्होंने उनको बचा लिया। इसको समझ लीजिए आप टेचरी या जो कुछ कहिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो आइडिया है पेटीयाटिज़्म का उस पर लोगों ने गौर नहीं किया। इसका लाजिकल कानक्लूजन यह निकलता है कि यह भी एक किस्म की सेल्फिशनेस है। इस पर मैं विस्तार से इस मौके पर नहीं कहना चाहता। मैं चन्द बड़ी-बड़ी स्टेटस के मुतालिक अर्ज़ करूँगा जैसे महमूदाबाद :—

“At last on the 18th of June, 1857, the troops (rebels) were invited by Rajah Nawab Ali to proceed to his place at Mahmudabad about twentyeight or 30 miles north-east of Lucknow. This Raja was the first of his class in Oudh to raise the standard of revolt, and has since shown himself the bitter enemy of the British.”

(अन्त में १८ जून सन् १८५७ को फ़ौज (विद्रोही लोगो) को राजा नवाब अली ने अपने स्थान महमूदाबाद में बुलाया जो लखनऊ से उत्तर पूर्व की ओर २८ या ३० मील है। अवध के राजाओं में यह अपने वर्ग का पहला राजा था जिसने विद्रोह को और भी बढ़ा दिया और तब से बराबर वह ब्रिटिश लोगो का कहर शत्रु रहा है।)

सुनिये, ओयल के बारे में कैप्टेन हियसों का सीतापुर की मारकाट और भगदड़ का वर्णन इस प्रकार है।



( श्री साजिद हुसैन )

"We travelled all night and by sunrise arrived at the village of Oel. I was refused admittance into the fort by Raja Anrudh Singh's people, but as the ladies were suffering much from fatigue and want of sleep, I sent a man begging permission to be allowed to rest ourselves for a couple of hours. Even this request, though trifling enough, was refused. With much difficulty I obtained two of his followers, in order to secure us safe passage through his district."

( हम रात भर चलते रहे और सूर्योदय होने तक ओयल नाम के गाँव में पहुँचे । राजा अनिरुद्ध सिंह के आदमियों ने मुझे दुर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, किन्तु चूँकि थकावट से और निद्रा के अभाव से स्त्रियाँ बहुत कष्ट पा रही थीं, मैं ने दो घंटे आराम करने की अनुमति माँगने के लिये एक आदमी भेजा । यह द्योटी सी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गयी । बड़ी कठिनाई से मैं उनके दो अनुगामियों को पा सका ताकि वे लोग उनके प्रदेश से सुरक्षापूर्वक हम को बाहर पहुँचा दें । )

अब सुनिये नानपारा :—

"They started off at once then northwards in the direction of Nanpara, 22 miles north of Bahraich, the seat of a minor raja. There, however, admission was refused them and they were forced to retrace their steps."

( वे तुरन्त रवाना हो गये और नानपारा की ओर चले जो बहराइच से २२ मील उत्तर की ओर है और एक छोटे राजा की राजधानी है । परन्तु वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया और उन्हें वापस होना पड़ा । )

अब मैं चौड़ा साम्राज्य की निशानी यानी मेरी नाचीज़ स्टेट पर जो रिकार्ड है वह मैं खुद अंग्रेजों के रिकार्ड से यानी अवध के गजेटियर से पेश करता हूँ ।

"The Raja of Kotwara thought that he could oppose the British Army in its successful march across Oudh after the battle of Buxar in 1764. He was defeated and killed, bayoneted through the flowing pyjamas which, this degenerate Chhatttri thought, was a suitable panoply for the battlefield. They rose again and again. Their Chief took up the losing cause in 1857..... and was known as the archrebel of Mutiny."

( वक्सर की सन् १७६४ की लड़ाई के बाद कोटवारा के राजा का इत्याल था कि वह अवध के बीच से सफलतापूर्वक मार्च करती हुई ब्रिटिश सेना का विरोध कर सकेगा । वह हार गया और मारा गया—वही लहराता हुआ पायजामा पहने हुये मारा गया जिसको यह अवनति प्राप्त क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र के लिये उपयुक्त कवच समझता था । उन लोगों ने बार-बार विद्रोह किया । उनके सरदार ने इस विफल होते हुए कार्य को सन् १८५७ में फिर निष्पन्न करने का प्रयत्न किया और वह उस विद्रोह में प्रधान विद्रोही बन गया । )

इस बुद्धिमान इस राजा को पता में उनके यह निराश्रम हैं जिन्होंने उनका यानी  
 गंगाजी का जो छुआ सफाई है वह है उद्धरण अंगरेजों के लुकावने में भिन्न बैठिल  
 का सफाई इस सफाई में, अन्तर्गत नौ जों के, रुई से छावनी हजार खानदान के काम  
 करने, अन्तर्गत नौ जों के रुद्धि का पता में नौ दिनिव यह किया।

इसका मतलब है कि हमें अपने अन्दर के अन्धकार को दूर करने के लिए प्रयास करना है। यह प्रयास हमें अपने अन्दर के अन्धकार को दूर करने के लिए प्रयास करना है।

[illegible]

श्री विष्णुशरण दुवल्लिश—श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, आज कल एक बड़ी भारी क्रांति का युग है और मैं समझता हूँ कि तमाम इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति की लहर इस दुनिया में कभी नहीं आई। अब तक दुनिया में जिनती क्रान्तियाँ हुईं हैं उनका एकही मार्ग रहा है और वह था हिंसा का। मगर महात्मा गान्धी जी ने क्रान्ति में भी क्रान्ति कर दी। उन्होंने हिंसात्मक मार्ग को हटा कर दुनिया के सामने अहिंसात्मक मार्ग को रख दिया। हिन्दुस्तान में दोनों तरीके मौजूद हैं। कांग्रेस का तरीका, गांधी जी का तरीका अहिंसात्मक क्रान्ति का है। हिंसात्मक क्रान्ति और अहिंसात्मक क्रान्ति में बहुत बड़ा अन्तर है, दोनों के आदर्श, काम करने का तरीका अलग-अलग है। इन दोनों के मुकामानिग ह, इनकी आइडियोलोजी, इनकी टेक्टिक्स, इनके एगेंड में फंडामेंटल डिफरेंस (मौलिक भेद) है। हिंसात्मक क्रान्तिकारी को विश्वास होता है कि पाप का अंगर हमें नाश करना है तो बिना पापी को नष्ट किये पाप का नाश नहीं हो सकेगा।

वे अपने विरोधियों को हत्या करते हैं और उनके खानदान वालों को तड़पते हुए देख खुश होते हैं क्योंकि वे हिंसात्मक क्रान्तिकारी तरीकों में विश्वास करते हैं। अहिंसात्मक तरीकों में विश्वास करने वाला अपने विरोधियों के सामने सहानुभूति की भावना से अप्रोच करना है। और उसने भी वह ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करता है जिससे कि वह अपना पान छोड़ कर एक अच्छा नागरिक बन जाए। वह आदमी की इनहैरेन्ट गुडनेस (स्वाभाविक अच्छाई) में विश्वास करता है। रूस का तरीका हिंसात्मक क्रान्ति का तरीका था

[ श्री विष्णुगुप्ता दुबलिश ]

लेकिन भारत अहिंसात्मक तरीके में विश्वास करता है। भारतवर्ष में हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास करने वाली पार्टियाँ हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, रिबोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बोल्शेविक पार्टी तथा और भी छोटी-छोटी दूसरी पार्टियाँ हैं जो हिंसात्मक क्रान्ति में विश्वास करती हैं। लेकिन अहिंसात्मक क्रान्ति की प्रतिनिधि संस्था केवल एक संस्था है और वह कांग्रेस है। एक और संस्था ऐसी है जो किसी हद तक अहिंसा में विश्वास करती है लेकिन कभी वह गांधीवाद में विश्वास करने लगती है और कभी वह मार्क्सवाद में विश्वास करती है। कभी वह कंफ़ेन्सेशन देने को बिलकुल तैयार नहीं होती और कभी कहती है कि ५० लाख से ज्यादा न दिया जाय। उसका कोई बँधा हुआ प्रिंसिपल नहीं है। मेरा मतलब सोशलिस्ट पार्टी से है। इसके अतिरिक्त आर० एस० एस०, हमारे भवन की जनता पार्टी जो मुस्लिम लीग का ही विगड़ा हुआ रूप है, ज़मींदार पार्टीज़ हैं। इन्हें मैं रिबोल्यूशनरी पार्टी नहीं समझता, यह तो reactionary (प्रतिगामी) पार्टी है। रिबोल्यूशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के ज़रिये से अहिंसा को अपनाया। यह इसकी ही वज़ह है कि आज जो ज़मींदारी अबोलीशन हम करने जा रहे हैं उसमें एक सहानुभूति की भावना हमारे दिल में है। हमारे दिल में हिंसा की आग नहीं है। हम चाहते हैं कि ज़मींदारों को मुआवज़ा दें। हम उनको तथा उनके बच्चों को तंग करना नहीं चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ज़मींदारों में कोई निकम्मापन न रहे। अंग्रेजों के साथ भी हमारा यही व्यवहार था। रूस में ज़ार का तमाम ख़ानदान मौत का शिकार बना। किसी रिश्तेदार तक को नहीं छोड़ा। तमाम प्रिन्सेज और ताल्लुकदारों को ख़त्म कर दिया। सिवाय उनके जो भाग गये, कोई नहीं बचा। लेकिन यहाँ उसके बिलकुल विपरीत व्यवहार हुआ। हमारी क्रान्ति विरोधी को मजबूर कर देती है कि वह हमारे तरीके को इस्तिहार करे और यह कि उसको यह ज्ञात हो जाता है कि उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजों से हमें कितनी नफ़रत और घृणा थी। लेकिन १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जब कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गये और उन्होंने हमारे रास्ते को इस्तिहार कर लिया और महसूस किया कि इससे मुनासिब और सही रास्ता और कोई नहीं हो सकता है, नतीजा यह हुआ कि वह बालबच्चों सहित राज़ी से यहाँ से चले गये। उस दिन से हमारे दिल में उनके प्रति जो गुस्सा था एकदम गायब हो गया। दूसरा क़दम अहिंसात्मक क्रान्ति का सरदार पटेल ने रियासतों के सिलसिले में उठाया। रियासतों के वे राजे महाराजे और नवाब जिनसे कि पब्लिक बहुत ही ज्यादा नाराज़ थी जिन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़े जुल्म किये थे, जो भी इन रियासतों के अन्दर रहे हैं या गये हैं जिन्होंने वहाँ की हालत को देखा है, वही इन जुल्मों का अन्दाज़ा लगा सकते हैं। अगर यह राजा लोग मुकाबिला करते तो नतीजा इसका क्या होता? वह उन फ़ॉर्सेज़ की मदद करते जो हिंसात्मक क्रान्तिकारी फ़ॉर्सेज़ हैं और फिर नतीजा यह होता कि प्रजा उनके खिलाफ़ उठ जाती और उनका ख़ात्मा कर देती। आज उनकी प्रजा के दिल में उनके प्रति कोई ख़ास गुस्सा नहीं है। इसी तरह अब दूसरा बड़ा ज़बर्दस्त क्रान्तिकारी कदम ७ जुलाई को पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने उठाया है और वह यह है कि उन्होंने इस बिल को इस

हउम के सन्ने जेग किया है मेरे एक भाई जमींदारों की दुहाई देने के लिये खड़े हुये  
 ५ - ७६ - ३ अंग्रेजों के अंग स्टेट्स के अत्याचार में कहीं ज्यादा अत्याचार जमींदारों  
 के थे जमींदारों के अत्याचारों को अगर लिया जाय तो हिमा से केप कमोरिन तक  
 वह निरुद्ध नहीं हैं नकली मैं नकल नकली रखता हूँ उनके अत्याचारों का उनके सामने  
 ओर इस तरह के दस्तावेज अत्याचार होते थे। काकोरी केस में सजा होने के बाद जब मैं  
 मैंने जेल में था तो वह मुझे एक शब्द मिला। मैं डकूमंटरी चीज आपके सामने रख  
 रहा हूँ उसका नाम दस्तावेज है वह अवध की एक बड़ी रियासत का जिलेदार था।  
 मेरे उस वह अदालत उसको अजन्म कैद की सजा हुई थी। उसने यह कहा कि मेरी रहम  
 की इच्छा है कि वह दंडित है मैंने उसने कहा कि अगर आप अपने फैसले को नकल ले  
 आएं तो मैं आपको दण्डित रख दूंगा। वह जजमेंट की नकल ले आया। उसका  
 मुकदमा यह था कि गांव के किसी गरीब किसान की लड़की के साथ उसका नाजायज तात्सुक  
 हो गया था। उस केचारे किसान ने अपना मानला पंचायत के सामने रक्खा। इससे  
 जिलेदार स्ट हो गया। उसने कुछ गुण्डों को लगाकर उस किसान के साथ यह सलूक किया  
 कि उसके जवान नरेश दी गई, उनके कानों के पर्दे फाड़ दिये गये, उसकी आँखें फोड़ दी  
 गई और उसके दोनों हाथ और पैर काट दिये गये। इत्तनाक की बात है कि वह आदमी  
 मरा नहीं। जज ने उस फैसले में यह लिखा था कि अगर कोई कानून की खामी मुझे  
 नजर आई है तो आज, और वह यह है कि मैं उसे फाँसी की सजा नहीं दे सकता हूँ। मैं  
 कोष गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो ईश्वर ही रहम दे सकता है मैं यह मानता हूँ  
 कि वह एक व्यक्ति का जेल था और वह भी जमींदार नहीं था मगर बाद में तात्सुकदार  
 सहव ने उसकी रहम दरखास्त दिलाई और वह उसमें छूट गया—इस तरह की  
 चीजें रोज हुआ करती थीं। इन्सान की इन्सानियत का खून होता था। मेरे मेरठ के जिले  
 में एक गाँव ऐसा है जिसमें जमींदारी दूसरों की है और एक गाँव ऐसा भी है जिसमें भाई  
 चारे की जमींदारी है। आप को दोनों का अन्तर मालूम हो जायगा लोग सिर उठाने  
 के कदिल नहीं हैं दूसरे के लंग आत्माभिमान हैं। १०-१५ साल पहले अगर आप  
 अवध के गांवों को देखते तो आपको पता लगता कि जमींदारी से लोगों की  
 क्या हालत है। मैं जमींदार और जमींदारी को अलग-अलग रख रहा हूँ। मैं जो  
 कुछ कह रहा हूँ वह जमींदारों के लिये कह रहा हूँ। इसलिये जमींदारों को इसे बुरा नहीं  
 मानना चाहिये। शायद उनकी जगह मैं अगर होता या और कोई होता तो मुमकिन है  
 कि उनका भाग रखा यही होता। मैं अपने जमींदार भाइयों से यह बात कहना चाहता हूँ  
 कि आपने नहीं कितनी ही बहादुरी दिखलाई हो लेकिन जब से अंग्रेजों का इस सूवे में  
 कदम पड़ा है तबसे आप उनके साथ रहे हैं और हर बात में उनका साथ दिया है। मैं  
 आप से यह कहता हूँ कि आप उनका एक चीज में और साथ दीजिये और वह यह है कि  
 अंग्रेजों का जो आज़िज़ इस मुल्क में हुआ है वह काफी शानदार हुआ है। जिस शान के  
 साथ वह गए हैं उसी शान के साथ आप भी जाइये। अगर कांग्रेस जमींदारी खत्म नहीं  
 करेगी तो वह अपने रेवोल्यूशनरी रोल को पूरा नहीं करेगी और हमारे प्रान्त के और  
 देश के किसान उन क्रान्तिकारी शक्तियों से मिल कर जमींदारी को खत्म कर देंगे। नवाब  
 फा० नं० ६

[ श्री विष्णुशरण दुबलिश ]

मुहम्मद यूसुफ ने एक धमकी दी थी कि अगर ज़मींदारी स्वतन्त्र की गई तो मैं कम्प्यूनिस्ट बन जाऊंगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि कम्प्यूनिस्ट जिस तरह ज़मींदारी के प्रादुर्भाव हैं उसी तरह ज़मींदार के भी हैं। आपके यह कहने से कि आप कम्प्यूनिस्ट बनने जा रहे हैं वे आपको बख्शेंगे नहीं।

आप खामखा चिल्ला रहे हैं। मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। आपको जिन मुआवज़ा मिल रहा है, मैं साबित कर सकता हूँ फ़िर्गर्स से कि यह ठीक है और आप की नेट (असली) इनकम से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर ५ सौ के मालगुज़ार को लेता हूँ, उसको ८ गुना देते हैं मुआविज़ा और रीट्रिविलिटेशन ग्रांट ८ गुना। किन्हीं की आमदनी एक सौ रुपया है तो १६ सौ रुपया उसको मिलेगा। वह १६ सौ रुपया किसी इन्डस्ट्री में लगा सकता है और शेअर्स खरीद लेता है तो उसकी आमदनी ६५ से सौ के लगभग हो जाती है। इसी तरह ५ सौ के मालगुज़ार की ज़मींदारी जाने में कोई नुकसान नहीं है। २५ रुपये की मालगुज़ारी वाले ज़मींदार अपना रुपया इन्डस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा उसकी आमदनी एक रुपये के बजाय एक रुपया १२ आने हो जाती है। ६५ सौ रुपये का जो जमींदार है उसकी आमदनी भी एक रुपये के बजाय एक रुपया १२ आने हो जाती है। बड़े से बड़े जमींदार की जो नेट इनकम अगर सौ रुपये है तो ५० रुपये फिर भी रहते हैं। वह अपनी मुआविज़ी की रकम रोजगार में इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आपके सीर, खुदकाश और बागात तो नहीं लिये जा रहे हैं। उनकी आमदनी में तो कोई कमी होगी नहीं। उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े जमींदार जैसे महाराज बलरामपुर हैं उनकी आमदनी एक रुपये के बजाये १२ आने रह जायगी। बेशक नज़राने बग़ैरा की जो इल्लीगल और गैर कानूनी आमदनी है, उसका सवाल नहीं। एक रुपये में १२ आने जमींदार को मिलते हैं और वह जमींदारी के भूकट से छूट जाता है। दूसरे कामों से वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ किसानों की सद्भावना उनके साथ रहेगी। यह ठीक है कि कुछ जमींदार घर हैं, जिनकी बहादुरी की पुरानी हिल्ली है। आज़ाद भारत की फ़ौज़ें हैं उनमें उनके बच्चों को नौकरी मिल सकती है, उनके लड़के डाक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, देश के वफ़ादार नागरिक बन सकते हैं। जमींदारी एबालिशन से उनका कोई नुकसान नहीं। ६६.५ जमींदार ऐसे हैं जिन्हें कि किसी तरह का नुकसान नहीं। बड़े-बड़े जमींदार हैं उनका कुछ नुकसान है मगर वह इतना कम है कि वह आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त जमशेदअली ख़ाँ ने कहा कि किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुँवर जगदीश प्रसाद के नोट मैंने देखे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान का इतना फ़ायदा है। ५ परसेंट सूद पर सरकार उनसे रुपया ले रही है। ५ परसेंट सूद मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इस ऐक्ट के बनने से पहिले ८% किसान १० गुना रुपये दाखिल करेगा। क्योंकि किसान का इतना जबरदस्त माली फ़ायदा है जो खुद काश्तकार की ज़मीन है मेरठ के जिले में ४ सौ रुपये कच्चा बीघा पानी की और ३ सौ रुपये कच्चा बीघा खाकी उसके दाम हैं। औसतन ३ सौ रुपये

अच्छे दान हैं। जब लगान छूटा हो जायगा तो खर्च कम हो जायगा और जमीन का दान और बहुत जायगा जो मैं नहीं लगान देने वाला हूँ। उनके पास ६० बीघा मेरठ में हैं जहाँ जंगल लगान है क्योंकि मेरठ जिले में नदने ऊँचा लगान है। दूसरे जिस जिले में ७०-८० बीघे होंगे किमान ६० बीघे का नालिक दान जाता है। उसको ट्रस्टर का राइट मिल जाता है जो वह तीन बीघे में छत्र लगान का दान गुना अदा करेंगे। और ५७ बीघे उसके पास रह जायगा। इस तरह में किमान में जो कुछ लिया जा रहा है उसमें २० गुना ज्यादा उने मिल रहा है। वह १ हजार देता है तो २० हजार का नालिक दान जाता है। यह बिल जो हमारे सामने आया है इसको कने मैंने किमानों के जलमें मैं उनके मानने कहीं भेरा न्याय है कि जिन वक्त तक यह देखत होंगा, उन वक्त तक ६८ मीसदी रुपये किमान जमा कर देंगे।

इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है कि २५ की नदी किमान अपना रुपया जमा कर देंगे। मैं देखता हूँ कि जब किमान अपना मुआविजा दे देंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं है बल्कि बड़ा भारी नायदा है। और सब में ज्यादा माइक्रोलोजिकल नायदा है। उनके दिमाग के ऊपर कोई बंध नहीं रहेगा कि वे किमानों को रियाया हैं। किमानों की बहुत बड़ी तादाद इस मुक्त में है। इस तरह में उनके अन्दर मेन्स रेस्पेक्ट का भाव आयेगा। जब किसानों के अन्दर मेन्स रेस्पेक्ट का भाव आयेगा तो वे अपना सर उठा सकेंगे और हम दुनिया के मानने अपने सर को ऊँचा कर सकेंगे। रुपया जमा करने में किसानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि बड़ा भारी नायदा है। एक दूसरी किस्म शिकमी काश्तकारों की है उनके ऊपर एक भारी एतराज उठाया गया है कि जब आप पांच वर्ष के बाद भूमिधर बना देंगे तो पांच वर्ष पहले ही बना देने में क्या नुकसान है? अगर उनको इसी वक्त ये राइट्स दे दिये जायँ और वे भूमिधर बना दिये जायँ? एक बात यह है कि जो सीर या शिकमी के या मौखली किसान के शिकमी हैं उनका जो जमींदार था और जिसकी जमीन लगान पर थी तो उस वक्त उसने यह समझा कि कोई दिन ऐसा आवेगा जब उसकी जमीन वापस मिल जावेगी। वह इसी आशा में था कि कुछ अरसे बाद शायद उसकी जमीन आइन्दा मिल जाय। तो ऐसी हालत में उसका कोई नुकसान न हो इसी का न्याय करके यह रखा गया है कि अगर पांच साल में वह शिकमी अपना मुआविजा अदा कर दे तो वह भूमिधर हो जायगा। ५ साल के अन्दर वह अपना गुजारे का कोई और प्रबन्ध कर लेगा। इस तरह से मैं कहता हूँ कि यह बात बिलकुल न्याय पूर्ण है। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। एक साहब ने अनइकनामिक होलिंग और लैंड लेम लेवरर के बारे में कहा है। मैं इन दोनों चीजों को साथ साथ ही लेता हूँ। एक मेरे दोस्त जो मेरे करीब बैठे हुये हैं उनसे मैंने यह कहा कि लैंडलेस लेबरर का नाम जमीन की मिलिक्यत के सिलसिले में नहीं लेना चाहिये। इस पर वे नाराज हो गये और उन्होंने मुझको रीऐक्शनरी कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि मैं एक रेवोल्यूशनरी के नाते ही इस चीज को रखता हूँ कि लैंडलेस लेबरर का नाम जमीन की मिलिक्यत के सिलसिले में नहीं लेना चाहिये। आजकल हमारे देश में खेती करने वालों को तादाद ५१ प्रतिशत है और २४ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर कहलाते हैं। यानी इस तरह से ७५ प्रतिशत आदमी खेती पर मुनहसर हैं। अगर

[ श्री विष्णुशरण दुबलिश ]

हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो हमें चाहिये कि खेती करने वालों की तादाद कम करें। अगर जमीन के मामिलों की तादाद हम कम नहीं करते तो हमारा मुल्क कमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, और न दुनिया के सामने सर उठा कर खड़ा हो सकता है। दुनिया के और किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद खेती करने वालों की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में खेती करने वालों की तादाद ३३ फी सदी से अधिक न हो। खेती करने के लिये कोई दूसरा अच्छा तरीका निकाला जाय जिससे हमारे यहां अन्न की पैदावार काफी हो। जो लैंडलेस लेबरर हैं उनसे मेरी पूरी हमदर्दी है। मैं समझता हूँ कि आज वे हमारे यहां सबसे ज्यादा परेशान सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा नंगे हैं और सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमारे गाँवों में जो लैंडलेस लेबरर हैं उनको रेहैविलिटेड करने का ठीक तरह से सही तरीका जमीन नहीं है। श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ने कुलियों के आँकड़े लेकर नक्शा आपके सामने रखा है कि अगर सब फालतू जमीन उनमें बांट दी जाय तो आधा बीघा हर एक के हिस्से में पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जैसा हमारे एक दोस्त ने कहा, शायद तारी साहब ने कहा था कि अनइकनामिक होल्डिंग का लगान बिलकुल माफ कर दिया जाय। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में किसानों की आदत कुछ ऐसी है कि अगर बीस बीघा एक के पास जमीन है और उसके दो लड़के हुये तो दोनों आपस में दस-दस बीघा बांट लेंगे। अगर दस ही बीघा हुआ तो पांच-पांच बीघा बांट लेंगे। उसको चिपटे रहेंगे और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। हम इस तरह की टेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज उनको दी जाय जिससे वे अपनी अपनी अलग अलग होल्डिंग में चिपके रहें। जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है उसके मुताबिक तो मैं सोचता हूँ कि जो बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं जो रोजमर्रा के कंज्यूमर्स गुड्स बनाने वाली इन्डस्ट्रीज हैं, उनका डिसेन्टलाइजेशन होगा।

मैं समझता हूँ कि कपड़े की इन्डस्ट्री डिसेन्टलाइज होगी, और चार-चार पांच-पांच गांवों के बीच में एक-एक फैक्टरियां होंगी और इस तरह से हम काम करेंगे जिसमें कि हमारे लैंडलेस लेबरर्स और अनएकनामिक होल्डिंग रखने वाले काश्तकार अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करें और उनके जरिये से अपनी रोजी पैदा करें। इन्डस्ट्रीज डिसेन्टलाइज होने से उनकी देहातों की सारी गरीबी सारे प्राबलम्स खत्म हो जायेंगे और जो लेबर के सिलसिले में हाउसिंग वगैरह के प्राबलम्स खड़े हुये हैं वह भी खत्म हो जायेंगे क्योंकि लोग अपने छोटे छोटे कारखाने कायम करेंगे और हमारे गांव हमारे शहरों को भी चीजें बना कर जो उनकी एरियाज से फालतू होंगे मेजेंगे। इस तरह से मैं यह समझता हूँ कि यह सारे प्राबलम्स हल हो जायेंगे। लोग कहते हैं कि यह लान्ग टर्म प्लान है मैं कहता हूँ कि आप कोई शार्ट टर्म प्लान निकालिये। मेरा यह ख्याल है कि लैंडलेस लेबरर्स का मसला एक बिल्कुल दूसरे ढंग से साल्व ( हल ) करना होगा जमींदारी अबालीशन से वह साल्व नहीं होगा। इतनी जमीन में ही आप सबको खपा नहीं सकते। हमें इस तरह की फैक्टरीज बनानी होंगी जिसमें लोगों को काम दिया जाय। गाँवों में छोटी-छोटी फैक्टरी

मे लैन्डलैम मजदूरों को उसमें कई ज़्यादा मजदूरी मिलेगी जो उन्हें आज खेत पर काम करने में मिलती है—लिहाज़ा बड़े-बड़े होल्डिंग वालों को मजदूर नहीं मिलेंगे और इन बड़े होल्डिंग के डिस इन्टिग्रेशन (छोटे होने) का पोसेस खुद शुरू हो जायगा जो जितनी जोत सकेगा उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकेगा। ऐसी ही एक बात और है जो मुझे बड़ी मुनासिब मालूम होती है और वह यह है कि जहाँ तक हो सके लैंड पर एक यूनीफार्म रेट रेवेन्यू का होना चाहिए। आज हमने प्रोक्वोरमेंट में भी देखा है। मुझे पूर्वी जिलों का तो इल्म नहीं है लेकिन मैं अपने जिले मेरठ की कहता हूँ कि कहीं कच्चे बीघा पर १५, १८ रुपए २० रुपए हैं और कहीं कुछ और है। मेरे ख्याल से यूनीफार्म रेट होना चाहिए। कुछ भाई कहते हैं उनका एतराज था कि चालीस साल तक का बन्दोबस्त कर दिया गया है कि चालीस साल तक कोई चेन्ज नहीं होगा। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने यह गारन्टी दी है कि चालीस साल तक कोई भी रेट किसी तरह से बढ़ाया नहीं जाएगा। कमी करने में, घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक बात और कहना है कि आप म्यूनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया के लिए बिल अलग ला रहे हैं। ठीक है म्यूनिसिपल बोर्ड और नोटीफाइड एरिया की बात ही दूसरी है। लेकिन जहाँ तक टाउन एरिया का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि वे भी बड़े-बड़े गाँव से हैं इसलिए उनका इसी बिल में समावेश होना चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं ज़्यादा डिटेल्स में इस वक्त नहीं जाना चाहता। जो मोटी-मोटी बातें हैं उनको देखते यह बिल बहुत सुन्दर और ठीक मालूम होता है। मैं आखिर में फिर अपने जमींदार भाइयों से अपील करूँगा कि वे खुशी-खुशी इस कानून को पास होने दें और जैसा राजा जगन्नाथ वल्शा सिंह ने अमेंडमेंट रखा है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट किया जाय। उससे ४ महीने के लिये अगर रोक दिया जाय; यह डाइलेटरी टेकटिक्स का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर जमींदार इसे नहीं छोड़ेंगे तो किसान तुले बैठे हैं कि जमींदारी जल्द तोड़ी जाय। वह परेशान हैं। अगर हम चार महीने के लिए और छोड़ देंगे तो वह ज़्यादा नाराज हो जायेंगे। और चूँकि उन्हें इस बात का दावा रहा है कि वे किसानों के हमदर्द हैं और किसान उनके पूरी तरह साथ हैं लिहाज़ा मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी विलेज पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में क्या हुआ। क्या यह सही नहीं है कि छोटे किसान और गाँव के मजदूर मिल गये और उन्होंने तय कर लिया कि हम इन हवेली वालों को हरगिज गाँव समा का प्रधान नहीं बनायेंगे। इससे आपको पता लग गया होगा कि किसान आपसे कितने चिढ़े हुये हैं उन्हें और अधिक चिढ़ा कर अराजकता की सीमा तक न पहुँचाइये। उसका फल आपके लिये अच्छा न होगा।

काश्तकार परेशान हैं, वह बताव हैं कि जल्द से जल्द जमींदारी को खतम किया जाय। जब पिछली कांग्रेस मिनिस्ट्री ने टेनेन्सी बिल पास किया था तो उससे उनको कुछ राहत मिली थी। इसी तरह से इस बिल के पास हो जाने पर उसको बहुत परेशानियों से छुटकारा मिल जायगा। जिस तरह से अंग्रेजों की हालत यहाँ पर १४ अगस्त की रात को थी क्योंकि सुबह ही उनका बिस्तर बोरिया यहाँ से बँधने वाला था उसी तरह से आज



[ श्री विष्णुशरण दुबलिश ]

हमारे जमींदारों की हालत है। जब जमींदारी का खातमा हो जायगा तब आप देखेंगे कि जो किसान आज आपका दुश्मन हैं, कल आपका दोस्त हो जायगा, आपके पुराने अत्याचारों को भूल जायगा। जैमे हम अंग्रेजों के पुराने अत्याचारों को भूल गये हैं। आप उनकी आँखों में धूल भोक्रना चाहें यह नहीं हो सकता। अब मौका है कि जमींदार ऐसा रास्ता पकड़े कि जिसमें कोई उनकी नीयत पर सन्देह न करें और वह एलान कर दें कि हम जमींदारी मिटाना चाहते हैं और इस विल को खुशी से मंजूर करते हैं तो यह आप देखेंगे कि इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग आपको अच्छी नजर से देखेंगे और आपको अपना लीडर बनाने को तैयार हो जायेंगे और आपकी पोजिशन ऊँची उठ जायगी। मैं आर समय लेना नहीं चाहता हूँ, जैसा डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए ताकि और लोगों को भी बोलने का मौका मिले। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि पन्त जी ने जो यह प्रस्ताव किया है कि इस विल को मेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और राजा जगन्नाथ बख्श सिंह का जो अनैडमेंट है उसकी मुखालिफत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह विल मेलेक्ट कमेटी में भेजा जायगा।

श्री राजाराम शास्त्री — जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय पन्त जी की तरफ से जो विल इस हाउस के सामने पेश किया गया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ और राजा जगन्नाथबख्श सिंह की तरफ से जो संशोधन पेश किया गया है मैं उसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ।

इस विल का जब मैं स्वागत करता हूँ तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि यद्यपि मैं इस विल को अपूर्ण समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि गरीब किसानों को या मज़दूरों को इससे इतना फायदा नहीं होगा जितना कि आज वे इससे आशा लगायें बैठे हैं फिर भी मैं यह सोचता हूँ कि मौजूदा जो हालत है, आज हमारे किसानों की जो दुर्दशा है या जो कुछ भी जमींदार हालत करते जा रहे हैं उन तमाम बातों को देखते हुए मैं यह सोचता हूँ कि यद्यपि यह विल नाकाफी है फिर भी मौजूदा हालत से यह एक कदम आगे बढ़ता है और इसी नीयत से मैं इसका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं इस विल का स्वागत खास तौर से इस बात के लिये भी करना चाहता हूँ कि इस विल के पास हो जाने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जायगी और वह यह कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसानों और देहात के मज़दूरों के दिल में एक भावना यह पैदा की है कि कांग्रेस की पार्टी गरीबों की पार्टी है, मज़दूरों की पार्टी है, गरीब किसानों की पार्टी है। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस विल के पास हो जाने के बाद कुछ दिनों तक तो किसानों में बड़ी खुशी मनायी जायगी, जिस तरह से १५ अगस्त के बाद “आजादी मिली, आजादी मिली” का ढिंढोरा पीटा गया, उस समय सारे हिन्दोस्तान की जनता में उल्लास और उमंग पैदा हुई लेकिन जब जनता को आजादी का सवाद चखने को न मिल सका तो जनता निराश होने लगी। वैसे ही मेरा यह अकीदा है कि इस विल के पास हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सारे देहातों में दीवाली मनायी जायगी, किसानों में ढिंढोरा पीटेगा कि हमने जमींदारी को खत्म कर दिया तो किसानों में एक खुशी की लहर आयेगी, लेकिन इस विल

यह १.५ वरस तक जब काम हो चुकेगा तो गरीब किसान इस बात को देखेगा कि हमारे देश में मजदूरों के हितों के लिये दीवानी बनायी थी, इसी लिये खुशी मनायी थी कि जमींदारों मिटेगें। जमींदारी के मिटने के बाद हमारी मुसीबतें खत्म होंगी। देश में का सुख बन हो जायगा। लेकिन यह क्या है ? तब मेरा विश्वास है एक बार हममें अमन का लहर जरूर आयेगी क्योंकि जो आर्थिक संकट है, जो उत्पादन की समस्या है वह हम बिल के पास हो जाने के बाद किसी भी हालत में ठोक तौर से हल नहीं हो सकती, जैसा कि उनी श्री अल्लर राय रास्त्रो ने कहा कि इस बिल में जिस तरह से हम के अन्दर स्ट्रेलिन के जलाने में मन् १९०५ में ११ ई० तक ऐसा ही कानून आया जिसमें छे-छे-छे-छे किसानों के जमीनों और और चीजें दें लेकिन उनके बाद में भी किसान संतुष्ट नहीं हुए और एक क्रांति की बुनियाद पड़ी। मैं चाहता हूँ कि आप हम में सबक लें। अगर आप किसानों की पूरी क्रांति नहीं करते हैं, अधूरी क्रांति करते हैं तो आप एक दूसरी क्रांति के लिये दरवाजा खोलते हैं। आज अगर किसानों के अन्दर आप यह भावना पैदा करते हैं कि हमने जमींदारी को खत्म किया अब उत्पादन बढ़ाएंगे, गरीबों को खाना मिलेगा तो दो में से एक बात कोजिये ' या तो ऐसा काम मन कीजिये, ऐसी आशाएँ पैदा मत कीजिये या फिर इस बात के लिये तैयार रहिये कि एक और क्रांति आवे। यदि क्रांति-कारी भावना आप किसानों में पैदा करते हैं, आवे दिल में करते हैं, किसानों और जमींदारों दोनों को दुःख करना चाहते हैं तो नतीजा क्या होगा ? अगर अधूरी क्रांति हुई तो देहात के किसान आगे आयेगे, दूसरी क्रांति होगी और जो राजनीतिक क्रांति पूर्ण नहीं हुई है उसको देहात के इंकलाबी किसान पूर्ण करेंगे। इस लिये मैं समझता हूँ कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो किसानों के चेहरे पर पर्दे पड़े हुए होंगे वह हट जायेंगे और किसान इस बात को सनभ लेगा कि वास्तव में कांग्रेस की पार्टों की तजवीज़ क्या है और उसके बाद ही सही राजनीतिक क्रांति इस देश में आयेगी। मेरा विश्वास है कि किसानों की जो मनोभावनाएँ हैं, देश की जो हालत है उस पर गौर करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बिल इस लिये पेश नहीं किया गया है जैसा कि पंत जी ने उस रोज कहा कि देश की बड़ी बुरी हालत है, गरीबों की बहुत बुरी हालत है, गरीबों को उठाने के लिये कांग्रेस ने उन पर मेहरबानी की और उनको रहम आया और इस लिये इस बिल को पेश किया।

यह बात नहीं है मैं यह देखता हूँ कि इस बिल के दो उद्देश्य हैं और वह यह कि चूंकि किसान जमींदारों के जुल्मों से आजिज हो गया है। वह जानते हैं कि अगर जमींदारी न मिटाई गयी और कांग्रेस गवर्नमेंट नाना प्रकार के वादे करती गयी और उसकी आशा पूर्ण न हुई तो उसका एक ही लाजिमी नतीजा होगा कि फिर किसान कांग्रेस की तरफ नहीं देखेगा, फिर वह अपनी ताकत और लाठी का भरोसा करेगा और जमीनों पर कब्जा करने के लिये आगे बढ़ेगा। कांग्रेस यह समझती है कि हम कानून के जरिये से जिस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं बढ़ कर चाहे जमींदारी पूर्ण रूप से न समाप्त करें, लेकिन किसानों में आशा पैदा किये जायें।

महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि जिस वक्त कोई मौका

[ श्री राजाराम शास्त्री ]

आयेगा जमींदारी को खत्म करने का, अगर किसानों ने अपनी ताकत के जोर से खत्म किया तो न तो शान्तिपूर्ण तरीके से होगा और न कोई मुआविजा होगा। आपको याद होगा कि सन् १९४२ ई० में लुई फिशर ने महात्मा गाँधी से पूछा कि अगले आने वाले आन्दोलन में किसान कैसे शामिल होंगे ? महात्मा गाँधी ने कहा कि किसान अगर जमींदारी खत्म करने के लिये आगे बढ़ेगा तो वह कोई कानून नहीं बनायेगा वह अपनी ताकत के जोर से जमीनों पर कब्जा कर लेगा और एक पैसा भी मुआविजा देने के लिये तैयार नहीं होगा। जब महात्मा जी से पूछा गया कि क्या बिला मुआविजा के ज़मींदारी ले ली जायगी, तो महात्मा गाँधी ने कहा कि किसान भूखा है, नंगा है उसके पास पैसा नहीं है, इस लिए उससे यह उम्मीद करनी कि वह पैसा देगा यह बिल्कुल ग़लत बात है। आप यह अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसानों को आशा न दिलाई जाय तो मेरा ख्याल है कि ऐग्रेरियन क्राइसिस ( कृषिविधियक संकट ) और सख्त हो जायगा। मुझे आशा है कि इस अहमियत को जो बुरी हालत आ रही है इसको कांग्रेस ने महसूस किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के ३६७ पृष्ठ पर लिखा है “यदि ज़मींदारी का उन्मूलन कुछ वर्षों के लिए और रोक दिया जाय तो उस हालत में उन्मूलन का अर्थ बिना मुआविजा के ज़मींदारी की अधिकारच्युति हो सकता है, और बहुत सम्भव है कि खून खराबी तथा हिंसा भी हो।” वे आगे कहते हैं ‘जैसा कि प्रोफ़ेसर हेरोल्ड जे० लास्की ने कहा है, इतिहास को दृष्टि में रखते हुए क्रान्ति के खतरे को दूर करने का एक ही उपाय हो सकता है। वह उपाय ऐसे सुधार करना है जिनसे उन लोगों में आशा और प्रसन्नता का संचार हो सके जिनको, विपरीत अवस्था में, क्रान्तिकारियों की बातें अनिवार्य रूप से पसन्द आ जाती हैं।” कांग्रेस इस बात को देखती है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस पर से जनता का विश्वास हटता जा रहा है और जो उसके दिल में आशा थी उसमें कमी आती जा रही है और देश के अन्दर समाजवाद जोर पकड़ता जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस यह भी देखती है कि देहातों और खास कर शहरों में कलकत्ते और बम्बई के अन्दर आपने देखा कि एक के बाद दूसरी जगह चुनाव में कांग्रेस पराजित होती जा रही है। कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है कि शहरों की जनता हमारे हाथ से जा रही है। अगर देहातों की जनता भी हमारे हाथ से चली गयी तो हम कहीं के न रहेंगे। इस लिये कांग्रेस इस सिद्धांत पर चल रही है कि जब क्रान्ति का भय, मालूम हो तो जनता के दिल में आशा का संचार करो। ऐसी हालत में कांग्रेस को इस बात की फ़िक्र है कि वास्तव में अगर देश को इन चीजों से बचाना है तो एक ही तरीका है कि जनता के बीच में आशा का संचार कर दो। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूँ और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि यह बिल इस भवन के सामने इस लिये पेश किया गया है कि किसानों के साथ कोई उदारता की जा रही है, कोई दान दिया जा रहा है, या किसानों पर कोई मेहरबानी की जा रही है।

मैं यह समझता हूँ कि जब कभी चाहे वह अंग्रेज हो, चाहे वह फ्रांसीसी हो, चाहे वह डच हो या कोई भी साम्राज्यवादी लोग जब दुनिया के किसी मुल्क को गुलाम बनाते हैं या राष्ट्रवादी पार्टी पावर में आती है तो वह भी यही कहा करती है कि हम फलों का काम

तुम्हारे हित में करते हैं। इसी तरह से अंग्रेज भी कहते थे कि हमने रेलें हिन्दुस्तानियों के लिये चलाई हैं, सड़कें हिन्दुस्तानियों के लिये बनवाई हैं लेकिन असलियत यह थी कि उन्हें विदेशी माल हिन्दुस्तान में बेचना था। इसके लिये उन्हें रेलें खोलना और सड़कें बनवाना जरूरी था, जिससे कि हिन्दुस्तान से कच्चा माल ले जायं और वहां से पक्का माल यहां बेचने के लिये आ सके।

आज हिन्दुस्तान आजाद हुआ है और हिन्दुस्तान पर पूंजीवादी वर्ग शासनारूढ़ है। आज वह समझता है कि उसके लिये विदेशी बाजार तो बन्द है इसलिये उसको हिन्दुस्तान की मंडी को खोलना है। जब वह हिन्दुस्तान का बाजार खोलने लगता है तो देखता है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और देहात का बाजार बंद पड़ा है क्रय-शक्ति काफी नहीं है। यदि इसको बढ़ाया न जायेगा तो पूंजीवादी वर्ग के लिये हिन्दुस्तान का बाजार भी बंद हो जायेगा। बिना इसके पूंजीवादी वर्ग को फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये एक ही मार्ग है कि पूंजीवादी वर्ग में जो रोड़ा है उसको हटा दिया जाये। सब से बड़ा रोड़ा यही है कि हिन्दुस्तान की क्रय शक्ति काफी नहीं है और जमींदारी प्रथा एक खास रोड़ा है। इसलिये यदि पूंजीवादी वर्ग का उद्धार करना है तो इसके लिये सीधा सादा रास्ता यही है कि इस को बिलकुल हटा दिया जाये।

आज यह बात कहना कि कांग्रेस के दिल में रहम आ गया और कांग्रेस देहाती जनता की भलाई के लिये यह चीज करने जा रही है। ठीक नहीं है। मैं पूछता हूँ कि किस मुल्क में पूंजीवादी वर्ग ने जमींदारी खत्म करने की कोशिश नहीं की। फ्रांस में हम देखते हैं कि जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो फ्रांस के किसानों ने सामंतशाही को उलट दिया एक दिन में पार्लियामेंट ने पूरी सामंतशाही को फेंक दिया। रूस में किसानों ने सामंतवाद को उलट दिया। रूस में भी जब सामंतशाही को उलट दिया गया तो पूंजीवादी वर्ग आगे बढ़ा। हर एक मुल्क में आप देखेंगे कि प्रत्येक पूंजीवादी वर्ग ने यह कोशिश की है कि जमींदारी प्रथा को हटा कर किसानों का शोषण करके अपनी तरफ़ी करे।

मैं मानता हूँ कि आपने जो तरीका इस्तिहार किया है वह आपको पीछे ले जाने वाला नहीं है बल्कि इससे मुल्क आगे बढ़ेगा लेकिन यह कहना कि गरीबों की भलाई के लिये, रहम के लिये हम यह करने जा रहे हैं यह बात गलत है। वास्तव में पूंजीपतियों के हित में यह चीज है। इसलिये आप यह काम करने जा रहे हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि देश में अगर पूंजीवादी वर्ग आगे बढ़ता है तो किसान भी आगे बढ़ेंगे और किसान जमीन पर खुद बखुद कब्जा कर लेंगे, तब कांग्रेस को फिक्र पड़ी है कि कोई नया चक्र ब्यूह बनाया जाये जिससे आने वाली शक्तियों का मुकाबला किया जा सके।

मैंने इस बिल पर काफी गौर किया है। मैंने इस बिल को समझने की कोशिश की है। मैंने इसकी धाराओं पर गौर किया है। मेरे ऊपर एक ही असर पड़ा है कि जब तक हिन्दुस्तान गुलाम था तब तक राजे महाराजे, जमींदार और अंग्रेज एक तरफ़ थे और हिन्दुस्तान के किसान, पूंजीवादी, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ थे अब अंग्रेजों का परदा हट गया है। अब पूंजीवादी वर्ग आगे आया है। हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर तथा निम्न मध्यम वर्ग एक खीमे में होंगे और दूसरी तरफ़ राजे

[ श्री राजाराम शास्त्री ]

महारजे, साहूकार तथा पूंजीवादी लोग दूसरे खीमे में नजर आयेंगे। हिन्दुस्तान का संघ अब नया रूप धारण करता है। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में दो पार्टियाँ मैदान में आयेंगी जब कांग्रेस शासनारूढ़ हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आप यहां की परिस्थिति को देखें तो पता लगेगा कि यहां की जो भविष्य की राजनीति है उस से नजर आता है कि इस बिल के जरिये से कांग्रेस यह करेगी कि ज़िम तरह से उसने पूंजीपतियों के सम्बन्ध में नीति अख्त्यार की है और उनकी पीठ ठोकी है और मजदूरों को तबाह किया है और देशी रियासतों की जनता को तबाह करके आज राजे महाराजाओं को राज्यप्रमुख बनाकर उन्हें जेब खर्च के लिये ३३ लाख और ४० लाख रुपए तक दिया है और इस तरह से पूंजीपतियों और राजे महाराजाओं को मिलाया है इस कानून की दफात पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह बात स्पष्ट है कि जितना पुराना जमींदार वर्ग है और जितने बड़े धनी काश्तकार हैं उनको इस कानून के जरिये से कांग्रेस ने अपनी तरफ खींचा है लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि जमींदार भाई क्यों कांग्रेस के और इस बिल के खिलाफ हैं। अगर मेम्बरान इसकी भाषा पर गौर करें तो वह इसको जमींदारी एबालिशन बिल न कहकर जमींदारी रक्षक बिल कहेंगे। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस पर गौर करें इसकी दफाओं को देखें तो यही बात पायेंगे। मेरा ख्याल है कि आज जमींदार इस बिल का हाउस के अन्दर भले ही विरोध करें और कहें कि सरकार ठीक नहीं कर रही है और हमें तबाह कर रही है लेकिन वह हृदय में इसको जानते हैं कि अगर उनका कोई हमदर्द या साथी है तो वह पन्त जी और कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरा नहीं है और इसीलिये मैं राजा जगन्नाथ बख्श सिंह की इस बात की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने सफाई के साथ कहा कि “अरे पन्त जी, अपने दोस्तों को दुश्मन न बनाइये” जो आपके लिये तलवार चलाने को बन्दूक चलाने को तैयार हैं और कह सकते हैं कि हम आपकी मदद करें आप हमारी मदद कीजिये और यह ठीक है कि किसानों मजदूरों और सोशलिस्टों के खिलाफ और कम्युनिस्टों के खिलाफ वह तलवार उठा सकते हैं और उनका आफ़र ठीक है वह तुम्हारे कन्धों पर अपनी बन्दूक चला सकते हैं। पन्त जी खुल्लमखुल्ला उनको अपना न कहें लेकिन भविष्य में यह जरूर साथ देंगे। आप तवारीख़ उठा कर देखें कि फ्रांस में १८वीं सदी में राज्य-क्रान्ति हुई और वहां पूंजीवादी और सामन्तशाही वर्ग को क्रान्ति द्वारा उलट दिया गया लेकिन हिन्दुस्तान में जिस तरीके से क्रान्ति हुई वह आपको मालूम है कि सत्याग्रह के द्वारा हुई। लेकिन फ्रांस में यह नहीं हुआ कि सामन्तशाही को जैसे रूस में उल्टा गया वैसे वहां नहीं उल्टा गया। फ्रांस की क्रान्ति जिस प्रकार पहले विफल रही उसी प्रकार रूस में भी दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता पड़ी और उसका केवल एक यही कारण था कि पहली क्रान्ति के द्वारा किसानों की समस्या का पूरा-पूरा हल नहीं किया गया था और सरमायेदारों को समाप्त नहीं किया जा सका था और न पूंजीवादियों को ही समाप्त कर सके थे तब रूस के किसानों ने स्वयं तैयार होकर पूंजीवाद और सामन्तशाही के खिलाफ लड़ाई की और उसमें उनको सफलता मिली। लेकिन आज इस देश में जिन तरीकों से

कांग्रेस कानून के जरिए ने किसानों की समस्या को हल करना चाहती है वह तरीके यह नहीं हैं कि जो इस बिल में दिए गए हैं। इस कार्य के लिए कानून भी क्रान्तिकारी होना चाहिए और वह ऐसा होना चाहिए कि जो सामंतशाही को पूर्णतः नष्ट कर सके और किसान व मजदूरों की समस्याओं को हल कर सके और उनको शक्तिशाली बना सके और यदि आप ऐसा कानून लावेंगे तो इनमें सन्देह नहीं कि किसी तरह भी और देशों की तरह यहां दूसरी क्रान्ति की आवश्यकता न होगी। लेकिन जिस रूप में यह कानून आज हमारे सामने है। उसको देखने से हमारी यह सम्भावना कुछ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही नजर आती है।

लेकिन जिस तरीके से कानून हाउस में पेश किया गया, मैंने शुरू ही में कह दिया कि एक कदम आगे अवश्य है लेकिन जिस तरह से पूरी क्रान्ति का मतलब होता है कि जमींदारी समूल नष्ट हो, एक साथ नष्ट हो, गरीब किसान और खेतिहर मजदूर इनके हाथ में ताकत दी जाय और वह महमूस करें कि हमें कुछ मिला तब तो उन्हे क्रान्ति कहा जा सकता है वरना मेरा ख्याल है कि इस कानून के पास हो जाने से भूमिधर अवश्य बन जायेंगे और जैसा कि राजा जगन्नाथराव सिंह ने कहा कि नाम बदला जा रहा है इन जमींदारों को भूमिधर के नाम से पुकार लिया जायगा और किसानों के तबके में से एक तबके को खींचकर भूमिधर बनाने की कोशिश की जायगी। नतीजा यह होगा कि आइन्दा भूमिधर और कांग्रेस पार्टी एक तरफ होंगे और यह खेतिहर मजदूर, शिकमी काश्तकार दूसरी तरफ। आप यह देखेंगे कि कोई संतुष्ट नहीं होगा। लड़ाई के मैदान में कांग्रेस भूमिधर को मैदान में रख देगी।

गांधी जी ने कहा था कि हम वर्ण विहीन समाज बनाना चाहते हैं। हमारा समाज वर्णाश्रम पर अवलम्बित है, वह पुरानी चीज है। नये समाज की रचना शुरू करने के पहले एक नया वर्ण शुरू किया जा रहा है। उसमें, ४ वर्ण होंगे पहला भूमिधर, दूसरा सीरदार, तीसरा असामी और चौथा होगा अधिवासी। चूंकि पूँजीवादी युग है, जिस वर्ग के पास जितनी पूँजी होगी उसकी उतनी ही कद्र होगी। सबके ऊपर होंगे भूमिधर। उनके साथ यह रियायत की गई है कि जितनी खुदकाश्त है पुराने जमींदारों के पास उसको नहीं छुआ जायगा। पंतजी ने कहा कि हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जो जितना ही बढ़ा है उसके साथ हमने उतना ही बढ़प्पन का बर्ताव किया है। जो राजा है, नवाब है जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है वही यहाँ के पूँजीवादी हैं इतने बीघे जमीन, खुदकाश्त और सीर के रखनेवाले सबसे बड़े जमींदार हैं और जो जितना बढ़ा है उसके साथ उतना ही बढ़प्पन का बर्ताव किया जायगा। उनसे कह दिया गया कि अपनी जमीन अपने पास रखो, हम न सीर छुएँगे, न खुद काश्त छुएँगे, जितनी हो अपने पास रखो, जिसने जिस पर कब्जा कर रखा है वह अपना कब्जा रखे, न हमारी सरकार और न हमारा कानून कुछ उनसे बोलेगा। इतने बड़े जमींदार, सैकड़ों बीघा सीर रखनेवाले जमींदार भूमिधर बनेंगे। जो कानून है उसके मुताबिक उनसे एक पैसा नहीं लिया जायेगा। यह पूँजीवादी युग है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जिसके पास जितना पैसा हो उसके साथ उतनी ही रियायत की जायगी और जो कंगाल है, गरीब है उसके ऊपर उतना ही बोझा लादा जायगा। केन्द्रीय सरकार के बजट को ही देख लीजिये कि अमीरों

[ श्री राजाराम शास्त्री ]

के सब टैक्स माफ लेकिन गरीबों के लिये पोस्ट कार्ड, लिफाफे सब चीजों पर दाम बढ़ा दिये गये । इस तरह से बड़े जमींदार भूमिधर बन जायेंगे बगैर कुछ दिए हुए लेकिन जो बेचारे सीरदार हैं वे भूमिधर बनने की कोशिश करेंगे तो उनसे कहा जायेगा कि अग्ने लगान का १० गुना हमको दो तो भूमिधर बन सकते हो और उसके नीचे जो शिकनी काश्तकार हैं वह ५ वर्ष बाद चाहे कि मैं भूमिधर बन जाऊँ तो उसे भूमिधर बनने के लिए १५ गुना लगान एक साथ अदा करना पड़ेगा । यह इसी तरह से है जिस प्रकार पंतजी जिस बँगले में रहते हैं और लखनऊ के किसी भिखारी से कहा जाए कि तुम भी अगर ३ हजार रुपया माहवार किराया दे सकते हो तो तुम भी उस बँगले में रह सकते हो, मना कौन करता है । मेरा ख्याल है कि उन गरीबों से जिनके पास एक पैसा नहीं है उनसे यह कहना कि तुम १० गुना दो और १५ गुना दो तब भूमिधर बन सकते हो और इधर यह राजा साहब बैठे हैं सैकड़ों बीघा जमीन लिये हुए और बगैर कुछ दिये लिए ही भूमिधर बन बैठेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ तक सुनासिव है ।

यह जो नया वर्णाश्रम धर्म आ रहा है इसमें आप मार्क कीजिये कि जिनके पास कमती पैसा है, और जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास कुछ नहीं लंगोटी लगाये फिरते रहते हैं, उनसे कहा गया है कि तुमको जमीन से क्या वास्ता । श्री दुबलिश जी ने अभी कहा कि अगर सभी लोग काम करने लगें तो कैसे काम चलेगा । जमीन की मिल्कियत सब को कैसे दे दें । मतलब यह है कि देहातों में पूंजीवाद को फैलाना है । अगर ऐसा नहीं करते तो देहातों में जो बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी-अपनी फैक्टरियाँ खोलने को सोच रहे हैं उन्हें मजदूर कैसे मिलेंगे, उनका काम कैसे चलेगा । चाहे १५ गुना रुपया दें लेकिन वे जमीन नहीं पा सकते । उनको मजबूरन नौकरी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी । अगर दुनिया उसी तरह चला करे जैसा आप चाहते हैं तो आप कोई भी कानून पास करा लें, लेकिन दुनिया की हवा देखिये, एशिया की रंगत देखिये, अपने हिन्दुस्तान की रंगत देखिये । आपका यह कहना कि ये खेतिहर मजदूर जमीन को छोड़ दें, शिकमी काश्तकार जमीन को छोड़ दें, और दूसरे लोग भी बैठे रहें, इस तरह से काम नहीं चल सकता । याद रखिये अगर आपने खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं किया और दूसरे मजदूर लोगों की समस्या हल नहीं की तो यही वह क्षेत्र होगा जो हिन्दुस्तान में कम्युनिज़्म पैदा करेगा । आपने बिल पेश किया और उद्देश्य बताया कि कम्युनिज़्म की लहर को रोकना है । कम्युनिज़्म की लहर आप इन आने वाले भूमिधरों की सहायता से रोक सकेंगे, यह गलत बात है । राजा साहब ने कहा कि हमारी तोप तलवारें आपके साथ हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एक नहीं हजारों तोप तलवारें लेकर यह आपके साथ आ जायें, कुछ काम नहीं आयेंगे । उनके प्रयोग का जमाना अब मर चुका है । इन्हीं लोगों ने च्यांगकाई शेक से कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तोप तलवारें तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कम्युनिज़्म को नहीं रोक सके । च्यांगकाई शेक मिटा दिये गये, क्यूमिंगांग मिट गया, और कम्युनिज़्म का वहां दौरदौरा होता जा रहा है । मेरा विश्वास है कि अगर आपका कोई मददगार हो सकता है तो ये खेतिहर मजदूर हैं जिनके पास कोई चीज़ नहीं, उन्हें आशा है कि कांग्रेस

## नव् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३४७

हमने भलाई के लिये और और हमने इस औरा को निरारा में परिणत किया तो देश में एक ऐसी लहर उठेगी कि आप भी उसमें खत्म हो जायेंगे। हो सकता है कि कानून के नष्ट होने के बाद दिवली देहाने में उम्मे प्रकर मनाई जाय जिन प्रकार १५ अगस्त मनया गया था मन्तु १५ अगस्त के बाद जो देश देश को हो रही है वह आपने छिपी नहीं है वह देश देहाने के अन्दर भी होगी !

मैं मोरालिस्ट पार्टी के लोग ने एक बात कहूँगा, और वह यह है कि जहां तक आपका दिल आगे जाता है वह तक मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जब तक खेतिहर मजदूरों को, गरीबों को मैन नहीं मिलेगा, उनके साथ इन्साफ नहीं होगा, तब तक देहाने में मोरालिस्ट पार्टी आपसे लड़ें लड़ती रहेगी। हमारा नारा होगा, खेतिहर मजदूरों को जमीन दो। मैं जानता हूँ आप इसे दान करने हैं, आपके मान तकत है। लेकिन क्रान्ति की लहर इस तरह से दबाई नहीं जा सकती, रोकी नहीं जा सकती।

मोरालिस्ट पार्टी को नद ने बड़ी आलोचना इस बात की की गई है कि आप लोगों की नीति मनक में नहीं आती कि आप मुआवजा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते।

लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस नानले में सोशलिस्ट पार्टी के साथ मैं न पंत जी ने इन्साफ किया है और न त्रिगठी जी ने। सोशलिस्ट पार्टी की आधी बात तो हाउस के गमने पेरा की गई और आधी बात पेरा नहीं की गई। सोशलिस्ट पार्टी का हमारा यह सिद्धांत रहा है कि वह जायदादों का मुआवजा देने के लिये लतई और किसी हालत में भी कमी भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर समझौता होता है तब आपसी कम्प्रोमाइज के लिये इस तरह से उसने रखा है कि जमींदार जो गरीब हैं और काश्तकारों की हैसियत रखते हैं और ज्यादा मालगुजारी नहीं देते हैं और जिनकी हालत जमींदारी की समाप्ति के बाद खराब होने का डर है उनको पुनर्वास के लिए सहायता देने को हम तैयार हैं। लेकिन आप इतनी बात ही कहते हैं कि सोशलिस्ट के कहने के मुताबिक ही मुआवजा दिया गया लेकिन आप आधी बात को क्यों छिपा जाते हैं। जब आप जमींदारियों का बटवारा नहीं करते हैं तो मुआवजा किस बात का ? जहाँ तक बड़े जमींदारों का तात्किक है जो इतनी बड़ी मालगुजारी देते हैं, मैं पूछता हूँ कि अगर आप उनको मुआवजा नहीं देंगे तो उनमें से किसका घर तबाह हो जायेगा या कौन भूखों मर जायगा लेकिन आपके दिल में उनके लिए रहम आता है वह रहम उन खेतिहर मजदूरों के लिये क्यों नहीं आता जिसके पास जमीन नहीं है, दौलत नहीं है और मकान नहीं है। आप कहते हैं जमीन नहीं है। चूंकि इतनी जमीन नहीं है जो सबको दी जा सके इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि किसी को न दें। जब उनके पास इतनी सीर और खुद काश्त है और आगे आनेवाले भूमिधर ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेंगे तो फिर यह आप क्यों नहीं रखते कि जिनके पास सैकड़ों हज़ारों बीघा जमीन है वे ५० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन यह चीज़ आपको रुच नहीं सकती। यह केवल आपकी दरियादिली है। आपके दिल में उनके लिए रहम है और फिर भी मैं तो यह कहता हूँ कि आपका जमींदारों के साथ यह पक्षपात है। यह दिल आपका गरीबों के लिये इतना क्यों नहीं पसीजता। जैसा कि कहा गया है कि बड़ों के लिये आपका बड़प्पन का सा वर्ताव है और छोटा के लिये छोटे



[ श्री राजाराम शास्त्री ]

दंग का बर्ताव है। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से इंसफ हो तो सोशलिस्ट पार्टी की बात मान लीजिये। त्रिपाठी जी ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात का साफ़ तौर से एलान किया जाना चाहिए। हम सोशलिस्ट जमींदारी को जायदाद मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह कमीशन एजेंटी अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई। किसी ने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ १८५७ में या किसी और जमाने में कोई देश की सेवा नहीं की। १८५७ में कितने जमींदार ऐसे रहे जिन्होंने बेशक मुल्क की खातिर कुरबानी की। जिन्होंने ऐसा किया मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। अगर आज कांग्रेस सरकार यह नियम बना दे कि जिस किसी जमींदार ने १८५७ की जंगे आज़ादी में मुल्क का साथ दिया सन् १९२०, ३० या ४२ में अपनी कुरबानी की हम उसको मुआवजा देने को तैयार हैं। हम उस देश भक्त की तारीफ़ करते हैं। मेरा विश्वास है कि राजा साहब भी इस बात के लिये तैयार होंगे कि देश भक्तों को मुआवजा दिया जा सकता है। क्या ऐसे जमींदार नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में तलवार चलाई? क्या ऐसे जमींदार नहीं हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। क्या आप उन देशद्रोही जमींदारों को भी मुआवजा देना चाहते हैं।

डिप्टी स्पीकर—मैं समझता हूँ कि आप दो एक मिनट में तकरीर खत्म कर देंगे।

श्री राजाराम शास्त्री—जी नहीं। अभी मुझे काफी कहना है।

माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि कल शुरू से ही इस बहस को ले लिया जाय और सवालियों को कल न लिया जाय तो बेहतर होगा।

(भवन की अनुमति से निश्चित हुआ कि कल प्रश्न नहीं लिये जायेंगे और प्रारम्भ से ही वाद विवाद जारी रहेगा।)

(इसके बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर मंगलवार १२ जुलाई, १९४६, ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लेखनऊ  
११ जुलाई, १९४६

कलासचन्द्र भटनागर,  
मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,  
संयुक्त प्रान्त

नत्थी ( क )

देखिये ६ जुलाई, १९४६ के प्रश्न

सं० ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर

सरकारी प्र'इमरी स्कूल	लड़कों की पाठशाला	कन्या पाठशाला	सरकारद्वारा सहायता
१९४६****४७	....	....	६०८६८
१९४७****४८	२६	४	
१९४८****४९	४५	८	
बोर्ड के प्र'इमरी स्कूल			
१९४६****४७	१५	२	२१९४
१९४७****४८	३	१	
१९४८****४९	....	१	
बोर्ड के मिडिल स्कूल			
१९४६****४७	२	....	२२४७
१९४७****४८	१	....	
१९४८****४९	....	....	
प्राइवेट मिडिल स्कूल			
१९४६****४७	....	....	५००
१९४७****४८	४	....	
१९४८****४९	२	....	
हायर सेकेन्डरी स्कूल			
१९४६****४७	....	....	६७००
१९४७****४८	....	....	
१९४८****४९	५	....	

## नत्थी (ख)

देखिये ६ जुलाई १९४६ के प्रश्न ४५ के उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर  
गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर के १९४७-४८ ई० और १९४८-४९ ई० के  
कामों के बारे में एक नोट

गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर जनवरी, १९४७ ई० में नियुक्त किये गये थे। उन्होंने १९४७-४८ ई० में इस प्रान्त की सब गौशालाओं को देख लिया और गौशालाओं के प्रबन्ध करने वालों से स्वयं मिले जिससे कि वह उनकी कठिनाइयों को समझ सकें और दूर कर सकें। गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर की सलाह से बहुत सी गौशालाओं की रजिस्ट्री कराई गई।

२. गौशालाओं को देखने के समय उन्होंने उनके प्रबन्ध करने वालों को यह सलाह दी कि वे बूढ़ी और बेकार गायों को दूध देने वाली गायों से अलग रखें। बूढ़े और बेकार मवेशियों का पालन थोड़े खर्च में करने के लिये सरकार ने श्रीमती मीरा बहन के चार्ज में ऋषिकेश में एक पशुशाला (कन्सेन्ट्रेशन कैम्प) खोलने के लिये एक स्कीम मंजूर की है।

३. इस प्रान्त में गौशालाओं के संगठित रूप से सुधार करने में सहायित पैदा करने के लिये गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर एक प्रान्तीय गौशाला फेडरेशन बनाने में सफल हुये हैं जिसकी शाखाएँ हर जिले में खोली गई हैं। गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर ने गौशालाओं के सुधार के लिये एक पंचशाला स्कीम भी तैयार की है और उसे सरकार के पास भेज दिया है। इस स्कीम में यह तजवीज किया गया है कि हर स्वीकृत गौशालाओं को आधे दामों पर औसतन २० गाय असली हरियाना नस्ल की दी जायें। मथुरा जिले में ५ छः गौशालाओं को आधे दामों पर गायें दी जा चुकी हैं।

४. मथुरा और पीलीभीत जिलों में पशुशालाएँ (कन्सेन्ट्रेशन कैम्प) खोलने के लिये गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर ने स्थान तय कर लिये हैं और स्कीम तैयार कर ली हैं।

५. दूध न देने वाली गायों का उद्धार करने के लिये एक स्कीम हापुड़ और गाजियाबाद के शहरों के लिये श्री कृष्ण गौशाला गाजियाबाद, जिला मेरठ में चलाई गई है।

६. गौशाला फेडरेशन, मेरठ पर खर्च किये जाने के लिये सरकार ने १०,००० रुपये का एक अनुदान (ग्राण्ट) पशु पालन विभाग के डायरेक्टर के अधिकार में भी रख दिया है। अस्ली नस्ल के मवेशियों को मोल लेने के लिये १५,००० रुपये का ऋण काशी गौशाला बनारस को मंजूर किया था। पर वह अपनी कुछ कठिनाइयों के कारण इस रकम को काम में नहीं ला सकी।

७. आल इंडिया कैटिल प्रोटेक्शन कानफरेन्स के अधीन आगरे में गौशाला के कार्यकर्ताओं के लिये एक ट्रेनिंग क्लास खोला गया था और उसमें १८ कार्यकर्ताओं को काम सिखाया गया है।

८. ऊपर बताये हुये कामों के अलावा गौशाला डेवलपमेण्ट अफसर ने एक गौशाला सुधार बिल (Gaushala Improvement Bill) का भी मसविदा तैयार किया है जिस पर आजकल सरकार विचार कर रही है।

नत्थी ( ग )

देखिये ६ जुलाई १९४६ के स्टार्ड प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर  
विवरण सरकारी अनुदान जो दिसम्बर १, १९४८ में फरवरी २८, १९४९ तक  
जिला विकास बंड में मैनपुरी से दिया गया ।

नाम उस सज्जन का जिसको रु० दिया गया	उनकी हैसियत लगान माल गुजारी आदि संबन्धी क्या है	किस काम के लिये दिया गया	कितना रुपया दिया गया	सम्बन्धित सज्जन दलित या पिछड़े वर्ग के हैं या नहीं	विशेष विवरण
श्री चेताराम काछी	ग्राम उफैया फकीरपुर डा० ज्योती जि० मैनपुरी	किसान ६ रु० लगान देते हैं	नये कुएँ के लिए १३३)	पिछले वर्ग में हैं ।	
श्री हृदय नारायण	ग्राम नादऊ डा० कुचेला जि० मैनपुरी	किसान ५० रु० लगान भरम्मत कुआँ देते हैं	२६६॥)	सम्पूर्ण जनता के लिए यह रुपया सन् १९४२ के सामुहिक जुर्माने का था	



# मंयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, १२ जुलाई, सन् १९४६ ई०

असेम्बली की बैठक असेम्बली भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई :

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची ( १८६ )

अचल सिंह  
अजित प्रताप सिंह  
अब्दुल वाक्की  
अब्दुल मजीद  
अब्दुल मजीद ख्वाजा  
अब्दुल वाजिद, भीमती  
अब्दुल हमीद  
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स  
अम्मार अहमद खां  
अल्फ्रेड धर्मदास  
अलगूराय शास्त्री  
असगर अली खां  
अश्वयंकर सिंह  
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री  
इन्द्रदेव त्रिपाठी  
इनाम हबीबुल्ला, भीमती  
उद्देदुरहमान खां शेरवानी,  
ऐजाज रसूल  
कमलापति तिवारी  
करीमुर्रबा खां  
कालीचरण टण्डन  
किशनचन्द पुरी  
कुंजबिहारी लाल मिश्रा  
कुशलचन्द्र नैसेल  
कृपाशंकर  
कृष्णचन्द्र  
कृष्णचन्द्र गुप्त  
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री  
केशव गुप्त

खुशवक्त राय  
खुशीराम  
बृजसिंह  
गङ्गाधर प्रसाद  
गणपति सहाय  
गणेश कृष्ण जैतली  
गिरवारी लाल, माननीय श्री  
गोपाल नारायण सक्सेना  
गोविन्द कल्लभ पन्त, माननीय श्री  
गोविन्द सहाय  
गङ्गाधर  
गङ्गा प्रसाद  
गङ्गा सहाय चौबे  
चतुर्भुज शर्मा  
चन्द्रमानु गुप्त, माननीय श्री  
चन्द्रमानु शरण सिंह  
चरण सिंह  
चेतराम  
छेदालाल गुप्त  
जगन्नाथ दास  
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल  
जगन्नाथ सिंह  
जगन्नाथ नन्दा सिंह  
जगन प्रसाद रावत  
जगमोहन सिंह नेगी  
जमशेद अली खां मुहम्मद  
जवाहरलाल रोहतगी  
जाकिर अली  
जाहिद हसन

जगुल किशोर  
जैपाल सिंह  
जयराम वर्मा  
दयाल दास भगत  
दाऊदयाल खन्ना  
द्वारिका प्रसाद मोर्य  
दीन दयाल अवस्थी  
दीन दयाल शास्त्री  
दीप नारायण वर्मा  
नफीसुल हसन  
नवाजिश अली ख  
नवाब सिंह  
नारजिन अल  
नारायण दास  
निसार अहमद शेखानी, माननीय श्री

प्रकाशवती सुद, श्रीमती  
प्रागनारायण  
परागी लाल  
प्रेमकिशन खन्ना  
फखरुल इस्लाम  
फजलुर्रहमान खां, उपनाम छोटे खां  
फतेह सिंह राण  
सैह

वंशगोपाल  
बनराजी दाव  
बलदेव प्रसाद  
बलमद सिंह  
बशीर अहमद  
बादशाह गुप्त  
बाबूराम वर्मा

बृजमोहन लाल शास्त्री  
भगवती प्रसाद हुवे  
भगवती प्रसाद शुक्ल

भगवानदीन मिश्र  
भगवान सिंह  
भारतसिंह यादवाचार्य  
भीमसेन  
महफुजुर्रहमान  
महमूद अली खां  
मिजाजी लाल  
मुकुन्दलाल अग्रवाल  
मुत्तफकर हुसैन  
मुनफैत अली  
मुहम्मद अदील अब्बासी  
मुहम्मद अख्तर अहमद  
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री  
मुहम्मद इस्माइल  
मुहम्मद नजीर  
मुहम्मद फारूक  
मुहम्मद याकूब  
मुहम्मद यूसुफ  
मुहम्मद रज़ा खां  
मुहम्मद शकूर  
मुहम्मद शमीम  
मुहम्मद शाहिद फ़खरी  
मुहम्मद शौकत अली खां  
मुहम्मद सुलेमान अधमी  
यशनारायण उपाध्याय  
रघुनाथ विनायक धुलेकर  
रघुवीर सहाय  
रघुवंश नारायण सिंह  
राघवदास  
राजकुमार सिंह  
राजाराम मिश्र  
राजाराम शास्त्री  
राधाकृष्ण अग्रवाल  
राधामोहन सिंह  
राधेश्याम शर्मा  
रामकुमार शास्त्री

शिवदुर्गा रण्डेय  
 शिवकुमार निश्र  
 शिवदया उपाध्याय  
 शिवदान सिंह  
 शिवमंगल सिंह  
 शिवमंगल सिंह कपूर  
 श्यामलाल वर्मा  
 श्यामसुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द सिधल  
 श्रीपति मन्नाय  
 सईद अहमद  
 सज्जन देवी महनोत, श्रीमता  
 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 सरवत हुसैन  
 सरीम हामिद खां  
 साजिद हुसैन  
 सालिग्राम जैमवाल  
 सिहासन सिंह  
 सिराज हुसैन  
 सीताराम अष्टाना  
 सुदामा प्रसाद  
 सुचेता कृपलानी, श्रीमती  
 सुल्तान आलम खां  
 सूर्यप्रसाद अक्स्थी  
 हबीबुररहमान अन्सारी  
 हरगोविन्द पन्त  
 हरप्रसाद सत्यप्रेमी  
 हसन अहमद शाह  
 हसरत मुहानी  
 होतीलाल अग्रवाल  
 त्रिलोकी सिंह



## असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये श्री अज़ीज़ अहमद खां का प्रार्थना पत्र

**माननीय स्पीकर**—पहला मद आपके सामने कार्यक्रम में यह है कि श्री अज़ीज़ अहमद खां के प्रार्थना पत्र पर आप विचार करें। वह बीमार हैं। ४७ दिन वह इस समा से अनुपस्थित रह चुके हैं। आज ४८वां दिन है। उनका प्रार्थनापत्र कार्यक्रम में नती 'क' के रूप में छपा हुआ है। उनकी इच्छा है कि असेम्बली के नियम ६ के अनुसार उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति आपकी ओर से हो। यही विषय आपके सामने है।

**माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)**—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री अज़ीज़ अहमद खां की छुट्टी की दरखास्त मंजूर कर ली जाय।

**माननीय स्पीकर**—प्रश्न यह है कि श्री अज़ीज़ अहमद खां की भवन से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना स्वीकार की जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

## संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट प्रिज़नर्स एंड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

**माननीय पुलिस सचिव (श्री जालबहादुर)**—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री चन्द्रिका लाल के रिक्त हुए स्थान पर संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट प्रिज़नर्स एंड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

**माननीय स्पीकर**—प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रिकालाल के रिक्त हुए स्थान पर संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट प्रिज़नर्स एंड सोसाइटी की केन्द्रीय समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

**माननीय स्पीकर**—मैंने ऐसा विचार किया है, यदि आप लोगों को इसमें कुछ कहना है तो मैं सुनने के लिये तैयार हूँ, मेरा विचार यह है कि कल ही—आज १२ तारीख है—कल १३ तारीख इस काम के लिये रख दूँ। नामांकित पत्र आ जाय। इसमें कोई असुविधा तो आपके नहीं है ?

(कुछ ठहर कर)

मैं कल की तिथि नियत करता हूँ। नामांकित पत्रों की प्राप्ति के लिए १२½ बजे दिन तक परसें यानी १४ तारीख मैं नियत करता हूँ। नाम की वापसी के लिये दो बजे दिन तक और १५ तारीख को १२ बजे से २ बजे तक लाइब्रेरी रीडिंगरूम में चुनाव होगा।

## सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विज

माननीय स्पीकर — संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विज पर माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव और श्री जगन्नाथ बरुश सिंह जी के संशोधन पर अब विचार जारी होगा।

श्री राजा राम शास्त्री — कष्ट में इस बात पर विचार कर रहा था कि मुआविजे के सम्बन्ध में मोरारजी पार्टी की क्या नीति है। आचार्य नरेन्द्रदेव की गवाही का जिक्र किया गया है। जिस गवाही में उन्होंने कांग्रेस की एक कमेटी के सामने दिया था। उसके सम्बन्ध में यह बात कही गयी है कि सनाजवादी लोगों की कोई नीति नहीं है। किसी वक्त कोई बात कहते हैं किसी वक्त कोई। किसी वक्त में तो आचार्य जी कांग्रेस में थे। जब सनाजवादी कांग्रेस में बाहर हो गये तब वह और बात पेश करते हैं।

हमारा ख्याल यह है कि सनाजवादी पार्टी की जो नीति उस वक्त में जाहिर की गई थी उसमें कोई विशेष अन्तर मुझे तो दिखता नहीं पड़ता। मेरा अपना ख्याल यह है कि आचार्य जी ने गवाही में जो कुछ कहा था अगर उसे ध्यानपूर्वक देखें, जाय तो मान्य होगा कि दो तीन चीजें तो विस्फुट स्पष्ट थीं। एक चीज तो यह कि जहां पर उन्होंने जमींदारों को दस गुना से लेकर पचीस गुना तक मुआविजा देने की बात कही वहां पर उन्होंने यह भी विस्फुट स्पष्ट तोर से कहा था कि किसी भी जमींदार को पांच लाख से ज्यादा मुआविजा न दिया जाय, जब पांच लाख की बात स्पष्ट कर दी गयी है तो फिर इन बात पर जोर देना कि उस गुना से लेकर पचीस गुना तक मुआविजा देने की बात कही गयी है, इनको मैं ठीक नहीं समझता। क्योंकि जब ५ लाख की एक मियाद मुकर्रर कर दी गयी है तो उसी पर सब को ध्यान देना चाहिये। इसके बाद मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर आचार्य जी ने पांच लाख तक मुआविजा देने की बात कही थी वहां पर उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से ही यह कहा था। उसके बाद जब पार्टी की मीटिंग हुई तो गार्स ने यह पारसी अखितार की कि एक लाख से ज्यादा किसी को भी मुआविजा देना ठीक नहीं है। उसी वक्त आचार्य जी ने अपनी राय विस्फुट स्पष्ट कर दी थी कि गवाही के सामने जो कुछ मैंने कहा था वह मेरी व्यक्तिगत राय थी। पार्टी की नीति यह है कि किसी जमींदार को भी एक लाख से ज्यादा मुआविजा नहीं देना चाहिये। अब मुआविजे के सम्बन्ध में हमारी पार्टी की जो नीति है वह यह है कि जहां तक जमींदारों को मुआविजा देने का सवाल है, हम उनके इस नैतिक अधिकार को मानने नहीं हैं। हम समझते हैं कि यह गलत बात है। मेरा अपना निजी ख्याल यह है कि जमींदारों को मुआविजा पाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एंग्लो-इंडियन रिफार्म के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान वीकली' लिखनऊ में एक आर्टिकल मैंने देखा है। उसके सम्बन्ध में बाबू संपूर्णानन्द का भी एक लेख है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जमींदारों को जहां तक मुआविजा देने का ताल्लुक है उनके कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरह से हम भी उनके इस अधिकार को नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जमीन का बटवारा समझौते से होता हो तो भी हमारी पार्टी की नीति यह है कि किसी भी जमींदार को एक लाख से ज्यादा मुआविजा नहीं दे सकते। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस बात पर भी गौर किया जाय और देखा जाय तो मान्य

[श्री राजागम शास्त्री]

होगा कि जितने यू० पी० के जमींदार हैं, उनमें शायद ही कोई बच गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ८ अगस्त सन् ४६ ई० के बाद, जब से यह प्रस्ताव आपने पास किया है कि हम जमींदारी को खत्म कर देंगे तब से जमींदारों ने देहातों में खूब पैसा लूटा है। जमीनें लूटी हैं, पेड़ों को लूटा है, तालाबों को लूटा है और रास्तों को लूटा है। जिस किसी तरह से भी हो सका है उन्होंने लूटा है। अगर सरकार इस बात की जांच करावे कि ८ अगस्त सन् ४६ से लेकर आज तक यू० पी० में जमींदारों ने कितना लूटा है और कितना नजराना लिया है, कितना अपने घरों को मरा है तो मेरा अपना ख्याल यह है कि शायद किसी को मुआविजा देने की जरूरत आपको महसूस न हो। क्योंकि जितना मुआविजा आप देंगे उतना मुआविजा तो उन्होंने किसानों को मारपीट कर या गैरकानूनी तरीके से वसूल कर लिया है। और मेरा अपना ख्याल यह है कि जबतक यह कानून पास होगा और पास होकर ऐक्ट बनेगा तब तक देहातों में वे एक भी पेड़ को बाकी न छोड़ेंगे। किसी पेड़ को अगर उन्होंने छोड़ दिया तो यह बड़ी गनीमत की बात होगी। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि देहातों की किसी तरह से रक्षा हो सके और आगे कोई पेड़ नहीं कट सकें तो जितनी जल्द हो सके इस सम्बन्ध में एक आर्डिनेन्स पास करें कि आज के बाद कोई पेड़ कटने नहीं पावे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि लाठियों से सर फूटने तक की नोबत आ जायगी। और यह देखा गया है कि अक्सर जमींदार लाठी के जोर पर गैरकानूनी कार्यवाहियां करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि किसान भी तैयार होते हैं और इस तरह से झगड़ा बढ़ता है और इस तरह की सब चीजें होती हैं।

( एक आवाज :— "इस तरह का आर्डर मेज दिया गया है। )

अगर इस तरह का आर्डर मेज दिया गया है तो यह बड़ी खुशी की बात है। ऐसे : को इसी तरह से रोकना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरह से जमींदारों ने बहुत काफी मुआविजा वसूल कर लिया है और अब अगर उनको मुआविजा नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आयी कि हमेशा कांग्रेस अपनी तमाम जिन्दगी चिल्लाती आयी कि दौड़ सौ रुपये तक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों की हैसियत किसानों की है, वे गरीब हैं, काश्तकार हैं, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन जब मुआविजा बांटने का सवाल आया तब मैं देखता हूँ कि आप मालगुजारी को तादाद बढ़ाते चले जाते हैं कि ५ हजार तक जो मालगुजारी देते हैं उनको इतना मुआविजा मिलेगा। यह तो मैं नहीं कहता कि आप जो दौड़ सौ रुपया तक मालगुजारी देते हैं उनको मुआविजा न दीजिये। मैं जमींदारों को तबाह नहीं करना चाहता। आप जिस तरह से दूसरे लोगों की मदद करते हैं, शरणार्थी लोगों की सहायता करते हैं, जो जमींदार गरीब हैं और उनकी जमीनें लेते हैं तो आप उनकी अवश्य सहायता कीजिये, उस वक्त तक जब तक कि वह दूसरे धंधे में न लग जायें। लेकिन आप तो जमींदारों की, बड़े जमींदारों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। त्रिपाठी जी ने यह बात कही कि हमारी समझ में नहीं आता कि मुआविजे में और पुनर्वासन में क्या फर्क है। आप की समझ में न आवे लेकिन हम लोग इस बात को मानते हैं कि अगर आप जमीन का बटवारा करने को तैयार हैं तो मुआविजा देने का सवाल है। अगर आप जमीन का बटवारा करते हैं तो हम मुआविजा देने को तैयार हैं और अगर आप जमीन का बटवारा करने को तैयार नहीं हैं तो

हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि मुआविजा दिया जाय। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो लेकिन हम इसको सही मानने हैं और अगर आप दूसरी पार्टों की बात सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं तो आपका समझाने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने इसी के साथ यह मंजूर किया है कि यू० पी० की किसान व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी जो है वह है अनएकनामिक होल्डिंग्स की; आज देहातो में बहुत सी अनएकनामिक होल्डिंग्स हैं। आपके यू० पी० के अन्दर देने जों बहुत हैं जो लानकर नहीं हैं। किसान उसमें खया भी खर्च करता है और मेहनत भी लगाता है। सब कुछ लगाता है लेकिन उसके पास इतना भी नहीं होता कि वह अपना घेठ भर सके। स्वयं जमींदारी उन्मुक्त समिति की रिपोर्ट पृष्ठ २१ पर आपने यह स्वीकार किया है कि इस समय जैसी कृषि-व्यवस्था है उसके अनुसार छोटे और दूर दूर स्थित खेतों में किसान और हल खींचने वाले बैलों की शक्ति और श्रम का उतना उपयोग नहीं होता जितना होना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकतम लाभ नहीं हो पाता। प्रान्त की कृषि-प्रगती का सबसे बड़ा दोष यही है। साधारणतः इस दुर्न्यवस्था से उन्नति में बाधा पहुंचती है और कहीं कहीं तो प्रगति एकदम ठन हो जाती है। तो हमने इस बात को देखा कि जब आप इस बात को मानने हैं कि आज देहातों में यह अवस्था हो गई है तब भी आप इसको दूर करने के लिये ऐसी अधूरी कोशिश कर रहे हैं। किसान खिदमत करते करते आज इस नतीजे पर पहुंचा कि आज उसकी हाज़त यह है कि वह लगान भी नहीं भर पाता। हमें इस बात को मानना पड़ता है। दूसरी ओर इसी रिपोर्ट के पृष्ठ २८ पर भी यह बात मानी गई है। आज कहा यह जाता है कि लड़ाई के जमाने में चीजें बहुत तेज हो गई हैं, किसान बहुत मायामाल हो गये, किसान की हाज़त बहुत अच्छी हो गई इसलिये अक्सर जनता का ध्यान इन बात की ओर दिलाया गया है कि अगर किसान गल्ल नहीं देता है तो वह बड़ो बेईमानी करता है और शहरों के लोगों को भूखा मारना चाहता है। लेकिन इस रिपोर्ट के पृष्ठ २८ पर यह मान लिया गया है—“यह सब देखते हुए हम बेखटके कह सकते हैं कि चीजों के दाम बढ़ने से किसी भी तरह अभान्वित होने को कौन कहे अधिकतर किसानों में इतना दम नहीं रह गया कि वे थोड़े समय तक भी गल्ल दबाकर रख सकें। प्रान्तीय सरकार की गेहूं की खरीद सम्बन्धी रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग ४० प्रतिशत खेतिहरों के पास बेचने को कुछ बचता ही नहीं। शेष ६० प्रतिशत लोगों में ३३ प्रतिशत को लगान, कर्ज और अन्य प्रकार का भार उतारने के लिये समूचा गेहूं बेच देना पड़ता है। इस प्रकार केवल २७ प्रतिशत किसान ऐसे बच जाते हैं जो अतिरिक्त गल्ल दबाकर रख सकते हैं।” आज लड़ाई के जमाने के बाद काश्तकारों की हाज़त यह है कि तनाम मेहनत करने के बाद भी, पैसा लगाने के बाद भी और सब कुछ करने के बाद भी उनके पास इतना भी नहीं बचना कि वह लगान अच्छी तरह से चुका सकें। ६० पी सदी ऐसे लोग हैं जो कि भिरा गल्ल पैदा कर सकते हैं और लगान दे सकते हैं, लेकिन और जो उनकी जरूरियात हैं उनको वह पूरा नहीं कर सकते। हमारी समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट किस लिये तैयार की जाती है। रिपोर्ट इसलिये तैयार की जाती है कि जांच हो और आंकड़े तैयार किये जायं। उसने जो हाज़त मायूम पड़े उन हाज़त को देवकर उनके अनुसार उसका इलाज निकाला जा सके और जो मुसीबत है वह दूर हो सके। जब जांच करने के बाद हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि लोगों के पास मौजूदा अनएकनामिक होल्डिंग के

[श्री राजाराम शास्त्री]

होते हुए भी गरीबी मिट नहीं सकती तो उसका प्रबन्ध करना भी जरूरी है। जब आप किसानों की इन सब बातों को लेकर इस बिल को यहां पर लाये हैं तो जितनी अनएकनामिक होलंडिंग हैं उनको एकनामिक बनाया जाय। मेरा कहना यह है कि इस बिल में सिर्फ कोशिश यह होनी चाहिये कि अगर कोई आदमी खेती करता है तो कम से कम उसको इतना तो मिल सके जिससे कि वह अपना और अपने बाल-बच्चों का पालन पोषण कर सके। अगर इस प्रकार आप नहीं कर सकते तो फिर इससे कोई लाभ उनकी पहुंचने वाला नहीं है। और यू० पी० के अन्दर आज आपको जितने किसान खेती करने वाले दिखाई देते हैं उनमें से कितने ही किसान ऐसे होंगे जो अपनी खेती-बारी के काम को छोड़ देंगे और कितने को तो अपनी ज़मीन ही बेच देना पड़ेगी या किसी कारखाने जगह में भागना पड़ेगा या कहीं दूसरी जगह जाकर कोई काम करेंगे क्योंकि खेती के अन्दर उनको कोई उल्लास पैदा नहीं होगा। इसलिये कोशिश यह होनी चाहिये कि जितनी अनएकनामिक होलंडिंग्स हैं उन सब को एकनामिक होलंडिंग बनाया जाय। अब इसका तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो यह है जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जो जमींदार हैं उनके पास दो सौ या खुदकाशत हैं उसके लिए आप एक मियाद मुकदर करें कि १० एकड़ या २० एकड़ या ३० एकड़ से ज्यादा कोई जमींदार नहीं रखेगा। उनसे जो जमीन बच जाती है वह ज़मीन उनसे ले लीजिये। मैं जानता हू कि उनके जमीन देने के बावजूद भी कुछ किसान ऐसे बच जायेंगे कि जिनको जमीन नहीं मिल पायेगी, लेकिन मैं यह दखील नहीं मानता हू कि सब को नहीं मिल सकती है, इसलिये हम यह न करें। मैं बड़े अदब से सरकार से यह निवेदन करता हू कि किसी काम को करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि कोई भी काम करने की वजह से जनता पर प्रभाव क्या पड़ता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि कोई भी काम करें उससे जनता पर बहुत असर पड़ता है। कहा जाता है कि अगर उनसे जमीन आप ले लेंगे तो इससे क्या होता है। १०-२० एकड़ जमीन लेने से क्या होता है। लेकिन आप यकीन मानिये कि एक परसेंट या दो परसेंट जमीन आप यदि उनसे लेते हैं तो जिस दिन यह ऐलान होगा कि कोई जमींदार अपनी ज़मीन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकेगा और अगर रखेगा तो उससे वह ज़मीन छीन ली जायगी तो इससे जनता के अन्दर, किसानों के अन्दर बहुत बड़ा उत्साह पैदा होगा। यह बात तो है कि ज़मींदारी के खातमें से किसानों के अन्दर, उत्साह पैदा होगा लेकिन मेरा यह दावा है कि चाहें एक या दो परसेंट ही क्यों न हो जिस दिन आप यह ऐलान कर देंगे कि ज़मींदारों की जमीन ले ली गई है जिन पर कि उनका बहुत पुराना कब्ज़ा था, जब यह किसानों को मालूम होगा, चाहे थोड़े आदमियों को मालूम हो, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा पड़ेगा। इससे भाग नहीं खेती भी कर सकेंगे और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी आप दे सकेंगे। तीसरी बात यह है कि जब ज़मीन का बंटवारा हो तो मेरी राय यह है कि उसमें कोशिश यह होनी चाहिये या आप कोई ऐसा संशोधन कर सकें कि कोई भी काश्तकार अगर अपनी ज़मीन को बेचता है तो खरीदने का पहले हक उसको होना चाहिये जिसके पास जमीन नहीं है। बहुत सी ज़मीन ऐसी हैं जिसमें हमारा काम पूरा नहीं होता, जो पूरी तरह से पैदावार नहीं करती हैं। तो पहले हक उस व्यक्ति को होना चाहिये कि जो व्यक्ति उस अनएकनामिक होलंडिंग को लेकर उसको एकनामिक होलंडिंग बना ले। अगर उसके बाद भी कोई ज़मीन वैसी हो तो वह फिर

उससे ले ली जाय। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर सब अपनी कंठिध में उस जमीन को एकान्तिक होलेंडिंग बना लेंगे और वह बगलर आनी कोशिश करने लेंगे। जिसके पास अन्तः-कानानिक होलेंडिंग होगी वह एकान्तिक होलेंडिंग बना लेगा। अगर आप इस तरह से कोई संशोधन कर सकें तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ मदद मिल सकती है। एक बात कही गई कि जमीन का बंटवारा एकदम से नहीं हो सक्त, अगर जमीन के बंटवारे में अंतर तनाम दली दें तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन बड़े मार्के की बात यह है कि हममें यह दली द गयी है, प्रष्ठ ३९७ पर कहा गया है, ऊपर कहा है कि हम मनजो हैं कि बिना जमीन के बंटवारे के कैसे काम चल सकता है, जमीन का बंटवारा बहुत जरूरी है, लेकिन आखि में दली द दी जाती है—“इसके विरुद्ध हमें इस तथ्य के सम्बन्ध में यह सोचना विचारना है कि इनके फलस्वरूप समृद्ध खेतिहरों, जमींदारों और कारनरों में विरोध की भावना उत्पन्न होगी, जमींदार लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे और उनकी आय जमींदारी उन्मूलन की हनारी योजना से, कितनी भी शालत में घट जायगी।” जहां कहीं समस्या के मुद्दों ने का प्रश्न आया गवर्नमेंट रिपोर्ट देखिये, कानून देखिये, हर जगह यही लिखा हुआ है कि जमींदार नाराज हो जायेंगे और जमींदारों के बीच में कठिन-इयां पड़ जायेंगी, बेचारों को जो रुपया मिलने वाला है उसमें कमी हो जायगी। अगर आपका कहना यह है कि जमीन नहीं बंट सकती है क्योंकि कहीं जमींदार कठिनाई में न पड़ जायें, चाहे किसान कठिनाई में पड़ जायें या न पड़ें, तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। जब तक देहातों में आप इस बात की कोशिश नहीं करेंगे कि जमीन का बंटवारा हो तब तक एक नहीं दस उपाय आप सोचिये देहातों की गरीबी दूर नहीं हो सकती। जो हमारी काबिठ सरकार दुनिया के बड़े बड़े कानूनों को पास कर लेती है उसकी समझ में कोई बात इस समस्या को सुझाने के लिए न आवे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरी एक बात और समझ में नहीं आती है कि जहां कहीं कोई इन्कलव होता है, इन्कलव होने के बाद जब कोई पार्टी पावर में आती है वह जमीन का कैसे बांट लेती है। पन्त जो को हनेश दली यही होती है कि “जमीन कोई खड़ नहीं है कि हम उसको बड़ा लें। आज तो जमीन खड़ नहीं है, कठ, मैं पूछता हूँ कि फ्रांस की क्रांति जब होती है और वहां के क्रांतिकारी नेता जब पार्लियामेंट में बैठते हैं तो कैसे किसानों में जमीन का बंटवारा करने बैठते हैं, जब कि हिन्दोस्तान की जमीन खड़ नहीं बन सकती है तो क्या वहां की खड़ बन सकती है? अगर यह समस्या आप नहीं सुझाते तो किसान खुद आ कर सुझा लेंगे। तब आप देख लीजियेगा कि कैसे खड़ की तरह बढ़ती हुई नजर आती है। आज तो आप इन तरह की बहस करते हैं कठ आप सोचिये कि सन् ४२ का आन्दोलन सकल हो गया होता और आप पार्लियामेंट में बैठे होते और यहां पर क्रांतिकारी किसान बैठे होते और किसानों के बीच में जमीन का बंटवारा हाता तो क्या यही दली दी जानी कि जमीन क्या खड़ है? राजा जगन्नाथ बख्श सिंह को नाराज मत करो, क्योंकि जमींदार बेचारे कठिनाई में पड़ जायेंगे, क्या यह दली मुनासिब होगी? जमीन खड़ हो या नहीं हो, लेकिन किसान जब गद्दी पर बैठेगा तो वह जमीन का खड़ की तरह खींच कर और बांट कर दिला देगा। मालूम यही होता है कि आपमें वह जोश नहीं है, हिम्मत नहीं है, वह भावना नहीं है जो क्रांतिकारियों में होती है, बिनका खयाल होता है कि हमें यह समस्या इस प्रकार से हल करनी है जिसमें जनता और गरीबों का हित हो। जिस वर्ग का नाश करने के लिए आप बैठे हैं उसी के

[श्री राजाराम शास्त्री]

लिए आप सुबह से शाम तक सोचते हैं, ५ हजार और ऊपर तक वालों को नुआविजा देने की बात करते हैं, उनको नुकसान न हो, वह कठिनाई में न पड़ें इसलिये जमीन न बटे। अगर उनकी की नाराजगी का सारा खयाल है तो यह जो जोश आप पैदा कर रहे हैं किसानों में कि इन समस्याओं को आप हल करना चाहते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यह इस तरह से हल नहीं होगी। यह तभी हो सकती है जब कि कांग्रेस सरकार इस भावना को लेकर बैठे कि हमको यू०पी० को गरीबी को मिटाना है, देहात की हालत को ठीक करना है। इसके लिए अगर जमींदारों को नाराज भी करना पड़े और समस्या हल करने के लिये यह जरूरी हो तो यह भी करके इनको इसे हल करना चाहिये। लेकिन जो कुछ किया जा रहा है उससे तो यह अधूरे ही रह जायगी।

साथ ही साथ मैं यह देखता हूँ कि कल सवाल उठा कि आखिर ये बाग बगीचे जमींदारों के पास क्यों रहने देते हैं? एक जगह रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बाग जमींदारों से इसलिये नहीं ले सकते क्योंकि जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें अभी इतनी काबलियत नहीं है कि वह जमींदारों के बाग का इन्तजाम कर सकें। इन ग्राम पंचायतों को आने विलेजरिपब्लिक की सूरत में कायम किया है। उनमें इतनी अकल है कि वह देहात का पूरा प्रबन्ध कर सकती हैं और लगान भी आप उनसे वसूल करवायेंगे। यह काम करने की अकल उनमें आ सकती है, मगर एक बात की अकल उनमें नहीं है कि जमींदारों के बाग बगीचों का इन्तजाम कर सकें। फिर वही बात आ गयी। सब कुछ होता है। लेकिन जा हमदर्दी उनके लिए आपके दिल में छिरी है, वह हर मुकाम पर, हर मौके पर आ जाती है, हर जगह पर, ऊपर से नीचे तक उनके लिए हमदर्दी, हमदर्दी, हमदर्दी। तो यह चीज जब तक है, तब तक मेरा यह कहना है कि आप चाहे जितनी डुग्गी पीटिये, १५ अगस्त मनाइये, दिवाली मनाइये, लेकिन किसानों के हृदय में प्रकाश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक आप इस बिन्दु में यह मुधार नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी।

साथ साथ लगान का सवाल भी आता है। हमने देहातों में यह नारा बुलन्द किया है कि जिन किसानों की अनएकानामिक होल्डिंग है उनका लगान और आपनाशो आवे कर दिये जायें। हमारे कांग्रेस पार्टी के दोस्त रोजमर्रा कहते हैं कि नारों से काम नहीं चलेगा। नारों की बात गैर-जिम्मेदारी की बात है। सारी जिन्दगी गैर जिम्मेदारी का काप करने के बाद, आज गद्दी पर बैठते ही आपको अकल आने लगी। अगर कोई यह कहे कि जमीन को इस ढंग से बांटो, बाग बगीचों और सीर का इस तरह इन्तजाम करो, लगान आधा करो, तो यह गैरजिम्मेदारी की बात है। सारी जिम्मेदारी की बात वह है जो मैंने आपके सामने अभी पेश की है। किसी काम को करने का ढंग भी होना चाहिये, अगर आज आप यह ऐलान कर दें कि जो अनएकानामिक होल्डिंग, गरीब किसानों की है, जिनके बारे में लिखा है कि किसानों का दम निकल गया है, वे मुर्दा हैं, अगर आप यह एलान कर दें कि हमने उनका लगान आधा कर दिया है जो मुर्दा हो चुके हैं, तो देहात के किसान को क्या महसूस होगा? सचमुच वह महसूस करेगा कि अब जमींदारी का खात्मा हुआ, और हमें आजादी मिली। काम को इस ढंग से कीजिए, जैसा कि पं० जवाहरलाल नेहरू अक्सर यह शब्द इस्तेमाल करते हैं कि “ब्लो आफ फ्रीडम” हो जाय। आजादी का प्रकाश उसके दिल में आलोकित हो जाय, और वह अनुभव करने लगे कि अब हम आजाद हो गये।

हमें यह कहना कि जमींदारों के पास जाइये, कलेक्टर के पास जाइये, तहसीलदार के पास जाइये, पुलिस थानेदार के पास जाइये, उनमें सभमें आपको वह 'ग्रेज आन कोडन' मिलेगी। लेकिन मैंने वह 'ग्रेज आन कोडन' नजरूर और जिन न ने नहीं देखी। इस बात को कहते हुए मुझे यह आशा श्री निश्चयनगढ़वाल विप्लवों ने कहा कि "एक दिन प्रान्तीय महाराज ने मुझसे पूछा कि 'क्यों भाई विप्लवभक्त हमारे राज्य में जनता का क्या हाल है। उनका आजादी का प्रकाश मिला या नहीं?' मैंने उनसे कहा, आपके राज्य में आजादी की फिरंगें घर घर में, हर किसान के यहां बूट निकली हैं।" मुझे यह सुन कर बड़ा आनंद हुआ। (एक आवाज), बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि करीब करीब नानक्य वही रहा होगा। शायद उसका जिक्र आपने जरूर किया था। ए० आ०। अच्छा अब मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत ही कह रहा हूं, पर विप्लवों की बात सुन कर मुझे यह अनर पड़ा कि वह जनता था जब कि राजा महाराजा बाहर निकल करने थे तो अपने मुसाद्वियों से पूछने थे कि "कहीं हमारी प्रजा का क्या हाल है?" तो वह कहते थे कि 'जहांनाह मला आपके राज्य में कहीं तकलीफ हो सकती है, जहां देखिये दो-दूध की नदियां बहती नजर आ रही हैं।' वही हाल यहां हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब आप जरा सुन लीजिये क्योंकि आपने भी बहुत कुछ कहा है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि जमींदारी का अगर आप खत्म करने हैं तो दो चार बातें ऐसी कर लीजिये जिनकी वजह से गरीब दुर्ग किसान यह महसूस करें कि जिन्दगी भर कांग्रेस के लिये मरे, अपनी जमीनें कुर्क करार तथा बेगल होये, ऐसी हालत में कांग्रेस ने कुछ रियायत की है और कुछ लगान माफ किया है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि जो किसान गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है उनका अगर आप आधा लगान कर दें तो इस बिल के पास करने के बाद उनके दिलों में एक बड़ा भारी उछाह पैदा होगा।

एक बात मैंने इस कानून में ओर खूबी की देखी और वह यह है कि अगर यह कानून पास हो जायेगा तब भी इसके लागू करने का तुलना ऐसा निकाला गया है कि कांग्रेस सरकार यदि चाहे तो सबको रुक दे। इसकी धारा ५ या शायद ६ में लिखा है कि जिन जगह सरकार नुनामिब समझती गवर्नर ने निकाले वहां पर यह लागू होगा लेकिन मैंने दिखाई यह पड़ता है कि जिस दिन यह कानून लागू होगा उसी दिन से सारे यू० पी० में जमींदारी खत्म हो जायेगी, लेकिन वास्तव में जब पार्लियमेंट नुनामिब समझेगी और गवर्नर ने चापेगी वहां लागू होगा। इसमें लफ्ज 'अपेक्षा' लिखा हुआ है। मुझे डर है कि इसका भी कहीं नकलिया या सा दुरुपयोग हो कि मन्त्रिमंडल जमी है और अगर सरकार का आमतनी भी बड़ रही है। वैसे ही कहीं कहीं जमींदारी खत्म हो जाये और मन्त्रिमंडल जगह २ दिखाई पड़े कि कलां जिले के कलां परगने में अभी जमींदारी बची है। अगर कांग्रेस को ओर से कहीं यह प्रोपोजंडा कर दिया गया कि जो कांग्रेस का विशेष फायदा उत्पन्न होगा ही है, फौज उठी जगह कानून लागू हो जायेगा। कोई शक अगर कुछ व्यवस्था करेगा तो पहले वर्षों यह कानून लागू किया जायेगा। ऐसी हालत में आप यह ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि कलां तारीख से सारी यू० पी० में यह लागू होगा। अपेक्षा गये तो यह नहीं हुआ कि दिल्ली से चला कर कानपुर रुक गये हों या लखनऊ रुक गये, या बनारस या कलकत्ते रुक गये हों वह तो एकदम चले गये और आपका हिन्दुस्तान एकदम अजाद हो गया है। अगर देहानों से आप जमींदारी खत्म करते हैं तो ऐसा



[श्री राजाराम शास्त्री]

ही कर जैसा कि और कानूनों में करते हैं कि फार्म तारीख से यह कानून सारे यू० पी० में लागू होगा। इसमें क्या खस बात है आने तीन सत्र में जमींदारों को किसानों के रुपये का दौम दिया है। फिर अब भी यह बात है कि यह कानून न जगद एन साथ लागू न होगा। यह गलत बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को पारित करने के प्रयत्न में लोगों के दिलों में आशा का कभी संचार कर दिया है और किसान आशा लगाने लगे हैं। इसलिये इसकी दफाये ऐसी हों उनमें ऐसे सुधार हों जिनसे गरीब किसानों को कुछ राहत मिले। मैं कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों से अपील करता हूँ कि वोट आप कांग्रेस को देगे ही, जल्द दीजिये लेकिन जो लोग देहात की समस्याओं को समझते हैं, अपना कुछ अनुभव रखते हैं और समझ माहिर हैं और मैंने सुना है कि दारुणशक्ता में लोग ऐसा कहने भी हैं कि इसमें यह कमी है, वह कमी है, लेकिन पार्टी अनुशासन के कारण बोल नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि अगर वोट चाहे कांग्रेस को ही दीजिये लेकिन आपका जो अनुभव है, जो आनकी कावचियन है उसके आधार पर आप इस हाउस में आने सजेडन्य तो जरूर दें। यह कोई आप लोगों के खिलाफ वोट आफ सेंसर नहीं हो जायेगा। इसलिये मैं कुछ मेम्बरों से उम्मीद करता हूँ कि वह ज़रा हिम्मत दिखायें, कुछ साहस का संचार करें क्योंकि यह गंगेशों का मानना है। जो शिङ्खू कास्ट के मेम्बर बैठे हुए हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिज से खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। आज ज्यादातर जो खेतिहर मजदूर हैं वे अश्रुत जग्गि और शिङ्खू कास्ट ही के हैं और उनके लिए भ्रम २० नेम्बर ही सब कुछ करा सकते हैं यह मुझे यकीन है। चाहे मेरा ऐसा कहने का मतलब यह भन्ने ही लगाया जाय कि मैं कांग्रेस के बाहर का हूँ और कांग्रेस में फूट डालने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर अभी इतने कमजोर हो गये हैं कि वह मेरे या किसी के बहाने में आ सकें। उनके पास इतनी अकल है और इतनी ताकत है कि वाकई अगर वह २० मित्रकर हाउस में लड़े तो जरूर करें कि अछूतों के मसलों को लीजिये तो मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस पार्टी उनके लिये कुछ करने को तैयार न होगी। मैं नहीं जानता कि सेलेक्ट कमेटी में शिङ्खू कास्ट के कितने मेम्बर थे व कोई नहीं था लेकिन मेरा विश्वास है कि शिङ्खू कास्ट के मेम्बर उसमें नहीं रहे होंगे और अगर होते तो मेरा दावा है कि बिज में उन गरीब खेतिहर मजदूरों की समस्या ऐसे न छोड़ दी जाती और कुछ न कुछ तरीका जरूर होती। मैं शिङ्खू कास्ट के मेम्बरों से कहना हूँ कि आप खूब कांग्रेस की भक्ति काजिये, चाहे मुझे गाठिया सुनाइये लेकिन गरीब खेतिहर मजदूर जो आपके भाई हैं उनके लिये कुछ तो करिए। चाहे आपके विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी शुद्ध से आखिर एक पन्त जी की इमनिस्टरी के गुगगान करने रहें और एक दफा भी नेता जी, आजाद हिन्द फौज और पुराने जमाने का जिक्र तक न करें और न पुराने जमाने का और समाजवाद वगैरा किसी चीज का भी जिक्र करें। उन्होंने भी आखिर मे खेतिहर मजदूरों के लिये दो असू बहाल हैं। जब ब्राह्मण होते हुए श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी को उनका ख्याल है और उनकी भक्ति है तो क्या शिङ्खू कास्ट के मेम्बरों को अपने भाइयों का भी ख्याल न होगा। मैं उनको याद दिलाता हूँ कि त्रिपाठी जी ने इस बात को तरफ जाकर के साथ इशारा किया था। इसके अलावा और भी पेंतरेबाज़ी दिखलाई कि हमने आपके महारथियों को घराशायी कर दिया, और यह बहादुरी दिखलाई और



[श्री राजाराम शास्त्री]

है। कानून में और उन्नत में जाकर पूछिये कि वहां क्या हो रहा है। जो आदमी खुद कांच के मकान में रहता हो वह दूसरे पर टैच फेंके, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहता कि पर्सनल बातें यहां हाउस में उठाई जायें। आप में खराबी हो सकती है और हमें भी खराबी हा सकती है। कांग्रेस पार्टी को ही लीजिये। फलों ने रिवत ली, फलों ने चोरी की। एक आदमी अगर बदमाश साबित होता है तो इसके लिये कांग्रेस पार्टी को बदनाम नहीं किया जा सकता। इस तरह से काम नहीं चल सकता। इसके हल करने का तरीका यही हो सकता है कि एक भी व्यक्ति जो बेईमान हो और कांग्रेस पार्टी में चुन आया हो आप उसकी निन्दा करें कि उसे निकाल दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को चाहे वह कांग्रेसी हो या सोशलिस्ट उसे कोई जगह नहीं मिलना चाहिये लेकिन अगर कोई सोशलिस्ट गलती करे और हाउस में खड़े होकर सारी पार्टी और जयप्रकाश को एक ही घाट पर उतार दें यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता। सोशलिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान में खड़ी है गरीब जनता के हित में, आप जैसे हजारों आदमी कोशिश करें कि भी वह मर नहीं सकती, वह जिंदा रहेगी आप उसे भिटा नहीं सकते। मुझे सबसे ज्यादा अरुसोस इस बात पर हुआ कि इस हाउस में और कोई कहे तो कहे, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी जी ने इस तरह की स्वीच दी। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्होंने कौन से घाट का पानी नहीं पिया। आप नेताजी के भक्त रहे, और न जाने किस किस के भक्त रहे। आखिर वक्त तक आप जोर दे देकर कहते रहें कि हम क्रांतिकारी हैं, नेताजी के साथी हैं, कांग्रेस गद्दार है, हम कांग्रेस को छोड़ देंगे। हमसे कहा कि आप विश्वास रखिये ४ दिन के बाद ही चर्चा आऊंगा लेकिन जब विश्वास हो गया कि नेताजी जिन्दा नहीं हैं और अब उनके नाम पर ज्यादा दिनों तक दुःखान नहीं चल सकती तो सोचा चलो भाई कांग्रेस हां में रहो। जब तक यह विश्वास था कि नेता जो जिन्दा हैं तब तक बड़ी बड़ी बातें बनाते रहे। यह बहुत गलत तरीका है। इस तरह की बहस हाउस में नहीं होना चाहिये। बहस इस बात पर हो कि मजिस्टर को क्या दफा दिये जा रहे हैं और सीटदार को क्या हक मिल रहे हैं। बहस इस बात पर हो कि इसमें सुधार कैसे हो। जिस दिन पंत जी ने तकरीर की उस दिन से सब पर सोशलिस्टों का भूत सवार है। बिल पर किसी शख्स ने कोई बहस की होती तो बात थी, शुरू से आखिर तक जितने सज्जन बोले केवल इसलिये कि अखबारों में खबरें छप जाय। यह छप जाय कि सोशलिस्ट बदमाश, अंधाचारी आर धूर्त हैं। यह छप जाय कि कांग्रेस इस जमींदारी बिल को लाई है, कांग्रेस ने कांग्रेसियों का नाश किया है। न मालूम क्यों यह डुंगी पिटवाने का शौक चर्चारा हुआ है। मेरा तो कहना है कि अगर सही काम होगा, किसानों का फायदा होगा, मजदूरों को लाभ होगा, तो खुद डुंगरों डुंगी पिटेगी, इस तरह की देकार बातें करना मुनासिब नहीं है।

दुर्गे बनारसीदास आये, वह थे श्री अल्लभूराय शास्त्री। इनको तो सबसे ज्यादा दोश उतार हो गया था। मुझे तो भूतपूर्व सनजवादीयों से बड़ा शोम होता है शर्मा भी लगनी है। अल्लभूराय जी ने जनता स्पीच में बड़ी बड़ी बातें कहीं। मार्क्स से लेकर, लेनिन और स्टैलिन नवत द्वाय दे डाक और फिर जाकर हवनकुंड में गिरे। ऐसी स्वीच दी कि हाउस में मालूम पड़े कि वह पक्के सोशलिस्ट हैं लेकिन फिर भी जो संस्कार पड़े हैं वे कैसे छूट सकते

हैं। अन्त में हस्तक्षेपों का सम्मेलन ही निगले, मादाम, लेनिन और स्टैलिन का नाम भी आवाज़ में नैला ही मुँह में चढ़ना है कि इनके पास नहीं होगा।

कमाली चीन में अपने क्रांती के नाम से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना इस दृष्टिकोण बना लें, जो आपका भी मान्य हो और सुनने का भी मान्य होना। जब तक एक दृष्टिकोण नहीं रहता—जब तक आपका ही सुनना है और सुनने का भी। जब कोई क्रांती नहीं स्वीच देने लगे होते हैं तो कहते हैं कि हमने यह कुरखानी की, यह किया वह किया, १९२२ में यह किया, १९२५ में यह किया, १९५२ में यह किया, जितना भी डींगें हो नकली हैं मार जने हैं। यह इसलिये कि मुल्क में यह करना पैदा हो जाय कि जब इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया है तो अब मुल्क के आजाद हो जाने के बाद अगर वे चाहे पाव भी कर लेते हैं तो क्या बात है। धुकेर जी ने अपनी स्वीच में और ही रंगत दिव्यार्ह। बड़ी बड़ी बातें सुनाईं। आरंभ बताया कि कितना जादू हम लोगों ने किया, कितना कमाल किया। आपने कहा कि जब एक दिन रात को सोये तो सुबह उठकर क्या देखते हैं कि मुल्क आजाद हो गया। कैसा बड़ा जादू टोना हुआ। यही यह जादू टोना क्रांतिमें का किया हुआ था कि रात को वे जागरी सोये और सुबह मुल्क आजाद मिलवाई पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि १८५७ में केवल उन देश-भक्तों ने अपना खून अर्पित, जो क्रांती के तख्ते पर लगे, क्या उन्होंने देश की आजादी के लिये कुछ नहीं किया। हिन्दुस्तान के हजारों किसान और मजदूरों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जने कुरखाने पर दी उनका इन क्रांतिमें का कोई खयाल नहीं है। यही जो हमने मजदूरों से उनका कोई अंतर देश की आजादी लाने में नहीं पड़ा। क्या आप मनसुब हैं कि इस जगह से ही आपने हिन्दुस्तान को आजाद कराया है? कौन नहीं जानता कि आतंकी दजह में हिन्दुस्तान जामुत हुआ, आजाद हुआ, लेकिन यह बड़े स्वार्थ की बात है कि आप अपना दिव्यार्ह नीचे डाल कहें कि हमारे इस जादू की वजह से ही हिन्दुस्तान आजाद हुआ। यह इसलिये है कि क्रांती जनता में यह सारका बली पैदा करना चाहते हैं, कि जिस जादू के जोर से एक रात में अंग्रेजों को भगा लेंगे, उसके ऊपर यकीन रखे और धीरे धीरे उर्ध्व जादू के दाय से मुंजीमियों को हटा देंगे, जर्मनियों को हटा देंगे, और गान्धोगी देखने देखने एक दिन में पैदा कर देंगे। इनमें उनका का कोई दिन नहीं हो सकता, इस जादू टोने की बात से काम नहीं चलेगा।

अंत में मैं क्रांती वीरों से यह कहूँगा कि आप जो कुछ कार्य और जिसे आपने हाथ से सामने पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा मान्य है कि हमने सुनने अंग्रेजों, हमारा मूँवा अंग्रेजों बड़ेगा, परन्तु जो कदम आपने उठाया है वह कदम उनका आगे नहीं जाता, जिनको कि भाँकर स्थिति देश के सामने उपस्थित है। इस क्रान्तिकारी कदम को जब आरंभ उठाया है तो हमारे जो स्थिति उपस्थित होते बाँकी है उनका देखते हुए मेरा कहना यह है आप उन वर्गों को अपने साथ लेने की कोशिश कीजिये जो वर्ग इस कानून के पास हो जाने से असंतुष्ट होंगे। और जब आप उनके उनसुने की कोशिश करेंगे तभी वे नतुष्ट हो सकेंगे। अब जो नयी राजनीति आ रही है उस राजनीति में अंग्रेजी संघर्ष कम नहीं होगा और बढ़ेगा। मेरी दिव्य खयालिय है कि आतंकी कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी साथ में आगे बढ़ें। मेरा यह भी विश्वास है कि आज की हालत में अर्द्धत मानिये अब मैं आतंकी आगे चना करता हूँ तो मेरी निगाह इस बात पर रहती है हमारा देश ऊपर की उठे। कांग्रेस पार्टी का

[ श्री राजगोपाल अक्षरी ]

बोधी होते हुए, सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर होते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम चाहे किनकी ही आनकी मुखालिफत करें, और हालांकि ऐकनिया आपको गद्दी से उतारना चाहते हैं लेकिन अगर आप अच्छी तरह राज्य करते हैं तो बढ़ने दिये कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो अवश्य ही गद्दी से उतारे जायेंगे। अगर हिन्दुस्तान के राजे महाराजे अगर हिन्दुस्तान के पूँजीपति और जमींदार, अगर हिन्दुस्तान के आर०एस०एस० वाले और कम्युनिस्ट अगर राष्ट्र का विरोध करेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी अपनी पूरी ताकत से हर एक का विरोध करेगी और आरक्षक रक्षा में सदा उद्यत रहेगी। हम नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान में कोई खून खराबी हो, जो आज्ञादी हमने प्राप्त की है वह गड़बड़ में पड़ जाय। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बीड़ा आपने उठाया है और जो बात हम कहते हैं उस पर आप विचार करें। हम दावे के साथ कहते हैं और इमलिए कोई बात कहते हैं कि आप एक कदम और आगे बढ़ जायें। पन्तजी ने अपने इस दिल को पेश करने का उद्देश्य बताया कि हम हिन्दुस्तान में कम्युनिज्म को रोकना चाहते हैं। हम भी कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं लेकिन उसकी इस पायिस्ती को कि राजसत्ता को उलट दिया जाय, राष्ट्रीय सरकार को उलट दिया जाय, इसमें हम विश्वास नहीं करते, अच्छा नहीं समझते। अगर राष्ट्रीय सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो हम भी चाहते हैं कि वह उलट दी जाय लेकिन कायदे और कानून से। ताकि उसकी जगह दूसरी पार्टी आ जाय और काम को संभाल ले। और कांग्रेस के गद्दी छोड़ने पर मुस्क में असुरक्षता न फैल जाय। आलोचना होने से कोई कमजोर नहीं होता है। आप आलोचनाओं से घबराइये नहीं। लेकिन अगर आप विरोधी पार्टियों को दबायेंगे तो प्रकृति अपना काम करती है। आपने सोशलिस्ट पार्टी को अच्छादा कर दिया इससे क्या हुआ। आपके बीच और बहुत सी कमजोरियाँ आ रही हैं। कल भी अखबारों में यही रोग था और आज भी। आप अगर यहाँ लोगों को नहीं बोलने देंगे तो क्या। हाउस के अन्दर ही ६० आदमी ऐसे बैठे हुये हैं जो यहाँ नहीं तो बाहर निकल कर आपके खिलाफ आवाज बुलन्द करेंगे। फिर आप ऐसा क्यों करते हैं, इतना क्यों दबाते हैं कि वह चीज फूट ही निकले। आप कहते हैं कि हम कम्युनिज्म के खिलाफ हैं लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं यही कम्युनिज्म पार्टी न बन जाए। इस तरह की पार्टीज़ बन जाया करती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है आपको जनता को उठाना है। विरोध को बर्दाश्त करना है। मैं केवल एक भीख कांग्रेस पार्टी से मांगता हूँ। जिस तरह हमने कहा कि हम हर तरीके से इस मसले में आपके साथ हैं उसी तरह से आपसे भी हम यह आशा करते हैं कि आप जो भी काम करें वह ज़रा डेमोक्रेटिक ढंग से करें। हमने देखा कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स बय स्पीच करते हैं तो कहते हैं कि जनता ठीक नहीं है। सरकार का साथ नहीं देती है। जनता बदमाशी करती है। सब खराबी जनता में है आपमें कोई खराबी नहीं है। आपकी भी जिम्मेगरी है, आपको भी यह महसूस करना चाहिए कि हम में भी कोई खराबी हो सकती है। जनता हमारी खराबी को कहे ओर इस तरह से दूर करे जिस तरीके से गांधी जो ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उसकी ५० प्रतिशत आजादी हमें दीजिए। हम सत्याग्रह की लड़ाई लड़ा करें और सत्य और अहिंसा को अगुआकर डेमोक्रेटिक तरीके से सार्वजनिक आन्दोलन चलायें, जन सन्तर्प को चलायें, जनता को आगे बढ़ाएं तब जाकर यह चीज़



[श्री राजाराम शास्त्री]

ऐसी हालत में मैं कांग्रेस से यह उम्मीद करूंगा कि वह देश की सही परिस्थिति को देखते हुए सही कदम उठायेगी जिससे किसानों की बहबूदी हो सके। जो सुझाव मैंने आपके सामने रखे हैं, मुझे आशा है कि कांग्रेस के मेम्बर उन पर संजीदगी से गौर करेंगे और इस कानून में जो और खराबियाँ हैं उन्हें हाउस के सामने रखेंगे। मैं यह चाहता हूँ कि कानून ऐसा बने जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री सिंहासन सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में एक नहतपूर्ण बिल पर बहस हो रही है। कई दिन से भिन्न भिन्न सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया और कुछ ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना है कि यह बिल कहां तक उपयुक्त है और कहां तक अनुपयुक्त है। मैं पहले जमींदार भाइयों से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह बिल उनके हित में है और उनको इस बिल का स्वागत करना चाहिये। इस बात में मैं भी भाई राजाराम जी से सहमत हूँ कि यह बिल जमींदारों के हित में है। अब प्रश्न यह है कि देश की राष्ट्रीय आजादी के बाद देश का आर्थिक ढांचा कैसा बने। कांग्रेस यह चाहती है कि एक वर्गहीन समाज बने और रामराज्य का उदय हो। इसी तरह सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि एक वर्गहीन समाज बने और कम्युनिस्ट पार्टी भी यही चाहती है कि एक वर्गहीन समाज हो। तीनों पार्टियों का दृष्टिकोण एक है परन्तु तीनों के रास्ते तीन हैं। कांग्रेस महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलना चाहती है। गांधी जी ने कहा था कि हम किसी की बुराई नहीं चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से भी यह कहा था कि हम अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी हैं परन्तु हमारा अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं है। उसी तरह से कांग्रेस आज यह चाहती है कि समाज का ढांचा बिगाड़ने वाले न खत्म किये जायें। यदि जमींदार काश्तकारों के रक्षक बनते और यह समझते कि ज़मीन उनकी नहीं है बल्कि काश्तकारों की है तो शायद आज इस बिल को लाने की आवश्यकता न पड़ती। सन् ३१ में महात्मा गांधी ने जमींदारों से एक अपील की थी और उसमें उन्होंने जमींदारों से यह कहा था कि आप अपने खेतियों के प्रतिरूप होकर रहें। यदि आप उनके शब्दों को सुनें तो आपको माफ़ूम होगा कि उनके हृदय में कितना दर्द था और उसी दर्द के कारण वह जमींदारों से कहते थे कि आप काश्तकारों के प्रतिरूप होकर रहें। उन्होंने टेनेन्ट की परिभाषा, श्री हूपर, सेट्टलमेंट अफ़सर, के शब्दों में, जमींदारों से अपील करते हुए दिया है वह इस प्रकार है —

‘ One who is ready to live on one meal a day and, in native phrase, to sell his wife and children, to pay the highest possible rent on his holding, who is prepared to submit to any cesses which may please his landlord to demand and who is always willing to work for him without payment, to give evidence for him in court and, speaking generally, to do any conceivable thing he is told to do.

( असामी वह है जो केवल एक बार भोजन करके रहने के लिए और देशी भाषा में, अपनी ज़ोत का आवक से अधिक लगान देने के लिये, अपनी छी और बच्चों को बेचने के लिये तैयार है और जो किसी भी प्रकार का कर जो उसका जमींदार मांगे, देने को और उसका बिना कुछ लिए

कार्य करने को, उनके हेतु न्यायिक में गवाही देने को, या यों समझिये कि किसी प्रकार का भी कार्य जो उसमें कहा जाय करने को तत्पर है।)

महान्ना गांधी के यह शब्द ऐनेन्स के बारे में थे। परन्तु महात्मा गांधी की वह अपील बेकार रही और आपके कानों पर जूं न रेंगी। नामचा आगे बढ़ता गया और अन्त में परिणाम यह हुआ कि इस वि० को भवन के सामने अना पड़ा। जमींदारों के बारे में मेकैवली ने कुछ बातें कही हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है—

And of the nobles: "Gentiluomini are called those, who live fatly and lazily from the revenues of their land without even giving themselves the trouble of improving them. In every republic or provincia they are harmful, but especially where they have castles and vasals who obey them: because there they are enemies of all civilization."

(यह जमींदारों के विषय में—बड़े आदमी उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी जमीन को मातृगुजारी से आराम और दिवस का जीवन व्यतीत करते हैं और कभी उस भूमि की उन्नति करने का श्रम भी नहीं करते, ऐसे लोग प्रत्येक देश में हानिकर होते हैं और ऐसे देशों में तो वे विशेष रूप से हानिकर हैं जहां उनके महल बने हैं और उनकी आज्ञा पालनार्थ नौकरों का समूह विद्यमान है क्योंकि वे लोग सभ्यता के शत्रु हैं।)

मेकैवली के यह शब्द कहां तक आप पर लागू हैं आप स्वयं विचारें और सोचें, मैं नहीं कहता कि आप सभ्यता के विरोधी हैं किन्तु आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में यह शब्द कुछ हद तक सही प्रतीत होते हैं। आप कबूतकारों को अपना दुश्मन समझते थे और उनसे बरहनी के साथ व्यवहार किया। मैं कहना हूं कि समाज की ज्ञा व्यवस्था गांधी जी के नेतृत्व में कायम हो रही है, उसका आप विरोध न करें। हम गांधी जी के आदेशों के अनुसार चलने वाले हैं। आपका नुकसान हो यह इस वि० की और कांग्रेस की धारणा नहीं है। हम जमींदारी को तोड़ेंगे लेकिन जमींदारों को नेस्तोनाबूद नहीं करेंगे। वि० में प्राविजन किया है कि मुआविजा दिया जाय। लेकिन सोशलिस्ट कहते हैं कि वगैर मुआविजा दिये हुए आम्की सारी सम्पत्ति ले लेंगे। उनके विचारों में जो आम्की सम्पत्ति कहानी है वह आम्की नहीं है। आप चोर के रूप में उसे पकड़े हुए हैं। उसको ले लेना नमाज के हित में यह हिनकर समझते हैं। एक तरफ कन्जुनिस्ट भाई हैं जो कहते हैं कि मुआविजे का स्वाग ही नहीं, उनको कोई हक इस संसार में कायम रहने और जीवित रहने का नहीं है। उनको मार कर और नाश छीन कर वर्गहीन समाज कायम करें। तीन रास्ते हैं। एक रास्ता कांग्रेस का है जो कि उचित दान देकर, बहुतां के खयाल में ज्यादा, आपका हक लेना चाहती है। दूसरा क्लस, वही चीज लेना चाहता है लेकिन वगैर कुछ दिये हुए, तीसरा क्लस आम्को स्वयं से भिटाकर भूमि स्वामी कराकर ले लेना चाहता है। आपका ध्यान करना चाहते हैं। दो रास्ते हैं। यदि आपने संशोधन पर ज्यादा जोर दिया, डिमंडन करवा तो आपका जीवन कष्टकर होता जायगा। वह दिन आयेगा जब आप संसार से मिट जायेंगे। हम हद तक मैं श्री राजराम जी से सहमत हूं कि यह वि० आपको पुविधा देता है। हम आप भिचकर दमको दान करें। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप संजीवन उठा लें। इस प्रस्ताव को ज्ञा जमींदारों उन्मुख का है एक मत से बिना किसी विरोध के स्वीकृत



[श्री सिंहासन सिंह]

करें। बिल जैसा है ठीक ही है। इस पर बहुत काफी बहस हो चुकी है, लेकिन अधिक बहस इस पर रही है कि जमींदारी प्रथा भली है या भरी नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया। इस बात पर कम रोशनी डाली गई है कि इस बिल में किन चीजों की कमी है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूँ। इस पर सरकार ध्यान दे। पहले एक बात यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव अगस्त सन् ४६ में पास हुआ था कि जमींदारी प्रथा तोड़ दी जाय और ८ जुलाई सन् ४९ को इसका मसविदा हमारे सामने पेश हुआ। सिर्फ तीन वर्ष में एक महीने की कमी है। पुरानी मुसलिम लीग पार्टी जो अब जनता पार्टी है वह कहती है कि यह बिल देर से आया। हम भी सहमत हैं कि बिल देर से आया। इसे बहुत आगे आना चाहिये था और अब तक पास हो जाना चाहिये था। देर हुई। शिकायत करने से काम नहीं चलता। इस कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो पता चलेगा कि जो मुसलिम लीग पार्टी और जनता पार्टी के लीडर हैं वे जमींदारी एनालिसिस कमेटी के मेम्बर भी थे। बेगम एजाज ख़ान भी इसकी मेम्बर थीं। इन चार व्यक्तियों ने सहयोग नहीं दिया जो मुसलिम लीग के मेम्बर थे। इस पर गौर कीजिये कि क्या करें। उस समय मुसलिम लीग जमींदारों का बनी हुई थी। वह इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने वाली संस्था थी। मुसलिम लीग जमींदारी प्रथा के खत्म होने की विरोधी थी। इसलिये आप उस वक्त जमींदारी एनालिसिस कमेटी में नहीं आ सके। उस वक्त आने जा कुछ किया वह देश की खून खराबी पर ही अधिक जोर दिया। और इस तरह से इस बिल को यहाँ आने में जिलम्ब हुआ। इतना विलम्ब होने के बाद जब जनवरी सन् १९५८ ई० में आप कमेटी में गये उसके थोड़े दिनों के बाद ही रिपोर्ट निकली। और उस रिपोर्ट में चार मेम्बरों में से बेगम साहिबा ने तो बिल्कुल विरोध किया और यह राय दी कि जमींदारी टूटे ही नहीं। लारी स हब ने दूरी जमान से इसको स्वीकार किया और यह राय दी कि अनएकनामिक होल्डिंग का लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाय। हमारे यहाँ ५७ फी सदी कास्तकार हैं। इस तरह से अगर ५७ फी सदी अनएकनामिक होल्डिंग का लगान माफ कर दिया जाय तो फिर हमारी माली हालत क्या होगी? लेकिन तो भी हम लगान कम करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बतायेंगे। अब बिल के मूठ अंग पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस बिल के क्लॉज ५ में दिया हुआ है कि सरकार को अधिकार है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वह डिबलेयर करे कि फलों तारीख से जमींदारी का इकूफ महामहिम को वेस्ट करेगा। मेरा इससे विरोध है। आज तीन वर्ष के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस विधान की एक एक धारा इस हाउस के सामने पेश हुई है और इसके पास हो जाने के बाद फिर यह लागू कब होगा इसका अधिकार सरकार के ऊपर छोड़ देना कि वह जब चाहे तब इसको लागू करे उचित नहीं जान पड़ता। इससे जिलम्ब होगा और अगर विलम्ब होगा तो श्री राजाराम शास्त्री के ही शब्दों में यह हमारे लिये घातक होगा, कांग्रेस के लिये घातक होगा। क्योंकि इस बिल के पास होने में भी अभी कम से कम एक साल का समय लग जावेगा। एक वर्ष के बाद फिर नया चुनाव होने वाला है। अगर नये चुनाव के पहले यह नहीं लागू होगा तो हमारे लिये बड़ी दिक्कत की बात पैदा हो जावेगी कि हम जनता के सामने यह कहें कि हम तो कानून

को पास करके चले आये हैं और फिर लौट कर जाने पर उसको लागू करेंगे। हम लोगों की इस बात का वे विश्वास भी करेंगे या नहीं इसमें मुझे सन्देह है। इस तरह से हाउस के अंदर भी और बाहर भी हमारा प्रति विश्वास की बरगल बन जायेगी। गवर्नमेंट जब चाहे तब इसको लागू करे यह चीज नहीं होनी चाहिये बल्कि जब गवर्नर का एजेन्ट मित्र जाय उसी तारीख में महामहिम में सारी जायदाद वेस्ट हो जानी चाहिये। इसके बाद हमारे ऊपर किसी तरह का दोगावोपण नहीं होगा कि उस कानून को किस तारीख से लागू किया जायगा। मसबूत एक कानून का हवाला मैं आपको देना चाहता हूं। आठ दो वर्ष हुए इस मसबूत ने रैंड युटीयइजेशन ऐक्ट पास किया। उसमें एक प्रोवीजन था जिसमें कल्चटर को यह अधिकार दिया गया था कि ऐसी सारी परती जमीन और यहां तक कि जो सीर की जमीन दो वर्ष से परती पड़ी हुई हैं उसके लिये भी वह जमींदार को नोटिस देगा कि वह परती जमीन का १५ दिन के अंदर बन्दोबस्त कर दे। अगर जमींदार इसका बन्दोबस्त नहीं करेगा तो कल्चटर का अख्तियार होगा कि वह जमीन कास्तकारों के हाथ या जिस तरह से चाहे किसी अन्य के साथ बन्दो-स्त कर दे नाकि अब का अभाव जो अधिकता से है वह न हो। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह कानून जिस तरीके के साथ जिस उद्देश्य से पास किया गया उस उद्देश्य को पूर्ण आब तक नहीं हो सकी। जितनी परती जमीनें पड़ी हुई थीं उनमें शायद ५ की सही की बन्दोबस्त नहीं हुई हैं। सारी परती जमीनें ज्यों की त्यों पड़ा हुई हैं। बहुत से जमींदार लोग कहते हैं कि हमारी जमीन खो रहा है और वह खोयेगी। इसी तरह वे परती जमीनें खो रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो आर कंट्रोल अफिसर सुकरर करते हैं, फूड प्रोफ़ेसरमेंट के सिर्जिबले में और दूसरी तरफ कल्चटर को परती जमीन के बन्दोबस्त का अख्तियार देने के बाद भी आप देखते नहीं हैं कि अब उस अधिकार का ठोक तरह से समुचित रूप से पालन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं, बन्दोबस्त न होने के कारण ही अब देश में इतनी जमीनें परती पड़ी हुई हैं जिससे अब का अभाव है। इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिये। इसीलिये मुझे डर लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद शायद गवर्नमेंट के अंदर सुस्ती आ जाय। इसलिये मैं हाउस से आर प्रधान मन्त्री जी से यह अपील करूंगा कि वे इस पर गौर करें और इस बिल को पास करने में जितनी जल्दी हो की जाय। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल में से दफा ५ और ६ को निष्काट दिया जाय और उसके बजाय यह रख दिया जाय कि जिस समय इस बिल पर गवर्नर जनरल का एजेन्ट मिल जायगा उसी वक्त से यह लागू होगा और यह महामहिम के अख्तियार में चला जायगा। अब इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम लोगों ने वर्गहीन समाज बनाने का विचार किया है और इस बिल में वह है भी, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्गहीन नहीं बल्कि एक बढ़ता हुआ वर्ग कायम हो रहा है। अब तक जमींदार और कास्तकार थे। कास्तकार की चार पांच किस्में थीं। इस प्रकार ५-६ किस्मों को तोड़ कर आप सिर्फ ४ क्लास कर रहे हैं यानी भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी। यह ठीक है कि आगे चल कर दो ही क्लास रह जायेंगे, यानी सीरदार और अधिवासी मुआविजे देकर भूमिधर हो जायेंगे। केवल भूमिधर और आसामी ये दो ही क्लासेज रह जायेंगे। एक को पूरा अख्तियार रहेगा और एक को कुछ भा अख्तियार न रहेगा। मेरा सबसे पहला विरोध तो इन शब्दों से है। ये शब्द नये गढ़े गये हैं। इन शब्दों के लाने से या सिर्फ शब्दों के परिवर्तन से ही कोई लाभ नहीं होता। इससे हमारा

[श्री सिंहसन सिंह]

उद्देश्य जो वर्गहीन समाज के स्थापन करने का है उसमें हठ नहीं हो सकता है। आपको कहना चाहिये कि जो खेती करने गया है वह कारगर है। इन नये शब्दों को सुन कर कारगर क्या समझेंगे। वह उनका कुछ समाज नहीं समझ सकेंगे। आज तक हम केवल किमान सभा के नाम से काम करते रहे हैं, क्योंकि जो खेती करने वाले सब लोग वे किसान हैं। और उस किसान सभा के अध्यक्ष हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वे ही हमारा से रहे हैं। आज तो भूमिधर और सीरदार हो जायगा। तो न आगे बढ़ रहा है कि आप भूमिधर और सीरदार के चक्कर में न पड़ कर यह कहिये कि जो खेती जाते जाते हैं उनका नाम किमान होगा। जब किमान के बाद जो दूसरा उपाय आता है और उन लोगों का जो मुजराजा देने के लिये आश्वासन देंगे उनको आप अ, ब, ग का उन आदि का नाम किमान कह सकते हैं। यह कहिये कि जब तक वे मुजराजा नहीं दें तब तक वह उन किसान रहेगा और मुजराजा देने के बाद वह किसान समाज जायगा। इसी तरह से अधिवासी के लिये भी पोजिये कि जिस समय वह मुजराजा दे देंगे भूमिधर हो जायगा। मेरा समझ में नहीं आता कि इन नामों के बदल देने से किसान का क्या होने वाला है। यहाँ तक तो नाम के बारे में मैंने कहा। अब मैं एक बात आगे कहना चाहता हूँ कि अधिवासी और सीरदार का जो आपने फर्क किया है वह कुछ उचित या नहीं मान्य पड़ता। आपने यह रखा है कि अधिवासी यदि पाँच साल बाद १५ गुना दे दे तो वह सीरदार हो जायगा। उसको पाँच वर्ष तक वैसे ही रखा

कि इस वक्त है। ५ वर्ष तक उसके अख्तियार में कोई परिवर्तन नहीं। इस बिल के पाठ हो जाने के बाद भी ५ वर्ष तक वह किसान शिकमी ही रहेगा। वह तब तक उसके गले में पटकती रहेगा। अगर वह १५ गुना लगान अपना नहीं दे पायेगा तो उसके हक में कोई परिवर्तन नहीं हो पायेगा, उसको कोई हक नहीं मिलेगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह बात निकाल दी जाय तो अच्छा है। अधिवासी को भी हक होना चाहिये कि वह भी आज की तारीख से यह मतलब करे कि उसे भी हक हो गया है लेकिन कानून के पास हो जाने के बाद भी ५ वर्ष में उसको कोई हक नहीं मिलता है। नतीजा यह होता है, यह नहीं मालूम है कि वह १५ गुना लगान दे पायेगा या नहीं तो वह बेदखल हो जायगा। वह उस जमीन से कोई दिल बस्ती नहीं रखेगा जिससे कि वह बेदखल हो जायगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ भी तयज्जद की जाय और उनको भी हक देना चाहिये। ५, ६ वर्ष तक उनके हक को सुलतवी नहीं करना चाहिये। अब सुलतवी का जमाना निकल गया है। आपने देखा कि अभी शास्त्री जी वहाँ पर खोल गये हैं। वह अपने लिये इन सब बातों का प्रयोग करेंगे और इसका प्रचार करेंगे। वह शिकमी क्राइकारों से कहेंगे कि तुमको क्या हक मिला। तुम्हारी किस्मत ५ वर्ष के लिये टल गई। और ५ वर्ष के बाद कौन जाने कौन गवर्नमेंट आवे और वह इन बातों पर कायम रहेगी या नहीं। जो बातें हम आज सोच रहे हैं वह पूरी हो सकेंगी या नहीं। यह कोई नहीं जानता है। आज वैसे भी हमारे लिखफ काफी लोग कहते हैं कि हम जमींदारों से सहानुभूति रखते हैं और कैपिटलिस्टों की मदद करते हैं। ५ वर्ष तक उनको हक न देकर भुगतान दिया है और भुगतान देने के बाद फिर ५ वर्ष में गवर्नमेंट वापस आयेगी या नहीं



[श्री सिंहासन सिंह]

पैदा होगी, इसलिये उचित काम न किया जाय यह कुछ जंचता नहीं। तो मैं अपने भाइयों में अपील करूँगा कि अभी तक कोई इस पर प्रकाश नहीं डाला गया, श्री राजाराम ने डाला है कि ऊपरी सीमा होनी चाहिये, वे भी अपना मत प्रकट करें। बहुतों ने कहा कि बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि आप सहमत हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की और मवन की राय का ख्याल करके ऊपरी सीमा अवश्य बंधेगी। इस हाउस के विशेष भाइयों की राय है कि ऊपरी सीमा होनी चाहिये। कितनी हो, यह हम आपस में साथ बैठकर तै कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें एक ओर बात रह गयी जो छोटे जमींदारों के संबंध की है। हम सन् ३७ में और ४५ में भी कांग्रेस की ओर से लड़े और हमने कहा था कि छोटे जमींदारों को हम किसानों की श्रेणी में रखते हैं और छोटे जमींदारों ने यह समझ कर हमेशा कांग्रेस का साथ दिया और बराबर साथ रहे। आज भी उनको हम नहीं छोड़ रहे हैं। उनको भी सीर और खुदास्त मिल रही है क्योंकि उनको शुरू से इसका ही सहारा रहा है। लगान से उनको बहुत कम मुनाफा हुआ करता था। छोटे जमींदार अक्सर नौकरी के कारण बाहर रहते थे और अपने खेतों को उठा देते थे। हमने सन् १९५० ई० के कानून में यह व्यवस्था कर दी थी कि जिसके पास पचास एकड़ से कम सीर हो वह अपने ज़िन्दा कास्तकारों को बेदखल करके ५० एकड़ पूरा कर सकता है। लेकिन अब हमने उसको सवा छः एकड़ कर दिया है। यह हमने बिल के २२४ दफा में रखा है कि जिसके पास सवा छः एकड़ से कम हो, वह भूमिधर अपने अधिवासी को बेदखल करके सवा छः एकड़ जमीन कास्त करने के लिए पूरा कर सकता है। आप सवा छः एकड़ एकानामिक होलिंग रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि २० एकड़ रहे, ३० एकड़ रहे। बड़े बड़े राजाओं के पास कम्पनी लम्बी सीरें रहती थीं, और उनके पास इस विधान के अनुसार रह भी जाते हैं लेकिन छोटे ने नौकरी करने के कारण बटाई पर खेत को उठा रखा था या लगान पर भी दे रखा था, उसको बटाई जोतने वाला यह सोचता था कि इसमें हमको कोई हक नहीं मिल रहा है, सिर्फ पैदावार कट कर मिलेगी। इस मवन में कुछ भाइयों की राय है कि वह सवा छः एकड़ के बजाय, पंद्रह एकड़, २५ एकड़ या ५० एकड़ होना चाहिये। जो हो, यह एक गम्भीर मसला है। इसमें छोटे छोटे जमींदारों और कास्तकारों का ख्याल करना है। प्रान्त के पूर्वी भाग में पहले से कुछ शरह मुअय्यन कास्तकार चले आते हैं। जमींदार की तरफ से उनका भी मुस्तकिल हक हासिल है। उस हक के रहते हुए उन्होंने अपने खेतों को लगान पर दे दिया है और आज वह बेदखल हो जाता है। सवा छः एकड़ से ज्यादा जमीन होने की वजह से अगर वह भी बेदखल हो जाता है, तो वह मर जाता है। मैं राजाराम शास्त्री जी से कहता हूँ कि वह कास्तकार हमारे साथ नहीं, बल्कि आपके साथ हो जायेंगे। वह कहेंगे कि भाई हमारे पास १० एकड़, २० एकड़ जमीन थी, वह हमने बटाई पर दे दी थी, और आज हम बर्बाद हो रहे हैं। और वह हमारे खिलाफ हो जायेंगे। इस विचार से ऐसे कास्तकारों को भी १०, २०, और २५ एकड़ तक जोतने का हक दें और मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस पर गौर करें।

अब आइन्दा चल कर हम खेत उठाने का हक केवल उसी भाई को दे रहे हैं जो अपा-हिज, लंगड़ा, झुल्ला, नाबालिग या पल्टन में है। इस तरह से कोई भी सरकारी मुलाजिम,

हैं, जो आगे इस मजदूरी में भी बढ़े हुए हैं, अगर उनके पास इस कीमत खेत है और वह चाहते हैं कि वे उसे अपने और नानाई की कोरीव कर मरने दें। जो मजदूर न ले करे, जो रहे उनको अगर अधिकार है, वह नानाई को नानाई नानाई है कि प्रान्त सरकार ने मुआवजे में जो उम्मीदों को अपने आगे ले लिया है, उसे नानाई अधिकार देना जरा जरा उनको १० बीघा देने है जो मजदूर दायर कि वह मरने मरने रहे यह प्रान्त को नानाई अधिकारों को उठा दे तो मैं आगे प्रार्थना करना हूँ कि इस बात में जहाँ आपने रखा है कि नानाई मरने को दायर के मरने दूसरे को खेत देने का हक होगा, वह मरने के आदमियों को भी रख दे जो बोनकाइड मरने के मुआवजे में जो मरने के मुआवजे में मुआवजे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रान्त को आसकी सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार वह भी आप की सेवा कर रहे हैं कोई बजह नहीं है कि उनको वह हक न मिले। मैं आगे प्रान्त मुआवजे की तरफ दिखाना चाहता हूँ वह बहुत ज्यादा मालूम हो रहा है। अब आप यह देख रहे हैं कि जमींदारों को खुदकाश और भीर का हक आप दे रहे हैं। आप निर्मल उनका वसूली लगान का हक ले रहे हैं। जमींदार के अथ तक दो हक थे। एक तो वसूली लगान करके गवर्नमेंट को दिया करने थे और उसमें से कुछ कमीशन के रूप में वसूल किया करते थे और दूसरा हक था अगला मर और खुदकाश को जो देने का। इसके दो हक में से आप निर्मल एक हक वसूली लगान को ले रहे हैं। वह सीर और खुदकाश को बगैर मुआवजा दिये हुए जो देगा। अब कि वह लगान वसूल करने का मुआवजा पटा है। इसलिये अब उसे लगान वसूल करने के एवज में मुआवजा दिया जा रहा है तो सीर खुदकाश का बगैर मुआवजा फिर हुये उसको जो देने देना ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये उसने खुदकाश के जो देने के एवज में कुछ मुआवजा जरूर लेना चाहिए अन्यथा किसान वह कहेगा कि हमसे तो मुआवजा लिया जा रहा है लेकिन जमींदार ने कुछ नहीं लिया जा रहा। वैसे वह खुशी से देगा लेकिन जमींदारों पर भी यह लगाया जाये कि इतने एकड़ जमीन जोनेगा तो इतना मुआवजा देना पड़ेगा। क्योंकि अब तो सारे जमीन जिस तारीख से सरकार घोषित करेगी सरकार की हो जायगी। इसलिए सरकार उस जमीन का मुआवजा लेगी। मुआवजे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि काइलर १० गुना नहीं देगा। मेरे ग्याल में यह तो बेजा प्रिटिसिज्म है। काइलर को बड़ी खुशी से दाना देगा। गवर्नमेंट उसने जो उस गुना ले रहा है वह एक तरह से कर्ज के रूप में ले रहा है जो ४० वर्ष में मरने के बर्तिस कर देना चाहती है। अगर हिनाब लगाने। कोई काइलर ५ रुपये का है तो वह ५० रुपये इस दिव के मुद्राधिक अगला हक पाने के लिये गवर्नमेंट को देगा। ५ रुपये के दान गुने के हिनाब ने ५० रुपये होते हैं। उसका लगान अब दाह रुपया हो जायगा। ठीक तारीख में कर्ज को अदायगी शुरू हो गई और ४० साल तक कोई बन्दोबस्त नहीं होगा। याना ४० वर्ष में १०० रुपये लगान देगा और ५० रुपये पहले हक पाने का लिए देगा। इस तरह से वह १५० रुपये सरकार को देगा। अगर वह ५ रुपये के हिनाब से ५ रुपये लगान देता है तो २०० रुपये उसे लगान देना होगा। इस तरह से ५० रुपये सरकार ने उसका बर्तिस कर दिये। इसलिए यह कर्जा गवर्नमेंट का है। यह कोई तराबी या जरा नहीं है। वह हक मिल रहा है इसके लिये वह गवर्नमेंट को देना है। और गवर्नमेंट उसने जमींदार के पजे से मुक्त करेगी। यह रुपया जो उनसे मांगा जा रहा है वह बड़ी खुशी के साथ रुपया देंगे। जिस दिन आपका बिज पास होगा वह रुपया देने लगे। दूसरा बिज हाउस के सामने नहीं है। उसमें एक

[श्री सिद्दासन सिंह]

खामी है। वह १० गुना रकबा देने के बाद आपा लगान जमीन्दार को देगा। यह ठीक नहीं है। जब किसान ने १० गुना रकबा दे दिया और लगान आधा हो गया तो उस के बाद उसका सीधा सम्बन्ध सरकारी खजाने में देना चाहिये और जमींदार से उसका कोई सम्बन्ध न रहना चाहिये। बाद में सरकार जमींदार से हिसाब किताब कर सकती है लेकिन रकबा जमा करने की तारीख से वह लगान जमींदार को दिया जाय यह उचित नहीं है। अगर उसका लगान दस गुना बढ़ा करने पर ५ रुपये से ढाढ़ रकबा भी हो जाता है लेकिन अगर वह उसे फेर भी जमींदार को ही अदा करना है तो उसके दिमाग में यह बात पैदा नहीं होगी कि उसे कुछ आजादी या छुटकारा मिले और न वह समझ सकता है कि मैं आज से मुक्त हो गया। इसपर कुछ माह एतराज कर रहे हैं उनके कहने पर भी वह बढ़ाया जा सकता है अगर आपने किसान का कुछ भी तात्त्विक जमींदार से रखा। और वह गुमराह हो सकता है और समझ सकता है कि अभी यह चीज कुछ गोलमाल है। मूक ऐक्ट अभी पास नहीं हुआ है और उसमें यह भी है कि सरकार जब चाहेगी उसको लागू कर देगी और वह समझेगा कि अभी कास्तकार जमींदार के संबंध में कोई अन्तर नहीं हुआ। लिहाजा आप यह प्राविजन कर दें कि रकबा जमा करने के बाद वह सीधा खजाने में लगान जमा करे और उसका कोई सम्बन्ध जमींदार से न रहे। एक बात मैं, आवजे के बारे में और कहना चाहता हूँ कि मुभावजा जमींदारों को दिया जा रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में जब से जमींदारी एक्साइजन का सवाल उठा है और कांग्रेस सरकार आई है तब से इन लोगों के दिल में एक आशा सी हो गई है कि जिनकी जमींदारी सन् १८५७ में खीनी गई थी और जिनके पुरखाओं ने उस प्रथम आजादी की लड़ाई में भाग लिया था उनके खानदान वालों को यह आशा हुई थी कि यह जो राष्ट्रीय सरकार और आजादी की सरकार कायम हुई है वह हमारा खयाल करेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। यह ठीक नहीं है कि आप जो मुभावजा दे रहे हैं वह उन देशद्रोही लोगों को मिले कि जिन्होंने उस जमाने में अंग्रेजों की मदद की थी, जिन्होंने अपनी जान देकर आजादी की प्रथम लड़ाई में हिस्सा लिया और फांसी पर चढ़े उनकी सन्तानों को आज कुछ भी न मिले यह ठीक नहीं है। आप सारी सीर और खुदकास्त भी इन्हीं के हाथ में रहने देते हैं जो कि मुल्क के दुश्मन हैं उनको आज अपना दोस्त समझकर मुभावजा दे रहे हैं और जिन्होंने सन् ५७ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उनके लिये आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने विदेशी सरकार को निकालने की काशिश में फांसियों की सजा भई उनका आप आज भी कुछ नहीं दे रहे हैं यह मुनासिब बात नहीं है। आप जमींदारों को दो चीजें दे रहे हैं एक तो सीर व खुदकास्त और दूसरे मुभावजा उस जमीन का जिसका कि वह लगान वसूल करते हैं। एक तो आप उनको सीर व खुदकास्त पर कब्जा दे रहे हैं और दूसरे मुभावजा। अगर आप इन दोनों चीजों का बंटवारा कर दें और दोनों में से एक चीज उनको दे दें तो ठीक होगा। जिन को आप मुभावजा दें उनको सीर व खुदकास्त न दें, और वह उन लोगों की सन्तानों को दें जो कि सन् १८५७ में फांसी चढ़े। इसलिए खास तौर पर इस सरकार के लिये यह मुनासिब नहीं है कि जो सरकार देश के नाम पर विदेशियों का हटा कर कायम हुई है और आजादी हासिल की है उसके राज्य में वे लोग जो देश के लिये प्राण दिये उनकी सन्तान

भूमी मरे यह इनके लिये उचित नहीं है। इनके अन्त में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इन बातों पर विचार करे।

\* श्री सुभाष चन्द्र बोस :—जगज्जीवर महोदय, जो नमस्त्रिंश कानून आज हमारे सामने पेश है और जिस पर ४ दिन से बराबर चर्चा हो रही है वह एक बहुत तारीखी बिल है। मैं इन निश्चितियों में अपने स्वयंसेवा का कुछ हद तक करके इस बिल को बनाना चाहता हूँ और मुझे इनके बनाने में बड़ी विफलता नहीं है कि मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूँ। जहाँ तक जमींदारी अधादेशन का सवाल है मेरी जानी राय यह है कि जो मूल्य मूल्य में और मूल्य में पैदा हो गये हैं और जिस न्याय का उन लोग पहुँच गये हैं वही पहुँचने के लिए समय इसके कोई दूसरा माग नहीं हो सकता। कि जमींदारी को खत्म कर दिया जाय और इस मामले में न सिर्फ मैं सहमत हूँ बल्कि जमींदारी को भी एक कानून बड़ी तयारी जो हम पहले पर गौर से निगाह डालता है, उनकी भी पूरी राय होगी। लेकिन जमींदारी के मामले पर गौर करने से पहले हमें दो एक चीजें यह हो जाना हैं। इस मसाले में ८ अक्टूबर १९४६ ई० को सरकार की तरफ से एक रिजॉल्यूशन पेश किया गया था और इस रिजॉल्यूशन में यह एजेंडा किया गया था कि कैपिटलिज्म (पूंजीवाद) को बहुत मूल्यों में इस मूल्य और इन मुक्त से खत्म कर दिया जाय। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेनीफेस्टो निकला उसमें भी यह बात बड़ी गंभीर थी कि जमींदारी को खत्म कर दिया जाय और कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाय। मुझे बड़ा तोर पर यह एक दृष्टि है कि मैं हुकूमत से यह सवाल पर सक्त कि जहाँ तक जमींदारी का सवाल है हम इस स्टेज पर पहुँच गये हैं कि यह बिल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि कैपिटलिज्म को दूसरी मूल्यों का लान्च है उसमें उन्होंने अब तक क्या कदम बढ़ाया, क्या कोशिश की, उनके क्या एक्सीप्टेंस रहे और वह आगे क्या करने वाले हैं। अगर जमींदार यह सवाल हुकूमत से बराबर करें तो एक बजाबिल है। हुकूमत का फर्ज है कि वह इसका सही तौर पर जवाब दे। एक बात जिसे मैं महसूस करता हूँ वह यह है कि हमारे मुक्त में खुशकिस्मी या बकिस्मी से जब इलेक्शन आता है उस वक्त हम लोग अगर कुछ सोचें समझें, अगर वाक्यात की अभिप्राय तौर पर जांच किया हुए बड़े बड़े स्प्रोगन्स दे देते हैं। उस वक्त हम भूल कर यह स्थापना नहीं करते कि जो वादा हम जनता से कर रहे हैं वह वादा कहा तक ईफा हो सकता है, कहां तक उन पर अमल हो सकता है। अगर हम दूसरे देशों को लें, खुद इंग्लैंड में, जहाँ मे हमारे मुक्त ने डेमोक्रेसी ली है वहाँ सोशलिस्ट हुकूमत बरसरे इच्छा है लेकिन उसी मशीनलिस्ट हुकूमत के जमाने में वह जमींदारी किसी न किनी सूत में मौजूद है। लेकिन इस हुकूमत ने अब जो इलेक्शन लड़ने जा रही है उसने इस बात का कोई स्प्रोगन्स नहीं दिया है कि वह जमींदारी को खत्म करने जा रही है। लेकिन हमारे पक्ष यह दस्तूर हो गया है कि जो पार्टी इलेक्शन लड़ने जाती है वह बड़े से बड़े स्प्रोगन्स (नारे) देती है और ऐसा साबित हुआ है कि उन वादों का पूरा नहीं किया जा सकता और हम लोगों को अक्सर कदम पीछे हटाना पड़ता है। मिमात्र के तौर पर हम लोग अगर यह कहते आये हैं कि हम ब्रिटिश कामनवेल्थ में नहीं रहेंगे। किन अमरी तौर पर टिकने महसूस हुई और फेसल हमें आज यह करना पड़ा कि हिन्दुस्तान ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहे, चाहे उसका नाम ब्रिटिश कामनवेल्थ रहे या केवल कमनवेल्थ। इसी तरह से हम यह भी देख रहे हैं कि

\* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।



[श्री सुन्तान आलम खां]

कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया, मुल्क में दूसरी जो पार्टियाँ हैं वह भी उसी के नक्शेकदम पर चल रही हैं। मैंने सुना कि सोशलिस्ट पार्टी यह कह रही है कि सूत्र में जमीन की अड़सरेनौ तकसीम हो और इस तरह में तकसीम हो कि हर शख्स को २० बीघा जमीन मिले, एक गांव भीमिले और प्रीमियर सहाय ने इस एनराज का जवाब देते हुए कहा कि एक गांव के साथ एक दो हाथी और एक मोटर भी मिले। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो मतालबात किये जा रहे हैं, जनता से जो वादे किये जा रहे हैं कहां तक ऐसे हैं कि पूरे होंगे। यही वजह है कि जो पार्टी मुल्क में ऐसे वादे लेकर आती हैं और जब उन वादों को पूरा नहीं कर सकती तो लोगों में उनकी तरफ से मयूसी पैदा होती है, लोगों में ऐतराज पैदा होता है जो कि नफरत की हद तक पहुंच जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि एलेक्शन (चुनाव) में पार्टियों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इस मामले से मेरा कोई ज्ञाती ताल्लुक नहीं लेकिन सूत्र के एक वाशिन्डे की हैसियत से मैं महसूस करता हूं कि अगर कांग्रेस ने इस तरीके से बड़े बड़े वादे न किये होते और कांग्रेस वालों ने महसूस किया होता कि जमींदारी एवालाशन में कितनी दिक्कतें हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं तो इस स्थिति में जो इतने एतराजात किये जा रहे हैं वे न होते। उनको इस बात की जरूरत न महसूस होती कि इस बिल को ऐसे बेमौके लायें, जब मुल्क की हालत बहुत खराब है। इसी तरह से मेरे सोशलिस्ट दोस्तों ने, जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर रही थी, उस वक्त यह बात रखी थी, कि हम प्रोक्योरमेंट के खिलाफ नहीं हैं, पर प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट अपीशियलों के बजाय पंचायतों को करना चाहिये। क्या कोई शख्स, जो इस ऐवान में बैठे हैं या इसके बाहर हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि ये पंचायतें जो अभी बनी हैं इस पोजीशन (स्थिति) में हैं कि वे प्रोक्योरमेंट का काम आसानी से चला सकें। अगर हम ईमानदारी से समझते हैं कि प्रोक्योरमेंट की जरूरत है तो साफ साफ कहें और अगर प्रोक्योरमेंट के खिलाफ आने को समझते हैं तो थैक डोर से उसकी मुखातिब करना मुनासिब नहीं। इस किस्म की तस्मीम सामने रख देना कि प्रोक्योरमेंट तो हो पर उसे गांव पंचायतें करें, इनकार भी है और इकार भी है, जो किसी तरीके से मुनासिब नहीं मालूम होता।

अगर मेरी आवाज़ नकारखाने में तृती की आवाज़ न समझी जाय तो मैं हुकुमत को यह मन्त्रिणा दूंगा कि पेन्तर इसके कि वह कोई रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर चले, उसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया से इस मामल में सबक लेना चाहिये। हमें मालूम है कि कांग्रेस ने अपने एलेक्शन मैनीफेस्टो में क्रैसिटिडियम को खत्म करने की आवाज़ लगाई थी, पर मैं ज़रूरत हूं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने इंडस्ट्रियलियों ने १० वर्ष का एग्जीमेंट कर दिया है। अगर इसी तरह से मौजूदा दुश्वारियों और मुश्किलों को देखते हुए इस रिस्क की कोई सूरत पैदा की जाती तो मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब होता। जमींदारी के खात्मा के लिये जो यक्त तज़वीज़ किया गया है वह बहुत खतरनाक है। हमें उन फॉरेंज (शक्तिशाली) को रोकना : जिन्होंने चीन, बर्मा और दुनिया के दूसरे मुल्कों में तब ही ला दी है। अगर हमें मुल्क को शांति और इतमीनान के रास्ते पर चलाना है, अगर वाकई इसे हम महात्मा जी के अहिंसा के बसूलों पर चलाना चाहते हैं तो जिस तरीके से भी हो हमें हिन्दुस्तान को उनकी लपेट में आने से रोकना है।

(समस्त १० वें प्रश्न में १०० रुपया का प्रश्न है जो गरीबों के लिये है, जो कि १०० रुपया का प्रश्न है जो गरीबों के लिये है।)

अ सुनना = ...  
 लोग उन्हें से नज़र न डालें थे तो मैं उन ...  
 के बलिदान ...  
 लोगों के मुनासिब यह ...  
 गया। उनको ...  
 गयी। ...  
 सकत है उनमें ...  
 लेकिन एक ...  
 को उसके ...  
 चाहें हम उनके साथ ...  
 के जो डिपेंडेंट्स (अश्विन) हैं, उनके ...  
 हूँ कि जिस तरह से ...  
 खत्म हो रही है। हमारे ...  
 में प्रीमियर ...  
 है कि क्या यह ...  
 है ज़मींदारों को वह ...  
 को कुछ न कुछ ...  
 जाय। हमें यह ...  
 अब १००० ...  
 अगर २५ फीस ...  
 है लेकिन ...  
 यह ...  
 हूँ उनका ...  
 मैं इस बात ...  
 ज़मींदारों की ...  
 हम तरह से ...  
 बड़ा ...  
 जाय, ऊंचा और नीचा ...  
 पर अगर इस ...  
 यह बात भी ...  
 मुल्क में एक नया ...  
 आइर कायम ...  
 आइर कायम ...

[श्री सुभाष आर्यम् त्वा]

गर्त। - - के जहा तक मुझे मादम है उसमें तो यह पकड़ नहीं है। वह वायव्यसे के जरिये से वना-बुद्ध के जरिये से किनी गिरी चीज में मरदून नहीं मना चली। अगर हम इस बात के साथ हैं कि हम अपने मुक्त में लेजिस्लेटिव के जरिये से रिफॉर्म करें तो यह रिफॉर्म कभी भी मना नहीं हो सकता कि वह री-व्यूशन की तरह तो। अगर हम अपने मन्त्रों से री-व्यूशन में बचाना चाहते हैं तो निरन्तर बहुत ज्यादा धनो-ट होना पड़ेगा। हमको अपनी जामा पहनना पड़ेगा, जमरी उखूट अखिबार करने होंगे तो एक जमरी तौर पर काम करना पड़ेगा और इसी तर्ज से हर बात का फैसला करना होगा। हमें तर्ज से यही मकसद है कि हम एक उज्ज्वल टेबिल प्लेन में आपस में भाई चारे के तौर पर बैठ कर इसका फैसला करें। कोई भी फैसला जो अस्मरियत अकिञ्चत के ऊपर नाफ़िज करे उसका बुनियादी उसूत नान-याय लेन्स और सन्नाई होना चाहिये। उनका उसूत वह नहीं होना चाहिए जो आम तौर पर लोग अकिञ्चत और अस्मरियत में सनसते हैं, याने कम्युनिज किस्म का नहीं होना चाहिये। अकिञ्चत और अस्मरियत अक्सर एक-दूसरे के बिगड़ने पर होती हैं। कम्युनिज क्वेश्चन तो 'सर्फ' हिन्दुस्तान में ही है। अकिञ्चत इकानाफिक की हाती है और बुनिया में ज्यादातर इकानाफिक ही भ्रमलये हैं। ऐसी सूरत में अकिञ्चत और अस्मरियत को बैठ कर इस बात का फैसला करना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि महज बोर्ड के जार पर या आन्विशागत के जार पर हम एक बात का फैसला कर दें। अगर यह चीज बुनियादी न हाती तो हमने इसका आईन में हो न रखा होता। हमें मादम है कि गवर्नमन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९२५ में ऐसा, प्राविज्ञत मौजूद है कि किसी की प्राइवेट प्रापर्टी उस वक्त तक नहीं खत्म होगी जब तक कि इक्विटेबल कम्पसेशन न दे दिया जाय और इस बुनियादी हक को हमने माना भी है। उनको सूचना यह है कि जब कन्स्टिट्यूट असेम्बली इस मुल्क के आईन का मनादेश तैयार करने के ठिये गयी तो सन् १९२५ के ऐक्ट में जो दफायें थी उसी की नकल कर दो। अभी तक वह दफा मजूर होकर अन्तर्गत से बाहर नहीं आई है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह दफा उसी तरह मजूर होकर बाहर आयेगी। जब हम इस बुनियादी हक को तख्तीम करते हैं तो उनके बाद जरूरत हम बात की यह जागे है कि जा बातें इस सिजिस्लेट में तय हों वह अकिञ्चत और अस्मरियत का सगाठ बना कर न तय हो बल्कि निगोशियेशन (बातचीत) के तरीके से तय होना चाहिये। एक दिक्कत जरूर पैदा होता है और वह यह है कि हमने इतने बड़े बड़े वादे दिये हैं कि अब अगर जना-दास का मन्तव्य हठ नहीं किया जाता है जैसा कि हमने एलेक्शन मैनीफेस्टो में बतलाया था तो उनका पार्टी का गवर्नमेंट पर असर पड़ता है। यह सही है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि अब हमारा मन्त्र आजाद हो चुका है। १५ अगस्त, सन् १९४७ के बाद हम वहां नहीं हैं जहां पहले थे। अगर एक पार्टी अब बसरे इकनदार नहीं रहती है और दूसरी पार्टी उसकी जगह आती है तो वह भी इन्हीं मुक्त की पार्टी होगी। अब हमारे मुल्क को जितना पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लोशक्रेट पार्टी हो, चाहे कजवे-टिव पार्टी हो, लेकिन सब इसी मुल्क की पार्टियां हैं। फर्ज मन्त्रिये फार्मेट ऐडमिनिस्ट्रेशन चयन में कांग्रेस को दिक्कत होती है और कांग्रेस इलेक्शन हर जाती है तो मैं यह कहूंगा कि इलेक्शन की हार भी उसी का मिशाना है क्योंकि उनके बाद जो पार्टी बसरे इकनदार होगी अपने

वह बड़े बाढ़ों की दुनियाद पर तो मैं कह देता हूँ कि कांग्रेस ने जो इतने दिनों तक टुकड़त कर ली है लेकिन वह पाठियाँ उससे चौथाई दिन भी टुकड़त नहीं कर पायेगी और कि अगर कांग्रेस टुकड़त में आयेगी तो बहुत शानदार ढंग से आयेगी और फिर प्रेस के साथ इंग्लैंड हांग अरबिया में दूर-दूर के ताल्लुकत देश किये जायेंगे।

जनमानस, अब मैं चन्द बरों इन बिज के मुतालिक अर्ज करना चाहता हूँ जो इन वक्त हमारे सामने है। जो १३ जनवरी १९४९ का था, उनके गणतंत्र और गणतंत्र में यह भी मतभेद था है कि वह बिज के मुतालिक अर्ज करना और नुनखिया, नोटोफा ड रिया, डाउन एग्जा और कैम्पेट डेट डेट के। ये एक अलग-अलग में १३ डाउन किश जायगा जो वह ने इन भयन के मानने पेन हा। इतने अलवा एक आर बिज के आने की तयकता है और वह बिज हांग इतिहास के मुतालिक। कम, जग वह दोनों बिज ब्यक्त वक्त हमारे सामने पेन हाते जो हम इन वक्त का अलवा जगा सकते थे कि आ तस्वीर हमारे सामने पेन भी गई है वह कदा तक ठीक है और उनमें कौन २ सी कौन है और उसने कहा २ रंग मरना है। लेकिन हम नदी नदी है कि वह दोनों बिज कव लायेंगे और वह किस नवय्यत के होंगे और इस बिज से उनका क्या लगाव होगा। अगर वह दोनों बिज भी हम बिज के साथ आते तो हमें उन पर गौर करने का मौका मिलता। बाहर है कि देश में जो कर्ज की हालत है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस ने जो कुनरपा कमेटी बनाई थी उस कमेटी की सिफारिशों को मने पूरा नहीं पढ़ा है। लेकिन जो कुछ सुझे पाने को मिल है उससे मालूम होता है कि उस कमेटी ने यह सिफारिश का है कि देश का कर्ज खन होना चाहिये। जो बिल इस वक्त हमारे सामने है वह मई में तैयार हो गया था और कुमारपा कमेटी की रिपोर्ट उसके बाद तैयार हुई थी। टुकड़त और उनके कागज इस वक्त का जानते होंगे कि उन्होंने उस रिपोर्ट को इस बिज में ५५ तह इन्फोर्पोंट कर लिया है, लेकिन बहरहाल कुमारपा कमेटी ने जो सिफारिशों कर्जों के माफी के मुतालिक का है वह ऐसी हैं जिन पर इन गवर्नमेंट को काफी गौर करना चाहिये। गोकि वह दोनों बिज इस वक्त नहीं आ सके हैं लेकिन बहरहाल अब वह बिज आये तब मैं उनमें इन चाजों की तयकता रखता हूँ।

जनमानस इस बिज के देखने से यह पता चलता है कि गवर्नमेंट की जो आन टेंडेन्सी बिल के बनाने के मुतालिक है वही हम बिज में भी नुमाया है। आम तौर पर जो मसौदे फानून पेश किये जाते हैं उनमें बहुत सा बुनियादी बातें कर्वा जानी हैं।

जहां तक बुनियादी बातों का ताल्लुक है वह बातें ऐक्ट में सफाई से अना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूँ कि जहां तक इस बिज का ताल्लुक है वह बातें बिज में नहीं आ है और वह लूस में आयेगा। हम नहीं मालूम कि वह क्या है। मसलन मुआविजे का सवाल है। इसके मुतालिक कस सफाई के साथ होना चाहिये। इस बात पर आम तौर पर आवाज उठाई जा रही है और महसूस किया जा रहा है जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है, वह तय किया जाव। मैंने चरण सिंह साहब का एक बयान पढ़ा है जिसमें यह तयकता दिखाई गयी है। अगर अशायी हो सकेगी तो नकद में की जायगी। ऐसा मैंने चरण सिंह साहब का स्टेटमेंट पढ़ा है, जिससे उम्मीद पड़ती है कि मुआविजा नकद में हागा। बुनियादी एराज यह था जहां तक मुआविजे की अशायी का

[श्री सुन्तान आलम खां]

ताल्लुक है उसको पूरी सफाई से आना चाहिये। ऐसा नहीं है रूल्स पर छोड़ दिया गया। कुछ डिटेल्स (तफसील) की बातें होती हैं कुछ बुनियादी और उसूरी होती हैं। उसका इंतजाम होना चाहिये। दूसरी एक बात की आमतौर पर डेफोशेन्सी (कमी) है जिसकी शलक इसमें दिखलाई देती है। वह यह है कि बाब ऐसी चीजें हैं कि जिनका रिट्रापेसक्टिव इफेक्ट (यानी पहिले वक्त पर असर) होगा। हमारे यहां जितने कानून बनते रहने हैं अकसर ऐसे हैं जिनका असर पहिले से होता है। जहां तक कानूनसाजी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं यह मुनासिब तरीका नहीं है। कानून हमेशा इस तरह से बनाना चाहिये कि वह जिस तारीख को पास हो, गवर्नर जनरल की मंजूरी हो, उसी तारीख से लागू हो। ऐसा न होना चाहिये जिससे इस कानून का मंशा साठ दो साल इधर उधर पूरा किया जाय। इस तर्ज से लोगों का एतबार हुक्मत में जाता रहेगा। इसलिये कानून इजाजत देता है कि यू० पी० सरकार इस तरह का कानून लागू करे कि हमारी बुनियाद गैरकानूनी करार दी जायगी। अगर यह चीज आमतौर पर की जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस कानून की मांग करने के लिये कोशिश करेंगे आइन्दा ऐसा कानून सरकार लखी कि पहला कानून गैरकानूनी बना देगी। इस वजह से हो सकता है कि दुश्चारिया और दिक्रते हों और हमें इन दुश्चारियों को हल करना चाहिये। हमें यह ख्याल जरूर करना पड़ता है कि बुनियादी उसूलों को ठोकर न लगाने दें।

बनाबवाला, जर्मीदारी अवालिशन बिल के सिलसिले में मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसमें जो दफा सबसे अहम है, वह मुआविजे की है। उसके मुताल्लिक मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं। सोशलिस्ट लोग यह कहते हैं कि किसी किस्म का मुआविजा न मिलना चाहिये। जर्मीदारों का मताल्बा है कि पूरा मिलना चाहिये। सरकार ने दरमियानी राह अखिन्यार की है और मुआविजा दे रही है। मैंने जर्मीदारी अवालिशन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है। उस कमेटी की रिपोर्ट में मुझे कोई चीज ऐसी न मिली जिससे मैं यह महसूस करता कि मुआविजा की वह सफाई करना चाहते हैं। इसमें क्या उसूल है? इसकी थ्योरी को नापसंद किया गया है। सोशलिस्ट की तरफ से कहा गया है कि मुआविजा न दिया जाय। आचार्य नरेन्द्र देव की जो शहादत हुयी है, उन्होंने इस बात को माना है कि मौजूदा हालात में मुआविजा मिलना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि आचार्य जी ने इस सिलसिले में कोई बयान दिया है और वह अपनी जगह से हटे हैं। राजागम साहब तकरीर फरमा रहे थे तो उसको पेश किया था। वह एक जिम्मेदार लीडर हैं। उन्होंने सोच समझ कर बात कही होगी। वह यकीनन अपनी बात पर कायम होंगे। मैं ज़ाती तौर पर इन चीजों का ज्यादा कायल नहीं हूँ। सोशलिज्म, कम्युनिज्म कोई इज्म हो, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का सवाल आता है तो इंसाफ की रोशनी में, गांधी जी की तान्हीम की रोशनी में फैसला करना चाहिये। हर शाख के साथ मसावात का बर्ताव किया जाय। मैंने जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है उसमें सिर्फ यह चीज मालूम हुई है कि कमेटी को ऐतगज नहीं होता अगर मात्री पहलू से मुआविजे को देखा जाता। दुश्चारी और दिक्रत यह है कि सरकार की मात्री हान्त इस बात को ईजाजत नहीं देती। कमेटी ने जो आर्गुमेंट (दलील) दिया है वह इस पर मबनी है। वह कहते

हैं कि गवर्नमेंट की फाइनैन्शियल कण्डीशन (आर्थिक दशा) ऐसी है कि मुआविजा मार्केट वेन्ड से नहीं दे सकती।

यहां पर 'एक्वीटेबिलिटी' का लफ्ज़ है। इसके लिये हमें सोचना चाहिये कि फाइनैन्शियल कण्डीशन कैसे दुस्त हो, उससे लिये क्या कदम ले लिए जायें और किस सूत्र में इतना जान करें। गवर्नमेंट बहुत से काम ऐसे करती है जिसके लिये मजिद रुपये की जरूरत होती है और जहां कहीं मजिद रुपये की जरूरत होती है उसके लिये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और उसके जरिये से रुपये बसूल किया जाता है। पहले एग्जीक्यूटिवल इन्कम टैक्स लगा था, सेल्स टैक्स लगा था और दूसरे दूसरे टैक्स लगे थे। इसके लिये कि जो जरूरी काम थे उनके लिये क्या फराहम करने की जरूरत थी। जो इन्हीं तरीकों से अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि जमींदारों को मुआविजा देना चाहिये और जब उसने इस ट्रिडिशन (रिवाज) को स्वीकार कर लिया है तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिये। गवर्नमेंट कहीं से क्या हासिल करे लेकिन जब आपने इक्विटेबिलिटी कम्पेन्सेशन देने को कहा है तो उससे किसी तरह भी कम नहीं देना चाहिये। इस मिल-सले में मैं यही कहना चाहता हूं कि लफ्ज़ 'एक्वीटेबिलिटी' इस कानून में ही नहीं दिया हुआ है बल्कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट में है और जो मौजूदा कांस्टीट्यूशन है उसमें भी दिया हुआ है। आखिर इसका कोई उसूल भी तो हो, एक्वीटेबिलिटी की कोई तारीफ हानी चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसका फैसला किया कि आठ गुना मुआविजा दे देना ही एक्वीटेबिलिटी है। इसको तो मैं अविश्वसनीय समझता हूं। गवर्नमेंट को इनके ऊपर सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने बिल को पेश करते वक्त कोई ऐसा दलील नहीं पेश की है जिसके जरिये वह साबित कर सके कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से वह इसे इक्वीटेबिलिटी समझती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें फाइनैन्शियल काम्प्लेक्शियन है, इसको दूसरे तरीके से हल करना चाहिये। आपने इक्वीटेबिलिटी मुआविजा देने का वादा किया था जो कांस्टीट्यूशन और कानून में मौजूद है। उससे पूरा करने के लिए आपको सही कदम उठाना चाहिये।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है, जमींदारों को जो कम्पेन्सेशन मिलेगा उसमें उनके सीर और खुदकास्त का कम्पेन्सेशन उड़ा दिया जायगा। मेरा मतलब यह है कि वह जमीन जो जमींदार के कास्त में है, सीर है या खुदकास्त है उसका कम्पेन्सेशन उसको नहीं मिलेगा। मैं सवाल करता हूं कि ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम है कि आपने ऐसा कोई फैसला किया था। कोई वजह है, यह जाहिर है कि जमींदारों हर सूत्र में इन सूत्रों से खत्म हो जायगी। इसके बाद कोई जमींदारी बाकी नहीं रहेगी। जमींदारी के जितने हक हैं वह सब गवर्नमेंट हासिल कर रही है। इसके बाद जो कास्तकार तबका रहेगा वह भूमिधर होगा, सीरदार होगा, आसामी होगा, अधिवासी होगा। बहरहाल भूमिधर किसी किसम का हो, जमान पर जमींदार का जो हक था उसको एक्वायर करके उसको दे दिया जायगा और उसके एवज में जमींदार को कोई कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायगा जो दूसरे कास्तकारों के लिये दिया जाता है। दूसरा शख्स जो जीतता है, अगर भूमिधर रहेगा तो जमीन पर जमींदार का हक हासिल होगा। उसको तो न दिया जाय लेकिन भूमिधर एक कास्तकार है। उसकी हैसियत बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी दूसरे कास्तकारों की है। जो जमींदार भूमिधर नहीं बन रहा है बल्कि दूसरे तरीके से बन रहा है उसके लिये यह अप्पाई नहीं होता है तो फिर मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती कि जो हक आप उससे हासिल

[श्री मुस्तान आत्म खां]

कर रहे हैं उस का मुआविजा उस को न दे। मैं समझता हूँ कि हर मूलत में वह दिना जाना चाहिये। जनाव वाला, मैंने जैसा पढ़ते अर्ज किया कि चाहे जमींदारों ने कुछ भी कसूर किया हो लेकिन न किसी का मरुत हो सकता है और न होना चाहो कि जो जमींदारों के बच्चे हैं वे नकलीफ में रहे या न उठें। मैं तो यह समझता था कि जब गवर्नमेंट हम क्रिस्म का बिठ लावेगी तो उसमें एक धर्म का प्राविजन रहेगी कि उन जमींदारों, जिनकी जमींदारी खत्म हो गई है उनके अपने वांछी न.म.के अच्छे दंग में रहने का प्राविजन हो जैसा कि काशन की तरफ़ी के लिए ए. ७ पुछल्ल इस बि. में लगा हुआ है उनी नीक से काई प्राविजन जमींदारों के आने वांछी न.म.के अग्रे हो जाता तो अच्छा होगा। मैं समझता था कि गवर्नमेंट शायद यह करे कि जो मुआविजा वह देना चाहती है उसमें से एक हिस्सा तो वह जमींदारों को दे दे और बाकी हिस्सा गवर्नमेंट अपने यहां जना कं ओर उस रकम से जमींदारों के लिये एक इण्डस्ट्री स्टार्ट (उद्योग अरंभ) करे जिसके नेशन गइज करने में भी मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर उन्हें और इंडस्ट्रीज को इनक्रेज (उत्पन्न) करने के लिये जमींदारों के बच्चों को ओर जमींदारों के डेपण्डेण्ट्स को ट्रेनिंग दी जाय और वे संभल जायें और उनके बारे में यह सब काम किया जाता। मेरे दिमाग में यह चीज है लेकिन मैं इस वक्त डिटेल्स तो उसको नहीं बयान कर सकता लेकिन इस क्रिस्म की चीज होनी चाहिये थी ताकि वे अच्छे शहरी बन सकें और उनकी जिन्दगी बरबाद होने से बच सकें।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ और वह ओकाफ के मुनाल्लिक है। जहां तक वक्फों का ताल्लुक है इस बिल में वक्फों का दो तरीके के वक्फों में तरसीम किया है। एक तो खैरती वक्फ हैं और जिनकी आमदनी खैरती कामों में सर्फ होती है। उनके लिये गवर्नमेंट ने यह इंतजाम किया है कि उन वक्फों की पूरी आमदनी जितनी अब है वह उनके मैनेजर्स को दे दी जायगी ताकि वह खैरती कामों में सर्फ हो सकें। उसके लिये मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि उसने सही फेसल किया है। दूसरे वक्फ अठठ-उठ ओगद है। यह वह है जो एक शख्स अपने औलाद को वक्फ कर देता है लेकिन उसका बुनियादी उद्देश्य यह है ख्वाह वह खैरती हो, या मजहबी हो या वक्फ अठठ उठ औलाद हो उनमें अनूमन यह रहता है कि जो बेनीफिशरीज होते हैं उसमें उनके लिये यह प्राविजन रहता है कि उस वक्फ का इतना रकम खैरती कामों में सर्फ हो। और अगर बेनीफिशरीज में कोई नहीं है तो सबका सब रकम खैरती कामों में सर्फ कर दें। मगर तीनों में मजहबी हैसियत से इसके लिये कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि वाकिफ जो वक्फ करता है फर्क कीजिये कि उसकी आमदनी पांच हजार रुपये है लेकिन उसके बेनीफिशरीज जो हैं वह पांच है। वह एक एक हजार रुपये बांट जाता है तो इस हैसियत से हर एक की आमदनी एक एक हजार रुपये होती है तो जाहिर है। कि जो शख्स उसकी जमींदारी के अक्वलीशन के बाद और उन राइट्स अक्वायर (अधिकार उपार्जन) करने के बाद उस पर काबिज होगा उसको क्या क्या प्रिविलेज (विशेषाधिकार) मिलेंगे। उसको कम मिलेगा और जो छोटे छोटे बेनीफिशरीज हैं उनकी ज्यादा मिलेगा। तो क्या बज्रह है कि अगर बेनीफिशरी अख्ददा रहता है तो महज इस बज्रह से कि वह वक्फ १० या १५ सल पहले कर दिया गया था वह उस हक से महकूम कर दिया जाय ? मैं समझता हूँ कि यह किसी सूत में

मुनासिब और मुनिफाना बान नहीं मान्य होनी। कोई वजह नहीं है, फर्ज कीजिये कि उन लोगो ने अपना बक्फ नहीं किया होता और आज से पांच सान साठ पहले वह जमीन बेच देता लेकिन बक्फ हान का बजह में वह जयशद को अलदना नहीं कर सगा और अब वह पांच हिस्से में बगबग तलसीम होनी तो उनको उनका मुनाफा मिलना लेकिन इसमें ऐसा नहीं है यह मुनासिब किसी तरीके से नहीं मान्य होगा। मैं समझता हूं कि जब सेलेक्ट कमेटी में यह सगा उठाना जायगा तो इस पर गौर किया जायगा और इसमें मुनासिब तरकीब की जायगी। और भी चन्द बातें इस बिल में मान्य होनी हैं। मसलन् एक तो यह है कि उन में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई टनेण्ट बकिया लगान की वजह से बेदखल नहीं किया जायगा; मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है कि अगर चाहे हुकूमत हो या जमींदार हो या कोई आदमी हो जिसको कि कश्तकार से लगान लेना पड़े उसके लिये कुछ निष्कल न हो अगर कश्तकार लगान देना है तो उसको हर एक विधायन देने के बाद भी यह जरूर होना चाहिये, कोई पायन्टी जरूर होना चाहिये कि जिससे वह लगान आउतनी से अदा करे। इस बिल में एक चीज यह है कि लगान का ज़िम्मेदार भूमिज और सींगदर को बनाया गया है कि वह वसूल्याबी मायगुजारी करके गवर्नमेंट को अदा करे। अब जमींदारों का खान्ना हो चुका, जमींदारी खत्म हो चुकी और हर शख्स अपनी अपनी कश्तकारी का अपने तरीके पर नाज़िक और जमींदारों को कोई हक नहीं है तो फिर ऐसी मूल में किसी एक या दो शख्स पर मायगुजारी अदा करने का ज़िम्मा डालना किसी मूल में मुनासिब नहीं मान्य होता है। एक बात और है कि जो तरीका अब तक चला आता था कि नम्बरदार मायगुजारी वसूल करके गवर्नमेंट को दे वही बख्श रखा जा सकता है। नम्बरदार मायगुजारी वसूल करके अदा करता जाय और उसको कुछ कमीशन गवर्नमेंट देती रहे तो यह भी ठीक हो सकता है। जबकि जमींदारी का ख़ातमा हो चुका है तो फिर किसी एक या दो शख्स पर इसका ज़िम्मा डालना मुनासिब नहीं है। जहां तक वसूल्याबी का ताल्लुक है यह ठीक है कि गवर्नमेंट जब चाहे पंचायतों के जरिये से जैसे मुनासिब समझे वसूल करके या दूसरी तरह से वसूल करके मगर पंचायतों के जरिये से वसूल करके जैसा इस वक्त है और आगे चलकर जिस वक्त पंचायतें बेहतर तरीके पर फंक्शन (काम) करने लगे तो यह तरीका ठीक हो सकता है तब किसी कारिन्दे या ज़िन्देशर के जरिये से वसूल किया जाय तो बाज लोगों को, मैं ज़ाती तरीके से यह समझता हूं कि एतराज होगा। मैं समझता हूं कि जिलेदार वगैरह ने वसूल्याबी करवाई गई तो इससे और भी खराबी हागी। वह गैर ज़िम्मेदार लोग होंगे २०-३० रुपया उनकी तनखाह होगी। वह ज़िम्मेदारी से इस काम को नहीं कर पायेंगे। आज भी वसूल्याबी का तरीका देहातों में जारी है। वे लोग इन्तहाई तरीके पर क़ाश्तकारों को परेशान करने हैं और उनसे कोई आदमी वहां का खुश नहीं है। अच्छा है कि अगर उनके जरिये से वसूल्याबी न की जाय। मुझे खुशी है कि इस बिल में एक दफा ऐसी रखी गई है जिससे वाकई में वार्निंग (चेतावनी) दी गई वहां तक हमारी ज़रात की हालत दुस्त करने का ताल्लुक है और ऐग्रीकल्चर को बढ़ाने का ताल्लुक है इसमें जो तरीका रखा गया है यह इस बात की ज़मानत नहीं हो सकता कि इससे हमारी हालत बेहतर हो जायगी। इसके लिये गवर्नमेंट को २३ बातें लयज़िमी करनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि हमारे यहां एक ऐक्ट पास हुआ था कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट।



[श्री सुल्तान आलम खा]

उसको पास हुए एक जमाना गुजर गया है करीब दस साल का अरसा हो चुका है। लेकिन वह आज तक डेड लेटर सा हो गया है और उसका सही तरीके पर अमलदरामद नहीं हुआ है। क्योंकि इकोनामिक होल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जब तक इकोनामिक होल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं की जायगी उस वक्त तक वह लाजिमी तौर पर कामयाब नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में वह काश्तकार जो आसामी है उनकी तरफ खास तौर से तवज्जह करने की जरूरत है। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की थी कि जो १० बीघे का काश्तकार है उसके लगान का १ रुपये से ६ रुपये तक कम हो जाना चाहिये। यह बात कही गयी कि उसका लगान कम नहीं हो सकता लेकिन बात मुझे दुस्त नहीं मालूम होती है। त्रिपाठी जी ने कल बड़े जोर से यह फरमाया था कि जब स्लम्प का जमाना था अब चीजों की कीमत बढ़ गई है अब कम नहीं किया जा सकता। आपने कम करने का वादा किया उसको पूरा करना चाहिये। चीजों की कीमत बढ़ जाने का वजह से आपको अपने बायदे को रोकना नहीं चाहिये। २३ साल के बाद स्लम्प आना तो लाजिमी है और ऐसा नहीं होना चाहिये कि जो तरीका आपने एक बार कायम कर दिया वह हनेशा के लिए कायम रहे। जो आपने वादा कम करने का किया है उसको पूरा करना चाहिये। अगर आप उस बायदे से दूरे हैं तो यह बात मुनासिब नहीं मान्य होती यह चीज कुछ मुनासिब और दुस्त नहीं मालूम होती। हाथ में इस बिल के सिलसिले में मुझे मालूम हुआ है कि बोर्ड आव रेवेन्यू की तरफ से एक आर्डर भेजा गया है जिसमें बेदखलियां रोक दी गयी हैं और मेरे सुनने में यह भी आया है कि दना १८० के मातहत बेदखली भी रोक दी गयी है इसलिए कि जमीनों का नया इतजाम होगा। तो इस सिलसिले में जिस किसी के पास जमीन है वह उसी के कब्जे में बनी रहेगी। लेकिन यह जो आर्डर बोर्ड आव रेवेन्यू के सेक्रेटरी की तरफ से निकाला गया है मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या मानों हैं। १८० में वह जमीन होती है जो जमिंदारों के ऊपर होती है और जो जबरदस्ती दूसरा दखल कर लेता है। ऐसी मूल में अगर कानूनी तौर पर अख्तियार मिल जाय और बेदखली न हो सके तो मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर इतजाम नहीं चला सकता और लोगों का एक लाइसेंस मिठ जायगा कि वह जा चाहें वह करने लगे। यह मुद्दा सर बात थी जो मैंने उस वक्त पेश कर दी। जब सिलेक्ट कमेटी से निकल कर यह बिल हमारे सामने आयेगा और इसके ऊपर क्लब बाई क्लब गौर होगा तो जो चीजें मेरे सामने आयेंगी वह उस वक्त पेश की जायेंगी लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया है वह मैं फिर कहूंगा और हुक्मत से इस बात की अपील करूंगा कि यह ऐसा प्रस्ताव है कि जिसका ताल्लुक तमाम एकोनामिक स्ट्रक्चर (अर्थिक ढांचे) से है और यह ऐसा कानून और बिल नहीं है जो हम रोजाना असेम्बली में बैठक पास करते रहे। इस पर जहां तक हो सके हमें बुनियादी तौर पर गौर करना चाहिये जिससे कि इसमें लोगों की मैनेजमन सपोर्ट और अप्रीमेट हासिल हो। मैं समझता हूँ कि जमींदार भी मोर की जरूरत और नज़ाकत को समझेंगे और ऐसा मौका नहीं देंगे कि लोगों को यह महसूस हो कि जिस वक्त मुल्क को उनकी जरूरत थी वह अपने फर्ज से पीछे हटे। जमींदारों में काफी पैटर्न हैं जो वक्त की जरूरत को समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि हुक्मत भी गौर करेगी और हमारे कबीर आजम जो दानिशमन्दी के लिये मशहूर हैं वह जरूर गौर करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी

मे और जो यहां अक्सरियन में हैं उनसे अग्रिम करूंगा कि वह उंडे दिग्ग से गौर करें और यह कोशिश करें कि सही अग्रिमेंट हासिल हो सके और इस तरह से इस कानून को पास करने की कोशिश करें जिससे लोगों की जिन्दगी का जो निज़ार है वह नाजबज्ज़ तौर पर गिरने न पाये और मुल्क में अनरक्युलियमेंट बढ़ने न पाये जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं वह सेक्रिफाइस करें लेकिन वह इस मुल्क में अमन से और बआसानी अपनी जिन्दगी गुज़ार सकें और हम मुल्क में एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें सब लोग मुसलवी हैलियन रखते हों। क्लासलेस सोसाइटीज़ बनें। ऐसा न हो कि एक सोसाइटी को विस्कुल आउटकस्ट करना पड़े बल्कि सब लोग इस बात की कोशिश करें कि जो यह बड़ा काम हमारे मूख के सामने है उसमें सबकी हमदगी और कोआनरेशन हासिल हो और इन एक ऐसा निज़ाम बना सकें जिसमें सब लोगों को अनन चैन मिल सके और इक्कीकत में जैसा कि दावा किया जाता है उसी के मुताबिक सब लोग अच्छी तरह से रह सकें। यू० पी० का मूख दूसरे सबों को यह निसाल दे सके कि उसने वाकई अपने यहां का लैंडलार्ड सिस्टम ऐसा बदल दिया जिसमें लोगों को विस्कुल तकलीफ नहीं होने पाती।

एक बात मैं और कहूंगा और उसके बाद मैं अपनी नक़ीर खत्म कर दूंगा, और वह यह है कि अगर हम यह चाहते हों कि सिरे जमींदारी के अवगर्दीशन से मुल्क की ज़राई हासिल बेहतर बन जाय तो यह नामुमकिन है। जब तक इत निज़सिले में हम कोई और ज़रूरी कदम नहीं उठायेगे तब तक यह नहीं हो सकता; जैसा कि मैंने कहा है कि कन्सलिटेशन अब होल्डिंग्स अन्पेकनामिक होल्डिंग्स का सवाल है, इनको हल करने की ज़रूरत है, और जब तक कि ऐसा बिल जैसा कि मदरास में है यहां नहीं आता जिससे कि मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो बोई जाती हैं उनके मिलसिले में लोगों को मार्केटिंग सुवूलियतें दी जाय और उनको एडवाइस (सलाह) दी जाय कि कितनी फसल किस चीज़ की बोई जाय, जब तक यह चीज़ें प्लान के मुताबिक अमल में नहीं लायी जायंगी तब तक पीसमील (टुकड़े टुकड़े) लेजिस्लेशन, लाने से कोई फायदा नहीं।

मुझे उम्मीद है कि जो मुख्तलिफ़ अक्ताज़ मैंने इस ऐवान के सामने पेश किये हैं उन पर हमदगी से गौर किया जायगा।

माननीय प्रबान सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर, जैसे कि हर बिल पर एतराज होते हैं, एतराज हुए हैं। और इस बिल पर अगर एतराज न होते तो ताज़्जुब की बात थी, क्योंकि यह मसविदा कानून कोई मामूली मसविदा कानून नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सारे ढांचे को एकदम बदलने वाला है। इस लिये इस पर एतराज होना स्वाभाविक है। लेकिन उन एतराजात में से कुछ एतराजात ऐसे हैं जो गलतफहमी पर मबनी हैं, या जानबूझ कर राजनैतिक प्रचार के लिये किये गये हैं। इसके अलावा कुछ तफसीली बातें हैं, जिन पर एतराजात किये गये हैं। वे एतराजात जो तफसीली बातों पर हैं उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उनके ऊपर सेलेक्ट कमेटी में गौर किया जायगा और उसके बाद इस हाउस में भी। लेकिन जो बुनियादी एतराजात उठाये गये हैं राजनैतिक प्रचार के विचार से या गलतफहमी की बिना पर, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

एक साहब ने यह फरमाया कि गवर्नमेंट ने इस बिल के लाने में बहुत देर कर दी है। यहां तो एक आधे साहब ने ही फरमाया है। लेकिन अब से पहले सारे देहात और प्रेस में, और

[श्री चरण सिंह]

बहुत से प्लेटफार्मस पर यह कहा गया है कि कांग्रेस देर ही नहीं कर रही है, बल्कि उसकी नियत खराब है और वह जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहती, क्योंकि उनका जमींदारों से साज्जाज है। एक पालिटिकल पार्टी जो अब तक कांग्रेस के अन्दर शामिल थी, उसने २१ मार्च, सन् १९४८ ई० को नासिक में बैठ कर एक प्रस्ताव पास किया। वह यह कह कर हम लोगों से अलहदा नहीं हुई कि इन लोगों का रास्ता गलत है बल्कि उन्होंने हमारी नीयत पर हमला किया। उसमें जो अलफाज इस्तेमाल किये गये हैं, कि “यह लोग पूँजीपतियों के एजेंट हैं और इसलिये हम लोग अलहदा होते हैं।” आखिर यह कहाँ तक मुनासिब और कहाँ तक अखलाक का तकाजा है और कहाँ तक जनतंत्र के सिद्धांत पर आश्रित है। मैं इस का निर्णय समझदार लोगों पर छोड़ता हूँ। जब से वह कांग्रेस से अलहदा हुए रात दिन प्रोपैगैंडा किया गया कि दरअसल हमारा इरादा जमींदारी को खत्म करने का नहीं है। हम लोग महज किसानों को धोखा दे रहे हैं।

कहा जाता है कि इस बिल के लाने में तीन साल लग गये। देखना यह है कि तीन साल क्या बहुत ज्यादा अरसा है? मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत थोड़ा अरसा है। जब जमींदारी उन्मूलन का नाम लिया जाता है तो उसके नेगेटिव ऐस्पेक्ट (विध्वंसक पहलू) पर ही जोर दिया जाता है कि जमींदारी खत्म करने का ही महज काम है। मैं अर्ज करूंगा कि यह गुपराह करने वाली बात है। दरअसल जमींदारी को खत्म करना बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लाई जाय, इस पर हमें गौर करना था। अगर इस पर हमने तीन साल लगाये तो कुछ भी नहीं लगाये। एक मकान को ढा देना आसान है, लेकिन उस पर दूसरा मकान बनवाना जिसमें जो तकलीफ पहले मकान में थी वह न हो और आइन्दा आने वाली संतानें आराम से रह सकें, इसके लिये तो बहुत कुछ गौर करने की जरूरत होती है। जमींदारी को तो सिर्फ दो धाराओं के बिल से खत्म किया जा सकता था कि जमींदारों के जितने हकूक हैं आज से उनकी मालिक सरकार हो गई। लेकिन हम लोगों की तसल्ली इससे नहीं होती। हम यह चाहते थे कि वर्तमान जमींदार-आसामी व्यवस्था की जगह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक भूमि व्यवस्था कायम करें जो आपके आदर्श के मुताबिक हो, जिसमें किसानों का शोषण बन्द हो जाय, जिससे जनतन्त्र कायम हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और जिसमें फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। वास्तव में यह मसला हमारे सामने था। जो लोग कहते हैं कि देरी हुई, उनके सामने आम तौर पर उनके आदर्श देश रूस का नक्शा होता है। वह कहते हैं कि रूस में सन् १९१७ ही में एक दम जमींदारी खत्म कर दी गई। मैं इस चीज को तसलीम करता हूँ कि वहां बहुत जल्द जमींदारी खत्म कर दी गई लेकिन उसकी जगह आल्टरनेटिव सिस्टम (दूसरी व्यवस्था) तय करने में १० साल लग गये और पांच छै बार उनको अपनी नीति बदलनी पड़ी। अप्रैल, सन् १९१७ में जब केरेन्स्की की गवर्नमेंट आई तो उनका नारा यह था कि जमीन की मिलकियत पंचायत को दे दी जाये और किसानों के लिए जो पुराने उसूल थे कि एक जमीन किसान के पास १२ साल तक रहेगी उसके आधार पर उसको तकसीम कर दिया जाए। लेकिन इसके छः महीने बाद ही लेनिन ने नारा उठाया कि जो जमींदारों से चीज लूट ली गयी है अब किसानों को चाहिये कि उसे लूट ले। इसके ४ महीने

बाद फरवरी १९१८ में घोषणा हुई कि सारी जमीन लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाय। जो जमीन के मुन्तकिल करने का हक हासिल नहीं होगा और न जमीन किसी को लगान पर उठाई जा सकेगी। इसके मात्त भर बाद फरवरी, सन् १९१९ में फिर यह ऐलान किया गया कि सारी जमीन मिनिस्टर स्टेट फंड (राष्ट्र की निधि) है और खेतों बड़े २ सरकारी फार्मों का कलेक्टिव फार्म (समूहिक खेत) के जरिये की जाय। इसके बाद सन् १९२१ में लेनिन ने एक न्यू एकोनॉमिक पॉलिसी (नयी आर्थिक स्थिति) की घोषणा की जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वह किसानों का मतभूत को तब्दील करने में असफल रहे हैं। पांचवीं बार सन् १९२४ ई० में फिर तब्दील की गई और जमीन लगान पर उठाने, मजदूर रखने, कृषि की मशीनों खरीदने को इजाजत दे दी गई इसके बाद दो कम्युनिस्ट पार्टी के दो दल हो जाने हैं। सन् १९२४-१९२७ तक दोनों दलों में बराबर बहस जारी रही कि आगे के लिये कौन सा व्यवस्था हो। दिसम्बर सन् १९२७ ई० में यह तय किया गया कि कलेक्टिव फार्मों की सन्तुष्टि खेती की जाय। इस प्रकार की खेती किसानों पर बबरदस्ती आदी गई और कई बार इसके नियमों में तब्दीली हुई। इस सबके कहने से मेरा मतलब यह है कि वहां पर जमींदारी तो एकदम खत्म कर दी गई लेकिन इसकी जगह दूसरी भूमि व्यवस्था क्या हो इनको तय करने में वहां पर पूरे डम वर्क को थे। और इसके बाद भी जो व्यवस्था कायम की गई उसने किसान आज भी खुश नहीं हैं। यहां हमने केवल तीन साल लिखे हैं और वह भी एक अनाधरम संकट काल में जो सब पर ज़हिर है। मैं चैलेन्ज के साथ वह मेरे मित्र दूसरी ओर बैठे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि संसार का वह कौन सा देश है जिसमें तीन साल के अन्दर जमींदारी खत्म कर दी गई हो और वह भी इस प्रकार जैसे हमारे यहां शत प्रतिशत किसान संतुष्ट हैं।

दूसरा ऐतराज यह किया गया है कि हम पूंजीवाद को मिटाना नहीं चाहते और जब हम पूंजीवाद को कायम रखे हुए हैं तो कोई बजह नहीं है कि जमींदारों को पूरा मुआविजा न दिया जाये। आप जरा इस दलील के औचित्य पर गौर फरमायें यह इल्जाम लगाना कहाँ तक ठीक है कि पूंजीवाद क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है जब कि हम सन् १९४६ ई० में ही इसको समाप्त करने को निश्चय कर चुके थे ?

श्रीमान् स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिये अर्ज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस वॉलेंटियर एक सरकार और वॉलेंटियर एक संगठन प्रतिज्ञाबद्ध है कि वह पूंजीवाद को खत्म करेगी लेकिन कब, किस तरह से और किन ढंग से करेगी इसके बारे में कोई पाबन्दी नहीं है। जैसी कि स्थिति होगी और देश के हित का तकाज़ा होगा वैसे ही उसको खत्म किया जायगा। विचार यह करना है कि क्या जमींदारों और पूंजीपतियों को एक ही स्तर पर रखा जा सकता है ? जमींदारों के जितने शुभ-चिन्तक हैं उनकी तरफ से हमेशा यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम कारखानेदारों को क्यों नहीं खत्म करते और पहले जमींदारों को ही खत्म करते हैं। इनका कारण यह है कि हम समझते हैं कि यह दो किस्म के शोषण जरूर हैं लेकिन जमींदारी और पूंजीवाद इन दोनों के शोषण करने के तरीकों में बड़ा अन्तर है। उदाहरणार्थ, जमींदार लोग स्वयं कोई कार्य या सेवा नहीं करते। बस यही है कि जमीन उनके नाम खेवट में है और वह उसका लगान वसूल करते हैं। किसान जमीन को जोतते बीते हैं। यानी जमींदार के अलहदा कर देने से पैदावार के घट जाने का कोई

[श्री चरण सिंह]

सवाल पैदा नहीं होता । इसके विरुद्ध पूंजीपति अपने परिश्रम और बुद्धि से एक कारखाना लगाता है और उन कारखानों को अपनी बुद्धि से चलाता है जो कि इस देश में पहले नहीं थे। वह अपने यहां सामान बनाता है अर्थात् पैदावार करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वह देश की दौलत में इजाफा करता है परन्तु जमींदार ऐसा कोई कार्य नहीं करता। दूसरा कारण कि हम पूंजीपतियों को इस समय हाथ नहीं लगाते यह है कि जमींदारी के खत्म होने से किसान की पूरी जिन्दगी पर असर पड़ता है लेकिन फैक्ट्रीज़ और कारखानों के नेशनलाइजेशन और राष्ट्रीयकरण से यानी पूंजीवाद को इस तरह से खत्म करने से कि जिस तरह आज सोशलिस्ट चाहते हैं उन मजदूरों की जिन्दगी पर कि जो कारखानों में काम करते हैं कोई असर नहीं पड़ता और न कोई फर्क होता है। वह पहले भी मजदूर था और पूंजीपतियों के हुक्म का पाबन्द था और नेशनलाइजेशन के बाद भी सरकार के हुक्म का बन्दा रहेगा और वही मजदूर का मजदूर ही रहेगा। इसलिए आज जितनी जल्दी जमींदारी को खत्म करने की है उतनी अरजेन्सी देश के हित में पूंजीवाद को खत्म करने की नहीं है।

तीसरी बात यह है कि अभी हमारे पास टेक्निकल क्वालिफाइड परसनल ( शिक्षित विशेष गण ) नहीं है जो कि कारखानों को चला सके। आगे चल कर हमें आशा है कि हमारे सरकार (नौकरों का चरित्र और सुधरेगा और उस वक्त हम पूंजीपतियों को खत्म करके वह प्रबन्ध उनके हाथ में दे सकते हैं। लेकिन आज जब चारों तरफ शिकायत है हालांकि मैं जानता हूं कि तीन चौथाई शिकायत बेजा है और किसी सही बात पर आधारित नहीं है लेकिन फिर भी शिकायत है कि सरकारी अफसर ठीक काम नहीं करते। इसलिये जब आप इन सरकारी अफसरों की बात ऐसी राय रखते हैं तो फिर किस तरह से उनके सुपुर्द अभी इतना बड़ा काम किया जा सकता है। मुझे डर है कि अगर आज सरकारी अफसरों के हाथ में यह कारखाने दे दिये जायं तो उनकी पैदावार जरूर गिर जायेगी और इस समय ऐसा ख़तरा मोल लेना देश के लिये हानिकर और अहितकर होगा।

चौथा कारण कि पहले जमींदारी को ही खत्म करने की आवश्यकता क्यों समझी गई यह है कि मौजूदा भूमि व्यवस्था से ७५ प्रतिशत देहाती जनता का वास्ता है और इस समय इस व्यवस्था को ठीक करने से ७५ प्रतिशत आदमी मौजूदा बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे कारखानों में मुश्किल से २५ लाख मजदूर काम करते हैं। अब एक तरफ सवाल यह है कि २५ लाख आदमियों की मुक्ति पहले की जाय या ७५ फी सदी करोड़ों इन्सानों की? तो स्वभावतः यही बात माननी पड़ती है कि पहले वही काम करना चाहिये कि जिसके करने से करोड़ों आदमियों के भाग्य का निर्णय होता है। इसलिये आज जो लोग यह कहते हैं कि हम पूंजीपतियों को खत्म करना नहीं चाहते वह जानबूझ कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिये यह दूसरा एतराज़ भी बिल्कुल निराधार है। और सही नहीं है। अब जमींदारी को खत्म तो होना चाहिये लेकिन किस प्रकार? अब तक दुनिया के इतिहास में तीन तरीके बरते गये। एक तो जापान में बरता गया, दूसरा रूस में और तीसरा अन्य देशों में। जापान में जमींदारों की संख्या २५० थी। सन् १८७० ई० में एक सभा करके एक प्रस्ताव के

जरिये वह लुट अपने हुकूम और अधिकारों से उस्तकदर हो गये। वहां मुआविजे का कोई खयाल ही नहीं उठा। दूसरा तरीका रूस में बना गया। जर्मनी के मोर्चे पर रूसी जैत्रें हार गयीं और वहां की जनता पहले से ही जंग और जमींदारों से परेशान थी। उसके हाथ में राजसत्ता नहीं थी: मजबूर होकर उसने तलवार उठायी और जमींदारों को खत्म कर दिया। तीसरा तरीका जर्मनी और आयरलैंड में बना गया जो अहिंसानुसार था यानी कानून और कठम के जरिये। जहां तक जागन का रस्ता है वह हमारे हाथ में अर्थात् सरकार के हाथ में नहीं। परमात्मा को जमींदारों को इतनी सद्बुद्धि दे कि वह स्वयं त्याग व बहिदान का रस्ता अपनायें। यह हमारे देश के लिये बड़ी बुद्धिमाननी की बात होनी, लेकिन अन्तोल के साथ कहना पड़ना है कि ऐसी आशा उनसे की नहीं जा सकती। दूसरा रस्ता रूस का है। महात्मा जी ने हम लोगों को सिखाया था कि रूस का रस्ता मुनासिब नहीं है। वहां १२ लाख जमींदार नारे गये थे और उस अनुपात से वहां ४० लाख नारे जायेंगे। हिंसा करना मुनासिब नहीं मान्य होता। उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर सारे समाज में हिंसक वृत्ति पैदा होने का अंदेशा रहता है जो हम देश के लिए हानिकार और अपनी संस्कृति के विरुद्ध समझने हैं। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि उसकी आज जरूरत भी नहीं है। रूस में उस समय राजसत्ता जनता के हाथ में नहीं थी: इस कारण वहां रक्तपात हुआ। लेकिन आज राजसत्ता यहां हमारे हाथ में है। हो सकता है कि हम गच्छी कर रहे हों, ऐसी दशा में जनता को अधिकार है कि वह अपने दूसरे प्रनिधियों द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवाये। परन्तु किसी भी मूल में तलवार उठाना अनावश्यक है। तीसरा तरीका है कानून के जरिये जमींदारी को खत्म करना जिसको हम अपनाते जा रहे हैं। सवाल आता है कि मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय। जागन में मुआविजा नहीं देना पड़ा क्योंकि लोगों ने खुद ही त्याग दिया। रूस में लेने वाले रहे ही नहीं, दिया किसको जाता? तीसरा तरीका जो कानून के जरिये जमींदारी को खत्म करने का है उसके अनुसार दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां मुआविजा न दिया गया हो। कानून के अर्थ यह हैं कि सब बातों और पहलुओं को सामने रख कर देश के हित में नियम बनाना और मर्यादा बांधना। अगर मुआविजा नहीं देना है तो फिर कानून बनाने की ही क्या आवश्यकता है, तलवार के जरिये ही उसे खत्म किया जा सकता है। मेरे एक सौदालिट्ट दोस्त ने पूछा कि जब महात्मा जी ने सन् १९४२ ई० में लुई फिशर से कहा था कि वह मुआविजा देने के हक में नहीं थे फिर मुआविजा क्यों दिया जा रहा है। यह ठीक है। परन्तु मेरे मित्र को शायद यह मालूम नहीं है कि १२ दिसम्बर सन् १९४७ ई० को कलकत्ते में जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें इलेक्शन मेनीफेस्टो जिधमें चुनाव घोषणा-पत्र तैयार हुआ और मुआविजा देना निश्चय हुआ उस बैठक में खुद महात्मा जी मौजूद थे। पूछा जा सकता है कि सन् १९४२ में महात्माजी मुआविजा देने के विचारफ थे लेकिन फिर मुआविजा देने के माफिक क्यों हो गये।

बात मोटी सी और बहुत साफ है। सन् ३७ और ३८ में इस भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में जो कानून यहां और दूसरी असेम्बलियों में पेश हुए तब तक महात्मा जी ट्रस्टीशिप थ्योरी में विश्वास करते थे लेकिन वह जमींदारों के एंटीथ्यूड (रवैये) को देखकर निराश हो गये। एक कारण तो यह मालूम होता है; लेकिन प्रधान कारण दूसरा था और वह यह था कि जो कुछ भी

[ श्री चरण :

उन्होंने लुई फिशर से कहा वह आने वाली अगस्त सन् १९४२ की क्रान्ति के प्रोग्राम के रूप में कहा। उसी काण्टेक्स्ट (संदर्भ) में अमेरिकन पत्रकार ने सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि जो आगे आने वाला आन्दोलन है जिसके लिये आप देश को तैयार कर रहे हैं उसमें किसानों के लिए क्या रास्ता होगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया था कि वे अपने जोतों पर काबिज़ हो जायेंगे। तब पत्रकार ने पूछा था कि क्या इससे अराजकता न फैलेगी, बदअमनी न फैलेगी, महात्मा जी ने फरमाया कि हो सकता है कि कुछ बदनामी फैले, लेकिन मुझे अपने कांग्रेस के सेवकों पर विश्वास है कि वे १५ दिन के अन्दर इस बदअमनी पर काबू पा लेंगे। जब महात्मा जी ने यह बात कही थी तो देश को क्रान्ति के लिए तैयार कर रहे थे, और क्रान्ति की अवस्था के लिए कही थी। होती वह क्रान्ति अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन अगर हिंसा भी होती तो महात्मा जी उसके कारण क्रान्ति को रोकते नहीं। अगर तभी हम ज़मींदारी का खात्मा कर देते तो मुआविजा देने का सवाल नहीं था।

एक बात मुआविजा देने के सिलसिले में और अर्ज करना चाहता हूं। कहा जाता है ज़मींदारों ने देश के साथ गद्दारी की, धोखा दिया, देश को बेचा। फिर उनको मुआविजा कैसा? लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने गद्दारी की थी वह सन् १८५७ में की थी, उनकी वजह से उनकी औलाद को सजा देना कहाँ तक न्यायानुकूल होगा? पूर्वजों के जुर्म की वजह से औलाद को सजा देना, मेरी तुच्छ राय में मुनासिब नहीं होगा। एक दूसरी बात यह है कि सब लोगों ने तो गद्दारी की नहीं थी और कुछ के देशद्रोह के लिये सबको जायदादें बिना मुआविजा दिये छीन लेना न्यायोचित न होगा। हां, एक बात और है, वह यह कि अगर मुआविजा न दिया जाय तो कुछ ज़मींदार ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सीर और खुदकास्त बिल्कुल न हो, तो क्या उन्हें निकाल कर सड़क पर खड़ा कर दिया जाय, बिना उनका कोई इंतजाम किये, बिना किसी प्रबन्ध के। इस प्रकार के सामाजिक व्यवहार को इस प्रकार के तरीके को कम से कम कांग्रेस गवर्नमेंट उचित नहीं मानती।

आज सवाल यह हो जाता है कि कितना मुआविजा दिया जाय। यह जो स्केल इस बिल में रक्खा गया है, उस पर एक साहब, शायद रोशन ज़मा खां साहब, फरमाते हैं कि पहले बड़े ज़मींदारों के लिये मुनाफे का दुगुना रक्खा था, अब मुनाफा का अठगुना रख दिया गया है। ठीक है उसका गुणक बढ़ा दिया है, लेकिन जो मुनाफे के दुगुने के हिसाब से मुआविजा ज़मींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मिलता, ठीक उतना ही मुआविजा इस स्केल में मिलेगा। हो सकता है दो चार लाख इंचर या दो चार लाख उंचर। गुणक आठ होने से भी मुआविजा पहले के बराबर ही इसलिये मिल रहा है, क्योंकि ऐग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को ज़मींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में आमदनी में नहीं घटाया गया था, और बिना इस टैक्स को घटाये दो गुना रक्खा गया था।

इस ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को जब ज़मींदार की इस आमदनी से निकाल दिया जाता है तो मुआविजा उतना ही होता है जितना कि पहले होता था। इसलिये यह कहना कि मुआविजा बढ़ा दिया गया है बिल्कुल गलत है। अब एक बात यह कही गई है कि सब ज़मींदारों को अर्थात् छोटे और बड़ों को मुआविजा एक दर से ही नहीं देना चाहिये।

परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि यह इंसान के अनुकूल नहीं मान्य हो सकता। इसके बारे में किसी कानून के पंडित को भी एतराज हो सकता था। मान लीजिये एक ही खेत में एक छोटा जमींदार और एक बड़े जमींदार शामिल हैं। आलयेचकों की बात मानो जाय तो छोटा जमींदार बड़ी दरद में मुआवजा पायेगा और बड़ा जमींदार उम्मी हैसियत की जमीन का थोड़ा मुआवजा पायेगा। स्पष्ट है, ऐसा करना न्यायानुकूल तो है ही नहीं। परन्तु शायद कानून विद्वत् भी होता।

इस मिलटले में एक दस्तावेज यह भी किया गया है कि एक साल से ज्यादा मुआवजा न दिया जाय और यह भी इन दस्तावेजों पर दिया जाय कि रिडिस्ट्रीब्यूशन किना जाय। जब त्रिपाठी जी ने दस्तावेज या पहले रोज गैशन जनों का साहस का ध्यान उनके लीडर आचार्य नरेन्द्र देव जी की रायही अगर बयान की ओर लींचा तो उसके जवाब में कहा गया कि उनका वह बयान बहसियत एक सोशलिस्ट के नहीं है। क्या वे उस समय सोशलिस्टों के लीडर नहीं थे? और अगर उन्होंने वह बयान सभासदों होने की हैसियत से नहीं दिया था तो और किस हैसियत से दिया था? उनकी लिखित साक्षी में जो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कमेटी के पास भेजे थे उसमें उन्होंने लिखा है :—

“We, therefore, lay the following principle :—

1. Zamindars paying land revenue upto Rs. 100/- to be paid 25 times their Revenue demand.
  2. Zamindars paying land revenue between Rs. 100/- + 250/- 20 times
  3.        "        "        "        "        "        250/- + 500/- 15        "
  4.        "        "        "        "        "        500/- + 1000/- 12        "
  5.        "        "        "        "        "        Rs. 1000/- + over -10        "
- or Rs. 5,00,000/- which soever is less.

This scale is meant only for arable land but so far as waste land forests, tanks, pasture lands and abadi lands are concerned no compensation ought to be paid except the most nominal say Rs. 2/- per acre. Similar is the case for Sir and Khudkasht and land left in the possession of the intermediary.

According to this sale the total amount the state would be required to pay will come approximately to Rs. 100/- crores. It is not possible to pay it in a lump sum. To a large extent it has to be paid out of the rents realized from the peasantry. The total rental demand at present is approximately 24 crores. After the abolition of zamindari system we must give remissions to the tenants to the extent of 4 crores thereby reducing the total demand to Rs. 20 crores.

“इसलिये हम निम्नलिखित सिद्धांत रखते हैं:—

१—१००) तक मालगुजारी देने वाले जमींदार—उनको मालगुजारी की मांग का २५ गुना मिले।



[श्री चरण सिंह]

२—१००) से २५०)	तक मालगुजारी देने वाले जमींदार	२० गुना
३—२५०) से ५००)	„ „ „	१५ „
४—५००) से १०००)	„ „ „	१० „
५—१०००) से अधिक	„ „ „	१० „ या

५,००,०००) दोनों में से जो रकम कम हो।

यह दर केवल कृषि योग्य भूमि के लिये है। ऊसर, वृक्षाच्छादित भूमि, जंगल, चरागाह और आबादी की भूमि के बदले किंचिन्मात्र अर्थात् २) प्रति एकड़ के अतिरिक्त और कोई हर्जाना देना नहीं चाहिये। यही बात सीर, खुदकास्त और मध्यमों के कब्जे में छोड़ी हुई भूमि के विषय में है।

इस दर के अनुसार कुल रकम जो सरकार देगी वह लगभग सौ करोड़ रुपये होगी। इसको एकबारगी पूर्णतया चुका देना सम्भव नहीं है। किसानों से लगान वसूल करके उसी में से इस रकम का अविकतर भाग देना होगा। इस समय कुल लगान जो वसूल होना चाहिये वह लगभग २४ करोड़ है। जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त हम लोग किसानों को इसमें से ४ करोड़ की छूट देगे जिससे कुल लगान घट कर २० करोड़ रह जायगा।

आचार्य जी ने ठीक-ठीक हिसाब नहीं लगाया है। उन्होंने अनुमान से एक अरब रुपया रक्खा है। परन्तु हिसाब फैलाया जाय तो उनकी रकम हमारे निश्चित किये हुए प्रतिकर से कुछ कम न बैठेगी। रोशन ज़मा खां साहब २५ या ५० करोड़ से ज्यादा नहीं देना चाहते। लेकिन उनके लीडर साहब कहते हैं कि उसकी तादाद कम से कम १ अरब होगी। विरोधी दल के प्रोपेगण्डा की यह तो बिल्कुल सीधी सदी बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट कितने ही माफूल काम क्यों न करे वह उसे मानने को तैयार न होंगे। कहा जाता है कि लगान घटाया जाय। हम अपनी स्कीम के मुताबिक जो रेंट वसूल कर रहे हैं वह साढ़े आठ करोड़ होता है। लेकिन आचार्य नरेन्द्र देव किसान से २० करोड़ वसूल करना चाहते थे। और फिर भी शिकायत है कि हमने लगान नहीं घटाया।

अब सवाल यह होता है कि मुआविजा दे कौन? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि तरीका जो कोई भी हो अन्ततोगत्वा उसका बोझ उत्पादक पर ही पड़ेगा। जो भी टैक्स लगाये जायेंगे वह सब उत्पादन करने वालों की जेब से ही आयेंगे। अब उनकी दो किस्में हैं एक तो सबसे बड़ा खेती में काम करने वाला किसान है और दूसरा फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर। तो चाहे जिस सूरत में ले लीजिये चाहे उसे किस्तबन्दी से ले लीजिये चाहे एक दम ले लीजिये। किसान को किसी न किसी रूप में अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादकों में किसान ही सबसे ज्यादा हैं, बल्कि ८५ फी सदी हैं, कभी न कभी या घूम फिरकर टैक्स किसान की जेब से निकलेगा।

लिहाज़ा यह कहना कि मुआविज़ा स्टेट अपनी तरफ से दे दे और किसान से न दिलाया जाय, यह अपने आपको धोखा देना है क्योंकि स्टेट कहाँ से देगी। स्टेट अपने जनरल रेवेन्यूज़ में से देगी लेकिन वह भी तो किसान की जेब से आया है। जो स्कीम इस बिल में रखी गयी है उसके मुताबिक यह एतराज़ किया जाता है कि किसान बड़ा गरीब है, वह नहीं दे सकता। मैं

इसे तसल्लीम करता हूँ किसान गरीब है, लेकिन गरीबी और अमीरी रिलेटिव टर्म्स हैं (अपेक्षा से हैं)। किसान गरीब है बहुकालिक पूँजीपतियों के और जमींदारों के। लेकिन देखना सिर्फ यह है कि आज जो फ़ायदा उसको पहुंचेगा, जो उसकी इच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खेतों की मिल्कियत लेने की चन्नी आई है उसको पूरा करने के लिये जो प्रतिकर हम उसको, यानी जमींदार के लिये दिये जाने को कहते हैं, किसान उसको दे सकता है या नहीं। केवल ऐन्सोल्यूट टर्म्स में यह बात कहना कि वह गरीब है इससे मसला हल नहीं होता। देखना यह है कि जितना रुपया जिस किसान से मांगा जा रहा है उसमें उसे देने की क्षमता है या नहीं। इसके बजाय में मुन्त्रालिफ़ैन ने जमींदारी अवाल्लिशन कमेटी की रिपोर्ट के सफ़ा २८, २९ और ३० के उद्धरण दिये हैं और कहते हैं कि 'यू आर कण्डेम्ड आउट आफ़ योर ओन माउथ' आपकी रिपोर्ट में यह है कि किसान इस लड़ाई की वजह से गरीब हो गया है। उसकी हालत बजाय बेहतर होने के बदतर हो गई है। इसके मुन्त्रालिफ़िक मुझे यह अर्ज़ करना है कि बदतर हो गई हो लेकिन किसकी अपेक्षा? शहर के आदमियों की अपेक्षा। यह नहीं है कि उसकी आर्थिक दशा जो बहुकालिक दूसरे वर्गों के पहले थी वह बदतर हो गई है। इसके अलावा एक बात और है। सिर्फ़ मदरास की रिपोर्ट पर और बम्बई प्रेसीडेन्सी के एक प्रोफ़ेसर की रिपोर्ट के ऊपर यह नतीजा निकाला गया है कि क्योंकि इन दोनों प्रेसीडेन्सी में किसान की ऐसी हालत है लिहाज़ा यू० पी० में भी हो गई होगी। यहां कोई खोज इस बात की नहीं हुई कि यू० पी० के किसान किसी प्रकार से रुपया देने के नाक़ाबिल हैं या उनकी हालत पहले से खराब हो गई है। कहा गया है कि मदरास में ऋण-बढ़ता बढ़ गई है। मुमकिन है वहां ऐसा हो गया हो। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि यहां के किसानों की ऋण-बढ़ता बढ़ गई है, क्या वह मक्कूरुज़ हो गया है? हरगिज़ नहीं। बल्कि उसके ऊपर जो कर्ज़ा सन् १९३९ में था वह अगर सब नहीं तो ९९ फी सदी ख़त्म हो चुका है। मदरास में जो हालत हो उससे यह नतीजा निकालना कि यहां के किसानों की भी वही हालत है, बिल्कुल ग़लत है।

दूसरी युक्ति जो जमींदारी अवाल्लिशन कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पेश करते हैं वह यह है कि इस कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफ़ारिशें हैं उससे यह सरकार पात्रन्द है। लेकिन यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के विचारार्थ रक्खी गई थी। इसलिये यह दलील करना उसमें कोई अर्थ नहीं रखता। वाक्या यह है कि सन् १९४० में हमारे देश में २ अरब ९० करोड़ की करेन्सी थी अर्थात् काग़ज के नोट ये और सन् १९४६ में ११ अरब ८० करोड़ के नोट हमारे देश में थे। वह करेन्सी कहां है? ब्लैक मार्केटियर्स के पास, प्राफ़ीटियर्स के पास होगी, यह ठीक है। अब दूसरा वर्ग रह जाता है मिडिल क्लास का। वह तो रो रहे हैं। मध्यम श्रेणी की हालत बहुत खराब है। आज मध्यम श्रेणी कोई बचत नहीं कर पाती है। इसीलिये उद्योगपति कहते हैं कि मिडिल क्लास के पास से कोई पूँजी उनको नहीं मिल रही है। अब रह गये मजदूर और किसान। उस १२ अरब रुपये में से बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि ७५ फी सदी हिस्सा, इन्हीं हमारे गरीब किसानों में बंटा हुआ है। मुझे यह रुपया अख़रता नहीं है। हम यह चाहते हैं कि उनके पास रुपया चौगुना और पचगुना हो। उनके पास वह हवेलियां और पक्के मक़ानात हों जैसे कि शहरों में खड़े हुए हैं। और वह आज चाहता भी है। इसीलिये सीमेंट के लिये, लोहे के लिये, अर्थात् मक़ान बनाने के सामान के लिये और उपभोग की दूसरी वस्तुओं के लिए उसकी तरह तरह की मांग हैं। लेकिन

[श्री चरण सिंह]

उन चीजों की हमारे देश में कमी है इसीलिए हमको कंट्रोल करना पड़ता है। आज हमको सामान पैदा करने की जरूरत है। महज करेंसी उसकी जेब में देने से सामान नहीं पैदा हो जायेगा। जितना माल हमारे देश में सन् ३९ में पैदा होना था उतना आज भी पैदा होता है। लेकिन करेंसी ठीक चौगुनी हो गई है। यही कारण है कि आज ६७८ प्रतिशत भाव बढ़ गये हैं। आज नोट या सिक्का बढ़ गया है लेकिन उत्पादन जहां का तहां ही है। करेंसी अर्थात् नोटों से किसानों का भत्ता नहीं होगा। इसके अलावा जैसा माननीय पन्त जी ने अपने ७ तारीख के भाषण में कहा था और प्रेम कान्फ्रेंस में बतलाया था। इस वक्त हमारा एडवर्स ट्रेड बैलेन्स ९५ करोड़ रुपये का है। इसका मतलब यह है कि हम चीजें बाहर से मंगाते हैं लेकिन बदले में चीजें हम नहीं भेज सकते हैं। जरूरत यह है कि जितनी चीजों की हमें जरूरत है उनको हम अपने मुल्क में पैदा करें और उपभोग की वस्तुएं बाहर से न मंगावें। सिर्फ कैपिटल गुड्स अर्थात् कारखानों की मशीनें आदि ही बाहर से मंगा लें जो हमारे यहां नहीं बनती हैं। मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश का किसान अपनी पेटी कस ले जिस तरह हर देश के किसान वक्त पड़ने पर करते हैं। जो रुपया किसान के पास है उसका इस्तेमाल वह नहीं जानता है।

एक बात और है जो कुछ कड़वी सी मालूम होती है लेकिन कहना ही पड़ना है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ जिलों में शराब-बन्दी तो हो गई, लेकिन शराब के टैक्स से कुछ प्रान्त की आमदनी बढ़ गई। यह सही हो सकती है। कम से कम मैं इसकी तरदीद करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आप से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपका यह मतलब है कि जिन जिलों में शराब-बन्दी हुई है वहां पहले से ज्यादा शराब पी जाने लगी है या आपका यह मतलब है कि सन् ३९ के मुकाबले में लोग शराब ज्यादा पीने लगे हैं। स्पष्ट सी बात है जहां शराब-बन्दी हो गई है वहां तो शराब की आमदनी ही बन्द हो गई। तो बावजूद कुछ जिलों में शराब-बन्दी हो जाने से कुछ प्रान्तों की आमदनी बढ़ जाने का केवल एक ही अर्थ है और वह यह कि अब पहले की अपेक्षा लोग शराब अधिक पीने लगे। परन्तु आज यह शराब कौन ज्यादा पी रहा है। आप देखेंगे कि गांवों में जो आबकारी की दुकानें हैं उनका जूरे नीलाम चौगुना और पंचगुना हो गया है। अर्थात् जिस रुपये का दुरुपयोग होना चाहिये था उसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर प्रतिकर किश्तों में या दस्तावेज के शक्ल में दिया जाय तो एक अरब और ४० करोड़ नई करेंसी पैदा करनी पड़नी और इससे कीमतें और बढ़ जातीं। बहरहाल हम बिना में जो अपने लगान का दम गुना रुपया देकर सदैव के लिए अपने लगान या माउगुजारी को आधा करवाने की बात रखी है उसमें दूकानदारी की दृष्टि से भी किसानों को नुकसान नहीं है। परन्तु यह सब तो मामूली चीजें हैं। अगले चीज यह है कि अब किसान अपने खेत का मालिक हो जायेगा। अब भूमिधर हो जाने के बाद जमींदार का जिनेदार उनके खेत पर डंडा लेकर नहीं जायेगा। जमीन की कीमत वही आदमी जानता है जो अपने खेत का मालिक नहीं है। इसकी कोई कीमत आंकी ही नहीं जा सकती है। जो किसान बाप दादों के जन्म से जुल्म सहता आया है और जो कभी अपने खेत को यह नहीं कह सका कि “मेरा” खेत है वह अब दस गुना रुपया दाखिल करने के बाद आराम की सांस लेगा।

वह संसद सभ्यता को होगी उसको वह स्तुति होगी जिसके लिये मैकडॉनॉल्ड से भूवा था कि सन्स के सामने वह सन्स खुले हैं एक तो यह कि जमींदारी खत्म होनी है, वह अपना पुराना खान देना रहे और सदेव काम करना रहे। परन्तु अपनी जमीन का मालिक नहीं होगा, यानी वह न कर सकेगा, रेंट न का सकेगा, और न सम्पन्न कर सकेगा। दूसरा यह है कि अपने लगान का उस गुना सरकार जो दे दे तो वह अपनी खरीद का मालिक हो जायगा। मेरा विश्वास है कि उसके पास नकद न होगा जो वह पैसा देव देगा, राय देव देगा मगर वह अपना अवश्य देगा और खेन का मालिक हो जायगा। मेरे इस विश्वास का कारण यह है कि मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ। किसान अपनी औरन का खर ख देवना मंजूर करेगा परन्तु खेन की मिलिक्यट इस्तिफा करना मस्त करेगा। यह किसान को मनेवृत्ति है। रहे जमींदार, उनकी सबसे बड़ी मंग यह थी कि हन्को मुआविजा नकद में मिलना चाहिये। इन आदम कने थे कि माननीय प्रीनियर साइव ने जब जमींदारी उन्मूलन कौन कामन करने का फैसला किया था तो जमींदार यूनि-यन या ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक बयान निकालता। परन्तु मालूम होना है आप लोग ऐसी बने सीखे ही नहीं हैं। भावना का जवाब भावना से देना जमींदारों को आना ही नहीं है। उल्टे इस पर एतराज है। श्री जगदीश प्रसाद बड़ौत में जाते हैं और तकरीर में कहते हैं कि इस गुना दखिल करने से किसान को बड़ा नुक-सान होगा। इस मनोवृत्ति की जितनी निन्दा की जाय वह कम है। जमींदारों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिये कि उन्हें मुआविजा नकद देने का इन्तजाम किया जा रहा है। जमींदार माई यहां असेम्बली में और कौंसिल में भी तकरीर करने खड़े हों तो इस बात का शुक्रिया अदा करें। सरकार को धन्यवाद दें। उनकी अन्देशा था कि सम्भव है उनके किस्तबन्दी के बाण्ड्स कोई भावी सरकार कैसिल कर दे तो वह इस खतरे से बच गये। अब वह कहते हैं कि मुआविजा बाजारी भाव से नहीं मिल रहा है। उनको केवल इतना ही प्रतिकर मिल रहा है जितना कि जनता के मुमाइन्दे उचित व माकूल समझते हैं। क्योंकि जमींदारी उन्मूलन कोई सौदे की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश-हित की दृष्टि से किया जा रहा है। अतएव पूरी कीमत देने या छैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) के उसूलों पर चलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो तजवीब इस बिल में रखी गई है, उसने देश को एक लाभ होगा अर्थात् उद्योगीकरण में वृद्धि। पंजाब के बरबाद हो जाने वहां का हिंदू पूंजीपति अब उद्योगों में पूंजी नहीं लगा सकता है, मध्यम श्रेणी के लोग कीमतें बढ़ जाने से कोई बचत नहीं कर सकते हैं जो कि उद्योगों में लग सके और सेठ व कारखानेदार कई कारणों से नये कारखानों में पूंजी लगाने में झिझक रहे हैं। मतलब यह हुआ कि पूंजी की कमी से देश का उद्योगीकरण रुक रहा है। मेरी राय में जो खपया मुआविजे के रूप में जमींदारों को मिल रहा है उससे अब वह गुच्छरें नहीं उड़ा सकते। वरन् दो तीन साल बाद उनका पास कुछ न बचेगा। यह जो एक अरब सैंतीस करोड़ खपया मुआविजे के रूप में मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि हर जमींदार इसी फिक्र में होगा कि जो खपया उनको मिल रहा है उसको बैंक में न रखें, लेकिन उद्योगों में लगावें। मैं बिल्कुल इनकारमय तरीके पर कहता हूँ कि बहुत मुमकिन है उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन हो और प्रधान सचिव उसके मुता-ल्लिक कुछ फरमायें। खैर ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट की हो या न हो लेकिन आप लोगों के लिये

[श्री चरण

इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है कि उस रुपये को इण्डस्ट्रीज में लगा दें ? बेहतर यह है कि बजाय इसके कि रेस के घोड़े और अलसेशियन कुत्तों के खरीदने में रुपया लगावें, उद्योगों में ही सारे रुपये को लगा दें । यह जो एक अरब चालीस करोड़ रुपया मिल रहा है उसमें से हर सूरत में कम से कम एक अरब रुपया आप लोग इण्डस्ट्रीज में लगा दें । इससे देश का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा । जो स्कीम आपके सामने है उस पर अगर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय तो एक पत्थर से कई चिड़िया मारने के अनुरूप उससे कई मसले हल हो जाते हैं ।

अब इसके बाद एक एतराज यह है और खास तौर से अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है कि हम बीस लाख जमींदारों को तो खत्म कर रहे हैं लेकिन उनकी जगह एक करोड़ बाईस लाख नये जमींदार या कैपिटलिस्ट पैदा करने जा रहे हैं । भूमिधर से मतलब तो उस आदमी से है जिसके पास जमीन है । लेकिन जिस तरह से जमींदारी अवालिशन कमेटी के सिलसिले में लोगों का यह ख्याल था कि जमींदारी को खत्म करना मात्र ही हमारा काम है और कोई दूसरा काम ही नहीं, इसी तरह से जमींदार लफ्ज के मुताल्लिक भी लोगों में गलत-फहमी है । जमींदारी अवालिशन का लफ्ज जब आता है तो लैंडलार्डिज्म और टिनेण्टशिप की व्यवस्था को खत्म करना ही उसका मतलब है । जमींदार और आसामियों की जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हम खत्म करने जा रहे हैं । हम ऐसे आदमियों को नहीं खत्म कर रहे हैं जिनके पास जमीन है । हम ऐसे आदमियों को खत्म कर रहे हैं जो निहले बैठ कर महज दूसरे लोगों की कमाई पर अपनी गुजर करते हैं । जमींदार का माने के महज पूर्वी इलाके में और बीच के इलाके में यही लगाया जाता है कि जमींदार वही है जो लगान पर अपनी जमीन उठाता है । लेकिन अम्बाला और राजपूताने में जहां कहीं जमींदार शब्द का इस्तेमाल होता है उसके माने जमीन जोतने वाले से होता है । सन् १९३७ में जब जमींदारी अवालिशन की बात चली तो अम्बाला के गाँवों में किसान यही कहते थे कि क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सब जमीन ले लेगी ? हम लोगों से जमीन छीन ली जायगी ? जमींदार के माने लैंडहोल्डर से है । आप कहेंगे कि जब जमींदार के माने यही है तो जहां कहीं भी इस बिल में किसान का जिक्र आता है इस अर्थात् जमींदार शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है ? इसके लिये मैं यही कहूंगा कि उसका एसोसियेशन कुछ ऐसा बुरा रहा है जिसकी वजह से हम पिछली बातों को बिल्कुल भुला देना चाहते हैं । इस समय उसका इस्तेमाल अच्छे माने में नहीं किया जाता है । लोगों का कहना है कि हम कैपिटलिस्ट जमींदार पैदा कर रहे हैं । यह गलत है । चाहे बड़े जमींदार हों या छोटे जमींदार हों, हम लैंडहोल्डर को नहीं बल्कि लैंडलार्ड को खत्म करने जा रहे हैं । चाहे वह लैंडलार्ड एक बिसवे का ही लैंडलार्ड क्यों न हो । यही हमारा असली उद्देश्य है । दूसरा उद्देश्य कानूनी, शांतिपूर्ण कब्जे के सम्बन्ध में है । खाह वह सब टिनेंट हो, या टिनेंट इन चीरु हो या मारगेजी हो या ठेकेदार हो या जिस किसी तरह का भी काश्तकार हो अगर उसका लाफुल पोजेशन है तो वह रहेगा ।

अगर मेरे मित्र जो सामने बैठे हैं उनके पास सौ या दो सौ एकड़ या एक हजार एकड़ का फार्म है तो वह उनके पास रहेगा । पहली बात तो यह है कि जब आलोचक यह कहते हैं कि इतने बड़े फार्मर्स, इन सबको रहने दोगे तो कितने बड़े फार्मर्स हैं ? जमींदार अवालिशन कमेटी की

रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो ९ हजार जमींदारों के पास ५० एकड़ से बड़े फार्म हैं लेकिन जिस हद तक वह काश्तकार है उस हद तक हम उसको नहीं छू रहे हैं और जो जमींदार हैं वह उस हद तक जड़ से जा रहा है। उसमें कोई भी रियायत नहीं है बराबरी भी और आगे के लिये भी जमींदार न पैदा हों इसके लिये भी यह कर दिया गया है कि भूमिधर सबलेटिंग नहीं कर सकते सिवाय उन विशेष सूक्तों के, कौन सी सूक्तें? वह सूक्तें हैं नाकाबिलियत काश्त की। जैसे नाकाबिलियत, विधवापन, अपाहज या पागल होने के कारण या अपने देश के हित के लिये तलवार लेकर लड़ने में जाने की वजह से हो, या किसी जुर्म की वजह से उसे सजा हो जाय और जेल में चला जाय। ऐसी सब सूक्तों में उसे अपनी जमान काश्त पर उठाने की इजाजत हो। यह और रहन दखली दोनों किस्म के इन्तकाल को हमने खिलाफ-कानून कर दिया और ताकि वह धोखा देने की कोशिश न करे इसलिये हमने ज़बती की सज़ा रखी है। तो मौजूदा जमींदार खत्म हुये और आगे के लिये जमींदार पैदा नहीं हो सकता। फिर कैसे कहा जाता है कि जमींदारी कायम रखी जा रही है। मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि ऐसा कहने वाले ईमानदारी से नुक्ताचीनी नहीं करते। क्या वह कह सकते हैं कि जमींदारी कायम हो रही है। अभी ९ तारीख को नेशनल हेराल्ड में सोशलिस्ट पार्टी का एक बयान निकला था कि जमीन नान कल्टीवेटिंग क्लास अर्थात् ग़ैर-किसान के हाथ में आ जायगी। नान कल्टीवेटिंग क्लास के पास कैसे चली जायगी? जो बड़े बड़े सेठ थे वह पैसा बड़े बड़े सूद पर देकर जमीन नीलाम करा लेते थे और इस तरह से शहरों में रहने वाला जो साहूकार या वह नीलाम करा कर जमींदार हो जाता था लेकिन खेती नहीं करता था। उसके हाथ में जमीन आगे आ नहीं सकती है क्योंकि वह जमीन नीलाम तो करा सकता है लेकिन स्वयं खरीद नहीं सकता क्योंकि जानता है कि या तो गाँवों में जाकर काश्त करनी पड़ेगी या फिर उसको बेचना होगा। इस तरह से जमीन उसके हाथ में नहीं जा सकती। पट्टा कर नहीं सकता, और काश्त करने के लिये तैयार नहीं है तो जमीन उसके पास रह नहीं सकती। गवर्नमेंट का एक विचार यह हो रहा है कि प्राइवेट मनीलैंडिंग अर्थात् निजी लेन देन बन्द कर दी जाय और सहकारी सोसायटियों के जरिये मनीलैंडिंग हो। खैर, अगर प्राइवेट मनीलैंडिंग भी जारी रहे तो प्राइवेट मनीलैंडिंग क्लास या कोई ऐसा क्लास लैंडलॉर्ड या ज़मीन्दार नहीं हो सकता क्योंकि खरीद तो सकता है लेकिन पट्टे पर ज़मीन उठा नहीं सकता। फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि नान कल्टीवेटिंग क्लास या ग़ैर-किसान के हाथ में लैंड एकट्ठा हो जायगी। इसके अतिरिक्त एक बात और कही जाती है कि खेती के अतिरिक्त जमीन दूसरे कामों में, जिनमें कोई पैदावार नहीं होती, इस्तेमाल होने लगेगी और इस प्रकार देश को हानि होगी। ठीक है भूमिधर खेती के अलावा दूसरे कामों के लिये जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे काम क्या हैं? कारख़ाने लगा सकता है, किराये के लिये मकान बनवा सकता है, कंकड़ की खान खोद सकता है। कौन ऐसा पागल निकलेगा जो हानिकर या अमर्शनी कामों के लिये अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि जब किसी के पास इससे बेहतर प्रोग्राम न हो तो वह बेचारा क्या करेगा, गालियाँ देगा और बेजा अल्लोचना करेगा। विपक्षियों को जब इस बिल में कोई एतराज़ मिला नहीं तो उन्होंने इसको नान प्रोटेक्टिव चेनाल ज़मीन के चले जाने की बात कही। यह भी कहा गया है कि हम चतुर्वर्ण

[श्री चरण सिंह]

कायम करने जा रहे हैं। मैं उस लहजे में तो अपनी बात नहीं कह सकता जिस लहजे में राज-राम जी शास्त्री ने अपनी बातें कही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि चतुर्वर्ण कैसे कायम हो रहा है? जहां तक अधिवासी का प्रश्न है वह तो ५ साल के बाद नहीं रहेगा। और जहां तक सीरदार की बात है या गवर्नमेंट को यह आशा है और हममें से हर एक को यह विश्वास है कि इस कानून के पास होने के तीन महीने के अन्दर यू० पी० में कोई सीरदार नहीं रहेगा। सब भूमिधर हो जायेंगे। क्योंकि किसान समझता है कि मिलिकियत के हक के क्या माने हैं। लिहाजा सीरदार कोई नहीं रहेगा और अधिवासी जो वैसे ही अस्थायी होंगे या तो बेदखल हो जायेंगे या सब भूमिधर हो जायेंगे। और जो भूमिधर स्वयं काश्त करने के असमर्थ होंगे वही जमीन दूसरे को दे सकेंगे और ऐसी जमीन लेने वाले आसामी कहलायेंगे जिनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी।

अब लाभहीन जोतों का सवाल आता है। इनके दो इलाज बनाये गये। एक तो यह कि अभी कानपुर जिले के किसी गाँव में दो महीने हुए जब हमारा बिज प्रकाशित हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी की एक कान्फ्रेंस हुई। उसमें आचार्य नरेन्द्रदेव साहब भा तशरीफ ले गये थे। तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि प्रान्त भर की जमीन किसानों में बराबर तक्लीम होनी चाहिये। मैं अब करूंगा कि रोशनज़मा साहब ने ४१ लाख किसानों के परिवार वहाँ पर बतलाये। लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ ७५ लाख किसानों के परिवार हैं। ४१ लाख के हिसाब से तो कुल २ करोड़ की आबादी ही आती है। क्या हमारे यहाँ सूबे में ६ करोड़ में से २ करोड़ ही यानी ३३ फी सदी ही खेती करने वालों की संख्या है। मैं आपकी तबज्जह जमींदारी अवालियन कमेटी की रिपोर्ट के पेज १४ की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसमें सन् १९३१ ई० की जन-गणना की ओर संकेत करके लिखा है—

“At this census 53.2 per cent of male and female earners (excluding market gardeners and growers of special crops), in British territory only, returned actual cultivation as the principal source of income. A further 3.8 per cent returned actual cultivation as their subsidiary source of income to some other principal occupation. This means that 57 per cent of the total population is dependent on the income derived from actual cultivation of holdings. This involves 5,781,000 families.

(इस जन-गणना में केवल ब्रिटिश राज्य के पुरुष और स्त्री उपार्जकों में से (उपज के विक्रयार्थ उद्यान लगानेवालों को और विशेष फसलें बोने वालों को छोड़ कर) ५३.२ प्रतिशत थे। अपनी आय का प्रधान साधन खेती को ही लिखाया। इससे अलग ३.८ प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनका प्रधान व्यवसाय कुछ और था लेकिन खेती भी आय का सहायक साधन था। इसका अर्थ यह है कि कुल आबादी का ५७ प्रतिशत भाग जोतों की खेती से होने वाली आय पर आश्रित है। इसमें ५,७८१,००० परिवार सम्मिलित हैं।)

यह १९३१ के जन-गणना की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है। तब से अगर आप हिसाब लगायें तो १०० के पीछे आज जन संख्या १२९ हो गई है। इस हिसाब से किसानों के आज ७५ लाख परिवार से कम नहीं हो सकते। तो ७५ लाख परिवार में फिर से बराबर-बराबर जमीन बांट

देना क्या हमें लेना है ? दूसरी बात यह कि उन्होंने हिस्सा लगा कर यह बतला दिया कि ४१ लाख परिवार हैं और १.३३ लाख एकड़ मजदूरी रकबा है और १,७,१८ लाख कृषि-कास्त बंबड़, जो सारे बंबड़ एकड़ में परिवार आते । ५ करोड़ जमीन और सारे बंबड़ में तकनीक कर दिया, ४१ लाख आबाद जगह ४१ लाख से न, किसान परिवार की अधिक हैं, ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन मजदूरी जमीन आती है और १८ लाख एकड़ का बंबड़ा बनने हैं क्या वह सारी कृषि जमीन में जमीन है और यह भी बतला कर दिया कि हो सकती है और ७५ लाख परिवारों में जमीन और कुछ नकद बंबड़ा २ बट भी दिया तो क्या सबके सब न मक जोन हो जायगी ? नहीं, हाँ, हाँ - हाँ

अब जमीन है कि मजदूरी आ - इनका नहीं कर समझे, तो जिनसे बड़े बड़े लाने हैं उनको ही जमीन में नकद बट दिया जाय १ हजार जमीन के जगह हैं बड़े लाने हैं और उनके पास कुछ १ लाख एकड़ जमीन है । ५० एकड़ में जमीन अगर छोड़ी गयी तो सारे चार लाख एकड़ में उनमें नकद रहे, सारे चार लाख में ली । लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के लीडर श्री उद्दीनत हमें नकद लगी ने कहा है कि २ लाख एकड़ जमीन एकदम है और कमसे कम सारे लाख में नकद लगी तो लाख कर का जा सकती है । २५ लाख एकड़ उनको कहाँ से मिल गयी ? जमींदारी उद्दीनत हमें नकद रिपोर्ट की जिल्द २ में पेज ६ पर २५ एकड़ से बड़े लाने के जिनसे लाने में १,१४,६५५ हैं जिनका क्षेत्रफल कुछ ५३,९०,५३० एकड़ है । २५ एकड़ में ज्यादा नकद का लाना कोई २६ एकड़ का हो सकता है और कोई ५१ एकड़ का । इसमें किसान में नकद जमींदार भी । लेकिन अधिकतर वे लाने ५० एकड़ में छोटे मादूम होते हैं क्योंकि अगर उन एक लाख १४ हजार आदमियों को ५०-५० एकड़ देना चाहें तो ५७ लाख एकड़ रकबा पहुँचना है, जबकि यहाँ ५३ लाख ही है । चार लाख तो लगी साहब को देना चाहिये ।

इस मिसाल में एक बात यह भी है कि जमींदारी उन्मूलन का बड़े लानों के काटने और उनकी जमीन को बांटने में कोई बस्ता नहीं है । उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । लेकिन फर्क कर लीजिये कि बांटना ही चाहें तो मैं अर्ब करूँगा कि जिन खतों को हम तोड़ेंगे, उनमें से ५० एकड़ का नकद दुकड़ा तो जमींदार के लिये अलग उसकी मरजी का निकालना होगा उसके बाद बाकरी जमन के बाँबर बराबर टैक्स के दुकड़े करने होंगे । मान लो अढ़ाई अढ़ाई एकड़ के पन्द्रह दुकड़े हो गये । लेकिन माँगने वाले हर गाँव में होंगे सौ । तो फिर किस को दिया जाय और किस को न दिया जाय ? नतीजा यह होगा कि हमारे कर्मचारी इसी काम में फँस जायेंगे और इस काम की वजह से जिनसे कोई समस्या भी हल नहीं होती जमींदारी अवालिशन का काम रुक जायेगा ।

एक वर्ग है जिसके लिये बहुत जोर दिया गया है, वह वर्ग है भूमि-हीन लोगों का । मालूम होता है कि इन लोगों के लिये सारा दर्द हमारे सोशलिस्ट भाइयों के दिल में ही केन्द्रित हो गया है और हम कांग्रेस-जन गरीब आदमियों की भावनाओं से रहित हो चुके हैं । इसके लिये मविष्य-वादी की गयी है कि खून खबूबर होगा । सोशलिस्ट पार्टी गरीब किसानों और भूमि-हीन लोगों को लेकर लड़ेगी और न मालूम क्या क्या करेगी ।

हमारे लायक दोस्त ने कहा कि श्री अल्लू राय शास्त्री ने वेदों और न मालूम कहाँ कहाँ



[श्री चरण सिंह,

का जिक्र कर डाला, जिसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अर्ज करूंगा कि फिर रूस और चीन के कम्युनिज्म का जिक्र क्यों किया गया। सोशलिस्ट पार्टी वाले वेदों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं लेकिन कम्युनिज्म का जिक्र करना जरूरी समझते हैं। हर बात में मर्क्सिज्म का नाम लिया जाता है। पहली बात तो मैं यह पूछूंगा कि क्या चीन में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दे दी गयी है? रूस में हमारे यहां से ४० प्रतिशत आबादी है, जब कि हमारे यहां से साढ़े पांच गुना रकबा है। रूस में आबादी कम है और ज़मीन ज्यादा है। और हमारे यहां आबादी ज्यादा है और ज़मीन कम है। बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है। जहां तक चीन का सवाल है वहां कम्युनिस्ट लैंडलेस लेबर को जब ज़मीन दे दें तब आप यह ताना दें। अगर हमारे यहां ज़मीन तकसीम की जाय तो ३-४ एकड़, या ४ एकड़ या साढ़े चार एकड़ ज़मीन हर एक किसान-परिवार को मिलती है और ७५ लाख परिवारों में १८-१९ लाख परिवार मजदूरों के और जोड़ दिये जाय और सबको बराबर-बराबर तकसीम कर दी जाय तो सबको काफी मिल जायगी और सब खुश हो जायंगे? इसका इलाज सोशलिस्टों के दिमाग में कुछ और है। लेकिन जिसको कहने से डरते हैं। एक समाचार में दो बार उसका जिक्र किया गया और एक आध साहब ने यहां भी उस तरफ इशारा किया। और वह है ज़बरदस्ती सहाकारी खेती। मेरे दोस्त फूल सिंह ने यह कहा था कि ज़बरदस्ती कोओपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती और सहयोग—इनमें परस्पर विरोध है। कोओपरेटिव फार्मिंग का मतलब यह है कि रज़ामन्दो से, सहयोग करके खेती की जाय। परन्तु इसके लिये तो हमारे बिल में गुंजाइश है। यही नहीं बल्कि इस किस्म के आलोचक और इस किस्म के लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने पूर्ण रज़ामन्दी के सिद्धांत को थोड़ा सा छोड़ भी दिया है। अगर दो-तिहाई छोटे काश्तकार सहाकारी फार्म बनाना चाहते हैं तो हम एक-तिहाई को मजबूर करेंगे। यह हमने इस बिल में रख दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमने साफ लिख दिया है कि हम उनको प्रोत्साहन देंगे। यानो टैक्स में कमी करेंगे और तकाबी देंगे और भी बहुत सी बातें हैं जो इस बिल में दी गई हैं। एक बात तो यह हुई।

परन्तु चाहे भूमि-हीन लोग हों या लाम-हीन जोतों वाले किसान, देखना तो यह है कि असल समस्या क्या है। वह यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले। मान लीजिये कि सौ आदमी हैं उनके पास ढाई सौ एकड़ ज़मीन है तो अगर उनकी ज़मीन को इकट्ठा कर दें तो क्या वह लोगों को ज्यादा काम दे सकेगी। हाँगी नहीं। बस बेकारी सब में बराबर बंट जायेगी। पहली बात यह है कि जहां तक ऐच्छिक आधार पर कोओपरेशन का ताल्लुक है वह तो हमने इस बिल में रख ही दिया है। लेकिन जहां तक मजबूरी का आधार है वहां मुझे यह अर्ज करना है कि किसान काम नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोग आपके मामूली कोओपरेटिव स्टोर्स नहीं चला सकते हैं। अपने देश का तज़ुर्बा है कि बी० ए० एम० ए० इकट्ठा हुए कि हम कोओपरेटिव स्टोर्स चला लेंगे। बेकार बनिये को पैसा क्यों दें। लेकिन साल भर भी नहीं चला सके। तो फिर गांव वालों से जो अपनपढ़ हैं कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह इस काम को कर लेगा। किसानों पर ज़बरदस्ती सामूहिक खेती लादने से उनका मन मारा जायगा। इसके अलावा और भी जो नुकसानात होंगे उनका मैं यहां जिक्र करना नहीं चाहता हूँ।

मैं जहां तक सहकारी खेती का सम्बन्ध है इन बातों के दृष्ट में हूं कि वह ऐच्छिक आधार पर हो। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह चाहते हैं कि पूरा कम्पल्शन (compulsion) रखा जाये और उन किसानों पर यह जबरदस्ती लाद दिया जाये। तो यह चीज नामुमकिन है। वह कभी चल नहीं सकती है। इनारे देश में भूमि होन लोगों की समस्या का एक ही इलाज है और वह यह है कि गांव गांव में बिजली ला जाये और उनके जरिये छोटे पैमाने पर नये नये उद्योग-धंधे चलाये जायें। उद्योग-धन्धों में बैम भी खेती से चौगुनी आमदनी होती है। यदि देश को मालदार बनाना है तो इसका उद्योगीकरण चाहिये। और जिनके पास आज लाभ-हीन ज़ेत हैं उनसे भी ज़मीन छुड़ाकर उनको दूसरे रोजगारों में लगाना होगा, न कि भूमि हीन और अन्य सब लोगों में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े बांट दिये जाय और सब को खेती से बांधकर देश को और गरीब बना दिया जाय।

कल मेरे एक मित्र ने कहा था कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए ही आप लैंडलेस लेबर को ज़मीन दे रहे हैं ताकि वह फैक्टरी में काम करे लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि हम तो जिन सुरतों में बड़े उद्योग अनिवार्य हैं उन सुरतों का छोड़कर बाकी सब में छोटे पैमाने के रोजगारों पर ही जोर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गांवों से हटकर लाखों और करोड़ों आदमी शहर में आवें। बल्कि हम चाहते हैं कि उन सब का वहीं गांव में रोजगार मिले। अमेरिका में केवल २० फी सदी, इंग्लैंड में ५ फी सदी और फ्रान्स में २८ फी सदी खेती में लगे हुए हैं। इन और दूसरे उन्नतशील देशों में गत ७०-८० वर्षों में खेती करने वालों की तादाद घटती चली गयी है और दूसरा रोजगार करने वालों की संख्या बढ़ती गई है। इस कारण वह देश मालदार होते चले गये हैं। यहां भी आज जहां फैक्टरियां हैं वहां कोई भी मजदूर खेतों में काम करने के मुकाबले में कारखानों में काम करना अच्छा समझता है। मेरठ जिले में मोदी फैक्टरी है और वहां मजदूर खेतों पर काम करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि शुगर फैक्टरी में उस को ५५ रुपया मिल जाता है। सब जगह मजदूर इण्डस्ट्रीयल लेबर के मुकाबले एग्रीकल्चरल लेबर को पसन्द करता है क्योंकि वहां अधिक आमदनी होती है। आज बहुत से देश ऐसे हैं कि जो अपने देश की जरूरत के मुताबिक भी गन्ना पैदा नहीं करते और कतई तौर पर उद्योग धंधों में लगे हुए हैं और वहां के राजनीतिज्ञों ने अब "ग्रेक टू लैंड" अर्थात् फिर कृषि की ओर परत दिया है और लोगों को खेती की आमदनी से टेकन हटाकर उधर रागिब किया है। लेकिन हमारे बदकिस्मत देश में उल्टा हुआ कि जितने लोग सन् १८८० में इंडस्ट्रीयल एम्प्लायमेंट में लगे हुए थे सन् ३१ में उनकी तादाद और कम रह गई बजाय इसके कि बढ़ती। सन् १९३१ की जन-गणना की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में ९.७ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में लगे हुए थे, जब कि सन् १८८० के अकाल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उस समय १२-३ प्रतिशत उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं।

रायल एग्रीकल्चर कमीशन के अनुसार खेती पर एम्प्लायमेंट सन् १८७१ में ५३ प्रतिशत और सन् १९२८ में वह बढ़कर ७१ प्रतिशत हो गयी। इस तरह से दूसरे देशों में उद्योग-धन्धे बढ़े और खेती घटी। लेकिन हमारे यहां ठीक उल्टा हुआ। लिहाजा देश इस कदर खराब और सराबतर होती चली गयी। हमारी समस्या है कि लोगों को उद्योग-धन्धों में कैसे लगाया जाय।

[श्री चरण सिंह]

परन्तु इस बिल के आलोचक देश-हित को ध्यान में न रखकर उल्टा ही मशवरा दे रहे हैं। यह भी कहा गया है कि इस बिल से पैदावार नहीं बढ़ेगी और गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी दूर करने के लिये मोटी सी बात है पैदावार बढ़ाना चाहिये और पैदावार बढ़ाने के दो स्थान हैं अर्थात् खेत व कारखाने। खेत के लिये पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है और बीज की जरूरत है। यहां तीनों चीजें इस बिल में नहीं रखी जा सकतीं यानी पानी, खाद और हाइड्रो-एलेक्ट्रिक जिससे ट्यूबवेल लगाये जाएं। जहां यह पैदावार बढ़ाने का सवाल आता है वहां हमें किसान की मनोवृत्ति को भी देखना है। किसान अपनी जमीन का मालिक होगा। दुनिया भर के आंकड़ों में पता चलेगा कि मजदूरों के और शिकमी क्राश्टिकारों के मुकाबिले में वह किसान जो अपने खेत का मालिक होता है ज्यादा मेहनत करता है। जमीन के अपनेपन की भावना हम किसान को दे रहे हैं। अपने जमीन समझ कर वह खूब मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी चीज है इंसेप्टिव। इस बिल के द्वारा हम किसान के अन्दर वह भावना पैदा कर देंगे कि जिससे वह अपने खेत में अधिक मेहनत करेगा। इससे ज्यादा हम इस बिल में और कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ज्यादा समय न लेकर अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं। बस एक दो बातों का और जिक्र करके मैं बैठ जाऊंगा। राजा जगन्नाथ बख्श सिंह साहब ने कहा कि इतने लम्बे चौड़े बिल की क्या जरूरत थी। एक छोटा सा बिल ले आया जाता जिससे क्राश्टिकारों को यह इजाजत दी जाती कि दस गुना लगान खजाने में जमींदार के नाम दाखिल कर दो और अपने खेत के मालिक हो जाओ। यह शरत करने की क्या जरूरत थी। सन् ३७ में यह आफर करते तो उसका स्वागत होता लेकिन वह वक्त निकल गया। अब बिल आने के बाद आपने बड़ी मासूमियत के साथ कह दिया कि छोटा सा बिल ले आइये, इस बिल की क्या जरूरत थी। आपके सुझाव का नतीजा यह होगा कि बड़े जमींदारों को ज्यादा मुआविजा मिल जायेगा क्योंकि ज्यादा जमीन उनके पास होगी लेकिन छोटे जमींदार जिनको मुनाफ़े का २८ गुना दिया जा रहा है वह इससे घाटे में आ जायेंगे। दूसरी हानि यह होगी कि गांव समाज को कोई जमीन नहीं मिलेगी। तीसरा जो बड़ा नुक़स है वह यह कि जो बक्क व धर्मार्थ संस्था को है उनकी आमदनी कम हो जायेगी। हम तो उनकी मौजूदा आय की गारण्टी करते हैं, राज्य की तरफ से।

मेरी तुच्छ राय में इससे बेहतर तजवीज़ जमींदारों के लिये और कोई नहीं हो सकती। यह जो हमसे कहा जाता है कि सामाजिक विद्रोह होगा, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि १९४७ के बाद अगर कोई अहिंसात्मक रेव्युल्यूशन हो रहा है तो यह है। इससे बड़ी क्रान्ति यू० पी० में हमारी जिन्दगी में नहीं हो सकती, रूस की मिसाल दी जाती है। रूस में सन् १९१६ के दिसम्बर में केवल १०.७ फीसदी किसान अपनी जमीन के मालिक थे। इसलिये वहां रेव्युल्यूशन हुआ। दूसरा कारण जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, यह था कि राजसत्ता जनता के हाथ में नहीं थी। यहां तो खूनी क्रान्ति का कोई सवाल ही नहीं है। जमींदार लोग अपने कार्यों से हिंसा को नियन्त्रण दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम उनकी रक्षा करेंगे। हम देश के अन्दर हिंसा नहीं होने देंगे। अब सोशलिस्ट भाई जो कहते हैं उस पर मैं आता हूं। मुझे ताज्जुब होता है कि इख़्तलाफ़ राय कितनी ही हो, लेकिन अगर मामूली सी इख़्तलाफ़ राय पर नियत पर हमला

[illegible]

[ श्री मुहम्मद शौकत अली खां ]

सिर्फ जमींदारी को खत्म करने का था। मैं इससे इख्तिलाफ़ करता हूँ। जमींदारी खत्म करने के साथ साथ दूसरा निज़ाम लाना भी लाज़िमी है। हम देखते हैं कि इस बिल के दो असरात हैं। एक तो यह कि जमींदार अब खत्म किये जा रहे हैं। बहरहाल जमींदार भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं इसी कौम के हिस्ते हैं। उनके अख्तियारात क्या थे, वे किस तरीके से खत्म किये गये हैं और उनके असरात मुल्क व सोसाइटी पर किस हद तक पड़ेंगे यह देखना लाज़िमी है। दूसरी बात जो देखने की है वह यह है कि गांव के किसानों की बाहरी तरक्की और मुल्क की पैदावार बढ़ाने का हमारा जो मक़सद है वह इस नये निज़ाम में कहां तक पूरा होता है। सबसे पहले जमींदारी के निज़ाम को खत्म करने में यह मसला तो बिल्कुल ख़ारिज अज़ाब है कि जमींदार किस तरह से आये क्योंकि यह मसला तो उस दफ़ा बिल्कुल तय हो चुका था। सवाल तो यह है कि जमींदार इस वक्त मौजूद हैं और मुल्क की सियासी हालत को देखते हुए हमें इस बात की ज़रूरत है कि इससे बेहतर निज़ाम जमीन के मुताल्लिक हम लायें। यह तभी हो सकता है जब कि हम इस निज़ाम को खत्म कर दें। लेकिन हमारे दोस्त चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा है कि जो निज़ाम इसके बदले में आवेगा उसका हम वक्त बतलाना मुमकिन नहीं है। आप एक इमारत को ढायेंगे तो इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि कोई दूसरी इमारत का नक्शा उसकी जगह तैयार करें। यह नक्शा जो तैयार किया गया है पूरे तरीके से उन उम्मीदों को पूरा नहीं करता। यही मेरा एतराज़ है।

मेरे खयाल में जमींदारों के साथ सबसे पहली चोज़ जो है वह यह है कि उनको मुआविज़ा दिया जा रहा है मुआविजे के लिये इस वक्त क़ानून में है कि यह ज़रूर दिया जाय। लिहाज़ा यह भी कहना कि मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय यह भी यक़ीनी है कि आप बग़ैर मुआविजा दि। ले ही नहीं सकते। लिहाज़ा मुआविजा देना तो क़ानूनन ज़रूरी है और वह मुआविज़ा मुनासिब होना चाहिये। वह मुनासिब मुआविज़ा क्या होगा इसको तय करने के लिये बहुत सी रायें हो सकती हैं। एक तरफ़ तो लोग कहते हैं कि २० गुना और २५ गुना हो, दूसरी तरफ़ तजवीज़ में ८ गुना लिखा है। मेरे खयाल में मुनासिब न तो २० गुना है न २५ गुना है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह ८ गुना भी कम है। अगर जमींदार इस पर यह शिकायत करते हैं कि ८ गुना मुआविज़ा कम दिया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं है, जैसा कि क़ानून ने हमें हक़ दिया है कि हम मुनासिब मुआविज़ा पायें तो यह कहना ठीक है। इसलिये मैं यह खयाल करता हूँ कि अगर सेलेक्ट कमेटी स्टेज में इसमें ८ गुना की जगह १० गुना कर दिया जाय तो वह बेजा न होगा और यह क़ानूनी लिहाज़ से भी ठीक होगा। क्योंकि क़ानून जो कुछ है उसका भी मतलब किसी तरह से पूरा करना ज़रूरी है।

एक सबसे बड़ा नुक़स जो हम देखते हैं वह यह है कि उस वक्त भी यह वादा किया गया था और बार बार यह कहा गया है कि कर्ज़ का सवाल जो जमींदारी के साथ इस तरह बंधा हुआ है कि उसके लिये यह कह देना कि हम इसके लिये एक नया क़ानून लायेंगे यह किसी तरह तशफ़्फ़ीबख़्श नहीं है। जहां यह क़ानून बना था वहां कर्ज़ के मुताल्लिक भी क़ानून बनना ज़रूरी था ताकि जमींदार के सामने एक सही तस्वीर आ जाय और उसको यह यह अहसास हो जाय कि इतना मुझे मुआविज़ा मिलेगा और इतना कर्ज़ है वह कम हो जायेगा, लिहाज़ा मुझे इतना

मिलेगा। ऐसे करने में आने इस चीज को उठ दिया है कि यह नहीं कहा जा सकता कि बाद में उसे आप पूरा करेंगे या नहीं या कब करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि यह सबसे बड़ी कमी इस बिल में है जो गवर्नमेंट ने कर रखा है। और यह इन्फिनिट कर रखी है कि आइन्दा के लिए इस चीज को किन्तुल अपन हाथ में रखा जाय और पैसा मौल तो उसके मुत थिक काम किया जाय। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर गौर करेगी और बन्द में जन्द कोई मस्विदा कर्जे के मुनालिक लायेगा क्योंकि वह भी ऐसा ही जरूरी है जैसा कि यह मस्विदा खुद।

दूसरा जो सबसे बड़ा नुक्स है वह यह है कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने भी बड़े बड़े कानून बना कर मुकदमेबाजी का दरवाजा खोल दिया था और रिश्तसतानी का बाजार गर्म कर दिया था। लेकिन जब हमें आजादी मिल गई और मुल्क अजाद हो गया तो न मुकदमेबाजी कम हुई और न रिश्तसतानी कम हुई है। मेरे दोस्त इनने इन्कार न करेंगे कि इस भवन में एक मर्तबा हमारे लायक बज्जोर आज़म साहब ने लड़े होकर कहा कि ७० फीसदी रिश्तसतानी कम हो गई है। मैं तो यह कहना हूँ कि अगर इसका शुनार किया जाय तो मैं यह कहूँगा कि रिश्त ७० फीसदी नहीं बल्कि १०० फीसदी बढ़ गई है। यह एक ज़रिया और रिश्तसतानी का होगा। हमें यह मालूम है कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टेक्म लगाया गया तो उसमें क्या हो रहा है। हमें यह भी मालूम है कि प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है। यह बात तो आप को और साफ रखना चाहिये थी कि जो मुआवजा आप देंगे वह मुआवजा मिलनेवाले को अगर रिश्त के और बगैर किसी दिक्कत के मिल जायेगा ताकि यह न हो कि ५ फीसदी उसके पास रिश्त में जा रहा है और दस फीसदी उसके पास रिश्त में जा रहा है। इसने होगा यह कि जो अपने मोरेल को नीचा कर लेगा और रिश्त देगा वह तो फायदा उठा लेगा लेकिन जो रिश्त नहीं देगा वह किसी घर का नहीं रहेगा। इससे मुकदमेबाजी इतनी लम्बी होगी कि शायद वर्षों मुकदमेबाजियां खत्म नहीं होंगी। जब मुकदमेबाजी का यह आलम है कि मामूली माल के मुकदमे में एक एक साल की मुदत की तारीख पड़ती है तो पता नहीं को लोगों को मामला तै कराने में किन्ने दिन लगे। अगर कहीं यह कर दिया गया कि जो कम्प्लेन्टेशन की लिस्ट तैयार होगी वह सन् ५९ में मुकम्मल होगी तो तातो बमन मीरखी मन बखुदा मीरसम, '( जब तक तुम मुझ तक पहुंचोगे मैं अल्ला मियां के यहां पहुंच जाऊंगा ), इस दरमियान में आपकी दफा ६ नाफिज हो ही जायेगी। ऐसी हालत में फिर जमींदार क्या करेगा, उसे आपन प्रोवाइड किया है कि कुछ इन्टीम सन्सीडी मिल सकती है यानी इस दरमियान में जमींदार पहले दरख्वास्त दें, कुछ रिश्त दे और किनी कांग्रेसी नेता की सिफारिश लये तब जाकर उसका काम बनेगा। इस तरह से जो क्लर्क हो उसको भी वह कुछ दे तब कहीं १ महीने में उसको कुछ मिलेगा। यह तो एक अजीब मजाक है। आप फरमाने हैं कि हमें जमींदारों खत्म करना जरूरी है। वैसे तो जमींदारी ८ अगस्त सन् १९४६ को ही खत्म हो चुकी है, सवाल यह है कि जमींदारी खत्म करने में आप जमींदारों को परेश न या मरुदस क्यों कर रहे हैं। इस की जगह कोई निजाम सही ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। छोटे २ जमींदारों के बारे में मैं कहता हूँ, कि बड़े २ जमींदारों के मुन्दी और कारिन्दे तो जाकर रिश्तें भी दे सकते हैं और मुकदमाबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे जमींदार हैं जिनका आपके दिल में इस कदर दर्द है वह क्या करेंगे। जिस की पांच रुपया, दस रुपया की मालगुजारी होगी उसको अगर मुकदमाबाजी

[ श्री मुहम्मद शोकत अली खां ]

करना पड़ा तो उसको जो मुआविजा मिलेगा वह उसी में खत्म हो जायगा। उसको उम्मीद तो होगी कि कुछ मिलेगा। लेकिन जब वह अपना बन्दी खाता देखेगा तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इस चीज को जितना आप आसान कर सकते हैं उतना आसान कीजिये। जितनी दिक्कतें आप कम कर सकते हैं आप कम कीजिये। अच्छी सोसाइटी की सबसे बड़ी जो गैरान दलील होती है वह यह है कि इन्सान दुश्चारियों को मिटाता है और आसानियों को पैदा करता है। लेकिन आप तो आसानियों को मिटा रहे हैं और दुश्चारियों को पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यह एक बड़ा नुकस और एक बड़ी खामी इस बिजु में है जिसका दूर होना लाजिमी और जरूरी है बरना मैं कहूंगा कि इसके यह माने हैं कि अपने क्लर्कों, अम्मालों और वकीलों के लिये एक बड़ी खुराक का सामान आप वहम पहुंचा रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं इसके मुताल्लिक यह कहूंगा और यह अर्ज करना जरूरी है कि जिस सूरत से यह पेश किया गया है इस तरह से सेलेक्ट कमेटी स्टेज में इसके कम्पेन्सेशन के तरीके में तबदीली की जरूरत है और इसके तरीके को सादा और मुस्तसिर किया जाय। यह ऐसा कानून है जिसमें ३१० दफात हैं। मेरे ख्याल में सरकार ने पिछले कानून जो पास किये हैं जैसे टेनेन्सी ऐक्ट पिछली असेम्बली में आया था। मुन्शी की तारीफ पढ़े लिखे यह किया करते हैं (मुमकिन है कि चौधरी चरण सिंह साहब को मालूम हो चुंकि वह मकतब में पढ़े हैं) कि जो थोड़े अल्फाज में ज्यादा मतलब अदा कर दे, वह मुंशी है। इस कानून की दफात को हिफज करना मेरी जैसी उम्र के आदमी के लिये नापुमकिन है। दूसरी बात यह अर्ज करनी थी कि सरकार ने यह वादा किया था कि ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स इसमें मुजरा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी असलियत है। मैंने सुना है चौधरी चरण सिंह साहब ने अभी फरमाया था कि कास्तकारों के पास रुपया है, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है। अगर मैं सही सुन सकता हूं तो उन्होंने कहा यह था कि मिडिल क्लास के पास बचत नहीं है। मुझे उम्मीद है अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वह तशरीह कर देंगे। मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास जमींदार पर होता है। यह बात मैं साबित करूंगा। जो २५ रुपये का मालगुजार है जाहिर है कि उसका जरिएमाश सिर्फ जमींदारी नहीं हो सकता इसलिये कि २५ रुपये मालगुजारी देने के यह माने हैं कि उसका मुनाफा जमींदारी से ज्यादा से ज्यादा ३० रुपया हो सकता है। ३० रुपये सालाना के हिसाब से २½ रुपया होता है। दुनिया का कोई भी अक्ल और अक्लमन्द इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा कि कोई इन्सान ढाई रुपया महीने पर रह सकता है। वह कुछ और काम भी जरूर करता है। और तभी वह अपनी गुजर कर सकता है। उसको २० गुना मुआविजा दिया जा रहा है। जरूर दिया जाय। खुदा आप के हाथ को बसी करे। इससे भी ज्यादा दीजिये अगर इस बिना पर दिया जाय कि वह गरीब है। लेकिन चूंकि वह उजड़ गया इसलिये बहाली का मुस्तहिक है यह बिल्कुल गलत है। हरगिज नहीं उजड़ा। अगर मेरी आमदनी का चार या पांच फी सदी हिस्सा कम हो जाता है तो मैं उजड़ता नहीं। मैं उस वक्त उजड़ता हूं जब मेरी आमदनी का बेशतर हिस्सा ले लिया जाय। बेशक मैं उजड़ता हूं। जब उजड़ता नहीं तो किसी बहाली की मदद का मुस्तहिक नहीं हूं। मेरी यह दलील २५ रुपये से कम मालगुजारी देने वालों पर लागू होती है और उनकी तादाद

१०. राजा के उद्योग से सब १ करोड़ से ज़्यादा धन प्राप्त हुआ है। यह सब धन उसकी कृपा से ही प्राप्त हो १० करोड़ से ज़्यादा धन प्राप्त हुआ है। इससे सब १ करोड़ से ज़्यादा धन प्राप्त हुआ है।

अगर किसी का सम्मान उस तरह करने के लिये मेरा बदमाश ब्रह्मा नहीं और उसका दो हजार रुपये की जमींदारी की आमदनी का न हो तो उसे बदले में कोई हक हमिश नहीं है। इसलिये कि इसीमान करने दो हजार के मुन्ने के कम हो जाने की वजह से वह उजड़ नहीं जाता। दो लाख के मुन्ने वाले कम्बनेदार को बदली देने की क्या जरूरत है? बदली की नियत तो यह होती चाहिये थी और बदली मिलनी उसी को देनी चाहिये थी जिसकी मदद से जिन्दगी में जमींदारी की आमदनी के कम हो रहे, और जो किसी दूसरी चीज से अपनी आमदनी को पूरा नहीं कर सका था। यह कह देना बहुत आसान है कि कोई बर्बाद और उसकी आमदनी साल में १० हजार की है और वह एक हजार का मालगुजार भी है तो उसको भी रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की जरूरत है। मशरूफाजी तो इन्साफन हर शख्स को देना जरूरी है और राजनीति है। इनमें कोई शक नहीं कि मुशरूफाजी देना चाहिये लेकिन जहाँ तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की जरूरत है, अगर यह बात सच है कि अपने लोगों को बदलने के लिये उनका नाम रिहैबिलिटेशन ग्रांट रखा है तो कोई सम्मति नहीं होगी। हमने हमारा मतलब कुछ और ही है। हो सकता है कि कठिनाई मिस्टेज की वजह से इनको बदली में रव दिया गया है तो मेरे ख्याल में बदली की ग्रांट के लिये इस चीज को जानने की जगह जरूरत थी कि वह गलत किस हद तक अपनी आमदनी में हमेशा के लिए महलूम कर दिया गया है और वह किस हद तक उजड़ गया है। अपनी यह बहाली ग्रांट तो सर पद्मन सिंहानिया को भी मिलेगी और जो जमींदार २५ या ५० रुपये का मालगुजार होगा उसको भी मिलेगी। इन्साफ की बात तो यह थी कि जो शख्स महज जमींदारी की आमदनी पर ही अपनी माश क इनहिमार रखना था और उसकी आमदनी आप ले रहे हैं तो उसको बदली देने की जरूरत थी। दूसरी बात मैं वह कहूंगा कि यह अजीब हिमाव दानी है। मैं कुछ हिमाव का माहिर तो नहीं हूँ लेकिन चौधरी चरण सिंह जरूर उनके नाहिर हैं। यह अजीब हिमाव है कि जो २५ रुपये का मालगुजार है उसको तो २० गुना बदली मिले। मैं थोड़ी देर के लिये फर्ज कर लूँ कि एक २५ रुपये का मालगुजार है और उसको अगर अववाव प्रोग्राम काट कर ज़िम्मे २५ रुपये बचना है तो उसको रिहैबिलिटेशन ग्रांट ५०० मिलेगा यानी बीस गुना और अगर एक आदमी २६ रुपये की आमदनी वाला है तो उसे ४४२ रुपये मिलेगा यानी १७ गुना।

श्री चाला हि—५०० रुपये से कम किसी क' नहीं मिलेगा ।

श्री मुहम्मद शोकत अली खाँ—आपने एग्रीकलचर इन्कम टैक्स में एक टप्पा रखी है, शायद इस वक्त अब समझा गया हो कि यह गलत लिखा गया था तो उसको ठीक कर दिया गया हो। इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी हाथ में भिड़ले से कम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि उस स्टेज पर आप इसमें सही फर्मायगे। जिस वक्त चौवरी चरण सिंह लगान बगैरह का पीगर्स दे रहे थे तो इन पत्रों के लगने की वजह से ठीक से मैं उनको मुन व समझ नहीं सका। यहां से अच्छा तो लावी में ही सुनाई देता है। जो पीगर्स उन्होंने दिया उनको मैं ठीक से समझ नहीं सका हूँ लेकिन अपने आप जो पीगर्स मैंने इकट्ठे किये हैं उनको बिना पर मैं कहता हूँ कि



[ श्री मुहम्मद शौकत अली खां ]

इस वक्त १७ करोड़ के करीब लगान का तयार दे रहे हैं। तो अगर आपके खवाब का तयार पूरी होती है, जिसके मुताबिक में आगे अत्रे कहेंगे तो इसका मानें यह दुना कि इस गुन, के हिमाब से १७० करोड़ रुपया गवर्नमेन्ट के खजाने में आ सकता है। आपने मुआविजे का अन्दाजा किया है कि वह १४० करोड़ है। तो इसके माने यह है, मैं चौधरी चरण सिंह साहब से नहीं कह सकता क्योंकि वह भी एग्जीक्यूटिव मेरी ही तरह से हैं लेकिन अगर कोई और साहब होते तो मैं कहता कि थोड़ी डण्डी जरूर मारी है। यह तीस करोड़ दुनाफे निकाला है। पानी आपने जमीन की भी गन्तम कर दिया और काश्तकारों से भी वाइपाही ले ली और खजाने आमरा में भी ३० करोड़ आ गया। कांग्रेस को यह जीत रही, बड़ी मुबारक है अगर यह हिसाब सही है। आपने हर तरह फायदा ही फायदा किया। दूसरा खगल यह है कि १७ करोड़ में से भी जो मालगुजारी के खेत हा जायगे उनमें साढ़े अठ करोड़ आमदनी होगी। लेकिन इन साढ़े आठ करोड़ में से साढ़े ६ करोड़ आपने पेश किया है तो इसके माने यह है कि आपने मालगुजारी को आमदनी में भी एक या दो करोड़ अलग कर दिया।

श्री चरण सिंह—एक करोड़ अवबाब का भी इसमें शामिल है।

श्री मुहम्मद शौकत अली खां—मैं अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं तो डण्डी मारी में माहिर नहीं हूँ मेरी समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। मैं तो सीधा सादा किसान हूँ। यह जानता हूँ कि जमीन को किस तरह से जोतना चाहिए और किस तरह से उसकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिये। अब हमें यह देखना है कि यह बिल काश्तकारों के लिए किस हद तक मुसफ़ीद हो सकता है। दो फायदे हैं : एक तो एकतमादी और दूसरा सेन्समेण्टल पानी जजबानी। तो किसानों का जजबती फायदा हो गया कि जमींदारी खत्म हो गई हालांकि मुझे इसमें भी ताम्मुल है क्योंकि मैं गावों के रहने वाले काश्तकारों से नावस्ता हूँ, किसानों से मिठता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जो जमींदारी के खान्ने से जोश आया हो तो हो लेकिन जो जज्बा काश्तकारों के दिलों में था उसका २० फीसदी भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जमींदारी खत्म नहीं कर रहे हैं। उसके लिये हम कमिटेड हैं लेकिन हाँ क्या रदा है। मैं उसके लिये क्या कहूँ ? जब यह बिल जिसके लिए सन् १९३७ से लेकर यह कहा जा रहा था कि एक जमाना आयागा जब ऐसा बिल आयागा तो इन्कलाब ऐसा होगा जो दुनिया भर में कभी भी न हुआ हो, लायक वजीर साहब, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त इस बिल पर तकरीर करने खड़े हुये तो शायद किसी तरफ़ से भी ब्लैपिंग नहीं हुई। यह मालूम होता था कि शहरे खमोशा के मकी हैं। मालूम होता था कि यह मारे बाघे बजार लगाई जा रहा है। गैररोज भी अगर देखी जाती तो वह भी खाली थी। मामूली मामले होते हैं तो लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और १० हजार किसानों के गिरोह आ जाते हैं। यहां इस इतने अहम बिज पर कम से कम दो लाख आदमियों का मजना होना चाहिए था। (एक आवाज) करीब २० आदमी गैलरीज में रहे होंगे। क्या वजह है, कभी आपने इसकी तरफ़ गौर किया। इसकी वजह साफ़ और बेयअन है। मैं किसी तलखी के लिये नहीं कह रहा हूँ या किसी ताने के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह बात सही है कि अब आपके बादों में



[ श्री मुहम्मद शौकत अली खां ]

अगर आप यह कहें कि बोझ हल्का है तो आपका मुआविजा मांगना सख्त गलत है। कौन सी वजह है कि सूबे के खजाने में १७ करोड़ क्यों न जायं, ८ करोड़ क्यों जायं ? तो मैं बहसियत एक जिम्मेदार एम. एल. ए. के यह पूछूंगा कि यह आमदनी साढ़े आठ करोड़ की क्यों कम किये देते हैं ? और अगर आपको रुपये की जरूरत है तो कर्जा फ्लोट कर लें। ऐण्टी इन्फ्लेशन वाली बहस में तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूर है कि यह १० गुना मुआविजा वसूल करने की है किसी शातिर की तजवीज़ ! और यह यकीनी बात है कि अगर यह चुपके से, खामोशी से पूछा जाय तो चौपरी साहब भी बतला देंगे कि यह नज़राना लेने का हथकण्डा उन्होंने किसी ज़मींदार ही से सीखा है। गवर्नमेंट आज नज़राना ले रही है। ज़मींदार तो नज़राना लेकर हमेशा के लिये दस्त बरदार हो जाता है। नवाब साहब ने नज़राना लिया, फिर नवाब साहब का कोई सरोकार न रहा लगान लेने के सिवा। लेकिन आप ४० बरस के बाद बढ़ा देंगे। नवाब साहब बढ़ाएंगे तो बर्मजुरी गवर्नमेंट के, जो रेट होगा वही लिया जायगा, लेकिन आप खुद ही हाकिम होंगे, खुद ही वकील होंगे, खुद ही जज होंगे और खुद ही मुहासिल लगान होंगे। जो बी चाहे कीजिये। जब अगला इलेक्शन आवेगा तो फिर कोई नया स्टंट सोचेंगे और वोट लेने के लिये नये तरीके अख्तियार किये जायंगे। तो अगर तरकीब के लिहाज़ से देखा जाय तो मैं फड़क गया, बहुत अच्छी सूझ है ! लेकिन जैसा कि हमें मामलेदारी रखनी चाहिये, उसके एतबार से देखा जाय तो यह कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मालूम होती। इसलिये कि अगर आप यह कहेंगे कि साहब यह काश्तकार के लिये मुफ़ीद है तो उसको ऊंच नीच समझाने वाले भी बहुत से पैदा हो गये हैं जिनका भूत हमारे दोस्त त्रिपाठी जी को सताता रहता है। वह भी समझाएंगे और मैं भी समझाऊंगा कि अपने पास ही रखो। अब तो हम और वह एक से ही हो गये।

दूसरी बात यह कि हम यह सुनते चले आ रहे हैं कि यह स्लोगन है, यह वाक्या है। हम पर भी वह ज़माना गुजरा है कि हम भी स्लोगन से बहुत मरऊब हुए हैं और कभी दिमागी इन्विजिलिब्रियम भी खो दिया करते थे। हमें भी कांग्रेस की बातें अच्छी मालूम हुआ करती थीं जब तक कि कांग्रेस को अन्दर से नहीं देखा था, औरों की भी अच्छी मालूम होती थीं। तो कहा तो जाता था कि मियार ऊंचा होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी लेकिन हकीकतन तो आपने क्लासिज़ रखीं जो पहले थीं, कोई नई बात किसी तरीके से नहीं की। हां यह अख्तियार जरूर दिया है कि अगर वह खुद चाहे तो एक क्लास से दूसरे क्लास में आ सकता है। मेरा ख़तरा तो यह था कि एक क्लास होती टेनेन्ट्स की, एक लगान होता। एक अजीब इत्तिफाक है कि फर्ज कर लीजिये कि कोई दखीलकार काश्तकार आपके इस कानून के निफाज़ के बाद उसका लगान तो मैं अपने यहां की शरह से कह रहा हूँ--४ रुपया पक्का बीघा होगा और जो मौरूसी काश्तकार उसी किस्म की जमीन का, उसी जगह के बराबर, मेंड से मेंड मिले हुए वह ७ रुपया लगान अदा करेगा। तो इसके मानी यह हैं कि उनमें भी तफरीक रही। और अगर इत्तिफाक से उनके पास रुपया भी हुआ और उन्होंने बग़ैर अपना हिसाब लगाये, महज़ जज़्बात के अंदर आकर आपको १० गुना भी दे दिया तो उस १० गुना देने के बाद उसको तो साढ़े तीन रुपया रहेगा और जो पछला दखीलकार है उसका २ रुपया रह जायगा।

तो ज्योदा फर्क तो तब भी होगा। हमकी कोई दलील आप पेश कर सकते हैं कि बिन्दु एक सां खेत है, एक मां हाथान हैं, सारी चीजें एक सां हैं, नगर एक शब्द दो रुपया लगान देता है और दूसरा शब्द माढ़े तीन रुपया देता है। क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि लगान एकसां हो? मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट कमेटी इसके ऊपर गार करेगी।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह बय करने का अख्तियार भी देते हैं और पाबंदियां भी लगाते हैं। तीस एकड़ से ज्यादा कोई न ले सके। हमारे पास पचास एकड़ जमीन है। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि मैं खेती न करूंगा। मेरे हाथ पैरों में दम नहीं रह है। मैं तो घर बैठ कर खाऊंगा। और अपनी जमीन को फरोख्त कर डानूंगा। भूमिधर अपनी जमीन को फरोख्त कर सकता है। लेकिन खुदा के वास्ते बतचाइये तो सही कि मैं आप से कहता हूं कि मेरी पचास एकड़ जमीन ले लीजिये। आप कहते हैं कि हमारे पास पचीस एकड़ मौजूद ही है पांच ही एकड़ मैं ले सकता हूं। पांच एकड़ आपको दिया और फिर तय्यार कर रहे हैं कि तीस एकड़ से कम का काइतकार कौन है। उससे कहा कि बाबा तुम ले लो। वह कहता है कि बीस एकड़ मेरे पास है दस ही एकड़ ले सकता हूं। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स तो आज तक नहीं हुआ। यह कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स होगा या डिस्पंटीग्रेशन आफ होल्डिंग्स होगा? आप दस गुना लेकर उसको भूमिधर तो बना देते हैं और कहते हैं तुम जमान के मालिक हो गये हो और अगर चाहो तो फरोख्त कर सकते हो। उसने भी कहा कि बाह बाह कैसी अच्छी गवर्नमेंट है जो ऐसा अख्तियार दे दिया। बहुत से हमारे दोस्त कानून पेशा हैं। उनके पास गया और कहा कि वकील साहब मैं बय कराना चाहता हूं। उन्होंने अपनी फीस चार्ज की और कहा कि शर्त यह है कि जिसके पास तीस एकड़ से ज्यादा न हो उसी के हाथ बेच सकते हो। दो तीन चार एकड़ बेचेगा। उसकी कीमत कैसे आयेगी? आपने उससे दस गुना ले लिया और कह दिया कि तुम मालिक हो लेकिन उसकी वैसी ही हालत हुई जैसी कि हमारे यहां एक मसल है घर बार का मालिक तो है, लेकिन कोठी कोठालियां में हाथ मत लगाइयो। भूमिधर जमीन का मालिक तो है लेकिन बेच उसी के हाथ सकता है जिसके पास तीस एकड़ से कम हो। फिर उसकी मर्जी पर है। उस गिरोह में सिर्फ वही एक ऐसा आदमी है जिसके पास तीस एकड़ से कम जमीन है। इसलिये वह कहेगा कि मैं पांच रुपये देता हूं। आप यह पाबन्दी क्यों लगाते हैं, और वह उस जमीन का मालिक है? आप कह सकते हैं कि ज्यादातर तीस एकड़ से कम ही हैं। लेकिन जहां के मैं और चौधरी चरण सिंह रहने वाले हैं वही सिर्फ यू० पी० नहीं है। चौधरी साहब ठीक कहते हैं, यह तो मेरठ के रहने वाले हैं, यह तो जमींदारी की जमींदारी खरीद सकते हैं अगर काइतकार हों। लेकिन दूसरी जगह ऐसी हैं जहां यह दिक्कतें पेश आएंगी। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पचास एकड़ की एक कम्पैक्ट होल्डिंग है। फर्ज कीजिये कि मिल भी गया खरीदार तो वह टुकड़े टुकड़े होगी या नहीं। मैं उस जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस जिम्मेदारी से एक इन्सान अपने पेशे के मुताल्लिक कह सकता है जैसे डाक्टर किसी मर्ज के मुताल्लिक कह सकता है और वकील कानून के मुताल्लिक कहता है, उसी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि कम पैदावार के जो वजूहात हैं उनमें एक बड़ी वजह यह है कि खेत मुतफर्रिक हैं। चरण सिंह साहब ने कहा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जबरदस्ती लाई नहीं जा सकती।

[श्री मुहम्मद शौकत अन्दी खां]

जबर्दस्ती और लाजिमी किया नहीं जा सकता और रज़ामन्दी से होता नहीं है फिर तो मायूस इलाज है। फिर जनाब बाग़, गोर फरमायें कि जब इलाज कुछ है ही नहीं तो नुस्खा लिखन-वेकार है। फिर साफ कहे कि को आनरेटिव फार्मिंग कभी आयेगी ही नहीं और वाक कहे कि शेल्डिंग्स जिनकी नुंताशिर हो सकेगी की जायगी। मेरा खयाल है कि सेलेक्ट कमेटी में आप इसको तरजीम कर दें कि यह पावन्दी एक हद तक हटा दी जाय। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसी हालत में मुल्क में बड़े २ काश्तकार हों। हाज़ाकि अभी यह चीज़ बइस तलब है कि आया बड़े काश्तकार पैदावार के लिये बेहतर हैं या छोटे काश्तकार। मैं भी समझता हूँ कि जब तक हमारे यहां इण्डस्ट्रीज़ नहीं खुलेंगी तब तक बड़े काश्तकार हमारे लिये ठीक नहीं है। लेकिन एक हद तो सुर्करर की जायगी। अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मशविदा लें तो वह आपको बतलायेगा कि इस हद तक खेती इस रकबे में की जाती है तो भी एकड़ इतनी पैदावार ज्यादा आती है अगर इसमें इतना बढ़ा दिया जाय तो इतनी पैदावार कम हो जायगी। आगे जाकर आपको मालूम होगा कि एक दरम्यानी चीज़ ऐसी आती है जब कि दोनो का तबाजुन हो जाता है और वह फायदेमन्द हो जाता है। आर फिक्स कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही यह पावन्दी लगाना कि बेच नहीं सकते ज्यादाती है।

एक बड़ा बहस तलब मसला यह है कि आजकल लोगों का खयाल है कि किसान के पास आजकल बहुत दोलत है। शुरू में यह स्लोगन पूंजीपतियों से निकला। आप रेलों में जाइये वहां आप सुनेंगे कि किसान सोने के बिस्तर पर लेटता है और चांदी की जमीन पर सोता है। मैं उन किसानों में से हूँ जो कमाते खूब हैं और खर्च भी खूब करते हैं लेकिन जमा कुछ नहीं कर पाते। जिनके रकबे फैक्ट्री एरिया से लगे हुये हैं वर किसान बेशक माछदार है। जिनके रकबे फैक्ट्री एरिया में नहीं है वह मालदार नहीं है। यह हमारी हुकूमत की होशियारी है कि फैक्ट्री एरिया में दो रुपये मन गन्ना था ' हम लोग भी कहा करते थे कि हमारे पास अनादीन का चिराग होता तो हम लोग भी अपने जमीन वहाँ उठा ले जाते। बैसे आमतौर से काश्तकारों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह जमींदारी के हुकूम हासिल कर सके। अगर देते हैं तो उसी तरह से कि जिन्होंने इस तरह से कमाया है कि न खाने को अब और न तन ढकने को कपड़ा और मुश्किल से गुजर की है। अगर मैं गवत कह रहा हूँ तो आप इसकी तरदीद कर दें और वह मोटे से मोटा अनाज जो जिन्दगी के लिए काफी हो सकता है वही खाता है। ऐसा सुतबर्क पैसा आप जमींदारी में लगा रहे हैं मेरे खयाल में यह जायज़ नहीं है और इस पैते को देखते हुए उसकी आत्मा कितनी दुखेगी। मेरे दोस्त फरमा रहे हैं कि वह हजम नहीं होगा लेकिन मेरा खयाल है कि हुकूमत में अच्छा बुरा सभी कुछ हजम करने की ताकत है लेकिन आप उसे बड़ी अहति-यात से लीजिये। चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा कि मकानों की क्या जरूरत किसानों को है। वह कोठी में नहीं रह सकते और मैं और आप ही दशहरी के आम खा सकते हैं। उसने ऐसी चीजें देखी भी नहीं है और वह तो एक साधू की सी जिन्दगी बसर कर रहा है। अगर आपको इनफ्लेशन दूर करना है तो एक तरफ तो आप उसको सीमेंट, लोहा और ईंट मोहैया कीजिये और उस बतलाते जाइये कि रणायश का तरीका यह है और उसे बतलाइये कि खाने का और रहने का और पैदावार करने का यह तरीका है। अब तो सिर्फ यह है कि सरकार को कहीं से पता चल गय



[श्री मुहम्मद शौकत अली खां]

मसला है। मैंने काफ़ी वक्त ले लिया हालांकि मेरा ऐसा इरादा कदापि नहीं था। मैं इस तज़वीज़ की तार्ज़ुद करता हूँ कि बिज़ सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इन अल्फाज़ के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

श्री: होशीज़ाज़ अम्रयाज़—उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने जो बिज़ उपस्थित है उसके लिये मैं अपनी कांग्रेस सरकार और खास तौर से माननीय प्रधान सचिव को बधाई देता हूँ। यह बिज़ एक ऐसा बिल है जो देहात की, जिस तरह से हमारे मुल्क में जब आज़ादी आई उसने सारे मुल्क की काया पलट दी, एकदम से काया पलट देगा। आज तमाम किसान प्रसन्न हैं। जो किसान आये दिन इस बात की शिकायत करता है कि ज़मींदार हमें तालाब से मिट्टी नहीं लेने देता, लगान लेता है तो रसीद नहीं देता आये दिन इस बात की शिकायत होती है कि ज़मींदार हमारे खेत जबरदस्ती बेदखल कर लेता है और दरख्तों को काटा जाता है और अगर मकान इज़ाज़त लेकर बना लिया, रुपया देकर बनाया है, नज़राना देकर बनाया है तब भी ज़मींदार दावा कर देता है और बेचारे पर अदालत से डिग्री हो जाती है और उसका मकान ढा दिया जाता है। यह शिकायतें प्रस्तुत कानून के बनने पर खत्म हो जायंगी।

हाउस के सामने जो बिल पेश है, उसके लागू होने के बाद किसान अपनी सच्ची आज़ादी अनुभव करेंगे और उनकी आज तक जो बहुत सी दिक्कतें थीं वे सब दूर हो जायंगी। मैं कहता हूँ कि इसके बिना देहात में कोई किसान अपने को आज़ाद नहीं समझ सकता था। यह एक ऐसा बिल है जिसके बिना देहातों में राम राज्य नहीं आ सकता। इस असम्बली में पहले भी दो बातें ऐसी हो चुकी हैं, जिनसे कि राम राज्य की स्थापना हम देख सके हैं। एक बात तो हरिजनों के साथ जो बुरे कानून थे उनको बदल कर उनकी दिक्कतों को हटा देना और दूसरी बात है पंचायत ऐक्ट का पास करना। यह बिज़ भी इसी तरह का होगा। इन तीनों बिलों के बिना देहातों में राम राज्य नहीं आ सकता था।

पांच दिन से इस बिल पर जो बहस हो रही है उसमें तरह-तरह की बहस हुई है। मेरा ख्याल यह है कि बहुत सी बहम प्रोपेगण्डा और गलतफहमी के आधार पर हुई है। गलतफहमी यह है कि बिल के मकसद को ही समझने में लोगों ने गलती की है। मेरे ख्याल से बिल का पहला मकसद यह है कि ज़मींदारी खत्म हो और जो भूमि व्यवस्था की बात है वह तो बाद में आती है। इस भूमि व्यवस्था में अगर कोई दिक्कत रह जाय तो यह बाद में दूर की जा सकती है। यह ख्याल कि यह अंतिम भूमि व्यवस्था है, गलत है और इस विचार से भी बहुत सी मुखालिफ़त बिल की की गई है। हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी में इस भूमि व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातों पर विचार हो और यह शिकायत न रहे, जो इस समय हम कह रहे हैं। मैं देखता हूँ कि हमारी बहुत सी अनएकनामिक होल्डिंग्स हैं, जिन्हें एकनामिक बनाना है। मैं कहता हूँ कि इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें रखी गई हैं जिनसे कि अनएकनामिक होल्डिंग्स खत्म हो जायंगी और एक दिन वह आयेगा, जब हमारे खेतों में कोई अनएकनामिक होल्डिंग न रहेगी।

डिप्टी स्पीकर—अब आप अपनी तकरीर कल जारी रखियेगा।

**माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)**—कल भी मैं दरखास्त करूँगा कि अगर आप मुनासिब समझे, और हाउस मुनासिब समझे तो सवालान न हों, ताकि बहस के लिये जय दा वक्त मिल सके। दूसरी मेरी यह भी दरखास्त है कि कल हर हालत में चार बजे तक बहस समाप्त हो जाय ताकि मुझे योल्ने का मौका, आपकी इजाजत से मिल सके।

**डिप्टी स्पीकर**—इस वक्त तो यही दरिपास्त करना है कि कल के लिये सवाल रखे जाय या न रखे जाय।

( भवन की अनुमति से तय हुआ कि कल के लिये सवाल न रखे जाय )

**माननीय प्रधान सचिव**—४ बजे बहस समाप्त करने वाली बात भवन की इच्छा के लिये मैंने बता दी और भवन भी राजामन्द मान्दम होता है।

**डिप्टी स्पीकर**—यह ठीक है।

(इसके बाद भवन ५ बज कर १६ मिनट पर बुधवार १३ जुलाई १९४९, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ

मंगलवार, १२ जुलाई, सन् १९४९ ई०

कैलासचन्द्र भटनागर,

मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,

संयुक्त प्रान्त।





# संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बुधवार. १३ जुलाई, सन् १९४६ ई०

असेम्बली की बैठक: असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई।

स्पीकर—माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

१३-७-४६ १३-७-४६

## उपस्थित सदस्यों की सूची ( १८६ )

अजित प्रताप सिंह	कृष्णचन्द्र गुप्त
अदील अन्वारी	केशव गुप्त
अब्दुल्लाह अन्सारी	केशवदेव मालवीय, माननीय श्री
अब्दुल बाकी	खुशवक्त राय
अब्दुल मजीद	खुशीराम
अब्दुल मजीद ख्वाजा	खूब सिंह
अब्दुल वाजिद, श्रीमती	गंगाधर प्रसाद
अब्दुल हमीद	गणपति सहाय
अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स	गणेश कृष्ण जैतली
अम्मार अहमद खाँ	गिरधारीलाल, माननीय श्री
अल्फ्रेड धर्मदास	गोपाल नारायण सक्सेना
अल गुराय शास्त्री	गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
असगर अली खाँ	गोविन्द सहाय
अक्षयवर सिंह	गंगाधर
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	गंगाप्रसाद
इन्द्रदेव त्रिपाठी	गंगा सहाय चौबे
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	चतुर्भुज शर्मा
एजाज रसूल	चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
करीमुर्रजा खाँ	चन्द्रभानु शरण सिंह
कालीचरण टण्डन	चरणसिंह
कुंजबिहारीलाल शिवानी	चेतराम
कुशलानन्द गौरोला	छेदालाल गुप्त
कृपाशंकर	जगन्नाथ दास
कृष्णचन्द्र	जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल

जगन्नाथ सिंह  
 जगन्नाथ बख्श सिंह  
 जगन प्रसाद रावत  
 जगमोहन सिंह नेगी  
 जवाहरलाल रोहतगी  
 ज़ाकिर अली  
 ज़ाहिद हसन  
 जुगुल किशोर  
 जैपाल सिंह  
 जैराम वर्मा  
 दयालदास भगत  
 दाऊदयाल खन्ना  
 द्वारिका प्रसाद मौर्य  
 दीन दयालु अवस्थी  
 दीन दयालु शास्त्री  
 दीपनारायण वर्मा  
 नफीसुल हसन  
 नवाजिश अली खाँ  
 नवाब सिंह  
 नाज़िम अली  
 नारायण दास  
 निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री  
 पूर्णमासी  
 प्रकाशवती सूद, श्रीमती  
 प्रागनारायण  
 प्रेमकिशन खन्ना  
 फ़ख़रुल इस्लाम  
 फ़ख़रुर्हमान खाँ  
 फ़तेहसिंह राणा  
 फूल सिंह  
 बदन सिंह  
 बंश गोपाल  
 बनारसी दास  
 बलदेव प्रसाद  
 बलभद्र सिंह

बशीर अहमद  
 बादशाह गुप्त  
 बीरबल सिंह  
 बृजमोहन लाल शास्त्री  
 भगवती प्रसाद दुबे  
 भगवती प्रसाद शुक्ल  
 भगवान दीन  
 भगवानदीन मिश्र  
 भगवान सिंह  
 भारत सिंह यादवाचार्य  
 भीमसेन  
 मंगला प्रसाद  
 महफ़ूज़ुर्रहमान  
 महमूद अली खाँ  
 मिर्जाजी लाल  
 मुकुन्द लाल अग्रवाल  
 मुजफ़्फ़र हुसैन  
 मुनफ़ैत अली  
 मुहम्मद असरार अहमद  
 मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री  
 मुहम्मद इस्माईल  
 मुहम्मद उबैदुर्रहमान खाँ  
 मुहम्मद जमशेद अली खाँ  
 मुहम्मद नज़ीर  
 मुहम्मद फ़ारूक़  
 मुहम्मद याक़ूब  
 मुहम्मद यूसुफ़  
 मुहम्मद रज़ा खाँ  
 मुहम्मद शक़ूर  
 मुहम्मद शमीम  
 मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री  
 मुहम्मद शौकत अली खाँ  
 मुहम्मद सुलेमान अधमी  
 यज़नारायण उपाध्याय  
 रघुनाथ विनायक धुलेकर

रघुवीर सहाय  
 रघुवंशनारायण सिंह  
 राघव दास  
 राजकुमार सिंह  
 राजाराम मिश्र  
 राजाराम शास्त्री  
 राधा कृष्ण अग्रवाल  
 राधा मोहन सिंह  
 राघश्याम शर्मा  
 राम कुमार शास्त्री  
 रामकृपाल सिंह  
 रामचन्द्र सेहरा  
 रामचन्द्र पालीवाल  
 रामजी सहाय  
 रामधर मिश्र  
 रामधारी पाण्डे  
 राम बली  
 राम मूर्ति  
 राम शंकर लाल  
 रामशरण  
 राम स्वरूप गुप्त  
 लक्ष्मी देवी, श्रीमती  
 लताकृत हुसैन  
 लालन दास जाटव  
 लाल बहादुर, माननीय श्री  
 लालबिहारी टण्डन  
 लीलाधर अष्ठाना  
 लुत्फ अली खाँ  
 लोटनराम  
 विजयानन्द मिश्र  
 विद्यावती राठौर, श्रीमती  
 विनय कुमार मुकर्जी  
 विश्वनाथ राय  
 विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी

विष्णु शरण दुब्लिश  
 बीरेन्द्र शाह  
 वेंकटेश नारायण तिवारी  
 शंकर दत्त शर्मा  
 शान्ति प्रपन्न शर्मा  
 शिव कुमार पाण्डे  
 शिव कुमार मिश्र  
 शिव दयाल उपाध्याय  
 शिवदान सिंह  
 शिव मंगल सिंह  
 शिव मंगल सिंह कपूर  
 सुचेता कृपलानी, श्रीमती  
 श्याम लाल वर्मा  
 श्याम सुन्दर शुक्ल  
 श्रीचन्द सिंघल  
 श्रीपति सहाय  
 सज्जन देवी महनोत, श्रीमती  
 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री  
 सरवत हुसैन  
 सलीम हामिद खाँ  
 साजिद हुसैन  
 सालिग्राम जैसवाल  
 सिंहासन सिंह  
 सिराज हुसैन  
 सीताराम अष्ठाना  
 सुलतान आलम खाँ  
 सूर्य प्रसाद अवस्थी  
 सईद अहमद  
 हबीबुर्रहमान अन्सारी  
 हरगोविन्द पन्त  
 हरप्रसाद सत्यप्रेमी  
 हुकुमसिंह, माननीय श्री  
 होतीलाल अग्रवाल  
 त्रिलोकी सिंह

## सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल

\*श्री होती लाल अग्रवाल—माननीय स्पीकर महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि बहुत सी बहस जो इस हाउस में हुई है वह इस ख्याल से हुई है कि इस बिल की जो नेचर (प्रकृति) है उसको समझने में थोड़ी सी भूल हुई है। मैं यह समझता हूँ कि यह बिल साधारणतः जमींदारी के अबोलीशन (विनाश) का बिल है, जमींदारी के खत्म करने का मसविदा है। जहाँ तक भूमि की व्यवस्था का ताल्लुक है यह अभी प्रारम्भ की ही बात है। कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से यह अंतिम बात नहीं है। सारी बहस जो की गई है, उसमें कहा गया है कि मालगुजारी साइंटिफिक बेसिस (वैज्ञानिक आधार) पर नहीं है, उसका उसूल वैज्ञानिक नहीं है और यह कि वह केवल अन्दाजे से रख दी गई है। और यह कि हर हैरिडेटरी (मौरूसी) को आधा लगान देना होगा। हर जमींदार की आधी मालगुजारी होगी। भूमिधरों को आधा लगान देना होगा और सीरदारों को पूरा लगान देना पड़ेगा। यह कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन यह भूमि व्यवस्था का अन्तिम बिल नहीं है, इस लिये इन चीजों का अभी खयाल नहीं करना चाहिये। अगर यह सब बातें की जातीं तो जमींदारी खत्म करने में देर होती। इसलिये इस बिल से यह उम्मीद नहीं करना चाहिये कि मालगुजारी जो इस बिल में कायम की गई है वह साइंटिफिक होगी। और यह भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि सारे सूबे की भूमि-व्यवस्था ऐसी हो जाय जिसमें आइन्दा किसी किस्म की तरक्की करने का मौक़ा न हो। इन बातों के लिये थोड़े दिनों के लिये बेट (प्रतीक्षा) करने की जरूरत है। इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि ४० साल के बाद जो सेटिलमेंट (बंदोबस्त) होगा उसमें यह सब चीजों की जायेंगी। लेकिन इसी समय इन सब चीजों की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि अन ऐकोनामिक होल्डिंग्स पर जो लगान है वह भी कम होना चाहिये या यह कि अनऐकोनौमिक होल्डिंग्स नहीं रहना चाहिये। यह सब बातें आगे चलकर हो जायेंगी। जो टेनेन्सी का बिल है उससे कुछ ऐसी सहूलियतें हो जायेंगी जिनसे अनएकनौमिक होल्डिंग्स कम हो जायेंगी।

जमींदारों के मुताल्लिक भी बहुत सी बातें कही गई हैं। किसी ने कहा है कि वह बहुत बुरे थे। उन्होंने यह किया वह किया, और जमींदार पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने देश के लिये बड़े बड़े काम किये। यहाँ तक कहा गया कि सन् ५७ की लड़ाई में अँगरेजों के खिलाफ लड़ने में, जमींदार ही सबसे आगे थे। जो हिस्सा उन्होंने आजादी की लड़ाई में लिया है, वह ठीक है। लेकिन जिन जमींदारों ने हिस्सा लिया था उन बेचारों का नाम तक नहीं है। वे आज ऐसी हालत में पड़े हुये हैं कि उनका नाम तक कोई नहीं जानता। मेरे जिले में एक शंकरनगर रियासत

है, जिन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और इसमें उन्होंने अपने को भिटा दिया। आज उनकी संतति को मैं जानता हूँ। शंकरनगर में १०-२० बीघा ज़मीन भी उनके पास नहीं है। उन थोड़े लोगों को जाने दीजिये, लेकिन बाकी जो ज़मींदार लोग हैं उन्होंने देश का कोई ज्यादा लाभ नहीं किया। इन बातों को छोड़िये, ये इस समय कहने की नहीं हैं। आज तो यह विचार करना चाहिये कि हमारे देश के लिये कौन-सी चीज़ ज्यादा उपयुक्त होगी और कौन-सी चीज़ अनुचित होगी और हमारे देश की तरफ़ी किस व्यवस्था से हो सकती है या किससे नहीं। देखना यह है कि जो ज़मींदारी व्यवस्था कायम थी, उससे देश की कोई तरक्की हो सकती थी। यह जाहिर है कि ज़मींदारी की जो व्यवस्था थी उससे देश की कोई तरक्की नहीं हुई बल्कि नुक़सान ही हुआ है। अगर ज़मींदारी प्रथा को देखा जाय तो मालूम होगा कि उसकी वजह से हमारे सूबे की पैदावार में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ बल्कि यह साफ़ जाहिर है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ की पैदावार कम हो गई। वे जो मुनाफ़ा ज़मींदारी से लेते थे, उसके एवज़ में उन्होंने कोई काम खेती की तरक्की के लिये नहीं किया। अगर उन्होंने खेती की तरक्की में हाथ बटाया होता तो ज़मींदारी की वजह से हमारी पैदावार में कमी न हुई होती और फिर यह भी नहीं हो सकता था वह आज हटाई जाती। वास्तव में ज़मींदारों ने प्रोडक्शन (पैदावार) के बढ़ाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। वास्तव में यह ऐसी संस्था थी, जिसके होते हुये तरक्की की कोई आशा न थी।

आज हम यह देख सकते हैं कि आर्थिक इकनामिकली (आर्थिक दृष्टि से) यह व्यवस्था रही है। मैं देखता हूँ कि कार्तकारों से लगान इतना बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई। उनके पास खेती की तरक्की करने के लिये कोई पैसा या साधन नहीं रह गया। तो ऐसी सूरत में यह बात नहीं है कि ज़मींदारी प्रथा इसलिये मिटाई जा रही है कि उनसे कोई द्वेष है या उन्होंने कोई देश-द्रोहिता की है या देश के खिलाफ़ काम किया है जिसकी वजह से यह ज़मींदारी प्रथा हटाई जा रही है। वास्तव में अब ऐसा बक्क़ आ गया है कि बिला इसके हटाये काम नहीं चलता। हम यह कोई बदले की भावना से नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे मुल्क की तरक्की के लिये ज़रूरी है। इसीलिये यह व्यवस्था ख़तम की जा रही है।

तो अब सवाल यह है कि जब इस व्यवस्था को ख़तम करने के लिये ज़रूरत है। तो वास्तव में ज़मींदारों को मुआवज़ा मिलना चाहिये था नहीं। सोशलिस्ट की तरफ़ से यह कहा गया है कि कोई मुआवज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ़ से ज़मींदार लोग बाज़ार रेट (दर) से मुआवज़ा चाहते हैं। देखना यह है कि वास्तव में मैं यह कहूँगा कि इन सब बातों को देखते हुये हमें यह उचित है कि हमारी तरक्की के लिये, हमारे मुल्क में अमन व अमान रखने के लिये और हमारी ग्रामीण जनता की आर्थिक दशा सुधारने के लिये जो चीज़ उचित समझी जाय, बड़ी होनी चाहिये। अगर यह देखा

[ श्री होतीलाख अग्रवाल ]

जाय कि बाज़ार रेट पर हम उनको मुआवज़ा दें तो यह हमारे लिये नानुमकिन है। हम बाज़ार रेट पर मुआवज़ा नहीं दे सकते। जो उनका मुनाफ़ा है, उस पर अगर ढाई रुपया सैकड़ा सालाना सूद के हिसाब से, यानी मुनाफ़े के हिसाब से अगर हम हिसाब लगायें और यह मान लें कि करीब १० करोड़ के उनका मुनाफ़ा है तो १० करोड़ के माने यह होते हैं कि हमें ४०० करोड़ रुपया ज़मींदारों को मुआवज़े में देना चाहिये। अब यह ४ अरब रुपया कहाँ से आये। अगर यह रुपया काश्तकारों से, जैसा कि इस ऐक्ट में प्रबन्ध किया गया है लिया जाय, तो इसके माने यह होंगे कि एक काश्तकार से उसके सालाना लगान के तौर पर बजाय १० गुने के ४० गुना लगान लें तो यह रुपया हम उनको अदा कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। अगर यह कहा जाय कि ४० साल में क्रिश्तों के जरिये से यह दे दिया जाय तो भी हमारे लिये यह नानुमकिन है कि हम इसे बिना काश्तकार की आर्थिक दशा को ख़तम किये कर सकें। इस वक्त हमें ज़मींदारी के हटाने से जो लगान आता है, और उसमें जो मालगुजारी का फर्क है, उसको निकाल दें तो वह करीब करीब ६ करोड़ रुपया साल में होता है। अगर ज़मींदारों को ४०० करोड़ रुपया मय सूद के अदा करें तो ४० साल में १४ करोड़ अदा करने से कहीं अदा होगा। जो मुनाफ़ा इस वक्त हमें होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा १० करोड़ रुपये बचते हैं। ज़मींदारी ख़तम करने के बाद जो सरकार को देना होगा वह अगर साढ़े नौ करोड़ रुपये के हिसाब से देखें तो हमें ४ या साढ़े चार करोड़ रुपया साल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर लगान का इज़ाफ़ा काश्तकार पर किया जाय तो उनकी दशा और ख़राब हो जायगी। इसलिये ज़मींदारों को ज्यादा देने के लिये तमाम काश्तकारों की हालत को बिगाड़ना ठीक नहीं है। यह तो तभी हो सकता था जब विदेशी राज्य था और ज़मींदारों ने उनसे मिलकर बातचीत की होती। आज तो यहाँ पर किसानों की और मजदूरों की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। यह सरकार ऐसा कदापि नहीं कर सकती कि करोड़ों आदमियों की जिन्दगी बर्बाद करके चन्द आदमियों को इतना पैसा दे। इसलिये यह तो सही बात है कि इतना पैसा नहीं दिया जा सकता। तो फिर क्या करना चाहिये। ज़ाहिर है कि हमने जो प्रस्ताव ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को पास किया था, उसमें सिकारिश की गई थी कि हम इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन (न्याय संगत मुआविज़ा) दे सकने हैं। यानी हम ऐसा कम्पेन्सेशन दे सकते हैं जिससे ज़मींदारों की जिन्दगी भी ठीक चल सके और हमारे ऊपर बोझ भी न पड़े। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

तो यह कहना कि इक्विटेबिल कम्पेन्सेशन (उचित मुआविज़ा) अदालतें ही तै करेंगी और व्यवस्थापिका सभा नहीं तै करेगी उचित नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूँ कि कम्पेन्सेशन को दुनिया में हमेशा व्यवस्थापिका-सभाओं ने ही तै

किया है। आयरलैंड को देखिये, वहां पर हाउस ऑफ् पार्लियामेंट ने जमींदारों को खत्म करने के वक्त १० गुना मुआविजा देना तै किया था। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने जो मुआविजा देना तै किया है वह काफी उचित है। अगर आप पूरी तौर से देखें तो मालूम होगा कि जमींदारों ने जमींदारी खरीदने में कोई कीमत नहीं लगाई है। शुरू में अंगरेजों ने मिल कर उन्होंने ऐसे कानून बनवाये, जिसमें जमींदारियों की कीमत पढ़ हो गई। अंगरेजी सरकार बराबर जमींदारियों का मुनका बढ़ाती गई और धीरे-० हासन यह हो गई कि पहले जिसे १० फीसदी मुनका मिलता था, उसको आज ३० फीसदी मिल रहा है। इस तरह धीरे-धीरे जमींदारी की कीमत बढ़ाई गई है। मैं समझता हूँ कि जमींदारों को कोई मुआविजा नहीं मिलना चाहिये, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं की है। अगर किसी ने बीच में कोई कीमत अदा की है तो वह उसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि अगर कोई अन्धा होकर व्यापार करता है और अपना रुपया खर्चाद करता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता है। बल्कि उसको खुद उसकी जिम्मेदारी लेना होगी। इसी तरह अगर जमींदारों ने ऐसी चीज खरीदी है, जिसकी पहले कोई कीमत नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि वह उस कीमत के लेने के हकदार नहीं हैं। उसके अलावा जो उनके कारनामे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देहात खराब हो गया है, उस ख्याल से भी उन्हें कोई मुआविजा नहीं मिलना चाहिये। अगर किसी वजह से वह मुआविजे के हकदार हो सकते हैं तो वह यह है कि इस वक्त जो २२ लाख जमींदार हैं, उनमें से जो २५ रुपया से कम मालगुजारी देनेवाले जमींदार हैं, उनकी तादाद १७ लाख है। इस तरह १७ लाख का असर पड़ता है करीब ८५ लाख आदमियों पर और हमको यह देखना पड़ता है कि कहीं इन ८५ लाख आदमियों की जिन्दगी ऐसी दूभर न हो जाय कि वह अपनी जिन्दगी गजर कर ही न सकें। यही वजह है, जिसकी वजह से वह जरूरी हो गया है कि उनको मुआविजा दिया जाय। जहाँ तक बड़े बड़े जमींदारों का ताल्लुक है, उनको मुआविजा देना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने बड़ी जनरासिटी (उदारता) के साथ उनको मुआविजा देना तै किया है। मुआविजा के लिये एक और हमारे ऊपर बंधन है। जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ् इण्डिया ऐक्ट है, उसमें यह लिखा हुआ है कि विला उचित मुआविजा दिये हम किसी की सम्पत्ति को नहीं ले सकते हैं और जो हमारा नया विधान बन रहा है, उसमें भी यह चीज रक्खी गई है। इस चीज को नये विधान में रखने का एक कारण है। अगर हम बिना मुआविजा दिये कोई चीज छीन लें तो फिर आगे चलकर हमें दिक्कत होगी। ऐसा करने से जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है लोग अपनी पूँजी लगाने में हिचकेंगे। जब हम बाहर की पूँजी लगाने के लिए तैयार हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि हम उचित मुआविजा देने की व्यवस्था न रक्खें। पूँजीवाद



[ श्री होतीलाल अग्रवाल ]

को हम खत्म करेंगे, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है। अभी ऐसा करने से हमारे देश को नुकसान होगा। जब हमारे देश को फायदा होगा तभी हम पूँजीवाद को खत्म करेंगे। इसलिए हमें मुआविजा देने की जरूरत है। बिला मुआविजा दिये हुये हम अपना काम नहीं चला सकते हैं।

एक बात मैं यह अर्ज करूँगा कि किसी तरह से जमींदारी अबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट में और बिल में भी एक बड़ा आइटम गलती से लिख गया है। ५ हजार और १० हजार के यह बीच के जमींदार हैं। इन्हें ८ गुना मुआविजा मिलना चाहिये। उन्हें ८ गुना मिलेगा और इस पर इन्कमटैक्स लगेगा। इसलिए बड़े-बड़े जमींदारों को ज्यादा मिल जायगा। इस श्रेणी के जमींदार ५ हजार से १० हजार मालगुजारी देनेवाले, बीच के जो जमींदार हैं, उनको कम मुआविजा उससे मिलेगा जो जमींदारी अबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर गौर कर लिया जाय।

दूसरी बात यह मुझे अर्ज करना है कि सन् १८५७ ई० में जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने बगावत की और देश के खिलाफ अंगरेजों से मिले और इन पैटरीआट्स ( देश भक्तों ) के खिलाफ युद्ध में कार्यवाहियाँ कीं। वह ऐसी बात है कि हमें उसका ज्यादा खयाल करना चाहिये। दक्षिणी पूर्वी योरप के कई मुल्कों में जमींदारियाँ खत्म हुई हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को, जिन्होंने देशद्रोही का काम किया था तो मुआविजा नहीं दिया था बिल्कुल कम दिया है। मैं समझता हूँ इस चीज का जरूर खयाल होना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे काम किए वास्तव में उनको कोई हक नहीं है। वह लोग जिन्दा हैं तो उनको या अगर मर गए तो उनके वारिस को मुआविजा देते वक्त इस बात का खयाल करना चाहिए। और अगर उनकी जमींदारी दूसरों के पास चली गई तब तो दंड देने और मुआविजा देने का कोई सवाल नहीं उठता। अगर वह जमींदारी उसी के घराने में है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी डकैत को क्या हक है। अब हमारे हाथ में ताकत है। हम इन्साफ करें। इन्साफ कहता है कि उन्हें मुआविजा न दिया जाय। अगर दिया जाय तो थोड़ा दिया जाय। उनके एवज उन लोगों का ज्यादा खयाल किया जाय, जिन लोगों की जायदाद इस तरह से दूसरों को दे दी गई है। वह आज भी गरीबी में परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के वारिसों को, जिन्होंने प्राण दिये, लड़ाई से निर्जीव कर दिये गए। उनका कोई खयाल होना चाहिये, इस तरह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार ने सब लोगों का खयाल किया है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस उन जमींदारों का जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में बहुत काम किया, कोई ज्यादा खयाल किया जाय। उनको थोड़ा सा ज्यादा मुआविजा दिया जाय।

कोई और डिस्टिक्शन (फर्क) न किया जाय, जिन जमींदारों ने आजादी की लड़ाई में काम किया उनको कुछ ज्यादा मिले। मुझे इसके सिवाय कम्पेन्सेशन के बारे में

ज्यादा अर्ज करना नहीं है। वास्तव में जो कुछ किया गया है काफी अच्छा है। एक बात रह गई है जो मुझे खास तौर से मुआविजे के संबंध में कहना है, मैं चाहूँगा कि चौधरी चरणसिंह जी इस बात पर गौर कर लें। जहाँ तक दूसरी जमीन का ताल्लुक है, वहाँ मुआविजा जो जमींदारों को दिया गया है और रिडेम्प्लिशमेंशन ग्रांट दी गई है वह ठीक है। लेकिन जिनका सीर और खुदकाशत का रकबा है, वह जमींदारों को भूमिधर बना दिया गया है। बिला उनसे कुछ लिये ठीक है उसके लिये मुआविजा नहीं दिया गया लेकिन यह छोटे जमींदारों के साथ ज्यादानी होगी। इसका मतलब यह है जो जनरल स्कीम है मुआविजे की उसमें बड़े जमींदारों को ८ गुना मिलेगा और छोटे जमींदारों को २८ गुना लेकिन जो सीर और खुदकाशत की जमीन है वह काफी है। सारी जमीन का पाचवाँ हिस्सा है। करीब २० फीसदी है। इस सम्बन्ध में बड़े जमींदारों को जमीन का एकसाँ मुआविजा मिल जाता है, वह उनके पास रहती है। जनरल स्कीम को देखिये। मुआविजा सीर और खुदकाशत का बड़े जमींदारों को कम और छोटे जमींदारों को ज्यादा मिलेगा।

और मैं यह भी जानता हूँ कि बड़े जमींदारों के पास जो सीर और खुदकाशत का रकबा है, वह बहुत ज्यादा है। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस पर काफी गौर किया जाय और इसको जेनरल स्कीम में मिला दिया जाय। सीर और खुदकाशत के अलावा जमींदारों को जो मुनाफा काशत से होता है, उस मुनाफे में उन लोगों को जिस तरह से जेनरल स्कीम है, उसी तरह से मुआविजा दे दिया जाय और फिर उसके बाद उन लोगों से जो साक्रिटुल मिलिकियत का रेट है, उस रेट के हिसाब से दस गुना ले लिया जाय और तब मानगुजारी आधी कर दी जाय तो मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी बात है, जिससे छोटे जमींदारों को राहत मिलेगी और जो बड़े-बड़े जमींदार हैं जिनकी हालत अच्छी है, जिनके पास बहुत सीर है, उनको कोई दिक्कत न होगी। एक सवाल यह उठता है कि यह रुपया जो दिया जाय वह आए कहाँ से। एक साइब ने तो यह कहा कि कम्पेन्सेशन टैक्स लगा दिया जाय। अगर आज हम टैक्स लगाने के लिये बैठते हैं और उससे रुपये की उम्मीद करें तो मैं समझता हूँ कि फिर जमींदारी कम्पेन्सेशन के लिये हमें कई साल तक इन्तजार करना पड़ेगा और कई साल तक हमारा सूबा जमींदारी की बला से नहीं बच सकेगा। इसलिये यह बात भी प्रेक्टिकल (क्रियात्मक) नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर रुपया कहाँ से आवे। लार्ड साइब ने तो कहा है कि न तो किसानों से लगान का दस गुना लिया जाय और न असामियों से पन्द्रह गुना लिया जाय बल्कि एक जादू ऐसा किया जाय जिससे ज्यादा रुपया आ जाय और जमींदारों को कम्पेन्सेशन दे दिया जाय। कम्पेन्सेशन के खिलाफ वे नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों से रुपया न लिया जाय। तो सवाल हुआ कि रुपया कहाँ से आवे? क्या गवर्नमेंट और लोगों पर टैक्स लगावे? अगर और टैक्स लगाया जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे की

[ श्री होतोलाल अग्रवाल ]

व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह चीज बिल्कुल गलत है कि किसानों से रुपया न लिया जाय। आज यह कहा जाता है कि किसानों की हालत खराब है। मैं समझता हूँ कि यह आँख मीच कर कहनेवाली बात है। यह ठीक है कि किसानों की हालत जमींदारों के बराबर नहीं है। यह भी ठीक है कि उनकी हालत दूकानदारों और दूसरे लोगों के बराबर नहीं है लेकिन यह भी ठीक है कि आज से दस वर्ष पहले जो किसानों की आर्थिक दशा थी, उसमें कुछ तरक्की हुई है। उनका लगान तो उतना ही रहा जितना कि पहले था, लेकिन पैदावार की जो कोमत है उसमें चौगुना और पाँचगुना तक इजाफा हुआ है। और इसकी वजह से वे कई साल से रुपया बचाकर रक्खे हुये हैं। आज उनके पास जो पैसा है वह पैसा उनका मकान बनाने में नहीं लगेगा, क्योंकि सीमेंट और ईंटें उनको नहीं मिलेंगी और दूसरे तरक्की के कामों में वे रुपया नहीं लगायेंगे लेकिन एक बड़ी तरक्की का काम जो उनके लिये आवश्यक है वह यह कि वे जमीन के मालिक हो जायँ और वह रुपया जो आज उनके पास है अगर उसमें लगाया जाय तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत न होगी। बहुत लोग काश्तकारों की हालत जानने का दावा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका यह दावा बिल्कुल गलत है। जिस पार्टी से लारी साहब ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी के लोग शायद ही कभी देहातों में जाते होंगे। लेकिन हम कांग्रेसवाले तो एक एक घर की बात जानते हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जब यह प्रस्ताव काश्तकारों के सामने रक्खा गया तो उन्होंने इस चीज का हृदय से स्वागत किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी काश्तकार ऐसा नहीं बचेगा, जो अपने लगान का दसगुना रुपया नहीं देगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवा इसके कि हम काश्तकारों से रुपया ल। आप जानते हैं कि काश्तकारों के लिये जमीन कितनी जरूरी है। आज काश्तकार एक एक बीघा जमीन को एक एक हजार रुपये तक नज़राना देकर लेते हैं। जब एक एक हजार रुपया जमींदारों को नज़राना देकर किसान जमीन लेते हैं तो जिस जमीन का लगान ५-६ रुपया हो उसके लिये ५०-६० रुपये देने में उनको क्या दिक्कत होगी जब कि उनको जमीन पर सारा हक मिल जायगा ? मैं समझता हूँ कि काश्तकार इससे इन्कार नहीं करेगा और इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो व्यवस्था है वह निहायत ही अच्छी व्यवस्था है।

मान लिया जाय कि अगर इस वज़त किसी तरह से टैक्स लगाकर जमींदारों को रुपया दिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि जमींदारों की परचेजिंग पावर (क्रय-शक्ति) बहुत ज्यादा बढ़ जायगी और काश्तकारों की तो बढ़ ही चुकी है तो इसका नतीजा यह होगा कि आज जो गिरानी की मुसीबत है वह और ज्यादा बढ़ जायगी और उससे देश की आर्थिक व्यवस्था के ढाँचे के बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह चीज जो की गई है, यह बहुत ही सोच-

समझ कर की गई है और यही एक चांज है, जिससे हम जमींदारी को खत्म कर सकने हैं। मान लीजिये यह रुक्या न लिया जाय तो फिर कोई और तरीका नहीं समझ में आता कि जमींदारी कैसे खत्म हो सकती है। जब यह कानून हो गया है कि जमींदारी उस वजह तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक उचित मुआविजा उन को न दिया जाय और मुआविजे के लिये रुपया नहीं है, तो फिर वह कैसे खत्म होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस के साथ ही कारतकारों के सामने यदि यह रक्खा जाय कि तुम इतना रुपया देना चाहते हो या जमींदारी को ऐसे ही बिना रुक्या दिये रखना चाहते हो तो मैं आप से कहता हूँ कि वे अपने भाग्य की मरहना करेंगे और परमात्मा को धन्यवाद देंगे और इस बात को कबूल करेंगे कि १० गुना रुपया दे दिया जाय और जमींदारी खत्म कर दी जाय। इस लिये धर-उधर की बातें कहकर कारतकारों को बरगलाने की कोशिश से और किसी और बात से कोई फायदा नहीं है। असल बात तो देखना चाहिये कि हमारा जो मकसद है वह इस बिल से पूरा होता है या नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद बिना कारतकारों से रुपया लिये हुये पूरा नहीं हो सकता और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता। अब सवाल यह है कि आया जो भूमि-व्यवस्था हम इस बिल के जरिये से करने जा रहे हैं वह व्यवस्था कैसी हो। आया वह मकसद जो हम चाहते हैं, वह इस बिल से पूरा होगा या नहीं। कहा यह जाता है कि हम वह भूमि-व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अगर दो तीन बातें हो जायँ तो वह भूमि-व्यवस्था अच्छी हो जायेगी। एक तो यह कि गाँवों में कोई इनइक्वालिटी (असमानता) पैदा न हो और सब लोग बराबर हो जायँ। रामराज्य तभी हो सकता है, जब सब की अवस्था करीब-करीब एक साँ हो। अगर उसमें बहुत ज्यादा फक है, तो वह रामराज्य हरगिज नहीं हो सकता। दूसरी बात, ऐसी भूमि-व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमें हमारे यहाँ खेती की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। अगर पैदावार में कमी रह जाती है तो मैं समझता हूँ कि वह भूमि-व्यवस्था अच्छी नहीं कही जा सकती। भूमि-व्यवस्था के लिये जितना ज्यादा हम पैदा कर सकें वह भूमि-व्यवस्था उतनी अच्छी है। मैं यह मानता हूँ। तीसरी बात यह होनी चाहिये कि बेकारी बढ़ने न पावे, कम हो सके हो जाय लेकिन बढ़ने न पावे। तो हमें इन्हीं सब बातों पर गौर करने से पता चलेगा कि इस बिल में जो भूमि-व्यवस्था है वह हमारे लिये फायदेमंद और उचित है। मैं समझता हूँ कि अगर एक एक चीज को लिया जाय तो यह बिल उन सब बातों को पूरा करता है। देखना यह है कि इस बिल से देहात में बराबरी बढ़ेगी या नहीं। इस समय जमींदार हैं और बीच में हक वाले और कई तरह के लोग भी हैं। इसके अलावा और कई तरह के कारतकार हैं। कोई शिकमी कारतकार है, कोई फिक्स्ड रेट टेनेंट है, कोई आकूपेन्सी टेनेंट है, कोई हेरीडिटरी टेनेंट है और तरह-तरह के लोग हैं तो आज देखा जाय इन

[ श्री होतीजाल अग्रवाल ]

सब हकवालों के हक एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। मैं समझता हूँ कि आज यह बात कोई नहीं कह सकता कि इनइक्वालिटी नहीं है। बड़ी भारी इनइक्वालिटी है। पड़ोसी का एक काश्तकार जो लगान देता है ठीक उसी तरह का दूसरा पड़ोसी उसका ठीक दुगुना या तिगुना लगान देता है तो मैं समझता हूँ कि यह चीज जो है वह इनइक्वालिटी की है वह इस बिल में हमने कम की है जिससे इनइक्वालिटी खत्म हो। जाहिर है कि सरकार और काश्तकार के बीच में जमींदार नाम की कोई चीज तो अब रहेगी नहीं। बिल में न कोई ऐसा प्राविजन है जिसमें वह मौजूद रहे और न भविष्य में पैदा होने के लिये कोई जगह है।

कहा जाता है कि भूमिधर तो जमींदार लफ्ज का ट्रांसलेशन है। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वह भूमिधर कितने होंगे। आज जमींदार कितने हैं। ५० रुपये से कमवाले को हम जमींदार नहीं कहते हैं। बड़े जमींदार चन्द थोड़े से हैं। देहातों में अगर आप देखें तो मालूम होगा कि एक फीसदी भी नहीं हैं। और अगर अब काश्तकारों में ६० फीसदी हो जायँ तो कोई बेजा बात नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। जो भूमिधर के राइट्स (हक) दिये जा रहे हैं वह आम तौर पर मजारिटी (बहुसंख्यक) को दिये जा रहे हैं। मजारिटी को हुकूम दे देना बहुत अच्छी बात है। तो अब देखना यह है कि आगे कितने तरह के काश्तकार होंगे। चार तरह के काश्तकार होंगे। दो तरह के काश्तकार तो ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों के लिये रहेंगे। इस बिल के मुताबिक अधिवासी ५ साल तक के लिये रहेंगे लेकिन मैं तो यह चाहता था कि जो कुछ भी होना है उसके लिये ५ साल के लिये यह नहीं टालना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि जो इस वक्त में काश्तकारान हैं वह चाहे सीर का हो या असली हो, जो कुछ भी उनको देना है वह आज ही दे दिया जाय। आगे ५ साल के लिये सस्पेन्स (असमंजस) में डाले रखना कोई फायदेमन्द बात साबित नहीं हो सकती है। इसमें न जमींदार का फायदा है और न काश्तकार ही का फायदा हो सकता है। इस तरह से यह चीज बहुत दिनों तक चलाना कि कोई शिकमी बना रहे, कोई असली बना रहे और कोई सीर का मालिक बना रहे और उसका शिकमी काश्तकार उसको लगान देता रहे यह उचित नहीं जान पड़ता। इसका अन्त अभी हो जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि बजाय १० गुने के १५ गुने उनसे ले लिया जाय और इस वक्त उनको अधिकार दे दिये जायँ। भूमिधर के अधिकार उनको दे दिये जायँ तो एक क्लास आज ही खतम हो सकती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बात पर गौर करे। अगर आप यह समझते हैं कि ५ साल तक सीरदार या असली काश्तकार को लगान का फायदा हो जायगा तो यह बात भी कुछ जँचती नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि १० फीसदी कर दें या और ज्यादा करा दें लेकिन खातमा उसका आज ही कर दें। वह गरीब आदमी है। अगर १५ फीसदी न रक्खें तो ठीक है। १० फीसदी रक्खें तो अच्छा है या २० फीसदी रक्खें। जो कुछ भी हो सरकार जिस नतीजे

पर पहुँचना चाहती है उस नतीजे पर आज ही पहुँच जाना चाहिये और इस अधिवासी की क्लाम को नवन कर देना चाहिये और वह आज ही खनम हो सकती है। मैं समझता हूँ कि १० गुना रुपया लेने के बाद आन भूमिधर को कुछ अख्तियार दे रहे हैं। वह इतने ज्यादा अधिकार हैं जो काफी हैं। वह अपनी जमीन को चाहे किसी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, वह उसको बेच सकता है, वह उसको रेहन कर सकता है, तो जो आपने यह बड़े अख्तियार उसको दिये हैं इसके माने यह है कि हमारी पैदावार में यह बड़ा काम देगा। आज तक काश्तकारों के पास जितनी काश्त थी उसकी वह हैसियत नहीं थी। बाजार से उसको जो कर्जा लेना पड़ता था उसका भारी सूद उसको देना पड़ता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब उसको यह अख्तियार मिल जायेंगे तो उसकी हैसियत बहुत अच्छी हो जायगी। और उसको जरूरत पड़ेगी, या ग्वेनी की तरक्की के लिये जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त वह रुपया ले सकता है और कम सूद पर पर उसको रुपया मिल सकता है। यह चीज देखने में आती थी कि कोआपरेटिव सोसाइटी के होते हुए भी आज जब काश्तकार को जरूरत पड़ती है तो उसे दो रुपया सैकड़ा सूद देना पड़ता है लेकिन इस बिल के पास होने के बाद मैं समझता हूँ कि काश्तकारों की करजे की समस्या, उसकी बैल की समस्या, बीज की समस्या वगैरह यह सब समस्याएँ हल हो जाँयगी, क्योंकि उसको रेहन और बय करने का अख्तियार हो जायगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो उसको रेहन और बय करने का अख्तियार दिया जा रहा है एक बहुत बड़ा अख्तियार है। इस तरह के अख्तियार के होते हुए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा सीरदार न होगा जो इस चीज को मंजूर न करे। ४० साल तक यह व्यवस्था है जो आधा रुपया के हिसाब से उससे लिया जायगा। जितना रुपया वह देगा उसका दुगुना रुपया सरकार के पास हो जायगा। इस तरह से मैं यह समझता हूँ कि कोई सीरदार ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो सीरदार का रुपया देकर भूमिधर के अख्तियार न ले तब फिर केवल दो रह जायेंगे। एक तो भूमिधर रह जायगा। सारे सूबे में भूमिधर लोग रह जायेंगे, इसके अलावा अगर कोई रहेगा तो वह आसामी रह जायगा। आसामी भी एक जरूरी दिक्कत है। अगर वह दिक्कत न होती तो मैं समझता हूँ वह भी न रहते। लेकिन उनकी तादाद कितनी होगी? आम लोगों को तो शिकमी उठाने का अख्तियार नहीं होगा, केवल उनको होगा जो या तो माइनर नाबालिग हैं, या बेवाएँ हैं, या किसी तरह से डिसएबिलिड (लाचार) हैं या जो हमारी फौज में इधर-उधर काम करेंगे वह। इनके अलावा किसी को अख्तियार नहीं होगा। तो उनका जो अख्तियार होगा वह आन तौर से बरतेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से लेकर के खेती ही करेंगे, क्योंकि खेती में फायदा होगा वनिस्वत शिकमी उठाने में। तो वे तो किसी न किसी तरह से इन्तजाम करके खेती करेंगे। तो इसलिये जो आसामी होंगे उनकी तादाद बहुत

[ श्री होतीलाल अग्रवाल ]

थोड़ी होगी। मेरा खयाल है कि वह एक फीसदी भी नहीं हो सकते। तो जब ६६ फीसदी काश्तकार एक तरह के हो जायेंगे, उनके हक एक तरह से होंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे ईक्वालिटी (समानता) लाने में बहुत मदद मिलेगी, तो इस बिल से हमारे देहात में भी अनईक्वालिटी जो भेद-भाव, जो असमानता फैली हुई है वह बिलकुल खत्म हो जायगी और सब लोगों की बराबरी हो जायगी।

अब सवाल यह है कि हम प्रोडक्शन (पैदावार) बढ़ा सकेंगे या नहीं। इस बिल के आने के पहले और पीछे की हालत में क्या तबदीली होगी? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो होगी जो काश्तकार की पैदावार को बढ़ायेगी वह यह कि सारे संसार ने यह माना है जिस आदमी का यह खयाल होता है कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ तो वह उसकी तरक्की करने में अपनी जान लड़ा देगा और जब उसकी हैसियत भी ऐसी होगी कि जो जरूरी चीजें हैं उनको मुहइया कर सके तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज से ज्यादा उसकी तरक्की क्यों नहीं होगी?

दूसरी बात यह कही जाती है कि हमारे सूबे में ज्यादातर ऐसी जोत है जो बहुत छोटी छोटी हैं, एक एकड़ से कम की हैं, दो एकड़ से कम की हैं। ठीक है, आज ८७ फीसदी ऐसी जोतें हैं जो बहुत छोटी हैं, अनएकानामिक (अलाभकर) हैं, जिनमें इतनी पैदा नहीं होती कि काश्तकार को खाने के बाद कुछ बच जाय और ऐसी जोतों में मैं जानता हूँ कि बहुत कम पैदावार होती है, क्योंकि ऐसे काश्तकार के पास साधन नहीं होते। इसलिये वह इतना पैदा नहीं कर सकता जितना कि बड़े काश्तकार कर सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों के पास बड़ी २ जोतें हैं, ५०० बीघे की हैं, २००० बीघे की हैं उनके लिये भी आजकल बहुत सी दिक्कतें हैं, इसलिये उनक खेतों में सिवाय उन लोगों के जो मिकेनाइज्ड (यांत्रिक) ढंग से खेती करते हैं, इतनी पैदावार नहीं होती जितनी कि पैदावार बीच की जोतों में होती है। इसके मानी यह है कि सिवाय मशीन की खेती के ५० एकड़ के बाद औसत पैदावार कम हो जाती है। इसलिये मैं चाहता यह हूँ कि इस तरह की दोनों जोतों में कमी हो। तो देखना यह है कि इस बिल में इसके लिये कुछ है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भूमिधर को यह अख्तियार दिया गया है कि वह अपनी काश्त को बेच सकता है, रेहन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है तो इस राइट के जरिये से अपने आप ऐसी टेडेंसी (रुझान) पैदा होती है कि यह कायदा है कि हर आदमी को अपनी चीज़ छोड़ने में बुरा लगता है तो जिसके पास एक एकड़ जमीन है, आध एकड़ जमीन है आज वह भी इस काम को छोड़ कर दूसरे काम को नहीं शुरू करेगा। सैकड़ों काश्तकारों से मेरी बात चीत हुई है वे ज्यादा फायदे का काम भी नहीं करते अगर इसके लिये उन्हें अपना काम छोड़ना पड़े तो इसलिये जो बेचने का हक उनको मिल गया है तो ऐसे लाखों आदमी जिनके पास एक-एक, दो-दो, पाँच-पाँच बीघे काश्त है वह अपनी काश्त दूसरे लोगों को दे देंगे ताकि वे दूसरी जगह जाकर अपनी गुज़र करें। तो इस तरह से जो अनएकानामिक होल्डिंग्स हैं वह कम होंगी।

तीसरी बात जो इसमें गन्वी गयी है वह यह है कि वह काश्तकार उस काश्त में अपना हाथ नहीं मींच सकता; जिसके गम ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है।

तो इस लिये बड़ी-बड़ी जमीनें नहीं होंगी, लेकिन मैं एक चीज और चाहता हूँ; जहाँ तक कि नई जमीन का ताल्लुक है हमारी सरकार ने बिल में रक्खा है कि नई जोत पहले उस आदमी को उठाई जाय जिसके पास अनएकोनामिक होल्डिंग है; उसको पहले मिन्नना चाहिये और उसके बाद खेती का जो मजदूर है उसको मिन्नना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि जो बय करने का अधिकार है, उसमें यह शर्त लगा दी जाय कि जो कोई बेचेगा, जिस तरह से तीस एकड़ से ज्यादा वालों को दे नहीं सकता, उसी तरह से उन लोगों को बेचेगा जिनके पास अनएकोनामिक होल्डिंग है और उसके बाद उन लोगों को जिनके पास खेत नहीं होगा। तो इस का नतीजा यह होगा कि जितनी अनएकानामिक होल्डिंग्स हैं वह कम होती चली जायगी और इसी तरह से बड़ी-बड़ी जमीनें भी इस कानून के जरिये से ही धीरे-धीरे बँट कर छोटी हो जायँगी। आज हम देखते हैं कि बड़ी जमीन वालों को बड़ी दिक्कत है। उन्हें मजदूर नहीं मिलते, जिससे वह अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकें। अगर बड़ी जमीनों में ज्यादा पैदावार कर लें तो फिर एतराज ही क्या होता। लेकिन चूँकि नहीं कर पाते हैं, इसलिये वह भी सोचेगा कि जब मैं खेती कर नहीं पाता हूँ तो उस खेत की कीमत ही ले ली जाय तो अच्छा है। तो अगर वह बेचेगा तो अपने जोत के उसी हिस्से को बेचेगा, जिसमें वह अच्छी तरह से पैदा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भी उनके साथ शर्त यह रहे कि वह भी पहले उसी को बेचेगा जिन की होल्डिंग अनएकानामिक हैं और उसके बाद लैंडलेस लेबर (भूमि-हीन मजदूर) को बेचेगा। अगर ऐसा कर दिया जाय तो हमारी जो समस्या है वह हल हो जायगी। तो मैंने यह दिखाया कि हमारे यहाँ जो पैदावार में कमी है वह छोटी और बड़ी जमीनों के कारण है, जिसके लिये मसाला इस बिल में मौजूद है। दूसरी बात मैंने यह बताई कि काश्तकार जब मालिक होगा तो यह भी बड़ी जबरदस्त वजह होगी जिसकी वजह से जोत की पैदावार बढ़ जायगी। इस ख्याल से भी अगर देखा जाय तो यह बिल बहुत अच्छी चीज है।

अब उन लोगों का सवाल आता है जिनके पास खेत नहीं है और वह मजदूरी करते हैं। मेरा ख्याल यह है कि यह बात बिल्कुल साफ है कि जितने आदमी इस वक्त खेती में लगे हैं उनके लिये जमीन पर्याप्त नहीं है। जमीन इतनी नहीं है कि सबको दे दी जाय। तब सवाल यह आता है कि जमीन जितने लोगों को दी जा सकती है, जो अच्छी तरह से पैदा कर सकते हैं उससे ज्यादा को देने के माने यह होंगे कि अनएकानामिक होल्डिंग को बढ़ाया जाय।

बहुस जो की गई है वह अजब तरीके की है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जितने लोग हैं सबमें बराबर-बराबर जमीन बाँट दी जाय और दूसरी तरफ इस बात पर भी बड़ा जोर है कि अनएकानामिक होल्डिंग्स न होने पायँ।



[ श्री होर्नालाल अग्रवाल ]

मेरी समझ में नहीं आता कि यह दोनों चीजें तो ऐसी हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। अगर लैंडलेस लेबर को जमीन बाँट दी जाय तो यह न उनके फायदे की चीज होगी, न किसी के फायदे की चीज होगी और न सूबे के फायदे की चीज होगी। जोतों के छोटी छोटी हो जाने पर उसको उसमें फायदा नहीं हो सकता। असली हाल तो यह है कि बहुत से धंधे अपने सूबे में जारी करने होंगे और जो बड़े बड़े पैमाने पर काम होते हैं अगर वह देहात में चलाये जायँ तो मैं समझता हूँ कि हमारे देहात की समस्या पूरे तौर से हल हो जायगी।

एक बात और यह कहता हूँ कि यह कहा गया है कि लगान कम नहीं किया जा रहा है गो कांग्रेस हमेशा इसके माफिक रही कि लगान कम किया जाय लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह कहा गया कि सन् १९२१ ई० में कांग्रेस चाहती थी कि लगान जो जमींदारों ने पिछले कई वर्षों में चार करोड़ के करीब बढ़ा लिया है उसे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिये यह माफ होना चाहिए और यह भी कहा गया कि कांग्रेस का यह बराबर दावा रहा है कि अनएका-नामिक होर्लिंडग्स का लगान कतई माफ कर दिया जाय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह ठीक बात है। लेकिन हमें देखना यह है कि आज लगान जैसा कि हम चाहते थे वैसा है या नहीं। जिन हमारे विरोधी दल के नेता श्री लारी ने यह बात कही कि हमने सन् २१ में क्या कहा था और सन् ३६ में क्या कहा था। जमींदारी कमेटी की रिपोर्ट के वक्त क्या कहा लेकिन उन्होंने यह नहीं फरमाया कि क्या आज भी रुपये की वही वैल्यू (मूल्य) है जो सन् १९२१ ई० में सन् १९३६ ई० में या जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के वक्त थी। मैं दावा करता हूँ कि सन् २१ में जो रुपये की कीमत थी वह आज चार आने से ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूँ कि जो १८ करोड़ रुपया लगता था आज साढ़े चार करोड़ रुपया लगता है तो मैं यह कहता हूँ कि आज क्या कांग्रेस ने जो कहा था उसके खिलाफ कोई काम कर रही है? कांग्रेस ने यह कहा था कि अगर रुपये की वैल्यू यही रही तो चार करोड़ रुपया काश्तकार बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जब रुपये की वैल्यू बढ़ गई और वह मुसीबत जो सन् १९२१ ई० में थी वही अगर काश्तकार के लिये आयैगी तो हमारी गवर्नमेंट खूब समझती है कि बिना लगान बढ़ाये काम नहीं चल सकता है। जब टाइम (वक्त) निकल जायेगा तो लगान और माल-गुजारी को साइंटिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से कर देंगे। इसलिये इस वक्त लगान कम की बात करना ठीक नहीं है और यह बात समझ में भी नहीं आती है सिवाय इसके कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं उनको बरगलाया जाये। इसलिये हर एक बात खूब सोच-विचार कर कहना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं बैठ जाऊँगा। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। एक बात मुझे बहुत खटकती है जो इस बिल में काश्तकार से, मालगुजारी वसूल करने का तरीका रक्खा गया है वह मुझे कुछ जँचा नहीं। मालगुजारी वसूल करने में

सबसे पहली बात यह रक्खी गई है। मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हो जाये तो सबसे अच्छी बात है लेकिन ज़ना कि मनुष्य का स्वभाव है और जैसी हमारी अवस्था है उस अवस्था में मैं इन चीजों को उचित नहीं समझता। जो ज्वाइंट और इंडिविजुअल रिस्पान्सीबिल्टी (सम्मितित और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व) रक्खी गई है यानी सबको मिनाकर और अलग अलग जिम्मेदारी होगी। आज मैं समझता हूँ कि इन बातों में बड़ी दिक्कत होगी और आज भी हमें बड़ी दिक्कत पड़ रही है। हमने प्रोक्चोरमेंट (गल्ला उलूनी) में देखा है कि जहाँ चार सामीदार थे उनके लिये ज्वाइंट रिस्पान्सीबिल्टी कर दी गई थी उनसे ही सबसे कम अन्न मिला। क्योंकि एक आदमी में तो इतनी सामर्थ्य होती नहीं है कि सबके हिस्से का अन्न दे सके और लोग यह देखते हैं कि पहले वह दे दे तो मैं हूँ। जो यह रिस्पान्सीबिल्टी (उत्तरदायित्व) रक्खी गई है इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। इससे वसूली में दिक्कत पड़ेगी और काश्तकारों में आपस में मनमुटाव तथा मुकद्दमे-बाजी होगी। मान लीजिये चार सामीदारों में से दो दे देते हैं और दो नहीं देते तो दीवानी में दावा दायर करना पड़ेगा। इन चीजों को खत्म करने के लिये मैं उम्मीद करूँगा कि इन पर गौर किया जाये और जहाँ तक मुमकिन हो सके इन चीजों को खत्म कर दिया जायगा।

इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होने का डर है। इसके बाद मैं बार बार यह कहता रहा हूँ कि रुक्या वसूल करने के लिए किसी को गिरफ्तार करके डिटें (हिरासत में) करना उचित नहीं है और अगर कानून में यह चीज रहेगी तो यह डर है कि उसका मिसयूज (गलत इस्तेमाल) जरूर होगा। थोड़ा पैसा होने पर मेरा ख्याल है कि यह नौबत नहीं आवेगी। और अगर ऐसा रहेगा तो लोगों को इज्जत पर बन आवेगी इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस प्राविजन को निकाल दिया जाय और रुपया वसूल करने के डिटेन्शन के अलावा दूसरे तरीके भी हो सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सन् ३६ में यह रक्खा गया था कि सेना (सहना) बिठा कर फसल कुर्क की जाती है। यह चीज ऐसी है कि जिससे मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूँ कि अब वह मौक़ा नहीं है कि सरकार की तरफ से इस तरह से सेना मुकर्रर करके खड़ी फसल को कुर्क करने की जरूरत पड़े। इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए था।

मैं आपका और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, इतना वक्त भी मैंने इस लिये लिया क्योंकि यह बहुत इम्पारटेंट (महत्त्वपूर्ण) बिल था। आखिर मैं मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सब मिलकर कोशिश करें और इस बात का ख्याल न करें कि हम सोशलिस्ट हैं, या कांग्रेस पार्टी के हैं या इस फिर्के या उस फिर्के से सम्बन्ध रखते हैं। और फिजूल के आरगूमेंट्स (दलीलों) का सहारा लेकर लोगों को बरगलाइये नहीं और जमींदार भी यह ख्याल न करें कि हमारा ख्याल नहीं रक्खा गया है और

[ श्री होतीलाल अग्रवाल ]

अगर कोई असन्तुष्ट भी हो तब भी सबको मिलकर ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हमारे देहातों की प्रजा का भला हो। अन्त में मैं फिर सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि यह एक ऐसा बिल है कि जिससे हमारे देहात के रहनेवाले खुश होंगे और सम्पन्न होंगे और हमेशा आपको धन्यवाद देते रहेंगे।

श्री मुहम्मद रज़ा ख़ाँ—जनाबवाला, मैं न कांग्रेसी हूँ, न सोशलिस्ट हूँ, न कम्युनिस्ट हूँ और न स्मार्गदार हूँ, बल्कि एक गरीब शख्स हूँ और खेती करता हूँ और इसी उसूल के मानहत में जो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ करूँगा।

जनाबवाला, इस वक्त हमारे सामने जो मसला पेश है वह ऐसा मामूली नहीं है कि जिसको हम यह खयाल कर लें कि वह आसानी के साथ मामूली तरीके से हल हो सकता है। मेरा खयाल है कि इस सूबे के करोड़ों आदमियों पर किसी न किसी तरह इसका असर पड़ता है जहाँ तक कि जमींदारों की तवारीख का सवाल है मैं उन की तवारीख बयान करना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करूँगा कि दुनिया आज तक मुस्तलिफ़ दौरों से गुजरी है और उसकी तारीख भी बदली है। एक जमाना वह था कि जब जमींदार नहीं थे और राजा थे और हर चीज राजा की मिल्कियत समझी जाती थी। उसके बाद जमाने और मौके ने जब मजबूर किया तब जमींदारी सिस्टम रायज हुआ और उसके बाद फिर आज जमाना मजबूर करता है तो जमींदारी सिस्टम को दूर किया जा रहा है और दुनिया में ऐसा हमेशा होता आ रहा है। मैंने सन् ३८ में इसी हाउस में अपनी एक तकरीर में कहा था कि जमींदारी को खत्म करना होगा। इसके बाद सन् ४७ में मैंने कहा था कि एक तरीका इसको खत्म करने का मुनासिब होगा और वह यह कि काश्तकारों से जमींदारों को मुआवजा दिलाया जाय। आज मुझे याद है कि एक साहब ने कहा था कि इस तरह बजाय लाखों जमींदारों के करोड़ों जमींदार इस सूबे में बनजायेंगे। मैंने उसका जवाब उनको यह दिया था कि आपको जमींदार के नाम से नफरत है या उसके अग्राज से। मैं आज भी कहता हूँ कि भूमिधर काश्तकार क्या होगा। मैं उसको अगर उर्दू जवान या हिन्दुस्तानी में कहूँ तो उसे भी जमींदार कहा जा सकता है। जनाबवाला यह भी कहा जाता है कि इस सूबे के अन्दर कम्युनिज्म को रोकने के लिये जमींदारी का खात्मा जरूरी है। मैं यह कहता हूँ कि जहाँ एक तरफ जमींदारी का खात्मा जरूरी है वहाँ दूसरी तरफ मैं यह भी कह सकता हूँ कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए सिर्फ जमींदारी का खात्मा ही जरूरी नहीं है इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी हम कम्युनिज्म को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम अवाम के सामने रखना पड़ेगा जिसको वह यह खयाल करे कि यह कम्युनिस्टों के प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह निहायत जरूरी है कि हम ऐसा तरीका अस्तियार करें कि जिससे कम्युनिज्म हमारे सूबे के अन्दर न फैले। मैं इसको बुरा समझता हूँ और इसकी मुखालिफ़त करता हूँ लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अगर हम कोई इस किस्म का फैल करते हैं जो हमको कम्युनिज्म

के करीब न जाना है तो करीब जाने के मानी यह है कि एक रोज ऐसा आयेगा कि हम उनके अमल करने पर मजबूर होंगे। जहाँ तक कम्यूनियज्म के उन्नों का ताल्लुक है वह ऐसे उन्नों हैं जिनकी वजह से हमको अपनी तमाम तारीख से बिल्कुल अनेहदा हो जाना पड़ेगा। मगर हमें इस जमाने के अन्दर यकीन है कि अगर इंमानियन के तरीके से, ग्राफन के तरीके से और प्राइवेट प्रापर्टी को बरकरार रखने हुए जान चाना चाहें तो चल सकता है और कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने सूबे के अन्दर कम्यूनियज्म को फैलने दें। मैं यह यकीन रखता हूँ कि यह जमाना जम्हूरियन का है और हम जम्हूरियन के उन्नों को अपना रहे हैं। मैं यह भी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत दरअमल हमारी है और वह जम्हूरियन के उन्नों की महारिज है लेकिन अगर हमारी हुकूमत गलती करती है तो हमारा फर्ज है कि उसे सुनवाई करें कि वह गलती कर रही है और हुकूमत का फर्ज है कि उसे उस आत्मी की बात, चाहे वह पार्टी से ताल्लुक रखता हो या न रखता हो, सुनना पड़ेगी। अगर हुकूमत गलती करेगी तो इस सूबे के ६ करोड़ आदमियों पर उसका असर पड़ेगा। जहाँ तक कि जमींदार और काश्तकार का सवाल है दोनों की ही यह हुकूमत है। मैं पूछता हूँ कि अगर एक तबके को तकलीफ होती और जम्हूरी उन्नों को मानने हुए इस मुल्क को एक यूनिट की हैसियत देना पड़ेगी तो क्या उस तबके की तकलीफ रफा करना सरकार का फर्ज नहीं होगा। जैसे जिस्म है और उसके एक हिस्से को काटा जाता है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। मैं इसी तरह से कम्यूनियज्म के फोड़े की मिसाल लेता हूँ कि वह फोड़ा पका हुआ है और हम उसका आपरेशन करना चाहते हैं तो यकीनन जिस्म के हर हिस्से में दर्द होता है लेकिन मजबूरी है कि उसका आपरेशन करें ताकि उसका असर और जहर जिस्म के अन्दर न फैले।

अब मुझे यह अजें करना है कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि छोटे और बड़े जमींदारों में कोई फर्क नहीं करना चाहिये। जहाँ तक कि मुआविजे का सवाल है, इसे जमींदारों और हुकूमत दोनों को मिलकर तय कर लेना चाहिए, और जिस नतीजे पर ये पहुँचें उस पर अमल करने के लिये काश्तकार तैयार हैं। यह कहना कि बड़े जमींदारों को मुआविजा कम दिया जाता है या छोटे को ज्यादा, बिल्कुल फिजूल है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वह मुआविजा इतना भी नहीं है कि एक छोटा जमींदार जिसकी मालगुजारी ५० या १०० रु० है, वह एक ड्रैक्टर भी खरीद करके आइन्दा खेती कर सके और अभी हुकूमत भी बहुत अरसे तक इस काबिल नहीं हो सकती है कि वह आम तरीके से, कोआपरेटिव सिस्टम के तरीके से फार्म्स बनाकर तमाम लोगों को उस पर लगा सके। मैं समझता हूँ कि देहात के काश्तकार इसके लिये तैयार न होंगे कि उन्हें बजाय काश्तकारी के और किसी मजदूरी के काम में लगाया जाय। इसलिये बेहतरीन मूरत यही हो सकती है कि जमींदार और काश्तकार के मामले को हुकूमत

[ श्री मुहम्मद रज़ा ख़ाँ ]

तय कर दे और जो मुआविजा हुक्मत तय करे उसे काश्तकार अदा कर दे। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि काश्तकार से एक तरफ यह कहा जाय कि वह ज़मींदार या भूमिधर होगा और दूसरी तरफ उसकी मिलिकयत न मानी जाय, या हुक्मत यह कहे कि ये कौमी मिलिकयत बना दो गई है। मैं कहता हूँ कि कौमी मिलिकयत तो तमाम हिन्दुस्तान ही है। वह ज़माना गुज़र गया जब कौमी मिलिकयत का सवाल अँगरेजों के मुकाबिले में पैदा होता था, आज तो हर चीज़ कौमी मिलिकयत है। तो यह सवाल पैदा करना कि हर चीज़ कौमी मिलिकयत बना दिया जाय, मेरे खयाल में मुनासिब नहीं मामूली होता। प्राइवेट प्रापर्टी का हक किसी तबके को न देना मेरे खयाल में बड़ी गलती होगी।

छोटे काश्तकार के मुताज़िक मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि १० एकड़ तक का काश्तकार ऐसा काश्तकार है जो अपने बच्चों के खाने के लिये और कपड़े के लिये भी पूरी आमदनी नहीं पैदा कर सकता है। इस गरानी के ज़माने में भी वह तकलीफ महसूस करता है। इसी तरह वह काश्तकार जो २५ बीघे का काश्तकार है, वह भी अच्छी हालत में नहीं है। बदकिस्मती से हमारे सूबे की हुक्मत और हमारे हिन्दुस्तान की हुक्मत यह महसूस करती है कि इस वक्त देहातों के काश्तकारों के पास रुपया बहुत है, और टैक्स की सूरत में या दूसरी वजह से उसे ले लें। मैं हुक्मत को यकीन दिलाता हूँ कि देहातों के अन्दर इस वक्त इसी प्रोक्योरमेंट में काश्तकारों को और ज़मींदारों को बहुत तकलीफ हुई है। मेरे जिले में ही गल्ले की पैदावार कम हुई और दूसरी बात यह थी कि जो पैदावार हुई थी वह अच्छे किस्म की नहीं थी, गेहूँ पतले हो गये थे। बहुत से लोगों ने अपने मवेशी बेचकर, अपने जेवरों को बेचकर गल्ला दिया है और अपनी हुक्मत के हुक्म की तामील की है। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों के लिये ऐसे तरीके अख्तियार किये जायँ जिनसे वे सही तरीके पर काश्तकारी पेशे से महरूम न हों। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को खेती से महरूम करना जायज़ न होगा। इसके लिये यह तरीका मुनासिब होगा कि अगर वह लगान अदा न करें तो उसकी कुछ ज़मीन को पट्टे पर दे दिया जाए जैसा कि पहले किया करते थे, लेकिन हक नीलाम का इसमें रखना मुनासिब नहीं है क्योंकि इससे तमाम फ़ायदे सरमायेदार ही उठायेंगे। और तमाम ज़मीनें कुछ अर्से के बाद सरमायेदार, तबक्के के पास चली जायँगी काश्तकार लोग गरीब हो जायँगे और मज़दूर हो जायँगे। मैं इस तरीके को नापसंद करता हूँ। मेरे खयाल से यह बात बहुत मुनासिब नहीं है। कुछ काश्तकारों की बेदखली की रोक की गई है लेकिन अगर ५ बरस तक इन काश्तकारों की बेदखली की रोक की गई तो बाकी जो बारात हैं वे सब ख़राब हो जायँगे। काश्तकार लोग बागों को काट लेंगे और नतीजा यह होगा कि वे बेदखल भी न हो सकेंगे और बाकी बारात ख़राब हो जायँगे। मुझे यह भी अर्ज करना है कि काश्त से मुसत-स्ना होने की दफ़ा की सख्त ज़रूरत है। इस बिल में ऐसा रक्खा तो गया है लेकिन

बुड़े, अंग्रे नूने और नंगड़े करनकरों को जेनी से मुनतस्ता करना चाहिये। अगर उनको मुनतस्ता नहीं किया जायगा तो मेरे ख्याल में एक बहुत भारी खानी इन विल में रह जायेगी। मैं एक बात और हुकूमत से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस विल कोई ऐमा तर्का नहीं किया गया है कि हिन्दोस्तान के यहूदी लोग अपनी दरकात से बाज्र आ जायँ। मेरा ख्याल है कि इन विल में ऐसी कोई दका जरूर होनी चाहिये मैं यह देख रहा हूँ कि जब कि पड़िने-१ रु० संकड़ा सूद लिया जाना था लेकिन वह अब बढ़ कर एक आना रुपया महीना हो गया है यानी एक रुपये पर १०० आना सूद हो गया है और जहाँ चीजों की गिरानी हुई है वैसे इस मूद की गिरानी बहुत तक्रनीक देह हो गई है लेकिन मुशी इस बात की है कि काश्तकार लोग उसको समझ गये हैं और उससे बचने की काशिश करने लगे हैं। इस साल में मनी आर्डर्स बहुत ज्यादा हुये हैं। जो वह सूद १ रुपये पर १०० आना लत थ अब उनको नतीआर्डर्स की वजह से बहुत कम मौका मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि ऐसे तबके को रोकने के लिये हुकूमत की तरफ से कुछ किया जाना चाहिये। इस विल के अन्दर ऐसी दका कराहम करना चाहिये कि जिससे यह तबका गरीबों का खून न चूस सके। दुनिया के अन्दर जो नए निजाम या आईन आने हैं या अख्तियार किये जाते हैं लोग उससे हमेशा डरा करते हैं। बात कुछ ऐसी है—

“आईने नौ से डरना, तरफे कोहन पे अड़ना,  
मज्जिल यही कठिन है कौमों की जिन्दगी में।

मैं समझता हूँ कि जमींदारी को खत्म करना और काश्तकारों के लिये नये हुकूम देना कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें इतनी दिक्कत पैदा हो कि जो लोगों को महसूस हो। अलवत्ता ऐसी बात जरूर है कि जो बड़े बड़े रहस हैं, जिनकी यकीनन् बहुत बड़ी आमदनी थी वे उस आमदनी से महसूस रह जायेंगे। यह मुमकिन है कि उनका दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ तक आम जमींदारों का ताल्लुक है जमींदार भी गवर्नमेंट के हैं, जमीन भी गवर्नमेंट की है और काश्तकार भी गवर्नमेंट के हैं।

तो मैं कहता हूँ—

दिल तुम्हारा है, जाँ तुम्हारी है,  
बोलो दोनों में किसकी बारी है।

जहाँ तक हुकूमत करने का सवाल है मैंने कहा है कि हुकूमत जम्हूरियत की मुहाफिज है। बाज्र बातें इस किस्म की हुई हैं कि जिनसे यह ख्याल होता है कि हुकूमत बाज्र मामलात में सही तरीका अख्तियार नहीं करती। अब वह गुजिस्ता जमाना नहीं रह गया जिसमें लोगों का एजीडेशन और उनका गुस्सा हुकूमतों को बहुत ज्यादा परेशानी में डाला करता था। अब तो हम एक जम्हूरियत और जम्हूरी हुकूमत बना चुके हैं। मैं अपनी हुकूमत से पछने का मुस्तहक हूँ कि आप हमें

[ श्री मुहम्मद रज़ा खाँ ]

बतलायें कि आप इस सूबे के ऊपर कलम से हुकूमत करना चाहते हैं या बन्दूक से। आप वोटों के भरोसे पर हुकूमत करना चाहते हैं या कौजों के। मैं इसका जवाब खुद देने का गुस्तहक नहीं हूँ। मेरी राय में इसका जवाब हुकूमत को अपनी अक़ल से देना चाहिये। जहाँ तक कि हालात का तकाजा है, हुकूमत यह देख रही है कि उसको अब क्या तरीका अख्तियार करना चाहिये। मैं हुकूमत से यह उम्मीद करता हूँ कि वह ऐसे तरीके अख्तियार करेगी जिनसे जम्हूरी उसूलों को तत्कबियत हासिल हो। अगर उसने ग़लती की तो यकीनन हम और हुकूमत दोनों मुश्किलत में मुस्तज़ा हो जायेंगे। मुझे कुछ और अज़े करना नहीं है।

श्री भगवानदीन मिश्र—श्रीमन्, जो जमींदारी उन्मूलन बिल तथा भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार कई दिन से जारी है और जिस पर श्री जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने एक संशोधन भी पेश किया है कि ३१ दिसम्बर तक यह स्थगित कर दिया जाय उस पर भवन में हमारे बहुत से सदस्यों ने अपनी सम्मतियाँ प्रकट कीं। इस समय हर बात पर मैं भवन का समय नहीं लेना चाहता। केवल दो-चार आवश्यक बातें भवन के सामने रख देना उचित समझता हूँ।

पहली बात तो यह है कि ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को इस भवन ने यह प्रस्ताव पास किया था कि सूबे में जो जमींदारी प्रथा एक अर्से से जारी है और जिससे किसानों का शोषण चल रहा है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं और उस समय से लेकर आज तक कुछ असुविधाओं के कारण और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यह बिल हाउस के सामने नहीं आ सका। लगभग तीन वर्ष हो गये। ऐसी अवस्था में सूबे के अन्दर एक बहुत बड़ी हलचल तथा बहुत बड़ी भावना, यह चल रही है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात भवन में आकर भवन के द्वारा पास होकर तीन वर्ष हो चुके, अभी तक खत्म नहीं हुई। जिसकी प्रतिक्रिया यह हो रही है कि जमींदारी के कारण बहुत से किसान बुरी तरह से सताये भी जा रहे हैं। इस पर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। यह ध्यान में रखने की बात है इसलिये मैं समझता हूँ कि अब इसको पुनः स्थगित करने का जो संशोधन है वह किसी तरह मान्य और उचित नहीं है। जहाँ तक जमींदारी प्रथा के पुराने और नये होने की बात है मैं समझता हूँ कि उसके अन्दर बहुत ज्यादा वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं। पुरानी प्रथा हो या नई प्रथा हो, मैं तो यह कह सकता हूँ कि हमारे वैदिक काल में जमींदारी प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। किसान ही पृथ्वी का स्वामी माना गया है, यह मनु के वाक्य हैं। इसी के साथ साथ राज का अंश रक्षा करने के लिहाज़ से छठवाँ हिस्सा शाखा में बताया गया फिर भी मैं कहता हूँ कि एक अरसे से यह प्रथा चली आ रही थी। लेकिन इस प्रथा को पुनर्जीवन करके यहाँ की रड़नेवाली जनता का शोषण करने में धीरे धीरे जमींदार भाइयों को मजबूत किया और जिसकी वजह से आज यह आवश्यक हुआ कि

जनतन्त्र राज्य में ऐसी जगह पर एक मिनट के लिए भी रहना अनुचित नहीं है। ऐसी अवस्था में हमें क्या हो जाने में दोष है? मैं देखता हूँ कि भवन के प्रायः सभी सदस्यों ने इस बात को यह कहा है कि यह क्या कुछ मनमं होना ही चाहिये। यह बात अवांछनीय है कि इनके अन्दर जो व्यवस्था रखी गई है, उसमें भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं। जहाँ तक इनमें प्रतिस्पर्धा देने की बात है, उसमें बातों में भी भिन्न-भिन्न मत हैं। लेकिन सभी ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि प्रतिकार देना भी आवश्यक है की, क्रिया देना चाहिये और क्रमेण देना चाहिये। इस पर भिन्न-भिन्न रायें अवश्य हो सकती हैं लेकिन प्रतिकार देने की विन्यास में ऐसी व्यवस्था की गई है वह बहुत लोच समझकर की गई है और छोटे-बड़े सभी का ध्यान रख कर की गई है। निश्चय मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रतिकार देने की व्यवस्था की गई है वह सर्वथा अनुचित है। प्रतिकार देने में एक बात में अवश्य कहना चाहना है और वह बात कई बार भवन के सानने किमी न किसी स्तर पर आ चुकी है। छोटे-जमा-दार होने का जो स्वत्व है, उस स्वत्व के कारण (उन अधिकार के कारण) आज जनतन्त्र राज्य की सरकार भी उनको प्रतिकार देना उचित समझती है। ऐसी अवस्था में सन १९५७ ई० में जो क्रान्ति हुई और जिस क्रान्ति में हमारे राजे महाराजे शामिल हुये जिनकी जायदादें अंगरेजों ने हड़प कर लीं आज मैं समझता हूँ कि यह शुभ अवसर है, जब उनके ऊपर भी विचार किया जाय। जब आप प्रतिकार देने की बात करने हैं, तो आपको विचार करना चाहिये कि कहाँ तक इन जायदादों में उनका हिस्सा है जिनकी जायदादें अंगरेजों ने हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करनेवाले लोगों को दी थीं। उनका कितना हिस्सा होना चाहिये इस पर हमारी सेलेक्ट कमेटी को अवश्य विचार करना चाहिये।

दूसरी बात हमारे भाई रोशन जमा साहब ने वक्फ और ट्रस्ट के बारे में कही। उन्होंने गवर्नमेंट पर यह आक्षेप किया कि शायद महन्तों से आचार्य जो के चुनाव में यह वादा किया गया है कि आपकी जायदादें सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए वक्फ और ट्रस्ट को इस विन्यास में पूरी पूरी सुविधा दी गई है। मैं तो यह कहता हूँ कि यह आक्षेप बहुत ही हास्यास्पद है। ऐसी बात कहना किसी तरह उचित नहीं है। एक उचित सी बात को भी अनुचित बताकर पेश करना उचित नहीं कहा जा सकता। वक्फ और ट्रस्ट के लिए अगर हमारी सरकार कोई सुविधा न रखती तो शायद हाउस के सभी मेम्बरान यह कहने के लिए तैयार होते कि यह तो बड़ी ज्यादाती है। मैं भी यह कहूँगा कि इसमें वक्फ और ट्रस्ट के लिये जो सुविधा रखी गई है वह उचित है परन्तु इसमें एक बंधन लगाना आवश्यक है। वक्फ और ट्रस्ट की जायदाद का उपभोग जिस तरह से हमारे महन्त और मुस्ला कर रहे हैं वह अवश्य संशोधन करने के योग्य है।

इसमें जो प्रतिकार दिया जाय किसी तरह व सख्त न कर सकें। विला डिस्ट्रिक्ट



[ श्री भगवानदीन मिश्र ]

जज की अनुमति के खर्च करने का अधिकार न हो। दूसरे जो सालाना खर्च बकक और ट्रस्ट को दिया जाय उसका हिसाब और देख-रेख सरकार को अवश्य अपने अधीन रखना चाहिए जिससे वास्तव में ट्रस्ट करनेवालों की आत्मा को शांति मिले और समाज में उसका स्थान हो और ठीक सुधार हो सके। उसके अतिरिक्त म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया के बारे में इस बिल में कहा गया है कि इन पर अलग कानून लाने की आवश्यकता है जिनका कृषि से संबंध है। मैं निवेदन करता हूँ कि जो बातें शहरों में देखने में आती हैं जो नाजायज टैक्स वसूल होता है किस तरह जमीनों की बिक्री होती है किस तरह लोगों को तंग किया जाता है, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो जमींदारी अधिकार म्युनिसिपैलिटी के हैं जिस तरह आपने गाँव सभा के अधीन जितने परती तालाब, जितनी ऐसी सर्व उपयोग की चीजें हैं वह चीजें गाँव सभा के अधीन कर दी गई हैं। इसी प्रकार शहरों के अन्दर, नोटीफाइड एरिया के अन्दर जो ऐसी सम्पत्ति है जिनका सार्वजनिक सम्बन्ध है उस सम्पत्ति का अधिकार चुने हुए बोर्डों को दे देना आवश्यक है। उसका तरीका एक तो यह है कि मैं देखता हूँ कि उसके अन्दर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनमें केवल आदर्श की दुहाई दी गई है और वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं देखता हूँ कि जमींदारों के लिये सीर और खुदकाशत की जो जमीनें हैं वह दी गई हैं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। बाग दिए गये हैं, ठीक है। दिए जाना चाहिये। कोई बजह नहीं है कि अगर एक ग्रूप को हटा रहे हैं तो उनके प्रति ऐसी भावनाएँ रखें कि वह अपनी बसर का अच्छा प्रबंधन कर सके। यहाँ आपने अवश्य रक्खा है कि जो सीर और खुदकाशत है उनको मिलेगी। वास्तव में सीर और खुदकाशत वास्तविक रूप में उनकी जोत में है। इस बात की देखरेख और छान-बीन करना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि जितनी जमीनें जमींदार भाइयों की हैं। ६५ फीसदी ऐसे लोग हैं जिनका रेकार्ड में नाम है और किसान जोते हुए हैं। वह सारी सीर और खुदकाशत देने के लिये तैयार हैं आपको यह भी विचार करना है कि अब तक जो बड़े किसान हैं जिनकी जोत में अधिक जमीनें हैं और वास्तव में हैं, इसी ख्याल से सरकार ने शिकमी देने का अधिकार दे रक्खा है। शिकमी अधिकार का फायदा उठाया है उनको आपको एक और अवसर और मौका देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि शिकमी काशतकारों को हटाकर उनको बिला जीविका और बिला भूमि का बना दे। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भलना न चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि नौकरी पर हैं, जेल चले गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास धन की कमी है। बैल नहीं रख सकते। अगर उनकी जमीन लेंगे तो उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजा बन्द करते हैं। इसके साथ साथ जिनका जीवन निर्वाह केवल खेती से होता रहा है। उसके अलावा कोई साधन नहीं है। उनके लिये इतनी सुविधा दें जितनी एक परिवार के लिए जमीन

अवश्यक होती है. उनकी जमीन न हो. तो उसकी व्यवस्था की जाय। ऐसा न करना अन्याय होगा. ज्यादानी होगी।

उनको भी देना मैंका आपको मेलेक्ट कमेटी के सामने जिस समय यह बात विचार के लिये आये देने का अवसर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त एक और बात है और वह यह है कि मैं कह सकता हूँ, सम्भव है कि उन्हाहीं जिनों में इस बात की सम्भावना न हो लेकिन हमारे पूर्वा जिनों में आन तौर से यह है कि एक तो अजबान बन करनेवाला आदमी वैसे ही नहीं मिलता, दूसरी बात यह है कि कोई भी किसान जो भी आदमी हलवा हा या मेहनतदार रखना है तो उस किसान के लिये यह मसला होता है कि उसको नौकरी पर रखने के लिये वह उनके लिये खेत की भी व्यवस्था करे और खेत भी वह ज्यादातर किसान के ही हल बैन से जोतकर बोया करता है। आज अगर आपने यह व्यवस्था कर दी कि जो काश्तकार शिकमी जोतना है वह करतकार फिर असली काश्तकार बन जायेगा। अगर यह व्यवस्था आप सब जगह लागू करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि एक बार मैंने किसी आदमी को हलवाही के सिलसिले में ५ बीघे जमीन दे दी तो वह उसकी हो जायगी और अगर इसके बाद दूसरा आदमी रखता हूँ तो फिर ५ बीघे जमीन उसके पास चली जायगा। इनका परिणाम यह होगा कि अन्त में हम कृषि-हीन होकर इतस्ततः भटकते फिरेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम ऐसी अवस्था में न पहुँच सकें। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कुछ जगहों में धार्मिक आधार पर सामाजिक बन्धन ऐसे हैं जिनकी वजह से कुछ लोग खेत का सारा काम करते हैं, कुदाल चलाते हैं, खेत काटते हैं, खेत बोते हैं लेकिन वे हल नहीं पकड़ सकते, वे हल नहीं जोत सकते। आज भी इस तरह की सामाजिक प्रथा मौजूद है। हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि यह बुरी बात है। हो सकता है कि कुछ लोग यह कहें कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन यह वास्तविक सत्य है कि धार्मिक आधार पर सामाजिक जो रीतियाँ चली आयी हैं उनके आधार पर बहुत जातिथों के लोग ऐसे हैं, जो खेती के सब काम करते हुये भी हल नहीं जोत सकते हैं। अब अगर यह कहा जाय कि जो खुद नहीं जोतेगा उसकी जमीन नहीं होगी तो अव्वल तो आपकी जो ग्री मोर फूड की स्कीम है जिसके जरिये आप कृषि के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, नये तरीके से हल जोतना सिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से चार वर्ष में वे हल जोतना सीखेंगे। फिर आप पैदावार कैसे बढ़ा सकेंगे? इसलिये मैं यह समझता हूँ कि विचार करने के समय इतनी सुविधा अवश्य देनी चाहिये कि फी हल ५ बीघा या जो आप उचित समझें उनको देने का आदेश दिया जाय जिसके आधार पर वे अपनी खेती को अच्छी तरह से करा सकें। यह कोई जिद करने की बात नहीं है, यह आदर्श के विरुद्ध बात नहीं है और वह इस शर्त के साथ है कि जो शिकमी काश्तकार हैं, जिनके पास जमीनें हैं वे पन्द्रह गुना देकर भूमिधर बन जायेंगे, लेकिन जो केवल इसलिये कि वह

[ श्री भगवानदीन मिश्र ]

किसान का काम करता है या जमींदार का काम करता है इसलिये उसको ५ बीघा या दस बीघा जो भी उचित समझें इस शर्त पर देना चाहिये कि जब तक वे काम करेंगे वह जमीन उनकी रहेगी। किन्तु इस कारण यदि वे जमीन से अलग हो जायँ और उनके पास जमीन न रहेगी तो हो सकता है कि वे कोई ऐसा पेशा अख्तियार करें जिससे समाज को हानि पहुँचे, क्योंकि वे लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं होंगे। उनके लिये आपको ऐसी सुविधायें देनी चाहिये जिससे वे कोई गलत काम न कर सकें। मैं आपको उदाहरण के लिये यह कह सकता हूँ कि मान लीजिये कि किसी के पास दो बैल हैं और ऐसी अवस्था आ गयी कि एक बैल मर गया। आज बैल की कीमत एक हजार से कम नहीं है। तो जो बैल नहीं खरीदेगा वह या तो अपनी जमीन को परती डाले और परती डालने पर वह अपना और राष्ट्र का नुकसान करेगा क्योंकि इससे उत्पादन कम हो जायगा और इसलिये किसान स्वभावतः इस बात के लिये विवश होगा कि वह अपनी जमीन किसी दूसरे को उठा दे। लेकिन वह जमीन इस ढर से नहीं उठायेगा कि हमारी जमीन छिन जायगी। ऐसी सूरत में उसके लिये कोई ऐसी सुविधा अवश्य रखनी चाहिये जिससे अगर ऐसी आपत्ति आ जाय जिससे वह मजबूर हो जाय तो उसे साल भर या दो साल का जैसा भी आप उचित समझें एक ऐसा मौका दें जिससे वह अपनी किसानी को फिर सँभाल सके।

इन बातों पर जो आवश्यक बातें हैं उन पर मैंने अपने विचार प्रकट कर दिये। इसके अलावा कुछ और बातें कही गई हैं जैसे कि हमारे श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह जी ने कहा था कि अब तो जमींदार के बजाय भूमिधर बन रहे हैं और उसके भी वही माने हैं और वह बजाय २० लाख के १ करोड़ के तादाद में बन रहे हैं। लेकिन मैं राजा साहब से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो भूमिधर बन रहे हैं वह भूमिधर ऐसे भूमिधर बन रहे हैं जो अपने स्वत्व की रक्षा करके अपनी आर्थिक परतन्त्रता से छुटकारा पा करके आर्थिक स्वतंत्रता में अपने स्तर को ऊँचा बनायेंगे। वह जमींदार जो जनता का शोषण करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहे हैं उस जमींदारी प्रथा का अन्त होने के बाद हर काश्तकार अगर अपनी जमीन का मालिक बनता है, तो यह बड़े सुअवसर की बात है।

इन शब्दों के साथ मैं राजा साहब के संशोधन का विरोध करता हूँ और बिल का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूँ।

**श्रीमती इनाम हबीबुल्ला—**ई चे शोरेस्त कि दर दौरे कमर मी बीनम। जनाब सदर अगर यह जंग और यह बहस मुबाहिसा और यह बातें सरमायेदारी के खिलाफ होती तो मुझे बड़ी मसरत होती और दिली खुशी होती। जमाना बदल रहा है, हालत बदल रही है, मुल्क की हालत तबाह हो रही है ऐसे वक्त में जो मुल्क को बरबाद करनेवाले हैं अगर उनके साथ यह जंग होती तो मैं निहायत मसरत के साथ इसमें शरीक होती, लेकिन अफसोस है कि यहाँ चीज

कुछ अगर हो दिन्दाइ देनी है आज यह हो रहा है कि उन लोगों के साथ यह सब किया जा रहा है जिनके साथ हजारों इन्सानों की जिन्दगी बावस्ता है गो कि उनमें बुढ़ाई भी थी मैं यह नहीं कहना हूँ कि इन्सान में बुढ़ाईयाँ नहीं होती। मुझमें और आरमें कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कह सके कि वह बुढ़ाई से बालातर है लेकिन उसकी बुढ़ाई की जा सकती है। तो इसी तरह से उन्हें भी बुढ़ाई बनाना जा सकता है किमी मरीज की हालत इस तरह से बेहतर नहीं बनई जा सकती कि उसका गला ही काट दिया जाय तभी वह सेहत पा सकता है मैं तो यह समझती हूँ कि सिर्फ जमींदार ही नहीं बल्कि हजारों इन्सान की जिन्दगी उनसे बावस्ता है जहा पर किमी को कोई मुलाजिम नहीं मिला, हिन को कोई काम नहीं मिला तो वह किमी रियासत में चला गया वहाँ उसकी परवरिश हुई उसके बाल बच्चे बड़े और पढ़े। लेकिन इतने दिनों में मैंने कभी नहीं सुना किमी साहब ने एक लफ्ज भी उनके बारे में कहा होना जो उनमें अच्छाईयाँ हैं और किमी की जवान पर कभी एक लफ्ज भी उन लोगों के बारे में नहीं आया जो आज मुल्क को तबाह कर रहे हैं और व्जेक माफ्टिंग के जरिय से मुल्क को बरबादी की तरफ लिये जा रहे हैं उनके खिलाफ आज तक मैंने नहीं देखा कि इस ऐवान में किमी ने एक लफ्ज भी कहा हो कि हमारी हाजत को ये लोग किस तरह से तबाह कर रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ क्या कायबाही करनी चाहिए। मैं तो यह समझती हूँ कि इस हुकूमत का सबसे पहला काम यह है कि इन तबाह करनेवालों के खिलाफ जो आज मुल्क को भूखा मार रहे हैं और भख से तबाह कर रहे हैं इनके खिलाफ इन्तजाम करे और फिर यह देखे कि इन्तजाम जमींदारी का किस तरह से किया जाय। लेकिन सबसे पहले जो जहोजहद इस ऐवान में हो रही है वह यही कि जमींदारों की हालत को बदतर से बदतर और बुरी से बुरी करके दिखाया जाय और ग्यौफनाक मूरत बनाकर उनको लोगों के सामने पेश किया जाय। उसमें सिर्फ आपका नफा है। आप अपने बोट के खातिर लोगों की तबाही और बरबादी का खयाल नहीं कर रहे हैं और उनको बरबाद होने देखना चाहते हैं। आखिर यह लाखों इन्सान कहाँ जायेंगे कि जिस वक्त यह जमींदार तबाह हो जायेंगे और वह लोग बेचारे वहाँ से निकाल दिये जायेंगे, उनके बाल-बच्चों का क्या होगा वह कहाँ जायेंगे। वह अपनी परवरिश कैसे कर पायेंगे। क्या आप यह नहीं सोचते हैं कि वह मजबूर होकर वह चीज भी करने को तैयार हो जायेंगे जो आपके लिये बहुत नुकसानदेह और खतरनाक साबित होगी क्योंकि इन्सान मजबूरों हाजत में सब कुछ करने को उत्तारु हो जाता है। इस वास्ते इस वक्त हर एक चीज का मोचकर और बहुत समझकर करना चाहिये। हमारा मुल्क इन वक्त मुमीबत के दौर से गुजर रहा है बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिये। मैं तो यह समझती हूँ कि काश्तकारों की

[ श्रीमती इनाम हबीबुल्ला ]

बाबत जितना आप लोग बतलाते हैं कि उनके ऊपर जमींदारों ने इतने मजालिम किये हैं। मगर ऐसा नहीं है मुद्दे सुन्न गवाह चुस्त। अस्त तो यह है कि उस वक्त जमींदारों ने अपने काश्तकारों के साथ वह बरताव नहीं किया, जैसा कि उनके साथ अब किया जा रहा है और आप लोग जबरदस्ती उनको तैयार कर रहे हैं कि वह इस चीज के लिये तैयार हो जायँ, जो मुल्क के लिये निहायत खतरनाक और नुकसानदेह है। काश्तकारों से कहा जाता है कि तुम्हारे दर्द को दूर किया जा रहा है। जमींदारी को मिटाकर तुम्हारे लिये जन्नत बनाई जा रही है। जहाँ पर दूध की नदियाँ बहेगी, बेक्री का आलम होगा, जहाँ पर अमनचैन होगी। मगर, जनाब, यह हवाई महल बनाकर उसको पूरा न करना एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा। यह समझ में नहीं आता कि काश्तकार बेचारा भोलाभाजा जो अभी तक इस इन्तख़ाब के भगड़े में कभी पड़ा नहीं, वह आसानी के साथ अपनी गुजर-बसर कर रहा था। जमींदार के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना बरताव रखता था, इसलिये कि वह उनका सरपरस्त था, वह दुख, सुख और अच्छाई-बुराई हर एक चीज में हमेशा शरीक रहता था और उनका वह साथी था। उनको अब मैं समझती हूँ कि अब मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में तब्दील किया जा रहा है, इसलिये कि लगान माफ़ नहीं किया गया है। लगान तो उनसे ही वसूल किया जायगा। लेकिन उसका तरीका मुमकिन है दूसरा हो, और तो कुछ नहीं हो सकता है। १० साल का लगान अगर वह अदा कर देगा, तो वह भूमिधर हो सकता है, उससे उसको फायदा हो सकता है। लेकिन जिसके पास रुपया नहीं है, तो वह १० साल का लगान किस तरह देगा, यानी वह उन हकूक से महरूम रहेगा। बरखिलाफ़ इसके अगर काश्तकार जमींदारान को अपना लगान अदा नहीं करते थे, तो जमींदार उनका लगान मुआफ़ कर देते थे। उनकी शादी-विवाह में मदद होती थी, उनकी तकलीफ में और उनकी राहत में जमींदार हमेशा शरीक रहता था। इस एवान में कभी उसकी बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया कि जमींदारों ने काश्तकारों के लिये क्या-क्या भलाइयाँ कीं। अब उनको इस चीज से महरूम किया जा रहा है। वह लगान अपना देंगे। मगर यह कि उसकी अदायगी उस तरह से नहीं होगी, उनके साथ वह बरताव नहीं होगा। आपके तहसीलदार वगैरा अब वहाँ होंगे, जिनके साथ उनकी हमदर्दी होना मुश्किल है। और फिर आप कैसे यक़ीन कर सकते हैं कि उसका बरताव उनके साथ वैसा होगा, जैसा कि अभी तक जमींदार करते आए हैं। यह नए लोग होंगे जिस तरह का बरताव करेंगे, जिस तरह से मेहरबानी करेंगे, जिस तरह से वह तकलीफ देंगे, इसका किसी तरह से पता भी आपको नहीं लग पायेगा। आप देखते हैं कि आजकल मुल्क की क्या हालत हो रही है। रिश्तसतानी से दुनिया खोज उठी अगर है। पब्लिक नीम जान है। अगर उसने १० साल का लगान अदा नहीं किया, तो उसको कोई अख्तियार उसको बेचने वगैरा का हासिल नहीं होगा, यानी वह कुछ बक्त

के बाद छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में नकलीम होकर खत्म हो जायगी। दफा २३० की रु से बड़े भूमिधर और सौरदार मजदुर और इनकरादी हैंदियत से गाँव के कुल मालगुजारी के जिम्मेदार होंगे। अगर एक कारनकार की मालगुजारी अदा नहीं हुई, तो दूसरे से वसूल की जायगी। इनके मानो यह है कि एक के पास रुपया है तो उससे एक मर्तबा अदा करने के बाद फिर दूसरी मर्तबा दूसरों की मालगुजारी भी जबरदस्ती अदा करती होंगी और जिस नारेइन्द ने आपको नहीं दिया हुकूमत को नहीं दिया उससे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह किसी दूसरे शख्स को नसबूत भूमिधर को या किसी दूसरे सौरदार को दे देगा। निहाजा नहीजा यह होगा कि सिवाय इसके कि वह मुकदमा लड़े, वहाँ दूसरों के सामने या आपके सामने फिर चाराजोई करे और फिर भी वह कामयाब हो या नाकामयाब हो सब उसके सर पर है। अतःवना आपके जो कारिन्दे हैं उनके लिये एक बहुत उम्दा रास्ता खुल जायगा, एक उम्दा चीज हाथ आजायगी, कि वह जिस तरीकेसे चाहें उन गरीब लोगों के ऊपर ज्यादाती करें और उनकी भी सुनवाई कुछ नहीं होगी तो यह तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं वह इस बक्क नानौजू हैं। उनको आप थोड़े दिन के लिये मुल्तवी कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वक्त तमाम हुकूमत और मुल्क की क्या हालत रही है इसका तो पहले देखिये, तब आप इस चीज को लाइये अभी आपने पंचायत राज्य कायम किया है। एक साथ ही जमींदारों को उनके हकूक से महरूम कर देना कहाँ का इन्साफ है। अभी आपको यह भी नहीं मालूम है कि पंचायत राज के नतायज क्या होंगे, उसका हश्र क्या होगा। लेकिन हमारे ऐवान के मेम्बरों को तो यह है कि नहीं, जिस तरह से हो, इसी वक्त यह गला काटें। अगर इस वक्त यह गला नहीं कटा, तो कोई मौका नहीं आयेगा। चाहे अपने ऊपर कुछ भी गुजर जाय, लेकिन इसी वक्त यह सब करना चाहिये। मैं समझती हूँ कि यह तो अर्जब आलम है, इस वक्त यह किसी तरह मुनासिब नहीं है।

दूसरे मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यह तो कोई इन्साफ की बात नहीं है कि एक को आप कम्पेन्सेशन का रुपया ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे को कम, यानी एकसा धर्नाब नहीं है। आपको किसी और चीज से क्या वास्ता? आपको तो सिर्फ अपने इन्साफ से और अदल से मतलब होना चाहिये। आपको तो यह करना चाहिये कि हरएक शख्स को जो बाज़ार का निख है, उसी के मुताबिक कम्पेन्सेशन अदा करना चाहिये, जैसा कि आपने भूमिदारों से यानी आधी मालगुजारी १० गुना लगान लेना वै किया है। हुकूमत की निगाह में हर शख्स बराबर है। हरएक छोटा बड़ा आपकी नज़र में एक होना चाहिये। आपके हाथ में हुकूमत है, ताकत है, जैसा आप चाहेंगे, वैसा आप करेंगे लेकिन आपका इन्साफ का तराफ बुजन्द होना चाहिये, आपको सबको बुलन्दी से देखना चाहिये कौन कैंसा है, किसी के घर में क्या है, इसकी तरफ आपको नहीं देखना चाहिये। आपको बुलन्दी से देखना चाहिये

[ श्रीमती इनाम हबीबुल्ला ]

कि किसके साथ क्या सलूक करना है, क्या फेयर डील है। अफसोस है कि मैं यह देख रही हूँ कि उल्टा हो रहा है। इधर से कहा जाता है कि पब्लिक की राय लेने के लिये छ महीने का मौका दे दिया जाय। तब आपकी तरफ से इखतलाफ आवाज उठती है। टाइम देने में बहुत से फायदे हैं, क्योंकि आम पब्लिक को इस पर सोचने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने जो तजवीज पेश है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। हुक्मत को हर पहलू पर गौर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह मामला बहुत संगीन है। मैंने अपने बचपन में यह सुना था कि एक जमाना होगा कि ऐसी आफतें आएँगी जैसी कि एक माले के टूट जाने से उसके दाने एक के बाद दूसरे गिरते हैं। इस वक्त यह आफतें कहिये या रहमत कहिये अच्छा कहिये या बुरा कहिए, यही हो रहा है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आफतें नाज़िल हो रही हैं।

अभी साल भर हुआ, जमींदारी के ऊपर टैक्स लगाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि इस टैक्स का, जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब जमींदारी पर टैक्स लगाने का बिल पेश था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि जमींदारों की जायदादों की कीमतों को घटाने के लिये यह टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि कम्पेन्सेशन कम देना पड़े। उस वक्त आपने इसकी तरदीद की थी। मगर अब आज जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, उसमें टैक्स का भी लिहाज नहीं रख रहे हैं। कम्पेन्सेशन आप उसी तरह से रखिये, जैसा कि आपने कहा था।

दूसरी चीज जो मुझे बहुत परेशानी में डाले हुए है, वह यह है कि जिन जमींदारों की जमींदारियाँ खत्म की जा रही हैं, उनके मुताबिलकीन की तादाद तकरीबन एक करोड़ होगी, या इससे ज्यादा होगी। मैं जानना चाहती हूँ कि एक करोड़ इन्सानों के लिये आपने क्या सोचा है, कहाँ पर रखे जायँगे, उनके लिये क्या किया जायगा, या जिससे वह आइन्दा अपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे या बेकारों की इतनी बड़ी जमात और बना दी जायगी, जिससे तमाम मुल्क में बद-अमनी पैदा हो। इस हालत में कोई मुल्क खुशहाल व खुश इन्तजाम नहीं कहा जा सकेगा। जिसके करोड़ों आदमी अनएम्प्लवायड (बेकार) होंगे या क्या? मुझे इससे बड़ी तशवीश है। आपने यह एक करोड़ इन्सान जो बेकार हो जायँगे उनके लिये क्या सोचा है? मैं यह समझती हूँ कि आप लोग जमींदारों के खिलाफ जो नाखुशगवार और बुरे-भले अल्लाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहरबानी करके इस को छोड़ दीजिये। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि आपस के ख्यालात बुरे हो रहे हैं। इस लखनऊ में, इस यू० पी० में जमींदारों की ही बदौलत यह यूनिवर्सिटी, यह कालेज, यह रिफाहेआम और दूसरे इदारे हैं, जिनमें हजारों लड़के इस वक्त तालीम पाकर निकल रहे हैं। यह सब किसकी बदौलत है, यह सब जमींदारों की ही बदौलत है। यह तो अहसानफरामोशी है, यह तो बहुत बुरी बात है। मुझे बताइये कि किस तबके ने, किस सरमायादार ने ऐसा किया है, जो

ताल्लुकेशों ने किया है और इस वक्त करना चाहते हैं ? तो यह जवदेन्तो और बेकार का जो मजहूर किया जा रहा है, यह वेदवर्षी बुरा है। इसकी वजह से यह तबका रिवोल्यूट कर गया तो जिनके सुरक्षणान इहू लैवेंगे यह आपको नोचना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं बहने चाहिये जो बाज्यन और हकीकत से दूर हों। मेरे ल्याल में सबसे पहले यह इन्जल होना चाहिये कि पब्लिक इस परेशानी और दुर्द से नजात पाये, आज मन्ना मेर का अनाज बिक रहा है, कोई इंसान मन्ना सेर का अनाज खकर अपनी जिन्दगी आसानी से बनर नहीं कर सकता है। पब्लिक आपके साथ है, लेकिन जब इन किस्म की बनें आप लोग करेंगे, तो उनके हाथ से सब का दामन छूट जायेगा और आपके बन्ने भी यह चीज अच्छी नहीं होगी। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती हूँ। मैं इन अल्फाज के साथ आपको बनलाना चाहती हूँ कि आपको जमींदारों को दगा दगा और इंसफ के साथ कम्पेन्सेशन देना चाहिए और आप इसका भी ल्याल कीजिये कि उनको काफी वक्त सोचने समझने के लिये दिया जाये, ताकि वह मोच और समझ सकें कि उन्हें क्या करना है। आप यह कहते हैं कि वक्त क क्या जरूरत है, जमाना बहुत हो चुका है। जमाना तो क्या मन के लिये भी मुकरर है, तो एक दिन सबको मर जाना है। लेकिन मतलब तो यह है कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं इसे बगैर सोचे समझे न करें, क्योंकि यह बहुत बड़ी चीज है। यह इतनी बड़ी नब्दीली है कि यह बहुत जरूरी है कि जमींदारों के लिये भी और आपके लिये भी सोचने और समझने के लिये काफी वक्त होना चाहिये, ताकि मुतमइन होकर सब लोग गौर कर सकें। आप गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, समझिये, जनाना क्या है, क्या होनेवाला है और क्या होगा। इस पर हम और सोचेंगे और समझेंगे। मैं तो यह चाहती हूँ कि इसके लिये ६ महीने से ज्यादा वक्त दिया जाये। आप आगे तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि हम किसी तरह ऐसा कदम न उठायें जो हमारे लिये और आपके लिये नाजेबा हो। आप जो यह कहा करते हैं कि एक दिन वह आयेंगा, जब दुनिया की जन्तों यहाँ पर टूट पड़ेंगी। यह तभी होगा, जब हम और आप ठंडे दिल से एक दूसरे को समझ कर मुत्तहिद होकर किसी से इखिलाफ न रखकर जब कोई काम करेंगे, तभी फायदा होगा। ये जो लम्बी लम्बी तकरीरों की जाती हैं और बड़े से बड़े और खराब से खराब अल्फाज ढूँढ़ ढूँढ़कर जमींदारों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। यह निहायत बुरा है, इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ।

श्री बदन सिंह—माननीय सभापति जी, आजकल आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि जमींदारों की तरफ से बड़े-बड़े मजामीन निकल रहे हैं और एक साहब तो सीरीज पर सीरीज निकाल रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी जायदाद बड़े जायज तरीकों से हासिल की गई है। मैं इन साहब का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह स्टेट इनको गदर में मिली थी। आप



[ श्री बदन सिंह ]

उनके बुजुर्गों के कारनामे सुन लीजिये कि किस तरह से यह स्टेट उनको दी गई थी। यह ताल्लुकेदार मुरादाबाद जिले के रहनेवाले हैं।

“The services rendered by the Chowbey Ghanshyam Dass, though differing in their nature, were not inferior to those that have been just described. He had long been connected, as Tehsildar and officer of Police, with Koel and Hathras, but struck by paralysis and quite blind, he had retired from the service of the Government. Gifted with singular sagacity and wisdom, he was implicitly relied upon both for his intelligence and his advice by the civil and military authorities, who continued to occupy portions of the district and maintained our communication with the east during the months of May and June. Compelled with them to fall back upon Agra, he continued to render the same invaluable aid to the authorities there during July and August. He spared no expenses to procure the most accurate information by sending spies from among his own faithful retainers in all directions, and he was daily at the fort to communicate the result, and to offer the suggestions which his experience and tried knowledge qualified him to give. It was first by his counsel that toward the end of August the expedition to Allygurh was planned; and though unable from his disease to stand without support he accompanied our troops into action. Thenceforward he remained with Mr. Cock in the district, and eventually preferred his services in watching the ghats north of Khasgunga, with his followers and the aid of loyal zamindars. Here he was mainly instrumental in aiding the escape of several Christian refugees from Rohilkhand. As the insurgents continued to press forward from Farrukabad the position of the Chowbey became critical, and he was for some time urged by Cock to return to Allygurh, but he refused to desert his post, and shortly before the relief of the district by Brigadier Seaton's force, he was surprised at Khasgunge and cut to pieces.

Had Chowbey Ghanshyam Dass survived, His Lordship would have conferred upon him the highest distinction. It has

now been proved that the favour of the Government be marked by honours conferred upon his heirs, who are not unworthy of them.

Chaubey Jaikishan Das, the eldest brother of the deceased, has been Tehsildar at Hathras, throughout the disturbances and by his courage and prudence contributed to the security of the district. A younger brother was also Tehsildar, having accepted office in a neighbouring Parganah at a time when the distinction was a dangerous one.

( चौधरी घनश्यामदास की सेवाएँ, यद्यपि वे विभिन्नता रखती थीं. इन वर्णित सेवाओं से किन्नी प्रकार कम न थीं। वह चिरञ्जीव तक तहसीलदार तथा पुलिस-अफसर के रूप में कोल और हाथरस में रहे. किन्तु कालिज का उन पर आक्रमण हुआ, और वे बिल्कुल अन्धे हो गये। वे सरकारी नौकरी से पेंशन पर चले गये। उनको असाधारण बुद्धिमत्ता प्राप्त थी और उनकी बुद्धिमत्ता तथा सम्मति के लिये सिविल और मिलिटरी के अधिकारी उनका विश्वास करने थे. जिन्होंने जिला के हिस्सों पर अधिकार रक्खा और मड़े और जून के महीनों में हमारे यातायात संबंध को पूर्व के साथ प्रचलित रक्खा। उनके साथ आगरा जाने के लिए सज्जूर होकर उन्होंने जुलाई और अगस्त में अधिकारियों की अमूल्य सेवा की. उन्होंने प्रत्येक दिशा से अपने विश्वासी रिटर्नर्स को गुप्तचरों के रूप में भेजकर बिल्कुल ठीक सूचना को प्राप्त करने में व्यय की चिंता न की और परिणाम को भेजने के लिए वह नित्य किले में रहते थे और अपनी बुद्धिमत्ता तथा अनुभव के आधार पर सुझाव देते थे। उन्हीं की राय पर प्रथम आगस्त के अन्त में अलीगढ़-आक्रमण की योजना बनाई गई थी और यद्यपि वह बीमारी के कारण सहारे के बिना खड़े नहीं रह सकते थे, वे हमारे सैनिकों के साथ कार्यवाही करने में भी रहे। इसके बाद वे मिस्टर काक के साथ जिले में रहे और अन्त में उन्होंने स्वामिभक्त जमींदारों तथा अनुयायियों के साथ खसगंगा के उत्तर में घाटों की निगरानी करने के लिये अपनी सेवाएँ दीं। यहाँ अनेक ईसाई शरणार्थियों को भगाने में वे सहायक रहे। जैसे ही उपद्रवकार फर्रुखाबाद से आगे बढ़ने लगे, चौबे की दृष्टि बड़ी चिन्ताजनक हो गई और उन पर काक ने जोर दिया कि वे अलीगढ़ आ जायँ, किन्तु उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया और विगेडियर सीटन के सिपाहियों द्वारा जिले की मुक्ति होने से पूर्व उन पर अचानक आक्रमण किया गया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये।

यदि चौधरी घनश्यामदास जीवित होते तो हिज लार्डशिप उनको सर्वोत्तम उपाधि प्रदान करते। अब यह सुझाव रक्खा गया है कि सरकार की कृपा उनके उत्तराधिकारियों पर हो, जो उसके योग्य हैं।

चौबे जैकिशनदास मृत के बड़े भाई समस्त गड़बड़ी तक हाथरस में तहसील-

[ श्री बदन सिंह ]

दार रहे और उनके साहस और बुद्धिमत्ता से जिले में शान्ति रही। उनका छोटा भाई भी तहसीलदार था, उन्होंने पड़ोसी परगने में आकर उस समय स्वीकार किया जब कि डिस्ट्रिक्शन एक खतरनाक चीज थी।”)

मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि राजा जयकृष्णदास कुंवर सर जगदीश-प्रसाद के दादे थे।

Ch. Mohanlal, nephew of the deceased, used to be in constant attendance with him when he visited the authorities to communicate information, and when his uncle left Agra he continued to supply his place in that respect. His intelligence was trustworthy and valuable.

Ch. Jai Kishandas and Ch. Mohanlal are thus themselves worthy of reward and worthy of bearing the honours which would have been conferred on their noble relation. Had he survived.

It is suggested that the title of Raja be conferred upon Chaubey JaiKishan Das and an estate suitable to support the dignity of the title will be provided for him if possible in Moradabad district, to which district the family belongs; and a similar grant will be made to Chaubey Mohanlal of an estate of smaller extent.

( “चौधरी मोहनलाल, मृत के भतीजे, लगातार उनके साथ रहते थे जब कि वे सूचना देने के लिए अधिकारियों के पास जाते थे और जब उनके चाचा ने अलीगढ़ छोड़ा तो वे उनके स्थान में कार्य करते रहे। उनकी बुद्धिमानी विश्वसनीय और अमूल्य थी।

चौबे जैकृष्णदास और चौबे मोहनलाल पारितोषिक के पात्र हैं और उस सम्मान को प्राप्त करने के योग्य हैं, जो कि उनके सम्बन्धी को मिलता, यदि वह जीवित रहता।

यह सुझाव दिया गया है कि राजा की उपाधि चौबे जैकृष्णदास को दी जायगी और उपाधि के अनुकूल कोई जागीर यदि सम्भव हो तो मुरादाबाद में उनकी सहायता के लिए दी जाय, जिस जिले में वह परिवार है और एक उसी प्रकार की जागीर चौबे मोहनलाल को दी जायगी।” )

( इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर १ मिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। )

श्री बदर सिंह—लख ने रहने में मुगादाबद जिले के एक तालुकदार साहब का जिक्र कर रहा था जिने मालगिर के एक बहुत ऊँचे ओहदे पर रह चुके हैं। उनके कहने के मुताबिक उन दिनों में लिखा हुआ है वह मैं पढ़ रहा हूँ।

"Raj. Chaudhary, J. K. Das, and Chaudhary Mohanlal. Brahmans, J. K. Das."

These persons rendered valuable service to Government in A. J. K. Das. Their services have been sanctioned by the Government.

The title of Raja and a jagir of the following 17 villages have been granted to Chaudhary Jagdish Das, and his brother, Chaudhary Mohanlal, under the title of Raja.

( "राज चौधे जेमुगादाब और चौधे मोहनलाल, ब्राह्मण, मुगादाबाद ।

इन लोगों ने अंगरेज जिले में सरकार के असह्य सेवा की सरकार ने इनको पारिवारिक दिये हैं ।

राज की उपाधि और १७ निम्नलिखित गांवों की जागीर चौधे जयकृष्णदास को रहने हो दी जा चुकी है और १००० रुपये की उसी प्रकार की जागीर उनके भाई मोहनलाल को सरकारी आदेश के अनुसार दे दी गई है । )

अब मैं उन १७ देहातों के नाम आपके सामने पड़े देता हूँ । वह इस प्रकार हैं—मुकनपुर, वारपुर, बरयार, उकरीनी, कहीली, बुरन, पुतरीआ, कुरैली, कोकाबास मूई, पालनपुर, उमानपुर, भूवनपुर, कतेहलतापुर, पीपली, रामपुर मंगल, फुरेहरी, लोदीपुरवानू, जकरपुर ।

बहुत से मेम्बर साहबान कह रहे थे कि आप यह कहाँ से पढ़ रहे हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि यह एक किताब में है, जिनमें रिकार्ड रक्खा गया है और मैं उसी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई गलतफहमी की बात नहीं है । यह इसलिए रक्खा जाता है ताकि अच्छे लोगों के अच्छे कारनामे सोने के लफ्जों में और बुरे लोगों के बुरे कारनामों के बुरे लफ्जों में रक्खे जा सकें । अब मैं मुगादाबद को एक स्टेट का जिक्र कर रहा हूँ, वह अंगरेजों के जमाने के नहीं हैं, बल्कि पुराने हैं । यह मरहटों की अमनदारी के वक्त की बात है, लेकिन जब १८०३ में लड़ाई हुई तो इन्होंने मरहटों का साथ अंगरेजों के मुकाबले पर नहीं दिया, इसके संबंध में भी अब एक चिट्ठी सुनें—

"Rup Shan, Raja Jagmanpur

This is the chief of the Sengar clan in this district. It appears from a Sanad, dated the 21st Nov. 1852, signed by Major W. E. Esme, Supdt. of Jhaln that the taluka of Jagmanpur, consisted of 46 villages said to yield a yearly revenue of Rs 65,000 but in reality not yielding more than

[ श्री बदन सिंह ]

Rs. 32,000 was granted to Raja Bapuka in the year 1100 by Raja Tej Chandra of Kanauj as dowery when his daughter married the former. In 1717 Raghunath Rao Balajee Peshwa continued the grant to Ratan Sah, grandfather of the late Raja Mohbat Sah. The grant is in perpetuity to his heirs on payment of a yearly quit-rent of Rs 4,574.

### रूपशाह जगमनपुर के राजा

यह इस जिले में सेंगर जाति के मुखिया हैं। एक २१ नवंबर, १८४२ की सनद जिस पर मेजर डब्ल्यू ई० एस्काइन, सुपरिंटेंडेंट, जालौन, से विदित होता है कि जगमनपुर का ताल्लुका जिसमें ४६ गाँव हैं, जिसकी वार्षिक आय ६५ हजार रु० कही जाती है किन्तु वास्तव में ३२ हजार रु० से अधिक नहीं है सन् ११०० में कनौज के राजा तेज इन्द्र ने अपनी लड़की की शादी के समय उनको दहेज में दिया। सन् १७१७ में रघुनाथ राव बालाजी पेशवा ने स्वर्गीय राजा मुहम्मद शाह के दादा रतन शाह को वह ग्राम जारी रखी। उनके उत्तराधिकारियों के पास वह जागीर ४.५७४ रु० वार्षिक लगान पर निरंतर चली आती है।” )

अब मैं जमींदार एसोशियेशन के प्रेसीडेंट जो बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका कुछ किस्सा सुनाता हूँ। इनका नामेनामी रानी फूलकुमारी है और चौधरी उमरावसिंह और चौधरी वसंत सिंह इन के ससुर के पिता थे:— लीजिये इस संबंध में भी आप एक चिट्ठी सुनें—

Chowdhrys Omrao Singh and Bussunt Singh, Chauhan Rajpoots of Sherkot, Zamindars, the forefathers of the present Rani of Sherkot, President of the Zamindars' Association.

These Chowdhrys, as being reputed the wealthiest of the landholders in the district, and at the same time the best able to make opposition, were the first to feel the power of the rebels, who on their requisition for revenue being refused on the ground that the Nawab had no authority to make such a demand, attacked and plundered their property, keeping possession of their gurhee for several days until they were driven out by a combined attack on the part of the Hindus. Like the rest of the loyllay disposed these men had to fly the district, leaving their villages at the mercy of the rebels, but before doing so they joined with others in sending a supply of money to Naini Tal, their share being Rs. 1,000. They re-entered the district with me and made themselves very useful in re establishing order in their part of the district.

For the good service rendered I would recommend that outstanding balances amounting to Rs. 46,741, be remitted, that confiscated villages paying an annual Jumma of not less

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ४५७

than Rs. 1500 be transferred to them, and that khillut be conferred on each of them.

(“चौधरी उमरावसिंह और वसंतसिंह चौहान, गेर कोट के राजपूत चौहान, वर्तमान शेर कोट की रानी, जमींदार एसोसिएशन की समन्वयी के पूर्वज ।

ये चौधरी जिले में सबसे अमीर जमींदार प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ विरोध करने में भी उन्होंने सर्वप्रथम क्रान्ति करियों की शक्ति का अनुभव किया, जिन्होंने लगान की मांग की जाने पर इन्कार कर दिया, इस कारण कि नवाब को इस मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी मांग करने पर उनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया तथा लूटा और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी गद्दी पर कब्जा रक्खा, जब तक कि उनको हिन्दुओं ने मिलाकर निकाल नहीं दिया। अन्य लोगों की भाँति ये भी जिले से भाग गये और अपने गावों को उपद्रवियों के पाम छोड़ गये। किन्तु इसके पूर्व उन्होंने दूसरों के साथ धन को नैनीताल भेजने रहे, उनका हिस्सा १००० रु० था। वे मेरे साथ जिले में आये और जिले में शांति स्थापन में बड़े सहायक सिद्ध हुए।

जो अच्छी सेवा उन्होंने की मैं सिकारिश करना हूँ कि ४६,७४१ की उनके ऊपर जो रकम है, माफ की जाय और जब १,५०० रु० जमावाले गाँव उनको दे दिये जायँ और उनमें से प्रत्येक को खिलत दे दी जाय।”)

**डिप्टी स्पीकर**—अगर आपको कुछ कहना है तो कहें। इतिहास पढ़ने का मौका नहीं है। आज अन्तिम दिन है, और लोग भी बोलना चाहते हैं जो कुछ आप कहना चाहें, कहें इतिहास छोड़ दें।

**श्री बदर सिंह**—यह इतिहास बुलन्दशहर के बड़े से बड़े जमींदार हैं, उनके बारे में है। सुन लीजिए—

“Estates of Bulandshahr District.

The Talukaidars of Chatari, Pahasu, Danpur and Dharampur, Mahmood Ali Khan, Faiz Ali Khan, Imdad Ali Khan and Zuhoor Ali Khan, the first and last brothers and the other two sons of Mardan Ali Khan have proved themselves as the family always has right loyal subjects. As at the cession their ancestors gave in their allegiance to and assisted Lord Lake, while the ancestors of Raham Ali Khan and Mazhar Ali Khan of Khaitia opposed Government for which part of the estates of the latter were confiscated and made over to the former. So now the descendants have acted in each case following the examples of their forefathers. Raham Ali Khan and Mazhar Ali Khan have become rank rebels while Murad Ali Khan till his death and his brother and sons have most resolutely taken the Government side, and the reward and punishment should again be awarded.

[ श्री बदन सिंह ]

जिला बुलन्दशहर की रियासतें

छतारी पहरू, दामपुर और धरमपुर के ताल्लुकदार महमूद अली खाँ, फैयाज अली खाँ, इमदाद अली खनंद जाहूर अली खाँ, प्रथम और अंतिम कई ओर मर्दान अलीखाँ के दूसरे दो लड़कों का परिवार सदैव राजभक्त रहा। क्योंकि सुनुर्दगी में उनके पूर्वजों ने लार्ड लाफा को अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित की तथा सहायता प्रदान की और रहम अलीखाँ तथा मजहर अलीखाँ के पूर्वजों ने सरकार का विरोध किया अतः रहम अली खाँ तथा मजहर अली खाँ की रियासत का भाग जप्त किया गया तथा मुराद अली खाँ आदि को दे दिया गया। इस कारण इन लोगों के उत्तराधिकारियों ने अपने पूर्वजों का अनुकरण किया। रहमत अलीखाँ और मजहर अली खाँ कट्टर विद्रोही बन गए और मुराद अली खाँ ने मृत्यु-पर्यंत तथा उसके भाइयों और पुत्रों ने पूरा रूप से सरकार के साथ योग दिया अतः पारितोषिक तथा दंड पनः दिये जाने चाहिए।” )

सबसे पहले उनको जायदाद दी गयी। फिर रहमअली खाँ से मजहर अलीखाँ को दे दी गयी। १८५७ का जब गदर हुआ तो इनको औजाद से छीनकर, उनकी औजाद को दे दी गयी। एक ही खानदान के यह लोग थे।

“It is to be hoped that not a single member of the disloyal family will be left alive to repeat the offences. Their estates should be entirely transferred to the relations of Murad Ali Khan and dress of honour should be bestowed on each member of the family” Mahmood Ali Khan well deserved the grant of estates and a dress of honour.

( “यह आशा की जाती है कि राजद्रोही परिवार का कोई भी आदमी जीवन न रहने दिया जायगा, जिससे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति कर सके। उनकी समस्त जमींदारियाँ मुरादअली खाँ के सम्बन्धियों को दे देनी चाहिए और उनके परिवार के लोगों को खिलत दे देनी चाहिए। महमूद अली खाँ सवथा इस योग्य है कि उसे जमींदारी और खिलत दी जाय।” )

यह आपने सुना। इस तरह से यह बड़े बड़े जमींदार मज्जा उठा रहे हैं और इस तरह से उन्होंने जायदादें पैदा कीं। तीन-चार तरीके से उन्होंने जायदादें पैदा कीं।

जब अंग्रेज अमलदारी आई, तो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेज भी चाहते थे कि कुछ लोग उनकी मदद करने के लिये मिल जायँ, इसलिये इनको कायम रक्खा। दूसरे उस समय हुये, जब गदर हुआ। गदर में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने भाइयों को कटवा दिया। तीसरे गदर के बाद ये लाजा लोग जमींदार हुये। ये सूद दर सूद से हुये। मुझे ऐसी बहुत सी मिसालें मालूम हैं जिनमें एक लाख कर्ज के लिये १॥ लाख की डिग्री हुई। छैर, ये तीन किस्म के जमींदार हैं, जो इस समय एक हो रहे हैं। मेरा तो कहना है कि उन्होंने कोई जायज तरीके से इसे हासिल नहीं किया है, इसलिये इसे खत्म करने में किसी को

एनाइड न होना चाहिये। जैसे एनाइड का आई थी वैसे ही वह जा भी रही है। मेरा कहने का मत यह है कि इन दिनों में जो इन्ना बड़े-से मच रहा है, विन्ना विन्ना है वह तो एनाइड है। एनाइड है कि जमीन-माल ने क्या किया। एनाइड ने जमीन के निवासी एक दो तीन चार और किसी ने कोरेन का लाल नहीं किया। इन्ना देखा कि रा ने देना इतर साध के साथ है या डिटी को इतर साध के साथ।

डिटी को इतर साध, कुन जो एनाइड है विन्ना इनाइड हो तो तुन है। बाकी बात तो मुना चुन है। ऐलिन जमीन है और जमीन से लोग दोनेव भी हैं। इन्ना ये इन्ना करन-माल के साथ सँभरनी नभरि कम करना है।

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः—जनव मंदर, इन विन के ऊपर, जो इस ऐवान के सामने है आज एनाइड ने बदन हो गई है। हर जगह अपने तुनने खयाल की बकात कर रहा है अभी चौधरी बन-निह ने बाइल लान-माल का हवाला बयान किया, ऐलिन मुझे यह बयान चौधरी मंदर ने दिया है जिस खानदान के तुगीमों के साथ गदर के इमाने से ज्यादतियाँ हुई थी। जायदाद एनाइड की गई थी और उनके तुजुगों को गोन्दियों से उठाया गया था, आज उन दिने वह क्या सिना तजवीज कर रहे हैं, यह उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं कहा था। कश, वह यह भी बतला देने कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुरबानी मुल्क के खातिर की थी, उन्हें क्या सिला मिलना चाहिये। उन्होंने सिर्फ उन्हीं खानदानों का हवाला दिया, जिन्होंने गहारी की पर जिन्होंने मुल्क के खातिर मुसीबतें उठाईं, जिनकी जायदादें जब्त हुईं, उनका कोई जिक्र नहीं किया। बहरहाल ऐसे भी लोग हैं कि उन्हें अगर जायज सुआविजा दिया जाय तो गवर्नमेंट के सामने वे लाये जा सकने हैं। चुनांचे रहमन खाँ सा-ब का नाम इस तबारीक में लिखा हुआ है। उन्होंने जो कुरबानी की उससे कोई भी शख्स बेखबर नहीं हो सकता। आज उनकी आलाद जिस हात में है, उससे लोग वाकिफ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस हुकूमन से इन पार्टी से जो बरसरे इकदार है कि क्या वह उसको कोई सिना अदा करेंगे या यह महज अदानी जमाद-व है ?

हुजूरवाला, मुझको यह अर्ज करना था कि एक तजवीज इस वक्त बजीर आजम साहब की इस ऐवान के सामने है, वह यह कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय। दूसरी तजवीज राजा जगन्नाथ बगशसिंह साहब की है कि यह राय आम्मा मालूम करने के लिये सरक्युलेट किया जाय। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सरियत इसके माफिक है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जनाबवाला, आपकी इजाजत से मैं यह तरमीम पेश करना चाहता हूँ कि १५ अगस्त सन १९४६ तक पब्लिक की राय सेक्रेटरी साहब सेलेक्ट कमेटी की खिदमत में भेज दी जाय, ताकि सेलेक्ट कमेटी उन रायों पर

ॐ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।



[ श्री मुहम्मद उबेदुर्हमान खाँ शेरवानी ]

गौर कर सके। मैंने १५ अगस्त, सन् १९४६ कसदन् रक्खा है, वह इसलिये कि वह योने आजादी है और लोगों को अभी एक महीना बाकी है। जब कि इस ऐवान में काफ़ी बहस-मुवाहिदा हो चुका है, दूसरे ऐवान में भी मुवाहिदा होने-वाला है, अख़बारों को भी राय देने का मौक़ा मिला है, इसलिये पब्लिक को भी और पब्लिक बॉडीज़ को भी यह हक़ हासिल होना चाहिये कि वह अपनी राय जाहिर कर सकें। इस तरह से पब्लिक की राय आने का भी मौक़ा मिल जायेगा और देरी लगाने का जो सवाल है, वह भी दूर हो जायेगा।

एक और अहम मसला जो काबिले गौर है वह यह है कि इस ऐवान में लैण्डलेस लेबरर्स के मुताल्लिक भी तजक़िरा किया गया है, उसके साथ एक गौर-तलब बात यह भी है कि एक बड़ी जमाअत उन लोगों की भी है, जो ज़मींदारों के ऊपर मुनहसिर थे या उनके यहाँ मुताज्जिम थे, वह सब बेकार हो जायेंगे। उनके पास कोई ज़मीन न होगी, न उनके पास कोई तिजारत होगी, उनमें से बहुत लोग ऐसे कमज़ोर भी हैं, जो तिजारत भी नहीं कर सकते हैं और न उन लोगों के पास कोई ज़्यादा पैसा ही है। उन लोगों के लिये क्या सोचा गया है। उनकी माश का क्या ज़रिया होगा? मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की पार्टी अक्सरियत में है और उसी अक्सरियत की वजह से बरसरे इक्तिदार हैं, लेकिन क्योंकि वह इस सूबे के वज़ीर आज़म हैं, इसलिये हर शख्स को यह हक़ हासिल है कि वह उनके सामने अपने मतालिबात पेश करे, अपनी तबक्को को उनके सामने रखे और उनका भी यह फ़र्ज़ है कि वे हर एक की तकलीफ़ात को दूर करें। इसलिये मैं वाजह तौर पर वज़ीर आज़म साहब के गोश गुज़ार करना चाहता हूँ कि जब सेलेक्ट कमेटी बैठे तो इस पर भी गौर कर लिया जाय। इस गिरोह की माश का ज़रिया पैदा करने के लिये कोई कदम ज़रूर उठाया जाय। अगर वह बेकार रहा तो एक बहुत बड़ा तबका तकलीफ़ से अपनी जिन्दगी बसर करेगा। बाज़ लोग ऐसे हैं, जो नस्लों से अपनी जिन्दगी तकलीफ़ से वहाँ बसर कर रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर है कि हर एक आदमी अपना बोझ उठाया करता है, दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। अपनी ख़ता की सज़ा खुद उठा सकता है, दूसरा उसका हक़दार नहीं। सवाल यह है कि इन हज़रात की माश का ज़रिया क्या होगा, इस पर गौर फ़रमाया जाय।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल में जो कम्पेंसेशन का तरीका पेश किया गया है, वह एक ऐसा तरीका है कि अगर उसकी तमाम दफ़ात को गौर से पढ़ा जाय, तो यह मालूम होगा कि कम्पेंसेशन की बड़ी मुहत् रक्खी गई है। उसमें यह ज़रूर कहा गया है कि नौ महीने के बाद इण्टरिम कम्पेंसेशन दिया जायेगा। लेकिन ६ महीने की मियाद भी एक बहुत बड़ी मियाद है। यह सोच लेना कि हर एक ज़मींदार पर इस कदर सरमाया मौजूद है कि वह नौ महीने तक निहायत इत्मीनान से अपनी गुजर-

बसर कर सकता है और अपनी नगम जरूरियां पूरी कर सकता है। सही नहीं है। बहुत से जमींदार ऐसे भी होंगे, जो अपनी आमदनी के अन्दर सिर्फ गुजर-बसर हो कर जाते हैं, और उनमें से बहुत से कर्जदार भी हैं।

सवाल यह उठा होता है कि अगर यह आमदनी उसकी बन्द हो गई और वह महीनों इन कम्पेंसेशन के चक्कर में पड़ा रहा, तो उसका नाश कैसे चलेगा। वह अपने बच्चों की तालीम कैसे जारी रख सकेगा, अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, तो उनके इलाज के लिये वह कहाँ से पैसा लायेगा और क्या मूलतः ऐसी हालत में वह अखिरकार करेगा। उसके पास कोई जायदाद भी नहीं रह जायगी, ताकि उसको कर्जा मिल सके। इसलिये यह बेहद जरूरी है, जैसा कि नवाब साहब ने कहा था और मैं समझता हूँ कि उन्होंने निहायत मकूल बात कही थी कि कोई ऐसा मूल्य तिकाची जाय कि जिस वक्त उनसे जायदाद ली जाय उनी वक्त उनके हवाले मुआवजा कर दिया जाय। दुनिया में यही तरीका मुतासिल और मकूल खर्चदारी का हुआ करना है कि इस हाथ दान दिया जाय और उन हाथ चीज ली जाय। इनकी बड़ी चीज जब आप ला रहे हैं और उनके नाश का जरिया कुछ न रहेगा तो वे कैसे अपनी गुजर करेंगे।

इसके अलावा यह जो रुपया होगा यह इन्सान की परवरिश के लिये काफ़ी नहीं हो सकता। इस जमाने में शहर सूद इस कदर कम है कि वह किसी के गुजर के लिये काफ़ी रकम नहीं दे सकती है। यानी ढाई फौलदी। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यह भी हुकूमत का फर्ज है कि इसके साथ-साथ जब कि वह यह कंसजा कर रही है कि जमींदारी खत्म की जाय तो वह ऐसी बात करे, ऐसे तरीके अखितयार करे, जिनसे उन लोगों की आश-यश भी बनी रहे और रुखा भी सही मसरफ से सर्फ हो।

बिल का एक फायदा यह भी बताया गया है कि यह प्रोडक्ट (पेंदावार) को बढ़ायेगा। जो लोग बेकार हैं, उनको कारआमद बनायेगा। लेकिन मैं फिर अदब से यह अर्ज करूँगा कि नकद मुआवजा देने से वे कारआमद नहीं बन सकते लिहाजा मेहरबानी करके यह सोचिये और इसके लिये इस बिल के अन्दर कोई ऐसी दफा रखिये, जिससे कि वे हकीकतन् कारआमद हो सकें। इसलिये जब आपके हाथ में हुकूमत है तो उस तबके को जो अब तक बेकार था, उसको काम से लगाया जाय। यह आपका एक कारनामा होगा। लोग इसको अच्छी तरह से याद करेंगे कि उन्होंने एक जरिया कानून अगर खत्म किया तो दूसरा जरिया उनके वास्ते ऐसा अच्छा तजवीज कर दिया कि वे कारआमद बन गये और आराम से और राहत से अपनी जिन्दगी बसर करने लगे। अगर वही तरीका, यानी जो दफात इस बिल में कम्पेंसेशन देने के मुताल्लिक रखी गई हैं, मुआवजा देने का रहा, तो मुझे अन्देशा है कि मुकदमेबाजी होगी, इसलिये कि स्पेशल आफ़ीसर मुक़रर किये जायेंगे जो पूरी-पूरी तहकीकात करेंगे, उसके बाद

[ श्रीमुहम्मद उबेदुर्हमान ख़ाँ शेरवानी ]

मामजात हाईकोर्ट में जायेंगे। तो जो कुछ उनको मिलेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वकीलों, अहलकारों और उनके सफ़र खर्च की नज़र हो जायगा।

एक तरफ़ तो आपने १५ फ़ीसदी तज़बीज़ किया है कि आप उसमें से कलेक्शन चार्जेज़ मुजरा करेंगे और दूसरी तरफ़ आप फ़रमाते हैं कि ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स, जो कि अभी हाल ही में आयद हुआ है, इस बिल से मालूम होता है कि मुजरा किया जायगा। और बाज़ लोगों का इसके मुताल्लिक जो ख्याल था जब कि वह पेश हो रहा था, वह सही हुआ यानी यह कि इस गरज से इसको किया जा रहा है कि जिस वक्त मुआवजा देने का वक्त आवेगा तो एक बड़ी रकम मुजरा हो जावेगी। अगर हिसाब लगाया जाय तो मेरे ख्याल में करोड़ों रुपयों का इससे फ़र्क पड़ जायगा। मैं तो यह समझता हूँ कि यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है कि आप ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स को मुआवजे से वजह करें। अगर आपने इन दफ़ात को नहीं बदला और उनको वैसी ही कम्प्लीकेटेड रक्खा जैसी कि वे अब हैं, तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक बड़ा हिस्सा उनकी रकम का वकीलों की जेब में जायगा और अहलकारों की जेबों में जायगा और सफ़र खर्च में खर्च हो जायगा।

मुझे एक बात यह भी अर्ज़ करनी है कि कुछ लोगों की तरफ़ से यह कहा जा रहा है कि ज़मींदारियाँ अँगरेज़ों ने पैदा कीं, लिहाज़ा उनको ख़त्म किया जाय। ख़ैर यह तो वाक़यात तारीखी हैं जैसा कि बेगम ऐजाज़ रसूल साहिबा ने अपने नोट ऑफ़ डिसेंट में बतलाया है कि बहुत सी ज़मींदारियाँ उस वक्त भी थीं जब कि अँगरेज़ों का यहाँ वजूद भी नहीं था और मिसाल के तौर पर उन्होंने मैनपुरी और दूसरी रियासतों का जिक्र भी किया है।

इन्साफ़ का जो तरीका अँगरेज़ यहाँ छोड़ गया है, वह निहायत ही ख़राब है। स्टाम्प बेचे जाते हैं, कोर्ट फीस वसूल की जाती है और वकीलों को बड़ी-बड़ी फीसें दिलवाई जाती हैं। हर शख्स इस बात को मानेगा कि यह तरीका किसी तरह दुरुस्त नहीं है। गाँव पंचायत ऐक्ट के कुछ दफ़ात की मुझे याद आती है। उनमें यह चीज़ साफ़ कर दी गयी है कि वकीलों को पंचों के सामने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं इस बिल की कुछ दफ़ात की तरफ़ आपकी तवज़्जह दिलाना चाहता हूँ। कम्पेंसेशन के सिलसिले में इतनी दफ़ात का रखना गोया इस मसले को और भी कम्प्लीकेटेड (उलझा हुआ) बनाना है। बहुत से कम्पेंसेशन लेनेवाले इस दुनिया में न रहें, बहुत से बीमार ठीक इलाज न होने की वजह से मर जायें, बहुत से बच्चे तालीम से महरूम रह जायें। इस तरह यह ऐसा नुकसान होगा, जो कौम और मुल्क का नुकसान होगा और हमें इसको किसी तरह बरदाश्त नहीं करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जो हज़ारात् सेलेक्ट कमेटी में इस बिल पर गौर करने के लिये बैठेंगे, वह ज़रूर यह कोशिश करेंगे कि जो नुक़ायस इन दफ़ात के अन्दर हैं वह दफ़ा हो जायें, और दुबारा जब बिल इस ऐबान में आये तो उसमें कम्पेंसेशन

देने का तरीका बहुत ही निम्न हो। बेइतमीन तरीका यह होगा कि पहले आप जायदाद का जम्मेदार बनने के लिये उनमें जायदाद नोटिस दे कि यह जायदाद हुकूमत के कब्जे में आ गई और यही जमीन जन्तिये कि हमारा इसमें हरगिज यह मकसद नहीं है कि हमने देर लगे जो चीज जानी है, उनको जन्तिये दिया जाय और प्रेम के साथ जन्तिये दिया जाय मैं इनका विस्तृत ज्ञान हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि अगर ज़िदा करना है तो ज़िदा ज़िदा में ज़िदा किया जाय, कुन्द ज़िदा से ज़िदा न किया जाय हमने कि न वह मरने पायेगा और न ज़िदा में होगा और यह बड़ी ज्यादाती होगी मुझे यकीन है कि आप भी इसको ग़वार नहीं करनायेंगे।

दूसरी बात मुझे यह अज कर्नी थी कि मेरा यह खयाल था कि जमींदारी के खत्म होने के बाद कोई ऐसा दूसरा निरुद्ध अख्तियार किया जायेगा, जो मौजूदा सिस्टम से हकीकतन बेहतर होगा। कल चरण सिंह साहब ने अपनी नक़्सीर में यह फ माया था कि इस विज्ञ के पेश करने में जो देर लगी है, उसकी वजह यह थी कि यह सोचा जा रहा था कि जो मौजूदा सिस्टम है, उसके खत्म होने के बाद कौन सा सिस्टम लाया जाय। मैंने निहायत गौर के साथ पूरे विज्ञ को पढ़ा और उन तमाम तक़रीरों को देखा, जो उनके सिलसिले में की गई हैं और जो इसकी मुआफ़िकत में मजबूत ज़िखे गये हैं, उनको भी पढ़ा लेकिन मुझे निहायत अफ़सोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि कोई माकूल सिस्टम मौजूदा सिस्टम की जगह तजवीज़ नहीं किया गया है। आपका सिर्फ यह खयाल है कि जो मौजूदा इमारत है, उसको अगर गिरा दिया जाय, तो जो इसकी बुराइयाँ हैं, वह खुदबखुद दूर हो जायेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह ऐसा खतरनाक उसूल है और अगर इसे इस्तेमाल किया तो यकीनन नुक़सान पहुँचने का अन्देश है। मालगुजारी वसूल नहीं होगी तो इससे जरूर इसका अर्ज मुश्क़ल असर बजट पर पड़ेगा। इस वक्त बजट में इनकी गुंजायश नहीं। वह स्कामें जो आपके पेशे नज़र हैं लैंड रेवेन्यू का जो आइटम है उसमें खराबी पड़ा हो गई और वक्त पर मालगुजारी वसूल न हुई, तो यकीनन इसका नतीजा होगा कि बहुत सी दिक्कतें हुकूमत के चिज़ाने में पेश आ जायेंगी। मैं इनके साथ एक बात और अज करने की जरूरत समझता हूँ। यह तो सही है कि आप बार-बार इरशाद फरमाते हैं कि यह आपकी पार्टी का फैसला है कि जमींदारी खत्म की जाय। इससे यह तबक्को नहीं की जाती कि जमींदारी खत्म होने से काश्तकार की बहाली होगी। तरक्की हो लेकिन देखा यह गया कि जो आप जमीन काश्तकार के सिद्ध फरमा रहे हैं तो काश्तकार की पैदावार उसके अख्तियार में नहीं है। प्रोक्योरमेंट की जो स्कीम है उसके तहत मैं एक खास हिस्सा काश्तकार अपनी पैदावार का उन दामों में जो यहाँ से मुकरें हो जायेंगे वह हुकूमत के हाथ फरोख्त करेगा। जो बेज्जमानियाँ इस प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में हुई हैं रोज़ रोशनी की तरह चमक रही हैं। मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर सवालता हो रहे हैं। बहस-मुबाहि़सा हो रहा है। कई रोज़ से अख़बारों में खबर आ

[ श्री मुहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ाँ शेख़ानी ]

रही है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर दूसरी पार्टी बन रही है। जो बेउनमानियाँ हैं, उनको आप रफ़ा करें। मेरे अर्ज करने का मकसद है कि जो सीरदार हैं, असामी हैं, जो किसान हैं अगर ज़मीन उनकी रहे, लेकिन पैदावार पर उसका कोई हक़ न रहे, अपनी पैदावार को अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक़ बेच न सके यह निहायत ना-मुनासिब होगा। आज दुनिया के अन्दर क्या हालत है। अब तो ज़मींदारों को भी काश्त करना है, वह ज़मींदार खुद अपनी पैदावार की तरक्की की कोशिश करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी आमदनी का एक बड़ा ज़रिया काश्त है। अलावा मुआविजे के अगर वह फ़ार्मिंग करेंगे, पैदावार बढ़ाएँगे, तो यकीनन् उनके लिए यह मुफ़ीद साबित होगी। यह जरूर गौर करना पड़ेगा कि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ज़मींदार से लिया जा रहा है, जिससे उसका नुक़सान हुआ है। अख़राजात वही हैं, कैसे पूरे हो सकेंगे। लेकिन एक बड़ी वजह है, आपको गरानी भी दूर करना है। क्या आप यह बता सकेंगे कि गरानी दूर करने की क्या सूरतें अख़्तियार की और जो सूरतें अख़्तियार कीं, उनसे कितनी गरानी दूर हुई? इस वक्त तक जो मुसीबतें मुल्क पर मुसल्लत हैं, वह हटीं नहीं। आपकी जो ख़्वाहिश है कि शहद और दूध की नहरें बहने लगें, यकीनन् हम यहाँ के रहनेवाले मुसीबत से छूट जायँ और हमारी तमन्ना है कि कम से कम पानी ही की नहरें इफ़रात से बहने लगें और यही एक बड़ा ज़रिया ज़राअत की तरक्की का है। सवाल यह है कि जब तक गरानी न जायगी, यह मकसद हासिल नहीं हो सकता।

जनाबवाला, आपस में इस वक्त तक इख़्तलाफ़ात हैं और यह उसी का नतीजा है कि इस वक्त दुनिया में जो मुसीबत फैली हुई है, यह गरानी जो दुनिया में छाई हुई है, हमें सोचना यह है कि इसे रफ़ा करने के लिए क्या करें। इसके साथ यह भी हमें सोचना चाहिए कि इस गरानी को रफ़ा करने की क्या शक़्त अख़्तियार करनी होगी। मुझे अर्ज करना है कि वक्फ़ अलल उल औलाद का कोई प्राविजन बिल में नहीं है। दो किस्म के वक्फ़ आपने रक्खे हैं। एक तो चैरिटेबुल और दूसरे 'प्राइवेट, वक्फ़ अलल उल औलाद जो शरअन् और कानूनन् इस सूबे में किए गए हैं, उनकी' गरजोगोयत यह है कि एक हिस्सा कारे ख़ैर के वास्ते रक्खा जाय।

तो बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ़ अलल उल औलाद कारे ख़ैर के वास्ते किए हैं। जाहिर बात है कि इससे बहुत से मदरसों, बहुत से गरीब तालिबइस्मों, बहुत सी बेवाओं और बहुत से यतीमों की मदद हो रही है। सवाल यह पैदा होता है कि वक्फ़ अलल उल औलाद के साथ क्या बर्ताव किया जाय। मेरी नाचीज राय यह है कि सेलेक्ट कमेटी को खास तौर से इसकी तरफ़ गौर करना चाहिए। वक्फ़ अलल उल औलाद एक ऐसी अजीमुश्शान चीज़ है, जिसकी निरन्तर ख़ास तौर से गौर करना चाहिये कि उसका क्या इन्तजाम हो, उसको किस तरह से बरतना चाहिये जिससे 'कारे ख़ैर की मदद जागी रह सके। और उन लोगों को जो मुहताज हैं, जो वाकई में हाजतमन्द हैं और जिनकी इमदाद वक्फ़ मुहत से चल रही है उनको

नुकसान न पहुँचे, बल्कि यह बहुत दूर जा रहा है। उसके साथ ही साथ वृत्तगत उत्तम औजारों के लिये जिस नगर का क़द्वन है, उसके लिये भी जो धन खर्ची है, उसका भी पूरा लिहाज रखना है। निम्नलिखित प्रकार का धन जो औजारों के लिये बिल में एक प्रोजेक्शन की निहायत जरूरत है, जिसमें उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हो सके। आने एक यह भी नक्कल दिनांशों के बिल में, कि जो नक्कल जमींदार हैं, उनके कर्जों को धटा दिया जायगा, उसको कम किया जायगा और उनके लिये कोई बिल लाया जायगा। लेकिन मैं यह चाहता था कि वह बिल भी इन दिनों के साथ ही साथ इस ऐवान के सामने आ जाना, तो बहुत अच्छा होता। इसलिये कि जब उनके पास कोई जायदाद ही नहीं रहेगी, जिसके ऊपर वह कर्ज था तो वे कर्ज अदा वहाँ से करेंगे? और वह जो कर्ज का भार है, वह उनकी जान पर रहेगा या जान उससे सुस्थिर हो जायगा या जो मुआविजा ले पायेंगे, वह उनके कर्ज के बढ़ते में कुंठित हो सकेगा? सवाल यह पैदा होता है कि इन दिनों के साथ ही साथ वह बिल भी आ जाता, तो पूरा भिन्न सामने आ जाना। मेरा ख्याल यह है कि जिसने बिल इसके मुताल्लिक हैं वे सब इस ऐवान के सामने रहने और इस पर बहस-मुवाहिदा जारी रहता, ताकि सब लोग आसानी से अपने खयाल को जाहिर कर सकें। इस बिल में किसी भी बिल के लिये आगे कोई प्रोजेक्शन नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि तमाम बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने आ जाने चाहिये, ताकि सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को पूरी तौर पर गौर करके अपनी राय देने का मौका मिले।

अब एक सवाल यह पैदा होता है कि इस बिल में जो जमीन उठाने का कारनकारों को दिया गया है, वह सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है, जो बेबा औरतें होंगी, जो नाबालिग बच्चे होंगे और जो फौज में मुलाजिम होंगे।

अब सवाल यह पैदा होता है कि बाज लोग ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होंगे और उनके घर पर भी कोई नहीं होगा तो उनको अपनी जमीन उठाने का हक होगा या नहीं? मेरे खयाल में कोई इसको पसन्द भी नहीं करेगा कि वह काश्त की हाजत ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मुलाजमत को छोड़ कर घर पर बैठे और काश्त करना शुरू कर दें। इससे मुल्क को भी बहुत नुसक़ान होगा। बाज लोग बहुत एन्डिशियरेंट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वे भी देश की खिदमत कर रहे हैं तो उनको भी इससे महत्त्व देना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा। बाज लोग ऐसे हैं, जो और ही शक्ल में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर भी यह पाबन्दी आयद कर दी जाय कि वे अपने घर पर बैठ कर काश्त करें, तो मेरी नाचीज राय में यह भी नामुनासिब होगा। ऐसे ईमानदार, मेहनत करने वाले, समकदार और खिदमत करनेवाले से मुल्क महत्त्व हांगा तो यह मुल्क की बढ़किस्मती ही होगी। बाज लोग तो ऐसे हैं, जो अपना नुक़सान बर्दाश्त करके भी आज मुल्क की खिदमत अन्जाम दे रहे हैं और वे उसे छोड़ना हरगिज

[ श्री मुहम्मद उवेदुर रहमान ख़ाँ शेखानी ]

गवारा नहीं कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर पाबन्दी लगा दी जाय, तो यह बिल्कुल नामुनासिब होगा। हो सकता है कि उनके जवान बेटा न हो जो उनके घर पर रह कर खेती करा सके, तो उस सूरत में उसको कम से कम अपनी काशत उठाने का हक देना चाहिये। और बहुत सी बातें ऐवान के सामने कही जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जरूर अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त इसपर गौर किया जाय तो इस नजर से किया जाय कि हकीकत में मुस्क को बेहतरी हो। एक तबके को अगर आपमिदा रहे हैं तो कम-से-कम उसको यह तसक़ोन हो कि मुस्क बेहतरी का काम हुआ, उसको यह इत्मीनान हो कि उसकी तबाही ने दूसरों को फायदा पहुँचाया और वह उसी शक्त में हो सकता है जब आप सब का बराबर लिहाज़ रखें और साथ ही इस ऐवान में जितनी बातें कही गई हैं उन्हें रही की टोकरी में न डाल दें बल्कि आजादी के साथ सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरान साहबान उस पर गौर करें और इत्मीनान के साथ बहस-मुबाहि़सा करें और जो मुनासिब समझें फैसला करें और अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह बतायें कि जो प्वाइंट्स इस ऐवान में उठाये गये हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया तो मेम्बरान को भी इत्मीनान होगा कि उनकी जो राय होती है उसकी वक़्त की जाती है और वह जो अपने खयालात का इजहार करते हैं उसका कोई फायदा होता है या मइज़न वक़्त का जाया करना होता है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आजम साहब का कि उन्होंने इतना मौक़ा हम लोगों को दिया कि हम लोग अपने खयालात का इत्मीनान के साथ उनके सामने इजहार कर सकें। मुझे इसका जरूर अफ़सोस है कि बाज़ लोगों ने इसे अपने पार्टी प्रापेगैंडे का जरिया समझा। मैं समझता हूँ कि यह बिल इतना अहम है कि इसे किसी पार्टी प्रापेगैंडे का जरिया बनाना किसी तरीके से मुनासिब नहीं था। इस वक़्त तो करोड़ों आदमियों की रोजी का, उनकी बेहतरी का, उनकी इस्ज़ाह और एक चीज़ जो असज़ी बंक्रोन है इस सूबे की यानी जराअत की तरक्की का सवाल पैदा है। यहाँ अशख़ास को भूल जाना चाहिये। यहाँ पार्टी को पसेपुशत डाल देना चाहिये। इस वक़्त तो सबका मुतफ़िद और मुतहि़द हो कर सूबे को, यह के रहने वाले लोगों को और जराअत की तरक्की की तमाम तजवीज़ों को सोचना चाहिये ताकि वह तमन्ना जो एक अरसे से सबके दिलों में रही है मुमकिन है कि इस तमन्ना के हुसूल के लिये बाज़ लोगों ने ज्यादा सरगरमी दिखाई हो और बाज़ ने कम लेकिन एक अरसे से लोगों में और सब के सब लोगों के दिलों में तमन्ना थी कि इस तरह की जिन्दगी बसर हो कि उसमें इत्मीनान हो, लुकून हो, फायदे की बातें हों और इस मुस्क को जो आजादी मिली है उसको कायम रखते हुये उसकी इज्जत दूसरे मुस्कों में कायम हो, बढ़े और तेज़ी से बढ़े। इस वक़्त हर शख्स को यह चाहिये कि दूसरे मुस्कों में इस मुस्क की कद्र हो। इसमें यह सूरत पैदा हो कि दूसरे मुस्कों के लिये यह मिसाल होकर रहे और लोग यह महसूस करने लगे कि हकीकतन यह लोग मुस्तहक हैं और इन्होंने अपनी तरक्की किस तरह से

हामिन् करनी है, यह भी आप देखेंगे कि हमारे बजौर आजम पंडित जवाहर लाल नेहरू इस बिल इस मुद्दे की ओर ध्यान देने के लिये इस तरह के सुझावों उठाने का लक्ष्य था कि यह बिल यह चाहे कि हमारे मुल्कों में यह मुल्क वह तरह की हामिन् करे और वह मुल्की हामिन् करे कि दुनिया का वह चमकता हुआ सिनारा हो कर रहे, तो उन्होंने इनको और आपकी लिखकर मदद करने चाहिये और आपकी मनाई और आपकी इच्छा करने शिक्कों को दूर कर देना चाहिये। इन अलमज के साथ से इनको नहीं करता हूँ और चाहता हूँ कि यह बिल सेनेट कमेटी में जाय और १५ अगस्त तक इस पर राय आम्मा आ जाय और उसके बाद यह नेकेंडी सेनेट कमेटी में जाय ताकि वह उन पर गौर कर सकें और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि ऐसे अहम बिल पर उनकी राय जरूरी नहीं समझी गई और अगर इस तरह से उनको मौका मिल जायेगा तो उन्हें पूरा इर्मनान हो जायगा।

माननीय प्रधान मन्त्रि के महा मंत्री ( श्री गोविन्द महाराज )—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, इस बिल के उपर आज ६ रोज से बहस हो रही है। काफी सामग्री मेम्बरान के सामने आयी है। मैं ज्यादा बज्ज न लेकर के जो कुछ वार्ने इस के खिलान उठई गई हैं, उन के बारे में कहना चाहता हूँ। बिल के बारे में दो तरफ से सुखालिफत की आवाज आयी। एक जमींदार साहवान की तरफ से, जिनका कहना था कि यह बिल कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं था, जमींदारी तुम्हें अभी खत्म नहीं करनी चाहिये थी। इसके करने से हमारा मुकलान हुआ और किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ। नवाब गुरुफ साहब ने यह भी कहा था कि अगर तुम हमें जिवह करोगे, तो याद रखो तुम भी जिवह हो जाओगे। दूसरा सोशलिस्ट दोस्तों की तरफ से आया। उनका कहना था कि यह बिल मुकम्मिल नहीं है। किसानों का कुछ थोड़ा-सा फायदा हो जाएगा।

लेकिन लाखों-करोड़ों जो मजदूर हैं, उनका फायदा नहीं होगा। यह अनइकानामिक होल्डिंग के सवाल को हल नहीं करता है। इसलिए यह बिल कोई क्रान्तिकारी बिल नहीं है। कांग्रेसी नेता जिन्होंने इस बिल को बनाया है, उनके अन्दर रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है। कोई क्रान्तिकारी स्पिरिट इस बिल के बारे में इस्तेमाल नहीं की गई है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस जमींदारी-प्रथा का सवाल है, यह एक बुनियादी सवाल है। आखिर इस प्रथा को क्यों खत्म किया जाय। क्या इसलिये कि जमींदार लोग जो हैं वह कांग्रेस के खिलाफ थे, या इसलिये कि उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत का साथ दिया था या इसलिये कि एक बड़ी वजह थी और बड़ी वजह यह है कि हम चाहें या न चाहें कि सामाजिक संस्था का विकास होता है सामाजिक संस्था प्रारम्भ से फलती फूलती है और उन्नत होती है और आखिर में उसकी तनज्जुली होती है। इसी तरीके से एक जमाने में जमींदारी प्रथा



[ श्री गोविंद सहाय ]

दुनिया के अन्दर फली-फूली और अन्त में उसका खात्मा हुआ। यह हो सकता है कि एक दुनिया ऐसी रही हो कि जमींदारी प्रथा का नाम रहा हो, लेकिन जिन मुल्कों में जमींदारी प्रथा जबरदस्ती रखने की कोशिश हुई, उन मुल्कों में आप देखेंगे कि बाऊई में वहाँ आखिर में ऐसी हातत पैदा हुई कि अन्त में वहाँ पर तबाही के जरिये से, मारकाट के जरिये से उस जमींदारी संस्था का सत्यानाश हुआ। यही हालात यहाँ पर भी हैं कि आप लोग इसको चाहें या न चाहें कि जमींदारी प्रथा को कायम रक्खा जाय, लेकिन इसके अन्दर जो पारस्परिक विरोध के कारण हैं, जो बुनियादी इखतलाफात हैं, वह खुद ही इसको खत्म कर देंगे, इसका नाश कर रहे हैं। अब ऐसे दोष इसके अन्दर पैदा हो गये हैं कि जिससे यह खुद ही खत्म होकर रहेगी। इसीलिये दुनियाँ के अन्दर यह संस्था खतम हुई है। अब सवाल आता है और आप देखेंगे कि जिन मुल्कों में इस नेचुरल ला को लोगों ने रोकना चाहा वहाँ पर इन्कलाब हुआ। जो मार्क्सवाद साइण्टिफिक सोशलिज्म के नाम से कहा जाता है, उसकी थीसिस केवल इसी वजह से गलत साबित हुई है कि दुनिया में जहाँ इन्कलाब होना चाहिए था, वहाँ न होकर खेती प्रधान देशों में हुआ। जहाँ पर इंडस्ट्रियलिज्म का विकास हुआ, वहाँ पर इन्कलाब नहीं हुआ। आपके सामने इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि जिन मुल्कों में इंडस्ट्रियलिज्म पूरे तरीके से पनपा है, वहाँ पर इन्कलाब नहीं हुआ; रूस एक एथिकलचरल कंट्री है वहाँ पर इन्कलाब हुआ। क्योंकि वहाँ पर ज़ारशाही ने जबरदस्ती एक गिरती हुई संस्था को कायम रखना चाहा। दुनिया के और मुल्कों में जिनके अन्दर जमींदारी प्रथा है, वहाँ पर कानून के जरिये से इस प्रथा का खात्मा हुआ और दूसरी जगहों पर इन्कलाब हुआ है। इसलिये जो कदम हिन्दुस्तान में उठाया गया है, मैं समझता हूँ कि वह बुनियादी तरीका है और वही बहुत-से मुल्कों ने अपनाया है उससे कोई और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है कि जो चीज खत्म होने वाली थी उसको कैसे खत्म किया जाय। खत्म करने के दो-तीन तरीके हो सकते हैं—एक तो म्युचुअल कन्सेन्ट, दूसरे मारकाट और तीसरे कानून। हो सकता है कि ज़मींदार लोग यह समझें कि यह वज्रत का तक्राजा है हमें खुद ही अपनी जमींदारी को अपनी मरजी से ही खत्म कर देना चाहिये। दूसरा तरीका कुश्तोखून का है। जो रशा में हुआ और आज चीन में हो रहा है। तीसरा तरीका नेगोशिएशन से हो सकता है। पार्लियामेंट के जरिये कानून बनाकर उस कानून के जरिये से खत्म किया जाय, सलाह के जरिये से, एक दूसरे को समझने के जरिये से इस चीज को खत्म करें। अब देखना यह है कि जो तरीका आज हिन्दुस्तान में इस चीज को खत्म करने का बरता जा रहा है, उससे बेहतर तरीका बरता जा सकता था या नहीं, हर मुल्क ने जिसने जिन्दा रहना चाहा है, उसने इसी तरफ़ से अपने यहाँ सोशल आर्डर के जरिये इस चीज को खत्म किया है। मैं इस बात को मंजूर करता हूँ कि कांग्रेसी मिनिस्ट्री की तरफ से

कोई सन्तुष्टि नहीं जा सकती है। प्रधान मन्त्री को अनुरोध ठहराया जा सकता है तो इसी बात पर कि उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखा कि जनसंख्या को कम्पन्सेशन के साथ खत्म किया जाय। लेकिन दुनिया में जिन तरह से यह सिस्टम खत्म किया गया है, उनमें मजदूर और नेक्स्टरन का तरीका ही अच्छा रहा है और इन लेजिस्लेशन के जरिये से हम यहाँ यह चीज खत्म कर रहे हैं। अब जैना कि मैंने आपने कहा, मैं इसका तस्मात्त में नहीं जाऊँगा। तस्मात्त में आपको बहुत कुछ बनाना पड़ा है। इन बातों की बुनियादी बातें क्या हैं, मैं उनको आपके सामने बनाना चाहता हूँ। एक एनरज किया गया है, कम्पन्सेशन के बारे में एक सवाल आता है कम्पन्सेशन का। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं अगर कोई यह कहे कि कुछ मन दो ठीक है। नाद्विन्दों की तादाद दुनिया में ज्यादा रही है और यह स्मॉगन हमेशा लोगों को अशान करना है कि बिल्कुल मत दो, लेकिन जब आप कोई चीज किया करते हैं, जिता दिनात्ता नजरिये में किया करने हैं तो आपका जो तरीका यह है कि उसे पुरस्मन तरीके से करें मुन्ह से करें, मेज से करें तो इनका लाजिमी नतीजा यह है कि जब आप लोगों की जमीनें ले तो इस तरह से लें कि उनके साथ इन्साफ हो और उन्हें यह मइमूस हो कि उनके साथ इन्साफ करने का प्रयत्न किया गया है, अगर सनाज के सुदुर्भी-भर आदमियों के दिल में यह चोट और कसक रही कि हमारे साथ में बेइन्साफी हुई, तो यह डिस्-टिस्फाइड (असंतुष्ट) तबका किसी भी राज्य के लिये खतरनाक हो सकता है। तो जब हम इन्साफ करने बैठते हैं तो हमें यह देखना होगा कि जिन लोगों ने अपना रुपया इन्डस्ट्री (रोजगार) में नहीं लगाया, जमीनों में लगाया और यह समझकर लगाया कि यही बेहतर इनवेस्टमेंट है और हिन्दोस्तान-जैसे कृषि प्रधान देश में यही बेहतर है, तो आज इस्लाफी तरीके से मैं कहता हूँ कि वह उनके साथ जुल्म होगा कि उन जमीनों को बिना कम्पन्सेशन के लें, उनकी औलादों को सजा दें कि उनके बुजुर्गों ने ऐसे जगह रुपया क्यों लगा दिया जो संस्था खत्म होने जा रही है। तो कम्पन्सेशन की बात उस दिमागी नजरिये के साथ मेल खाती है जिसके मतहत जमींदारी प्रथा को आप खत्म कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि उसकी हद एक लाख हो या आठ लाख हो तो यह तो प्रेक्टिकल कन्सिडरेशन की बातें हैं। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता है वहाँ लोगों को मौका है कि वह इस चीज को तय करें, लेकिन जहाँ तक उसूल का ताल्लुक है और जिस तरह यहाँ पोलिटिकल इक्वालिशन हुआ है, जिस तरह से हमारा देश आजाद हुआ है, पालियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन का विकास हुआ है, उसके साथ कन्सिस्टेंट यह है कि हम कम्पन्सेशन के उसूल को मानें। उसके बाद उसकी तादाद पर बहस हो सकती है, हर एक आदमी को कहने का हक है।

तीसरी बात जो इस बिल के बारे में उसूलों तरीके से उठाई गई, वह यह कि इस

[ श्री गोविन्द सहाय ]

बिल के से कोई खास फायदा नहीं होनेवाला है। जमींदारों की तबाही होनेवाली है, काश्तकारों को कोई खास फायदा नहीं होगा और कई बातें इसके सिलसिले में पैदा की गईं कि इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, आप इतना तो सोचिये कि इससे मंहगाई पर क्या असर पड़ेगा। इसमें शक नहीं कि यह सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बिल के अन्दर कमाल की बात यह है कि दोनों उसूलों का, आइडियलिज्म (आदर्शवाद) और प्रेक्टिकल रियलिज्म (क्रियात्मक यथार्थवाद) आदर्श और वास्तविकता का व्यावहारिक रूप इस बिल में मौजूद है। इसमें स्लोगन नोट नहीं है। इसमें हर बात पर विचार करके इस बात का ख्याल रक्खा गया है कि सबके साथ इन्साफ हो और समाज की तरक्की कैसे हो। यह इन्सानी फितरत है कि इन्सान अपनी जरा सी चीज के लिये अपनी जान भी दे देता है। इसी वजह से इस बिल के बनानेवालों के दिमाग में यह हर अमली चीज भी थी कि प्रचलित प्राइवेट प्रापर्टी का सिद्धान्त किसी तरह से उसको कायम रखें और जो आने वाला युग है, जो सोशलिज्म का युग है, जिसमें कल्टिवेटेड फार्मिंग होगी उसके लिये इस उसूल की प्रगति के लिए कैसे प्रोत्साहन दें। इस तरह से दोनों चीजों को कायम रक्खा गया, ताकि दोनों सिद्धान्तों को मिलाकर दोनों का समन्वय हो। साथ ही एक चीज और है कि हमारे दिमाग इस तरह से बदल गये हैं कि जिस चीज की कीमत न देनी पड़े वह ठीक नहीं मालूम पड़ती, उसमें खराबियाँ नज़र आती हैं और शक होता है कि यह चीज अच्छी है या नहीं। अगर कोई डाक्टर फीस कम लेता है, दवा के दाम कम लेता है तो मरीज के दिमाग में यह बात आती है कि वह दवा ठीक है या नहीं। हर चीज जो तकलीफ उठाने और दाम देने के बाद मिलती है, वह अच्छी मालूम होती है। लोग इस बिल के बारे में शक यह करते हैं कि इस बिल से जमींदारों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, जमींदारों को इस तरह से कि उसे जो रुपया मिलेगा, उसे वह इंडस्ट्री में लगायेगा, तो जमींदार का फायदा, किसान का फायदा और गाँव-पंचायत का फायदा, सबको तो फायदा हो नहीं सकता, यह नामुमकिन है कि सबका फायदा हो जाय।

यह हमारी दिमागी जहन्नियत का नतीजा है। हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि दुनिया में कोई इन्सान ऐसी चीज कर सकता है जिसमें सभी वर्गों का हित हो सके, क्योंकि हम समझते हैं कि किसानों के फायदे के मानी जमींदारों का अन्त है, मजदूरों के फायदे के मानी सरमायादारों का अन्त है। जब हमारे दिमाग में यह चीज बैठ गयी है कि एक के फायदे के मानी दूसरे का अन्त है तो हमारी समझ में यह बात नहीं आ सकती। मैं इस को इन्सानी दिमाग का करिश्मा समझता हूँ।

इस बिल में जितने भी इन्सेंटिव (प्रोत्साहन) हो सकते थे, जमीन से ज्यादा पैदा करने का इन्सेंटिव, किसानों की बढ़बूदी करने का इन्सेंटिव, कोआपरेटिव फार्मिंग

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विज्ञ ४७१

करने का प्रोत्साहन इंसेंटिव गांव की तरक्की करने का ग्याल मारे के सारे प्रोत्साहन इनमें दिये गये हैं। इस लिये जब इस विज्ञ पर गौर किया जाय तो इसके अमली पहलू पर भी गौर किया जाय। जब कोई चीज बनाई जानी है, तो उसमें जो पेचीदगियां पैदा होती हैं, उन पर भी गौर करना चाहिए।

इस में कोई शक नहीं कि रुम ने आर्डिनंस के जरिये से जमींदारी खत्म कर दी और जमीनों पर कब्जा कर लिया। यह कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। डा० लोहिया का कहना है कि चौबीस घंटे के अन्दर जमींदारी खत्म हो सकती है। मैं कहता हूँ कि एक मिनट के अन्दर खत्म हो सकती है। लेकिन किसी चीज को खत्म करने से वह खत्म नहीं हो सकती है उसके बनाने का सवाल आ जाना है। मुझे इल्म है कि इनने पेचीदे सवाल के ऊपर रूस-जैसे मुल्क को जहाँ पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी डिक्टेटरशिप थी, सारी सुविधाएँ थीं, के होने भी उस जैसे मुल्क को दस साल लगे और मैं अपने जाती तजुर्ब से कहता हूँ कि सन् १९३६ ई० तक रूस के किसानों के अन्दर यह प्रवृत्ति थी कि वह यह सुनना नहीं चाहते थे कि वह जमीन उनकी नहीं है, वह उसका मालिक नहीं है। मैं एक गाँव में गया और उन से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कलेक्टिव फार्मिंग होती है तो छुप-छुप कर किसान कहते थे कि जमीन पर हमारा ही नाम लिखा हुआ है। यह इन्स्टिक्ट प्रवृत्ति कि हमारी प्राइवेट जमीन है जब से इमान कायम हुआ है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह आप ज्ञान से दूर नहीं कर सकते। इस बिल में इन तमाम बातों का ख्याल रक्खा गया है जिस से यह एक व्यावहारिक तरीके का बिल बन सके। श्री राजाराम शास्त्री ने कल बड़ी मजेदार बातें कहीं निस्संदेह जब कोई स्पीच देता है तो उसको अख्तियार है कि वह ऐसी बातों का जिक्र भी कर सकता है जिस का मजमून से ताल्लुक हो या न हो। लेकिन मैं यह तबक्को करता हूँ और इसलिये ज्यादा तबक्को करता हूँ क्योंकि सोशलिस्ट लोगों का कहना है कि वह कांग्रेस वालों के मुकाबले में ज्यादा साइंटिफिक और कलचढे होते हैं। इस लिये जो बोलने का तरीका होना चाहिये, एक्सप्रेसन का तरीका होना चाहिये, और जो दलीलें होनी चाहिये, उनमें हमारे मुकाबले में ज्यादा बजन होनी चाहिये। कल स्पीच सुनकर मुझे हैरत हुई, हालाँकि कुछ लोग हँस रहे थे। लेकिन यह कोई एलेक्शन हाउस नहीं है न वोटर बैठे हैं, जिन को तोड़ने का सवाल हो। जो उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि बुनियादी तरीके पर वह उनकी पालिसी के अनुकूल है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी की पालिसी एक खास किस्म की है। गाँव में जाकर किसानों से कहेंगे कि गल्ला मत दो और शहर वालों से कहेंगे कि राशन जरूर होना चाहिये अगर छः छँटाक मिलता है, तो आठ छँटाक करवाओ। इस पालिसी के मातहत जहाँ भी मौका मिलता है, वह चूकते नहीं। इसी तरीके से मैं जानता हूँ कि पहले वे कहते हैं कि जमींदारी खत्म नहीं करेंगे और मुझे यकीन है कि जब जमींदारी खत्म हो

[ श्री गोविन्द सहाय ]

जायगी तो यही सोशलिस्ट जाकर जमींदारों से कहेंगे कि आप के साथ यह बेइन्साफी हुई है, आप की जमीन छिन गयी है इस लिये अब आप सोशलिस्ट हो जाइये वह तो दोनों तरीकों से काम लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो पालिसी की बात कही है मैं तबको करता था कि कोई ऊँची चीज होगी। लेकिन इस बिल के अन्दर बुनियादी तरीके से जो बात कही गयी वह इस के सिवा कुछ न थी कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं, अनएकोनामिक होल्डिंग्स है। यह एक वाक्या है। लेकिन इस के बजाय अगर आप यह कहते कि आप अपनी जमीन में उतना पैदा नहीं करते जितना पैदा करना चाहिये तो आप देखते कि क्या हालत होती।

अगर अनएकोनामिक होल्डिंग्स मिटाना है तो लोगों में इस चीज का अहसास होना चाहिये कि इस तरह की खेती नुकसानदेह है। इस लिये खेती को अपरेटिव फार्मिंग के बेसिस पर करनी चाहिये। पहले जब जमींदारी बिल नहीं आया था तो कहा यह जाता था कि यह बिल कभी नहीं लायेंगे क्योंकि यह जमींदारों से मिल गये हैं लेकिन अब बिल भवन में आ गया है तो यह कहा जाता है कि किसानों को तो फायदा हो गया लेकिन मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ है। हाज़ाँकि गाँव की इकानामी किसान के इधर उधर ही घूमती है। अगर किसान तरक्की करता है तो मजदूर की तरक्की जरूर होती है। गाँव में किसान के पास पैसा आता है और उसके घर में रौनक आती है तो स्वभावतया मजदूर पर भी असर पड़ता है उसे भी खुशी होती है कि किसान के घर में आज रौनक आई है। तो कल मेरे घर में भी रौनक आवेगी और उसकी मजदूरी की दर भी बढ़ जाती है यह एक ऐसा इंटर कनेक्टेड प्रोबलम है कि एक दूसरे से इसको काटा नहीं जा सकता। इनको तो स्लोगन्स लगाना ही अच्छा मालूम देता है। मैं यह कहता हूँ कि यह कोई प्रेक्टिकल तरीका नहीं है। बावजूद इसके कि सोशलिज्म अच्छा है या नहीं। लेकिन जो तरीका सोशलिस्ट पार्टी बर्त रही है उन तरीकों से तो अगर यह अच्छी चीज भी है तो भी उसको बड़ा नुकसान पहुँचा रहे है। मेरा यकीन है कि दुनिया भर में, हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं यह दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलते। सोशलिस्ट का रोल हमेशा एक ही रहा है।

“Either sappers and miners of communists or active agents of fascism.”

अर्थात् या तो कम्युनिस्टों के लिये रास्ता साफ करने वाले हैं सेपर्स या मायनर्स का काम करते हैं या फासिज्म को लाते हैं। और यह किसी पार्टी के बफादार नहीं रहते। मैं उनकी बात को समझना चाहता था कि उनकी इन तमाम बातों का और क्या अर्थ है। अगर उसके माने अवाम के फायदे के हैं, अगर इसके माने समाज के अंदर तरक्की करने के हैं, तब तो उनका हमारा मतभेद नहीं होना चाहिये। आखिर मैं मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने डिटेल्स को आवाइड किया है।

जो मुआविजा देने की वन गवकी गई है और जंगल-जमीन को इंसेन्टिव दिया गया है, वह ऐसा अमनी तरीका यानी मोन्यूशन है जिसमें वह जो काम चाहे कर सकता है। वैसे आप मुआविजा कहाँ से देंगे? अगर आप करेन्सी बढ़ा कर देंगे तो देश में इंफ्लेशन आयेगा। इस लिये जो मुआविजा दिया गया है, उससे समाज की चानका तरक्की होती चाहिये। इनमें इंफ्लेशन (मुआविजा) भी नहीं बढ़ेगा। जिनको दिया जाता है उनके अंदर प्रेरणा होती है कि इनका रुकना हमारे पास है इसको किमी न किसी उद्योग धंधे में लगें। इनमें देश की चानका तरक्की होती है। क्योंकि उद्योग-धंधों में रुकना रुकने से देश-का-ब्यापक बढ़ने है। समाज के अंदर फासदार को अगर फायदा होता है, तो मजदूर को भी फायदा होगा। गाँव का मजदूर खेती करना चाहता है, लेकिन आज उसके पास जमीन नहीं है। विज्ञेज पंचायत जमीन एक्वायर (ग्राम) कर सकती है और उनमें प्रेरणा पैदा कर सकती है। गाँव के अंदर जो दिक्कत है, उनको दूर कर सकती है। वसू-यात्री के गन्ने को तय कर सकती है। जमींदारों को भी एक मौका यह मिल देता है कि एक मोरल आर्डर जा रहा है चाहे उसे खुरी से जाने दीजिये या नाराजगी से वह तो जायेगा ही। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि दुनिया हवा के बहाव की रोक नहीं सकती है। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि आप लैण्ड लैंड्स को तो खत्म करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट (पूँजीपतियों) को खत्म क्यों नहीं करते।

ठीक है आजकल मूवमेंट बनाए जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि यह लैण्डनार्डिज्म (भूमि स्वामित्व) या कैपिटलिज्म (पूँजीवाद) ऐसी चीजें हैं कि जिन के खिलाफ दुरमनी रखने से कुछ नहीं होता और इन दोनों को किसी ताकत से भी खत्म नहीं किया जा सकता है लेकिन एक वक्त आता है कि जब यह एक आर्डर में ठीक नहीं बैठते और समाज का तकाजा होता है उम्मीद वक्त खुद-ब-खुद इनमें मिटने के कारण पैदा हो जाते हैं। आज जमींदारी निस्सन की वही हालत है कि आज का आर्डर खुद-ब-खुद उस को नहीं कायम रख सकता। लेकिन अभी कैपिटलिज्म उस हालत को नहीं पहुँचा है उस परिपक्व स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ है और जब वह उस परिपक्व स्थिति को पहुँच जायगा तो विनाश के कारण स्वयं ही पैदा हो जायेंगे। आज योरप में वह उस दशा को पहुँच गया है लेकिन अभी एशिया में वह अपनी उस मंजिल पर नहीं पहुँचा है कि जिस मंजिल पर उसको यहाँ का सोशल और एकानामिक आर्डर खुद ही मिटा दे। जिस तरह से जिस वक्त पेड़ में लगा हुआ आम पक जाता है, तो थोड़े से इशारे में ही गिर पड़ता है, लेकिन अगर आप कच्चे को ही गिराना चाहें तो वह मुश्किल से गिरता है और वह जायकेदार न होकर दातों को भी खट्टा कर देता है। कोई भी संस्था हो, संस्थाएँ उसी समय खत्म होती हैं कि जब उन में तरक्की करने के कारण लोप हो जाते हैं और गिरावट और विनाश के कारण बढ़ जाते हैं और उस का विनाश प्रारंभ हो जाता है। मुझे ताज्जुब होता है कि जब हमारे पढ़े-लिखे सोशलिस्ट भाई

[ श्री गोविन्द सहाय ]

ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने सोशलिज्म पढ़ा है, मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने पढ़ा है या नहीं। सोवियट रशिया में भी पूँजीवाद से सोशलिज्म की तरफ बढ़ने के लिए उन्होंने कोई तजुर्बा एकदम शुरू नहीं कर दिया, बल्कि उन्होंने जब नई जनरेशन को तैयार कर लिया उस वक्त यानी करीब २२ साल के बाद उन्होंने कहा कि अब हम सोशलिस्ट एकानामी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से स्लोगन्स से कैपिटलिज्म खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आप को एक आर्डर में तब्दीली पैदा करनी होगी। लोग यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे देश में कैपिटलिज्म का मसला कैसा है। कैपिटलिज्म एक एकानामिक आर्डर से ही नहीं आता है। उसका विकास बड़े पेचीदा तरीके से हुआ है—उसने लोगों के जीवन को बदला है और अपनी प्रणाली पर आश्रित बनाये रखने के लिये एक प्राचीन इनसीक्योरिटी का वातावरण पैदा कर दिया है—आदमी को बाजार में बिकने की सामग्री बना दिया है। आज महज्र जवान से कहने से या स्लोगन लगाने से कैपिटलिज्म दूर नहीं हो सकता। जब उस के खिलाफ समाजवादी सिद्धान्त और विचार-धारा लोगों में आ जायगी तब वह एक दिन भी नहीं ठहर सकता। आज आप यह हालत देखते हैं कि कोई भी स्टेट की चीज हो तो उस को लोग मुफ्त का माल समझते हैं और हर एक की नीयत होती है कि सरकार का माल है, आप का क्या जाता है एक बोरी सीमेंट दे दीजिए, उसमें क्या बनता-बिगड़ता है। जब यह हालत है तो आप कैसे अभी स्टेट इन्डस्ट्री की बात कह सकते हैं। जब तक हर एक के दिल में यह भावना पैदा नहीं होती कि स्टेट अपनी है और हम जो कुछ भी ईमानदारी से करते हैं वह अपनी स्टेट के लिए करते हैं और अपने ही फायदे के लिये करते हैं तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि यहाँ पर स्टेट की इन्डस्ट्री होनेसे कोई फायदा हो सकता है। सोवियट रूस ने इन्डस्ट्री पर कब्जा करने के बाद उस जनरेशन के लाखों आदमियों को ट्रेन किया और उस ने एक साथ कब्जा नहीं किया बल्कि आंशिक तरीके से और दूसरे तरीकों से किया। लेकिन यह सब इस तरीके से नहीं होता कि जिस तरह से यहाँ समझा जाता है कि गाली दो स्लोगन लगाओ और जिस तरह से भी हो, जो कुछ स्टेट करे उस की मुखालफत करो और वह समझते हैं कि यह तो क्या इस तरीके से ही अंग्रेज जैसे जबरदस्त लोग चले गए। यह स्लोगन मूवमेंट का जो प्रोसिन्चोर है मैं समझता हूँ कि किसी के भी हित में नहीं हो सकता। ऐसी चीज को दिमाग से निकाल कर हम लोगों को चाहिए कि वास्तविकता को देखते हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना चाहिए, न कि यह कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाय।

मैं कबूल करता हूँ कि मैं कानून नहीं जानता यह भी श्री चरण सिंह जी की मेहरबानी है जिससे मैं कुछ जान सका और जो कुछ समझा इस कानून से, जो खूबी मालूम होती है वह यही मालूम देती है हर प्वाइंट ऑफ व्यू से इंसानी दिमाग

मे जो कुछ मोचा जा सकता था और जिनको वंशान्त की स्थिति के साथ और अनन्वित के साथ मनाने हुए एक अर्थ में रज कर जा सकती थीं, एक निर्मा आदर्श की प्रेरणा दी जा सकती थी, वह सब इनमें है। इन सब बातों का संबंध इसमें है। एक ऐसा बिल पेश किया जा सकता जो चीनरू हो, जिनकी जमीन छिने वह भी मइमून करे कि सारे छिननेवालों था, इनकी नेमों की कि कुछ बच गयी, इन सब बातों का ख्याल रख कर इस बिल को पेश किया गया है। दुनिया में एक प्रमोशन पैदा करके, एक जगह पैदा करके कोई भी समाज को चला नहीं सकता है, अपने पक्ष के समर्थन के लिए इस बिल की जरूरत है कि आप एक नैतिक समर्थन प्रान कीजिए जिसके लिए किया जाए वह मइमून करे कि कुछ किया गया उससे अधिक हो नहीं सकता था और जिसके बिनाफ हो वह रहे, हालांकि बिनाफ है लेकिन इससे ज्यादा यह बेचारे कर नहीं सकते थे, यह सब पैदा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि जिस बुनियाद पर आप सोशल आर्डर रखना चाहते हैं, उसकी बुनियाद मजबूत होगी, वह ज्यादा दिन तक कायम रहेगी, वह कम्यूनिज्म के नूफान को और फासिज्म का मजबूती से मुकबला करेगी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और प्रधान सचिव को इस बिल पर मुबारकवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बिल के द्वारा वह सारी चीजें रक्खी हैं जिससे समाज में जो आर्थिक प्रश्न है, जो नफरत है, द्वेष-भावना है, इस किस्म की बातें जो लोगों में फैली हुई हैं, उनका खात्मा होकर लोगों में यूनिटी बढ़े। लोग मेल की बातें करें। इसी ख्याल से मैं कहता हूँ कि इस बिल में सब चीजें रक्खी गयी हैं, जो कमियाँ हैं वह तो कानून के पंडित बतलायेंगे, लेकिन जहाँ तक बिल की बुनियादी बातों का ताल्लुक है इससे ज्यादा गौरव की बात और नहीं हो सकती थी यह कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**माननीय माल सचिव ( श्री हुकुम सिंह )**—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बिल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करूँ इससे पहले मैं इस ऐवान से माफी का तलबगार हूँ क्योंकि ७ तारीख को मैं उपस्थित नहीं हो सका और विशेष कारण उसका यह था कि मेरी लड़की की शादी थी और मैं अस्वस्थ भी था। मुझे आशा है कि आप सब साहेबान मुझे माफ करेंगे।

जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है करीब ६ रोज से इस पर वहस-मुबाहसा हो रहा है और हमारे बहुत से साथियों ने अपनी-अपनी रायजनी की है और हमारे माननीय प्रीमियर साहब ने जो मोशन सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का इस हाउस के सामने पेश किया है, उसकी मुखालफत जमींदार पार्टी की तरफ से हुई है। एक तरमीम इस बात की लाई गयी है कि जनमत जानने के लिये इस बिल को प्रकाशित कराया जाए। मैं इस सम्बन्ध में कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर करना नहीं चाहता। जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है मैं अपने राजा साहब से यह अर्ज करूँगा कि वह इस तरमीम को वापस ले लें, क्योंकि आम राय सूबे में यही है कि



[ माननीय मान सचिव ]

जितनी जल्दी यह मसला तय हो जाये, उतना ही ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यह बात गलत नहीं है कि जमींदार तबके के कुछ लोग उसमें बहुत से मेरे दोस्त भी हैं इस जमींदारी के खत्म के सवाल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अगर राजा साहब की तरमीम मंजूर होती है, तो उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी, जिनकी नुमाइंदगी राजा साहब करने का दावा करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में मैं उस तरमीम की मुखातिफ भी करना अपना फर्ज समझता हूँ।

अब जहाँ तक बिल की उझूली बातों का तात्लुक है, माननीय प्रीमियर साहब ने बिल को इण्ट्रोड्यूस करते वक्त बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मुख्तसरन चन्द बातें मैं कह देना जरूरी और अपना फर्ज भी समझता हूँ। यह सूबे की माँग थी, देश की माँग थी, किसानों की माँग थी कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाय और यह माँग बिला वजह नहीं थी। उसके वजूहात थे, सैकड़ों प्लेटफार्म से उन वजूहातों का इजहार भी किया गया। कांग्रेस ने भी इस बात का ऐलान किया था कि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जायगा। उसने अपने एलेक्शन मैनीफैस्टो में इसे रक्खा था। वसी को पूरा करने के लिये यह बिल इस ऐवान के सामने लाया गया है। लोग भले ही कहें कि एलेक्शन मैनीफैस्टो में ऐसी बात नहीं थी, किसी की जबान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वह मैनीफैस्टो देखा जाय, तो उसमें इस बात का साफ ऐलान है कि एलेक्शन के बाद अगर कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस की मजारिटी हुई, तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया जायगा। लिहाजा उसकी पूर्ति के लिये, जैसा मैंने कहा, यह बिल इस ऐवान के सामने है।

यहाँ बहुत सी बातें इस बिल के सम्बन्ध में कही गईं। जमींदार पार्टी की तरफ से कहा गया, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया, जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी की तरफ से भी कहा गया, तमाम खामियाँ बयान की गईं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे इतने काबिल दोस्त साहबों ने तकरीरें कीं, खराबियाँ बताईं, लेकिन किसी ने कोई कान्सट्रक्टिव सजेशन नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं बताई जिस पर हम गौर कर सकते और जो खराबियाँ हों उन्हें दूर करने की कोशिश करते। अगर मुझे कोई शिकायत अपने दोस्तों से है तो वह इस बात की है। यह शिकायत आपसे ही नहीं, सेलेक्ट कमेटी से भी है। हमने मुस्लिम लीग पार्टी के काफी तादाद में और बहुत काबिल आदमियों को उसमें मेम्बर रक्खा था और मेरा ख्याल था कि वे उस कमेटी में जा कर अपनी राय से हमें इस बात का मौक़ा देंगे कि इस सवाल की जो दूसरी साइड है वह भी हम जान सकें और उस पर विचार करें। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती थी कि उन्होंने पसन्द नहीं किया कि उस कमेटी में शिरकत की जाय। शिरकत की गई, लेकिन आखीर में, जब तमाम फंडामेंटल बातें तय हो चुकी थीं। उस वक्त वह

कोई हमें मुलायम नहीं दे सकने थे, जिससे कि हम पूरा-पूरा फायदा उठा सकने। जैसा कि मैंने कहा हर रुदम पर दिक्कतें हमारे सामने पैदा की गईं। आज भले ही हमारे दोस्त लाली साहब बहुत सी बातें कहें कि इसमें यह न्यामी है। मुझे खुश है कि उन्होंने हमारे प्रान्तीय साहब की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो तक्रारों को बड़ गैलरी के लिये थी, इस ऐवान के लिये नहीं थी। महज प्रोपेगेन्डा के लक्ष्य से, सार्ज रोडरन हासिल करने के लिये और अचाम में अपना नाम पैदा करने के लिये ये बातें उन्होंने कही। जिस तरीक़ा से उन्होंने कमेटी में रिवरन्स की, उन तरीक़ा से इसी तरह की बातें करने आये हैं, और अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में भी इसी तरह की बातें की।

मैं तक्रारीत में नहीं जाना चाहता। न मेरी नवियन मौजू है, न इतना वक्त ही है, और दूसरे सदस्यों का वक्त मैं लेना भी नहीं चाहता। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें काम की मदद नहीं दी, हमेशा वे इधर-उधर की बातों करते रहे और अपना प्रोपेगेन्डा करने रहे।

अब आने हैं सोशलिस्ट भाई। हमारे भाई श्री गोविन्द सहाय को श्री राजाराम से शिकायत होगी। मुझे तो उनसे कोई शिकायत नहीं। उनकी ऐसी आदत ही है। वे ऐसा ही कहा करते हैं। वे स्तोत्र लگانा जानते हैं। अस्तित्व से उन्हें कोई ताल्लुक नहीं है। वे नहीं देखते कि उनके अल्फाज मौजू कहाँ पर हैं और नामौजू कहाँ पर। उनको पूरा लाइसेन्स (स्वच्छंदता) है। उनकी ज़बान की कोई पाबन्दी नहीं। उनके लिये मौ नियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे उनसे कोई शिकायत ही नहीं है। वे हमेशा यही कहते हैं कि इससे लेबरर्स को ज़रा भी फायदा नहीं है। वह ५ को ५ कभी कहेंगे ही नहीं, अगर कांग्रेस वाले ५ को ५ कहें तो वह कहेंगे नहीं यह तो १० हैं चाहे वाकई वह ५ ही हों। सोने हुये आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जागने हुये को कोई नहीं जगा सकता। इसलिये राजा रामसाहब की बातों को मैं ज्यादा अहमियत देना नहीं चाहता हूँ और इस बात में ज्यादा वज़न भी सर्क करना नहीं चाहता हूँ। रोशन जमाँ खाँ साहब ने भी कुछ कहा। ब्रद-किस्मती से मैं उस समय गैर हाज़िर था और मुझे यहाँ की बहुत सी और तक्रारों को सुनने का फ़क़ हासिल नहीं हुआ। अखबारों में जो पढ़ा उसी की बिना पर कहता हूँ। रोशन जमाँ खाँ साहब ने बड़ी लंबी तक्रार की। रालिबन वे गोंडा से सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और उस पार्टी की ओर से पटना कांग्रेस में नुमाइंदा होकर भी गये थे। अगर यह ठीक है तो कल तक तो बकीलों में भी उनका नाम रोशन नहीं था और वे मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से इस हाउस में आए और उस समय वह किस तरह की तक्रार करते थे, वह भवन को रोशन ही है। उनकी हर स्पीच से साम्प्रदायिक भावना टपकती थी और हर स्पीच कम्युनल होती थी आज वे सोशलिस्ट होकर क्लासलेस सोसाइटी के हामी हो गये हैं। कितनी जल्दी कम्युनलिस्ट से सोशलिस्ट हुये। हमारे भाई अगर यहाँ होते तो मैं कहता।

[ माननीय माल सचिव ]

जो इतनी जल्दी कार्यापलट करता है, वह कैसा हो सकता है, मैं इतनी जल्दी कार्यापलट नहीं करता। आदमी को हमेशा कान्सटेन्ट (एकसाँ) होना चाहिये और जो वह आज है उसको वहीं रहना चाहिये। यह नहीं कि आज लीग के हैं तो कल को जनता पार्टी के बन गये। फ़ख़रुल-इसलाम साहब अभी आपके बारे में तो कहा नहीं है आप क्यों परेशान होते हैं। जब लीग ख़त्म हुई तो जनता पार्टी बना ली अगर आज यह गड़बड़ हो जाती है तो कोई दूसरी पार्टी बना लेंगे। अभी कहीं सोशलिस्ट चुनाव में कामयाब हो जाते तो देखते कि कितने सोशलिस्ट होते। रोशन ज़माँ खाँ साहब ने जो बातें कही हैं, बदकिस्मती से उनमें एक भी बात ऐसी नहीं कही जो कन्स्ट्रक्टिव हो। ज़रा साफ़-साफ़ कहिये। हमें सोचने और आगे काम करने का मौक़ा दीजिये। अगर आपकी बातें मुनासिब हों तो हम उन पर ग़ौर करेंगे। सेलेक्ट कमेटी में बिल जा रहा है, इसी वजह से कि गवर्नमेंट इस बिल को ज़बरदस्ती नहीं ठूँसना चाहती है। वह जानती है कि यह करोड़ों आदमियों कि रफ़ा दफ़ा का सवाल है। एक दूसरा ही आर्डर चेन्ज करना है और उसकी जगह एक नया आर्डर लाना चाहते हैं। हम उसे इसी ऐवान में नहीं कर देना चाहते हैं, बल्कि सब को बहुत काफ़ी मौक़ा देना चाहते हैं, जिससे कोई ग़ल्ती न हो। और जो बात हो, सही हो। यही मतलब हमारे इस बिल का यहाँ पेश करने का है और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ़ से इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव यहाँ रक्खा गया।

लिहाज़ा यह कोई नहीं कह सकता है कि गवर्नमेंट इस बिल को ज़बरदस्ती पास करना चाहती है। इसलिये जब यह सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है, तो हमारे सामने कान्सट्रक्टिव सजेशन्स होने चाहिये। मैं अब भी दरख़्वास्त करूँगा जो मेम्बरान सेलेक्ट कमेटी में होंगे उनको, वे तैयार होकर आवें और कान्सट्रक्टिव सजेशन्स हमको दें। हम उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने राजा साहब से और ज़मींदार पार्टी से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको अब कम से कम प्रिन्सेज से सबक़ ले करके इस ज़मींदारी अवालिशन के उसूल को मान लेना चाहिये और उसूल को मानने के लिये वे बाध्य भी हैं। इस ऐवान ने ८ अगस्त, सन् १९४६ को जिस वज़त ज़मींदारी अवालिशन प्रस्ताव पास किया और उसके बाद जब कमेटी फ़ायम हुई तो इस ऐवान में जितने भी मेम्बरान हैं, उस उसूल को मान चुके हैं और उसको मानने के लिये बाध्य भी हैं। लिहाज़ा मैं फिर दरख़्वास्त करूँगा कि उस उसूल को मान करके आप सेलेक्ट कमेटी में आवें और जो कुछ भी आप कान्सट्रक्टिव सजेशन्स कर सकते हैं करें। अगर आप आज इस यूनियन के प्लैटफ़ॉर्म से, कल बारादरी से, पर्सों उन्नाव से और कहीं-कहीं से, जगमनपुर से, इस तरह से मीटिंग्स करके उस उसूल को भी नहीं मानते तो आप ज़मींदारी अवालिशन की ही मुख़ालिफ़त करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में आप क्या कान्सट्रक्टिव सजेशन दे सकेंगे आपकी कार्रवाई एक तरफ़ा होगी। यह मैं आप को

यक़ीन दिलाना चाहता हूँ, यह वाजदायर नहीं हो सकती। क्योंकि इस ऐवान के फैसले में कोई वाजदायर नहीं हो सकती। अदातनों के फैसले में वाजदायर हो सकती है। जब आप हाज़िर हैं और आप जवाबदेही नहीं करने हैं तो वाजदायर नहीं हो सकते।

अब मैं दो-एक बातें और करके ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इस बिल में हम लोगों ने और इस ऐवान के सदस्यों ने सबने काफ़ी वक़्त सर्क किया-अक़्त भी ख़र्च की और काफ़ी इनर्जी ख़र्च की। सोच-साच करके हम लोगों ने इसको बनाया। किसी साहब ने कहा, नाम मुझे याद नहीं-कि यहाँ तो मूवों में कम्पटीशन (होइ) है कि कौन सूवा पहले अवालिशन करता है। यह इल्जाम यू० पी० के सूवे पर नहीं हो सकता और सूवों ने चाहे जल्दी की हो, लेकिन हमने नहीं की। हमारे ऊपर हर तरह के इल्जामात भी लगाये गये। डाक्टर लोहिया साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम इन्वेक्शन के जमाने में लगाया था कि वह होने तो २४ घंटे में ज़मींदारी को ख़त्म कर देने और यह यू० पी० की गवर्नमेंट इसको ख़त्म करना नहीं चाहती। हमने काफ़ी वक़्त ज़मींदारी अवालिशन कमेटी में भी सर्क किया। हर सवाल पर हर पहलू से देख करके रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी वक़्त उसमें लिया और बिल तैयार हुआ। बिल में हमने इण्टरमिडियरीज (मध्यवर्ती वर्ग) का ख़ात्मा किया जैसा कि हमारे उस रेज़ोल्यूशन में था जो इस ऐवान ने पास किया था। और जो मौजूदा ज़मींदारी का टेन्योर है उसको ख़त्म किया। हमने वहीं क़नाअत नहीं की उसकी जगह हमने नया लैंड टेन्योर सिस्टम भी रक्खा, अनइकॉनामिक होल्लिडिंग्सके इकॉनामिक होने की गुंजाइश रक्खी और यह भी ख़याल रक्खा कि एक आदमी के पास बहुत सी ज़मीन अक्यूमुलेट न हो जाय जिससे फिर वही लैंडलार्ड और टेनेंसी सिस्टम कायम न हो जाय। ट्रान्सफ़र पर भी हमने पाबन्दी लगाई। कोआपरेटिव और करेक्टिव फ़ार्मिंग की भी हमने गुंजाइश रक्खी है। हमने ज़मींदारों की बड़ी-बड़ी फ़ार्मिंग और मैकेनिकल कल्टीवेशन को भी टच नहीं किया और इसको भी हमने गुंजाइश रक्खी है कि कम्पेन्सेशन के सवाल के बारे में जहाँ तक स्टेट की कैपैसिटी है, वी हैव गान दु दि अटमोस्ट। हमने बड़े ज़मींदारों को आठ गुना कम्पेन्सेशन देने की कोशिश की है। हमने छोटे ज़मींदारों को भी आठ गुना दिया है। लेकिन उनके साथ एक रियायत उनको रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट देने की रक्खी है। एक साहब ने अभी कहा है कि दोनों में डिफ़रेन्स न होना चाहिये। ज़रा रहम कीजिये उन छोटे ज़मींदारों पर। आप बड़े हैं। आपको आठ गुने में काफ़ी मिल जायगा और आप अपनी जीविका का इन्तज़ाम कर सकेंगे। लेकिन उन छोटे ज़मींदारों का क्या होगा, जिनकी आज हमारे ज़मींदार पार्टी के कुछ लोग नुमाइन्दगी करने को कहते हैं। ज़मींदार साहबान साफ़ तो नहीं कहते, लेकिन भावना इस बात की है कि छोटे ज़मींदारों को अगर रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट मिले तो हमको क्यों न मिले। वे छोटे हैं, ग़रीब

[ माननीय माल सचिव ]

हैं। उनको अगर हम रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट नहीं देते तो वे अपनी जीविका निर्वाह नहीं कर सकते। लिहाजा अगर उनको इतना मिलता है तो इससे आपको प्रज नहीं करना चाहिये बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिये और शाबाशी देना चाहिये कि छोटे गरीब तबके के ज़मींदारों का इस तरह से खयाल किया गया। ऐसी सूरत में इन सब बातों को देखते हुये आप जानते हैं कि १४० करोड़ रुपया का खर्च हो रहा है। ज़मींदार भाई यह भी कहते हैं कि हमको नक़द दिया जाय और यह भी कहते हैं कि आप तो ज़मीन किसानों के हाथ बेच रहे हैं। आप परेशान क्यों हैं। आप रुपया लीजिये और अपने घर जाइये। आज किसान रुपया देने के लिये तैय्यार हैं। किसानों की नब्ब को हमने टटोला है। हम जानते हैं कि वह रुपया देकर के ज़मीन लेना चाहता है। १० गुना रुपया देना उसके लिये बिल्कुल एक खेल है। लिहाजा आप ऐसा प्रोपेगेंडा और स्लोगन न उठाये कि आप उनके साथ रियायत क्या करते हैं, आप तो उनके हाथ ज़मीन बेचना चाहते हैं। आप यह भले ही कहते रहिये कि किसानों का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन यह सब बातें किसान खूब समझता है। किसानों को मुझसे भी बात करने का मौका मिलता है। वह समझता है कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। आजकल यह बार बार कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन (पैदावार) की बड़ी कमी है, इस लिये प्रोडक्शन बढ़ाया जाय, लेकिन सवाल यह है कि प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे जाय? आज हमारे सामने प्राइवेट प्रापर्टी (निजी सम्पत्ति) का सवाल है। जैसा गोविंद सहाय जी ने कहा। यह इन्सानी फितरत है कि जब तक आदमी अपने को किसी चीज़ का मालिक नहीं समझता है तब तक उसका जी नहीं लगता है। जब हम यह समझते हैं कि जो खेत आज हमारे पास है, उससे कल सुल्तान आलम खाँ साहब बेदखल कर देंगे तो हम उस खेत में काफी दिल नहीं लगा सकते हैं। अब अबालिशन (उन्मूलन) के बाद कोई काश्तकार बेदखल नहीं होगा। लिहाजा अब जब खेत उसकी प्रापर्टी (जायदाद) होगी तो वह हर तरह की कोशिश कर के प्रोडक्शन बढ़ायेगा। इससे जो हमारा आपका मतलब है, वह भी पूरा हो सकता है।

कुवर गुरुनारायण साहब ने दो सफ़ा पायनियर में निकाल दिये कि कम्युनिस्टों का जोर ज़मींदारियाँ खत्म होने के बाद और बढ़ जायेगा। मैं यह कहता हूँ कि जिन किसानों को वह बहकाकर फायदा उठाते हैं, अगर हम उनको मुतमइन कर देते हैं और वह अपनी-अपनी ज़मीन के मालिक हो जाते हैं जैसाकि उनको होना चाहिये तो वह भले ही प्रोपेगेंडा करते रहें, लेकिन वह नाकामियाब होंगे, नाकामियाब होंगे, इस तरह की बातें करना मुझे गलत सा मालूम होता है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। ज़मींदारी खत्म करने के कई वजहों हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ वह भी एक वजह है, लेकिन वह कोई

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रांत का जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विन ४८१

नई वान नहीं है। वह वान इस स्कोर पर कड़े मर्नवा रिपोर्ट की गई है। हमारे बदन सिंह माधव ने नवारीयों पर। जिनका उम्रसे नाल्टुक गडा होगा वह उनको ज्यादा सनने होंगे मैं तो ज्यादा समझ नहीं सका लेकिन उनमें यह जरूर मान्य हुआ कि बहुत सी जमींदारियाँ अंग्रेजों ने क्रियेट (निर्माण) की थीं उन्होंने ऐसा जरूरतन किया था। जब उनकी जल्दजल्द कायम हुई तो इनने करोड़ आदमियों से लगान वसूल करना उनके लिये नामुमकिन सी बन थी इसके अलावा जब तक घर का कोई भेदी नहीं होता है तब तक लंका भी फेंक नहीं हो सकती है। तो अंग्रेजों ने एक जमींदार क्लान क्रियेट करके उनके सुपुर्द एक कान किया कि आप हमारा इतने करोड़ आदमियों से लगान वसूल करने रहिये अगर मेरी यह दारत ठीक काम करती है तो मैं यह वनल अँगा कि शुरू शुरू में गालिवन १० फीसदी लगान वसूल करने के लिए जमींदारों को मिला था लेकिन जैसे जैसे जमींदार जोर पकड़ने लगे और उनका सिकका गवर्नर, बड़े बड़े आफिसर और बाइसराय पर जमता गया वैसे वैसे परसेंटेज प्रतिशत) बढ़ता गया इस वक्त परसेंटेज ५० से ६५ तक है।

इस ६५ फीसदी से ३५ फीसदी गवर्नमेंट रेविन्यू आता है। अब समझ लीजिये कि यह जिलेदारी कितनी मँहगी है। १६ करोड़ के करीब या १८ करोड़ कुछ लाख रेंटल सूबे में वसूल होता है। मालगुजारी वसूल होती है ७ करोड़ ८० लाख के करीब और १२ करोड़ के यह जमींदार फायदा उठाने हैं जिन के सुपुर्द कलेक्शन का काम किया गया है। कोर्ट आफ वार्ड्स को कलेक्शन के लिये २० फीसदी मिलता है। ६६ फीसदी वसूली चार्ज कहाँ तक वाजिब है, मुनासिब है। अंग्रेजी हुकूमत इसे कर सकती थी। इस क्रीमती एजेंसी को जनता की हुकूमत कायम नहीं रख सकती। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इतना रुन्या नेशन विल्डिंग डिपार्टमेंट में सर्फ हो सकता है। और इस से अवांम का फायदा हो सकता है इससे न देश का हित है न जनता का हित है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत आई तो देश गुनाह हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने जमींदार तबका पैदा करके ऐक्चुअल टिलर आफ दी स्वायल यानी काश्तकार थे उनको गुलाम बनवाया है। उनकी गुलामी की कोई हद नहीं। मैं बयान नहीं कर सकता। जब कांग्रेस के आन्दोलन हुए तो किसान कांग्रेस के कहने के मुताबिक और पूज्य महात्मा गांधी के अहकाम के मुताबिक अमल किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जेलों को भर दिया। यह उन्हीं किसानों की सहायता की वजह से हम लोग आसानी से अंग्रेजों को यहाँ से १२ बजे रात को रवाना कर सके। देश को आजाद कर सके। उनको आजाद होना चाहिये। इस जमींदारी का खात्मा करके हम किसानों की गुलामी को दूर करना चाहते हैं ताकि वह आजादी का पूरा पूरा फायदा उठा सके लिहाजा इस वजह से भी यह बहुत जरूरी अम्र है कि जमींदारी जल्द से जल्द खत्म की जाय। मैं

[ माननीय माल सचिव ]

अपने दोस्त राजा साहब जगमनपुर से फिर इस्तुद्घा करूँगा कि जो मैंने छोटी मोटी टूटी फूटी सलाह दी है, उसपर अमल करेंगे। वह कोशिश करें और यह देखें कि प्रिन्सेज ने कितनी बड़ी सैक्रीफाइसेज ( कुर्बानी ) की हैं, उन्होंने उफ़ नहीं की। देश के हित और कल्याण के लिए बड़ी बड़ी रियासतें आनन फानन में देश के सामने पेश कर दीं सारी जिम्मेदारी सरकार के सिपुर्द कर दी। वह नादान नहीं थे। वह बड़े समझदार हैं। उन्होंने यह समझा कि जाती फायदे के मुकाबले में देश का फायदा होना बहुत जरूरी है तो उन्होंने ऐसा कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरे सूबे के जमींदार और अवध के ताल्लुकदार उन से पीछे नहीं रहेंगे। वह अपनी उदारता का परिचय जरूर देंगे। जरूर उनसे किसी तरह कम न रहेंगे न पीछे रहेंगे। जो सैक्रीफाइसेज उन्होंने की हैं वह भी आजादी के लिए कदम आगे बढ़ाएँगे। हमारे नवाब साहब जमशेद अली ख़ाँ ने अपनी तकरीर में कहा कि किसान वोटर न होते तो कौन उन को पूछता ? जमींदारी कौन मिटाता ? जिन लोगो ने कांग्रेस का इतिहास देखा है, वह जानते हैं कि किसान जब वोटर नहीं था तब कांग्रेस उसकी हामी थी। जब हमारा शुमा को वोट देने का अख्तियार नहीं था। राजों महाराजों के दस पाँच वोट हुआ करते थे उस वक्त भी कांग्रेस ने किसानों की मदद को तैयार रही। उनके तहफ़फ़ुज के लिए लड़ी। उसी की कोशिश का यह नतीजा हुआ कि वक्तनफ़क्तन किसानों को भी वोट देने का हक़ मिला। यहाँ तक कि अब हर बालिग को वोट देने का हक़ मिला। लिहाजा उनका वोट नहीं था जब भी उनके पैरोकार थे। उन्हें वोटर बनवाया। अब भी उनके पैरोकार हैं। किसान हमारे सूबे की बैकबोन हैं। किसान की हालत अच्छी न हुई तो हमारे सूबे की हालत कभी अच्छी नहीं हो सकती। लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि वह समझेंगे। पुराने तरीके जो भी रहे हों नए ढंग से सब को चलना है। उन की खिदमत करने के शौक में लग जायेंगे।

हमको भी उनकी खिदमत करनी चाहिये। लिहाजा इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि कांग्रेस किसानों की मदद के लिये चँकि वे वोटर्स हैं इसलिये ऐसा करना चाहती है। मैंने आप साहबान का ज्यादा वक्त ले लिया इसलिये मैं अब ज्यादा कुछ न कह कर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब इस मसले पर बहस बन्द की जाय।

डिप्टी स्पीकर—कल भवन ने तय किया था कि ४ बजे तक और तकरीरें हों और ४ बजे माननीय प्रधान सचिव जवाब देने के लिये खड़े हो जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसके लिये प्रस्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है।

( इस अवसर पर श्री ऐजाज रसूल बोलने के लिये खड़े हुये । )

सन १९७२ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी-बिनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ४८३

डिप्टी स्पीकर—आप यह समझ लें कि ४ बजे आपको अपनी तकरीर खत्म कर देनी होगी।

श्री ऐजाज रसूल—मेरा कोई रुत तो नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—कल भवन ने तय कर दिया था और मैं समझता हूँ कि भवन के फैसले के बाद अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री ऐजाज रसूल—जनाववाला कोई रिज्योनरान नाम हुआ था।

डिप्टी स्पीकर—मैंने कहा कि यह भवन का फैसला है। अगर आप मौजूद होते तो आपको भी उनका इल्म होना।

श्री ऐजाज रसूल—जनाववाला, मुख्यतः मुअज्जिज मेम्बरान ने अपने मुख्यतः खयालान को इस ऐवान के सामने पेश किया और अपने नुकतेनजर को रक्खा। कांग्रेस गवर्नमेंट हम वहाँ से कि जगायती और इकतनादी हालत अच्छी करे और काश्तकारों की हालत अच्छी हो, जमींदारी को खत्म करना चाहती है। जमींदारी एवानिशन रिपोर्ट में भी इस मसले पर काफी कोशिश की गयी, लेकिन मैं चन्द बातें इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ कि आया इसके करने से फायदा होगा या नुकसान।

अगर आप देखें तो मालूम होगा कि स्कैटर्ड होल्डिंग (नितरे बितरे खेत) हमेशा के लिये कायम रही। कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग (खेतों की चकबंदी) के नाम पर एक काश्तकार की एक बीघा जमीन ले ली जाय और उसकी बिना पर वह काश्तकारी में तरक्की कर सके तो यह इस बिल में बिलकुल नामुमकिन हो गया है। फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग (खेतों के टुकड़े) भी कायम रहे और अनइकनामिक होल्डिंग भी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो जायगी। लिहाजा उसका नतीजा यह होगा कि काश्तकारों में पार्टेशन (बटवारा) बराबर होता रहेगा और भूमिदार और सीरदार भिन्न जुल कर काम करेंगे। यही जो दो बातें मैंने आप को बतलायीं उस से आप को साफ जाहिर होगा कि जिस जगह काश्तकारी कायम थी वही रहेगी। फ्रैगमेंटेशन आफ होल्डिंग और स्कैटर्ड होल्डिंग भी कायम रही। नतीजा यह हुआ कि कोई भी इम्प्रूवमेंट (सुधार) सूबे के किसानों की हालत में जाहिर नहीं हुआ। अब रहा यह कि बिल मेरे खयाल में काश्तकारों और सूबे के फायदे के लिये नहीं बनाया गया है, बल्कि एक खास मकसद के लिये इसलिये बनाया गया है कि आइन्दा के लिये भूमिधरों और सीरदारों की एक आर्मी (फौज) पैदा की जाय ताकि इससे पोलिटिकल राजिनीतिक फायदा उठाया जा सके।

ॐ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।



[ श्री ऐजाज़ रसूल ]

मेरे ख्याल में जब जमींदारी खत्म हो जायेगी तो कम्पेन्सेशन उसे बहुत दिनों में मिलेगा । नतीजा यह होगा कि जमींदारों को उनकी औलाद को उनके रिश्तेदारों को और उनके मुवाजिमीन को बहुत परेशानी होगी और उसका नतीजा यह होगा कि कम्प्यूनिज्म बढ़ेगा और इस सूबे में लोग बजाय इत्मीनान के जिन्दगी बसर करने के जिन्दगी एक नर्क और परेशानकुन हो जायेगी । इसलिये गवर्नमेंट को चाहिये कि कम्पेन्सेशन को एक साथ फौरन अदा कर दे, बजाय इसके कि बाद को यह रक्खा जाय कि वह लिटीगेशन ( मुकदमें बाजी करे ) और तमाम और कार्यवाहियाँ करें और उसकी वजह से तमाम और बहुत सी मुसीबतें उठावे । दूसरी बात यह है कि इससे खुशहाल काश्तकारों को बढ़ाया गया है यानी वह काश्तकार जो भूमिधर होने के लिये १० गुना दे सकता है उनको राइट्स हकूक मिल जायेंगे वरना और जो और काश्तकार हैं उनकी हालत वही रहेगी । जो गरीब काश्तकार हैं, जो अधिवासी हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स भूमिहीन मजदूर हैं उनके पास रुपया है नहीं इसलिये उनकी हालत अभी खराब ही रहेगी क्योंकि जमीन किसी तरह निकाली नहीं जा सकती । लिहाजा ज्वाइंटली (सम्मिलित रूप से) और सेपरेटली (व्यक्तिगत रूप से) उनका उसमें खर्चा होगा । अगर वह लगान नहीं अदा कर सकेगा तो गवर्नमेंट तो अपना लगान बसूल कर ही लेगी । जो जमीन जिसके पास है वह करीब करीब कायम रहेगी और अनएकनामिक होलिडिंग्स का मसला बिलकुल हल न हो पायेगा । जो मौजूदा काश्तकार है अगर वह अपने लगान का १० गुना अदा करता है तो भूमिधर हो जाता है और नहीं करता है तो काश्तकार की सूरत में कायम रहेगा । हाँ, भूमिधरों को इस बिल में बढ़ाया गया है । उनको राइट्स आफ ट्रांसफर (हस्तांतरण का अधिकार) मिल गये । ट्रांसफर के राइट्स पंजाब और एन० डब्लू० एफ० पी० में भी दिये गये थे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों आदमियों की जमीनें खत्म हो रही हैं तो उनको मजबूरन लैंड एलियनेशन ऐक्ट जारी करना पड़ा । वही आपको भी करना पड़ेगा वरना कुछ दिनों के बाद इस तरह से एक के बाद दूसरे के पास जमीन चली जायगी और आपको कोई फायदा नजर न आवेगा ।

अब इसके साथ यह भी देखना है कि गवर्नमेंट ने कोई प्रोपोजल ( प्रस्ताव ) कर्जे के बाबत नहीं किया है अगरचे इस सूबे में रिजोल्यूशन भी पास हो चुका था । अगर आप कोई उस पर कार्यवाही नहीं करते और कोई बिल ऐसा नहीं लाते तो जो जमींदार मकरूज हैं और जिन्हें न कम्पेन्सेशन मिलेगा उसकी हालत वेसी ही उसी सूरत में चली जायगी । हमारे आनरेबिल प्रोमियर साहब ने बहुत मेहरबानी से यह कहा था कि ऐथीकल्वर इनकम टैक्स लगेगा । मुझे डर है कि कहीं वह कम्पेन्सेशन उसी के अन्दर न मान लिया जाय । इस सूरत में कहीं यह न हो कि परेशानी बढ़े और हमें आप को इसका नतीजा बुरा भोगना पड़े । और इधर यह है कि कर्जे की डिगरी हो जायगी । उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वह

फाके मन्म हो जायेंगे ! लिहाजा इसकी तरफ भी आनरेबल प्रीमियर साहब को नजरअंदाज करनी चाहिये और भी बहुत सी चीजों के बारे में काफी कहा जा चुका है । लिहाजा बचन कम होने की वजह से मैं कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ । डिप्टी स्पीकर साहब की यह इजाजत है कि १५ मिनट से ज्यादा कोई साहब न लें । मैं बहुत सी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और वह है कंइनैन्स (अर्थ) के बारे में । गवर्नमेंट को कंइनैन्स में किस तरह से फायदा होगा । सरकार पहले १० गुना काश्तकार से लेगी । आनरेबल प्रीमियर ने अपनी तकरीर में खुद फरमाया था कि चार करोड़ रुपया हमें अपने फंड से खर्च करना पड़ेगा और इसमें दो करोड़ रुपया और अपनी तमाम मशीनरी के तैयार करने में खर्च करना होगा । नतीजा इसका यह होगा मेरे ख्याल में कि बजाय फायदे होने के गवर्नमेंट को नुकसान होगा क्योंकि यह बिल जो बनाया गया है इसमें देखा जाय तो हममें एक मशीनलिटिगेशन (मुकदमे बाजी) की कायम कर दी गई है । उसका नतीजा यह होगा कि उससे बकता को फायदा होगा । दूसरी बात यह है कि लैंड रिकार्ड तैयार किये जायेंगे और रेविन्यू मुनाजमीन जो हैं उनको ठीक करने के लिये रखने पड़ेंगे । तो बजाय इसके कि फायदा हो और नुकसान होगा और खर्च बहुत ज्यादा होगा । अगर गवर्नमेंट सिम्पुल सीधा तरीका अख्तियार करे तो अच्छा है । उसके लिये एक सिम्पुल कानून बना दे और कम्पन्सेशन के लिये बक्त मुक़र्रर कर दे, जमींदार खुद अपनी तरफ से अपने काश्तकार के हाथ अपनी जमीन बेच दे । सेलिंग प्राइस (क्रय मूल्य) गवर्नमेंट मुक़र्रर कर दे कि उससे ज्यादा कोई न ले तो इससे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा होगा । रजिस्ट्री की इन्कम आमदनी हो जायगी और उससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फायदा उठायेगी । लिहाजा मेरे ख्याल में बजाय इसके कि कोई काम्प्लीकेटेड उलका हुआ, कानून बनाये उसके लिये एक सिम्पुल तरीका अख्तियार करे तो बहुत फायदा हो सकता है । हुकुमसिंह साहब ने कहा था कि कोई कन्स्ट्रक्टिव सजेशन (सक्रिय सुधार) नहीं पेश किया गया । लिहाजा मैं यह अपना सजेशन पेश करता हूँ कि इस पर गौर किया जाय । मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट कमेटी में इस मामले पर गौर किया जायगा । बजाय इसके कि गवर्नमेंट १० गुना वसूल करे और एक लम्बी मशीनरी बनाये और एक बिल पेश करे और दूसरी तरह की दिक्कत आवें और दूसरे किस्से पैदा हों गवर्नमेंट को चाहिये कि एक सिम्पुल बिल पेश कर दे कि जमींदार अपनी जमीन को अपने काश्तकार के हाथ बेच दे और जमीन की प्राइस सरकार मुक़र्रर करदे तो इससे बहुत रुपया सरकार का बच जायगा और आसानी से यह काम हो जायगा और यह तमाम फगड़े जो कम्पन्सेशन के होंगे वह भी नहीं होंगे कि साहब ६ महीने तक अगर कम्पन्सेशन नहीं मिला तो फिर वह दरखास्त दे और कुछ उसको ढाई परसेण्ट का इण्टरेस्ट मिलेगा । और अगर गुजारेदार अब दावा कर दे कि साहब हमारा हिस्सा है हमको भी कुछ

[ श्री ऐज़ाज़ रसूल ]

मिलना चाहिये, इनको पूरा कम्पेनसेशन न दिया जाय तो और भी लम्बे ऋगड़े पैदा हो जायँगे जिनमें बहुत दूर हो जायगी और रुपया भी ज्यादा खर्च होगा। इसी तरीके से और भी किस्से बढ़ते जाँयगे और परेशान हाल हो जायँगे। अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि डिप्टी साहब की नज़र मेरी तरफ है और मेरी नज़र घड़ी पर लगी हुई है। इसलिये मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ।

\* माननीय प्रधान सचिव ( श्री गोविन्द वल्लभ पंत )—श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल पर छः दिन से बहस मुबाहिसा इस ऐवान में हो रहा है। मैंने इस बात की कोशिश की कि जो कुछ भी बातें इस बिल के बारे में कही गयीं उनको गौर से सुनूँ। मैं इस बिल को इस नजरिये से नहीं देखता जो कि आम तौर पर अपोजीशन के मेम्बरों की तकरीरों में भलकता था। मैं इसको एक बहुत गम्भीर और अहम मामला समझता हूँ और इस बारे में कोई सियासी, राजनीतिक या और तरह के किसी जज़्बात को लाकर अपने दिमाग को सही नतीजे पर पहुँचाने में कोई रुकावट डालना, इस मामले में किसी तरह से मुनासिब नहीं समझता और मैं उम्मीद करता था कि कम से कम ज़मींदार साहबान और और लोग जिनके ऊपर कि इस बिल का असर पड़ता है वह काफी एक जिम्मेदारी के साथ इसके ऊपर अपने ख्यालात जाहिर करेंगे और अपनी तबियत को उसी तरीके पर रक्खेंगे। मगर जब गौर मुताल्लिक बातें कही जाती थीं, उनके ऊपर उनके क्रहक्रहों को मुनता था तो मालूम होता था कि वह इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं कि कितनी बड़ी अहम बातों का फैसला इस वक्त हाउस कर रहा है और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज है कि हर बात पर जो कि यहाँ कही गयी उस पर गौर करें और सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को सुधारने की कोशिश करें। हमारी ख्वाहिश यह है कि इस बिल के जरिये इस सूबे की बहबूदी और बेहतरी हो। इस बिल के जरिये, आज चाहे न दीखे, आखिर में ज़मींदारों की भी तरक्की और बहबूदी होगी और आमतौर पर जो कि इस सूबे में करोड़ों की तादाद में किसान और काश्तकार रहते हैं जिनकी मेहनत से हम सब लोग पलते हैं और जिनके दिये हुए नाज से हम ज़िन्दा रहते हैं और जिनके दिये हुए पैसे से हमारी गवर्नमेंट चलती है, उनकी भी इससे भलाई है और वह बराबर आगे बढ़ते रहें इन ख्वाहिशों से, इन जज़्बात से और इन मकसदों को सामने रख कर हमने इस बिल को पेश किया और जो भी बातें कही गयीं उनको इन्हीं कसौटियों में कस कर हम देखेंगे। अगर वह हमारे इन उद्देश्यों के पूरा करने में किसी तरह से मदद दे सकेंगे तो उनके ऊपर हमें हमदर्दी से गौर करना होगा और अगर उनका असर उनके खिलाफ हो तो इन्हें छोड़ना होगा। आज कोई कतई फैसला इस मसले पर हमें करना नहीं है, मगर तब भी जो कुछ बातें कही गयीं उनके सिलसिले में जो ज्यादा बुनियादी और ज्यादा अहमियत की बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वाक्यात

❖ माननीय प्रधान सचिव ने अपना साधण शुद्ध नहीं किया।

आपके सामने वेग कर रहे हैं कि अगर कोई गन्तव्य नहीं है तो वह दूर हो जाय। जब गन्तव्य नहीं है और जागना हुआ सोने का बहाना करे, वह तो किनारा है उनमें हिन्दीओ वह जागना नहीं। मगर दर अन्त कोई सोया हुआ हो तो उनको जाग कर, असहियत को उम्मे समझाना हर एक के लिये सुनायित होना है।

राजा जगन्नाथ बख्श सिंह ने एक तजवीज यहाँ यह की कि इन बिल को दिवसवार तक मकसद (गन्तव्य) में डाल दिया जाय ताकि उन पर गौर हो सकें और उन्होंने कहा कि उन को बक्त नहीं मिला कि इस के उपर वह और दूसरे जमींदार गौर कर सकें। मुझे उन को तजवीज सुन कर ऐसा लगा कि अब भी जब कि जमींदारों के बिल का बक्त आ गया है जमींदार चेने नहीं हैं। एक महीने के करीब बक्त मिला चुका ऐसे जरूरी बिल पर जिस का नतीजा उन के लिए आइन्दा जवर्दन हो सकता है।

श्री जगन्नाथ बख्श सिंह - मैं अपनी मफाई में दो अलफाज कहना चाहता हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैंने बिल को देखा या समझा नहीं है। मैंने जो मोशन किया है, उन के सपोर्ट (अनुमोदन) में मैंने जो दलीलें प्रीमियर के सामने पेश कीं उन को मद्देनजर रख कर मैं जवाब सुनने का मुस्तहक हूँ।

माननीय प्रधान सचिव—राजा साहब ने जो बात कही है वह नयी नहीं है और न वह ऐसी है जिस की मुझे जानकारी न थी। अगर उन को इस बिल की अहमियत मालूम थी और उन्होंने इस की काफी जानकारी हासिल कर ली थी और जहाँ तक उनका ताल्लुक है उन को देरी से फायदा नहीं है तो जमींदार लोग तो हमेशा औरों की ही भलाई हर तरह से करते रहे हैं। तो अब मालूम हुआ कि यह भी जो तजवीज राजा साहब ने की वह जमींदारों की भलाई की नीयत से नहीं की, या उनको और बक्त देने की नीयत से नहीं की बल्कि इस लिए की कि जिस से गैर जमींदारों को मौका मिल सके कि वह जमींदारों के मसले को ज्यादा समझ सकें। अगर यह सही होता तो गैर जमींदारों की तरफ से यह उज्र आ सकता था और वह कह सकते थे कि हम को बक्त नहीं मिला, हम समझ नहीं पाए, हमारी ज्यादा हमदर्दी जमींदारों के साथ है और वह खुद इतनी अक्ल और समझ नहीं रखते कि किसी नतीजे पर पहुँच सकें, लिहाजा हम को बक्त दिया जाय ताकि उनकी मदद कर सकें। मगर किसी की तरफ से ऐसी आवाज आई नहीं। और जहाँ तक और तबकों का ताल्लुक है, चाहे वह जनता के नाम से कहा जाय, चाहे मुस्लिम लीग की पार्टी के नाम से कहा जाय, चाहे लारी साहब की पार्टी के नाम से कहा जाय या फखरुल इस्लाम साहब के नाम से कहा जाय लेकिन जहाँ तक राजा साहब के अमेंडमेंट का ताल्लुक है सब ने उस का विरोध किया है और कोई उस की ताईद करने वाला जमींदारों के बाहर मिला नहीं। तो औरों की फिक्र अगर राजा साहब

[ माननीय प्रधान सचिव ]

को थी तो अब उन को मालूम हो गया कि उन लोगों की खाहिश नहीं है कि इस पर ज्यादा गौर करने के लिए इस को और ज्यादा मुलतवी किया जाय। लिहाजा बेहतर यह है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

राजा साहब ने अपने संशोधन के सिलसिले में कहा कि मैंने इस को इस लिये पेश किया है कि जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट और इस बिल में फर्क है। मैं जानना चाहता हूँ कि राजा साहब को जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट ज्यादा पसन्द है या बिल ज्यादा पसन्द है। वह अब भी कह सकते हैं। अगर वह जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को ज्यादा पसन्द करें तो फिर हम बजाय इस बिल के जो जमींदारी अबालिशन कमेटी की सिफारिशों थीं उन्हीं के मुताबिक सेलेक्ट कमेटी में कार्यवाही करें।

श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—मैं तो यह अर्ज करता हूँ कि मैंने जो फर्क बतलाया है रिपोर्ट और इस बिल में, उस के बारे में काश्तकारों की राय मालूम की जाय। इस की राय काश्तकारों से मिली है या किसी दूसरे से मिली है ?

माननीय प्रधान सचिव—तो सवाल है कि जहाँ तक जमींदारों का ताल्लुक है राजा साहब को कोई शिकायत नहीं है। इसके बारे में जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में जो तरमीमात इस बिल में की गई है उसके लिए राजा साहब कोई वक्त नहीं चाहते हैं। उन तरमीमों के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं है। मगर भेड़िये को हमेशा भेड़ ही की फिक्र रहती है। इसलिये राजा साहब को फिक्र है काश्तकारों की कि उन्होंने अभी इसको नहीं देखा लिहाजा उनको वक्त मिलना चाहिये ताकि वे इसपर राय दें। क्या मैं राजा साहब को बतला सकता हूँ कि काश्तकारों की राय बगैर इसको देखे हुये यह है कि मुआविजा कुछ न दिया जाये और उनको जमीन का मालिक बना दिया जाय ? अगर राजा साहब इसके लिये कोई प्लैवीसाइट ( जनमत संग्रह ) कराना चाहते हों तो मैं तैयार हूँ। जमींदार इस बात पर तैयार हो जायँ कि काश्तकारों से पूछा जाय कि जमींदारों से जमीन मुआविजा देकर ली जाय या बगैर मुआविजे के ली जाय और जो उनकी राय हो उस पर अमल किया जाये तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। अगर यह बात मान ली जाये तो मैं इस बिल को ही मुलतवी करने के लिये तैयार हूँ।

श्री जगन्नाथ बरुश सिंह—मैं यह रिक्वेस्ट ( प्रार्थना ) करता हूँ कि जमींदारों को मुआविजा काश्तकारों से नहीं मिलेगा बल्कि सरकार से मिलेगा। इसलिये काश्तकारों की राय की जरूरत नहीं है।

माननीय प्रधान सचिव—तो जहाँ तक राजा साहब का ताल्लुक है उनका ताल्लुक सिर्फ सरकार से है। कोई मतलब उनका काश्तकारों से नहीं है। लिहाजा जब काश्तकारों से उनका कोई मतलब नहीं है तो फिर सरकार के बारे में उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है और जो हम काश्तकारों

से रिश्ता या नत्ता रखने हैं वह इस बात की है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह हमारा लक्ष्य है कि उसको वह जानें है और हम भी जानते हैं कि जो कुछ हम उसमें लिये कर रहे हैं वह उनको पसंद है। लिहाजा इसके बारे में उनको ज्यादा किरा करने की जगह नहीं है। अब और किसी नदके की कोइ बात रह नहीं जाती है।

दूसरी जो बातें इस बारे में कही गई उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। विल में जहाँ तक हो सका है इन बातों की कोशिश की गई है कि मुआविजा बड़े और छोटे जमींदारों को एक शर्ह में दिया जाये यानी छठगुने के हिस्से से दिया जायेगा। राजा साहब राजा हैं, वह बहुत बड़े जमींदार हैं। अगर वह यह चाहते हों कि मुआविजा एक शर्ह में दिया जाना ठीक नहीं है और यह चीज उनकी शान के खिलाफ है तो जैसा कि विल में पहले था यानी जमींदारी अवलिशन कमेटी की रिपोर्ट में था, वही उनकी शान को कायम रखने के लिये दुगुना ही कायम रक्खा जाये तो इसके ऊपर भी हम लोग गौर करने के लिये तैयार हैं। इसके अलावा इस विल में यह नजवीज की गई है कि यह जो मुआविजा दिया जाये वह नकद देने की कोशिश की जाय और जमींदारी अवलिशन कमेटी की रिपोर्ट में था कि मुआविजा बौण्ड्स के रूप में दिया जाय, जो कुछ तो निगोशिएबिल बौण्ड्स हो और कुछ नॉन निगोशिएबिल बौण्ड्स हो। अगर आपको बौण्ड्स ही पसंद हो तो हम आपके हुक्म की तामील करने के लिये तैयार हैं। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिये क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में जिस वक्त आप यह तरमीन करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मुखातिफत नहीं होगी। इसके अलावा इस विल में जो कुछ मुआविजा और जमींदारों के लिये रक्खा गया है वह पहले से बहुत ज्यादा है। अगर जमींदार साहबान चाहते हैं कि इनको कम कर दिया जाये तो इसके लिये हमें कोई शिकायत नहीं होगी। अब कौन सी बात बाकी रह जाती है जिसकी उन्हें शिकायत है, मैं नहीं जानता। विरसत के बारे में कहा गया है कि यह टेनेंसी ला के मुताबिक करीब करीब होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जिस जमींदारी अवलिशन कमेटी की रिपोर्ट पर वह भरोसा रखते हैं उसमें भी यही कहा गया है—

और अगर वह ५२३ पन्ने पर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि—

“The right of succession shall be governed not by personal law but by the provisions of the U.P. Tenancy Act to prevent fragmentation and subdivision of holdings”.

( जोतों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने से बचाने के लिये, उत्तराधिकार वैयक्तिक कानून के अनुसार नहीं बल्कि संयुक्त प्रान्तीय कानून कब्जा आराजी की धाराओं के अनुसार नियमित होगा। )

लिहाजा अगर उनको इससे शिकायत थी तो मैं समझता हूँ कि उनकी शिकायत अब इससे दूर हो जायगी क्योंकि यह नई बात नहीं है, पहले की है। अब जिस

[ माननीय प्रधान सचिव ]

पहलू से भी देखा जाय कोई बुनियाद नहीं रहती कम से कम उस संशोधन के लिये, न तो पैर ही खड़े रहने को रह गए, न आधी टाँग. न पूरी टाँग और कमर भी टूट गई बल्कि यों कहिए कि चारों खाने चित्त । मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा साहब अब इस संशोधन को छोड़ देंगे ।

अब सबसे पहले मैं हाउस को एक तरह से इस बात के लिए मुबारकवाद देता हूँ कि आम तौर से इस बिल को सब ने ही मंजूर किया है । राजाराम शास्त्री जी ने जिनके कि बोलने का एक खास तौर का लहजा है और उनको इस हाउस में लोग काफी गौर से सुनते हैं, उन्होंने अपने भाषण में कम से कम यह तो कबूल किया है कि वह इस बिल का स्वागत करते हैं बल्कि वह इससे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं लेकिन उनको डर यह है कि कहीं इसके हो जाने से झगड़े न हों लिहाजा बहसियत सोशलिस्ट के जो हमेशा वर्गवाद को चाहते हैं और संघर्ष को पसन्द करते हैं और इसीलिये वह उस संघर्ष को कायम रखने की कोशिश करते हैं । लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम यकीन करते हैं कि उनकी ऐसी नीयत न होगी । फिर भी उन्होंने जो कुछ भी कहा वह इतने ज्यादा जोशोखरोश से कहा कि उससे लोग यह समझते थे कि वह इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं । जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बिल का स्वागत करते हैं और वह एक अच्छी चीज है लेकिन उससे इतनी पूरी बेहतरी न होगी जितनी कि वह चाहते हैं ऐसा कहने में ज्यादा जोशोखरोश की जरूरत नहीं थी । फिर तो वह धीरे धीरे भी कहते कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो उनकी बात लोगों की समझ में आ सकती थी लेकिन इस कदर जोशोखरोश का नतीजा यह हुआ कि उनकी बात का तमाम वजन उनके जोश में गुम हो गया और दलीलके बजाय आवाज के जोर ने उसको दिमागों तक अच्छी तरह से न पहुँचने दिया । मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे दरखास्त करूँगा कि जो मसला उनके सामने है अगर उस पर वह अपने कलम-खैर कम रखें तो वह सब के लिए ज्यादा फायदेमन्द होगा । हमारी जनता पार्टी को भी किसानों की बड़ी फिक्र है । वह कब से पैदा हुई मालूम नहीं । लारी साहब, ऐजाज रसूल साहब, और शौकत अली साहब को लफ्जों में किसानों की बहुत फिक्र मालूम होती है लेकिन उनकी तजवीजात किसानों के खिलाफ ही होती हैं । मालूम नहीं कि उनका अब भी वही ख्याल है या नहीं और आज हम भले ही भूल जायें कि कुछ महीनों पहले वह मुस्लिम लीग में थे और इसको न सोचें लेकिन एक ही सौंस में दो बातें कहना कोई ज्यादा असर नहीं रखता । यहाँ एक दूसरे से इस्तेलाफ वाली बातें कहीं जायें तो इससे कोई फायदा नहीं पहुँचता । यह ठीक नहीं कि पहले जुमले में कुछ और दूसरे में कुछ और तीसरे में बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही जाय ।

लारी साहब एक तरफ जाते हैं, फखरुल इस्लाम साहब दूसरी तरफ, ऐजाज

रमूल मादव तमरी तमर और जौकन अली मादव चौथी तरफ। लिहाजा उसमें बहुत ज्यादा गुंजायश आदमी को मनाने की नहीं रहती कि यह चाहता क्या है। तमीजा यह निकलता है कि वह चाहता कुछ नहीं बिनाय इसके कि हम लोगों के विनाय कुछ कह कर कहकर पैदा कर दे। लिहाजा इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता किम तरीके पर जवाब दूँ। जोड़े भी दर्जीन उनकी नहीं हैं। मैं यह समझता हूँ कि जन्ता पार्टी वाले बहुत सभ्य आदमी हैं। मगर जब सन १९४५ में यह मसला यहाँ पैदा हुआ तब अमन में इनकी सुवार्तिफन की गयी। वे अवांतिशन के नानिक नहीं थे। उसी मुअफिकन में जिन वक्ता बोट देने का वक्त आया तो हाउस छोड़ कर चले गये। इस हद तक उनकी नाराजी थी कि बोट देना तो उनको नानुमकिन ही था, लेकिन उन्हें इतनी बुरी यह चीज मालूम हुई कि दूसरों का बोट देना भी नहीं देना सकने थे।

श्री ऐजाज रमूल— पोजीशन स्थिति) यह थी कि हम लोगों ने एक अमेन्डमेंट पेश किया था जिनको सरकार ने मंजूर नहीं किया था।

माननीय प्रधान सचिव— गवर्नमेंट आपके कई अमेन्डमेंट मंजूर नहीं करती तो क्या आप छोड़ कर चले जाते हैं? माकूल या नामाकूल जो कुछ भी आपने अमेन्डमेंट पेश किया, ताकि उसको वहाना बना सकें इस बात का कि इस रेजोल्यूशन की नाईद न करें और उसकी मुखालिफत करने की आपकी जुरत नहीं थी। साफ बातें जो हैं, कम से कम गुनाह करने के बाद जब काफी वक्त आदमी को तोबा करने का मिन जाए तब तो सही बात कह दी जाए। लिहाजा अब उसके लिए गलत बात कहने की कोई जरूरत नहीं रही।

अब यहाँ इस बिल के बारे में कुछ बातों पर उअ्र किये गये हैं। एक तो मुआविजे के बारे में दो उअ्र किए गये हैं। एक तो यह कि बहुत कम है, दूसरा यह कि बहुत ज्यादा है। जब इस तरह से दो आदमी लड़ें तो समझ लेना चाहिए कि जो जज है उसका काम बहुत आसान है और जो उसने किया वह सही है और जो लड़ रहे हैं वे एक दूसरे को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लिहाजा जब एक तरफ से कहा जाता है कि मुआविजा बहुत कम है और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मुआविजा ज्यादा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ गुंजायश समझने की रह जाती है और खास कर जब इस बात की याद रखें कि कम्पेनसेशन इस बिल में इक्विटेबिल होगा और इक्विटेबिल कम्पेनसेशन के लिए अगर एक पार्टी वाले लोग कहें कि बहुत ज्यादा है और दूसरी पार्टी वाले लोग कहें कि बहुत कम है तो समझ लेना चाहिये कि वह इक्विटेबिल और जस्ट (सही) है और इसके बारे में कोई दो रायें नहीं रहती। इसलिये वह मसला हल हो जाता है। मगर मैं इसके मुतालिक कुछ आगे बढ़ कर कुरेदना चाहता हूँ। क्या किसी फरीक को दरअसल



[ माननीय प्रधान सचिव ]

गुंजायश है कि उसको उन्न करना चाहिए ? जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें मुआविजा दिया गया है ८ गुने के हिसाब से, दूसरे रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट दी गयी है २० गुने से लेकर २ गुने तक । मैं दोनों को जोड़ कर आपके सामने आँकड़े पेश करता हूँ । वह मुआविजा इस तरीके पर गाजिबन १४० करोड़ के करीब होगा, यह तखमीना है । इसकी मालगुजारी ७ करोड़ से कम है । लिहाजा कुल मुआविजा जो जमींदारों को दिया जा रहा है उनकी सीर और खुदकाशत को छोड़ कर, वह २० गुनी मालगुजारी से कम नहीं बल्कि कुछ ज्यादा है । मैं पूछता हूँ कि क्या इसको कोई नाकाफी बतला सकता है ? क्या कुछ अर्से पहले तक २० गुनी मालगुजारी पर प्रापर्टीज ( जायदादें ) नहीं बिका करती थीं ? इसको नाकाफी कहना कतई गलत है ।

बावजूद इसके कि आज इसको हम पब्लिक परपज (सार्वजनिक प्रयोग) के लिये ले रहे हैं, बावजूद इसके कि जिन शोषितों ने जमींदारों को सैकड़ों वर्ष तक ऐशो-आराम करने का मौका दिया, उनको उनके कुदरती हक़ दिलाने के लिये ले रहे हैं तब भी हम उसका उतना मुआविजा दे रहे हैं जितनी कुछ दिन पहले आपकी जमीन की मिलिकयत समझी जाती थी, २० गुनी मालगुजारी से ज्यादा, फिर भला शिकायत, को कोई गुंजायश रहती है ? मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आवाज अब जमींदारों की तरफ से नहीं उठेगी । यह जरूर है कि सब जमींदारों को मुआविजा तो आठ गुना दिया गया, मगर रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट मुस्तलिफ दी गई । यह सही है । आपने बार बार कहा कि हम तो छोटे जमींदारों की हिफाजत करते हैं, हम आप तो अपनी कार्यवाही खुद कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी फिक्र न करे, हम चाहते हैं कि किसानों की किसी तरह से परेशानी दूर की जाय, हम चाहते हैं कि छोटों को किसी तरह की तकलीफ न पहुँचे । आप, जैसा कि बड़े को होना चाहिये, इस बात को चाहते रहे कि छोटों को नुकसान न पहुँचे और आपकी फैयाजी कायम रहे । आपकी इस हिदायत के मुताबिक हमने काम किया और बड़ों को कोई रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट नहीं दी, जिनकी शान उसको मंजूर ही नहीं कर सकती थी । उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्राण्ट के बोम्बे से अलग करके छोटों को यह ग्राण्ट दी ताकि आपकी शान कायम रहे । बड़ों की शान बड़ी होती है, छोटों की छोटी ही होती है, जिसको गौर करना है । इसलिये इस तरीके से दोनों बातें आपकी होती हैं, और मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई उन्न नहीं होना चाहिये ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कुछ सोसलिस्ट भाइयों की तरफ से कहा गया कि साहब यह तो बहुत ज्यादा रुपया दिया जा रहा है । मैं जानता नहीं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी की जो कई स्पीचें लिखी और जबानी, का हवाला दिया गया वह सही है या नहीं, मगर मैं उनसे कह सकता हूँ कि आचार्य जी ने अपने बयान में कहा है कि १० गुने से २० गुने तक मुआविजा दिया जाय और पाँच लाख से ज्यादा किसी को न

दिया जाये और जो नें इ देन्ट नैड हें, उसका भी इ करय एरड दिया जाय। उनका तन्मनन यह था कि इस तरह के कर करव १०० करोड़ रुपया मुआविजा होगा। मैंने देखा कि आचार्य जी क नखर्मने में और हमारे में कितना फर्क आता है। आचार्य जी ने सब के लिये, ऊपर वालों के लिये भी, दण्डगुना कहा, हमने इसमें बड़ों के लिये अण्डगुना ही किया है, लिहाज सौशलिस्टों को धक्का लगाने का मंता नहीं। दूसरे दान उन्होंने यह कही कि लोगों को पाँच लाख से ज्यादा न दिया जाय, मैंने देखा कि फर्क इतना आता है कि जितने को पाँच लाख से ज्यादा मुआविजा मिलेगा, उसकी कुल रकम करव तीन करोड़ के आती है और अगर उनका पाँच लाख में ही रक्खा जाय तो करीब दो करोड़ आता है, यानी फर्क आता है एक करोड़ या सवा करोड़ के। इतना ही फर्क जो आचार्य जी ने तरफ बणाई है उसमें आता है, और अगर उनके मुताबिक उन वेस्ट लैंड और दूसरे जमीन, जैसे बंजर बगैरा जो काम में नहीं आती, उनका दण्डगुना लगाया जाय तो एक करोड़ से बहुत ज्यादा हो जाय है। नतीजा यह है कि जितनी कुल मुआविजे की रकम आचार्य जी ने समझी थी, करीब करीब वही हमने रक्खा है। इसलिये सौशलिस्ट दोस्तों का इसके बारे में कोई खास दिक्कत होने का मौका नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद वे किसी देहंत में जाकर यह नहीं कहेंगे कि मुआविजा उससे ज्यादा दिया गया जितना कि उनके लीडर ने हमको हिदायत की थी, बल्कि यह कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, हालाँकि उसे छोड़कर वे चले गये हैं, उनकी हिदायतों के मुताबिक ही अमल किया है।

अब आप कहते हैं कि हमने अब राय बदल दी है। राय बदलने का अख्तियार तो आपको है ही और राय बदल कर जिस जगह पर आप हैं वहीं रहने का अख्तियार आपको है और फिर अब भी आप राय बदल सकते हैं और रोज ब रोज बदल सकते हैं लेकिन रोज ब रोज बदलनेवाली राय सही राय नहीं मान जाते हैं। वह राय क्यों बदली उसकी वजूहात नहीं बतलाई जाती है। जहाँ तक वे अगर यह कहते कि मुआविजा सन १९४६ में ११०, १०० या १२० करोड़ आता था और रुपये की कीमत गिर गई है, लिहाजा हमने राय बदल दी और उसको आज बढ़ा देना चाहिये, तो किसी हद तक ठीक हो भी सकता था। लेकिन इस कमी के लिये कौन सी बात हो गई यह मेरी संकुचित बुद्धि में तो आता नहीं है। फिर यह कहा गया कि उनको तो देना न था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह देखा कि नहीं कि ७० फीसदी मुआविजा २५० करोड़ और इससे कम मालगुजारी देनेवालों को मिल रहा है गो कि उनकी कुल मालगुजारी २८७ करोड़ रुपया थी। यदि उनको ७० फीसदी मुआविजा मिलता है और जो कि ५ हजार से ज्यादा मालगुजारी देते हैं चाहे ५ हजार दें या १० हजार दें या १० लाख दें, उनको कुल का करीब-करीब ६ फीसदी मिल रहा है।

[ माननीय प्रधान सचिव ]

पर अब उनका कुल भालगुजारी और कुल जागजी पर २५० रु० भालगुजारी देनेवाले के मुकदिले में ३ से ज्यादा यानी ७० फीसदी हो जाता है, मगर उनको फिर्त नवाँ हिस्सा मिल रहा है, अगर उनकी भी हम शरह से मिलता तो बहुत ज्यादा मिलता। नई कीमतों के मुकदिले में ११वाँ हिस्सा मिल रहा है यानी ६ फीसदी मिल रहा है। जहाँ तक उसूल की बात है आप लोगों को उसकी खबर भी नहीं है। इनमें भी कुछ किया गया है, वह सब इन्नाफ के मातहत किया गया है। हर एक की हलत को देख कर काम किया गया है। इसलिये जिस तरीके से इस मुआविजे पर अमल किया गया है, इसके लिये किसी को भी किसी शिकायत की गुंजायश नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा सोशलिस्ट्स को तो सबसे कम शिकायत होनी चाहिये।

दूसरी बात यह कही गई है कि इसमें लेबरर्स (मजदूरों) के लिये कुछ भी नहीं किया गया। इसमें जमीन का तकसीम नहीं किया गया है, जमीन नहीं दी गई है। किन्तु यहाँ पर और इस भवन के बाहर सोशलिस्टों की तरफ से जो स्पीचें हुई हैं उनमें वे कहते हैं कि ५० एकड़ तक तो छोड़ दी जाय और जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा है उनसे ले लो जाय। मैंने देखा और आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यदि उनके मुआविके कार्यवाही की जाय तो जो हिन्दसे इसके बारे में मैंने जमा किये हैं उनसे यह लगता है कि ५० एकड़ से ज्यादा जमीन जिनके पास है, चाहे वे जमींदार हों या काश्तकार उनकी तादाद १,१४,६५५ है।

उनके पास कुल जमीन ५३,१०,५७२ एकड़ है। गगन यह कि अगर इन १,१४,००० को औसतन आप ५० एकड़ हर एक को दें तो जितनी जमीन है उससे ५० हजार एकड़ और चाहिए, यानी इसके लिये करीब-करीब ५७ लाख और कुछ एकड़ चाहिये। इसलिये इसमें कोई ४ लाख एकड़ की कमी रह जाती है। तो अगर आपके ही हिसाब को हम मान लें तो किसी दूसरे के लिये कुछ नहीं बचती और इन्हीं में सब रुत्म हो जाती है। फिर शिकायत किस बात का। फिर इतनी बड़ी लम्बी २ बहसों और मजदूरों के किस्मे और जोशखराश जिनको कि अगर बेचरे मजदूर देखते तो समझते कि अगर एक दिन की गोटी मिल जाती तो बेहतर था, बमुक़ाबले इसके कि इतना जोश राजाराम जी दिखाते उसकी क्या बुनियाद रह जाती है। क्योंकि ५० एकड़ हर एक को देने के बाद तो एक हब्बा नहीं रहता, जो बाँटा जा सके तो फिर बाँटा क्या और कहाँ से जाय ?

अब दूसरी बात कही गई कि साहब ३ एकड़वालों से कुछ न लो और औसत भी काश्तदार कुल ३ ही एकड़ पढ़ता है। तो लो किससे ? वहाँ से लो ? मजदूरों से लो ? लेकिन मैं समझता हूँ कि राजाराम जी को यह हरगिज मंजूर न होगा तो

मन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रांतीय उर्मिदारी-विनश और भूमि-अवस्था विन ४६५

ले कहीं से। इन बातों का स्पष्ट कर देने का जरूरत होती है। इस बारे में आचार्य तरेन्द्रदेव जी ने अपनी राय दी और कहा कि जयपुर में जो लगान काया है उसमें जो कुछ सुम-विज्ञे का रुपया निकलना चाहिए। उन्होंने यह राय दी कि २० करोड़ रुपया सालाना लगान रहना चाहिए। उन्होंने अपने प्रयास में २४ करोड़ में से ४ करोड़ छोड़ दिया, २० छोड़ रखे। २० करोड़ में से ८ करोड़ तो सुम-विज्ञे देन में काम में लाए, ४ करोड़ खेतों सुधारने के काम में लाए और ८ करोड़ अपनी लागत-खर्चा में ला। परन्तु यह कि दावाने कबूल हुई। अब तो २० करोड़ रुपया सालाना लगान रहना चाहिये, दूसरी तरफ सुम-विज्ञे का कुछ राधा करनकर से बनूल दिया जाय और तीसरी यह कि इन ट्र-ऑक्शन से सरकार का व २ नम से कम ४ करोड़ रुपया सालाना का तो मुनाफा करे ही और जब सुम-विज्ञे बढ़ा दी जाय तो ८ करोड़ रुपया सालाना का मुनाफा करे। यह तजवीज आचार्य तरेन्द्रदेव जी के हुई, तो इसमें एक यह बात तो तय हो गई कि किसानों को ही यह सुम-विज्ञे देना है और उनके अलावा किसी दूसरे को इसे नहीं देना है। अगर इन बातों को मान लिया जाय तो सोचने की बात यह हो जाती है कि आया यह तजवीज किसानों के लिये फायदेमन्द है या जो तजवीज हमने की वह फायदेमन्द है। हमारी तजवीज के बाद किसान को निर्दिष्ट जगह से जगह ८ करोड़ रुपया सालाना गवर्नमेंट को देना होगा २० करोड़ के बदल में, यानी १२ करोड़ का छुटकारा किसान का इससे होता है और यह छुटकारा किसान को कोई दो या चार दिन के लिये नहीं होता, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिये होता है। ऐसी हालत में फिर उसका २० करोड़ देना बेहतर है या ८ करोड़ बेहतर है। मैं समझता हूँ कि जो तराका किसान के लिये हमने रक्खा है उसके अलावा अगर उससे १२ करोड़ रुपया सालाना लें तो उनके साथ बहुत ज्यादा जगहदारी की बात होगी। १२ करोड़ रुपया सालाना हम किसान से लें तो हमका करोड़-करीब ६ करोड़ रुपया सालाना की बचत होगी। लेकिन जो तराका किसान से इस गुना लगान लेकर उसके लगान को आधा करने का हमने रक्खा है उससे हमका बहुत नफा नहीं होता और सरा मुनाफा १२ करोड़ रुपया सालाना का जो तरेन्द्रदेव जी के उस हिम-व में था वह किसान को ही मिलता है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि कि सांशिलस्ट भाई हमारी इस तजवीज को देशत में फैलायेंगे और किसानों से कहेंगे कि यह बहुत मुकद्द तजवीज है, इससे तुम्हारा बड़ा फायदा होगा और जल्द से जल्द इस बात की कोशिश करें जिससे यह रुपया जमा हो जाय।

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाबू वक्त्र यह कश जाता है कि लगान कम करना चाहिये। अब सबान यह अता है कि लगान कम करना चाहिए या नहीं। यह तो एक ऐसी बात है, जिसके बारे में अगर कोई भी किसान के सामने जाय तो यह कहने की जुर्रत नहीं कर सकता है कि तुम्हारा लगान बढ़ना चाहिये

[ माननीय प्रधान सचिव ]

और हमने लगान बढ़ाया भी नहीं है। जब से हमने गवर्नमेंट सँभाला, लगान बढ़ता ही आ रहा है। आपको मैं बतलाऊँ कि सन् १९३६-३७ से पहले कुल लगान जो इस सूचे में वसूल होता था, वह आज से ज्यादा था।

सन् १९१८, १९ में १७ करोड़ ८४ लाख।

सन् १९१९, २० में १७ करोड़ ६४ लाख।

सन् १९२५, २६ में १६ करोड़ १ लाख।

सन् १९२६, २७ में १६ करोड़ २४ लाख।

सन् १९२७, २८ में १६ करोड़ ३३ लाख।

१९२८, २९ में १६ करोड़ ४० लाख।

और सन् १९४५, ४६ में १७ करोड़ ५४ लाख।

गरज यह है कि अब गोकि काश्त की ज़मीनें बढ़ गई हैं, मगर कुल लगान जो आज वसूल होता है, पहले से कम है। लिहाज़ा काश्तकारों के लगान का बोझ आज पहले से कम हो गया है।

बाज़ लोग कहते हैं कि काश्तकार से जो यह १० गुना लिया जायेगा, वह कैसे लिया जायेगा? मैं आपसे कहता हूँ कि काश्तकार खुश खुशी देगा। उसक लिए इससे बेहतर और कोई मौक़ा नहीं हो सकता है। आप एक काश्तकार को लीजिये जा मसलन एक रुपया लगान देता है, एक रुपया लगान देनेवाले काश्तकार को आज अपने भूसे से उतनी आमदनी होती है, जितनी कि गेहूँ से पहले होती थी। इस तरह वह आसानी से १० रुपया दे सकता है, अपना ज़मीन के लिए, अपने लिए, अपने लड़कों के लिये और अपने लड़कों के लड़कों के लिए और इस तरह वह एक मौरूसी जायदाद छोड़ कर मरेगा। आज उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज वह लगान में एक रुपया देता है, जबकि एक मन गेहूँ की क़ामत उसको २२ रुपया और २० रुपया मिलती है, जिसकी क़ामत उसको पहले ३ रुपया मिलती थी। अगर वह एक मन गेहूँ भी पैदा करता है और उसकी आधी क़ामत दे देता है तो वह हमेशा के लिए अपने लगान को आधा कर लेता है और हमेशा के लिए अपनी ओलाद के लिए बोझ हल्का करके मरने की उम्मीद करता है। आज आप देखिए, किसान पैसे का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह नोटों को छप्पर के नीचे रखता है जिससे होता यह है कि या तो चूहे उन नोटों को खा जाते हैं या वह पानी में भीग कर खत्म हो जाते हैं। बाज़ बक्क चोर-डाकू भी ले जाते हैं। काश्तकारों के पास पैसे ज्यादा हो गये हैं, इससे भले आदमी भी डाकू बन गये हैं। इस तरह इन चीज़ों से भी उसका पैसा बच जाता है और उसको पैसे के अच्छे इस्तेमाल का भी मौक़ा मिलता है। जो लोग उसके पास पैसा देखकर उसको मुयास्ते में डालते हैं और उसको बुरी आदत सिखलाने की

मन १९४६ ई० का संयुक्त पन्नाय जर्मन-री-बनाया और भूमि-सम्बन्ध विन ४६७

कोशिश करने हैं, उनको भी उनके पास जाने में सुनाना नहीं रहेगी अगर कोई यह कहता कि कारशकार जर्मन जर्मन को दे दे तब तो यह बात ही जा सकती थी कि जब कारशकार जर्मन दे देगा तो फिर वह क्या रहेगा ? लेकिन अगर वह पैसा दे देगा और जर्मन उनकी हमेशा के लिए हो जायेगा तो उस पैसे का और अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और उस पैसे का और उपयोग करना जर्मनी और जर्मन के लिए और क्या कर सकता है।

इसलिये मैं आप से कहता हूँ कि उन वस्तु जर्मन पैसा में जर्मन इन्क है जबकि जो चीज एक रुपया की मिलती थी अब ६ रुपये की मिलती है। उन वस्तु पर कारशकार की तरफ नहीं हो सकता जिन में उनके लगान का शरद हमेशा के लिए कम हो जाय। अगर हमेशा के लिये वह मालिक हो जाय, जर्मन का तो इसमें कोई फायदे हैं। मालिक हो जाता है तो उसकी आत्म का सनाय होता है। इनका आप जानते हैं कि क्या लैंडलेस प्रापर्टी ( भूमि-सम्बन्ध सम्पत्ति ) की हगर ( भूय ) है।

मैं आप से कहता हूँ कि यह ठीक है जिनसे हम कारशकारों के बेहतर कर सकते हैं। फिर लोग यहाँ लैंडलेस लेबरर की बात कहते हैं। मैं आप से कहता हूँ कि किसी ने इस बिजु को गौर से देखा है, किसी ने समझा है ? मैं अजब गत हूँ कि लैंडलेस लेबरर के लिये जो इन बिल में किया गया है वह मुश्किल से कोई कर सकता है। लैंडलेस लेबरर अपने गाँव की कुल जमीनों का सिवाय उन जमीनों के जिन में कारश होती है, हिस्सेदार है, औरों के साथ मिलकर रखने वाला है, इन जान करने वाला है, जितनी वेस्ट लेड है उसकी तनाम कार्यवाही और इन जमान का उनका भी यह हक हासिल है। लैंडलेस लेबरर को उठाने वाला कोई और बात हो सकती है आप उसको देखें, आप के खयाल में यह चीज नहीं हो सकती। इनके अलावा कुछ, तालाब वगैरा जो हैं उसका इंतजाम भी वह कर सकता है, वह गाँव का मालिक और लोगों के साथ रहेगा। यह कहना कि लैंडलेस लेबरर के लिये इस में कुछ नहीं है, यह बिजुकुल राजत है। इसमें यह कहा गया है कि सबलोट नहीं कर सकता। सबलोट करने के क्या माने हैं। जितना आदमी असल में करत कर सकता है, जा नहीं कर सकता वह लैंडलेस लेबरर को और जिसका ह लैंडिंग अनइकनामिक है, कुदरती तरीका पर वगैर जत्र के खुशी से करना चाहता है, जत्र से उसका जान नहीं लगता। फिर जो समझदार हैं, उनसे पूछता हूँ अगर वह कोई और तराका कहें कि जर्मन को सब में बराबर तकमीम कर दिया जाय जिससे सबो तीन एकड़ से ज्यादा पहुँचे, अनइकनामिक हो लैंडिंग आधी रहेगी। वह जिन मादवान को मजूर है वह उनको मिलेगा। हम उनके लिये रास्ता बन्द नहीं कर रहे हैं। यह तो कोई अक्लमन्दी नहीं है और न कभी हो सकती है। दूसरी बात हमने है कि हम जर्मन को कारश करने के लिये सबलोट नहीं कर सकता। कोई पारिशान नहीं हो सकता। राजाराम जी को हमारी नेकनीयती पर भरोसा नहीं है। यह ठीक है

[ माननीय प्रधान सचिव ]

हमारी ईमानदारी के प्रति उनको ऐसा समझाने का पूरा हक है। उनको हमें सप्रभावा चाहिए कि हम लोग ईमानदारी पर अमल नहीं कर रहे हैं। अपनी स्पीच में कई दफा उन्होंने ईमानदारी लफज का इस्तेमाल किया। यह उनको हक है। मगर मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या वह समझते हैं कि अगर इस बिल को हम जल्दी अमल में लाना चाहें तो जा तरीका वह चाहते हैं उसका क्या असर होगा ? इनका माने यह है कि सारे सूबे का सेटलमेंट आपरेशंस किया जाय। एक जिले का सेटलमेंट आपरेशन कराने में तमाम आकिसर्स को लगाने पर कम से कम ५ साल लगते हैं। एक वक्ता मैं गवर्नमेंट कभी भी ४-५ जिले से ज्यादा सेटलमेंट आपरेशंस के लिये नहीं ले सकती। जिहाजा अगर उनके तरीके को बरतता कम से कम ५० साल लग जायगा, जिस जमीन्दारी को हम एक साल के भीतर एवालिशन करना चाहते हैं। इसलिये उन हो सोच-समझ कर हम बात पर गौर करना चाहिये कि सेटलमेंट आपरेशंस के बमुआबिले तमाम किसानों में हम तरीके पर जमीन का बटवारा करें तो यह बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। लैब्लेस लेबरर की हमारे मुल्क में बहवूरी कैसे होगा, देहातों की हालत कैसे सुधरेगी, इसके ऊपर भी हमें गौर करना है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में खेती करनेवालों की तादाद क्या है ? जब कि पश्चिमी मुल्कों में बहुत मुद्त सं खेती करनेवालों की तादाद साल ब साल कम होती आयी, हमारे यहाँ खेती करनेवालों की तादाद बराबर बढ़ती ही गयी और जमीन पर पहले के मुक़ाबिले में बहुत ज्यादा बोझ हो गया। हमारे यहाँ सब से बड़ी मुश्किलत अनवैलेंसड इकनामी (असमान आर्थिक स्थिति) की है। जरूरत है कि नेचरल तरीके पर रूरल एरिया को इंडस्ट्रीअलाइज (औद्योगिकरण) करें और हम यह चाहते हैं कि अगर हमें रकम मिले और इससे रकम बचा सकें तो हम रूरल एरिया में बिजली की रोशनी सब के लिये पैदा करें। हम मुल्क के किमानों के अंदर एक नई बिजली पैदा करें जिससे उनका होसना ऊँचा हो और सूबे के अन्दर एक नयी दुनियाँ कायम कर डालें और उनके लिये हमें रूरल इकनामी की जरूरत है। आप जानते हैं एक जमानदारी एवालिशन फंड बनाया गया है। एक-एक पैसा जो काश्तकारों का हमें जमा हागा वह सिर्फ काश्तकारों की भलाई के काम में लाया जायगा और किली काम में नहीं लाया जायगा। और हम चाहते हैं कि इस रुपये के जरिये से काश्तकारों के लिये देहातों में नयी इंडस्ट्रीज पैदा करें। हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनको रखें, ताकि जिस मोटर में वे चले तो कह सकें कि यह मेरी माटर है जो यहाँ चल रही है। जिस मोटर में हम बैठे हुये हैं वह हमारी गवर्नमेंट की है, जिसमें हमारा भी पैसा लगा हुआ है। यह हमारा इरादा है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि देहातों में नये-नये कारखाने बन और नयी-नयी आबपाशी हो जिसमें रुपया लगे और अगर कहीं जरूरत हो और हम ज्यादा पैसा बचा सकें तो आबपाशी देने की जरूरत ही न हो ताकि काश्तकार भी समझे कि हमारे लिये नया दिन आया है। और इसलिये यही तरीका है जिससे

वहाँ जो अनबले-ह इन्तज है वो प्रेडेन (वन) है व दूर हो जाय और देशत फनें कने और जहर वाले को वा-नो सुधरे इसन्दि में उन्म-द करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्द नरे का भाउड (देाने) में कोई इंडस्ट्रीयन मने कि- ज दगा त कि दम डव कि उर्मन्गरी के जलन होने पर क्या करा मीजु इंडस्ट्री कदा पर जान हो न-ने " और उनो काम करने के लिये कोशिश करें, जियने जो नो-ि लैड-न लंघर को दहई देने है. उनके भा देखने का मौक मिले नि वल्लव मे अन-ा त के से उनने क्या कायड-हात है ? यहाँ कुछ यम भ जिक क्रिय-नय डि उम न्गरी एकात्रित की बन त-हानी है लेकिन नेशनलाइजेशन (राष्ट्रियकरण) की ब-वन में कुछ नो कदा। मैं नही जानता कि नेशनलाइजेशन का म ने लाग पूरा तरह से समझते भी हैं या नहीं, क्यों कि नेशनलाइजेशन किस ढग से हा लोगों को कहने क पड़ते यह समझ लेना चाहिये।

मान लीजिये कि कल को हम सब कल नगरवाने ले लें, और स्वर्गीद जे औरमान लीजिये कि हमारे पास हाशियार राइमी हैं और ईमानदार आदमी हैं, नबकुत्र हम कर स ते हैं तब भी उनके लिये कय-ई से आवे ? आज यह भी कहा जाता है कि करपशन है, नेपोटिज्म है ब्राड्बरी (भूमस्वरी) है और हमारे भाई भी उन आवाजों में अपनी आवाज मिताने हैं तो फिर अगर इन सरो इंडस्ट्रीज का नेशनलाइज कर दें तो आखिर किस दुनिया से आदमी काम करने के लिये आयंगे ? जब तक लोगों का मारल नही बनता और लोग सारे गवर्नमेंट के कामो को सारे मुल्क के कामों को अपना काम समझ कर नहीं करते. तब तक नेशनलाइजेशन सिफ लफ्जों के आडम्बर से नहीं होता। आज कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये कहा जाता है लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अगर हम सब इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में ले ले, तो कैपिटल हम कहीं से जावे। हम नेशनलाइजेशन काने का कैपिटलिज्म (रूजीवाद) का खत्म करन का तरका भी शायद थमल में लाना पमन्द करें, लेकिन किस तराके पर, कम से कम मैं उनमें से नही हूँ जो कैपिटलिज्म के नाम से घबड़ाते हैं। मैं (प्रोडक्शन) पैदावार को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क क हर आदमी का स्टेटस और स्टैण्डड अर स्तर को ऊँचा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खुशहाल हा। लकूजों से मुके चबराहत नही होनी, मैं कैपिटलिज्म से घबड़ाता नही हूँ, न सोशलिज्म से और न कम्यूनिज्म से डरता हूँ बल्कि मैं तो मुहब्बत करता हूँ गांधीज्म से, मगर डरता किमा से नही हूँ, न कम्युनिस्ट आइडियलोज. से ही डरता हूँ। चाहे कम्युनिस्टों की हरकतों की वजह से सख्त से सख्त कायवाही करमी पड़ती है लेकिन मैं उनकी आइडियोजर्जाज से डरता नही घबड़ाता नही हूँ। अगर वे लोग कैपिटलिज्म का बरवाद करने की बात कहते हैं तो उनको सोचना चाहिये कि कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिये भी कैपिटल चाहिये। तो कैपिटल आये कहाँ से ? आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी



[ माननीय प्रधान सचिव ]

दिक्र त यह है कि नये काम हम करना चाहते हैं, लेकिन कैपिटल नहीं है। जो काम चल रहे हैं, उन्हीं के लिये वर्किंग कैपिटल नहीं है और कोई चीजें आगे बढ़ती नहीं हैं, तो उस कैपिटल को जमा करने का और काम में लाने का जरिया यह जमींदारी अवालिशन फण्ड है, जिस से हम उस रकम को पावेंगे जिससे हम कैपिटलिज्म को खत्म करें। इसलिये जब आप लोग कहते हैं कि कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहिये तो उसी गहरी बुनियाद में जाना चाहिये और देखना चाहिये कि कैपिटल कहाँ से आये, जिससे कैपिटलिज्म खत्म हो सके।

श्री मुहम्मद शौकत अली खाँ—मैं तरीक़ा बता दूँ ?

माननीय प्रधान सचिव—आपको उसका मौक़ा मिलेगा। जब आपका मौक़ा आयेगा आप उसे करके दिखला दीजियेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि आज कल बड़ी दिक्कतें हैं, आज कल बड़े बड़े इकनामिक (आर्थिक) सवाल उलझे हुये हैं और बहुत बार तो ऐसा मालूम होता है कि उनको सुलझाना मुश्किल है लेकिन अब मैं इकनामिक्स के प्रोफेसर्स से कह दूँगा कि शौकत अली साहब के पास चले जावें और जो कोई उनको दिक्कत हो उनके सामने पेश करें तो वह हल बतला देंगे। लिहाजा एक ही सवाल के लिये नहीं, जितने भी सवाल पैदा होंगे वह उनके पास रख दिये जायेंगे। अगर इस वक़्त एक बात वह बतला भी देंगे तो आइन्दा बहुत सी संभंटे आयेंगी। उस के ऊपर उनसे बराबर गुफ्तगू जारी रखना शायद उनके लिये फायदेमन्द न हो लेकिन मैं तो कुछ न कुछ सीखूँगा ही। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह भी एक तरीका है जिससे अगर यह बात हो सकती है तो हमें यह देखना है कि आज मुल्क की हालत क्यों दिक्कत तलब है, क्यों लोग इतना परेशान हैं, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है पर प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। अगर आप एक छोटी सी फैक्टरी कायम करें तो उसके लिये भी कैपिटल चाहिये, उसके लिये आपको अमेरिका से प्लांट मँगाना पड़ेगा, यूरोप से या और कहीं से तो उसके लिये भी कैपिटल चाहिये, मगर पैसा मिलता नहीं है। पैसा जिनके पास है वह देते नहीं हैं। जो गरीब हैं उनसे थोड़ा-थोड़ा करके लें तो उससे काम चलता नहीं है। इसलिये जो यह एक तरीका जमींदारी अवालिशन फण्ड का है यह ऐसा है जिससे यह सब बातें हल हो सकती हैं। और आइन्दा के लिये हम एक ऐसी बात करते हैं जिससे आइन्दा हमारे काम बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं इस बिल के बारे में और आपका बहुत वक़्त लेना नहीं चाहता। यह सेलेक्ट कमेटी में जायेगा, मैंने सिर्फ कुछ बुनियादी सवालों के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कहने की कोशिश की है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने अर्ज किया है उससे आप चाहे इत्फ़ाक न करें मगर इसकी मंजूर फरमायें कि जो कुछ हमने किया वह समझ बूझ कर किया है, बिना गौर के

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रस्ताव जर्मन-बर्लिन और भूमि-व्यवस्था बिल ५०६

नहीं किया है, बिना वाजिब खयाल के नहीं किया है और ऊँचे होमने को मानने रखने हुए ठोस जमीन पर खड़े होकर किया है। यहाँ पर कुछ यह भी जिक्र किया गया कि कई जगहों पर हमने 'डिज मैजैस्ट' का नाम दिया है। 'डिज मैजैस्ट' का नाम जर्मन में यद्वे भी कह चुका है कि जो जानून अर्थात् एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जैसे कि गवर्नर के नाम पर हमारे यहाँ में मारे आर्डर जार होने हैं उसी तरह से इसका नाम रहना है। जर्मन जो हम होमिनियन में हैं भी, तो उस ऐक्ट के मुताबिक यह रखा गया है। जर्मन मैंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि यह बिल जब सेलेक्ट कमेटी में वापस जाएगा और इस हाउस में पास हो जाएगा। हमका एक होगा कि इस बिल में डिज मैजैस्ट की 'मैजैस्ट इंडियन इंडियन रिपब्लिक' लिखा होगा और इसके लिये यह बिल बहुत नई चीज होगी।

यहाँ कुछ ऐजाज रमून माहव ने जिक्र किया मुवाअजे का। ऐजाज रमून साइब को बड़ी फिक्र थी कि माहव जमीन तो जमींदारों से ले ली जायगी मगर मुआविजा कर्मा मिलेगा नहीं। उनको शायद उन लोगों की आदत का खयाल रहा जो चीज ले लेते थे मगर उसका कर्मन मुहल तक देते नहीं थे। वह किम सबके के हाते थे इसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर इस बिल में यह प्राविजन है कि ऐडजस्ट करने के ६ महीने के अन्दर बहुत हद तक देना पड़े। गवर्नमेंट ने खुद अपने ऊपर यह शर्त कायम की है, शायद दफा ७५ में इसका जिक्र है। मैं ठीक तो बतला नहीं सकता मगर हमने खुद यह खयाल रखा है कि ऐडजस्ट होने के बाद ही मुआविजा मिलने में देरी न हो। इस लिये हमने अपने ऊपर यह रोक रखी है ताकि ६ महीने के अन्दर जैसे कोई बच्चे पैदा होता है उसी तरह से ६ महीने के अन्दर यह कीमत मिल जाय। लिहाजा इसके बारे में जमींदारों को कोई पशोपेश की जरूरत नहीं है। जो कीमत उनकी हो उससे उनको खुश होना चाहिये जैसे की एक अच्छे बच्चे के पैदा होने में होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जमींदारी अवालिशन होने के बाद जो नई नस्ल इस मुल्क में पैदा होगी, उनके दिल में वही जगह होगी जो कि अपने बच्चे के लिये एक आदर्श को हुआ करती है। यह जमींदारी अवालिशन कोई एक निगेटिव तरीके पर नहीं किया जा रहा है। यह एक नई दुनिया में नया युग कायम करने के लिये किया जा रहा है। इसलिये मैंने इसको बच्चे की मिसाल इरादतन दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नये जमाने में हिन्दुस्तान में जो कि दो साल के करीब हुए आजाद हुआ है, यह एक नई नस्ल का पैदा करेगा। इस बिल के जरिये एक नया सोशल, स्प्रिचुअल और इकानामिक आर्डर हमारे मुल्क में कायम होगा और हमारे यहाँ के कामन मैन को ऊँचे से ऊँचे उठ कर गान्धी जी का नाम सुबह और शाम लेने का मौका मिलेगा।

**डिप्टी स्पीकर**—सवाल यह है कि सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी ( अबालिशन ) 'विनाश' और भूमि व्यवस्था बिल को ३१ दिसम्बर सन् १९४६ ई० के पूर्व सम्मति प्राप्त करने के हेतु प्रकाशित किया जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**डिप्टी स्पीकर**—अब मैं मूल प्रस्ताव के ऊपर राय लेता हूँ । सवाल यह है कि सन् १९४६ ई० का प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल एक संयुक्त विशिष्ट समिति के अधीन किया जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**माननीय प्रधान सचिव**—मैं आपकी इजाजत से यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि व रजामन्दी अपर हाउस के इसकी ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी ३१ मेम्बरों की बनायी जाय, जिनमें से २० मेम्बर इस हाउस के और १० अपर हाउस के और मिनिस्टर इन चार्ज, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू हों । जो आवाजें चारों तरफ से आती हैं कि ज्यादा तादाद मेम्बरों की हो, अपर हाउस के और यहाँ के लोग भी चाहते हैं तो अगर मुनासिब समझा जाय तो इस तजवीज को मंजूर किया जाय ।

**श्री जगन्नाथ बरूश सिंह**—माननीय डिप्टी स्पीकर, मैं माननीय प्रधान मंत्री के इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता कि रजामन्दी के साथ दोनो हाउसेज की ज्वायंट सेलेक्ट कमेटी कायम की जाय । मैं इस पर कोई तकरीर भी नहीं करना चाहता, मगर मैं यह निवेदन जरूर गवर्नमेंट से और माननीय प्रधान मंत्री से करूँगा कि रजामन्दी के मानी यह हैं कि हम लोगों को मालूम हो कि कौन से मेम्बर जायँ ।

**माननीय प्रधान सचिव**—जो मेम्बर कि यहाँ से २० होंगे तो उसके लिये तो हाउस के सामने तजवीज आयेगी कि ये २० मेम्बर इस हाउस से रखे जायँ और उनके नाम इस हाउस से मंजूर हों, कोई दूसरा तरीका उनको चुनने का नहीं है ।

**श्री जगन्नाथ बरूश सिंह**—मैं इसमें इतनी दिक्कत देखता हूँ, कि इसमें अगर २० मेम्बरों की मंजूरी दे दें और किसी ग्रुप या पार्टी की हकतलफी हो तो वह इसके सिलसिले में कोई मेम्बर तजवीज नहीं कर सकती ।

**डिप्टी स्पीकर**—आप गालिबन किसी गलतफहमी में हैं । इस वज्रत जो आपने अपने नियमों का संशोधन किया है, उसके मुताबिक संयुक्त विशिष्ट समिति के २४ सदस्य होने चाहिये. १६ इस भवन के और ८ कौंसिल के माननीय सचिव के अलावा । लेकिन इस बिल के सम्बन्ध में माननीय प्रधान सचिव यह प्रस्ताव करते

सन १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ५०३

हैं कि इस बिल की विशिष्ट समिति के, वजाय २४ के ३० सदस्य हों, २० इस भवन से और १० कौंसिल से और माननीय माल सचिव भी उनके मेम्बर हों। तो इस तरह से वजाय २५ के ३१ सदस्यों की तजवीज है। तो अगर यह तजवीज यहाँ मंजूर होनी है, तब कौंसिल की रजामन्दी के लिये वहाँ पेश होगी और वहाँ से पास होने के बाद यह भवन २० सदस्य चुनेगा। अभी उनके नाम नहीं पेश हुए हैं। जब नाम पेश होंगे तो आनका आधिकार होगा कि जो गवर्नमेंट नाम पेश करनी है उसके मुकाबिले में आप और पेश करें और इस सम्बन्ध में भवन का जो तरीका है उस पर अमल किया जायगा। सवाल यह है कि २० हों या १६ हों। इस भवन से १६ के वजाय २० लिये जायँ और कौंसिल से ८ के वजाय १० लिये जायँ, यह प्रस्ताव का मतलब है।

**श्री जगन्नाथ बरूवा सिंह**—मैं सिर्फ इस बात को साफ कर लेना चाहता हूँ कि २० आदमियों के नाम पेश किये गये और उसके अज्ञात भी २१ वीं नाम पेश कर दिया जाय तो एलेक्शन हो जाय। तो मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि २० नामों के अनिरिक्त नाम आने पर हम एलेक्शन कर सकेंगे ?

**डिप्टी स्पीकर**—चुनाव तो जरूर होगा, अगर २० नामों से ज्यादा नाम आयेंगे। सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल की संयुक्त विशिष्ट समिति में वजाय २५ के ३१ सदस्य हों, यानी माननीय सचिव के अलावा ३० सदस्य हों।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

( इस के बाद भवन ५ बजकर ८ मिनट पर बृहस्पतिवार, १४ जुलाई, १९४६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया । )

लखनऊ  
बुधवार, १३ जुलाई,  
१९४६

कैलासचन्द्र भटनागर,  
मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली,  
संयुक्त प्रान्त ।



1991

400 700 800 900 1000

*[The page contains faint musical notation consisting of staves with notes and rests.]*

## अस्पताल—

प्र० वि०—बलरामपुर —, लखनऊ के कर्मचारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २८९, २९०।

प्र० वि०—रानीखेत की छावनी का—। खं० ५९, पृ० ३२।

प्र० वि०—रानीखेत तहसील के हेड-क्वार्टर में—का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।

## अस्पतालों—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में नये—का खोला जाना। खं० ५९, पृ० २६।

प्र० वि०—प्रान्तों के विभिन्न जिला बोर्डों के—का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० ३०—३१।

## अस्वस्थता—

प्र० वि०—मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की—के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

## आ

## आन्दोलन—

प्र० वि०—सन् १९४२ ई० के—में पहाड़ियां तथा खमा ग्रामों की क्षतिपूर्ति। खं० ५९, पृ० १११।

## आर्डिनेंस—

सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज इवेंकुई प्रापर्टी—की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

## इ

## इनाम—

प्र० वि०—पुलिस अधिकारियों को सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिए तरक्की और—। खं० ५९, पृ० ११३।

## इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४४६—४५१।

## इलाज—

प्र० वि०—आगरे के थामसन अस्पताल में दांतों के—का प्रबंध। खं० ५९, १११।

## इलेक्ट्रिक इनर्जी—

प्र० वि०—कस्बा डिबाई, जिला बुलन्द-शहर में जन-कार्यों के लिए—(विद्युत् शक्ति)। खं० ५९, पृ० ११०।

## उ

## 'उजाला'—

प्र० वि०—दैनिक पत्र—के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २४—२५।

## उत्पत्ति—

प्र० वि०—प्रान्त में गेहूं, चना, मक्का इत्यादि की—तथा बाहर से आये हुए अनाज की मात्रा। खं० ५९, पृ० ५—७।

## ए

## एजेण्टों—

प्र० वि०—बाराबंकी के सीमेंट के—द्वारा दूसरे जिलों को सीमेंट की सप्लाई। खं० ५९, पृ० १०२।

## ऐ

## ऐजाज रसूल, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५०, ४८३—४८६।

## क

## कमिशनर—

प्र० वि०—लखनऊ स्थित—के आफिस को फेजाबाद ले जाने के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २३।

## कमेडियों—

प्र० वि०—मैनपुरी जिला बोर्ड की—की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३, २९४।

## ५५

प्र० वि०--प्रान्त में—और बहरों की  
शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ०  
७-८।

देखिए “प्रश्नोत्तर” ।



गोविन्द सहाय, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४६७—४७५।

गोशाला—

प्र० वि०—के सुप्रबंध के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति। खं० ५९, पृ० २८२, २८३।

ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों—

प्र० वि०—जिला अल्मोड़ा में—की दुबारा नियुक्ति का आधार। खं० ५९, पृ० ३२—३३।

घ

घोषणा—

सन् १९४८ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज स्टोरेज रिक्वीजिशन (कंटेन्युएंस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रुई ओटने के और गांठे बनाने के कारखानों के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय स्पुनिसिपैलिटीज (अमेडमेंट) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की—। खं० ५९, पृ० २००।

च

चक्कियों—

प्र० वि०—टांडा जिला फैजाबाद की आटे की—को तेल का मासिक कोटा। खं० ५९, पृ० ३४।

चने—

प्र० वि०—बनारस व गोरखपुर में—का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४।

चेयरमैन—

प्र० वि०—मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के—की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१७७।

चोरबाजारी—

प्र० वि०—फैजाबाद जिले में चीनी की—। खं० ५९, पृ० २९२।

चोरियों—

प्र० वि०—जिला गोंडा में—, डकैतियों और हत्याओं की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

ज

जगन्नाथ दास, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५२।

जगन्नाथ बख्श सिंह, श्री—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४७—४८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० ३३-४५,  
४८७, ४८८, ५०० और ५०३।

नगमोहन सिंह नेगी, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

जंगल—

प्र० वि०—कुल्हा जिला हमीरपुर के—  
से रेनी। खं० ५९, पृ० २१-  
२२।

जमींदारी-विनाश—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय—  
और भूमि व्यवस्था बिल खं० ५९,  
पृ० ३०-३१, १६०-१६१, २००-  
२६०, २९-३६८, ३५७-४१३,  
४२४-५०३।

जयराम वर्मा, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

जहीरुल हसनन लारी, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० २०८-  
२१४, २१५-२२४, २२५।

जिला अधिकारियों—

प्र० वि०—को शासन संबंधी  
मामलों के संबंध में गुप्तज्ञा।  
खं० ५९, पृ० १०५।

जिला बोर्डों—

प्र० वि०—प्रान्त के विभिन्न—के  
अस्पतालों का प्रान्तीयकरण। खं० ५९,  
पृ० ३०-३१।

जुलाहों—

प्र० वि०—जिला सहारनपुर के—  
को सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ०  
२७५।

जेल—

प्र० वि०—फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट—में  
१७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को  
कम्युनिस्टों की संख्या। खं० ५९, पृ०  
१८७-१८८।

जेलों—

प्र० वि०—सैदूल तथा जिला—के  
संबंध में प्रश्नोत्तर। खं० ५९, पृ०  
२८३, २८४।

ट

टी० बी० अस्पताल—

प्र० वि०—आगरा—में दो साल के  
अन्दर टी० बी० का इलाज किये  
गाएँ गरीबों की संख्या। खं० ५९,  
पृ० ११०।

ड

डकैनियों—

प्र० वि०—दिल्ली में चोरियों,  
—और—की संख्या।  
खं० ५९, पृ० ११०।

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले से—की  
संख्या और उनकी संख्या। खं०  
५९, पृ० १८-१९।

डाकूओं—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ मिट्टी के पास  
—की गिरफ्तारी। खं० ५९,  
१६-१८।

डिप्टी स्पीकर—

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली  
के नियमों तथा स्थायी आदेशों  
में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं०  
५९, पृ० ५१, ५२, ५३, ५५,  
५६, ५७-६०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के कई  
ओटने और गाँव बनाने के कारखानों  
के बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल  
की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९,  
पृ० २००।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय  
म्युनिसिपैलिटीज (अमेडमेंट) बिल  
पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति  
की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० ६०, ७९, ९१,  
१५२-१६५, २००, २१५, २६०,  
३१३, ३२३, ३४८, ४५७, ४८२,  
४८५, ५०२-५०३।

## डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर—

प्र० वि०—की योग्यता तथा उनका बेतन। खं० ५९, पृ० २६।

## डेपुटेशन—

प्र० वि०—मेडिकल लाइसेंशिएट संघ के —की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

## डेवलपमेंट बोर्ड—

प्र० वि०—मैनपुरी—के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

त

## तरक्की—

प्र० वि०—पुलिस अधिकारियों की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के लिये—और इनाम। खं० ५९, पृ० ११३।

थ

## थानेदार—

प्र० वि०—बलुवा, जिला बनारस के—के खिलाफ शिकायत। खं० ५९, पृ० १९९।

## थामसन अस्पताल—

प्र० वि०—आगरे के—में दांतों के इलाज का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १११।

द

## दान—

प्र० वि०—दियरा राज, जिला सुल्तानपुर के राजा साहब का सरकार को—। खं० ५९, पृ० १०४।

## दूध—

प्र० वि०—बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से—का क्रय व उसके विक्रय का भाव। खं० ५९, पृ० २८२।

## द्वारिका प्रसाद मोर्य, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

न

## नत्थियां—

—खं० ५९, पृ० ९२—९७, १६६—१७३, २६१, २६२—२६३, २६४, २६५, २६६—२६७, २६८, २६९।

## नदियों—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से—की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

## नायर नदी—

प्र० वि०—में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

## नारायण दास, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## नियम—

प्र० वि०—गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के—। खं० ५९, पृ० १११।

## निहालुद्दीन, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० २५९—२६०, २९५—२९८।

## नीलाम—

प्र० वि०—पुलिस सुपरिटेण्डेंट आजमगढ़, के मातहत (सरकारी) जीप कार का—। खं० ५९, पृ० ११५।

## नुमायशें—

प्र० वि०—विभिन्न विभागों के इंतजाम में सरकार के अधीन—। खं० ५९, पृ० १९४—१९५।

५

पतरौल—

प्र० वि०—का कानूनकरो मे निम्नलेन । खं० ५९, पृ० ३००।

पटिलिन्टी वाला—

प्र० वि०—का जिनों से काम खं० ५९, पृ० १८३।

परमिट—

सन् १९५६-५७, १९५७-५८ ई० व इस साल से शहर बदायूं और उमानी के रहने वालों को सैमेट व लोड के—। खं० ५९, पृ० १९३-१९४।

परीक्षाएं—

प्र० वि०—महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेन्ट जुबली कालेज, लखनऊ मे प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) —। खं० ५९, पृ० १०९।

पशु विभाग—

प्र० वि०—श्री भंवर सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, —की पेशन का भुगतान खं० ५९, पृ० १८३-१८४।

पानी—

प्र० वि०—किसानों द्वारा खेतों की सिंचाई करते समय—का बेकार बहना । खं० ५९, पृ० २९।

पुलिस अधिकारियों—

प्र० वि०—की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के लिये तरक्की और इनाम । खं० ५९, पृ० ११३।

पुलिस सुपरिटेण्डेंट—

—आजमगढ़ के मातहत (सरकारी) जीप कार का नीलाम । खं० ५९, पृ० ११५।

पूछताछ—

प्र० वि०—कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों के संबंध में—। खं० ५९, पृ० १०६।

प्र० वि०—रंजीतबाद मे आतरेरी मजिस्ट्रेटों की बैठ बनाने के विषय मे—। खं० ५९, पृ० १८९।

प्र० वि०—मिर्जापुर में विदुः मल्लाई के डरे मे—। खं० ५९, पृ० १११।

प्र० वि०—मैनपुरी में मजे-रमजिन्ने: व रेवेन्यू अफसर के मजूर मे—। खं० ५९, पृ० १८४।

प्र० वि०—रोडवेज की मोटरगाड़ियों के संबंध मे—। खं० ५९, पृ० १९५, १९६-१९७।

पुजिमा बनर्जी, श्रीमन्—

देविए "प्रश्नोत्तर"।

पेशन—

प्र० वि०—श्री भंवर सिंह रिटायर्ड, इंस्पेक्टर पशु विभाग की—का भुगतान । खं० ५९, पृ० १८३-१८४।

प्रतिनिधित्व—

प्र० वि०—आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी मे फ रोजाबाद प्रतिनिधित्व बोर्ड का—। खं० ५९, पृ० १८८-१८९।

प्र० वि०—मैनपुरी के नोटीकाइड एरियाओं में जनता का—। खं० ५९, पृ० २९४।

प्रतिलिपि—

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविमज मेडिनेय आर पब्लिक आर्डर (कार्य-वाही को बंध करने के) अध्यादेश की—का मेज पर रखा जाना । खं० ५९, पृ० १२०।

प्रधान सचिव, माननीय—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद । खं० ५९, पृ० ३६-३९।

[प्रधान मन्त्रि, गन्तव्य]

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन  
पर शोक-सन्नाह । खं० ५९, पृ०  
३४-३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली  
के नियमों तथा सारी आदेशों में  
संशोधन करने का प्रस्ताव । खं०  
५९, पृ० ४१-४५, ५३-५५।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विभाग और भूमि व्यवस्था  
बिल । खं० ५९, पृ० ६०-  
७६।

सन् १९४९ ई० के ग्राइंडेड प्रॉपर्टी  
होल्डर्स का नॉटिफिकेशन की शर्तों पर  
का मेस पर रखा जाना । खं० ५९,  
पृ० ४१।

प्रबंध—

प्र० दि०—जिना गड़वाल में अन्न, बीज  
और तिल का—। खं० ५९, पृ०  
२७८।

प्र० वि०—मुल्तानपुर जिना जेल के मुर्दों  
के जलाने या दफनाने का—।  
खं० ५९, पृ० १०४।

प्रश्न उत्तर

अचल सिंह, श्री—

विभिन्न जिलों में स्त्रियों को भगाने वाला  
संछित गुंडों का गिरोह तथा उसकी  
रोकथाम । खं० ५९, पृ०  
१०-११।

अब्दुल हमीद, श्री—

न्यू लेजिस्लेचर रेजिडेंस का फरनीचर ।  
खं० ५९, पृ० १९२-१९३।

परगने मंगलौर की मुन्सफी 'देवबन्द'  
जिला सहारनपुर में होने के कारण  
असुविधा । खं० ५९, पृ० १९२।

कृपा शंकर, श्री—

सचिवालय में हिन्दी का प्रयोग । खं०  
५९, पृ० १८४-१८५।

खुशबख्त राय, श्री—

खोरी में सीमेंट का वितरण । खं० ५९,  
पृ० ९-१०।

प्रान्त में जेड, चना, मक्का इत्यादि की  
उत्पत्ति तथा बाहर में आयात अनाज  
की मात्रा । खं० ५९, पृ०  
५-७।

रोडवेज की 'पेंटरगाड़ियां' के संबंध में  
पूछताछ । खं० ५९, पृ० १९५,  
१९६-१९७।

गंगा प्रसाद, श्री—

जिना में जेड और जेडों के जेडों और  
हस्ताक्षरों की रिया । खं० ५९, पृ०  
११२।

पुलिस अतिथियों की तस्वीरें, वेडिंग  
और इत्यादि के काम करने के  
लिए तस्वीरों और इनका । खं०  
५९, पृ० ११३।

फरीजाबाद में आरंभ की गई जेडों की  
बैठक बनाने के विषय में पूछताछ ।  
खं० ५९, पृ० १८५-१८६।

गजाधर प्रसाद, श्री—

किछीडा शरीर जिना फैजाबाद में  
वस-हुज्जत । खं० ५९, पृ० २०-  
२१।

कृषि महाविद्यालय कानपुर के अध्यापकों  
के संबंध में पूछताछ । खं० ५९, पृ०  
१०६।

गांव कुर्था, तहसील सदर, जिना गाजी-  
पुर के बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्था ।  
खं० ५९, पृ० १९७-१९८।

गुंडों की संख्या बढ़ने के कारण । खं०  
५९, पृ० १९९-२००।

तहसील पडरौता, जिना देवरिया के  
विभिन्न गांवों की माछाजारी और  
लगान । खं० ५९, पृ० २४।

पुलिस सुपरिटेण्डेंट आजमगढ़ के मातहत  
(सरकारी) जपकार का नीलाम ।  
खं० ५९, पृ० ११५।

प्रान्त में जिलेवार गुंडों की संख्या । खं०  
५९, पृ० १९९।

बलुवा जिला बनारस के थानेश्वर के  
खिलाफ शिकायत । खं० ५९, पृ०  
१९९।

जगन्नाथ दास, श्री—

जिला सहारनपुर के कुलाहों को सरकारी सहायता । खं० ५९, पृ० २३५ ।

सहमील नकुर (सहारनपुर) में सिचाई । खं० ५९, पृ० २३४—२३५ ।

जगमोहन सिंह नेनी, श्री—

जिला गढ़वाल की जन योजना के इंस्पेक्टर आरु एकाउन्ट्स की सुझावें । खं० ५९, पृ० १०७ ।

नयार नदी में बांध बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट । खं० ५९, पृ० १२२—१२३ ।

जयराम वर्मा, श्री—

ठांडा, जिला फंजाबाद की आटे की चक्कियों को तेल का मासिक कोटा । खं० ५९, पृ० ३४ ।

हारिका प्रसाद मौर्य, श्री—

गांव सभा के सेक्रेटरी के चुनाव के नियम । खं० ५९, पृ० १११ ।

जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का प्रान्तीयकरण । खं० ५९, पृ० २७ ।

जौनपुर जिले में अदालती पंचायतें और गांव अदालतों में चुने गये हरिजन । खं० ५९, पृ० ११० ।

जौनपुर जिले में नए अस्पतालों का खोला जाना । खं० ५९, पृ० २६ ।

जौनपुर जिले में बेदखलियां तथा किसानों की भूमि की वापसी । खं० ५९, पृ० २७—२८ ।

जौनपुर जिले में सिचाई का प्रबंध । खं० ५९, पृ० २७ ।

डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर की योग्यता तथा उनका वेतन । खं० ५९, पृ० २६ ।

नए प्रेसों तथा नए अखबारों के संबंध में सरकार की नीति । खं० ५९, पृ० २६ ।

मड़ियाह—केराकत सड़क का प्रान्तीय-करण । खं० ५९, पृ० २८ ।

विभिन्न जिलों में अछूतों की सहायता के लिए जिला अफसरों को नियुक्ति । खं० ५९, पृ० २४—२६ ।

सन् १९४८-४९ ई० में दिवंगत जातियों, अछूतों और मोनिमों के लिये शिक्षा के मद में निश्चित रकमें । खं० ५९, पृ० १२९ ।

नारायण दास, श्री—

महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेंट जुबली कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा थ्योरेटिक (संगीत) परीक्षाएं । खं० ५९, पृ० १०९ ।

लखनऊ नगर के बहुत से मुहालों में रोगनी का प्रबंध । खं० ५९, पृ० १०९ ।

पूणिमा बनर्जी, श्रीमती—

प्रान्त में नए विधान के अनुसार जन-वाताओं की सूची । खं० ५९, पृ० १२९ ।

फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या । खं० ५९, पृ० १२७—१२८ ।

बलभद्र सिंह, श्री—

कस्बा डिबाई, जिला बुलन्दशहर में जनकार्यों के लिए इलेक्ट्रिक इनर्जी (विद्युत् शक्ति) । खं० ५९, पृ० ११० ।

प्रान्तीय रजक दल, बुलन्दशहर द्वारा राष्ट्रीय पताकाओं का खरीद जाना और उन्हें अधिक सूझ पर बेचना । खं० ५९, पृ० १२—१३ ।

श्री भंडर सिंह रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पशु विभाग की पेंशन का भुगतान । खं० ५९, पृ० १२३—१२४ ।

बशीर अहमद, श्री—

जिला बिजनौर में लाइसेंसधारियों की संख्या । खं० ५९, पृ० ११३ ।

धामपुर जिला बिजनौर के सुगर मिल पर कार्रवारियों का कर्मी । खं० ५९, पृ० २९३ ।

## [प्रश्नोत्तर]

शक्कर की उपज में कमी। खं० ५९, पृ० २९२-२९३।

बादशाह गुप्त, श्री—

गैर सरकारी किराए पर चलने वाली लारियों के किराए की शरह और सवारियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११६।

जिला विकास बोर्ड मैनपुरी तथा उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८, २८९।

पब्लिसिटी वान्स का जिलों में काम। खं० ५९, पृ० १८७।

मैनपुरी की सहकारी समितियों में गबन तथा चुनाव संबंधी शिकायतें। खं० ५९, पृ० २८६-२८८।

मैनपुरी के नोटीफाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० २९४।

मैनपुरी के स्पेशल मजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफसर के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।

मैनपुरी जिला बोर्ड की सब कमेटियों की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३-२९४।

मैनपुरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन की, अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६-१८७।

वनस्पति घी में रंग देने के लिए जनता की मांग। खं० ५९, पृ० १४-१६।

वाहन विभाग का राष्ट्रीयकरण। खं० ५९, पृ० २९४।

सरकारी योजनाओं के प्रचारार्थ समाचार-पत्र निकालने की योजना। खं० ५९, पृ० १८७।

भारतसिंह यादवाचार्य, श्री—

किसानों द्वारा खेती की सिंचाई करते समय पानी का बेकार बहाना। खं० ५९, पृ० २९।

पतरौल का काश्तकारों से रिश्वत लेना। खं० ५९, पृ० ३०।

प्रान्त के जिलों से खुफिया रिपोर्टें। खं० ५९, पृ० १२।

प्रान्त में शरणार्थियों तथा युद्ध से लोटे सैनिकों के लिए भूमि की प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।

शेरपुर, जिला गाजीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच मनमुटाव। खं० ५९, पृ० १२।

सन् १९४७-४८ ई० में सब-इंस्पेक्टरों के पदाभिग्राहियों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११।

सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी। खं० ५९, पृ० ३०।

मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री—

अयोध्या शहर मिल राजा का सहस्रपुर और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५-२७६।

केन कोआपरेटिव सोसाइटी पीलीभीत के कर्मचारियों का वेतन। खं० ५९, पृ० २७६, २७८।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री—

राजनीतिक कैदियों के घरवालों को भत्ता। खं० ५९, पृ० २८-२९।

विभिन्न विभागों के इंतजाम में सरकार के अवीन नुमायशों। खं० ५९, पृ० १९४-१९५।

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ व इस साल में शहर बढ़ाई और ऊझानी के रहने वालों को सोमेट व लोहे के परमिट। खं० ५९, पृ० १९३-१९४।

यशनारायण उपाध्याय, श्री—

गुप्तकाशी (गढ़वाल) में फलों के बीज के विवरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।

गोशाला के सुप्रबंध के लिए एक अधि-कारी की नियुक्ति। खं० ५९, पृ० २८२, २८३।

चमोली तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी लोअर सेकेंड स्कूल और उन्हें सरकारी महाना। खं० ५९, पृ० २७०—२८०।

चमोली तहसील, गढ़वाल में प्रांतीय रक्षक दल के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८०।

चमोली तहसील, गढ़वाल में विक्रम योजना के अन्तर्गत कार्य। खं० ५९, पृ० २८०—२८१।

चमोली तहसील जिला गढ़वाल में गन दो वर्षों में स्थापित संस्थाये। खं० ५९, पृ० २७८, २७९।

जिला गढ़वाल में अन्न, बीज और शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७८।

बनारस जिले के इंटरमीजिएट कालिजों में सैनिक शिक्षा। खं० ५९, पृ० १९०।

बनारस तहसील में नए स्कूल और उनको सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

बनारस तहसील में बाढ़ पीड़ितों की सहायता। खंड ५९, पृ० २८१।

बनारस तहसील में सहकारी संस्था द्वारा किसानों से दूध का क्रय व उसके विक्रय का भाव। खं० ५९, पृ० २८२।

बनारस में प्रौढ़ शिक्षा। खं० ५९, पृ० २८६।

बनारस में बिजली की सप्लाई। खं० ५९, पृ० २८५।

बनारस व गोरखपुर में चने का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४।

बनारस शहर में निजी बधागार व उनमें मारे जाने वाले पशुओं की संख्या। खं० ५९, पृ० २८२।

बनारस शहर में बाढ़ पीड़ा। खं० ५९, पृ० २८६।

राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी और बनारस के वन्दी। खं० ५९, पृ० २८३।

रुद्रप्रयाग में बीरी तक की सड़क। खं० ५९, पृ० २७८।

सेंट्रल तथा जिला जेलों के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २८३—२८४।

राजाराम मिश्र, श्री—

फैजाबाद के हज़रती केशी। खं० ५९, पृ० २९०, २९१।

फैजाबाद जिले के ज़मीन चोगव-जारी। खं० ५९, पृ० २९०।

फैजाबाद में सिद्धों के देव का विवरण। खं० ५९, पृ० २९१, २९२।

फैजाबाद शहर में तन्दगीयों की गुम-दियों के कर्मग जनन को कष्ट। खं० ५९, पृ० २०—२३।

राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री—

लखनऊ में न कमिश्नर के अफिस को फैजाबाद ले जाने के संबंध में पृष्ठ-ताछ। खं० ५९, पृ० २३।

रामकृपाल मिश्र, श्री—

गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ पर सरकारी व्यय। खं० ५९, पृ० १४।

रामचन्द्र पालीवाल, श्री—

आगरा जिले की हाउसिंग कमेटी में फैरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—१८९।

फैरोजाबाद में कांच के व्यवसाय का विकास। खं० ५९, पृ० ११४।

रामचन्द्र मेहरा, श्री—

आगरा टी० बी० अफिस में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किए गए मरीजों की संख्या। खं० ५९, पृ० ११०।

आगरे के ग्राम्यन अफिस में दांतों के इलाज का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १११।

रामबली मिश्र, श्री—

जिला अधिकारियों को सामान संबंधी मामलों के संबंध में गुप्तज्ञा। खं० ५९, पृ० १०५।

दिल्ली राज्य, जिला मुल्तानपुर के राजा साहब का सरकार को दान। खं० ५९, पृ० १०४।

मुल्तानपुर जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना। खं० ५९, पृ० १०४।

मुल्तानपुर जिला जेल में मुर्तों के जलाने या दफनाने का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०४।



## [ प्रश्नोत्तर ]

सुल्तानपुर जिले में क्षय रोगियों की सूची। खं० ५९, पृ० १०४।

सुल्तानपुर में भ्रष्टाचार। खं० ५९, पृ० १०५।

सूबे में बने हुए हवाई अड्डों को प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना। खं० ५९, पृ० १०५।

लाल बिहारी टंडन, श्री—

राष्ट्र भाषा विद्यालय, बहराइच खं० ५९, पृ० १९१।

विजयानन्द मिश्र, श्री—

गाजीपुर में वर्तमान बिजली कम्पनी के ठेके की अवधि। खं० ५९, पृ० ११८।

मिर्जापुर जिले में बीज गोदामों के विषय में विवरण। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८०।

मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

मिर्जापुर में विद्युत् सलाई के बारे में पूछताछ। खं० ५९, पृ० ११९।

विद्याधर बाजपेयी, श्री—

सुल्तानपुर पुलिस का एक बदमाश की गिरफ्तारी के लिए प्रयत्न। खं० ५९, पृ० १०५।

सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा बाल-न्ट्रियरों की भर्ती। खं० ५९, पृ० १०६।

विश्वनाथ प्रसाद, श्री—

मेयो मेमोरियल पुस्तकालय को सहायता। खं० ५९, पृ० १०६।

शिवदानसिंह, श्री—

दैनिक पत्र "उजाला" के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० २४-२५।

श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री—

प्रतापगढ़ जिले में डकैतियों की संख्या और उनकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १८-१९।

प्रतापगढ़ जिले में बाढ़ से क्षति। खं० ५९, पृ० २०।

प्रतापगढ़ में बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९, पृ० १९।

प्रतापगढ़ सिटी के पास डाकुओं की गिरफ्तारी। खं० ५९, पृ० १६-१८।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के कर्म-चारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २७९-२९०।

श्रीचन्द्र मिश्र, श्री—

मेडिकल लाइसेंसिएट संघ के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेट। खं० ५९, पृ० १०२।

श्रीपति सहाय, श्री—

कुन्हाटा जिला हमीरपुर के जंगल में खेती। खं० ५९, पृ० २१-२२।

सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में पहाड़ियां तथा खमा ग्रामों की क्षति-पूर्ति। खं० ५९, पृ० १११।

हरगोविन्द पन्त, श्री—

किस्मत कुमार्थ में मूक और बधिरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ८-९।

ग्रामसुधार के सुपरवाइजर तथा आर्गेनाइजरों की योग्यता में भेद। खं० ५९, पृ० ३३।

जिला अल्मोड़ा में ग्रामसुधार आर्गेनाइजरों की दुबारा नियुक्ति का आधार। खं० ५९, पृ० ३२-३३।

प्रान्त के विभिन्न जिला बोर्डों के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण। खं० ५९, पृ० ३०-३१।

प्रान्त में गुंगे और बहरों की शिक्षा का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ७-८।

रानीखेत की छावनी का अस्पताल। खं० ५९, पृ० ३२।

रानीखेत तहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री—

प्रान्त में कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस हथियार रखने की इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

बन्दरों तथा अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसल को हानि। खं० ५९, पृ० १०३।

बाराबंकी के सीमेड के एजेंटों द्वारा दूसरे जिलों को सीमेड की मज्दारी। खं० ५९, पृ० १०२।

#### प्रान्तीयकरण—

प्र० वि०—जिला बोर्डों के अध्यापकों की नौकरी का—। खं० ५९, पृ० २७।

प्र० वि०—मद्रियाह—केराकत सड़क का—। खं० ५९, पृ० २८।

#### प्रान्तीय रक्षक दल—

प्र० वि०—चमोली तहसील, गढ़वाल में—के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८०।

#### फ

#### फखरुद्दुल इस्लाम, श्री—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक—संवाद। खं० ५९, पृ० ३६-३९।  
श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शोक संवाद। खं० ५९, पृ० ३४-३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४५-४६।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १५४-१६०।

#### फर्नीचर—

प्र० वि०—न्यू लेजिस्लेचर्स रेजिडेंस का—। खं० ५९, पृ० १९२-१९३।

#### फलों—

प्र० वि०—गुप्त काशी (गढ़वाल) में—के बीज के वितरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।

#### फसलों की हानि—

प्र० वि०—बन्दरों तथा अन्य जंगली जानवरों द्वारा—। खं० ५९, पृ० १०३।

#### कूट निर्यात, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १३५-१३६।

#### क

#### कदन निर्यात, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४५१-४५२।

#### कानूक—

प्र० वि०—गढ़वाल में—के लाइसेन्सों के लिए प्रार्थना पत्र। खं० ५९, पृ० १९-२०।

#### कानूनों—

प्र० वि०—जिज बिजनौर में—के लाइसेन्सधारियों की संस्था। खं० ५९, पृ० ११३।

#### कम-हुर्ज-मना—

प्र० वि०—फिरोजा शरीफ जिला फैजाबाद में—। खं० ५९, पृ० २०-२१।

#### कलभद्र मिश्र, श्री—

देतिए "प्रश्नोत्तर"।

#### कशीर अहमद अमारी, श्री—

देतिए "प्रश्नोत्तर"।

#### काढ़—

प्र० वि०—प्रतापगढ़ जिले में—से क्षति। खं० ५९, पृ० २०१।

प्र० वि०—बनारस शहर में—पी।। खं० ५९, पृ० २८६।

प्र० वि०—निर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की—से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

#### काढ़ पीड़ितों—

प्र० वि०—गाँव कुर्था, तहसील सदर, जिला गाजीपुर के—की व्यवस्था। खं० ५९, पृ० १९७-१९८।

प्र० वि०—बनारस तहसील में—की सहायता। खं० ५९, पृ० २८१।

बादशाह गुप्त, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

बांध—

प्र० वि०—रायर नदी से—बांधने के संबंध में सरकार द्वारा नियत विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ५९, पृ० १८२, १८३।

बिजली—

प्र० वि०—ब्रनारस से—की सप्लाई। खं० ५९, पृ० २८५।

बिल—

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त के रई ओटने ओर गांठ बनाने के कारखानों के—पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज (अमेडमेट)—पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० २००।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था—। खं० ५९, पृ० ६०—९१, १२०—१६५, २००, २९५—३४८, ४२४—५०३।

बीज गोदाम—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले के—के विषय में विवरण। खं० ५९, पृ० १७८, १७९, १८०।

बैंच—

प्र० वि०—हीरोजाबाद में आनरेरी मजिस्ट्रेटों की—बनाने के विषय में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५—१८६।

बैदखलियां—

प्र० वि०—जीनपुर जिले में—तथा किसानों को भूमिकी वापसी। खं० ५९, पृ० २७—२८।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

बिल। खं० ५९, पृ० ४४२—४४६।

भर्ती—

प्र० वि०—सुल्तानपुर में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के मिपहसालार द्वारा चालंटियरों की—। खं० ५९, पृ० १०६।

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

भुगतान—

प्र० वि०—श्री भंवर सिंह रिटायर्ड इंस्पेक्टर पशु विभाग की पेंशन का—। खं० ५९, पृ० १८३—१८४।

भूमि—

प्र० वि०—प्रान्त में शरणार्थियों तथा युद्ध में लोटे सैनिकों के लिए—की प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।

भेंट—

प्र० वि०—पेडिकल लाइमेशिएट संघ के डेपुटीजन की माननीय चिकित्सा सचिव से—। खं० ५९, पृ० १०२।

भेद—

प्र० वि०—ग्रामसुधार के मुपरवाइजर तथा आर्गनाइजर्स की योग्यता में—। खं० ५९, पृ० ३३।

म

मजिस्ट्रेट—

प्र० वि०—मैनपुरी के स्पेशल—ब रेवेन्यू अफसर के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।

मजिस्ट्रेटों—

प्र० वि०—हीरोजाबाद में आनरेरी—की बैंच बनाने के विषय में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८५—१८६।

मड़ियाह—केराकत—

प्र० वि०—सड़क का प्रान्तीय करण। खं० ५९, पृ० २८।

पतदाताओं—

प्र० वि०—प्रान्न में नए विधान के अनुसार—की सूची। ख० ५९, पृ० १८९।

सनमुटाव—

प्र० वि०—गोरपुर, जिला गार्गीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच—। ख० ५९, पृ० १२।

मरीजों—

प्र० वि०—गंगरा टी० बी० अस्पताल में दो साल के अन्दर टी० बी० का इलाज किए गए—की संख्या। ख० ५९, पृ० ११२।

महिला विद्यालय कालेज—

प्र० वि०——गोर गवर्नमेंट जुबिली कालेज, लखनऊ में प्रैक्टिकल (अभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) परीक्षाएं। ख० ५९, पृ० १०९।

मालगुजारी—

प्र० वि०—तहसील पडरौना, जिला—देवरिया के विभिन्न गांवों की—और लगान। ख० ५९, पृ० २४।

मिट्टी के तेल—

प्र० वि०—कैजाबाद में—का वितरण। ख० ५९, पृ० २९१, २९२।

मुअत्तली—

प्र० वि०—जिला गढ़वाल की ऊन योजना के इंस्पेक्टर आफ एकाउन्ट्स की—। ख० ५९, पृ० १०७।

मुंसफी—

प्र० वि०—परगने मंगचौर की—देवबन्द जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा। ख० ५९, पृ० १९२।

मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

मुर्वों—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिला जेल के—के जलाने या बफनाने का प्रबन्ध। ख० ५९, पृ० १०४।

मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड—

प्र० वि०—मुल्तानपुर में—के मयमलार द्वार, वाइंटियर, की भर्ती। ख० ५९, पृ० १०६।

मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। ख० ५९, पृ० ४५९—४६७।

मुहम्मद जनशेद अल्ले खां—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। ख० ५९, पृ० ३१३—३१८।

मुहम्मद यूसुफ श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। ख० ५९, पृ० १४३—१५२।

मुहम्मद रजा खं, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। ख० ५९, पृ० ४३८—४४२।

मूक—

प्र० वि०—किशन कृमायूं में—और बहिरों की शिक्षा का प्रबंध। ख० ५९, पृ० ८।

मेडिकल लाइसेंसिएट संघ—

प्र० वि०——के डेपुटेशन की माननीय चिकित्सा सचिव से भेंट। ख० ५९, पृ० १०२।

मेयो मेमोरियल पुस्तकालय—

प्र० वि०—को सहायता। ख० ५९, पृ० १०६।

मोटर गाड़ियों—

प्र० वि०—रोडवेज की—के संबंध में पूछताछ। ख० ५९, पृ० १९५, १९६—१९७।

सन् १९३९ के—के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के—के नियम

## [मोटर गाड़ियों—]

७८ में किसे गए संशोधन की प्रति-  
लिपि का मेज पर रखा जाना। खं०  
५९, पृ० ४१।

## मोमिनो—

प्र० वि०—सन् १९४८-४९ ई० में  
पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों  
और—के लिए शिक्षा में मदद  
में निर्धारित करने। खं० ५९, पृ०  
१८९—१९०।

## म्युनिमिल बोर्ड—

प्र० वि०—आगरा जिले की हाउसिंग  
कमेटी में फीरोजाबाद—का  
प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—  
१८९।

## य

## यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## योजना—

प्र० वि०—चमोली तहसील गढ़वाल में  
विकास—के अन्तर्गत कार्य। खं०  
५९, पृ० २८०, २८१।

प्र० वि०—जिला गढ़वाल की ऊन—  
के इंसपेक्टर आफ एकाउन्ट्स की  
मुअत्तली। खं० ५९, पृ० १०७।

प्र० वि०—सरकारी योजनाओं के प्रचा-  
रार्थ समाचार-पत्र निकालने की—।  
खं० ५९, पृ० १८७।

## र

## रक्षकों—

प्र० वि०—सन् १९४८-४९ ई० में  
पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और  
मोमिनो के लिए शिक्षा के मद में  
निर्धारित—। खं० ५९, पृ०  
१८९—१९०।

## रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० १६१—  
१६४, २०१-२०८।

## रघुवीर सहाय, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था

बिल। खं० ५९, पृ० २५०-  
२५९।

## राजनीतिक कैदियों—

प्र० वि०—के घरवालों को  
भत्ता। खं० ५९, पृ० २८—२९।

## राजाराम मिश्र, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राजाराम नास्त्री, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० ३२३,  
३४०—३४८।

## राधाकृष्ण अप्पवाल, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राम कृपाल सिंह, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राम चन्द्र पालीवाल, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राम चन्द्र मेहरा, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राम बली मिश्र, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

## राष्ट्र भाषा—

प्र० वि०—विद्यालय, बहराइच।  
खं० ५९, पृ० १९१।

## राष्ट्रीय पताकाओं—

प्र० वि०—प्रान्तीय रक्षक दल, बुलन्द  
शहर द्वारा—का खरीदा जाना  
और उन्हें अधिक मूल्य पर बेचना।  
खं० ५९, पृ० १२-१३।

## राष्ट्रीय स्वयंसेवकों—

प्र० वि०—की गिरफ्तारी और  
बनारस के बन्दो। खं० ५९, पृ०  
२८३।

## रिपोर्ट—

प्र० वि०—नायरनदी में बांध बांधने  
के संबंध में सरकार द्वारा नियत  
प्रतिवेदनों की—। खं० ५९, पृ०  
१८२, १८३।

रिजिस्ट्रार—

प्र० वि०—परकारी विभागों में—  
खं० ५९, पृ० ३०।

रेजिडेंट—

प्र० वि०—न्यू रेजिडेंट्स—का  
फरनीचर। खं० ५९, पृ० १९०—  
१९३।

रेवेन्यू अफसर—

प्र० वि०—मैनपुरी के स्टेशन मैजिस्ट्रेट  
के संबंध में पूछताछ।  
खं० ५९, पृ० १८४।

रोगियों—

प्र० वि०—मुन्तानपुर जिले में रोग  
के—का सूची। खं० ५९,  
पृ० १०४।

रोडवेज—

प्र० वि०—की मोटर गाड़ियों के  
संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ०  
१९५-१९६, १९७।

रोशन जमा खां, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० ८५-९१,  
१२०-१३५।

रोशन की प्रबंध—

प्र० वि०—जनक नगर के बहुत से  
मुठ्ठलों में—। खं० ५९, पृ०  
१०९।

ल

लाइसेंस—

प्र० वि०—जिला बिजनौर में बन्दूकों  
के—दारों की संख्या। खं० ५९,  
पृ० ११३।

प्र० वि०—प्रतापगढ़ में बन्दूक के—  
के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९,  
पृ० १९-२०।

प्र० वि०—प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को  
बिना—हथियार रखने की  
इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

लारियों—

प्र० वि०—मैनपुरी की लार पर  
कर देने वाली—के लिए लार  
के—के लिए—। खं०  
५९, पृ० ११३।

लालबिहारी—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

लोट्टे—

सन् १९४९-५०, १९८०-८८ ई० में  
इस साल में रंगबद्ध जार उमा-  
नी के रंग बलों की संमेट  
के परमिट। खं० ५९,  
पृ० १९३-१९४।

व

ववागार—

प्र० वि०—जनारम नगर में निजी—  
व उनमें मारे जाने गले पशुओं  
की संख्या। खं० ५९, पृ० २८२।

वनस्पति घी—

प्र० वि०—में रंग देने के लिये  
जनता की मांग। खं० ५९, पृ०  
१४-१६।

वाहन विभाग—

प्र० वि०—का राष्ट्रीयकरण।  
खं० ५९, पृ० २९४।

विकास—

प्र० वि०—फीरोजाबाद के कांच व्यवसाय  
का—। खं० ५९, पृ० ११४।

विकास बोर्ड—

प्र० वि०—जिला—मैनपुरी नगर  
उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८  
२८९।

विजयानन्द मिश्र, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

विद्याधर बाजपेयी, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

विद्यालय—

प्र० वि०—राष्ट्रभाषा—बहराइच ।

खं० ५९, पृ० १९१।

विद्युत् सप्लाई—

प्र० वि०—मिर्जापुर में—के बारे में

पूछनाछ। खं० ५९, पृ० ११९।

विधान—

प्र० वि०—प्रान्त में नए—के

अनुसार मतदाताओं की सूची।

खं० ५९, पृ० १८९।

विभागों—

प्र० वि०—विभिन्न—के इन्तजाम में

सरकार के अधीन नुमायशों। खं०

५९, पृ० १९४-१९५।

विवरण—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले के बीज

गोदामों के विषय में—। खं० ५९,

पृ० १७८, १७९, १८०।

विशेषज्ञों—

प्र० वि०—नायर नदी में बांध बांधने के

संबंध में सरकार द्वारा नियत

—की रिपोर्टें। खं० ५९, पृ०

१८२, १८३।

विश्वनाथ प्रसाद, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

बिल। खं० ५९, पृ० २२४,

२२५—२३८, २३९, २४०,

२४१—२४४।

विष्णुशरण दुबिलिश, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

बिल। खं० ५९, पृ० ३३३—

३४०।

वीरेन्द्र शाह, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था

बिल। खं० ५९, पृ० २४४—

२५०।

वेतन—

प्र० वि०—केन कोआपरेटिव सोसाइटी,

पीओभीत के कर्मचारियों का—।

खं० ५९, पृ० २७६-२७८।

व्यक्तिगत प्रश्न

भंवर सिंह, श्री—

—, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पशु विभाग

की पेंशन का भुगतान। खं० ५९,

पृ० १८३, १८४।

व्यवस्था—

प्र० वि०—गांव कुर्या, तहसील सदर,

जिला गंजोपुर के बाढ़ पीड़ितों

की—। खं० ५९, पृ० १९७—

१९८।

श

शक्कर—

प्र० वि०—की उपज में कमी। खं०

५९, पृ० २९२, २९३।

शरणार्थियों—

प्र० वि०—प्रान्त में—तथा युद्ध से

छोटे सैनिकों के लिए भूमि की

प्राप्ति। खं० ५९, पृ० १२।

प्र० वि०—फंज वाद शहर में—

को गुप्तियों के कारण जनता को

कष्ट। खं० ५९ पृ० २२-२३।

शहर—

प्र० वि०—गैर सरकारी किराए पर

चलने वाली लारियों के किराए

की—और सवारियों की संस्था।

खं० ५९, पृ० ११६।

शिकायत—

प्र० वि०—बलुवा, जिला बनारस के

थानेदार के खिलाफ—। खं०

५९, पृ० १९९।

शिक्षा—

प्र० वि०—प्रान्त में गूंगे और बहरों की—का प्रबंध। खं० ५९, पृ० ७-८।

प्र० वि०—बनारस जिले के इंटर-मीजिएट कालेजों में सैनिक—। खं० ५९, पृ० १९०।

प्र० वि०—बनारस में प्रौढ़—। खं० ५९, पृ० २८६।

प्र० वि०—सन् १९४८-४९ ई० में पिछड़ी हुई जातियों, अछूतों और मोमिनों के लिए—के मद में निर्धारित रकमें। खं० ५९, पृ० १८९-१९०।

शिवदान सिंह, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

शुगर मिल—

प्र० वि०—अयोध्या—राजा का सहसपुर और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५, २७६।

प्र० वि०—वामपुर, जिला बिजनौर के—पर काश्तकारों का कर्जा। खं० ५९, पृ० २९३।

शोक-संवाद—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर—। खं० ५९, पृ० ३६-३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर—। खं० ५९, पृ० ३४-३६।

श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

श्रीचन्द्र सिंघल, श्री—

देखिए “प्रश्नोत्तर”।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ३१८-३२७।

श्रीपति सहाय, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

स

संस्थाएं—

प्र० वि०—जिला गढ़वाल की चमोली तहसील में गत दो वर्ष में स्थापित सहकारी—। खं० ५९, पृ० २७८, २७९।

संख्या—

प्र० वि०—प्रान्त में जिलेवार गुंडों की—। खं० ५९, पृ० १९९।

प्र० वि०—फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च, सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की—। खं० ५९, पृ० १८७-१८८।

सचिव, माननीय उद्योग—

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ५१-५२।

सचिव, माननीय चिकित्सा—

प्र० वि०—मेडिकल लाइसेंसिएट संघ के डेपुटेशन की—से भेंट। खं० ५९, पृ० १०२।

सचिव, माननीय पुलिस—

सन् १९३९ के मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के अनुसार सन् १९४० ई० के मोटर गाड़ियों के नियम ७८ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविसेज मेंटिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (कार्य वाही को बंध करने के) अध्यादेश की प्रतिलिपि का मेज पर रक्खा जाना। खं० ५९, पृ० १२०।

सचिव, माननीय प्रधान—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १६४, २२४, ३४८, ४७५-४८२, ४८६-५०१, ५०२।



## सचिवालय—

प्र० वि०—में हिन्दी का प्रयोग।  
खं० ५९, पृ० १८४-१८५।

## सड़क—

प्र० वि०—रुद्रप्रयाग से गीरी तक को  
- —-; खं० ५९, पृ० २७८।

प्र० वि०—बादकी के सीमेंट के  
एगों द्वारा दूसरे जिलों में सीमेंट  
की—। खं० ५९, पृ० १०२।

## सब-इंस्पेक्टर—

सन् १९४७-४८ ई० में—के पदा-  
भिलाषियों की संख्या। खं० ५९,  
पृ० ११।

## समझौता—

प्र० वि०—अयोध्या शहर मिल, राजा  
का सहसपुर और उसके नौकरों  
के बीच—। खं० ५९, पृ०  
२७५-२७६।

## समाचार-पत्र—

प्र० वि०—सरकारी योजनाओं के  
प्रचारार्थ—निकालने की योजना।  
खं० ५९, पृ० १८७।

## सरकार—

प्र० वि०—विभिन्न विभागों के इन्तजाम  
में—के अधीन नुमायशों। खं०  
५९, पृ० १९४-१९५।

## सरकारी व्यय—

प्र० वि०—गवर्नमेंट स्कूल, मेरठ  
पर—। खं० ५९, पृ० १४।

## सवारियों—

प्र० वि०—गैरसरकारी किराए पर  
चलने वाली सारियों के किराए की  
शरह और—की संख्या। खं० ५९,  
पृ० ११६।

## सहकारी समितियों—

प्र० वि०—मैनपुरी की—में गबन  
तथा चुनाव संबंधी शिकायतें।  
खं० ५९, पृ० २८६-२८८।

## साजिद हुसैन, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय  
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था  
बिल। खं० ५९, पृ० १३७, ३२७-  
३३३।

## सिंचाई—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में—का  
प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७।

प्र० वि०—तहसील नकुर (सहारनपुर)  
में—। खं० ५९, पृ० २७४, २७५।

## सीमेंट—

प्र० वि०—खीरी में—का वितरण।  
खं० ५९, पृ० ९-१०।

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व  
इस साल में शहर बढ़ाया और  
उत्तानी के रहने वालों को—  
व लोहे के परमिट। खं० ५९,  
पृ० १९३-१९४।

## सुपरवाइजर—

प्र० वि०—ग्रामसुधार के—तथा  
आर्गेनाइजर्स की योग्यता में भेद।  
खं० ५९, पृ० ३३।

## सुल्तान आलम खां, श्री—

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-  
संवाद। खं० ५९, पृ० ३६-३९।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन  
पर शोक संवाद। खं० ५९, पृ०  
३४-३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली  
के नियमों तथा अस्थायी आदेशों में  
संशोधन करने का प्रस्ताव। खं०  
५९, पृ० ४८-५०।

## सूची—

प्र० वि०—प्रान्त में नए विधान के  
अनुसार मतदाताओं की—। खं०  
५९, पृ० १८९।

## सेक्रेटरी—

प्र० वि०—गांव सभा के—के चुनाव  
के नियम। खं० ५९, पृ० १११।

सेनीटोरियम जेल—

प्र० वि०—सुल्तानपुर जिला जेल का  
— बनाया जाना । खं० ५९,  
पृ० १०४।

स्कूल—

प्र० वि०—चमोली तहसील, गढ़वाल में  
प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी—और  
उन्हें सरकारी सहायता । खं० ५९,  
पृ० २७९, २८०।

प्र० वि०—बनारस तहसील में नए  
—और उनको सहायता । खं०  
५९, पृ० २८१।

स्त्रियों—

प्र० वि०—विभिन्न जिलों में —को  
भगाने वाला संगठित गुंडों का  
गिरोह तथा उसकी रोकथाम । खं०  
५९, पृ० १०-११।

स्थानिक प्रश्न

अल्मोड़ा—

जिला—में ग्रामसुधार आर्गेनाइजर्स  
की दुबारा नियुक्ति का आधार ।  
खं० ५९, पृ० ३२-३३।

आगरा—

—के थामसन अस्पताल में दांतों के  
इलाज का प्रबंध । खं० ५९, पृ०  
१११।

—जिले की हाउसिंग कमेटी में  
फीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का  
प्रतिनिधित्व । खं० ५९, पृ० १८८-  
१८९।

—टी० बी० अस्पताल में दो साल के  
अन्दर टी० बी० का इलाज किये  
गए मरीजों की संख्या । खं० ५९,  
पृ० ११२।

आजमगढ़—

पुलिस सुपरिटेंडेंट—के मातहत (सर-  
कारी) जीप कार का नीलाम । खं०  
५९, पृ० ११५।

उझानी—

सन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व इस  
साल में शहर बढ़ायें और —के  
रहने वालों को सीमेंट व लोहे  
के परमिट । खं० ५९, पृ० १९३-  
१९४।

कानपुर—

कृषि महाविद्यालय,—के अध्यापकों  
के संबंध में पृच्छनाछ । खं० ५९,  
पृ० १०६।

किछौछा शरीफ—

—,जिला फैजाबाद में बम-दुर्घटना ।  
खं० ५९, पृ० २०-२१।

कुन्हा—

—,जिला हमीरपुर के जंगल में खेती ।  
खं० ५९, पृ० २१-२२।

कुर्या—

गांव—,तहसील सदर, जिला गाजी-  
पुर के बाढ़-पीड़ितों की व्यवस्था ।  
खं० ५९, पृ० १९७-१९८।

खीरी—

—में सीमेंट का वितरण । खं०  
५९, पृ० ९-१०।

गढ़वाल—

जिला—की ऊन योजना के इंस्पेक्टर  
आफ एकाउन्ट्स की मुअत्तली । खं०  
५९, पृ० १०७।

जिला—में अन्न, बीज और शिक्षा का  
प्रबंध । खं० ५९, पृ० २७८।

गाजीपुर—

—में वर्तमान बिजली कम्पनी के  
ठेके की अवधि । खं० ५९, पृ०  
११८।

## शुप्तकाशी—

——(गढ़वाल) में फलों के बीज के वितरण केन्द्र। खं० ५९, पृ० २७९।

## भोडा—

जिला—में चोरियों, डकैतियों और हत्याओं की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

## नोरखपुर—

बनारस —में चने का विक्रय। खं० ५९, पृ० २८४।

## बमोली—

——तहसील, गढ़वाल में प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी स्कूल और उन्हें सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७९-२८०।

——तहसील गढ़वाल में प्रान्तीय रक्षक दल के केन्द्र। खं० ५९, पृ० २८०।

——तहसील, गढ़वाल में विकास योजना के अन्तर्गत कार्य। खं० ५९, पृ० २८०, २८१।

जिला गढ़वाल की—में गत दो वर्षों में स्थापित सहकारी संस्थायें। खं० ५९, पृ० २७८-२७९।

## जौनपुर—

——जिले में अदालती पंचायतों और गांव अदालतों में चुने गए हरिजन। खं० ५९, पृ० ११०।

——जिले में नए अस्पतालों का खोला जाना। खं० ५९, पृ० २६।

——जिले में जेदखलियां तथा किसानों को भूमि की वापसी। खं० ५९, पृ० २७-२८।

——जिले में सिंचाई का प्रबंध। खं० ५९, पृ० २७।

## टांडा—

——,जिला फैजाबाद की आटे की चक्कियों को तेल का मासिक कोटा। खं० ५९, पृ० ३४।

## डिबाई—

कस्बा—,जिला बुलन्दशहर में जन कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक इनर्जी (विद्युत शक्ति)। खं० ५९, पृ० ११०।

## बियरा इस्टेट—

——जिला सुल्तानपुर के, राजा साहब का सरकार को दान। खं० ५९, पृ० १०४।

## देवबन्द—

परगने मंगलौर की मुन्सफी—,जिला सहारनपुर में होने के कारण असुविधा। खं० ५९, पृ० १९२।

## धामपुर—

——,जिला बिजनौर के शुगर मिल पर काश्तकारों का कर्जा। खं० ५९, पृ० २९३।

## नकुर—

तहसील—(सहारनपुर) में सिंचाई। खं० ५९, पृ० २७४, २७५।

## पडरौना—

तहसील—,जिला देवरिया के विभिन्न गांवों की मालगुजारी और लगान। खं० ५९, पृ० २४।

## पीलीभीत—

केन कोआपरेटिव सोसाइटी,—के कर्मचारियों का वेतन। खं० ५९, पृ० २७६-२७८।

## प्रतापगढ़—

——जिले में डकैतियों की संख्या और उनकी रोकथाम। खं० ५९, पृ० १८-१९।

——में बन्दूक के लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र। खं० ५९, पृ० १९-२०।

——में बाढ़ से क्षति। खं० ५९, पृ० २०।

——सिटी के पास डाकुओं की गिर-फ्तारी। खं० ५९, पृ० १६-१८।

## फतेहगढ़—

——डिस्ट्रिक्ट जेल में १७ व १८ मार्च सन् १९४९ ई० को कम्युनिस्टों की संख्या। खं० ५९, पृ० १८७-१८८।

**फीरोज़पुर—**

- अगरा जिले की इन्फार्म कमेटी में—  
 व्युत्पत्ति बोर्ड का प्रतिनिधित्व।  
 खं० ५९, पृ० १२२-१२९।  
 —के जंग के व्यवसाय का विकास।  
 खं० ५९, पृ० ११८।  
 —में आनरेरी जिम्मेदारों की बैठक  
 बनाने के विषय में पृष्ठनाछ। खं०  
 ५९, पृ० १२५-१२६।

**फैजाबाद—**

- प्र० वि०—के हवालाना की कड़ी खं०  
 ५९, पृ० २००, २०१।  
 —जिले में चीनी की ची-बाजारी।  
 खं० ५९, पृ० २००।  
 —के सिद्धी के तेल का विवरण।  
 खं० ५९, पृ० २०१, २०२।  
 —शहर में शरणार्थियों की समस्याओं  
 के कारण जनता को काट। खं०  
 ५९, पृ० २०-२३।  
 लखनऊ-स्थित कमिशनर के आगम को—  
 ले जाने के संबंध में पृष्ठनाछ।  
 खं० ५९, पृ० २३।

**बदायूं—**

- मन् १९४६-४७, १९४७-४८ ई० व  
 हम माल में शहर—और उस नी  
 के रहने वालों को सीमेंट व लोहे  
 के परचिट। खं० ५९, पृ० १९३-  
 १९४।

**बनारस—**

- जिले के इंटरमीजिएट कालेजों  
 में मैट्रिक शिक्षा। खं० ५९, पृ०  
 १९०।  
 —तहसील में नए स्कूल और उनको  
 सहायता। खं० ५९, पृ० २२१।  
 —तहसील में बाढ़-पीड़ितों की  
 सहायता। खं० ५९, पृ० २२१।  
 —तहसील में सहकारी संस्था द्वारा  
 किसानों से दूध का क्रय व  
 उसके विक्रय का भाव। खं० ५९,  
 पृ० २२२।  
 —में प्रौढ़ शिक्षा। खं० ५९, पृ०  
 २२६।

- में विज्ञान की मांग। खं० ५९  
 पृ० २२६।  
 —के रोगरहित होने का विवरण।  
 खं० ५९, पृ० २२६।  
 —शहर में बाढ़ पीड़ितों। खं० ५९, पृ०  
 २२६।  
 राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की नियुक्तारी और  
 —के बन्दे। खं० ५९, पृ०  
 २२६।

- शहर में शरणार्थी व उनमें मरे जाने  
 वाले पशुओं की संख्या। खं० ५९,  
 पृ० २२६।

**बलुआ—**

- जिला दफ्तर के अनेदार के  
 विवरण। खं० ५९, पृ०  
 १९१।

**बहराइच—**

- राष्ट्र भाषा विद्वत्ता खं० ५९,  
 पृ० १९१।

**बाराबंकी—**

- के सीमेंट के एजेंटों द्वारा दूध  
 जिलों को सीमेंट की मलाई। खं०  
 ५९, पृ० १०२।

**बिजनौर—**

- जिला—में बंदूकों के लड़नेदारों  
 की संख्या। खं० ५९, पृ० २१३।

**बुलन्दशहर—**

- प्रान्तीय न्यायिक इल—द्वारा राष्ट्रीय  
 दफ्तरों का बंदीज जना और  
 उन्हें अतिरिक्त न्याय प्रदान करना। खं०  
 ५९, पृ० १२-१३।

**भीरी—**

- रुद्रप्रयाग में—नदी की मड़ल।  
 खं० ५९, पृ० २३८।

**मंगलौर—**

- प्र० वि०—परगने—की सहायकी  
 देव बन्द, जिला सहारनपुर में होने  
 के कारण अम्बुविद्या। खं० ५९, पृ०  
 १२२।

**मिर्जापुर—**

- जिले के बीज गोदामों के  
 विषय में विवरण। खं० ५९, पृ०  
 १७८, १७९, १८०।

—जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ से हानि। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

—में विद्युत् सप्लाई के बारे में पूछ-ताछ। खं० ५९, पृ० ११९।

**भैरठ—**

गवर्नमेन्ट स्कूल, —पर सरकारी व्यय। खं० ५९, पृ० १४।

**मैनपुरी—**

जिला विकास बोर्ड, —तथा उसका खर्चा। खं० ५९, पृ० २८८, २८९।

—की सहकारी समितियों में गबन तथा चुनाव संबंधी शिकायतें। खं० ५९, पृ० २८६—२८८।

—के नोटीफाइड एरियाओं में जनता का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० २९४।

—के स्पेशल मैजिस्ट्रेट व रेवेन्यू अफसर के संबंध में पूछताछ। खं० ५९, पृ० १८४।

—जिला बोर्ड की सब-कमेटियों की समाप्ति। खं० ५९, पृ० २९३, २९४।

—डेवलपमेन्ट बोर्ड के चेयरमैन की अस्वस्थता के कारण कार्य करने में असमर्थता। खं० ५९, पृ० १८६—१८७।

**राजा का सहसपुर—**

अयोध्या शुगर मिल, —और उसके नौकरों के बीच समझौता। खं० ५९, पृ० २७५, २७६।

**रानीखेत—**

—की छावनी का अस्पताल। खं० ५९, पृ० ३२।

—सहसील के हेडक्वार्टर में अस्पताल का अभाव। खं० ५९, पृ० ३२।

**रूपप्रयाग—**

—से भीरी तक की सड़क। खं० ५९, पृ० २७८।

**लखनऊ—**

बलरामपुर अस्पताल, —के कर्मचारियों की लापरवाही। खं० ५९, पृ० २८९—२९०।

महिला विद्यालय कालेज और गवर्नमेन्ट जुबिली कालेज, —में प्रैक्टिकल (आभ्यासिक) तथा म्यूजिक (संगीत) परीक्षाएं। खं० ५९, पृ० १०९।

—नगर के बहुत से मुहल्लों में रोशनी का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०९।

—स्थित कमिश्नर के आफिस को फैजाबाद ले जाने के संरक्ष में पूछ-ताछ। खं० ५९, पृ० २३।

**शेरपुर—**

—, जिला गाजीपुर के किसानों तथा जमींदारों के बीच मनमुटाव। खं० ५९, पृ० १२।

**सहारनपुर—**

जिला —के जुलाहों की सरकारी सहायता। खं० ५९, पृ० २७५।

**सुल्तानपुर—**

—जिला जेल का सेनीटोरियम जेल बनाया जाना। खं० ५९, पृ० १०४।

—जिला जेल के मुर्दों के जलाने या दफनाने का प्रबंध। खं० ५९, पृ० १०४।

—जिले में क्षय के रोगियों की सूची। खं० ५९, पृ० १०४।

—पुलिस का एक बदमाश की गिर-फ्तारी के लिए प्रयत्न। खं० ५९, पृ० १०५।

—में भ्रष्टाचार। खं० ५९, पृ० १०५।

—में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के सिपहसालार द्वारा बालन्टियों की भर्ती। खं० ५९, पृ० १०६।

**स्थायी आदेशों—**

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा —में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४१—६०।

**स्पीकर, माननीय—**

श्री अब्दुल हकीम के निधन पर शोक-संवाद। खं० ५९, पृ० ३६—३८।

श्री भुवनेश्वरी नारायण वर्मा के निधन पर शो-कसंवाद। खं० ५९, पृ० ३४—३६।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के नियमों तथा स्थायी आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव। खं० ५९, पृ० ४६, ४७।

पन् १९४८ ई० के कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४१।

सन् १९४८ ई० के यनाइटेड प्रोविसेज स्टोरेज (रिवीजिशन कंतिन्यूएस आफ पावर्स) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

पन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्त की दुकानों और व्यापारिक संस्थाओं के (संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय अपराध रोकने के (विशेषाधिकार) (अस्थायी) बिल पर महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति की घोषणा। खं० ५९, पृ० ४०।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० १२०, २९५।

ह

हत्याओं—

प्र० वि०—जिला गोंडा में चोरियों, डकैतियों और—की संख्या। खं० ५९, पृ० ११२।

हथियार—

प्र० वि०—प्रान्त के कुछ व्यक्तियों को बिना लाइसेंस— रखने की इजाजत। खं० ५९, पृ० १०३।

हरगोविन्द पन्, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

हरप्रसाद मय्यप्रेमी, श्री—  
देखिए “प्रश्नोत्तर”।

हरिजन—

प्र० वि०—जौनपुर जिले में अदालती पंचायतों और गांव अदालतों में चुने गए—। खं० ५९, पृ० ११०।

हवाई अड्डों—

प्र० वि०—पूर्व में बने हुए—को प्रान्तीय सरकार के अधिकार में लेना। खं० ५९, पृ० १०५।

ह्वालाना कदी—

प्र० वि०—फैजाबाद के—। खं० ५९, पृ० २९०, २९१।

हाउसिंग—

प्र० वि०—आगरा जिले की—कमेटी में फीरोजाबद म्युनिसिपल बोर्ड का प्रतिनिधित्व। खं० ५९, पृ० १८८—१८९।

हानि—

प्र० वि०—मिर्जापुर जिले में लगातार तीन वर्षों से नदियों की बाढ़ ने—। खं० ५९, पृ० १८०, १८१, १८२।

हिन्दी—

प्र० वि०—मन्त्रिवालय में—का प्रयोग। खं० ५९, पृ० १८४—१८५।

होतीलाल अग्रवाल, श्री—

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। खं० ५९, पृ० ४२४—४३८।